

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

तेरहवाँ संस्करण

भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएँ

(Problems of Indian Economy)

(द्वितीय वर्ष टी०डी०सी० के सिलेबस में स्थानित पाठ्य-पुस्तक)

सहमीनारायण नाथूरामका
पूर्व रीडर, अर्थशास्त्र विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, -जयपुर

1990



कॉलेज बुक हाउस

जयपुर-3

(ii)

इस बार कुछ प्रचलित अवधारणाओं जैसे असमानता के विवेचन में गिनी-अनुपात (gini-ratio), विकास की वार्षिक दर के माप, आदि के लिए परिशिष्टों में सांख्यिकीय उदाहरण देकर समझाया गया है ताकि उनके बारे में अधिक मुनिश्चित जानकारी हो सके। "आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण" पर एक स्वतन्त्र अध्याय जोड़ा गया है जिसमें 29 अगस्त 1989 की योजना आयोग द्वारा अनुमादित प्रारूप का विस्तृत विवेचन दिया गया है। जवाहर-रोजगार-योजना पर बेरोजगारी के अध्याय में भी एक विस्तृत नोट लिखा गया है।

आशा है अत्यधिक परिवर्तित व परिवर्द्धित रूप में यह संस्करण विश्व-विद्यालय व प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी व लाभकारी सिद्ध होगा। लेखक ने अपने RAS व IAS वक्षों के "भारतीय सर्व-शास्त्र" के प्रत्यापन के अनुभव के आधार पर विभिन्न खण्डों में काफी नयी व आवश्यक सामग्री जोड़ी है जिससे सभी का बहुत लाभ होगा।

लक्ष्मीनारायण माधूरामका
बी 17-ए, चोमू हाउस कॉलोनी,
सी स्कीम, जयपुर।

Syllabus

Second Year T D C Arts Examination

ECONOMICS

Part II—Problems of Indian Economy

Section 'A

Salient Features of Indian Economy on the eve of Independence

Population—Growth of population and labour force
Occupational distribution

Agriculture—Size and distribution of land holdings, Land Reforms in India Growth of irrigation fertilizer and other inputs, food policy Agricultural credit with special reference to institutional credit

Section 'B

Industry Transport and Labour Role of cottage and small-scale industries Industrial Finance Industrial Policy and Licensing policy Measures to check concentration of economic power Main trends of transport development since 1961 Problems of Trade union movement Social security programmes

Foreign Trade and Foreign Aid—Recent trends in India's foreign trade Foreign trade policy Foreign aid—size and utilization Problems of repayment

Section C

Planning in India—Broad Objectives of Five Year Plans Pattern of public investment under various plans Financing of VI and VII plans A review of economic progress under planning in India Unequal distribution of income and unemployment and underemployment in Indian Economy

Economy of Rajasthan—A brief review of economic resources of the State Land Water Mineral resources and livestock Review of economic progress under planning in Rajasthan with special reference to agricultural and industrial development

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ संख्या

- 1 स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण 1-15
(Salient Features of Indian Economy on the Eve of Independence)
- 2 जनसंख्या, श्रम-शक्ति एवं व्यावसायिक वितरण 16-54
(Population, Labour-Force & Occupational Distribution)
- 3 भू-जोतों का आकार व वितरण—उप-विभाजन व अपसंख्यन की समस्याएँ 55-70
(Size and Distribution of Land Holdings Problems of Subdivision and Fragmentation)
- 4 सिंचाई, उर्वरक व अन्य साधन तथा कृषि में यन्त्रीकरण 71-95
(Irrigation, Fertiliser, Other Inputs and Mechanisation of Agriculture)
- 5 भूमि सुधार 96-122
(Land Reforms)
- 6 खाद्यान्नों का उत्पादन व खाद्य नीति 123-145
(Food Output and Food Policy)
- 7 कृषि-साख 146-169
(Agriculture Credit)
- 8 कुटीर एवं लघु उद्योग 170-192
(Cottage and Small Scale Industries)
- 9 औद्योगिक वित्त 193-228
(Industrial Finance)
- 10 औद्योगिक नीति व लाइसेंस व्यवस्था 229-258
(Industrial Policy and Licensing System)
- 11 भारत में औद्योगिक प्रगति व सातवीं योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरेखना 259-272
(Industrial Growth in India and Strategy For Industrial Growth in the Seventh Plan)

12. निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण व इसकी रोकने के
उपाय 273-300
(Concentration of Economic Power in the Private
Sector and Measures to Check it)
13. 1961 से परिवहन-विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ 301-324
(Main Trends of Transport Development since 1961)
14. श्रमिक-संघ आन्दोलन 325-336
(Trade Union Movement)
15. औद्योगिक विवाद 337-350
(Industrial Disputes)
16. श्रम-कल्याण कार्य तथा सामाजिक सुरक्षा 351-360
(Labour Welfare and Social Security)
17. विदेशी व्यापार में आधुनिक प्रवृत्तियाँ 361-378
(Recent Trends in Foreign Trade)
18. विदेशी व्यापार नीति 379-408
(Foreign Trade Policy)
19. विदेशी सहायता : आकार, उपयोग व मुश्किलों की समस्याएँ 409-429
(Foreign Aid : Size Utilisation & Problems of
Repayment)
20. पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य 430-441
(Objectives of Five-year Plans)
21. भारतीय योजनाओं में सार्वजनिक परिव्यय का रूप, 1951-85 442-461
(Pattern of Public Outlay Under Indian Plans,
1951-85)
22. बीस-बिंदु कार्यक्रम, चलते रहने वाला योजना व भारतीय नियोजन 462-484
(Twenty-Point Programme, Rolling Plan & Indian
Planning)
23. सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 तथा नई आर्थिक नीति 485-502
(Seventh Five Year Plan, 1985-90 and New Economic
Policy)
24. योजनाकाल में आर्थिक प्रगति, 1951-89 503-523
(Economic Progress During Plan Period, 1951-89)
25. योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था 524-542
(Financing the Plans)

26.	भारत में आय का असमान वितरण (Unequal Distribution of Income in India)	543-554
27.	बेरोजगारी तथा अल्परोजगार (Unemployment and Underemployment)	555-590
8	आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण (Approach to Eighth Five-year Plan)	591-600

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

29.	राजस्थान के आर्थिक व मानवीय साधन - भूमि, जल, पशु, खनिज- समृद्धि व जनसंख्या (Economic and Human Resources of Rajasthan : Land, Water, Livestock, Minerals and Population)	1-25
30.	राजस्थान का कृषिगत विकास (Agricultural Development of Rajasthan)	26-48
31.	राजस्थान में भूमि सुधार (Land Reforms in Rajasthan)	49-56
32.	राजस्थान में अकाल व सूखा (Famines and Droughts in Rajasthan)	57-67
33.	राजस्थान का औद्योगिक विकास (Industrial Development of Rajasthan)	68-105
34.	राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम (Public Enterprises in Rajasthan)	106-115
35.	राजस्थान में आर्थिक नियोजन (Economic planning in Rajasthan)	116-153
36.	राजस्थान के बजट व राज्य की वित्तीय स्थिति (Rajasthan Budgets and State Finances)	154-180
परिमिष्ट 1.	चुने हुए प्रश्नों के उत्तर-सूत्र (Hints for Answers to Selected Questions)	181-202
परिमिष्ट 2.	राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर दम्बुनिष्ठ व लघु प्रश्नों पर (Objective and Short-answer questions on the Economy of Rajasthan)	203-225
परिमिष्ट 3.	चुने हुए आँकड़े (Selected Data)	226-235
परिमिष्ट 4.	चुने हुए सन्दर्भ-ग्रन्थ, रिपोर्ट व लेख (Selected Reference Books, Reports and Articles)	236-238

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय

अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण

(Salient Features of Indian Economy
on the Eve of Independence)

सन् 1947 में स्वतन्त्रता की पूर्ण सन्ध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई व प्रविकसित दशा में थी। यह मुख्य रूप में ग्रामीण व कृषि-प्रधान थी। इसमें आर्थिक गतिहीनता व गिरावट के चिह्न विद्यमान थे। विभाजन के बाद भारतीय सघ की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ आकी गयी है। 1951 की जनगणना के अनुसार यह 36.1 करोड़ हो गई थी। इसमें से 85% लोग गाँव में रहते थे जो कृषि व सहायक क्रियाओं में सदियों पुरानी व कम उत्पादक पद्धतियों का उपयोग करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। उस समय जीने की औसत आयु लगभग 32 वर्ष की थी जो 1986 में 57 वर्ष हो गयी है।¹ 1951 में साक्षरता का अनुपात 16% था तथा 6 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 60% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। मलेरिया, चेचक व हैजा जैसी बीमारियों का काफी प्रकोप रहता था और मृत्यु-दर 27 प्रति हजार तक होने के कारण बहुत ऊँची थी जो अब 12 प्रति हजार पर आ गई है। देश में निर्धनता, निरक्षरता व बीमारी के साथ-साथ विभिन्न समूहों व विभिन्न प्रदेशों के बीच आर्थिक साधनों का वितरण भी काफी असमान था।

1947 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये थी और इसमें बहुत धीमी रफ्तार से वृद्धि हुआ करती थी। 1900 से 1947 तक की लगभग पाँच दशान्दियों में इसमें कुल 20% वृद्धि ही हो पायी थी।

1. World Development Report 1988, p. 222.

1950-51 में सकल घरेलू उत्पत्ति (GDP) का 59% अंश प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व सहायक क्रियाएँ) से, 14% द्वितीयक क्षेत्र (खनन, विनिर्माण तथा निर्माण) से तथा 27% तृतीयक क्षेत्र (व्यापार परिवहन, बैंकिंग, सार्वजनिक प्रशासन आदि) से प्राप्त हुआ था। 1987-88 में ये बदल कर क्रमशः 33%, 28% व 39% हो गये हैं। 1950-51 के आकड़ों का आधार वर्ष 1970-71 है, जबकि 1987-88 के आकड़ों का आधार-वर्ष 1980-81 है।¹ इसलिए तुलना में कठिनाई है। फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 1950-51 में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश लगभग 60 प्रतिशत था जो 1987-88 में घट कर 33 प्रतिशत हो गया है। अन्य क्षेत्रों में ये प्रतिशत बढ़े हैं, विशेषतया सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार काफी तेजी से हुआ है। अतः योजना के प्रारम्भ में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान काफी ऊँचा रहता था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय कृषि व उद्योग की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर द्वितीय महायुद्ध (1939-45) तथा देश के विभाजन के क्या प्रभाव पड़े? इनका नीचे उल्लेख किया जाता है।

द्वितीय महायुद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

1. मुद्रास्फीति की समस्या—द्वितीय महायुद्ध ने भारत में महंगाई की समस्या को जन्म दिया। प्रभेजों ने भारत से कई प्रकार का घाल खरीदा जिसका भुगतान पौण्ड-पावना (sterling balances) में किया गया। मार्च 1939 में भारत सरकार पर स्टलिंग कर्ज की देनदारी 470 करोड़ रुपये की थी जो युद्धकाल में समाप्त हो गई तथा मार्च 1946 में भारत के पक्ष में 1740 करोड़ रुपये की स्टलिंग-मुद्रा एकत्र हो गई जिसके आधार पर देश में ज्यादा मुद्रा निकाली गई। इस प्रकार युद्धकाल में भारत ऋणी से ऋणदाता, अथवा कर्जदार से साहूकार देश, बन गया। स्टलिंग राशि का युद्ध-काल में उपयोग नहीं होने दिया गया और भागे चरकर इसमें से प्रथम योजनाकाल में 250 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया। इस प्रकार एक तरफ भारतीय करेंसी की मात्रा बढ़ गई और दूसरी तरफ देश में उपयोग्य वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो गया। भारत में करेंसी की मात्रा 1938-39 में 182 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1948 में 1320 करोड़ रुपये हो गई जो पहले में लगभग सात गुना थी। देश में मुद्रास्फीति के कारण कई प्रकार के प्राथिक नियंत्रणों का महारा लेना पड़ा, जैसे वस्तुओं के आयातों पर नियन्त्रण, साधारण, वस्त्र, चीनी, सीमेंट व इस्पात के मूल्यों व इनके वितरण पर नियन्त्रण,

पंक्तियों में रोजगार 1939 में 18 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 1945 में 31 लाख व्यक्ति हो गया। उद्योगों की प्रचलित उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग किया गया। युद्धकाल में कई नये उद्योग प्रारम्भ किये गये, जैसे एल्यूमिनियम, डीजल इंजन, साइकिलें व सिलार्ड की मशीनें, रसायन जैसे सोडा एश व कॉस्टिक सोडा एवं कई प्रकार के मशीनी औजार व मशीनरी आदि। लेकिन युद्ध का विशेष प्रभाव मध्यम व लघु उद्योगों पर पड़ा जैसे हल्के इन्जीनियरी पदार्थ, दवा व चाकू-छुरी, आदि। युद्ध के तुरन्त बाद रेयोन्, मोटर-गाड़ी, बाल व रोलर बियरिंग, इन्जन आदि उद्योगों में नया विनियोग किया गया। उर्वरक, सीमेंट, काँच आदि उद्योगों में भी उत्पादन की नई इकायाँ स्थापित की गयीं।

युद्ध व युद्धोत्तर काल में औद्योगिक विकास पर मुद्रास्फीति व भ्रम/व की दशाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप दीर्घकालीन दरवा, जैसे सबसे अधिक लाभप्रद स्थान का चुनाव पैमाने का चुनाव, कच्चे माल की उल्लिखित बाजार का प्रकार तथा वित्तीय व तकनीकी संगठन आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका। युद्धकाल में कई शिफ्टों में काम करने तथा बाहर से मशीनों व कल-पुर्जों के आयात में कठिनाई उत्पन्न होने से पुरानी मशीनों व उपकरणों की बदलने की समस्या भी काफी गम्भीर हो गयी थी।

स्मरण रहे कि 1923 के बाद औद्योगिक विकास पर सरकार की विभेदात्मक संरक्षण की नीति (Policy of Discriminating Protection) का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था जो प्रथम फिस्कल आयोग ने 1923 में सुझायी थी। इस संरक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी उद्योग को 'तीन शर्तें पूरी करनी होती थी : (1) उसे प्राकृतिक लाभ हो, जैसे कच्चे माल की बहुतायत, विस्तृत घरेलू माँग सस्ती विद्युत-शक्ति तथा पर्याप्त श्रम की पूर्ति। (2) वह संरक्षण के बिना विन्तुल न पनप सके अथवा आवश्यक तेज गति से न पनप सके, तथा (3) वह आगे चल कर निम्न संरक्षण के विषय की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। इन तीन शर्तों को पूरा करने पर उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जा सकता था, जिससे उस उद्योग के विदेशों से आने वाले माल पर आयात-शुल्क लगा दिये जाने ताकि देश में उस उद्योग का विस्तार हो सके। इस नीति की छत्रछाया में ही भारत में इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, माचिस, कागज आदि उद्योग विकसित हुए। उदाहरण के लिए, चीनी उद्योग को 1932 में संरक्षण प्रदान किया गया था। चीनी मिलों की संख्या 1930-31 में 29 से बढ़कर 1936-37 में 140 हो गयी तथा उत्पाति $3\frac{1}{2}$ लाख टन से बढ़कर 12 $\frac{1}{2}$ लाख टन हो गई और देश चीनी में आत्म-निर्भर हो गया। संरक्षण की यही नीति युद्ध व युद्धोत्तर काल में भी जारी रखी गयी। लेकिन इसमें नये उद्योगों की उपेक्षा होने तथा संरक्षण की शर्तों की अनावश्यक नडाई से लागू करने से संतोषजनक परिणाम

नहीं मिल सके। फिर भी यह नीति कुछ सीमा तक औद्योगिक विकास के अनुभूत सिद्ध हुई और सम्भवतः विदेशी शासन इससे ज्यादा और कुछ कर सकने की सोच भी नहीं सकता था।

देश के विभाजन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव¹

1. कृषि पर प्रभाव—भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूसरा प्रबल प्रभाव देश के विभाजन का पड़ा। इसने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को भकभोर डाला। विभाजन के फलस्वरूप भारतीय संघ में अविभाजित भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77 प्रतिशत, कृषित क्षेत्र का 73 प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत भाग आया। शुद्ध मिचित क्षेत्रफल का 69% भारतीय संघ में आया तथा 31% पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। यह स्मरण रखने की बात है कि उस समय पाकिस्तान में शुद्ध जोते-रोये गये क्षेत्र के 48% भाग में सिंचाई की जाती थी, जबकि भारतीय संघ के लिए यह अंश लगभग 20% ही था। भारतीय संघ के हिस्से में कुल गेहूँ के उत्पादन का 65 प्रतिशत, चावल के उत्पादन का 68 प्रतिशत, तिलहनो के उत्पादन का 55 प्रतिशत, कपास के उत्पादन का 60 प्रतिशत तथा जूट के उत्पादन का 19 प्रतिशत अंश आ पाया था। इसलिए प्रारम्भ से ही भारतीय मद्य की राद्यानों व कच्चे माल के अभाव का सामना करना पड़ा।

2. उद्योगों पर प्रभाव—देश के विभाजन का औद्योगिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव पड़ा। अधिकांश मिल-कारखाने भारतीय संघ के हिस्से में आये तथा उच्च माल के बड़े क्षेत्र पाकिस्तान में रह गये। अनुमान है कि 12675 बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 91% अर्थात् 11,462 औद्योगिक प्रतिष्ठान भारतीय संघ के हिस्से में आये और शेष 9% पाकिस्तान में रह गये। जूट, लोहा व इस्पात व कागज के सभी कारखाने भारत में रह गये। सूती वस्त्र, माचिस, काच व चमड़े के लगभग सभी कारखाने भारत के हिस्से में आये। सीमेंट के 90% कारखाने भारत के हिस्से में आये और शेष पाकिस्तान में रह गये।²

इस प्रकार भारतीय संघ की स्थिति बड़ी औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से ज्यादा अच्छी रही। लेकिन प्रारम्भ में कपास व कच्चे जूट के अभाव के कारण इनके आयात की व्यवस्था करनी पड़ी तथा देश में इनका उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने पड़े।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर द्वितीय महायुद्ध व विभाजन के प्रभावों का दर्शन करने के बाद अब हम स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करेंगे।

1. Report of the National Commission on Agriculture, 1976, Part I, p. 219.
2. Report of the Fiscal Commission 1950, Vol. I, p. 24.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि की दशा (Indian Agriculture on the Eve of Independence)

जैसा कि पहले बतसाया जा चुका है सरकार ने द्वितीय महायुद्ध की अवधि में कृषि में स्थाई सुधार करने के उपाय किये तथा 1943 से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ली। इसके अनुरूप प्रभाव सामने आए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय कृषि की स्थिति का परिचय नीचे दिया जाता है :

क्षेत्रफल—विभाजन के समय भारत में समस्त फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर था जिसमें से 81% खाद्यान्नों में तथा शेष 19% अ-खाद्यान्नों के अन्तर्गत था। इससे 15 वर्ष पूर्व भी लगभग यही स्थिति थी। लेकिन 1939-40 के बाद खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाया गया तथा अ-खाद्यान्नों के अन्तर्गत घटाया गया, जिससे खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का अनुपात कुछ सीमा तक बढ़ा। सरकार ने व्यापारिक फसलों की कृषि को उनके निर्धारित कम हो जाने के कारण सीमित करने की जो नीति अपनायी थी तथा साथ में धरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने की जो नीति अपनायी थी, उसके अच्छे परिणाम मिले।

विभाजन के समय भारत में चावल के अन्तर्गत क्षेत्रफल लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर था जो गेहूँ की तुलना में $2\frac{1}{2}$ गुना था। मुद्रकाल में तिलहन व कपास में से क्षेत्रफल निचलकर खाद्यान्नों की तरफ गया था।

द्विगुणित उत्पादन—जॉर्ज ब्लिन (George Blyn) के अनुसार “1946-47 को समाप्त होने वाले चालीस वर्षों में भारत में खाद्यान्नों में उत्पत्ति की वृद्धि-दर 12 प्रतिशत रही जो जनसंख्या की 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि-दर से बहुत पीछे रह गई थी।”¹ स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व के दो वर्षों में देश में राजनीतिक उथल-पुथल, साम्प्रदायिक दंगों व प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन की घटका पहुँचा। 1930-47 की अवधि में द्विगुणित उत्पादन लगभग स्थिर बना रहा।

द्विगुणित उत्पादकता—विभाजन से पूर्व की अवधि में खाद्यान्नों की उत्पादकता घटी तथा अ-खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ी। 1900-05 की उत्पादकता को 100 मानन पर 1946-47 में खाद्यान्नों की उत्पादकता का सूचकांक 84 तथा अ-खाद्यान्नों का 107 तथा समस्त फसलों का 90.5 रहा। विभाजन के समय प्रति एकड़ उपज न्यूनतम स्तर पर थी तथा उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी।

विभाजन से पूर्व के 40 वर्षों में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल (net cropped area) में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी। 1910 से 1947 के बीच सकल कृषि

1 George Blyn, *Agricultural Trends in India, 1891-1947*, p. 96

क्षेत्रफल (gross cropped area) में केवल 10% वृद्धि हुई थी। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में स्थिरता या गतिहीनता ने चित्त विचलित किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय कृषिगत साधनों या इन्पुटों के सम्बन्ध में

पायी जाने वाली स्थिति

1931-47 की अवधि में भारतीय कृषि पर सिंचाई सुधरे हुए बीज व कृषिगत शिक्षा का कुछ प्रभाव प्रकट होने लगा था। लेकिन उर्वरकों का उपयोग ज्यादातर किसानों व व्यापारिक पसलों तक ही सीमित था क्योंकि इनके लिए सामग्री मूल्य मिल सकते थे। कृषि की विधियाँ पुरानी व गिरावटी हुई थी। किसानों में लोहे के हल भी लोकप्रिय नहीं हो पाये थे क्योंकि इनसे बैलों पर भार पड़ता था तथा इनकी मरम्मत की भी पर्याप्त सुविधाएँ नहीं थीं। इन व जिले हुए क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त भी थे।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत में भावन में हूँ बना गया कपास नूट सम्बन्ध तथा तिलहन की नई व सुधरी हुई किस्मों का उपयोग होने लगा था। कृषिगत शिक्षा का कुछ सीमा तक विस्तार हुआ था लेकिन वह उगाहवर्धन नहीं था।

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

प्रवात जीव भाष्य ने अपनी 1945 की रिपोर्ट में बताया था कि देश में गोबर का 40% मात्र ही खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। शेष में से 40% ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था तथा 20% एक्काई लिए जाने के कारण नष्ट हो जाता था। हडिडको का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता था तथा खाद भी ज्यादातर निर्यात की जाती थी अथवा पशुओं को खिलाई जाती थी।

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत कम मात्रा में हो जाता था क्योंकि लोग इनके सामने से परिचित नहीं थे। द्वितीय महायुद्ध की अवधि में उर्वरकों के आयात घटे। रासायनिक उर्वरकों की कुल उपलब्धि का ज्यादा अंश किसानों व व्यापारिक पसलों में लगाना जाता था, इसलिए किसानों के लिए इसकी बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती थी।

सिंचाई

1945-46 में अविभाजित भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 28.1 मिलियन हेक्टेयर था जो कुल क्षेत्रफल का 2.4% था। इसमें 45% भाग पर सरकारी महरो से सिंचाई की जाती थी। विभिन्न प्रान्तों की स्थिति सिंचाई की दृष्टि से ऐसी नहीं थी। इसी वर्ष पंजाब में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के 59% भाग पर सिंचाई की जाती थी। बंगाल में 17% तथा सी पी (Central Provinces) में 6.6% भूमि में सिंचाई की व्यवस्था थी।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, विमाजन के फलस्वरूप केवल 69% निचिंत क्षेत्रों में भारतीय मध्य के हिस्से में आया तथा शेष 31% पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। पाकिस्तान में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल के 48% भाग में मिचाई की सुविधा थी, जबकि भारतीय मध्य में यह केवल 20% में ही थी। इस प्रकार विमाजन ने मिचाई की दृष्टि से भारतीय मध्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला क्योंकि अधिकांश उपजाऊ व निचिंत क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये थे।

1947-1951 की अवधि में परिवर्तन—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होने से पूर्व की अवधि में कृषिगत उन्नति बढ़ाने के उद्देश्य लिए गए। इस अवधि में समस्त फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ा। इस अवधि में चावल, बाजरे व गेहूँ का उत्पादन बढ़ा। जबकि ज्वार, मक्का, जौ व चने का घटा। बरफा व सूट के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जबकि पिल्लू व गन्ने के उत्पादन में कमी आई।

1947-48 व 1949-50 के बीच शुद्ध निचिंत क्षेत्रफल 13 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा। इनमें अधिकांश वृद्धि कुर्छों व मिचाई के मध्य छोटे भागों से हुई। नहरों व तालाबों की मिचाई लगभग स्थिर बनी रही। मिचाई का अधिक लाभ मुख्यतया खाद्यान्नों की फसलों को मिला।

1950-51 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 28.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि था जिसमें 14.2% भाग पर दल है, 16.7% भाग पर कृषि के लिए उपलब्ध नहीं था, 17.4% भाग मध्य प्रकृति क्षेत्र था (चरागाहों, कुँडों व बजर भूमि के कारण), 9.9% परती भूमि का था तथा 41.8% शुद्ध कृषि क्षेत्रफल था। 1950-51 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र कुल मौसमिक क्षेत्र का 86.5% था तथा शेष 13.5% क्षेत्रफल के लिए अधिक उपलब्ध नहीं थे।

1950-51 में 76.7% क्षेत्रफल खाद्यान्नों के अन्तर्गत था तथा शेष 23.3% अखाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत था। इस प्रकार 3/4 क्षेत्रफल पर खाद्यान्नों का फसल बोयी जाती थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि की स्थिति का मूल्यांकन

1. भूमि-सुधारों की आवश्यकता—स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि काफी पिछड़ी हुई दशा में थी। देश की भूमि-व्यवस्था सामन्ती (feudal) थी जिसमें जमींदारी, महालवादी व रैसतवादी प्रथाओं के अन्तर्गत कृषक व कृषि दोनों गिराई अवस्था में थे। कान्तकारों को बेदमनी व ऊँचे सगनों की स्थिति का सामना करना पड़ना था। भूमि के उप-विमाजन व अपव्ययन के कारण वैज्ञानिक कृषि सम्भव नहीं थी तथा भूमि का वितरण भी काफी असमान था। इस प्रकार भारत 'छोटे कृषकों' का बना हुआ था तथा उत्पादन का स्तर भी नीचा था। कृषि के क्षेत्र में सम्पादन परिवर्तनों प्रथम भूमि-सुधारों की आवश्यकता महसूस की

जा रही थी। कांग्रेस के नारे 'भूमि स्वयं भूमि जोतने वाले की' (Land to the Tiller) को लागू करने की आवश्यकता थी। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान सर्वे भूमि-सुधारों पर बल दिया गया था।

2. कृषि का कमजोर तकनीकी आधार—जहाँ एक तरफ देश की भू-स्वामित्व-प्रणाली दोषपूर्ण थी, वहाँ दूसरी तरफ कृषि का तकनीकी आधार (technical base) भी कमजोर व पिछड़ा हुआ था। कृषकों की आर्थिक स्थिति गिरी हुई होने के कारण वे विनाश के लिए अधिमाधन लगाने की स्थिति में नहीं थे। कृषि बँलों की सहायता से परम्परागत विधि से की जाती थी तथा सुपरे ह्यूबोजी, रासायनिक उर्वरकों, कृषिगत यन्त्रों, माल की पूर्ति, सिंचाई आदि की दृष्टि से काफी अभाव की दशा थी। 1950-51 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 2.1 करोड़ हैक्टेयर था जो शुद्ध कृषित क्षेत्र का 17.6% था। इस प्रकार लगभग 1/6 कृषित भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त थी। 1952-53 में तीनों प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपभोग केवल 66 हजार टन हुआ था। सकल कृषित क्षेत्र के प्रति हैक्टेयर पर उर्वरकों का उपयोग लगभग आधा बिलो था। 1952-53 के ये स्तर कितने नीचे थे इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1987-88 में रासायनिक उर्वरकों का कुल उपभोग बढ़कर लगभग 90 लाख टन हो गया तथा प्रति हैक्टेयर उपभोग लगभग 50 किलो तक पहुँच गया है। उस समय अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) का आविष्कार नहीं हुआ था। 1951 में देश में कुल 9 हजार ट्रैक्टर थे जबकि आज 4 लाख से अधिक हैं। इसी प्रकार 1951 में तेल-इंजनों व विद्युत पम्प-सेटों की संख्या भी काफी कम थी। 1950-51 में प्रति हैक्टेयर चावल का उत्पादन 6.7 क्विंटल था जो 1987-88 में 14.7 क्विंटल एव गेहूँ का 6.6 क्विंटल से बढ़कर 20 क्विंटल हो गया है। इससे पता चलता है कि योजनापूर्व अवधि में प्रति हैक्टेयर चावल व गेहूँ की पैदावार आज की तुलना में काफी कम थी।

कृषकों को साख प्रदान करने की दृष्टि से ग्रामीण साहूकारों व महाजनों का बोलबाला था। इनके लिए सस्थागत साख (सहकारी संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों व सरकारी ऋणों) का नितान्त अभाव था। 1950-51 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों ने कृषकों को कुल 23 करोड़ रु. के कर्ज प्रदान किये थे, जबकि 1987-88 में यह रशि 4057 करोड़ रु. (अल्पकालीन तथा मध्यकालीन व दीर्घ-कालीन कर्ज) हो गई है।

इस प्रकार 1947 में किसान महाजन, व्यापारी व जमींदार के आर्थिक शोषण के शिकार थे और देश के प्रमुख व्यवसाय अर्थात् कृषि की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। द्वितीय महामुद्र की अवधि में कृषिगत सुधार की दिशा में कुछ प्रयत्न अवश्य किए गये थे तथा देश एक राष्ट्रीय खाद्य-नीति के निर्माण की ओर बढ़ रहा था। स्वतन्त्रता

प्राप्ति ने राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति दिलाकर मावी विकास की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार के कंधों पर ढाल दी थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत की औद्योगिक स्थिति

एसी लेखक जी. के. शिरोकोव (G. K. Shirokov) के अनुसार स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय सभी उपनिवेशों व स्वतन्त्र देशों में भारत की औद्योगिक क्षमता सबसे अधिक थी। यहाँ औद्योगिक उपकरणों व अधिक की सरप्ला, सकल औद्योगिक उत्पादित व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य* (Value-added by manufacture) की मात्रा तथा औद्योगिक विविधीकरण अन्य विकासशील रहे जाने वाले देशों से काफी अधिक था। लेकिन इससे अन्य देशों का औद्योगिक विविधीकरण प्रकट होता है, न कि भारत के औद्योगिकरण की विकसित दशा का।¹

1947 में भारतीय कृषि पिछड़ी हुई थी तथा उद्योग अपर्याप्त व अपूर्ण रूप से तथा सीमित दायरे में ही विकसित हो पाए थे। नीचे उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है—

1. देश का औद्योगिक ढांचा (Industrial Structure)—स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगिक ढांचे में निम्न उद्योगों की प्रधानता थी : चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, लोहे व इस्पात की गलाई, रोलिंग, व रिरोलिंग तथा सामान्य इन्जीनियरिंग। 1946-47 में भारत में बिजली योग्य इस्पात का वार्षिक उत्पादन 9.4 लाख टन था जिसमें अक्सेले टिस्को का अंश 80% था। इस प्रकार अकेला टाटा का लोहे व इस्पात का कारखाना इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। उसी समय सूती वस्त्र का जोड़े गये मूल्य (Value-added) में 46% तथा जूट वस्त्रों का 17.5% स्थान था। रोजगार की दृष्टि से भी ये ही उद्योग प्रमुख थे। सूती वस्त्र उद्योग ने कुल रोजगार में 44.4% योगदान दिया, जबकि जूट वस्त्र उद्योग ने 22.5% योगदान दिया। उस समय उपरोक्त उद्योगों का कुल जोड़े गये मूल्य में 84% तथा कुल रोजगार में 86% स्थान था।

1951 में देश में उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों की प्रधानता थी तथा पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव था। 1950-51 में जोड़े गये मूल्य का 70% अंश उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार देश के औद्योगिक ढांचे में उपभोग्य वस्तुओं के कारखानों की प्रधानता थी। भारत का औद्योगिक ढांचा असन्तुलित, अविकसित, विवृत व विपरीत विरम का था।

1 C. K. Shirokov, *Industrialisation of India*, 1973, p. 13.

*विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य को निकालने के लिए उत्पादित के मूल्य में से इनपुटों के मूल्य, अर्थात् कच्चे माल, ईंधन व पावर की लागतें घटायी जाती हैं।

2. व्यावसायिक ढाँचा व राष्ट्रीय उत्पत्ति में विनिर्माण का अंश—1951 में विनिर्माण (manufacturing) व खनन कार्य में श्रम-शक्ति का 9.5% मतलब था तथा कृषकों व खेतिहर मजदूरों का अनुपात 72% था। उस समय उद्योग व खनन में कुल 1.34 करोड़ व्यक्ति कार्यरत थे। इनमें से 35 लाख व्यक्ति संगठित उद्योग व खनन में लगे थे तथा 99 लाख व्यक्ति लघु इकाइयों में लगे हुए थे। 1948-49 में राष्ट्रीय आय लगभग 8,650 करोड़ रु. थी, जिसमें से उद्योगों से लगभग 17% राशि प्राप्त हुई थी। इसमें संगठित उद्योग व खनन से कम राशि प्राप्त हुई थी तथा अगणित क्षेत्र से अधिक राशि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय खनन व उद्योग का रोजगार व राष्ट्रीय आय की दृष्टि से योगदान क्रमशः 9.5% व 17% था।

3 परिवहन व संचार की स्थिति—देश की औद्योगिक स्थिति परिवहन व संचार के विकास पर निर्भर करती है। गणवती व डेसाई के अनुसार 1947 तक भारत परिवहन व संचार की दृष्टि से काफी प्रगति कर चुका था। देश में सड़कों की लम्बाई 3 लाख मील थी जिसमें से 1/3 दूरी में पक्की सड़कें थी। रेलों की लम्बाई 41 हजार मील थी तथा जहाजरानी की माल ढोने की क्षमता 3.3 लाख टन थी। हवाई यातायात विकास की प्रारम्भिक अवस्था में था।

4. विदेशी पूँजी व भारतीय उद्योग—1948 में भारत में दीर्घकालीन विदेशी निजी विनियोग की राशि 320 करोड़ रु. थी जिसमें से 25% राशि खनन व निर्माण उद्योगों में लगी हुई थी। उद्योगों में कुल विनियोग का 16% खनन में 34% वस्त्र में तथा 8% लौह धातुओं के उद्योगों में लगा हुआ था। औद्योगिक विनियोग का 72% ब्रिटेन के द्वारा तथा 6.4% संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लगाया हुआ था। विदेशी एकाधिकारियों का घरेलू बाजार पर लगभग एक-चौपाया नियन्त्रण था।

शिरोकोव का मत है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय पूँजी विदेशी पूँजी से ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। भारतीय उद्योगपतियों का देश के उद्योगों तथा बाजार पर अधिक प्रभाव था। इनके हाथों में पूँजी का केन्द्रीकरण भी अधिक था।

■ विनिर्मित माल का आयातों में स्थान—1947-48 में भारत के खनन व विनिर्मित माल का सकल मूल्य लगभग 1,500 करोड़ रु. था। आयातित माल की लागत इसका लगभग $\frac{1}{3}$ थी। उत्पादक वस्तुओं के आयात पर भारत की निर्भरता अधिक थी। यदि स्वदेशी बाजार में माल की माँग घरेलू उत्पादन व आयात के जोड़ के बराबर मानी जाए, तो 1948 में आयातित माल की मात्रा कॉस्टिक सोडा, साइक्लो, अमोनियम सल्फेट, जीट काच तथा एल्यूमिनियम में इनकी कुल माँग का काफी ऊँचा अंश थी। देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय अधिकांश मशीनरी बाहर

से मगायी जाती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय देश में सूती वस्त्र मशीनरी को छोड़कर अन्य मशीनें नहीं बनती थी। इस प्रकार मशीनों, औजारों व उपकरणों के लिए देश पूर्णतया आयाती पर निर्भर रहता था।

6. श्रम की नीची उत्पादकता—उस समय भारत में बड़े व विकसित उद्योगों में श्रम की उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में नीची थी। उदाहरण के लिए 1949 में सूती वस्त्र उद्योगों में प्रति श्रम घण्टे सूत का उत्पादन भारत में 1.9 किलोग्राम, जापान में 3.3 किलोग्राम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 6.9 किलोग्राम होता था। 1947 में भारत में प्रति श्रमिक सकल उत्पत्ति का मूल्य 5,000 रुपये था, जबकि ब्रिटेन में (1948 में) यह 24,400 रुपये था (लगभग पाँच गुना)। इससे भारत व अन्य विकसित देशों के बीच श्रम की उत्पादकता के अन्तर का पता लगता है।¹

7. औद्योगिक दक्षता, औद्योगिक श्रम तथा औद्योगिक वित्त आदि—1947 में देश में दक्ष श्रमिकों का अभाव था। टाटा समूह ने स्वदेशी दक्षता को विकसित करने का प्रयास किया था। उस समय देश में आधुनिक फैक्ट्री क्षेत्र में 20 लाख श्रमिक कार्यरत थे। यह कुल प्रम-शक्ति का 2% था। समय के साथ-साथ श्रम-शक्ति स्थिर होती जा रही थी। औद्योगिक वित्त देश की व्यावसायिक फर्मों के स्वयं के साधनों से प्रदान किया जाता था जो व्यापार करने व उधार देने से प्राप्त हुआ था। देश में 400 संयुक्त पूँजी वाले बैंक व शाखाएँ थी। देश में शहरीकरण की वृद्धि हो रही थी। 1951 में 17.6% व्यक्ति शहरो में निवास करते थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक स्थिति का मूल्यांकन

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था, हालांकि अन्य कई विकासशील देशों की स्थिति भारत से भी बदतर थी। यहाँ का औद्योगिक ढांचा विकृत व असन्तुलित था। इसमें उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों की प्रधानता थी तथा पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का निम्नतम अभाव था। ब्रिटिश-शासन काल में स्वदेशी उद्योगों का पतन हुआ, लेकिन उनका स्थान लेने के लिए आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के कारखाने पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हो पाये। इस प्रकार देश को एक तरफ से अनौद्योगीकरण (de-industrialisation) की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। इसके अन्तर्गत देश का पुराना उद्योग प्रायः नष्ट होते गये, लेकिन इनका स्थान नये उद्योग नहीं ले पाये। फिर भी उस समय देश में सूती वस्त्र, जूट, चीनी, वनस्पति तेल व कई प्रकार के अन्य कारखाने विद्यमान थे। पूँजीगत वस्तुओं के कारखानों का काफी अभाव था। मुदीर व ग्रामीण उद्योगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा

था। उद्योगों के लिए वित्त व विकास की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय व राज्यीय स्तरों पर निगमों का सर्वेया प्रभाव था। 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के गैर-विभागीय औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल 5 औद्योगिक उपक्रम थे जिनमें त्रिनियोजित पूँजी की राशि केवल 29 करोड़ रु. थी, जबकि 31 मार्च 1988 को यह 221 उपक्रमों में 71,299 करोड़ रु. हो गई है।

चूँकि अंग्रेज भारत को 'रुखे माल का उत्पादक देश' ही देगना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी औद्योगिक नीति प्रस्तुत नहीं की जो औद्योगिक विकास की दिशा में देश को आगे बढ़ा सके। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति, औद्योगिक टेक्नोलॉजी, औद्योगिक विकास, औद्योगिक वित्त व औद्योगिक प्रबंधन की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं जिनका वर्णन आगे चलकर परामर्शान किया जायगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय सार्वजनिक वित्त की स्थिति—

ब्रिटिश भारत में भू-राजस्व (land-revenue) में 1946-47 में 31.3 करोड़ रु. की आय प्राप्त हुई थी जो नग्न कृषिगत आय का केवल 2% थी।

उस समय सार्वजनिक व्यय व कुल राजस्व की स्थिति इस प्रकार थी—

	सार्वजनिक व्यय (करोड़ रु.)	कुल राजस्व (करोड़ रु.)
1946-47	797.3	594.2
राष्ट्रीय आय का अंश	16%	12%

इस प्रकार 1946-47 में सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय का 16% तथा कुल राजस्व राष्ट्रीय आय का 12% था। उस समय केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों का करोड़ों में कुल आय 442 करोड़ रु. की हुई थी जिसमें ग्स्टम्स (आयात-निर्यात शुल्कों) का स्थान 22%, उत्पादन-शुल्कों का 22%, तथा आय-करोड़ का 37% था। कुल सार्वजनिक व्यय का 26% अंग सुरक्षा पर व्यय किया जाता था जो काफी ऊँचा था।

सारांश—उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशिक (colonial), अर्द्ध-सान्नी (semi-feudal), पिछड़ी हुई (backward), गतिहीन (stagnant), पूँजी की जमीन से वंचित (depleted) तथा अंग-भंग या अंग-विच्छेदित (amputated) जिम्मे की अर्थव्यवस्था थी। इसका उपनिवेशिक स्वरूप तो इस प्रकार सामने आया कि अंग्रेजों ने भारत को अपने लिए अच्छे माल का स्रोत व विनिर्मित माल का

वाज़ार बना दिया था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिटिश पूँजी का प्रवेश हो गया था। यह छद्म-सामन्ती इसलिए था कि जमींदारी बन्दोबस्त के अन्तर्गत वास्तविक रूप से लगान वसूल करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर दिये गये तथा उद्योगों में भारतीय व विदेशी पूँजीवादी क्षेत्र विकसित हो गया। वह पिछड़ी हुई इसलिए थी कि कृषि पर 70% श्रम-शक्ति निर्भर थी तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत नीची थी और भारत मशीनों के लिए पूर्णतया विदेशों पर आश्रित था। यह गनिमिनी इसलिए थी कि ब्रिटिश शासन काल में लगभग एक जनाश्री तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक शृद्धि-दर मुश्किल में आया प्रतिशत हो पायी थी तथा देशव्यापी सभी अवधि तक उपनिवेशीय व सामन्ती शोषण के शिकार रहे। द्वितीय महायुद्ध की अवधि में अर्थव्यवस्था में पूँजी की काफी कमी आ गई थी क्योंकि विदेशों से मशीनों व कच्चे-पुर्जों का आयात नहीं किया जा सका था, जिससे युद्ध के बाद देश में वास्तविक पूँजी में गिरावट प्रतीत होने लगी थी। उस समय पूँजी-निर्माण की दर राष्ट्रीय आय की 6% थी। इसी प्रकार इसे अग्रगण्य या अग्रविच्छेदित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा गया कि 1947 में राजनीतिक विभाजन के कारण देश के टुकड़े हो गये जिससे पीछे मूलत: अंग्रेजों की 'विभाजन करो व शासन करो' (divide and rule) की नीति ही जिम्मेदार थी। हम देख चुके हैं कि विभाजन ने भारतीय सभ में किस प्रकार कच्चे माल व साधनों का अभाव उत्पन्न कर दिया था। देश को बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों तथा शरणाधिकियों की समस्या का सामना करना पड़ा था।¹

उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था, हालांकि देश में परिवहन की व्यवस्था व प्रशासनिक ढांचा आर्थिक विकास का आधार प्रदान करने की दृष्टि से विद्यमान थे। यदि केवल भावी विकास की सम्भावनाओं की दृष्टि से ही देखा जाय तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, हालांकि यह विश्व के कई अन्य विकसशील देशों की तुलना में अपेक्षा कम थी। इतने पर भी कृषि में प्रति हैक्टेयर उपज कम थी एवं इसमें भूमि-सुधार व तकनीकी परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। देश में पूँजीगत व उदात्त वस्तुओं के उद्योगों का निरन्तर अभाव था तथा औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए गरीब उद्योगों का विकास करना आवश्यक समझा जा रहा था। साथ में लघु उद्योगों की समस्याओं का समाधान करना भी आवश्यक था। इस प्रकार देश में आर्थिक विकास की विनाश सम्भावनाएँ विद्यमान थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के

1. K.S. Gill, *Evolution of the Indian Economy*, Second Edition, May, 1985, Chap. 3. (NCERT Publication).

बाद भारत सरकार ने नियोजित विकास की पद्धति के द्वारा देश के प्राथमिक साधना का विदोहन, संरक्षण व उपयोग करके जनता का जीवन-स्तर ऊँचा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रागे के अध्यायो में योजनाकाल में विविध क्षेत्रों में हुई प्राथमिक प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्न

- 1 सन् 1947 में भारतीय कृषि व उद्योगों की मूलभूत विशेषताएँ क्या थीं ? क्या उस समय ये दोनों पिछड़ी अवस्था में थे ?

(Raj Iyer T D.C , 1987)

- 2 स्वतन्त्रता की पूर्व सन्ध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएँ थीं ?

(Raj Iyer T D C., 1982, 1984 and 1986)

- 3 स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या थे ? तब से अब तक क्या विशेष परिवर्तन आये हैं ?

(Raj Iyer T D C , 1989, ऐसा ही प्रश्न 1988)

[उत्तर—संकेत—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय कृषि व उद्योग पिछड़ी दशा में थे। कृषि में सामंती प्रथा का बोलबोला था। मध्यस्थ-वर्ग का प्रभाव था। महाजन व गाँव के व्यापारी कृषक से ऊँचा व्याज लेकर उसका शोषण करते थे। कृषि में सिंचाई, उर्वरकों, उत्तम बीजों व अन्य इनपुटों का अभाव था। साल की सुविधाएँ कम थीं। कृषि परम्परागत व जीवन-निर्वाह का साधन मात्र थी।

योजनाकाल में भूमि-सुधारों के अन्तर्गत मध्यस्थ-वर्ग को समाप्त किया गया है। सस्यागत साल के माध्यम से सहकारी साल का विकास किया गया। सहकारी बित्री का भी विकास हुआ है तथा कृषि में उन्नत बीजों उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, आदि का उपयोग बढ़ा है। 1966 से हरित क्रान्ति हुई है। कृषि का आधुनिकीकरण व व्यवसायीकरण हुआ है। अब किसान बाजार के लिए फसल उगाने लगा है।

इसी प्रकार योजनाकाल में उद्योगों में विविधता आयी है। मशीना व रासायनिक पदार्थों के कारखाने विकसित हुए हैं। नई सूर्योदय-उद्योग (sun-rise industries) जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रो-रासायन व कम्प्यूटर आदि विकसित हुए हैं। उद्योगों के लिए वित्त की नई व्यवस्था सामने आयी है। औद्योगिक प्रबन्ध-व्यवस्था बदली है। औद्योगिक टेक्नोलोजी उन्नत हुई है। औद्योगिक नीति के फलस्वरूप औद्योगिक विकास की दर तेज हुयी है। देश का औद्योगीकरण किया गया है।

भारत ने आत्म-निर्भरता, आधुनिकीकरण, विकास, समानता, आदि की दिशाओं में कदम बढ़ाये हैं। लेकिन मविध्य में पचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की दिशा में आवश्यक कदम उठाने बाकी हैं, जिसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।]

2

जनसंख्या, श्रम-शक्ति एवं

व्यावसायिक वितरण

(Population, Labour-Force and Occupational Distribution)

भारत में जनसंख्या की वृद्धि

जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद काफी रुचिप्रद है। चन्द्रगुप्त मौर्य (200 ईसा पूर्व) के समय से लेकर ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों (1845) तक भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ पर स्थिर बनी रही। आज के भारतीय मध्य की जनसंख्या 1845 में 10 करोड़ से बढ़कर 1981 की जनगणना के अनुसार 68.52 करोड़ (घनम व जम्मू-कश्मीर सहित) हो गई है, जो पूर्व सरकारी अनुमानों से घटिक निकली है। इस प्रकार 136 वर्षों की अवधि में यह लगभग सात गुनी हो गयी है। विश्व के प्रत्येक सात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय माना जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 1988 के अनुसार 1986 के मध्य में भारत की जनसंख्या लगभग 78.1 करोड़ व्यक्ति थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की 24.2 करोड़ तथा सोवियत मध्य की 28.1 करोड़ थी। अतः भारत की जनसंख्या अमेरिका व सोवियत मध्य की मिला-जुमी जनसंख्या से भी अधिक है। एक और रुचिप्रद तुलना इस प्रकार के की जा सकती है कि भारत की जनसंख्या अमीरात के समस्त 55 देशों व लेटिन अमेरिका की जनसंख्या के जोड़ के बराबर आती है। भारत में विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत भाग आता है तथा यहाँ की जनसंख्या विश्व की कुल भाग के 1.6 प्रतिशत भाग पर अपना मुजारा करती है। विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है और 1986 के मध्य में वहाँ की जनसंख्या 105.4 करोड़ व्यक्ति हो गई थी।

1901 में भारत की जनसंख्या लगभग 23.8 करोड़ थी जो बढ़कर 1981 में 68.5 करोड़ हो गई है। अब देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.6 करोड़ व्यक्ति

जनसंख्या में जुड़ जाते हैं जो आस्ट्रेलिया की वर्तमान जनसंख्या के बराबर हैं। इस प्रकार यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत प्रतिवर्ष एक नया आस्ट्रेलिया उत्पन्न कर देता है। निम्न तालिका में 1911-1981 तक की अवधि के लिए भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर्शायी गई है—

1911 से 1981 तक की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि-दर¹

वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	दस वर्षों की वृद्धि दर (%)
1911	25.2	5.7
1921	25.1	(—) 0.3
1931	27.9	11.0
1941	31.9	14.2
1951	36.1	13.3
1961	43.9	21.6
1971	54.8	24.8
1981	68.52*	25.0

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि 1921 तक काफी अनियमित तथा घीमी बनी रही, लेकिन 1921 के बाद यह काफी तीव्र हो गई। 1951 के जनगणना अधिकारी ने वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या

1. Statistical Outline of India 1988-99, June 1988, p. 39, (Tata Services Limited), ये अनुमान 1 मार्च के लिये हैं, केवल 1971 की जनगणना के लिये 1 अप्रैल से सम्बद्ध है।*

* के. सुन्दरम का मत है कि 1981 की जनगणना में कुछ लोग गिनती से छूट गये थे, विशेषतया 0-4 वर्ष के आयु-समूह में जनसंख्या की गिनती कम हुई है। उसी सुधारने पर 1 मार्च, 1981 को मशोचित जनसंख्या 70.35 करोड़ आती है, जो जनगणना के अंक से 1.8 करोड़ अधिक है। इतने लोग गिनती से भले ही छूट जायें, लेकिन वे भोजन, वस्त्र व रोजगार वगैरह तो अवश्य मांगेंगे। अतः इन पर ध्यान देना आवश्यक है। ये जनसंख्या के भावी अनुमानों को भी प्रभावित करेंगे। देखिए—

K. Sundaram, Registrar General's Population Projections 1981-2001, An Appraisal and Alternative Scenario, EPW, August 25, 1984, p. 1479.

के इतिहास में एक महान विभाजन (The great divide) बतसाया है क्योंकि इससे पूर्व जनगणना में प्रकाश, अमेरिका व अन्य महाशक्तियों के प्रयोग के कारण वृद्धि नहीं हो सकी थी। उच्च 1911-21 के बीच में कुल जनगणना में थोड़ी गिरावट आई थी। पिछले 40 वर्षों में विकास की गुणियाओं के बहून एक गाढ़ापा की पूर्ति के अग्रिम नियमित होने से जनगणना में तेजी से वृद्धि हुई है। 1921-51 तक तो जनगणना की दर वार्षिक वृद्धि की दर 11 में 14 प्रतिशत के बीच में रही थी। लेकिन 1951-61 के बीच में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस अवधि में 21 (प्रतिशत वृद्धि की दर प्रथम लगभग 7.8 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि वास्तव में जनगणना की दृष्टि से एक विशाल संख्या को उत्पन्न करने वाली रही है। यदि 1921 के वर्ष को एक 'महान विभाजन' (A great divide) कहा जाय तो 1951-61 की अवधि को 'आगे एक सम्पी छलाव' (A great leap forward) कहा जा सकता है। 1961-71 की अवधि में दशवर्षीय वृद्धि-दर 24 में प्रतिशत तथा 1971-81 की अवधि में 25 प्रतिशत रही है।

1971-81 के दशक में भारत में जनगणना की वार्षिक वृद्धि दर 2.2%, रही जो पिछले दशक में समान थी। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट (1988) के अनुसार 1980-86 की अवधि में जापान में जनगणना की वार्षिक वृद्धि-दर 0.7%, अमेरिका की 1%, रूस की 1% तथा समुदाय दर अमेरिका की 5.6% रही। यू.के. में यह केवल 0.1% तथा फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में यह (-) 0.2% तथा इसी अवधि में भारत के लिए यह 2.2% रही। इस प्रकार विकसित देशों में जनगणना की वृद्धि दर काफी नीची पायी जाती है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी व हंगरी में तो यह ऋणात्मक हो गयी है।

भारत में प्रतिवर्ष 1.6 करोड़ व्यक्तियों का बढ़ जाता रोजगार, कीमती, उपयोग के स्तर प्रति व्यक्ति भारतविश्व प्रायः, आदि पर प्रतिभूत प्रभाव डालने वाला तत्व है। हमारे देश में प्रत्येक डेढ़ सैकड़ में एक बच्चा जन्म लेता है। एक वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और लगभग 90 लाख व्यक्ति मर जाते हैं। इस प्रकार 1.6 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष जनगणना में जुड़ जाते हैं। भारत में जनगणना की वृद्धि की गम्भीरता इस बात से जानी जा सकती है कि 1971-81 की अवधि में जो 13.7 करोड़ की वृद्धि हुई जो जापान की वर्तमान जनगणना 12 करोड़ से अधिक थी। इसी प्रकार 1951-81 के 30 वर्षों में जो 32.4 करोड़ व्यक्तियों की जो वृद्धि हुई वह सोवियत गण (28.1 करोड़ व्यक्ति) अथवा अमेरिका (24.2 करोड़ व्यक्ति) से भी अधिक की कुल वर्तमान जनगणना से अधिक थी। 1989 के मध्य में भारत की जनगणना 82 करोड़ से कुछ अधिक मानी जा सकती है जबकि 1951 में यह 36 करोड़ थी। इस प्रकार जनगणना की दृष्टि से योजनाकाल में एक नया भारत का निर्माण और हो गया है।

विभिन्न राज्यों में 1971-81 की अवधि में जनसंख्या की दशवर्षीय वृद्धि दरें—भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की दशवर्षीय वृद्धि-दरों में काफी असमानता पाई गई है। 1971-81 की अवधि में समस्त देश में जनसंख्या की वृद्धि-दर 25 प्रतिशत रही है। इसी अवधि में दिल्ली राष्ट्रीय प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि-दर 53 प्रतिशत रही, जबकि तमिलनाडु में यह 17.5 प्रतिशत ही रही। कुछ अन्य राज्यों में वृद्धि-दरें इस प्रकार रही—आंध्र-प्रदेश 23.1% असम 36.1%, बिहार 24.1%, पंजाब 23.9%, उत्तर प्रदेश 25.5, मध्य प्रदेश 25.3%, राजस्थान 33%, पश्चिमी बंगाल 23.2%, गुजरात 27.7%, कर्नाटक 26.8% तथा केरल 19.2%। इस प्रकार केरल व तमिलनाडु में यह 20% से कम रही है। राजस्थान में 33% वृद्धि-दर काफी ऊंची रही है।

1981 में भारत की कुल जनसंख्या 68.52 करोड़ व्यक्ति भी जिसमें उत्तर-प्रदेश का अंश 16.2%, बिहार का 10.2%, महाराष्ट्र का 9.2%, पश्चिम बंगाल का 8% तथा राजस्थान का 5% था। इस प्रकार देश की लगभग आधी आबादी इन 5 राज्यों में केन्द्रित थी।

भारत में जन्म-दर व मृत्यु-दर सम्बन्धी आंकड़े

किसी भी देश में जन्म-मृत्यु, स्वास्थ्य व सौख्य आगु से सम्बन्धित आंकड़ों को 'जन्म-मरण के आंकड़े' (Vital Statistics) कहते हैं। भारत में ये आंकड़े बहुत अपूर्ण तथा कम विश्वसनीय माने जाते हैं। हमारे देश में जन्म व मृत्यु की स्थिति का ठीक से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। यही कारण है कि भारत में जन्म-दर व मृत्यु-दर के रजिस्ट्रेशन से प्राप्त व जनगणना से प्राप्त आंकड़ों में अंतर पाया जाता है।

1981-85 की अवधि में जन्म-दर 33.2 प्रति हजार तथा मृत्यु-दर 12.2 प्रति हजार एवं जनसंख्या में वृद्धि-दर 21.0 प्रति हजार आंकी गई थी। लेकिन बाद के अध्ययन में पता चला है कि जन्म-दर 34.6 प्रति हजार तथा मृत्यु-दर 12.4 प्रति हजार एवं जनसंख्या की वृद्धि-दर 22.2 प्रति हजार रही है। यह एक चिंता का विषय है। 1980 में शिशु मृत्यु-दर (Infant mortality rate) (प्रथम जन्म दिवस पूरा करने से पहले अथवा एक वर्ष से कम आयु में मर जाने वाले शिशुओं की संख्या) प्रति एक हजार जीवित जन्में शिशुओं पर 114 हो गई थी। उत्तर के दशक में यह 125 प्रति हजार थी। विभिन्न राज्यों में जन्म-दर व मृत्यु-दर में अंतर पाये जाते हैं। आज भी जन्म-दर उत्तरप्रदेश में 40.4 प्रति हजार है, जबकि केरल में यह केवल 25.2 प्रति हजार है। इसी प्रकार मृत्यु-दर उत्तर प्रदेश में 20.2 प्रति हजार है, जबकि केरल में यह 7 प्रति हजार है।

1. Statistical Outline of India 1988-89 (Tara Services Ltd.) p. 34.
2. Seventh Five Year Plan 1985-90, Mid-term Appraisal, p. 195.

भारत में पिछले 40 वर्षों में जन्म-दर व मृत्यु-दर दोनों में गिरावट आयी है, मृत्यु-दर में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आयी है। इतना होने पर भी ये दोनों दर अन्य देशों की तुलना में ऊँची हैं।

चुन हुए देशों की जन्म-दरें व मृत्यु-दरें निम्न तालिका में दी जाती हैं :

प्रति एक हजार जनसंख्या पर (वर्ष 1986)		
देश	कूट जन्म-दर	कूट मृत्यु-दर
संयुक्त राज्य अमेरिका	16	9
जर्मनी (फेडरल रिपब्लिक)	10	12
रूस	19	10
जापान	12	7
भारत	32	12

इस प्रकार विश्व के औद्योगिक देशों में जन्म-दर व मृत्यु-दर दोनों काफी नीची हैं। न्यूनतम जन्म-दर 10 प्रति हजार फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में पहुँच गई है, जहाँ यह मृत्यु-दर 12 प्रति हजार से भी कम है। जापान में मृत्यु-दर 7 प्रति हजार है जो काफी कम है। उपर्युक्त तालिका में अधिकांश देशों में जन्म-दरें भारत की तुलना में आधी या उससे भी कम हैं।

भारत में पिछले वर्षों में मृत्यु-दर में गिरावट के निम्न कारण रहे हैं—

देवायुषी मलेरिया व अन्य महामारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य में सुधार व पीने के पानी की सुविधाएँ एवं दवाओं का अधिक प्रयोग। नवित्य में मृत्यु-दर के घटने की सम्भावनाएँ हैं।

जनसंख्या वृद्धि के भावी अनुमान

सातवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप, खण्ड I के अनुसार जनसंख्या के भावी अनुमान इस प्रकार हैं।¹

वर्ष	अनुमानित जनसंख्या (करोड़ों में)
एक मार्च को	
1986	76.1
1991	83.7
1996	91.3
2001	98.6

1. Seventh Five Year Plan 1985-90 Vol. I, pp. 11-12, table 2.1.

इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि-दर 1981-86 की अवधि में 21.0 प्रति हजार से घट कर 1996-2001 की अवधि में 15.3 प्रति हजार हो जायेगी। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट (1988) के अनुसार भारत की जनसंख्या 2000 में 100.2 करोड़ हो जायेगी। अतः इसीसवी शताब्दी की पूर्वसंध्या में भारत में लगभग एक अरब जनसंख्या हो जाने की सम्भावना है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया है कि भारत में शुद्ध पुनरुत्पादन की दर (Net Reproduction Rate or NRR) 2006-2011 की अवधि में 1 के बराबर हो पायेगी। तब देश की जनसंख्या में स्थिरता की प्रवृत्ति होगी। यह तभी सम्भव होगा जबकि परिवार का औसत आकार 4.2 बच्चों से घट कर 2.3 बच्चे हो जाय एवं जन्म-दर 21 प्रति हजार व मृत्यु-दर 9 प्रति हजार हो जाय तथा 60% दम्पति परिवार-नियोजन के उपाय अपनाय लगे।

$NRR = 1$ का आशय यह है कि माताओं की प्रत्येक पीढ़ी अपने पीछे अपनी सलाह के बराबर ही पुत्रियाँ छोड़ कर जाती हैं, जिससे आगे चलकर जनसंख्या स्थिर हो जाती है।

कै. सुन्दरम ने अपने पूर्ववर्णित लेख में अनुमान लगाया है कि भारत की जनसंख्या 1981 में 70.35 करोड़ से बढ़कर 2001 में 105 करोड़ हो जायेगी। इस प्रकार इसमें औसतन प्रतिवर्ष 1.7 करोड़ की वृद्धि होगी। आगामी वर्षों में श्रम-शक्ति भी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। अनुमान है कि 1990 की दशाब्दी में श्रम-शक्ति में प्रतिवर्ष 1 करोड़ की वृद्धि होगी तथा शहरी जनसंख्या का अनुपात 1981 में 23.5% से बढ़कर 2001 में 31.5% हो जायेगा। इन कारणों की वजह से भारतीय नियोजन में शहरी नियोजन अथवा शहरी-पक्ष पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो जायेगा ताकि शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का सामना किया जा सके।

भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारण

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, ऊँची जन्म-दर भारत में जनसंख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण है। पिछले वर्षों में मृत्यु-दर घटने से जनसंख्या की वृद्धि और भी अधिक होने लगी है। लेकिन आधारभूत कारण अभी तक वही है। अतः जो कारण जन्म-दर को ऊँचा रखते हैं वे ही कारण भारत में जनसंख्या की वृद्धि के लिए प्रमुखतया उत्तरदायी माने जा सकते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारण निम्नांकित हैं—

(1) जलवायु व भौतिक परिस्थितियाँ—गर्म देशों में ठण्डे देशों की तुलना में शादी जल्दी की जाती है, क्योंकि जलवायु के प्रभाव से परिपक्वता की अवस्था (maturity) शीघ्र ही आ जाती है। इसलिए सन्तानोत्पत्ति की अवधि अधिक होने से जन्म-दर का ऊँचा होना स्वभाविक है।

(2) **आर्थिक कारण**—प्रायः देखा गया है कि निर्धन व्यक्तियों के परिवार बड़े होते हैं, जबकि सम्पन्न व्यक्तियों के परिवार छोटे होते हैं। निर्धन परिवारों में एक नये बच्चे के आने से रहन-सहन के स्तर पर विशेष प्रभाव महसूस नहीं होता, क्योंकि इनमें रहन-सहन के स्तर का अर्थ ही नहीं समझा जाता है और कई बार तो आने वाला बच्चा छोटी उम्र में ही काम करने लग जाता है जिससे परिवार की आय आय में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। इसलिए गरीब परिवारों में शादी व सन्तानोत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत असावधानी बरती जाती है। पाश्चात्य देशों में ऊँचे जीवन स्तर के कारण जन्म-दर नीची पाई जाती है।

(3) **सामाजिक व धार्मिक कारण**—(1) शादी की अनिवार्यता—भारत में शादी केवल जन्मी ही नहीं होती बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को शादी करना होती है। शादी की प्रथा सर्वव्यापक है। शादी ऐच्छिक नहीं, बल्कि अनिवार्य मानी जाती है। एक विशेष अवस्था प्राप्त करने पर प्रत्येक व्यक्ति को शादी के बन्धन में बधना पड़ता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शादी की उम्र तक पहुँचने के कुछ वर्ष बाद शादी नहीं करना चाहे तो उसे सामाजिक बाढ़ावरण ऐसा नहीं करने देता। इसलिए आय शादी के लायक प्रत्येक व्यक्ति को शादी कर दी जाती है। भारत में गरीबी शादी में बाधक न होकर साधक होती है। अमीरों के परिवार में नई बहू भी काम-काज में हिस्सा बँटाती है और यह केवल घर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि दैनिक आर्थिक कार्य में भी पाया जाता है।

(1) **कम उम्र में शादी**—भारत में सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनेक वर्गों में शादी की आयु अपेक्षाकृत नीची रहती है। जनसंख्या-विशेषज्ञों का मत है कि यदि लड़की की शादी 15 वर्ष के स्थान पर 20-21 वर्ष में होन लग जाय तो इसका प्रभाव जन्म-दर को घटाने पर काफी प्रबल रूप में सामने आयेगा। शिक्षा के प्रसार से यह कार्य वास्तव में हो गया है। लेकिन अभी तक हम दिशा में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

(ii) **समूक्त परिवार प्रणाली का प्रभाव**—भारत में समूक्त परिवार प्रणाली की प्रतीक रूप से जन्म-दर घटाने में सहायक सिद्ध हुई है। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जितनी सावधानी व समझदारी बरती जाती है, उतनी समूक्त परिवार में नहीं बरती जाती। कारण यह कि एक नया

1. कुछ पुस्तकों में जनसंख्या की वृद्धि के कारणों में 'बाल-विवाह' का भी उल्लेख मिलता है। हमारे मत में बाल-विवाह एक सामाजिक अनिष्ट या कुप्रथा अवश्य है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि की दृष्टि से 'कम उम्र में शादी' का प्रभाव स्वीकार करना ही काफी होगा।

वच्चा बड़े परिवार में विशेष भार मासूम नहीं पड़ता। सीमित परिवार में सम्पन्न में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के पनपने के लिए व्यक्तिगत परिवार प्रणाली अधिक अनुकूल मानी गई है।

(iii) धार्मिक व सामाजिक विश्वास एवं संस्कृति का प्रभाव—भारत में शादी के बाद कम से कम एक पुत्र उत्पन्न होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि माता-पिता की मोक्ष के लिए एक पुत्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिनके केवल लड़कियां होती रहती हैं वे एक लड़के की प्रतीक्षा में परिवार को बढ़ाते जाते हैं। ऐसा प्रायः शिक्षित व अशिक्षित सभी प्रकार के परिवारों में देखने को मिलता है। जिनके केवल लड़के होते हैं वे उनको परिसम्पत्ति (asset) मानने के कारण परिवार-नियोजन में सीधता नहीं साते। जब लड़के-लड़की की स्टेटस बराबर होगी, तब वे मनोदशाएँ बदलेंगी। इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है। यही नहीं बल्कि बड़े परिवार ईश्वर का वरदान समझे जाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक व धार्मिक परम्पराएँ भी जन्मदर को बढ़ाने में सहायक रही हैं, घटाने में नहीं। ऊँची जन्म-दर हमारी संस्कृति का घंग बन गई है। अतः जब स्वेच्छा से अथवा परिस्थितियों के दबाव से समाज की प्रचलित धार्मिक व सामाजिक भावनाएँ बदलेंगी, तभी भारत में जन्म दर घटेगी।

4. भारत में जनसंख्या की वृद्धि में मृत्यु-दर की गिरावट का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, मृत्यु-दर बालीस के दशक में 27.4 प्रति हजार से घटकर 1981-85 की अवधि में 12.2 प्रति हजार आ गई है। भविष्य में मृत्यु-दर में और गिरावट आने की सम्भावना है। मृत्यु-दर का घटना मानवीय दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन जन्म-दर के स्थिर रहने की दशा में इसका प्रभाव जनसंख्या की वृद्धि के रूप में प्रकट होता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि अधिक बच्चे जन्म लेने लग गये हैं, बल्कि यह इसलिए बढ़ रही है कि कम व्यक्ति मरने लग गये हैं। अतः भविष्य में जन्म-दर को घटाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

5. परिवार नियोजन का अभाव—शिक्षा की कमी, गरीबी व पर्याप्त साधनों के अभाव में आज भी भारत में परिवार नियोजन का उपयोग देहातो में उतना नहीं होता जितना शहरों में होता है और शहरों में भी यह कुछ शिक्षित व मध्यम श्रेणी के परिवारों में ही अधिक प्रचलित हो पाया है। अभी भी अनेक परिवार इसके उपयोग से दूर हैं जिससे जन्म-दर का ऊँचा रहना स्वाभाविक है। 1981-85 की अवधि में जन्म-दर 33.2 प्रति हजार आ गई थी जो भारत में 34.6 प्रति हजार निकसी है (सातवी योजना का भव्यावधि मूल्यांकन)। जन्म-दर को कम करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

6 शरणार्थियों का आगमन—भारत में समय-समय पर राजनीतिक कारणों से विभिन्न देशों से शरणार्थियों के आने से भी जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान, बंगला देश, तिब्बत तथा श्रीलंका से आये शरणार्थियों का उदाहरण दिया जा सकता है। जब तक ऐसे शरणार्थी अपने स्थानों पर वापस नहीं लौट जाते तब तक हमारी कठिनाई बनी रहती है। असम में बंगला देश के नागरिकों का काफी समस्या में बम जाने से वहाँ विदेशी नागरिकों की समस्या उत्पन्न हुई है। समाचार पत्रों में छपी सूचना के आधार पर राजस्थान के सीमावर्ती गाँवों में पाकिस्तानी से कुछ घुसपैठियाँ के आने से भी जनसंख्या बढ़ी है, हालाँकि इसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान के पाँच जिलों तक ही सीमित रहा है।

7 मनोरंजन के साधनों का अभाव—कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि का एक कारण देश में मनोरंजन के साधनों का अभाव है। हालाँकि हम कारण की सत्यता से इकार नहीं किया जा सकता, फिर भी प्रायः हम तब की भी पाठ्य पुस्तकों में अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य कारण तो परिवार नियोजन के उपायों का व्यापक रूप से नहीं अपनाया जाता है। जैसे जैसे लोग परिवार नियोजन को अपनाते जायेंगे, वैसे वैसे इन कारणों का महत्व कम होता जायगा। देश में बच्चों की बाढ़-सी (Torrent of babies) आ रही है। भारत जनसंख्या के विस्फोट (Population explosion) की स्थिति में मग्न रह रहा है। इस पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित किया जाना चाहिए। जनसंख्या की समस्या का मुझ स्तर पर मुकाबला करने की आवश्यकता है। इसके लिए अनेकपूर्ण राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए।

भारत में जनसंख्या सम्बन्धी बातें

जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)

प्रायः जनसंख्या के घनत्व से हमारा अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की संख्या से होता है। यदि किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या का वहाँ का क्षेत्रफल में विभाजित किया जाय तो वहाँ की जनसंख्या का घनत्व ज्ञात हो जायगा। हमें दया कि भारत में जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है परन्तु देश का भू-क्षेत्र लगभग स्थिर है। फलस्वरूप भारत में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। भारत में जनसंख्या का घनत्व 1971 में 177 था जो बढ़कर 1981 में 216 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। स्मरण रहे कि जनसंख्या का घनत्व हम किसी भी देश का आर्थिक विकास के बारे में विवेक ज्ञान नहीं करता। इसका अनावश्यक अथवा अनापेक्षित अर्थ नहीं होता। घनत्व का अधिक होना आर्थिक पिछड़ेपन का सूचक भी नहीं माना जाता।

भारत में विभिन्न राज्यों के जनसंख्या के घनत्व में परम्पर बार्फी घ-नर पाया जाता है। 1981 में एक घोर दिल्ली में घनत्व 4,194 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था तो दूसरी घोर झारखण्ड प्रदेश में केवल 8 व्यक्ति ही था। घ-घ राज्यों में घनत्व की स्थिति इस प्रकार थी - बिहार (402), मध्यप्रदेश (118), महाराष्ट्र (204), पंजाब (333), राजस्थान (100); उत्तर प्रदेश (377) तथा पश्चिमी बंगाल (615)।¹ एक राज्य के विभिन्न भागों में भी जनसंख्या के घनत्व में काफी अन्तर पाया जा सकता है।

जनसंख्या के घनत्व की विभिन्नता के कई कारण होते हैं, जैसे भूमि की बनावट, मिट्टी की रीति, वर्षा, सिंचाई, जलवायु, भौगोलिक व आर्थिक माधन एवं आर्थिक विकास की अवस्था, आदि। उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की उपलब्धता व आर्थिक विकास से जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है।

लिंग-अनुपात (Sex-ratio)—प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंग-अनुपात (Sex-ratio) कहलाती है। भारत में लिंग-अनुपात 1971 में 930 था जो बढकर 1981 में 933 हो गया। इस प्रकार देश में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक है। लेकिन 1981 में केरल में लिंग-अनुपात 1032 था, यानी वहां पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक थी। दिल्ली में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम था (808) एवं राजस्थान में 919 था।

भारत में साक्षरता की दरें (Literacy Rates in India)—भारत में 1981 में साक्षरता की दरें में थोड़ी वृद्धि हुई है, फिर भी यहाँ पर साक्षरता की दर विश्व में सबसे कम पायी जाती है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 36.2% व्यक्ति साक्षर थे। पुरुषों के लिए साक्षरता की दर 47% तथा स्त्रियों के लिए 25% थी। 1971 में साक्षरता की दर 29.5% थी।

1981 में कुछ राज्यों में साक्षरता की दरें इस प्रकार थी :

	(%)
केरल	70.4
उत्तर प्रदेश	27.2
बिहार	26.2
पंजाब	40.9
राजस्थान	24.4

स्रोत Statistical Outline of India, 1988-89, p. 35

इस प्रकार केरल में साक्षरता की स्थिति बहुत उत्तम है। उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि समस्त देश में आज भी दो-तिहाई व्यक्ति निरक्षर हैं। आर्थिक

विकास में शिक्षा का काफी योगदान माना जाता है। अतः साक्षरता का विस्तार तेजी में किया जाना चाहिए। इससे परिवार-नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद मिलती है। स्त्री-शिक्षा के प्रचार से शादी की उम्र भी बढ़ती है, जिसका प्रभाव जन्म-दर को घटाने की दृष्टि से अनुकूल होता है। चीन में प्रयत्न करके लोगों को मारी मर्यादा में साक्षर बनाया गया है। हमें उसके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। 1980 में चीन में प्रौढ़-साक्षरता (adult-literacy) की दर 69% तथा श्रीलंका में 85% हो गई थी। प्रोफेसर ए. के. सेन (Prof. A.K. Sen) ने भारतीय ग्रंथभ्यवस्था की प्रगति पर अपने विचार प्रकट करते हुए बतलाया है कि 1981 में भारत में साक्षरता की दर 36% पाया जाना देश के पिछड़ेपन का सूचक है। हमारे विपरीत यहाँ उच्च शिक्षा में चीन की तुलना में घाट मुने विद्यार्थी पाये जाते हैं। लेकिन दो-तिहाई जनता साधारण ढंग भी पढ़ पा सकती नहीं। उसके लिए काला ग्रंथर में बराबर होता है।

पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में साक्षरता की दर और भी कम पायी जाती है। गहरो की अनिश्चित गाँवों में साक्षरता की दशा ज्यादा खराब है और गाँवों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में साक्षरता की दशा अधिक दयनीय है। राजस्थान में ग्रामीण स्त्रियों में साक्षरता की दर 1981 में 5.5% रही, जो भारत में सबसे नीची थी। इससे राजस्थान के देहातों में स्त्रियों में सामाजिक-पिछड़ेपन की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है।

भारत में जन्म के समय जीने की प्रत्याशा (Expectation of Life at Birth)

भारत में जन्म के समय जीने की प्रत्याशा 1986 में 57 वर्ष हो गयी थी। अब एक औसत भारतवासी पहले की तुलना में अधिक वर्ष तक जीता है। यह आर्थिक विकास का सूचक तथा देश की प्रगति का प्रतीक माना जा सकता है। लेकिन यहाँ भी चीन व श्री लंका हमसे काफी आगे निकल गये हैं। चीन में यह 69 वर्ष व श्रीलंका में 70 वर्ष हो गयी है। सामाजिक-सेवाओं के विस्तार व लाद्याओं के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता ने इस दशा में काफी मदद की है।

भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति व आर्थिक विकास

भारत में 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 19.9% शहरी में निवास करता था और शेष 80.1% गाँवों में बसा हुआ था। 1981 में शहरी जनसंख्या अनुपात 23.3% हो गया है। इस प्रकार आज भी 76.7% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

इस प्रकार भारत में शहरीकरण की दशा में कुछ प्रगति हुई। 1981 में 23.3 प्रतिशत जनसंख्या शहरी में बसी हुई थी। जपान में यह अनुपात 93.6% तथा अष्टराचल प्रदेश में 6.6% था।

1981 की जनगणना के अनुसार 12 नगरो की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो गई थी।¹ इनमें कलकत्ते की जनसंख्या 91.9 लाख, बम्बई की 82.4 लाख, दिल्ली की 57.3 लाख तथा जयपुर की 10.1 लाख थी। इन 12 नगरो की कुल जनसंख्या (मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर व सखनऊ सहित) 4.16 करोड़ व्यक्ति थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 6.1% थी। महानगरो में आवास, जल-सप्लाई, सफाई आदि की समस्याओं के निरन्तर बढ़ने के कारण भारतीय नियोजन में शहरी-पक्ष पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है। प्रोफेसर के सुन्दरम का भी मत है कि 2001 में शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.5% हो जायेगा। शहरो की जनसंख्या 1981 में 16.5 करोड़ से बढ़कर 2001 में 33 करोड़ व्यक्ति हो जायेगी (दुगुनी)। अतः भविष्य में शहरी नियोजन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

भारत में श्रम-शक्ति व इसका व्यावसायिक वितरण

प्रत्येक देश के आर्थिक विकास पर वहाँ की श्रम-शक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्रम-शक्ति में रोजगार प्राप्त व्यक्ति तथा वर्ष भर बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति शामिल माने जाते हैं। श्रम-शक्ति देश की कुल जनसंख्या का एक अंश होती है। इस अंश को काम में भाग लेने की दर (Work Participation Rate) कहते हैं जिस पर जनसंख्या की वृद्धि-दर, आर्थिक-सामाजिक व अन्य परिस्थितियों का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है। 1981 में श्रमिकों का अनुपात कुल जनसंख्या का 34% पाया गया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बताया गया है कि भारत में मार्च 1985 में 5 वर्ष व अधिक आयु के श्रमिक 30.5 करोड़ थे, जो मार्च 1990 में 34.5 करोड़ हो जायेगे। इस प्रकार इस समूह में श्रम-शक्ति में वार्षिक वृद्धि-दर 2.46% आती गयी है। इन अनुमानों के लिए राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 32वें दौर (1977-78) से प्राप्त की गयी काम में भाग लेने की दरों का उपयोग किया गया है।

भारत में वर्तमान समय में श्रम-शक्ति में वार्षिक वृद्धि-दर 80 लाख व्यक्ति मानी जा सकती है। आगामी वर्षों में इसके 1 करोड़ सालाना होने की सम्भावना है।

1981 की जनगणना में मुख्य श्रमिकों (main workers) व सीमान्त श्रमिकों (marginal workers) के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किये गये थे। मुख्य श्रमिकों को माना गया जिन्होंने वर्ष में 183 दिन अथवा 6 महीने या इससे अधिक

1 Statistical Outline of India, 1988-89, pp 48-50, (Tata Services Limited, (June, 1988)

अवधि के लिए किसी आर्थिक दृष्टि से उत्पादन क्रिया में भाग लिया। सीमान्त श्रमिक उनको माना गया जिन्होंने 183 दिन या 6 महीने से कम अवधि के लिए काम किया, पर्याप्त जिन्होंने वर्ष के अधिकांश भाग तक उस क्रिया में भाग नहीं लिया।

मुख्य श्रमिकों (main workers) का कुल जनसंख्या में अनुपात (प्रतिशत)

1971	33.1
1981	33.4

1981 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश में मुख्य श्रमिक (main workers) 22.25 करोड़ तथा सीमान्त श्रमिक 2.21 करोड़ थे। इस प्रकार कुल श्रमिक 24.46 करोड़ व्यक्ति थे जिनमें 19.73 करोड़ ग्रामीण व 4.73 करोड़ शहरी थे एवं 18.10 करोड़ पुरुष व 6.36 करोड़ स्त्रियाँ थी।

जे. डब्ल्यू. एन. के अनुसार संशोधित मुख्य क्रिया (सीमान्त श्रमिकों सहित) को देने पर कान में भाग लेने की कूट दर (1981 की जनगणना के आधार पर) ग्रामीण पुरुषों के लिए 34%, ग्रामीण महिलाओं के लिए 23%, शहरी पुरुषों के लिए 49% तथा शहरी महिलाओं के लिए 8% रही। इस प्रकार महिलाएँ पुरुषों की तुलना में श्रम-शक्ति में कम भाग लेती हैं तथा बाकी की अपेक्षा शहरी महिलाएँ श्रम में कम भाग लेती हैं।

विकासित देशों में कार्यशील आयु (Working age) में जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में विकासशील देशों की तुलना में ऊँची पायी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समान परिभाषा देने पर 1985 में भारत में कार्यशील जनसंख्या (15-64 वर्ष के आयु समूह में) कुल जनसंख्या का 56% घाँकी गयी थी, जबकि जापान में यह 68 प्रतिशत, यू.के. में 65 प्रतिशत तथा फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में 70% थी।¹

अतः हम श्रम-शक्ति के व्यावसायिक या पेशेधार विवरण का अध्ययन करना है। श्रमिक का विभिन्न व्यवसायों या पेशों के अनुसार विवरण इसका व्यावसायिक विवरण कहलाता है। विभिन्न व्यवसायों को प्रायः तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)—इसमें कृषि, पशु-पालन, वन, मछली-पालन, निवार करना तथा वायान की क्रियाएँ शामिल होती हैं। इनमें प्रायः खनन क्रिया (Mining) शामिल नहीं होती (जैसे ढाँची के भार की राव के अनुसार)। उर्वरक के क्षेत्र मॉनोपॉलीय संगठन (C. I. O.) खनन को भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करता है।

2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)—इसमें गन्तव्य व परिवहन निरालना घरेलू उद्योग, अन्य विनिर्माण उद्योग तथा निर्माण (Construction) व कार्य शामिल होते हैं।

3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)—इसमें अन्तर्गत व्यापार-व्यवसाय परिवहन, मण्ड व संचार तथा सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा व अन्य प्रकार की सेवाएँ शामिल हैं। वार्षिक विकास के साथ इस क्षेत्र का अपेक्षाकृत अधिक तेजी से विकास होता है।

कोलिन क्लार्क व साइमन क्यूजनटस आदि विद्वानों ने श्रम-शक्ति के व्यावसायिक वितरण का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि वार्षिक विकास के परम्परागत प्राथमिक क्षेत्र में श्रम-शक्ति का प्रविष्टन घटता है, द्वितीयक क्षेत्र में यह बढ़ता है तथा तृतीयक क्षेत्र में यह और भी तेज गति से बढ़ता है।

कार्दगील समग्रता का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण विभिन्न देशों में अलग-अलग पाया जाता है। इसका अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है।

1980 में श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण¹ (प्रतिशत में)

	कृषि	उद्योग	सेवाएँ	कुल
भारत	70	13	17	100
जापान	11	34	55	100
संयुक्त राज्य अमेरिका	3	31	66	100

इस प्रकार विकसित देशों में श्रम-शक्ति का अधिक अंश सेवाओं के क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान देने की बात है कि भारत में श्रम-शक्ति का 70% कृषि में संलग्न है, जबकि अमेरिका में यह लगभग 3% ही है।

भारत में श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण 1901-1951 के 50 वर्षों में इस प्रकार रहा।

1901 में कृषक व खेतिहर मजदूरों का कुल श्रमिकों में 67.5% अंश था जो 1951 में 69.7% हो गया। पशु-पालन, वन, मछली, सिंचार, बागान आदि में यह 4.2% से घटकर 2.4%, खनन व विनिर्माण में 11.8% से घटकर 9.6% तथा व्यापार, निर्माण व परिवहन, आदि में 16.5% से बढ़कर 18.3% हो गया। इस प्रकार 1901-51 की अवधि में कृषकों व खेतिहर मजदूरों का अनुपात कुल श्रमिकों में बढ़ा, खनन व विनिर्माण में यह घटा तथा व्यापार, निर्माण व परिवहन में थोड़ा बढ़ा।

1. World Development Report, 1988, pp. 282-283.

निम्न तालिका में श्रमिकों का व्യാवसायिक धर्मोकरण 1971 व 1981 के लिए वर्गीकृत किया है :— (प्रतिशत में)

प्राथमिक क्रिया	1971	1981
(1) कृषक	43.4	41.6
(2) सेविहर मजदूर	26.3	24.9
(3) पशुधन, वन, मछली वगैरा	2.4	2.3
(4) खनन व पत्थर निकालना	0.5	0.6
(5) निर्माण (घरेलू + अन्य)	9.5	11.3
(6) निर्माण (Construction)	1.2	1.6
(7) व्यापार व वाणिज्य	5.6	6.2
(8) संप्रदा, परिवहन व संचार	2.4	2.7
(9) अन्य सेवाएँ	8.7	8.8
	100.0	100.0
(क) प्राथमिक क्षेत्र (1+2+3)	72.1	68.8
(ख) द्वितीयक क्षेत्र (4+5+6)	11.2	13.5
(ग) तृतीयक क्षेत्र (7+8+9)	16.7	17.7
	100.0	100.0

1. Basic Statistics Relating to the Indian Economy, Vol. 1, India, August, 1986 (CMIE, Bombay), table 9.1

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1971 में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों का 72.1% अंश लगा हुआ था जो 1981 में घटकर 68.8% पर आ गया। द्वितीयक क्षेत्र में यह 11.2% से बढ़कर 13.5% तथा तृतीयक या सेवा-क्षेत्र में 16.7% से बढ़कर 17.7% हो गया।

इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र में श्रम-शक्ति का अंश लगभग 3.3% घटा है एवं बदले में द्वितीयक क्षेत्र में यह 2.3% तथा सेवा-क्षेत्र में 1% बढ़ा है।

वृष्णमूर्ति का भी यही मत है कि भारत के अधिकांश भागों में पिछले दशक (1971-81) में श्रम-शक्ति का कृषि से अन्य क्षेत्रों में कुछ अन्तरण हुआ है। इस निष्कर्ष की पुष्टि एन. एस. एस. व सेन्सस दोनों के आँकड़ों से होती है। उनका यह भी कहना है कि यह प्रवृत्ति पिछले दशक में अधिन स्पष्ट हुई है। हो सकता है यह काफी लम्बी अवधि से चली आ रही हो। लेकिन सम्भव है तुलनीय आँकड़ों के सिलसिले के अभाव में यह छिपी रह गई हो। इस प्रकार 1981 में पहली बार व्यावसायिक वितरण में एक नया व अनुकूल मोड़ आया है जिसके अनुसार कृषि में श्रम-शक्ति का अनुपात 3 से 4 प्रतिशत तक कम हुआ है। डॉ. बी. के. धार. बी. राव ने भी अपनी पुस्तक : *India's National Income : 1950-1980* में इन परिवर्तनों की पुष्टि की है।

1965-80 की अवधि में श्रम-शक्ति में कृषि का अंश कई अल्प-विकसित विकासशील देशों में घटा है, कुछ देशों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।¹

श्रम-शक्ति में कृषि का अंश (प्रतिशत में)

देश	1965	1980	परिवर्तन
1. बंगला देश	84	75	(—) 9
2. पाकिस्तान	60	55	(—) 5
3. भारत	73	70	(—) 3

तालिका से पता लगता है कि 1965-80 की अवधि में भारत व उसके पड़ोसी देशों में कृषि में श्रम-शक्ति का अनुपात घटा है, हालांकि भारत व बंगला देश में आज भी यह काफी ऊँचा बना हुआ है।

1981 में राज्यों में श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण—

विभिन्न राज्यों में औद्योगिक श्रेणियों के अनुसार श्रम-शक्ति का वितरण काफी असमान पाया जाता है। उदाहरण के लिए, 1981 में बिहार में कुल श्रमिकों

में 43.6% कृषक तथा 35.5% सेतिहर मजदूर थे। इस प्रकार 79.1% कृषि में सलग्न थे। यह प्रतिशत सर्वाधिक था।

राजस्थान में श्रम-शक्ति का वितरण इस प्रकार रहा—

(प्रतिशत)

कृषक	सेतिहर मजदूर	घरेलू उद्योग (विनिर्माण, प्रोसेसिंग, सेवा व मरम्मत)	अन्य
61 6	7.3	3.3	27 8

इस प्रकार राजस्थान में 69% श्रमिक कृषि में सलग्न पाये गये, जबकि 1971 में इसमें 74% लगे हुए थे।

प्राज ही भारत में श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण काफी असंतुलित व प्रतिवृत्त बिस्म का है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं, जबकि विकसित देशों में तृतीयक क्षेत्र में श्रम-शक्ति का अधिक भ्रम पाया जाता है।

आर्थिक विकास के साथ-साथ यह देखा गया है कि गैर-कृषि व्यवसाय में श्रम-शक्ति का प्रतिशत बढ़ता जाता है और फलस्वरूप कृषि पर जनसंख्या का दबाव घटता जाता है। बड़े पैमाने की यन्त्रीकृत खेती का प्रयोग होने से विकसित देशों में कृषि में कम श्रम-शक्ति पायी जाती है। भारत अभी तक औद्योगीकरण की दिशा में सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर पाया है। इसलिए कृषि में अधिक लोग लगे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण को कैसे ठीक किया जाय।

प्राधुनिक ढंग के कुटीर व लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकता—इसके लिए अधिकारी मर्यादाश्रितियों ने सुझाव दिया है कि देश में छोटे व मध्यम पैमाने के उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए। ये उद्योग गाँवों में स्थापित हों। वे प्राधुनिक पद्धति पर विद्युत का प्रयोग करके चलाए जाएं। इनमें अधिक श्रमिकों को खदाया जा सकेगा। पाश्चात्य देशों का पूँजी-गहन औद्योगीकरण हमारे यहाँ उपयोगी नहीं होगा; क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों का विस्तार करके विशाल श्रम-शक्ति को काम देना कठिन है। इसलिए हमें शहरी में उद्योगों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना है। देश को सम्पन्न बनाने के लिए हमें विकेंद्रित पद्धति पर आधारित प्राधुनिक ढंग के लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए।

क्या जनसंख्या को कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में से जाना सम्भव होगा ?

जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को ठीक करने के सम्बन्ध में प्रायः यह कहा जाता है कि ऐसा करने के लिए लोगों को कृषि से हटाकर गैर-कृषि व्यवसायों

म ले जाना होगा। लेकिन भारतीय परिस्थिति में यह सुझाव व्यावहारिक नहीं लगता है। डॉ. बी. के. आर. वी. राव का मत है कि भविष्य में कृषि से लोगों को हटाने की बजाय इसमें ही अधिक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार उन्होंने लोगों को कृषि से हटाकर अन्यत्र ले जाने की प्रचलित धारणा को गलत सिद्ध किया है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. ए. एम. एतरो ने भी एक अध्ययन में यह स्वीकार किया था कि कृषि से लोगों को हटाने की बजाय इसमें ही अधिक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी।

यह निष्कर्ष काफी सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके व्यावहारिक पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिवर्ष जनसंख्या व श्रम-शक्ति के बढ़ने के कारण हमें यही रास्ता अपनाना होगा। भविष्य में भी कृषि में काफी लोगों को रोजगार देना होगा। भारत में पूँजीवादी यन्त्रीकृत खेती उभर चुकी नहीं होगी। यहाँ भू-जोती पर सीमा-निर्धारण करना भी आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर अधिक श्रमिक खाद, पानी आदि देकर गहन खेती करनी होगी। पशु-पालन, मछली-उद्योग, बागवानी, रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी-पालन, मुरगी-पालन आदि कृषि के सहायक कार्य भी विकसित करने होंगे। कृषिगत क्षेत्र में ही लोगों के लिए अधिक रोजगार की सम्भावना देना भी आर्थिक विकास की योजना के लिए एक चुनौती के समान है।

डॉ. राव ने परिवार नियोजन के द्वारा जन्म-दर घटाकर जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित करने का भी समर्थन किया है। विकसित देशों में श्रम-शक्ति का अधिक अग्र-क्षेत्रों में लगा हुआ होता है। उदाहरण के लिए 1980 में जापान में 55% श्रमिक सेवा-क्षेत्र में कार्यरत थे तथा अमेरिका में इस क्षेत्र में 66% श्रमिक लगे हुए थे। भारत में निकट भविष्य में श्रम को कृषि से विनिर्मित माल बनाने वाले उद्योगों की ओर ले जाने की बजाय निम्न आर्थिक क्रियाओं की ओर ले जाना होगा, जैसे शहरी व्यापार व सेवा, असंगठित वर्कशाप, परिवहन, व्यक्तिगत पेशेवर व सामाजिक सेवाएँ, (सेवा-केन्द्र, पेट्रोल-पम्प, होटल, दर्जी, नार्सी, घोड़ी व बढई की दुकानें, टैक्सी की सेवाएँ, लाइब्रेरी) आदि। स्मरण रहे कि ये सभी कार्य तृतीयक क्षेत्र (Tertiary sector) में आते हैं। अतः भारत में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सभी क्षेत्रों के अनुसार रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। आनुपातिक दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र की सर्वोपरिता कुछ सीमा तक भले ही कम की जा सके, लेकिन फिलहाल इसमें विकसित देशों की भाँति कोई क्रान्तिकारी व तीव्र परिवर्तन कर सकना सुगम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष श्रम-शक्ति तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है। के. सुन्दरम् के अनुसार 1990 के दशक में भारत में श्रम-शक्ति में सालाना वृद्धि लगभग 1 करोड़ होने लग जायेगी जिसके लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था करना कठिन हो जायगा।

भारत में जनसंख्या की समस्या का स्वरूप

(Nature of the Population Problem in India)

एक देश में जनसंख्या की समस्या के कई पहलू हो सकते हैं जैसे बड़ा जनघनत्व या जनघनत्व हो सकता है। कुल जनसंख्या में बच्चों व बूढ़ों का प्रतिशत अधिक हो सकता है जिससे योद्धों से कमाने वालों पर आर्थिक भार बढ़ जाता है एवं पुरुषों व स्त्रियों के अनुपात में अंतर आ सकता है। भारत में आर्थिकता का भार कम ही ऊँच है। एक व्यक्ति कम खाता है तथा कई व्यक्ति उसकी कमाई पर आश्रित रहते हैं।

1 सख्यात्मक पहलू—लेकिन जब हमें 'जनसंख्या की समस्या' का उत्खनन किया जाता है तो प्रायः इसके सख्यात्मक पहलू (Quantitative aspect) पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 54.8 करोड़ थी। 1981 की जनगणना के अनुसार यह 68.5 करोड़ (प्रसन्न व जम्मू-कश्मीर सहित) प्राचीन हुई है। के. सुन्दरम ने इस अंक को गौरव माना है और वास्तविक अंक 1.8 करोड़ बढ़ाकर 70.3 करोड़ कर दिया है। यह कहा जाता है कि भारत में जन्मदर ऊँची है और मृत्यु-दर घट रही है जिससे जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 1.6 करोड़ व्यक्तियों की रफ्तार से बढ़ रही है। इससे प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि रोजगार के अवसरों रहन-सहन के स्तर, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों, मकानों की सुविधा, शिखा के अवसर, चिकित्सा व स्वास्थ्य की सुविधाओं आदि पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। डा. आशीष बोस के अनुसार जनसंख्या का तीन बातों से गहरा सम्बन्ध है, यथा, Environment (पर्यावरण), Energy (ऊर्जा) तथा Employment (रोजगार)। भारत में जनसंख्या की समस्या का स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :

यह तो सर्वविदित है कि हमारे देश में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा व चिकित्सा आदि की दृष्टि से उपभोग का स्तर बहुत नीचा है। काफी लोग घाघे भूखे रहते हैं तथा ये सर्वजन्य अवस्था में जीवन बिताते हैं। गाँवों में मकानों की कमी बहुत गंभीर है। शहरों में गन्दी वस्तुओं की समस्या बहुत उग्र रूप धारण किये हुए है। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अतः वास्तविक रूप में जनसंख्या की समस्या गरीबी की समस्या हो है। जनसंख्या की समस्या का अभिप्राय लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा करना है और इस सम्बन्ध में जनसंख्या पर नियन्त्रण स्थापित किया जाना चाहिए। हम जनसंख्या की दृष्टि से इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि प्रगति व परिवर्तन के बावजूद हम आर्थिक दृष्टि से एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आर्थिक विकास के सामान्य आदमी तक नहीं पहुँच पाते। इस तथ्य को देखवासी जितनी जल्दी व जितनी अच्छी तरह से समझें उसे उमीद उनका कल्याण है।

2 गुणात्मक पहलू—बहुधा जनसंख्या के गुणात्मक पहलू (Qualitative aspect) पर भी ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कि लोग स्वस्थ बुद्धिमान,

सम्यक् व सुमस्कृत बने। सच पूछा जाय तो सख्यात्मक पहलू पर इसलिये जोर दिया जाना है कि जनसख्या का गुणात्मक पहलू भी सुधारा जा सके। अतः इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है।

क्या भारत में जनाधिक्य है ? (Is India over-populated ?)

अर्थशास्त्रियों में प्रायः इस विषय पर विवाद पाया जाता है कि भारत में जनाधिक्य है अथवा नहीं। एक वर्ग तो यह मानता है कि भारत में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्यान्नो का अभाव व नीचा जीवन-स्तर आदि को देखते हुए देश में निश्चित रूप से जनाधिक्य है और इसका मुकाबला देश-व्यापी परिवार नियोजन को अपनाकर किया जाना चाहिए। दूसरा वर्ग, जिसमें मुख्यतः साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा वाले व्यक्ति शामिल हैं, यह मानता है कि समस्या मूलतः कम उत्पादन व असमान वितरण की है, जनाधिक्य की नहीं। इनके अनुसार सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन करके जनसख्या की समस्या का सन्तोषजनक हल निकाला जा सकता है।

यह तो स्वीकार करना होगा कि भारत में आर्थिक समस्या उत्पादन बढ़ाने तथा वितरण को सुधारने की है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या 1981 में 68.52 करोड़ जनसख्या अथवा 1989 में लगभग 82 करोड़ जनसख्या आवश्यकता से अधिक मानी जायगी ?

उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भारत में निश्चित रूप से जनाधिक्य की स्थिति है। इसके लिए निम्न प्रमाण दिये जा सकते हैं—

1. मातृस के अनुसार देश में ऊँची जन्म-दर, ऊँची मृत्यु-दर व प्राकृतिक प्रक्षोभों का पाया जाना जनाधिक्य की स्थिति को प्रकट करता है। भारत में पिछले वर्षों में जन्म-दर कुछ कम हुई है, लेकिन आज भी यह लगभग 33-34 प्रति हजार है जो काफी ऊँची है। इसे निकट भविष्य में 25 प्रति हजार तक लाने में काफी प्रयास करना होगा। इसी प्रकार हमारे देश में मृत्यु-दर अथवा विकसित देशों की तुलना में कुछ ऊँची है। भारत में प्रकाल, बीमारी, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक प्रक्षोभों से भी जान-माल की काफी हानि होती रहती है। आजकल दुर्घटनाओं, सगठित हिंसा, एक कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण भी अलबारी में लोगों के मरने की रिपोर्टें काफी बढ़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारत में जनसख्या की प्रबंध-व्यवस्था (management of population) गड़बड़ा गई है। अतः मातृस के सिद्धान्त के अनुसार भारत व चीन जैसे देशों में जनाधिक्य की स्थिति निस्तदेह विद्यमान है।

2. भारतवासियों का जीवन-स्तर नीचा है—भारत की प्रति व्यक्ति GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति) 1986 में 290 डॉलर थी, जबकि समुक्त राज्य अमेरिका में यह 17,480 डॉलर थी। इस प्रकार आय का यह भारी अन्तर भारत में निम्न जीवन-स्तर का सूचक है।

भारी मात्रा में आयात करना पड़ा है ताकि देश में इनके मूल्यों को स्थिर रखा जा सके तथा इनकी उपलब्धि अधिक नियमित की जा सके।

4. बेरोजगारी की दशा—भारत में बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की दशा जनाधिक्य का ज्वलन्त प्रमाण है। योजनाओं में रोजगार बढ़ा है, लेकिन साथ में बेरोजगारी भी बढ़ी है। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के 38 वें दौर के आधार पर मार्च, 1985 में (सामान्य स्टेट्स या स्थिति के अनुसार) 5 वर्ष व अधिक आयु-समूह में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 92 लाख पायी गयी है। सामान्य स्टेट्स (Usual status) में काम की स्थिति 365 दिन की अवधि के लिये देखी जाती है, अर्थात् इसमें स्थायी रूप से या वर्ष भर बेरोजगार रहने वालों की संख्या आती है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत में वर्तमान समय में जनाधिक्य की स्थिति विद्यमान है। तबिन इसका समाधान केवल जननरथा पर नियन्त्रण स्थापित करना ही नहीं है, बल्कि देश का आर्थिक विकास करना भी है, जिसके लिए देश में काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः हमें दोनों पक्षों पर एक साथ प्रभावपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।

अब हम भारत में परिवार-नियोजन तथा जनसंख्या-नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।

भारत में परिवार-नियोजन

(Family Planning in India)

पिछले कई वर्षों से परिवार नियोजन काफी चर्चा का विषय रहा है। यह जनसंख्या को नियन्त्रित करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। हाल के वर्षों में परिवार नियोजन के संदेश में एक परिवार में बच्चों की जनसंख्या को दो तक सीमित करने पर बल दिया जाने लगा है। सम्भव है हमें भी चीन की भाँति 'एक बच्चे' (one child) के नॉर्म पर गीघ्र ही आना पड़े।

आजकल एक स्त्री के दो से ज्यादा सन्तान होना 'अविवेकपूर्ण मातृत्व' (Improvident maternity) का सूचक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि माता-पिता अपनी सन्तान व परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में आवश्यक समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। परिवार-नियोजन में दो बातें होती हैं—(1) एक दम्पति के परिवार को दो बच्चों तक सीमित करना, तथा (2) दो बच्चों के सन्तानोत्पत्ति काल के बीच में पर्याप्त फासला रखना (Proper spacing)। जैसा कि ऊपर कहा गया है आजकल परिवार नियोजन में 'केवल दो' पर बल दिया जाने लगा है। इसलिए "हम दो हमारे दो" तथा 'पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दा नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं," "दो में शान्ति, तीन में त्राण्ति" आदि नारे सुनने को मिलते हैं।

हमारे देश में भी परिवार-नियोजन के प्रबल व कट्टर समर्थक "प्रत्येक सम्पत्ति के केवल एक सन्तान" की चर्चा करने लगे हैं, हालांकि इसके प्रचार में अभी पर्याप्त तेजी नहीं आ पाई है। इस प्रकार परिवार-नियोजन एक परिवार में सदस्यों की संख्या को इस प्रकार से सीमित करता है कि वह परिवार आर्थिक व शारीरिक दृष्टि से सुखी रह सके।

1938 में नेताजी सुभाषचन्द्र बास ने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मापण देते हुए भारत में परिवार-नियोजन कार्यक्रम अपनाये जाने का समर्थन किया था। भोर समिति ने अपनी 1946 की रिपोर्ट में जन्म-दर को नियन्त्रित करने के लिए परिवार-नियोजन की आवश्यकता स्वीकार की थी। लेकिन उन्होंने सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का समर्थन नहीं किया था। भारत के सभी प्रधानमन्त्रियों ने अपने मापणों में परिवार-नियोजन की आवश्यकता पर सदैव जोर दिया है। आज-कल राजनीतिज्ञ परिवार-नियोजन में स्वेच्छा की भावना पर अधिक जोर देने लगे हैं। 20 सूची आर्थिक कार्यक्रम में भी परिवार-नियोजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने भी जनसंख्या की वृद्धि को भारत की प्रमुख समस्या माना है तथा देश के आर्थिक विकास के लिए परिवार-नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च स्थान दिया है।

इस प्रकार भारत में स्वयं सरकार ने परिवार-नियोजन आन्दोलन में रुचि ली है और इसका सामाजिक प्रभाव आर्थिक संस्थाओं द्वारा विरोध नहीं हुआ है। विश्व में अन्यत्र यह एक व्यक्तिगत कार्य माना गया है, लेकिन भारत में यह एक सामूहिक व राष्ट्रीय जन-आन्दोलन के रूप में चलाया गया है।

भारत में परिवार-नियोजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में तो कोई दो मत नहीं हैं लेकिन साधनों के सम्बन्ध में अलग-अलग मतभेद पाये जाते हैं। कुल लोग आत्म-नियम पर अधिक बल देते हैं और सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधनों के उपयोग को अनैतिक अथवा अनावश्यक मानते हैं। हम यहाँ इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद में न पड़कर इतना ही कहना चाहेंगे कि इस विषय में कोई सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाना हितकर नहीं होगा। प्रमुख आवश्यकता जन्म-दर कम करने की है। इसके लिए समय-देर से शादी सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधन आदि सभी को व्यक्तिगत पक्ष-द के अनुसार अपनाया जा सकता है। कृत्रिम साधनों में रासायनिक (Chemical) यांत्रिक (Mechanical) एवं जैविक (Biological) सभी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। स्त्रियों के लिए सन्तानोत्पत्ति बन्द करन का ट्यूब-रेमोशन (tubectomy) (आजकल दूरबीन से नसदन्दी) एवं पुरुषों के लिए नसदन्दी वास्क्टमी (vasectomy) भी परिवार-नियोजन के प्रभावपूर्ण उपाय हैं। डॉक्टर की सलाह पर खाने की गर्भ-निरोधक गोलियाँ माला-डी तथा माला एन का भी प्रचलन हो गया है। व्यक्तिगत रुचि, उपलब्ध साधन व व्यक्तिगत परिस्थिति के

आधार पर परिवार-नियोजन की पद्धति का चुनाव किया जाना चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा उपयोगी होगा। 1965 में स्त्रियों के लिए 'लूप*' का प्रयोग निकाला गया था। पिछले वर्षों में गर्भपात (Abortion) को भी कानूनी मान्यता दे दी गई है। इस सम्बन्ध में भी पहले काफी विवाद रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अनचाही सन्तान को रोकना ज्यादा आवश्यक समझा गया है। भारत के लिए निरोध के रूप में सस्ते, सुगम और सुरक्षित साधन की नितान्त आवश्यकता है जिसका प्रयोग विशाल जन-समुदाय द्वारा किया जा सके और देश में जन्म दर कम की जा सके। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है।

पञ्चवर्षीय योजनाओं में परिवार-नियोजन

1. **व्यय की राशियाँ**—प्रत्येक योजना में परिवार-नियोजन पर व्यय हेतु राशि निर्धारित की जाती रही है जिसका उपयोग सेवाओं, साधनों की सप्लाई, शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान आदि पर किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवार नियोजन पर वास्तविक व्यय की राशियाँ इस प्रकार रही हैं¹—

(करोड़ रुपये में)

प्रथम योजना	0.14
द्वितीय योजना	2.16
तृतीय योजना	24.9
तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69)	70.4
चतुर्थ योजना	278.0
पञ्चम योजना (1974-79)	491.8
1979-80	118.5
छठी योजना	1448

सातवीं पञ्चवर्षीय योजना, 1985-90 (प्रस्तावित)**** 3256.3

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में परिवार नियोजन पर केवल 14 लाख रुपये और द्वितीय योजना में 2.16 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। सरकार ने तृतीय योजना से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक गम्भीरता से लागू करना प्रारम्भ किया था। पांचवी योजना की अवधि में परिवार-नियोजन पर 492 करोड़ रु. व्यय हुए। सातवी योजना में परिवार-कल्याण-कार्यक्रम पर व्यय हेतु 3256.3 करोड़ रु की राशि निर्धारित की गई है।

*. Intra-uterine contraceptive device (IUCD)

1. Economic Survey 1988-89, p. S-40. (तृतीय योजना से 1979-80 तक के वास्तविक व्यय के लिए)

2. 'लूप की प्रगति'—तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में इण्डियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 'लूप' के व्यापक प्रयोग का समर्थन किया था। वानपुर में लूप बनाने का कारखाना चालू किया गया। जनवरी 1965 से मार्च 1981 तक कुल लगभग 88 लाख लूप लगाये गये। 1975-76 व 1976-77 में लूप की प्रगति काफी तेज रही थी।

3. वन्ध्यकरण अभिवा नसबन्दी की प्रगति—1956 से मार्च 1981 तक वन्ध्यकरण या नसबन्दी के कुल मामले 3 34 करोड़ घाके गये हैं। 1976-77 में 82 6 लाख व्यक्तियों की नसबन्दी की गई जो घरेलू आप में एक रिकार्ड था। बाद में नसबन्दी की प्रगति धीमी रही, क्योंकि सरकार ने आपातकाल जैसी सत्ता नहीं बरती। लूप की तुलना में वन्ध्यकरण के आपरेशन ज्यादा सफल हुए हैं।

पिछले वर्षों में वन्ध्यकरण पर प्रौद्योगिकी अध्ययन बढ़ गया है, क्योंकि राज्यों में भ्रूण निर्माण व गाइडों की सफाई वर्गों पर ध्यान बढ़ा है। लेकिन इनकी तुलना में नसबन्दी, लूप आदि कार्यक्रम अपनाने की दृष्टि से सफलता कम हो गयी है। अतः भविष्य में सक्रिय कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना होगा। त्रिवेन्द्रम में सार्वजनिक क्षेत्र में निरोध (Condoms) बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। निरोध की प्राथमिक बिक्री (Primary Sale) कार्यक्रम के चालू होने के बाद से 120 मिलियन इकाई तक पहुँच गई है। यह जनसंख्या की समस्या के हल का अधिक उपयुक्त व व्यावहारिक साधन माना गया है। भारत में प्रतिवर्ष औसत रूप से 30 लाख नवदम्पति सन्तानोत्पत्ति के आयु-समूह में प्रवेश करते हैं। इस समूह में इसका उपयोग बढ़ाया जा सकता है।

भारत में परिवार-नियोजन कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए कुछ नगठनात्मक परिवर्तन भी किये गये हैं। स्वास्थ्य मन्त्रालय को स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मन्त्रालय का नाम दिया गया है। बाद में यह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्रालय में परिवर्तित कर दिया गया है। पूर्ण समग्रीकृत परिवार नियोजन व मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवार्थें उपलब्ध करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचा (Infrastructure) तैयार करने में प्रयत्नशील रही है। इन प्रयासों में काफी सफलता भी मिली है, लेकिन कुछ कमियाँ भी रही हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लक्ष्य व उपलब्धियाँ

छठी योजना, 1980-85 में परिवार नियोजन पर व्यय हेतु 1010 करोड़ रु की राशि निर्धारित की गई थी। NRR को 1996 तक 1 करने का दीर्घकालीन लक्ष्य स्वीकार किया गया था। परिवार-नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियाँ अग्रे तालिका में दिये गये हैं—

छठी योजना में परिवार-नियोजन कार्यक्रमों के लक्ष्य व उपलब्धियाँ¹

कार्यक्रम	1984-85 तक	उपलब्धि
	लक्ष्य	
(1) वन्ध्यकरण या नसबन्दी (sterilisation)	24 मिलियन	17 मिलियन से कुछ अधिक
(2) लूप (IUD)	7.9 मिलियन	7 मिलियन
(3) निरोध-प्रयोगकर्ता (CC-users)	11 मिलियन (1984-85 में)	9.31 मिलियन
(4) प्रभावपूर्ण दम्पति सुरक्षा-दर ² (कुल दम्पतियों का वह अनुपात जो परिवार-नियोजन अपना रहा होता है)	36.6%	32% (मार्च 1985 में)

छठी योजना में परिवार-नियोजन की उपलब्धियों की समीक्षा

छठी योजना में परिवार-नियोजन की उपलब्धियों से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं—

(1) उपलब्धियाँ लक्ष्यों से कम रही हैं। विशेषतया नसबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत। लूप लगाने व निरोध-प्रयोगकर्ताओं के सम्बन्ध में 80% व अधिक लक्ष्य प्राप्त किये जा सके हैं।

(2) परिवार-नियोजन अपनाने वाले दम्पतियों का अनुपात मार्च 1985 में 32% हो गया था, जो लक्ष्य (36.6%) से नीचा रहते हुए भी पहले के 22% की तुलना में 10% बिन्दु अधिक था।

(3) दम्पति-सुरक्षा की दर छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में 0.5% व 1% बढ़ी, लेकिन अन्तिम तीन वर्षों में 2.5% वार्षिक दर से बढ़ी।

1 Seventh Five Year Plan, 1985-90, Vol. II, pp. 279-282.

2. Effective Couple Protection Rate. (ECPR)

(4) छठी योजना के अन्तिम वर्ष में उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान में परिवार-नियोजन अपनाते वाले दम्पतियों का अंश 20% से नीचा रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत 32% हो गया। मध्य प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में यह 29% रहा। अतः भविष्य में प्रभावपूर्ण दम्पति-सुरक्षा-दर को घटाने के लिए इन पाँच राज्यों में अधिक प्रयास किया जाना चाहिए।

छठी योजना में उपलब्धियों में कमी के लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं—

(i) आधारभूत सुविधाओं की कमी, (ii) लक्ष्यों का अपेक्षाकृत ऊँचा निर्धारित किया जाना (iii) उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम से कम उपयोग किया जाना, (iv) राजनीति, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रतिबन्ध, (v) शिशु मृत्यु-दर, जो सत्तर के दशक में 125 प्रति हजार के समीप थी वह 1980 में 114 पर आ गई। लेकिन यह अब भी काफी ऊँची है जिससे दम्पतियों को अपने बच्चों के जीवित रहने के सम्बन्ध में पूरा भरोसा नहीं होता और वे परिवार-नियोजन के लिए आवश्यक उत्साह नहीं दिखाते।

(vi) अन्य देशों की तुलना में माताओं व बच्चों की मृत्यु-दरें काफी ऊँची पायी जाती हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य

सातवीं योजना में परिवार-कल्याण-कार्यक्रम पर व्यय-हेतु 3256.3 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। 1990 के लिए प्रभावपूर्ण दम्पति सुरक्षा-दर (परिवार नियोजन काम में लेने वाले दम्पतियों का अनुपात) 42% करने का लक्ष्य रखा गया है। जन्म-दर 29.1 प्रति हजार मृत्यु-दर 10.4 प्रति हजार एवं शिशु मृत्यु-दर 90 प्रति हजार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य लक्ष्य इस प्रकार हैं—

1989-90 तक

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| (1) नसबन्दी का बन्धनकरण | 31 मिलियन |
| (2) लूप लगाना | 21.25 मिलियन |
| (3) निरोध-उपयोगकर्ता-संख्या | 14.5 मिलियन (1989-90 में) |

सातवीं योजना में उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न कार्यों व पहलुओं पर जोर दिया जायगा।

- (1) प्रोग्राम के आधारभूत ढांचे को अधिक प्रभावशाली बनाया जायगा।
- (2) राज्यों को विभिन्न कार्यक्रमों में आवश्यक फंड-बदल करने की दृजाजत दी जायगी।

(3) अपेक्षाकृत युवा-आयु समूह के दम्पतियों में दो सन्तानों के बीच दूरी रखने पर अधिक जोर दिया जायगा।

(4) सूचना, शिक्षा व संचार का उपयोग करके सहवियों के जन्म के विपक्ष में फैली पारणा को हटाने पर जोर दिया जायगा।

(5) शादी की न्यूनतम आयु का कानून लागू किया जायगा।

(6) उन राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जायगा जहाँ प्रभावपूर्ण दम्पति सुरक्षा दर नीची पायी जाती है। इस सम्बन्ध में शहरी गन्दी वस्तियों, पहाड़ी व पिछड़े क्षेत्रों व ग्रामीण निर्धन-वर्ग पर ज्यादा ध्यान दिया जायगा।

(7) 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि अधिक दम्पति परिवार-नियोजन अपनाते लगे।

(8) ऐच्छिक संगठनों से अधिक योगदान लिया जायगा।

(9) स्त्रियों व युवा-वर्ग का अधिक सहयोग लिया जायगा। ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों व महिला मण्डलों के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जन-आन्दोलन में बदलने का प्रयास किया जायगा।

(10) जिन राज्यों ने अभी तक परिवार-कल्याण कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव पास नहीं किये हैं उन्हें ऐसे प्रस्ताव पास करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा।

ग्रामा है सातवी योजना के अन्तिम वर्ष में परिवार-नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगे जिनके फलस्वरूप जन्म-दर लगभग 29 प्रति हजार हो सकेगी।

भारत के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रश्न (The Problem of National Population Policy for India)

भारत में आर्थिक विकास के सम्दर्भ में सदैव जनसंख्या नीति (Population Policy) पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और पञ्चवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन के लिए धनराशि निश्चित की जाती रही है। लेकिन जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर को कम करने की आवश्यकता निरन्तर बनी रही। तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार-नियोजन मन्त्री डॉ. वरतसिंह (हाल में अमेरिका में भारत के राजदूत) ने 16 अप्रैल, 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रस्तुत की थी जिसकी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं—

1976 की जनसंख्या नीति—

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत में विश्व के भू-क्षेत्र का 2.4% अंश है और यहाँ विश्व की जनसंख्या का लगभग 15% भाग निवास करता है। भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या की वृद्धि आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर होती है जो हमारे देश से 2½ गुना बड़ा है। यदि जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि-दर को कम नहीं किया गया तो यह इस शताब्दी के अन्त तक एक अरब हो जायेगी। जनसंख्या

का यह विस्फोट हमारे आर्थिक विकास की सफलताओं को मिटा सकता है। इसलिए निर्धनता व बीमारी को मिटाने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया गया है।

भारत के लिए शिक्षा व आर्थिक विकास के द्वारा जन्म-दर की गिरावट के लिए प्रतीक्षा करना व्यावहारिक नहीं माना गया है। इसलिए निम्न राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रपनाने पर जोर दिया गया है—

1. शादी की उम्र का निर्धारण—यह निश्चित किया गया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष कर दी जाए। इसके लिए कानून भी आवश्यक माना गया। शादियों के अनिवार्य पंजीकरण पर बल दिया गया है।

2. लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक स्थिर करने पर जोर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि 1981 व 1991 की जनगणना के परिणाम लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों के सयोजन व सशोधन में नहीं गिने जावेंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक माना गया।

3. केन्द्र के द्वारा राज्यों की योजनाओं में जो सहायता जनसंख्या को आधार मानकर निश्चित की जाती है तथा कर, शुल्क व अनुदान सहायता का केन्द्र से राज्यों की ओर जो हस्तांतरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, वह 1971 की जनसंख्या के आकड़ों के आधार पर 2001 तक जारी रखने पर जोर दिया गया।

जनसंख्या-नीति में यह कहा गया कि राज्यों की योजनाओं में केन्द्रीय सहायता का 8 प्रतिशत अन्न परिवार-नियोजन की उपलब्धि के आधार पर निश्चित किया जायेगा। इसका विस्तृत व्योरा योजना आयोग तैयार करेगा।

4. स्त्री-शिक्षा में सुधार किया जायेगा—मिडिल स्तर से आगे व पिछड़े क्षेत्रों में युवतियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं खालू की जायेंगी। बाल-पौष्टिक कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। राज्य सरकारों को इन दोनों कार्यक्रमों पर विशेष रूप से बल देना होगा।

शिक्षा-प्रणाली व जनसंख्या सम्बन्धी मूल्यों (Population values) तथा जनसंख्या जैसे विषय का समावेश कराने के लिए पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया जायगा। यह आवश्यक है कि युवा-पीढ़ी जनसंख्या की समस्या के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़े और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना सुदृढ़ हो। इस सम्बन्ध में डॉ. कर्कशह ने निम्नोक्त्यों का कहा था कि "युवा-पीढ़ी पर परीक्षार-नियोजन के लिए जोर देना ज्यादा उचित है, वरिन्तत उन लोगों के जो जनसंख्या के क्षत्र में पहले ही अपना योगदान दे चुके हैं।

5. छोटे परिवार को अपनाने का कार्य एक मन्त्रालय की जिम्मेदारी न मानकर विभिन्न मन्त्रालयों व राज्यों पर डाला जायेगा ताकि नागरिक स्वयं से जिम्मेदार की भावना विकसित कर सकें। यह कहा गया कि राज्यों को परिवार-नियोजन की उपनियमों की सूचना ज्यादा व्यवस्थित रूप में देनी होगी और केंद्रीय मन्त्रि-मण्डल वर्ष में कम से कम एक बार स्थिति की गहुराई में समीक्षा करेगा।

6. वध्वकरण या नसबन्दी (Sterilisation) (पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए) कराने के लिए भौतिक सुगमता की गति दी या कम जॉर्जिन बच्चों की स्थिति में 100 स्त्रियाँ तीन जीवित बच्चों पर 100 स्त्रियाँ तथा चार या अधिक बच्चों की स्थिति में 70 स्त्रियाँ कर दी गईं। भूतकाल का अनुभव यह रहा कि निर्जन परिवारों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह सुविधा 1 मई, 1976 में लागू की गयी। वध्वकरण की सुविधा का तभी में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने पर जोर दिया गया।

7. समुदाय आधारित प्रेरणाएँ (Group incentives) बढ़ाना आवश्यक माना गया ताकि चिकित्सक, चिन्ता व पचायत समितियाँ, ग्रामीण स्तर पर अध्यापक, सहकारी समितियाँ व मगठित सत्रों के समिक अधिक मात्रा में परिवार नियोजन को प्रोत्साहित बनाने में मदद दे सकें। ऐच्छिक मगठनों का सहयोग प्राप्त करने पर भी बल दिया गया। इसके लिए उन्हें महायाना देने की बात भी कही गई।

8. सरकार द्वारा स्थानीय समूहों व पञ्जीकृत ऐच्छिक मगठनों को परिवार नियोजन कार्यों के लिए धनराशि देने पर आयकर-निर्धारण में पूरी रिबेट देने का निर्णय किया गया। अनुमोदित कार्यों को उचित प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई।

9. अनिवार्य वध्वकरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक व अन्य तैयारियों का प्रभाव रहा। धन. इस सम्बन्ध में कोई केंद्रीय कानून लाने का समर्थन नहीं किया गया। लेकिन यदि कोई राज्य इसके लिए तैयार हो तो वह आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। उसे यह कार्यक्रम तीन बच्चों से अधिक वाले दम्पतियों पर जाति, धर्म व समुदाय का भेदभाव किये बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करना होगा।

10. कुछ राज्य परिवार नियोजन स्वीकार करने वाली की मकान व ऋण आदि देने में प्राथमिकता देने हैं। यह मापना वैयक्तिक राज्यों पर ही छोड़ा गया है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 'छोटा परिवार' अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु उनके सेवा/आचरण नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने पर भी जोर दिया गया।

ग्यानों में तो लोगों के खेतों व पहाड़ों में छिप जाने तक की घटनाएँ भी सुनने को मिली, हालाँकि इन सूचनाओं को प्रायः बड़ा-बड़ा कर जो प्रस्तुत किया गया था।

5. नसबन्दी के तथ्य को पूरा करने के 'नये' में अधिक उम्र के व्यक्तियों की नसबन्दी, कम उम्र के व्यक्तियों की नसबन्दी व दुबारा नसबन्दी के मामले भी सामने आये इससे वास्तव तथ्य पर झूठा प्रभाव नहीं पड़ा।

6. आवश्यक साधनों की उपलब्धि पर विचार किया बिना ही कुछ स्थानों पर नसबन्दी का कार्यक्रम अत्यधिक व प्रचलित तेजी से चलाया गया जिससे लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुँची और वे बहुत मयमौत हो गए।

उपरोक्त चर्चा के मुख्य निष्कर्ष श्री डी बनर्जी के लेख (EPW, वार्षिक अंक, फरवरी 1977) में विस्तार से दिये हुए हैं। स्वामाधिक है कि लोकनायिका परम्परा वाले देश में ऐसे कदमों के प्रति जनता में राय फैले। 1 मार्च, 1977 में लोक मन्त्रा के चुनाव हुए और विरोधी दल ने इसे चुनाव-प्रचार में अपने पक्ष में एक मुद्दा बनाया और उसे काफी राजनीतिक लाभ भी मिला एवं केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी।

जनता सरकार का परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण

जून 1977 में जनता सरकार ने परिवार-कल्याण कार्यक्रम के बारे में अपना नीति सम्बन्धी कथन प्रस्तुत किया जिसमें निम्न बातें शामिल की गईं—राष्ट्र की प्राप्ति में वृद्धि, स्त्रियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार, जननरत्न नियंत्रण के पक्ष में मनोदशा व लघु परिवार के नॉर्म का फैलाव, कार्यक्रम में ऐच्छिक महिला व युवा-मगठनों, मजदूर सघों, पंचायतों, सहकारिताओं आदि को शामिल करना, स्वनि-मित्र के सभी उपायों को यथोचित प्रोत्साहन देना, केन्द्र व राज्यों में सभी मन्त्रालयों/विभागों द्वारा कार्यक्रमों को महत्व देना तथा इसके लिए कार्य करना आदि। जनमन्त्रालय-नीति सम्बन्धी कथन की अन्य बातें इस प्रकार थी—(i) ऐच्छिक वध्य-करण के लिए नकद मुग्तान की व्यवस्था जारी रखना, (ii) राज्यों की योजनाओं के लिए 5% केन्द्रीय सहायता परिवार-कल्याण की सफलता से जोड़ना, (iii) राज्यों में केन्द्रीय साधनों का बँटवारा 2001 तक 1971 की जकणना के आधार पर करना, (iv) परिवार-कल्याण के लिए दिये गये खन्दों को आसकर से पूर्णतया मुक्त रखना, (v) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध करना।

मुख्य बातों का स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है—

परिवार कल्याण पर बल—परिवार नियोजन कार्यक्रम को संकीर्ण दायरे से निष्कातकर 'परिवार-कल्याण' की ओर मोड़ने पर बल दिया गया। अतः कार्यक्रम के लिए 'परिवार-नियोजन' के स्थान पर 'परिवार-कल्याण' नाम रखा गया। परिवार-कल्याण के क्षेत्र से अनिवार्यता का तत्व सदा के लिए समाप्त कर दिया

गया। कहा गया कि ऐच्छिक व गैरऐच्छिक दृष्टिकोण के जरिए परिवार-नियोजन के प्रयत्न में कोई कमी नहीं रखी जायगी।

गर्भ-निरोध की सभी विधियों पर समान बल—गर्भ-निरोध की सभी विधियों पर समान बल दिया गया। यह कहा गया कि प्रत्येक परिवार अपनी पसन्द की विधि चुनेगा। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं आदि के समन्वय लघु परिवार के आदर्श को अपना कर दूसरों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे।

मौद्रिक मुक्तान की व्यवस्था जारी रखी गई—परिवार-नियोजन व परिवार कल्याण का अपनाते के लिए मौद्रिक मुक्तान देने की व्यवस्था जारी रखी गई और अन्य संघर्ष भी निःशुल्क प्रदान करना जारी रखा गया।

‘कंप्य दृष्टिकोण’ की जगह पुनः विस्तार दृष्टिकोण—यह स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय व राज्य सरकारें प्रचार के लिए विस्तार दृष्टिकोण (Extension approach) अपनायगी ताकि लोगों को समझाकर स्वेच्छा से लघु परिवार के लिए तैयार किया जा सके। जनता सरकार ने पूर्व राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कुछ पहलुओं का स्वीकार किया था जैसे परिवार कल्याण के लिए दान देने पर आय-कर में रिश्त, सभी मन्त्रालयों का सहयोग आदि।

यान स देखने पर प्रतीत होता है कि जनता सरकार के परिवार-कल्याण कार्यक्रम में अग्रिमता बाते वही थी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तथा चौथी व पाचवीं पंचवर्षीय योजनाओं व प्रारूपों में दी गई थी। लेकिन जनता सरकार ने स्वेच्छा की भावना पर अधिक जोर दिया और उसके कार्यकाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपस्थिति नीची रही।

भारत के लिए एक विवेकपूर्ण व व्यावहारिक जनसंख्या-नीति (A Rational and Pragmatic Population Policy for India)

हम पहले बतला चुके हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तदर्थ हमको आर्थिक योजनाओं के घटती आर्थिक साधनों के उपयोग, आर्थिक विकास की दर और जनसंख्या की वृद्धि की दर में आवश्यक तात्तमल बँटाना होगा। भारत को एक विवेकपूर्ण, प्रभावशाली व्यावहारिक तथा सांख्यिक जनसंख्या-नीति की नितान्त आवश्यकता है। हमें प्रमुख तत्व नीचे दिये जाते हैं—

1. जन्म दर कम करना—हम हर सम्भव उपाय अपना कर जन्म-दर कम करनी चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि आज भारत ‘जनसंख्या-विस्फोट’ (Population explosion) की अवस्था से गुजर रहा है। देश में बच्चों की बाढ़-सी आ रही है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में स्वास्थ्य सुधार व चिकित्सा

की सुविधाएँ बढ़ने से मृत्यु-दर गिरी है और लगातार गिरती जा रही है। लेकिन देश में सामाजिक दृष्टिकोण व सामाजिक आदतें न बदलने से जन्म-दर पर्याप्त रूप से नहीं गिरी है। योजना के प्रथम वर्षों में परिवार-नियोजन पर थोड़े से धन्य की व्यवस्था करना इस बात का चेतक है कि हमारे योजनाधारा की स्थिति की सम्मोचता से पूर्णतया परिचित नहीं थे। लेकिन 1961 से 1981 तक की तीन जन-गणनाओं ने हमारी आँखें खोल दी। जनसंख्या पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए व्यापक व गहन कार्यक्रम अपनाए जाने की आवश्यकता है। लोगों को शिक्षित करना होगा और उन्हें परिवार-नियोजन का महत्व समझना होगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार-नियोजन के लिए अधिक सफल विधि तलाश करनी होगी। इसके लिए आवश्यक अनुसंधान जारी है और बर्च वन्दोल ने लिए 'पिल' (pill) (माता-पी तथा माला-एन) का प्रयोग भी प्रारम्भ हो गया है। जिन अभी तक यह प्रयोगशाला में ही है। अतः नसबन्दी (पुरुष व स्त्री में से किसी एक के लिए) के प्रारंभ पर अधिक धन देना होगा। गर्भ-निरोधक के धन्य उपयोग का भी प्रचार बढ़ाना होगा।

सरकार ने वर्ष 2000 तक 60 प्रतिशत दम्पतियों को प्रभावपूर्ण रूप से सुरक्षित प्रुप (Couples effectively protected) में लाने का लक्ष्य रखा है ताकि जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सके। यह कार्य अत्यन्तव नहीं तो कठिन अवश्य है। इतने दम्पतियों द्वारा गर्भ-निरोध के उपाय अपनाने से जन्म-दर में धन्य वमी होगी।

2 परिवार-नियोजन व परिवार कल्याण में आवश्यकतात्मक—विस्तृत शिक्षा व जनता में आवश्यक प्रचार के जरिये परिवार-नियोजन के प्रति व्यापक जागरूकता तो उत्पन्न हो गयी है, लेकिन आज भी जागरूकता का व्यावहारिक प्रयोग के बीच की खाई का पाटने के लिए एक नई दिशा की आवश्यकता है। परिवार-नियोजन की आवश्यकता 'जनसंख्या के विस्फोट' की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धन्य की सहायता देने वाले कार्यक्रम के रूप में भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। परिवार-नियोजन का सम्बन्ध बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा एवं स्त्रियों के लिए उचित पोषण व उनकी उमादा अच्छी देखभाल के साथ किया जाना चाहिए। यह संदेश पचायती राज मन्त्रालयों समाज कल्याण संस्थाओं एवं महिला-मण्डलों, भजदूर-समो आदि ऐच्छिक संस्थाओं के माध्यम से दूर-दूर तक फैलाया जाना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि व नियन्त्रण सम्बन्धी विषय स्तर-स्तर के पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने चाहिए।

भारत में प्रतिवर्ष औसतन 10 करोड़ प्रजननशील दम्पतियों के 2.2 करोड़ बच्चे होते हैं। इनमें से 1.3 करोड़ प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रम के बच्चे होते हैं और 90 लाख चतुर्थ व पंचम क्रम के बच्चे होते हैं। यदि सभी दम्पति 3 बच्चों

नक मौमिन रह तो एक वर्ष में 90 लाख सन्तानें उत्पन्न होने से रोकी जा सकती है। जन्म-दर को 25 प्रति हजार पर लाने का यह एक कारगर उपाय हो सकता है।

१ विभिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना—
अर्थशास्त्रियों का मत है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में विभिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व राजस्थान में 1971-81 की अवधि में अधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। पहले बताया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश बिहार व राजस्थान में प्रभावपूर्ण सम्पत्ति सुरक्षा-दर (effective couple protection rate) क्रमशः 16.7%, 16.8%, 19.3% पाये गये हैं। (छठी योजना के अन्त में)। ये दरें राष्ट्रीय औसत (32%) से काफी कम हैं।¹ प्रोफेसर के. सुन्दरम के अनुसार वर्ष 2000 में इन राज्यों में ये दरें क्रमशः 35.2%, 25.6% तथा 31.7% हो हो पायेंगी, जबकि समस्त राज्यों के लिए इस सम्बन्ध में 60% का लक्ष्य रखा गया है। अतः परिवार-नियोजन कार्यक्रम को जनसंख्या की दृष्टि से इन समस्याग्रस्त राज्यों में अधिक फलाना चाहिए। जनसंख्या-नीति में प्रादेशिक दृष्टिकोण को अपनाता काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

जनसंख्या-नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक नया दृष्टिकोण यह सुझाया गया है कि गृहन कृषि-जिला कार्यक्रम की भांति गृहन परिवार-नियोजन जिला कार्यक्रम देश के उन जिलों में संचालित किया जाना चाहिए जिनमें पुरुषों व स्त्रियों की शादी की औसत आयु बहुत नीची पायी जाती है। भारत में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार व उत्तर-प्रदेश में लड़कियों की शादी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम उम्र में होती है।

1981 में कुछ राज्यों में लड़कियों की शादी की औसत उम्र इस प्रकार रही है²—

राज्य	(वर्षों में)	राज्य	(वर्षों में)
राजस्थान	17.0	उत्तर प्रदेश	18.3
बिहार	17.1	केरल	21.9
मध्य प्रदेश	17.2	पंजाब	21.1

अतः जिन राज्यों में शादी की औसत उम्र 17-18 वर्ष है, वहाँ इसे बढ़ाकर 20-21 वर्ष तक लाने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। इससे जन्म-दर को कम करने में मदद मिलेगी। इन राज्यों में भी वे जिले विशेष रूप से लिये जा सकते हैं, जहाँ शादी की औसत आयु भी नीची पायी जाती है।

1. Seventh Five Year Plan 1985-90, Vol. II, p. 280.

2. Ashish Bose, Presidential Address, Indian Association For the Study of Population, Dec. 1983, Jaipur.

4. शिक्षा का प्रसार आवश्यक—समाज में प्रायः यह चर्चा भी सुनने को मिलती है कि परिवार-नियोजन कार्यक्रम हिन्दुओं में तेजी से अपनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह भुगतमानों में बहुत कम लोकप्रिय हुआ है। शिक्षा के प्रभाव में सम्भवतः लोग यह सोचें कि अमृत जाति या सम्प्रदाय की जनसंख्या ज्यादा होने से उसे नवविषय में उसका अधिक राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा सोचना अनुचित व भ्रामक है और गंभीर गनोवृत्ति का सूचक है। सरकार को व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके एवं आवश्यक प्रभावपूर्ण प्रचार द्वारा इन गलत धारणाओं को दूर करना चाहिए। सरकार को ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिनमें लोग स्वेच्छा से परिवार-नियोजन कार्यक्रम को अपना सकें। निरक्षर लोगों को सभी प्रकार की सहायता व आशवासन दूर की जानी चाहिए और उन्हें निरन्तर व धैर्यपूर्वक समझा-बुझाकर सीमित परिवार के लिए तैयार करना चाहिए।

हमारे देश में स्त्रियों में, विशेषतः ग्रामीण स्त्रियों में, साक्षरता का अनुपात बहुत नीचा है। 1981 में यह समस्त देश के लिए 18% (ग्रामीण महिलाओं के लिए) था, जबकि ग्रामीण राजस्थान में यह 5.5%, मध्यप्रदेश में 9.0%, उत्तरप्रदेश में 9.5%, तथा बिहार में 10.2% था।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व बिहार में 10-14 वर्ष की 20% से कम लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। इन राज्यों में 15-19 वर्ष के आयु समूह की लगभग 2/3 लड़कियाँ (1981 की जनगणना के अनुसार) विवाहित थीं। ऐसी स्थिति में परिवार-नियोजन के मार्ग में आने वाली कठिनाई का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः स्त्री-शिक्षा के प्रचार से शादी की उम्र थोड़ी आगे खिसकेगी, जिम्मा जन्म दर को कम करने की दृष्टि से काफी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

5 निर्धन वर्ग में अधिक प्रचार की आवश्यकता तथा 'रेस्त्रा दृष्टिकोण' का महत्व—इस प्रकार परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उचित संगठन, प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सम्पर्क व प्रेरणा एवं निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस आन्दोलन का निर्धन जनता में अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। अधिकांश जनसंख्या-विशेषज्ञ शादी की उम्र को बढ़ाने और गर्भपात के विधियों को उदार बनाने के पक्ष में हैं। श्रमिक वर्ग व निर्धन वर्ग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव व पसन्द के अनुसार परिवार-नियोजन की उपयुक्त व उचित पद्धति का चुनाव करना चाहिए। यह 'रेस्त्रा दृष्टिकोण' (Cafeteria approach) माना जाता है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत पसन्द के अनुसार परिवार-नियोजन की विधि का चुनाव किया जाता है।

6 नकद राशि या अन्य प्रेरणाओं का उपयोग—लोकतान्त्रिक देशों में जनसंख्या नियन्त्रण के कार्य में पूरी सफलता पाने के लिए 10-15 वर्ष का समय लग सकता है। यह किसी भी परिणाम देने वाले कार्यक्रम के रूप में सम्पन्न नहीं किया जा सकता। सरकार निम्न आय वाले समूह में लोगों को नकद राशि देकर

परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने लगी है। हमें हर सम्भव उपाय अपनाकर जन्म-दर में शीघ्र व प्रभावपूर्ण कमी करने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिनायक-वादी व्यवस्थाओं में कठोर नीति लागू करने जन्म-दर में अधिक शीघ्रता से गिरावट लायी जा सकती है जैसा कि पिछले पाँच वर्षों में चीन में किया गया है।

हाल के कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यदि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 20 वर्ष कर दी जाए तो जन्म-दर में 10 से 30 प्रतिशत की कमी आ जायेगी। देश में ग्रामीण युवक-युवतियों को इस दिशा में विशेष प्रयास करना होगा क्योंकि शहरी में तो शिक्षा के प्रचार-प्रसार से शादी की उम्र में स्वाभाविक रूप से थोड़ी वृद्धि अपने आप हो रही है। वस्तुतः जनसंख्या की समस्या का युद्ध स्तर (War-footing) पर मुकाबला किया जाना चाहिए एवं विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभावपूर्ण समाधान निश्चाला जाना चाहिए।

7. आर्थिक विकास को तेज किया जाय—विद्वानों का मत है कि विकास स्वयं एक सर्वोत्तम निरोध होता है (Development is the best contraceptive)। इसलिए आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाना चाहिए। स्त्रियों को रोजगार दिया जाना चाहिए ताकि वे आर्थिक क्रियाओं में अधिक समय लगा सकें। जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाकर भारत मानवीय शक्ति का उपयोग आर्थिक विकास में कर सकता है। चीन में भूमि-धर्म-अनुपात भारत से भी ज्यादा विपरीत है, लेकिन उसने खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। जहाँ एक ओर हमारे देश में 'जनसंख्या के विस्फोट' के सम्बन्ध में गम्भीर रूप से चिन्तित होने की आवश्यकता है, वहाँ इस विस्फोटक शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाये जाने की सम्भावना पर भी विचार किया जाना चाहिए। जिलेवाले आगामी कुछ वर्षों में जन्म-दर को 25 प्रति हजार पर लाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए।

8. शिशु मृत्यु-दर को कम किया जाय—भारत में शिशु मृत्यु-दर (Infant mortality rate) के ऊँचा होने से (1980 में यह 114 प्रति हजार थी) लोग नसबन्दी कराने में हिचकिचाते हैं। इसलिए शिशु-मृत्यु दर को कम किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों में यह गिरी है। शिशु मृत्यु-दर घटाने से परिवार-नियोजन कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय होगा। भारत में 2000 ईस्वी में इसे 60 प्रति हजार से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है।

9. कुछ लोगों का मत है कि तीन या तीन से अधिक जीवित बच्चों वाले दम्पतियों में से पुरुष अथवा स्त्री का अनिवार्य बन्धनकरण कर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के नमूने पर कानून बनाया जा सकता है, जिसमें परिवार-नियोजन न अपनाये जाने पर सजा की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे परिवार-नियोजन के प्रति आस्था बढ़ेगी और इसमें शीघ्र सफलता मिलेगी।

1. चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1965-80 की अवधि में 2.2 प्रतिशत से घटकर 1980-86 की अवधि में 1.2 प्रतिशत पर आ गई है। इन्हीं अवधियों में भारत में यह 2.3 प्रतिशत से घटकर केवल 2.2 प्रतिशत पर हो आयी है। (World Development Report, 1988, p 274)

10 डॉ. सी. गोपालन की ग्रामीण लड़कियों के लिए एक योजना—डॉ. सी. गोपालन ने सातवी योजना, 1985-90 में शामिल करने के लिए ग्रामीण लड़कियों के लिए एक स्कीम प्रस्तुत की थी जिसको ग्रामीण वर्षों में लागू करने से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। यह 11 से 20 वर्ष की ग्रामीण लड़कियों के लिए है (इनको गांवों में आधे दिन तक ध्वनि व चित्र के साधनों का उपयोग करके हाम साइन्स व व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए)। सभी लड़कियों को 25 रु मासिक भुगतान व प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न दिया जाना चाहिए। शादी देर से करने के लिए शादी-बोनेस व ब्याज वाले ऋण 50 रु मासिक के अनुसार पाँच वर्ष तक दिये जाएँ जिनको 5 वर्ष बाद या लड़की की 20 वर्ष की आयु होन पर ही भुनाया जा सकता है। समय से पहले शादी कर लेने पर बॉन्ड रद्द माना जाना चाहिए। हम स्कीम के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा का विस्तार होगा, महिला-वर्ग में चेतना आयेगी तथा जन्म-दर कम हो सकेगी। सरकार द्वारा इस स्कीम की छानबीन की जानी चाहिए तथा इसे आवश्यक सशोधन व तैयारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। इससे सरकार पर वित्तीय भार तो पड़ेगा लेकिन इससे परिणाम काफी स्थायी व लाभकारी होंगे।

स्मरण रहे कि ऐच्छिक-परिवार नियोजन का अन्त फलपरिवार नियोजन में नहीं होना चाहिए। परिवार-नियोजन कार्यक्रम को विभिन्न प्रकार की उपादतियों, ऋणों तथा अन्य कमियों से मुक्त रखना होगा, लेकिन इसे बड़ी गम्भीरता से लागू करना होगा ताकि ग्रामीण विकास के लाभ सर्वसाधारण तक पहुँच सकें। इस सम्बन्ध में लोगों में काफी जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। सरकार न सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक 31 करोड़ नसबन्दी, 21 करोड़ लूप लगान व 145 करोड़ निरोध-प्रयोगकर्ताओं के लक्ष्य रखे हैं तथा प्रभावपूर्ण-दम्पति सुरक्षा-दर के लिए 42% का लक्ष्य रखा है। लोगों का वर्तमान है कि वे इस सम्बन्ध में सरकार को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। विद्वानों ने अध्ययन करके बतलाया है कि सन्तानोत्पत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय अभी फिजूल नहीं जाता, क्योंकि एक सन्तान की शिक्षा, चिकित्सा भोजन, वस्त्र आदि पर जो व्यय होता है वह उस राशि से वही अधिक होता है जो उसको रोकने में व्यय की जाती है। अतः सरकार को परिवार-नियोजन पर व्यय बढ़ाकर अधिक लाभकारी परिणाम प्राप्त करना चाहिए। लेकिन परिवार-नियोजन के व्यय से आवश्यक तथा आशानुकूल परिणाम प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हमें ग्रामीण महिला-वर्ग पर हर प्रकार से अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे वांछित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। साथ में शहरी गन्दी वस्तुओं गहाड़ी जाति व पिछड़ी जाति के लोगों में परिवार-नियोजन का संदेश शीघ्र पहुँचाया जाना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर जनसंख्या की भावी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अतः समय रहते सभी व्यक्तियों को, 'एक या दो बच्चे' वाले सीमित परिवार के सिद्धांत को अपना लेना चाहिये। इसमें अब अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या के दबाव चारों तरफ दिवाली देन लगे हैं। शहरो में ट्रेफिक की दशा, पानी व आवास की कमी व कठि-

नार्ई तथा शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं की कमी, आदि जनसंख्या के नियन्त्रण की आवश्यकता के सूचक हैं।

जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य युद्ध-स्तर पर होना चाहिए।

प्रश्न

1. 'तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है।' इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा सरकार की जनसंख्या (नियन्त्रण) नीति की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
(Raj II year T D C, 1988)

- 2 निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(i) भारत में जनसंख्या का व्यवसायानुसार वितरण।

(Raj II year T D C, 1984)

- 3 भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की समस्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह वितरण लगभग स्थिर सा क्यों रहा? क्या श्रम-शक्ति को कृषि क्षेत्र से हटा कर उद्योगों में लगाना संभव होगा?

(Raj II year TDC, 1989)

उत्तर संकेत—भारत में श्रम-शक्ति को कृषि-क्षेत्र से हटाकर उद्योगों में लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि (i) शहरी में श्रम-शक्ति बढ़ रही है जिसे उद्योगों में लगाया जा सकता है (ii) स्वयं कृषि में सिंचाई का विकास करके अधिक श्रम शक्ति का उपयोग करना होगा (iii) गांवों में कृषि के सहायक उद्योगों का विकास करके श्रम शक्ति को काम देना होगा जैसे पशु पालन, मछली पालन, कुटीर उद्योग, आदि। कृषिगत माल की प्रोसेसिंग का काम बढ़ा कर रोजगार बढ़ाया जा सकता है (iv) सेवा क्षेत्र का विकास करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है।

अतः श्रम-शक्ति के कृषि से उद्योगों की तरफ हस्तान्तरित करने की बात भारत में व्यावहारिक नहीं जान पड़ती।

- 4 भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं? (Raj II year T D C 1981 & 1985)
- 5 भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने आर्थिक परिणामों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय लिए जा रहे हैं? (Raj II year T D C 1982)

सन्दर्भ

- 1 P M Varnia The Demographic Dimensions of Indian Economic Development Chapter 41 in the Development Process of the Indian Economy edited by E R Brahma-nanda and V R Pancharamukhi

भू-जोतों का आकार व वितरण- उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्याएं (Size and Distribution of Land Holdings- Problems of Sub-division and Fragmentation)

कृषि के उत्पादन पर सम्भवतः सबसे ज्यादा प्रभाव भू-जोतों के आकार (size of land holdings) का पड़ता है। भारत में छोटी जोतों की संख्या अधिक है। पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि के निरन्तर बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जाता है, जिसे खेतों का उप-विभाजन (sub-division) कहते हैं। यही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के कई खेत एक स्थान पर इकट्ठे नहीं पाये जाते तथा वे दूर-दूर तक बिखरे हुए होते हैं। यह समस्या अपखण्डन (fragmentation) की होती है जो उप-विभाजन से भी ज्यादा गम्भीर मानी जाती है। भारतीय कृषि को आधुनिक व अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्या का उचित समाधान निकाला जाना चाहिए।

जोतों का आकार

कृषिगत संगठना के आधार पर 1970-71 में कार्यशील जोतों (Operational holdings)¹ का औसत आकार 2.30 हेक्टेयर था जो घटकर 1976-77

1. यहाँ पर कार्यशील जोत (Operational holding) व स्वामित्व की जोत (Ownership holding) में अन्तर किया जाना चाहिए। मान लीजिए एक कृषक 50 हेक्टेयर भूमि का स्वामी होकर इसे पाँच समान टुकड़ों में विभाजित करके खेती करवाता है तो स्वामित्व की जोत का आकार तो 50 हेक्टेयर है लेकिन कार्यशील जोत का आकार 10 हेक्टेयर माना जायेगा।

कृषिगत विकास के कार्यक्रम में निर्यात सेने की दृष्टि से मूलभूत इकाई कार्यशील जोत (Operational holding) ही होती है। परिभाषा— यह वह समस्त भूमि होती है जिसे कृषिगत उत्पादन में पूर्णतः स्वयंशतः काम में लिया जाता है। यह एक टेक्निकल इकाई के रूप में एक व्यक्ति या अन्य के साथ काम में ली जाती है और इसमें अधिकार (टाइटल) कानूनी स्वरूप, आकार या स्थिति से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहता।”

में 2 हेक्टेयर तथा 1980-81 में 1.82 हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार भारत में जोतों का औसत आकार पहले से घटा है। विभिन्न राज्यों में जोतों के आकार में काफी अन्तर पाये जाते हैं जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने भूमि-युग्म अनुपात को प्रतिवृत्त बना दिया है जिससे भूमि कम व अश्रम अधिक हो गया है। परिवर्णमस्वरूप प्रति अश्रमिक कृषिगत भूमि की मात्रा घट गयी है। 1976-77 में राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 4.65 हेक्टेयर एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 1.1 हेक्टेयर पाया गया था। एक तरफ नागालैण्ड में जोतों का औसत आकार 7.61 हेक्टेयर था जो सर्वोच्च था तो दूसरी तरफ केरल में 0.49 हेक्टेयर था, जो न्यूनतम था।

भारत में कार्यशील जोतों का आकार के अनुसार वितरण (Size Distribution of Operational Holdings in India)

भारत में अधिकांश व्यक्तियों के पास कुल भूमि का छोटा हिस्सा और छोड़े व्यक्तियों के पास कुल भूमि का अधिक हिस्सा पाया जाता है। अन्तर्भू-स्वामित्व छोड़े व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हुआ गया है तथा कृषिगत सीधों के सबसे निचले भाग पर अत्यधिक मीड भाड पायी जाती है।

भारत में प्रथम कृषिगत सगणना 1970-71 तथा द्वितीय 1976-77 के लिए की गई थी। 1980-81 की अवधि के लिए की गयी तृतीय कृषिगत सगणना के आँकड़ों के अनुसार देश में कुल कार्यशील जोतें (operational holdings) 8.94 करोड़ थी जिनमें 16.28 करोड़ हेक्टेयर भूमि समायें हुई थी। इनमें से 56.5% जोतें एक हेक्टेयर से कम की थी जिन्हें सीमांत आँतें कहा जाता है। 1970-71 व 1980-81 के लिए भू-जोतों का आकारानुसार कुलनात्मक वितरण निम्न तालिका में दिया गया है।

1970-71 व 1980-81 में कार्यशील भू-जोतों का आकार के अनुसार वितरण¹

भूजोतों का आकार (हेक्टेयर में)	1970-71		1980-81	
	कुल जोतों का प्रतिशत	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	कुल जोतों का प्रतिशत	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
(सीमान्त) 1.0 हेक्टेयर से कम	51.0	9.0	56.5	12.2
(तथा) 1.0-2.0 हेक्टेयर	18.9	11.9	18.0	14.1
(अर्द्ध-मध्यम) 2.0-4.0 हेक्टेयर	15.0	18.5	14.0	21.2
(मध्यम) 4.0-10.0 हेक्टेयर	11.2	29.7	9.1	29.7
(बड़ी) 10.0 व अधिक हेक्टेयर	3.9	30.9	2.4	22.8
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

1. Statistical Outline of India 1988-89, (Tata Services Ltd), June 1988, p. 62.

भारत में 1970-71 में एक हैक्टेयर से नीची जोतो (सीमान्त जोतो) की संख्या 3 62 करोड़ थी जो बढ़कर 1980-81 में 5 05 करोड़ हो गई है। इस प्रकार 10 वर्षों में इनकी संख्या 1 43 करोड़ बढ़ गई है। इसे भू-जोतो के सीमान्तीकरण (marginalisation) की प्रक्रिया कह सकते हैं, अर्थात्, सीमान्त जोतो की संख्या में प्रतिवर्ष काफी तेज रफ्तार से वृद्धि हुई है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1980-81 में एक हैक्टेयर तक की जोतों की संख्या कुल कार्यशील जोतों की 56 5 प्रतिशत थी लेकिन उनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% अंश था, जबकि 10 हैक्टेयर से अधिक की जोतों का कुल क्षेत्रफल का 2 4% था और उनमें क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग समाया हुआ था। इस प्रकार 1980-81 में भी भूमि के वितरण में काफी असमानता पायी गयी है। आज भी हमारे देश में सीमान्त कृषकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनके पास कुल कृषि भूमि का अंश बहुत कम है। बड़े कृषक संख्या में थोड़े हैं लेकिन उनके अधिकार में कृषि भूमि का अधिक अंश पाया जाता है। 1970-71 में 2 हैक्टेयर से नीचे की जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 21% था जो 1980-81 में 26% हो गया। इसके विपरीत 1970-71 में 10 हैक्टेयर से इससे ऊपर जोतों में कृषि भूमि का लगभग 31% अंश था जो 1980-81 में घटकर 23% हो गया है। इसका अर्थ यह है कि कृषि भूमि का वितरण कुछ सीमा तक बड़ी जोतों से छोटी जोतों की तरफ हुआ है। लेकिन भूमि के वितरण की असमानता 1980-81 में भी जारी रही है।

यदि हम अपने देश के खेतों के आकार की तुलना अन्य देशों के खेतों के आकार से करें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे देश के खेतों का आकार कई देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में 1980-81 में कार्यशील जोतों का औसत आकार 1 82 हैक्टेयर था, जो अमेरिका व कनाडा की तुलना में काफी नीचा था क्योंकि वहां बड़े खेतों पर मशीनों की सहायता से खेती की जाती है।

जोतो का अपखण्डन

अपखण्डन के अर्थ—भारत में भूमि का उप-विभाजन (Sub-division) प्रायः अपखण्डन के साथ-साथ पाया जाता है। हमारे खेतों का आकार केवल छोटा ही नहीं है बल्कि वे एक स्थान पर स्थित न होकर कई स्थानों पर बिखरे हुए पाये जाते हैं। इससे खेती करने वालों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। भारत में प्रभावपूर्ण कृषिगत नियोजन व कृषिगत उत्पादकता बढ़ाने के मार्ग में सबसे गम्भीर बाधा भू-जोतों का अत्यधिक टुकड़ों में बिखरा होना है।

1980-81 में कुल 8 94 करोड़ कार्यशील जोतों में से अधिकांश जोतें 4 से 8 टुकड़ों में एक-दूसरे से दूर बिखरी हुयी थीं। एक अपखण्ड (Plot) का

श्रीमंत प्राकार लगभग $\frac{1}{2}$ हैक्टेयर होता है। इस प्रकार का अपखण्डन एक गम्भीर समस्या है।

जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन के कारण

1. उत्तराधिकार के नियम—इंग्लैण्ड में ज्येष्ठाधिकार का नियम प्रचलित है जिसके अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी भू-सम्पत्ति का विभाजन नहीं होता बरन् सबसे बड़ा पुत्र उसकी सारी भू-सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है। फलस्वरूप बड़ा भतीजा का अधिकार बड़ा होता है। हमारे देश में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी भू-सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों में बंट जाती है। प्रत्येक उत्तराधिकारी को उसके पूर्वज की भूमि का एक भाग प्राप्त होता है। प्रत्येक हिस्सेदार पारिवारिक भूमि की प्रत्येक किस्म की भूमि में अपना हिस्सा लेना चाहता है। वह अपना सारा हिस्सा एक ही स्थान में लेना पसन्द नहीं करता। फलस्वरूप प्रत्येक हिस्सेदार को कई छोटे-छोटे टुकड़े एक-दूसरे से काफी दूर पर प्राप्त होते हैं।

2. भूमि पर जनसंख्या की वृद्धि—भारत की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यहाँ उद्योग-धन्यो का विकास पर्याप्त तेजी से नहीं हुआ, बल्कि विदेशी माल की प्रतिযোগिता के कारण ब्रिटिश काल में स्वदेशी उद्योग-धन्यो काफी सीमा तक मर चुके गये। फलस्वरूप भूमि पर अधिकतम लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई।

उद्योग और व्यवसाय के अभाव में प्रत्येक उत्तराधिकारी परिवार की भू-सम्पत्ति में अपना हिस्सा लेने का इच्छुक रहता है। इस प्रकार परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने से प्रत्येक का क्षेत्रफल घटता जाता है। हमारे देश में कृषि पर अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में औसतन एक एकड़ से भी कम भूमि होती है। इस प्रकार एक औसत परिवार के पास भूमि की मात्रा काफी कम होती है।

3. संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन—प्राचीनकाल में हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। परिवार के सब सदस्यों की सम्पत्ति सामूहिक व अविभाजित रहती थी परन्तु वर्तमान अवस्था में व्यक्तिगत स्वार्थ सदैह और ईर्ष्या के कारण इस प्रणाली का केवल नाम ही शेष रह गया है। परिवार के सदस्य पारिवारिक हित से व्यक्तिगत हित को अधिक महत्व देते हैं और पारिवारिक सम्पत्ति का विभाजन करके अपने हिस्से की सम्पत्ति को अलग रखना पसन्द करते हैं। फलस्वरूप जो भू-सम्पत्ति पहले अविभाजित रहती थी उसके अब टुकड़े में बंट जाती है।

4. साझेदारी की प्रथा—अनेक भू-स्वामी अपनी भूमि स्वयं खेती नहीं करते। वे किसानों द्वारा खेती कराते हैं। वे सारी भूमि एक ही किसान को नहीं देते

वर्तक प्रसंग-प्रसंग किसानों को देते हैं। इस प्रथा में स्वामित्व अधिप्राजित रहते हुए भी खेती प्रसंग-प्रसंग भू-खण्डों पर होती है और प्रत्येक किसान को छोटे-छोटे खेत प्राप्त होते हैं। बहुधा एक ही किसान कई भू-स्वामियों के साथ साझे के सम्बन्ध रखता है और उगको दूर-दूर स्थित खेतों पर काम करना पड़ता है।

उप-विभाजन और अपखण्डन के दोष—

भारत के सुप्रसिद्ध धर्मशास्त्री प्रो बी एस. मिन्हास का मत है कि 'प्रत्येक जोत कई टुकड़ों में विभक्त है ही, लेकिन ये टुकड़े इतने अस्त-व्यस्त ढंग से बिखरे हुए हैं कि जहाँ सिंचाई सुलभ है वहाँ उसका सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो सकता, और जहाँ कृषि वर्षा पर आश्रित है वहाँ मिट्टी व नमी के उत्तम संरक्षण की दशाएँ बिगड़ जाती हैं। इन्हीं कारणों से भूमि व जल-निकास का मावी नियोजन एवं पानी के निवास व नमी की रक्षा के कार्य भी बिगड़ जाते हैं।' इन शब्दों से अपखण्डन का घातक व विनाशकारी परिणाम साफ तौर पर प्रकट हो जाता है।

बहुत छोटे खेतों पर खेती करने से कई तरह के अपव्यय होते हैं जिनसे लागत बढ़ जाती है और खेती आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद हो जाती है। इसके मुख्य दोष इस प्रकार होते हैं :

1. पूँजीगत साधनों का घटिया व अपूर्ण उपयोग—खेतों का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण बैलें और मशीनों के लिए पूरा काम नहीं मिलता। मान लीजिए, एक जोड़ी बैल और हल की सहामता से एक किसान दस बीघा भूमि पर अच्छी तरह काश्त कर सकता है, किन्तु उसके पास केवल पाँच बीघा ही भूमि हो तो वह अपने साधनों का पूरा लाभ नहीं उठा सकेगा। फलस्वरूप, प्रति इकाई उत्पादन-लागत अधिक आती है। कोई-कोई खेत तो इतने छोटे होते हैं कि वे भती-भाति जोते-चोये भी नहीं जा सकते। उनमें काश्त करने का व्यय उनकी पैदावार के मूल्य से अधिक आता है। उन पर खेती करना अलाभकारी (uneconomical) होता है। कभी-कभी इस प्रकार के खेत बिना खेती किये ही छोड़ दिये जाते हैं एवं भागे चलकर उन पर खेती का काम बन्द कर दिया जाता है।

2. छोटे-छोटे और दूर-दूर स्थित खेतों में अलग-अलग बाड़े लगाने व मेड़ें बनाने में व्यय करना होता है तथा भूमि खेती के काम नहीं आ पाती है। यदि बाड़े नहीं लगाई जाती हैं तो जानवर फसलें नष्ट कर देते हैं।

3. छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेतों के लिए अलग-अलग कुएँ नहीं खोदे जा सकते क्योंकि छोटे खेतों के लिए अलग कुआँ बनाना लाभकारी नहीं होता है। कृषि के अभाव में इन खेतों की सिंचाई का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता। दूसरों के

बुझो से पानी लाने मध्यम अधिक होता है और रास्ते में पानी व्यर्थ नष्ट होने और आपसी भगड़े होने का डर रहता है। यदि परस्पर सम्बन्धों में कुएँ बनाये जाएँ तो मरम्मत के अभाव में वे शीघ्र ही तराब हो जाते हैं।

4 छोट-छोट और बिल्लरे हुए खेतों में श्रम को बचत करने वाले यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। यांत्रिक खेती असम्भव हो जाती है क्योंकि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ब्रून-डोजर, ब्रेशर इत्यादि मशीनें काम में नहीं लायी जा सकती। इस प्रकार उपविभाजन व अपखण्डन के कारण प्राधुनिक विस्म की प्रगतिशील और वैज्ञानिक खेती असम्भव हो जाती है।

6 दूर-दूर पर स्थित खेतों में खेती करने में खाद, बीज व अन्य साधन तथा औजारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने-ले जाने में समय, शक्ति और धन का अपव्यय होता है।

6 खेतों के बिल्लरे हुए होने से वाडें बनाने तथा पानी को नालियाँ बनाने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के भगड़े होते रहने हैं और अनावश्यक मुकदमेबाजी में किसानों की शक्ति व धन का ह्रास होता रहना है।

7 छोटे-छोटे और दूर-दूर पर स्थित खेतों पर निगरानी करना कठिन और खर्चीला होता है।

8 छोटे-छोटे खेतों की जमानत पर आसानी से रकम उधार नहीं मिलती और ब्याज की ऊँची दरें देनी पड़ती है।

9 छोटे-छोटे खेतों पर खेती करने से होने वाली हानि से बचन का एक तरीका जापान की तरह गहरी खेती करने का है। परन्तु जब किसानों को एक ही पक्ष में खेती करने के बजाय अलग-अलग बिल्लरे हुए छोटे-छोटे खेतों पर खेती करनी हानी है तो वे किसी एक खेत पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकने। इस प्रकार खेती के अपखण्डन से गहन व वैज्ञानिक खेती को अपनाने में कठिनाई होती है।

उप-विभाजन और अपखण्डन के पक्ष में तर्क

खेतों के उप-विभाजन और अपखण्डन के पक्ष में भी निम्नलिखित दलीलें दी जाती हैं

1 उप विभाजन के पक्ष में कहा जाता है कि इससे भूमि का अपेक्षाकृत समान वितरण होता है और भूस्वामियों के एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो शोक्तन्त्र व विकास का समर्थक व पोषक होता है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अत्यधिक छोटे छोटे खेतों पर काश्त करने वाले लोग प्रायः बहुत गरीब हात हैं, जिन्हें राष्ट्र कमजोर हो जाता है।

2 खेतों के अपखण्डन के पक्ष में भी इसी प्रकार की बातें कही जाती हैं :

(1) अलग-अलग खेतों में मिट्टी अलग-अलग तरह की होती है और उन पर अलग-

करण का एक मापन मात्र माना गया है। यही कारण है कि चक्रवर्दी के व यंत्रम में पञ्जाब व उत्तर प्रदेश में निजी सिंचाई का विस्तार किया गया है जिससे पैदावार बढ़ी है तथा लागत में कमी आयी है एवं कई अन्य लाभ प्राप्त हुए हैं जिसका उत्तम प्रागे चलकर दिया जायगा।

2. चक्रवर्दी की प्रक्रिया—चक्रवर्दी अधिकारी ग्राम सलाहकार समिति प्रथम ग्राम-योजना में मिलकर चक्रवर्दी की योजना तैयार करते हैं। समिति व निर्माण व वा. भूमि के रिवाइज से समोचित व सही रूप में बनाये जाने हैं और चक्रवर्दी की स्कीम का प्रारम्भिक समीक्षा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश व जम्मू-काश्मीर में चक्रवर्दी के नियम भी बनाये गये हैं, जैसे भू-स्वामी को भूमि वहाँ मिश्री जहाँ समका सबसे बड़ा टुकड़ा होगा, आदि। चक्रवर्दी अधिकारी योजना बनाकर एवं कृषकों से स्वीकृत कराकर समझौता कमिशनर को देते हैं जो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है।

3. चक्रवर्दी के लिए भूमि का मूल्यांकन करना—चक्रवर्दी में भूमि के मूल्यांकन करने का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह काफी कठिन होता है। इसमें मिट्टी की किस्म, सिंचाई की सुविधाएं भूमि की उत्पादकता, भू-वर्णन की गाँव में दूरी, आदि तथ्यों पर ध्यान देना होता है। मूल्यांकन के लिए लागत-मूल्य प्रथम भूमि का बाजार-मूल्य प्रथम उत्पादकता को ध्यान रखा जाता है। यदि किसी को उसकी भूमि के मूल्य से कम मूल्य की भूमि दी जाती है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति आवश्यक हो जाती है। इसके लिए उसको मुद्रा देने की व्यवस्था करनी होती है।

4. भविष्य में होने वाले अवसंरचना की रोक—इसके लिए भूमि के टुकड़े करने, इसका हस्तान्तरण करने प्रथम इसकी गिरवी रखने की स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करना होता है। इस कार्य के लिए स्टैंडर्ड क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक हो जाता है। स्टैंडर्ड क्षेत्र भूमि का वह न्यूनतम क्षेत्र होता है जो सामान्य ढग से जोता जा सकता है। स्टैंडर्ड क्षेत्र निर्धारित करने के बाद इससे नीचे के सभी टुकड़ों का गाँव के मैदानों में टुकड़ों (fragments) के रूप में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड आकार के टुकड़ों व इसमें छोटे टुकड़ों में विभाजन आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। तमिलनाडु, केरल, जम्मू-काश्मीर व हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में अवसंरचना की रोक के लिए आवश्यक कानूनी व्यवस्था की गयी है।

5. चक्रवर्दी की लागत—चक्रवर्दी की लागत विभिन्न कर्मचारियों, पुनर्विस्थापन एवं आप पर किये गये व्यय पर निर्भर करती है। इसमें चक्रवर्दी के आस्तिक व न पर होने वाला व्यय भी शामिल होता है। महाराष्ट्र व गुजरात में समस्त लागत पूर्णतया राज्य सरकारों के द्वारा वहन की जाती है। अन्य राज्यों में यह भू-स्वामियों से मानगुजारी के माध्यम से वसूल की जाती है।

व जालियारपुर) व उत्तर प्रदेश के तीन जिलों (मुजफ्फरनगर, दहरिया व नौमी) में चकबन्दी के प्रभावों का अध्ययन किया था जिसमें पता चला कि यह कार्यक्रम बहुत लाभदायक निश्चि हूँ है। उनके प्रमुख लाभ निम्नांकित रहे हैं—

1. इससे गाँवों में परस्पर सहयोग का बानाबनर उत्पन्न हुआ है और मुकदमे-द्वारा न कमी हुई है।

2. कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त हुई है क्योंकि खतों की मटे तथा हदबन्दिनी बदन से राज्य के ल'यक अनिरित भूमि निकल सकी है।

3. निजी तौर पर सिंचाई (Private irrigation) का लेनी से विस्तार किया गया है कृषिगत इन्फुग का अतिर तपसा करने से उत्पादन व उत्पादना बड़ी है जिससे लागत में कमी आयी है।

4. फसलों के प्रारूप (cropping pattern) में परिवर्तन आया है आहारिक या नकद फसलों का विस्तार किया गया है जिससे किसानों की आमदनी बनी है।

5. चकबन्दी से फसलों की बड़ाईकारी की प्रथा में कमी आई है क्योंकि अब भूमिवासी स्वयं कानन में अधिक भाग लेन लग हैं, जबकि पहले बड़ाई के आधार पर भाग लेते थे। इन प्रकार चकबन्दी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं जिसमें इनकी उपयोगिता में किसी को सन्देह नहीं रह गया है।

(आ) उप विभाजन की समस्या के हल

1. सहकारी समुक्त खेती (Co-operative Joint Farming)—सहकारी समुक्त खेती में कृषक अपनी छोटी-छोटी जोतों का मिलाकर खेती करते हैं। लेकिन व भूमि-भूतन दुकानों के म्बाधी बन रहे हैं। लगभग 30 वर्ष पूर्व समुक्त खेती के प्रथम का लकर हमारे देश में काफी विवाद हुआ था और उस विवाद में स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह, मौनू मन्गनी, एन बी रंगा तथा स्वर्गीय प्रोफेसर राजकृष्ण भास्कर न भारतीय परिस्थितियों में सहकारी समुक्त खेती की उपयोगिता के बारे में काफी नयेह प्रकट किये थे। लेकिन कई विचारकों का मत था कि अत्यधिक छोटी व अनाधिक किस्म की जोतों की समस्या को हल करने का एक मात्र उपाय समुक्त ही हो सकता है। छोटे खेतों के स्वामियों का अपने दुकानें आपस में मिला लेने चाहिए और उन पर समुक्त रूप से खेती करनी चाहिए। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और भूमि का सदुपयोग भी किया जा सकेगा।

हम यहाँ पर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि समुक्त खेत का आकार किना हो, इस पर उपज का बँटवारा कैसे किया जाए, आदि। मुख्य बात यह है कि अत्यधिक छोटे खेतों को मिलाकर खेती करने से सबको लाभ प्राप्त होगा। यही नहीं बल्कि इस प्रकार की खेती एन्जिन्ड एव प्रजातान्त्रिक आधार पर संगठित की जा सकती है। पहल सरकार ने समुक्त खेती का प्रचार करने के लिए कई तरह की

सुविधाएँ प्रदान की थी, जैसे वित्त, औजार, रासायनिक उर्वरक व अन्य तकनीकी सहायता आदि। संयुक्त खेती का विकास करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी कृषि मलाह-कार बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन भारतीय कृषक सहकारी दृष्टिकोण के स्थान पर वैयक्तिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता रहा है। भूतन्त्राल में लोगों में यह भ्रम फैलाने का भी प्रयास किया गया था कि सहकारिता के दरवाजे से सरकार उन्नी जमीने छीन कर समितियों को दे देगी। इन सब कारणों से भारत में सहकारी संयुक्त कृषि के कार्यक्रम को विशेष सफलता नहीं मिल पाई और इस नभ्यन्ध में आन्दोलन की प्रगति आगे चलकर काफी धीमी हो गई। आजकल तो वहाँ सहकारी संयुक्त कृषि की चर्चा भी सुनने को नहीं मिलती। लेकिन हम यह भी ध्यान रखना होगा कि समय गुजरने के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक समस्याओं के पुराने, व्यावहारिक व सही हल पूर्णतया व्यर्थ नहीं हो जाते। आज भी ऐच्छिक आधार पर ग्रामीणिक जोतों के स्वामी संयुक्त खेती को अपनाएँ तो उन्हें तथा सनस्त समाज को इस फायदे से काफी लाभ हो सकता है।

2. सहकारी सेवा समितियों (Co-operative Service Societies) का विकास करके सभी कृषक भूमि की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उत्तम बीज, औजार खाद, साख आदि की व्यवस्था सहकारी समिति के द्वारा करने से कृषकों को काफी लाभ पहुँचता है। इस पद्धति में भूमि के टुकड़ों को मिलाएँ बिना भी उत्तम खेती (Better Farming) की जा सकती है। इसके विकास का सभी ने समर्थन किया है क्योंकि सहकारी सेवा समितियों के विकास में कोई विवादग्रस्त बात नहीं है। कृषक सहकारी सेवा-समिति के सदस्य हो जाते हैं, जहाँ से उनको रियायती शर्तों पर विभिन्न कृषिगत साधन प्राप्त होते हैं। साख को सुविधा मिलती है तथा बिक्री की सुविधा भी प्राप्त होती है। अतः सहकारी सेवा समितियाँ छोटे कृषकों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। सेवा-सहकारिता में आकृतान्त्रिक व्यवस्था में विशेष रूप में उपयोगी मानी गई है। अतः इनको प्रयत्न करके कामयाब बनाया जाना चाहिए।

3. आर्थिक जोत (Economic holding) का निर्धारण और अनाधिक जोतों के स्वामियों को अधिक भूमि उपलब्ध करने की व्यवस्था करना—खेतों के अत्यधिक उप-विभाजन और अपखण्डन को रोकने के लिए भूमि की आर्थिक जोत निर्धारित करने का भी सुझाव दिया जाता है। आर्थिक जोतों की परिभाषा व माप का कार्य काफी जटिल माना गया है। यह कहना गलत होगा कि सभी छोटी जोते अनाधिक और सभी बड़ी जोते आर्थिक होती हैं। भूमि के काफी उपजाऊ होने पर छोटी जोते भी आर्थिक हो सकती हैं और अनुपजाऊ होने पर बड़ी जोते भी अनाधिक हो सकती हैं। अतः केवल जोत का आकार ही उसे आर्थिक या अनाधिक नहीं बनाता, बल्कि हमें साथ में वर्षा, सिंचाई की मात्रा, खाद, उत्तम बीज, औजारों व

घोड़े जाने वाली कमतों की किरानों आदि बातों को भी देखना चाहिए जिनका भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। अतः आर्थिक जोत का विचार स्थिर (Static) न होकर प्रारंभिक (dynamic) होता है। प्रायः इस सम्बन्ध में यही कहा जाता है कि खेतों का आकार कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि औसत कृषक परिवार इन पर काम करके आवश्यक व्यय निकाल कर शेष आय के आधार पर आराम से अपना गुजर-बसर कर सके। यह तभी सम्भव हो सकता है जब उसके परिवार के लोगों को खेतों पर साल भर लगातार काम मिलता रहे और पर्याप्त मात्रा में उपज और आमदनी प्राप्त हो सके।

आर्थिक जोत और अनुकूलतम (Economic holding and optimum holding) में भी अन्तर होता है। कांग्रेस भूमि सुधार समिति (कुमारप्पा समिति) ने अपनी 1949 की रिपोर्ट में बतलाया था कि अनुकूलतम जोत या अधिकतम जोत का आकार आर्थिक जोत का तिगुना होना चाहिए। बाद में जब योजना-प्रपत्ति में पारिवारिक जोत (जो वस्तुतः आर्थिक जोत से मिलती-जुलती धारणा है) का प्रयोग किया जान लगा तो यह कहा गया कि एक कृषक परिवार को सीमा-निर्धारण में ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक जोत की तिगुनी मात्रा दी जा सकती है। द्वितीय योजना में पारिवारिक जोत पर दो तरह से विचार किया गया यथा एक तो कार्यशील इकाई (operational unit) के रूप में जिस पर एक कृषक के धर्म व पूंजीगत साधनों को पर्याप्त मात्रा में काम मिल सके और दूसरे भूमि का वह क्षेत्र जिससे लगभग 1600 रु की औसत वार्षिक आय प्राप्त की जा सके। इसे आमदनी इकाई (income unit) की धारणा कह सकते हैं। अतः बहुत छोटी जोतों को मिलाकर आर्थिक जोत बनायी जा सकती है जिससे कृषि अधिक कार्यकुशल हो जाती है। जैसाकि हम ऊपर कह चुके हैं आर्थिक जोत निर्धारित करने के लिए मिट्टी के उपजाऊपन, वर्षा की मात्रा, सिंचाई के उपलब्ध साधन, उपलब्ध पूंजी तथा खेतों के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों, आदि कई बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर भी खेतों का व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष क्षेत्र में आर्थिक जोत की मात्रा कितनी होगी।

बीस वर्ष पूर्व डी एस मेहरा ने आर्थिक जोत की कुछ परिभाषायों पर विचार करके इसी निम्न परिभाषा सुझायी थी जो काफी ठीक प्रतीत होती है। यह "अति परिवार भूमि की वह मात्रा है जिस पर खेतों की लागत निकालने के बाद एक परिवार के धर्मिकों को इनकी रोजी-रोटी मिल जाती है कि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि के अलावा कहीं भी अतिरिक्त काम करने की आवश्यकता नहीं होती (EPW, 23 सितम्बर 1969)" कहने का आशय यह है कि आर्थिक जोत से कृषि की उत्पादन-वाहन के साथ-साथ पारिवारिक धर्मिकों का उपयोग व्यय भी निकल जाना चाहिए।

1966 से भारत में हरित क्रान्ति की शुरुआत से अधिक उपज देने वाली किस्मों, रास यनिक उर्वरकों मिचाई आदि के उपयोग से स्थिति काफी बदली है और निरन्तर बदलती जा रही है। पहले की कुछ अनाधिक जोतें बदली हुई परिस्थितियों में सम्भवतः घायिक बन गई है। इस प्रकार अधिक जोतों का आकार पहले से कम हो गया है।

अतः जोतों के आकार सम्बन्धी प्रश्नों पर अब नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है।

आर्थिक जोत की चर्चा करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि अनाधिक जोतों के स्वामियों को आर्थिक जोत प्राप्त करने में किस प्रकार मदद की जाए। यह प्रश्न भूमि के पुनर्वितरण (Redistribution of Land) से जुड़ा हुआ है। भारत में भूमि सुधारों के कार्यक्रम में सीमा-निर्धारण पर बल दिया गया है। बहुत बड़े आकार के खेतों का बहुधा कुशल प्रबन्ध नहीं हो पाता। अतः सामाजिक न्याय और कुशल उत्पादन दोनों दृष्टियों से ऐसे खेतों का सीमा-निर्धारण के जरिए विभाजन कर दिया जाना चाहिए। इससे सरकार को अतिरिक्त भूमि प्राप्त होगी। प्रश्न उठता है कि इस अतिरिक्त भूमि का उपयोग कैसे किया जाए? इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि इस पर व्यक्तिगत अथवा सहकारी ढंग पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाया जा सकता है। लेकिन इस अतिरिक्त भूमि में से कुछ हिस्सा अनाधिक जोतों के स्वामियों के लिए भी रखा जा सकता है। उनके लिए अधिक भूमि की व्यवस्था इस शर्त पर की जानी चाहिए कि वे सहकारी समुक्त खेतों को अपना लेंगे। इस प्रेरणा व प्रोत्साहन से सम्भवतया वे सहकारी समुक्त खेतों को अपना सकेंगे। हमें यह स्मरण रखना होगा कि अतिरिक्त भूमि में अनाधिक जोतों के स्वामियों को हिस्सा देते समय पुनः चकबन्दी का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसका समाधान कर सकना कठिन नहीं होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में अनाधिक जोतों के स्वामियों का अपना आर्थिक हित व बल्याण भी धिया हुआ है। नयी भूमि के वितरण के समय भी यथासम्भव अनाधिक जोतों के आकार को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ग्रामोस भूमि-सुधार समिति ने 1949 में 'बेसिक जोत' या 'बुनियादी जोत' (basic holding) के विचार का भी समर्थन किया था। बुनियादी जोत आर्थिक जोत से कम आकार की होती है, लेकिन इस पर भी खेती करके किसान अपना गुजर-बसर कर सकते हैं। बुनियादी जोत से कम भूमि निश्चित रूप से अलाभप्रद खेती को जन्म देती है और साथ में अनेक समस्याएँ भी पैदा करती है। लेकिन सामाजिक न्याय के आधार पर बुनियादी जोत पर की जाने वाली खेती का समर्थन किया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनाधिक जोतों के स्वामियों को अपनी जोतों के आकार में वृद्धि करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों व अन्य पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण—भारत में भूमि पर जनसङ्ख्या का भार कम करने के लिए सभी किस्म के उद्योगों का विकास किया

जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लिए विशेष रूप से आधुनिक ढंग पर चलाने वाले कुटीर ग्रामीण व छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व है। गैर-कृषि व्यवसायों का राजी से विकास करने से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की नूल नहीं बनेगी और दक्षी हुई श्रम शक्ति को उद्योगों में काम करने का अवसर भी मिल जाएगा। इसके लिए ग्रामीण उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

जनसंख्या की वृद्धि पर निष्कर्ष—यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि भारत में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से विभिन्न समस्याएँ काफी जटिल बनी हुई हैं। हम पहले बता चुके हैं कि जनसंख्या की वृद्धि से भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्या अधिक खेचीदा हो गई है। अतः भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि पर भी प्रभावपूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए।

छोटे कृषकों व सीमान्त कृषकों की आर्थिक प्रगति के लिए सरकारी प्रयत्न छोटे कृषकों में बहुधा एक से या हैबटेयर जोतों के कृषक आते हैं और सीमान्त कृषकों में एक हैबटेयर तक की जोतों के कृषक आते हैं।

चतुष पञ्चवर्षीय योजना व बाद में तृतीय कृषक विकास एजेंसी (SFDA) कार्यक्रम के माध्यम से इनके कल्याण के लिए आवश्यक योजनाएँ संचालित की गई थी। पाँचवी योजना में देश के 1818 खण्डों में 168 परियोजनाओं पर कार्य किया गया जिससे छोटे कृषकों का सिंचाई की सुविधायें मिलीं।

अब SFDA कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का अंग बना दिया गया है। इस सम्बन्ध में महान कृषि व बहु फल कार्यक्रम, बागवानी सधु सिंचाई भू संरक्षण, भूमि विकास व अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रचार प्रसार के प्रस्ताव सुनी लेती व कार्यक्रमों दुग्ध उत्पादन, मुरगी पालन, सूअर पालन भेड़-बकरी पालन आदि पर भी बल दिया जा रहा है। इस प्रकार सधु सीमान्त कृषकों की आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्ग में प्रयास किया जा रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी दूर करने का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत चुन हुए गरीब परिवारों को कोई परिसम्पत्ति (asset) जैसे दुग्ध पशु, मिलाई की मशीन आदि दी जाती है। इसके लिए सरकार सन्निधी देती है तथा बैंक कर्ज दिया जाता है। यह स्वरोजगार (Self employment) प्रदान करने का तरीका है।

कुछ लोगों का विचार है कि भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता क्योंकि एक बार चक्कड़ों हो जाने के बाद पुन अपखण्डन का खतरा बना रहता है। उत्तराधिकार का नियम बराबर क्रियाशील होने से सुधरी हुई स्थिति पुन बिगड़ सकती है। इस सम्बन्ध में हम पहले बता चुके हैं कि भूमि की एक स्टेण्डर्ड मात्रा तय की जानी चाहिए जिससे जीने की, पढ़ने के, अन्तरण (insurance) व निष्काशन (disposal) पर चालनी संचालन लगायी जानी चाहिए। सहकारी सेवा समितियों के विकास से भी स्थिति में काफी सुधार होगा। तीव्र गति से ग्रामीण औद्योगीकरण व प्रभावपूर्ण परिवार नियोजन से

भी इस समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। स्मरण रहे कि वैयक्तिक कृषि-प्रणाली (individual farming) या कृषक-मूस्वामित्व प्रणाली (Peasant Proprietorship) को कायम रखते हुए भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्या को हल करने के लिए हमारे समस्त उपयुक्त मार्ग हो चुके हैं। जिन देशों में सरकारी अथवा पूँजीवादी खेती (जो क्रमशः सोवियत संघ व अमरीका में) घटे पैमाने पर यन्त्रीकृत खेती के रूप में की जाती है, वहाँ उपविभाजन एवं अपखण्डन का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इस समस्या का सम्बन्ध विशेषतया एक क्षेत्र में प्रचलित कृषि की पद्धति से होता है। हम भारत में ग्रामीण उद्योगों का विकास करना होगा तथा साथ में लघु-वृषकों, सीमान्त वृषकों तथा सतिहर मजदूरों के आर्थिक लाभ के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलायित करने होंगे, तभी इनकी आर्थिक दशा सुधारी जा सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन की स्थिति आधुनिक कृषि के मार्ग में बाधक है और इस समस्या का उचित व स्थायी समाधान निताला जाना चाहिए। सरकार को पचासवीं राज सभाओं व माध्यम से पुन नये निरे में महकारिता व विकास पर बल देना चाहिए। इससे देश को बहुत लाभ होगा।

प्रश्न

1. मक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

(1) भारतीय कृषि में उप-विभाजन व खण्डन की समस्या।

(Raj HYr. T.D.C., 1988)

2. भारत में खेती का उप-विभाजन एवं अपखण्डन किस प्रकार कृषि के विकास में बाधक है? इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?

(Raj HYr T D C., 1985)

3. सहकारी खेती की भारत में क्या आवश्यकता है? इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिये।

(Raj HYr. T.D.C., 1982)

[उत्तर—संकेत—सहकारी खेती के कई रूप होते हैं जैसे (1) सहकारी उन्नत खेती, (2) सहकारी समुक्त खेती, (3) सहकारी सामूहिक खेती, (4) सहकारी वास्तविक खेती। सहकारी उन्नत खेती में सदस्यों की सभी प्रकार के कृषिगत इ-पुट समय पर एवं उचित भावी पर उपलब्ध किये जाते हैं ताकि व उत्पादन बढ़ा सकें। सहकारी समुक्त खेती में छोटे किसान अपने खेत मिलाकर समुक्त खेती करके उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाते हैं। सहकारी सामूहिक खेती में भूमि व अन्य साधन समिति के हो जाते हैं और वृषकों को मजदूरी करनी होती है। सहकारी वास्तविक खेती में सदस्य वास्तविक एक योजना के माफत काम करते हैं तथा यह भी प्रायः नई भूमि पर खेती के लिए अपनाई जाती है।

भूतकाल में भारत में सहकारी समुक्त खेती को लागू करने की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया था। लेकिन इसके मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ पाई गई हैं :

1 कृषकों का अपनी भूमि के प्रति प्रगाढ़ मोह होने के कारण वे दूसरों के साथ अपनी भूमि का टुकड़ा मिलाने के लिए तैयार नहीं होते.

2 पैदावार के वितरण की समस्या काफी गम्भीर होती है.

3 प्रशासनिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं एवं

4 राजकल सहकारी संयुक्त होती पर जोर काफी घट गया है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने विवादरहित विकल्प यही रह गया है कि देश में सहकारी सेवा समितियों को सफल बनाया जाय। कृषकों को इनका सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह बहुउद्देश्यीय हो तथा कृषकों को साख की सुविधा देने के अलावा उर्वरक, बीज, औजार व अन्य कृषिगत इन्पुट उपलब्ध करें तथा उनकी उपज की बिक्री की व्यवस्था कर एवं उनके आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं उचित भावों पर उपलब्ध करें। वे सुभाव ऊपर से बड़े सरल लगते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में प्रगति सतोष-जनक नहीं हो पाती। अतः जो कुछ सैद्धान्तिक दृष्टि से सही जान पड़ता है उसे व्यावहारिक, प्रशासनिक, संगठनात्मक व वित्तीय दृष्टि से घाठवी योजना में सफल बनाया जाना चाहिए।

भारत में प्रत्येक समस्या के जाने-माने हल विद्यमान हैं, आवश्यकता है उनकी कड़ाई से लागू करके समस्या का समाधान करने की। इसके लिए प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक होती है।

जिस प्रकार सरकार ने हाल में पचासवीं राज सभाओं को सक्रिय करने की ठान ली है, उसी प्रकार यदि सहकारी कृषि व उत्पादन की दिशा में ठोस प्रयत्न हों तो ग्रामीण क्षेत्रों को काफी लाभ पहुँच सकता है।



सिंचाई, उर्वरक व अन्य साधन तथा कृषि में यन्त्रीकरण

(Irrigation, Fertiliser, Other Inputs and
Mechanisation of Agriculture)

भारतीय कृषि को 'मानसून का जुझा' कहा जाता है। वर्षा पर निर्भर रहने के कारण ही हमारी कृषि में अनिश्चितता व अस्थिरता पाई जाती है और कृषि के वाणिज्य उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। सिंचाई के लिए साधनों का विकास करके कृषि में अधिक स्थिरता की दशाएं उत्पन्न की जा सकती हैं।

भारत में सिंचाई का महत्व

ग्रन्थ देशों की अपेक्षा भारत जैसे देश में सिंचाई का विशेष रूप से महत्व है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :

(1) वर्षा की अनिश्चितता—भारत में वर्षा के सम्बन्ध में अनिश्चितता की स्थिति पायी जाती है। किसी वर्ष वर्षा कम होती है, तो किसी वर्ष ज्यादा। कभी शुरु में अच्छी वर्षा हो जाती है, लेकिन बाद में कई महीने व सप्ताह सूखे निकल जाते हैं और फलस्वरूप पैदावार नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में खेती पूर्णतया 'मानसून का जुझा' बन जाती है। ऐसी दशा में सिंचाई की व्यवस्था होने से ही मानसून की अनिश्चितता से मुक्ति मिल सकती है।

(2) वर्षा की अपर्याप्तता—भारत में वर्षा का वितरण सर्वत्र एक-सा नहीं है। एक ओर चेरापूँजी में वर्षा का वार्षिक औषत 428 इंच पाया जाता है, तो दूसरी तरफ जंजलमेर में 4 इंच ही। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने से ही खेती की जा सकती है।

(3) वर्षा की मौसमी प्रकृति—भारत में वर्षा अधिकतर वर्षा-ऋतु में ही होती है जिसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। इन महीनों में होने वाली फसलें तो वर्षा के सहारे भी हो सकती हैं, लेकिन साल के शेष महीनों में सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। पंजाब में थोड़ी वर्षा बाड़े के दिनों में भी होती है,

लेकिन वह प्रायाग रहनी है। इसलिए सात मर लेनी करन के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था का होना आवश्यक माना जाता है। भारत में एक से अधिक फसलों के कार्यक्रम अथवा बहु-फसल कार्यक्रम (multiple cropping) को सफल बनाने के लिए सिंचाई का विस्तार करना बहुत आवश्यक है ताकि देश में कृषिगत उत्पादन बढ़ाया जा सके।

(4) विशेष फसलों के लिए—गन्ने व चावल की भेती को पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और यह सिंचाई से ही मिल सकता है। आजकल खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में रबी के उत्पादन का अंश बढ़ रहा है। यह 1960 की दशादी में 1/3 से कम था, जो 1987-88 में 45% में भी कुछ अधिक हो गया है। इनसे भी निचई में यह वृद्धि बढ़ गया है जो रबी की फसलों में गेहूँ, जौ चना आदि फसलें सिंचाई की महामयता से अधिक पैदावार दे सकती हैं।

(5) कृषिगत क्षेत्रों में सुधार—सिंचाई के माध्यम से कृषिगत क्षेत्रों का मजबूत हो रहा है। यह देखा गया है कि पहाड़ों के क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की कमी रहती है और उन क्षेत्रों की पूर्ति के लिए सिंचाई के साधन नहीं होते हैं। जब से भारत में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है तब से पहाड़ों की समस्या व भीषणता में कमी आयी है। पहले सिंचाई के साधनों में उत्पादक (productive) व रक्षात्मक (protective) नाम से दो भेद किये जाते थे। इनमें रक्षात्मक साधनों का उद्देश्य कृषिगत क्षेत्रों में सुधार लाना ही होता था।

(6) गहन खेती सम्भव एवं कृषिगत उत्पादकता में सुधार—भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गहन खेती बहुत आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई, उत्तम बीज, खाद व कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इन सबका प्रयोग एक साथ किया जाना चाहिए अन्यथा उपज नहीं बढ़ेगी। अतः गहन खेती के कार्यक्रम में सर्वोच्च स्थान सिंचाई का ही दिया गया है। इससे कुल उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती है। कृषि-विकास की नई नीति में सिंचाई का स्थान प्रमुख माना गया है, क्योंकि अधिक उपज देने वाली किस्में आवश्यक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों की आवश्यकता के साथ बहुत निश्चित क्षेत्रों में ही प्रयुक्त की जाती है।

(7) उपज की किस्म में सुधार—भारत में सिंचाई के उपयोग से उपज की मात्रा में बढ़ने के साथ-साथ उसकी किस्म में सुधार होता है जिससे किसानों की आय बढ़ती है और उनका रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होता है।

(8) नई भूमि पर खेती करना सम्भव—भारत में कुछ कृषि-योग्य भूमि बंकार पड़ी है। सिंचाई के साधनों का विस्तार करके प्रतिरिक्त भूमि खेती के प्रयुक्त लायी जा सकती है। सिंचाई के अभाव में ऐसी भूमि को खेती के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के बन जाने से नयी भूमि पर पहली

बार कृषि प्रारम्भ की गई है। इस प्रकार सिंचाई से विस्तृत भेती (extensive cultivation) में सम्भावनाएँ भी बढ़ती हैं। सातवी योजना में अनुमान लगाया गया है कि सिंचित क्षेत्र में 1% की वृद्धि से कुल कृषित क्षेत्र में 0.31% की वृद्धि होगी।

(9) रोजगार में वृद्धि—ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई का विस्तार करना बहुत आवश्यक माना गया है। इसमें शुरू में सिंचाई के निर्माण कार्यों में रोजगार मिलता है और बाद में उत्पादन बढ़ाने पर अन्य सहायक कार्यों में भी रोजगार बढ़ता है। इस प्रकार सिंचाई के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मात्रा में रोजगार के नये अवसर बढ़ते हैं।

(10) सरकारी आय में वृद्धि—सिंचाई की व्यवस्था बढ़ने से सरकार की आय में प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से वृद्धि होती है। कृषकों की आय बढ़ने से सरकार को भूमि-करों व कृषिगत आय-करों से अधिक आमदनी होती है। यह सरकार की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि मानी जा सकती है। कृषिगत उपज के बढ़ने से रेलों को अधिक माल ढोने के लिए मिलता है जिससे रेलों की माल भाड़े से प्राप्त आय भी बढ़ जाती है। यह सरकारी आय में परोक्ष रूप से होने वाली वृद्धि कही जा सकती है।

(11) यातायात की सुविधा—नहरों से सिंचाई के साथ-साथ यातायात की सुविधा भी बढ़ती है। रेलों से केवल यातायात ही हा पाता है, जबकि नहरों से सिंचाई व यातायात दोनों सम्भव हो जाते हैं।

(12) सिंचाई से मूल्य स्थिरकरण में सहायता मिलती है—क्योंकि कृषिगत उत्पादन से अनिश्चितता का तत्व काफी सीमा तक कम हो जाता है। इसलिए अनाज व कच्चे माल के भाव अधिक स्थिर हो जाते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्रन्थ-व्यवस्था में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। नहरों की सिंचाई से प्रायः हानियाँ भी होती हैं और विशेषतया ये अवस्थित किस्म की सिंचाई कई बार भारी शक्ति पहुँचा देती है।

हानियाँ—(1) भूमि की ऊपरी सतह पर नमक जमा हो जाता है जिससे क्षारयुक्त या खारी मिट्टी (alkaline soils) की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे बहुत सी भूमि खेती के योग्य नहीं रहती। (2) मलेरिया व अन्य रोग उत्पन्न होने लगते हैं। (3) बाढ़ का भय उत्पन्न हो जाता है।

सिंचाई की उपर्युक्त हानियाँ पानी के उचित वहाव की व्यवस्था (proper drainage) करके तथा पक्की नहरें आदि बनावर कम की जा सकती हैं।

विभिन्न स्रोतों व फसलों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल

भारत के विभिन्न भागों में घातल की रचना एक-सी न होने से देश में कई प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिये जाते हैं। उत्तरी भारत में नहरों और कुओं की सिंचाई की प्रधानता है और दक्षिण में तालाबों का सिंचाई के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है।

भारतीय योजनाओं में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 1950-51 में 2.26 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई जो बढ़कर 1986-87 में 6.44 करोड़ हेक्टेयर में होने लगी। इसमें बृहद् व मध्यम स्कीमों का अंश 2.65 करोड़ हेक्टेयर तथा लघु स्कीमों का अंश 3.79 करोड़ हेक्टेयर पाया गया है। इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्र में लघु योजनाओं का योगदान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। 1987-88 में सिंचित क्षेत्रफल 6.63 करोड़ हेक्टेयर हो गया था।

1971-72 में मकस सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का 24% था जो 1984-85 में 33.7% आया गया है। इसके 1989-90 में 37.6% हो जाने का लक्ष्य रखा गया है।¹ इस प्रकार भारत में अब लगभग 1/3 कृषित क्षेत्र में सिंचाई की जाने लगी है।

भारत में सिंचाई की विशेष सुविधा गन्ने, गेहूँ, जौ व चावल की फसलों को प्राप्त है। अन्य फसलों के लिए सिंचाई का प्रायः प्रभाव पाया जाता है। 1985-86 में गन्ने के कुल क्षेत्रफल 87.3% भाग पर सिंचाई की गई। गेहूँ के 75% क्षेत्रफल जो के 49.0% क्षेत्रफल व चावल के 42.1% क्षेत्रफल में सिंचाई की गई। ज्वार का सिंचित क्षेत्रफल केवल 4.6% व बाजरे का 5.4% ही रहा। कपास के 27.9% तथा तिलहन के 16.0% क्षेत्रफल में सिंचाई की गई।²

पहले के वर्गीकरण के अनुसार सिंचाई के साधनों का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।³

1. कुएँ—1983-84 की सूचना के अनुसार भारत में सिंचित क्षेत्रफल के लगभग 46.5% भाग में कुओं से सिंचाई की गई थी। कुएँ दो प्रकार के होते हैं नलकूप व ग्रन्थ। पंजाब, हरियाणा व उत्तर-प्रदेश में ट्यूब-वैल का बहुत प्रयोग हुआ है। योजनाकाल में इन राज्यों में ट्यूब-वैल लगाने का कार्यक्रम रखा गया था जिससे कुओं की सिंचाई का क्षेत्रफल काफी बढ़ा है।

2. तालाब—उसी वर्ष विस्तृत सिंचित क्षेत्र के लगभग 9% भाग में तालाबों से सिंचाई की गई थी। बनारस, हैदराबाद, रायस्थान का दक्षिणी-पूर्वी पहाड़ी भाग और मध्य प्रदेश तालाबों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तमिलनाडु का पेरियर बाघ काफी विस्तृत रहा है। दक्षिणी भारत में नदियों की धाराएँ तेज होती हैं। वे साल भर नहीं बहती हैं। भूमि सघन नहीं है एवं पथरीली है। इसलिए

1. Seventh Five Year Plan : Mid Term Appraisal, 1988, p. 79.
2. Economic Survey 1988-89, p. S-22.
3. Statistical Outline of India, 1988-89, p. 59.

घरातल की बनावट तालाब बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त पायी गई है। तालाबों की सिंचाई में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनमें वर्षा का पानी एकत्र होता है, इसलिए जिस साल वर्षा कम होती है, उस साल इनमें पानी कम आता है। इनमें मिट्टी भी भर जाती है। भारत में बहुत से तालाबों में प्रायः मरम्मत की आवश्यकता बनी रहती है।

3. नहरें—विशुद्ध सिंचित क्षेत्र के 38.7% लगभग (2/5) भाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है एवं शेष 5.7% भाग में अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। नहरों की सिंचाई में सरकारी नहरों का अंश 37.5% तथा गैर-सरकारी या प्राइवेट नहरों का 1.2% है। भारत में नहरों की कुल लम्बाई सप्ताह में सबसे अधिक है। नहरों की सिंचाई सस्ती, सुविधाजनक और सुनिश्चित होने से आजकल बहुत प्रचलित हो गयी है। नहरें तीन प्रकार की होती हैं—

(1) बाढ़ वाली नहरें (inundation canals), (2) बाध वाली नहरें (perennial canals), (3) स्टोरेज या जलाशय की नहरें (storage canals)।

(1) बाढ़ की नहरों में नदी में बाढ़ आने पर ही पानी आता है। अतः इनसे थोड़े समय के लिए ही सिंचाई हो पाती है। आजकल इस प्रकार की नहरों का प्रचलन बहुत कम हो गया है। (2) बाध की नहरें नदी पर बांध बनाकर निकाली जाती हैं। इनसे साल भर सिंचाई होती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पूर्वी पंजाब, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान व अन्य राज्यों में बांध वाली नहरें बनायी गयी हैं। (3) स्टोरेज की नहरों में वर्षा का जल घाटों के आर-पार बांध बनाकर एकत्र किया जाता है। ऐसी नहरें तमिलनाडु व दक्षिण भारत में पायी जाती हैं। इन नहरों का सम्बन्ध नदियों से नहीं होता है।

भारत में सिंचाई के साधनों का विकास

सिंचाई के साधन बड़े, मध्यम व छोटे—तीन भागों में बांटे जाते हैं। पहले 10 लाख रुपये या इससे कम लागत की सिंचाई की योजनाएँ छोटी (minor), 10 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की मध्यम (medium) और 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत की योजनाएँ बड़ी (major) मानी जाती थी। लेकिन अप्रैल, 1978 से सिंचाई के साधनों का निम्न वर्गीकरण लागू किया गया है—

(अ) लघु स्कीम—2,000 हेक्टेयर तक कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र (culturable command area) (CCA)।

(ब) मध्यम स्कीम—2,000 हेक्टेयर से अधिक, लेकिन 10,000 हेक्टेयर तक का कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र,

(स) बृहद् स्कीम—10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र।

यह ध्यान देने की बात है कि भारत में सिंचित क्षेत्र विश्व के अन्य सभी देशों के मुकाबले में सबसे अधिक है। लेकिन हमारे देश की आवश्यकताओं को देखते हुए

आज भी यह कम है। आजकल भारत में कुल सिंचित क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र का 33 प्रतिशत हो गया है। जापान में यह आधे से भी अधिक है। मिस्र में गत-प्रतिगत कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। पाकिस्तान में भी यह 40% से अधिक है। इस प्रकार सिंचाई की दृष्टि से भारत की स्थिति पहले से काफी सुधरी है, हालांकि समय और प्रयत्न की जा सकती है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के साधनों का विकास

सिंचाई पर व्यय—1951-80 की अवधि में सिंचाई की वृद्धि व मध्यम योजनाओं पर 7510 करोड़ रु तथा लघु योजनाओं पर 2503 करोड़ रु व्यय किए गए। इस प्रकार सिंचाई पर कुल 10,013 करोड़ रु. व्यय किये गये। यह ज्ञातना रुचिपूर्ण होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 की अवधि में सिंचाई की वृद्धि व मध्यम योजनाओं पर 7516 करोड़ रु व लघु योजनाओं पर 1802 करोड़ रु व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार छठी योजना में सिंचाई से विकास पर 9318 करोड़ रु. की राशि के व्यय होने का अनुमान था। सातवीं योजना, 1985-90 की अवधि में वृद्धि व मध्यम सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 11,556 करोड़ रु तथा लघु योजनाओं के लिए 2805 करोड़ रु. निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार सिंचाई के विकास के लिए कुल 14361 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है जो पहले से काफी अधिक है।¹

1950-51 से 1986-87 तक की अवधि में सिंचाई का विकास निम्न तालिका में दर्शाया गया है।²

सिंचाई के साधन	1950-51		1986-87	
	सम्भाव्यता	उपयोग	सम्भाव्यता	उपयोग
1. वृद्धि व मध्यम स्कीम	0.97	0.97	3.12	2.65
2. लघु स्कीम	1.29	1.29	4.08	3.79
कुल	2.26	2.26	7.20	6.44

1 Seventh Five Year Plan 1985-90, Vol II, p. 73, p. 87 and p. 91.

2 Ibid, p. 72, & Economic Survey 1988-89, p. 20, and p. S-21.

जैसा कि पहले भी बतलाया गया है 1950-51 में सिंचाई का उपयोग 2 26 करोड़ हेक्टेयर में किया गया था जिसे बढ़ाकर 1986-87 में 6 44 करोड़ हेक्टेयर में किया गया है। छठी योजना की अवधि में सिंचित क्षेत्रफल में लगभग 23 लाख हेक्टेयर प्रनिवर्ण की वृद्धि हुई जो उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। 1986-87 में सिंचाई की सम्भ्यता (Irrigation potential) 7 2 करोड़ हेक्टेयर में उत्पन्न कर दी गई थी लेकिन सिंचाई का वास्तविक उपयोग (utilisation) 6 44 करोड़ हेक्टेयर में किया गया। इन प्रकार सिंचाई की सम्भाव्यता व उपयोग में अन्तर पाया जात है जो विफलता, वृहद् व मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत अधिक दान को मिलता है। भारत में सिंचाई की अन्तिम सम्भाव्यता (ultimate potential) लगभग 11 35 करोड़ हेक्टेयर घाटी गयी है, जिसमें 5 85 करोड़ हेक्टेयर वृहद् व मध्यम स्वीमा क अन्तर्गत तथा शेष 5 50 करोड़ हेक्टेयर लघु स्वीमा क अन्तर्गत है। इसका प्रत्यक्ष कर लिया जान पर कृषि क्षेत्र व आधे भाग पर सिंचाई होन लगेगी।

भारत में सिंचाई की सम्भाव्यता व इसके वास्तविक उपयोग के बीच अन्तर 1986-87 में 76 लाख हेक्टेयर रहा।

सिंचाई की सम्भाव्यता के कम उपयोग के लिए निम्न तत्व जिम्मेदार रहे हैं। सिंचाई के प्रोजेक्ट के मुख्य कार्य पूरे हो जाने पर भी कमांड-क्षेत्र-विकास का काम धीमा रह गया। खेतों में नालिया व बहाव के मार्ग बनाने में विलम्ब पाया गया, सिंचाई-यवस्था के ऊपरी मार्ग पर कृषकों ने ज्यादा पानी खींच लिया, कमलों का प्रारूप ऐसा अपना लिया जो प्रोजेक्ट-रिपोर्ट से सर्वथा भिन्न निकला एवं पानी के जमीन में अत्यधिक सोखे जाने से भी सिंचाई की उत्पन्न-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है।

भारत में सिंचाई का विकास सभी राज्यों में समान रूप से नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों में सिंचित क्षेत्रफल का अंश बहुत ऊँचा है और कुछ में बहुत नीचा है।

सिंचाई के विकास की दृष्टि से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश की स्थिति पिछड़ी हुई है, जबकि तमिलनाडु, पंजाब आदि की स्थिति काफी अच्छी है। पंजाब में सकल कृषि क्षेत्र के लगभग 88 प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है जबकि मध्य प्रदेश में 12 प्रतिशत भाग पर ही की जाती है (1983-84 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का औसत लेने पर)। भविष्य में पिछड़े राज्यों में सिंचाई के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।¹

भारत में ग्राजकस सिंचाई के छोटे साधनों पर विशेष बल दिया जाने लगा है क्योंकि उन पर थोड़ा व्यय होता है और कृषियुक्त पैदावार अल्पकाल में ही बढ़

जाती है। इसके अतिरिक्त उनकी व्यक्तिगत देख-रेख की जा सकती है और प्रबंध आदि की कठिनाई भी नहीं होती। भारत में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए छूटे, मध्यम व बड़े सभी प्रकार के सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। इनमें परस्पर प्रभावपूर्ण ताल-मेल व समन्वय भी स्थापित किया जाना चाहिए।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है पिछले वर्षों से एक समस्या और सामने आयी है। वह यह है कि सिंचाई की नयी उत्पन्न की नयी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार उत्पन्न-क्षमता व वास्तविक उपयोग के अंतर को कम करने का प्रयास कर रही है।

1986-87 में लगभग 76 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया था। बिहार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में विशेष रूप से सिंचाई की क्षमता के उपयोग का अभाव पाया गया है। बिहार में कोसी व मध्य प्रदश में पम्बल क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता का कम उपयोग हुआ है। महाराष्ट्र में भी कई परियोजनाओं में यह लक्षण पाया गया है। सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं की लागत के अनुमानों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है जिससे सरकार के समक्ष वित्तीय कठिनाईयाँ उत्पन्न हो गई हैं।

सिंचाई के साधनों का उपयोग बढ़ाने के लिए खेतों तक पानी की नालियाँ (field channels) बनानी होती हैं। गुजरात व उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई भाग में एव कर्नाटक व महाराष्ट्र के लगभग आधे भाग में फील्ड चैनल्स का काम मार्च 1982 तक पूरा कर लिया गया था, लेकिन अन्य राज्यों की स्थिति असन्तोषजनक थी। पंचायत समितियों व ग्राम-पंचायतों की देख-रेख में यह कार्य किया जाना चाहिए। किसानों को नई फसलों का ज्ञान एव सुधरी हुई खेती की पद्धतियों की जानकारी कराई जानी चाहिए। पानी के प्रयोग में कृषिगत की जानी चाहिए। सुधरे हुए बीज, खाद, साख, बिजली, गोबर व परिष्कृत की व्यवस्था तेजी से करनी चाहिए जिससे सिंचाई का अधिकतम लाभ मिल सके। प्रारम्भिक वर्षों में सिंचाई के लिए पानी की दरों में रियायतें दी जा सकती हैं।

भारत में सिंचाई की मुख्य परियोजनाएँ¹

योजनाकाल में सिंचाई की बृहद् परियोजनाओं तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर काफी बल दिया गया है। नदी-घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई के अलावा विद्युत्, नौकायन पर्यटन, भ्रसरक्षण, वृक्षारोपण आदि का विकास करना भी है।

आगे सिंचाई की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है :

1. India 1984 pp 275-282. आगे India 1987 में ये नहीं दी गयी है।

1. **भाखड़ा-नागल परियोजना (पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान)**—यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी-घाटी योजना मानी गयी है। यह 236 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई है। इसने प्रन्तर्गत भाखड़ा के पास सतलज के द्वार-पार 518 मीटर लम्बा तथा 226 मीटर ऊँचा सीधा प्रविटी बाँध, 29 मीटर ऊँचा नागल बाध, 64 किलोमीटर लम्बी नागल हाइडल चैनल, भाखड़ा बाध पर दो बिजली घर तथा हाइडल चैनल पर गगुवान व कोटला बिजली घर तथा 1,110 किलोमीटर लम्बी नहरें व 3,400 किलोमीटर लम्बी वितरिकाएँ प्राप्ती हैं। भाखड़ा की नहरों से 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है।

2. **दामोदर घाटी निगम (पश्चिमी बंगाल तथा बिहार)**—इसमें निलया, कोनार, माइयन व पचेट पहाड़ी नामक चार बाध बनाये गये हैं। चारों बाँधों के साथ पन बिजली घर बनाये गये हैं। बोकारो, दुर्गापुर एवं चन्द्रपुरा में तीन ताप (थर्मल) बिजली घर बन हैं। दुर्गापुर में एक सिंचाई जलाशय बना है जिससे नहरें एवं शाखाएँ निकाली गयी हैं। दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में दामोदर नदी पर एक जलाशय बनाया गया है।

3. **हीराकुड (उड़ीसा)**—हीराकुड बाँध महानदी पर बनाया गया है और यह विश्व का सबसे लम्बा बाँध है। इसका प्रथम चरण पूरा हो गया है और उससे सम्बलपुर एवं बोलनगीर जिलों में सिंचाई होने लगी है। द्वितीय चरण में बिपनिमा बिजली घर की स्थापना एवं हीराकुड बिजली घर का विस्तार कार्य पूरा हो गया है। महानदी डेल्टा सिंचाई स्कीम पर काम जारी है। इसके पूरा होने पर कटक और पुरी जिलों में सिंचाई की जा सकेगी।

4. **तुंगभद्रा (प्रान्ध प्रदेश और कर्नाटक)**—इसमें मल्लापूरम में तुंगभद्रा नदी पर एक बाँध बनाया गया है। इसमें बायें किनारे की नहर एवं ऊँची व नीची सतह वाली नहर प्रान्ध प्रदेश तथा कर्नाटक में सिंचाई का कार्य करेगी। इस योजना पर अभी काम जारी है।

5. **कोसी (बिहार)**—इस परियोजना से बिहार में बाढ़ की क्षति कम हुई है। इसकी प्रथम इकाई में नेपाल में हनुमाननगर के पास जलाशय, दूसरी इकाई में बाढ़ की पालें व अन्य कार्य एवं तीसरी इकाई में पूर्वी कोसी नहर प्रणाली शामिल किये गये हैं। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से उत्तरी बिहार में पूर्णिया एवं महरमा जिलों में सिंचाई होगी।

कोसी परियोजना के दूसरे चरण में कोसी बिजलीघर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर एवं पूर्वी बाढ़ की पालों का विस्तार कार्य शामिल है। इन सभी पर काम जारी है। इसकी सिंचाई की अन्तिम क्षमता 8.48 लाख हेक्टेयर होगी।

6. **चम्बल (मध्य प्रदेश एवं राजस्थान)**—इसके प्रथम चरण में गाँधी सागर बाँध, इसका 115 मेगावाट का बिजलीघर, वितरण की व्यवस्था, कोटा जलाशय

(barrage) एवं दोनों तरफ की नहरे हैं, जो पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में राणाप्रताप सागर बांध और इसके नीचे एक विजलीघर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तीसरे चरण के अन्तर्गत जवाहर सागर बांध और एक विजलीघर का निर्माण कार्य जारी है। तीनों चरणों के पूरा होने पर 5.15 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी।

7 व्यास (पञ्जाब हरियाणा तथा राजस्थान)—इसकी पहली इकाई में 8 गम सतलज नदी है दूसरी में पोग स्थान पर व्यास बांध है तथा तीसरी में व्यास ट्रांसमिशन सिस्टम है। तीनों इकाइयों की कुल लागत 715 करोड़ रुपये अनुमानित है। व्यास-ममनल नदी (link) मुख्यतया एक पावर प्रोजेक्ट है। पोग पर व्यास बांध मुख्यतया एक सिंचाई की योजना है। यह बांध 1974 में पूरा हो गया था। यह योजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में 17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। व्यास परियोजना राजस्थान को प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई की सुविधा नहीं देगी, बल्कि यह स्थायी रूप से इन्दरा गांधी नहर परियोजना के लिए पन की पूर्ति करेगी।

इराडी आयोग की 1 मई 1987 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब की रावी-व्यास नदियों के जल का 50 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को 38.3 लाख एकड़ फुट पानी तथा राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी मिलेगा। राजस्थान के हिस्से में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस प्रकार राजस्थान के हिस्से की पूरी तरह रक्षा नहीं हो पाये है।

8 राजस्थान नहर (श्री इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान)—यह पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरीके जलाशय (Harake (barrage) से निकाली गई है। इस परियोजना के दो भाग हैं—राजस्थान फीडर : 204 किलोमीटर लम्बी होगी जिसका प्रथम 167 किलोमीटर का भाग पंजाब तथा हरियाणा में होगा और शेष 37 किलोमीटर राजस्थान में। (ii) राजस्थान मुख्य नहर यह 445 किलोमीटर लम्बी होगी और राजस्थान तक ही सीमित होगी। मुख्य नहर मगानगर जिले में हनुमानगढ़ के 40 मील उत्तर से चलकर जैसलमेर जिले में रामगढ़ तक जायगी। इस नहर पर जून, 1958 से कार्यारम्भ हो गया था। इसके पूरा हो जाने से अकाल-साहू पर व्यय घटाया जा सकेगा। इससे रावी तथा व्यास के जल का भी पूरा उपयोग हो सकेगा।

यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जा रही है। प्रथम चरण में सम्पूर्ण फीडर नहर और 189 किलोमीटर राजस्थान मुख्य नहर व 3075 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली है। फीडर नहर और मुख्य नहर का काम पूरा हो गया है। मुख्य लूनकरनगर-बीकानेर लिफ्ट नहर तथा पूगल शाखाएँ भी पूरी कर ली गई हैं। प्रथम चरण का महत्व बढ़ गया है क्योंकि राज्य की योजना में क्षेत्रीय विकास पर धन

दिया जा रहा है और विश्व बैंक से भूमि-विकास के लिए सहायता मिली है। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर एवं उसकी 4800 किलोमीटर लम्बी वितरण व्यवस्था होगी। इस योजना से नई भूमि पर खेती की जायेगी। योजना के पूर्ण होने पर बीकानेर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर जिलों में 13.88 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा सकेगी।

आगामी 10 वर्षों में जैसलमेर का क्षेत्र गंगानगर से भी ज्यादा हरा-भरा हो जायेगा। अनुमान है कि सिंचाई के फलस्वरूप 37 लाख टन अनाज पैदा होगा एवं करोड़ों ह. की अन्य फसलें उगाई जा सकेंगी। दोनों चरणों की कुल अनुमानित लागत 1186 करोड़ रुपये रखी गयी है। इसमें प्रथम चरण की 255 करोड़ र तथा द्वितीय चरण की 931 करोड़ र रखी गयी है।

जनवरी 1987 तक मुख्य नहर का काम लगभग पूरा हो गया था। मोहनगढ़ से आगे राजस्थान नहर के अन्तिम छोर से लीलवा झाला निकाली जा रही है जिसका निर्माण भी तजी से प्रारम्भ किया गया है। एक और बड़ी शाखा दीघा भी निकाली जायेगी। जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सिरीज के क्षेत्र का भारी योगदान होगा। वहाँ की समतल भूमि में पानी पट्टवते ही खेती होने लगेगी। आज भी वहाँ माझूली वर्षा से सीवण घास पैदा होती है जो पशुओं के लिए काफी पोषित्व मानी गई है।

इन्दिरा गांधी सशोधित यात्रना में छ जलोत्थान या लिफ्ट योजनाओं—साहवा, गजनेर, कोलाग्रत, फनौदी, पोंकरन तथा बाड़मेर से थार रेगिस्थान में खेती व पेड़ों का विस्तार करने पर काम चल रहा है। इनके अन्तर्गत 60 मीटर ऊँचाई तक नहरी पानी को उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी।

इसके अलावा सिंचाई की अन्य बड़ी योजनाओं में पंजाब के धीन बांध (Thein dam) को लिया जा सकता है जो पंजाब में रावी नदी पर बनाया जा रहा है। इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। अन्य योजनाओं में नागार्जुन सागर (आंध्र-प्रदेश), पोचमपाड (आंध्र), गडक (बिहार व उत्तर प्रदेश), काकरापारा, उर्दू और माही (गुजरात) बाद्रा, ऊपरी कृष्णा, व मालप्रभा (कर्नाटक), तावा (मध्य प्रदेश) भीमा, जयकवाडी (महाराष्ट्र), सारदा सहायक व रामगंगा (उत्तर प्रदेश) तथा मयुराक्षी व कागसावाटी (पश्चिमी बंगाल) के नाम उल्लेखनीय हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय योजनाओं में काफी धनराशि का विनियोजन किया गया है। इनके लाभ काफी लम्बी अवधि तक प्राप्त होंगे और देश में कृषिगत पैदावर बढ़ेगी।

भारत में सिंचाई की परियोजनाएँ समय पर पूरे क्यों नहीं होती ?

प्रायः यह देखा गया है कि सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने में बहुत विलम्ब हो जाता है। इससे लागत अनुमान से ज्यादा हो जाती है और योजनाओं

से लाभ मिलने में देर हो जाती है। अग्रेज 1976 से पूर्व चालू की गई 40 परियोजनाएँ अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं।

छठी योजना में 574 मिलियन हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक उपलब्धि केवल 40 मिलियन हेक्टेयर हो रही है।

सिंचाई की परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं—

1. मुद्रास्फीति के कारण प्रोजेक्टों की लागत में वृद्धि 2. पर्याप्त वित्तीय साधनों का अभाव 3. प्रोजेक्टों की अरमार जिससे, 4. साधनों को अनेक प्रोजेक्टों पर छोड़ा-छोड़ा फैलाना पड़ता है, 5. भूमि प्राप्त करने में विलम्ब, 6. पुनर्वास की समस्याएँ, 7. विदेशी सहायता नये प्रोजेक्टों के लिए मिलती है जब चालू परियोजनाओं के लिए स्वदेशी साधनों पर निर्भर रहना होता है, 8. सीमेंट, इस्पात व विस्फोटक पदार्थों का अभाव होता है तथा 9. आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है।

सरकार की सिंचाई नीति—द्वितीय सिंचाई आयोग ने 1972 में एक उच्च-स्तरीय 'राष्ट्रीय जल साधन परिपद' की स्थापना की सिफारिश की थी जो नीतियाँ व प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है। नवी घाटी योजनाओं को तैयार करने व प्रोजेक्ट के अनुसार विकास कार्यक्रम बनाने के लिए नदी घाटी आयोगों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। भूछात्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के कार्यक्रमों की ऊँची प्राथमिकता देने, नहरी क्षेत्रों में सतह व भूतल के जल के इकट्ठे उपयोग पर बल देने, चालू सिंचाई के कार्यक्रमों में सुधार करने और बहाव व पानी के निरास को अधिक व्यवस्थित करने के सुझाव दिये गये थे।

कुछ वर्ष पूर्व कैप्टन दस्तूर ने गारलैंड नहर योजना (Garland Canal Plan) प्रस्तुत की थी जिसमें हिमालय की तलहटी के जल-साधनों को दक्षिण भारत की नहरों से जोड़ने का सुझाव दिया गया था। डॉ. के.एस. राव ने गंगा-कावेरी नहर लिंक योजना का सुझाव दिया था जिसके अन्तर्गत गंगा के जल को कावेरी में मिलाने का कार्यक्रम था, ताकि दक्षिण भारत में सिंचाई का विस्तार किया जा सके। प्राकृतिक साधनों के अभाव में इस योजनाओं को कार्यान्वयन के लिये स्वीकार नहीं किया जा सका। पिछले वर्षों में सरकार की सिंचाई नीति की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं—

1. केन्द्रीय जल आयोग के सत्वावधान में (एक सेंद्रीय मॉनिटरिंग (monitoring) समूह स्थापित किया गया है जो चालू परियोजनाओं की प्रगति की देख-रेख करता है और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सुझाव देता है। इसने कुछ राज्यों में चुने हुए प्रोजेक्टों में काफी प्रगति करने में मदद की है। ऐसे ही नगठन राज्यों में भी स्थापित किये जान चाहिए।

2. भूतल के जल-साधनो (ground water resources) के विकास को ऊँची प्राथमिकता दी गई है। परिणामस्वरूप खुदे हुए कुएँ, (dug-wells), नन कूपों, पम्प-सेटो (डीजल व बिजुत) का तेजी से विस्तार किया गया है।

भूतल के जल-साधनो का अध्ययन किया जाना चाहिए और इनका पूरा लाभ उठाने के लिए अपवर्णन की समस्या हल की जानी चाहिए तथा चक्रवन्दी के कार्यक्रम को सफल बनाया जाना चाहिए। साथ में गाँवों में विराम का आधार-टाचा भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3. कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया है। पाँचवी योजना में एक एकीकृत कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास-प्राधिकरण (CADA) की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में भूमि व जल प्रयोग के प्रवर्णन में सुधार करना था ताकि सिंचाई की उत्पन्न क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

इस कार्यक्रम में नेतों की नालियों (फील्ड चैनलों) का निर्माण करना, भूमि को समतल बनाना (Land levelling) व सिंचाई की व्यवस्था को आधुनिक बनाना पर बल दिया गया है। छठी योजना के आरम्भ में 76 परियोजनाओं पर काम जारी था जो बढ़ कर सातवी योजना के आरम्भ में 102 हो गई हैं।

छठी योजना में इस कार्यक्रम पर 818 करोड़ रु. व्यय किये गये तथा सातवी योजना में 1671 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया। फील्ड चैनल बनाने, भूमि को समतल करना व 'बाराबन्दी' (Warabandi) जल-वितरण प्रणाली लागू करने के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जायेगा। बाराबन्दी प्रणाली में प्रत्येक मज्दाह बारी-बारी से टुकड़ों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाता है ताकि सबको समान रूप से सिंचाई का पानी मिल सके।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में सिंचाई के विकास का कार्यक्रम

भारत में सिंचाई की अन्तिम सम्भाव्यता (Ultimate Irrigation Potential) 11.35 करोड़ हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें 7.35 करोड़ हेक्टेयर में सतह के जल की है तथा 4 करोड़ हेक्टेयर में भूतल के जल की है। सातवी योजना की अवधि में सिंचाई के विकास के लिए 14361 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है (11556 करोड़ रु. बृहद् व मध्यम योजनाओं के लिए तथा शेष 2805 करोड़ रु. लघु योजनाओं के लिए)।

यह अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई का क्षेत्रफल 1984-85 में 6.04 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 7.1 करोड़ हेक्टेयर हो जायेगा। इस प्रकार सातवी योजना में अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य लगभग 1.1 करोड़ हेक्टेयर रखा गया

जिसमें 39 लाख हेक्टेयर वृहद् व मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत तथा 70 लाख हेक्टेयर लघु कार्यक्रमों के अन्तर्गत होगा ।

1988-89 में बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनाओं पर 1,546 करोड़ रु का घाटा रहने का अनुमान है । इससे पूर्व भी इनमें काफी घाटा हुआ है । कई सिंचाई की स्कीम 15-20 वर्षों से चल रही हैं, लेकिन अभी तक पूरा होने का नाम नहीं लेती, जैसे नागार्जुनसगर (आन्ध्र प्रदेश), गडक व कोसी (बिहार), मालप्रभा (कर्नाटक), कल्लाड (केरल), तावा (मध्य प्रदेश) तथा काम्साबाटी (पश्चिमी बंगाल) ।

भारत में सिंचाई की सम्भाव्यता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि खेतों में नालियाँ व जल-मार्गों के निर्माण, भूमि को समतल करने व भूमि को सही शकल में लाने में काफी विलम्ब हुआ है । सिंचाई से पानी के रुकने व क्षारयुक्त भूमि के बनने की समस्या उत्पन्न हो गई है । सातवीं योजना में भूमि को समतल करने, भूमि की ठीक स्वरूप प्रदान करने, खेतों में नालियों का निर्माण करना, जल-वितरण की क्षारबन्दी प्रणाली को शुरू करने (जिसके अन्तर्गत फेर-बदल कर (by rotation) जल की पूर्ति की जाती है) तथा मिट्टी-कमल-जल-प्रवन्ध की एकीकृत पद्धति को लागू करने पर अधिक ध्यान दिया जायगा ।

सातवीं पञ्चवर्षीय योजना में सिंचाई-विकास के मुख्य उद्देश्य (main objectives) नीचे दिये जाते हैं ।

1. इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देना जो काफी प्रागे की अवस्था में पहुँच चुकी हैं । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति, सूबाप्रभावित क्षेत्रों व ग्राम पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने वाली सिंचाई योजनाओं का प्राथमिकता देना ।

2. सूखरग्रस्त क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में ही नये मध्यम दर्जे की परियोजनाओं को लागू किया जायगा तथा शीघ्र लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर बल दिया जायगा ।

3. सिंचाई की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए खेतों में नालियाँ बनाने व भूमि को समतल करने पर अधिक ध्यान दिया जायगा एवं जल-वितरण की क्षारबन्दी योजना लागू की जायगी ।

4. सिंचित क्षेत्रों में क्षारयुक्त भूमि व पानी के रुकने की समस्या के हल के लिए जल-निकास स्कीमों (drainage schemes) पर अधिक ध्यान दिया जायगा ।

5. देश के पूर्वी व उत्तरी-पूर्वी प्रदेशों में भूमि के नीचे के जल (ground water) की खोज व विदोहन का कार्य तेज किया जायगा ।

6. नहरो व वितरण-प्रणालियों के रख-रखाव (maintenance) के लिए वित्तीय साधन आवंटित किये जायेंगे।

7 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें लागू की जायेंगी ताकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अतिक्रमण रोका जा सके।

सरकार उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चुने हुए प्रोजेक्टों पर धन-राशि आवंटित करेगी, कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को लागू करेगी, पानी की दरों में समोधन करेगी तथा जल-प्रबन्ध में सुधार करके अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी।

ड्रिप-सिंचाई या टपक-विधि की सिंचाई (Drip Irrigation)—1987-88 के अग्रपूर्व सूचे के वर्ष में ड्रिप-सिंचाई का गुजरात में प्रयोग किया गया। इसके अग्रतम पानी कुए या नहर से लिपट करके खेत पर एक टैंक में जमा किया जाता है। वहाँ से कन्ड्यूट-पाइपों द्वारा सारे खेत को दिया जाता है। इसमें कन्ड्यूट-व्यवस्था को स्थापित करने का व्यय आता है लेकिन पानी की काफी बचत होती है। इस विधि में बोड़े पानी से अधिक लाभ मिलता है। इसमें पानी की मात्रा के अनुसार चार्जेंज लिये जाते हैं न कि क्षेत्रफल के आधार पर। इसलिए प्रति हेक्टेयर पानी के चार्जेंज कम हो जाते हैं। पानी के अभाव की दशा में ड्रिप-सिंचाई (टपक-विधि की सिंचाई) बहुत लाभकारी रहती है। इससे फसल को काफी फायदा होता है।

रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilisers)

भारत में कृषिगत विकास के लिए रासायनिक उर्वरकों का महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। 1966 में बाद अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग के बढ़ने से रासायनिक उर्वरकों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। नीचे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग, उत्पादन, आयात, आदि की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

उपयोग—भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत विशेषतया पिछले दशक में बढ़नी चालू हुई है। नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेट उर्वरक तथा पोटाश उर्वरकों की खपत 1960-61 में 3 लाख टन से बढ़कर 1987-88 में 90 लाख टन हो गई। अग्र तालिका में पिछले वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की प्रगति दर्शायी गयी है।

चुने हुए वर्षों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की खपत (Consumption) अग्र तालिका में दर्शायी जाती है।¹

1 Economic Survey 1988-89, p. S-21. & P. 23.

	1970-71	1987-88	1988-89 (तक)
नाइट्रोजन (N)	1.49	5.82	7.38
फोस्फट (P_2O_5)	0.46	2.27	2.81
पोटाश (K_2O)	0.23	0.92	1.14
कुल NPK	2.18	9.01	11.33

इस प्रकार उर्वरका का उपभोग 1987-88 म लगभग 90 लाख टन पर पहुँच गया जबकि 1970-71 मे यह 21.8 लाख टन ही था।

व्यापारिक फसलों के उत्पादक बहु पोषण उर्वरकों (multi nutrient fertilisers) की ज्यादा माँग करने लगे हैं। इसे उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, अथवा खाद्य व अखाद्य फसलों की उत्पादकता में अंतर बंद जाएगा। कुछ वर्षों के अनुभव से यह भी देखने में आया है कि विभिन्न फसलों के लिए गुंथायी गयी उर्वरकों की मांगा ऊँची मिढ़ हुई है। अतः उनमें उचित परिवर्तन किया जाना चाहिए। उर्वरकों की सपत बढ़ाने के लिए साख, सग्रह व वितरण आदि की व्यवस्था सुधारी जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का संतुलित उपयोग (balanced use) किया जाना चाहिए। इसके लिए फास्फेट उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। सरकार ने उर्वरकों के उपयोग में कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिए कई जिलों में कार्यक्रम चालू किए हैं। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न फसलों तथा विभिन्न प्रकार के कृषकों में उर्वरकों की सपत बढ़ानी चाहिए।

भारत में उर्वरकों के उपयोग में प्रदेश भौसम व फसलों के अनुसार काफी अंतर पाये जाते हैं। आजकल भारत में प्रति हेक्टेयर सकल कृषित क्षेत्रफल पर 50 किगो उर्वरक का उपयोग होने लगा है। पंजाब में उर्वरकों का उपयोग राष्ट्रीय औसत का तिगुना तमिलनाडु में दुगुना तथा राजस्थान मध्य प्रदेश व उड़ीसा में काफी कम होता है। लगभग 1/3 कृषित क्षेत्रफल में उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्वरकों का ज्यादातर उपयोग घान गेहूँ गन्ना व सरस कपास में किया जाता है। मोट अनाजों निरन्तर व दालों में उर्वरकों का उपभोग काफी कम पाया जाता है। देश में औद्योगिक खादों का भी उपयोग किया जाता है। बायो-गैस प्राग्राम का भी विकास किया जा रहा है।

उत्पादन व आयात—भारत में सुपर फॉस्फेट व अमोनियम न्हाट्रेट थोड़ी मात्रा में द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भी उत्पन्न किये जाते थे, लेकिन वे मुख्यतः वाणिज्यिक फसलों में प्रयुक्त किये जाते थे। योजना-काल में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग विशेष रूप से प्रचलित हुआ है। इस समय उर्वरकों का उत्पादन सांख्यिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र में होता है। लेकिन देश में उत्पादन की मात्रा मींग से कम रहती है। इसलिए उर्वरकों का आयात करना होता है। पोटैश खाद का तो पूर्णतया आयात किया जाता है।

इस समय उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है जो अमेरिका, चीन व रूस के बाद आता है। पिछले वर्षों में देश में नाइट्रोजन व फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन तेजी से बढ़ाया गया है। 1951-52 में नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 16 हजार टन से बढ़कर 1987-88 में 54.7 लाख टन एवं फॉस्फेट उर्वरकों का 11 हजार टन से बढ़कर 16.7 लाख टन पर आ गया था।

इस समय सांख्यिक क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन करने वाले निम्न उपक्रम हैं—(i) भारतीय उर्वरक निगम (चार उर्वरक उत्पादन इकाइयाँ (सिंदरी, गोरखपुर, तलचर (उड़ीसा) व रामगुडम (आंध्र-प्रदेश) तथा एक जिप्सम निकालने के लिए जोधपुर माइनिंग सगठन), (ii) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि (तीन इकाइयाँ उत्पादन में [नामरूप (असम), दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) व बरौनी (बिहार)] तथा दो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन), हल्दिया व नामरूप (III), (iii) राष्ट्रीय केमिकल्स व उर्वरक लि. (दो इकाइयाँ) (iv) राष्ट्रीय उर्वरक लि. (चार इकाइयाँ) (v) उर्वरक व रासायन ट्रावनकोर लि. (FACT) (तीन इकाइयाँ), (vi) मद्रास उर्वरक लि. (एक समुक्त उपक्रम वाली कम्पनी) (vii) पारादीप फॉस्फेट लि. (viii) दी प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि. जो पहले उर्वरक (नियोजन व विकास इण्डिया लि.) था तथा (ix) पाइराइट्स, फॉस्फेट एवं केमिकल्स लि। राउरकेला इस्पात संयंत्र, नैवेली लिग्नाइट निगम व हिन्दुस्तान तांबा लि में उर्वरक उपोत्पत्ति के रूप में उत्पन्न किया जाता है। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी सगठन की गुजरात व उत्तर प्रदेश में उर्वरक इकाइयाँ हैं।

निजी क्षेत्र की इकाइयाँ कानपुर, कोटा, गोआ, विशाखापटनम, तूतीकोरिन व डीडा, मंगलोर, एन्नोर व वाराणसी में स्थित हैं।

भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (GAIL) हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (HBJ) गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 17 अरब रुपये की लागत से पूरा करने में जुटा है। यह पाइपलाइन 1730 किलोमीटर लम्बी होगी। यह गुजरात में हजीरा से प्रारम्भ होकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व यू. पी. में जायगी और इस पर गैस-आधारित बड़े प्रकार के छ' नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जायेंगे जिनमें चार उत्तर

प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में तथा एक राजस्थान होगा। यह पावर-सयंत्रों को भी सप्लाई करेगा।

भारत में रासायनिक खाद के उत्पादन व आयात की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है।²

[पीपल के हजार टनों में]

वर्ष	नाइट्रोजन खाद		फॉस्फेट खाद		पोटेश खाद (NPK)	कुल खाद
	उत्पादन	आयात	उत्पादन	आयात		
1960-61	98	399	52	—	20	569
1987-88	5466	175	1665	—	809	8115

तालिका से पता लगता है कि योजनाकाल में तीनों प्रकार की खादों की मण्डाई काफी बढ़ायी गई है। पोटेश के लिए आवश्यक कच्चे माल के अभाव में हम आयातों पर निर्भर रहना पड़ा है। उदयपुर के पास कामर-कोटरा के क्षेत्र में राँव-फॉस्फेट के उत्पादन के चालू हो जाने से फॉस्फेटिक खाद के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध हुआ है जिससे इस किस्म के उर्वरक का आयात घटाया जा सकेगा।

भारत में खाद के प्रोजेक्टों की लागू करने में विलम्ब हुआ है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं - (1) इस्पात की कमी, (2) स्थानीय निर्माताओं (fabricators) द्वारा साज-सामान की सप्लाई में विलम्ब (3) विदेशी धनित्तव के लिए लम्बी अवधि के समझौते न होना। फॉस्फेट खाद के उत्पादन में भी लक्ष्य की तुलना में कमी रही है।

अब तक प्रस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग न होने के निम्न कारण रहे हैं।

(1) राउरकेला में कोक प्रोसेसिंग गैस की अपर्याप्त उपलब्धि, (2) सिंदरी में जिप्सम व कोयले की कमी व घटिया किस्म, (3) कुछ कारखानों के सम्बन्ध में डिजाइन व साज-सामान की कमी, (4) सिंदरी में एलवाय कारखानों में 25 वर्षों से

साज-सामान की कम कार्यक्षमता, (5) नाभल में पावर की बढ़ती एव ग्रन्थ में पावर की रुकावटें, (6) कुछ इकाइयों में औद्योगिक विवाद। सरकार इन बाधाओं को दूर करने में प्रयत्नशील है। भारत में क्रूड उर्वरक व तैयार उर्वरक आयात किया जाता है जिनकी कुल राशि 1987-88 में लगभग 310 करोड़ रु. रही। सरकार उर्वरक का उपभोग बढ़ाने के लिए सब्सिडी देती है, जिसकी राशि 1987-88 में 2,164 करोड़ रु. हो गई थी तथा 1988-89 में इसके 3000 करोड़ रु. (आयातित उर्वरकों पर 250 करोड़ रु. व घरेलू उत्पादन पर 2750 करोड़ रु.) रहने का अनुमान है।¹ इस प्रकार सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का वित्तीय भार बहुत ज्यादा हो गया। भारत की तेल के स्थान पर कोयला-आधारित उर्वरकों के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

आजकल औद्योगिक खाद व रासायनिक उर्वरकों का सन्तुलित उपयोग करने तथा देश में गोबर-मैस व बायो-मैस सयन्त्रों का कार्यक्रम तेज करने तथा बायो-मैस सयन्त्रों के माध्यम से गोबर के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उर्वरक प्रोत्साहन नीति में उर्वरकों को अधिक क्षेत्रों व अधिक कृषकों में फैलाकर अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, बमिसूत इसके कि इन्हे सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाय। उर्वरकों का उपयोग उन इलाकों में बढ़ाया जा रहा है जहाँ वितरण व संचार की व्यवस्थाएँ अपर्याप्त हैं। कृषकों को उर्वरक उचित समय पर व उचित मूल्यों पर उपलब्ध बनाने की नीति अपनाई जा रही है।

उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने की नीति के फलस्वरूप भारत का नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग में चीन, अमेरिका व रूस के बाद चौथा स्थान हो गया है। फॉस्फेट उर्वरकों के उपयोग में भारत का छठा स्थान है। 1980-81 में भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपभोग 31 किलोग्राम हो गया था, जबकि चीन में यह 155 किलोग्राम एव विश्व का औसत 80 किलोग्राम था। अतः भारत में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

पौध-संरक्षण (Plant Protection)

अधिक उपज देने वाली किस्म के विस्तार के फलस्वरूप पौध-संरक्षण का महत्व बढ़ गया है। फसलों को कीटाणुओं व बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक दवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक साज-सामान की सप्लाई व वितरण का ठीक करना होगा। कपास, दाल व तिलहन में कीटाणुओं के नियन्त्रण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक प्रणालियों से पता चला है कि 1976-77 में कृषि क्षेत्रफल के लगभग 20% भाग में कीटाणुओं व बीमा-

मियों का प्रकार था, जबकि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग केवल 7.2% क्षेत्र में ही किया गया था। जिन फसलों की सर्वाधिक क्षति हुई है वे इस प्रकार हैं : मूंगफली, कपास, धान व मक्का। इससे कुल कृषिगत उत्पादन का 10 से 15% भी नष्ट माना जाय तो भी एक वर्ष में हजारों करोड़ रुपये का कृषिगत माल गँ हो बरबाद हो जाता है। प्रथम योजना के आरम्भ में 100 टन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया था जो 1987-88 में 75 हजार टन का लक्ष्य रखा गया है। 1986-87 में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग 72 हजार टन हुआ है।

मानवी पंचवर्षीय योजना में कीटनाशक दवाइयों (टेक्नीकल) का उपयोग 50 हजार टन से बढ़ाकर 75 हजार टन करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके प्राप्त हो जाने की आशा है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम (HYVP)

1966 से हरित क्रांति के फलस्वरूप विभिन्न फसलों में नयी किस्म के बीजों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा व गेहूँ में अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग बढ़ा है। 1970-71 में यह कार्यक्रम 1.54 करोड़ हेक्टेयर में फैला दिया गया था जो 1986-87 में 5.61 करोड़ हेक्टेयर में फैल गया है। 1987-88 में सूखे के कारण यह घटकर 5.12 करोड़ हेक्टेयर पर आ गया था। पुन 1988-89 के लिए लक्ष्य 6.5 करोड़ हेक्टेयर रखा गया है।

विभिन्न फसलों के अनुसार कार्यक्रम की प्रगति आये दी जाती है¹—

	1970-71	1987-88	मातृभाषा पाठना के अन्तिम वर्ष 1989-90 में (लक्ष्य)
(1) धान (मिलियन हेक्टेयर)	5.6	20.8	32.0
(2) गेहूँ (, ..)	6.5	19.6	22.0
(3) मक्का (, ..)	0.5	1.9	3.0
(4) ज्वार (, ..)	0.8	5.4	6.5
(5) बाजरा (= ..)	2.0	3.5	6.5
कुल HYP (मि हेक्टेयर)	15.4	51.2	70.0

देग म गेहूँ की तुलना में चावल का उपयोग अधिक होता है। अतः चावल की किस्मों में परिवर्तन करना अधिक आवश्यक हो गया है। अभी तक हरित क्रांति मुख्यतया गेहूँ की कृति रही है। 1987-88 में गेहूँ के क्षेत्रफल का लगभग

86.5% तथा चावल के क्षेत्रफल का 54.8% अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) के अन्तर्गत आ गया था। बाजरे में भी यह 36% तक पहुँच गया था। ज्वार व मक्का में लगभग 1/3 भूमि में HYV का उपयोग होने लगा है। सातवीं योजना में कुल HYV क्षेत्रफल लगभग 5½ करोड़ हेक्टेयर से बढ़ाकर 7 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना आयोग के सदस्य डॉ. वाई. के. अस्कर ने नवम्बर, 1987 में प्रथम इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्मृति व्याख्यान में बताया कि भारत में गेहूँ व घान में लगभग समस्त सिंचित क्षेत्रफल HYV के अन्तर्गत आ चुका है जिससे भविष्य में इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए घटिया मिट्टी व घटिया जलवायु वाले क्षेत्रों में जाना होगा। छठी योजनाविधि में 84 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र बढ़ने पर भी सकल कृषि क्षेत्रफल नहीं बढ़ पाया है। अतः भविष्य में जल-प्रबंध सुधारना होगा तथा सूखी-कृषि की पद्धति पर अधिक ध्यान देकर उत्पादन बढ़ाना होगा।

प्राप्त प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल में नयी किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाने की दृष्टि से प्रगति धीमी रही है। राष्ट्रीय बीज निगम राष्ट्रीय स्तर पर फाउण्डेशन बीज के लिए उत्तरदायी है। पिछले वर्षों में बीज-वितरण की दृष्टि से इसका कार्य काफी महत्वपूर्ण रहा है। देश में कपास, दाल, तिलहन व चारे की फसलों के लिए उत्तम किस्म के बीजों का अभाव रहता है जिसकी पूर्ति को जानी चाहिए।

भू-संरक्षण (Soil Conservation)

कृषिगत साधनों में सिंचाई, रासायनिक खाद, पौध-संरक्षण व नयी किस्म के बीजों के साथ-साथ भू-संरक्षण के उपायों का भी उल्लेख करना आवश्यक है। यह कार्य राज्यों की योजनाओं में किया जाता है। 1970-71 में भू-संरक्षण के कार्य 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में व्याप्त थे जिन्हें 1988-89 के अन्त तक 3.29 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक फैला देने का लक्ष्य रखा गया है। नदी घाटी परि-योजनाओं के क्षेत्रों (Catchment areas) में भू-संरक्षण का कार्य केन्द्रीय सरकार चला रही है।

अन्य साधन (Other Inputs)

कृषिगत साधनों में सुधरे हुए कृषिगत औजार, फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर व कृषिगत साख, वगैरह का भी स्थान होता है। कृषिगत साख का विस्तृत विवेचन आगे एक पृथक अध्याय में किया गया है। इस बात पर बल देना आवश्यक है कि कृषकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मिलने वाले प्रत्यक्ष व परोक्ष वित्त में काफी वृद्धि हुई है। जून 1969 के अन्त में प्रत्यक्ष वित्त की बकाया राशि कृषि के अन्तर्गत 40.21 करोड़ रुपये थी जो जून 1987 के अन्त में 9,300 करोड़ रुपये हो गयी है। परोक्ष वित्त की राशि भी काफी बढ़ी है। आजकल कृषि व ग्रामीण विकास का

योजनाकाल में काफी बढ़ गया है। ट्रैक्टर व अन्य मशीनों का मूल्य इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। वर्ष के जिस भाग में कृषक बेवार बंठा रहता है उस समय पशुओं पर व्यय जारी रहता है। लेकिन ट्रैक्टर का व्यय शून्य हो जाता है।

3 ट्रैक्टर से प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ती है एवं कुल कृषित क्षेत्रफल बढ़ता है क्योंकि बहु-फसल कार्यक्रम व नयी भूमि को तोड़ने के कार्य तेजी से पूरे हो जाते हैं। यह दखा गया कि गहरी जुताई से धान या ज्वार की उपज 20 से 25 प्रतिशत बढ़ती है।

4 बढ़ती हुई मजदूरी व कारण भी देहाती म श्रम के स्थान पर पूँजी को प्रतिस्थापित करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। भूमि-सुधारों ने भू-स्वामियों को श्रमिकों के स्थान पर मशीनों लगाने के लिए प्रेरित किया है।

5 सस्ते ऋमाज पर यन्त्रों को खरीदने की सुविधा ने भी यन्त्रीकरण पर अनुकूल प्रभाव डाला है।

6 फार्म यन्त्रीकरण से फार्म-रोजगार तो कम होता है, लेकिन यन्त्र चलाने वाले उद्योगों औजारों को सुधारने के केन्द्रों तथा गहन कृषि के अन्य कार्यक्रमों में श्रमिकों को अधिक रोजगार मिलने लगता है। इस प्रकार यन्त्रीकरण से सम्भवतः कुल रोजगार में थोड़ी वृद्धि की आशा की जा सकती है। इस प्रकार फार्म-यन्त्रीकरण से दोनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं—

पहली प्रक्रिया म श्रम की माग घटती है और दूसरी प्रक्रिया में श्रम की माग बढ़ती है तथा कुल परिणाम को देखकर यह पता लगता है कि श्रम की माग थोड़ी बढ़ती है घटती नहीं।

7 अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) के आने से यन्त्रीकरण को बढ़ावा मिला है और अधिक उपज देने वाली किस्में व यन्त्रों का उपयोग दोनों एक साथ मिलकर अधिक श्रम को प्रयुक्त कर सकते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों को बोम पर प्रति हैक्टेयर अधिक श्रम दिनों का उपयोग किया जाता है।

कृषि में यन्त्रीकरण के दोष—अब हम यन्त्रीकरण के दोषों का उल्लेख करेंगे। ये निम्नांकित हैं

(1) यन्त्रीकरण ने पशु-शक्ति की माँग घटा दी है जिससे कालसू पशुओं की समस्या उत्पन्न हो गयी है और ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ने से यह समस्या दिनोदिन अधिक तीव्र होती जा रही है।

(2) बड़े पैमाने पर कृषि का यन्त्रीकरण करने से अथवा अ-वाधु-य यन्त्रीकरण करने से बेरोजगारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है जो भारतीय परिस्थिति में एक नयी समस्या का रूप ग्रहण कर सकता है।

(3) यन्त्रों को चलाने व लिए डीजल तेल आदि की माग बढ़ेगी और भारत में इनकी सप्लाई का अभाव है। अतः हम इनका आयात बढ़ाना होगा जिससे हमारी

विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जायेगी। डीजल तेल के भाव बढ़ जाने से समस्या और भी जटिल हो गई है। आज देश के समस्त डीजल तेल का सकट विद्यमान है।

(4) भारत के सुदूर देहातों की स्थानीय परिस्थितियों में प्रायः विदेशों से मगाये गये ट्रैक्टर एवंतया सफल प्रमाणित नहीं होते। उनमें सराबी या जाने से यान्त्रिक ज्ञान की कमी व अन्य कठिनाइयों के कारण (कल-पुर्जों के अभाव व आवश्यक मरम्मत की सुविधाओं की कमी) उनका उपयोग कष्टदायक प्रतीत होना लगता है।

(5) ऊँचो लागत के कारण अधिकांश कृषकों के पास इनकी खरीदने के लायक पर्याप्त मात्रा में पूँजी नहीं होती। इसलिए सरकार को लागत की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि यन्त्र कारगर सिद्ध होता है तो भुगतान में कठिनाई नहीं होती; अन्यथा भुगतान में दिक्कत उत्पन्न हो जाती है।

(6) प्रायः यह देखा गया है कि स्थानीय आवश्यकताओं व छोटे कृषकों के लायक आवश्यक यन्त्रों का अभाव होता है। अतः देश की परिस्थिति के अनुसार यन्त्रों का निर्माण व प्रचार अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है।

भारत में कृषि के यन्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएँ

भारत में पिछले वर्षों में, विशेषतया 1966-67 में, कृषि के यन्त्रीकरण को बढ़ावा मिला है। देश में पम्प-सेटों व ट्रैक्टरों आदि की माँग बढ़ रही है और कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा है। इससे कई समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं जिनका हल ज़ीद ही निकाला जाना चाहिये। ये समस्याएँ इस प्रकार हैं।

1 यन्त्रों के उत्पादन में कमी—नये यन्त्रों के उत्पादन में कच्चे माल की कमी व धनुमधान का अभाव बाधा डालते हैं। सरकार ने उत्पादन की क्षमता तो उत्पन्न कर दी है, लेकिन साधनों के अभाव में वास्तविक उत्पादन कम हो रहा है।

2 कृषकों के पास यन्त्र खरीदने के लिए वित्त की कमी—कृषकों के पास ऋण-शक्ति का अभाव है। अतः उनको साह्य प्रदान करनी होती है और इसमें काफी विनम्र हो जाता है। भूमि की गिरामी रखने की शर्तें पेशीदा होती हैं।

3 सेवा सुविधाओं व मरम्मत का अभाव—फार्मों के पास पास मरम्मत व अन्य सेवाओं को प्रदान करने की व्यवस्था नहीं होती है जिससे मामूली सराबी से भी यन्त्र बेकार हो जाता है।

4 विस्तार सेवाओं की कमी—कृषकों को सही क्रिस्म के अजीजों के चुनाव में मदद देने वाली विस्तार संस्थाओं (extension institutes) का अभाव पाया जाता है। उन्हीं मशीनों का उपयोग भली प्रकार समझाया जाना चाहिए ताकि वे देश में निर्मित यन्त्रों का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग कर सकें।

5 छोटे कृषकों की कठिनाइयाँ—भारत में छोटे कृषक कीमतों में मशीनें खरीदने की स्थिति में नहीं होते। उनकी सामर्थ्य कम होती है जिससे वे कृषि में

धूँजी-निवेश नहीं कर पाते। अतः उनको किराये पर मशीनें उपलब्ध की जानी चाहिए। किराये पर मशीनें देने की व्यवस्था दो तरह से की जा सकती है। एक तो मध्यम श्रेणी के किसान मशीनें किराये पर देकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और छोटे किसानों को लाभ पहुँचा सकते हैं। दूसरे सहकारी एजेंसियाँ किराये पर मशीनें देने का कार्यक्रम चला सकती हैं। कृषक-सेवा-केन्द्रों (Farmer's Agro-Service Centres) के माध्यम से उद्यमकर्त्ताओं, कृषक-समूहों व सहकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण व सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे लघु व सीमान्त कृषकों को विभिन्न प्रकार की सप्लाई व सेवाएँ उपलब्ध कर सकें।

6 खेतों का छोटा आकार यन्त्रीकरण में बाधक—भारत में छोटे व बिगरे खेतों की भरमार यन्त्रीकरण के मार्ग में बाधक है। इसके लिए खेतों की चक्करी व संयुक्त खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसा करम से यन्त्रीकरण ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकेगा।

भारत में यन्त्रीकरण ने 'विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याओं' को जन्म दिया है जिनका कुशलतापूर्वक मुकाबला किया जाना चाहिए। हमें नियन्त्रित व धीमी रफ्तार से यन्त्रीकरण करके भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण व व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना चाहिये। जनाधिक्य की समस्या के कारण भारत में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही यन्त्रीकरण किया जाना चाहिए और श्रम का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों में बढ़ाना चाहिए।

भारत में ट्रैक्टरों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, जहाँ बैलों की शक्ति ठीक समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती और सीमित अवधि में नमी का उपयोग करने के लिए ट्रैक्टरों की सहायता आवश्यक होती है। कृषि के लिए नई भूमि या जटिल भूमि को काम में ले सकने के लिए भी ट्रैक्टर प्रयुक्त किये जा सकते हैं लेकिन कृषि में अनियन्त्रित किस्म का यन्त्रीकरण ग्रामीण बेरोजगारी को बढ़ा सकता है। इसलिए चुने हुए ढंग से ही यन्त्रीकरण (selective mechanisation) किया जाना चाहिए। हमारे लिए चुनाव यन्त्रीकरण करने अथवा न करने के बीच नहीं है बल्कि देश की जरूरतों के मुताबिक चुने हुए ढंग का यन्त्रीकरण करने से है।

प्रश्न

- 1 भारतीय आर्थिक जीवन में सिंचाई के महत्व को बतलाइये भारत में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पिछले बीस वर्षों में क्या किया गया है?

(Raj Ilyr T D C, 1987)

- 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(1) भारतीय कृषि का यन्त्रीकरण (मशीनीकरण)

(Raj Ilyr T.D C, 1983)

5

भूमि सुधार

(Land Reforms)

भारत में कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए संस्थागत परिवर्तनों (institutional changes) पर जोर दिया गया है। बहुधा अर्थशास्त्री संस्थागत परिवर्तनों में भू-स्वामित्व को प्रणाली, कृषिगत साख तथा कृषिगत बिक्री के परिवर्तनों को शामिल करते हैं। एक प्रगतिशील संस्थागत परिवर्तन के अन्तर्गत भूमि को जो नये वाला भूमि का मालिक हो जाता है और साख व बिक्री के लिए सहकारी संस्थाओं का उपयोग होने लगता है। आजकल निचैन-वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनमें विस्तार-सेवाओं (extension services) को शामिल करने पर भी बल दिया जाता है। लेकिन संस्थागत परिवर्तनों में भूमि सुधारों का स्थान केन्द्रीय तथा सर्वोच्च माना गया है। भूमि सुधारों में काश्तकारी सुधारों (tenancy reforms) ने मलका भू-जोतों पर सीमा निर्धारण, चढ़बन्दी, सहकारी कृषि भूमिहीनों में भूमि का वितरण, आदि कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनको अपनाते से कृषि का उत्पादन बढ़ता है और साथ में सामाजिक न्याय का वातावरण भी तैयार होता है। इस प्रकार भूमि-सुधारों का काम कृषि के ढाँचे व संगठन में आवश्यक परिवर्तन करना माना गया है। कृषि का सामग्री ढाँचा भूमि के

- I काश्तकारी सुधारों में काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाना, उनसे उचित लगान वसूल करना तथा उनकी बेदखली से रक्षा करना शामिल होता है। काश्तकारी सुधार भूमि-सुधारों के आवश्यक अंग होते हैं और इनका सम्बन्ध काश्तकारों के कल्याण से होता है। इस प्रकार भूमि-सुधारों का दायरा काश्तकारी सुधारों से अधिक व्यापक होता है। भूमि सुधारों का भूमि को समतल करने, उसमें धास-पात हटा कर उसे मैनी के लायक बनाने आदि के अर्थ में नहीं लिया जाता। इनका अर्थ भूमि-व्यवस्था या भूमि के सम्बन्धों (land relations) के परिवर्तनों से लगाया जाता है जिनमें सरकार, किसान व जमींदार के परस्पर नये सम्बन्ध आते हैं।

रहनी है, जो कृषि का विकास नहीं होने देती। धार्मिक विवास के लिए भूमि का न्यायपूर्ण बटवारा आवश्यक माना गया है।

भूमि-सुधारों से ही सहकारिता आन्दोलन बन सकता है। इनको कार्यान्वित करने से एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण बन जाता है जिसमें सहकारिता का प्रयोग कृषि, साख बिक्री आदि क्षेत्रों में फैल सकता है।

कई बार यह कहा जाता है कि कृषिगत उत्पादन बढ़ाना तो एक तकनीकी समस्या है जो उचित मात्रा में खाद, बीज व सिंचाई की व्यवस्था आदि को अपनाने से अपने आप हल हो जाती है। लेकिन यह धारणा सही नहीं है। जब तक भूमि-सुधार के जरिये भूमि-सम्बन्धी या भूमि-अधिकारों की समस्या हल नहीं की जाती तब तक चक्रेले तकनीकी परिवर्तन अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकते। इसलिए भूमि-सुधारों व तकनीकी सुधारों को साथ-साथ लागू किया जाना चाहिए।

किसान खाद, बीज व सिंचाई की बिना उस समय करता है जब वह भूमि का मालिक बन जाता है, यद्यपि उसे काश्त की पूरा सुरक्षा मिलती है और वेदवली (भूमि से हटा दिये जाने) का भय नहीं होता। यह एक सामान्य बात है कि जब तक रोग की जड़ें नहीं कटती, तब तक चैप्टिक पदार्थ अपना उत्तम प्रभाव नहीं दिखा पाते और रोगी कमजोर बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जब तक भूमि-सुधार नहीं होते, तब तक अन्य तकनीकी सुविधाएँ अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाती। अतएव कृषिगत विकास के लिए सर्वप्रथम भूमि-सुधारों पर आवश्यक बल दिया जाना चाहिए।

भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भू-धारण की तीन प्रणालियाँ विद्यमान थीं। (1) जमींदारी प्रथा (2) महालवाड़ी प्रथा, और (3) रयतवाड़ी प्रथा। इन प्रणालियों में दास्तिक काश्तकार का शोषण होता था और कृषि में पूँजी लगाने की ओरला सरकार, भू-स्वामी व कृषक तीनों में से किसी को भी नहीं थी। परिणाम-स्वरूप कृषि व कृषक की दशा अत्यन्त शोचनीय व पिछड़ी हुई थी। इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम भूमि-सुधारों की आवश्यकता प्रतीत हुई।

भारत में भूमि-सुधार—नीति व प्रगति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने काश्तकारी, उप-काश्तकारी, बटाईदारी व भूमिहीन भूजदूरों की दशा सुधारने के लिए नयी भूमि-नीति अपनायी। वंसे 1947 से पूर्व भी काश्तकारों की सुरक्षा व लगान-नियमन के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों में कानून बनाये गये थे, लेकिन व्यवहार में उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। काश्तकारों की स्थिति में स्थायी सुधार करने के लिए भूमि व्यवस्था में क्रांति-कारी परिवर्तनों की आवश्यकता निरन्तर बनो रही। अन्त में प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह निश्चय लिया गया कि भूमि का मासिक स्वयं किसान को ही बनाया जाना चाहिए तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा और कृषिगत उत्पादन बढ़ सकेगा। प्रथम योजना में भूमि-सुधार सम्बन्धी निम्न कार्यक्रम अपनाये गए और दिया गया,

(क) मध्यस्थों का अन्त (ख) लगान में कमी और काफ़्तकारी को भू-स्वामी के अधिकार दिलाना । भू-स्वामी के लिए सुदकाशत के वास्ते भूमि छोड़ना, (ग) जोतो पर सीमा निर्धारित करना और अतिरिक्त भूमि बांटना, (घ) जोतो की चक्कादी और भूमि का व्यवस्थापन रोचना (ङ) महकरी कृषि का विकास और महकरी ग्राम प्रबन्ध की ओर अग्रसर होना ।

प्रथम योजना की अवधि में म. व.स्थो का लगभग अन्त कर दिया गया लेकिन भूमि-सुधार के अन्य पहलुओं पर काम करना शेष रह गया था ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि-सुधारों पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि देश समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की ओर अग्रसर हो सके । बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि भूमि-सुधारों में अनावश्यक देर होने एवं अनिश्चितता बनी रहने में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जायेगी और कृषि व औद्योगिक उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा । दूसरी योजना में सुदकाशत के निष्कार को सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया गया । सीमा-निर्धारण व सहकारी रीती के कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया गया एवं कृषि के पुनर्गठन के लिए आवश्यक सुझाव दिये गये ।

दिसम्बर, 1969 में मन्त्रिमंडल काँग्रेस के सम्बन्धी अधिवेशन में एक वर्ष में भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता स्वीकार की गई । केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने अगस्त 1971 से 'भू-सीमा' को घटाकर 10 से 18 एकड़ के बीच में करने का सुझाव दिया था । 22 जुलाई, 1972 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भूमि सुधारों पर अपने निर्णय घोषित किये । मार्च, 1976 में मुख्य-मन्त्रियों के सम्मेलन में सीमा-निर्धारण कानूनों को 30 जून, 1976 तक लागू करने का कार्यक्रम घोषित किया गया था ।

यह सब सब इतिहास के पन्नों की वस्तु बन गई है लेकिन इन तथ्यों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि पाठकों को भूमि-सुधारों की पृष्ठभूमि की जानकारी हो सके । आज भी सरकार के समक्ष भूमि-सुधारों को लागू करने की समस्या बनी हुई है ।

जून, 1978 में स्वर्गीय राजकृष्ण की अध्यक्षता में नियुक्त भूमि-सुधार समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि भूमि-सुधारों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए ऐसे समस्त कानूनों का संविधान की नवी अनुसूची (Ninth Schedule of the Constitution) में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भूमि-सुधारों को अदानतो में चुनौती न दी जा सके । ऐसा करने से भूमि-सुधारों को लागू करने में अग्रिम गुणिता हो जायेगी ।

अब हम भारत में पिछले 38 वर्षों में भूमि-सुधारों की प्रगति की समीक्षा करेंगे ताकि अग्र तर के अनुभवों से भविष्य में लाभ उठाया जा सके ।

croppers) द्वारा उपज का आधा या इससे अधिक हिस्सा लगान के रूप में दिया जाता था। लगान के अतिरिक्त अन्य भुगतान भी वास्तकारों के द्वारा किया जाते थे।

आन्ध्र प्रदेश पंजाब व हरियाणा की छोड़कर शेष सभी राज्यों में लगान सकल उपज के $1/4$ से घटाकर $1/5$ कर दिये गये। अन्य राज्यों में भी लगान घटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में सारी निम्न श्रेणी की रैयत या अप्रहर्-रैयत को राज्य के सीधे सम्पर्क में ला दिया गया लेकिन बरगदारी (उदाईदारी) को शामिल नहीं किया गया हालांकि उनकी ऐच्छिक वेदखली से रक्षा की गयी।

काश्तकारी कानून बन जाने के बाद प्रारम्भिक वर्षों में पुरानी दर में ही लगान लिया जाते रहे। यदि भूमि का मालिक किसान की बीज, बैल व सिंचाई की सुविधा प्रदान करता तो वह उससे अधिक लगान ठहरा लेता। वास्तकारों को अपने कानूनी अधिकारों का पूरा ज्ञान नहीं है और अपनी सामाजिक और आर्थिक दशा परावृत्त होने से भी वे कानूनों का पूरा सरक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं। तृतीय योजना में यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे भू-स्वामियों को वास्तकार से प्राप्त लगान की रमीटें देने के लिए बाध्य करें और वास्तकार रेवेन्यू आफसर के पास लगान की रकम जमा करा दे एवं भू-स्वामियों को सूचित कर दें।

लगान नियमन कानून को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वास्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना एवं स्वामित्व के अधिकार देना अत्यन्त आवश्यक माना गया है।

(ख) भू-धारण की सुरक्षा (Security of Tenure)—कई राज्यों में भू-धारण की सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाये गये। इनके द्वारा काश्तकारों की वेदखली रोक दी गई है। लेकिन ऐच्छिक परित्याग (Voluntary surrenders) के बहाने वास्तकारों की वेदखली की गई है। द्वितीय योजना की अवधि में ऐच्छिक परित्याग के मामलों में रजिस्ट्री करवाने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि वास्तकार से भूमि का परित्याग कराते समय भू-स्वामी केवल खुदकाश्त में रहती जा सकने वाली भूमि की मात्रा ही अपने पास रखने का अधिकारी माना जाय। लेकिन ये दोनों ही बातें व्यवहार में लागू नहीं की जा सकी हैं।

द्वितीय योजना में 'खुदकाश्त' (Personal cultivation) की परिभाषा में भू-स्वामी पर चार शर्तें लागू करने का सुझाव दिया गया था - (1) निजी देखरेख (2) गाँव या उससे पटोस में रहना (आजकल भूमि में पाँच किनोमीटर की दूरी का सुझाव दिया जाता है), (3) निजी श्रम, (4) कृषि की जोखिम उठाना। महाराष्ट्र व राजस्थान में पहली और चौथी शर्तें लागू की गईं। असम में दूसरी शर्तें लागू की

गई। लेकिन 'निजी भूमि' की शर्तें किसी भी राज्य में लागू नहीं की जा सकी। भूमि-सुधार के पैनल का सुझाव था कि जब प्रमुख कृषि-कार्य होते हैं, उस अवधि में भू-स्वामी गांव में या उसके आस-पास अवश्य रहे।

बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र, गुजरात के सोराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब व हरियाणा में कानूनी व बंटाईदारों की दशा वर्तमान कानून के अन्तर्गत अरक्षित पाई गई है।

(ग) कानूनी अधिकारों का पुनर्ग्रहण (Resumption of Tenancies)—इस सम्बन्ध में राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(अ) वे राज्य जिनमें भू-स्वामियों को पुनर्ग्रहण को इजाजत नहीं मिली, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली व पश्चिम बंगाल की निम्न श्रेणी की रीयत।

(आ) वे राज्य जिनमें खुदकाश के लिए सीमित क्षेत्र ग्रहण करने का अधिकार दिया गया, लेकिन साथ में यह शर्त लगा दी गई कि कानूनी अधिकार के पास एक ग्यूनतम क्षेत्र या जोत का टुकड़ा अवश्य छोड़ा जाये। ऐसा बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व मणिपुर में किया गया।

(इ) वे राज्य जिनमें पुनर्ग्रहण का अधिकार इस शर्त पर मिला कि कानूनी अधिकारों को एक निर्धारित सीमा तक भूमि प्रदान की जायेगी। भूमि राज्य ही सलाह करेगा। ऐसा पंजाब व असम में किया गया।

(ई) वे राज्य जिनमें ग्रहण करने का अधिकार सीमा-निर्धारण के स्तर तक दिया गया और कानूनी अधिकार के लिए एक ग्यूनतम क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ऐसा मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में किया गया।

खुदकाश के लिए भू-स्वामियों को पुनर्ग्रहण का अधिकार मिलने से कानूनी अधिकारों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन छोटे भू-स्वामियों के साथ विशेष रियायत होनी चाहिए। वसति जोत (पारिवारिक जोत का 1/3) से कम के भू-स्वामियों को समस्त क्षेत्र खुदकाश में रखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जिस कानूनी अधिकार के पास भूमि न रहे, अथवा वसति जोत से कम रहे, उसे स्वयं सरकार भूमि देने की व्यवस्था करे।

खुदकाश के लिए भूमि-ग्रहण करने का कार्य एक निश्चित अवधि तक लागू किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होने पर मध्यम श्रेणी के भू-स्वामी भूमि का हस्तान्तरण करके छोटे भू-स्वामी बनने का प्रयास करते हैं।

(घ) कानूनी अधिकारों को स्वामित्व का अधिकार देना—(Ownership rights for Tenants)—द्वितीय योजना में यह कहा गया था कि पुनर्ग्रहण न किये जाने वाले क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों को भूमि का मालिक बना दिया जाय। मालिक बनाने के लिए

ऐच्छिक अधिकार (Optional rights) न दिये जायें, क्योंकि व्यवहार में इनका उपयोग नहीं हो पाता है।

यह कार्य तीन प्रकार से किया गया :

(अ) काश्तकारों को मालिक घोषित कर दिया गया और उतसे मालिकों को उचित किस्तों में मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की गई। सरकार ने मालगुजारी की वकाया के रूप में न चुकाई गई किस्तों को वसूल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ऐसा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान में किया गया।

(आ) सरकार ने मुआवजा देकर स्वयं स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर लिये और काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया तथा मुआवजा उचित किस्तों में वसूल करने की व्यवस्था की। ऐसा दिल्ली में किया गया।

(इ) सरकार ने भूस्वामियों के अधिकार प्राप्त कर लिए और काश्तकारों से सीधे सम्बन्ध स्थापित कर लिए। काश्तकारों को यह छूट दी गई कि वे सरकार को उचित लगान देकर पहले की भांति ही अपना कार्य जारी रखें अथवा निर्धारित मुआवजा देकर भूमि के पूरे मालिक बन जायें। ऐसा केरल और उत्तर प्रदेश में हुआ।

सभी राज्यों में काश्तकारों के लिए भूधारण की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाये गये। परिणामस्वरूप 80 लाख काश्तकारों/बटाईदारों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हुए। पश्चिमी बंगाल में बटाईदारों (share-croppers) का पंजीकरण अधिकार सम्बन्धी रिकार्ड (records of rights) में किया गया ताकि उन्हें काश्त की सुरक्षा के लाभ मिल सकें।

छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार असम, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पश्चिमी बंगाल में 70 लाख पंजीकृत काश्तकार/बटाईदार पाये गये, जिनमें 24.4 लाख अकेले केरल में थे।

पी एस अण्णु का मत है कि भारत में ज्यादातर काश्तकारी सुधार (tenancy reforms) विफल रहे हैं तथा काश्तकारी-प्रथा को नियमित व नियन्त्रित करना बहुत कठिन रहा है क्योंकि देश में भूमिहीन श्रमिकों की भरमार है। इसलिए मौखिक व अनौपचारिक (oral and informal) काश्तकारी प्रथा प्रचलन में अधिक देखने को मिलती है। इसके अन्तर्गत जवानी तौर पर काश्तकारों को भूमि काश्त के लिए दे दी जाती है और इस सम्बन्ध में कोई लिखा-पढ़ी नहीं की जाती। इससे रिकार्ड में तो काश्तारी प्रकट नहीं होती, लेकिन व्यवहार में काश्तकारी, उपकाश्तकारी तथा बटाईदारी प्रथाओं का बोलबाला रहता है। कुछ कृषि-अर्थशास्त्रियों का मत है कि छोटे कृषकों को अपनी भूमि पट्टे पर दूसरों को देने (lease-out) की मनाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि से गैर-कृषि कार्यों में श्रम की गतिशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए यह सामग्री सिद्ध होगी।

बहुत से छोटे फार्म हैं जिन्हें अनाधिक जोत कहते हैं। उन पर साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और सेती अकुशल और अलामप्रद रहती है। अतः बहुत बड़े फार्म और बहुत छोटे फार्म दोनों स्थितियों को समाप्त करके उचित आकार के फार्म बनाने के लिए भूमि पर सीमा निर्धारित करना उचित ठहराया गया है।

(2) सीमा निर्धारण के बाद अपेक्षाकृत छोटे खेतों पर रोजगार की मात्रा बढ़ेगी—सीमा निर्धारण के पक्ष में विशेषता नीची सीमा-निर्धारण के लिए एक तर्क यह दिया जाता है कि इससे रोजगार की मात्रा बढ़ेगी। कारण यह है कि गरीबों के स्वामी मजदूरी पर श्रमिक रखते हैं जिससे वे श्रमिकों को उस बिन्दु तक काम पर लगाते हैं जहाँ अन्तिम श्रमिक को काम पर लगाने से प्राप्त उत्पत्ति की वृद्धि उसको दी जाने वाली मजदूरी के बराबर नहीं हो जाती। छोटे खेतों पर यह शर्त लागू नहीं होती, क्योंकि उन पर पारिवारिक श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। रोजगार के वैकल्पिक अवसर नहीं होने से पारिवारिक श्रम उस बिन्दु तक काफी अधिक दूरी तक लगाया जाता है जहाँ प्रति इकाई धन की सीमांत उत्पत्ति मजदूरी के बराबर होती है। अतः छोटे खेतों पर गहन कृषि के कारण अधिक श्रमिकों को काम मिल सकता है। प्रो ए के सन ने कहा है कि छोटे खेतों पर अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। थार पी डार ने अपनी पुस्तक *Land Reforms in Japan* में बतलाया है कि वहाँ सीमा निर्धारण के बाद प्रति एकड़ उत्पादनता बढ़ी है। ऐसा विशेषतया चावल की पैदावार में हुआ है।

(3) भूमिहीनों में भूमि का बितरण—सीमा से ऊपर की भूमि भूमिहीनों में बाँटी जा सकेगी जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। उनका समाज में स्थान ऊँचा हो सकेगा। इससे गाँवों में निर्धन लोगो की आय बढ़ेगी। जिन लोगो को नई भूमि मिलेगी उनमें उत्तरदायित्व की ज्यादा भावना होना से वे उत्पादन में वृद्धि करेंगे। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि जिन लोगो को भूमि आवंटित की गई है उनको पर्याप्त माना में कृषिगत साधन भी उपलब्ध किये जायें ताकि आवंटित भू-खण्डों पर खेती करके वे स्वयं को व समाज का लाभ पहुँचा सकें तथा उत्पादन बढ़ा सकें।

(4) सहकारिता की प्रगति—सीमा लगने से गाँवों में समानता के आधार पर समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिससे सहकारिता आन्दोलन तेजी से चल सकेगा। इससे उत्पन्न कृषि का बढ़ावा मिलेगा।

(5) भूमि का सदुपयोग व उत्पादन में वृद्धि—कुछ लोगो के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि वे इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते और बची-भरी भूमि बिना जोते पड़ी रह जाती है। सीमा लगाने से उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि भूमि का सदुपयोग होगा और गहन कृषि के लाभ प्राप्त किये जा सकेंगे।

(6) पारिवारिक श्रम का अधिक उपयोग—छोटे खेतों के स्वामी अपने खेतों पर अधिक ध्यान देते हैं जिससे तम्बाकू, लाल मिर्च, सब्जी आदि की पैदावार बढ़ती

है, क्योंकि इनके लिए पारिवारिक धन का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। केरल में धनी किसान धान की खेती के स्थान पर नारियल के बागान लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन छोटे कृषक ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके पास पारिवारिक धन की अधिकता रहती है। धनी किसानों को मजदूरी पर धनिक रखने होते हैं।

7 सामुदायिक विकास व ग्राम पंचायतों की प्रगति के लिए—गांवों में पंचायतों के विकास एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सहकारी ढंग पर ग्रामिक हितों का विकास करने के लिए भूमि का समान वितरण करना बहुत आवश्यक है। जब तक गांवों में समानता का वातावरण उत्पन्न नहीं होता तब तक सामाजिक व राजनीतिक समानता की प्राप्ति एक सुदूर का स्वप्न बनी रहेगी। इससे लिए समानता के आधार पर भूमि का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए।

8 भूमि व धन का केन्द्रीयकरण कम करने के लिए—योजनाकाल में निबाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, कृषि विस्तार, आदि से अप्रभाकृत अधिक लाभ धनी व मध्यम श्रेणी के कृषकों को मिले हैं। इससे कृषि की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे अधिक भूमि वाले किसान ज्यादा सम्पन्न हो गये हैं और उनके हाथों में धन का केन्द्रीयकरण बढ़ा। जो राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के विपरीत है। ऐसी दशा में सीमा-निर्धारण का उपाय निर्धन लोगों की सामाजिक स्थिति को सुधारन का एक श्रेष्ठ साधन बन सकता है।

गांवों की एक मात्र सम्पत्ति भूमि ही होती है। उसके स्वामित्व में असमानता का बना रहना ज्यादा अनुचित है। भूमिहीनों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति बहुत निम्न कोटि की मानी जाती है। इसके विपरीत भू-स्वामियों को सामाजिक सम्मान व राजनीतिक अधिकारों के उपयोग करने का अधिक अवसर मिलता है।

सीमा निर्धारण के पक्ष में ऊपर कई प्रकार के तर्क दिये गये हैं। लेकिन कुछ विचारकों ने इसकी उपयोगिता में सन्देह प्रकट किया है उनका कहना है कि सीमा-निर्धारण (विशेषतया नीची सीमा लगाने से) देश की कृषि-व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी उत्पादन घट जायेगा और सर्वत्र छोटे-छोटे अनाधिक खेत ही नजर आने लगेंगे।

सीमा निर्धारण के विपक्ष में तर्क

1 सीमा लगाने से ग्रामीण भाग व शहरी भाग में अन्तर बढ़ जायेगा। यदि भूमि पर सीमा लगाकर गांव के निवासियों की आमदनी सीमित की जाती है तो प्रश्न उठता है कि अन्य उद्योगों व व्यवसायों से होने वाली आय भी सीमित क्या नहीं की जाती? शहरी में प्रति वर्ष विभिन्न व्यक्तियों को कारखानों, व्यापार एवं मकानों से लाखों-करोड़ों रुपये की आय होती है। स्वर्गीय डी आर गाडगिल का मत था कि "यदि गैर-कृषि-भाग पर सीमा लगाने का विचार नहीं किया जाता तो

कृषि आय पर सीमा लगाना अन्यायपूर्ण हो नहीं होगा, बल्कि समाज में भारी असंतुलन व असंतोष उत्पन्न कर देगा। गाँव के लोग अपनी सन्तान को उच्च शिक्षा (डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि) नहीं देता सक्ते। समाज में उनका राज-नौतिक प्रभाव घट जायेगा। शहरी वर्ग ग्रामीण वर्ग पर शासन करने लगेगा। उद्यमी व उत्साही व्यक्ति कृषि व्यवसाय में न लगकर शहरी की ओर जायेंगे। इससे कृषि और भी ज्यादा पिछड़ जायेगी और उसमें पूँजी-निवेश घट जायेगा।

2. छोटे पैमाने की खेती—सीमा लगाने के बाद छोटे पैमाने पर खेती हागी जिसमें पशुओं व यन्त्रों का प्रयोग ठीक से नहीं किया जा सकेगा। अतः बड़े पैमाने की खेती की विफायते या बचतें नहीं मिल पायेंगी। लेकिन इस समस्या का समाधान सेवा-सहकारिताओं का विकास करके किया जा सकता है जिसमें बड़े पैमाने की विफायने छोटे खेतों को भी मिल सकती हैं।

सीमा लगाने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। आज स्वामित्व की जोत (ownership holding) बड़ी होने पर भी कृषि की जोत (operational holding) कई भागों में बटी होने से छोटी ही होती है। सीमा लगाने के बाद यदि सिंचाई का प्रयोग करके गहन कृषि की जाय तो उत्पत्ति के घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। सीमा-निर्धारण का उद्देश्य अनार्षिक जोतें बनाना नहीं है, बल्कि अत्यधिक बड़ी जोतों के आकार का सीमित करना अथवा कम करना है। अत्यधिक बड़ी सीमा लगाने से उत्पादन के घटने का भय हो सकता है जापान, बेल्जियम व नीदरलैंड में छोटे खेतों पर भी प्रति एकड़ उपज काफी ऊँची पायी जाती है। अतः भू-जोतों पर सीमा लगाने से प्रति एकड़ उपज का घटना आवश्यक नहीं है।

3. बिक्री योग्य बचत में कमी की सम्भावना—सीमा लगाने के बाद छोटे-छोटे बहुत से भू-स्वामी बन जायेंगे। वे कुल उत्पत्ति में से अपने लिए मात्र मर का अनाज रखकर शेष की बिक्री के लिए बाजार में ले जायेंगे। स्वर्गीय गुन्नार मिडेल ने भी स्वीकार किया था कि इससे बिक्री-योग्य बचत (marketable surpluses) में कमी आने की सम्भावना हो सकती है। इससे शहरी मालिकानों की कमी आने से मूल्य बढ़ेंगे और देश में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। विद्वानों का मत है कि बड़ी जोतों पर बिक्री-योग्य बचतें अधिक होती हैं।

4. अनार्षिक जोतों के बढ़ने का भय—सीमा लागू करने के बाद यदि उत्तराधिकार के नियम के अनुसार भूमि का विभाजन जारी रहा तो एक ही पीढ़ी में एक साथ सारे देश में अनार्षिक जोतें उत्पन्न हो जायेंगी और उय स्थिति की सम्भालना बहुत मुश्किल हो जायेगा। इस सम्बन्ध में भी गुन्नार मिडेल का मत है कि यह भय निराधार है, क्योंकि भारत में आज भी खेती बटाईदारों व काश्तकारों तथा खेतिहर मजदूरों की सहायता से छोटे-छोटे खेतों पर ही की जाती है।

5 विभिन्न प्रशासनिक कठिनाइयाँ—सीमा निर्धारण के विरुद्ध म एव तक यह भी दिया जाता है कि इसमें कई प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं जिनका हल निकालना बहुत कठिन है जैसे—(अ) सीमा ऊँची हो या नीची हो ? (आ) सीमा निर्धारण का आधार क्या हो ? आय को आधार माना जाय या नुन के आधार को ? (इ) घातिरिक्त भूमि का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाय ? (ई) घातिरिक्त भूमि का मुआवजा कैसे निर्धारित किया जाय ? (उ) अनुचित प्रन्तरणों (malafide transfers) (बेनामी व फर्जी प्रन्तरणों) को कैसे रोका जाय ?

6 भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि नहीं मिल पायेगी—सीमा निर्धारण से जो भूमि प्राप्त होगी वह भूमिहीनों में बाँटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और उसमें उनकी गरीबी नहीं मिटेगी। भारत में अधिकांश मत छोटे होने से सीमा निर्धारण का प्रभाव सम्पन्न किसानों को दरिद्र बनाना होगा।

7 प्राचीण बेरोजगारी में वृद्धि का भय—सीमा निर्धारण से जो लोग बड़ानों पर मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं उनका रोजगार दन की जटिल समस्या खड़ी हो जायगी। इस प्रकार सीमा निर्धारण से गाँवों में बेरोजगारी या भ्रष्ट वरोजगारी के बढन का भय हो सकता है।

8 नये लोगों के पास विनियोग का अभाव—सीमा निर्धारण के विरुद्ध एक एक यह दिया जाता है कि भूमि के पुनर्वितरण से जिन नये लोगों को भूमि मिलेगी उनके पास विनियोग के लिए पूँजी इतनी कम होगी कि वे वेनी व लिए आवश्यक धन राशि ही जुटा पायेंगे। परिणामस्वरूप भूमि का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा और कृषिगत उत्पादन घट जायगा। इस तक म कुछ सार अवश्य है लेकिन भारत में सहकारी मस्याओं व्यावसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक के माध्यम में उत्पादन ऋण (Production loan) की व्यवस्था करके इस समस्या का उचित समाधान निकाला जा सकता है।

की जा सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़े व छोटे दोनों प्रकार के सेतो पर समान रूप से लागू की जा सकती है। यह वस्तुतः उत्पादन के पैमाने के प्रति तटस्थ (scale-neutral) होती है।

11 महाजन के प्रभाव में वृद्धि की आशंका—बटाईदारों व भूमिहीन श्रमिकों को भूमि के अधिकार मिल जाने से उनकी कर्ज लेने की क्षमता व इच्छा बढ़ जायेगी जिससे वह महाजन के चंगुल में फँस जायेंगे और अन्त में अपनी भू-जोतें खो देंगे।

12 अनाधिक व बहुत छोटी जोतों की भरमार—दांडेकर व रयन अपने सुप्रसिद्ध अध्ययन 'Poverty in India' में बताया है कि सीमा-निर्धारण से देश में अनाधिक व अलामप्रद जोतों की संख्या बढ़ जायेगी क्योंकि हमारे देश में बाँटन के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल पायेगी। भूमि के छोटे-छाटे स्वामी या तो अपनी भूमि बेच देग अथवा बड़े कृषकों को शिराय पर उठा देंगे जिससे उल्टा या विपरीत ढंग की काश्तकारी प्रथा प्रचलित हो जायेगी। यही कारण है कि दांडेकर व रयन ने सीमा-निर्धारण के स्तर को नीचा करने का समर्थन नहीं किया है।

इस प्रकार सीमा-निर्धारण के विषय में कई प्रकार के तर्क पेश किये गये हैं। अतः यह प्रश्न बहुत पेचीदा है और कई प्रकार की समस्याओं से भिरा हुआ है। याम्यन में इतना ब्रान्तिकारी कदम आसान हो भी नहीं सकता। इससे करोड़ों भू-स्वामियों काश्तकारों व भूमिहीन मजदूरों के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसका लागू करना और भी कठिन माना गया है। पिछले वर्षों में सीलिंग से ऊपर की भूमि सम्बन्धियों मित्रों आदि से बाँट दी गई है और अनुमान है कि सीलिंग ऊँची रखने से अतिरिक्त भूमि (surplus land) कम मिलती है और नीची रखने में गाँवों के उत्साह व बूमठ कुपक निराश हो जाते हैं। इन सब कारणों से सीमा-निर्धारण की मामला व्यवहार में काफी जटिल बन गया है।

भारत में सीमा-निर्धारण की शिक्षा से प्रसंग

सीमा-निर्धारण से सम्बन्धित सुझावों के प्रश्नों को जाँच करने का कार्य केन्द्रीय भूमि सुधार समिति को सितम्बर 1970 में सौंपा गया था जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1971 में पेश की थी। इसमें विभिन्न राज्यों के सीमा-निर्धारण-कानूनों में समानता लाने हेतु कई सुझाव दिये थे। 23 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सीमा-निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें की गई थी—

फॉलोइंग (1)

(1) सीमा-सम्पूर्ण परिवार के लिए लागू होना चाहिए। परिवार से व्यक्ति-वर्ती नहीं होना चाहिए। अल्पवर्गीय वर्गों के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए।

- (ii) परिवार में सदस्यों की संख्या पांच से अधिक होने पर प्रत्येक सदस्य के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था की जाय लेकिन एक परिवार क पांच निर्धारित सीमा के दुगुने से ज्यादा भूमि न रहने दी जाय ।
- (iii) पांच सदस्यों के परिवार के लिए सीमा 10 से 18 एकड़ स्थायी सिंचित भूमि या दो फसल उगाने लायक सिंचित भूमि रखी जाय । विभिन्न राज्यों एवं एक ही राज्य के विभिन्न भागों में मिट्टी की दशाओं भूमि की उर्वरता, उगाई गई फसल की किस्म में अंतर होना संभव सीमाएँ सुझायी गयी थी ।
- (iv) सूखे क्षेत्रों के लिए भी पांच सदस्यों के परिवार के लिए एक निरपेक्ष सीमा (Absolute Ceiling) 54 एकड़ सुझायी गयी थी जिसमें विशेष परिस्थितियों को देखकर ही परिवर्तन किया जाना चाहिए जैसे मिट्टी की किस्म, वर्षा, सूखे की दशाएँ आदि ।
- (v) राज्यों के प्रचलित कानूनों में यन्त्रीकृत खेतों मुनियोजित खेतों आदि के सम्बन्ध में जो छूटें दी गई हैं, वे हटा लेनी चाहिए ।
- (vi) चाय, कहवा, इलाइची व रबड़ आदि बागानों के पक्ष में दी गई छूटों की सम्बन्धित मन्त्रालयों व राज्य सरकारों के साथ मिलकर ध्यान से जांच की जानी चाहिए । उसके बाद उन छूटों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए मुख्य-मंत्रियों से बातचीत की जानी चाहिए ।

सीमा-निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति—बाद में अधिकांश राज्यों में सीमा निर्धारण कानूनों में संशोधन किये गये और ज्यादातर राज्यों में सीमा का स्तर नीचा बिना गया और परिवार को लागू करने की इकाई माना गया । केवल उड़ीसा में पनेले भू-स्वामी को ही इकाई माना गया ।

घुटे हुए राज्यों में जोतों पर वर्तमान सीमा का स्तर (हैक्टेयर में)

राज्य	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
(1) बिहार	6 07—10 12	12 14—18 21
(2) मध्य-प्रदेश	7 28—10 93	21 85
(3) राजस्थान	7 28—10 93	21 85—70 82
(4) उत्तरप्रदेश	7 30	10 95—18 25
(5) पश्चिमी बंगाल	5	7

इस प्रकार विभिन्न राज्यों में सीमा-निर्धारण के स्तरों में काफी असमानताएँ पायी गयी हैं । नागालैंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम में भूमि प्रायः 'समुदाय' के द्वारा रखी जाती है इसलिए इनको छोड़कर अन्य सभी राज्यों में

मीमा-निर्धारण के कानून बनाये गये हैं, लेकिन सीलिंग से ऊपर की भूमि को ग्रहण करने तथा उसका वितरण करने का काम बाफ़ी धीमा रहा है। अब तक लगभग 29.7 लाख हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त भूमि (surplus) घोषित की गई है जिसमें से 23.6 लाख हैक्टेयर भूमि राज्य ने अपने अधिकार में ली है तथा 18.2 लाख हैक्टेयर भूमि का वितरण 33.7 लाख व्यक्तियों में किया जा चुका है। इससे कई लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों का अंश आधे से ज्यादा रहा है। अतिरिक्त घोषित भूमि के 6.6 लाख हैक्टेयर के सम्बन्ध में मुकुंदमेवाजी चल रही है जो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल में अधिक है।¹ सीलिंग से ऊपर की भूमि पर बसाये गये लोगों को बेतौ म मदद देने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

सीलिंग कानूनों को व्यवहार में लागू करने की दृष्टि से बाफ़ी कमिया रही है जिससे अतिरिक्त भूमि की मात्रा लक्ष्य से बहुत कम मिली है। द्वितीय कृषिगत सन्तम 1976-77 के अनुसार 'अतिरिक्त या सरप्लस भूमि' की मात्रा 88.84 लाख हैक्टेयर होनी चाहिए थी, जबकि राज्यों द्वारा 29.7 लाख हैक्टेयर ही सरप्लस घोषित की गई है। इन दोनों में विशाल अन्तर का प्रमुख कारण भूमि के बेनामी व पर्जा हस्तान्तरण हैं जिन्हें न रोकने से यह स्थिति बनी है।

4. कृषि का पुनर्गठन - (क) चकबन्दी (Consolidation of holdings)— भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्र करना ही चकबन्दी कहलाता है। अब तक विभिन्न राज्यों में 5.26 करोड़ हैक्टेयर भूमि में चकबन्दी की जा चुकी है जो देश में कुल कृषित भूमि का 33 प्रतिशत (लगभग 1/3) है। योजनाओं में चकबन्दी के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में चकबन्दी का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। अन्य राज्यों में उसकी प्रगति धीमी रही है। चकबन्दी से काश्तकारों व बटाईदारों को हानि भी हुई है, क्योंकि भू-स्वामी बड़े खेतों पर स्वयं खेती करने लगे हैं। कई राज्यों में भूमि के हस्तान्तरण व टुकड़ों पर रोक लगाई गई है और भूमि की व्युत्पन्न सीमा भी निर्धारित की गयी है जिसके नीचे भूमि का विभाजन नहीं होने दिया जाता।

1 D Bandyopadhyay's article on Land Reforms in India, EPW, June 21-28, 1986, p A-50 ऊपर सीलिंग के आकड़े भी इसी लेख से लिये गये हैं। India 1987 (पृ 399) के अनुसार जून, 1987 तक 44.2 लाख एकड़ भूमि 41 लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व अन्य व्यक्तियों में बांटी गयी है। एब हैक्टेयर = 2.471 एकड़ होता है।

हम पहले बतला चुके हैं कि चक्करी से अपखण्डन व दोष दूर हो जात है और भूमि की उत्पादकता में सुधार होता है। एक कृषक के विभिन्न टुकड़ों एक जगह पर आ जाये से उत्पादन लागत कम हो जाती है और खतों की देखभाल अच्छी होती है और कायमोली जात का आकार भी बड़ा जाता है जिससे प्राथमिक कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोफेसर बी० एस० मिहस न कुवियत सुधारों में चक्करी पर काफी बल दिया है जिससे इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हम उपविभाजन व अपखण्डन के प्रयास में बतला चुके हैं कि पञ्जाब व उत्तरप्रदेश में चक्करी से काफी लाभ आता है जैसे अनिश्चित भूमि पर खती होने लगी है (मीमाया व मेडा) में भी मिलती गई है जो वास्तव में नष्ट हो गई है। फसलों का प्राथमिक व्यापारिक फसलों के साथ में बढ़ता है जिससे किसानों की आमदना बढ़ी है जिससे तौर पर सिंचन का विचार होने से कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता बढ़ी है उत्पादन का लागत घटा है तथा गाँवों में मुकदमवाजी कम हुई है तथा ग्रामीण समाज पहले से अधिक पारम्परिक बहुयोग व आधार पर काम करने लगा है।

(ख) भूमि का प्रबंधन व सुधार—इसके अन्तर्गत बजर भूमि का उपयोग सुरक्षित क्षेत्रों का प्रयोग बीटनमस्टर दबाइया का उपयोग आदि आते हैं। प्रथम व द्वितीय अंशों में भूमि के प्रबंधन व सुधार करने पर जोर दिया गया था। उनमें यह सुझाव दिया गया था कि सर्वप्रथम भूमि का कुशल प्रबंधन व प्रयोग उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहाँ इसके लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।

(ग) सहकारी सेवा—पहले बताया जा चुका है कि भूमि का छांट-छांट करने का निष्कर्ष समुक्त खेतों करना भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सरकार में सरकार ने ऐच्छिक सहकारी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना व आग्रह करने पर विचार किया है।

हमारे देश में उनमें कृषि सहकारी समितियाँ अथवा सहकारी सेवा समिति बना कर उन पर जोर दिया गया है ताकि किसानों का खाद बाजार एवं बीजालाभ और भी अधिक बढ़े।

30 जून 1981 का दस्तावेज 5345 समुक्त कृषि समितियों (Farmer's group societies) की जिनका सदस्य संख्या 2.07 लाख व क्षेत्रफल 4.7 लाख हैकटायर था। इसमें प्रथम में 3798 सामूहिक कृषि समितियाँ (Collective farmer's societies) का जिनकी सदस्य संख्या 1.50 लाख व क्षेत्रफल 2.4 लाख हैकटायर भूमि था। इनमें से बहुत कम समितियाँ लाभ में चल रही थी।

एक प्रकाश (30 जून) 1981 का कृत सहकारी कृषि समितियाँ 91103 की संख्या में नष्ट हो गई थी।

भूमि के अन्तर्गत सहकारी समितियों का प्रचार बहुत कम हो गया है। कृषि विभागों के भी जिनमें से हमें परीक्षाएं जरूरी नहीं होती हैं। बहुत छोटे खेतों में भी यह प्रचार नहीं हो पाया है।

के लिए तथा नये क्षेत्रों में भूमिहीनों को बसाने के लिए इनकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(घ) भूमिहीन मजदूरों को बसाना एवं भूदान-आन्दोलन—1951 में भूदान आन्दोलन भूमिहीन मजदूरों को भूमि पर बसाने के लिए प्रारम्भ किया गया था। इसमें इच्छा से प्रत्येक भू-स्वामी से 1/6 भूमि दान में माँगी गई थी। बाद में यह आन्दोलन ग्राम-दान में परिवर्तित हो गया। 1952 में स्वर्गीय विनोबा भावे ने बिहार में 'पदयात्रा' करके 84 लाख हेक्टेयर भूमि भूदान में प्राप्त की थी। अब तक भूदान में लगभग 42 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई है जिसमें से 13 लाख एकड़ भूमि का ही आवंटन किया गया है। राज्य सरकारों ने भूदान की भूमि के विकास के लिए आवश्यक कार्य नहीं किया है। देश में 167 कराड़ हेक्टेयर द्विपयोग्य व्यर्थ-भूमि भी उपलब्ध है लेकिन इसका भी समुचित उपयोग व विकास नहीं हो पाया है।

भूदान आन्दोलन का मूल्यारूढ-भूदान या ग्रामदान आन्दोलन न भूमि-सुधार के लिए और विशेषतया सहकारी ग्राम-प्रबन्ध के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया था। भारत में भूमि-सुधार के कार्यक्रमों को लागू करना बहुत आवश्यक है। यह कार्य केवल सरकारी कानूनों से पूरा नहीं हो सकता है। व्यवहार में सरकारी कानूनों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा सका है, जिससे वांछित परिणाम नहीं निकले हैं। ऐसी परिस्थिति में भूदान ग्रामदान व सम्पत्ति-दान आदि के रूप में जो सर्वोदयी विचारधारा उभरी थी, उसके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक शान्तिपूर्ण व अहिंसक क्रान्ति का मार्ग माना गया है और गाँधीजी के विचारों पर आधारित है। निस्संदेह इससे नये समाज की रचना सच्चे अर्थ में हो सकती है।

लेकिन व्यवहार में भूदान आन्दोलन को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसकी प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नांकित हैं

(1) सच्चे कार्यकर्ताओं का अभाव पाया गया है। (2) भूदान में प्राप्त भूमि का काफी भाग बजर व अनुपयुक्त किस्म का पाया गया है। (3) कुछ भूमि के कानूनी अधिकारों के सम्बन्ध में विवाद पाया गया है। (4) भूमिहीनों को केवल भूमि का वितरण कर देने से पर्याप्त लाभ नहीं होगा; उन्हें कृषि के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध कराने होंगे जिनका प्रायः अभाव पाया जाता है। (5) आजकल लोगों का यह विचार हो चला है कि भूमि-क्रान्ति से ही वास्तविक समस्या हल हो सकती है और इसके लिए सरकार ही भूमि-सुधारों को कठोरता से लागू करे तो ज्यादा अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। निहित स्वार्थों वाला वर्ग भूमि पर से आसानी से अपने अधिकार छोड़ने वाला नहीं है। (6) भूदान से भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्या का हल नहीं निकल पाया है।

उपयुक्त बाधाओं को देखते हुए भूदान व ग्रामदान का भूमि-सुधारो की दृष्टि से महत्व बहुत सीमित हो गया है। लेकिन ग्रामीण अधिकों व ग्रामीण निर्धनों को संगठित करने में सर्वोच्च नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिसकी आज की परिस्थितियों में नितान्त आवश्यकता है। गाँव के गरीबों व भूमिहीनों को संगठित करके उनको विभिन्न साधन प्राप्त करने में मदद की जानी चाहिए जो सरकार उन तक पहुँचाना चाहती है।

भूमिहीन मजदूरों के लाभ के लिए स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने 1 जुलाई, 1975 को घोषित किये गये 20 सूत्री वार्षिक कार्यक्रम में निम्न सुझाव दिये थे :

(1) भू-जोतो पर सीमा लगाकर भूमिहीनों में प्रतिरिक्त भूमि का वितरण करना; (2) भूमिहीनों व निर्धनों के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था करना; (3) भूमिहीन अधिकों, लघु कृषकों व वासीरों को ग्रामीण वर्ज से मुक्ति दिलाना, तथा (4) ग्यूनतम कृषि-मजदूरों के कानूनों की पुन. जाँच करना। इस प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम में उपादा ध्यान भूमिहीनों की वार्षिक दशा को सुधारने पर दिया गया था। 14 जनवरी, 1982 के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में भी भूमिहीन मजदूरों के लिए निम्न कार्यक्रम रखे गये थे - (i) खेतिहर श्रम के लिए ग्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करना तथा उसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना (ii) बहुधा श्रम को फिर से बसाने की व्यवस्था करना (iii) ग्रामीण परिवारों को रिहायशी भूखण्ड आवंटित करना तथा निर्माण-सहायता के कार्यक्रमों का विस्तार करना।

भारत में भूमि-सुधारो की प्रगति का मूल्यांकन

संस्तोषजनक क्रियान्वयन—उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत में योजनाकाल में भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों की बाढ़-सी आ गयी थी। मध्यस्थ-वर्ग की समाप्ति, वास्तुकारों की बेदखली से रक्षा करने, लगान का नियन्त्रण करने, भूमि को जोतने वाले को भूमि का मालिक बनाने, सीमा-निर्धारण करने, सहकारी खेती, चण्डी एव भूदान आदि के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में आवश्यक अधिनियम पास किये गये। भारत में भूमि-सुधारो के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफी प्रगति मिली है। राज्यों में क्रियान्वयन में पर्याप्त तत्परता व गम्भीरता नहीं दिखाई है, बल्कि अनावश्यक देरी व धील-शाल की है, जिससे प्राप्त परिणाम बहुत-बुद्ध निराशाजनक रहे हैं।

जब हम यह देखते हैं कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को वहाँ तक लागू किया गया है, व्यवहार में वास्तुकारों की बेदखली से कहीं तक रक्षा हुई, लगान वहाँ तक कम हो पाये हैं, कितने किसान भूमि के वास्तविक मालिक बन पाये हैं, सीमा-निर्धारण से कितनी प्रतिरिक्त भूमि मिली है, कितनी प्रतिरिक्त भूमिहीनों में वितरित की गई है कितने मजदूर सहकारी में नौकर रहे हैं, एव कितने भूमिहीन

मजदूरो अथवा किसानों को नई भूमि पर बसाया गया है, तब हमें असंतोषजनक स्थिति ही मिलती है। देश में कानून तो बहुत बनाये जा चुके हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया है। कानूनों में कहीं-कहीं ऐसे छिद्र छोड़ दिये गये जिनका दुरुपयोग निहित स्वार्थी-वर्ग ने अपनी स्थिति को मजबूत करने में किया है और कानूनों को अदालतों में बराबर चुनौती दी गई है। भूमि-सुधारों की ठीक से लागू नहीं किया जाना एक भारी चिन्ता का विषय है, क्योंकि इससे गाँवों में अनिश्चितता व असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ है। स्वयं सरकारी प्रकाशनों में यह स्वीकार किया गया है कि भारत में भूमि-सुधार-कार्यक्रमों में गामीण क्षेत्रों में सामाजिक अन्धकार को मिटाने एवं भूमि को जोतने वाले की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों जैसे सहकारी कृषि सीमा-निर्धारण से अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने तथा उस पर भूमिहीन मजदूरों को बसाने व कاشتकारों को भू-स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने की दिशा में पर्याप्त रूप से प्रगति नहीं हुई है।

भूमि-सुधारों के कानूनों का लाभ विस्तृत क्षेत्रों में कاشتकारों को नहीं मिल पाया है। भू-स्वामियों ने खुदकाश के नाम पर काफी जमीनें स्वयं दबा ली हैं और कاشتकारों को बेदखल कर दिया गया है। उन्हें भूमि का ऐच्छिक परित्याग (Voluntary Surrender) करने को बाध्य किया गया है। प्रोफेसर गुन्नार मिडेल ने अपने ग्रन्थ (Asian Drama) (खण्ड I) में कहा है कि भूमि सम्बन्धी कानूनों के पारित हो जाने से कاشتकारों में बेदखली की एक लहर-सी दौड़ गयी और तथाकथित 'खुदकाश' के लिए भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया। खुदकाश की भूमि पर प्रायः बटाईदार व खेतिहर श्रमिक कार्य करते हैं। सीमा-निर्धारण से बचने के लिए अनियमित व भ्रष्टानिक अन्तरण (Malafide Transfers) भी किये गये हैं और अतिरिक्त भूमि नगण्य मात्रा में ही मिल पायी है।

1 जाली सहकारी कृषि समितियाँ—प्रायः यह देखा गया है कि सहकारी कृषि-समितियाँ बड़े भू-स्वामियों द्वारा बनायी गयी हैं जिनके माध्यम से विभिन्न सहकारी सुविधाओं व साधनों का अनुचित लाभ उठाया गया है। ऐसी सहकारी कृषि-समितियाँ नगण्य हैं जो प्रचारिक जोतों के स्वामियों अथवा भूमिहीन मजदूरों के द्वारा उन्हीं के लाभ के लिए बनाई गई हैं। इससे सहकारी संगठन भी अनावश्यक रूप से बदनाम हो गया है जो अनुकूल राजनीतिक वातावरण में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता था।

ऐसी स्थिति के होने से ही भूमि का असली जोतने वाला व्यक्ति ग्राज भी अपने आपको असहाय, निर्धन व घोषित ही मानता है। भारतीय भूमि-सुधारों के विशेषज्ञ स्वर्गीय डेनियल थोर्नर का भी यही कहना था कि भूमि-सुधार अपने केन्द्रीय व घोषित उद्देश्यों में सफल नहीं हुए हैं।

2. काश्तकारों व बटाईदारों की शोचनीय दशा—काश्तकारों की मूलकाल में देवसली की गई है और नू-स्वामी काश्तकारी कानूनों को विफल करने के लिए एक प्लाट से दूसरे प्लाट पर काश्तकारों को बदलते रहते हैं। दीर्घकाल से जारी रहने वाले काश्तकार भी अपने आपको अशुभित (insecure) महसूस करते रहते हैं। इस प्रकार काफी सख्या में कृषकों को 'लीज' की भूमि पर कोई हक नहीं मिला है। वे ऊँचे लगान भरते रहे हैं और अपनी स्थिति के बारे में कभी निश्चित नहीं रहे हैं। उनके पास गुजारे के लिए कम धन-राशि रही है और विनियोग के लिए तो और भी कम।

जब तक नू-स्वामी स्वाहति न दें, ग्राम-सेवक काश्तदार-वित्तान के लिए उत्पादन-योजना बनाने में हिचकिचाते हैं। अतः उन्हें साल की सुविधा नहीं मिल पाती है। विद्वानों का मत है कि भूमि के नवीनतम रिकार्ड तैयार करने चाहिए, फसलों के रूप में लगान को नकदी लगान में बदल देना चाहिये तथा काश्तकारों को बिना पहलू करने लायक भूमि पर स्वायत्त के अधिकार दे देने चाहिये। यदि सहकारी समिति काश्तकारों को ऋण न दें तो सरकार को इन्हें तत्काली ऋण देना चाहिये।

3 ऊँचे लगान—भूमि मुधारों की समीक्षा करते हुए डॉ. के एन. राज न कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि 'मुख्य बात यह है कि भारत में विद्यमान दशाद्वियों में भूमि-सम्बन्धी कानून तो काफी बने हैं और अशत. लागू भी किये गये हैं, लेकिन प्रायः भी कुल दृष्टिगत क्षेत्र का बड़ा नाम कानूनी-प्रथा (tenancy) के अन्तर्गत आता है और लगान प्रायः कानून द्वारा निर्धारित सीमा से काफी ऊँचे देखने को मिलते हैं। भूमि सम्बन्धी कानूनों ने वास्तव में अनेक प्रदेशों में काश्तकारों के कुछ रूपों को तो मिटा दिया है और उनके स्थान पर अनौपचारिक (informal) व दमनकारी फसल बटाई व्यवस्था को लागू कर दिया है। इसका कारण यह है कि नू-स्वामी अथवा काश्तकारों को मिल सकने वाले अधिकारों से काफी डर गये हैं। भूमि पर जन-नार अधिक होने से नू-स्वामी भूमिहीन किसानों पर ऐसी व्यवस्था लादने में समर्थ हो जाते हैं या शासन पर आधारित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज-व्यवस्था और राजनीतिक शक्तियों के संतुलन के कारण काश्तकारों के लिए उन अधिकारों का प्राप्ति कर लेना कठिन होता है जो उन्हें कानून की ओर से मिले हुए होते हैं।' फसल-बटाई के आधार पर काम करने वाले काश्तकारों को स्थायी गतिहर श्रमिकों में शामिल मान लिया गया है। सिंचित क्षेत्रों में लगान ऊँचे होने से कानूनी-कृषकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा नहीं मिलती। देश के सिंचित व अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में लगान कुल उपज के 50% से 60% (कभी-कभी और भी अधिक) तक पाये जाते हैं और फसल-बटाई पद्धति व काश्तकारों की सुरक्षा व अभाव में समय-समय पर बदलने भी रहते हैं। इस प्रकार व्यवहार में ऊँचे लगान पाये जाते हैं।

4. सीमा निर्धारण के क्रियान्वयन में देरी—सीमा-निर्धारण के कानूनों में कई कमियाँ व दोष रह गये हैं। इसमें काफी छूटें दी गई हैं। कानूनों को लागू करने में विलम्ब, कार्याकुशलता व भ्रष्टाचार पाया गया है।

विद्वानों का मत है कि तथाकथित अधिराश अतिरिक्त भूमि घटिया रिश्तों की पाई गई है एवं कुछ तो बाँटने के लायक ही नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है द्वितीय कृषिगत सगराना (सेन्सस), 1976-77 के अनुसार अतिरिक्त भूमि की मात्रा 88.84 लाख हेक्टेयर होनी चाहिए थी लेकिन राज्यों द्वारा घोषित अतिरिक्त भूमि की मात्रा केवल 29.7 लाख हेक्टेयर ही रही है। अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित की गई भूमि कुल कृषिगत क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत से भी कम रही है। इतने भारी अन्तर के लिए कई कारण उत्तरदायी माने जाते हैं—जैसे वेंनामी (किसी दूसरे के नाम से) व कर्मी अन्तरण पिछली तारीख में कुछ व्यक्तियों के नाम काश्तकारी दिखा देना (बाद में उनकी भूमि बेच देना या दे देना) ट्रस्ट व संस्थाओं का निर्माण करना, भूमि के विभाजन की व्यवस्था कर लेना आदि। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में वन-भूमि व कॉमन-भूमि भी बाँट दी गई है जो भूमि-सुधारों का उद्देश्य नहीं था। इस प्रकार के वितरण से लोगों की कठिनाइयाँ घटने के बजाय बढ़ गई हैं।

5 भूमि सुधारों से बचने के प्रयास—हमने भूमि-सुधार जैसे नातिवारी कार्यक्रम को प्रजातान्त्रिक व शांतिपूर्ण तरीकों से अपनाने का रास्ता अपनाया है। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति के ले लिए जाने पर सरकार ने उचित मुआवजा देने की व्यवस्था स्वीकार की है। भूतकाल में भूमि-सुधार कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार पहले अपने इरादों की घोषणा करती थी, फिर बहुत देर से आवश्यक कानून बनता था, तत्पश्चात् उस कानून को लागू करने की कोशिश की जाती थी। इस बीच में निहित स्वार्थी-वर्ग सावधान हो जाता है और कानून से बचने के अनेक हथकण्डे व तरीके तलाश कर लेता है। गाँवों में महाजनों व जमींदारों की साम्राज्य व आर्थिक स्थिति का प्रभाव अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। ऐसी हालत में वर्षों का घोषित काश्तकार, जिस पर बर्जों का भार लदा हुआ है, जो कानून या तो समझता नहीं अथवा समझते हुए भी अपने अधिकार लेने के लिए अपने आपको असमर्थ पाता है, वह भूमि-सुधारों के लाभों से वंचित ही रहेगा।

6. भूमि के वितरण में परिवर्तन का अभाव—कई वर्षों के भूमि-सुधारों के बाद भी भूमि के स्वामित्व में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सीमा-निर्धारण के कानूनों के लागू न होने से स्वामित्व की स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। कार्यशील जोतों के वितरण में भी विशेष अन्तर नहीं आया है 1980-81 की तृतीय कृषि सगराना के अनुसार 10 हेक्टेयर तक की सीमान्त जोतें 56.5 % थी और उनमें 12% क्षेत्र समाया हुआ था, जबकि 10.0 हेक्टेयर से अधिक आकार की जोतें

(2.4%) थी और उनमें 23% क्षेत्र समाया हुआ था। लगभग इसी प्रकार की स्थिति 20 वर्ष पूर्व 1960-61 में पायी गयी थी, हालांकि इस बीच बड़ी जोतो से मध्यम व छोटी जोतो की और मामूली परिवर्तन की स्थिति अवश्य आई गई है। इस प्रकार दश में घाज भी छोटे खेतों की मरमार बनी हुई है। नियोजन के 38 वर्ष बाद भी भू-जोतो का आकारानुसार वितरण काफी असमान बना हुआ है जो इस बात का सूचक है कि भूमि-सुधार भू-जोतो के वितरण को अधिक समान बनाने में असमर्थ रहे हैं।

भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारण

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में भूमि-सुधारों का प्रियान्वयन दोषपूर्ण रहा है। इसके निम्न कारण माने जाते हैं।

1 राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी (lack of political will)—भूमि-सुधारों जैसा सक्रिय व शान्तिकारी कार्यक्रम राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में लागू नहीं किया जा सका है। भू-स्वामियों के हितों के समर्थकों ने राज्यों में भूमि-सुधारों को लागू नहीं होने दिया है। स्थानीय रेवेन्यू स्टॉफ व बड़े कृषकों में परस्पर साठ गांठ पायी जाती है जिससे विभिन्न भूमि-सुधार-कार्यक्रम व्यवहार में लागू नहीं हो पाते हैं।

2 कारतकारों व अन्य शोषित वर्गों के दबाव व राजनीतिक संगठन की कमी—एतिहर मजदूरों व काश्तकारों और उपकाश्तकारों ने भूमि-सुधारों को लागू करवाने में लिए सरकार पर आवश्यक दबाव नहीं डाला है। उनमें आवश्यक राजनीतिक संगठन का भी अभाव पाया गया है। अतः गांवों में सेतिहर मजदूरों को संगठित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

3 कानूनी रुकावटें व प्रशासनिक बाधाएँ—कानूनों में दीये रहे जून स भू-स्वामी मुकदमेवाजी का सहारा लेते हैं और उन कानूनों को लागू होने से रोकवा देते हैं। प्रशासकीय का रण भी भू-स्वामियों के पक्ष में रहा है जिससे वे कानूनों का लागू करन व प्रति उदासीन पाय गय है।

4 भूमि के नवीनतम दिशाओं का धम व—प्राथम्य की बात है कि ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बिना लाजा रिवाइंड व सही सूचना के लागू किया जाता रहा है जिससे इसका मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हा गई है।

5 भूमि सुधारों के एकीकृत कार्यक्रम (integrated programme) का अभाव—हमने भूमि-सुधारों के अलग अलग कार्यक्रमों जैसे चबूकड़ी, सहकारी कृषि व सीमा-निर्धारण व बांध परस्पर ताल-मेल बैठान की चप्टा नहीं की है। इसी प्रकार भूमि व वितरण के साथ कृषिगत माध के कार्यक्रम नहीं जोडे गय है। अतः भूमि सुधारों को कई टुकड़ों में लागू करने से भी कम सफलता मिल पायी है।

सरकार को चाहिये कि वह ऐसे असहाय, निर्बल व निर्धन लोगों की विभिन्न प्रकार के प्रत्याचारों से रक्षा करे।

जून 1978 में भूमि-सुधारों की प्रगति की जांच करने व प्रावश्यक सुझाव देने के लिए स्वर्गीय राजकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि भूमि-सुधारों को संविधान की नवी अनुसूची (ninth schedule) में शामिल कर लिया जाय ताकि इन्हें अदालतों में चुनौती न दी जा सके। इससे भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन पर प्रच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा भूमि पर सीमा निर्धारण कानून लागू करना सम्भव हो जायगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 में भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यक्रम—

सातवीं योजना में भूमि-सुधार-कार्यक्रमों को निर्धनता-उन्मूलन नीति व कार्यक्रम का प्रावश्यक अंग माना गया है। इस योजना में भूमि-सुधार सम्बन्धी निम्न कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है :

(i) जिन राज्यों ने बांश्तरारों के अधिकारों की सुरक्षा व लगान-निश्चयन के कानून नहीं बनाये हैं, वे सातवीं योजना में ये कानून बनायेंगे।

अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमि के अधिकारों की रक्षा की जायगी ताकि उनसे भूमि न छिन जाय।

(ii) सीलिंग में घोषित भूमि व वितरित भूमि का अन्तर कम किया जायगा। बंभाज क्षेत्रों व अन्य गए संचित क्षेत्रों में सीलिंग से ऊपर की भूमि का पुन. जायजा लिया जायगा। जो अतिरिक्त भूमि अती के लायक न होने से वितरित नहीं की जा सक्ती उसे राज्य सरकारें अपने अधिकार में ल लेंगी ताकि उनका भावी विकास किया जा सके।

(iii) सीलिंग से ऊपर की अतिरिक्त भूमि जिन लोगों की मिली है, उन्हें वित्तीय सह यता दी जायगी। इनके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व ग्राम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का भूमि-सुधारों से ताल-मेल बँढाया जायगा ताकि ऐसे लोगों का मदद मिल सके।

(iv) देश के पूर्वी भाग में सावन का उत्पादन बढाने के लिए खखबन्दी का काम पूरा किया जायगा। खखबन्दी कार्यक्रम में सधु व सीमान्त कृषकों की प्रावश्यकताओं पर अतिर ध्यान दिया जायगा ताकि भूतल व जल का अधिक उपयोग किया जा सक तथा कृषियत सेवाओं व इपुटों का उपयोग अधिक कियायत से किया जा सके।

(v) सभी राज्यों में भूमि-रिकाड़ों की नवीनतम बनाने पर पूरा ध्यान दिया जायगा। बिना मापी गई भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जायगा। बांश्तरारों व बडाइशरों के अधिकारों के रिकाड़ बनाए जायेंगे। इस कार्य में राज्य सरकारों को मदद दी जायगी ताकि वे रेवेयू मशीनरी को सुदृढ़ कर सकें। कर्मचारियों को

प्रशिक्षण दिया जायगा और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन साने की कोशिश की जायगी।

(vi) सीसिंग से ऊपर की भूमि प्राप्त करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता दी जायगी ताकि वे उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकें।

इस प्रकार सातवी योजना में भूमि-सुधार कार्यक्रमों को लागू करने पर पुन. ध्यान केन्द्रित किया गया है।

भूमि-सुधार व तकनीकी परिवर्तन—दोनों की समान आवश्यकता

निष्कर्ष—भारत में 1966-67 से कृषि-विकास की नयी नीति के लागू होने से उद्यमकर्ता किसान या व्यवसायी कृषक-वर्ग का उदय हुआ है। कृषि भी उद्योग का स्वरूप धारण करती जा रही है। ऐसी दशा में कुछ विद्वान यह मानने लगे हैं कि अब भूमि-सुधारों के बजाय तकनीकी सुधारों, जैसे सिंचाई, अधिक उपज देने वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरक, मोजार, साख व कीटनाशक दवाइयों आदि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ सके। ये विचारक कृषिगत क्षेत्र में बड़ी हुई माघ पर माघ-कर लगान का समर्थन करते हैं और जितनी मजदूरी को उचित मजदूरी देने का भी समर्थन करते हैं। लेकिन वह भूमि-सुधार कार्यक्रम में केवल कारतकारी (tenancy reforms) तक ही जाना चाहते हैं, जैसे उचित लगान व भू-धारण की सुरक्षा, आदि। वे सीमा-निर्धारण व सहकारी खेती आदि को जियोप आवश्यकता नहीं समझते।

लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि कृषि में केवल तकनीकी परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि चक्रवर्दी, सीमा-निर्धारण, अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने, आदि का भी समान रूप से महत्व है। अतः कृषि में सत्यागत परिवर्तनों की दृष्टि से भूमि-सुधारों को अवश्य कार्यान्विन किया जाना चाहिए अन्यथा देहातो में अमन्तोप बढ़ेगा और सामाजिक दृष्टि से विस्फोटक व विपरीत किस्म का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। सरकार को हरिजनो व आदिवासियों को धनी व शक्तिशाली भू-स्वामियों व सर्वर्ण हिन्दुओं के अत्याचारों से बचाना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी उनसे भूतकाल में आवृत्ति की गई भूमि अनुचित दबाव डालकर न छीन सके।

अतः लगान कम करने, वास्तकार को भू-धारण की सुरक्षा दिलाने, वास्तकार को भू-स्वामी के अधिकार दिलाने, चक्रवर्दी करने, सहकारी सेवा समितियों को सुदृढ करने, सीमा-निर्धारण करने व अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बाँटने आदि कार्यक्रमों के प्रति नये जोश-खरोश से काम करने की आवश्यकता है। सभी तन्त्रों की परिवर्तन ज्यादा मात्रा में सफल प्रमाणित होये। भूमि-सुधारों में दी गई ढील व शिथिलता बहुत गम्भीर परिणामों को जन्म दे सकती है। अतः हमें भूमि सुधार, तकनीकी परिवर्तन व कृषि के आधार-ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को सुदृढ करने के लिए किए जाने वाले सार्वजनिक विनियोग में आवश्यक तालमेल बैठाकर कृषिगत उत्पादन

बढ़ाना चाहिए। प्रोफेसर एम. एल. दांतवाला का मत है कि विभिन्न स्थानों व विभिन्न समयों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही कार्यक्रम अपनाये जाने चाहिए। जहाँ भूमि-सुधार हो गये हैं वहाँ तकनीकी प्रगति व कृषिगत इन्पुटों की सप्लाई पर अधिक जोर देना चाहिए एवं जहाँ कृषिगत विकास की नयी नीति लागू हो गयी है और भूमि सुधार लागू नहीं किए गए हैं वहाँ भूमि-सुधारों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभी क्षेत्रों में सड़क, बिजलू, सिंचाई आदि की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिए। इस प्रकार इतिवृत्त ज़ाति व भूमि-सुधार दोनों पर समन्वित रूप से जोर दिया जाना चाहिए, सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक अधिक न्याय-संगत व अधिक प्रगतिशील बन सकेगी। भूमि-सुधार व तकनीकी परिवर्तन दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। भूमि-सुधार तकनीकी परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि बनाते हैं तथा तकनीकी परिवर्तन कृषिगत विकास की दर को ऊँचा करने में सहायक होते हैं।

जून 1989 में केन्द्र ने भूमि-सुधारों के लिए 7 सूत्री योजना तैयार करके राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजी है। इसके सात सूत्र इस प्रकार हैं—(i) सरप्लस भूमि के आवंटन में 40% भूमि स्त्रियों के लिए सुरक्षित करना, (ii) भूमि के बेनामी व फर्जी सौदों की पहचान करना, (iii) ज़बानो, यतोपचारिक व बढाईदारों को न्याय दिलाना, (iv) वनवासियों को स्थायी अधिकार दिलाना, (v) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटित भूमि का सत्यापन (Verification) करना, (vi) कानूनी झगड़ों में ज़मीन सरप्लस भूमि के शीघ्र वितरण की व्यवस्था करना, तथा (vii) सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों को मकान देने की व्यवस्था करना।

सरकार विवादों में उलझी भूमि का मुक्त कराने के लिए कानूनों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। भूमि, मकान व पेटों के पट्टे स्त्रियों के लिए रिजर्व करने से भूमि की प्रदूषण-व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। आशा है इन नये प्रयासों का कार्यान्वित करने में पंचायती राज संस्थाएँ उचित भूमिका निभायेंगी।

प्रश्न

1. भारत में 1951 से अब तक लागू किये गये भूमि-सुधारों के कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। (Raj Ilyear, T.D.C. 1983)
2. भारत में भूमि-सुधार विफल हुए हैं, लेकिन इन्हें अधिकृत में सफल बनाया जाना चाहिए? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विवेचन कीजिए। (Raj Ilyear, T.D.C. 1980)
3. भारत में 1951 से अपनाये गये भूमि-सुधारों की समीक्षा कीजिए। (Raj Ilyear, T.D.C. 1988)
4. भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है? भारत में भूमि सुधार की प्रगति प्रस्तोप-जनक क्यों रही है? तर्कसहित समझाइये (Raj. Ilyr, T.D.C. 1989)

खाद्यान्नों का उत्पादन व खाद्य-नीति

(Food Output and Food Policy)

भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की निरन्तर आवश्यकता है क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ रही है और निर्धन जनता का उपभोग का स्तर ऊँचा करने के लिए भी अधिक मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की राष्ट्रीय स्वावलम्बन की दृष्टि से भी महत्व है। पहले 'राम के बदले अनाज' की योजना के द्वारा देश में रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme) (NREP) के अन्तर्गत भी खाद्यान्नों का उपयोग रोजगार बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे गाँवों में श्रमिकों को अनाज मिल जाता है तथा नहरें, सड़कें व अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने में मदद मिलती है।

भारत में खाद्य-समस्या की प्रकृति

भारत में खाद्य-समस्या के चार पहलू माने जाते हैं—मात्रात्मक (quantitative), गुणात्मक (qualitative), प्रशासनिक (administrative) और आर्थिक (economic)। इनमें से प्रत्येक पर नीचे प्रकाश डाला जाता है :

१. मात्रात्मक पहलू—इनका सम्बन्ध खाद्यान्नों की कुल माँग और कुल पूर्ति से होता है। भारत में विभाजन के बाद से निरन्तर खाद्यान्नों का अभाव रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए विदेशों से प्रतिवर्ष इनका आयात करना पड़ा है। इस रूप में खाद्य-समस्या भारत के लिए एक अल्पकालीन सकेत नहीं, बल्कि एक पुराने व दीर्घकालीन समस्या मानी गई है। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर ही माँग और पूर्ति में आवश्यक सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। यदि किसी वर्ष प्राकृतिक प्रकोप व मौसम की प्रतिकूलता के कारण उत्पादन कम हो जाता है तो खाद्यान्नों का अभाव बढ़ जाता है और आयात किये बिना काम नहीं चल सकता। 1966 में खाद्यान्नों का विशुद्ध आयात (net imports) एक करोड़ तीन लाख टन हुआ था।

बाद में आयातों की मात्रा घटी, लेकिन आयात बराबर जारी रहे। 1978 से 1980 की अवधि में आयातों के आयात ऋणात्मक (negative) रहे, अर्थात् आयातों की तुलना में निर्यात अधिक हुए, जिससे पता चलता है कि देश की बाह्य स्थिति पहले से बेहतर हुई। 1981 में पुनः आयातों का आयात धनात्मक (positive) हो गया (निर्यातों से आयात अधिक)। 1983 में आयातों के शुद्ध आयातों की मात्रा 40.7 लाख टन तथा 1984 में 23.7 लाख टन रही। ये आयात देश में अनाज का बफर स्टॉक बनाये रखने के लिए किये गये ताकि आयातों के अभाव की स्थिति का मुकाबला किया जा सके। 1985 से 1987 के वर्षों में पुनः शुद्ध आयात ऋणात्मक रहे। जिससे पता चलता है कि देश की बाह्य स्थिति में सुधार हुआ। 1988 में अभाव के कारण आयातों के शुद्ध आयात 18.7 लाख टन रहे।

भारत की बाह्य-स्थिति सुधरने से इसे आयातों की दृष्टि से आत्म-निर्भर कहा जाने लगा है। लेकिन अभी तक हमारे देश में "स्थायी किस्म की आत्म-निर्भरता" प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत से अब कुछ मात्रा में अनाज का निर्यात भी किया जाने लगा है। अतः आत्मनिर्भरता पहलू की दृष्टि से पहले की तुलना में स्थिति बेहतर प्रकट हुई है, लेकिन अविष्य में आमदनी व श्रमशक्ति के बढ़ने से आयातों की मांग बढ़ेगी जिससे कम उत्पादन के वर्षों में देश में आयातों की कमी महसूस हो सकती है। भारत को आयातों में सम्पूर्ण अवधि तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा तथा जनसंख्या की वृद्धि पर भी नियंत्रण करना होगा।

2. गुणात्मक पहलू—अधिकांश देशवासियों की अल्पव्युक्ति मोजन मिलता है। हमारे मोजन में दूध, फल, सब्जियाँ आदि स्वाभाविक पदार्थों का बहुत अभाव पाया जाता है। अतः लोगों की पर्याप्त मात्रा में पोषण-तत्व नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि मानव शक्ति की कार्यक्षमता कम होती है और उनका स्वस्थ कमजोर रहता है। अतः आत्म-निर्भरता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सर्व-मानवता का मनुष्य और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। अंतर्राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय में पौष्टिक-इकोनोमी के प्रमुख प्राध्यापक तथा 1987 के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मण्डल (International Economic Association) के प्रथम भारतीय प्रेसिडेंट डॉ. अमरलता सेन का कहना है कि भारत में आजीवन जनता का जीवन एक-दिल्ली-मात्र नियमित रूप से मूल्य व कुपोषण का शिकार रहता है। लोग भुज में मरने लगे हैं (क्योंकि सरकार अनाज से उनकी रक्षा करती है) लेकिन वे भुज प्रवास करने रहते हैं।

3. प्रभावित पहलू—इसका सम्बन्ध आयातों के विवरण-पक्ष से होता है, न कि उत्पादन-पक्ष से। अतः ऐसा भी हो सकता है कि आयातों का उत्पादन तो

बढ़ जाय, लेकिन वितरण-व्यवस्था के दोषपूर्ण होने से खाद्य-समस्या बनी रहे। ऐसी स्थिति में खाद्य-समस्या प्रशासनिक रूप धारण कर लेती है। सार्वजनिक वितरण की उचित व प्रभावपूर्ण व्यवस्था ही खाद्य समस्या के इस रूप का निराकरण कर सकती है। यदि सरकार की खाद्य-नीति अस्पष्ट, द्वितीय तथा अक्षयवादी होती है, तो खाद्य-समस्या और भी जटिल हो जाती है। भारत में पिछले वर्षों में खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गहरी में अधिक विनष्टित किया गया है। इसे अग्रिम में अधिक व्यापक व उपयोगी बनाने के लिए गांवों में भी विनष्टित करना होगा ताकि ग्रामवासियों को भी खाद्यान्नों की सस्ते दामों में अधिक नियमित की जा सके।

4 **ग्रामिण पहलू**—भारत में कई बार यह भी कहा जाता है कि हमारे अनाज को खरीदने के लिए लोगों के पास आवश्यक व्रण शक्ति का अभाव रहता है। अतः 'खाद्यान्नों के अभाव' (food-famine) व स्थान पर मुद्रा या व्रण-शक्ति का अभाव' (money famine) पाया जा सकता है। इस पहलू का सम्बन्ध आम जनता की गरीबी तथा खाद्यान्नों के ऊँचे भावों से होता है। अतः सर्वसाधारण की आय में वृद्धि करके एक खाद्यान्नों के भावों में समुचित कमी लाकर ही खाद्य-समस्या के इस रूप का उचित समाधान निकाला जा सकता है। प्रोफेसर रोम का कहना है कि भारत में प्रायः 'खाद्यान्नों में अल्प-निर्भरता' प्राप्त कर लेने की बात सुनने को मिलती है। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में बाजार-मांग व बाजार-पूर्ति में संतुलन स्थापित होने पर देश अल्प-निर्भर तो हो सकता है, फिर भी व्रण-शक्ति की कमी होने से बहुत से लोगों की 'अनाज की आवश्यकता' इसकी बाजार मांग में परिवर्तित नहीं हो पाती जिससे तथान्वित अल्प-निर्भरता की दशा में भी बाकी लोग भूत व कुपापण के शिकार बने रहते हैं। अतः लोगों की व्रणशक्ति बढ़ाकर खाद्य-समस्या के इस रूप का हल निकाला जा सकता है।

पञ्चवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्नों का उत्पादन

प्रथम तालिका में 1950-51 से 1987-88 की अवधि में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन की स्थिति दिखाई गई है।¹

1 The Economic Survey, 1988-89, p S-15 (1970-71 व बाद के भागों के लिए)

1988-89 में भी खाद्यान्नों का उत्पादन 17 करोड़ टन या अधिक रहने की आशा है।

इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूँ का अना बढ़ा है तथा मोटे अनाजों का घटा है एवं चावल व दालों के यथास्थिर रहे हैं।

इसी तरह उत्पादन की दृष्टि से भी विभिन्न खाद्यान्नों के अनुपात बदले हैं। चावल का अना कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में 19५0-५1 से 1986-87 के बीच 40% से बढ़कर 42% हो गया, जबकि गेहूँ का 13% से बढ़कर 12% हो गया एवं मोटे अनाजों (Coarse cereals) का 10% से घटकर 18% हो गया तथा दालों का 17% से घटकर 8% पर आ गया। इस प्रकार योजनाकाल में मोटे अनाजों व दालों का कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में अनुपात काफी घट गया है जिससे निम्न वर्ग की कठिनाइयाँ बढ़ गयी हैं।

1980-85 से 1985-86 की अवधि में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार बदली है। 1980-81 में चावल का उत्पादन 5.4 करोड़ टन से बढ़कर 1987-88 में 5.6 करोड़ टन, गेहूँ का 3.6 करोड़ टन से बढ़कर 4.5 करोड़ टन एवं दालों का 1.1 करोड़ टन पर स्थिर रहा है। इसी अवधि में मोटे अनाजों का उत्पादन 2.9 करोड़ टन से घटकर 2.1 करोड़ टन हो गया है जो एक चिन्ता का कारण है।¹

खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। प्रायः एक वर्ष उत्पादन बढ़ जाता है तो दूसरे वर्ष घट जाता है। अतः खाद्यान्नों का उत्पादन अस्थिर रहा है। सिचाई के साधनों का विकास करके यह अस्थिरता कम की जा सकती है।

खाद्यान्नों के आयात²

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से खाद्यान्नों का निरन्तर आयात किया गया है। वर्ष 1966 में इनके विमुक्त आयात एक करोड़ टन हुए जो अभूतपूर्व थे। उसके बाद आयातों में कमी आई और ये 1977 में घटकर बेवस्त। साल टन पर आ गये। 1978-80 की अवधि में अनाज के आयात से निर्यात अधिक हुए जिससे शुद्ध आयात ऋणात्मक (negative) रहे। 1981 से पुनः शुद्ध आयात धनात्मक (positive) हो गये (निर्यात से आयात अधिक)। पिछले कुछ वर्षों में आयात की स्थिति अग्र तालिका से स्पष्ट हो जाती है :

1. Economic Survey, 1988-89, p. S-15.

2. ibid, p. S.-23.

वर्ष	साधानों के विनिर्दिष्ट आयात (net imports) (लाख टन में)
1983	40.7
1984	23.7
1985	(-) 3.5
1986	(-) 0.6
1987	(-) 3.8
1988	18.7

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1985 से 1987 तक के तीन वर्षों में कुछ आयात अणुआत्मक रहे, लेकिन 1988 में अभूतपूर्व सूखे के कारण आयात फिर प्रारम्भ किये गये और इस वर्ष आयात की मात्रा लगभग 19 लाख टन रही है।

भूतकाल में भारत ने अमेरिका से पी. एन. 480 के अन्तर्गत काफी मात्रा में खाद्यान्नों व अन्य वस्तुओं का आयात किया था जिनके अ विकास भुगतान की व्यवस्था रुपये में की जाती रही है। पहले इस समझौते के अन्तर्गत भारत में काफी धनराशि अमेरिका के पक्ष में एकत्र हो गई थी। इन रुपये के उपयोग से भारतीय धर्म-संवस्था पर काफी प्रतिबल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। अमेरिका ने एक समझौते के अन्तर्गत 1973 में भारत को लगभग 1,664 करोड़ रुपये की राशि में-स्वल्प प्रदान कर दी थी, जिससे इस सम्बन्ध में अणु-भार काफी हल्का हो गया था। भारत से विदेशों को प्रायः चावल का निर्यात किया जाता है।

भारत में खाद्य-समस्या के कारण*

पिछले वर्षों से भारत की खाद्य-स्थिति में सुधार हुआ है और देश की खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर माना जाने लगा है। लेकिन भूकाल व सूखे के वर्षों में आयात पुन. करने होते हैं तथा मूल्य स्थिर रखने के लिए भी आयात किये गये हैं। लोगों के पास अन्न-शक्ति का अभाव रहने से उनकी प्रभावशाली मात्रा कम होती है। अतः खाद्य-

*भारत में वर्तमान समय में खाद्य-स्थिति में सुधार होने से इन कारणों को ऐतिहासिक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में भारत की खाद्य-स्थिति कैसी रहेगी? जन-संख्या के बढ़ने दबाव व लोगों के पास अन्न-शक्ति के अभाव की देखते हुए तथा लगातार सूखे वी दशाओं के कारण यह कहना सही नहीं जान पड़ता कि भारत ने खाद्य-समस्या स्थायी रूप से हल करली है।

समस्या को समाप्त नहीं माना जा सकता । ऐतिहासिक दृष्टि से इस समस्या के कारण नीचे दिये जाते हैं :—

1. जनसंख्या की वृद्धि—पहले बताया जा चुका है कि 1971-81 के दशक में भारत में जनसंख्या की वृद्धि-दर प्रतिवर्ष लगभग 2.2% रही । वैसे योजना-काल में खाद्यान्नों का उत्पादन भी 3 से 3.4% वार्षिक दर से बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने व देश में भ्रान्तियों के बढ़ने से खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ी है जिससे अकाल व सूखे के वर्षों में देश में खाद्यान्नों की कमी महसूस की जाती है । हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि खाद्य-समस्या का प्रमुख कारण मानी जा सकती है ।

2. देश का विभाजन—1947 में देश के विभाजन का भी हमारी खाद्य-स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । विभाजन के फलस्वरूप भारतीय संघ को अविभाजित भारत की 82 प्रतिशत जनसंख्या मिली, परन्तु वास्तविक सिंचित क्षेत्र का 69 प्रतिशत और प्रमुख खाद्यान्नों की पूर्ति का 75 प्रतिशत अंश ही मिल पाया था । इसके साथ ही बड़ी नस्या में विस्थापितों के भारत में आने के फलस्वरूप खाद्यान्नों की मांग काफी बढ़ गई थी ।

3 प्राकृतिक कारणों से फसलों की हानि—भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर करती है । जब कभी वर्षा बहुत कम या अधिक होती है या समय पर नहीं होती तो फसलें खराब हो जाती हैं और खाद्यान्नों की पैदावार काफी घट जाती है । वर्षा की अनिश्चितता के अनिश्चित प्रतिवर्ष आधी, तूफान व झोलों आदि से भी फसलों को नुकसान होता रहता है । इसी प्रकार टिड्डियाँ, जूहे आदि बड़ी मात्रा में फसलें नष्ट कर देते हैं । फसलों की बीमारियों से काफी नुकसान होता है । इन सब कारणों से खेती की उपज घट जाती है और खाद्यान्नों का सकट पैदा हो जाता है । 1965-66, 1966-67, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1979-80, 1982-83 एवं 1984-85 व 1987-88 के वर्ष कृषिगत उत्पादन की दृष्टि से खराब रहे और इन वर्षों में विशेषतया सूखे के कारण देश के अधिकांश भागों में फसलों की क्षति पहुँची तथा खाद्यान्नों का उत्पादन नीचा हुआ । 1987-88 में खाद्यान्नों का उत्पादन 13.8 करोड़ टन हुआ था ।

4 उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन—पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में अनेक कारणों से ज्वार, बाजरा, मक्का आदि घटिया अनाजों के स्थान पर गेहूँ, चावल आदि बढ़िया अनाजों की खपत बढ़ गई है । देहातों में खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ जाने से शहरों में खाद्य-स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इसके अतिरिक्त मोटे अण्डा घटिया अनाजों की पैदावार में थोड़ी कमी हुई है । 1980-81 में ज्वार, बाजरा व मक्का का उत्पादन 2.9 करोड़ टन हुआ था, जो 1987-88 में लगभग 2.1 करोड़ टन हो गया । इस प्रकार मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आयी है,

तथा साथ में अनाजों के उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन होने से खाद्य-समस्या अधिक जटिल हो गई है।

5. योजनाकाल में आय के बढ़ने से माग में वृद्धि—भारत में 1951 से आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की गई हैं जिनसे सांस्कृतिक क्षेत्र में विनियोगों के बढ़ने से लोगों की आयदनी बढ़ी है। निर्धन देश में आयदनी के बढ़ने से खाद्यान्नों का उपयोग तेजी से बढ़ता है। खाद्यान्नों के लिए माग की औसत आय लोच (income elasticity of demand for foodgrains) 0.4 से 0.5 के आस-पास होती है। सबसे निर्धन लोगों की खाद्यान्नों के लिए सीमांत आय-लोच 0.7 से 0.8 के समीप होता है। इसका अर्थ है कि निर्धन व्यक्ति की एक रुपया आय बढ़ने पर इनमें से 70 से 80 पैसे खाद्यान्नों पर व्यय किये जाते हैं। अतः आर्थिक विकास के प्रारम्भिक वर्षों में खाद्यान्नों की माग का तेजी से बढ़ना खाद्य-समस्या को उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि खाद्य-समस्या को हल करने के लिए उत्पादन में काफी वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है।

6. आयों की अमान्यता से होने वाली उपलब्धि एवं इन पर निर्भरता के कारण सम्भवतः आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने पर पर्याप्त रुचि से ध्यान नहीं दिया गया। यदि हमारा देश योजना के प्रारम्भ से ही पूरी शक्ति से खेद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में जुट जाता तो हम खाद्यान्नों में कमी के आत्म-निर्भर हो गये होते।

7. खाद्यान्नों के सप्लाइ की प्रवृत्ति—खाद्य-सकट का एक कारण उत्पादक, व्यापारी व उपभोक्ता सभी के द्वारा अनाज की सप्लाइ करने की प्रवृत्ति भी है। काली मुद्रा की सहायता से भी प्रायः व्यापारियों के द्वारा अनाज का सप्लाइ कर लिया जाता है जिससे खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार सट्टे के उद्देश्य के लिए अनाज का सप्लाइ किया जाता है जिससे कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाने से मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

8. एक प्रभावपूर्ण व दीर्घकालीन खाद्य-नीति का अभाव—भारत में खाद्य समस्या का एक कारण देश के लिए एक प्रभावपूर्ण, सुनिश्चित तथा दीर्घकालीन राष्ट्रीय खाद्य-नीति का अभाव भी माना जा सकता है। सरकार ने विछले वर्षों में अनाज खरीद कर अण्डर स्टॉक बनाने का कार्य किया है। 1973 में नेट के थोक व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित करने का कदम उठाया गया था जिसमें सफलता न मिलने से 1974 में खाद्य-नीति में कुछ परिवर्तन किये गये। बाद में 1975 में पुनः खाद्य-नीति बदली गई। अप्रैल, 1977 में जनता सरकार न खाद्य-नीति में परिवर्तन किये और खाद्यान्नों की अविवाय सेवी की व्यवस्था समाप्त कर दी। उन्ही नीति को 1978 व 1979 में जारी रखा गया। बाद के वर्षों में कांग्रेस (भाई) सरकार ने खाद्यान्नों के वगुनी मूल्यों में वृद्धि की है तथा पूर्व खाद्य-

नीति को ही जारी रखा है। इनका आगे चलकर वर्णन किया गया है यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि हम एक दीर्घकालीन सुनिश्चित व सुदृढ़ खाद्य-नीति का निर्माण करना चाहिए और उसे काफी प्रशासनिक कार्यबुशलता व बहाई से लागू करना चाहिए।

भारत में खाद्यन्नों की कीमतें

भारत में भूतकाल में खाद्यान्नों की क्षेत्रीय व्यवस्था (zonal system) व वनस्वरूप खाद्यान्नों के भावों में क्षेत्रीय अन्तर (regional variations) पाये गये हैं। क्षेत्रीय व्यवस्था में खाद्यान्नों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच स्वतन्त्रतापूर्वक आना-जाना नहीं हो पाता था। लेकिन एक क्षेत्र व अन्तर एक भाग से दूसरे भाग में खाद्यान्नों की गतिशीलता हो सकती थी। हमारे देश में विभिन्न मौसमों में भी खाद्यान्नों के भावों में अन्तर पाया जाता है। साधारणतया पसल के तुरन्त बाद अनाज के भावों में गिरावट आती है बाद में धीरे-धीरे भाव बढ़ते जाते हैं। अनाज के धोक भावों व सुदरा भावों में भी अन्तर होता है। यहाँ पर हम खाद्यान्नों के धोक मूल्यों के सूचकांकों के आधार पर इनके भावों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनाज के मूल्यों में काफी कमी हुई थी। मार्च 1951 के अन्त में अनाज के धोक मूल्यों का सूचकांक 100 था (1952-53 = 100) जो मार्च, 1955 के अन्त में 70 हो गया था। सरकार को खाद्यान्नों के गिरते हुए भावों को रोकने के लिए निश्चित मूल्यों पर इनको खरीदने की व्यवस्था करनी पड़ी। जुलाई 1955 में पुनः मूल्य बढ़ने लगे। मार्च, 1956 के अन्त में अनाज के भावों का सूचकांक बढ़कर 86 पर पहुँच गया था। बाद में द्वितीय योजना की अवधि में अनाज व दालों के भावों में निरन्तर वृद्धि होती गयी। मार्च 1961 के अन्त तक अनाज के धोक मूल्यों का सूचकांक 100 पर आ गया था। इस प्रकार प्रथम योजना की अवधि में अनाज के भाव घटे और द्वितीय योजना में बढ़े। तृतीय योजना की अवधि में भी अनाज के भावों में तीव्र गति से वृद्धि हुई और वे इन्फ्लेशन से भी अधिक हो गये। अनाज के भावों की यह वृद्धि 1966-67 में भी जारी रही। बाद में धोक मूल्यों के सूचकांकों का आधार वर्ष 1952-53 से बदल कर 1961-62 कर दिया गया। 1961-62 = 100 मानने पर खाद्यान्नों के धोक भावों का सूचकांक (सप्ताहों का औसत लेने पर) 1968-69 में 201 पर आ गया। बाद के वर्षों में यह वृद्धि जारी रही। 1974-75 में खाद्यान्नों के भावों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिससे सूचकांक 401 पर जा पहुँचा। यदि दालों का सूचकांक देखें तो यह 1974-75 में सप्ताहों का औसत लेने पर 507 रहा। अब धोक मूल्यों के सूचकांक का आधार वर्ष 1970-71 कर दिया गया है। 1987-88 में सप्ताहों का औसत लेने पर खाद्यान्नों का धोक मूल्य सूचकांक 332 तथा दालों का 494 हो गया था।

दिसम्बर 1988 में खाद्यान्नों का मूल्य-सूचकांक 404 तथा दालों का 715 रहा। इस प्रकार 1970-71 के बाद दालों के भावों में काफी वृद्धि हुई है।

पहले बतलाया जा चुका है कि अनाज के भावों के बढ़ने का प्रमुख कारण माँग का पूर्ति से अधिक होना है। योजना-काल में सार्वजनिक व निजी विनियोगों में वृद्धि हुई है जिससे खाद्यान्नों की प्रभावपूर्ण माँग भी बढ़ी है। अब हम सरकार की खाद्य-नीति का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

सरकार की खाद्य-नीति (Food Policy of the Government)

1 उत्पादन में वृद्धि—भारत में खाद्य-समस्या एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है। सरकार ने खाद्य-समस्या का समाधान करने के लिए कई प्रकार के उपाय काम में लिये हैं। इसने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं इन उपायों के अन्तर्गत सिंचाई का विस्तार, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग, माल की सुविधा, वसूली मूल्यों का निर्धारण, आदि कार्यक्रम आते हैं। इनमें कुछ का वर्णन पहले किया जा चुका है। सरकार को यहाँ का उत्पादन बढ़ाने में विशेष रूप से सफलता मिली है जो 1970-71 में 2.4 करोड़ टन से बढ़कर 1987-88 में 4.5 करोड़ टन हो गया है। चावल का उत्पादन 1970-71 में 4.2 करोड़ टन से बढ़कर 1987-88 में 5.6 करोड़ टन हो गया है, हालांकि 1985-86 में यह 6.4 करोड़ टन हो गया था।

2 आयात की व्यवस्था—देश में खाद्यान्नों का अभाव दूर करने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों के आयात की व्यवस्था भी की है, ताकि आन्तरिक सप्लाई बढ़ाई जा सके। इस पर विस्तार से पहले प्रकाश डाला जा चुका है। आन्तरिक देश में पैदावर अन्धरी होने पर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए एक् बफर स्टॉक बनाये रखने के लिए खाद्यान्नों का थोड़ा-बहुत आयात जारी रखा जाता है। उदाहरण के लिए 1981 से पुनः अनाज का विशुद्ध आयात वहाँ एक् 1983 में यह 40.7 लाख टन रहा। 1984 में यह घट कर 21.7 लाख टन के स्तर पर आ गया। 1985 से 1987 तक शुद्ध आयातों के क्रमात्मक रहने के बाद 1988 में पुनः आयात 18.7 लाख टन किये गए।

3 सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली व सार्वजनिक वितरण—पिछले वर्षों में सरकार ने खाद्यान्नों के वसूली मूल्य (Procurement Prices) निर्धारित किये हैं और निर्धारित भावों पर अनाज खरीद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के माध्यम से ग्राम जनता में अनाज के उचित वितरण का प्रयास किया है। 1988 में खाद्यान्नों की सरकारी खरीद 1.4 करोड़ टन रही तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1.8 करोड़ टन खाद्यान्न ग्राम जनता को उपलब्ध किया गया।

खाद्यान्नों के भावों को स्थिर रखने की दृष्टि से बफर स्टॉक का महत्व

सरकार प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के बसूली-मूल्य घोषित करती है और उन पर अनाज खरीदने की व्यवस्था करती है। सरकार अनाज का बफर स्टॉक बनाये रखना चाहती है। बफर स्टॉक बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य अनाज की कीमतों में स्थिरता लाना होता है। यदि अनाज के मूल्य बढ़ते हैं तो सरकार बफर स्टॉक में से निर्धारित भावों पर अनाज बेचने की व्यवस्था करती है जिससे खुले बाजार में कीमतें स्थिर हो जाती हैं। यदि कीमतें गिरने लगे तो बफर स्टॉक का उद्देश्य उल्टा हो जाता है। सरकार निर्धारित भावों पर अनाज खरीद कर बफर स्टॉक बढ़ा लेती है। इस प्रकार सरकार बफर स्टॉक की क्रियाओं के माध्यम से उत्पादक व उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करती है।

सरकार ने जनवरी, 1962 में भारतीय खाद्य-निगम (Food Corporation of India), (FCI) की स्थापना की थी जिसको अनाज की खरीद, सग्रह, परिवहन व वितरण का काम सौंपा गया है। सरकार अनाज को खरीद कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं को बेचने की व्यवस्था भी करती है। अभाव के वर्षों में सार्वजनिक वितरण-प्रणाली पर भार बढ़ जाता है। सार्वजनिक वितरण-प्रणाली तभी ठीक से चल सकती है जबकि सरकार के पास अनाज के पर्याप्त मात्रा में भण्डार विद्यमान हो। इसके लिए सरकार को एक तरफ देश में अनाज को खरीदने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ अनाज के आयात का भी इन्तजाम करना पड़ता है। यदि सरकार को आन्तरिक खरीद में पर्याप्त मात्रा में सफलता न मिले तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

निम्न तालिका में सरकार के द्वारा की गई खाद्यान्नों की खरीद व सार्वजनिक वितरण की प्रगति का उल्लेख किया गया है।¹

वर्ष	खाद्यान्नों की शुद्ध उपलब्धि (मिलियन टनो में)	खरीद (procurement) (मिलियन टनो में)	सार्वजनिक वितरण (मिलियन टनो में)	सार्वजनिक वितरण की मात्रा (कॉलम 4) खाद्यान्नों की शुद्ध उपलब्धि (कॉलम 2) के प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1966	73.5	4.0	14.1	19.2
1987	134.6	15.7	18.4	13.8
1988	128.4	14.1	18.3	14.3

उपर्युक्त तालिका के कॉलम (3) में खाद्यान्नों की सरकारी बसूली/खरीद के प्रांकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। 1988 की खाद्यान्नों की बसूली 14 मिलियन टन रही, 1988 में सार्वजनिक वितरण की मात्रा खाद्यान्नों की शुद्ध उपलब्धि का 14.3% रही जबकि 1966 में यह 19.2% तक पहुँच गयी थी। अतः भविष्य में सार्वजनिक वितरण के अर्थ को बढ़ाना होगा।

4 खाद्यान्नों की क्षेत्रीय व्यवस्था—भारत में पहले के वर्षों में खाद्यान्नों के लिए क्षेत्रीय व्यवस्था का उपयोग किया गया था जिसके अन्तर्गत एक क्षेत्र में तो अनाज के अनाज होने की छूट होती थी, लेकिन निर्धारित क्षेत्र से बाहर अनाज को भेजने की स्वतन्त्रता नहीं होती थी। सरकार ने क्षेत्रीय व्यवस्था के समर्थन में यह कह दिया था कि इससे अनाज की बसूली में सहूलियत रहती है। पहले यह सोचा जाना था कि क्षेत्रीय व्यवस्था के टूट जाने से सरकारी खरीद का काम कठिन हो जायगा। लेकिन समय-समय पर इस व्यवस्था में ढील दी गई है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनाज की क्षेत्रीय व्यवस्था को सकीर्ण व अनुचित बताया है। अप्रैल 1977 में सरकार ने गेहूँ के क्षेत्र (Wheat-zones) समाप्त कर दिये और इसके लिए सम्पूर्ण देश को एक क्षेत्र ही मान लिया था। अनाजकल गेहूँ के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर रोक-टोक नहीं है। यही बजह है कि तमिलनाडु, केरल व प. बंगाल जैसे घाट के राज्य पञ्जाब, हरियाणा व मध्य राज्यों के खुले बाजारों में अनाज खरीदकर अपने नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति करने लगे हैं।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य-नीति में प्रमुख प्रश्न निम्नांकित होते हैं—(1) सरकार खाद्यान्नों की बसूली के भाव क्या रखे ? (2) किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद कर सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के संचालन को सुदृढ़ कर सके ? (3) किस प्रकार उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके ? दूसरे शब्दों में, उत्पादकों को प्रेरणादायक मूल्य मिलें ताकि व उत्पादन बढ़ायें एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज मिल सके ताकि उनके उपयोग का स्तर बच सके।

5 खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मूल्य नीति (Price policy regarding food-grains)—खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मूल्य-नीति खाद्य नीति का एक आवश्यक घटक होती है। वैसे कुछ अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि भारत में कृषिगत पैदावार पर कृषिगत मूल्यों में किये गये परिवर्तनों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी कृषक की आय में होने वाले परिवर्तन पैदावार की मात्रा को कुछ सीमा तक अवश्य प्रभावित करते हैं।

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price), सरकारी खरीद/बसूली मूल्य (Procurement prices) व सार्वजनिक सस्थाओं के लिए विन्नी

मूल्य या निकासी मूल्य (issue prices) निर्धारित करके खाद्यान्नों के मूल्यों को प्रभावित किया है। इनकी आवश्यकता व निर्धारण विधि नीचे दी जाती है :

(घ) न्यूनतम/समर्थन मूल्य (minimum/support prices)—इन्हे प्रायः समर्थन-मूल्य कहा जाता है। नियमानुसार ये फसल बोने से पूर्व घोषित किये जाते हैं और इन पर सरकार कृषको द्वारा प्रस्तुत समस्त खाद्यान्न खरीदने के लिए उद्यत रहती है। इससे कृषको में अनिश्चितता दूर होती है और वे उचित समय पर उत्पादन सम्बन्धी निर्णय ले सकते हैं।

इनके निर्धारण पर औसत लागत तथा प्रतिफल की उचित दर का प्रभाव पड़ता है। औसत लागत 'कुशल कृषक' (efficient farmer) की न होकर 'रेण्डम' आधार पर चुने गये प्रतिनिधि कृषक' (representative farmer) की होनी चाहिए। यह 3 से 5 वर्षों की चल औसत लागत (moving average cost) के बराबर होनी चाहिए, ताकि इनके निर्धारण में वार्षिक उतार-चढ़ावों का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जा सके।

न्यूनतम मूल्य वसूली-मूल्यों से नीचे रखे जाते हैं। लेकिन बहुत नीचे होने पर ये अवास्तविक हो जाते हैं। अभाव के वर्षों में बाजार-भाव ऊँचे होने से ये निरर्थक व निष्क्रिय हो जाते हैं। उत्तम फसलों के वर्षों में ये उपयोगी हो सकते हैं। भारत में 1977 से वसूली-मूल्यों को ही न्यूनतम मूल्यों में बदल दिया गया है। राजकल सरकार विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के लिए वसूली/खरीद मूल्य घोषित करती है जिन पर कृषक द्वारा बाजार में प्रस्तुत किये जाने वाले माल को खरीदा जाता है। ये ही न्यूनतम समर्थन-मूल्यों का काम करते हैं।

(आ) वसूली-मूल्य (Procurement Prices)—ये खेती मूल्य भी कहलाते हैं। सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करने के लिए वसूली-मूल्यों पर व्यापारियों या किसानों से अनाज खरीदने की व्यवस्था कर सकती है। वसूली-मूल्य बाजार मूल्यों से नीचे होते हैं। इनके निर्धारण पर निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है (i) फसल की पैदावार के अनुमान, (ii) बाजार-मूल्य की प्रवृत्ति, (iii) वसूली की मात्रा का अनुमान, (iv) अन्य सम्बन्धित फसलों के मूल्य, (v) कृषिगत इन्पुटों के भाव (input prices)। ये मूल्य फसल कटने के समय घोषित किये जाते हैं और प्रायः साथ में वसूली की मात्रा के साथ भी घोषित किये जाते हैं। राजकल कृषक पारिवारिक श्रम की लागत, जोखिम व परिवहन-लागत में वृद्धि के कारण ऊँचे वसूली मूल्यों के लिए आन्दोलन करने लगे हैं। इनकी मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ऊँचे वसूली मूल्यों से मुद्रास्फीति की भाग भटक सकती है। लेकिन कृषको को लागत-वृद्धि के लिए उचित मूल्य-वृद्धि की गारन्टी देनी आवश्यक होती है।

(इ) निकासी मूल्य (Issue Prices)—ये वे मूल्य होते हैं जिन पर भारतीय खाद्य-निगम राज्य सरकारों की सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। ये छाटा मूल्य से थोड़े ऊँचे लिए जाते हैं। ये वसूली मूल्यों से ऊँचे व साधारण बाजार मूल्यों से नीचे होते हैं। भारत में निकासी मूल्य नीचे रखने पड़ते हैं जिससे खाद्यान्नों की विनी पर आर्थिक सहायता के रूप में करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ती है। 1989-90 के केन्द्रीय बजट में खाद्यान्नों की सन्निदी के लिए 2200 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है। स्मरण रहे कि वसूली मूल्य ऊँचा करने तथा निकासी मूल्य यथास्थिर रखने का अर्थ होना है खाद्यान्नों पर मन्निदी की राशि में वृद्धि करना। एक अनुमान के अनुसार भारत में गेहूँ के वसूली मूल्य 152 रु प्रति क्विन्टल रखने पर इसकी प्रतिष्ठित लागत लगभग 210 रु. प्रति क्विन्टल आती है, क्योंकि परिवहन व्यय, बोरी में भरने की लागत व अन्य कई प्रकार के चार्ज होते हैं। ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों की सन्निदी की राशि का घटना स्वाभाविक है।

गेहूँ के वितरण व वसूली मूल्यों के सम्बन्ध में सरकारी नीति

अप्रैल 1973 में गेहूँ के थोक व्यापार को सरकारी नियन्त्रण में लेने की नीति घोषित की गयी थी। इसका उद्देश्य थोक व्यापारियों द्वारा मध्यम वर्ग के शोषण को समाप्त करना व विनी की अधिक कार्यकुशल प्रणाली को विकसित करना था। लेकिन किसानों व व्यापारियों के विरोध के कारण यह नीति सफल नहीं हो सकी। बाजार में आने वाले गेहूँ की मात्रा कम हो गयी जिससे खाद्य स्थिति अधिक जटिल बन गयी थी। सरकार के द्वारा गेहूँ की खरीद लक्ष्य से काफी नीची रही। आयरनक तैयारी के अभाव में सरकार की गेहूँ के थोक व्यापार के समाजीकरण की नीति पूर्णतया विफल रही थी।

अप्रैल 1974 में सरकार ने गेहूँ के वसूली-मूल्य 76 रु से बढ़ाकर 105 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिए जो पिछले वर्ष से 38% अधिक थे। सरकार ने व्यापारियों पर लब्धी की व्यवस्था लागू कर दी तथा उन्हें अपनी खरीद का 50% अन्न विधार्तित नाबों पर सरकार को बेचने के लिए कहा गया। इस नीति के अनुसार भी सरकार अपने वसूली के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

मार्च 1975 में उत्पादकों से लब्धी लेन की नीति अपनायी गयी। वसूली-मूल्य 105 रुपये क्विन्टल ही जारी रखे गये। सरकार ने इन भावों पर नियमित बाजारों में अनाज खरीदने की नीति अपनाई। 1976 में वही नीति जारी रखी गई। सरकार की वसूली में काफी सफलता मिली।

अप्रैल 1977 में जनता सरकार ने गेहूँ के वसूली-मूल्य 110 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिये और वसूली मूल्य समर्थन-मूल्यों में बदल दिये। उत्पादकों व व्यापार-

रियों से लेवी सेना समाप्त करके सरकार ने 110 रुपये प्रति बिबटल पर सीधे किसानों से गेहूँ खरीदना चालू कर दिया। गेहूँ की क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। बाद में प्रति वर्ष गेहूँ के वसूली मूल्यों में वृद्धि की गयी है। 1990-91 की त्रित्री-मौसम के लिए गेहूँ के वसूली भाव 200 रु प्रति बिबटल रमे गये हैं जो पिछले वर्ष से 17 रुपये प्रति बिबटल अधिक है। ये मूल्य कृषि-मूल्य आयोग (अथवा कृषि लागत व मूल्य आयोग) द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

सरकार ने अन्य अनाजों के भी वसूली/समर्थन-मूल्य घोषित किये हैं, ताकि कृषकों को प्रेरणादायक मूल्यों की गारण्टी मिल सके। इस प्रकार सरकार उत्पादक व उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित खाद्य-नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन कर रही है। इस नीति के संचालन के लिए सरकार को खाद्यान्नों के लिए भारी मात्रा में आर्थिक सहायता (food subsidy) भी देनी पड़ती है।

हमने देखा कि 1977 से 1989 तक की नीतियों में न्यूनतम समर्थन/वसूली मूल्यों का महत्व काफी बढ़ गया है। सरकार ने जी, चना, दालों, सरसों, मूगफली, सनपलीवर बीज, सोयाबीन, कपास, गन्ना आदि के लिए भी समर्थन-मूल्य तालू किये हैं। यह नीति खाद्यान्नों के उत्तम वर्ष के लिए तो उपयुक्त मानी जा सकती है, लेकिन इसमें स्वतन्त्र व्यापार की ओर अधिक भुकाव प्रतीत होता है। यह खाद्यान्नों व अभाव में वर्ष में अनुपयुक्त व बंठिनाई उत्पन्न करने वाली सिद्ध हो सकती है। अतः भारत में आज भी एक दीर्घकालीन व अधिक स्थायी खाद्य-नीति की आवश्यकता बनी हुई है जिसमें खाद्यान्नों की वसूली, मगह, मूल्य व सार्वजनिक वितरण आदि में आवश्यक समन्वय या तानमेन बँठाया जा सके और जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों के हितों की समान रूप से रक्षा कर सके। भारत में एक देशव्यापी खाद्यान्नों की वितरण व्यवस्था के विकास की नितांत आवश्यकता है।

भारत की खाद्य-समस्या की हल करने के लिए सुझाव अथवा

भारत के लिए एक उचित खाद्य-नीति क्या होनी चाहिए ?

भारत में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्नों की माँग में तेजी से वृद्धि हो रही है। योजनाओं में सार्वजनिक व निजी विनियोगों के बढ़ने से खाद्यान्नों के लिए प्रभावपूर्ण माँग का बढ़ना स्वाभाविक है। सरकार ने खाद्य समस्या का हल करने के कई प्रयत्न किये हैं, लेकिन उसको खाद्य-समस्या के सभी पहलुओं का उचित हल निजालने में अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है। खाद्य-समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. आधुनिक व गहन खेती की आवश्यकता—भारत में नई भूमि पर जिम्ना खेती की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं। अतः प्रचलित कृषि भूमि पर गहन खेती के उपाय अपनाने पर प्रति हैक्टेयर उपज में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए मुख्य

हुए बीजों, उत्तम खाद और रासायनिक उर्वरकों, उत्तम हल तथा अन्य मशीनों और मनी के मुद्दे हुए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई के विस्तार द्वारा जिन क्षेत्रों पर एक फसल उगायी जाती है उन पर दो या अधिक फसलें उगाई जानी चाहिए। इस दिशा में जितना भी प्रयत्न किया जा सके उतना ही उत्तम रहेगा। भारत की जल और मिट्टी के सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना बाकी है। खानानों में स्थानीय आत्मा-निर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। योजनाकाल में चावल, गेहूँ, प्याज, बाजरा व मक्का आदि में प्रति हेक्टेयर पंदावार बढ़ो है। 1955-56 में चावल की प्रति हेक्टेयर पंदावार 874 किलोग्राम थी, जो 1987-88 में 1473 किलोग्राम हो गयी है एवं गेहूँ की 708 किलोग्राम से बढ़कर 1995 किलोग्राम हो गयी है। 1985-86 में यह और भी अधिक रही थी क्योंकि 1987-88 एक अनुसूचित क्षेत्रों का वर्ष रहा था, इसलिए उसमें उपज नीची रही थी। कृषि की उन्नत विधियों को अपनाकर प्रति हेक्टेयर उपज और बढ़ायी जा सकती है।

2 सूखी खेती के विस्तार की आवश्यकता (Need for Dryland Farming)—

भारत में वर्षा पर आश्रित कृषि क्षेत्रों से लगभग 42% खाद्यान्न प्राप्त होते हैं।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों से कुल कृषित क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग में सिंचाई की जाती है और शेष 67% क्षेत्र वर्षा पर आश्रित रहता है। लगभग समस्त माट प्रजाति व दालें, अधिकांश कपास व तिलहन वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में उत्पन्न किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन में काफी उत्पाद-बढ़ाव आते रहते हैं, जिससे कृषिगत अर्थव्यवस्था अस्थिर बनी रहती है।

वर्षा पर आश्रित खेती वाले क्षेत्रों में सूखी खेती की विधियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध नमी की रक्षा करने की आवश्यकता है। पानी की ठालावों व बंधा आदि में सग्रह करके रखा चाहिए ताकि वह पूरक सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखी नती की विधियों को अपनाकर स्तरीय की कमलों को सूखे के प्रभाव से बचाया जा सकता है, सब्जियों की फसलों के लिए बोने से पूर्व सिंचाई की जा सकती है, दर में पक कर तैयार होन वाली फसल जैसे जल चना, अण्डी (castor) आदि के लान व दिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जल की सुरक्षा के आधार पर फसल उगाने की तकनीक (Water harvesting technology) का उपयोग करके खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सूखी नती में मृत्ति व नमी से प्रबन्ध पर जोर दिया जाता है।

तब उपभोक्ता भी आवश्यकता से अधिक अनाज संग्रह करने लगते हैं जिससे भाव बहुत ऊँचे हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए अशोक मेहता समिति ने मूल्यों के स्थिरीकरण का सुझाव दिया था। समिति ने राज्य द्वारा अनाज का शोक व्यापार अपना हाथ में लेने और सस्ते अनाज की दुकानों, सहकारी समितियों व नियोजितों के संगठनों द्वारा अनाज के वितरण की सिफारिश की थी। ग्राजकल अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित भावों पर ग्राम जनता को अनाज उपलब्ध किया जाता है। भारतीय राज्य-निगम इस सम्बन्ध में काफी सक्रिय रूप से काम करता रहा है। सरकार को बफर स्टॉक की नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।

8 उपभोग में सुधार—एक औसत भारतवासी के दैनिक भोजन में अनाज की प्रधानता होती है। अनाज के स्थान पर केले, शकरकंद व आलू आदि अधिक उपज देने वाली फसलों का उपभोग बढ़ाया जाना चाहिए तथा फल, सब्जी, अण्डे, मांस-मछली आदि पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन बढ़ा कर तथा इनकी कीमतें नीची रख कर सर्वसाधारण द्वारा इनके उपभोग में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि कम अनाज से काम चलाया जा सके और ग्राम नागरिक की दैनिक खुराक की क्वालिटी में भी सुधार हो सके।

9 जनसंख्या का नियन्त्रण—खाद्यान्नों की समस्या का स्थायी हल करने के लिए वृद्धिगत उपज बढ़ाने, फसलों की रक्षा तथा उपभोग में सुधार करने के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन प्रान्दोलन द्वारा जनसंख्या की वृद्धि की रफ्तार को भी कम किया जाना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण स्थापित बिना खाद्यान्नों में स्थायी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। भारत में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि-दर को 2.1% से घटाकर 1.8% या इससे भी कम पर लाने का प्रयास तेज किया जाना चाहिए।

10. छोटे कृषकों और कर्षककारों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण बदलना होगा—जिसमें इन्हें सात की अधिक सुविधाएँ मिल सकें और ये उत्पादन बढ़ाने में अपना अधिक सहयोग दे सकें। इसके लिए सातवी योजना के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development programme) (IRDP) को कामयाब बनाया जाना चाहिए।

11 खाद्यान्नों के लिए आर्थिक सहायता (Food subsidy) कम करने की आवश्यकता—पिछले वर्षों में खाद्यान्नों की वित्तीय पर आर्थिक सहायता काफी बढ़ गयी है। 1989-90 के केन्द्रीय बजट में खाद्यान्नों के लिए सब्सिडी की राशि 2200 करोड़ रु० रखी गयी है। यदि सरकार खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में वृद्धि करती है और निकासी मूल्य (issue prices) स्थिर रखती है तो खाद्य-सब्सिडी का बढ़ना स्वाभाविक है। खाद्यान्नों के संग्रह-व्यय, वितरण-व्यय आदि में

कमी करके आर्थिक महामना कम की जानी चाहिए। खाद्य-प्रणामन को अधिक कार्य-कुशल बनाये जाने की भी आवश्यकता है। इससे जनता पर कर-भार कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य-सन्निधि कम करने के लिए विकासोन्मुख बढाने होते हैं जिसमें निर्यात-वर्ग पर आर्थिक भार पड़ना है। अतः भारत में खाद्य-सन्निधि की रक्षा को घटाना ध्यान नहीं है। पिछले वर्षों के अनुभव के अनुसार यह निरन्तर बननी जारी रही है।

12 खाद्यान्नों के सम्बन्ध में उचित मूल्य-नीति की आवश्यकता—रिजल्ट वर्षों में खाद्यान्नों की मूल्य-नीति के प्रश्न पर काफी विवाद हुआ है। सरकार ने उत्पादकों को प्रेरणा देने के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता स्वीकार की है। खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में वृद्धि की गयी है। इसका कारण यह बताया गया है कि उर्वरक, डीजल, लेन व अन्य कृषिगत साधनों के भावों में वृद्धि हुई है। कृषिगत वर्ष 1990-91 के लिए गेहूँ के वसूली-मूल्य (जो समर्थन-मूल्य भी हैं) 200 रु प्रति क्विंटल रख गये हैं जो पिछले वर्ष से 17 रु प्रति क्विंटल अधिक हैं। इस प्रकार अनाज के वर्षों में अनाज की वसूली व वसूली मूल्य का महत्व हाथा है, ता आर्थिक के वर्षों में समर्थन मूल्यों का अधिक महत्व हाथा है। कृषि-साग्न व मूल्य-आयोग अनाज के मूल्य-निर्धारण का कार्य काफी दक्षता से कर रहा है। सरकार को इनकी सलाह पर अधिक ध्यान देना चाहिए और मूल्य-निर्धारण के प्रश्न की राजनीति से दूर रहना चाहिए। यदि घनी किसानों के बहुत पर वसूली-मूल्य बढाय जाते रहें, तो मुद्रास्फीति को बढावा मिलेगा। इसलिए समस्त स्थिति पर आर्थिक दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। इसका ही उचित माता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन बढाने की प्रेरणा पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

13 अधिक स्थिर व अपेक्षाकृत अधिक स्थायी व दीर्घकालीन खाद्य-नीति की आवश्यकता—योजना आयोग के पूर्व सदस्य तथा भारत के नुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रा बी एन मिन्हास का मत है कि “एक स्थिर खाद्य-नीति के अभाव में खाद्यान्नों के उत्पादन के क्षेत्र में हमारी कमियाँ और भी तीव्र हो जाती हैं। हमारी खाद्य नीति काफी अस्थिर भी रही है। एक वर्ष खेते बाजार में खरीद दूसरे वर्ष एकाधिकारी खरीद तीसरे वर्ष व्यापारियों व मितर्स पर लेवी और चौथे वर्ष में इनमें से कुछ का मिश्रण तथा पाचवें वर्ष में पुनः इनमें से किसी भी एक पर वास्तव में जाने की स्थिति आती है। इस प्रकार विद्युती इन बड़ी में एक स्थायी व स्थिर खाद्य-नीति की कमी ने हमें बहुत सख्त पहुँचायी है। इसी के फलस्वरूप हमें खाद्यान्नों के आदान की शरारत लेनी पड़ी है जिसमें दीर्घकाल तक रियायती शर्तों पर भी एत 480 के आदानों के अन्तर्गत आवश्यक के व्यवसायिक आयात भी शामिल हैं।”

भारत जैसे विशाल देश के लिए जहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन काफी अस्थिर रहता है, वहाँ एक सुदृढ़ व स्थायी किस्म की खाद्य-नीति की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। सरकार को खाद्यान्नों की खरीद, संग्रह व वितरण को एक ऐसी व्यवस्था प्रदाननी चाहिए जो अभाव व अधिव्यय दोनों प्रकार के दोषों की कठिनाइयों को दूर करके उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों की मली-मंति रक्षा कर सके। इसके लिए प्रो. मिन्हास द्वारा बतलायी गई कमी को दूर करके एक सुदृढ़ व दीर्घकालीन खाद्य-नीति विकसित की जानी चाहिए।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य व नीति¹ —

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1989-90 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 17.8 करोड़ टन से 18.3 करोड़ टन के बीच रखा गया है। मोटे तौर पर यह 18 करोड़ टन माना जा सकता है। इस प्रकार खाद्यान्नों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर का लक्ष्य $3\frac{1}{2}\%$ से 4% तक रखा गया है। राज्य सरकारें इन लक्ष्यों को जिलावार व फसलवार निर्धारित करेंगी ताकि उत्पादन व उत्पादकता को अधिकतम किया जा सके।

खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाते हैं :—

फसल	(करोड़ टन में)	
	1984-85 का अनुमानित आधार-स्तर	1989-90 का लक्ष्य
(1) चावल	6.0	7.4
(2) गेहूँ	4.5	5.6
(3) मोटे अनाज (जौ, मक्का व बाजरा)	3.2	3.4
(4) दालें	1.3	1.6
कुल	15.0	18.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना में चावल व दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष रूप से बल दिया जायगा। चावल के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 4 से $4\frac{1}{2}\%$ रखा गया है।

1989-90 में 18 करोड़ टन के खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य में कुछ राज्यों के अंश इस प्रकार रखे गये हैं।

1	उत्तर प्रदेश	3 63
2	पंजाब	1 70
3	मध्य प्रदेश	1 55
4	झारख प्रदेश	1 30
5	बिहार	1 30
6	महाराष्ट्र	1 25
7	राजस्थान	1 00
8	तमिलनाडु	1 00
9	पश्चिमी बंगाल	1 00
		13 73

इस प्रकार खाद्यान्नों के उत्पादन का लगभग 3/4 अंश इन नौ राज्यों से प्राप्त होने की आशा है। देश के पूर्वी भाग में चावल का उत्पादन बढ़ाया जायगा। लगभग 20% ब्लॉक (blocks) में चावल का उत्पादन बढ़ाने का एक विशेष कार्यक्रम चलाया जायगा।

वासों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीति का उपयोग किया जायगा

(i) सिंचित क्षेत्रों में दालों का श्रीगणेश (ii) चावल की परती भूमि पर मूंग व उड़द की जल्दी पक कर तैयार होने वाली फसलों को उगाना, (iii) अन्य फसलों के साथ धरहर, मूंग व उड़द की दालों की उपजाऊ, (iv) सुधरे हुए बीजों का उपयोग करना (v) पौध संरक्षण के उपाय अपनाना (vi) उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना (vii) फसल के बाद की टेक्नोलॉजी में सुधार करना (viii) प्रेरणादायक मूल्य देना तथा (ix) बिजली की व्यवस्था में सुधार करना। सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम संचालन करेगी।

सातवीं योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें इन लक्ष्यों को जिलावार व फसलवार तथा सिंचित व असिंचित क्षेत्रवार विभक्त करें एवं उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर ताल मेल स्थापित कर। तभी सातवीं योजना की अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर 18 करोड़ टन हो सकेगा। 1988-89 में अनुसूक्त सीमा में करण उत्पादन के 14 करोड़ टन या अधिक रहने की आशा है। अतः सातवीं योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जाने की आशा है।

प्रश्न

1. भारत में खाद्य समस्या के विभिन्न पक्षों की विवेचना कीजिये। इसको हल करने के लिए क्या किया गया है ?
(Raj. Hyr. T. D. C., 1985)
 2. भारत में हाल के वर्षों में सरकार की खाद्य-नीति की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। कोई सुझाव हो तो दीजिए।
(Raj. Hyr. T. D. C., 1981)
 3. संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए :—
(प्र) भारत में खाद्य-समस्या
(Raj. Hyr. T. D. C., 1982, 1984 and 1986)
 4. हाल के वर्षों में भारत की खाद्य-स्थिति की जाँच कीजिए। क्या देश आयातों में आत्म-निर्भर हो गया है ? सरकार की खाद्य-नीति का विश्लेषण कीजिए।
(Raj. Hyr. T. D. C., 1980)
-

कृषि--साख

(Agricultural Credit)

महत्व—भारत में कृषिगत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक कारण साख की सुविधाओं का अभाव माना जा सकता है। गाँवों में कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साख की आवश्यकता होती है। कृषि ग्रामीण उद्योग, प्रोसेसिंग के कार्य, पशु-पालन आदि सभी कार्यों के लिए साख की आवश्यकता होती है। ग्रामीण जनता की आमदनी बहुत कम होती है, अतः उसकी खपत भी कम होती है। आर्थिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। नियोजित अर्थव्यवस्था में कृषि का तेजी से विकास करने के लिए तो साख की आवश्यकता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए गैर-कृषि-उत्पादन को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। अतः मविप में ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी की माँग तेज गति से बढ़ेगी। ग्रामीण साख की एक सुनियोजित एवं सुसंगठित योजना के द्वारा ही उसकी पूर्ति की जा सकेगी।

ग्रामीण साख में कृषि-साख के अतिरिक्त कुटीर व विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक साख की मात्रा शामिल की जाती है। फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा पूँजी की आवश्यकता कृषिगत कार्यों के लिए ही होती है। कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए साख की उपलब्धि उचित समय पर, उचित मात्रा में व उचित व्याज की दर पर होनी चाहिए।

कृषि-साख का वर्गीकरण—भारतीय किसान की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है जैसे—(प) अवधि के अनुसार, (पा) उद्देश्य के अनुसार, (इ) जमानत के अनुसार, (ई) ऋणदाता के अनुसार। इनका मसिद्ध परिचय नीचे दिया जाता है।

(प) अवधि के अनुसार (Period-wise) (i) अल्पकालीन—इसकी अवधि 15 महीने तक होती है। अल्पकालीन ऋण चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त किये जाते हैं, जैसे खाद, बीज आदि के लिए किमान गाँव के महाजन या

सहकारी समिति से इस प्रकार के ऋण लेता है। ऐसे ऋण उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लिये जाते हैं।

(ii) मध्यमकालीन—इनकी अवधि 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। किसान बैल की जोड़ी खरीदने के लिए, कुर्मा खुदवाने एवं भूमि में बर्द प्रकार के सुधार करने के लिए ऐसे ऋण लेता है। शादी व मृत्यु पर उपभोग-खर्च के लिए भी मध्यमकालीन ऋण लिए जाते हैं।

(iii) दीर्घकालीन—इनका भुगतान पाँच वर्ष के बाद होता है। ये पुराने ऋण चुकाने लघु सिंचाई भू संरक्षण बजर भूमि को तोड़ने भूमि खरीदने व भूमि में स्थाई सुधार करने भारी मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि खरीदने एवं ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लिए लिए जाते हैं। भूमि विकास एवं दीर्घकालीन ऋण देते हैं। गाँवों में महाजनो से भी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किये जाते हैं।

विविध अवधि ऋणों की माँग का अनुमान

भारत में कृषि विकास की नयी नीति अपनाने के बाद 1966 से अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन साख की माँग में काफी वृद्धि हुई है और भविष्य में यह वृद्धि जारी रहेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में सहकारी ऋणों के लिए निम्न लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं।¹

(करोड़ रु में)

सहकारिताओं के माध्यम से	1984-85 में प्रत्याशित उपलब्धि का स्तर	1989-90 के लिए लक्ष्य
अल्पकालीन ऋण	2500	5540
मध्यमकालीन ऋण	250	500
दीर्घकालीन ऋण	500	1030
कुल	3250	7070

इस प्रकार सहकारिताओं के माध्यम से सभी अवधियों के लिए कुल ऋणों की मात्रा 1984-85 में 3250 करोड़ रु से बढ़ाकर 1989-90 में लगभग 7070 करोड़ रु करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घा) उद्देश्य के अनुसार (Purpose-wise)—ऋण उत्पादन व अनुत्पादन (उपभोग के लिए) दो प्रकार के होते हैं। उपभोग के लिए प्राप्त किये गये ऋण भी दो भागों में बाँटे जा सकते हैं। फसल की अवधि में किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऋण लेने को बाध्य हो जाता है। इसके अलावा शादी, मृत्यु, मुकदमेवाजी आदि में व्यय करने के लिए भी ऋण लेने पड़ते हैं। प्रथम श्रेणी के ऋण

उपयोग के लिए, लिए जान पर भी उत्पादक ऋणों की मांगि ही होते हैं, और उनका लेना बुरा नहीं होता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उपभोग-ऋण पूर्णतया अनुत्पादक होने हैं और इन्हें यथासम्भव कम किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका चुकाया जाना काफी कठिन होता है।

(ई) जमानत के अनुसार (Security-wise)—प्रायः ऋण जमानत या बिना जमानत दोनों प्रकार से दिये जाते हैं। महाजन प्रायः बिना जमानत के भी अल्प-कालीन ऋण देता है, लेकिन सहकारी मज्जाएँ भूमि की जमानत पर ही ऋण प्रदान करती हैं। इससे बड़े किसानों को ही विशेष सान पहुँच पाता है और छोटे व मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी सास प्राप्त करने में कठिनार्थ का अनुभव करते हैं। यदि 'भूमि की जमानत' के स्थान पर 'मुग़तान की छमता' के आधार पर ऋण दिये जाएँ तो ऐसे कृषकों को ज्यादा लाभ मिल सकता है।

(इ) ऋणदाता के अनुसार (Creditor-wise)—भारत में ऋणदाता के अनुसार किसानों को सास प्रदान करने के माधन दो मार्गों में बाँटे गये हैं। (1) व्यक्तिगत (Individual) (2) संस्थागत (Institutional)। व्यक्तिगत साधनों में साहकार, दशौ बैँक, व्यापारी, जमींदार व किसानों के मित्र-मज्जायी आदि आते हैं और संस्थागत साधनों में सहकारिताएँ, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैँक, प्रादेशिक ग्रामीण बैँक व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आते हैं। आजकल संस्थागत साधनों को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जान लगा है ताकि कृषकों को महाजन व साहकारों के आर्थिक जोपल से बचाया जा सके, छोटे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक ध्यान दिया जा सके तथा कृषि के लिए कर्ज की कुल मात्रा में वृद्धि की जा सके।

कृषि के लिए संस्थागत वित्त

(Institutional Finance for Agriculture)

कृषि के लिए संस्थागत वित्त को भी दो मार्गों में बाँटा जा सकता है—(प्र) प्रत्यक्ष वित्त (direct finance) इसके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैँक व प्रादेशिक ग्रामीण बैँक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देते हैं। प्राथमिक कृषि सास समितियाँ कृषकों को अल्पकालीन व मध्यमकालीन कर्ज देती हैं तथा भूमि विकास बैँक दीर्घकालीन कर्ज देते हैं। राज्य सरकारें किसानों का 'तकवी' ऋण देती हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैँक (प्रादेशिक ग्रामीण बैँकों सहित) कृषि व सहायक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन व सावधि-कर्ज (term loan) प्रदान करते हैं। (व) परोक्ष वित्त (indirect finance) इसके अन्तर्गत राज्य सहकारी बैँक, केन्द्रीय सहकारी बैँक, अनुसूचित व्यापारिक बैँक, प्रादेशिक ग्रामीण बैँक व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परोक्ष रूप से कृषि को वित्त प्रदान करते हैं। इन्हें परोक्ष ऋण हम-विग कहा जाता है कि इनमें ऋण देने वाली मज्जा किसी अन्य मज्जा के माध्यम से मिलती

को कर्ज देती है; जैसे अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहीं-कहीं प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किसान को कर्ज देते हैं जो परोक्ष कर्ज के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इसी प्रकार सहकारी समितियाँ खाद्यान्नों की जमूली, कृषि पदार्थों की बिक्री आदि के लिए ऋण देती हैं। कृषि-साख को नई व्यवस्था में प्रत्यक्ष व परोक्ष सम्पादन वित्त दोनों का योगदान बढ़ाया जा रहा है।

कृषि-साख की पूर्ति के साधन

ग्रहिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण में अपनी दिसम्बर, 1954 की रिपोर्ट में 1951-52 की अवधि से सम्बन्धित कृषि-साख के विविध पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रहिल भारतीय ग्रामीण ऋण व विनियोग सर्वेक्षण (All India Rural Debt and Investment Survey, के अन्तर्गत 1961-62 तथा 1981-82 की अवधि के लिए ग्राइंडे एक्स्ट्र किये गये थे। निम्नलिखित तालिका से प्रकट होता है कि ग्रामीण साख की पूर्ति में 1951-52 से 1981-82 की अवधि में विभिन्न एजेंसियों का तुलनात्मक स्थान काफी बदल गया है।

कृषि-साख के स्रोत¹

साख प्रदान करने की एजेंसी	कृषि की कुल उधार में प्रत्येक एजेंसी से प्राप्त उधार का प्रतिशत अंश		
	1951-52	1961-62	1981-82
सरकार	3.3	2.6	4.0
सहकारी समितियाँ	3.1	15.5	28.6
कृषक के सम्बन्धी	14.2	8.8	38.8
भू-स्वामी	1.5	0.6	
कृषक-महाजन	24.9	36.0	
पेशेवर महाजन	44.8	13.2	
व्यापारी व कमीशन एजेंट	5.5	8.8	28.0
व्यापारिक बैंक	0.9	0.6	
अन्य	1.0	13.9	0.6
	100.0	100.0	100.0

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि ग्रामीण साख की एजेंसी के रूप में 1951-52 से 1981-82 की अवधि में सरकार, सहकारी समितियों व व्यापारिक

* RBI Bulletin, June 1986, for All India Debt and Investment Survey 1981-82 results.

नोट—कुछ पुस्तकों में इसी नाम के ग्राइंडे अन्य वर्षों के लिए दिये गये हैं। लेकिन उनका कोई स्रोत या आधार नहीं होने से वे मनगढ़न्त व मिथ्या हैं। अतः उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ग्रहिल भारतीय ऋण व विनियोग सर्वेक्षण के ग्राइंडे ही सही व विश्वसनीय माने जाते हैं। पाठक इसका विशेष ध्यान रखें।

बैंकों तीनों के द्वारा दी जाने वाली साख, अर्थात् संस्थागत साख (Institutional credit) का अंश 7% से बढ़कर 61% हो गया है। निजी एजेंसियों जैसे महाजन, व्यापारी, कमिशन एजेंटों तथा सम्बन्धियों आदि का स्थान 93% से घटकर लगभग 39% हो गया है। इस प्रकार 1981-82 संस्थागत एजेंसियों व निजी एजेंसियों का योगदान लगभग 60-40 के अनुपात में रहा है। इस प्रकार संस्थागत एजेंसियों का योगदान 60% से भी अधिक हो गया है जो एक सही दिशा की ओर प्रगति है और ग्रामीण वर्गों में इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

कृषि के लिए संस्थागत वित्त¹

(Institutional Finance for Agriculture)

सहकारिताएँ, अनुसूचित व्यापारिक बैंक व प्रादेशिक ग्रामीण बैंक तीन मुख्य संस्थागत एजेंसियाँ हैं जो कृषिगत साख प्रदान करती हैं। जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना से कृषिगत साख के क्षेत्र में पुनर्वित्त की सुविधा काफी बढ़ गई है जिसका लाभ विभिन्न एजेंसियों ने उठाया है।

सहकारिताओं, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व राज्य सरकारों ने 1986-87 में कृषिगत कार्यों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (direct finance) के रूप में 7,921 करोड़ रु. प्रदान किये जो पिछले वर्ष से 10.6% अधिक थे। इनमें से 49.3% राशि सहकारिताओं द्वारा प्रदान की गई। दूसरा स्थान व्यापारिक बैंकों का रहा। इन्होंने लगभग 42.1% राशि दी। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा 6% तथा राज्य सरकारों द्वारा शेष 2.6% राशि प्रदान की गई।

राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक व ग्रामीण वित्तीयकरण निगम कृषि के लिए परोक्ष वित्त (indirect finance) प्रदान करते हैं। राज्य व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माफ़त परोक्ष ऋण की राशि 1986-87 में 4803 करोड़ रु. से बढ़कर 1987-88 में 6047 करोड़ रु. हो गई। 1983-84 व 1984-85 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रति वर्ष परोक्ष कर्ज के रूप में 8 से 9 करोड़ रु. देते रहे हैं लेकिन बाद में नहीं दिया है। ग्रामीण वित्तीयकरण निगम ने परोक्ष ऋण के रूप में 1986-87 में 440 करोड़ रु. दिये जिनकी मात्रा 1987-88 में बढ़ कर 655 करोड़ रुपये हो गयी (वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च) संस्थागत साख के क्षेत्र में प्रमुख समस्या

देश में कृषिगत ऋण संस्थाओं की दशा काफी निराशाजनक है। कई राज्यों में जानबूझकर समय पर भुगतान न करने व बढ़ते हुए धोवरद्यूज की समस्या जारी गम्भीर हो गई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र व गुजरात जैसे सहकारी दृष्टि से

1. Report on Currency and Finance 1987-88, Vol. I, pp. 100-102.

विकसित राज्यों की दशा भी खराब है। कुछ राज्यों ने कृषिगत ऋणों को बढ़ते खाते लिखकर तथा सहकारी खजाने से सविस्ती देकर देश के समक्ष गलत विरम का दृष्टांत रखा है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो सत्यागत एजेन्सियों कोषों के अभाव में अपना काम ठीक से नहीं कर पायेंगी।

पिछले कुछ वर्षों से ओवरड्यूज की राशि पाय के अंश के रूप में 40% से अधिक रही है। जून 1987 के अन्त में प्राथमिक कृषि साख मर्मितियों के ओवरड्यूज माँग-राशि का 41.1 प्रतिशत तथा राज्य व केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के लिए 48.1 प्रतिशत रहे हैं। हरियाणा केरल व पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में कर्ज की वसूली सतोपजनक नहीं रही है।¹

इतने ओवरड्यूज रहने से कोषों की गतिशीलता रुक जाती है।

सातवी योजना में वर्ष 1989-90 तक के लिए विभिन्न सत्यागत एजेन्सियों के लिए कृषिगत साख के निम्न लक्ष्य रखे गये हैं— (करोड़ रु में)

I सहकारिताएँ

(अ) अल्पकालीन कर्ज	5540
(ब) मध्यकालीन ,,	500
(स) दीर्घकालीन ,,	1030

II व्यापारिक बैंक (प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों सहित)

(अ) अल्पकालीन कर्ज	2500
(ब) अवधि कर्ज	3000

कुल 12570

इतनी बड़ी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों के कार्यों में काफी ताल-मेल बैठाना होगा एवं जिला-साख-योजनाएँ तैयार करनी होंगी। अतः भविष्य में सत्यागत साख के क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। कर्ज की राशि की वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

1987-88 की अवधि में सत्यागत एजेन्सियों से कुल साख का वितरण 7991 करोड़ रु तक हो गया था तथा 1988-89 के लिए लक्ष्य 11751 करोड़ रु रखा गया है। इसमें सहकारिताओं का योगदान 5,441 करोड़ रु तथा बैंकों का 6,310 करोड़ रु, आंका गया है।²

इस प्रकार कृषि साख में सत्यागत एजेन्सियों का योगदान काफी बढ़ा है।

नीचे ग्रामीण साख के विभिन्न साधनों का संक्षिप्त विवेचन किया जाता है—

1. महाजन—किसान को सबसे ज्यादा ऋण महाजन से मिलता है। महाजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो खेतिहर महाजन और दूसरे पेशेवर महाजन।

1 Report on Trend and Progress of Banking In India, 1987-88, p 156.

2 Economic Survey 1988-89 p 24

खेतिहर महाजन खेती भी करने हैं लेकिन पेशेवर महाजन नेबल उधार देने का ही व्यवसाय करते हैं और इनका देहातों में अधिक प्रभाव पाया जाता है। पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों में महाजनों प्रथा के नियमनकारी कानूनों के द्वारा इसकी गति-विधियाँ पर कुछ सीमा तक अनुशासित किया गया है।

महाजन के काम करने के तरीके बड़े सरल, लचीले व निराले होते हैं। वह प्रत्यक्षालीन मध्यमकालीन व दीर्घकालीन सभी प्रकार के ऋण देता है। उसे ऋण के उद्देश्य—उत्पादन या उपभोग से विशेष सरोकार नहीं होता। वह जमानत व बिना जमानत दोनों तरह के ऋण देता है। महाजन बहुत शोषणा से जिन समय पर ऋण देता है। इन विशेषताओं के कारण आज भी महाजन ग्रामीण साख के क्षेत्र में जमा हुआ है।

महाजन के काम करने के अपने ही ढंग होते हैं। उसे ऋणी किसान की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। यह उसके आचरण व चुकाने की क्षमता से भी परिचित होता है। कृषक से ऋण वसूल करने के लिए वह शायद ही कभी मझालत या कानून का सहारा लेता है। कई प्रकार से आर्थिक व सामाजिक दबाव डालकर वह अपने ऋण की रकम वसूल कर लेता है। आर्थिक दबाव में वह उधार बन्द करने की क्षमता देता है अथवा किसान पर जमींदार या व्यापारी के मार्फत दबाव डलवाता है। प्रायः वह स्वयं जमींदार या व्यापारी भी होता है या इनसे सम्बन्ध रखता है। सामाजिक दबाव में वह किसान को अपमानित करने अथवा सामाजिक या जाति-बहिष्कार करवाने का मय भी दिखाता है। वह बड़े पैमाने से इन्तज़ार करता है और अन्त में व्याज सहित अपनी रकम वसूल कर लेता है। महाजन की व्याज की प्रभावपूर्ण दरें काफी ऊँची रहती हैं।

महाजन अपनी हरकतों के लिए काफी बदनाम रहा है। अग्रिम व्याज, गिरहलुआई व अन्य भेंट, खाली कामज पर अगुठे की निशानी लेकर मनमानी रकम भर लेना, हिसाब में गड़बड़, आदि के कारण उसे कृषक का शोषक माना गया है। भूतकाल में उस पर कानून के द्वारा नियन्त्रण करने के प्रयत्न किये गये हैं, लेकिन उनमें विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। 1954 की अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट (गोरवाला समिति की रिपोर्ट) के अनुसार, "महाजन द्वारा किसान को दी जाने वाली साख में लोच व शोष प्राप्त के गुणों के अतिरिक्त कोई भी अन्य सराहनीय बात नहीं है और कुछ बातें इसको निरुद्ध व हथिनी बनाने वाली हैं।"

महकारी शासक समितियों ने पर्याप्त विकास से ही कृषकों पर महाजनों का शिकवा दूर किया जा सकता है। इनके लिए भारी प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

2. व्यापारिक बैंक—1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन्होंने प्रचलन रूप से कृषकों के लिये साख की व्यवस्था करने में बहुत कम भाग

लिया था। इस सम्बन्ध में इनका ज्यादातर कार्य ग्रामीण व शहरी महाजनो, देशी बैंकरो व व्यापारियो की पूँजी देना रहा था। 1951-52 में किसानो की अपनी कुल उधार का मुश्किल से 0.9% व्यापारिक बैंको से मिल पाया था जो काफी कम था, लेकिन 1981-82 में यह अनुपात बढ़कर 28% हो गया है। 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने भी देश के विभिन्न भागो में अपनी शाखाएँ खोलकर अपनी वचतो को एकत्र करने एवं ग्रामीण साख की सुविधाएँ बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंको का कृषि-साख में योगदान—सितम्बर, 1967 से बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की नीति के अन्तर्गत व्यापारिक बैंक कृषिगत मशीनरी की खरीद व पम्प-सेट लगाने आदि के लिए साख प्रदान करने लगे थे। जुलाई, 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के पीछे एव उद्देश्य यह था कि बैंक कृषि व अन्य क्षेत्रो को अधिक मात्रा में कर्ज दे सकेंगे। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पिछले वर्षों में व्यापारिक बैंकों ने अपनी शाखाओ का तेजी से विस्तार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको ने काफी नई शाखाएँ खोली हैं। 30 जून, 1969 से 30 जून 1988 के बीच में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के कार्यालय की सख्या 6596 से बढ़कर 47385 हो गयी है। इस प्रकार इनकी सख्या में 40789 की वृद्धि हुई है, जिनमें से 65.4% कार्यालय ग्रामीण केन्द्रो (जहाँ की जनसख्या 10,000 तक हो) में स्थापित किये गये हैं। जून 1969 में कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त (direct finance) (बागान को छोड़कर) की बकाया राशि लगभग 40 करोड़ रुपया एवं परोक्ष वित्त की राशि 122 करोड़ रुपया थी जो जून 1987 के अन्त में बढ़कर क्रमशः 9300 करोड़ रुपये व 1366 करोड़ रुपये हो गयी है।¹ सातवी योजना में इनके कार्यों का विस्तार किया गया है, विशेषतया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमो (IRDP) के लिए इसके द्वारा साख की मात्रा बढ़ायी गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था जिसे भूमि-सुधारो के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कानूनों की विभिन्न व्यवस्थाओ की जाँच करने के लिये कहा गया था ताकि व्यापारिक बैंको के द्वारा कृषि-साख के मार्ग में आने वाली उन बाधाओ को दूर किया जा सके जो इन कानूनों की वजह से उत्पन्न होती हैं। विशेषतः दल ने ऐसी कानूनी अड़चनो की तरफ राज्य सरकारो का ध्यान आकर्षित किया था। राज्यों के कानूनों में प्रमुख बाधा भूमि-अधिकारो को हस्तान्तरित करने के बारे में पायी गयी है, विशेषतया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के मू-स्वामियो, काश्तकार-कृषको, मूदान की भूमि व सरकारी भूमि के प्राप्त करने वालो के भूमि के अधिकारो को हस्तान्तरित करने में अड़चन आती हैं। अध्ययन दल ने सिफारिश की

तकाली ऋणों को कमियों को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिए—(1) ऐसे ऋणों को सहकारी समितियों के मार्फत प्रदान करने की नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाय। (2) सरकार ने जो धनराशि कृषकों के उत्पादन व भूमि की उन्नति के लिए उधार देने के वास्ते रख छोड़ी है उसका उपयोग सहकारी समितियों के साधनों को बढ़ाने में किया जाय। (3) सहकारी समितियों को उनकी उधार देने की ब्याज की आर्थिक दर और निर्धारित ब्याज की दर के अंतर के बराबर सन्निधि दी जाय। राज्य सरकारों की तरफ से कृषि के लिए प्रत्यक्ष कर्ज की मात्रा 1977-78 में लगभग 98 करोड़ रु थी। इसकी मात्रा बढ़कर 1983-84 में 220 करोड़ रु. हो गई। यह अल्पकालीन कर्ज के अतर्गत आता है।

4 सहकारी संगठन¹—भारत में सहकारिता आन्दोलन बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में चालू हुआ था। इसका ज्यादातर प्रयोग किसानों को साख प्रदान करने में किया गया है। इस कार्य को केन्द्रीय स्तर पर राज्य सहकारी बैंक जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि-साख समितियाँ (PACS) कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े आकार की बहुउद्देश्यीय समितियाँ (Large-sized Multipurpose Societies) (LAMPS) भी कृषकों को कर्ज के अलावा अन्य इन्पुट प्रदान करती हैं। आजकल नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को वित्त की काफी सुविधा दी जाती है।

ऊपर बताया जा चुका है कि 1951-52 में ग्रामीण साख के सहकारी समितियों का योगदान 3.1% था, जो 1981-82 में बढ़कर 28.6% हो गया। 1950-51 में प्राथमिक कृषि साख समितियों ने अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों के रूप में केवल 23 करोड़ रु ही कृषकों को प्रदान किये गये थे, जबकि 1986-87 में इन्होंने अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों के रूप में 3,149 करोड़ रुपये प्रदान किये। इसी वर्ष राज्य/केन्द्रीय भूमि विकास बैंको ने कृषि के लिए 552 करोड़ रु के दीर्घकालीन ऋज प्रदान किये। इस प्रकार प्रत्यक्ष वित्त के रूप में सहकारिताओं द्वारा कुल 3701 करोड़ रु प्रदान किये गये। यह प्रगति काफी सराहनीय मानी जा सकती है, लेकिन साथ में कुछ कमियाँ भी सामने आयी हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। ये इस प्रकार हैं—

(1) लघु कृषकों को सस्थागत साख में कम अंश—अनुमान लगाया गया है कि सीमान्त व लघु कृषकों को (2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को) कुल सस्थागत उत्पादन-साख का 1/3 अंश मिला है, हालांकि उनके पास कुल जोतो का 70% अंश रहा है। इस प्रकार यद्यपि पिछले वर्षों में लघु कृषकों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाने लगा है, फिर भी भविष्य में इनके लिए विशेष प्रयास करने होंगे।

1. Report on Trend and Progress of Banking in India, 1987-88, pp 155-157

‘कमल-ऋण-योजना’ (Crop Loan System) अपनाकर ही सीमान्त व तपू हथकी की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं।

(ii) बढ़ते हुए ओवरड्यूज की समस्या—सहकारी साख की दूसरी गम्भीर समस्या बकाया ऋणों की वसूली की है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के लगभग 2/5 ऋण अवधि बीत जाने पर भी नहीं लौटाये जाते हैं। इससे सहकारी समस्याओं की वित्तीय स्थिति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ओवरड्यूज की समस्या केंद्रीय सहकारी बैंको व भूमि विकास बैंको के सम्बन्ध में भी काफी गम्भीर बनती जा रही है। इससे कौषों की गतिशीलता रूक जाती है। अतः सहकारी समस्याओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

(iii) विकास में प्रादेशिक असमानताएँ—भारत में सहकारी साख-समितियों की विशेष प्रगति आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व पश्चात् राज्यों में हुई है। इस प्रकार सहकारी साख के सम्बन्ध में काफी प्रादेशिक असमानताएँ पायी जाती हैं। नवित्प्य में सहकारी साख समितियों की विविध समस्याओं के हल करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

विद्यते वर्षों में कृषकों को साख की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए अन्य संगठन भी स्थापित किये गये हैं जिनका वर्णन नीचे किया जाता है। इनमें कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम (Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC), कृषि वित्त निगम लि (Agricultural Finance Corporation Limited) (AFC) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) (NABARD) (नाबाई) के नाम उल्लेखनीय हैं।

5 कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम (Agricultural Refinance and Development Corporation) (ARDC)—प्रारम्भ में इसका नाम कृषि पुनर्वित्त निगम (ARC) था। यह जुलाई 1963 में स्थापित किया गया था तथा 15 नवम्बर 1975 में इसका नाम बदल कर कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम (ARDC) कर दिया गया था। 12 जुलाई, 1982 को कृषि व ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय बैंक (नाबाई) की स्थापना के बाद ARDC के कार्य नाबाई को सौंप दिये गये हैं। अतः भविष्य में नाबाई की ग्रामिका कृषि साख में सर्वोपरि रहेगी।

उद्देश्य व कार्य—प्रणाली—कृषि-पुनर्वित्त निगम का प्रमुख कार्य कृषि के विकास से सम्बन्धित बड़े कार्यक्रमों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना रहा था, क्योंकि भूमि-रन्धक बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक वित्त की मात्रा अथवा प्रदायगी की शक्तों के कारण इन कार्यक्रमों में पूर्ण नहीं लगा सकते थे। निगम का कार्य सुदृढ़ व धार्मिक दृष्टि से लाभकारी एवं विशेष देशमान के लायक परियोजनाओं पर अधिक बन् देना था। यह निम्न कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देना था।

(क) भूमि को कृषि योग्य बनाने व इसके विकास के लिए वित्त प्रदान करना जिससे सिंचाई की सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किया जा सके ।

(ख) विशेष फसलों के विकास के लिए वित्तीय सुविधा देना, जैसे सुपारी, नारियल, काजू, इलायची, फलों के बाग, अमूर के उद्यान आदि ।

(ग) यन्त्रीकृत सेती का विकास, ट्यूब-वेल व पम्प-सैंट प्रादि के माध्यम से बिजली का प्रयोग करना । निगम मान्यता प्राप्त सस्थाओं के द्वारा विदेशों से खरीदें जाने वाली पूँजीगत माल के सम्बन्ध में स्थगित भुगतान पर गारण्टी देने का कार्य भी करता था ।

निगम से निम्न सस्थाओं को सुविधा मिलती थी जिससे कृषि, पशुपालन, दुग्ध-पचसाय, मछली-उद्योग व मुर्गी-पालन के विकास के लिए मध्यम कालीन व दीर्घकालीन साख की सुविधा बटी थी (1) राज्य भूमि विकास बंक (SLDB), (2) राज्य सहकारी बैंक; (3) अनुसूचित व्यापारिक बैंक; और (4) सहकारी समितियाँ (राज्य भूमि विकास बैंक या राज्य सहकारी बैंक को छोड़कर) जिनको यह निगम पुनर्वित्त के रूप में ऋण व अग्रिम राशि देता रहा और इनके डिबेंचर खरीदता रहा ।

पूँजी—आरम्भ में निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये की हो गयी थी जो 15 हजार शेयरों में (प्रत्येक शेयर 10 हजार रुपये का) विभाजित की गयी थी। 15 नवम्बर, 1975 के सशोधन के अनुसार यह 100 करोड़ रु. कर दी गयी । इसके शेयर रिजर्व बैंक, भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, जीवन बीमा निगम आदि ने खरीदे थे ।

निगम की प्रगति—ARDC ने 1981-82 (जुलाई-जून) में काफी प्रगति दिखाई थी । इसने इस वर्ष 600 करोड़ रुपये की राशि वितरित की, जबकि पिछले वर्ष 499 करोड़ रु. की राशि वितरित की थी । इसने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (IDA) के द्वारा स्वीकृत कर्ज का वितरण भी किया था ।

15 नवम्बर, 1975 के सशोधन से इसका कार्यक्षेत्र बढ गया था और इसकी शेयर पूँजी भी चौगुनी हो गई थी । ARDC ने प्रादेशिक असन्तुलन कम करने में योगदान दिया था । निगम ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया और इसके दायरे में अधिक विकास खण्ड लाये गये । जुलाई 1982 से इसका कार्य नाबाडें को सौंप दिया गया जिसका वर्णन आगे किया गया है ।

6 कृषि वित्त-निगम (Agricultural Finance Corporation) (AFC)—कृषि-वित्त निगम अप्रैल, 1968 में स्थापित किया गया था । इसका रजिस्ट्रेशन सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में किया गया । इसने कृषि सम्बन्धी क्रियाओं में सलाहकारी संगठन के रूप में काफी दक्षता प्राप्त की है । यह व्यापारिक

बैंकों को कृषि साख बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों या सदस्य बैंकों से प्राप्त कृषिगत कार्यक्रमों या स्वयं कम्पनी द्वारा निमित्त कार्यक्रमों की तकनीकी जाँच व मूल्यांकन करता है। फिर ऋण पुनर्मुं गतान के आधार पर वितरित किये जाते हैं। इस प्रकार निगम का मुख्य कार्य कृषिगत साख को बढ़ावा देना है जिसमें इसकी भूमिका काफी सराहनीय रही है। यह ऋणों के उचित उपयोग की भी देख-भाल करता है। निगम प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था केवल उन कृषि-कार्यों के लिए करता है जो तकनीकी दृष्टि से ऊँची श्रेणी में आते हैं।

कृषि-वित्त निगम ने राज्य विजसी बोर्डों, केरल वागान निगम लिमिटेड आदि को ऋण प्रदान किये हैं। इसने सदस्य बैंकों को विछड़े प्रदेशों में जाने के लिए प्रेरित किया है। निगम की सहायता से पम्पसेटों की खरीद हुई है। ग्रामी विस्म ने पम्प-सेटों का प्रचार बढ़ रहा है। निगम ने इसकी ग्रामी विस्म, उचित भूतय व रिश्वी के बाद भी सेवाओं पर समुचित ध्यान दिया है।

निगम ने विभिन्न साख प्रदान करने वाली संस्थाओं के मन्त्रिम स्थापित करके एक समन्वयात्मक एजेन्सी (Coordination agency) का काम भी किया है। निगम की अधिकारिता परिलक्षित पूँजी राज्य विद्युत बोर्डों में लगी हुई है। अविष्य में स्वीकृत ऋणों को सम्पूर्ण राशि सबस्य बैंकों के द्वारा ही प्रदान की जायेगी। 14 राष्ट्रीयकृत बैंक इस निगम की 86 प्रतिशत शेयर पूँजी में हिस्सेदार हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस निगम का सार्वजनिक स्वरूप और भी उभर कर सामने आया है।

निगम प्रोजेक्ट-निर्माण/मूल्यांकन के कार्यक्रम अपना हाथ में लेता है। इनमें कमाण्ड-क्षेत्र विकास, सखट स्तर पर नियोजन, समन्वित आदिवासी विकास, वाटरशेड प्रबन्ध व कमजोर वर्ग के क्षेत्रों में पशु-पालन के कार्यक्रम शामिल होते हैं।

AFC कुछ विकासशील देशों व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए सलाहकारी संगठन का काम करता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कृषिगत विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, अफ्रिकन विकास बैंक, इस्लामिक विकास बैंक आदि के लिए यह प्रोजेक्ट निर्माण वगैरा का काम करता है। इस वगैरा देश में उर्वरक-मूल्य विनियन्त्रण के लिए अध्ययन किया है। इस प्रकार AFC के विवेक तृतीय विश्व के देशों में प्रोजेक्ट तैयार करने में अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

जुलाई, 1982 में 'नाबाई' के बन जाने पर AFC का सनाह देने का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

7 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) (NABARD)—इसकी स्थापना

12 जुलाई, 1982 को लोकसभा में आवश्यक विधेयक पारित करके की गई थी। इसने ARDC के समस्त कार्य तथा रिजर्व बैंक के कृषिगत साख-विभाग के प्रमुख कार्य अपने हाथ में ले लिए हैं। नाबाड की शेयर पूँजी 100 करोड़ रु. है जिसमें केन्द्रीय सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक का बराबर का हिस्सा है। यह रिजर्व बैंक व भारत सरकार से उधार भी ले सकता है। यह बाड व ऋण-पत्र बेचकर भी वित्तीय साधन जुटाता है।

नाबाड के मुख्य कार्य नीचे बिये जाते हैं

(i) यह कृषि, लघु उद्योगों, कारीगरों, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारियों व ग्राम्य सहायक आर्थिक क्रियाओं के लिए सभी प्रकार के उत्पादन व विनियोग-साधन के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको धनराशि भारत सरकार, विश्व बैंक व ग्राम्य बहुपक्षीय व द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त होती है। यह बाजार से उधार भी ले सकता है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घकालीन कार्य व स्थायीकरण) कोषों से भी उधार ले सकता है। रिजर्व बैंक भी नाबाड को अल्पकालीन कार्यों के लिए उधार देता है।

(iii) राज्य सहकारी बैंको, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व ग्राम्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन साख प्रदान करने के अलावा यह राज्य सरकारों को 20 वर्ष तक की अवधि के लिए कर्ज देता है ताकि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहकारी साख समितियों की शेयर पूँजी में अपना अंशदान दे सकें। यह केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से, कृषि व ग्रामीण विकास में सलग्न किसी भी संस्था को दीर्घकालीन कर्ज प्रदान कर सकता है तथा उसकी शेयर-पूँजी में हिस्सा ले सकता है।

(iv) यह लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकारों आदि के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

(v) इसने कृषि व ग्रामीण विकास में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक रिसर्च व विकास कोष स्थापित किया है। यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोजेक्ट/कार्य-क्रम बनाता है।

(vi) विभिन्न प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन व मूल्यांकन की जिम्मेदारी नाबाड की होती है, तथा

(vii) यह प्रादेशिक ग्रामीण बैंको व सहकारी बैंको (प्राथमिक सहकारी बैंको को छोड़कर) की जाँच के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हे शाखाएँ खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन-पत्र नाबाड के माध्यम से भेजने होते हैं।

इस प्रकार नाबाड का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक रखा गया है।

नाबाई की प्रगति¹—30 जून, 1988 तक उसने कुल 62,615 योजनाएँ स्वीकृत की जिनका सम्बन्ध लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, बागान/फलों का उद्यान, भुर्गी-पालन/भेड़ पालन व सुप्र-पालन, मछली-पालन, डेरी विकास, मण्डारण व मण्डियों के निर्माण-कार्य, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि से था।

30 जून 1988 तक इसने स्वीकृत योजनाओं के लिए 9,435 करोड़ रु की राशि वितरित की।

1987-88 (जुलाई-जून) अवधि के लिए नाबाई के वायदे की राशि 2,037 करोड़ रु तथा वितरण की राशि 1482 करोड़ रु. रही, जबकि पिछले वर्ष ये राशिवां क्रमशः 1483 करोड़ रु. तथा 1,334 करोड़ रु. रही थी।

(अ) प्रयोजनवार (Purpose-wise) वितरण—1987-88 में नाबाई द्वारा 1482 करोड़ रु. की वितरित राशि में से सर्वाधिक राशि लघु सिंचाई के लिए थी जो 473 करोड़ रु. थी। द्वितीय स्थान कृषि-मशीनीकरण का रहा (200 करोड़ रु.) शेष राशि वृक्षारोपण/बागान, भूमि विकास, भुर्गी-पालन, भेड़ पालन, सुप्र पालन, मछली पालन, डेयरी विकास, मण्डारण व मण्डि याई बर्गरा के लिए वितरित की गई। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एगाविका) के लिए 783 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई (फरवरी 1988 तक)

(आ) एजेंसीवार (Agency-wise) वितरण—1987-88 में 1482 करोड़ रु की वितरित राशि का सर्वाधिक अंश व्यापारिक बैंकों के माध्यम से (प्रादेशिक ग्रामीण बैंको सहित) (951 करोड़ रु.), फिर राज्य भूमि विकास बैंको के माध्यम से (467 करोड़ रु.) एवं शेष राज्य सहकारी बैंको के माध्यम से (64 करोड़ रु.) प्रदान किया गया। इन संस्थाओं को नाबाई द्वारा पुनर्वित्त के रूप में सहायता दी जाती है।

(इ) क्षेत्रवार वितरण (Region-wise Disbursements)—1987-88 में नाबाई द्वारा वितरित कुल राशि का 28.5% दक्षिणी क्षेत्र को, 19.2% उत्तरी क्षेत्र को, 20.8% मध्यवर्ती क्षेत्र को, 14.6% पश्चिमी क्षेत्र को, 14.6% पूर्वी क्षेत्र तथा 2.3% उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र को प्राप्त हुआ। राजस्थान को 72 करोड़ रु. की राशि मिली जो 1482 करोड़ रु. का 4.8% थी।

नाबाई की स्थापना ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के कृषि व कृषीतर दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए हुई है। इसने लघु सिंचाई को बढ़ावा दिया है। लघु व सीमान्त कृषकों के लिए व्यापक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम चलाया गया है। भूमि-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि को समतल बनाने, इसको बेत का स्वरूप देने, नालियाँ

1 Report on Currency and Finance, 1987-88, Vol. I, pp. 214-216.

बनाने आदि पर जोर दिया गया है। कृषि की सहायक क्रियाओं में बाढ़ी (female buffalo calves) पालने की योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। नए 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में योगदान दिया गया है।

कृषीतर ग्रामीण कार्यकलापों में हथकरघों के आधुनिकीकरण, बुनकरी द्वारा शेरों के अधिग्रहण, रेशम, नारियल के रेशे, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के विकास आदि पर बल दिया गया है।

सत्यागत साख की वसूली पर जोर दिया गया है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के पुनर्गठन व पुनर्स्थापन पर बल दिया गया है। आशा है भविष्य में नाबाई का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में स्थान अधिक सुदृढ़ हो सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी साख में योगदान (ग्रामीण साख के संदर्भ में)

अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक की यह विशेषता रही है कि इसने ग्रामीण साख के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है। ऐसा करना आवश्यक भी था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है जिसके लिए साख की सुविधाएँ बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रारम्भ से ही रिजर्व बैंक अधिनियम में एक कृषि-साख विभाग स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी।

रिजर्व बैंक के सुभाव पर भारत सरकार ने 1945 में ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति नियुक्त की थी जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार के लिए कई सिफारिशें पेश कीं। श्री ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट दिसम्बर, 1954 में प्रकाशित की गई। इसमें ग्रामीण साख की विस्तृत रूप से जाच की गई और इस बात पर बल दिया गया कि सहकारिता आन्दोलन को सफल व सफल बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण साख की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Rural Credit) का सुभाव दिया गया जिसमें सहकारी संगठन में राज्य की साझेदारी, साख व गैर-साख दोनों क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन का विकास एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर काफी जोर दिया गया। नयी योजना को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रामीण साख में केन्द्रीय स्थान दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता का स्वरूप—रिजर्व बैंक कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान नहीं करता। राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से यह किसान तक साख की सुविधा पहुँचाता है। इनको रिजर्व बैंक की ओर से अल्पकालीन साख या तो पुनर्कटौती (Rediscounts) के रूप में मिलती है, अथवा अग्रिम (Advances) के रूप में मिलती है। पुनर्कटौती व अग्रिम की सुविधाओं का विवरण आगे दिया जाता है :

अन्त्यकालीन ऋण—रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (2) (a) के अन्तर्गत वास्तविक व्यापारिक मौदो से उत्पन्न प्रॉमिसरी नोट व बिलों की, जो 90 दिन में परिपक्व होते हैं, पुनर्कटौती की व्यवस्था की गयी है। धारा 17 (2) (b) के अन्तर्गत 15 महीनों में परिपक्व होने वाले उन प्रॉमिसरी नोटों/बिलों की पुनर्कटौती की व्यवस्था की गई है जो मौसमी कृषिगत कार्यों या फसलों की बिक्री के लिए बनाये जाते हैं। इस धारा के नीचे मिश्रित व कृषि परिनिर्माण-कार्य भी शामिल किये गये हैं।

धारा 17 (4) (c) के अन्तर्गत स्वीकृत विल व प्रॉमिसरी नोटों की जमानत पर प्रथम राशि देने की व्यवस्था की गई है।

जिन राज्यों में सहकारिता आन्दोलन पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाया है, उनमें बैंक इन विलों व प्रॉमिसरी नोटों की जमानत पर राज्य सहकारी बैंकों को ऋण तभी देता है जब उन पर राज्य सरकारों की ओर से पूरी गारण्टी दी जाती है। व्यवहार में व ऋण 12 महीने के लिये दिये जाते हैं।

अन्त्यकालीन साख के क्षेत्र में राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषिगत कार्यों के लिए साख की सुविधा बैंक-दर से 3% कम पर दी जाती है।

मध्यमकालीन ऋण—धारा 17 (4AA) के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष व राष्ट्रीय कृषि-साख (स्वाधीकरण) कोष में से मध्यमकालीन साख उपलब्ध होती है। इन ऋणों की अवधि 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। उत्पादन-कार्यों में ऋणों का उपयोग बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों पर यह बन्धन लगा दिया है कि वे मध्यमकालीन ऋणों का ज्यादा भरा निम्न कार्यों में ही लगायें : (1) कुओं व अन्य लघु सिंचाई कार्यक्रमों का विकास, (2) कुओं व अन्य सिंचाई की स्कीमों की मरम्मत, (3) पम्प-सेट आदि मशीनरी की खरीद, (4) कृषि-मौजारी की खरीद।

दीर्घकालीन ऋण—(अ) रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) फ़िन्साएँ [NAC (LTO)* कोष में से केन्द्रीय भूमि विकास बैंक को दीर्घकालीन ऋण देता है। जब यह कोष मार्गट को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(आ) रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देता है जिससे वे सहकारी साख मर्यादों की शायर पूँजी में हिस्सा ले सकें।

(इ) रिजर्व बैंक केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्र खरीद सकता है। यह राज्य सहकारी बैंकों को रियायती दर पर साख की सुविधा प्रदान करता है। राज्य सहकारी बैंकों को यह सुविधा मौसमी कृषिगत कार्यों व फसलों की बिक्री के

* National Agricultural Credit (Long Term Operations fund). इसका नाम बदलकर National Rural Credit (Long Term Operations) Fund कर दिया गया है।

लिए दिये गये अल्पकालीन ऋणों पर मिसती है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के साधारण ऋण पत्रों में सहकारिताओं के द्वारा राज्यों जीवा बीमा निगम व व्यापारिक बैंकों के अलावा रिजर्व बैंक भी भाग लेता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है तथा सहकारी वित्त संस्थानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। रिजर्व बैंक की कृपि साख पर एक स्थायी सलाहकार समिति भी बनायी गई है।

इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण साख व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। पहले इसका बाय सलाह आदि देने तक सीमित था लेकिन योजनावाला में इसने सहकारी संस्थाओं को बाकी वित्तीय साधन उपलब्ध किये हैं ताकि कृषकों तक अधिक मात्रा में आवश्यक वित्त पहुँचाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कृषिगत साख के क्षेत्र में बाकी सराहनीय माना गया है। अब इन कामों को ताबाड़ अधिक व्यापक व व्यवस्थित रूप से सम्पादित करने लगा है।

भारतीय स्टेट बैंक का ग्रामीण साख में योगदान

प्रखिल भारतीय ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भारत के इम्पीरियल बैंक पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की जाय। भूतकाल में व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण साख में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 1951-52 में कृषकों को केवल 0.9% ऋण प्रदान किया था। भारतीय इम्पीरियल बैंक देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक था। इसलिए इसके साधनों का उपयोग ग्रामीण साख की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए उपयुक्त समझा गया और दिसम्बर 1954 में इम्पीरियल बैंक पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित करके भारतीय स्टेट बैंक के निर्माण का सरकारी निर्णय घोषित किया गया। मई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कानून पास किया गया और 1 जुलाई 1955 से इसकी स्थापना कर दी गई।

प्रारम्भ में इम्पीरियल बैंक के भारत स्थित लेन देन को भारतीय स्टेट बैंक ने अपने हाथों में ले लिया था। इसे ग्रामीण साख की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Rural Credit) को कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया था। स्थापना के प्रथम पाँच वर्षों में 400 अतिरिक्त शाखाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें।

भारतीय स्टेट बैंक सहकारी संस्थाओं को वित्तीय साधन प्रदान करता है जिससे कृषि साख की सुविधाएँ बढ़ सकें। साथ में यह ग्रामीण बचत को एकत्र करने में मदद पहुँचाता है। योजनावाला में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास-बाय पर ध्यान देने से जागा की आगदी बढ़ रही है। इसलिए भारत को एतन करने की आवश्यक-

क्ता भी बढ रही है। अतः स्टेट बैंक कृषिगत-भास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप में भाग ले रहा है।

स्मरण रहे कि भारतीय स्टेट बैंक को अन्य व्यापारिक बैंकों के सभी काम करने का भी अधिकार है। यह देश के मुद्रा बाजार का शिरोमणि है। अतः यह एक विशिष्ट स्थान प्राप्त विषये हुये है और व्यापार, कृषि, उद्योग, आदि सभी क्षेत्रों में पूँजी का निवेश करके देश का आर्थिक विकास करने में सक्षम है।

प्रगति¹—सितम्बर 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम पास हुआ था जिसके अनुसार निम्न बड़े व राज्यो से सम्बन्धित बैंक (State Associated Banks) भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक बना दिये गये थे। इन बैंकों के नाम इस प्रकार हैं - दो बैंक ऑफ बोकानेर, दो बैंक ऑफ इंदौर, दो बैंक ऑफ जयपुर, दो बैंक ऑफ मैसूर, दो बैंक ऑफ पटियाला, दो ट्रावनकोर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र।

स्टेट बैंक से निकटतम सम्बन्ध होने से ये बैंक जनता की ज्यादा अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। दिसम्बर 1987 के अंत में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ 7577 तथा इसके सहायक बैंकों की शाखाएँ 3,784 थीं। इस प्रकार सहायक बैंकों सहित स्टेट बैंक समूह के 11361 कार्यालय थे, जो विस्तार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।

कृषि की वित्तीय व्यवस्था—भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृषि को प्रदत्त प्रत्यक्ष ऋणों की बढ़ावा राशि (सहायक बैंकों के अलावा) दिसम्बर 1987 में 2487 करोड़ रु. थी तथा आठों की संख्या 52 49 लाख थी। दिसम्बर 1986 के अंत में प्रत्यक्ष ऋणों की बढ़ावा राशि 2210 करोड़ रु. थी।

दिसम्बर 1987 के अंत में परोक्ष ऋणों की बढ़ावा राशि 323 करोड़ रु. थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह 337 करोड़ रु. थी। प्रत्यक्ष ऋण लेने वालों में अधिकांश कृषक 5 एकड़ या कम की जोतों वाले थे। इस प्रकार स्टेट बैंक छोटे कृषकों की वित्तीय व्यवस्था में विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। कृषियुक्त साख का आधे से कुछ कम अंश कमजोर वर्गों की प्राप्त हुआ है। आगामी वर्षों में स्टेट बैंक व सहायक बैंकों का काम प्रयत्न व परोक्ष साख में काफी बढ़ेगा। परोक्ष वित्त में उर्वरक-वितरण के लिए अधिक वित्त की व्यवस्था की गई है। परोक्ष वित्त में कृषकों की प्राथमिक कृषि-सहकारी साख समितियों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक ने विश्वी व प्रोसेसिंग से सम्बन्धित सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके लिए माल की गिरवी रखा जाता है। इसने सहकारी चीनी की फैक्ट्रियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

1. State Bank of India Monthly Review, April, 1989, p. 234.

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि भारतीय स्टेट बैंक बित्री व उपायन समूह भी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देता है। इस प्रकार यह सहकारिता को ग्राम-साथ के क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। मध्यम म गोदामों की व्यवस्था को बढ़ाने से स्टेट बैंक और भी ज्यादा साक्ष की सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस प्रकार ग्रामीण बात एकर करने और साथ की सुविधाएँ बढ़ाकर यह ग्रामीण अव्यवस्था को विकसित करने में यह वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks) व ग्रामीण साक्ष की व्यवस्था—जुलाई 1975 में घोषित नये ग्रामिण कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त देश में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने का निश्चय किया गया था। इसके लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 9 फरवरी 1976 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने जून 1988 के अन्त में 363 जिला में 196 बैंक स्थापित किये थे जिनके कार्यालय 31 दिसम्बर 1987 का 13 353 थे। इनका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश व बिहार में काफी विनाश हुआ है।

य बैंक लघु व सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों को कर्ज देने के लिए बनाये गये हैं। इनका उद्देश्य कृषि, व्यापार-वाणिज्य, उद्योग व उपायन विभाग के लिए साथ की सुविधाएँ प्रदान करना है। ये एक तरह व्यापारिक बैंकों से सम्पर्क रखते हैं तथा दूसरी तरह कृषि-मत्तक समितियों से।

इनकी शहर-पूँजी में केन्द्रीय सरकार का योगदान 50% राज्य सरकार का 15% तथा शेष (35%) सम्बद्ध व्यापारिक बैंक का होता है। इनका कार्य-क्षेत्र एक प्रदेश तक सीमित होता है। ये कम साधनवान श्रमिकों का कर्ज प्रदान करते हैं। इनकी उधार देने की दरें सहकारी समितियों की दरों से अनुरूप होती हैं।

ये साथ की वर्तमान समस्याओं—व्यापारिक बैंक तथा सहकारी समितियों के पूरक के रूप में काम करते हैं न कि इनके प्रतिस्थापन के रूप में। ये निर्धन लोगों को महाजनों के खगुल से मुक्त करने के लिए स्थापित किये गये हैं।

दिसम्बर 1987 के अन्त में 196 RRBs द्वारा प्रदत्त अग्रिम राशिवाँ (advances) 2232 करोड़ रु थी जबकि दिसम्बर 1986 के अन्त में ये 1784 करोड़ रु थी। इन्होंने अग्रिमवाँ कर्ज लघु व सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों व ग्रामीण कारीगरों को प्रदान किये हैं।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का नाबाई से पुनर्वित्त का सुत्रिका प्राप्त होनी है। RRBs ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा व्यापार, उद्योग व अय श्रियाओं पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया है।

कृषि-साक्ष की व्यवस्था को विकसित करने के लिए आवश्यक सुझाव
एक विनाशो-मुख अर्थ व्यवस्था के लिए एक उचित व प्रगतिशील साथ की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भारत में इसका तेजी से विकास किया जा

रहा है। कृषि-साख की व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्न गुभाव दिये जा सकते हैं—

(1) सहकारी साख और सहकारी बिजली के कार्यों में आवश्यक ताल-मेल स्थापित किया जाना चाहिए। कृषक को अपना उधार देते समय इस बात की व्यवस्था की जाय कि वह अपनी उपज प्रमुख सहकारी बिजली समिति के मार्फत ही वचें और इस सम्बन्ध में लिखित स्वीकृति दे। साख और बिजली का तात्प्रेत दोनों क्रियाओं को सफल बनाने में मदद देगा। (2) गाँवों में सहकारिता की भावना का ज्यादा प्रचार होना चाहिए। सहकारी सेवा समितियों (Service Co-operatives) की स्थापना की जानी चाहिए और उनके प्रबन्ध में सदस्यों की सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। (3) सहकारी साख समितियों के प्रौद्योगिक साधन बढ़ाये जायें जिससे वे किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्तरात्तर अधिक नाय ले सके। (4) व्यापारिक बैंकों को भी कृषि-साख में विशेष हितचक्षुषी दिलानी चाहिए। 20 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने इस दिशा में काफी प्रगति हो सकती है। (5) गोदाम बनाने का कार्यक्रम तभी से पूरा करना चाहिए जिससे साख की सुविधाएँ बढ़ सकें। (6) लघु व सीमान्त कृषकों व अन्य कारस्तकारों तक साख की सन्तुलित पहुँचाने के लिए जमानत के लिए 'भूमि' पर और न देकर 'बुझाने की योग्यता' पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। (7) जहाँ तक हो सके ऋण वस्तुओं के रूप में दिया जाय, न कि नकद रूप में। (8) यदि ऋण के लिए नकद राशि दी जाती है तो उसके उपयोग की देख-रेख विशेष रूप से की जाय। (9) कृषकों में बचत की भावना बढ़ाई जाय और प्राणीय बचत की एकत्र करने के सर्वोत्तम उपाय अपनाये जायें। (10) निचार्ड, चक-उन्दी, भूमि-मुधार आदि के एकीकृत कार्यक्रम को लागू करके कृषक की साख बढ़ायी जाय और अपनी प्रति स्थिति में सुधार किया जाय, (11) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) व ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP) सकल बनाए जाएँ, ताकि गाँवों में रोजगार व ग्रामदनी बढ़े तथा निर्धनता का कुछ सीमा तक उन्मूलन हो सके। अत्र जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण निर्धन परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति प्रति परिवार रोजगार प्रदान किया जायगा। इसके लिए पञ्चायती राज संस्थाओं को मुदूद किया जायगा।

कृषि-साख के क्षेत्र में नयी नीति

कृषि-साख के क्षेत्र में नई नीति के दो मुख्य पहलू हैं (1) बहु-एजेंसी (multi-agency) दृष्टिकोण का अपनाकर उत्तरात्तर मध्यमस्त साख का अधिक विकास करना, (2) बज्रों का उत्तरात्तर अधिक भ्रम निर्धन वर्ग के लोगों के लिए नियत करना, जैसे लघु व सीमान्त कृषक, भेतिहार श्रमिक तथा बर्दाश्तदारों को सहकारी व व्यापारिक बैंकों के बज्रों में अधिक हिस्सा दिलाना एवं प्रमुचित जाति

व अनुसूचित जनजाति के लोगों को बर्ज देने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास करना ।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (नाबार्ड) की स्थापना की है जिससे इस दिशा में एक नया व महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में कृषिगत साख के सम्बन्ध में लक्ष्य व नीति

छठी पंचवर्षीय योजना में सहकारिताओं व व्यापारिक बैंको (प्रादेशिक ग्रामीण बैंको सहित) द्वारा कृषि के लिए सत्यागत साख का काफी विस्तार किया गया था । 1979-80 में इनके द्वारा 2550 करोड़ रु की कृषिगत साख का वितरण किया गया जिसका स्तर 1984-85 में बढ़कर 5810 करोड़ रु हो गया जो 5415 करोड़ रु के लक्ष्य से अधिक था । छठी योजना में सहकारी संस्थाओं व व्यापारिक बैंको द्वारा साख प्रदान करने की विधियों में सुधार करने, कर्ज की समय पर वसूली करने, भोवरड्यूज को कम करने तथा साख को एक समूह से दूसरे समूह व एक जगह से दूसरी जगह गतिशील करने पर ध्यान दिया गया ताकि निर्धन-वर्ग को कर्ज की सुविधा बढ़ायी जा सके ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य का विस्तार किया गया है । उपरोक्त एजेन्सियों द्वारा 1989-90 तक के लिए कृषिगत साख का लक्ष्य 12570 करोड़ रु रखा गया है जो 1984-85 के स्तर (5810 करोड़ रु) से लगभग दुगुना है । 1989-90 के लक्ष्य में सहकारी संस्थाओं का अंश 7070 करोड़ रु तथा व्यापारिक बैंको व (प्रादेशिक ग्रामीण बैंको सहित) 5500 करोड़ रु रखा गया है । सातवीं योजना में कृषिगत साख के सम्बन्ध में नीति

1. समाज के कमजोर वर्गों, कम विकसित क्षेत्रों, विशेषतया उत्तर-पूर्वी प्रदेश, सूखी खेती के क्षेत्रों व दाल तथा तिलहन के विकास के लिए कर्ज की सुविधा बढ़ाई जायगी ।

2 कर्ज की वसूली पर ज्यादा ध्यान दिया जायगा ।

3 साख-नियोजन (Credit planning) का अधिक प्रयास किया जायगा ताकि राष्ट्रीय, राज्यीय व जिला स्तरों पर समन्वित रूप में कृषिगत साख का विकास किया जा सके ।

4 संस्थागत एजेन्सियों की मानवीय शक्ति, वित्तीय साधन व उधार देने की विधियों को सुदृढ़ किया जायगा । प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने पर अधिक जोर दिया जायगा ताकि साख के अलावा अन्य क्रियाओं का विस्तार किया जा सके ।

केन्द्रीय सहकारी बैंको, राज्य सहकारी बैंको व भूमि विकास बैंको को सुदृढ़ किया जायगा । अभी तक सिंचित क्षेत्रों में घान व गेहूँ की फसलों के लिए अधिक

कर दिया गया है, नविष्य में मूखी खेती के इलाकों व दाल तथा निलहन की खेती का विस्तार करने के लिए कर्ज की सुविधा बढ़ाई जायेगी।

5 विभिन्न संस्थागत एजेंसियों के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य-स्तरीय समन्वय समितियाँ स्थापित की गई हैं। लेकिन इनके काम में वित्त प्राप्ति नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक का कर्ज भी उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ा है जहाँ पहले से सहकारी गणना अधिक भजवूत पाया गया है। सातवी योजना में जिला-स्तर पर योजनाएँ (district credit plans) बनाकर विभिन्न एजेंसियों के कामों में अधिक सार्वजनिक स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

अतः नविष्य में कृषिगत साख में मात्रारमक व गुणवत्तक दोनों प्रकार के सुधारों से ही उत्पादकता में वृद्धि होगी। कर्ज की वसूली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 1985 को प्रान्सर ए एम सुसरो की अध्यक्षता में कृषिगत साख की समीक्षा के लिए एक वरिष्ठ अध्ययन दल नियुक्त किया है जो इसको सुदृढ़ करने के उपाय सुझायेगा।

प्रश्न

- 1 भारत में ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोतों का साख में महत्व बताइए। पिछले बीस वर्षों में साख के सम्बन्धित स्रोतों की प्रगति का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। (Raj Hys T D C 1984)
- 2 भारत में कृषि साख प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत क्या हैं? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली नृत्तिपय एजेंसियों के योगदान व प्रगति की संक्षेप में समझाइए। (Raj Hys T D C 1983)
- 3 भारत में कृषि साख प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत क्या हैं? पिछले बीस वर्षों में साख के सम्बन्धित स्रोतों की प्रगति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। (Raj Hys T D C 1986)

उत्तर-संकलित—कृषिगत साख के प्रमुख स्रोतों को दो भागों में बाँटा जाता है

- (1) निजी इसमें महाजन किसान के मित्र व सम्बन्धी जमींदार, बंगरा घात हैं
- (2) संस्थागत इसमें महावारियाँ व्यापारिक बैंक (शारदिक ग्रामीण बैंकों सहित) सरकार आदि प्रात हैं। भारत में पिछले वर्षों में संस्थागत स्रोतों से कृषि-साख का काफी विस्तार हुआ है।

जून 1969 के अन्त में सावजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा कृषि की प्रदत्त प्रत्यक्ष कर्ज की वसूली राशि 40.2 करोड़ रु थी जबकि जून 1987 के अन्त में 9300 करोड़ रु हो गई। इस अवधि में परमाण कर्ज की वसूली राशि 122 करोड़ रु से बढ़कर 1366 करोड़ रु हो गई।

जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना से व्यापारिक व सहकारी बैंको के लिए पुनर्वित्त (refinance) की सुविधा काफी बढ़ गई है। इस सम्बन्ध में वितरित राशि 1986-87 में 1334 करोड़ रु से बढ़कर 1987-88 में 1482 करोड़ रु हो गयी है।

सहकारी संस्थाओं ने 1979-80 में विभिन्न अवधियों के कर्ज 1700 करोड़ रु के दिये थे, जो 1987-88 में बढ़कर लगभग 4057 करोड़ रु हो गये। 1988-89 के लिए कर्ज का लक्ष्य 5441 करोड़ रूपयों का तथा 1989-90 के लिए 7070 करोड़ रु का रखा गया है।

इस प्रकार व्यापारिक बैंको प्रादेशिक धामीण बैंको व सहकारी संस्थाओं द्वारा साख की मात्रा में काफी वृद्धि की गई है।

लेकिन पिछले वर्षों में संस्थागत कृषि-साख के सम्बन्ध में निम्न समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिनका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए—

(i) इनके लिए ओवरड्यूज की समस्या गम्भीर हो गई है। कोषों का प्रवाह बढ़ाने के लिए कर्ज की वसूली पर जोर देने की नितांत आवश्यकता है।

(ii) इन एजेंसियों के लिए मानवीय शक्ति, वित्तीय साधना व कर्ज देने की विधियों की समस्या जटिल हो गई है।

(iii) विभिन्न एजेंसियों के कार्यों में परस्पर आवश्यक ताल-मेल स्थापित करने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है।

भूगामी वर्षों में जिला-साख योजनाएँ बनाकर संस्थागत कृषि-साख से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। राज्य स्तरीय समन्वय समितियों को अधिक सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। सरकार ने 1987-88 में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज की अदायगी की अवधि फिर से निर्धारित की है तथा अल्पकालीन कर्जों की मध्यमकालीन कर्जों में बदलने की सुविधा दी है एवं कुछ मामलों में ब्याज की दर घटायी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को निर्देश दिया गया है कि वे 1988-89 के अन्त तक अपने कुल कर्ज का 17% अथवा कृषि को प्रत्यक्ष विरा के रूप में प्रदान करें। कृषकों को राहत पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि-साख राहत-कोष स्थापित किया गया है। भविष्य में ओवरड्यूज की समस्या का समाधान निकालने पर काफी जोर दिया जा रहा है।

4 टिप्पणी लिखिये —

(i) भारत में कृषि साख का प्रमुख स्रोत।

(Raj Hyr T. D. C, 1989)

कुटीर एवं लघु उद्योग

(Cottage and Small Scale Industries)

भारत के आर्थिक विकास में कुटीर, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरकार ने सदैव ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर बल दिया है और योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास को रोजगार-नीति में केन्द्रीय स्थान दिया गया है। कुछ लोगों का मत है कि यदि भूतकाल में ग्रामीण उद्योगों के विकास पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाता और इसके सम्बन्ध में विकास के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते तो भारत की आर्थिक स्थिति आज की तुलना में काफी बेहतर होती। भारतीय लोकदल के नेता स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह का यह मत विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि “यदि मिलों का सारा वस्त्र निर्यात कर दिया जाय और देशवासी सादी, हथकरघा व शक्ति करपा पर बने वस्त्रों का ही उपयोग करें, तो देश से बेरोजगारी दूरतः समाप्त की जा सकती है।” इन विचारों से चाहे हम पूर्णतया सहमत न हों, लेकिन इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर व लघु उद्योगों का महत्व अवश्य स्पष्ट हो जाता है।

हम इस अध्याय में कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याओं व योजनाकाल में ऐसी प्रगति, आदि की चर्चा करेंगे। प्रारम्भ में कुछ परिभाषाएँ देना उचित होगा।

आर्थिक साहित्य में प्रायः कुटीर, ग्रामीण व लघु उद्योगों की एक साथ चर्चा देखने को मिलती है। लेकिन वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से यह उचित नहीं है क्योंकि लघु उद्योग प्रायः आधुनिक क्षेत्र (modern sector) में आते हैं, जबकि कुटीर व ग्रामीण उद्योग परम्परागत क्षेत्र (traditional sector) में आते हैं। कुटीर या घरेलू या ग्रामीण उद्योगों में बहुधा पारिवारिक धर्म का उपयोग किया जाता है। ये स्थानीय व विदेशी दोनों प्रकार की माँग की पूर्ति कर सकते हैं। भारत में हाथ-करपा उद्योग राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कुटीर व ग्रामीण उद्योग माना जाता है।

1987-88 में हथकरघा क्षेत्र में 85.33 लाख व्यक्तियों को रोजगार (अश-कालिक सहित) मिला हुआ था।¹

खादी दूसरा ग्रामीण या कुटीर उद्योग है जिसमें 1987-88 में 14.0 लाख व्यक्ति कार्यरत थे। इसके अलावा बहुत से कारीगर अन्य ग्रामीण उद्योगों में लगे हुए हैं। ग्रामीण उद्योगों में कृषि के सहायक धन्धों के अलावा कुछ अन्य उद्योग भी आते हैं। विभिन्न ग्रामीण उद्योगों में बागवानी, पशुपालन, मछली-पालन, मुर्गी-पालन, रेशम के कीड़े पालना (sericulture), रस्सी तथा चटाई बनाना, वास और बेत का सामान बनाना, कुटीर माचिस उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाना, साबुन, कुटीर चमड़ा उद्योग, चपड़ा उद्योग, फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग, हाथ से धान बूट कर चावल तैयार करना, सूत कातना, केन व पॉम-गुड तथा खाड़सारी का उत्पादन करना तथा मधुमक्खी पालन, आदि आते हैं।

गाँवों में रोजगार देने व लोगों की आय बढ़ाने की दृष्टि से कृषि के सहायक उद्योग-धन्धों का समुचित विकास करना आवश्यक है। आजकल निर्धनता-निवारण की दृष्टि से भी इनका महत्व बढ़ गया है। इनके अलावा अन्य ग्रामीण उद्योग जैसे जूते बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का सामान बनाना, आदि पर भी यथोचित ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि के सहायक धन्धे तो बहुधा कृषक को अधिक काम देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गये हैं। 1987-88 में खादी, ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा, रेशम, दस्तकारी व नारियल की जटा के उद्योगों में कुल लगभग 2.26 करोड़ व्यक्ति काम पाये हुए थे। इसके अलावा आधुनिक उद्योगों जैसे लघु उद्योगों व पावरलूम में 1.41 करोड़ व्यक्ति कार्यरत थे। इस प्रकार ग्रामीण व लघु उद्योग क्षेत्र (Village and Small Industries Sector) (VSI sector) में 1987-88 में कुल 3.67 करोड़ व्यक्ति काम पाये हुए थे जिसमें पूर्णकालिक व अशकालिक दोनों प्रकार के रोजगार शामिल हैं। इनमें अशकालिक रोजगार काफी लोगों को मिला हुआ है।

भारत में लघु इकाइयाँ परम्परागत लघु क्षेत्र व आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र दोनों में पायी जाती हैं। परम्परागत उद्योगों में खादी, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, रेशम, दस्तकारी व नारियल जटा के उद्योग आते हैं तथा आधुनिक लघु उद्योगों में पावरलूम, इन्जीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़, दवा आदि से सम्बन्धित बहुत से लघु उद्योग आते हैं। अब हम लघु उद्योग की वर्तमान परिभाषा को स्पष्ट करेंगे।

-
1. Annual Plan, 1988-89, p. 203, आगे भी 1987-88 के आंकड़े इसी स्रोत से लिए गये हैं।

15 मार्च 1985 को वित्त मन्त्री ने 1985-86 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय लघु उद्योगों के लिए सयंत्र व मशीनरी (plant and machinery) में विनियोग की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दी थी तथा सहायक उद्योगों (ancillary industries) के लिए 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी थी। इससे पूर्व जुलाई, 1980 में 'टाइनी' (प्रति लघु) इकाइयों के लिए सयंत्र व मशीनरी में विनियोग की सीमा एक लाख रु. से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई थी।

अति लघु, लघु व सहायक इकाइयों के लिए विनियोग की सीमाएँ बढ़ाने से पश्चिम मात्रा में लघु इकाइयाँ इनको मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी जिनसे अपेक्षाकृत अधिक इकाइयों का आधुनिकीकरण करना सम्भव हो सकेगा।

विवेचन की सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि परम्परागत लघु उद्योग में खादी, हथकरघा, लाख-तेल, नारियल के रेशे (coir) से बने पदार्थ, बमटा उद्योग, आदि आते हैं तथा आधुनिक लघु उद्योगों में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं। ये पम्प सेट, सीजल इ. जन, विद्युत मोटर्स, घड़ियाँ, रेडियो, ट्रांजिस्टर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट, बिजली के पत्ते, सिलाई की मशीनें, बुनाई की मशीनें, साइकिलें, बिजली के तार, प्लास्टिक व रबर की वस्तुएँ, मिश्रक-फ्राइडर्स, टेपरिवाइंडर, ऑप्टिकल लेन्सेज, टेलेस्कोप लेन्सेज, कंमरा, वैज्ञानिक यंत्रादिक, अनेक प्रकार के घरेलू विद्युत-उपकरण, होजियरी का सामान, इकाइयाँ आदि बनाती हैं जिनकी खपत देश-विदेश में हो सकती है। इस प्रकार ग्रामीण व लघु उद्योगों का अपना-अपना क्षेत्र होता है। भारतीय परिस्थितियों में ग्रामीण उद्योगों को विकास के क्रम में सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इन्हीं के विकास पर लाखों गाँवों तथा ग्रामवासियों, जनवासियों, व गिरिवासियों का आर्थिक जीवन निर्भर करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का महत्त्व

प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के वस्त्रों की मांग विदेशों में बहुत होती थी। भारत अपने कारीगरों की प्रतिभा व कला के लिए दूर-दूर तक विख्यात था। यह स्थिति कई शताब्दियों तक चलती रही। भारत में अंग्रेजी राज के दिनों में भारतीय वस्त्रों का विदेशों में बड़ा आदर होता था और बदले में भारत को कीमती धातु प्राप्त होती थी। शिथिल काल में हमारे कुटीर उद्योगों की तैयारी से प्रेरणा मिली है। परन्तु यह स्थान देने की बात है कि अवनति के बावजूद आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका

अँचा स्थान है और योजनाओं में भी सदैव इनका महत्व स्वीकार किया गया है जिसके निम्न कारण रहे हैं —

1 रोजगार—परम्परागत ग्रामीण व आधुनिक लघु उद्योगों में सलग्न व्यक्तियों की सख्या का सही अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि ये उद्योग देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। फिर भी इनमें काफी लोग काम पाये हुए हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है। 1987-88 में अकेले हथकरघा उद्योग में लगभग 85.33 लाख व्यक्ति रोजगार पाये हुए थे। इसी वर्ष खादी व ग्रामीण उद्योगों में 40.5 लाख व्यक्ति लगे हुए थे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है। 1987-88 में सभी प्रकार के ग्रामीण व लघु उद्योगों (VSI sector) में 3.67 करोड़ व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ था जो विनिर्माण क्षेत्र में कुल औद्योगिक रोजगार का 80% था। भविष्य में भी इनमें काफी सख्या में अतिरिक्त लोगों को काम दिया जा सकता है। 1989-90 के लिए इनमें रोजगार का लक्ष्य 4 करोड़ व्यक्तियों का रखा गया है। इस प्रकार देश में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से इनका स्थान काफी अँचा है। भविष्य में भी रोजगार देने के लिए हमारे पास कुटीर एवं लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य साधनों का अभाव रहेगा। कुटीर एवं लघु उद्योग बड़े-रोजगार या अल्परोजगार की समस्या को हल करने में मदद देते हैं। किसान अवकाश के समय कृषि के सहायक धन्धों में काम करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं तथा अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं।

2 उत्पादन का मूल्य—देश में कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग आधा अंश ग्रामीण व लघु उद्योगों से प्राप्त होता है। 1987-88 में ग्रामीण व लघु उद्योगों के क्षेत्र (VSI sector) में प्रचलित मूल्यों पर 85,790 करोड़ रुपये की उत्पत्ति हुई। CSO के अनुसार VSI क्षेत्र की उत्पत्ति का मूल्य विनिर्माण क्षेत्र के कुल योगदान का लगभग आधा रहता है। 1989-90 में इनके उत्पादन का मूल्य सम्भवतः एक लाख करोड़ रु की सीमा के आगे निकल जायगा। इनमें बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूँजी से ज्यादा माल बनाया जा सकता है। छोटे पैमाने की इकाइयाँ बड़े पैमाने की इकाइयों की तुलना में प्रति रुपये विनियोग पर अधिक माल का उत्पादन भी करती हैं। महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु में लघु उद्योगों की पहले से ही काफी प्रगति हो चुकी थी। लेकिन पिछले वर्षों में पंजाब में इनकी विशेष रूप से प्रगति हुई है। लघु उद्योगों की विशेष प्रगति वस्त्र, मशीनरी, धातु व विद्युत के साज-सामान के निर्माण में हुई है। फूड-प्रोसेसिंग का कार्य (अनाज व दाल आदि का) व वस्त्रों में आज भी माल के मूल्य व इकाइयों की सख्या की दृष्टि से इनकी प्रधानता बनी हुई है। लेकिन साथ में कई नये उद्योग भी पनप रहे हैं।

3 छोटे पैमाने की इकाइयों की बड़े पैमाने की इकाइयों की तुलना में उत्पादन कार्यकुशलता—प्रायः छोटी इकाइयों की उत्पादन सम्बन्धी कार्यकुशलता की

तुलना बड़े पैमाने की इकाइयों में की जाती है। यदि पैंकट्री ग्ज़र से नीचे की लघु इकाइयों को शामिल किया जाय तो लघु उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा घट जाता है। जैसे वस्त्रोद्योग में हथकरघा, शक्ति करघा तथा छादी सभी विवेन्द्रित क्षेत्र में आते हैं, एक कुल उत्पत्ति का लगभग आधा भग्न प्रदान करते हैं। इस प्रकार लघु उद्योगों का उत्पत्ति में भारी योगदान होता है।

4. कम पूँजी व अधिक धन की स्थिति में उपयुक्त—भारत में पूँजी का अभाव है, जबकि धन-शक्ति का आधिक्य पाया जाता है। इसलिए हमें ऐसी उत्पादन-विधियाँ अपनानी पड़ेंगी जिसमें पूँजी कम लगे और अधिक अधिक मजदूरी में काम पा सकें। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूँजी ज्यादा लगती है और रोजगार कम लोगों को मिलता है। कुटीर उद्योगों में कम पूँजी से ही काम चल जाता है और ज्यादा लोगों को काम मिलता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि छोटे पैमाने के उद्योगों में मशीनों व शक्ति पर व्यय करने के लिए पूँजी की आवश्यकता कुटीर उद्योगों की तुलना में अधिक होती है। भारत के प्रत्येक गाँव में कुटीर उद्योगों का विकास किया जाय तो श्रो-धन का भी उपयोग हो सकेगा और देश की कुल सम्पत्ति बढ़ेगी। तुलनात्मक आँकड़ों से पता चलता है कि एक लाख घरों के विनियोजन से बड़ी इकाई में केवल 4 व्यक्तियों को, लघु इकाई में 20 से 25 व्यक्तियों को तथा ग्रामीण उद्योगों में लगभग 70 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। इससे ग्रामीण व लघु उद्योगों की धन गहना, अर्थात् अधिक अधिकों को काम दे सकने की क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है।

5. आर्थिक शक्ति का समान वितरण—पूँजीवादी धर्मव्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों में धन व आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है, जिससे प्रायः की असमानता उत्पन्न होती है। कुटीर व लघु उद्योगों के विकास से आर्थिक समानता का वातावरण तैयार होता है। इनसे आर्थिक सत्ता का विवेन्द्रित-करण होता है। आर्थिक शोषण की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं। साथ ही गाँव व शहर की बीच की आर्थिक खाई कम हो जाती है। गाँवों में उद्योग स्तपने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और वे स्वयं के प्रयत्नों से ही अपना रहन-सहन का दर्जा उँचा करने में सफल हो सकते हैं।

6. रोजगार की अधिक स्थिरता—बड़े उद्योगों में माल की माँग घट जाने पर व्यापक रूप से बेरोजगारी फैलती है। लेकिन कुटीर एवं लघु उद्योगों में प्रायः तीव्र विस्म की मन्दो नहीं आती है और कारीगर देश के विभिन्न भागों में फैले होने के कारण किसी भी मकड़ का अघोषावृत्त अधिक सुगमता से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए इनमें रोजगार का अधिक स्थायित्व पाया जाता है। यह बात ग्रामीण उद्योगों पर अधिक लागू होती है।

7. सरल कार्य प्रणाली—कुटीर उद्योगों की स्थापना व कार्य प्रणाली अत्यन्त सरल होती है। इनके लिए उच्चकोटि के प्राविधिक विशेषज्ञों मैनेजरो, विशाल मयनो, विस्तृत हिसाब-किताब एवं प्रशिक्षण आदि के इन्तजाम नहीं करने पड़ते, जो बड़े पैमाने के उत्पादन में आवश्यक होते हैं। इस प्रकार उत्पादन कई प्रकार की कठिनाइयों से बच जाते हैं और सरलतापूर्वक अपना कार्य चला सकते हैं। इसलिए ग्रामीण व लघु उद्योग पिछड़े क्षेत्र व समाज के पिछड़े वर्गों के द्वारा भी चलाये जा सकते हैं।

8. परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा—इनके विकास से ही हम देश-वासियों की परम्परागत प्रतिभा व औद्योगिक दक्षता को बनाये रख सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में उत्पादन के अनेक कलात्मक कार्य प्रचलित हैं। उनके विकास की नितान्त आवश्यकता है। सभी राष्ट्रीय कला, दक्षता व प्रतिभा की रक्षा हो सकेगी, अन्धधा के कालान्तर में नष्ट हो जायेंगी।

9. सैनिक महत्व—यदि हमारी औद्योगिक शक्ति कुछ ही शहरों में केन्द्रित होती है तो शत्रु राष्ट्र हमें कभी भी भारी मुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन यदि छोटे उद्योगों के रूप में यह शक्ति सारे देश में फैली होती है तो हम आसानी से औद्योगिक दृष्टि से कमजोर नहीं हो सकते। अतः लघु उद्योगों का राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्व होता है।

10. औद्योगिक समस्याओं की कमी—कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने से हम बहुत सी औद्योगिक समस्याओं से बच जाते हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन से औद्योगिक क्षेत्रों में आवास की समस्या, गन्दा वातावरण, घालाबन्दी एवं हड़ताल आदि की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। छोटे पैमाने के उत्पादन में मालिक-मजदूर का सम्पर्क ज्यादा समीप का होता है। इसलिए बहुत सी समस्याएँ या तो उत्पन्न ही नहीं होती अथवा गम्भीर रूप धारण नहीं कर पाती। उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक नियमित व निरन्तर रूप से होता रहता है और प्रबन्ध आदि में भी सुविधा बनी रहती है।

11. उत्पादन की उत्तम दक्षिण—कुटीर व लघु उद्योगों में बने हुए माल की लागत चाहे ऊँची हो, लेकिन इनका माल प्रायः उत्तम, टिकाऊ एवं कलापूर्ण ढंग का होता है। छोटे उत्पादन में कारीगरों को अपनी कला को दिखाने का और माल में विविधता लाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। माल की कई प्रकार की विरसे बनाकर उपभोक्ता को अधिक सन्तोष प्रदान किया जा सकता है।

12. उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन—द्वितीय योजना के प्रारम्भ में अपनाई गयी विकास की महलनोबिस नीति में सुझाया गया था कि भारत के सीमित पूँजी-

गत मापनों का प्रयोग आधारभूत उद्योगों में किया जाना चाहिए और उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन विनियमना कुटीर व लघु उद्योगों द्वारा किया जाना चाहिए। उन समय यह सोचा गया था कि इससे मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिलेगी तथा जनता को उपभोग की आवश्यक वस्तुएँ भी उपलब्ध हो सकेंगी। बाद में इस नीति को दीर्घ से कार्यान्वित न कर सकने के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सके। लेकिन विकास की मूलभूत नीति के रूप में यह तत्कालीन परिस्थितियों में काफी सही नीति माना गया था। इस नीति में भारी उद्योगों के साथ-साथ पारिवारिक उद्योग (household industries) के विकास पर भी बल दिया गया था।

13 निर्यात-सवर्धन व देश को आत्म-निर्भरता की ओर ले जाने में सहायक-लघु उद्योग आयात-प्रतिस्थापन (import substitution) में मदद देते हैं और वे निर्यात की दृष्टि से भी महत्व रखते हैं। इन्होंने आयात-प्रतिस्थापन के माध्यम से प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की है। भारत में हथकरघे पर बना वस्त्र, रेगमी वस्त्र, नारियल के रेशे से बना माल, दस्तकारी का सामान काफी मात्रा में निर्यात किया जाता है और भविष्य में इस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

1987-88 में परम्परागत उद्योगों जैसे, खादी हथकरघा, रेगम उद्योग, दस्तकारी व नारियल की जटा के उद्योग का माल निर्यात करके लगभग 3358 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जन की गई थी। उनके अलावा लघु उद्योगों के माल का निर्यात करके 3300 करोड़ रु. प्राप्त किए गये थे। इस प्रकार ग्रामीण व लघु उद्योगों के माल का निर्यात करके कुल 6658 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जन की गई। भविष्य में इनमें वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा 1989-90 तक इस क्षेत्र से लगभग 7444 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जन करने का अनुमान लगाया गया है। इन प्रकार इनका निर्यात-सवर्धन में भी काफी योगदान होता है।

14 लघु उद्योगों की इकाइया बड़े पैमाने के उद्योगों की इकाइयों की सहायक हो सकती हैं। वे इनके लिए आवश्यक कल-सुर्जे व सहायक साज-सामान तैयार कर सकती हैं जिससे इनके कार्यों में परस्पर तात्-मेल बढ़ाया जा सकता है। पिछले वर्षों में सहायक इकाइयों (ancillary units) की संख्या में वृद्धि हुई है। भविष्य में सहायक इकाइयों के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं।

15 आबकत निर्धनता उम्मीद कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास पर अधिक धोर दिया जाने लगा है। इनके माध्यम से रोजगार व आम-दनी बढ़ाये जा सकते हैं। इनके पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास के कार्यक्रम रचे जाते हैं।

16 लघु इकाइयाँ बढ़ावा कच्चे माल की कमी आदि के कारण थोड़े समय के लिए रुका (sick) होती हैं, जबकि बड़ी इकाइयाँ रणनीति से लम्बी अवधि तक

प्रभावित हो जाती है। इसलिए लघु इकाइयों की हम्मतता की समस्या को हल करना अधिक आसान होना है।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ

बड़े कुटीर व लघु उद्योगों की समस्त समस्याएँ एकमो नही होती फिर भी उनमें कुछ समानता अवश्य होती है। इसलिए इनकी समस्याओं का बहुधा एक साथ विवेचन किया जाता है।

1. कच्चे माल की समस्या—कारीगरों को प्रायः उचित समय पर उचित किस्म का कच्चा माल उचित मूल्य पर एवं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। व स्थानीय व्यापारियों पर कच्चे माल के लिए निर्भर रहते हैं जो घटिया माल भी ऊँची कीमत पर देते हैं। भारत में बुनकरों को इस सम्बन्ध में काफी कठिनाई रही है। वे सूत के लिए मितो पर निर्भर करत हैं। यदि मित का सूत समय पर तैयार नहीं मिलता तो उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

लघु उद्योगों को भी दुर्लभ विदेशी कच्चा माल और बल-पुर्जों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार उन्हें कच्चा माल नहीं मिल पाता है। इनके मुकाबले बड़े कारखानों को कच्चा माल प्राप्त करने में आसानी होती है। परिणामस्वरूप, छोटी इकाइयों को अपनी आवश्यकता के बड़े अंश की पूर्ति खुले बाजार में ऊँचे मूल्य देकर करनी पड़ती है जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा में हानि उठानी पड़ती है। छोटी इकाइयों को प्राप्त होने वाले कच्चे माल में अधिक अनिश्चितता पायी जाती है। इन्फ़ोनियरी इकाइयों को प्रायः इस्पात की कमी का सामना करना पड़ता है। उन्हें उत्पादन-क्षमता के अनुसार कच्चे माल की सप्लाई की जानी चाहिए। छोटे व बड़े उद्योगों के बीच कच्चे माल वितरण में अन्तर्गत अन्तर्गत कच्चे माल का वितरण अधिक व्यवस्थित रूप से होना चाहिए।

2. उत्पादन का संगठन व उत्पादन की पद्धति कम कार्यकुशल व पुरानी—ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के कारीगर प्रायः असंगठित रूप में काम करते हैं। इनका सम्बन्ध अर्ध-व्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) से होता है। उनमें सहकारी संगठन का अभाव पाया जाता है। कारीगरों की शिक्षा व प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। इस क्षेत्र में आवश्यक अनुसन्धान व विकास का अभाव पाया जाता है। वे वर्षों से अपने पुराने व परम्परागत औजारों से काम करते चले आ रहे हैं। नये औजारों, यन्त्रों, मशीनों व पद्धतियों से वे अभी तक अपरिचित हैं अतः पुरानी उत्पादन-पद्धति को समाप्त करके नई अधिक कार्यकुशल पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक मात्रा में उतम व सस्ता माल बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में भारतीय कारीगरों की निरक्षरता एवं रूढ़िवादिता का उल्लेख करना भी आवश्यक है। अशिक्षित एवं परम्परावादी होने के कारण भारतीय कारीगर नवीन पद्धतियों को आसानी से नहीं अपनाते। अतः उनके काम में आवश्यक

कुछ सोमा तक कीमतें ऊँची होने पर भी खरीदा जाना चाहिए । इस समय लघु इकाइयों को 15% तक का कीमत-प्रधिमान मिला हुआ है ।

5. ऊँची लागत, ऊँचा मूल्य व कर भार—कुटीर व छोटे पैमाने पर बने हुए माल की लागत ज्यादा होने से प्रायः इनका मूल्य भी ज्यादा होता है । इसलिए इनकी माग कम हो जाती है । एक शिक्षायात यह भी की गई है कि व्यापारिक बैंक लघु उद्योगों से व्याज की ऊँची दर (प्रतिशत 15 प्रतिशत) वसूल करते हैं जिससे इन पर व्याज का भार भी काफी ऊँचा हो जाता है । नयी विधियों का प्रयोग करके ऊँची लागत व ऊँची कीमत का प्रश्न हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए ।

जहाँ तक करों का सम्बन्ध है, यह बतलाना आवश्यक है कि विशेषतया लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को करों की समस्या का सामना करना पड़ता है । यह समस्या कुटीर उद्योगों के मामले में नहीं है लेकिन यह लघु उद्यमकर्त्ताओं के सम्मुख अवश्य पायी जाती है । इन पर उत्पादन-शुल्क का भार होता है जिसे वे प्रायः उपभोक्ताओं पर डालने में असमर्थ पाये जाते हैं । इसी प्रकार इन पर विप्री-कर भी लगाया जाता है । इन दो करों के प्रतिरिक्त बारखाने वालों को आय-कर भी देना होता है । इस तरह उनके लाभ का बड़ा भाग कर देने में चला जाता है । नगरपालिकाएँ भी स्थानीय करों के रूप में इनसे कुछ राशि वसूल करती हैं । उत्पादन-शुल्क आदि के लिए रिकार्ड रखन व जटिल विधियों में पड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है । कर-विभाग के अधिकारी भी लघु इकाइयों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हुए पाये जाते हैं ।

इस वर्णन से स्पष्ट होता है हमारे देश में कुटीर एवं लघु उद्योगों के बीच भी एक-सी नीति नहीं बरती जाती । जितनी उदार नीति कुटीर उद्योगों के साथ बरती जाती है, उतनी लघु उद्योगों के साथ नहीं बरती जाती । केन्द्रीय सरकार ने लघु इकाइयों को लाभ पहुँचाने के लिये समय-समय पर करों में राहत दी है । वित्त मन्त्री ने 1989-90 में सघीय बजट में मुर्गीपालन (poultry farming) को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी आय में 33½% की दर से कर में छूट दी है, ताकि इसमें रोजगार बढ़ाया जा सके ।

6 समय पर भुगतान नहीं मिलना व माल का एकत्र हो जाना—छोटे पैमाने की इकाइयों को अपने माल का भुगतान समय पर नहीं मिलने से काफी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है । भुगतान में विलम्ब सरकारी विभागों की खरीद तथा निजी क्षेत्र की बड़ी इकाइयों की खरीद—दोनों में पाया जाता है । लघु इकाइयों को भुगतान अधिक भीघ्रता से मिलना चाहिए ताकि इन्हें अनावश्यक रूप से वित्तीय प्रभुविधा का सामना न करना पड़े ।

मन्दी की अवधि में लघु इकाइयों को कच्चा माल व निमित्त माल का स्टॉक जमा हो जाने से भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बड़े पैमाने की इकाइयाँ बहुधा कच्चा माल उधार सरीदती हैं व निमित्त माल नकद बेचती हैं, जबकि लघु इकाइयाँ अपना कच्चा माल नकद धरीदती हैं, व निमित्त माल उधार बेचती हैं, जिससे इनके समस्त प्रायः वायंशील पूँजी का अभाव उत्पन्न हो जाता है।

7. इन्फ्रास्ट्रक्चर (पावर) की कमी, लघु उद्यमकर्त्ताओं के लिए व्यावहारिक कठिनाइयाँ तथा सरकारी नीति का लघु उद्योगों पर दुष्प्रभाव—कुटीर एवं छोटे उद्योगों के सामने उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त नये यन्त्रों तथा डिजाइनों के लिए अनुसंधान की कमी, यातायात के साधनों के अभाव, प्रवन्चकीय दक्षता का अभाव, सस्ती शक्ति की कमी आदि प्रश्न भी होते हैं जिनका समुचित हल निकाला जाना चाहिए। वास्तव में सब प्रश्नों का एक माथ हल निकालने से ही इन उद्योगों की उन्नति की जा सकेगी। भारत में नामज पर तो लघु उद्योगों के प्रति बड़ी उदार नीति प्रतीत होती है लेकिन व्यवहार में इन्हे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक कंस्ट्रडी जानने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क स्थापित करना होता है, जैसे भूमि प्राप्त करने के लिए स्थानीय सत्त्वा से, पूँजी के लिए बैंकों या निजी से कच्चे भाग के लिए तीसरी सत्त्वा से, विद्युत के लिए राज्य विद्युत मण्डल से तथा रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य उद्योग-निदेशालय से, आदि आदि। इन सब कार्यों में काफी विलम्ब होता है एवं विभिन्न स्तरों पर आवश्यक काम करवाने के लिए काफी रुकड़ा भी व्यय करना होता है तथा लघु उद्यमकर्त्ता सभी तरह की औपचारिकताएँ पूरी करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए उत्पादन पर पूरा ध्यान दे सकना कठिन हो जाता है। पहले यह भाषा की गई थी कि जिला-उद्योग-केन्द्रों (DICs) की स्थापना से इस सम्बन्ध में सुविधा बढ़ेगी, लेकिन इस दिशा में अभी तक विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। कुछ परिस्थितियों में लघु उद्योगों को दक्ष कारीगर नहीं मिल पाते जिससे भात की क्रिम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

हाल में दवाई उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर देने से इन उद्योगों की लघु इकाइयों के समस्त स्टॉक उपस्थित हो गया है, क्योंकि बड़ी इकाइयों का उत्पादन बनाने का अधिक अवसर मिल गया है। इसी प्रकार नई दस्त्र-नीति (जून 1985) के अनुसार पावर लूम व मिल लूम की समान भात लेने में पावर लूम क्षेत्र के लिए नई कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं। मितो के प्रायुनिकीकरण से इस पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। पावर लूम में लगे लघु उद्यमकर्त्ताओं के लिए उत्पादन-सागत जैसी आती है।

कुटीर व लघु उद्योगों के लिए नई संगठन

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्नशील रही है। 1948 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में

कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व स्वीकार किया गया था। 1956 की नयी औद्योगिक नीति में उसे पुनः दोहराया गया। 23 दिसम्बर 1977 को तत्कालीन जनता सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में ग्रामीण व लघु उद्योगों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की और इनके विकास के लिए जिला-उद्योग केन्द्र (DICs) स्थापित करने पर विशेष रूप से बल दिया तथा अति लघु क्षेत्र (tiny sector) के विचार को भी बढ़ाया ताकि सयन्त्र व मशीनरी में 1 लाख रु तक की सीमा वाली इकाइयाँ के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। जुलाई 1980 में कांग्रेस (आई) सरकार के औद्योगिक नीति वक्तव्य में इनके महत्व को पुनः स्वीकार किया गया। पूर्व-योजनाओं में इनके विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और अन्तर्राष्ट्रीय योजना-दल (1954) वर्ष समिति (1955) व अन्तर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन योजना-दल (1963) के सुझावों को अपनाने का प्रयत्न किया गया था। प्रथम योजना में अन्तर्राष्ट्रीय योजना-दल के सुझाव के अनुसार चार प्रादेशिक लघु उद्योग-संस्था-संस्थान (SISI) स्थापित किये गये और 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम योजना की अवधि में केन्द्र ने विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए 6 बोर्ड भी स्थापित किये। इनमें से कुछ का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है—

1. अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड (All India Handicraft Board)—यह नवम्बर 1952 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य कार्य उत्पादन व विपरी बढ़ाने का रखा गया था। अप्रैल 1958 में भारतीय हस्तकला विकास निगम स्थापित हुआ जो निर्यात बढ़ाने में सहायता दे रहा है। देश में हस्तकला सप्ताह मना कर निर्मित वस्तुओं का प्रचार किया जाता है। 1987-88 में दस्तकारी के सामान का निर्यात लगभग 3253 करोड़ रुपये का हुआ जो निर्यात की मदों में सर्वोच्च स्थान पर था। इसमें मोती, कीमती व अर्द्ध-कीमती स्टोन्स के निर्यात की राशि 2614 करोड़ रु. थी।

2 अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामउद्योग बोर्ड (All India Khadi and Village Industries Board)—जनवरी 1953 में एक खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित किया गया था। 1956 में खादी व ग्रामोद्योग बमोशन (KVIB) भी स्थापित किया गया। इसके पास खादी व अन्य 25 चुने हुए ग्रामोद्योगों के विकास का कार्य है, जैसे साबुन बनाना, तेल निचालना, घान बूटना, दियासलाई बनाना, हाथ का कागज बनाना, मधुमक्खी-पालन, चमड़े का सामान बनाना, घाटे की चक्रिया और गांव में मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। राज्यों में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) बनाये गये हैं। इस समय 26 KVIB, 1114 पजीकृत संस्थाएँ व 30 008 सहकारिताएँ 1.5 लाख गाँवों में फैली हुई हैं। खादी व ग्रामीण उद्योग समिति (ग्रामोक्त मेहुता समिति) ने सुझाव दिया था कि खादी व ग्रामीण उद्योग

कमीशन को ग्रामीण उद्योग कमीशन (Rural Industries Commission) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। KVIC की क्रियाएँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर-प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में अधिक केन्द्रित हैं। खादी में 3 रोजगार उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा गुजरात में केन्द्रित हैं। खादी में ज्यादा व्यक्तियों को प्रशकालिक रोजगार प्राप्त हो पाया है।

अन्य बोर्ड इस प्रकार हैं : अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, नारियल रेशम बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और लघु उद्योग बोर्ड।

इनके प्रतिष्ठित कुटीर एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिए पिछले वर्षों में कुछ और संगठन बनाये गये हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है

1. लघु उद्योग सेवा संस्थाएँ (Small Industries Service Institutes)—

इस प्रकार की चार संस्थाएँ दिल्ली, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में स्थापित की गयी हैं। इनकी स्थापना का मुझाव प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल ने दिया था। ये छोटे उद्योगों को उत्पादन की विधियाँ, बिक्री एवं प्रबन्ध आदि सुधारने में मदद देती हैं तथा मशीनें, कच्चा माल व पूँजी प्राप्त करने में सहायता पहुँचाती हैं। इस प्रकार ये व्यापारिक एवं औद्योगिक सेवाएँ प्रदान करती हैं।

2. औद्योगिक विस्तार सेवा (Industrial Extension Service)—

लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) के अन्तर्गत 27 लघु उद्योग सेवा-संस्थान, 31 शाखा संस्थान एवं कुल 37 विस्तार/उत्पादन/प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनका कार्य प्राविधिक सलाह देना एवं प्रबन्ध के सर्वोत्तम तरीके सुझाना है।¹

3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (The National Small Industries Corporation Limited)—

यह फरवरी, 1955 में स्थापित किया गया था। इनमें समस्त पूँजी भारत सरकार द्वारा लगायी गयी है। इसका सम्बन्ध लघु इकाइयों से है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं

(अ) सरकारी विभागों के लिए छोटे पैमाने पर बनी हुई वस्तुएँ खरीदने की व्यवस्था करना तथा लघु इकाइयाँ को माल बनाने के लिए आर्डर देना, (आ) आर्डर के अनुसार माल बनाने के लिए पूँजी व तकनीकी सहायता प्रदान करना, (इ) बड़े पैमाने एवं छोटे पैमाने में तार-मेल बैठाना जिससे छोटे पैमाने पर सहायक माल बनाया जा सके (ई) बिजली की सुविधाएँ बढ़ाना एवं इसके लिए प्रदर्शनियो, मत्त-ह-समारोहों और विक्रय-केन्द्रों की व्यवस्था करना (उ) किश्तों पर मशीनें देना, (ऊ) इनमें प्रोत्साहन (नई दिल्ली हावड़ा मद्रास व राजकोट में 4 प्रोटोटाइप उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र खोलें हैं जहाँ मशीनरी के प्रोटोटाइप विकसित करके टक्नोलोजी के अंतरण (transfer) की व्यवस्था की गई है।

किशोरो पर मशीनें आदि खरीदने के प्राथमिकता-पत्र पहले सेवा-संस्थानों के पास आते हैं। इनकी वहाँ जाँच होती है और फिर ये राष्ट्रीय उद्योग निगम को भेज दिये जाते हैं। यह निगम मशीनें बनाने वालों को मांडर देता है और मशीनें खरीदने वालों से पेशगी वसूल करता है। इसने निर्यात, कच्चे माल के वितरण, मशीनों और औजारों की बिजली, केन्द्रीय सरकार के स्टोर क्रय-कार्यक्रम (Store Purchase Programme) के अन्तर्गत कई समझौते करने व प्रोटोटाइप-विवास व प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम भी पूरे किये हैं। निगम के समक्ष उधार लेने वालों के द्वारा विपत्तियों के न चुकाये जाने की समस्या काफी जटिल हो गयी है। अधिकांश इकाइयों को बड़ी इकाइयों की प्रतिस्पर्धा, कांश्चील पूँजी के अभाव, कच्चे माल की कमी, पावर कटौतियों आदि का सामना करना पड़ रहा है जिससे किशोरों की रकम वसूल करना व्यवहार में बहुत कठिन हो गया है। NSIC विकासशील देशों जैसे तन्जानिया, नाइजीरिया व कीनिया की टर्न-की (Turn-key) आधार पर प्रोजेक्टों के निर्यात की भी व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था में निगम उन देशों में समस्त प्रोजेक्ट का काम करता है तथा उसको चालू करने तक के विविध कार्यों का संचालन करता है।

4 औद्योगिक बस्तियाँ (Industrial Estates)—औद्योगिक बस्तियों में बहुत से लघु उद्योग एक स्थान पर चलाये जाते हैं ताकि कच्चे माल, बिजली, पानी, यातायात, बैंकिंग आदि की इकट्ठी सुविधाएँ मिल सकें। ये कार्यक्रम ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा सफल हुए हैं। औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम जनवरी, 1955 में प्रारम्भ किया गया था और इसे लागू किये काफी वर्ष हो गये हैं। इस समय देश में 800 से अधिक औद्योगिक बस्तियाँ हैं, हालांकि ये सभी काम नहीं कर रही हैं। इनके निर्माण पर करोड़ों रु. व्यय किये गये हैं। इनके माध्यम से लघु उद्योगों का विकास किया गया है ताकि रोजगार बढ़ाया जा सके।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक बस्तियों का चुनाव काफी सावधानी से किया जाना चाहिए। कच्चे माल, परिवहन, जल व शक्ति की सप्लाई व उपलब्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे बस्तियाँ उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास का मुख्य भूग बन सकें जिनमें विकास की सम्भावनाएँ अधिक हैं। औद्योगिक बस्तियों में रोजगार बढ़ाने पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इनको ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए जिससे कृषि में यन्त्रीकरण, कृषिगत उपज में सुधार एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोत्साहन मिल सके। शिक्षित बेरोजगारों व इन्जीनियरों को बहुत उदार शर्तों पर शेड्स मिलने चाहिए। औद्योगिक बस्तियाँ बनने से पूर्व उस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर—सड़क, रेल, विद्युत तथा जल आदि की व्यवस्था—को अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इनके अभाव में आगे चल कर इनके बन्द पड़े रहने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

घन्य सवर्धनात्मक संस्थाएँ—छोटी योजना की अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए कुछ और संस्थाएँ स्थापित की गई हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—
 (i) टूल डिजाइन का केन्द्रीय संस्थान (Central Institute of Tool Design) (C I T D), (ii) विद्युत माप-यन्त्रों का डिजाइन का संस्थान (Institute for Design of Electrical Measuring Instrument) (I D E M I), (iii) लघु उद्योग विस्तार व प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Small Industry Extension and Training) (N I S I E T) व (iv) उद्यमशीलता व लघु व्यवसाय विकास, प्रादि के लिए राष्ट्रीय संस्थान (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development etc) (NIES-BUD)। इन विभिन्न संस्थाओं की स्थापना से डिजाइन, विस्तार प्रशिक्षण, उद्यमशीलता व लघु व्यवसाय के विकास में मदद मिलने की आशा है।

कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकारी उपाय

सरकार ने कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए कई उपाय काम में लिए हैं जिनका सम्बन्ध विशेषतया इनके लिए कच्चे मास पूर्ण, तकनीकी सहायता, बिजली प्रादि की सुविधाओं से रहा है। इनका वर्णन नीचे किया जाता है।

1 **व्यापक सहायता कार्यक्रम**—भारत सरकार ने लघु उद्यमकर्ताओं को सहायता देने के लिए व्यापक सहायता कार्यक्रम अपनाया है। लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) के मातहत लघु उद्योग सेवा-संस्थान (SISI) शाखा-संस्थान व विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। SIDO प्राथमिक, तकनीकी व प्रबन्धीय सेवाएँ उपलब्ध करता है। राज्यों में उद्योग-निदेशालय भूमि या फैक्ट्री शेड प्रावदित करते हैं तथा इनके लिए कच्चे मास व पूँजी की उपलब्धि में सहायता करते हैं।

2 **लघु उद्योगों के लिए क्षेत्र सुरक्षित करने (रिजर्वेशन) की नीति**—बड़े पैमाने की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पादन को छोटे पैमाने के लिए रिजर्व या नियत कर दिया गया है। लगभग 5000 मदीयों में से 873 मदीयों का उत्पादन पूर्णतया लघु पैमाने के उद्योगों के लिए नियत (रिजर्व) किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने एस डी श्रीवास्तव समिति के सुझावानुसार जनवरी 1986 में 2550 मदीयों को रिजर्व सूची से हटाने का फैसला किया। इसका कारण यह है कि कई वर्षों तक इन उद्योगों का विकास नहीं हो पाया—मान की मात्रा व पैमाने प्रावश्यकतानुसार नहीं बन पायी। इनमें उच्च टेक्नोलॉजी व ऊँची पूँजी की प्रावश्यकता के कारण पर्याप्त विनियोग नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का प्रवेश हो गया जिससे इनकी लघु उद्योगों की रिजर्व सूची से हटाना प्रावश्यक हो गया।

3 **दुर्लभ कच्चे मास का आबंटन**—सरकार स्वदेशी व विदेशी कच्चे मास के आबंटन में लघु उद्योगों के हितों का ध्यान रखने लगी है। पिछले वर्षों में भारत

सरकार की आयात-निर्यात नीति में लघु इकाइयों को आयात लाइसेंस देने में अधिक उदारता बरती गयी है। लघु इकाइयों के लिए कच्चे माल, मशीनरी व कलपुर्जों के आयात की व्यवस्था बढ़ायी गयी है।

4. वित्तीय सहायता—लघु उद्योगों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सरकारी व सस्थागत एजेंसियाँ हैं—

(प्र) जोखिम पूँजी (Risk Capital) :

(i) राज्य वित्त निगम

(ii) लघु उद्योग निगम

(प्रा) दीर्घकालीन व मध्यमकालीन बर्ज—

(i) उद्योगों के राज्य-निदेशालय (उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत)

(इ) अल्पकालीन कार्यशील पूँजी—ध्यापारिक बैंक।

(ई) किरतों की स्कीम (Hire-Purchase Scheme)—

(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(ii) लघु उद्योग विकास निगम

जोखिम पूँजी—राज्य वित्त निगम उद्यमकर्त्ताओं, विशेषतया नये तकनीकी उद्यमकर्त्ताओं व पिछड़े क्षेत्रों में प्रोजेक्ट स्थापित करने वाले उद्यमकर्त्ताओं को सीड पूँजी (seed capital) के रूप में सहायता प्रदान करते हैं। यह सहायता भारतीय औद्योगिक विकास की एक स्कीम के अन्तर्गत दी जाती है। यह शायर पूँजी उदार गतों वाले बर्ज के रूप में होती है और उस अन्तर को पूरा करती है जो सस्थापक (Promoter) के प्रत्याशित अंशदान (expected contribution) व उसके वास्तविक अंशदान (actual contribution) के बीच होता है। सभी प्रकार के उपक्रम जैसे निजी स्वामित्व वाले, सामुदायिक, निजी व पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वाले इसका लाभ उठा सकते हैं।

सीड/मार्जिन मुद्रा स्कीम—ग्रामीण व ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारें जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत बर्ज के रूप में सीड/मार्जिन मुद्रा की सहायता देती है। यह स्कीम 50 हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है। जिन लघु इकाइयों की प्लान्ट व मशीनरी को लागत एक लाख रु से नीची होगी, उनको स्थिर पूँजी का 10% तक 'मार्जिन मनी' के रूप में दिया जाता है।

लघु उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भी वित्तीय सहायता मिलती है। इनके लिए बैंक वित्त की वकाया राशि जून, 1969 में 251 करोड़ रु. से बढ़कर जून 1987 के अन्त में 9309 करोड़ रु. हो गई। जून 1987 में लघु उद्योगों के

लिए बढ़ाया राशि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल कर्ज (25500 करोड़ रु.) का 36.5% थी।¹

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम निजों पर मशीनें उपलब्ध कराता है। जुलाई, 1960 में रिजर्व बैंक ने मास पागन्टी स्कीम लागू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यापारिक बैंक, राज्य वित्त निगम व सहकारी बैंक लघु इकाइयों को कर्ज देते हैं, लेकिन कर्ज की जोखिम में रिजर्व बैंक का भी हिस्सा होता है।

लघु उद्योग विकास कोष (Small Industries Development Fund) (SIDF) की स्थापना—देग में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक बैंक ने 20 मई, 1986 को एक लघु उद्योग विकास कोष (SIDF) की स्थापना की है। इस कोष में काफ़ी राशि होगी जब कि इसकी शुरुआत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 100 करोड़ रुपये के जनरल फंड से की गई है। इस कोष में लघु उद्योगों की इकाइयों का विकास, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण व पुनर्स्थापना के लिए कर्ज दिये जायेंगे। विनीय सहायता राज्य वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, व्यावसायिक बैंकों व अन्य संस्थाओं के माध्यम से दी जायगी। इस कोष से लघु उद्योगों के विकास के लिए दूरगामी परिणाम मानने आयेंगे।

एक राष्ट्रीय-इन्विटी कोष (NEF) (भारत सरकार की मालिकारी में) स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य दमण लघु पैमाने की इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए इन्विटी-रिस्क की सहायता देना है। यह प्रति प्रोजेक्ट 75 हजार रु. तक की सहायता स्वीकृत करेगा जिस पर सविम-वार्ज 1% लिया जायगा। यह बैंकों को पुनर्बल की सहायता देगा आ उद्योग को कार्यशील पूँजी व ऋण-कर्ज की सुविधा प्रदान करेगा।

लघु उद्योग विकास कोष (SIDF) व राष्ट्रीय इन्विटी-कोष (NEF) दोनों का मकानन भारतीय लघु-उद्योग विकास बैंक (SIDBI) का मौला गया है जो IDBI का सहायक (subsidiary) होगा।

5. इंजीनियरी स्नातको, सूत्रपूर्व सुरक्षा सेवा कर्मचारियों, विज्ञान-स्नातकों आदि का लघु इकाइयों स्थापित करने के लिए जो सुविधाएँ दी जाती हैं वे पिछड़े क्षेत्रों में अनुचित जातियों व जन-जातियों के व्यक्तियों को भी दी गई है।

6. औद्योगिक इस्तिथों के कार्यक्रम द्वारा लघु इकाइयों को लाभ पहुँचाया जाता है।

7. सरकार माल की खरीद में लघु इकाइयों को प्राथमिकता देती है। आज-कल कई प्रकार की वस्तुएँ लघु इकाइयों से खरीदी जाती हैं ताकि इनकी बिजली की समस्या काफ़ी सीमा तक हल हो सके।

8. पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष रियायतें—1 मार्च, 1973 में सरकार ने पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए अनुदान (subsidy) की राशि स्थिर पूँजी-निवेश का 15% या 15 लाख रुपये, जो भी कम हो निर्धारित की गई थी। 1971 से परिवहन-अनुदान (transport-subsidy) की सीमा लागू की गई थी जिसमें पिछड़े क्षेत्रों में कच्चे माल व निम्न मूल्य की कच्चाई पर परिवहन लागत का 50% अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गई थी जिसे मिनस्वर 1983 में बढ़ाकर 75 % कर दिया गया। इस प्रकार पिछड़े जिलों में लघु व मध्यम इकाइयों के विकास के लिए सन्निही की व्यवस्था की गयी है।

9. सरकार निर्यात बढ़ान में भी लघु इकाइयों का मदद करती है।

10. आजकल सहायक उद्योगों (ancillary industries) के रूप में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लघु उद्योग बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक साज-सामान बनाते हैं जिससे दोनों के उत्पादन में प्रभावपूर्ण ताल-मेल व समन्वय बँटाया जा सकता है। सहायक उद्योगों का विकास विशेषतया निम्न क्षेत्रों में किया गया है। संचार, इलेक्ट्रानिक्स व मोटर-गाड़ियाँ, भारी इंजीनियरिंग तथा कृषि-आधारित उद्योगों। इस क्षेत्र में आगामी वर्षों में अधिक प्रगति की आशा है।

11. सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए जिला-उद्योग केंद्रों (District Industries Centres) को पुनर्संरचित किया है। अब तक स्थापित DICs की संख्या 419 हो गई है जो 428 जिलों में फैले हुए हैं। इनमें कई लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और बहुत से लोगों को रोजगार दिया जा सका है। DICs के माध्यम में साख की व्यवस्था भी की गई है।

12. लघु उद्योगों के लिए चुने हुए क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को अपनाने (अपग्रेड) करने के नये कार्यक्रम—मई 1985 में श्री एम. एम. पाटिल की अध्यक्षता में नियुक्त एक कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि इन इकाइयों को मास की सुविधा देते के लिए एक विशेष संगठन बनाया जाना चाहिए। आजकल मशीनों की लागत बढ़ गई है। इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि लघु इकाइयों में समय व मशीनरी में निवेश की सीमा 50 लाख रु. तथा सहायक इकाइयों के लिए 75 लाख रु. कर देनी चाहिए। इनके लिए टेक्नोलॉजी का आयात करने की सुविधा भी बढ़ायी जानी चाहिए।

योजनाकाल में कुटीर व लघु उद्योगों की प्रगति

योजनाकाल में शामिल व लघु उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये व्यय की प्रगति इस प्रकार रही है—

शामिल व लघु उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि¹
(करोड़ रुपये में)

प्रथम पंचवर्षीय योजना	42
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	187
तृतीय पंचवर्षीय योजना	241
तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	126
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	243
पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79)	593
1979-80	256
छठी पंचवर्षीय योजना	1945
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)	2753 (लक्ष्य)

चतुर्थ व पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल व लघु उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय का लगभग 1.5% व्यय बिता गया। छठी योजना में यह 1.8% रहा जब सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह 1.6% प्रस्तावित किया गया है।

1951-61 की अवधि में अम्बर चरखा बनाने व वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था। कपड़े की मृदु वस्त्रों का उत्पादन हाथकरवा उद्योग एवं कृषि औजारों की वस्त्रों का उत्पादन लघु इकाइयों के लिए मुरसित किया गया था। बनस्पति तेल, चावलों की मिलों, दूधों, दियमलाई आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाने में रोका गया था। भाइकिलों व मिलाई की मशीनों में बड़े व छोटे पैमाने के उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

1973-74 में खादी का उत्पादन 56 मिलियन मीटर से बढ़कर 1987-88 में 114 मिलियन मीटर हो गया तथा इसी अवधि में हाथकरवे का 2,100 मि मीटर से बढ़कर 4000 मि. मीटर तथा जूतों का 2,400 मि. मीटर से बढ़कर 3669 मि मीटर हो गया। इस प्रकार योजना काल में विवेक्षित क्षेत्र में वस्त्रों का उत्पादन काफी बढ़ा है। देश में का उत्पादन 1973-74 में 29 लाख किनोडान कच्चे रेशम से बढ़कर 1987-88 में 95.3 लाख किनोडान हो

1 Economic Survey 1988-89 pp. S-40 and S-41 (तृतीय योजना व बाद की अवधि के लिए)

गया।¹ पिछले पन्द्रह वर्षों में लघु पैमाने के क्षेत्र में कई नई मर्दें शामिल की गयी हैं और लघु उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे जूते व अन्य चमड़े का सामान, साइकिलें व पुर्जे, कपड़ा सीने की मशीनें व पुर्जे, बिजली के पसे व मोटरें, मशीन टूल्स व हाथ औजार, पेन्ट व वार्निश और साबुन आदि का उत्पादन काफी बढ़ा है।

सप्लाई व बिनी के केन्द्रीय निदेशालय ने लघु उद्योगों के माल की खरीद काफी बढ़ायी है। दस्तकारी के माल का निर्यात 1973-74 में 195 करोड़ रु से बढ़कर 1987-88 में 3253 करोड़ रु हो गया है जिसका निर्यात में प्रथम स्थान है। देश में औद्योगिक सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है ताकि लघु उद्योगों का विकास जिया जा सके।

ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित प्रोजेक्टों के कार्यक्रमों की प्रगति (Progress under Rural Industries Projects (RIP) Programme)

देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण उद्योगों को पसवाने के लिए 1964 में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे। शुरू में 45 प्रोजेक्ट-क्षेत्रों का चुनाव किया गया था तथा 1965 में 4 अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किये गये। इस प्रकार 1965-66 में प्रोजेक्टों की संख्या 49 हो गई थी। मार्च, 1974 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 प्रोजेक्ट और आ चुके थे। इनमें 48 हजार औद्योगिक इकाइयाँ थी और 2 07 लाख व्यक्तियों को काम दिया गया एवं 1973-74 में इनमें 70.3 करोड़ रुपये के माल का उत्पादन किया गया। ये प्रोजेक्ट ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मदद करते हैं। ये केन्द्र द्वारा चलाये गये हैं। इनके लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई है।

ग्रामीण उद्योग प्रोजेक्टों से निजी बचत के संग्रह व निजी विनियोग को प्रोत्साहन मिला है और रोजगार में वृद्धि हुई है। इनका कार्य लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organisation (SIDO) को हस्तान्तरित किया गया है जिसमें विस्तार सेवाओं, कच्चे माल के आवंटन व साख की सुविधाओं पर अधिक बल दिया गया है। ग्रामीण उद्योग-प्रोजेक्टों ने जिन उद्योगों को विशेष रूप से मदद दी है वे निम्नलिखित हैं: कारिफल के रेशे से गलिये व चटाईया बनाना, कताई व बुनाई, गुड बनाना, तेल निकालना, बर्तन बनाना, हाथखरचा, कृषि के औजार बनाना, बेंत का फर्नीचर बनाना, सिचाई व बहाव के लिए स्पन-पाइप बनाना आदि। इस प्रकार के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

पिछले पन्द्रह वर्षों में लघु उद्योगों ने विकास के सम्बन्ध में प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार रखे गये हैं : लघु उद्योगों की उत्पादन-विधियों में उत्तरोत्तर सुधार करना जिससे वे उत्तम किस्म की वस्तुएँ बना सकें एवं सबल व कार्यकुशल स्तर प्राप्त कर सकें। उद्योगों के विकेन्द्रीकरण व फैलाव को प्रोत्साहन देना और कृषि-आधारित उद्योगों का विकास करना। ग्रामीण मेहुता-समिति ने इनके सम्बन्ध में सन्धि के तत्व को कम करने पर बल दिया था। मेहुता समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की थी कि लादी सहित प्रत्येक परम्परागत उद्योग में तकनीकी सुधार करने के लिए एक सप्ताहवर्षीय कार्यक्रम अपनाया जाया चाहिए ताकि वे सतत स्तर (variable level) पर आ सकें। समिति ने सिफारिश की थी कि सविध्य में परम्परागत धातु एवं लकड़ी की अतिरिक्त उत्पादन आत्मनिर्भरता के आधार पर होना चाहिए और तकनीकी परिवर्तन व शक्ति का उपयोग करने की छूट होनी चाहिए। गाँवों में कृषि-प्रोड्यूसर को सुधारने के लिए छोटे चककाप स्थापित किये जान चाहिए। श्रमिकों व वस्त्रियों के सम्बन्ध में पुराने कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की नीति सुझाई गई है। यह निश्चित किया गया है कि साधारणतः शहरी व बड़े नगरों के समीप कार्द नयी औद्योगिक इस्तिमा नहीं बनायी जायेंगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में प्राचीण व लघु उद्योगों के विकास के मुख्य लक्ष्य व विकास-सम्बन्धी नीति व दिशाएँ

सातवीं योजना में VSI क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 2,753 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जबकि छठी योजना में वास्तविक व्यय का स्तर 1,945 करोड़ रु रहा था।

जैसाकि पहले बताया जा चुका है सातवीं योजना में प्राचीण व लघु उद्योग क्षेत्र (VSI sector) में उत्पादन 1984-85 में 65,730 करोड़ रु से बढ़कर 1989-90 में 100,100 करोड़ रुपये (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) राजस्वार की यात्रा 3.15 करोड़ व्यक्तियों से बढ़ाकर 4 करोड़ व्यक्ति तथा नियमित की राशि 4,558 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,444 करोड़ रुपये तक पहुँचाने के लक्ष्य रखे गये हैं।

इस प्रकार उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर 8.8% तथा रोजगार में वार्षिक वृद्धि-दर 10.2% निर्धारित की गई है।

सातवीं योजना में प्राचीण व लघु उद्योगों के विकास की ध्येय-रचना या रणनीति निम्न प्रकार की रखी गई है—

1. आधुनिकीकरण करना तथा टेक्नोलॉजी को उन्नत करना ताकि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके माल की विस्म सुधारी जा सके जगहों कम की जा सकें तथा वस्तु मिश्रण (Product mix) बढ़ना जा सके।

2 वर्तमान क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना ।

3. घरेलू बाजार में VSI क्षेत्र का अणु बढ़ाना एवं इसके लिए प्रचार व विपरी सम्बन्धी सहायता देना ।

4 सहायक इकाइयों को सुदृढ़ करना ।

5 उत्पादन में विशिष्टीकरण लाना तथा निर्मातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना ।

6 स्वरोजगार बढ़ाने के लिए दक्षता-निर्माण को बढ़ावा देना तथा

7 श्रमिकों के कल्याण, रोजगार की सुरक्षा व बेहतर काम की दशाओं पर अधिक ध्यान देना ।

उपयुक्त व्यूह-रचना या रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए निम्न उपाय सुझाये गये हैं—

(i) प्रामीण व लघु उद्योगों के तीव्र विकास के लिए वर-सम्बन्धी व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक व तर्कसंगत बनाना,

(ii) आधारभूत ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करना,

(iii) प्रबन्ध की आधुनिक विधियाँ को अपनाना

(iv) उपयुक्त टेक्नोलॉजी का विकास व विस्तार करना ताकि काम की नीरसता कम की जा सके व सप्लाइ पर निर्भरता घटाई जा सके,

(v) मजदूरी में सुधार करना,

(vi) भारत व विदेशों में विपरी की व्यवस्था में सुधार करना,

(vii) पार्क, लोहे व इस्पात, कौमला व कोक, पेट्रो-रसायन व पेट्रोल-पदार्थों की सप्लाई बढ़ाना,

(viii) अति लघु (tiny) इकाइयों को विशेष सुविधाएँ (ix) सहायक मंडों को उप-ठेका (sub-contract) पद्धति के आधार पर उत्पादित करना । प्रामीण उद्योगों व दस्तकारियों के लिए पृथक् आयोगों की स्थापना की जाँच की जायगी ।

(x) कारीगरों के लाभ के लिए भवन व वर्कशेड की मिली-जुली सुविधाओं तथा बचत-कोप-स्कीम को अपनाने पर जोर दिया जायगा ।

आशा है इन उपायों को अपनाने से VSI क्षेत्र उत्पादन, रोजगार व निर्यात वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकेगा तथा भारतीय ग्रन्थव्यवस्था में इसका स्थान काफी मृदुल हो सकेगा ।

प्रश्न

1. भारतीय औद्योगिक ढाँचे में कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों के महत्व का परीक्षण कीजिए । कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योगों की वर्तमान वित्त व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिये ।

2. 1951 के पश्चात् कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रगति का वर्णन कीजिए । वर्तमान में इनकी क्या समस्याएँ हैं ?

(Raj. Hyr. T.D.C., 1984)

3. भारत की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्व को समझाईये और इन उद्योगों की मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए ।

(Raj. Hyr. T.D.C., 1981)

4. भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व को विवेचना कीजिए । इनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा हाल के वर्षों में अपनाये गये विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए ।

(Raj. Hyr. T.D.C., 1982, 1983 and 1985)

5. भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का क्या महत्व है ? इन उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया है ?

(Raj Hyr. T.D.C., 1989)

औद्योगिक वित्त

(Industrial Finance)

कृषि की भांति उद्योगों के लिए भी एक उचित वित्त-व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उद्योगों को स्थापित करते समय, इनको चलाने के लिए तथा इनमें समय-समय पर विस्तार करने तथा प्राधुनिकीकरण करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए पूँजी की आवश्यकता को साधारणतया दो भागों में विभाजित किया जाता है—

1. **मजबूत या स्थिर पूँजी (Fixed or Block Capital)**—कोई भी नया उद्योग प्रारम्भ करते समय भूमि, इमारत, मशीनें तथा अन्य साज-सामान खरीदने के लिए स्थिर पूँजी की आवश्यकता होती है। चालू उद्योगों को भी आवश्यक परिवर्तन, प्राधुनिकीकरण व विस्तार कार्यों के लिए स्थिर पूँजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की पूँजी को मजबूत या स्थिर पूँजी कहते हैं।

2. **चल पूँजी या कार्यशील पूँजी (Working Capital)**—जो पूँजी कच्चा माल खरीदने, मजदूरी चुकाने माल की बिक्री के सम्बन्ध में आवश्यक विज्ञापन आदि करने एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है, उसे चल या कार्यशील पूँजी कहते हैं। औद्योगिक वित्त में हम चल एवं मजबूत दोनों प्रकार की पूँजी की पूर्ति के साधनों का अध्ययन करते हैं। प्रायः यह अध्ययन दो भागों में बाँटकर किया जाता है : (1) बड़े पैमाने के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ। (2) सघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ।

बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए पूँजी के साधन

स्वतन्त्रता प्राप्ति तक बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए पूँजी की सुविधाएँ बहुत कम थीं। अप्रैल 1970 में मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली समाप्त करने से पूर्ण उद्योगों को वित्त प्रदान करने में मैनेजिंग एजेन्सी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। मैनेजिंग एजेन्सिया निजी व्यक्तियों या साझेदारी फर्मों या समुक्त पूँजी वाली कम्पनियों के अधिकार में होती थी, जो अपने नियन्त्रण वाली सम्पत्ति की स्थापना

व वित्तीय व्यवस्था करती थी तथा उसके प्रबन्ध का कार्य भी देखती थी। य एजेन्सिया स्वयं अगर व ऋण-पत्र खरीदता थी तथा मित्रों व बैंकों से पूँजी को व्यवस्था करती थी। लकिन इनमें कई प्रकार के सम्मोह दाप उत्पन्न होने के कारण सरकार को उनके स्थान पर नये समूहों की स्थापना करनी पड़ा। विद्युत, दार दरकों में मागत में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास एवं वित्त नियम स्थापित किए गए हैं जिन्होंने उद्योगों के लिए वित्त का कमी को दूर करने का प्रयत्न किया है।

वर्तमान समय में भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तीय माधना के निम्न स्रोत पाए जाते हैं—

- 1 शेयर (Shares) व ऋण-पत्र (Debentures)
- 2 सार्वजनिक जमाएँ (Public Deposits)
- 3 व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)
- 4 सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएँ (Public Financial Institutions)

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India)

(ii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India) (IFCI)

(iii) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (The National Industrial Development Corporation) (NIDC)

(iv) भारतीय औद्योगिक साधन एवं निवेश निगम लिमिटेड (The Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.) (ICICI)

(v) भारतीय यूनियन ट्रस्ट (The Unit Trust of India) (UTI)

(vi) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) (IDBI)

(vii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड (The Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.) (IRCI) अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में परिवर्तित)

(viii) भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा इसकी सहायक इकाइयाँ (The General Insurance Corporation of India (GIC) and its subsidiaries)

(ix) आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड (Housing Development Finance Corporation Ltd.) (HDFC)

(x) भारतीय निर्यात आयात बैंक (The Export Import Bank of India) (EXIM Bank)

नीचे इसका क्रमशः वर्णन किया जाता है।

(1) शेयर व ऋण पत्र—एक कम्पनी कई तरह के शेयर निकाल सकती है, जैसे साधारण शेयर व अधिमान शेयर (Preference Shares)। साधारण शेयर 'इक्विटी' (equity) भी कहलाते हैं। जो नये शेयर कम्पनी के वर्तमान शेयर होल्डरों को बेचे जाते हैं उन्हें राइट्स शेयर (Rights Shares) कहते हैं। कम्पनियाँ बोनस शेयर भी निर्गमित करती हैं जो वर्तमान शेयरहोल्डरों को कम्पनी के संचित या इकट्ठे किये गये पूर्व मुनाफो में से जारी किये जाते हैं। इससे कम्पनी की रिजर्व राशि पूँजी में बदल जाती है। विभिन्न प्रकार के शेयर विनियोगकर्ताओं की विभिन्न प्रवृत्ति तथा विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अधिमान शेयरधारी एक निश्चित लाभांश सबसे पहले प्राप्त करते हैं और पूँजी वापस करत समय भी पहले इनका अधिकार होता है। साधारण शेयरहोल्डरों को लाभ में हिस्सा इनके बाद मिलता है तथा इनका हिस्सा कम्पनी के लाभ की मात्रा के साथ घटता-बढ़ता रहता है।

पूँजी-बाजार में शेयरों का क्रय-विक्रय होता रहता है। भारत में 1947 से 1962 तक का समय पूँजी-बाजार का स्वर्ण-युग कहलाता है, क्योंकि इस अवधि में शेयर-पूँजी का बड़ा प्रचलन रहा था। 1962 के बाद कई वर्षों तक पूँजी-बाजार में गिरावट आई। 1985-86 के केन्द्रीय बजट के बाद शेयर बाजार में काफी प्रगति हुई थी। प्रत्यक्ष करो में वही व आधिक नियन्त्रणों में ढील देने के अनुकूल परिणाम सामने आये थे एवं शेयर बाजार लोगों के आकर्षण का केन्द्र बन गया तथा पूँजी-निर्गम में अत्यधिक वृद्धि हुई।

पूँजी निर्गम (Capital issues) में साधारण व अधिमान शेयर, ऋण-पत्र व राइट्स शेयर शामिल होते हैं। 1986-87 में पूँजी-बाजार का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। गैर-सरकारी पब्लिक व निजी लि. कम्पनियों के लिए इक्विटी व अधिमान शेयर की निर्गमित राशि लगभग 1600 करोड़ रु., ऋण-पत्रों की राशि 2614 करोड़ रु. व बोनस शेयरों की 303 करोड़ रु. रही। इस प्रकार कुल पूँजी-निर्गम (Capital issues) 4517 करोड़ रु. का हुआ, जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक था। 1987-88 में यह घट कर 2423 करोड़ रु. पर आ गया। इस वर्ष सबसे अधिक गिरावट ऋण-पत्रों की बिक्री में रही। ये 687 करोड़ रु. तक ही पहुँच पाये जब कि पिछले वर्ष 2614 करोड़ रु. तक पहुँच गये थे।¹ 1985-86 में नेशनल थर्मल पावर निगम, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज व ग्रामीण विद्युत निगम ने (सार्वजनिक क्षेत्र में) बाढ़ बेचकर लगभग 350 करोड़ रु. एकत्र किये थे। इस प्रकार पूँजी बाजार का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी किया जाने लगा है।

ऋणपत्र—ऋणपत्रों को बेचकर पूँजी इकट्ठी करना भी कम्पनियों की पूँजी का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इन पर कम्पनी को व्याज देना पड़ता है। ऋण-पत्रधारी कम्पनी के ऋणदाता होते हैं। जो विनियोगकर्ता जोखिम से बचना चाहते हैं लेकिन साथ में व्याज की एक निश्चित राशि से ही संतुष्ट रहना चाहते हैं उनके लिए ऋणपत्र बहुत सुविधाजनक व आकर्षक होते हैं। प्रायः ऋण-पत्रों के पीछे कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति की जमानत होती है जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचकर ऋणपत्रों का मुक्तान किया जा सकता है। भारत में भूतकाल में कई कारणों से ऋणपत्र लोकप्रिय नहीं हुए। औद्योगिक कम्पनियों की असफलता से जनता में इनके प्रति विश्वास नहीं जम पाया। लेकिन पिछले वर्षों में ऋणपत्रों की लोकप्रियता बढ़ी और विशेषतया परिवर्तनीय ऋणपत्रों (Convertible debentures) की भारी मांग में सरोदा गया। ये एक अवधि के बाद कम्पनी के शेयरों में परिवर्तित किये जा सकते हैं। इसलिए विनियोगकर्ताओं ने ऋणपत्रों की खरीद में अधिक रुचि ली है। इससे कम्पनियों को आवश्यक विस्तार-कार्यों के लिए भी पूँजी उपलब्ध हो सकी है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 1967-88 में ऋण-पत्रों की खरीद में भारी गिरावट आयी जबकि 1986-87 में ऋण-पत्रों की वित्तीय अधिक होने से पूँजी निर्धन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ऋणपत्रों व बांडों का उपयोग वित्तीय साधन जुटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी किया गया है।

(2) सार्वजनिक जमाएँ—भारत में व्यावसायिक बैंकों के विकास से पूर्व बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास हुआ। अतः जनता अपनी बचत कारखानों में जमा करना उचित मानती थी। ग्रहमदावाद व अम्बई से सृती बचत की मिली में इन प्रकार की जमा का काफी प्रचार दखा गया है। इस जमा का प्रयोग बढ़ती कार्यशील पूँजी के रूप में किया जाता है। जमा पर व्याज मिलता है। उचित समय पर सूचना देकर जमा की रकम वापस निकाली जा सकती है। यह साधन जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि जनता का कम्पनी में विश्वास डिम जाने पर वह अपनी जमा-राशि की वापस माँग करती है जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति ठाढ़ाडोल हो सकती है। इस प्रकार की सार्वजनिक जमाओं को 'अच्छे मौसम का मित्र' (fair weather friend) कहा गया है। अतः यह साधन सुरक्षित नहीं माना जा सकता। लेकिन कम्पनियाँ आज भी पूँजी एकत्र करने में इस साधन का उपयोग करती हैं। 1971-72 में मयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों (गैर-वित्तीय) के पास सार्वजनिक जमाओं की राशि 481 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1982-83 में 6764 करोड़ ₹ हो गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि आज भी औद्योगिक दित्त में इसका महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। इन पर व्याज की दर प्रायः 15% होती है तथा अधिकतम अवधि तीन वर्ष की होती है।

लिए आवश्यक स्तर (नॉर्म) निर्धारित किये थे ताकि वे माल या इन्वेण्टरी की मात्रा प्रनावश्यक रूप से अधिक न रहें। पहले वे ज्यादा मात्रा में माल रख लेते थे जिससे बैंक-माल का सदुपयोग नहीं हो पाता था।

यह आशा की गई थी कि टण्डन समिति की सिफारिशों को लागू करने से बैंक-माल का अच्छा नियोजन तथा उत्तम उपयोग हो सकेगा।

रिजर्व बैंक ने नकद-साख प्रणाली की जांच करने के लिए के. बी. चोरे (K. B. Chore) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1979 में प्रस्तुत की थी। इसने उधार की निम्न प्रणाली को अपनाते का मुझाफ दिया था :—

(i) उधार के विभिन्न रूप—नकद-साख, ओवरड्राफ्ट, ऋण व बिल-प्रणाली साथ-साथ प्रचलित रहेंगे, लेकिन कुल उधार में नकद-साख का अंश कम किया जाएगा।

(ii) एक इकाई अपनी कुल नार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं के लिए दीर्घ-कालीन स्रोतों (स्वयं के कोषों व अवधि-वर्जों) पर अधिक निर्भर करेगी। बड़ी औद्योगिक इकाइया बैंक से कम मात्रा में उधार लेंगी। इस प्रकार वे स्वयं के साधनों का ज्यादा उपयोग करेंगी।

(iii) कोषों की अल्पकालीन अप्रत्याशित माँग की पूर्ति के लिए बैंकों का सहारा लिया जाएगा जिसकी लागत ऊँची होगी।

(iv) उधार लेने वाले अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बैंकों को प्रामाणिक सूचना भेजेंगे ताकि नकद-साख की सीमाओं का ठीक ढंग से उपयोग हो सके।

(v) कच्चे माल की एवज में नकद-साख की सीमा का एक अंश बिलों के माध्यम से दिया जाएगा जिससे कच्चे माल की खरीद पर इन्वेण्टरी बढ़ोला ज्यादा अच्छा हो सकेगा। इस प्रकार चोरे समिति ने नकद साख प्रणाली के बजाय बिल-प्रणाली को अपनाने पर ज्यादा जोर दिया था।

यह आशा की गई थी कि इन व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋणों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, बिल-वित्त का उपयोग बढ़ेगा तथा कुछ सीमा तक नकद-साख का उपयोग घटेगा। व्यावसायिक क्षेत्रों में चोरे कार्यकारी दल के सुझावों को काफी बठोर माना गया और इनको उदार बनाने की राय दी गई।

पिछले वर्षों में उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था में बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1987-88 के प्रारंभ में (अप्रैल-मार्च) उद्योगों (सघु, मध्यम व बड़े) के बैंकों द्वारा की गई सकल साख की बकाया राशि (outstandings) 36,309 करोड़ ₹ रही जो पिछले वर्ष से 5216 करोड़ ₹. घटित थी। मार्च, 1988 के

ग्रन्त में उद्योगों को दी गई साख बकाया कुल बैंक साख का 51.6% हो गई थी, जबकि पिछले वर्ष यह 49.7% रही थी। कर्ज की ज्यादा राशि बढ़ी व मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए रही है तथा लघु इकाइयों के लिए इनसे कम रही है, हालांकि यह पिछले वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी है। कर्ज की अधिक बकाया राशि इंजीनियरी, सूती वस्त्र व रसायन उद्योगों के लिए पायी गई है। बैंकों का योगदान औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में काफी बढ़ रहा है तथा भविष्य में इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि बैंक उद्योगों की वांछित वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति प्रदाय कर सकें। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ मानक (नार्म) अवश्य निर्धारित हों तथा उनका पालन भी किया जाय और इन्स्पेक्टरी (माल) की मात्रा जल्द से ज्यादा न रखी जाय, क्योंकि ऐसा करने से बैंक के कोषों का दुरुपयोग होने लगता है जिसे टाला जाना चाहिए। पिछले वर्षों में उद्योगों के लिए बैंक ऋण की राशि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में ज्यादा तेज गति से बढ़ी है। फिर भी उत्तमवर्गी कोषों की कमी को शिवायत करते हुए पाये जाते हैं। भविष्य में नकद-साख प्रणाली के बजाय बिल-प्रणाली का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। बिल-प्रणाली यू.के. व जर्मनी में अधिक लोकप्रिय रही है।

(4) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएँ (Public Financial Institutions)

(1) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

भारतीय जीवन बीमा निगम उद्योगों के शेयर व ऋणपत्र खरीदता है। यह उन्हें मध्यमकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की सुविधा देता है। यह शेयरों व ऋणपत्रों का अभिगोपन (Underwriting) भी करता है। यह औद्योगिक वित्त-निगम व राज्य वित्त निगमों की पूँजी में हिस्सा लेकर परोक्ष रूप से औद्योगिक वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। इसके कोषों का 50% सरकारी व अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में लगाना होता है। शेष राशि 'स्वीकृत विनियोगों' में लगानी होती है जिसमें कम्पनियों के शेयर व ऋण-पत्र भी शामिल होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय-करण के बाद भी जीवन बीमा निगम के द्वारा निजी क्षेत्र को पूँजी देना जारी रखा गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम अभिगोपन के रूप में कम्पनियों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। यह कम्पनी-लेन के अलावा सहकारी क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता देता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वार्षिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। 1987-88 की अवधि में वितरित सहायता की राशि 342.3 करोड़ रु. रही जो पिछले वर्ष से कम थी।¹

इतनी वित्तीय सहायता प्रदान करके भी यह औद्योगिक इकाइयों में एक निष्क्रिय साझेदार (Sleeping Partner) के रूप में बना रहा है क्योंकि इतने सहायता-प्राप्त कंपनियों के प्रवृत्ति में शक नहीं लिया है। औद्योगिक साझेदारिता काच समिति (1969) ने इस कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

(II) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(IFCI)

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद समद के अधिनियम के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1948 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गयी थी। यह शेयर-धारियों का निगम है। इसके शेयर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, धनसूचित बैंको, जीवन बीमा निगम, सहकारी बैंको व अन्य वित्तीय संस्थाओं ने लिये हैं। शेयरों पर भारत सरकार ने गारण्टी प्रदान की है।

निगम का कार्य क्षेत्र—निगम उन सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनियों, सहकारी मण्डलों, निजी भीषित दायित्व वाली कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दीर्घकालीन ऋण देता है जो भारत में पकड़ित हुए हैं और जो माल की प्रोसेसिंग या निर्माण या खान खोदना, होटल उद्योग या बिद्युत के उत्पादन या वितरण या अन्य किसी प्रकार की पावर उत्पन्न करने के सम्बन्धित है। इन कंपनियों में समुद्री अड्डा की कंपनियों की शामिल की गई हैं। निगम के क्षेत्र में साझेदारी फर्म, एकाकी उत्पादक एवं सघु उद्योग शामिल नहीं हैं।

12 मार्च, 1982 से लागू औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन), अधिनियम के अन्तर्गत इसका कार्य-क्षेत्र बढ़ाया गया है। अब यह निगमित (कम्पनी) क्षेत्रों में स्थापित निम्न औद्योगिक उपक्रमों की भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है

(i) सड़क या जल-मार्ग या वायु-मार्ग या रस्सु तार्य (ropeway) या लिफ्ट द्वारा यात्री व माल का खाना-ले खाना, (ii) मशीनरी या वाहनों या जलपोतों या मोटर नौकाओं या ट्रैक्टरों का रख-रखाव, मरम्मत, बरीक्षण या सर्विसिंग, (iii) मशीनरी या पावर की सहायता से किसी भी वस्तु को जोड़कर बनाना, मरम्मत करना या पेंटिंग करना, (iv) समीप के किसी क्षेत्र का औद्योगिक वस्ती के रूप में विकास करना; (v) मछली पकड़ना या मछली पकड़ने के लिए तरीय भुविषाए देना या रख-रखाव करना, (vi) औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान या सेवाएँ देना एवं (vii) प्रक्रिया व वस्तु के लिए रिमचें व डिजाइन का कार्य।

वित्तीय सहायता के रूप—निगम को निम्न विधियों से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है :

(अ) औद्योगिक कम्पनियों ने खुले बाजार से जो ऋण लिये हैं, उन पर वह गारण्टी दे सकता है। ऐसे ऋणों की अवधि 25 वर्ष तक हो सकती है।

(आ) यह 25 वर्ष तक का ऋण स्वयं दे सकता है अथवा कम्पनियों के ऋण-पत्र खरीद सकता है। यह मध्यम-बड़े (medium-large) तथा बड़े पैमाने के क्षेत्र (large scale sector) में स्थापित किये जाने वाले उन औद्योगिक उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था पर विचार करता है जिनकी प्रोजेक्ट-लागत 3 करोड़ रु से ऊपर होती है। इससे नीचे की लागत वाले प्रोजेक्टों की वित्तीय व्यवस्था राज्य वित्त व विकास निगमों द्वारा की जाती है।

(इ) यह कम्पनियों के स्टॉक, डेयर, वाड या ऋण-पत्रों का अग्निगोपन (Underwriting) कर सकता है, लेकिन अग्निगोपन की तारीख से 7 वर्ष की अवधि में इनका बेचा जाना अनिवार्य होता है।

1957 से नियम आयातकर्ता को विलम्बित भुगतान पद्धति (Deferred Payment System) के सम्बन्ध में भी गारण्टी देने का अधिकार दिया गया था। यदि कोई आयातकर्ता विदेशी उत्पादक से मशीनें आदि खरीदने का इम्तजाम कर लेता है तो नियम उसके लिए गारण्टी दे सकता है जिससे विदेशी मशीनें व साज-सामान भी सुगमतापूर्वक मिल जाते हैं।

दिसम्बर 1960 के संशोधन के अनुसार निगम के द्वारा गारण्टी प्रदान करने का काम काफी बड़ा दिया गया तथा नियम को औद्योगिक उपक्रमों के डेयर खरीदने का भी अधिकार दे दिया गया, जो उसे पहले नहीं था। निगम की इच्छा से उनके द्वारा दिये गये ऋणों या डिबेंचरों की राशि को उद्योगों के डेयरों में परिवर्तित करना भी सम्भव कर दिया गया।

निगम की पूँजी के स्रोत—निगम की पूँजी के स्रोत निम्नलिखित हैं—

(1) डेयर-पूँजी—1982 के संशोधन-प्रधिनियम के अनुसार निगम की अधिकृत पूँजी 20 करोड़ रु से बढ़ाकर (केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित करके) 100 करोड़ रु तक की जा सकती है। प्रत्येक डेयर पाँच हजार रुपये का होता है। 30 जून 1988 को इसकी प्रदत्त पूँजी (paid-up-capital) 70 करोड़ रु. थी।

(ii) बाँड व ऋण-पत्र—पिगत को प्रदत्त पूँजी व रिजर्व कोष के 10 गुने तक बाँड व ऋण-पत्र निर्गमित करने का अधिकार है। निगम द्वारा निर्गमित बाँड के मूलधन व व्याज पर केन्द्रीय सरकार की गारण्टी होती है। 30 जून 1988 तक बाँडों की शुद्ध बकाया राशि 2083.80 करोड़ रु. हो चुकी थी। 1987-88 में

इसने तीन बार बाढ़ जारी किये। बाढ़ का 50वाँ तिरोज 14 जून 1988 को जारी किया गया था।

(iii) रिजर्व बैंक से उधार—1982 के संशोधन के अनुसार निगम अब भारतीय रिजर्व बैंक से 18 महीने तक के लिए 15 करोड़ रुपये तक की रकम उधार ले सकता है।

(iv) जमाएँ—अब निगम IDBI द्वारा स्वीकृत शर्तों पर कम से कम 12 महीनों की अवधि के बाद चुकाने की शर्त पर जमाएँ स्वीकार कर सकता है।

(v) केन्द्रीय सरकार से उधार—निगम भारत सरकार से भी कर्ज ले सकता है। 30 जून, 1988 के अन्त में भारत सरकार से लिये गये ऋणों की बकाया राशि 1.40 करोड़ रु. थी।

(vi) IDBI से उधार—यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी उधार ले सकता है। 30 जून, 1988 को IDBI से ली गई उधार की बकाया राशि 61.85 करोड़ रु. थी।

(vii) विदेशी मुद्रा—निगम विदेशी मुद्रा में उधार लेने का अधिकारी है। ऐसे ऋणों पर भारत सरकार की गारण्टी होती है। निगम को पश्चिमी जर्मनी से कई बार ऋण मिल चुके हैं। जर्मन मार्क में प्राप्त ऋणों का उपयोग पूँजीगत माल, इंजीनियरिंग ज्ञान व सेवाओं के आयात में पश्चिमी जर्मनी के भत्तावा ग्रन्थ देशों से (कुछ देशों को छोड़कर) भी किया जा सकता है। अमेरिका की एजेंसियों का रिएन्ट्रेशनल डवलपमेंट (AID) से हाल में ऋण प्राप्त हुए हैं। निगम को पेरिस बैंक में फ्रेंच में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। समुक्त राज्य (U.K.) से पूँजीगत माल व आयात में वित्त प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने निगम को पीण्ड स्टिलिंग प्रदान किया है। स्वीडन से क्रोनेर में सहायता स्वीकृत हुई है। दिसम्बर 1987 में जापानी येन में कर्ज लिया गया है जिसका कुछ भ्रष्ट धन्योकी डालर में है तथा शेष जापानी येन में है। इस प्रकार विदेशी ऋणदाता एजेंसियों से निगम को विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त हुआ है एवं इससे व्यवहारिक उधार लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया है।

निगम का प्रबंधन व कार्य-प्रणाली—निगम का प्रबंधन 12 सदस्यों के एक मन्त्रालय बोर्ड द्वारा होता है जिसमें सदस्य केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, प्रमुखित वेंग व अन्य मन्त्रालयों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

निगम मकान, भूमि अथवा मशीन की जमानत पर ऋण देता है। ऋण मजूर होने व दो या तीन साल बाद क्रिस्तो में मुग्तान आरम्भ हो जाता है। निगम की ब्याज की सामान्य दर 14.0 प्रतिशत तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह 12.5 प्रतिशत रही है। अपने हितों की रक्षा के लिए निगम स्वीकृत ऋणों के उपयोग पर भी ध्यान देती है। यदि कोई कम्पनी ऋण चुकाने में गड़बड़ करती है तो निगम

उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है भयवा गिरवी रखी हुई सम्पत्ति बेच सकता है।

निगम की प्रगति¹—औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1989 को अपने वार्षिकाल के 41 वर्ष पूरे किये हैं। 1987-88 में इसने 780 परियोजनाओं के लिए लगभग 1351 करोड़ रु की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 730 करोड़ रु की वितरित की।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इवाइया निजी क्षेत्र, समुक्त क्षेत्र, सावं-जनिक क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र में होती है। प्रतिवर्ष सबसे अधिक सहायता निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है।

30 जून 1988 को समाप्त होने वाले 40 वर्षों में इसने लगभग 5306 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की। वितरित की गयी सहायता की राशि 3612 करोड़ रुपये रही। यह मजूर की गई राशि का लगभग 68 प्रतिशत था। 30 जून 1988 तक कुछ स्वीकृत सहायता का लगभग 52 प्रतिशत अधिसूचित (notified) कम विकसित जिलों/क्षेत्रों को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार निगम ने समुचित प्रादेशिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान दिया है। 30 जून 1988 तक स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि में सर्वाधिक अंश 14.9% महाराष्ट्र को मिला। गुजरात को 12.0% व उत्तर प्रदेश को 14% राशि मजूर की गई थी। राजस्थान का अंश 4.9% रहा। अब तक की कुल स्वीकृत सहायता में यंत्रोद्योग को 12.2%, सीमेंट उद्योग को 10.3% तथा चीनी को 6.5% प्राप्त हुआ। कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 33.4% अंश आधारभूत या मूल उद्योगों (basic industries) को दिया गया जिसमें बेसिक मेटल उद्योग, बेसिक औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनिज व विद्युत-सृजन व वितरण शामिल हैं। पूर्वागत मान वाले उद्योगों (Capital goods industries) जैसे मशीनरी, विद्युत मशीनरी व परिवहन उपकरण का 16% अंश स्वीकृत हुआ, मध्यवर्ती उद्योगों (Intermediate goods industries) जैसे रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अणु उत्पाद, खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं टयूब आदि को 21.2% तथा उपभोक्ता माल के उद्योगों को जैसे चीनी, वस्त्र, कागज आदि को लगभग 26.9% एवं शेष लगभग 2.5% सेवा-क्षेत्र में होटल-परियोजनाओं आदि को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार स्वीकृत सहायता में आधारभूत उद्योगों व उपभोक्ता उद्योगों का अंश ऊँचा रहा है।

पिछले कुल वर्षों में निगम को कुछ मामलों में समय पर अपने ऋणों का वापसी भुगतान न मिल पाने (Default) की समस्या का सामना करना पड़ा है जो

वास्तव में एक चिन्ता का विषय है। ज्यादातर कठिनाई सूती वस्त्र मिलों की तरफ से उत्पन्न हुई है। गारण्टी देने वाली राज्य सरकारों ने भी पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं। निगम को समय पर मुग्तान न करने वाली फर्मों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

पिछले 41 वर्षों की अवधि में इसने भारत के औद्योगिक ढाँचे में अपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है। निगम का कार्य-क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके वित्तीय साधनों में भी वृद्धि की गई है। मध्य में ज्यादा पूँजीगत साधन होने पर ही निगम उद्योगों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अब यह उद्योगों की शेयर पूँजी में भी भाग ले सकता है, लेकिन निगम उद्योगों के लिए सभी आवश्यक कार्य नहीं कर सकता, जैसे कच्चे माल की व्यवस्था करना, बाजार-भाग को उत्पन्न करना एवं व्यावसायिक दक्षता का निर्माण करना, आदि। इसलिए निगम की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए सक्षम स्कीमों व दक्ष उद्यम-कर्त्ताओं की आवश्यकता है। निगम ने एक जोलिम पूँजी प्रतिष्ठान (Risk Capital Foundation) (RCF) जनवरी, 1975 से चालू किया था जो नये उद्यमकर्त्ताओं को उदार शर्तों पर वज्र देता रहा है ताकि ये शेयर-पूँजी में सहायक का भ्रश (Share of Promoters' equity) प्रदान कर सकें। यह अपने अस्तित्व के 12वें वर्ष (1987) में जोलिम पूँजी और औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया है। इसे संक्षेप में RCTFC कहते हैं। मार्च, 1974 से निगम के द्वारा स्थापित प्रबन्ध-विकास-संस्थान (Management Development Institute (MDI) व इसके विकास बैंकिंग प्रकोष्ठ (Development Banking Cell) (DBC) ने कई पाठ्यक्रम सम्पन्न किये हैं जिनमें प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

प्राजकल निगम निजी निगमित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहाकारी क्षेत्र में स्थापित उपक्रमों की वित्तीय सहायता देकर भारत का औद्योगिक विकास करने में प्रयत्नशील है। इसने पाँच तकनीकी सलाहकार संगठन (Technical Consultancy Organisations) (TCOs) स्थापित करने में योगदान दिया है जो ग्रामीण, अति लघु (tiny), लघु व मध्यम पैमाने के उद्यमकर्त्ताओं, सरकारी विभागों, व्यापारिक बैंकों राज्यस्तरीय वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक विकास व प्रबंध प्रोजेक्ट-निर्माण त्रियान्वयन व मूल्यांकन आदि में मदद देते हैं। इससे नये उद्यमकर्त्ताओं को लाभ पहुँचा है। ऐसे ही नौ तकनीकी सलाहकार संगठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व तीन भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम में स्थापित किये हैं। इस समय देश में कुल 18 TCOs काम कर रहे हैं। इनमें एक कर्नाटक सरकार ने स्थापित किया है। निगम ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विकास-बैंकिंग व औद्योगिक वित्त पर ष पीठें (Six Chairs) स्थापित की हैं जिससे इन विषयों पर अनुसंधान व उच्च स्तरीय अध्ययन को काफी प्रोत्साहन मिला है।

1982-83 में निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्यमशीलता विभाग संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India) (EDII) की स्थापना में सहायता प्रदान की है। साथ में विज्ञापन व टेक्नोलॉजी/उद्यमशीलता 'विकास कार्यक्रम' की लागत में अपना हिस्सा लेने की मजूरी दी है। इस प्रकार यह उद्यमशीलता के विकास को भी काफी प्रोत्साहन दे रहा है।

वित्तीय सेवाएँ (Financial Services)

पिछले वर्षों में IFCI की निम्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रविणित हुई हैं —

(i) मर्जेंट बैंकिंग—यह कार्य 1 जुलाई 1986 से प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत परियोजना-परामर्श तथा कम्पनी क्षेत्र में मध्यम व बड़े उपक्रमों को एक मुश्त मुबियाएँ उपलब्ध करना है ताकि उन्हें नए प्रोजेक्टों के निर्माण व क्रियान्वयन या आधुनिकीकरण या विविधीकरण में मदद मिल सके। इससे वित्तीय गृहाणा में मदद मिलती है तथा पूँजी के ढाँचे की स्कीम बनाने एकीकरण व समावेदन (merger) के प्रस्तावों को लागू करने में सहायता प्राप्त होती है।

(ii) उपकरण-लीजिंग—यह 1 जून, 1988 से प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत बालू औद्योगिक इकाइयों को सीज पर उपकरण (equipment) उपलब्ध किया जायगा। ये औद्योगिक इकाइयाँ कम्पनी या सहकारी क्षेत्र में हो सकती हैं। वित्तीय लीजिंग, सिडीक्टेड लीजिंग जिरी एवं लीजिंग के पुनः लीज रूप की आपाने व आयानित उपकरण की लीजिंग की व्यवस्था की जायेगी।

(iii) सप्तायर्स-उधार-योजना—यह 1987-88 से बालू की गई है। इससे उपकरण-निर्माता व उपकरण-प्रयोगकर्ता दोनों को लाभ होगा। मशीनरी आदि उधार पर दी जायेगी। मुग्तान विलम्बित-आधार पर होगा। उधार के सम्बन्ध में जो बिल बनेंगे IFCI उन्हें आधार पर अग्रिम राशि (advances) देगा। इस स्कीम को लागू करने से मशीनें काम में लेने वालों को मशीनें उधार पर मिलन लग जायेगी।

आशा है इन वित्तीय सेवाओं से उत्पादकों को लाभ पहुँचेगा। इससे देश का औद्योगिक विकास अधिक तेजी से हो सकेगा।

(iii) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (NIDC)

बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास व वित्त से सम्बन्धित दूसरा महत्वपूर्ण निगम राष्ट्रीय औद्योगिक निगम है जो 20 अक्टूबर, 1954 को स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने ही इसमें समस्त पूँजी लगायी है।

उद्देश्य—(1) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम मुख्यतः उन उद्योगों में पूँजी लगाने के लिए बना है जो नियोजित विकास के दौरान स्थापित किये जाते हैं। यह पूँजीगत माल, मशीन व अन्य साज-सामान बनाने को प्राथमिकता देता है। यह

औद्योगिक कार्यक्रमों का अध्ययन व जाँच करता है। (2) यह सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में सहयोग स्थापित करता है। जहाँ तक हो सकता है निजी क्षेत्र में उपलब्ध औद्योगिक साज-सामान, अनुभव व दक्षता का अधिकतम उपयोग करता है। यह ऐसे उद्योग स्थापित करता है जो आगे आकर निजी क्षेत्र में सहायक उद्योग स्थापित करने में मदद देने हैं। इस प्रकार यह देश में सन्तुलित व एकीकृत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। (3) निगम इंजीनियरों के दल तैयार करता है जो सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। (4) यह प्रमुख किस्म के औद्योगिक सामान तैयार करने का विशेष प्रयत्न करता है, जैसे कच्ची फिनिश, एल्यूमिनियम, कृत्रिम रबड़ व दवा, रंग व प्लास्टिक उद्योग का आवश्यक सामान। (5) किसी भी उद्योग को सरकारी ऋण देने के सम्बन्ध में यह सरकारी एजेंट के रूप में काम करता है। प्रारम्भ में यह सहायता का कार्यक्रम उट व सूनी वस्त्र उद्योग के प्राधुनिकीकरण व पुनर्स्थापन के लिए दिये गये सरकारी ऋणों पर लागू किया गया था।

प्रगति—गुरु के वर्षों में हमने सूती वस्त्र, उट व मशीनी योजारों के उद्योगों के विस्तार, पुनर्स्थापन या प्राधुनिकीकरण के लिए ऋण वितरित किये थे। पिछले वर्षों में NIDC का औद्योगिक विकास के लिए सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने का काम अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह विस्तृत डिजाइनों तैयार करता है तथा इंजीनियरी सेवाएँ उपलब्ध करता है। इसकी सेवाओं का उपयोग केंद्रीय व राज्य सरकार, भारत में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उपक्रम एवं विदेशी सरकारें, विदेशी उद्यमकर्ता तथा समुक्त राष्ट्र सच. आदि करते हैं।

पिछले वर्षों में हमने भारतीय टेलीफोन उद्योग के लिए नगर-निर्माण, कोन इण्डिया लि. के लिए भवन-निर्माण कम्प्लेक्स तथा भारतीय तेल निगम के लिए अनुसंधान व विकास केन्द्र के लिए इमारत बनाने के लिए डिजाइन आदि तैयार करने व सलाह देने का काम हाथ में लिया था। इसी वर्ष लीबिया, प्रदन व जजी-वार का भी इंजीनियरी व सलाह का कुछ काम लिया था।

तीन दशकों से अधिक अवधि तक काम करने के बाद भी निगम के कार्य की दिशा स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह एक सलाहकारी संस्था बन कर रह गया है। इसकी गतिविधियों में प्रशासनिक विफलताएँ, वित्तीय कुप्रबंधन व तकनीकी प्रचार-बुलन्दताएँ पाई गई हैं।

(IV) भारतीय औद्योगिक सलाह एवं वित्तियोग निगम (ICICI)

5 जनवरी, 1955 को भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक सलाह एवं वित्तियोग निगम स्थापित किया गया था। इस निगम का उद्देश्य निजी क्षेत्र के लिए पूँजी की व्यवस्था करना है। इसके कार्य अधाकित हैं :

(1) निजी क्षेत्र के उद्योगों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में मदद पहुँचाना, (2) ऐसे उद्योगों में आन्तरिक व विदेशी निजी पूँजी को भाग लेने के लिये प्रोत्साहन देना, (3) औद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना और पूँजी-बाजार का विस्तार करना। इसकी विशेषता यह है—(क) पूँजी या तो दीर्घकालीन व मध्यमकालीन ऋणों के रूप में प्रदान करता है अथवा यह श्रमों की परीद में भाग लेता है, रूपों में वज्र 15 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाना है, (ग) नये श्रमों व प्रतिश्रुतियों का बाजार में अभिगोपन करता है; (ग) अन्य निजी विनियोग के श्रोतों के ऋणों पर गारण्टी प्रदान करता है (घ) जितनी ज़रूरी सम्पत्ति हो सके उतनी ज़रूरी एक उद्योग में से विनियोग की रकम निशालकर दूसरे उद्योग में उसके पुनर्विनियोग की व्यवस्था करता है और (ङ.) भारतीय उद्योगों का प्रबन्धनीय, तकनीकी व प्रशासनिक सहायक सेवाएँ मुहूर्त करता है। अतः यह निगम निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के विकास के लिए भरसक प्रयत्न करता है। 1983 से इसने लीजिंग (Leasing) की क्रियाएँ भी प्रारम्भ कर दी हैं जिनसे अन्तर्गत पूँजीगत परि-सम्पत्तियों को पट्टे पर लेने वाले व्यक्ति इनके उपयोग से प्राप्त प्रत्याशित या अनुमानित आय के आधार पर लीज की एवज में भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रणाली आज़रम विकसित व विकसशील दोनों प्रकार के दशों में बहुत लोकप्रिय हो रही है।

पूँजी—इस मन्था के निर्माण में विदेशी वित्तीय सहायता ने भी हिस्सा लिया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग का एक नमूना प्रस्तुत करता है।

अब निगम की अधिकृत पूँजी 50 करोड़ रुपये की है, जो 100 रुपये वाले 50 लाख शेयरों में बटी हुई है। 1987-88 (अप्रैल-मार्च) में इसने 1946.4 करोड़ रु के कुल कोष एकाग्र किये जिनमें बाह्य साधन 1285.4 करोड़ रु के तथा आन्तरिक साधन 661 करोड़ रु के थे। ये 1986-87 से 84.6% अधिक थे। बाह्य साधनों में सरकार व IDBI से उधार, बाड/ऋण-पत्रों की राशि व विदेशी मुद्रा आती है तथा आन्तरिक साधनों में बर्जदारों की अदायगी व प्राप्त ब्याज तथा प्राप्त लाभान आते हैं। इसको विश्व बैंक, जर्मनी, ब्रिटन आदि से कई धार ऋण मिल चुके हैं। यह भारत सरकार व औद्योगिक निगम बैंक से ऋण लेता है और जनता का ऋण-पत्र बचता है।

प्रगति¹—औद्योगिक साधन व विनियोग निगम ने 31 दिसम्बर, 1988 का 34 वर्ष पूरे किये हैं। निगम ने 1987-88 (अप्रैल-मार्च) में सहायता के लिए 1283 करोड़ रुपये स्वीकृत किये तथा 771 करोड़ रुपये वितरित किये। इसमें सहायता उधार व लीजिंग के रूप में सहायता भी शामिल है।

1. Report on Development Banking in India 1987-88, Published by IDBI, Chapter 6.

स्थापना के समय से लेकर मार्च 1988 के अन्त तक वित्तीय सहायता—मार्च 1988 के अन्त तक कुल सहायता 7094 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई थी जिसमें 5138 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई थी। इसमें रुपये में कर्ज, विदेशी मुद्रा में कर्ज, अधिमोपन व शेयरों की सीधी खरीद, गारंटिया आदि सभी शामिल हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में स्थित प्रोजेक्टों की प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय राशि प्रदान की गई है। मार्च 1988 तक स्वीकृत राशि का 11.5% टेक्सटाइल्स, 11.8%, विविध रसायनों तथा 9.6 प्रतिशत बेसिक मेटल उद्योगों के हिस्से में आया। इसी प्रकार इस अवधि में स्वीकृत राशि का 24.1% घन महाराष्ट्र को 14.1%, घन गुजरात को तथा 9.1%, घन उत्तर प्रदेश को तथा 9%, तमिलनाडु को मिला। राज्यों के अनुसार स्वीकृत की गई सहायता का विभाजन देखा जाय तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को लगभग 56.4% मिला जबकि अन्य राज्यों को मिला। सहायता का विभिन्न राज्यों में वितरण काफी असमान रहा है।

निगम ने नई परियोजनाओं में पूँजी निवेश को बढ़ावा दिया है। यह पूँजी-बाजार का महत्वपूर्ण स्तम्भ रहा है। इसका योगदान औद्योगिक उपक्रमों को विदेशी विनिमय प्रदान करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना गया है।

(V) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI)

औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दिसम्बर 1963 में भारतीय संसद में यूनिट ट्रस्ट बिल पास किया गया और 1 फरवरी 1964 से इसकी स्थापना की गई। इसकी प्रारम्भिक पूँजी 5 करोड़ रुपये रखी गयी जिसमें रिजर्व बैंक का आधा हिस्सा तथा शेष जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और अनुमूचित व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों का रखा गया था।

यूनिट ट्रस्ट कम आय वाले लोगों की बचत एकत्र करके विनियोगों में लगाता है। यूनिटों की बिक्री बढ़ाने के लिए इनसे प्राप्त आय पर आयकर व सम्पत्ति कर में कुछ छूट दी जाती है।

प्रगति¹—यूनिट ट्रस्ट न जुलाई, 1964 से यूनिट ट्रस्ट की बिक्री प्रारम्भ की। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक यूनिट 10 रुपये का रखा गया है। यूनिट 10 के गुणन में बेचे जाते हैं और कम से कम यूनिट खरीदने पड़ते हैं। 30 जून 1989 को ट्रस्ट ने अपने कार्यक्रम के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

1 Report on Development Banking in India 1987-88, Chapter 8 pp 36-40

यूनिट ट्रस्ट की विनियोग संमन्धी नीति यह है कि पूँजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आय प्राप्त की जानी चाहिये। एक कम्पनी की प्रतिभूतियों में यूनिट ट्रस्ट अपने कुल विनियोज्य कोषों के 5% से ज्यादा नहीं लगा सकता है।

यूनिटों की बिक्री में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। 1987-88 (अप्रैल-मार्च) में यूनिटों की बिक्री 2059.4 करोड़ रु की हुई जा एक अभूतपूर्व रिकार्ड था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 63.3% अधिक थी। इस प्रकार 1987-88 में यूनिटों की बिक्री 2000 करोड़ रु की सीमा को पार कर गई है। इस वर्ष यूनिट स्कीम 1964 में यूनिटों की बिक्री सर्वाधिक हुई। (859.3 करोड़ रु की)। मासिक आय यूनिट स्कीम, अतिरिक्त बानस सहित साथ में विकास (मरया 10) 1988 में यूनिटों की बिक्री काफी हुई।

1982-83 में यूनिट ट्रस्ट ने एक मासिक आय यूनिट स्कीम, 1983 लू की थी जो 55 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों विधवाओं, शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों तथा कुछ संस्थाओं के लिए काफी उपयोगी रही है। इसमें 12% वार्षिक की दर से लाभान्वित पाच वर्ष तक प्रति माह दिया गया है।

30 जन, 1988 को ट्रस्ट के कुल विनियोज्य कोष 6738.8 करोड़ रुपये के थे। यूनिट ट्रस्ट ने अपने कोष सुदृढ़ संस्थाओं में लगाये हैं। ये संस्थाएँ वित्तीय सार्वजनिक सेवा व निर्माण-उपक्रमों में सलग्न हैं। 1987-88 में यूनिटों की पुन-खरीद (repurchase) की मात्रा लगभग 292 करोड़ रुपये रही जो पिछले वर्ष से काफी अधिक थी। 1966 से ट्रस्ट की पुनर्विनियोजन की स्कीम काफी प्रगति कर रही है। यूनिटहोल्डर अपनी आय ट्रस्ट में ही लगाना पसन्द करने लगे हैं। 1 जनवरी, 1971 से यूनिट-सम्बद्ध बीमा-योजना प्रारम्भ की गई थी। इसमें 10 वर्ष की अवधि के लिए 12 हजार रुपये तक की अधिकतम राशि की बचत-योजना होनी है और इसमें की गई बचत पर आय-कर में छूट मिलती है।

1969 में ट्रस्ट ने ऐच्छिक बचत योजना प्रारम्भ की थी। ट्रस्ट ने 1 जुलाई, 1970 से एक बाल-उपहार-योजना प्रारम्भ की थी जिसके अन्तर्गत 15 वर्ष से कम आयु के छोटे बालकों के लिए उनके माता-पिता या अन्य संरक्षक यूनिट खरीद सकते हैं (न्यूनतम 50)। इसमें लगाई गई राशि बालकों के 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर देने पर वापस मिल जाती है जिससे उनकी शादी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश-यात्रा, व्यापार-व्यवसाय की स्थापना, आदि कार्य अधिक सुगमता से सम्पन्न किये जा सकते हैं। इसने मासिक-आय-यूनिट-स्कीम, अतिरिक्त विकास सहित (10) 1988 में लागू की है। इन स्कीमों में यूनिटों की काफी बिक्री होती है।

1987-88 में इसकी कम्पनी शेन को 749 करोड़ रु की सहायता वितरित की 1 मार्च 1988 तक कुल 2443 करोड़ रु. की सहायता वितरित की गई।

(VI) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)

यह औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में एक सर्वोच्च या शीर्ष (apex) संस्था है। इसने 1 जुलाई, 1964 में कार्यान्वयन किया था और 30 जून, 1989 को इसके कार्यकाल के 25 वर्ष पूरे हो गये हैं। यह पहले के औद्योगिक पुनर्वित्त निगम को अधिन में विलीन करके स्थापित किया गया था। 16 फरवरी, 1976 से इसका पुनर्गठन किया गया जिसका उद्देश्य मखिल भारतीय व राज्यीय स्तर पर वित्तीय सहायता तथा सांख्यिक क्षेत्र के बैंकों में परस्पर समन्वय स्थापित करना है। उपर्युक्त तारीख से ही वह रिजर्व बैंक से पृथक् कर दिया गया (delinked from the RBI)। IDBI की जो पूँजी रिजर्व बैंक के पास थी, वह भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है। इसके दो प्रकोष्ठ (cells) कर दिये गये : पहला घरेलू वित्त प्रकोष्ठ तथा दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रकोष्ठ।

औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधन¹—जून, 1989 के अन्त में IDBI की प्रदत्त पूँजी 540 करोड़ रु. हो गई थी। यह भारत सरकार से उधार लेता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय औद्योगिक सहाय (दीर्घकालीन किया) कोष से उधार लेता है जिसके अन्तर्गत 1988-89 में 375 करोड़ रु. लिये गये। यह जीवन बीमा निगम से भी उधार ले सकता है। सहायता-प्राप्त उपक्रमों के बापसी मुग्तान से भी इसके साधनों का निर्माण होता है। यह विदेशी मुद्रा में उधार लेता है। इसने डालर व येन में कर्ज लिये हैं।

अन्य वित्तीय संस्थानों की तुलना में इसको अधिक स्वतन्त्रता दी गई है। यह पूँजीगत साधन बढ़ाने में बालू वित्तीय संस्थानों की मदद दे सकता है, उनके द्वारा दिये गये ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान कर सकता है, विविष्ट प्रोजेक्टों के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण दे सकता है और नये इंजीनियरी व अन्य उद्योगों के पूँजीगत मास के निर्धार में वित्तीय सुविधा दे सकता है। औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक उपक्रमों की छानबीन व जाँच का कार्य भी कर सकता है।

एक विशेष विकास सहायता कोष (Special Development Assistance Fund) का निर्माण किया गया है। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गयी धन-राशि जमा की गई है। यह कोष भी औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा ही संचालित होता है। इसका उपयोग उन आवश्यक उद्योगों में पूँजी लगाने में किया जाता है जो विशुद्ध व्यावसायिक आधार पर अथवा साधन-संस्थाओं के द्वारा निर्धारित सामान्य स्तरों के आधार पर ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार उन उपक्रमों की भी स्थापना की जा सकती है जिनमें पूँजी लगाने में साधारण बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएँ तैयार नहीं होती।

1. औद्योगिक उपक्रमों की प्रत्यक्ष सहायता (Direct Assistance to Industry)—यह औद्योगिक संस्थानों को प्रत्यक्ष सहायता निम्न रूपों में देता है .

(i) ऋण देना (ii) उनके बेयर बाण्ड व वृण-पत्र जारी करना और/अथवा अभिगोपन करना (iii) ऋण व विलम्बित भुगतानों पर गारण्टी देना । प्रत्यक्ष सहायता नये उपक्रमों की स्थापना तथा पुरानों के विस्तार व प्राधुनिकीकरण आदि के लिए दी जाती है ।

2. पुनर्वित्त की सहायता (Refinance Assistance)—औद्योगिक विकास बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य औद्योगिक ऋणों पर पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना है । यह सुविधा राज्य वित्त निगमों (SFC) व अन्य बैंकों को उनके द्वारा लघु व मध्यम उद्योगों (सड़क परिवहन आलमों सहित) को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में दी जाती है । इसका आशय यह है कि लघु व मध्यम उद्योगों के वर्जें तो राज्य वित्त निगम व व्यापारिक बैंक देते हैं । फिर वे स्वयं औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त की सुविधा के अन्तर्गत वित्त प्राप्त कर लेते हैं । लघु उद्योगों व पिछड़े जिलों के लिए पुनर्वित्त की रियायती दरें रखी गयी हैं । पुनर्वित्त सहायता को उत्तरोत्तर अधिक उदार बनाया गया है ।

3. पुनर्कटौती की सहायता (Rediscouting Assistance)—औद्योगिक विकास बैंक उन बिलों/प्रोमिसरी नोटों को पुनर्कटौती करता है जो विलम्बित भुगतान के आधार पर स्वदेशी मशीनरी की बिक्री से उत्पन्न होने हैं । इसका अर्थ यह है कि मशीनरी के उत्पादक या विक्रेता बिलों की कटौती अपने बैंकरो से करा लेते हैं और बाद में बेहर उन्ही बिलों की पुनर्कटौती औद्योगिक विकास बैंक से कराते हैं । इस व्यवस्था में स्वदेशी मशीनरी के उत्पादक अपने क्रेताओं को उधार दे पाते हैं लेकिन वे उत्पन्न बिलों के आधार पर अपने बैंकों से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं और बैंक पुनः औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्कटौती-सहायता के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त कर लेते हैं ।

4. निर्यात के लिए वित्तीय सहायता (Finance for Exports)—इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार की सहायताएं आती हैं (i) निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना (ii) निर्यात साख के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना (iii) विदेशी क्रेताओं या आह्वनों को भारत से पूंजीगत व इन्वोनियरी माल भगाने के लिए (व्यापारिक बैंकों की साभेदारी में) वर्जें मंजूर करना (iv) साख की विदेशी लाइनें । इसके अन्तर्गत विदेशी सरकारों को भारत से माल भगाने के लिए वर्जें दिया जाता है तथा (v) निर्यात पर गारण्टी प्रदान करना । इस प्रकार विभिन्न रूपों में निर्यात के लिए भारतीय व विदेशी दोनों आदि को वित्त प्रदान किया जाता है । अब यह कार्य Export Bank (निर्यात-आयात बैंक) को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

पिछले वर्षों में विभिन्न देशों में भारतीय माल का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर्ज दिये गये हैं। पहले इन्जीरिया, जाम्बिया व कीनिया में बन, टुक, बेनिन पुर्ज आदि का निर्यात बढ़ाने के लिये कर्ज दिये गये हैं। व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्त की सहायता दी गई ताकि निर्यात के लिए कर्ज दिये जा सकें। इण्डोनेशिया सरकार को भारतीय मशीनरी का निर्यात कर मुक्त करने के लिए कर्ज दिया गया ताकि वहां एक टूल-रूम व ट्रेनिंग केन्द्र स्थापित किया जा सके।

कीनिया सरकार, घाना गणराज्य सरकार व जमैका सरकार को भारत में इन्जीनियरी का मान व मशीनरी सरीदाने के लिए विदेशी साख की माहने स्वीकृत की गई। इण्डोनेशिया, मलयेशिया, मियायूर, चीन, नाइजीरिया व श्रीलंका में सयुक्त-उद्यमों की भी व्यवस्था की गई।

5 अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता (Assistance to other Financial Institutions)—औद्योगिक विकास बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे IFCI, ICICI, SFC, IRBI को उनके जयर व बोर्ड आदि खरीदकर वित्त प्रदान करता है। इस प्रकार यह वित्तीय संस्थाओं के पूँजीगत साधन बढ़ कर उन्हें अधिक काम करने के योग्य बनाता है। यह 'वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय संस्था' माना जा सकता है। औद्योगिक विकास बैंक एक समन्वयात्मक एजेंसी (Coordinating agency) है और विविध प्रकार में औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देने में संलग्न है। यह मार्बत्रनिक क्षेत्र व समुक्त क्षेत्र के उद्योगों को भी मदद देता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों की प्रगति¹—औद्योगिक विकास बैंक के विविध कार्यों में विशेषतः पुनर्वित्त (Refinance) व पुनर्मुनाई का पुनर्कटोरी (Rediscount) के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

बैंक ने बड़े आकार के प्रोजेक्टों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की नीति पर बल दिया है। यह टेक्नीशियन-उद्यमकर्ता के द्वारा मुक्तये गये छोटे प्रोजेक्टों पर भी ध्यान देता है। बैंक ने सुरक्षा-उत्पुल, आयात-प्रतिस्थापन, निर्माणोत्पुल एवं उप-मोचना-माल उत्पन्न करने वाले उद्योगों और कृषि-विकास व औद्योगीकरण व आधार तैयार करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी है।

1964-89 (कुल-वर्ष) तक अपने कार्यकाल के 25 वर्षों में हमने सकल वित्तीय सहायता लगभग 34400 करोड़ रुपयों की मजूर की और 25112 करोड़ रुपयों का वितरित की। मजूर की गई सहायता में से रिटर्न क्षेत्रों को 14123 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कुल मजूर की गई सहायता का लगभग 43% था।

1. IDBI, Annual Report 1988-89 Chapter 2, IDBI's Operations

1988-89 के प्रगति—1988-89 में सहायता के लिए कुल स्वीकृत राशि 4747 करोड़ रुपये थी जिसमें से वितरित की गई राशि 3381 करोड़ रुपये थी। इससे लघु उद्योगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता भी बढ़ायी गयी है।

1988-89 में कुल मजूर की गई सहायता का बड़ा अंश निम्न उद्योगों को प्राप्त हुआ था बिजली उत्पादन सड़क परिवहन वस्त्र विविध रसायन उद्योग तथा मोटर वाहन इत्यादि। इसमें सड़क परिवहन का अंश सर्वाधिक था।

1964-89 तक कुल मजूर की गई सहायता में महाराष्ट्र, गुजरात उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के अंश ऊँचे रहे हैं। इस अवधि में कुल मजूर की गई सहायता का लगभग 43% पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के हिस्से में आया है। इस प्रकार IDBI विद्युत् देणों व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दे रहा है।

विकास सहायता कोष

(Development Assistance Fund (DAF))

जैसा कि पहले बताया जा चुका है विकास सहायता कोष औद्योगिक विकास बैंक के अंगगत ही स्थापित किया गया है ताकि ज्यादा जोरित यात्री औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा सके। मार्च 1965 से मार्च 1989 के बीच तक DAF के कोषों में कुल सहायता लगभग 903 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई जिसमें से प्रयुक्त की गई सहायता की राशि 692 करोड़ रुपये रही।

1986 में सरकार ने एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया है जो IDBI का सहायक है। यह लघु उद्योग विकास कोष (SIDF) व राष्ट्रीय इन्वेंचरी कोष (NEF) का मंचालन करेगा। लघु उद्योग विकास कोष इस से लघु उद्योगों को विस्तार प्रीतिष्कीकरण व प्रभुत्विकीकरण के लिए ऋण दिये जायेंगे। औद्योगिक विकास बैंक में जनरल फण्ड से 100 करोड़ रु की व्यवस्था उपर्युक्त कोष के लिए की है। तृतीय सहायता राज्य वित्त निगमों व बैंकों आदि के माध्यम से दी जायगी। इस कोष से लघु उद्योगों के विकास पर महत्त्व प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय इन्वेंचरी कोष से भी लघु इकाइयों को सहायता दी जायगी।

निष्कर्ष—विद्युत् देणों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बड़े व महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टों के साथ साथ बड़ी परियोजना में मध्यम व लघु-मध्यम प्रोजेक्टों को अधिक उदारतापूर्वक सहायता प्रदान की है। बैंक की यह कोशिश रही है कि सहायता सहायता के अभाव में कोई भी उपयुक्त मध्यम व लघु मध्यम आकार की परियोजना नहीं हो जाय। इसके लिए बैंक को पुनर्वित्त व पुनर्गठनी की सहायता-योजनाओं में परिवर्तन किये गये हैं। इसने मध्यमकालीन नियमित सहायता का भी अधिक उदार

दनाया है। यह सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी सहायता देने लगा है। इनमें अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है।

भावी योजनाओं में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को धीमे बढ़ाना है। भारत में औद्योगिक विकास देकू के ऊपर औद्योगिक विकास की नई जिम्मेदारियाँ आई हैं। IDBI की नई स्कीमे —

(i) उद्यम पूँजी निधि-योजना (Venture Capital Fund Scheme) :- स्वदेशी टेक्नोलॉजी के विकास व उपयोग तथा आयातित टेक्नोलॉजी के अनुकूलन व विकास के लिए IDBI ने उद्यम पूँजी निधि-योजना चालू की है।

इन योजना में से इन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) बस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण निधि योजना (Textile Modernisation Fund Scheme) इसके अन्तर्गत बस्त्रोद्योग के आधुनिकीकरण के लिए बतर्ही व मिश्रित बस्त्र मिलों को सहायता दी जाती है।

यह अगस्त 1986 से लागू हुयी है। धारा है इन नई स्कीमों से उद्योगों को काफी लाभ होगा।

(VII) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (IRCI)

अथ भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI)

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (Industrial Reconstruction Corporation of India) अगस्त, 1971 में बीमार व बन्द मिलों के पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापन में मदद देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका कार्यालय कलकत्ता में स्थित है। इसकी अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये रखी गयी है और 10 करोड़ रुपये की निर्गमित पूँजी IDBI, LIC, ICICI, SBI व राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ली है। प्रदत्त पूँजी 5 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने इसे 10 करोड़ रुपये का व्याज मुक्त कर्ज भी दिया है। यह रिजर्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक व पूँजी बाजार में आवश्यकतानुसार ऋण को ले सकता है।

प्रगति¹—(i) अपनी स्थापना के समय से लेकर 31 मार्च, 1988 तक इसने औद्योगिक इकायों को 225 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जिसने से लगभग 511 करोड़ रुपये की राशि बिनशित की गई। 1987-88 में स्वीकृत ऋणों की राशि लगभग 186.5 करोड़ रु. व दिव्यरित राशि 102 करोड़ रु. रही। इसन बैंक व अन्य समस्याओं के माध्यम से भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है। इन सब सहायता कार्यों से हजारों व्यक्तियों का रोजगार कायम रखा जा सका है। यदि निगम मदद नहीं करता तो ये इकाइया सम्भवतः बन्द हो जानी और काफी व्यक्ति बेकार हो जाते।

1. Report on Development Banking in India 1987-88, pp. 45-46, ch. 10.

प्राप्त सहायता में परिवहन उपकरण रबड़, वस्त्र, बेमिन मेटल तथा वस्तुओं के उद्योग-मशूहों को अधिकांश सहायता मिली है। शेष सहायता बागज, रमायन मशीनरी व अन्य उद्योगों को प्राप्त हुई है।

अगस्त 1984 में IRCI एक वित्त प्राप्त करने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) में बदल दिया गया ताकि यह अपना काम अधिन मुच्चा रूप में कर सके।

(VII) भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) व इसकी सहायक इकाइयाँ*

1973 में देश में सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद में GIC व इसकी चार सहायक इकाइयाँ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही हैं। यह अपनी सहायता ऋणों अभिगोपन, प्रत्यक्ष अगदान आदि के रूप में देता है।

1987-88 (अप्रैल-मार्च) में इसने 98 करोड़ रु की सहायता स्वीकार की तथा 104 करोड़ रु. की वितरित की (पहले की बकाया सहित)। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व मयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई है। निगम की सहायता का विशेष लाभ निम्न उद्योगों को मिला है—टेक्स्टाइल्स, मशीनरी, विद्युत मशीनरी, विद्युत सृजन सीमेंट, लोहा व इस्पात आदि।

(ix) आवास-विकास वित्त निगम लि. (HDFC Ltd.)—1977 में ICICI ने इसकी स्थापना में मदद दी ताकि मध्यम व निम्न आय वालों को शहरों व गाँवों में मकान बनाने व खरीदने के लिए दीर्घकालीन कर्ज की सुविधा मिल सके।

यह व्यापारिक बैंकों से अधि-ऋण लेता है तथा जमाएँ स्वीकार करता है। 1987-88 (अप्रैल-मार्च) में इसने 297 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किये तथा 221 करोड़ रु वितरित किये। यह अमेरिका के पूँजी-बाजार से कर्ज लेने का भी प्रयत्न कर रहा है।

(x) भारत का आयात-निर्यात बैंक (Exim Bank)—यह समूह के अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी, 1982 को स्थापित किया गया था। इसने 1 मार्च 1982 में कार्य चालू किया था। इसने IDBI से सभी कार्य ले लिए हैं जिसका सम्बन्ध निर्यातकों की वित्तीय सहायता देने, विदेशी ग्राहकों को उधार देने, निर्यात माल पर पुनर्वित्त की सुविधा देने, आदि से था। इससे परिवहन-उपकरण, शक्ति-सृजन व वितरण-उपकरण के निर्यात की वित्तीय व्यवस्था में मदद मिली है। दक्षिण-पूर्वी एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया आदि को कई प्रकार की भारतीय मशीनरी

*दी यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स क. लि., ओरियेन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स क. लि., दी नेशनल इन्श्योरेन्स क. लि., तथा दी न्यू इण्डिया एश्योरेन्स क. लि.।

का निर्यात किया गया है। 1987 में इसने 691 करोड़ रु. की फण्डेड सहायता स्वीकृत की जिसमें से 599 करोड़ रु. की प्रयुक्त हुई।

लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था

भारत के औद्योगिक ढांचे में लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया है। इनके लिए स्थिर पूँजी व कार्यशील पूँजी दोनों की आवश्यकता होती है। इनको पूँजी प्रदान करने वाले कुछ परम्परागत साधन रहे हैं, लेकिन आधुनिक युग में वे पर्याप्त सिद्ध हो चुके हैं। लघु उद्योगों के स्वामी प्रायः अपनी पूँजी से कार्यरिक्त करने हैं। उन्हें समय-समय पर सरकारी, महाजनो व व्यापारियों से पूँजी की सहायता मिलती है। वे अपने मित्रों व सम्बन्धियों से भी पूँजी जुटाते हैं। लेकिन ये साधन अब लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते।

लघु उद्योग प्रायः व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी अथवा निजी मीमित दायित्व वाली कंपनियों के आधार पर संगठित किये जाते हैं। वही-वही ये मार्बजलिक कंपनियों के रूप में भी स्थापित किये जाते हैं। इन्हें संगठित मुद्रा-बाजार से पूँजी नहीं मिल पाती है क्योंकि इनके शेयरों का विक्रान्त अत्यन्त कठिन होता है। प्राजकल लघु उद्योगों को भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की सुविधा काफी बड़ा दी गई है।

लघु व मध्यम उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माधन इस प्रकार हैं : (1) उद्योगों को सरकारी सहायता सम्बन्धी अधिनियमों के अन्तर्गत (State Aid to Industries Act) मिलने वाली पूँजी, (2) राज्य वित्त निगम (SFC); (3) राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC), (4) भारतीय स्टेट बैंक व इनसे सम्बद्ध अन्य बैंक, (5) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तथा (6) रिजर्व बैंक की साथ भारतीय-व्यवस्था के अन्तर्गत लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता।

1. उद्योगों को सरकारी सहायता अधिनियमों के अन्तर्गत मिलने वाली पूँजी—राज्य वित्त निगम बनने से पूर्व राज्य सरकारें इन अधिनियमों के अन्तर्गत लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करती थी। सर्वप्रथम 1952 में तमिऴनाडु में एक अधिनियम पार हुआ था। बाद में अन्य राज्यों में भी ऐसे अधिनियम पार किये गये। इनके अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने वाषिक बजट में लघु एवं मध्यम उद्योगों को उधार देने के लिए धन की व्यवस्था करती रही है। आवेदन पत्र की पर्याप्त जाँच करने के बाद उधार की राशि स्वीकार की जाती है। भारत में ये ऋण अधिक लोकप्रिय नहीं रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे सरकार प्रतिवर्ष उधार के लिए मामूली रकम अलग रखती है, एक व्यक्ति को थोड़ी रकम प्राप्त हो सकती है, उधार की राशि स्वीकृत होने में बहुत समय लप्ट हो जाता है तथा उधार का सौदा गुप्त नहीं रखा जाता। इन कारणों से इन अधिनियमों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता सक्रम प्रमाणित नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को ऋण व अनुदान देती है ताकि लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

2 राज्य वित्त निगम (State Financial Corporations) (SFCs)—
 लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1951 में राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत इस समय 18 राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं। इसमें तमिलनाडु का औद्योगिक विनियोग निगम लि. भारतीय नम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में स्थापित किया गया था। लेकिन यह भी अन्य वित्तीय निगमों की तरह ही काम करता है।

राज्य वित्त निगम लघु एवं मध्यम प्रकार के उद्योगों की मध्यम न दीर्घ-वालीन सात प्रदान करते हैं। ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कम पर ही होते हैं और उस के छोटे रूप हैं। ये निजी उद्यमकोंवालों माभकारी पर्मा लन निजी सीमित दामिस्व वाली कम्पनियों को भी सात प्रदान करते हैं। राज्य वित्त निगमों की पूँजी में राज्य सरकार, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं आम जनता का भाग होता है। राज्य वित्त निगम अधिनियम अधिनियम 20 वर्ष के लिए काम दे सकते हैं। एवं राज्य वित्त निगम की अधिकृत कैपिटल-पूँजी प्रायः 50 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक होती है। ये आठ व अक्षयपन रखकर भी पूँजी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें जनसाधारण से जमा प्राप्त करने का अधिकार होता है।

राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों की सम्पत्ति की जमागत पर भरण देते हैं और जब ये 60 लाख रुपये तक का ऋण दे सकते हैं। राज्य वित्त निगम कम्पनियों का प्रत्यक्ष भरण व अग्रिम राशिवाँ देते हैं, इनके अक्षय व अक्षयपत्रों का अक्षयपोषण करते हैं तथा ऋणपत्रों की बिक्री पर गारण्टी देते हैं एवं अक्षयपत्र स्वयं भी जारी करते हैं।

राज्य वित्त निगमों के कार्यों की प्रगति—पिछले वर्षों में राज्य वित्त निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में काफी वृद्धि हुई है। 1970-71 (अग्रज-गार्क) में इन्होंने 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकार की जिसमें से 34 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। 1987-88 की अवधि के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृत राशि 1308 करोड़ रुपये तथा वितरित राशि 941 करोड़ रुपये रही। राज्य वित्त निगमों द्वारा प्रदत्त समग्र समस्त सहायता ऋणों के रूप में पायी जाती है। राज्य वित्त निगमों की सहायता से निम्न उद्योगों में विशेष काम उठाया है—

रसायन व रसायन-पदार्थ, खाद्य प्रोसेसिंग, रोषाएँ तथा टेक्सटाइल्स। पिछले दोनो व लघु दोनो को विशेष रूप से मदद दी गई है।

राज्य वित्त निगमों के समक्ष एक गम्भीर समस्या यह है कि इनको अपने उधार देने वालों से गृहणन व व्याज समय पर नहीं मिल पाता है। इसमें व उड़ीसा में स्थिति विशेष रूप से गम्भीर है और गुजरात, हरियाणा राजस्थान, केरल तथा हिमाचल प्रदेश में असन्तोषजनक रही है। परियोजनाओं के निर्माण व चालू करने

1987-88 में इन्होंने 636 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता स्वीकार की तथा 448 करोड़ रुपये की वित्तित की। वे राजिया पिछले वर्ष में ज्यादा रहे हैं।

इनकी सहायता से वस्त्र उद्योग, म्यापन, खाद्य, मोटर व इस्पात, मेटल पदार्थों, कानून, मशीनरी आदि उद्योगों का विंग्रह रूप में काम पहुँचा है। इनकी IDBI स पुनर्वित्त की सुविधाएँ मिलने लगी हैं।

IDBI ने मितम्बर, 1976 में नये उद्यमकर्ताओं के लिए मोड पुँजी-मॉड (seed capital scheme) चालू की थी जो SIDCs, SHCs के माद्वित्त कार्यान्वित्त की जाती है। इनके अन्तर्गत मध्यम पैमाने की नई इकाइयों के लिए जिनकी प्रोजेक्ट लागत एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, सहायता दी जाती है।

राजस्थान में भी 1969 में राज्य औद्योगिक व वित्तित विकास निगम (RIMDC) स्थापित किया गया था। 1979 में वित्तित निगम के प्रमग में वन जाने पर उसका नाम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व वित्तियोग निगम लि. (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd. (RISICO) कर दिया गया था। यह माईक्रोनिक एव अणुक क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर रहा है। कुछ वर्ष पूर्व डूंगरपुर जिले में माद्वी की-नार नामक स्थान में स्थापित किये जाने वाले पनौराइट बेरीडिनीमियम प्लांट पर प्रगति हुई है। टोंक में बमडा रहने की कारखाना स्थापित किया गया जो घाटे में रहा है। प्रमग औद्योगिक उपक्रम की स्थापित किये जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रोनिकस उद्योग का विकास करने का प्रयास कर रहा है।

4. भारतीय स्टेट बैंक और इनके सहायक बैंकों का सपु उद्योगों के लिये वित्तीय व्यवस्था करने में स्थान—उपनी स्थापना के समय से ही स्टेट बैंक लघु उद्योगों का वित्तीय सहायता पहुँचाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमि निभा रहा है। इनने सहायता की उदार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों की ऋण स्वावृत्त किये हैं।

स्टेट बैंक ने लघु उद्योगों की वित्तित व आधुनिकीकरण के लिए अग्रम-कारणीय ऋण की प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त वित्तित की माख योजना (Installment Credit Scheme) के अन्तर्गत (जिसमें लघु व मध्यम स्काकार के व्यवसायी मात्र-मामान या मशीनरी खरीदने की सुविधा पा सके) स्टेट बैंक व सहायक बैंकों ने ऋण स्वीकार किये हैं। इनने औद्योगिक सहकारी नम्बारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

स्टेट बैंक ने राज्य सरकारों के प्राधीत उद्योग प्रोजेक्टों में सहायी जाने वाला इकाइयों को भी आकरग्रह वित्तित प्रदान किया है।

5 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (The National Small Industries Corporation Ltd) (NSIC Ltd)—यह निगम फरवरी, 1955 में स्थापित किया गया था। यह लघु उद्योगों के विकास के लिए विविध प्रकार के कार्य करता है। इसने अतर्गत लघु इकाइयों की आधुनिक मशीनें किस्तों पर मिल सकती हैं। 1987-88 में इसने 21.9 करोड़ रु की मशीनें किस्तों पर सप्लाई की। निगम विदेशों से मुद्रा भी देता है ताकि विदेशों से मशीनें खरीदी जा सकें। इसने लघु उद्योगों के भारत के निर्यात को भी प्रोत्साहन देना आरंभ किया है। निगम न केवल माल के हिसा से स्थापित करके विभिन्न प्रकार के वस्तु माल के वितरण की व्यवस्था की है।

6 भारतीय रिजर्व बैंक का लघु उद्योगों की वित्त-व्यवस्था में योगदान—(अ) राज्य वित्त निगमों के माध्यम से—रिजर्व बैंक न विभिन्न राज्यों में स्थापित वित्त निगमों की पूंजी में हिस्सा लिया है। यह व्यवस्था दीर्घकालीन ऋणों के सम्बन्ध में होती है।

(आ) राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से—रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (2) (bb) के अनुसार यह राज्य सहकारी बैंकों को कुटीर व लघु उद्योगों के उत्पादन व विक्री से सम्बन्धित कार्यों के लिए बनाये गये बिल व प्रॉमिसरी नोटों पर पुनर्जटोनी (Rediscount) की सुविधा देता है। ये बिल या नोट 12 महीने की अवधि तक होने चाहिए और इनके मूलधन व व्याज की गारण्टी राज्य सरकार की होती है। इस प्रकार रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों के लिए अल्पकालीन पूंजी की व्यवस्था करता है।

(इ) रिजर्व बैंक की साल-गारण्टी स्कीम—1 जुलाई 1960 से रिजर्व बैंक ने 22 जिला में साल गारण्टी स्कीम लागू की थी, जिसके अन्तर्गत बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों पर रिजर्व बैंक गारण्टी देता था तथा ऋणों की जोखिम में भागीदार हो जाता था। गारण्टी स्कीम का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु उद्योगों को पूंजी देने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना था। जनवरी, 1963 से यह स्कीम सारे देश में लागू कर दी गई। इसे स्थायी आधार पर संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा पिछले वर्षों में इसको काफी उदार बनाया गया है। गारण्टी कमीशन घटाया गया है जिससे इस योजना का काफी विस्तार हुआ है।

भारत सरकार ने 31 मार्च 1981 को रिजर्व बैंक द्वारा संचालित साल-गारण्टी स्कीम समाप्त करके एक अप्रैल 1981 से एक लघु-ऋण (लघु-उद्योग) गारण्टी स्कीम लागू की है जो जमा बीमा व गारण्टी निगम द्वारा संचालित की जाती है।

यह स्कीम सभी व्यापारिक बैंको, प्रादेशिक ग्रामीण बैंको, राज्य वित्त निगमों व सहकारी बैंको के लिए खुली है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगों के लिए रहने की व्यवस्था वित्तीय सुविधाएँ बहुत बढ़ गई हैं। राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास व वित्तियोग निगम, भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं विभिन्न व्यापारिक बैंक, (भारतीय स्कीम का लाभ उठाकर) लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएँ बढ़ाने में लगे हुए हैं। यदि वित्त के अतिरिक्त इनकी अन्य समस्याएँ भी हल की जायें तो लघु उद्योगों का मजिद्व्य काफी उज्जवल बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक औद्योगिक वित्त व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए हैं। बड़े पैमाने व उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए कई निगम स्थापित किये गये हैं। बीमार व बन्द मिलों के पुनर्निर्माण के लिए अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) काम कर रहा है। लघु व मध्यम आकार के उद्योगों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कई संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। इन प्रकार औद्योगिक वित्त की सुविधाएँ काफी बढ़ गयी हैं। मजिद्व्य में औद्योगिक वित्त की माँग और बढ़ेगी, क्योंकि देश में सभी प्रकार के उद्योगों का विकास किया जायगा। वित्त की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना आवश्यक होगा, वरना औद्योगिक प्रगति तेजी से नहीं हो सकेगी। भारत में वित्तीय संस्थाओं का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। विभिन्न सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएँ वित्त प्रदान करने के साथ-साथ उद्योगों के लिए विकास-सम्बन्धी कई आवश्यक कार्य भी करती हैं जैसे आवश्यक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना, परियोजनाओं के तकनीकी स्तर की उचित जाँच करना एवं विभिन्न संस्थाओं में धरद्वार तालमेल व समन्वय स्थापित करना आदि। अब औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में एक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है जो वास्तव में बहुत सराहनीय है।

पिछली लगभग दो दशकियों में औद्योगिक वित्त की व्यवस्था बढ़ाने के लिए नये संगठनों का निर्माण किया गया है जिससे इस क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। 1987-88 (अप्रैल-मार्च) की अवधि में IDBI, IFCL, ICICI, ISIRBI, UTI LIC GIC व उसरी सहायक इन्डियो तथा SFCs व SIDCs ने कुल 9298 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकार की, जिसमें से 6779 करोड़ रुपये की विभिन्न महसूना वितरित हुई। कुल स्वीकृत सहायता में IDBI का अंश लगभग आधा था। इसमें ऋण तथा गैर ऋण के अन्विष्ट एवं इनमें प्रत्यक्ष अंश-दान आदि सभी प्रकार की वित्तीय सहायता शामिल हैं। औद्योगिक विकास के लिए अवधि-वित्त-सहायता (term-financing) काफी बढ़ी है और औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना ने इसे एक नया मोड़ दिया है। इन प्रगति पर सन्तोष प्रकट किया

जा सकता है। लेकिन मविप्य में योजनाकाल में औद्योगीकरण की गति तेज होने से पूँजी की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसलिए डमकी पूर्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। पिछले वर्षों में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कुछ कमियाँ भी देखी गयी हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है।

औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में दोष अथवा कमियाँ (Shortcomings in the field of Industrial Finance)

यद्यपि पिछले तीन दशकों में औद्योगिक वित्त के ढांचे में काफी सुधार हुआ है। फिर भी कुछ दोष रह गये हैं जिन्हें निम्न मविप्य में दूर किया जाना चाहिए। औद्योगिक लाइसेंस नीति-जाँच समिति ने औद्योगिक वित्त के सम्बन्ध में जुलाई, 1969 की अपनी रिपोर्ट में निम्न कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था—

1. विभिन्न संस्थाओं का सम्यक्स्थित फैलाव तथा कार्य में दोहराव—विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में दोहराव (Duplication) की स्थिति उत्पन्न हो गई है। IDBI, IFCI, ICICI, के कार्यों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। विदेशी ऋण प्रदान करने में IFCI व ICICI के कार्यों में दोहराव पाया जाता है। लेकिन विभिन्न कार्य बढ़ जाने से यह दोहराव आवश्यक समझा जाने लगा है।

2. LIC, UTI व SBI अपने प्रमुख कार्यों के अलावा उद्योगों को वित्त प्रदान करने के क्षेत्र में काफी आगे आ गये हैं। इससे इनके विभिन्न कामों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

3. औद्योगिक वित्त के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आ पायी है। प्रायः नीची प्राथमिकता वाले उद्योगों को वित्त प्राप्त हो जाता है। IFCI ने अवश्य सहकारी इकाइयों को ऋण प्रदान किया है।

पिछली दशकों में वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण देखने से पता चलता है कि सर्वाधिक राशि इन्जीनियरी उद्योगों को मिली है और उपभोक्ता माल के उद्योगों को कम राशि मिली है। इससे देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की माँग में पूर्ति में असम्यक् उत्पन्न हो गया है।

4. वित्तीय संस्थाओं ने बड़े औद्योगिक घरानों को विशेष रूप से मदद देकर भारत में प्राथमिकता के केन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया है। इन्होंने पिछले क्षेत्रों में नये उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने में अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त की है।

5. प्रोजेक्ट की स्वीकृति व सहायता के वितरण में अश्वधिक विलम्ब पाया गया है। मूलतः एक समस्या यह रही है कि एक ही प्रोजेक्ट की जाँच या मूल्यांकन का कार्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग-अलग कराया गया है जो अनावश्यक था क्योंकि IDBI के नेतृत्व में एक संस्था का मूल्यांकन ही काफी था। यदि IDBI

निजी प्रोजेक्ट को सुदृढ़ मानता है तो उस सभी संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ माना जाना चाहिए। इससे आवेदनकर्ता के लिए काफी सहूलियत ही जायेगी। हाल में कुछ संस्थाओं के द्वारा मिलकर सहायता देने के कार्यक्रम को लागू करने से स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

6 निजी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी तो लगायी गयी है लेकिन उनके प्रबन्ध में सावजनिक/विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं ने भाग नहीं लिया है। इस प्रकार निजी क्षेत्र को सावजनिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त हो गया है लेकिन समाज के प्रति इन्होंने अपना दायित्व पूरी तरह नहीं निभाया है।

7 श्री एस एल शेट्टी (S L Shetty) का मत है कि सावजनिक वित्तीय संस्थाओं में निजी क्षेत्र में पूंजी लगाकर पूंजी गहन परियोजनाओं (capital-intensive projects) को प्रोत्साहित किया है जिससे उत्पादन व रोजगार को बढ़ाने में आवश्यक सफलता नहीं मिल पायी है। इन्होंने इस में एक ऐसे भौद्योगिक ढांचे को पतपाया है जो नागरिकों को पर्याप्त रोजगार नहीं द सकता है।

8 सहायता के राश्वार विवरण को देखने से पता चलता है कि पिछले वर्षों में अधिक विकसित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल गुजरात कर्नाटक व तमिलनाडु को ही भौद्योगिक विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हुई है। असम उड़ीसा मध्यप्रदेश राजस्थान व केरल को कुल सहायता कम मात्रा में मिल पायी है। विकसित राज्यों के पिछड़े प्रदेशों को पिछड़े राज्यों के पिछड़े प्रदेशों/जिलों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है।

9 भौद्योगिक उपक्रम अधिकधिक मात्रा में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं पर प्राप्ति रहने लग है और पूंजी बाजार के परम्परागत साधन कमजोर पड़ गये हैं। यह निर्भरता बड़ पैमाने के उद्योगों में भी पाया जाती है।

10 SFCs आदि के सम्बन्ध में भुगतान की बकाया राशियों की समस्या जार पकड़ती जा रही है। ऋणों के उपयोग की देल रेल बढ़ान की आवश्यकता है। धीनार इकाइयों की समस्या के वढ़ने से भुगतान प्राप्त करने की कठिनाइया अधिक जटिल हो गई है। मार्च 1970 में नियत समय पर न चुकाई जाने वाली राशि का प्रतिशत (default percentage) 17.3 था जो मार्च 1985 में बढ़कर 47.5 हो गया। हिमाचल प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु असम उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल व केरल में डिफाल्ट का प्रतिशत ऊँचा पाया गया है।

11 हाल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम भारतीय टेलीफोन उद्योग भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा बाजार में बाढ़ बेचकर धन एकत्र करने के प्रयास से निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। दल बलों का खरीद पर बाधक की छूट भी दी जाती है जिससे ये बंधों आदि के लिए भी काफी लाभप्रद हो गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बाड़ा पर निजी की शर्तें अधिक अनुकूल होने से य जनता में लोकप्रिय हुए हैं। अतः भविष्य में जनता की सीमित वचन के लिए निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइया में परस्पर होड़ लगगी। सरकार का अपनी तरफ कोष आकर्षित करने के लिए ज्यादा विभेदकारी नीति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा विकास में निजी क्षेत्र अपनी कारगर भूमिका नहीं निभा सकेगा।

औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में सुधार के सुझाव

(Suggestions for Improvement in the
system of Industrial Finance)

1. पूँजी-बाजार को सक्रिय करने की आवश्यकता—औद्योगिक वित्त का प्रमुख स्रोत पूँजी-बाजार माना गया है जहाँ कम्पनियाँ अपने श्रम व ऋण-पत्र वचन-कर वित्तीय साधन जुटाती हैं। यह औद्योगिक वित्त का परम्परागत व प्राथमिक स्रोत कहा जा सकता है। कुछ वर्ष पूर्व पूँजी-बाजार सक्रिय व सञ्चन नहीं था। 1985-86 में मधोय वजट में प्रयत्न करो में कमो करन व अधिक नियन्त्रणों व नियमनों में टीन देने से श्रम-बाजार पर बहुत अनुकूल असर आया था तथा भयरो की खरीद काफी बढ़ी थी। आशा है आगे भी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों के अमलाने से पूँजी-निर्गम से अधिक वित्त की व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा जिससे सार्वजनिक वित्तीय समस्याओं पर भार कम हो जायगा। बड़े पैमाने की इकाइयाँ अपने अतिरिक्त मुनाफो का ज्यादा मात्रा में उपयोग कर पायेंगी।

2. वित्त निगमों एवं संस्थाओं के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे निजी क्षेत्र को ज्यादा ऋण प्रदान कर सकें। लेकिन इसकी भी अपनी मर्यादाएँ होती हैं। अतः औद्योगिक इकाइयों का जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे संस्थागत विनियामकताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। लोगों की अधिक वचन करन के लिए भी पोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. आज भी नये उद्यमकर्ताओं को (जो मध्यम आकार की फर्मों का निर्माण करना चाहते हैं और जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं) पूँजी की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन औद्योगीकरण के विकास व विस्तार के माध्यम यह वर्ग वृद्धि जाता है। अतः इनके लिए पूँजी की व्यवस्था बढ़ाना आवश्यक हो गया है। वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण मन्तूर करने समय ग्राहक के पुराने रिकार्ड व प्रविष्टि पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, वरन् कम्पनी की नवी आमदनी को देखकर जोखिम उठाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में व्याज की दर में जोखिम की मात्रा के अनुसार वृद्धि की जा सकती है। विनिष्ट वित्तीय संस्थाओं की पूँजी लगान की क्रियाओं पर लोकसभा व विधान-

6. भविष्य में अग्निपोषण (Underwriting) के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए—आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ इस सम्बन्ध में संयुक्त कार्यक्रम भी अपना सकती हैं।

7 तकनीकी जाँच सम्बन्धी संस्थाओं का विकास—दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते समय सम्बन्धित कार्यक्रमों की विस्तृत तकनीकी व आर्थिक जाँच करना आवश्यक होता है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए बड़ी तकनीकी व आर्थिक संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये सेवाएँ व्यापारिक बैंकों व सभी विशिष्ट संस्थाओं के काम आ सकती हैं। ऐसी संस्थाओं की स्थापना व विकास का काम किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों में IFCI, IDBI व ICICI द्वारा तकनीकी सलाहकार संगठन स्थापित किये गये हैं।

8 पहले इस बात पर प्रकाश डाला जा चुका है कि राज्य वित्त निगमों को आपस में कोषों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुछ राज्यों में वित्त निगमों के पास कोषों का अभाव और कुछ के पास आधिक्य न रहे।

9. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को आवेदन-पत्रों पर शीघ्रतापूर्वक विचार करना चाहिए जिससे सम्बन्धित कंपनियों को ऋण मिलने में अनावश्यक विलम्ब न हो। एक प्रोजेक्ट का मूल्यांकन व जाँच एक संस्था के द्वारा कर लिए जाने पर उसकी रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा किया जा सकता है जिससे वित्त की स्वीकृति में होने वाला विलम्ब काफी कम हो जायगा। इससे औद्योगिक परियोजनाओं को चालू करने में भी सहूलियत रहेगी।

10 नये उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन—ऊपर जितने भी सुझाव दिये गये हैं, उनसे निजी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों के लिए पूँजी की व्यवस्था में काफी वृद्धि होगी। लेकिन वित्त की सुविधा बढ़ जाने मात्र से ही औद्योगिक उपक्रम सामने नहीं आ पायेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि नये उद्यमकर्ता व नये प्रबंधक ऐसी योजनाएँ प्रस्तुत करें जो काफी स्पष्ट, सुदृढ़, लाभप्रद व सबल दिखाई दें और उनमें पूँजी लगाने में साधारणतया कोई भी वित्तीय संस्था न हिचके। बहुधा यह देखा जाता है कि अधिकांश कार्यक्रम अधूरे, अस्पष्ट व असन्तोषजनक किस्म के होते हैं जिनमें पूँजी लगाना काफी जोखिम से भरा होता है।

11 वित्तीय संस्थाओं की सहायता प्राप्त उद्योगों के प्रबन्ध में भाग लेना चाहिए। अभी तक इस दिशा में मामूली प्रगति हुई है। LIC भी एक निष्क्रिय साभेदार बना रहा है। भविष्य में यह स्थिति बदली जानी चाहिए।

आशा है औद्योगिक वित्त के ढाँचे में किये जाने वाले विभिन्न परिवर्तनों से भविष्य में उद्योगों के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति में काफी वृद्धि होगी। ग्रामीण, लघु, मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए सभी अग्नियों के लिए वित्त की पर्याप्त पूर्ति के होने से ही भारत में औद्योगीकरण की

प्रक्रिया तेज की जा सकेगी। साथ में यह व्यवस्था सार्वजनिक, निजी, संयुक्त तथा सहकारी सभी प्रकार के क्षेत्रों के उद्योगों के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार औद्योगिक वित्त की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए है जिसकी पूर्ति के लिए आगामी वर्षों में काफी प्रयास करना होगा।

प्रश्न

1. भारत में औद्योगिक वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं ? औद्योगिक वित्त की पूर्ति कम क्यों है ?
(Raj, Hycar T. D. C., 1985)
2. सघु एवं कुटीर उद्योगों की वर्तमान वित्त-व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। आप इसमें सुधार हेतु क्या सुझाव देंगे ?
3. भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्त प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत लिखिए। इस सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका का विवेचन कीजिए।
(Raj, Hycar T. D. C., 1980)

औद्योगिक नीति व लाइसेंस-व्यवस्था

(Industrial Policy and Licensing System)

औद्योगिक विकास के लिए एक सुनिश्चित एवं प्रगतिशील औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है ताकि औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का स्थान निश्चित किया जा सके और सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्राथमिकताएँ स्पष्ट हो सकें। एक उचित औद्योगिक नीति को अपनाकर ही देश की आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक विकास किया जा सकता है। औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जा सकता है, औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम किये जा सकते हैं, बहुराष्ट्रीय निगमों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, औद्योगिक दक्षता की समस्या हल की जा सकती है तथा ग्रामीण व लघु उद्योगों की समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सकता है। भारत में औद्योगिक नीति का कीर्तव्य का विषय रही है। देश का औद्योगिक विकास भूतरूप से 1956 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ही हुआ है। भारतीय संसद में 23 दिसम्बर, 1977 को तत्कालीन जनता सरकार ने भी नई औद्योगिक नीति घोषित की थी जिसमें अति लघु या टाइनरी क्षेत्र (सयन्त्र व मशीनरी में 1 लाख रुपये तक की विनियोग की सीमा) के विकास व जिला-उद्योग केन्द्रों (DICs) की स्थापना पर विशेष रूप से बल दिया गया था। 23 जुलाई 1980 को केन्द्र में तत्कालीन उद्योग राज्य-मन्त्री डॉ. चरणजीत बानना ने संसद में औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत किया था जिसमें औद्योगिक उत्पादन की अधिकतम करने के लिए चुने हुये उद्योगों में अतिरिक्त लाइसेंसशुदा क्षमता को नियमित करने तथा कुछ उद्योगों को प्रति वर्ष 5% स्वतः विकास की सुविधा देने की बात कही गई थी। पिछले वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए अनुसूच वातावरण बनाने के लिए सरकार ने कई नये कदम उठाये हैं। नई कम्प्यूटर नीति (नवम्बर 1984), नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (मार्च, 1985) व नई वस्त्र नीति (जून 1985) सम्बन्धित उद्योगों को नई दिना देने के लिए बनी हैं। 1985-86 के सप्तीय बजट में औद्योगिक उत्पादन को

1948 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर बत दिया गया था। औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारन के लिए उचित नजदूरी व धमिकों के लिए मकानों की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी एवं विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति स्पष्ट की गई थी।

1948 की औद्योगिक नीति में द्वितीय धरणी के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की धमकी निहित थी एवं यह पूर्णतया स्पष्ट व सुलभ हुई नीति नहीं थी।

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951

[Industries (Development and Regulation) Act, 1951]

(IDR Act, 1951)

निजी क्षेत्र के उद्योगों को उचित दिशा में विस्तार करन एवं उनकी क्रियाओं पर नियमन रखन के लिए 1951 में उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम पास किया गया। यह 8 मई, 1952 से लागू किया गया। धीरे-धीरे इनके दायरे में अधिकांश उद्योग आने लगे और अब यह 38 प्रकार के उद्योग-समूहों में 170 विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों पर लागू है, जो इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इसके प्रमुख उद्योग-समूह इन प्रकार हैं : विद्युत-उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, टर्बोमोटरों के अलावा रसायन सीमेंट व जिप्सम की वस्तुएँ, निर्रेमिक आदि।

इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) पंजीकरण (Registration)—अनुसूचित उद्योगों में समस्त चालू औद्योगिक उपक्रमों को एक निर्धारित अवधि तक सरकार के पास अपना पंजीकरण कराना होता है। केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई नया औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जा सकती, अथवा चालू व्यवस्था का काफी विस्तार नहीं किया जा सकता।

(2) विशेष सलाहकार समिति—1951 के अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति (Central Advisory Council), विकास समितियाँ (Development Councils) एवं एक लाइसेंस समिति (Licensing Committee) स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

(3) केन्द्रीय सलाहकार समिति (CAC)—यह मई, 1953 में स्थापित की गयी थी। इनमें उद्योग, धर्म एवं उपभोक्ता-वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति उद्योगों की सामान्य समस्याओं पर विचार करती है और पंजीकरण व लाइसेंस के विशेष मामलों पर राय देती है। किसी उद्योग का सरकार द्वारा प्रबन्ध अपने हाथ में लेते समय भी इससे विचार-विमर्श किया जाता है।

1956 की औद्योगिक नीति की मुख्य बातें :

1. बड़े उद्योग—इस औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने के उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया। इन श्रेणियों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि इनमें राज्य का किस रूप में एवं कितना स्थान होगा। प्रथम अनुसूची (Schedule A) में 17 उद्योग¹ शामिल किए गए जिनके मावों विकास की एकमात्र जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर डाली गयी। लेकिन यह कहा गया कि निजी उद्यमकर्त्ताओं को भी अपने वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने दिया जायगा और नई इकाइयाँ स्थापित करते समय सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग ले मकेगी जिससे देश को लाभ हो मक। यदि निजी क्षेत्र का सहयोग लिया गया तो सरकार पूँजी में अधिक भाग लेगी ताकि उस उद्योग की नीति को प्रभावित कर सके। बम्बय में यह श्रेणी 1948 की नीति की प्रथम व द्वितीय श्रेणियों को मिलाकर बनाई गई थी। 17 उद्योगों की देखने से पता चलता है कि इनमें तीन प्रकार के आयिक कार्यों पर बल दिया गया था : आधारभूत उद्योग, परिवहन एवं खनिज पदार्थ। मविष्य में इनका विकास सरकारी क्षेत्र में ही करने की नीति अपनाई गयी। इन तीनों का एक साथ विकास किये बिना औद्योगीकरण की नींव सुदृढ़ नहीं हो सकती थी। इसलिए सरकार ने उद्योगों में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने का निश्चय किया जो तीव्र आयिक विकास के लिए उचित था। लेकिन इस प्रस्ताव में राष्ट्रीयकरण की पहले वाली धमकी वही भी नहीं थी। इसलिए यह अधिक व्यावहारिक व सचीली नीति मानी गयी।

उद्योग की द्वितीय अनुसूची (Schedule B) में 12 उद्योग रहे मये² जिनके बारे में यह कहा गया कि ये धीरे-धीरे सरकार के स्वाभिस्व में आयेंगे (Progre-

1. प्रथम अनुसूची के उद्योग इस प्रकार हैं : अस्त्र-शस्त्र अणु-शक्ति, लोहा व इस्पात, लोहे व इस्पात की भारी ढलाई व तैयारी, भारी सयन्त्र व मशीनरी, भारी विजली के सयन्त्र, कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, मैंगनीज, ग्रेम, जिप्सम गन्धक, सोने व हीरे की खानें खोदना, ताँबा, मीसा, जस्ता, तागा आदि की खानें खोदना व प्रोसेसिंग करना. अणु-शक्ति के उत्पादन से सम्बन्धित खनिज, हवाई जहाज बनाना, हवाई यातायात, रेल-यातायात, समुद्री जहाज बनाना, टेलीफोन एवं इसके तार, तार एवं वेतार का सामान (रेडियो रिसेविंग सेट छोड़कर) एवं विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।

2. ये इस प्रकार थे : छोटे खनिजों को छोड़कर 'अन्य खनिज पदार्थ,' एल्यूमिनियम एवं अलौह धातुएँ जो प्रथम सूची में नहीं हैं, मशीन टूल्स, फैंरो-एलॉय एवं टूल-स्टील्स, रासायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, दवा, खाद, कृत्रिम रबड़, कोयले का कार्बोनाइजेशन, रासायनिक धोल, सड़क यातायात एवं समुद्री यातायात।

ssively state-owned) और इस क्षेत्र में भी साधारणतया नये कारखाने सरकार के द्वारा ही स्थापित किये जायेंगे । साथ ही निजी उद्यमकर्ताओं को भी इन उद्योगों का विकास करने का अवसर दिया जायेगा, चाहे व्यक्तिगत रूप में या सरकार की सहायता से । इस अनुसूची के प्रमुख उद्योग खाद, मशीन द्रव्य, दवाएँ, समुद्री एवं सड़क परिवहन आदि हैं ।

शेष सभी उद्योग तृतीय श्रेणी में रखे गए जिनका विकास सामान्यतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया । लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि यदि सरकार चाहेगी तो इस क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है । इस बात पर बल दिया गया कि सरकार परिवहन, शक्ति व अन्य सेवाओं का विस्तार करके तथा उचित राजकीय नीति अपनाकर इस क्षेत्र से उद्योगपतियों की सहायता करेगी । निजी क्षेत्रों को आवश्यक वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जायेगी, विशेषतया सहकारी ढंग पर चलाये गये उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा । राज्य इन उद्योगों के जेयर व डिजेन्चर जारी कर इनमें पूँजी लगाने को भी तैयार रहेगा । परन्तु निजी क्षेत्र को राज्य की आर्थिक और सामाजिक नीति के अधीन तथा सरकारी नियन्त्रण में कार्य करना होगा ।

उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटे जाने का यह प्रस्ताव नहीं था कि ये श्रेणियाँ एक दूसरे से पूर्णतया अलग-अलग थीं, बल्कि जैसा कि पूर्व विवरण से स्पष्ट होता है इन विभिन्न श्रेणियों में सावजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच परस्पर गहरा सम्पर्क स्थापित करने पर जोर दिया गया । इसी नीति के अनुसार सरकार आवश्यकता पड़ने पर तीसरी श्रेणी में कोई भी उद्योग चला सकती है और निजी उद्योग को अपने लिए या गील-उत्पत्ति के रूप में पहली श्रेणी की वस्तुएँ भी बनाने को दे सकती है । इस प्रकार यह नीति अधिक व्यावहारिक व लोचदार मानी गयी है और देश के नियोजित आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी उपयुक्त व व्यावहारिक समझी गई है ।

इस नीति में सी कुटीर व लघु उद्योगों के विकास, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास कर्मचारियों के प्रशिक्षण, औद्योगिक शान्ति व विदेशी पूँजी के प्रति भेदभाव न बरतने पर जोर दिया गया ।

1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ या गुण

1956 की औद्योगिक नीति द्वितीय योजना के बाद के वर्षों में देश के औद्योगीकरण के लिए काफी उपयुक्त समझी गयी है । इसका भी आधार 'मिश्रित अर्थ-व्यवस्था' होने के कारण इसमें सावजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का महत्व स्वीकार किया गया है । लेकिन इसमें सावजनिक क्षेत्र को घाटे बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया है ।

सावजनिक क्षेत्र पर अधिक बल देने के कारण प्रारम्भिक वर्षों में औद्योगिक नीति की निजी क्षेत्र के समर्थकों ने कटु आलोचना की थी । लेकिन बाद के वर्षों में

यह स्पष्ट हो गया कि 1956 की औद्योगिक नीति काफी लोचदार व प्रगतिशील है। इसमें अपनाया गया दृष्टिकोण सैद्धान्तिक न होकर व्यावहारिक था। उदाहरण के लिए, भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति को एक सिद्धान्त रूप में नहीं अपनाया गया, जैसा कि साम्यवादी देश में होता है। सरकार ने बिना सोचे-समझे राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं समझा। लेकिन यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हुआ तो वह राष्ट्रीयकरण करने में हिचकिचायेगी भी नहीं। अतः हमारी औद्योगिक नीति काफी व्यावहारिक व लचीली रही है। सरकार अपनी पूँजी नये कारखानों के विकास में लगाना चाहती है। देश में इतने औद्योगिक कार्य करने पड़े हैं कि सरकार एवं पूँजीपति दोनों मिलकर उन्हें करें तो भी बहुत कुछ करना शेष रह जायगा। इसलिए सरकार का नई दिशाओं में बढ़ना अनुचित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सरकार ने विकास की दृष्टि से अपने लिए वे ही क्षेत्र रखे जिनमें (क) विशाल मात्रा में पूँजी की आवश्यकता थी तथा जिनकी व्यवस्था करना निजी क्षेत्र की शक्ति से परे था, (ख) जिनमें जोड़ितम ज्यादा होने से साधारणतया उद्योगपति प्रवेश करना पसन्द नहीं करते थे। (ग) जो सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धित उपक्रम थे जिनमें सरकार का रहना राष्ट्रीय हित में आवश्यक था, (घ) राष्ट्र के तीव्र औद्योगीकरण की नींव सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत व मूल उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में छोड़ा जाना उचित नहीं था।

अतः सरकार की 1956 की औद्योगिक नीति व्यावहारिक व विकासोन्मुख रही है। इस नीति की सफलता इस बात से प्रकट होती है कि पिछले तीन दशकों में इस नीति ने भारत के औद्योगिक विकास की गति व स्वरूप को प्रभावित किया है। दिसम्बर 1977 में जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी, लेकिन उसमें 1956 की औद्योगिक नीति को नकारा नहीं गया था। केवल पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 1956 की औद्योगिक नीति को एक नया मोड़ दिया गया था, ताकि वह हमारी आवश्यकताओं को ज्यादा अच्छी तरह से पूरा कर सके। जुलाई 1980 में कांग्रेस (आई) के नये औद्योगिक नीति वक्तव्य में भी मूलतया 1956 की औद्योगिक नीति को ही स्वीकारा गया था, हालांकि इसमें भी परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक संशोधन किये गये थे।

1970 की लाइसेन्स नीति

भारत सरकार ने नयी लाइसेन्स-नीति 18 फरवरी, 1970 को घोषित की थी जिसमें दत्त-समिति (औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति) की महत्वपूर्ण विचारणों को स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व के वर्षों में औद्योगिक नियोजन एवं लाइसेन्स नीति पर विभिन्न क्षेत्रों में काफी चर्चा रही थी। स्वर्गीय डॉ. आर. के. हजारी ने योजना आयोग के लिए इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें मुक्त व गये उपायों को भी नई लाइसेन्स-नीति के निर्माण में ध्यान में रखा गया था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में औद्योगिक लाइसेन्स-नीति पर कुछ उपयोगी सुझाव दिए गये थे। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस विषय पर अपनी निवारण प्रस्तुत की थी।

लाइसेन्स नीति की मुख्य बातें

1. प्रमुख क्षेत्र—'प्रमुख' (core) उद्योगों की एक सूची दी गई जिसमें अत्यव्यवस्था के आधारभूत, सुरक्षा सम्बन्धी व केन्द्रीय महत्व रखने वाले उद्योग (Basic Strategic and Critical Industries) रहे गये। इन उद्योगों के लिए वित्तीय औद्योगिक योजनाएँ तैयार करने की बात कही गयी और इनके लिए प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर आवश्यक साब-सामान उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 9 बड़े उद्योग-समूहों की सूची तैयार की गयी जिसमें इस्पात सामान (उर्वरक, ट्रैक्टर आदि), लोहा व इस्पात, पेट्रोलियम, भारी औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग वगैरह शामिल किए गये।

2. भारी विनियोग क्षेत्र—'प्रमुख' क्षेत्र के अनिवारित 5 करोड़ रुपये से ऊपर के बड़े विनियोग-सम्बन्धी प्रस्ताव 'भारी विनियोग' (Heavy Investment) क्षेत्र में रहे गये। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 के अन्तर्गत मार्गदर्शक क्षेत्र के लिए निर्धारित उद्योगों को छोड़कर 'प्रमुख' व 'भारी विनियोग' के क्षेत्र में अनेकाङ्कित बड़े औद्योगिक समूहों (जिनकी पूँजी 35 करोड़ रुपये से अधिक थी) तथा विदेशी कंपनियों को भग लेने का अवसर दिया गया।

3. मध्यम क्षेत्र—एक करोड़ से पाच करोड़ रुपये तक के विनियोग के बीच वाले मध्यम क्षेत्र (Middle Sector) में अनेकाङ्कित बड़े औद्योगिक समूहों को छोड़कर अन्य उद्यमकर्ताओं के आवेदन-पत्रों पर विशेष हथ से ध्यान देने और उनकी उम्मीद उदारतापूर्वक लाइसेन्स देने की बात कही गई। साथ में यह स्पष्ट किया गया कि बड़े औद्योगिक समूहों व विदेशी कंपनियों को सामान्य वित्तियार के लिए लाइसेन्स दिये जा सकेंगे, जहाँ ऐसा वित्तियार लागत-गर्भकृत्यता को बढ़ाकर उत्पादन का न्यूनतम प्रकार का आर्थिक स्तर प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके।

4. एक करोड़ रुपये तक के विनियोग की इकाई लाइसेन्स-मुक्त—उद्योग (विकास व नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपये तक की विनियोग की इकाइयों के लिए, नए उद्यमों के लिए या कानूनी मात्रा में विस्तार करने के लिए लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं रखी गई।

5. तटु उद्योग के लिए आरक्षण जारी—तटु उद्योगों के क्षेत्र के लिए आरक्षण (Reservation) की वर्तमान नीति जारी रखी गई और यह कहा गया कि जब कभी यह क्षेत्र मांग की पूर्ति पर्याप्त रूप से कर सकेगा, तब इसका विस्तार भी किया जा सकेगा।

7वीं औद्योगिक साइसेंस नीति में एकाधिकार व नेगोशियेशन की पुष्टि को रोकने के लिए कई उपाय शुभाये गये थे। यह कहा गया कि सक्षम क्षेत्र में जहाँ विनियोग 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच होगा अपेक्षाकृत थोड़ा औद्योगिक समूहों से प्राप्त आगे बढ़ाने पर विशेष परिस्थितियों में ही दिया दिया जा सकेगा।

6 पित्तु क्षेत्रों का औद्योगिक विकास—पित्तु क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्न जारी रखने पर जोर दिया गया। यह निश्चित किया गया कि विदेशी व सात सस्थाएँ पित्तु क्षेत्रों में औद्योगिक निजीय व्यवस्था के लिए अधिक रियायत दगी। केन्द्रीय सरकार पित्तु क्षेत्रों में स्थापित किने जाँ पाते प्रोजेक्टों की पूँजीगत लागत में (जो 50 लाख रुपये तक हो सकती है) 10% तक सस्मिडी देगी। इससे उपर की लागत की परियोजनाओं पर भावश्यकता अनुसार सहायता की जायेगी। सस्मिडी नौ राज्यों—माध्य प्रदेश असम बिहार जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश मणिपुर उड़ीसा राजस्थान व उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व दो जिलों में उपलब्ध करने की बात कही गयी। अन्य राज्यों में इसे एक जिले के हिसाब से देने का निर्णय किया गया।

1970 की साइसेंस नीति में भी यह कहा गया था कि भारतीय टेक्नोलॉजी डिजिट व इजीनिरी में दक्षता का विकास किया जायेगा। उद्योग व मनुष्यता का सहारा स्थापित किया जायेगा। विदेशी सहयोग का उपयोग आवश्यक दिशाओं में ही किया जायेगा जिससे यह चरेखू तक सीकी भाँ व सेवा के उपयोग में लाया न सके। विदेशी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान से लिए एक इकोनोमीकार करने की पद्धति को अधिक उपयोगी बनाने के लिए एक विदेशी निविद्योग बोर्ड (Foreign Investment Board) (FIB) बनाया गया था।

1970 की साइसेंस सस्मिडी नीति के लागू होने के बाद पहले से अधिक साइसेंस दिये गये। उद्योगकर्ताओं में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की पूँजीगत माँग का आयात करने व सामञ्जस्य विस्तीय सरथाओं से प्राप्त होने के अधिक सविद्यता व सस्मिडी दिया। लेकिन बिजली की कमी कोविम बोर्ड ने आभास व परिष्कृत की कठिनाइयों के कारण औद्योगिक विकास में बाधाएँ जारी रही।

1970 की साइसेंस नीति में परिवर्तन—यह चूँकि उद्योगों में उत्पादन क्षमता का अधिक सहारा उपयोग करने क्षमता विस्तार करने के लिए सरकार ने जनवरी 1972 में बिना साइसेंस की औपचारिकता में पड़ प्रस्तावित क्षमता के 100 प्रतिशत तक प्रतिस्ति उत्पादन क्षमता की स्वीकृति दी गयी। निर्णय घोषित किया। लेकिन साथ में यह शर्त लगाई गयी कि इसने लिए पूँजीगत माँग के आभास की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रारम्भ में 54 उद्योगों को इसने अन्तर्गत दिया गया बाद में यह व्यवस्था 11 उद्योगों पर भी लागू की गई। अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक घरानों में

विदेशी कम्पनियों से सम्बन्धित फर्मों को उनकी क्षमता में स्वतः विकास का लाभ नहीं दिया गया। इस नीति के फलस्वरूप कई उद्योगों में उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया गया।

सशोधित लाइसेंस नीति, 1973

काफी विचार-विमर्श के बाद सरकार ने फरवरी, 1973 में सशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति घोषित की। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में मनादेशमक अनिवार्यता को दूर करना और पाँचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाना था। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी—

1 प्रमुख उद्योगों की सूची—सरकार ने उद्योगों की एक सूची प्रकाशित की जो अन्य आवेदकों के साथ-साथ अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक घरानों व विदेशी कम्पनियों को शाल दो के निर्धारित मानी गई। इन सूची में प्रमुख उद्योग (Core Industries) इनमें सम्बद्ध उद्योग व निर्यात बढ़ाने लायक उद्योग शामिल किये गये। लेकिन सूची में ऐसी मदें, जो 1956 के औद्योगिक प्रस्ताव की अनुसूची ए के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नियत थी, प्रथम तथु उद्योग के लिए नियत थी शामिल नहीं की गयी। इस नीति में भारी विनियोग के क्षेत्र (5 करोड़ रुपये से अधिक) का विचार समाप्त कर दिया गया।

2 अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा में परिवर्तन—पशोभिन्न नीति में अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा बदल दी गई। इसमें 35 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति की सीमा के स्थान पर 20 करोड़ रुपये की सीमा को ही अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा के लिए आधार बनाया गया।

3 तथु उद्योगों के लिए रिजर्वेशन की वर्तमान नीति जारी रखी गई।

4. तथुक्त क्षेत्र का विचार—यह कहा गया कि तथुक्त क्षेत्र की इकाइयों के निर्माण पर प्रत्येक मामले को सेक्टर-अलग-अलग विचार किया जायेगा। लेकिन बड़े औद्योगिक समूहों व विदेशी कम्पनियों को तथुक्त क्षेत्र का उपयोग करके ऐसे उद्योगों में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जो उनके लिए वर्जित माने गये हैं और यह स्पष्ट कर दिया गया कि सभी तथुक्त क्षेत्र की इकाइयों में सरकार ही नीति प्रवर्धन व प्रचालन में सक्रिय रूप से भाग लेगी।

सशोधित लाइसेंस नीति की विशेषताएँ

जैसा कि ऊपर बताया गया है सशोधित लाइसेंस-नीति का उद्देश्य पाँचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था। इस नीति में बड़े औद्योगिक घरानों के लिए कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया। लेकिन साथ में नये, मध्यम व तथु उद्यमकर्तृता का भी औद्योगिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए काफी अवसर प्रदान किए गये व ते देन में आवेदन पत्रों का केन्द्रीयकरण कम किया जा सके।

संगोषित नीति में समुक्त क्षेत्र का विचार सम्पष्ट छाड़ दिया गया, हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में अपना प्रमाण उठाने की घोषणा अवश्य की थी। निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने नयी नीति का स्वागत किया। यह नीति मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की धारणा व 1956 की औद्योगिक नीति के अनुरूप ही थी। इसकी मुख्य विशेषताएँ 19 उद्योग-समूहों की एक सूची थी जिसमें बड़े औद्योगिक समूहों या विदेशी कम्पनियों को प्रवेश करने की इजाजत दी गई थी। 19 उद्योगों की सूची में धातु-वामिन उद्योग, विद्युत-उपकरण, परिवहन उपकरण औद्योगिक मशीनरी मशीनी औजार, रासायनिक डबेरक आदि शामिल किये गये थे। यह सूची काफी लचीली व जिम्नूत थी। यह धारणा की गई कि इससे निजी क्षेत्र में विनियोग व उत्पादन में उद्दान को ज्यादा प्रेरणा मिलगी।

1973 की संगोषित लाइसेंस नीति का क्रियान्वयन

संगोषित औद्योगिक लाइसेंस-नीति की घोषणा के बाद नवम्बर 1973 में एक परियोजना-स्वीकृति-बोर्ड ((Project Approval Board) (PAB) स्थापित किया गया ताकि लाइसेंस शीघ्रतापूर्वक दिये जा सकें। अनावश्यक विलम्ब दूर कर के लिए। नवम्बर, 1973 से नयी पद्धति जारी की गई जिसके अनुसार 90 दिन के भीतर आवेदनकर्ताओं से इन्स्टेंट-प्रपत्रों (लाइसेंस प्राप्ति से पूर्व जारी स्वीकृत प्रपत्र) विदेशी सहयोग के समझौते व पूँजीगत माल की स्वीकृति के मामलों में निर्णय लेने की बात कही गई। जहाँ MRTF सम्बन्धी जाँच का मामला होगा उसमें 150 दिन की अवधि निर्धारित की गई। यह कहा गया, कि जहाँ विदेशी सहयोग व पूँजीगत माल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी वहाँ सीधे औद्योगिक लाइसेंस दिये जा सकते हैं।

परियोजना स्वीकृति बोर्ड (PAB) देख-रेख, निर्देशन व समन्वय का काम करता है। लाइसेंस समिति, विदेशी विनियोग बोर्ड व पूँजीगत माल समिति (CGC) परियोजना स्वीकृति बोर्ड (PAB) की समितियों के रूप में कार्य करते हैं। औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अधीन औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए एक एकीकृत सचिवालय (A United Secretariat for Industrial Approvals (SIA) स्थापित किया गया। यह सचिवालय (SIA) गतिष्प रिपोर्ट तैयार करने (PAB) के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में उदारता की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन, 1975

अक्टूबर 1975 में लाइसेंस-नीति को अधिक उदार बनाया गया ताकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत 21 उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त (Delicensed) कर दिया गया। इनमें मूल दवाइयों, मूल औद्योगिक पदार्थ, औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार, आदि शामिल हैं। 30 अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में (विदेशी कम्पनियों व बड़े घरानों सहित) लाइसेंस प्राप्त क्षमता से परे

असीमित मात्रा तक विस्तार करने की छूट दी गयी। इनमें वेस्तिव दवा, पोटैलेंड सीमेंट कागज, रसायन, विद्युत का साज-सामान आदि आते हैं। विदेशी कम्पनियों व प्रौद्योगिक घरानों को उत्पादन में असीमित विस्तार का अवसर देते समय कुछ शर्तें लगाई गयीं जैसे उन्हे प्रतिरिक्त माल का निर्यात करना होगा अथवा सरकार की स्वीकृति के अनुसार माल को बेचने की व्यवस्था करनी होगी।

31 मार्च 1978 को जनता सरकार द्वारा लाइसेंस-नीति में परिवर्तन

जनता सरकार ने रामकृष्ण अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार करके औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए छूट की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दी थी। सरकार ने अध्ययन दल की यह सिफारिश भी मान ली कि वे छूटें MRTTP कम्पनियों प्रभुतासम्पन्न उपक्रमों (dominant undertakings) तथा 40% से अधिक विदेशी शेयर वाली कम्पनियों को उपलब्ध नहीं होगी।

केन्द्र ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी मान ली कि जब तक लघु क्षेत्र के लिए रिजर्व की गई मदी के सम्बन्ध में देश में उत्पादन की पर्याप्त क्षमता का विकास नहीं हो जाता तब तक उनके आयात की व्यवस्था की जा सकती है। इससे कीमती को कम रखने तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसे आयातों की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब वर्तमान लाइसेंस-शुदा क्षमता का पूरा उपयोग कर लिया जाय।

अप्रैल 1982 में लाइसेंस नीति अधिक उदारता की ओर—भारत सरकार ने अप्रैल 1982 में लाइसेंस नीति को अधिक उदार बनाया। सरकार ने यह घोषणा की कि पाँच और क्षेत्रों में जैसे सीमेंट, उर्वरक, बरंग मे, बड़े घरानों की कम्पनियाँ व विदेशी कम्पनियाँ पिछले पाँच वर्षों में अपने सर्वाधिक उत्पादन से 33.3% अधिक क्षमता का निर्माण कर सकेंगी। यह छूट 25% प्रतिरिक्त उत्पादन के बराबर होगी। यह सुविधा उन मदी के लिए नहीं दी गई जो लघु क्षेत्र के लिए रिजर्व की ओर यह उन उद्योगों को भी नहीं दी गई जिन पर विशेष रूप से नियमन की व्यवस्था थी, जैसे बनस्पति व मिर्च फूड, आदि। इस परिवर्तन का उद्देश्य मूल क्षेत्र (Core Sector) में प्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना, निर्यात बढ़ने की सम्भावना वान उद्योगों या आयात-प्रतिस्थापन वाले उद्योगों को बढ़ावा देना, विविधित व उन्नत टेक्नोलोजी को अपनाने में मदद देना, बड़े पैमाने की क्षियायतों को प्राप्त करना तथा बड़े पैमाने पर सहायक इकाइयों का जाल विद्यमान था।

भारत सरकार ने 31 मार्च 1983 को औद्योगिक लाइसेंस से छूट की सीमा 3 करोड़ रु से बढ़ाकर 5 करोड़ रु करने का निर्णय किया क्योंकि प्रोजेक्ट लागत में काफी वृद्धि हो गई थी।

1985-86 के संघीय बजट में मार्च 1985 में MRTTP कम्पनियों के लिए परिमण्डलियों की सीमा 20 करोड़ रु से बढ़ाकर 100 करोड़ रु कर दी गई तथा

25 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया ताकि उत्पदन-क्षमता का तेजी से विकास हो सके। बाद में मई 1985 में 27 उद्योगों को MRTP अधिनियम की धारा 21 व 22 के दायरे से हटा दिया गया। दिसम्बर 1985 में इन 27 उद्योगों में से 22 उद्योगों में MRTP व FERA कम्पनियों (एकाधिकारी घरानों की व विदेशी कम्पनियों) को भी लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। इन पर विस्तार से आगे चर्चा की गई है। सरकार औद्योगिक नीति व लाइसेंस व्यवस्था को उत्तरोत्तर अधिक उदार बनाती जा रही है।

भारत में औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था किस तरह कार्य कर रही है ?¹

भारत में औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम (IDR act) 1951 के अन्तर्गत संचालित की गई है। लाइसेंस व्यवस्था का काफी महत्व माना गया है क्योंकि इसके माध्यम से निम्न बातों को प्रभावित किया जा सकता है :

(i) उद्योग कहाँ स्थापित किया जाय, अर्थात् उद्योग के लिए स्थान का चुनाव (ii) उद्योग कौन स्थापित करे ? यदि चालू औद्योगिक घरानों की वजह से नये उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस मिले तो आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, (iii) किस प्रकार के उद्योग स्थापित हों—उत्पादक बनाम उपभोक्ता, विलासिता की वस्तुओं के या घातक जंतुओं के काम की वस्तुओं के ? (iv) उत्पन्न होने की पद्धति कौन-सी हो (बड़ा पैमाना या लघु पैमाना) ? (v) विदेशी विनिर्मेय की राशतिग, (vi) वस्तु-मिश्रण क्या हों, आदि ?

भारत में दुर्भाग्यवश औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली ने आवश्यक कार्यक्षमता से काम नहीं किया है। यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है। इसके द्वारा 'निजी लाभ व सामाजिक हानि' का बातावरण उत्पन्न किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

डॉ. एस. के. गोयल व उनके सहयोगियों द्वारा किये गये अध्ययन से निम्न परिणाम सामने आये हैं :

1 प्रस्तावित क्षमता (installed capacity) व लाइसेंस-युक्त क्षमता (licensed capacity) में अन्तर पाया गया है।

1. **Functioning of Industrial Licensing System—Capacity and Production in Organised Industry**, article by S. K. Goyal & the Corporate Studies Group of IIPA, New Delhi, and Published in EPW, April 30, 1983, full report also published separately.

3105 लाइसेन्सों की जांच करने से ज्ञात हुआ कि 7% लाइसेन्सों में कोई प्रस्थापित क्षमता नहीं पाई गई, 20% में यह लाइसेन्सशुदा क्षमता में अधिक रही तथा 60% मामलों में वास्तव में 75-100% तक ही लाइसेन्स क्षमता स्थापित की गई। इस प्रकार वास्तव में स्थापित क्षमता लाइसेन्सशुदा क्षमता से प्रामाण्यता पर अधिक रही है।

2 वास्तविक उत्पादन लाइसेन्सशुदा क्षमता से अधिक पाया गया है, ऐसा विशेषतः जीयर शराब व इसी प्रकार के अन्य पेय पदार्थों में हुआ है। कल्याणी ब्रूअरीज (बीयर) में 83.8% अतिरिक्त उत्पादन पाया गया है। वहाँ-वहाँ वास्तविक उत्पादन लाइसेन्स-शुदा क्षमता से कम भी हुआ है।

3 ये दोष बड़े घराने की कंपनियों व विदेशी कंपनियों में भी पाये गये हैं। इनमें कहीं-कहीं वास्तविक उत्पादन लाइसेन्सशुदा क्षमता के दुगुने से भी अधिक किया गया है।

ये सब दोष औद्योगिक लाइसेन्स व्यवस्था (ILS) के होते हुए भी पाये गये हैं। इससे प्रति पूँजीकरण की समस्या को बड़ावा मिला है तथा विदेशी साधनों का सदुपयोग नहीं हो पाया है। अतः भारत में लाइसेन्स-व्यवस्था प्रभावहीन साबित हुई है। अब समय आ गया है जब इसमें आवश्यक सुधार किये जायें। इसने लिए गहरी छानबीन करने की आवश्यकता है।

जनता सरकार की औद्योगिक नीति, 23 दिसम्बर, 1977

श्री जॉर्ज फर्नाण्डेज ने 23 दिसम्बर, 1977 को सदन में जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इसकी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :

(i) लघु इकाइयाँ—यह कहा गया कि नई नीति ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे नगरों में कुटीर व लघु उद्योगों को तेजी से प्रोत्साहन देगी। लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित उद्योगों की सूची लगभग 180 मदों से बढ़ाकर 504 मदों तक कर दी गई। लघु उद्योगों की श्रृंखला में एक बहुत छोटा क्षेत्र या टारगेट क्षेत्र भी बनाया गया जिसमें मशीनरी व उपकरणों में निवेश की सीमा 1 लाख रु. तक रखी गयी।

इनके विकास के उपरान्त—(ii) जिला उद्योग केन्द्र—यह कहा गया कि उन्हें महानगरों व राज्य की राजधानियों से हटाकर जिला-केन्द्रों में ले जाया जायेगा। प्रत्येक जिले में लघु व ग्रामीण उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक एजेंसी होगी जिसे जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centre (DIC) कहा गया। इनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि ये जिले में कच्चे माल व अन्य साधनों की प्राप्ति जांच करेंगे तथा मशीनरी की सप्लाई, साख की पूर्ति आदि से सम्बन्धित कार्य करेंगे।

(iii) औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण व कुटीर उद्योगों की मास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पूण्ड्र इकाई स्थापित की।

(iii) इनके लिए वित्री, वस्तु-मानकीकरण, विस्म-नियन्त्रण, विपणन-सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान देने तथा सरकारी खरीद में इनको प्राथमिकता देने की बात कही गई।

जनता औद्योगिक नीति में 22 ग्रामाद्योगों में आधुनिक प्रबन्धकीय तकनीक के आधार पर विकास-कार्यक्रम पर जोर दिया गया।

बड़े औद्योगिक व्यावसायिक घरानों (Big Industrial or Business Houses) के प्रति नीति—इनके सम्बन्ध में निम्न बातों पर बल दिया गया—(i) बालू उपक्रमों का विस्तार व नये उपक्रमों की स्थापना MRTI Act के तहत ही की जायेगी। (ii) इन कार्यों के लिए सरकार से विशेष स्वीकृति लेनी होगी। (iii) बड़े घरानों को स्वयं के वित्तीय साधनों के द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना या प्रचलित परियोजना के विस्तार की व्यवस्था करनी होगी।

जनता सरकार ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी विनियोग, उद्योगों के लिए स्थान-निर्धारण व बीमार इकाइयों की समस्या के समाधान के लिए भी नीति स्पष्ट की थी।

सारांश—इस प्रकार तत्कालीन जनता सरकार ने रोजगारोन्मुख, प्रामाण्युल उपभोक्ता-उन्मुख तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण-उन्मुख औद्योगिक नीति प्रस्तुत की थी लेकिन इसमें बहुत छोटे क्षेत्र (tiny sector) व जिला उद्योग-केन्द्रों के अलावा कोई विशेष नई बात नहीं थी। बाकी सब बातें पहले जैसे ही थीं। इसलिए यह 'नई बोतल में पुरानी शराब' (old wine in a new bottle) की कहावत को चरितार्थ करती थी।

जनता औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन—

शुरू में जनता औद्योगिक नीति व कुछ अनुज्ञप्त प्रभाव सामने आये जैसे देश में विनियोग का वातावरण सुधरा, औद्योगिक लाइसेन्सों की संख्या 1976-77 में 908 से बढ़कर 1977-78 में 1392 हो गयी। सार्वजनिक वित्तीय सहायता ने पहले की तुलना में अधिक रकम दी, विदेशों से अधिक पूँजीगत माल मंगाया गया तथा आयत लाइसेन्स भी बढ़े। 1978-79 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 7.6% रही जो पिछले वर्ष में लगभग दुगुनी थी। देश में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये। लेकिन 1979-80 में कोयला-वावर-परिवहन संकट के कारण औद्योगिक विकास की दर ऋणात्मक (-1.4%) रही। औद्योगिक सम्बन्धों में बिगाड़ हुआ तथा देशव्यापी सूखे के कारण औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जनवरी 1980 में केन्द्र में कांग्रेस (घाई) की सरकार पुनः सत्तास्थ हुई और उसने जुलाई 1980 में अपना औद्योगिक नीति सम्बन्धी नया वक्तव्य प्रस्तुत किया तथा बाद के वर्षों में इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के विभिन्न प्रयास जारी रहे। इनका उन्मुख भाग चलकर किया गया है।

**कॉम्रेल (आई) सरकार का
औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य, 23 जुलाई, 1980
(Industrial Policy Statement, July 23, 1980)***

केन्द्र में नवम्बर 1979 में उद्योग-मन्त्री चरणजीत चानना ने 23 जुलाई, 1980 को भारतीय संसद में औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसमें 1946 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का इस वक्तव्य का आधार बतलाया गया था। नए वस्तुओं के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों में प्रस्थापित क्षमता (installed capacity) के पूर्ण उपयोग तथा औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करने, रोजगार बढ़ाने प्राथमिक घटकवस्तुओं को बचाने, कृषि-आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देकर कृषिगत विकास को नीचे की मुड़ कर देना व अनुसूचित क्षेत्रों में अन्तर्-क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्धों (Optimum inter-sectoral relationships) को विकसित करने, निर्यात-आश्रित व आयात-प्रतिरूपक से सम्बन्धित उद्योगों का पर्याप्त दायित्व देना तथा निर्यात से विकास करने तथा ऊँचे मूल्यों व घटिया किस्म के प्रति उपभोक्ता-वर्ग को संरक्षण प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया। यह कहा गया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लघु व विकसित इकाइयों के विनियोग का समान रूप से विचार किया जाएगा। पिछले वर्षों में जनता का सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वास कम हो गया था जिस पुनः स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक इकाई की समस्या का अध्ययन करके एक समयबद्ध (time-bound) कार्यक्रम को कार्यान्वयन में लाया जाएगा।

1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य की प्रमुख बातें—

1. **न्यूक्लियस प्लांट्स (Nucleus Plants) की स्थापना—** आर्थिक संघवाद (economic federalism) के विचार की मूर्तरूप देने के लिए प्रत्येक जिले में न्यूक्लियस-समन्वय स्थापित किए जाएंगे ताकि सहायक, लघु एवं कुटीर इकाइयों का विस्तार किया जा सके। इसके लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले चुने जाएंगे। एक न्यूक्लियस सहायक इकाइयों (ancillary units) की वस्तुओं का सफा करने पर ध्यान देना तथा छोटी इकाइयों के लिए आवाश्यक इन्पुट उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। इनके द्वारा विनियोग का स्थापक रूप से फैलाव होगा तथा औद्योगीकरण के भावों को दूर-दूर तक पहुँचाया जा सकेगा। इनके माध्यम से लघु इकाइयों की टेक्नोलॉजी को भी उन्नत करने में (upgrading the technology) मदद मिलेगी। इस प्रकार ये संपन्न औद्योगिक फैलाव या छिन्नराज (industrial dispersal) में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनसे नई उद्यम-शीलता का आहुति देना व विकास होगा। भारतीय कार प्रोड्यूसर केन्द्र प्लांट का

* सरकार की नई औद्योगिक नीति के बारे में पूछे जाने पर इसका विस्तृत जवाब दिया जाना चाहिए।

उदाहरण माना जा सकता है। इसके लिए बारखाने के भास-पास बार के प्राव-
श्यक कल-पूजें बनाने के लिए सहायक इकाइयों का विकास किया जायगा तथा
जापान से आयातित पार्ट्स को एनए करके बारों का उत्पादन किया जायगा।

2 लघु इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन—लघु इकाइयों में सद्यः च
मनीनरी के विनियोग की सीमा बढ़ा दी गई है। बहुत छोटी या टाहनी इकाइयों के
लिए विनियोग की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये लघु इकाइयों के
लिए 10 लाख रु से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा सहायक इकाइयों (ancillaries)
के लिए 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गयी ताकि अधिकांश मात्रा
में लघु इकाइयाँ उनको मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें तथा अधिक सरप्ला
में इनका प्राथमिकीकरण किया जा सके।

3 अनिश्चित तादर्थसमुदा क्षमता (excess licensed capacity) को
नियमित करना—सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चुने हुए
उद्योगों में तथा आम जनता के उपयोग की वस्तुओं के उद्योगों में अनिश्चित तादर्थस-
मुदा क्षमता को नियमित करने की घोषणा की। इसकी अधिसूचना 29 अगस्त
1980 को जारी की गई जिसमें कुछ शर्तों को पूरा करने पर निम्न उद्योगों को
यह सुविधा प्रदान की गई 2 फरवरी 1973 की नीति के परिशिष्ट 1 में वर्णित
19 उद्योग, तेल ड्रिलिंग उपकरण व सहायक पुर्जें, व अन्य कई प्रकार के इंजीनियरी
के उद्योग। 19 उद्योगों के अलावा 15 अन्य उद्योगों को भी यह सुविधा दी गई।
यह सुविधा उन उद्योगों को नहीं दी गई जिनकी गर्दे लघु क्षेत्र के लिए रिजर्व की
गई है।

4 स्वतः विकास की सुविधा-साधनों की कमी को देखते हुए तथा उत्पादन-
क्षमता के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से सरकार ने अगस्त, 1980 में पांच वर्षों की
अवधि में 25% स्वतः विकास (automatic growth) की स्कीम 19 अनिश्चित
थड़े उद्योग समूहों पर लागू की। यह स्कीम 1975 में 15 विभिन्न उद्योगों पर लागू
की गई थी जिससे कुछ इकाइयों में रण्यता को टाँसने में मदद मिली थी। ज्यादातर
प्रमुख उद्योगों (core industries) को इस प्रकार की सुविधा मिलने से प्रतिवर्ष
5% का विकास स्थग हो जायगा। यह सुविधा अनिवार्य/तादर्थसमुदा क्षमता में
सामान्य 25% की सीमा से ऊपर के विस्तार पर दी गई है। इस प्रकार यह स्वतः
विकास की सुविधा 34 उद्योगों पर लागू हो गई है।

5 औद्योगिक रण्यता की समस्या को हल करने के उपाय—औद्योगिक नीति
वक्तव्य में कहा गया कि जिन इकाइयों में रण्यता की समस्या जानबूझ कर कुप्रचल
व वित्तीय दुर्घटना के कारण हुई है उनसे सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
आयकर की धारा 72-ए के तहत भीमार इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ
विलयन/एकीकरण प्रोत्साहित किया जायगा तथा आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक

2 वक्तव्य में MRTP अधिनियम व आयोग का कहें जिन्न नहीं प्राया है जिससे लगता है कि सरकार इन्हे कोई महत्व नहीं देना चाहती। इससे निजी क्षेत्र में एकाधिकार के नियन्त्रण व नियमन में बाधा पहुँचेगी। सरकार न बीमार औद्योगिक इकाइयों का प्रबन्ध निजी क्षेत्र की स्वस्थ इकाइयों द्वारा अपने हाथ में लिए जान वा तो समर्थन किया है, लेकिन साथ में यह नहीं देना कि इससे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि MRTP अधिनियम के उद्देश्यों को मुत्ता दिया गया है। एक समय ऐसा था जब सरकार न MRTP अधिनियम को अपनी एक महत्वपूर्ण उपसब्धि माना था।

3 अतिरिक्त लाइसेन्सशुदा क्षमता (Excess Licensed Capacity) को नियमित करने से लाइसेन्स-व्यवस्था का महत्व ही समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में नागरिक सरकारी कानूनों के प्रति आदर क्यों दिखायेंगे। लाइसेन्स-व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों के लिए स्थान-व्यय औद्योगिक इकाइयों के आकार मशीनों के आघात, विदेशी सहयोग व नये उद्यमकर्त्ताओं के बाधों को प्रभावित करना माना गया है। इसलिए उनका उत्लघन करने वाले व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए न कि अनाधिकृत लाइसेन्स-क्षमता का सृजन करने पर उसको नियमित कर देना तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को नियमों का उत्लघन करने पर भी मुक्त कर देना। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार स्वयं अपने कानूनों व नियमों को विशेष आदर या महत्व नहीं देती है। सरकार ने IDR अधिनियम व MRTP अधिनियम को समाप्त किये जिना ही बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रति उदारता दिखाने का मार्ग अपना लिया है। इस प्रकार नये औद्योगिक नीति वक्तव्य का अधिकांश लाभ बड़े औद्योगिक घरानों को ही मिलेगा।

4 नये वक्तव्य में निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए 'संयुक्त क्षेत्र' (Joint Sector) की तनिक भी चर्चा नहीं की गई है। इस प्रकार 'संयुक्त-क्षेत्र' की धारणा का महत्व बाकी कम कर दिया गया है। संयुक्त क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने में कारगर मदद दे सकता है।

5 नय वक्तव्य से बड़े औद्योगिक घरानों व विदेशी रम्पनियों की अधिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि अधिकांश अतिरिक्त लाइसेन्स-शुदा क्षमता पर उनका ही अधिकार रहा है। रेफ्रिजरेटर पम्प लेम्प व ट्यूब आदि उद्योगों को अधिक लाभ मिलेगा, वनिस्वत पूँजीगत व अनिवार्य उपभोक्ता माल के उद्योगों के। इससे देश का औद्योगिक ढाँचा अधिक विकृत व ग्राम आदमी के हितों के विपरीत हो जाएगा। देश में ग्राम जनता के हितों का इतना ध्यान नहीं रखा गया है जितना धनी वर्ग का रखा गया है।

6 केन्द्रस्थ सघन्धों (nucleus plants) की चर्चा कोई नई बात नहीं है, केवल नये शब्दों पर जोर देने से देश का भला नहीं हो सकता। देश में इस प्रकार के

सयन्त्र स्थापित करने की निरन्तर आवश्यकता है। अतः सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विस्म के न्यूक्लियस सयन्त्रों को स्थापित करना चाहिए एवं उनका कार्यकुशल ढंग से सम्बन्धी भव्यपि तब संचालन करना चाहिए।

7 लघु इकाइयों के लिए विनियोग की सीमाएँ बढ़ा देने मात्र से इनमें पाई जाने वाली बेमामी व झूठी इकाइयों की समस्या हल नहीं हो जायेगी।

8. प्रदूषण-नियन्त्रण की आड़ में बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था की जायेगी। अर्थात् तो यह होता कि प्रदूषण-नियन्त्रण की लागत का अधिकांश भार औद्योगिक इकाइयों पर ही डाला जाता। अमेरिका में भी ऐसा ही किया गया है।

अन्य डॉ. पराजपे के अनुसार नये औद्योगिक नीति-सम्बन्धी वक्तव्य में औद्योगिक जगत को विभिन्न समस्याओं का समुचित समाधान नहीं प्रतीत होता। व्यावहारिक नीति के नाम पर तथा निर्यात-प्रोत्साहन एवं अधिकतम उत्पादन आदि की आड़ में निजी उद्यम व बड़े व्यावसायिक घरानों को ही अधिक सुविधाएँ दी गई हैं जिनसे आम जनता का कल्याण होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। औद्योगिक नीति चर्चामें में कहीं भी यह देखने की कोशिश नहीं की गई है कि बाहिर 1956 की औद्योगिक नीति के लगभग 30 वर्षों के बाद भी निजी हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण क्यों बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास की दर नीची क्यों रही, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार बढ़ाने में अधिक सक्षम क्यों नहीं हो पाया, श्रम का शोषण क्यों जारी है, निजी विदेशी विनियोग अपना विदेशी सहयोग की शर्तों में कौन-से परिवर्तन करने आवश्यक हैं, पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने तेजी से क्यों नहीं बन रहे हैं, आदि। जब तक इन मूल प्रश्नों के सही, सुनिश्चित, वांछित व व्यावहारिक उत्तर नहीं दिये जाते तब तक नीति सम्बन्धी वक्तव्यों को दोहराते जाने से देश का विशेष लाभ नहीं होना वाला है।

डॉ. पराजपे द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि नये औद्योगिक नीति वक्तव्य में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए साइसेन्स-शुद्ध क्षमता को नियमित करने तथा उद्योगों को स्वतः विकास की ओर सुविधा दी गई है, उससे देश में कुछ सीमा तक उत्पादन का विस्तार अवश्य होगा।

हाल में औद्योगिक नीति व साइसेन्स-व्यवस्था में परिवर्तन¹

पिछले वर्षों में औद्योगिक नीति व साइसेन्स-व्यवस्था को उदार बनाया गया है ताकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसके लिए कई उद्योगों को साइसेन्स

... पिछले तीन वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण, विशेषतया Economic Survey, 1988-89, pp 45-48.

नेने से मुक्त किया गया है तथा एकाधिकारी घरानों व विदेशी कम्पनियों को भी कुछ चुने हुए उद्योगों में नाइमेन्स-मुक्ति का लाभ दिया गया है। इन सब परिवर्तनों का उद्देश्य नीचे किया जाता है।

1. पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय सन्निधि देने की व्यवस्था—घन वन्ये शहरी व उद्योगों में जमघट का रोकने व इनके वितरण में प्रादुर्भाव ममानता लाभ व निगम औद्योगिक दृष्टि में पिछड़े क्षेत्रों का निम्न तीन श्रेणियाँ में बाँटा गया है—

(i) श्रेणी 'A' में 'बिना उद्योग वाले जिले' (No Industry Districts) लिये गये हैं जिनमें केन्द्रीय विनियोग की सन्निधियों की राशि (Central investment subsidy) विनियोग का 25% अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये रहती गई है।

(ii) श्रेणी B में विनियोग-सन्निधि 15% तथा अधिकतम राशि 15 लाख रुपये रहती गई है।

(iii) श्रेणी C में सन्निधि 10%, व अधिकतम राशि 10 लाख रुपये रहती गई है।

'A' श्रेणी के लिए 118 जिले 'B' के लिए 55 जिले तथा 'C' के लिए 113 जिले दर्ज किए हैं। सामान्यतया श्रेणी 'A' से कोई भी स्थान-परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जायगी। 'B' से 'A' में जान की इजाजत मिल जायगी, इसी प्रकार 'C' से 'A' या 'B' में स्थान-परिवर्तन की इजाजत दी जा सकेगी। लेकिन अन्य किसी भी प्रकार के स्थान-परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जायगी, जब तक कि वह मार्गजनिक हित में न हो।

2. पञ्चवीस उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति—केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मार्च 1985 में मधीय बजट पेश करते समय 25 उद्योगों का लाइसेंस से मुक्त कर दिया था ताकि जिन क्षेत्रों में हम उत्पादन की अनिच्छित क्षमता बढ़ाना चाहते हैं उनमें कार्य-विधि-सम्बन्धी विरम्व (procedural delays) कम किए जा सकें। इन उद्योगों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं—विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वन-युक्त, गाड़ियों के पार्ट्स, माइक्रो, औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार, कृषिगत औजार, औद्योगिक मिर्तों की मशीनें, कुछ दवाएँ, कुछ किस्म के कागज व नुदी, कुछ वनस्पति तेल, चमड़े की वस्तुएँ, आदि।

3. MRTP कम्पनियों की परिसम्पत्ति की सीमा 20 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. कर दी गई क्योंकि 1969 के बाद प्रोजेक्ट-आगत काफी बढ गई है। इससे कुछ कम्पनियाँ MRTP के दायरे से निकल गई हैं जिससे उन्हें इस अधिनियम के बधन से मुक्ति मिल गयी है।

4. लघु इकाइयों में प्लान्ट व मशीनरी में विनियोग की सीमा 20 लाख रु. से बढ़ाकर 35 लाख रु. तथा सहायक इकाइयों के लिए 25 लाख रु. से बढ़ाकर 45 लाख रु. कर दी गई और इनके विकास के लिए फिस्कल उपायों की भी घोषणा की गई।

5. गैर-एम. आर. टी. पी. (non-MRTP) कम्पनियों व गैर-फेरा (non-FERA) कम्पनियों द्वारा दी जा सकने वाली व्याज की दरें (परिवर्तनीय डिबेंचरों पर 13.5% से बढ़ा कर 15% कर दी गईं, ताकि ये बाजार से अधिक मात्रा में वित्तीय साधन जुटा सकें।

6. बड़े व मध्यम क्षेत्र में बीमार औद्योगिक इकाइयों के उपचार हेतु एक औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (Board for Industrial and Financial Reconstruction) (BIFR) की स्थापना की गयी है। बीमार औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में धर्मियों की बकाया राशि को अन्य राशियों की भांति उँचा ध्यान दिया जायगा ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसने 15 मई 1987 से कार्यरत कर दिया है।

7 मई 1985 में 27 उद्योगों की एकाधिकार व प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार-विधियों अधिनियम (MRTP Act) की धारा 21 (बाकी वित्तार के सम्बन्ध में) तथा धारा 22 (नये उपकरणों की स्थापना के सम्बन्ध में) से मुक्त कर दिया गया ताकि ये उत्पादन बढ़ा सकें। इन उद्योगों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं: पिंग लोहा, कुछ इलक्ट्रोनिक कल-युज, गाडियों के पार्ट्स व कल युज, प्रदूषण-नियन्त्रण-उपकरण, कुछ धराई की मशीनरी, मशीनी औजार, कुछ दवाई, मसबारी कागज, फर्टिलाइजर मीमट, आदि। इन उद्योगों के सम्बन्ध में MRTP अधिनियम की धारा 21 व 22 लागू नहीं की जायगी। इससे उत्पादन बढ़ाने में सहनियत होगी।

8 दिसम्बर 1985 में इन 27 उद्योगों में से 22 उद्योगों से सम्बन्ध MRTP व FERA कम्पनियों की नी नाइवेंस लेने से मुक्त कर दिया गया गया। इन उद्योगों में पिंग लोहा, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालियाँ, गाडियों के कल-युज, प्रदूषण-नियन्त्रण-उपकरण, रसायन प्रक्रिया मयन, आदि शामिल हैं।

9. 1985 के अन्त में सरकार ने उत्पादन-क्षमता की पुन स्वीकृति (re-endorsement) की स्कीम घोषित की जो उन समस्त लाइसेंसगुदा इकाइयों को प्राप्त होगी जिनमें 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले रिपोर्ट बर्षों में से किसी भी वर्ष में अपनी लाइसेंसगुदा क्षमता का 80% प्राप्त कर लिया था। व इका या अपने अतिरिक्त उत्पादन व इसके 1/3 अंश को जोड़ने से प्राप्त उत्पादन की मात्रा तक लाइसेंसगुदा क्षमता के लिए पुन स्वीकृति ले सकेंगी। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उपरोक्त स्कीम का अब और अधिक उदार बना दिया गया है। एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा 1 अगस्त 1988 से 31 मार्च, 1990 के बीच प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वतः फिर से जारी कर दिया जायगा। जिन उद्योगों का स्वतः पुन स्वीकृति की सुविधा नहीं होगी, उनकी सन्ध्या 77 से घटा कर 25 कर दी गई है।

10. सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए 28 उद्योग-समूहों में उत्पादकों द्वारा वस्तु या वस्तु-विषय में परिवर्तन करने (broad banding) की इजाजत देने

भारी विनियोग की स्थिति में कम से कम 5 करोड़ रु. का विनियोग करने पर फिलहाल इसकी भी इजाजत दे दी जायेगी।

आशा है इन उपायों से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का विकास होगा जो भारत को इसवीसवीं शताब्दी में प्रवेश कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास के लिए 14 कदम¹

पिछले दो वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में विकास की वार्षिक दर 40% रही है। कम्प्यूटरों व टी. वी. के मामले में। इस उद्योग में 2500 इकाइयाँ हैं जिनमें 30% सार्वजनिक क्षेत्र में, 45% लघु क्षेत्र में तथा 25% संगठित निजी क्षेत्र में है। 1984-86 में उत्पादन का मूल्य 2880 करोड़ रु. रहा है तथा 1986-87 में 3685 करोड़ रु. का अनुमान है। उद्योग में 2 लाख व्यक्ति रोजगार पाये हुए हैं।

सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए निम्न 14 उपाय किये हैं—

- (i) ब्रोड बैंडिंग वाले लाइसेंस जारी किये हैं,
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों के उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है,
- (iii) विदेशी सहयोग व टेक्नोलॉजी के आयात की इजाजत दी गई है,
- (iv) टेलीफोन उपकरण व ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों के लिए टेक्नोलॉजी के आयात के द्रव्यकृत आधार (centralised basis) पर किये जायेंगे,
- (v) राज्य उद्योग निदेशालयों द्वारा लघु पैमाने को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए विनियोग की सीमा 35 लाख रु. से बढ़ाकर 45 लाख रु. की गई है;
- (vi) इनकी स्थापना स्वीकृत स्थानों पर करने की इजाजत दी गई है,
- (vii) पैमाने की क़िफ़ायती का लाभ उठाने के लिए इनको आवश्यकतानुसार लघु पैमाने की रिजर्व सूची से हटाया गया है,
- (viii) टेलीकम्यूनिकेशन, टेलीफोन के विनिर्माण, EPABX टेलीप्रिन्टर्स, आदि में निजी क्षेत्र के प्रवेश की इजाजत दे दी गई है,
- (ix) MRTPL कम्पनियों को इस उद्योग के लिए अधिनियम की धारा 21 व 22 से मुक्त रखा गया है ताकि उत्पादन-क्षमता बढ़ायी जा सके,
- (x) कम्प्यूटर नीति में नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनायी जायेगी ताकि कीमते कम की जा सकें,

(xi) कच्चे माल, कल-पुर्जों व मशीनरी पर आयात शुल्क घटाया गया है।

(xii) आयात नीति को युक्तिसंगत बनाया गया है;

(xiii) सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया है एवं ।

(xiv) कल पुर्जों के उद्योग को फिस्कल प्रेरणाएँ दी गयी हैं ।

3 नई वस्त्र (टेक्स्टाइल्) नीति—यह 6 जून 1985 को घोषित की गई थी । इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग में ऐसे परिवर्तन लाना है जिससे वस्त्र का उत्पादन बढ़ सके । इस उद्योग में रोजगार बढ़े एवं इसके निर्यातों में वृद्धि हो सके । इस नीति के द्वारा वस्त्र उद्योग पर से कई प्रकार के अनावश्यक नियन्त्रण व नियमन हटा दिए गये हैं ।

इस नीति में उद्योग के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही बदल गया है । पहले वस्त्र उद्योग में मिल क्षेत्र, पावरलूम क्षेत्र व हथकरघा क्षेत्र के रूप में विचार किया जाता था । अब कुनाई कटाई व प्रोसेसिंग क्रियाओं के रूप में विचार किया जायेगा । मिलें अब कृत्रिम रेशों व धागों का भी प्रयोग कर सकेंगी । कृत्रिम रेशों, मूत व मध्यवर्ती माल पर उत्पादन शुल्क कम किया जायेगा । मिलों के प्राधुनिकीकरण के लिए मशीनरी का आयात कम शुल्क पर किया जायेगा । बीमार मिलों को आवेदी सक्षम (viable) व असक्षम (unviable) दो श्रेणियों में बांटा गया है । इनमें से द्वितीय श्रेणी की मिलों को बन्द किया जायेगा तथा इनके विस्थापित होने वाले मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिये रिपार्यती दर पर वित्त प्रदान किया जायेगा । सक्षम मिलों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जायेगी ।

पावरलूम क्षेत्र को मिल के समान माना गया है । सारे देश में इनका पञ्जीकरण अनिवार्य कर दिया गया है । पावरलूमों पर तो भी अनावश्यक बंधन हटा दिये गये हैं । सरकार का मानना है कि यह क्षेत्र अब काफी सुदृढ़ हो गया है और इसे अब अधिमानी या बरीयताओं की जरूरत नहीं रही है ।

हथकरघा क्षेत्र की पावरलूम क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से रक्षा की जायेगी । नियन्त्रित वस्त्र का उत्पादन अब हथकरघा क्षेत्र की तरफ अन्तर्हित कर दिया गया है । सातवी योजना के अंत तक हथकरघा क्षेत्र नियन्त्रित वस्त्र का पूरा उत्पादन करल लगेगा ।

इस प्रकार नई वस्त्र नीति में मिलों के प्राधुनिकीकरण की नीति अपनायी गई है जिसकी देश को नितान्त आवश्यकता थी ।

नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति व नई वस्त्र नीति के समक्ष चुनौती

नई सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स व टेक्स्टाइल उद्योगों के प्राधुनिकीकरण व विकास के लिए जिन नीतियों की घोषणा की है वे वस्तुतः सही दिशा में हैं । लेकिन

इसके क्रियाकलाप में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में कम्प्यूटर्स (कम्प्यूटर्स) का उत्पादन बढ़ाने में ही देश को वास्तविक लाभ मिल सकेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर्स उद्योग में भारी मात्रा में प्रतियोग बढ़ाना होगा, तथा उत्तम श्रमिकों का मान्यता के लिए टेक्नोलॉजी के आयात की व्यवस्था करनी होगी। यह काम उत्पादन का स्तर काफी ऊँचा रखना होगा। ये कार्य असम्भव भी नहीं, बल्कि व्यवहार में कठिन असम्भव है। इसलिए वर्ष 1989-90 तक इलेक्ट्रोनिक्स का उत्पादन 10 000 करोड़ रुपये तक करने में देश को काफी कठिनाई का सामना करना होगा।

इसी प्रकार अक्षय बीमार वस्त्र मिलें (unviable sick textile mills) को बन्द करने में बेरोजगारी का गहटा खड़ा हो जायगा जिससे मजदूरों में प्रतियोग बढ़ाने एवं सरकार को मजदूरों को बेकरीयों का काम पर लगाने की समस्या का सामना करना होगा। उनको रियायती वित्त देकर बेरोजगारों को काम में लगाना भी आसान काम नहीं लगती। इसके अलावा भारतीयों का मत है कि नई वस्त्र नीति से पावरलूम क्षेत्र को काफी क्षति होगी। पावरलूम के उद्योगकारों का कहना है कि पावरलूम को मिल लूम के समान माना नहीं जायेगा, क्योंकि उनको कई प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं जिससे उनकी लागत उंची आती है। इस प्रकार इस बात की सम्भावना है कि नई वस्त्र नीति से पावरलूम क्षेत्र को भारी क्षति पहुँचेगी। इसके अलावा मध्यम विनिर्गत वस्त्रों का अन्तर्गत (transfer) हथकरघा क्षेत्र की तरफ करना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि आजकल माध्यामिक वर्गों की उच्च लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी बजटिटी घटिया होती है। इसलिए भविष्य में हथकरघा वस्त्रों की मांग के अभाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

भारत में वस्त्र के मादुन्य की स्थिति के कारण आधुनिकीकरण के किसी भी औद्योगिक कार्यक्रम को लागू करना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी के उद्योग, प्रतियोगिता बढ़ाने, बड़े पैमाने की किरायाओं, मान्यता की विषय में सुधार, उत्पादकों में वृद्धि आदि के मार्ग में आकर बाधाएँ हैं। लेकिन इनका पूरा विचार भारत की अर्थव्यवस्था की प्रतियोगितात्मक क्षति से क्षमता भी नहीं बढ़ सकती। इसलिए देश के समस्त औद्योगिक जगत में भारी पुनर्निर्माण विद्यमान है। सरकार औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का मुख्य प्रयास कर रही है।

भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति व लाइसेंस-व्यवस्था का आन्तर्गतान्तरक मूल्यांकन

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने औद्योगिक नीति का उद्देश्य प्राप्त की दिशा में (विशेषतया राजीव सरकार ने) कई महत्वपूर्ण कदम उठाये

हैं। इस सम्बन्ध में कुछ उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त किया गया है, वस्तु-मिश्रण को बढ़ाने (broad-banding) की इजाजत दी गई है तथा एकाधिकारी कम्पनियों व विदेशी कम्पनियों को भी कई प्रकार की रिपायमें दी गई हैं। लाइसेंस से छूट की सीमा बढ़ायी गयी है। इन सब परिवर्तनों का उद्देश्य उत्पादन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना है और निजी क्षेत्र को अधिक विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि औद्योगिक नीति व लाइसेंस-व्यवस्था को उधार बनाने से देश में औद्योगिक विनियोग के प्रति बातावरण सुधरा है। विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों, विदेशी विनियोग की स्वीकृतियों, उद्योगों की स्थापना के लिए इन्टेलिजन्स व लाइसेंसों की स्वीकृतियों, उद्योगों के रजिस्ट्रेशन, पूँजी-निर्गम के लिए जारी की गई स्वीकृतियों, वित्तीय मस्याओं के द्वारा सहायता की स्वीकृतियों व बिजली की राशियों आदि में वृद्धि को देखते हुये ऐसा लगता है कि देश में औद्योगिक विकास की दर बढ़ेगी। अनावश्यक औद्योगिक नियन्त्रणों को हटाने से लाभ मिलने की आशा की जा सकती है।

उदारता की नीति के फलस्वरूप सीमट उद्योग में उत्पादन-क्षमता 1980-81 में 2 करोड़ टन से बढ़कर 1984-85 में $4\frac{1}{2}$ करोड़ टन हो गई है, तथा छड़ी योजना में सीमट का वार्षिक उत्पादन $11\frac{1}{2}\%$ बढ़ा है।

आशा है सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित वार्षिक दर 8% प्राप्त की जा सकेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक नीति को उदार बनाना सामर्थ्य रहा है। लेकिन सरकार की उदार औद्योगिक नीति को विभिन्न क्षेत्रों में समीक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में निम्न विचार प्रकट किये गये हैं—

1. निजी क्षेत्र के समर्थकों का कहना है कि व्यवहार में उदार नीति से विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि नीकराशी का दृष्टिकोण पूरी तरह नहीं बदला है। वह तीव्र औद्योगिक विकास में बाधा भी बाधा डालती है।

सरकारी नीति के अमानक बदलने से कुछ उद्योग कठिनाई में पड़ जाते हैं जैसे पहले सरकार ने पोलीथीन बैगों के निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की नीति अपनायी थी, लेकिन बाद में पुनः जूट उद्योग को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया जिससे पोलीथीन के निर्माताओं को भारी घुस्सा पहुँचा है। इस प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन कई प्रकार की दिक्कतें पैदा कर देते हैं।

2. सरकार ने टेली-कम्प्युनिकेशन, तेल-अनुसन्धान व हवाई परिवहन को कुछ सीमा तक निजी क्षेत्र के लिए खोलने की नीति घोषित की है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति-सिद्धान्त व दिशा-निर्देश सामने नहीं आ पाये हैं। इसलिए स्थिति अनिश्चित व अस्पष्ट बनी हुई है।

प्रश्न

1. मभिन्न टिप्पणी लिखिए—

(i) भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति ।

(Raj II year T D C , 1983, 1986, 1987)

(ii) भारतीय औद्योगिक नीति ।

(Raj IIyr. T. D C , 1981)

(iii) भारत की औद्योगिक नीति के प्रमुख लक्षण ।

(Raj IIyr T D C , 1989)

2 भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मातोषनामक मूल्यांकन कीजिये । यह कहाँ तक सन्तोषप्रद है ?

(Raj IIyr T. D C , 1982)

—————

भारत में औद्योगिक प्रगति व सातवीं योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना

(Industrial Growth in India and Strategy
for Industrial Growth in the Seventh Plan)

हमने पिछले अध्याय में भारत में औद्योगिक नीति व लाइसेंस-व्यवस्था के विकास का अध्ययन किया है। प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि योजना काल में औद्योगिक प्रगति पर सरकार की औद्योगिक नीति व लाइसेंस व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा है? इस प्रश्न का समुचित उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि औद्योगिक प्रगति पर औद्योगिक नीति के अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर (विद्युत, रेल-परिवहन आदि) की प्रगति पर सार्वजनिक विनियोग की मात्रा, कृषिगत प्रगति, देश में आमदनी के वितरण, आयात-प्रतिस्थापन की प्रगति, युद्ध, अकाल व राजनीतिक परिस्थितियों आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब तत्वों के प्रभाव एक दूसरे से पूरक कर सकना काफी कठिन होता है।

फिर भी हम उपलब्ध सूचना के आधार पर औद्योगिक प्रगति पर औद्योगिक नीति का प्रभाव जानने का प्रयास करेंगे। इस सम्बन्ध में हम श्रीमती ईशर जज अहलूवालिया व योजना आयोग के वर्तमान सदस्य डा. वाई. के. अलक (Y. K. Alagh) के विचार प्रस्तुत करेंगे।¹ श्रीमती अहलूवालिया ने 1966-67 से औद्योगिक विकास की वार्षिक दर पहले से नीची मानी है, जबकि डॉ. अलक ने 1976-77 से औद्योगिक विकास की वार्षिक दर ऊँची बतायी है।

भारत में साठ के दशक के मध्य से औद्योगिक विकास की वार्षिक दर पहले से काफी कम हो गई थी, श्रीमती अहलूवालिया के अनुसार 1959-60 से 1965-

1. Isher Judge Ahluwalia, *Industrial Growth in India : Stagnation since the Mid-Sixties*, 1985, &

Dr. Y. K. Alagh, *Some Aspect of Planning Policies in India*, 1986.

66 की अवधि में यह 8% बढ़ी रही जबकि 1966-67 से 1979-80 की अवधि में यह 5.7% बढ़ी थी। इस प्रकार द्वितीय अवधि में प्रगति 1966-67 की औद्योगिक विकास की दर काफी घटी हो गयी। विभिन्न अर्थशास्त्रियों जैसे डा. के. एन. राव दीपक नैयर सी. रमराजन अशोक मिश्रा प्रमद वर्धन ए. के. बागची अशोक धी दसाइ श्रीमती ईश्वर ज. ग्रहसूक्तानिया आदि ने इसके कारणों पर प्रकाश डाला है। दीपक नैयर ने आय के असमान वितरण के कारण उद्घाटन की वृद्धि को घटी औद्योगिक प्रगति के लिए जिम्मेदार ठहराया है जबकि डा. सी. रमराजन ने औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी उत्पत्ति अनुपात की वृद्धि को इसका प्रमुख कारण माना है।

हम आज चर्चा करते हैं कि श्रीमती ग्रहसूक्तानिया ने घटी औद्योगिक प्रगति के लिए भारत में औद्योगिक नीति के ढाँचे या प्रभावकों का बहुत कुछ उत्तरायी ठहराया है। इसमें अतन्त्र औद्योगिक नदमें व्यवस्था या आयत लाईमें व्यवस्था कीमत व वितरण-निर्धारण विदेशी सहायता के प्रति नीति एक टक्कानाजी के प्रसारण (transfer) का व्यवस्था आदि आते हैं। भारत में औद्योगिक विकास में बाधाएँ होकर बाधाएँ सिद्ध हुए हैं।

औद्योगिक प्रगति का विश्लेषण

डा. के. एन. कृष्णा क. मन्तानुसार 1951-86 के 35 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन छ गुणा हुआ गया। इस अवधि में औद्योगिक विकास की वार्षिक विकास दर 9.5% रहा है। 1900-1950 तक यह दर 2% वार्षिक रही थी।

सोनावान में भारत का औद्योगिक ढाँचा काफी व्यापक हुआ है। इसमें काफी विविधता आई है। आज देश में अनेक प्रकार की नई वस्तुओं का उत्पादन होना लगातार जिसका सम्बन्ध भारत के अर्थशास्त्र के उद्योगों के विकास से है। देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मशीनरी बनाने लगी है। औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। संयंत्र उत्पादों का उत्पादन 1950-51 में 10.4 लाख टन से बढ़कर 1987-88 में 1 करोड़ 65 लाख टन मात्र में 27 लाख टन से बढ़कर 37 करोड़ टन वषट्ट का (निर्माण सहित) 33 करोड़ टन से बढ़कर 19 करोड़ टन एच. क्रूड तेल का 2.6 लाख टन से बढ़कर 0.4 करोड़ टन (वजन 115 गुना) हो गया है। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षमता उत्तमशीलता व तकनीकी भ्रमना का काफी प्रसार हुआ है। भावजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार हुआ है। वार्षिक सरकार के व्यापारिक औद्योगिक उपक्रमों की संख्या मार्च 1951 में 5 थी जो मार्च 1988 में 221 हो गई तथा इनमें नियमितों की संख्या 29 करोड़ रु. से बढ़कर 71,299 करोड़ रु. हो गई। राष्ट्रीय में सड़क परिवहन विद्युत व सिंचाई के माध्याम का विकास हुआ है। ये सभी औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धियों का सूचित करते हैं।

औद्योगिक विकास की वार्षिक दर—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 1959-60 से 1965-66 तक औद्योगिक प्रगति की वार्षिक दर 8 प्रतिशत रही जो 1966-67 से 1979-80 तक 5.7 प्रतिशत पर आ गई थी। बाद के वर्षों में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर ऊँची हुई है। सातवी योजना के प्रथम चार वर्षों में यह 8-9 प्रतिशत सालाना रही है जो पहले से बेहतर है।

श्रीमती अहलूवालिया के अध्ययन के अनुसार 1970-82 की अवधि में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर भारत में 4.3 प्रतिशत रही जबकि मध्यम आय वाले अन्य देशों में यह 5.3 प्रतिशत रही थी जो भारत से एक प्रतिशत अधिक थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत का 71 देशों में 43वा स्थान रहा है।

विभिन्न योजनाओं में औद्योगिक विकास के लक्ष्य व उपलब्धियों में अंतर रहा है जो निम्न सारिका में दिया गया है

(% में)

योजना	वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य	वास्तविक वृद्धि पर
I	7	6
II	10 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{4}$
III	10 $\frac{3}{4}$	8
IV	12	1968-69 से 1982-83 तक 4.8% व पिन
V	8	
VI	7	
VII	8	औद्योगिक उत्पादन के नये सूचकांक (1980-81 = 100 के अनुसार)
		1985-86 में विकास की दर 8.7%
		1986-87 में 9.1%
		1987-88 में 7.3%
		1988-89.. 8.8% ¹

इस प्रकार छठी योजना की अवधि तक औद्योगिक विकास की वास्तविक दर लक्ष्य से सदैव नीची रही है।

1960-61 में विनिर्माण द्वारा कुल जोड़े गये मूल्य (total value-added by manufacture) में घाघारभूत व पूँजीगत उद्योगों का अंश 38% था जो 1979-80 में 49% हो गया, (लगभग आधा), मध्यवर्ती उद्योगों में यह 21% से घटकर 16% तथा उपभोक्ता उद्योगों में 45% से घट कर 35% (लगभग 1/3) पर

1. The Economic Times, September 8, 1989. (RBI का अनुमान)

(3) देश के विभिन्न भागों इन्फास्ट्रक्चर (विशेषतया विद्युत) काफी कम-जोर स्थिति में पाया गया है। लघु मध्यम व बड़े सभी प्रकार के उद्योगों को आवश्यकतानुसार 'पावर' नहीं मिल पाती, जिससे उत्पादन निर्वाध व निरन्तर गति में नहीं बढ़ पाता। देश के विभिन्न भागों में पावर की कमी, पावर की कटौतिर्षा, पावर के उतार-चढ़ाव आदि घाम बात बन गये हैं।

4 जैसा कि पहले बतलाया गया है श्रीमती अहलूवालिया ने औद्योगिक गतिहीनता के लिए विशेषतया औद्योगिक नीति-सम्बन्धी ढाँचे को जिम्मेदार ठहराया है।¹ कई वर्ष पूर्व जगदीश मगवती व पद्मा देसाई ने भी भारतीय औद्योगीकरण पर अपने अध्ययन में, औद्योगिक नीति व लाइसेंस-व्यवस्था को घीमी औद्योगिक प्रगति के लिए दोषी ठहराया था। भारत में प्रमुख उद्योगपतियों व विभिन्न विद्वानों ने भी इसकी ओर समय-समय पर सरकार का ध्यान आर्षित किया है।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, औद्योगिक नीति सम्बन्धी ढाँचे के दायरे में औद्योगिक लाइसेंस-व्यवस्था, आयात लाइसेंस-व्यवस्था, कीमत व वितरण-नियन्त्रण, विदेशी निनियोग व टेक्नोलोजी के सम्भोजे, आदि विषय शामिल होते हैं।

भारत में औद्योगिक नीति सम्बन्धी ढाँचे में औद्योगिक विकास पर जोर न देकर औद्योगिक नियन्त्रण पर अधिक जोर दिया है। औद्योगिक नियन्त्रणों व नियमनों का जल-जवाल काफी व्यापक हो गया है। इससे कई प्रकार के दुष्परिणाम निकले हैं। सर्वप्रथम, इनके कारण उद्यमकर्तओं को प्रशासनिक देरी व बकायटों का सामना करना पडा है। हमारे यहाँ उद्योगों को क के बाद एक बात की स्वीकृति/अनुमति लेते जाना पडता है, जैसे IDR अधिनियम के तहत लाइसेंस की मजूरी, फिर MRTP अधिनियम से मुक्ति, विदेशी सहयोग की शर्तों का सम्भोजे करना, पूँजी-गत माल के आयातों का लाइसेंस लेना, पूँजी-निर्माण बन्ट्रोलर से ओपर जारी करने की स्वीकृति लेना, आदि।

जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है, भारत में लाइसेंस-व्यवस्था काफी घीमी व अकार्यकुशल पाई गई है। वैयक्तिक उद्योगों में प्रवेश करना कठिन रहा है, और उनमें से निरलना उससे भी अधिक कठिन, जैसे मालों कोई चकधूह लगेडा जा रहा है, किसी भी उद्योग को मरने नहीं दिया जाता, उसे दोमार रहन दिया जाता है एव राज्य उसकी निरन्तर देखमाल करता रहना है। उद्यमकर्ता स्ट्रु-वर्जी व अल्पकालीन लामों को अधिकतम करन में लगे रहते हैं। वास्तविक उत्पादन घटान में कोई रुचि नहीं लेना चाहता। औद्योगिक क्षेत्र में व्यादातर प्रत्याधिकार की स्थिति (oligopoly) पाई जाती है, जिनके अन्तर्गत कुछ कमें उपमोजाओ

1. Ibid, Chapter 8, pp. 147-165.

के शोषण में लगी रहती है। विभिन्न उद्योगों में टेक्नोलॉजी पुरानी पायी जाती है तथा विदेशों से भी कई बार घटिया मशीनों का आयात कर लिया जाता है। प्रायः निजी विदेशी पूँजी के आयात की जगह निर्यात अधिक हो जाता है। विभिन्न चरणों पर उद्यमकर्ता को अपसरों व अधिकारियों के स्वेच्छिक निर्णयों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में औद्योगिक नियन्त्रणों ने औद्योगिक विकास का गला घोट दिया है। स्वर्गीय एल. के. भट्टा ने भी समय-समय पर अपने वक्तव्यों में औद्योगिक नियन्त्रणों व लाइसेंस-व्यवस्था का पुनरावलोकन करने तथा इनमें आवश्यक ढील देने का समर्थन किया था।

डॉ. वार्ड, के अलक ने इलाहाबाद में मार्च, 1985 में अपने गोविन्द बल्लभ स्मृति व्याख्यान में बतलाया कि 1976-77 का विभाजन रेखा मानने पर 1976-77 से 1981-82 की अवधि में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र (registered manufacturing sector) में विकास की वार्षिक दर 7.6% रही, जबकि 1971-72 से 1975-76 की अवधि में यह 4.6% रही थी। इस प्रकार डॉ. अलक ने औद्योगिक विकास की दर को 1976-77 से आभाजनक व उरसाह्वर्षक बतलाया है। उन्होंने इसको भारत में सत्तर के दशक में बड़े औद्योगिक देशों की तुलना में कम नहीं माना है। इस प्रकार 1966-67 से 1979-80 की अवधि में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 1959-60 से 1965-66 की तुलना में नीची रही (श्रीमती ग्रहलूबालिया के अनुसार), लेकिन 1976-77 से 1981-82 की अवधि में यह 1971-72 से 1976-77 की तुलना में अधिक रही (डॉ. अलक के अनुसार)। अतः विद्वानों के द्वारा विभिन्न अवधियों को लेकर विभिन्न प्रकार के परिणाम प्रस्तुत किये गये हैं। लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि देश में औद्योगिक क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएँ हैं जिनका समाधान करके विकास की दर बढ़ायी जा सकती है जैसे उत्पादन-क्षमता का कम उपयोग, निमित्त माल की घटिया किस्म, पूँजीगत उद्योगों में आयातित माल से प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की कमी, पावर की कमी, औद्योगिक सम्बन्धों में गिरावट, मांग की कमी, पुरानी टेक्नोलॉजी से उत्पन्न कठिनाई, आदि।

1985 में नई सरकार ने आवश्यक औद्योगिक नियन्त्रणों व नियमनों को कम करने की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। आयातों के क्षेत्र में उदार नीति अपनायी गई है तथा 1985-88 व 1988-91 की अवधि के लिए त्रिवर्षीय निर्यात-आयात नीति (Exim-policy) घोषित की गई है। प्रत्यक्ष करो (वैयक्तिक व निगमित) में कमी हो गई है। MRTP अधिनियम के अन्तर्गत विनियोग की सीमा 20 करोड़ रु से बढ़ाकर 100 करोड़ रु (पाँच गुनी) कर दी गई है। 25 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया है। 27 उद्योगों को MRTP अधिनियम की धारा 21 व धारा 22 के दायरे से हटा दिया गया है। MRTP व FERA कम्पनियों को पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए परिशिष्ट I व गैर-परिशिष्ट श्रेणी में काफी उद्योगों में

लाइसेंस से मुक्त किया गया है। कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स व टेक्सटाइल उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीतियाँ घोषित की गई हैं जिनमें आधुनिकीकरण व विम्वन-नियन्त्रण का दृष्टिकोण सर्वोपरि प्रतीत होता है। इन सब पर पिछले अध्याय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जा चुका है।

यह स्मरण रह कि औद्योगिक नीति में उदारता की ओर प्रवृत्ति भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। यह भूतकाल में भी (1973 से लगातार अब तक) अपनाया गया है। लेकिन नई सरकार ने इसे अधिक स्पष्ट रूप से अधिक व्यापक पैमाने पर तथा अधिक महत्वपूर्ण ढंग से अपनाया है। प्रधान मंत्री श्री राजीव गान्धी न सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाइयों को बन्द करने की बात कहें हैं जिनमें निरन्तर घाटे की स्थिति बनी रहती है। अन्य घाटे वाली इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचा जा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का घाटा कम करने के नये प्रयास करने पर भी बल दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के सञ्चालन-मण्डलों में निजी क्षेत्र के अनुभवों को नियुक्त किया गया है। रतन टाटा को एयर इण्डिया का चेयरमैन तथा राहुल बजाज को इण्डियन एयरलाइन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सरकार ने औद्योगिक नीति को उदार बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये हैं। भूतकाल में विभिन्न औद्योगिक नियन्त्रण व्यवहार में औद्योगिक प्रगति के मार्ग में बाधक सिद्ध हुए थे। इसलिए विद्वानों की इनकी उपयोगिता में काफी सन्देह होने लगा था। ऐसी स्थिति में कुछ उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने, उनको MRTP अधिनियम के दायरे से हटाने, उद्योगों को जोड़ बैण्डिन के द्वारा वस्तु-मिश्रण को बढ़ाने की स्वतन्त्रता देने आदि के पक्ष में वानाचरण का बनना स्वाभाविक था। सरकार ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए छठी योजनावधि में औद्योगिक व लाइसेंस नीति में कई परिवर्तन किए हैं जिनका विवेचन पहले किया जा चुका है। अधिकांश परिवर्तन 1985 व इसके बाद किये गए हैं जिनके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की वार्षिक दर ऊँची हुई है।

औद्योगिक उत्पादन का नया सूचकांक व वृद्धि दर

प्रब औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष 1970 से बदलकर 1980-81 कर दिया गया है जिससे औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 6 से 7 प्रतिशत की जगह 8 से 9 प्रतिशत (1981-82 से 1988-89 की अवधि के लिए) आती है। यह अप्रत्याशितता में दर्शायी जाती है? ¹

1 Economic Survey 1988-89, p. 43, तथा the Economic Times, Sept. 8, 1989.

वर्ष	नयी श्रृंखला या सिरीज (1980-81 = 100)
1981-82	93
1982-83	32
1983-84	67
1984-85	86
1985-86	87
1986-87	91
1987-88	73

औद्योगिक उत्पादन के प्रचलित सिरीज में कई प्रकार की कमियाँ महसूस की गयी थी। जैसे इस्पात रसायन, पेट्रो-रसायन, पोशाक, जेम्-कटिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को उचित भार नहीं दिया गया था जबकि मिल क्षेत्र के सूती वस्त्र उद्योग का आवश्यकता से अधिक भार मिला हुआ था। इसके अलावा प्रचलित सिरीज में लघु उद्योगों का उत्पादन भी असिद्धाति प्रगट नहीं हो पा रहा था।

इन कमियों को दूर करने के लिए नया सिरीज प्रारम्भ किया गया है। इससे औद्योगिक विकास की वार्षिक दर ऊँची हुयी है। यह 1986-87 में 91% रही एवं 1987-88 में सूँचे के बावजूद यह 73% रही। इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिक उत्पादन पर सूँचे का विपरीत प्रभाव बहुत सीमित रहा। औद्योगिक उत्पादन में तेज गति से वृद्धि के लिए माँग की अनुसूच दशाघो, कृषिगत विकास की सततपन्नक स्थिति व इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रगति को जिम्मेदार देखाया गया है। ऐसा नगन लगा है कि भारत की औद्योगिक प्रगति अब कृषिगत विकास में बन्धी नहीं रही। 1988-89 में औद्योगिक विकास की दर 88% रही है।

सातवी योजना के प्रथम तीन वर्षों में विद्युत मशीनरी व उपकरण तथा रसायन पदार्थों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन वेग पदार्थों, तम्बाकू, वस्तुओं जूट लकड़ी व लकड़ी से बनी वस्तुओं के उद्योगों में प्रगति की रफ्तार धीमी रही है।

अब हम सातवी पंचवर्षीय योजना 1985-90 में औद्योगिक विकास के उद्देश्यों व्यूहरचना व नीति सम्बन्धी ढाँचे पर प्रकाश डालते हैं।¹

(क) सातवी योजना में औद्योगिक विकास के उद्देश्य (Objectives)

सातवी योजना में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य 8% रखा गया था। औद्योगिक विकास के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये।

(i) उचित मूल्यो व उचित क्वालिटी की ग्राम जनता की उपयोग्य वस्तुओं व मजदूरी वस्तुओं (wage goods) की पर्याप्त सप्लाई करना,

(ii) उत्पादनता में सुधार करके तथा टेक्नोलॉजी को उन्नत करके उत्पादन की वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करना,

(iii) उन उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना जिनके लिए घरेलू बाजार काफी बड़ा है तथा निर्यात सम्भावनाएँ हैं एवं भारत उनमें विश्व में नेतृत्व कर सकता है।

(iv) नये उद्योगों पर ध्यान देना जिनमें विकास की काफी सम्भावनाएँ मरी पड़ी हैं,

(v) मुख्य क्षेत्रों में ग्राम-निर्मरता के लिए एकीकृत नीति का विकास करना तथा दक्ष व प्रशिक्षित मानवीय शक्ति की रोजगार के अवसर प्रदान करना।

सक्षेप में सातवीं योजना के दौरान उत्पादनता व आर्थिक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वस्तु की सागत में कमी करके तथा क्रिम में सुधार करके देशी व विदेशी मांग को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। एक तरफ पावर, रेलवे व कोयले जैसे क्षेत्रों का विकास किया गया है तो दूसरी तरफ लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाकर मांग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(ख) सातवीं योजना में औद्योगिक विकास की ध्युहरचना (Strategy)

औद्योगिक विकास की ध्युहरचना में निम्न मुख्य बातें शामिल की गई हैं—

(i) उद्योगों के ढाँचे में परिवर्तन करना (Restructuring of Industry)—भारत में उद्योगों के ढाँचे में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक हो गया है। हमें परम्परागत उद्योगों से ध्यान कम करके वैश्व मेटल, उर्वरक, नये उद्योगों व सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने वाले उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अतः ऊँची टेक्नोलॉजी व ऊँचे ज्ञान पर आधारित उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी औजारों व टेलीकम्यूनिकेशन्स आदि का भी विकास करना होगा। इस प्रकार देश में नवोदित उद्योगों (Sunrise Industries) का महत्व बढ़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोरसायन, कम्प्यूटर आदि उद्योग आते हैं।

(ii) पूँजी का कार्यकुशल उपयोग—उत्पादन की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने पर अधिक बल दिया जा रहा है ताकि भावी विकास के लिए बचने मिलने की संभावना

(iii) प्राथमिक व मध्यम उद्योगों का विकास—पावर के क्षेत्र में वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के साथ-साथ नए सुपर थर्मल व प्राणविक सयन्त्र स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है। जब तक ऊर्जा की स्थिति नहीं सुधरती तब तक ऐसे ऊर्जा-गहन उद्योगों पर कम बल देना आवश्यक है।

(iv) **आधुनिकीकरण व टेक्नोलोजी को उन्नत करना**—वस्त्र व चीनी जैसे उद्योगों में आधुनिकीकरण करना बहुत आवश्यक हो गया है। लागत घटाने व माल की हिस्सा सुधारने के लिए टेक्नोलोजी को उन्नत करना व प्रतियोगिता का वातावरण बनाना जरूरी है। उद्योगों को बाजार में नई वस्तुएं प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके लिए अनुसंधान पर खर्च देना होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास पर जोर देना होगा।

(v) **उत्पादकता** देश में इसका उर्वरक, अलौह धातुओं, पेट्रोरसायन, बाणज व सीमेंट जैसे उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा। इसका लिए कंप्यूटर की सहायता से संचालित क्रियाओं को बढ़ाना होगा तथा श्रमिकों का प्रयोग करना होगा।

(vi) **निर्यात के लिए विशेष क्षेत्रों का निर्धारण**—विदेशी मुद्रा अर्जित करने व नए चुनौतीपूर्ण उद्योगों में निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन-वृद्धि करनी होगी। निर्यात के नियंत्रणों का भी बहाल करना होगा। इसके लिए प्रतियोगिता व आवश्यकताओं की पूर्ति तैयारी करनी होगी।

उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट होता है कि भातवी योजना की औद्योगिक व्यवस्था में औद्योगिक ढांचे के परिवर्तन, पूँजी के कार्यकुशल उपयोग, इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार, आधुनिकीकरण, टेक्नोलोजी को समुन्नत करना, उत्पादकता बढ़ाने व निर्यात-वर्धन पर जोर दिया गया है ताकि भारत 21वीं शताब्दी में एक तबल औद्योगिक राष्ट्र बनकर प्रवेश कर सके।

उपरोक्त व्यूहरेचना के अनुसार औद्योगिक विकास कर सकने के लिए निम्न नीतियों का प्रचलन पर जोर दिया गया है।

(ग) सातवीं योजना में नीति सम्बन्धी ढांचा या क्रमबद्ध

(1) **सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का योगदान**—भारत में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। आधारभूत उद्योगों व इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों में सार्वजनिक विनियोग के बढ़ने से निजी विनियोग पर अनुकूल असर आता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में परस्पर प्रतियोगिता की दशा उत्पन्न की जानी चाहिए और इसी प्रकार निजी क्षेत्र से भी प्रतियोगिता बढ़ानी जानी चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में कार्यकुशलता के विभिन्न उपाय अपनाने आवश्यक हैं।

(ii) **बड़े, मध्यम व लघु उद्योगों के लिए एक समन्वित नीति**—भारत में बड़े व लघु दोनों प्रकार के उद्योगों का विकास करना होगा। बड़े उद्योगों में आधुनिक टेक्नोलोजी व परमाने की क्रियायतों के लाभ हैं एवं लघु उद्योगों में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है। शाही, इलेक्ट्रॉनिक्स व वस्त्र उद्योगों में इन दोनों का परस्पर पूरकता का भी सम्बन्ध है जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में लघु उद्योगों को संरक्षण भी देना होगा।

(iii) औद्योगिक नियन्त्रणों व नियमनों को सकारात्मक (Positive) कर देना होगा—नारन में औद्योगिक लाइसेन्स-व्यवस्था, विनियम-नियन्त्रण, एकाधिकारी कानून, मूल्य-निर्धारण, राजस्वानीय व औद्योगिक उद्योगों का इस दृष्टि से प्रपना होगा कि वे उत्पादन बढ़ाने में मदद दें, न कि इसमें रोक घटावें। जहां नहीं वे उत्पादन बढ़ाने में बाधा सिद्ध होते हैं, वहां इनका हटा दिया जाना चाहिए।

(iv) उद्योगों के लिए केन्द्रीय व राजकीय योजनाओं में समन्वय की आवश्यकता—साधारणतया केन्द्र का पूँजी-ग्रहण बड़े प्रोजेक्ट लेने चाहिए तथा राज्य का स्थानीय साधनों का उपयोग करने वाले योजना-ग्रहण प्रोजेक्ट लेने चाहिए। जहाँ केन्द्र व राज्यो के प्रोजेक्ट एक-से क्षेत्रों में हों, वहाँ उनमें तात्कालिक बैठकाय जाना चाहिए।

(v) सत्प्रयोग व्यवस्था—उद्योगों के विकास के लिए सम्भावित बिल की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए तथा टेक्निकल व प्रशासनिक निर्देशन भी व्यापक होना चाहिए।

(vi) उद्योगों का प्रादेशिक स्थितिक या केंद्रित—विद्युत क्षेत्रों व बिना म उद्योगों का विकास करने के लिए पावर, सड़क व जल-शक्ति का विकास करने, मजिदी देने, रियायती शर्तों पर बिजली की व्यवस्था करने व उचित लाइसेन्स-व्यवस्था प्रपनाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(vii) औद्योगिक कलता—देश में बीमार औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ रही है, उनकी समस्या को हल करने के लिए अधिक कारण उपाय किए जान चाहिए। शोपी प्रवन्धकों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जो औद्योगिक इकाई बाधन मसल नहीं हो सकती उसे बंद कर दिया जाना चाहिए।

(viii) प्रदूषण-नियन्त्रण व पर्यावरण-सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए उचित टेक्नोलोजी का उपयोग किया जाना चाहिए।

(ix) औद्योगिक सुरक्षा (Safety)—औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने व सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(x) एक नयी औद्योगिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्धि—मजदूरों, भातिशों व सरकारों अस्मरों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए ताकि वे नयी औद्योगिक व्यवस्था के अनुसार कार्य कर सकें। मजदूरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ाये जान चाहिए।

(xi) अन्त में औद्योगिक व प्रगतिशील उत्पन्नोत्पन्नता को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है जिसके बिना नई औद्योगिक संस्कृति नहीं पनप सकती। नए उद्यम-कर्ताओं का दृष्टिकोण उत्पादन बढ़ाने व लागत घटाने तथा मान की निम्न सुधार का होना चाहिए।

सातवी योजना में औद्योगिक व मनन-विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में ध्येय हेतु 19,708 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया था। 70% से अधिक धन-राशि इस्पात, उर्वरक, अलौह धातु, पेट्रो-रसायन व सीमेंट के लिए नियत की गई जो मूल क्षेत्र (core sector) में आते हैं।

घटे हुए उद्योगों में उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये :

उद्योग	1984-85 (वास्तविक उत्पादन)	1989-90 (उत्पादन का लक्ष्य)
(i) कोयला	14.7 करोड़ टन	22.6 करोड़ टन
(ii) बिक्रीयोग्य इस्पात	87.7 लाख टन	126 लाख टन
(iii) क्रूड तेल	2.9 करोड़ टन	3.4 करोड़ टन
(iv) सीमेंट	3 करोड़ टन	4.9 करोड़ टन
(v) उर्वरक-नाइट्रोजन	39 लाख टन	65.6 लाख टन
(vi) चीनी	62 लाख टन	1 करोड़ टन

इस प्रकार सातवी योजना में विभिन्न उद्योगों में उत्पादन-वृद्धि के ऊँचे लक्ष्य रखे गये ताकि औद्योगिक विकास की वार्षिक दर लगभग 8% प्राप्त की जा सके। सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास की व्यूहरचना व नीति का ढांचा भी तैयार किया। भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती लागत कम करने व माल की किस्म को सुधार कर मांग में अभिवृद्धि करने की है। इसके लिए सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था को एक नया मोह देने की आवश्यकता है।

प्राशा है भावी योजनाओं में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें औद्योगीकरण को नई दिशा देने में अधिक सिद्ध सफल होंगी। स्मरण रहे कि भारत में रोजगारान्मुख औद्योगीकरण व आधुनिक टेक्नोलोजी पर आधारित औद्योगीकरण में एक उचित संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, जो स्वयं में एक कठिन कार्य है, लेकिन असम्भव नहीं है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार औद्योगिक नियंत्रणों में उत्तरोत्तर अधिक ढील दी जायगी ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। सरकार लाइसेंस-प्रणाली के प्रभाव को और सीमित करना चाहती है।

MRTPLC कंपनियों के लिए परिसम्पत्ति की सीमा को 20 करोड़ रु से बढ़ा कर 100 करोड़ रु किया जा चुका है। प्रभुतासम्पन्न उपक्रम (dominant undertaking) की परिभाषा को 1 करोड़ रु की परिसम्पत्ति (assets) की सीमा से बढ़ाकर 5 करोड़ रु करने पर विचार चल रहा है। इन्फ्लेशन के असर्वांगत पावर की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया जा रहा है। माणा है सातवी योजना में औद्योगिक विकास की वांछित दर 8% प्राप्त की जा सकेगी तथा माठवी योजना में इसमें और वृद्धि करना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न

1. भारत में औद्योगिक नीति का औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है ? इसका मूल्यांकन कीजिए तथा सातवी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की औद्योगिक विकास की व्यूहरचना का विवरण कीजिए।

संदर्भ लेख

K. L. Krishna *Industrial Growth and Productivity in India in The Development Process of the Indian Economy*,
 Edited by Brahmananda and Panchanukhi, 1987

निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण व इसको रोकने के उपाय

(Concentration of Economic Power
in the Private Sector and
Measures to Check It)

निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण

भारत में निजी क्षेत्र ने विभिन्न किस्म के उद्योगों व व्यवसायों में भाग लिया है। देश में बड़े व्यावसायिक घराने (Big Business Houses), जैसे टाटा, बिड़ला, रिलायन्स, जे के सिंघानिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्हें एकाधिकारी घराने (Monopoly Houses) या औद्योगिक घराने (Industrial houses) भी कहा जाता है। इन औद्योगिक घरानों ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया है। अकेले बिड़ला घराने ने कई उद्योगों व व्यवसायों में भाग लिया है जैसे सूती वस्त्र मोटरगाड़ी व साइकिल उद्योग मशीनरी का निर्माण व परिवहन कागज की लुग्दी रेयोन, जूट, चीनी बिजली का सामान, सीमेंट व एल्यूमिनियम उद्योग आदि। इसी प्रकार अन्य औद्योगिक समूहों ने कई प्रकार के उद्योगों व आर्थिक क्रियाओं में भाग लिया है। नये औद्योगिक घरानों में रिलायंस ग्रुप सीलेण्ड, एम ए चिदाम्बरम, हिन्दुस्तान लीबर व टी वी एस आयरर आदि के नाम प्रमुख हैं।

राजवाज्जाल में निजी क्षेत्र ने औद्योगिक जगत में काफी प्रगति दिखलाई है। इस प्रगति की वृद्धि विरोधना रही है कि निजी क्षेत्र में असाधारण व अधिमान सत्ता के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढावा मिला है। देश की अर्थव्यवस्था पर घोर से औद्योगिक व व्यावसायिक घरानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है जो समाजवादी समाज के लक्ष्य के सर्वथा विरुद्ध है। यह वृद्धि अनुचित न होगा कि योजनावाज्ज की प्रगति को देखने हुए देश में पूर्वाज्जदी समाज की आर प्रगति अथवा आर प्रगति

वटी है। इस सम्बन्ध में कम्पनी व एम आर टी पी अधिनियमों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (राजिन्दर सच्चर समिति) का कहना है कि “एकाधिकार-जाँच-आयोग ने श्री के सी दास गुप्ता की अध्यक्षता में अपनी श्रद्धांश 1965 की रिपोर्ट में बताया था कि चोटी के 70 व्यावसायिक घरानों के अधिकार में 1536 कम्पनियाँ थी जिनकी परिसम्पत्ति 2606 करोड़ रुपये थी, जो देश की समस्त गैर-सरकारी कम्पनियों की कुल परिसम्पत्ति का 47% थी। इन्हीं 75 घरानों की परिसम्पत्ति पूँजी 646 करोड़ रुपये थी जो निजी क्षेत्र की कुल परिसम्पत्ति पूँजी का 44% थी। इसी प्रकार 1969 में दत्त समिति ने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि लाइसेंस-व्यवस्था ने बड़े औद्योगिक घरानों के विकास में सहायता पहुँचाई है।”¹

एकाधिकार-जाँच आयोग (MIC) के अनुसार आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के प्रमुखतया दो रूप होते हैं—(1) वस्तु के अनुसार केन्द्रीयकरण (Product-wise Concentration), और (2) देश के अनुसार केन्द्रीयकरण (Country wise Concentration)।

1 वस्तु के अनुसार केन्द्रीयकरण—वस्तु के अनुसार केन्द्रीयकरण में एक विशेष वस्तु या सेवा के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध के नियन्त्रण की शक्ति किसी एकल फर्म अथवा प्रोप्राइटी सीमित फर्मों अथवा काफी अधिक फर्मों (जहाँ इन फर्मों पर नियन्त्रण अनेक परिवार अथवा कुछ परिवारों या व्यावसायिक घरानों का हो) के पास होता है। यह नियन्त्रक शक्ति (Controlling Power) पूँजी के स्वामित्व अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न हो सकती है। जहाँ एक उद्योग में एक वस्तु का उत्पादन होता है, वहाँ इसे “उद्योगानुसार केन्द्रीयकरण” (Industry-wise Concentration) भी कह सकते हैं।

2 देश के अनुसार केन्द्रीयकरण—इसमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन अथवा वितरण में मलग्न अनेक फर्मों का नियन्त्रण एक व्यक्ति या परिवार या व्यक्ति-समूह, चाहे वे निगमित (Incorporated) हों या न हों में होता है। ये वित्तीय अथवा अन्य व्यावसायिक हितों के कारण परस्पर गहरे सम्बन्ध होते हैं। श्री आर सी दत्त ने देश के अनुसार केन्द्रीयकरण को अन्तर-उद्योग केन्द्रीयकरण (Inter-industries Concentration) कहा है, क्योंकि इनमें एक व्यावसायिक समूह का कई उद्योगों पर एक साथ नियन्त्रण होता है। उदाहरणार्थ, 31 मार्च 1964 को दिखला-समूह के अधिकार में 151 कम्पनियाँ थी जिनकी परिसम्पत्ति लगभग 283 करोड़ रुपये थी। इस समूह के औद्योगिक हितों का विस्तार काफी व्यापक रहा है। जैसा कि पहले

1 Report of the High-powered Expert Committee on Companies and MRTP Acts (Rajindar Sachar Committee), August 1978, p 248

चताया जा चुका है, इन कम्पनियों के कार्यक्षेत्र में कई प्रकार के उद्योग व व्यवसाय रहे हैं।

एकाधिकार-जाँच आयोग (MIC) ने वस्तु के अनुसार केन्द्रीयकरण का विस्तृत अध्ययन किया था और 100 चुनी हुई वस्तुओं जैसे शिशु दूध, चाय, चीनी, विभिन्न किस्म के यस्त्र, जालटॉ- रेफीजरेटॉ माचिस, सिगरेट, जूते, दवाएँ, टायर कारें, सीमेंट आदि में केन्द्रीयकरण के विस्तार का अनुमान लगाया था। MIC के अनुसार 100 वस्तुओं में से 65 में उच्च श्रेणी का केन्द्रीयकरण पाया गया, 10 में मध्यम दर्जे का एवं 8 में नीचे स्तर का केन्द्रीयकरण पाया गया। 17 वस्तुओं में केन्द्रीयकरण का अभाव था।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति (ILPIC) की रिपोर्ट (1969) के आधार पर साठवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में भारत में वस्तु के अनुसार केन्द्रीयकरण काफी ऊँचा हो गया था। देश में कई उद्योगों में अल्पाधिकार (Oligopoly) की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जिसके अन्तर्गत वस्तुओं के उत्पादन व बाजार पर थोड़ी-सी फर्मों का नियन्त्रण स्थापित हो गया था। एन एस सिद्धारथन ने धुने हुए उद्योगों में बाजार-केन्द्रीयकरण (market concentration) का अध्ययन करके बतलाया है कि भारत में इन्जीनियरी व रसायन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में थोड़ी-सी चार फर्मों का नियन्त्रण काफी ऊँचा रहा है। उदाहरण के लिए, मोटरगाड़ियों व सहायक उद्योगों की 102 वस्तुओं में से 96 वस्तुओं में थोड़ी-सी चार फर्मों ने शत-प्रतिशत उत्पत्ति पर नियन्त्रण कर रखा है, दवाइयों में 97 वस्तुओं में से 80 वस्तुओं में तथा कीटनाशक दवाइयों, प्लास्टिक व प्लास्टिक रसायनों में 114 वस्तुओं में से 105 वस्तुओं में इसी प्रकार का नियन्त्रण पाया गया है। अन्य रसायनों, दूध, रबड़-विनिर्माण, तेल, साबुन व पेप्ट, भारी रसायन, इन्जीनियरी, विद्युत इन्जीनियरी, चमड़ा व कागज उद्योगों में काफी वस्तुओं के उत्पादन में अल्पाधिकार की दशा विद्यमान रही है।¹

बम्बई विश्वविद्यालय के औद्योगिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे सी. सडेसरा के अनुसार 1970 में जूती, रबड़ व रबड़-वस्तुओं पेट्रोल-पदार्थों व कोयले तथा मनोरंजन की सेवाओं में उच्च केन्द्रीयकरण (33% या अधिक) पाया गया। 9 उद्योगों में जैसे फर्नीचर वेलिकेट मेटल उद्योगों, विद्युत मशीनरी के उपकरणों आदि में मध्यम श्रेणी का (16% से 32%) पाया गया तथा शेष में नीचा पाया गया। इस प्रकार भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों में ज्यादातर अल्पाधिकारी बाजार की दशाएँ पायी

1 Sudipto Mundle, *Growth, Disparity and Capital Reorganisation in Indian Economy*, EPW, Annual Number, March 1981, p. 394.

जाने हैं जिससे औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में ही भारत में वाजार-केन्द्रीयकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

एकाधिकार-आँचि आयोग ने देश के अनुसार केन्द्रीयकरण के लिए 2,259 कंपनियों के विस्तृत आँकड़े एकत्र किये थे। ये 83 बड़े व्यावसायिक घरानों के अधिकार में थीं। 75 समूहों की परिसम्पत्ति 5 करोड़ रुपये से कम नहीं थी। 1963-64 में परिसम्पत्ति में सर्वोच्च स्थान टाटा-समूह का था जिसके अधिकार में लगभग 375 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति तथा 53 कंपनियाँ थीं। दूसरा स्थान बिड़ला-समूह का था। इस समूह के अन्तर्गत 151 कंपनियाँ के लगभग 283 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति थी।

भारत में चोटी के औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियाँ, जिन्हीं आदि निरन्तर बढ़ती रही हैं। इनमें घन्यावधि में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।

1963-64 में भारत के चोटी के 20 व्यावसायिक घरानों की कुल परिसम्पत्तियों का मूल्य 1347 करोड़ रु. था जो बीस वर्ष बाद 1983-84 में 12262 करोड़ रु. हो गया। हालाँकि नये बीस व्यावसायिक घराने के नहीं रहे जो पहले थे। इस प्रकार इनकी परिसम्पत्तियों (assets) में प्रतिवर्ष 40.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुयी। यह वृद्धि प्रचलित मूल्यों पर हुयी है। यदि 1983-84 की परिसम्पत्तियों का मूल्य 1963-64 के मूल्यों पर लगाया जाय तो भी परिसम्पत्तियों में वास्तविक वार्षिक वृद्धि-दर लगभग 13.5 प्रतिशत आयेगी। स्वभाविक है कि स्थिर भावों पर यह नीची रहेगी। 1985 में चोटी के 20 व्यावसायिक घरानों की कुल परिसम्पत्ति 20137 करोड़ रुपये हो गयी थी। ताजा आँकड़ों के अनुसार 1986-87 में चोटी के औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियाँ निम्न तालिका में बतायी गयी हैं—¹

घराने का नाम (क्रमवार)	करोड़ रु.
1. टाटा	4940
2. बिड़ला	4771
3. रिलायन्स	2022
4. ज. के. सिन्घानिया	1427
5. थापर	1151

1. The Economic Times, May 4, 1989

6. मकतलान	1050
7. मोदी	860
8. लार्सन व टून्स	831
9 एम. ए. चिदाम्बरम्	808
10. बजाज	778

कुल 18638

तानिजा से स्पष्ट होता है कि 1986-87 में चोटी के दस व्यावसायिक घरानों की कुल परिसम्पत्ति 18638 करोड़ रुपये हो गई थी जिनमें प्रथम स्थान टाटा का हा गया था। टाटा-विडला दोनों की परिसम्पत्ति 9711 करोड़ रुपये थी जो इन चोटी के दस घरानों की कुल परिसम्पत्ति का 52% थी।

आजकल अकेल परिसम्पत्ति के मूल्य पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि साथ में त्रित्री-मूल्य को भी देखा जाता है। अतः परिसम्पत्ति-त्रित्री मूल्य-अनुपात (asset-turnover ratio) की जानकारी का महत्त्व बढ़ गया है। 1986-87 में यह अनुपात 1 : 1.3 मोदी घराने के लिए सर्वाच्च रहा; जबकि रिलायन्स के लिए यह 1 : 0.5 ही था। उस प्रकार मोदी घराने की स्थिति अधिक सम्पोजक मानी जा सकती है हालांकि परिसम्पत्ति के आधार पर घरानों के क्रम में इसका स्थान मातया था, जत्रि रिलायन्स का तीसरा था। अतः चोटी के व्यावसायिक घरानों की कार्यमिद्धि में परिसम्पत्ति का त्रित्री-मूल्य से अनुपात देयना ज्यादा उपयोगी रहता।

1986-87 में टाटा-विडला की परिसम्पत्तियों का दस व्यावसायिक घरानों की कुल परिसम्पत्तियों में आधा अंश भारत में 'केन्द्रीयकरण में केन्द्रीयकरण' (Concentration within Concentration) की स्थिति का सूचक माना जाता है। 1980 में 20 घरानों की कुल परिसम्पत्ति देश में निजी क्षेत्र की कुल परिसम्पत्ति का लगभग तीसरा अंश थी।

प्रत्येक त्रित्री का मत है कि चोटी के दस घरानों के योगदान को देखने के लिए त्रित्री-मूल्य ज्यादा अच्छा सूचक है क्योंकि परिसम्पत्ति के मूल्यांकन तथा मूल्य-ह्रास आदि का हिसाब लगाने में कई दिक्कतें आती हैं।¹

1 Pranab Bardhan, *The Political Economy of Development in India*, 1984, p. 42.

बड़े व्यावसायिक घरानों में आधिक सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है, क्योंकि उन्हें कई प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये निर्णय निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित होते हैं : धान्तरिक व बाह्य साधनों से पूँजी जुटाना, वित्तीय साधनों को नये उपक्रमों व चालू उपक्रमों के विस्तार के बीच विभाजित करना, चालू स्वतन्त्र कम्पनियों को खरीदना व उनका एकीकरण करना, सयनों के स्थान का चुनाव करना, टेक्नोलॉजी का चुनाव करना, अनुसंधान व विकास सम्बन्धी कार्य करना, उत्पादन की मात्रा व कीमत का निर्धारण करना, रोजगार की मात्रा निर्णयित करना, छोटी के व्यवस्थापकों के वेतन व प्रमुख मुक्तानों का निर्धारण करना, आदि। ये निर्णय एकाधिकारी घरानों में कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो रहे हैं जिससे इस व्यवस्था में पारिवारिक प्रबंध (family management) विकसित हो जाता है।

व्यावसायिक समूह व एकाधिकार में अन्तर

बड़े व्यावसायिक समूह व एकाधिकार के बीच में भी अन्तर पाया जाता है। पहले में आधिक शक्ति पर नियन्त्रण (Control over economic power) होता है, जबकि दूसरे में एक वस्तु के बाजार पर नियन्त्रण (Control over Market) होता है। बड़े व्यवसायों को सर्वत्र प्रत्येक वस्तु पर 'एकाधिकार' प्राप्त नहीं होता, जैसे टाटा व बिडला का अधिकार में पायी जाने वाली सूती वस्त्र की मिलों को वस्त्र-बाजार में एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक एकाधिकारी फर्म किसी बड़े व्यावसायिक समूह की ही फर्म हो; उदाहरण के लिए मशीन व चाकू बनाने वाली साल्टी प्राइवेट लि. का इस वस्तु के बाजार में तो एकाधिकार है, लेकिन यह किसी बड़े व्यावसायिक घराने से सम्बन्ध नहीं रखती।

एक बड़े व्यावसायिक घराने के द्वारा किसी कम्पनी पर नियन्त्रण कैसे स्थापित किया जाता है ?

एक बड़े व्यावसायिक घराने के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि इसके द्वारा किसी कम्पनी पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह उस कम्पनी की शेयर-पूँजी में बड़ा हिस्सा ही ले। यदि वह घराना उस कम्पनी में अकेले अल्पसंख्यक के रूप में सर्वाधिक शेयर (largest single minority shareholding) रखता है तो भी उसका कम्पनी पर नियन्त्रण स्थापित हो सकता है। जिन कम्पनियों की शेयरहोल्डिंग काफी फैली या धिन्तरी हुई होती है, उसमें यह सम्भव हो सकता है कि एक व्यावसायिक घराने के पास थोड़े से शेयर होने पर भी अकेले उसी के पास अल्पसंख्यक रूप में सर्वाधिक शेयर-राशि हो। उदाहरण के लिए, टाटा-समूह का टाटा आयरन व स्टील कम्पनी की कुल शेयर पूँजी में 6 या 7 प्रतिशत अधिकार या स्वामित्व रहा है, फिर भी उनका उस पर नियन्त्रण

है क्योंकि अकेले इतनी पूँजी का स्वामित्व अन्य किसी समूह के पास नहीं है। इसी तरह बिड़ला-समूह का हिन्दुस्तान मोटर्स में लगभग 15 प्रतिशत शेयर पूँजी (equity) पर ही नियन्त्रण पाया गया है, फिर भी कम्पनी उन्हीं के नियन्त्रण में मानी जाती है। इसलिए यह भ्रम मिथ्या है कि प्रत्येक कम्पनी में बड़े व्यावसायिक घराने की पूँजी उमरी कुल पूँजी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। इससे बड़े व्यावसायिक समूह व उमरे नियन्त्रण में होने वाली कम्पनी का पूँजी की दृष्टि से परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है जिसको समझना बहुत जरूरी है।

1981 के अन्त में छः बड़े व्यावसायिक घरानों (टाटा, बिड़ला, मफतलाल, जे. के. सिंघानिया, चापर व श्रीराम) की शेयर-पूँजी उनके अधिकार वाली कम्पनियों में केवल 33.3% ही थी। अपने नियन्त्रण वाली कम्पनियों में जे. के. सिंघानिया ग्रुप का शेयर पूँजी में 71% अंश था, जो सर्वाधिक था, तथा श्रीराम ग्रुप का 0.5% ही था। यदि कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों (total assets) में इन बड़े व्यावसायिक घरानों का अंश देखा जाय तो वह और भी कम मिलेगा जैसे मफतलाल ग्रुप के लिए यह 0.99% रहा, जबकि श्रीराम ग्रुप के लिए 0.04% ही था। कहने का आशय यह है कि अपने नियन्त्रण वाली कम्पनियों की शेयर-पूँजी व कुल परिसम्पत्ति में बड़े व्यावसायिक घरानों का अंश बहुत नीचा पाया जाता है।

निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण

1. टेक्नोलोजी की प्रगति—टेक्नोलोजी की तीव्र प्रगति के कारण बड़े उत्पादक उत्पादन-लागत घटा सकते हैं। आजकल औद्योगिक जगत में समन्त्र के आकार (Scale of Plant) का महत्व बहुत बढ़ गया है। निगम के प्रादुर्भाव से 'बड़े पैमाने की किफायतें' प्राप्त होने लगी हैं। अनेक व्यक्ति पूँजी की विशाल मात्रा जमा कर लेते हैं और निगम बना लेते हैं। शेयर-होल्डर प्रबन्ध का कार्य कुछ व्यक्तियों को सौंप देते हैं। जो उद्योगपति अपनी दक्षता व उद्यम के गुणों से एक या दो फर्मों पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, वे अपने नियन्त्रण का क्षेत्र ग्रामे बढ़ाते जाते हैं। लोगो का इनमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे अपनी वचतें भी इन्हें सौंप देते हैं।

2. मैनेजिंग एजेंसी का प्रभाव—मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली ने भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को बढ़ाने में मदद पहुँचायी है। इस पद्धति के अन्तर्गत एक निगम का प्रबन्ध दूसरे निगम या साझेदारी फर्म या व्यक्ति को प्रतिफल की एवज में सौंप दिया जाता था। इस प्रकार कुछ परिवारों के हाथों में आर्थिक सत्ता केन्द्रित होती जाती है। पहले एक मैनेजिंग एजेंट के पास कई प्रकार के उपक्रम होते थे, जिससे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण का बढ़ना स्वाभाविक था।

संस्थाओं की ऋण-नीति भी निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की बढ़ान में सहायक रही है।

6 सरकार ने व्यवहार में औद्योगिक नीति प्रस्तावों की अवहेलना करके बड़े घरानों को उन क्षेत्रों में साइसेन्स प्रदान किए हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने थे। बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ सार्वभौमिकता का लाभ भी बड़े व्यावसायिक घरानों को ही मिला जिससे निजी हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण बढ़ा है। भारत के बड़े व्यावसायिक घरानों व बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच गहरी व्यावसायिक साठ-गाठ पाई जाती है।

7 बड़े व्यावसायिक समूहों को बैंक की सुविधा—बड़े व्यावसायिक घरानों को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से काफी सुगमतापूर्वक रियायती दरो पर वित्त प्राप्त होता रहा है। इससे भी केन्द्रीयकरण का बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों के संचालक-मण्डल में व्यावसायिक समूहों के प्रतिनिधि होते थे। बैंक इन्हें ऋण देने में कम जोखिम मानते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकों ने बड़े घरानों को ऋण देना जारी रखा है तथा राष्ट्रीयकरण के मूल उद्देश्यों की मुला दिया गया है।

आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के अलावा औद्योगिक व व्यावसायिक जगत में कई प्रकार की एकाधिकारात्मक व प्रतिबन्धात्मक क्रियाएँ भी देखने को मिलती हैं जिससे समाज की निरन्तर हानि होती रहती है। इनका वर्णन आगे किया जाता है।

एकाधिकारात्मक व प्रतिबन्धात्मक-व्यापार-विधियाँ या क्रियाएँ—(Monopolistic and Restrictive Trade Practices)—एक बाजार पर कुछ विक्रेताओं का अधिकार होने से एकाधिकारात्मक दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब एकाधिकारी शक्ति रखने वाले व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग स्वयं लाभ उठाने के लिए अथवा इसको बढ़ाने व सुदृढ़ करने के लिए करते हैं तो इसे एकाधिकारात्मक व्यवहार या क्रिया कहते हैं। एकाधिकारी नये उद्यमकर्ताओं को डराकर आगे आने से रोकना या प्रयत्न करते हुए पाये जाते हैं।

प्रतिबन्धात्मक व्यापार-विधियाँ या कार्य एकाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अलावा ऐसे कार्य होते हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों के मार्ग में बाधक होते हैं अथवा जो अन्तिम वस्तुओं के वितरण में बाधक होते हैं। व्यवहार में प्रायः निम्न सात प्रकार की प्रतिबन्धात्मक व्यापार-विधियाँ देखी गयी हैं।

1. कीमतों का क्षैतिज निर्धारण (Horizontal Fixation of Prices)—व्यापारी माल का संग्रह करके एवं कृत्रिम रूप से इसकी कमी करके इसे ऊँचे भावों पर बेचने में समर्थ हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसा खाद्यान्नों, वनस्पति तेलों, बेबी फूड, तैयार, साबुन आदि उपभोक्ता वस्तुओं में काफी सीमा तक रहा है।

2. कीमतों का उदग्र व सम्भवतः निर्धारण और फिर से बेचने के मूल्यों को स्थिर रखना (Vertical Fixation of Price and Resale price Maintenance)—फिर से बेचने की कीमतों को निर्धारित कर देने से वितरकों में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और उपभोक्ता-वर्ग को ऊँचे मूल्य देने पड़ते हैं, क्योंकि वितरक चाहे तो भी कीमते घटाकर परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इससे उपभोक्ता-वर्ग को हानि उठानी पड़ती है।

3. उत्पादकों के बीच बाजारों का बटवारा (Allocation of markets Between Producers)—विभिन्न उत्पादक आपस में बटवारा का वितरण कर लेते हैं। यह भी एक प्रतिवन्धात्मक कार्य होता है। प्रत्येक उत्पादक अपने हिस्से के बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण करता रहता है और इसे रोकने में कठिनाई होती है।

4. क्रोताओं के बीच भेदभाव (Discrimination Between Purchasers)—जब विभिन्न खरीददारों के बीच भेदभाव की नीति बरती जाती है तो प्रतिवन्धात्मक क्रियाओं को जन्म मिलता है।

5. बहिष्कार (Boycott)—एक उत्पादक अपने वितरकों पर यह शर्त लगा देता है कि वे प्रमुख व्यक्तियों को उसका माल नहीं बेचेंगे। यह बहिष्कार की विधि कहलाती है। ऐसा प्रायः एक तेज बम्पनी अपने वितरकों के लिए करती है ताकि वे उस ग्राहकों को माल नहीं दें जिनके बारे में कम्पनी रोक लगा देती है।

6 एक ही फर्म का माल बेचने के सम्झौते (Exclusive Dealing Contracts)—बम्पी-कम्पी व्यापारियों से यह सम्झौता कर लिया जाता है कि वे अन्य प्रतिस्पर्धियों का माल नहीं बेचेंगे। इससे भी समाज को हानि होती है।

7 'जोड़ देने की शर्तें' (Tie-up Arrangements)—कई बार एक उत्पादक अपने व्यापारियों पर यह शर्त लागू कर देता है कि वह प्रमुख वस्तु के खरीदे जान पर ही उन्हें अपनी दूसरी वस्तु देगा—जैसा मान सीजिए, एक बिजली के पंखों का उत्पादक बिजली की ट्यूबें भी बनाता है। वह अपने व्यापारियों को कहता है कि उनकी पक्ष लेने पर ही ट्यूबें मिल सकेंगी। ऐसी सूरत में ट्यूबें लेने वालों को लाचार होकर कुछ पक्ष भी खरीदने पड़ते हैं, जिन्हें सम्भवतः वे अन्यथा उससे नहीं खरीदते। ऐसा उस समय होता है जब ट्यूबें अन्यत्र आसानी से नहीं मिल पाती हैं। प्रतिवन्धात्मक व्यापार विधि का एक सामान्य दृष्टान्त और देखने को मिलता है। एक गैस बम्पनी नया गैस का कनेक्शन देते समय प्रायः यह शर्त लगा देती है कि गैस का चूल्हा उसी से खरीदा जायगा। ऐसी दशा में नया कनेक्शन लेने वाला व्यक्ति लाचार होकर उसी से गैस का चूल्हा खरीदता है जिसे शायद वह अपनी

पसन्द के अनुसार किसी अन्य जगह से खरीदता। इस प्रकार मूल्य-निर्धारण उत्पादकों के बीच बाजार का वितरण, क्रेताओं के बीच विभेद, बहिष्कार, एक ही कम्पनी का माल बेचने के समझौते एवं जोड़ देने की शर्तों वाले समझौते आदि के रूप में प्रति-बन्धात्मक व्यापार विधि का व्यवहार में प्रचलन देखा जाता है।

निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के परिणाम (Consequences of Concentration of Economic Power in the Private Sector)

भारत में साधारणतया नागरिकों की निगाह में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण बहुत हेय, हानिकारक व बुरा माना जाता है। देश में धन व श्रम की विशाल असमानता व खाई के कारण आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण अनुचित माना गया है।

प्रायः यह शिकायत सुनी जाती है कि सरकारी नीति पर बड़े व्यावसायिक घरानों व बड़ी कम्पनियों का अनुचित प्रभाव पड़ता है। बहुधा लोकसभा में बड़े व्यावसायिक वर्ग के खिलाफ आवाज उठायी जाती है। लेकिन सरकार उनके विरुद्ध कोई सत्रिय कदम नहीं उठा पाती। प्रमुख उद्योगपति राजनीतिक सत्ताधारी वर्ग को समय-समय पर धन देते रहते हैं (विशेषतया आम चुनावों के समय)। बाद में वे इसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। बड़े व्यवसायी अपनी 'लम्बी जेब' के कारण राजनीतिज्ञों, मन्त्रियों तथा सरकारी अधिकारियों या नीकरसाही को भ्रष्ट करने में सकोच नहीं करते और निरन्तर अपना औद्योगिक साम्राज्य बढ़ाते जाते हैं। इससे देश में नैतिकता व ईमानदारी का सामान्य स्तर गिर जाता है। चुनावों में भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचार-सत्ताप रूपका स्वर्ण करके राजनीतिक सफलता प्राप्त कर ली जाती है। अ पातकाल में अधिकांश बड़े व्यावसायिक घरानों ने तत्कालीन सरकार को अपना समर्थन देकर यह सिद्ध कर दिया था कि वे अपने हितों को बनाये रखने के लिए अधिनायकवादी शासन तक का भी समर्थन कर सकते हैं, एवं वे लातन्त्र व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की विशेष परवाह नहीं करते। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के सामाजिक परिणाम भी प्रतिकूल ही हुए हैं—धनी अधिक धनी हो गया है और वे अपने आप को समाज के एक पृथक् व उच्च वर्ग के अन्तर्गत मानने लगे हैं।

भारत में विपक्षी दल के नेताओं ने अपने बयानों में देश की बड़ी औद्योगिक फर्मों पर यह दोष लगाया है कि उन्होंने स्विस बैंकों में धनराशि जमा करायी है तथा देश के हितों के खिलाफ काम किया है।

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा है कि बड़े औद्योगिक घरानों ने निर्यात बढ़ाने में उतना योगदान नहीं दिया है जितना लघु इकाइयों ने दिया है। इस प्रकार बड़े व्यावसायिक घरानों व बड़ी कम्पनियों के कार्य-कलापों की समय-समय पर तीक्ष्ण आलोचना की गयी है।

आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के आर्थिक परिणाम

(1) लाभ—कुछ लोगों का मत है कि केन्द्रीयकरण ने औद्योगिककरण की प्रक्रिया में मदद करके देश को काफी लाभ पहुँचाया है। इससे पूँजी-निर्माण में सहायता मिली है, नये उपक्रम प्रारम्भ किये गये हैं और उच्च स्तर की प्रगल्भ-वस्तुता का विकास हुआ है जिससे उत्पादन का स्तर ऊँचा हुआ है, औद्योगिक लाभ प्राप्त किये गये हैं और औद्योगिक जगत में विफलताएँ कम हुई हैं। विदेशी सहयोग प्राप्त करने में भी इससे मदद मिली है। इस प्रकार आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण आधुनिक औद्योगिक संघर्षव्यवस्था के विकास में भी सहायक रहा है। इससे बड़े पैमाने की वस्तुएँ या विस्तारित प्राप्त होती हैं जिससे लागत घटाने व लाभ की किस्म सुधारने का अवसर मिलता है।

(11) हानियाँ—(अ) एकाधिकार के दोष—इससे एकाधिकार व उससे उत्पन्न बुराईयाँ जैसे ऊँचे भाव, लाभ की किस्म में गिरावट और छोटे उद्योगपतियों के प्रवेश पर रोक आदि सामने आयी हैं। बड़े व्यावसायिक समूह लाभों से लेने व प्रत्येक सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते रहने के लिए दिल्ली में 'अपने कूताबास' बनाये रखते हैं, जबकि छोटे उद्योगकर्ताओं के लिए यह सब करना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार सरकारी नियंत्रणों के जाल-जाल में से भ्रमना मार्ग बनाने में बड़े व्यवसायी तो किसी तरह सफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें सरकारी अधिकारों व बड़े राजनीतिकों की प्रभावित करने की काफी क्षमता व दक्षता पायी जाती है। बड़े उद्योगपति अपने समाचार-पत्र चलाते हैं और वे वही राष्ट्रीय सहमति व राष्ट्रीय विचारधारा के निर्माण में बाधा पहुँचाते हैं। वे छोटे व्यक्तियों को सामने नहीं आने देते। प्रायः कीमन-युद्ध (price-war) व घमकियों के रूप में छोटे उद्योगकर्ताओं को निरुत्साहित किया जाता है।

इससे प्रगल्भकीय व उद्यम सम्बन्धी योग्यता व्यापक रूप से विकसित नहीं हो पाती है। राष्ट्रीय धन व राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता निरन्तर बढ़ती जाती है।

एकाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य डॉ एच के. पराशरे के अनुसार आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण का दो आधारों पर विरोध किया गया है। सर्वप्रथम, इसमें मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आवश्यकता से ज्यादा सत्ता केन्द्रित हो जाती है जो लोकतान्त्रिक समाज में ठीक नहीं मानी जाती। द्वितीय, इससे आर्थिक व सामाजिक भोपण की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। वस्तुओं में एकाधिकार की दशा उत्पन्न हो जानी है तथा आमदनी, अवसर व उपयोग की असमानताएँ बढ़ जाती हैं।

(आ) विनिवेश गलत दिशाओं में—आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण से विनिवेशों के गलत दिशा में जाने (misdirection of investments) की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। किसी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन होता है वह उसका उतना

ही अधिक मनमाना उपयोग किया करता है। इसलिए कई बार विनियोग विकास के पक्ष में न जाकर माल की मट्टेबाजी मग्न व अन्य अनुत्पादक क्रियाओं में चला जाता है। इस प्रकार केन्द्रीयकरण के आर्थिक परिणाम हानिकारक भी हो सकते हैं और प्रायः होते भी हैं।

भारत में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए सरकारी उपाय

भारतीय संविधान की धारा 39 (c) के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप सरकार आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए कृत-मत्त्व है।

सरकार ने 14 मई, 1969 को कम्पनी सशोधन बिल पास कर दिया था जिसके अनुसार मैनेजिंग एजेंटों प्रणाली 3 अप्रैल, 1970 से समाप्त कर दी गयी थी। इसी सशोधन के अनुसार कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों पर भी रोक लगा दी गयी थी। कम्पनी-प्रवन्धन अब व्यवसायवाद (Professionalism) की तरफ बढ़ रहा है तथा दल में व्यावसायिक प्रवन्धकों के दल तैयार हो रहे हैं। अब प्रवन्धन-मत्त्वों में शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त करके जो व्यक्ति निकलते हैं उन्हें प्रवन्धन का कार्य सम्भालने का अधिक अवसर मिलने लगा है। इससे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है जहाँ में 'पारिवारिक प्रवन्ध' (Family management) के स्थान पर व्यावसायिक प्रवन्ध (Professional Management) को बढ़ावा मिला है।

एकाधिकार व प्रतिवन्धात्मक व्यापार-विधियाँ अधिनियम, 1969,
(MRTP Act, 1969)

एकाधिकार व प्रतिवन्धात्मक व्यापार-विधियाँ अधिनियम (The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) जून, 1970 से लागू हो गया था। यह वैधानिक व्यवस्था एकाधिकार-जाँच आयोग (Monopolies Inquiry Commission, 1951) की निफारिश के आधार पर की गयी थी। 2 अगस्त, 1970 को सरकार ने तीन व्यक्तियों का एकाधिकार व प्रतिवन्धात्मक व्यापार विनि आयोग स्थापित किया था जिसे संक्षेप में एकाधिकार आयोग (Monopoly Commission) भी कहा जाता है।

MRTP अधिनियम के तीन उद्देश्य रहे गये हैं—

- (1) यह दर्शाना कि आर्थिक प्रणाली का संचालन आम जनता के हितों के विरुद्ध दल में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण उत्पन्न न करे,
- (ii) एकाधिकार पर नियन्त्रण,
- (iii) एकाधिकारात्मक प्रतिवन्धात्मक व अनुचित व्यापार-विधियों या क्रियाओं को रोकना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आयोग बड़े व्यावसायिक धरानों व प्रभुतासम्पन्न उपक्रमों (dominant undertakings) को क्रियामो पर कई तरह से अकुश लगाता है।

अधिनियम की धारा 2 (डी) के अनुसार एक प्रभुतासम्पन्न उपक्रम (dominant undertaking) वह है जो स्वयं अथवा कुछ सम्बद्ध उपक्रमों सहित एक वस्तु के उत्पादन, सप्लाई या वितरण की कम से कम एक चौथाई मात्रा को नियंत्रित करे अथवा भारत में प्रदत्त सेवाओं में से कम से कम एक चौथाई सेवाएँ अथवा इनका बड़ा भाग नियन्त्रण करे। यदि प्रभुतासम्पन्न कम्पनी IDR अधिनियम में आती है तो इसकी लाइसेंसनुदा क्षमता देश की कुल क्षमता का कम से कम $\frac{1}{4}$ अंश होती है। बड़े व्यावसायिक धराने व प्रभुतासम्पन्न उपक्रम MRTTP उपक्रम या कम्पनी कहलाते हैं।

अधिनियम में निम्न बातों की व्यवस्थाएँ की गयी हैं : (i) कम्पनियों के विस्तार मिलन, खरीद व एकीकरण (expansion merger, purchase and amalgamations) एवं प्रभुतासम्पन्न उपक्रमों (परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों सहित) के संचालकों की नियुक्ति का नियमन (regulation)। शर्त यह है कि इन प्रभुतासम्पन्न उपक्रमों की परिसम्पत्तियाँ 1 करोड़ रुपये से कम न हों और अन्य उपक्रम जिनकी परिसम्पत्तियाँ परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों सहित (Inter-connected undertakings) 100 करोड़ रुपये से कम न हों (ii) ऐसे नये उपक्रमों की स्थापना का नियमन जो ऐसे चालू उपक्रमों से सम्बद्ध हो जायेंगे जिनकी कुल सम्पत्ति 100 करोड़ से कम न हो। और (iii) सार्वजनिक हित के विपरीत होने वाली एकाधिकारात्मक व प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार-विधियों पर रोक व नियन्त्रण लगाना। ऐसे सभी उपक्रमों को अधिनियम के अन्तर्गत अपने पंजीकरण या सर्टिफिकेट लेना होगा। अधिनियम में आयोग के कहने पर केन्द्रीय सरकार को एक उपक्रम के व्यवसाय अथवा कम्पनी के विभाजन का अधिकार भी दिया गया है। एकाधिकार आयोग विस्तार, विविधीकरण, मिलन व एकीकरण जैसे विषयों व एकाधिकारात्मक पद्धतियों पर सलाह (advice) देगा। लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार-विधियों (RTP) पर यह न्यायिक अधिकार

1 D P S Verma, A Decade of MRTPC, a series of four articles in the Economic Times, April 7 to April 10, 1981.

*16 मार्च 1985 को सदन में पेश किये गये सघोष बजट 1985-86 में वित्त मन्त्री ने MRTP के अन्तर्गत परिसम्पत्ति की सीमा 20 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. कर दी थी।

(judicial powers) रखेगा। यह अधिनियम सरकारी क्षेत्र में स्थापित कम्पनियों पर लागू नहीं किया गया है।

M RTP अधिनियम का क्रियान्वयन (Implementation of MRTP Act¹)—जून, 1 1970 से 30 जून, 1978 तक 1395 कम्पनियों ने MRTP की धारा 26 के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करवाया था। इनमें से 234 उपक्रमों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इस प्रकार 30 जून 1978 को शुद्ध पंजीकृत इकाइयों की संख्या 1161 थी।

31 मार्च 1984 को देश में कुल पंजीकृत कम्पनियों की संख्या 96 470 थी जिसमें से 1334 कम्पनियाँ MRTP अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत थीं जो कुल कम्पनियों का 1½% मात्र थीं। इनमें से आधी कम्पनियाँ छोटी व 20 व्यावसायिक धरानों की थीं। इससे MRTP कम्पनियों की छोटी संख्या का प्रभाव लगाया जा सकता है।

इन उपक्रमों को अधिनियम के अन्तर्गत काफी विस्तार (substantial expansion) (धारा 21), नये उपक्रमों की स्थापना (धारा 22), एकीकरण विलयन व खरीद (धारा 23) के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है।

केन्द्रीय सरकार ने प्रथम 10 वर्षों की अवधि में 31 जुलाई, 1980 तक MRTP आयोग को कुल 65 मामले सौंपे गये जिनमें 34 मामले धारा 21 के अन्तर्गत, 24 मामले धारा 22 के अन्तर्गत तथा 7 मामले धारा 23 के अन्तर्गत थे। इनमें से आयोग ने 47 मामलों को निपटा दिया, 16 मामले वापस ले लिये गये अथवा बन्द कर दिये गये (withdrawn or closed) तथा 2 विचारणीय थे (लेकिन इन्हें भी अगस्त-सितम्बर 1980 तक निपटा दिया गया)।

सरकार ने बहुत से मामलों पर उनको आयोग को सौंपे बिना ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। शुरू के वर्षों में सरकार ने आयोग को कुछ मामले सौंपे थे जिनकी संख्या बाद में लगातार घटती गई।

धारा 27 का उपयोग करके सरकार किसी भी उपकरण (undertaking) को कई उपक्रमों में विभक्त कर सकती है। ऐसा करने वह उपक्रम को एक एकाधिकारवादी व प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार-विधि अपनाने से रोक सकती है। केन्द्रीय सरकार ने 10 वर्षों की अवधि में धारा 27 के तहत केवल दो मामले आयोग को सुपुर्दे रखे। प्रथम मामला जियाजी राव कॉटन मिल्स लि. खालियर का था जो आयोग को मई 1974 में सौंपा गया था। सौराष्ट्र केमिकल्स नामक औद्योगिक इकाई इस कम्पनी का एक डिवीजन थी जिसने बारे में केन्द्रीय सरकार ने आदेश जारी किया था कि इसने सोडा एश के उत्पादन में प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त कर ली है और इसकी कार्य-प्रणाली मार्गजनिक हितों के विपरीत है। इसलिए आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम किया जाना चाहिए। लेकिन कम्पनी ने आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जून 1974 में 'स्टे' जारी कर दिया था।

एकाधिकार आयोग को सफल बनाने की दिशा में सुझाव

1. धारा 21, 22, 23 व 27 के अन्तर्गत सारे आवेदन-पत्र आयोग को ही भेजे जाने चाहिए। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्धारित होने चाहिए। सच्वर समिति ने भी इस सुझाव को अंशतः स्वीकार किया था।

एकाधिकारात्मक व्यापार-विधि (MTP) के मामलों में भी आयोग को आदेश देने के कानूनी अधिकार दिये जाने चाहिए, जैसा कि इन समय प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार विधि (RTP) के मामलों में प्राप्त है। इस समय MTP के मामलों में यह केवल सलाह ही दे सकता है, जो काफी नहीं है।

3 MRTP अधिनियम नवोन्नत उपक्रमों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

4 MTP व RTP की परिभाषाओं में संशोधन करके इनके अन्तर्गत अनुचित व्यापार-विधियों (unfair trade practices) को भी शामिल किया जाना चाहिए जैसे नाप-तौल की गलत विधियाँ, धोखाधड़ी के अन्य मामल, आदि। इस सम्बन्ध में MRTP अधिनियम में 1984 के संशोधन में कुछ सीमा तक प्रयास किया गया है।

5. RTP के मामलों में आयोग को क्षति पहुँचाने वाली पार्टी को मोटिव हर्जाना दिलाने का अधिकार भी होना चाहिए।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना है कि नवविषय में MRTPC को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, ताकि यह अधिक नस्ला व केन्द्रीयकरण का रोक्ने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। वर्तमान रूप में इसमें अतिरिक्त अनुदान परिणामों की आशा करना व्यर्थ है। लेकिन इस अधिनियम व आयोग को सनापन करने का विचार भी नितान्त गलत होगा, क्योंकि इनके अभाव में एकाधिकार व केन्द्रीयकरण की प्रवृत्तियाँ और मजबूत हो जायेंगी।

MRTP अधिनियम में संशोधन हेतु सच्वर समिति की सिफारिशें

अगस्त, 1978 में सच्वर समिति ने MRTP अधिनियम में संशोधन करने तथा प्राधिक मत्ता के केन्द्रीयकरण को रोक्ने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें पेश की थी—

1. एक कम्पनी के प्रभुत्व की स्थिति को निश्चित करने के लिए बाजार में उसका अंश $\frac{1}{3}$ की बजाय $\frac{1}{4}$ कर देना चाहिए।

2. MRTP अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में सच्वर समिति ने परिमरूपिता को 20 करोड़ रु की सीमा को अपरिवर्तित रखा था।

3. MRTP अधिनियम में एकाधिकारात्मक व प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार-विधियों के अन्तर्गत अनुचित विधियों (unfair practices) को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता-वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके। फलस्वरूप आयोग का नाम एकाधिकार व व्यापार-विधि आयोग (Monopolies and Trade Practices Commission) कर दिया जाना चाहिए।

4 गुमराह करने वाले विज्ञापन (misleading advertisements) पर रोक लगायी जानी चाहिए। इनसे उपभोक्ताओं के हितों को हानि पहुँचती है। समिति की सिफारिशों के स्वीकार हो जाने पर उपभोक्ता गुमराह करने वाले विज्ञापन से होने वाली हानि के लिए हर्जाना ले सकेंगे।

5 चूंकि एकाधिकार कानून का उद्देश्य उपभोक्ता-वर्ग को लाभ पहुँचाना है, इसलिए MRTP अधिनियम सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू किया जाना चाहिए, जिन्हें अब तक इस अधिनियम से मुक्त रखा गया है।

6 हर्जाना वसूल करने के मामलों की सुनवाई MRTPC के समक्ष हो होनी चाहिए न कि मजिस्ट्रेट के नामने जैसा कि इस समय होता है।

7 यदि 1,000 व अधिक श्रमिकों वाली कंपनियों के 51% श्रमिक प्रबंधन में भागधारी का समर्थन करें तो उनमें यह व्यवस्था प्रतिबर्धन लागू कर दी जानी चाहिए।

MRTP अधिनियम में 1982 व 1984 के संशोधन

अगस्त 1982 में MRTP अधिनियम में दो संशोधन किये गये जो इस प्रकार हैं—

1. प्रभुत्व (dominance) की परिभाषा कुल उत्पात के एक तिहाई से बढस कर दोगे में कुल माइसेस-गुदा क्षमता का एक चौथाई कर दी गई। वृद्धि में उद्योगों में कुल लाइसेंस-गुदा क्षमता तेजी से बढ़ी है, जिससे प्रभुत्व के लिए 25% क्षमता का मापक घटाना अधिक उदार नहीं माना जा सकता। इन परिवर्तन से उत्पादन बढान में मदद मिलेगी। इसलिए यह मजबूत उत्पादन बढाने के अनुकूल है।

2 दूसरे संशोधन के अनुसार सरकार ने अपने पास यह वैधानिक अधिकार लेने का प्रयास किया है ताकि यह अधिसूचना जारी कर के उद्योगों, सेवाओं व उद्यमों को MRTP अधिनियम के अन्तर्गत धारा 21 के तहत बांधी विस्तार करने व धारा 22 के तहत नये उद्यमों की स्थापना करने के लिए इजाजत लेने से मुक्त कर सके। इससे 100% निर्यात इकाइयों की स्थापित करने एवं बांधू इकाइयों की विस्तार करने में काफी सहायता हो जायेगी। इन प्रस्तावों को लागू करने से बन्धुओं की सपनाई बढेगी जिसमें घरेलू व विदेशी भाग दोनों को पूरा करना सम्भव हो सकेगा। मई 1985 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 27 उद्योगों को MRTP अधिनियम की धारा 21 व 22 से मुक्त कर दिया था। इनमें से कुछ उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं पिय लोहा, कास्टिंग व फोर्जिंग, वैकल्पिक ऊर्जा के उपकरण व प्रणालियाँ, टनक्रीटिव कंड-युर्वे, मोटरगाडी के कन-युर्वे रसायन प्राप्ति, डबरी उद्योग-उपकरण, मशीनों औजार, बुद्ध इवाइयाँ, अलवणी काल्ड व पोर्टेबल मीसज पादि। बाद में दिसम्बर 1985 में इनमें से 22 उद्योगों के लिए MRTP व FERA कंपनियों को भी लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया गया। यह सरकार की उदार लाइसेंस नीति का सूचक है।

लिए मोल दिया गया थे ताकि देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ सके। बाद के वर्षों में साइमन्स नीति को बड़े घरानों के प्रति अधिक उदार बनाया गया है। लेकिन साथ ही नया व मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्ताओं को भी प्रोत्साहन देना जारी रखा गया है ताकि आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण न बढ़े। 1 मार्च 1985 में MRTPL कम्पनी के लिए परिसम्पत्ति की सीमा 20 करोड़ रु से बढ़ा कर 100 करोड़ रु कर दी गई इस प्रकार साइमन्स नीति बड़े औद्योगिक घरानों के प्रति भी कठोर व कभी नरम होती रही है। सब पूछा जाय तो भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने की दृष्टि से विस्तृत रही है।

2 सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विकास—भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के विकास के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करना रहा है। यह प्रदास किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभुतासम्पन्न स्थिति (commanding position) प्राप्त कर ले। 1951 में केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में (रेलो आदि को छोड़कर) 29 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ था, जो बढ़कर मार्च, 1988 में 71,299 करोड़ रुपये हो गया। जिस भीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होगा उस सीमा तक आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण निजी हाथों में कम होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि निजी क्षेत्र में भी बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्ति, प्रदत्त पूँजी तथा विप्री व मुताफे में दि की राजश्वों की तेजी से बढ़ रही है। इसलिए समस्या के समाधान की दृष्टि से यमी भी बहुत कुछ करना ज़रूरी है। भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास उपभोक्ता माल के उद्योगों तथा सहायक उद्योगों में करने की आवश्यकता है।

3 लघु उद्योगों का विकास—भारत में योजनाकाल में लघु इकाइयों का काफी विस्तार हुआ है और माचिस उद्योग में लघु उत्पादकों ने वेस्को (Western India Match Co) जैसी कम्पनियों का एकाधिकार कम किया है। इसी प्रकार में जूतियाँ, रेडियाँ, साबुन, सिलाई की मशीनें आदि में भी लघु उत्पादकों का महत्व बना है। लेकिन अभी तक लघु उद्योग कई समस्याओं से घिरे हुए हैं और इनको सफल बनाने की दिशा में काफी प्रयत्न करना होगा। पिछले वर्षों में अधिकांश लघु इकाइयाँ केवल कच्चे माल की खरीदने व बेचने के लिए बनायी गयी थीं जिससे उत्पादन इकाइयों के रूप में उनका विशेष योगदान नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीयकरण जैसी गम्भीर समस्या पर उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

4 सहकारी क्षेत्र में उद्योगों का विकास—सरकार ने चीनी उद्योग में सहकारी इकाइयों को आगे बढ़ाया है। यदि औद्योगिक उत्पादन से ग्रस्त क्षेत्रों में

व्यापक रूप से सहकारी इकाइयों को विकसित किया जाय तो समस्या के समाधान पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। इसने निए लघु उद्योगों का सहकारी ढंग पर संगठन करने की आवश्यकता है।

5 समुक्त क्षेत्र (Joint sector) का विकास—हाल के वर्षों में प्राधिक सत्ता का केन्द्रीयकरण कम करने की दृष्टि से समुक्त क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया है। डॉ एच के परान्जवे पूर्व सदस्य एकाधिकार आयोग का मत रहा है कि भारत में छोटी की बड़ी कंपनियों का एकाधिकारी घरानों से सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए उनको समुक्त क्षेत्र में परिवर्तित कर देना चाहिए। इसके लिए छोटी की कंपनियों को सार्वजनिक वित्तीय सहायता द्वारा दिये गये ऋणों को शयर पूँजी में बदल देना चाहिए जिससे इनके मालिक-मण्डलों में सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे और इनमें सरकार का प्रभाव बढ जायेगा। यह प्रश्न काफी विवादास्पद है इसलिए इस पर अगल अण्ड में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में निजी क्षेत्र में प्राधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण का कम करने की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण के विकल्प के रूप में समुक्त क्षेत्र के विकास पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास आदि पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा और उसकी समस्याएँ हल करने होंगी। MRTP अधिनियम व आयोग को प्रभावशाली बनाना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँचे में प्राधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने की ये दिशाएँ ही उपलब्ध हैं, अन्यथा नविष्य में बड़े औद्योगिक घरानों व छोटी की कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का मार्ग ही शेष रह जायगा।

अगस्त 1978 में मन्त्री अधिनियम व MRTP अधिनियम पर उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (राजिन्दर रावकर समिति) ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ललित जनता सरकार अपने आन्तरिक सचिवों व विरोधों में पसी रहने के कारण इसने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं ले सकी।

अब कांग्रेस (आई) सरकार के समक्ष भी निजी क्षेत्र में प्राधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को नियन्त्रित करने की समस्या विद्यमान है। इस समस्या का कोई सुगम हल नहीं प्रतीत होता। विभिन्न व्यक्तियों ने समस्या के समाधान के लिए कई प्रकार के सुझाव दिये हैं। सचचर समिति के सदस्य श्री के एन त्रिपाठी ने रिपोर्ट में अलग से जोड़े गये अपने नोट में कहा था कि व्यक्तिगत एकाधिकारी घरानों को परिसम्पत्तियों पर सीमा न लगाने के कारण इनमें वृद्धि का होना स्वाभाविक है।

जनता सरकार में तत्कालीन उद्योग मन्त्री जॉर्ज फर्नाण्डिस ने फरवरी 1979 में प्राधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए एक सुझाव यह दिया था कि उत्पात उद्योग में टिस्को, मोटर उद्योग में टेस्को तथा एल्यूमिनियम उद्योग में ट्रिण्डालको का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। इससे औद्योगिक क्षेत्र में पाप

जाने वाले एकाधिकार में अवश्य कमी आयेगी। इस सुभाव को भारतीय परिस्थिति में लागू करना कठिन जान पड़ता है क्योंकि राष्ट्रीयकरण के मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कम मुनाफों प्रथवा घाटे की दशाओं के साथ जाने के कारण इनके प्रति देश में विशेष उत्साह नहीं प्रतीत होता।

स्वर्गीय डी के रॉबिन्सन ने निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की समस्या को हल करने के लिए निम्न उपयोगी सुझाव दिये थे।¹

1. कर-प्रणाली का उपयोग किया जाय—साइगेंस-व्यवस्था एक नकारात्मक प्रवृत्ति है क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर रोक लगाती है। लेकिन इसको समाप्त करना भी कठिन है। अतः विनियोग की सही दिशा में ले जाने के लिए कर-प्रणाली का उपयोग करना उपादा लाभकारी होगा। जैसे वित्तासता की वस्तुओं के उपयोग पर प्रभावी कर लगाया जाना चाहिए। ऐसे कर से राजस्व की प्राप्ति होगी जिससे माय का पुनर्वितरण धनी से निर्धन वर्ग की ओर होगा तथा वित्तासता के भाल के निर्मात को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

2. पूँजी का विकिरण या छितराव (diffusion of capital) किया जाना चाहिए। इसके लिए उद्योगों में श्रम का स्वामित्व बढ़ाया जा सकता है। 1968 में फ्रांस में एक कानून द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से इयायी श्रमिकों को शेयर पूँजी में हिस्सा देने की व्यवस्था की गई थी और ऐसी कम्पनियों को वित्तीय छुट्टे भी दी गई थी। फ्रांस के लगभग एक चौथाई औद्योगिक श्रमिक अब शेयर-पूँजी व लाभ-सहभाजन स्कीमों में हिस्सा लेते हैं। फ्रांस का औद्योगिक परिसम्पत्ति का 15-20% अंश इस स्कीम के अन्तर्गत आ चुका है।

श्रमिक द्वारा पूँजी का स्वामित्व प्राप्त करने का आन्दोलन अब जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क व नार्वे में भी फैल गया है। भारत में इसमें भी बड़े प्रयोग की आवश्यकता है। इससे औद्योगिक सम्बन्धों में भी सुधार होगा।

भारत सरकार को इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करके निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने की कोई व्यापक, सुदृढ़ मुनिश्चित व समयव्यधित नीति व योजना घोषित करनी चाहिए। सरकार ने अब तक जो घोषणाएँ की हैं उससे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में कमी होने की सम्भावनाएँ नहीं लगती, क्योंकि MRTP अधिनियम की धारा 21 व धारा 22 से 27 उद्योगों को हटा दिया गया है एवं MRTP कम्पनी में परिसम्पत्ति में विनियोगों की सीमा 20 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. कर दी गई है जिससे इस सीमा

1. D K Rangneker, Growth of Big Business Houses, in Business Standard Annual 1982, pp.17-18.

से कम विनियोग करने वाली कम्पनियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इससे अनायास दिगम्बर 1985 में 27 में से 22 उद्योगों में MRTTP व FLRA कम्पनियों को लाउन्सेस लेने से भी मुक्त कर दिया गया है। सरकार की नई आर्थिक नीति निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की है। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने की दिशा में निवृत्त भविष्य में किसी विशेष प्रगति की सम्भावना नहीं प्रतीत होती।

संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector)

भारत में आर्थिक सत्ता को निजी हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के सम्बन्ध में 'संयुक्त क्षेत्र' को विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है। जैसे संयुक्त क्षेत्र का विचार कोई नया नहीं है। यह 1956 के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में धीज रूप में विद्यमान था जहाँ परोक्ष रूप में उद्योगों की तीनों श्रेणियों में मिश्रित उपक्रमों को आवश्यक स्थान दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंस-नीति जांच समिति (दत्त समिति) ने 1969 में निजी हाथों में आर्थिक शक्ति के बढ़ते हुए केन्द्रीयकरण का रोकने के लिए संयुक्त क्षेत्र के विचार को अपनाने पर बल दिया था। प्रमुख उद्योगपति जे आर डी, टाटा ने भारत सरकार को दिये गये औद्योगिक विकास पर अपने 'ममारेण्डम' में संयुक्त क्षेत्र के विचार का समर्थन किया था। अतः संयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

संयुक्त क्षेत्र का अर्थ

सांख्यिक अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्षेत्र का विचार बहुत सरल है। जब किसी उपक्रम (enterprise) में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का एक साथ योगदान पाया जाता है तो उसे संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम कहते हैं। भारत में संयुक्त क्षेत्र की जिस अर्थ में चर्चा पायी गयी है उसमें प्रायः यह मान्यता रही है कि इसमें प्रबन्धता निजी हाथों में रहेगी और पूँजी सरकार द्वारा उपलब्ध की जायेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूँजी में निजी क्षेत्र भाग नहीं लेगा और प्रबन्ध में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। पूँजी व प्रबन्ध में निजी या सरकारी दोनों क्षेत्रों का मिश्रित योगदान रहेगा। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रबन्ध-पट्टा का उपयोग करने की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है और पूँजीगत साधन विशेषण या सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान किये गये हैं। अतः संयुक्त क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सहसंस्थित्य पाया जाता है। जैसे यदि किसी एक राज्य की सार्वजनिक इकाई किसी दूसरे राज्य की सार्वजनिक इकाई को किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना में सहयोग दे तो उसे भी संयुक्त क्षेत्र की इकाई माना जा सकता है। इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र की स्थापना व संचालन के पीछे मूल भावना दो प्रकार के मण्डलों व इकाइयों के परस्पर मेल-जोल की होती है। लेकिन विशेषतया सार्वजनिक पूँजी व निजी प्रबन्ध के संगम से ही संयुक्त क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है।

भारत में मयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों के निम्न रूप प्रस्तावित किये गये हैं :

1 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित छोटी की कम्पनियों की समुक्त क्षेत्र में परिवर्तित कर देना चाहिए। इनके लिए सार्वजनिक वित्तीय सम्पार्थों द्वारा दिए गये ऋण का भय-रक्षि में बदल देना चाहिए ताकि निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभाव बढ सके।

2 केन्द्रीय सरकार ऐसी नई कम्पनियों की स्थापना करे जिसमें पूँजी व प्रबन्ध में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की साझेदारी हो।

3 स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की समुक्त क्षेत्र की कम्पनियों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की भय-रक्षि पूँजी निजी क्षेत्र के लिए खोली जा सकती है। इसका अनुभव भी टाटा के स्मरण-पत्र में दिया गया था।

4, राज्य सरकारें लाइसेंस की व्यवस्था करके अपने प्रदेशों में औद्योगिक विकास नियमों के माध्यम से नयी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की योजना बनाती है और उनमें भाग लेने के लिए निजी उद्यमकर्तारों को आमन्त्रित किया जाता है। इस व्यवस्था में निजी उद्यमकर्तारों को विशेष प्राप्ति हो सकता है क्योंकि उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लक्ष्य से मुक्ति मिल जाती है और उनके लिए सरकार वित्तीय साधन भी जुटाती है। निजी क्षेत्र पूँजी व प्रबन्ध में भागीदार बनाया जाता है।

5, जैसा कि पहले संकेत किया गया था, भारत में एक राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई दूसरे राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से हस्तान्तर जो औद्योगिक इकाई स्थापित करती है उसे जो समुक्त क्षेत्र की इकाई कहा जा सकता है। हालाँकि यह भ्रमनवा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ही होती है।

भारत में मयुक्त क्षेत्र के विकास के लक्ष्य में निम्नलिखित उपरोक्त श्रेणियों में से श्रेणी (1), (2) तथा (4) का ही विशेष महत्व माना जायेगा। श्रेणी (3) के सम्बन्ध में काफी विवाद है और श्रेणी (5) मयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र की ही इकाई है।

समुक्त क्षेत्र के उद्देश्य व सम्भावित मान :

भारत में निम्न कारणों से समुक्त क्षेत्र की औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में, इससे निम्न लाभ मिलने की आशा है।

1 बड़ी कम्पनियों पर निश्चित अवधि में नियन्त्रण—राष्ट्रीयकरण का फटोर कदम उठाते बिना उद्योगों पर सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करने का यह एक व्यावहारिक व सुगम मार्ग है। जब बड़ी कम्पनियाँ समुक्त क्षेत्र में आ जायेंगी तो वे अपनी उत्पादन नीति की राष्ट्रीय हितों में जोड़ सकेंगी। इस प्रक्रिया में सरकार को मुभावना नहीं देना पड़ेगा जो राष्ट्रीयकरण करने पर देना पड़ता।

को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा यह एक सर्वानामक द्वारा प्रयत्न बढ़ावा देने वाले उपकरण (Promotional instrument) के रूप में अपनाया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारें नये व मध्यम उद्यमकर्ताओं के साथ मिलकर प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के विस्तार में उनका मार्गदर्शन करेंगी।

2 सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जिन उद्योगों में बड़े धरानों, प्रमुख-सम्बन्धित उद्यमों तथा विदेशी कम्पनियों का प्रवेश बना है उनमें उन्हें समुक्त क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

3 समुक्त क्षेत्र की प्रकाशनों के प्रमुख रूपों में सरकार स्वयं नोटि-निर्धारण, प्रमुख-सम्बन्धित व मजानन सम्बन्धी मामलों में प्रभावपूर्ण रूप से भाग लेंगी। इनका वैधानिक रूप प्रत्येक मामले के अनुसार तय किया जाएगा।

इस प्रकार समुक्त क्षेत्र में सरकार अपना प्रभावपूर्ण स्थान रखना चाहती है।

उपसृत विवरण में स्पष्ट होना है कि सरकार देश में समुक्त क्षेत्र का विकास करना चाहती है और उसमें अपनी भूमिका सबसे ऊँची रखना चाहती है। प्रश्न यह है कि समुक्त क्षेत्र में पूर्णता में विकास हिम्मा कितना हो और इसी प्रकार प्रमुख में विकास हिम्मा कितना हो? इस सम्बन्ध में एकाधिकार प्रायोग के पूर्व महसूस की जाये, के पराजने के विचार इस प्रकार है।

औ पराजने के समुक्त क्षेत्र पर विचार

1. बड़े औद्योगिक धरानों की शोटी की कम्पनियों से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए उन्हें समुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। इसके लिए तांत्रिक वित्तीय संस्थाओं की ऋण-राशि की शेष-राशि में परिवर्तित कर देना चाहिए। समुक्त क्षेत्र के उद्यम में 49% शेष-पूर्णता निजी शक्तों में होनी तथा 51% शेष-पूर्णता सरकार के हाथों में होनी ताकि वह अधिक प्रभाव डाल सके। इस प्रकार बड़े औद्योगिक धरानों तथा शोटी की कम्पनियों के बीच पाये जाते वाले अनावश्यक व अकार्यक्षम सम्बन्ध (dysfunctional inter-connections) समाप्त किये जा सकेंगे।

2. पराजने का मत है कि इसके लिए MRTP अधिनियम की धारा 27 का उपयोग किया जा सकता है जिसमें औद्योगिक उपकरणों के विभाजन की व्यवस्था है। इसके लिए टिप्पणी, टिप्पणी, हिन्दुस्तान मोटर्स, हिन्दुस्तान तथा इण्डियन जैनी वनी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी।¹

1 TISCO = Tata Iron & Steel Co. Ltd

TELCO = Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd

HINDALCO Hindustan Aluminium Co, Ltd.

INDALCO = Indian Aluminium Co. Ltd.

2. बड़ी कंपनियों के संयुक्त क्षेत्र से आ जाने के उनका तन्त्रिकीय व आर्थिक आधारों पर विस्तार किया जा सकता है जो आज तक सम्भव नहीं हो पाया है। इससे बड़े पैमाने की किराये पर प्राप्त की जा सकती है जिनसे प्रति इकाई लागत व कीमत कम की जा सकती है।

3. प्रबन्ध का व्यावसायीकरण किया जा सकता है जिससे इनके सामने प्रबन्ध की समस्या नहीं रहेगी। जब पारिवारिक प्रबन्ध से व्यावसायिक प्रबन्ध की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है।

4. प्रारम्भ में उन सभी उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र में बदलने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें सार्वजनिक वित्तीय सहायता से चलाने की सुविधा मिली है। केवल छोटी की कंपनियों को ही संयुक्त क्षेत्र में लिया जाना चाहिए। कालांतर में जब मध्यम श्रेणी की कंपनियाँ बड़ी श्रेणी की कंपनियाँ हो जाएँ, तब उन्हें भी आवश्यकतानुसार संयुक्त क्षेत्र में लाया जा सकता है।

23 जुलाई, 1980 को प्रस्तुत किये गये नये औद्योगिक नीति दस्तावेज में 'संयुक्त क्षेत्र' का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार सम्भवतः निजी क्षेत्रों में आर्थिक सहायता के केन्द्रीकरण को कम करने की दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं समझती है।

भारत में संयुक्त क्षेत्र बाकी विचार-विमर्शों का विषय रहा है। कुछ व्यक्ति इसे निरर्थक मानते हैं और वे सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाने पर ही बल देते हैं। कुछ भी हो, भारत में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक समूहों का सह-अस्तित्व रहा है और भविष्य में भी रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक हिस्से का औद्योगिक समूह विकास में अपनी वांछित भूमिका निभा सके और देश में उत्पादन बढ़ाने तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहयोग प्रदान कर सके।

भारत में पिछले वर्षों में संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक विकास किया गया है। 1984-85 में संयुक्त क्षेत्र में देश की कुल फॅक्ट्रियों का 1.9% स्थिर पूँजी का 8.2% तथा विद्युत् जोड़े गये मूल्य (net Value-added) का 10.2% भंश पाया गया था।¹ संयुक्त क्षेत्र की भी दो धारणाएँ की गई हैं : एक संयुक्त क्षेत्र-सार्वजनिक (Joint Sector-public) तथा दूसरा संयुक्त क्षेत्र निजी (Joint Sector-private)। प्रथम श्रेणी की फॅक्ट्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। स्थिर पूँजी, बर्खास्तियों व विद्युत् जोड़े गये मूल्य में भी 'संयुक्त क्षेत्र-सार्वजनिक' का स्थान ऊँचा पाया गया है। "संयुक्त-क्षेत्र-सार्वजनिक" वाले उपक्रम में पूँजीगत साधनों में सार्वजनिक संस्थाओं का विशेष स्थान होता है, जबकि "संयुक्त क्षेत्र-निजी" वाले उपक्रमों में निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है।

1. Annual Survey of Industries 1984-85, (C. S. O.) Summary Results For Factory Sector, 1988, p. 22.

(अ) भारतीय रेलें¹

1987-88 में भारतीय रेल-व्यवस्था लगभग 61976 किलोमीटर लम्बी थी जबकि 1985-86 में यह 91 836 किलोमीटर थी जो एशिया में सबसे बड़ी और विश्व में राज्य के स्वामित्व वाली रेल-व्यवस्था में द्वितीय स्थान पर आती है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम माना जाता है। 1985-86 में रेलों में कर्मचारियों की संख्या 1 33 लाख थी जिनमें 16.13 लाख नियमित कर्मचारी थे तथा 2.2 लाख आनम्बिड थे। 1989-90 के बजट अनुमानों के अनुसार रेलों में पूँजी (Capital at-Charge) की राशि 14518 करोड़ रु. आती गयी है।

रेलों की लम्बाई 1950-51 में 53,596 किलोमीटर से बढ़कर 1987-88 में 61976 किलोमीटर हो गई है। इसमें 55% ब्रॉडगेज, 39% मीटरगेज व 6% सखरी गेज (narrow gauge) के घनत्व आती हैं। इस प्रकार 37 वर्षों में 8380 किलोमीटर अथवा लगभग 15.6% की वृद्धि को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि रेलों का विकास जाल अर्थों ने दिखा दिया था और बाद में उसी में पर अधिक भाल डोया गया तथा अधिक यात्री से जाये गये हैं। यह तर्क कुछ सीमा तक सही प्रतीत होता है। रेलों ने 1950-51 में 9.3 करोड़ टन माल डोया था जो 1988-89 में बढ़कर 33.2 करोड़ टन तक पहुँच गया। 1989-90 के लिए 34.5 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है।

1985-86 के घनत्व में 38,184 सवारी गाड़ी के हिस्से, 9,920 इंजन तथा 3,59,614 वैन थे। भारतीय रेलवे का रोजाना स्टॉक योजनाफल में काफी बढ़ाया गया है। प्रतिदिन रेलें 7,092 स्टेशनों के बीच आती जाती हैं।

आज भी देश में राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्रप्रदेश के विस्तृत भू-भागों में रेलों का वडा अभाव है और इसी वजह से उनमें आर्थिक विकास भी बना हुआ है। इसके अलावा भारत के रेल-मानचित्र पर भी गेज, मीटर गेज व सखरी गेज का एक ऐसा अनुपयुक्त व अमनुचित किस्म का जाल बिछा हुआ है कि कई स्थानों पर भाल की दुसई का व्यव बहुत ऊँचा आता है और अन्य अनुविधानें भी होती हैं।

रेलों का पुनर्गठन (Regrouping of Railways)—मार्च 1949 से पूर्व भारत में 37 रेल-प्रणालियाँ थी जिनमें प्रशासन में भिन्न-भिन्नता व कार्यकुशलता की दृष्टि से भी अनेक विभाजित किया गया था।

1 India 1987 Chapter 22, The Economic Times, April 20, 1989 and The Railway Budget for 1989-90

1985-86 में इन नौ क्षेत्रों में रेल-मार्ग की सम्बाई इस प्रकार थी¹

क्षेत्र	प्रधान कार्यालय	मार्ग की सम्बाई (किलोमीटर म)
1 केन्द्रीय	बम्बई	6 486
2 पूर्वी	कलकत्ता	4,281
3 उत्तरी	नई दिल्ली	10 977
4 उत्तरी-पूर्वी	गोरखपुर	5 163
5 उत्तरी पूर्वी सीमान्त	मालीगाँव (गुवाहाटी)	1 761
6 दक्षिणी	मद्रास	6 729
7 दक्षिणी-केन्द्रीय	सिकन्दराबाद	7,138
8 दक्षिणी पूर्वी	कलकत्ता	7 075
9 पश्चिमी	बम्बई-पर्थ गेट	10,224
कुल		61,836

तालिका से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा सम्बाई उत्तरी रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे की है जिसमें से प्रत्येक 10 हजार किलोमीटर से अधिक है। पुनर्वर्गीकरण से रेल-सेवा में सुधार हुआ है और व्यय में कमी हुई है लेकिन रेल दुर्घटनाएँ होने से चिन्ताएँ बढ़ गई हैं। कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि पुनर्वर्गीकरण के बाद बड़ी इकाइयाँ बनने से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आयी है। वस्तु-स्थिति यह है कि हमें रेलों के प्रबन्ध व इनकी क्षमता में आवश्यक सुधार करने के प्रयत्न जारी रखने हैं और क्षेत्रीय व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को स्वीकार करना है।

पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों की प्रगति

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यकुशल रेल परिवहन व्यवस्था का विकास करने के साथ साथ एक विशेष उद्देश्य भी रखा गया है। प्रथम योजना की अवधि में यह उद्देश्य पुरानी रेल परिसम्पत्ति को बदलना व इनका पुनर्स्थापन करना था। द्वितीय योजना में रेलों को नये इस्पात कारखानों व कोयले के अधिक उत्पादन से उत्पन्न स्थिति के लिए तैयार करने का उद्देश्य रखा गया था। तृतीय

योजना में अतिरिक्त क्षमता (additional capacity) के निर्माण पर ध्यान दिया गया ताकि वह ट्रैफिक-माँग से आगे जा सके और प्राथमिक विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आये। चतुर्थ योजना में रेलों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इनके आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। पाँचवी योजना में वर्तमान रेल-मार्ग व रोलिंग स्टॉक की क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग करने पर बल दिया गया ताकि रेलों की कार्यक्षमता को सुधारा जा सके। ऐसा महसूस किया गया था कि वर्तमान क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग करके तथा रेल-मार्ग का आधुनिकीकरण करके वस्तुओं व व्यक्तियों के लाने-से जाने की ट्रैफिक सम्बन्धी माँग को अधिक मात्रा में पूरा करना सम्भव हो सकेगा।

पञ्चवर्षीय योजनाओं में रेलों के विकास पर व्यय की स्थिति नीचे दी जाती है :

		(करोड़ ₹)
प्रथम योजना	..	422
द्वितीय योजना	..	1044
तृतीय योजना	1686
चतुर्थ योजना	..	1420
पंचम योजना		1492
छठी योजना	6300
सातवी योजना (प्रस्तावित)	*	12334

इस प्रकार छठी योजना की अवधि में रेलों के विकास पर सर्वाधिक राशि व्यय की गई। जैसा कि पहले कहा जा चुका है। 1950-51 से 1987-88 तक 8380 किलोमीटर में अतिरिक्त नई लाइन बिछाने से रेलों का जाल 61976 किलोमीटर में फैल गया है जिसमें से 8155 किलोमीटर दूरी में बिद्युतीकरण (electrification) किया जा चुका है, जबकि 1950-51 में यह 388 किलोमीटर में ही था।

भारतीय रेलों ने उपकरण व स्टोर्स के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करली है। 1950-51 में भारतीय रेलें इनका 23% आयात करती थी जो घटकर 1985-86 में 8.3% पर आ गया है। नियोजित विकास के फलस्वरूप यात्री-ट्रैफिक व माल-ट्रैफिक काफी बढ़ा है। योजनाकाल में डीजल इंजनों की संख्या 1951 में 17 से बढ़कर 1985-86 में 3,047 (179 गुनी) हो गई है। विद्युत इंजनों की संख्या 18 गुनी से अधिक हो गई है। रेलों द्वारा इस्पात, कोयला, बच्चा लोहा, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोल-पदार्थ, अन्य वस्तुएँ व रेलवे की वस्तुएँ बोयी जाती हैं।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है भारतीय रेलों में विद्युतीकरण की प्रगति इस प्रकार रही :

वर्ष	विद्युतीकृत मार्ग (किलोमीटर)
1950-51	388
1987-88	8155 (कुल का 13.2%)

रेलों में विद्युतीकरण की अधिक प्रगति तृतीय योजना की अवधि में हुई थी। मविध्य में रेलों पर यात्री-ट्रैफिक व माल-ट्रैफिक में अत्यधिक वृद्धि हो गयी जिससे इन पर कार्य-भार बढ़ेगा। अतः रेलों के विकास पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, (1985-90) में रेलों के विकास के लक्ष्य—रेलों के विकास के लिए सातवीं योजना में 12334 करोड़ रु की राशि का प्रावधान किया गया है। विकास-कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं

(1) योजनावधि में 96 हजार नैगन (4 व्हीलर के रूप में) 6970 सवारी गाड़ी के डिब्बे 950 विद्युत म-टीपल इकाइयाँ (EMU) तथा 1235 डीजल व विद्युत के इंजन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। (2) मार्ग-नवीनीकरण (track renewals) के लिए 19 हजार से 21 हजार किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। (3) 3400 किलोमीटर में विद्युतीकरण का कार्यक्रम रखा गया है एवं (4) सवारी गाड़ी के डिब्बों, EMUs व विद्युत इंजनों के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जायगी। सवार के नेटवर्क को उन्नत किया जायगा एवं कम्प्यूटर-प्राधारित माल डोने की सूचना-प्रणाली को लागू किया जायगा।

रेल-विकास में सम्बन्धित अथ आवश्यक लक्ष्य

(1) रोलिंग स्टॉक का उत्पादन—भारत में रेलों का सामान विभिन्न कैबिनेटों में उत्पन्न किया जाता है और देश रेल उपकरण में न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि निर्यात करने की स्थिति में भी आ गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1950-51 में आयात किये गये उपकरणों व कल-भुजों पर हमारी निर्भरता लगभग 23% थी जो घटकर 1985-86 में 8.3% रह गयी है। अब सम्पूर्ण डिजाइन व निर्माण का काम भारत में ही होन लगा है।

रेल-मंत्रालय ने इंजन व डिब्बे बनाने के लिए तीन इकाइयाँ स्थापित की हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है¹

1 चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW)—इसने 1950 से उत्पादन चालू कर दिया था और दिसम्बर 1971 के अन्त तक 2351 स्टीम इंजन तैयार कर दिये थे।

उसके बाद इनका उत्पादन बन्द कर दिया गया। 1961-62 से यह विद्युत इंजन बना रहा है। 31 मार्च, 1986 तक इसने 1082 विद्युत इंजन, 512 डीजल-हाइड्रालिक पण्टर्स व 68 सकरी गेज के डीजल-हाइड्रालिक इंजन बनाये थे। इनमें घरेलू सामान का तत्व काफी ऊँचा हो गया है।

2 डीजल लोकोमोटिव चवर्स, (DLW) बाराखसी—यह 1964 में स्थापित किया गया था। प्रथम इंजन उसी वर्ष प्रारम्भ कर दिया गया था। मार्च 1986 के अन्त तक इसने विभिन्न प्रकार के 2089 इंजन तैयार कर दिये थे। इनमें भी घरेलू तत्व का धरा काफी ऊँचा है।

3 इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री, (ICF) चेन्नै—इसने 1955-56 में उत्पादन शुरू किया था। यहाँ कई प्रकार की सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाये जाते हैं। 31 मार्च 1986 तक इसने 16637 सवारी गाड़ी के डिब्बे (पूरी तरह फिनिश किये हुए) तैयार किये थे।

इनके अलावा भारत अर्ध-मूवर्स लि बंगलूर तथा जेसप एण्ड क. लि, कलकत्ता ने भी सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाये हैं। बंगन बनाने का काम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। तीन रेलवे की मरम्मत सम्बन्धी वर्क शापो में भी बंगनो का उत्पादन किया जाता है। 1985-86 में 12,651 बंगन चार व्हीलर इकाई बनाए गए थे जिनमें से 12,097 बंगन उद्योग के द्वारा निर्मित किये गए थे। इन सभी उत्पादन-इकाइयों में अधिक माल तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) सरकार ने रेल-कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं तथा रेल-दुर्घटनाएँ रोकने के लिए स्टॉफ बढ़ाया है।

(3) लम्बे मार्ग वाली रेलगाड़ियाँ चलायी गई हैं जिनमें "गोताजलि" मुख्य है जो कलकत्ता व बम्बई के बीच नवम्बर, 1977 से चलने लगी है। इनमें ग्राम जनता की सुख-सुविधाओं को बढ़ाया गया है। यह विभिन्न ऊँचे व नीचे दर्जों की गार्ड को कम करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। ऊँची रफ्तार की रेल गाड़ियाँ भी बढ़ायी गयी हैं। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियाँ दिल्ली-हावड़ा तथा दिल्ली-बम्बई के बीच क्रमशः 130 व 120 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती हैं।

(4) भारतीय रेलों में ऊँचे स्तर की दक्षता का विकास किया गया है और हम दूसरे देशों की निर्माण व अन्य कार्यों में सलाह देने की स्थिति में आ गये हैं।

(5) 1984-85 में भारतीय रेलवे मेट्रो-युग (Metro-Age) में प्रवेश कर गयी है। कलकत्ते में एस्पलेनेड (Esplanade) व भोवनीपुर तथा दमदम व बेन्गलिया (Belgachia) के बीच भूमिगत रेलगाड़ियाँ चलने लगी हैं।

इस सम्बन्ध से रेल इण्डिया-टेक्निक्स एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज (RITES) तथा इण्डियन रेल्वेज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (IRCON) के नामों का उल्लेख करना आवश्यक है। ये मगठन भारतीय दक्षता व सेवा का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ वैंगन, सवारी गाड़ी के डिब्बे व अन्य वस्तुओं के निर्यात को भी प्रोत्साहित करते हैं।

इस प्रकार योजनामाल में रेलों ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है जिसे भविष्य में जारी रखना होगा।

भारत में रेलों को निरन्तर घाटा रहने के कारण

भारत में हाल के वर्षों में रेलों की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव पड़ा है। 1979-80 व 1980-81 में रेलों को घाटा रहा। इससे पूर्व 1964-65 से 1975-76 तक भी कई वर्षों में रेलों को घाटा रहा था। 1981-82 व 1982-83 में थोड़ी बचत की स्थिति रही। लेकिन 1983-84 में पुन 45 करोड़ रु का घाटा रहा। 1984-85 में भी लगभग 196 करोड़ रु. का घाटा रहा। 1985-86 से रेलवे बजट में बचत रही है। 1988-89 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 28 करोड़ रु. की बचत रही है तथा 1989-90 के बजट-अनुमानों में 140 करोड़ रु की बचत दिखायी गयी है। इस बजट में माल भाड़े में 11% से 18% की वृद्धि से 876 करोड़ रु के शुद्ध अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है।

लेकिन प्रश्न उठता है कि भूतकाल में भारतीय रेलों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब क्यों रही? रेलें राष्ट्र की अत्यन्त महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति मानी जाती हैं और इनकी वित्तीय स्थिति का नाजुक होना भारी चिन्ता का विषय है। भूतकाल में रेलों को निरन्तर घाटा रहने के निम्न कारण रहे हैं—

1. सामान की चोरी—रेल-सेवाएँ कई बारणों से अस्त-व्यस्त रहने लगी हैं। ऊपरी मार्ग से तारों की चोरी, टेलि-कम्यूनिकेशन केबल व सामान की चोरी, गाड़ियों व स्टाफ पर हमले, वैंगनों व माल वाहनों की संयुक्त लूट-पाट, वैंगन-फिटिंग्स व मार्ग-फिटिंग्स की बड़े पैमाने पर चोरी होती रही है। इन चोरियों के कारण रेलों से माल की दुलाई में काफी बाधा पड़ी है जिससे आर्थिक हानि का होना स्वाभाविक है।

2. अलामद शाखाएँ—अलामप्रद शाखाओं पर प्रतिवर्ष घाटा होता रहा है। यात्री-ट्रैफिक पर करोड़ों रुपये का घाटा होता रहा है। प्रतिदिन काफी रेल गाड़ियाँ लाखों यात्रियों को लाती-लेजाती हैं। लेकिन भूतकाल में इससे प्राप्त आम-दनी कुल व्यय से कम रही है। यात्री-भाड़ा भी लागत से कम रहा है। उप-नगरीय रेलों में कम किरायों के कारण काफी घाटा होता है।

3. भारी माल की दुलाई में अधिक व्यय—भारी माल जैसे कोयला, खनिज पदार्थ, पत्थर, सीमेंट, खाद, अनाज व नमक की दुलाई में शायद कम व लागत अधिक

प्राप्ती है। खाद्यान्नों व दालों एवं कोयले की दुर्लभता में काफी घाटा रहता है। एवं चारा खल, सनिज पदार्थ, आदि की दुर्लभता में भी घाटा होता है। कहने का आशय यह है कि रेलों की आम कम व व्यय ज्यादा रहता है।

4. संचालन-लागत में वृद्धि—रेलों की संचालन लागत (cost of operation) बढ़ रही है। पिछले वर्षों में स्टॉफ पर व्यय बढ़ गया है। कोयले, विजली व डीजल तेल के भाव बढ़ गये हैं। इस प्रकार संचालन-लागत में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, यात्र-माइरा व माल-किराया अपेक्षाकृत कम बढ़ा है। इस प्रकार लागत-वृद्धि पूरी तरह नहीं निकल पायी है। 1988-89 के सशोधित अनुमानों के अनुसार संचालन-अनुपात (operating ratio) अर्थात् कुल कार्यशील व्यय सकल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 93% रहा जिसके 1989-90 के बजट-अनुमानों में 92.01% रहने का अनुमान है।

5. वेतन-वृद्धि—रेल कर्मचारियों के वेतन व महंगाई भत्ते में वृद्धि करने से रेलों पर वित्तीय भार काफी बढ़ गया है। मुद्रास्फीति के कारण सभी सार्वजनिक उपक्रमों में वेतन-वृद्धि ऊँचा होता जाता है जिससे उनको घाटा होने लगता है।

6. कर्मचारियों के सहयोग में कमी—स्टॉफ-ग्रान्दोलन घीमा बाम व हड़ताल आदि के कारण भी रेलों में वित्तीय संचालन-लक्ष्यों पर प्रतिबल प्रभाव पड़ा है।

7. ऊर्जा-संकट (Energy Crisis)—ऊर्जा-संकट ने भविष्य के लिए हाईस्पीड डीजल (HSD) आदि के सम्बन्ध में नई समस्याएँ लड़ी कर दी हैं।

अतः राष्ट्र के इस प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम को सुधरे-स्थिर करने हेतु इसे लाभ की स्थिति में बनाये रखने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए लोको-कर्मचारियों का सहयोग बहुत आवश्यक है। सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भारतीय रेल-व्यवस्था एक शताब्दी से भी अधिक पुरानी हो चुकी है। पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलने व वर्तमान लाइनों को सुधारने की आवश्यकता नई साठवें विधान से भी ज्यादा प्रतीत होती है।

रेल-वित्त¹

1988-89 के सशोधित अनुमानों के अनुसार सकल ट्रेफिक-प्राप्ति 9376 करोड़ रु व कुल व्यय 8725 करोड़ रु. रहा जिससे शुद्ध ट्रेफिक-प्राप्ति 651 करोड़ रु रही। 1989-90 के बजट-अनुमानों में ये राशियाँ क्रमशः 10633 करोड़ रु व 9788 करोड़ रु रखी गई हैं जिससे शुद्ध ट्रेफिक-प्राप्ति 845 करोड़ रु.

1. Railway Budget, 1989-90. The Economic Times, February 24, 1989 p. 1.

पर आ गयी है। रेलों को सामान्य राजस्व खाते में सामाजिक की राशि देनी होती है जो 1989-90 के बजट में 805 करोड़ रु. रखी गयी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है अन्य प्राप्ति को वा समायोजन (adjust) करने पर 1988-89 के संशोधित अनुमानों के अनुसार रेलों को 28 करोड़ रु. की बचत रहेगी। 1989-90 के बजट-अनुमानों के अनुसार यह 140 करोड़ रु. रखी गयी है। 1989-90 के रेल-बजट में माल-मांडों में वृद्धि की गयी है। इस प्रकार रेल-बजट में उचित वृद्धि मिली है।

रेलों पर कार्य-भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इनमें मुख्य-क्षेत्रों में पेयजल पहुँचाना होता है। रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ी बोनस दी जाती है। हार्ड स्पीड डीजल (HSD) के भाव बढ़ गये हैं। इसलिए बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिए अधिक वित्तीय साधन जुटाने आवश्यक हो गए हैं। भविष्य में रेल-सेवा की कार्यकुशलता में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है।

सरकार ने भारतीय रेल वित्त निगम (Indian Railway Finance Corporation) (IRFC) की स्थापना की है जो बाजार में बाढ़ बेचकर धनराशि जुटाये है। इससे रेलों को विकास के लिए वित्तीय साधन प्राप्त हुए हैं।

(आ) भारत में सड़क-परिवहन

भारत में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से सड़कों का विशेष महत्व माना गया है। देश में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भी सड़क-विकास बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। भारत में सड़कों के विकास की विशेष जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर रही है।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं व तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि कुल (1951-69) में सड़क विनास पर 1104 करोड़ रु. व्यय किये गये। चतुर्थ योजना में व्यय की राशि 862 करोड़ रु. व पंचम योजना में 1353 करोड़ रु. रही। छठी योजना में सड़कों के विनास पर 3439 करोड़ रु. व्यय हुए।¹ सातवीं योजना में सड़कों के विनास के लिए कुल 5200 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 1020 करोड़ रु. रखे गये हैं।

योजनाकाल में सड़कों का विकास

सड़कों की कई श्रेणियाँ होती हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग (national highways), राज्यीय सड़कें, जिलों, गाँवों, नगरों व प्रोजेक्टों की सड़कें। योजनाकाल में इनकी कुल लम्बाई 1950-51 में 4 लाख किलोमीटर से बढ़कर 1984-85 में लगभग 17.7 लाख किलोमीटर हो गई है। इस प्रकार वार्षिक वृद्धि की दर 4.5 प्रतिशत रही है।

1. India 1987, pp 535-536.

भारत में सड़कों की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है। यही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों में भी सड़कों का विकास काफी असमान रूप में हुआ है। 1985-86 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल सम्बाई 31,987 किलोमीटर है जिसके द्वारा कुल सड़क-वर्क का 1/3 भाग दिया जाता है। ग्रामीण सड़कों का जाल 64% गांवों को परस्पर जोड़ता है, हालांकि इनमें सभी मौसम वाली सड़कें कम हैं। देश में आज भी 36% गांवों में किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं हैं तथा 65% गांवों में सभी मौसम वाली (all weather) सड़कें नहीं हैं।

सातवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए 1020 करोड़ रु तथा राज्यों व संघीय प्रदेशों के लिए 4180 करोड़ रु रत गये हैं। सड़कों के विकास के सम्बन्ध में निम्न उद्देश्य रखे गये हैं :—

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग व जिला सड़कों के स्तर को ऊँचा करना; (ii) गांवों में सड़कों का विकास करके 1990 तक ग्युप्ततम प्रावश्यकता कार्यक्रम (MNP) के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि 1990 तक 1500 व अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों का ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया जायगा तथा 1000-1500 के बीच जनसंख्या वाले 50% गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा। सातवीं योजना में MNP के अन्तर्गत सड़कों के विकास हेतु 1729 करोड़ रु रखे गये हैं, (iii) ऊर्जा-संरक्षण पर बल दिया जायगा, (iv) सड़कों की पर्यावरण गुणवत्ता को बनाये रखा जायगा एवं उसे बढ़ाया जायगा, (v) सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जायगी, (vi) सड़क परिवहन की उत्पादकता में सुधार करने के लिए सड़कों को ठीक किया जायगा, (vii) भीड़नाड वाले क्षेत्रों में नयी सड़कों का विकास हाथ में लिया जायगा एवं (viii) सड़क निर्माण के जरिए रोजगार में वृद्धि की जायगी। इसके लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व बंसाड क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, आदि का अर्थिक सफल बनाया जायगा।

सड़क-विकास की प्रमुख समस्याएँ

सड़क विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विकास का दृष्टिकोण सड़कों का विस्तार करने का था, न कि इनकी गहन करने का। विस्तार दृष्टिकोण के अनुसार सड़कों की नये क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास किया जाता है, जबकि गहन दृष्टिकोण में प्रचलित सड़कों के क्षेत्रों में ही अधिक विकास किया जाता है। पिछले वर्षों में गहन दृष्टिकोण अपनाने के कारण निम्न समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं

1. बड़े औद्योगिक स्तनिक-सम्बन्धी व अन्य विकास-परियोजनाओं से सम्बन्धित सड़कों की व्यवस्था—नया सिंचाई व जल-विद्युत परियोजनाओं के समीप सड़कों का तभी से विकास होने से ही उनकी प्राथमिक सम्भावनाओं का पूरा-पूरा

उपयोग हो सकता है। इस सम्बन्ध में दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

2. ग्रामीण सड़कें—यावतें तक रासायनिक खाद, औजार व अन्य साज-सामान पहुँचाने के लिए ग्रामीण सड़कों का गहन विकास किया जाना चाहिए। अभी तक इस दिशा में प्रगति सन्तोषजनक नहीं हुई है। नूतकाल में ग्रामीण सड़कों का काम स्थानीय ग्राम-समुदायों पर छोड़ दिया गया था जिससे इनकी प्रगति में बाधा पहुँची है। प्रत्येक राज्य में जिलेवार ग्रामीण सड़कों के विकास की योजना बनायी जानी चाहिए। गहन कृषि-विकास के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। राज्यों की योजना में सड़कों पर किये जाने वाले व्यय का कम से कम पाचवीं हिस्सा ग्रामीण सड़कों पर रखना चाहिए।

3. पिछड़े हुए व पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सड़कें—इसके लिए भी केन्द्र की ओर से राज्यों की अनुदान मिलना चाहिए। सड़कों का विकास ऐसे क्षेत्रों के लिए वरदान निश्च होना।

4. बड़े नगरों में सड़कें—कलकत्ता व बम्बई जैसे शहरों में सड़कों की समस्या न विकट रूप धारण कर रहा है। मद्रास, दिल्ली, कानपुर आदि नगरों में भी स्थिति पर सीधे ही ध्यान दिया जाना चाहिए। इनमें सड़कों के निर्माण की दीर्घकालीन योजना बनायी जानी चाहिए जिससे सड़कें बढ़ते हुए भार को वहन करने में समर्थ हों सकें।

मविध्य में सड़क विकास की योजना का औद्योगिक व आर्थिक विकास से अधिक ताल-मेल बँठाना चाहिए। राष्ट्रीय, राज्याय व स्थानीय स्तरों पर सड़क-विकास की समन्वित योजना बनायी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा सड़क-नियोजन-बोर्ड स्थापित किये जाने चाहिए। ये बोर्ड उच्च स्तरीय प्राविधिक सलाहकार संस्थाओं का काम करेंगे और ट्रंकिंग सर्वे, लागत-लान-प्रचयन, निर्माण-लागतों में किराये, सड़क-विकास से अधिकतम लान प्राप्त करने, पिछड़े हुए क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने, ग्रामीण सड़कें बनाने और बड़े नगरों में सड़कों का विकास करने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। आगामी वर्षों में सड़कों के विकास पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में सड़क परिवहन¹ (Road Transport in India)

सड़क परिवहन का छोटी व मध्य दूरी के परिवहन में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह लचीला, विश्वसनीय व उपयोगी साधन होता है।

1. Seventh Five Year Plan, 1985-90, Vol. II, pp. 219-221.

1950-51 में देश में बसों की संख्या 34 हजार से बढ़कर 1984-85 में 2 लाख 6 हजार हो गई। इस प्रकार औसत रूप से 5.4% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। इनमें सबसे अधिक बढ़ोतरी की संख्या 82 हजार से बढ़कर 7 लाख 63 हजार हो गई (वार्षिक वृद्धि-दर 6.8%)।

1960-61 में यात्री-ट्रैफिक में सड़क बसेलों का अनुपात 42 : 58 था, जो बढ़त कर 1977-78 में 59 : 41 हो गया। इसी प्रकार माल-नाटा ट्रैफिक में यह 1960-61 में 28 : 72 था जो बढ़त कर 1977-78 में 32 : 68 हो गया। इस प्रकार सड़कों का योगदान पहले से काफी बढ़ा है।

1984-85 में 38% नए सार्वजनिक क्षेत्र में घा चुकी थी, लेकिन ट्रक परिवहन लगभग निजी क्षेत्र में ही केन्द्रित रहा है।

व्यापारिक मोटर-परिवहन-आडिथों के लिए परमिट लेना पड़ता है जिसके लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राजकीय परिवहन अधिकारी और अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन आयोग से स्वीकृति लेनी होती है।

रेल-सड़क समन्वय (Rail-road Co-ordination)—रेल-सड़क प्रतियोगिता को दूर करने के लिए इन साधनों में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। समन्वय का अर्थ यह है कि प्रत्येक परिवहन के साधन का उपयोग उसी क्षेत्र में किया जाय जिसके लिए वह सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। एक परिवहन का साधन दूसरे परिवहन के साधन के क्षेत्र में प्रवेश न करे। ऐसा करने से परिवहन की मुद्रिमाएँ सस्ती व कार्यकुशल हो सकेंगी और समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा।

परिवहन के साधनों में समन्वय स्थापित करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो राष्ट्रीयकरण का है जिसमें सब साधन एक ही अधिकारी के नीचे आ जाते हैं और उनमें परस्पर प्रतियोगिता का अन्त हो जाता है। दूसरा वैधानिक समन्वय (Statutory Coordination) का तरीका है जिसमें एक वैधानिक नमूना विभिन्न परिवहन के साधनों के कार्यक्षेत्र निर्धारित व नियमित करता है। नाटवैस आदि देने पर नियन्त्रण किया जा सकता है। पहली विधि में परिवहन के साधनों पर राज्य का अधिकार हो जाता है, जबकि दूसरी विधि में यह आवश्यक नहीं होता। साधन निजी व्यक्तियों के हाथों में रह सकते हैं। लेकिन उनके उपयोग पर नियन्त्रण होता है। भारत में इस समय रेल-सड़क समन्वय की दूसरी विधि (वैधानिक समन्वय) चल रही है लेकिन पहली विधि (राष्ट्रीयकरण) की ओर भी प्रवृत्ति दिखाई देती है।

समन्वय की समस्याओं को हल करने के उपाय—

1) **समय कम की जाय**—परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग लेते अनुपात में किया जाना चाहिए जिससे समाज की कुल आवश्यकताओं की पूर्ति न्यूनतम मानक पर हो सके।

2 सामाजिक लागत-साम पर विचार किया जाय—समन्वय के प्रश्न पर विचार करते समय सामाजिक लागतों का महत्व बढ़ जाता है। सामाजिक लागतों के साथ सामाजिक लाभों पर विचार करना भी आवश्यक होता है। परिवहन के नियोजन में पूँजी, विदेशी विनिमय, दुर्लभ पदार्थ एवं कर्मचारी आदि पर ध्यान देना होगा, जो विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक होंगे और साथ में विनियोग के प्रतिफलों को भी देखना होगा।

3 आवश्यक सूचनाएँ व आंकड़े एकत्र किए जायँ—समन्वय की समस्या को हल करने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में आर्थिक व सार्वजनिक सूचना को एकत्र करने की आवश्यकता होती है। रेल व सड़क-परिवहन दोनों के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न अनुमानों और ट्रैफिक के विशिष्ट-प्रवाहों (specific flows) के सम्बन्ध में कुछ व सीमान्त लागत के बारे में लगातार कुछ समय तक बड़ी अध्ययन करवाये जायँ जिनसे ठेकी सामग्री प्राप्त हो सके जिसके आधार पर उचित निर्णय लिये जा सकें।

4. विनियोग में लागत-साम के आधार का उपयोग किया जाय—रेल व सड़क की लागतों की तुलना करते समय औसत लागत पर निर्भर करना जोखिमपूर्ण होगा। इसलिए यातायात के विशिष्ट-प्रवाहों की जाँच की जानी चाहिए। परिवहन के क्षेत्र में भी विनियोग व लागत-साम के आधार लागू किये जाने चाहिए। योजनाओं में विनियोग की नीतियों के माध्यम से परिवहन की विभिन्न सेवाओं में समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

रेलो में अधिकांश नया विनियोग रेल परिवहन की वर्तमान कार्यक्षमता बढ़ाने में लगाया जाना चाहिए बजाय विस्तार में लगाने के। नये व कम विस्तृत क्षेत्रों में सड़कों की सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए। गांवों में आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए, कृषि, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था व शहरी के अन्दर भी आवागमन को बढ़ाने के लिए सड़कों का विकास किया जाना चाहिए।

5 तीन प्रकार के सहायक उपाय—परिवहन के विकास की योजना में यातायात के आवंटन की स्कीम और विनियोग की योजना भी मुख्य अंग होते हैं। रेल व सड़क परिवहन के बीच समन्वय के लिए तीन किस्म के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए (अ) राजकोषीय उपाय व मूल्य-निर्धारण की नीतियाँ (आ) नियमन, और (इ) रागठन व कार्यों में एकीकरण। बरों व आर्थिक सहायता के जरिए परिवहन के विशेष साधनों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है अथवा उन्हें हतोत्साहित किया जा सकता है।

सड़क-परिवहन के नियमन के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन तो केन्द्रीय सरकार के अधिकार में होना चाहिए और एक ही राज्य के विभिन्न भागों में सड़क-परिवहन पर राज्य सरकारों

का नियन्त्रण होना चाहिए। पिछड़े हुए प्रदेशों में परिवहन की एकीकृत योजनाओं का विशेष रूप से महत्व होता है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क-परिवहन के विकास पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए।

सड़क-परिवहन को एक संगठित उद्योग का रूप लेना चाहिए। इसे समाज के प्रति जिम्मेदारी के माध्यम पर काम करना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, इसे रेलों से पूरक सम्बन्ध स्थापित करके कार्य करना चाहिए और देहाती में कम विकसित क्षेत्रों में विश्वास को प्रोत्साहन देने में प्रमुख रूप से भाग लेना चाहिए। सरकार ने परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक परिवहन-विकास-परिषद् (Transport Development Council) की स्थापना की है।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Road Transport)

पिछले वर्षों में सड़क-परिवहन का राष्ट्रीयकरण काफी चर्चा का विषय रहा है। सरकार की नीति सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करने की रही है जिसे उत्पादन के क्षेत्र के अलावा बैंकिंग, बीमा, परिवहन व व्यापार (मान्तरिक व विदेशी दोनों) में बढ़ाया गया है।

मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण के निम्न लाभ बतलाये गये हैं—

(1) इससे रेल-सड़क प्रतियोगिता की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी क्योंकि दोनों में ज्यादा प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

(2) परिवहन-विकास की योजना ज्यादा सफलतापूर्वक हो सकेगी। देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन के साधनों का विकास अधिक आवश्यक होता है। अतः राष्ट्रीयकरण से सड़क विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

(3) उपरोक्त की निजी बस चालकों व ट्रक-चालकों के द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं व शोषण से मुक्ति मिलेगी।

(4) सरकार सड़क-परिवहन में लागू करों को घटाने की योजना में वृद्धि कर सकेगी जिससे आर्थिक योजनाओं के लिए अधिक धनराशि जुटाई जा सकेगी।

(5) सड़क-परिवहन-सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा जिससे जनता को लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रगति—गोवा, दमन व दीव तथा पाण्डिचेरी को छोड़कर अधिकांश राज्यों एवं संघीय प्रदेशों में विभिन्न अंशों में राष्ट्रीयकृत यात्री-बसें चालू की गयी हैं। राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व दिल्ली में अधिकांश भागों पर राष्ट्रीयकृत बसें चलती हैं। 1984-85 में कुल बसों की संख्या लगभग 2 लाख 6 हजार थी जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र का अंश 38% तथा निजी क्षेत्र का 62% था। इसी प्रकार निजी क्षेत्र 62% यात्री-सेवाओं का संचालन

करता है, जबकि लगभग सम्पूर्ण ट्रक-व्यवसाय निजी क्षेत्र के पास है। यात्री-परिवहन का भी कुछ सीमा तक राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। अन्य राज्यों में भी विभागीय तौर पर बस-सेवाएँ जारी की गई हैं। माल-परिवहन अभी तक निजी क्षेत्र में ही है, हालांकि केन्द्रीय सड़क-परिवहन निगम असम व पश्चिमी बंगाल में काफी गाड़ियों के जरिए माल की ढुलाई भी कर रहा है।

सरकार ने राष्ट्रीयकृत सड़क-परिवहन सेवाओं के विकास के लिए प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजना में धनराशि की व्यवस्था की है। अभी तक राज्य सड़क-परिवहन निगम पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं कमा रहे हैं। इन्हें अपनी कार्य क्षमता बढ़ाकर अधिक प्रतिफल कमाने चाहिए ताकि योजनाओं के लिए अधिक धन राशि जुटायी जा सके। अतः इनकी कार्यकुशलता में सुधार करके घाटा समाप्त किया जाना चाहिए।

(इ) भारत में जल-परिवहन

जल-परिवहन तीन भागों में बाँटा जा सकता है (1) अन्तर्देशीय जल-परिवहन (Inland Water Transport), (2) तटीय-परिवहन (Coastal Transport), और सामुद्रिक परिवहन (Oceanic Transport)। अन्तर्देशीय जल-परिवहन के अन्तर्गत देश के आन्तरिक भागों में नदियों व नहरों का जल-परिवहन आता है। तटीय परिवहन में देश के एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक का जल-परिवहन आता है और सामुद्रिक परिवहन में एक देश से दूसरे देश तक समुद्री जहाजों से होने वाला परिवहन आता है।

भारत के लिए उपर्युक्त तीनों प्रकार के जल-परिवहन का महत्व है। इनमें से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति का उल्लेख आगे किया जाता है—

1 अन्तर्देशीय जल परिवहन¹

(Inland Water Transport)

भारत में लगभग 14 500 किलोमीटर लम्बा अन्तर्देशीय जल-मार्ग है। जिसका लगभग पाँचवाँ भाग नाव्य है। देश में विभिन्न नदियाँ व नहरें नाव्य (navigable) हैं। अन्तर्देशीय जल परिवहन-सेवाएँ इस समय मुख्यतया असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु में चलती हैं। देश का परिवहन व्यवस्था में अन्तर्देशीय जल-परिवहन का अंश केवल 1% है। अन्तर्देशीय जल परिवहन राज्यों का विषय है।

1 Seventh Five Year Plan, Vol II, pp 228-230, & Report of NTPC, May 1980 Ch. 15

योजनाकाल में प्रगति

प्रथम योजना में केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल व असम की सरकारों ने मिलकर गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भाग लेने वाली सरकारों के गंगा व ब्रह्मपुत्र प्रणालियों पर जल-परिवहन के विकास के प्रयत्नों में ताल-मेल बंठाना था। इसका एक कार्य इस बात की जाँच करना था कि पिछड़े जल-मार्गों पर आधुनिक नावों कहीं तक चलायी जा सकती हैं।

द्वितीय योजना में पाण्डु (गौहाटी) में आन्तरिक बन्दरगाह का निर्माण, बेरन में बाडागरा से माही तक पश्चिमी तटीय नहर का विस्तार और दामोदर घाटी में कई नाव मार्ग शामिल किये गये। आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु में बकिशम नहर से कीचड़ निकालने (Dredging) का कार्य प्रयोग के तौर पर करने की भी व्यवस्था की गयी।

तृतीय योजना में केन्द्र में एक ऐसे समूह की स्थापना का कार्य शामिल किया गया जो अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन के विकास पर प्राविधिक सलाह व निर्देशन दे सके। पाण्डु में आन्तरिक बन्दरगाह का कार्य पूरा करके और दामोदर घाटी निगम नहर पर नाव्य-कार्य करने के कार्यक्रम रमे गये। तृतीय योजना में गंगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड के द्वारा मुन्दर बन में एक प्रयोगात्मक नाव खींचने का प्रोजेक्ट (Pilot Towing Project) शामिल किया गया। मुन्दरबन और ब्रह्मपुत्र के लिए ड्रेजिंग और लॉन्चेज लरीइने का कार्यक्रम रखा गया। गौहाटी के तटीय भागों (Foreshores) के मुधार की व्यवस्था की गई और प्रतिप्रण के लिए धन-राशि रची गयी। बेरन में पश्चिमी तटीय नहर का विस्तार उड़ीसा में सातडण्डा और केन्द्रपारा नहरों के मुधार के कार्यक्रम रमे गये जिसमें पाराद्वीप से कच्चे सोहे के निर्माण में मूल्यांकन हो सके।

पिछले दो दशकों में केन्द्रीय क्षेत्र में जो बृहद् स्कीमों कार्यान्वित की गई हैं वे इस प्रकार हैं—असम में पाण्डु व जोगीगोपा बन्दरगाहों का निर्माण, राजबगान डॉकयार्ड व कुन्ती बर्कलापो का विकास तथा जहाज को डूबने से बचाने के उपकरणों का निर्माण, आदि।

मानवी पंचवर्षीय योजना 1985-90 में आन्तरिक जल परिवहन (IWT) के विकास के लिए 226 करोड़ रु की राशि रची गयी है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 155 करोड़ रु. की राशि तथा राजकीय क्षेत्र के लिए 71 करोड़ रु. की राशि है।

मानवी योजना में केन्द्रीय आन्तरिक जल-परिवहन-निगम (CIWTC) 83 नये नदीय जहाज प्राप्त करने का प्रयास करेगा तथा राजबगान डॉकयार्ड का विकास

क्रिया जायगा एवं अन्य आवश्यक सर्व विधे जायेगे। राजबगान डॉकपोर्ट के विकास से इसी प्रति वर्ष 4 जहाज निर्माण करने तथा 54 जहाजों की मरम्मत करने की क्षमता हो जायेगी। सातवी योजना के अन्त तक इसकी जहाज-निर्माण क्षमता बढ़कर 8 प्रतिवर्ष होने की आशा है। केन्द्रीय आन्तरिक जल-परिवहन निगम की स्थापना एक कम्पनी के रूप में 22 फरवरी, 1967 को हुई थी। इसके तीन खण्ड (divisions) हैं—(i) नदी सेवा खण्ड, (ii) राजबगान डॉकपोर्ट, (iii) गहरे समुद्र के जहाजों की मरम्मत का खण्ड।

आन्तरिक जल-परिवहन व अन्य साधनों में समन्वय की आवश्यकता—

रेल सड़क व अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। जहाँ जल मार्ग रेल व सड़को व समानान्तर हो जाते हैं वहाँ समस्त यातायात के अनुकूलतम वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे परिवहन के प्रत्येक साधन से अधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सकें। द्वितीय जहाँ अन्तर्देशीय जल-परिवहन का जल-मार्ग से दूर स्थित स्थानों के लिए रेल या सड़क परिवहन से मिलता है वहाँ जल मार्गों व परिवहन के अन्य साधनों में नावान्तरण (Transshipment) की लागत व समय कम करने के तरीकों का पता लगाना चाहिए।

जल-मार्गों के विकास की दीर्घकालीन योजना बनायी जानी चाहिए। इसके लिए प्राथमिक वित्त की व्यवस्था भी करनी होगी।

2 तटीय जहाजरानी (Coastal Shipping)

तटीय जहाजरानी का विकास लम्बी दूरी तक भारी माल ढोने का एक सस्ता साधन माना गया है, यद्यपि कि माल तट पर स्थित किसी स्थान तक पहुँचाना होता है। भारत का तट 7517 किलोमीटर में फैला है। अतः तटीय जहाजरानी का परिवहन विकास में महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है।

तटीय जहाजरानी की टन-भार क्षमता 1950-51 में 2.2 GRT (Gross-Registered Tonnage) थी जो 1979-80 में 2.54 लाख GRT तथा 1984-85 में 5 लाख GRT हो गई। 1950-51 में 36 लाख टन माल ढोया गया जो बढ़कर 1984-85 में 55 लाख टन तक पहुँच गया। 1989-90 तक इसके 70 लाख टन होने की आशा है।

तटीय जहाजरानी की 35% टन भार क्षमता पुरानी पड़ चुकी है जिसे शीघ्र बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा 17% क्षमता सातवी योजना में इसी धरे की में आ जायेगी।

तटीय जहाजरानी में पुराने जहाज ईंधन के उपयोग की दृष्टि से अकार्य-कुशल माने जाते हैं। बन्दरगाहों पर अत्यधिक विलम्ब की समस्या भी पायी जाती

है। अन्तः-सागरी योजना में इन कठिनाइयों को हल करने का प्रयास किया जायेगा।

3 सामुद्रिक जहाजरानी एवं जहाज निर्माण (Overseas Shipping and Ship-building)

अपने विस्तृत तट और विश्व में उत्तम स्थिति के कारण भारत कुशल और सुदृढ़ जहाजरानी प्रथम पोत-परिवहन का विकास कर सकता है। शान्ति और युद्ध दोनों में राष्ट्रीय जहाजरानी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत एशिया में दूसरा सबसे बड़ा सामुद्रिक जहाजरानी वाला देश है तथा विश्व में इसका सातहवाँ स्थान है।

योजनाकाल में सामुद्रिक जहाजरानी व जहाज-निर्माण की प्रगति

भारतीय जहाजरानी का विश्व के जहाजी बेड़े में केवल 1% अंश है। 1950-51 में इसकी टन-भार क्षमता 3.9 लाख जी. टन थी जो बढ़ कर 1986-87 में 57.74 लाख जी. टन हो गई है।

तृतीय योजना में स्थगित मुग़तानों की शर्तों पर जहाज खरीदे गये, पुराने जहाज सस्ते भावों पर प्राप्त किये गये, हिन्दुस्तान शिपयार्ड की क्षमता का पूरा उपयोग किया गया और नयी जहाजी कंपनियों ने विस्तार के कार्यक्रम अपनाये। तृतीय योजना में 11 भारी सामान ढोने के जहाज (Bulk Carriers) और 4 समुद्र-पार जाने वाले टैंकर्स प्राप्त किये गये ताकि खाद्यान्न, खनिज पदार्थ व पेट्रोल की वस्तुओं को ढोने में आसानी रहे। यह सन्तोषप्रद प्रगति मानी जा सकती है।

उपयुक्त प्रगति जहाजरानी उद्योग में सरकार की सहभागिता के कारण सम्भव हो सकी थी। 1950 में ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन स्थापित किया गया और 1956 में दूसरा शिपिंग कॉरपोरेशन बनाया गया तथा अक्टूबर, 1961 में दोनों एक शिपिंग कॉरपोरेशन में मिला दिये गये। पिछले वर्षों में जहाज निर्माण उद्योग और बन्दरगाहों के विकास में काफी प्रगति हुई है जो जहाजरानी के विकास के लिए आवश्यक है। आजकल बड़े जहाजों का प्रचलन बढ़ गया है। भारत में भी बड़े जहाजों की अपनाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके लिए बन्दरगाहों का विकास भी बहुत आवश्यक है। भारतीय जहाज समुद्रपार के व्यापार में ज्यादा हिस्सा लेकर विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में सहायक सिद्ध होने लगे हैं।

इस समय भारतीय समुद्री जहाज देश के कुल सामुद्रिक व्यापार का 41% सम्भालते हैं। देश का विदेशी व्यापार पिछले वर्षों में काफी बढ़ा है। आज भी हमारे जहाज तेल के आयात व कच्चे लोहे के निर्यात व्यापार में कम भाग ले पा रहे हैं।

गटेनर जहाजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

1950-51 में बड़े बन्दरगाहों पर 19.2 मिलियन टन माल ढोया गया जो बढकर 1984-85 में 106.7 मिलियन टन हो गया। माल में पेट्रोल, तेल व चिकनाई (POL), कच्चा लोहा, कोयला व उर्वरक, खाद्यान्न आदि शामिल होते हैं। भविष्य में बन्दरगाहों को अधिक माल ढोना पड़ेगा। अनुमान है कि 1989-90 में 147 मिलियन टन (14.7 करोड़ टन) माल ढोना पड़ेगा। इस समय बड़े बन्दरगाहों की माल ढोने की कुल क्षमता 13.3 करोड़ टन है। 1989-90 में इसके बढकर 16.1 करोड़ टन होने की आशा है।

जहाज-निर्माण उद्योग—देश में विशाखापटनम में समुद्री जहाज बनाने का कारखाना है, लेकिन इसकी उत्पादन-क्षमता सीमित है। दूसरा शिपयार्ड कोचीन में विकसित किया जा रहा है। भारतीय कम्पनियों को जहाजों की मरम्मत पर विदेशी मुद्रा व्यय करनी होती है। इसलिये मरम्मत की व्यवस्था बढाने की आवश्यकता है।

भारतीय जहाजों को कठिनाई के समय मदद देने के लिए एक बचाव-इकाई (Salvage Unit) की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने एक बचाव-इकाई की स्थापना पर बल दिया है। इसके लिए विदेशी विनिमय की कठिनाई महसूस की जा रही है। जहाज तो स्थगित भुगतान पद्धति पर प्राप्त किये जा सकते हैं, लेकिन बचाव की इकाई इस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती।

जहाजरानी कम्पनियाँ (Shipping Companies)

इस समय देश में 54 जहाजरानी कम्पनियाँ हैं, जिनमें से दो कम्पनियाँ—भारत का जहाजरानी निगम लि. तथा मुगल लाइन लि. सार्वजनिक क्षेत्र में हैं जो कुल माल का 55% संचालित करती हैं तथा शेष निजी क्षेत्र में है। 12 कम्पनियों के पास कुल शिपिंग टन-मार क्षमता का 90% अंश पाया जाता है।

जहाज निर्माण कार्य

भारत में तीन जहाज-निर्माण स्थल हैं—विशाखापटनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड, कलकत्ता में गार्डन रीफ वर्कशॉप्स तथा बम्बई में मङ्गलव डॉक। चौथा शिपयार्ड कोचीन में बनाया जा रहा है। सभी शिपयार्ड सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

बन्दरगाहों का विकास

भारत के लगभग 6000 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट पर 11 बड़े बन्दरगाह (कलकत्ता, बम्बई, नया मंगलोर, पारादीप, तूतीकोरिन, मद्रास, विशाखापटनम, कोचीन, कांदला, मारमगोआ व नेवा शेवा) तथा 139 छोटे कार्यरत बन्दरगाह हैं। आजकल बन्दरगाहों पर खाद्यान्न, कच्चे लोहे व पेट्रोल की वस्तुओं का घाताघात काफी बढ गया है। 1965-66 में सब मौसमों के लिए एक नया बन्दरगाह

पाराशीप चालू किया गया था। पहले बताया जा चुका है कि 1984-85 में बड़े बन्दरगाहों पर 106.7 मिलियन टन मात्र होया गया था, जबकि 1950-51 में 19.2 मिलियन टन ढाया गया था। अविध्य में पेट्रोल पदार्थों, कच्चे लोहे व उर्वरकों के लिए ट्रैफिक में वृद्धि की विशेष सम्भावना है। चतुर्थ योजना में हल्दिया डॉक-सिस्टम (dock system at Haldia), मयनौर व तूतीकोरिन पर खनिज पदार्थ टान की सुविधा को प्राथमिक बनाने, विशाखापटनम पर एक बाहरी पोताध्य का निर्माण करन एवं बम्बई के लिस् नेवा शेवा (Nheva Sheva) पर एक उपग्रह बन्दरगाह (Satellite port) बनाने के कार्यक्रम रने गये थे।

सातवीं योजना में परिव्यय व कार्यक्रम

छठी योजना में बन्दरगाहों के विकास पर 627 करोड़ रु. व्यय हुए। सातवीं योजना में इनके लिए 1105 करोड़ रु. की धनराशि प्रावर्तिन की गई है। उसमें नेवा-शेवा बन्दरगाह के विकास हेतु 402.4 करोड़ रु. की राशि रखी गयी है। सातवीं योजना में चालू परियोजनाओं को पूरा किया जायगा तथा बन्दरगाहों की सुविधाओं का विस्तार व आधुनिकीकरण किया जायगा।

सातवीं योजना में छोटे बन्दरगाहों के विस्तार पर 126 करोड़ रु. की राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई है। भारतीय ड्रेजिंग निगम के लिए 95 करोड़ रु. की राशि रखी गयी है ताकि प्राथमिक ड्रेजर्स भी लयदे जा सकें।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय जहाजरानों के विकास में पिछले वर्षों में गौर प्रगति हुई। अविध्य में इस दिशा में और प्रगति होने की आशा है। विदेशी विनिमय की कठिनाइयां हमारे मार्ग में बाधक रही हैं। अतः उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(ई) भारत में वायु परिवहन (Air Transport in India)

भारत में वायु-परिवहन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं, जैसे देश का महाद्वीपीय आकार, जो लम्बे हवाई मार्ग के लिए लाभप्रद है, अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु और स्वच्छ वायुमण्डल (वर्ष के कुछ महीनों को छोड़कर) उड़ानों को सुविधा प्रदान करने के लिये विस्तृत संज्ञान एवं भारत की विश्व में वैश्वीय स्थिति। इनकी सुविधाओं के बावजूद भी भारत में वायु परिवहन एक विनामिता की वस्तु ही बना हुआ है। अभी तक उसके विकास की सम्भावनाओं का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाया है।

हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण—सरकार ने नो एयरलाइन्स के राष्ट्रीयकरण का निर्णय करके अगस्त 1953 में एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम पास कर दिया था जिसके अन्तर्गत हवाई परिवहन के स्वामित्व का मन्त्रालय का काम सरकार के हाथ में आ गया था।

राष्ट्रीयकरण ■ वक्ष में सरकार ने निम्न दलों से प्रस्तुत की थी—(1) उपलब्ध साज-सामान का अधिकतम लाभ की दृष्टि से उपयोग किया जा सकेगा, (3) सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है; (1) वायु-परिवहन एक सार्वजनिक सेवा का उद्योग है। अतः इसमें मुनाफे का उद्देश्य सर्वोपरि नहीं होना चाहिए (4) नावी विकान के लिए प्राविधिक प्रगति को देखते हुए इसका सार्वजनिक क्षेत्र में होना उपयुक्त रहेगा। 1 अगस्त, 1953 से भारत में वायु-परिवहन न एक नया माड निय है। प्रतिनियम के अन्तर्गत दो निगम स्थापित किए गए हैं (1) एयर इण्डिया जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ संचालित करता है और (2) इण्डियन एयरलाइन्स जो देश में और पड़ोसी देशों के बीच हवाई सेवाएँ संचालित करता है।

राष्ट्रीयकरण के बाद से अब तक की प्रगति—विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद दोनों निगमों के कार्यों में तीव्र गति से विस्तार हुआ है। उपलब्ध साजनों का नियोजित ढंग से उपयोग किया गया है, पुराने मार्गों पर वायु परिवहन का विस्तार किया गया है, नये मार्ग खोले गए हैं और यातायात की क्षमता बढ़ाई गयी है।

1960-61 में 7-9 लाख यात्रियों ने हवाई परिवहन का उपयोग किया था। 1984-85 में इनकी संख्या 85.1 लाख यात्री हो गई है लेकिन आज भी घरेलू हवाई यात्री-ट्रैफिक कुल यात्री ट्रैफिक का 1% ही हो पाया है।

1986-87 में एयर इण्डिया 18 लाख यात्रियों को एक न्यान से दूसरे स्थान तक ले गया। आज इण्डियन एयरलाइन्स 69 स्टेशनों को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें 62 भारत में स्थित हैं एक शेय बेफगानिस्तान, बंगला देश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल व पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में स्थित हैं। एयर इण्डिया 41 देशों में 45 नगरों तक जाता है।

एयर इण्डिया का एयरक्राफ्ट फ्लीट 1987 में इस प्रकार था : 9 बोईंग-747, 3 एयरबस A 300-B-4 तथा 5 एयरबस A 310-300। एयर इण्डिया का एक विमान बोईंग-747 (कनिष्क) 23 जून 1985 को आयरलैंड के तट से दूर दुर्घटनाग्रस्त होकर एटलांटिक महासागर में जा गिरा था जिससे 329 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। यह एक भारी दुःखद घटना थी। 'इण्डियन एयरलाइन्स' की बड़े हवाई जहाज बड़ा रहा है। इसमें एच. एस 748 ट्रासपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल करने का कार्यक्रम है। इस समय इण्डियन एयरलाइन्स के पास 11 एयर बस 27 बोईंग-737, सात HS-748 तथा पाँच F-27 (एयरक्राफ्ट) हैं।

वायुदूत—भारत में ऐसे क्षेत्रों में वायु-परिवहन की सुविधा उपलब्ध करने के लिए जो पहुँच से परे हैं। (Inaccessible), वायुदूत (Vajudoot) के द्वारा अपनी सेवाएँ 10 नागरिक हवाई अड्डों, तीन सुरक्षा हवाई अड्डों, एक राज्य सरकार के हवाई अड्डे तथा दो लाइसेंसशुदा निजी हवाई अड्डों के माध्यम से दी जाती है।

वायुसेवा जनवरी 1981 में प्रारम्भ की गई थी। इसके द्वारा महत्वपूर्ण सुदूर स्थानों को इण्डियन एयर लाइन्स मार्ग के स्थानों से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है।

भारत में हवाई अड्डों का विकास किया गया है। योजनावात्त में नये हवाई अड्डे बनाये गये हैं : जैसे उदयपुर, पन्तनगर, कमलपुर, मुजफ्फरपुर, कादली, रंजमोल, खजुराहो, आदि। देश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा 85 अन्य हवाई अड्डे हैं। अब बड़े हवाई जहाजों का युग आ गया है और 400 यात्रियों की क्षमता के हवाई जहाज प्रयुक्त होने लगे हैं। भारत को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली व मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास करना चाहिए।

वायु-परिवहन उद्योग की सफलता हवाई जहाज के सही चुनाव पर बहुत निर्भर करती है। अन्तरिक्ष हवाई सेवाओं को लाभदायकता विभिन्न प्रकार के हवाई जहाजों को चलाने की लागत और भागों की प्रकृति पर विशेष रूप से निर्भर करती है।

इण्डियन एयर लाइन्स की सेवाएँ ट्रंक मार्गों पर तो पर्याप्त हैं, लेकिन प्रादेशिक मार्गों पर अभी विकास की सम्भावनाएँ बनी हुई हैं। कुछ प्रदेशों के आर्थिक विकास व प्रशासन में सुधार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु-सेवाओं की आवश्यकता है। असम, मध्य प्रदेश व आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में हवाई-सेवा के विस्तार की आवश्यकता है। दक्षिण प्रदेश में भी हवाई परिवहन का विकास किया जा सकता है। वर्तमान समय की आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए विकास व लाभदायकता दोनों उद्देश्यों में उचित सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन विकास कोष (Civil Aviation Development Fund) की एक करोड़ रुपये के प्रारम्भिक अनुदान से स्थापना की है जो इण्डियन एयरलाइन्स निगम को आर्थिक सहायता देगा ताकि यह सरकार के कहने पर प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने एवं पर्यटन-प्रोत्साहन आदि कार्यों में भाग ले सके।

इण्डियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन की कुल आय का 70% ट्रंक-सेवाओं से प्राप्त होता है। इसलिए सेवाओं के प्रादेशीकरण की अपनी मर्यादाएँ हैं। फिर भी प्रादेशिक इकाइयों स्थापित करके बसासम्भव विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

वायु परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हो रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली व मद्रास चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इनके विकास व प्रबन्ध का कार्य करदरी, 1972 में एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स प्राधिकारी मस्या (The International Airports

Authority of India) (IAAI) को सौंपा गया था। एयर इण्डिया व इण्डियन एयर लाइन्स का विकास किया जा रहा है।

छठी योजना में नागरिक उड्डयन पर 931 करोड़ रु. व्यय किये गये। सातवी योजना में इसके विवास के लिए साधनों के अभाव के कारण 730.2 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई।

एयर इण्डिया 9 दो इंजन वाले एयरक्राफ्ट प्राप्त करेगा, माल-ट्रैफिक की क्षमता बढ़ायेगा, वर्कशाप व प्रशिक्षण की सुविधाएँ सुदृढ़ की जायेंगी, कम्प्यूटर नेट-वर्क को विकसित किया जायेगा व अन्य सेवाएँ बढ़ायी जायेंगी। इण्डियन एयरलाइन्स भी एयरक्राफ्ट प्राप्त करेगा, दिल्ली में जेट 2 जन की मरम्मत की सुविधाएँ खोल करेगा तथा वर्कशाप सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जायगा। IAAI बम्बई, दिल्ली व मद्रास में सुविधाओं का विकास करेगा। इस प्रकार सातवी योजना में हवाई परिवहन के विकास में प्रयत्न जारी रखे जायेंगे।

मई 1986 में सरकार ने एयर इण्डिया व इण्डियन एयर लाइन्स के एकीकरण को क्रमबद्ध रूप से (phased manner) करने के निर्णय की घोषणा की है। विदेशी एयरलाइनों से समुक्त संचालन के लिए समझौते किये जायेंगे तथा राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। सरकार ने एयर टैक्सी सर्विस की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 10 सीट वाले हवाई जहाजों के लिए लाइसेंस दिये जायेंगे एवं उनके आयात की इजाजत भी दी जायेगी। लम्बी दूरी के यात्री ट्रैफिक की दृष्टि से वायु-परिवहन के विकास का विशेष महत्व है। लेकिन परिवहन का यह साधन ऊर्जा-गहन (energy-intensive) है। इसलिए तेल-साधनों के अभाव में इसके विस्तार में विशेष बाधाएँ आती हैं। आजकल 'हार्ड-जैव' व आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे के कारण नई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिनका सामना करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण

(National Airports Authority) (NAA) 1986 का परिचय¹

सरकार ने राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 21 मई, 1986 को स्थापित किया है। इसने 1 जून, 1986 से अपना कार्यारम्भ कर दिया है। इसका उद्देश्य भारत में नागरिक उड्डयन सम्बन्धी कार्यों के लिए आधार-ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की सुविधाएँ उपलब्ध करना है। इसके कार्यों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। हवाई अड्डों की व्यवस्था करना, हवाई ट्रैफिक सेवाएँ व हवाई परिवहन सेवाएँ उपलब्ध करना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाना, कर्मचारियों के लिए

1. Transport in India, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 1986, pp. 39-41.

रिहायशी भवनो का निर्माण करना, होटल आदि, (हवाई अड्डों के समीप) बनाना, हवाई अड्डों पर निगरानी की व्यवस्था करना, हेलिपोर्ट्स स्थापित करना तथा हवाई जहाजों के संचालन को सुरक्षित व कार्यक्षम बनाने से सम्बन्धित सभी तरह के अन्य कार्य करना। आशा है राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना से भारत में हवाई यातायात के विकास में पर्याप्त मदद मिल सकेगी।

प्रश्न

- 1 भारत में रेल परिवहन के महत्व एवं वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।
(Raj II year T. D C 1986)
 - 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—
 - (i) 1961 में भारत में जहाजों यातायात की प्रगति।
(Raj II yr. T D C, 1984)
 - (ii) योजनाबद्धि में रेलों का विकास।
(Raj II yr T. D C, 1988)
 - (iii) सन् 1961 से यातायात की मुख्य प्रवृत्तियाँ।
(Raj II yr T D C., 1982 & 1985)
 - (iv) राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1986)
 - (v) वायुदूत
-

श्रमिक-संघ आन्दोलन¹

(Trade Union Movement)

मजदूर-संघ श्रमिकों के ऐसे स्थायी संगठन को कहते हैं जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाये रखना तथा उनमें आवश्यक सुधार करना होता है। आजकल इनका कार्य-क्षेत्र केवल श्रमिकों की काम की दशाओं से ही सम्बन्धित नहीं रह गया है, बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक पहलू—आर्थिक, सामाजिक और राज-नीतिक तक फैल गया है।

आधुनिक युग में मजदूर यूनियन औद्योगिक लोकतन्त्र के आधार-स्तम्भ माने जाते हैं। पूँजीवादी व समाजवादी सभी देशों में उनके महत्व को स्वीकार किया गया है। इनके दो प्रकार के कार्य होते हैं—

1 सघर्षात्मक कार्य—मजदूर-संघ सामूहिक सौदाकारी (collective bargaining) एवं हड़ताल आदि साधनों का प्रयोग करके श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने, काम के घण्टे कम करने काम की दशाओं में सुधार करने, श्रमिकों को उद्योग के लाभों एवं प्रबन्ध में हिस्सा दिलाने आदि का प्रयत्न करते हैं। प्रायः कहा जाता है कि यदि मजदूरी श्रम की सीमांत उत्पत्ति के मूल्य से कम होनी है और श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है, तो मजदूर-संघ सघर्ष करके मजदूरी को श्रम की सीमांत उत्पत्ति के मूल्य के बराबर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे मजदूरों को आर्थिक शोषण से बचाते हैं।

2 कल्याणकारी कार्य—आजकल मजदूर संघों द्वारा किये जाने वाले रचनात्मक कार्यों के महत्व पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। शिक्षा, चिकित्सा, व मनोरंजन आदि की सुविधा बढ़ाकर मजदूर-संघ श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि

1 वर्तमान कानून के अनुसार 'ट्रेड यूनियन' शब्द में मालिकों व मजदूरों दोनों के संगठन शामिल होते हैं।

करते हैं इस प्रकार वे सीमान्त उत्तरति के वर्तमान मूल्य में वृद्धि करके मजदूरी को वर्तमान स्तर से ऊँचा उठाने में भी मदद देते हैं। इन कार्यों से मजदूरों में अनुशासन की भावना भी बढती है। किसी भी देश में श्रमिक सघ आन्दोलन की स्थायी प्रगति के लिए दोनों किस्म के कार्यों पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि मजदूर सघ केवल हड़ताल कराने वाली समितियाँ ही नहीं होती हैं, अपितु वे मजदूरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली और आधुनिक औद्योगिक संगठन में महत्वपूर्ण भाग लेने वाली संस्थाएँ होती हैं। उनका औद्योगिक लोकतन्त्र में प्रमुख स्थान होता है। उनकी आधुनिक औद्योगिक जीवन में व्यापक भूमिका होती है।

1939 से भारत में मजदूर सघ आन्दोलन की प्रगति

1939-40 में युद्ध प्रारम्भ होने के समय भारत में 667 मजदूर सघ थे जिनमें से 450 ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इनकी सदस्य संख्या लगभग 5 लाख हो गयी थी।

द्वितीय महायुद्ध के समय मजदूर-आन्दोलन ने जोर पकड़ा। महगाई के कारण मजदूरी बढ़ाने और महगाई भत्ता देने की माँग की गई। सरकार ने त्रिदलीय वार्ताएँ आरम्भ की जिससे भी श्रम-आन्दोलन को मान्यता मिली। परन्तु सरकार को युद्ध में सहयोग देने के प्रश्न पर श्रमिक सघों में मतभेद उत्पन्न हो गया। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने के पश्चात् श्री एम एन राय ने सरकार को युद्ध संचालन में सहयोग देने के लिए 'ट्रेड-यूनियन काँग्रेस छोड़कर 1939 में 'इण्डियन फ़ेडरेशन ऑफ़ लेबर' की स्थापना की जिसकी सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए काम करने के लिए उदार रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। 1945-46 में युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में रजिस्टर्ड श्रमिक-सघों की संख्या बढ़कर 1,087 हो गयी जिनमें केवल 585 ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी। उनकी सदस्य-संख्या लगभग 8 64 लाख थी।

युद्धोत्तर काल में महगाई के कारण श्रमिकों में काफी असन्तोष फैल गया था। 1945-47 के बीच अनेक हड़तालें हुई, जिनमें लाखों श्रमिकों ने भाग लिया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने नेताओं ने 1948 में 'इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस' (इन्टक) (INTUC) की स्थापना की और जो मजदूर-सघ समाजवादियों के प्रभाव में थे, उन्होंने मिलकर दिसम्बर, 1948 में 'हिन्द मजदूर पंचायत' बना ली। दिसम्बर, 1947 में सरकार, श्रमिकों और मित-मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच औद्योगिक शान्ति कायम करने के लिए एक समझौता हुआ। तत्पश्चात् कुछ वर्षों तक कोई बड़ी हड़ताल नहीं हुई। दिसम्बर 1949 में 'हिन्द मजदूर-पंचायत' और इण्डियन फ़ेडरेशन ऑफ़ लेबर' के प्रतिनिधियों ने

मजदूरी में एक सम्मेलन किया और दोनों ने मिलकर 'हिन्द मजदूर मंचा' (HMS) बनायी। इसी वर्ष अम-ग्रान्दोलन में कुल एकता स्थापित करने की दृष्टि में प्रोवेंसर के टी. शाह के प्रयत्नों से 'यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC) के नाम से एक अलग अलग भारतीय श्रमिक संगठन स्थापित किया गया। इस प्रकार देश में चार अलग भारतीय श्रमिक-मंच बन गये। सरकार ने इन्टर, एटव, एच एम एम व यूटुक को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मजदूरों का प्रातिनिधित्व करने व समय-समय पर देश में विचार-सम्मेलनों के लिए माध्यमता प्रदान की। बाद में 1955 में भारतीय मजदूर-मंच (BMS) की स्थापना की गई जिस पर प्रारम्भ में राजनीतिक दृष्टि में भारतीय जनमंच का प्रभाव था। अब यह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रभाव-क्षेत्र में है।

भारत में सभी पंजीकृत श्रमिक मंच कार्यों की रिपोर्ट नहीं भेजते हैं जिससे उनकी सदस्यता आदि के बारे में नियमित रूप से विश्वस्त व नवीनतम जानकारी नहीं मिल पायी। 1984 में कुल पंजीकृत ट्रेड यूनियन 42609 के लेकिन रिपोर्ट भेजने वाले मंचों की संख्या केवल 6372 ही थी। 1984 में प्रति मंच औसत सदस्यता 798 थी, जबकि 1983 में यह 792 रही थी।¹

कुछ वर्ष पूर्व एटव में फूट पड़कर एक नया श्रमिक संगठन 'सीटू' (Centre of Indian Trade Unions) का जन्म हुआ था। इस पर मार्क्सवादिवा [CPI (M)] का प्रभुत्व है। सीटू का मार्ग इंग्रानिर्धारण, धाम, मार्क्सवादि उपक्रम आदि में काफी प्रभाव है। इसका कैरल व पश्चिमी बंगाल राज्यों में विशेष प्रभाव पड़ा जाता है।

कुछ वर्ष पूर्व हिन्द मजदूर मंचा व हिन्द मजदूर पंचायत का भी परस्पर विवाद हुआ गया है।

अम मंचों की वर्तमान स्थिति

31 दिसम्बर 1980 को आगत के 10 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की जांच के बाद सत्यापित सदस्यता (Verified membership) इस प्रकार थी। जांच के से परिणाम 30 अगस्त 1984 को घोषित किये गये थे।²

1. Pocket Book of Labour Statistics, 1988, pp 132-135

2. India 1987, p 579.

सत्यापित सदस्यता (verified membership) के से श्राव्य श्रम-सन्त्रायण में प्रकाशित किये हैं। धन: इस सम्बन्ध में अन्य श्राव्य मिथ्या, कल्पित व अमान्य है। इसलिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

संगठन का नाम (Name of the Organisation)	सत्यापित उसके अन्तर्गत यूनियनों की संख्या No. of Unions)	(Verified) सदस्य संख्या (Member- ship)
(1) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC)	1604	(साफ़ों में) 22*36
(2) भारतीय मजदूर मंच (BMS)	1333	12*11
(3) हिन्दू मजदूर मंच (HMS)	426	7 63
(4) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (Lenin Sarani) (लेनिन सारनी) (UTUC) (LS)	134	6*21
(5) आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)	1080	3*45
(6) सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (CITU)	1474	3*31
(7) नेशनल लेबर मण्डल (NLO)	172	2*47
(8) नेशनल फ्रंट ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (NFITU)	80	0*84
(9) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC)	175	1*66
(10) ट्रेड यूनियन कांग्रेस (TUCC)	65	1*23
कुल	6543	61*27

तालिका से पता चलता है कि दिसम्बर 1980 में भारत में 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के अन्तर्गत 6543 यूनियन थे, जिनकी कुल सदस्य-संख्या लगभग 61*27 लाख थी। इनके सर्वाधिक सदस्यता इन्टूक की 22*36 लाख थी। इसके बाद दूसरा स्थान भारतीय मजदूर मंच (BMS) का था जिसकी सदस्य-संख्या 12*11 लाख थी। 31 दिसम्बर 1980 तक की सदस्यता के अन्तिम सत्यापन में ये परिणाम 30 अगस्त 1984 को घोषित किये गये थे।

विगत वर्षों में देश में शिक्षार्हीन रूप में अनेक राजनीतिक दलों के उत्पन्न होने में मजदूर-मंच आन्दोलन काफी अत्यन्त-व्यस्त व अव्यवस्थित की स्थिति में पड़ गया है। इन प्रकार की दिशाहीनता को समाप्त करके एक सुदृढ़ धार्मिक मंच आन्दोलन के निर्माण का प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिसकी रूपरेखा धार्मिक पृष्ठों में दी गई है। इनके लिए सर्वप्रथम कार्यक्रम-आधारित सुदृढ़ व मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा अल्पसंख्यक एवं सत्तापरक राजनीति समाप्त की जानी चाहिए। मुनिमिचुड नीतियों व कार्यक्रमों के बिना नयी राजनीतिक पार्टियों के

गठन से ग्राम जनता व श्रमिकों में दलीय राजनीतिक (party politics) के प्रति उत्साह कम हो जाता है।

भारत में मजदूर-संघ आन्दोलन की कमजोरियाँ व समस्याएँ

यद्यपि हमारे देश में श्रमिक संघवाद का काफी बोलबाला है, तथापि अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में यह आज भी काफी कमजोर स्थिति में है। इसकी कमजोरी के अधिकांश कारण आन्तरिक हैं, यद्यपि कुछ बाह्य कठिनाइयाँ भी मजदूर आन्दोलन के मार्ग में बाधक हैं। हम नीचे इन कमियों पर प्रकाश डालेंगे।

(अ) आन्तरिक कमियाँ

1. सीमित सदस्य—मजदूर-यूनियन अधिकांशतः औद्योगिक नगरों में ही सीमित है और यहाँ भी इनके सदस्यों की संख्या श्रमिकों की कुल संख्या का काफी नीचा अंश ही पायी जाती है। वास्तव में सक्रिय सदस्यों की संख्या तो प्रमाणित आंकड़ों से भी कम होती है और नाममात्र के सदस्य ज्यादा होते हैं। भारत में राजनीतिक अस्थिरता व नित्य नई पार्टियों के उदय से श्रमिक संघ-आन्दोलन काफी अनिश्चितता व अस्थिरता की स्थिति में फँसकर रह गया है। अधिकांश नयी पार्टियों के पास देश के विकास के लिए कोई सुनिश्चित राष्ट्रीय कार्यक्रम नज़र नहीं आने। वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने का साधन मात्र बनती जा रही हैं।

2. छोटे श्रमिक संघ—भूतकाल में भारत में श्रमिक संघों का आकार बहुत छोटा रहा है। छोटे संघों के पास धन और संगठन का अभाव होता है जिससे वे मिल-मालिकों तथा सरकार को ठीक से प्रभावित नहीं कर पाते। 1983 में प्रति संघ औसत सदस्यता 792 थी जो 1984 में 798 हो गई। इस प्रकार प्रतिसंघ औसत सदस्यता अभी भी काफी कम है।

3. कमजोर वित्तीय स्थिति—भारत में अधिकांश श्रमिक संघों के साधन इतने कम होते हैं कि वे बेटन देकर कर्मचारी नहीं रख सकते, रचनात्मक कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते और हड़ताल के दिनों में अपने सदस्यों की सहायता नहीं कर सकते। अधिकांश श्रमिक कम मजदूरी पाने के कारण संघों का बन्दा तक्रा नहीं देते हैं। प्रति संघ आय-व्यय की राशि बहुत कम पायी जाती है।

4. श्रमिकों की प्रवास-प्रवृत्ति—हमारे देश में आज भी स्थायी औद्योगिक श्रमिक-वर्ग का अभाव पाया जाता है। हमारे अधिकांश श्रमिक देहाती के रहने वाले होते हैं जो रोजगार पाने के लिए नगरों में चले आते हैं और पुनः अवनिर पाकर अपने गावों में लौट जाते हैं। ये लोग श्रमिक-संघों में विशेष रुचि नहीं रखते।

5. अवकाश का अभाव शिक्षा की कमी—श्रमिकों को कारखाने में इतने अधिक समय तक काम करना पड़ता है कि वे थक जाते हैं। इनको घर पर भी पूरा

भारत में नहीं मिल पाता है। प्रायः उनके घर भी कारखानों से काफी दूर होते हैं। अतएव उनके पास श्रमिक-संघ के कार्यों के लिए पर्याप्त समय, शक्ति व रुचि नहीं होती। शिक्षा के कारण भारत में मजदूर वर्ग संघों के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। इसी कारण बाहरी नेतृत्व का प्रभाव बढ़ जाता है जो श्रमिक-संघों का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उपयोग करते रहते हैं।

6 विविधता—श्रमिकों में जाति धर्म भाषा और क्षेत्र की अनेकता पाई जाती है और वर्ग चेतना का अभाव होता है जिससे उन्हें परस्पर एकता की भावना पैदा नहीं हो पाती।

7 विभिन्न संघों के बीच तथा एक ही संघ में आपसी फूट (Inter union and Intra-union rivalry)¹—प्रायः एक ही उद्योग/या एक ही औद्योगिक इकाई में कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए अलग-अलग श्रमिक संघ पाये जाते हैं जिनमें से कुछ तो नाममात्र के होते हैं और उनके नेतागण सर्वेसर्वा अपने राजनीतिक स्वार्थों की निधि में लगे रहते हैं। इस दशा में सामूहिक सौदाकारी में बाधा पड़ती है। श्रमिक-संघों में आपसी फूट पायी जाती है। प्रायः एक ही उद्योग में विरोधी भावनाओं में विश्वास रखने वाले दो या अधिक संघ होते हैं जो निरन्तर आपस में लड़ा करते हैं। इस प्रकार संघों की अधिकता के कारण मजदूरों के हितों को हानि होती है।

8 बाहरी नेतृत्व तथा राजनीतिक दलों का अभाव—श्रमिक-संघों के नेता अधिकतर वकील या सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें सम्बद्ध उद्योग का तकनीकी व व्यापिक ज्ञान नहीं होता और श्रमिकों के प्रति पूरी सहानुभूति भी नहीं होती। कुछ तो इतने व्यस्त होते हैं कि संघ के कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। कभी-कभी उनके हित भी श्रमिकों के हितों से भिन्न होते हैं। राजनीतिक दलों का श्रमिक संघों पर इतना प्रभाव होता है कि वे श्रमिकों में परस्पर संघर्ष की स्थिति बनाए रखते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए श्रमिक संघों का निरन्तर प्रयोग करते रहते हैं।

9 रखरखाव कार्यों का अभाव—भारत में वित्तीय साधनों के अभाव में श्रमिक-संघ अपने सदस्यों के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा व मनोरंजन आदि के कार्य करके दिलों में सच्ची एकता की भावना उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए मजदूर इनको ज्यादातर हड़ताल-समितियों के रूप में मानते हैं।

1 इंटर-यूनियन स्पर्धा में विभिन्न यूनियनों का आपसी संघर्ष होता है और इंट्रा-यूनियन स्पर्धा में एक ही यूनियन में कई नेताओं का आपसी संघर्ष होता है। इस प्रकार श्रमिक संघ आपसी मतभेद व फूट के अखाड़े बने रहने हैं और इनकी सीमित शक्ति और भी कम हो जाती है।

(भा) बाह्य कारण :

1. भरती का गलत तरीका—हमारे उद्योगों में भर्तियों की भरती एक प्रकार के मध्यस्थ वर्ग द्वारा होती है, जिन्हें सरदार या जॉबर (jobber) कहते हैं। ये लोग प्रायः मजदूर संघों के विरोधी होते हैं क्योंकि मजदूरों पर अपना प्रभाव बनाये रखना चाहते हैं।

2. मातृकी का विरोध—मातृकी भी प्रायः शक्तिशाली भूमि सच से करने रहते हैं। अतएव वे उचित या अनुचित उपायों से भर्तियों में छूट पातों का निरन्तर प्रयोग करते रहते हैं। ये विरोधी संघों को बड़ाबा देने हैं, एवं गुप्तचरों और हड़ताल तोड़ने वालों को नीकर रखकर या भर्तियों को बड़ा-धमका कर उनकी हड़ताले शांत कराते रहते हैं। ये दूनियन के नेताओं की अपनी तरफ करने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसी घटनाएँ बहूबा होती रहती हैं।

3. सरकारी बृष्टिकोण—प्रायः संसार में राजनीतिज्ञ इस भयने द्वारा नियंत्रित संघों को ही बड़ाबा देते हैं। संघों के जिस दल की सरकार होती है, प्रायः उसने मजदूर संघों को ही विशेष रूप से पंगति करने का प्रयत्न मिलता है। यह बृष्टिकोण ही प्रगतिशील भूमि-सच आन्दोलन के मार्ग में बाधक माना जाता है। देश में सुनिश्चित विचारधारा व कार्यक्रमों पर आधारित सीमित दलों के होने से लोकतन्त्र का विकास सही दिशा में हो पाता है। इससे भर्तियों को भी अपनी पसन्द की राष्ट्रीय पार्टी चुनने में सुविधा रहती है।

भारत में मजदूर-संघों की भावों प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव

समाजवादी अर्थव्यवस्था व औद्योगिक लोकतन्त्र की स्थापना एवं सामूहिक सौदागारी के द्वारा भर्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली व जिम्मेदार किम्वं वा भूमि-सच आन्दोलन आवश्यक माना गया है। भारत में एक शक्तिशाली मजदूर-सच आन्दोलन विकास के लिए निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं :

1. एक उद्योग-एक संघ (One industry-one union) का आदर्श अपनाना—एक औद्योगिक इकाई अथवा एक उद्योग में कई परस्पर-विरोधी संघ के होने से मजदूर-आन्दोलन कमजोर पड़ता है और सामूहिक सौदागारी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यह तय नहीं हो पाता कि कौन-सा संघ मातृकी से किसी भी प्रकार पर मजदूरों की तरफ से बातचीत करेगा व समझौता करेगा। हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अथास्तम्भ प्रत्येक औद्योगिक इकाई अथवा उद्योग में एक ही शक्तिशाली भूमि-सच हो। एक औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ होने से भर्तियों के हितों को लाभ होने की बजाय हानि भविष्य होती है। इसलिए एक औद्योगिक इकाई में एक संघ होने से भर्तियों को अधिक लाभ होगा। लेकिन दलगत राजनीति समाप्त किये बिना व्यवहार में यह स्थिति लाना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

संघ बनाना चाहे तो भी उनसे प्रतिनिधियों की एक 'एसेम्बली' आवश्यक बनायी जानी चाहिए जो मालिकों से विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर सके। यह सुभाव सही लगता है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता में संदेह प्रकट किया गया है।

4. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण—श्रमिक संघों के कार्य करने वालों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कॉलेज या अन्य प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इस तरह सरकार को विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए।

5. रक्षणात्मक कार्य—श्रमिक-संघों को अपना कार्यक्षेत्र केवल हड़ताल बनाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और आवास आदि की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

6. समल व शक्तिशाली श्रमिक संघ (Viable Unions)—छोटे-छोटे श्रमिक-संघों को मिलाकर बड़े श्रमिक संघ स्थापित किये जाने चाहिए। श्रमिक-संघों की वित्तीय स्थिति सुधारन के लिए सदस्यों से बराबर योग्यता बढ़ा वसूल किया जाना चाहिए। उद्योगपतियों को भी श्रमिक-संघों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सरकार और मिल मालिकों द्वारा मान्यता मिलने से श्रमिक-संघों की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ती है। प्रतिनिधि श्रमिक-संघों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर मान्यता देना अनिवार्य होना चाहिए।

7. राष्ट्रीय विकास की नीतियों में भाग लेना—मजदूर-संघों को विभिन्न आर्थिक व सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में भाग लेना चाहिए। ऐसा वे विभिन्न संघठनों में भाग लेकर कर सकते हैं, जैसे भारतीय श्रम-सम्मेलन, उद्योगों के विकास परिषदों, औद्योगिक समितियों, उत्पादकता-परिषदों, श्रम-कल्याण बोर्डों, पोर्ट-ट्रस्टों व मजदूरी-बोर्डों आदि संस्थाओं में भाग लिया जा सकता है।

भारत की इक्कीसवीं शताब्दी में प्रगतिशील रूप में प्रवेश दिलाने के लिए मजदूर-संघों को नयी भूमिकाएँ अदा करनी होंगी। मजदूर-संघ आधुनिकीकरण (modernisation) के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण अपना कर अपने सदस्यों को शिक्षित कर सकते हैं। आधुनिकीकरण से लागत, माल की किस्म व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन प्रारम्भ में कुछ बेरोजगारी भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मजदूरों के पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें रोजगार की नई दिशाओं में भेजा जा सकता है। अतः इन सबके बारे में पर्याप्त अध्ययन करवाये जाने चाहिए। मजदूर-संघों को श्रम की प्रवृत्ति में साझेदारी को साकार रूप देने में मदद देनी चाहिए। इन्हें औद्योगिक सुरक्षा (safety) पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में भोपाल गैस जैसी दुर्घटनाएँ रोकी जा सकें।¹

1. B. N. Datar, Into the 21st Century : Task for Trade Unions, an article in the Economic Times, May 22, 1986.

8 **भार-सघीय व एक सघीय स्पर्धा व फूट को दूर करना चाहिए**—सघो में आपसी फूट से श्रमिक आन्दोलन काफी कमजोर हो जाता है। अतः सघो की सहायता कम करके आन्दोलन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, एक औद्योगिक इकाई के विभिन्न सघो के प्रतिनिधियों को शामिल करके सघो की एक ऐसेम्बली बनायी जानी चाहिए। विभिन्न इकाइयों के सघो की ऐसेम्बली के प्रतिनिधियों को मिलाकर राज्यीय स्तर पर एक उद्योगवार श्रमिक-सघ ऐसेम्बलन बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न सघों के बीच आपसी सहर्ष व टकराव का क्षेत्र काफी कम किया जा सकता है।

9 **विकास-परिपदों को सक्रिय बनाना**—लोकतन्त्र में मजदूर-सघो सहकारी संस्थानों, धाम-कल्याणों एवं अन्य ऐकिक संगठनों का बड़ा महत्व होता है। मजदूर-सघ आन्दोलन को नयी दिशाओं में विकसित किया जाना चाहिए। उद्योगों की विकास-परिपदों को सक्रिय बनाना चाहिए।

जब उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम 1951 में बनाया गया था तब विकास-परिपदों के द्वारा धम व प्रबन्ध की तरफ से सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व की भांजा की गयी थी। इनके माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये जाते थे। लेकिन हमारे देश में विकास परिपदों ने सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया है। मजदूर-सघो को सामाजिक हित में उपयुक्त संगठनों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

10. **सार्वजनिक उद्योगों में मजदूर सघों को उद्योग की विनियम-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए**—ये इनके प्रबन्ध, नीति-निर्धारण व धम-कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों में भाग ले सकते हैं और निजी उद्योगों के लिए अनुकरणीय व उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

11 **अन्य क्षेत्र जिनमें मजदूर-सघो को अधिकारि भाग लेना चाहिए, वह है श्रमिकों की योग्यता व प्रशिक्षण में सुधार करना और धम-कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को पूर्णतया श्रमिकों का ही क्षेत्र बनाना। श्रमिकों की शिक्षा में व्यावसायिक, प्राविधिक व सामान्य तीनों प्रकार की शिक्षा का विकास किया जाना जरूरी है।**

12 **भारत में श्रमिकों का अभाव दूर करने के लिए मजदूर-सघो को पर्याप्त साधन उपलब्ध करने के उपाय ढूँढे जाने चाहिए। यदि प्रमुख मजदूर-संगठन एक राष्ट्रीय धम-प्रतिष्ठान स्थापित करें तो रचनात्मक कार्यों के लिए योजनाओं में धन-राशि की व्यवस्था की जा सकती है। भारत में एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली, जागरूक व जिम्मेदार मजदूर-सघ आन्दोलन के विकास की आवश्यकता है। इसमें राष्ट्रीय संगठनों को महत्वपूर्ण भाग लेना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, देश में कई प्रकार के राजनीतिक दलों के बन जाने से श्रमिक-सघ आन्दोलन काफी अस्त-व्यस्त, दिशाहीन व अनिश्चित किस्म का हो गया है।**

भारत में आज भी एक सबल मजदूर-मंच-आन्दोलन की आवश्यकता बनी हुई है जो एक तरफ श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सके और साथ ही देश में लोकतन्त्र की जड़ें भी मजबूत कर सके। देश में एक ऐसा श्रमिक संघ आन्दोलन विकसित किया जाना चाहिए जो लोकतन्त्र के सच्चे प्रहरी का काम करे और इस पर भरोसा करते ही उसका डटकर मुकाबला कर सके। इस दिशा में तेज गति से प्रगति करने के लिए सरकार, मिल-मालिकों, श्रमिकों तथा जनता के दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन लाया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वे दिन अब बीन गये जब मजदूर-यूनियन हड़ताल करने का साधन-मात्र होते थे। अब इनके कंधों पर नयी जिम्मेदारियाँ आ गयी हैं। इन्हें माधुनिकीकरण, श्रम की प्रवर्धन में साझेदारी, रोजगार-संवर्धन नीतियों, औद्योगिक सुरक्षा व देश की तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए प्रयत्न प्रयास करना होगा। सभी ये श्रमिकों व देशवासियों को लाभ पहुँचा सकेंगे। इसलिए मजदूर-संघ के कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए एवं इनका दृष्टिकोण रचनात्मक, व्यापक व प्रगतिशील होना चाहिए।

ट्रेड यूनियन व औद्योगिक विवाद (संशोधन) बिल, 1988 में मजदूर संघों को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में प्रमुख धाराएं—

यह एक बिल का विषय है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के चार दशक बाद भी मजदूर-संघों के संगठन व प्रतिनिधित्व में पर्याप्त सुधार नहीं आया है। 1988 के ट्रेड यूनियन व औद्योगिक विवाद (संशोधन) बिल में इस विषय में निम्न सुझाव दिये गये हैं—

(i) भावेदन के 60 दिनों में श्रमिक संघ का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए।

(ii) श्रमिक संघों में परस्पर विवादों का हल समझौते से अथवा श्रम-अदालतों के पंचनिर्णय से होना चाहिए। सदस्यता का सत्यापन श्रम अदालतों को करना चाहिए। चेक-ऑफ व्यवस्था के अन्तर्गत सत्यापन के लिए गुप्त मतदान भी किया जा सकता है। चेक-ऑफ में प्रत्येक श्रमिक प्रवर्धकों को यूनियन की अपनी पसंद बता देगा तथा उसका चन्दा मजदूरी में से काट लिया जायगा। श्रम-अदालतें सर्टिफाई करेंगी। इससे श्रमिक-संघ मजबूत होंगे।

(iii) सामूहिक सौदाकारी एजेंट/परिषद—इनमें यूनियनों का प्रतिनिधित्व उनकी सदस्यता के आधार पर दिया जायगा। इसके लिए तीन वर्ष की अवधि होगी।

(iv) कोई सात सदस्य यूनियन बना सकते हैं। 100 श्रमिकों से ऊपर की स्थिति में एक यूनियन में न्यूनतम सदस्यता की शर्त 10% होगी ताकि अनेक मजदूर संघ न बनें।

औद्योगिक विवाद (Industrial Disputes)

प्रत्येक देश में वहाँ की सरकार औद्योगिक शान्ति बनाय रखने का प्रयास करती है जिससे एक तरफ मालिकों व मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके और दूसरी तरफ समाज को औद्योगिक अशान्ति के कारण आर्थिक क्षति न पहुँचे। राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा देश के आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करती है और हस्तक्षेप का ठग देश की राजनीतिक प्रणाली और लोगों की सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं पर निर्भर किया करता है। भारत जैसे विकसित देश के लिए औद्योगिक शान्ति का विशेष रूप से महत्व है क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता उत्पादन बढ़ाने की है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनाने के कारण औद्योगिक विवाद निपटाने के लिए हमें समझौता व पंच-निर्णय आदि का ही विशेष रूप से सहारा लेना होता है।

भारत में सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से भी औद्योगिक शान्ति का रहना आवश्यक है। इस प्रकार निरन्तर उत्पादन-वृद्धि व देश की सुरक्षा के लिए औद्योगिक शान्ति का रहना आवश्यक माना गया है।

विवाद (dispute) की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि इसमें किसी उत्पादन की इकाई में श्रमिकों का एक समूह अथवा सभी श्रमिक अल्पकाल के लिए काम रोक देते हैं अथवा मालिक अल्पकाल के लिए कारखाने के ताला लगा देते हैं। इस प्रकार 'हड़ताल' व 'तालाबंदी' दोनों ही 'विवाद' या 'झगड़ों' की परिभाषा में शामिल होते हैं। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप, सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन या कच्चे माल के अभाव अथवा मशीनों के टूट जाने व बिजली की सप्लाय के विफल हो जाने के फलस्वरूप काम रुक जाने से उत्पन्न स्थिति औद्योगिक विवाद में शामिल नहीं मानी जाती।

औद्योगिक विवादों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ

द्वितीय महायुद्ध की अवधि में औद्योगिक विवादों से काम के दिनों की विशेष क्षति नहीं हुई थी। इन वर्षों में वस्तुओं के मूल्य बढ़े, लेकिन साथ में मजदूरी भी बढ़ा। अतः मजदूरों का असन्तोष नहीं बढ़ पाया था। इन्हीं वर्षों में भारत सुरक्षा कानून (Defence of India Rules) अथवा DIR की धारा 81-A का हड़तालों का दमन करने में प्रयोग किया जा सकता था। इसलिए मजदूर असन्तुष्ट होने पर

भी शांत बैठे रहे। महायुद्ध के वर्षों में औद्योगिक सम्बन्ध ठीक न बने रहे, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही मजदूरों ने अपनी स्थिति सुधारने और मजदूरी बढ़वाने के लिए हड़तालें चालू कर दी जिससे 1946 व 1947 में काफी श्रम-दिनों की हानि हुई। बाद में भी औद्योगिक विवादों से श्रम-दिनों की व उत्पादन की हानि होती रही।

जून 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद औद्योगिक विवादों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई और मार्क्सवादी संघों में हड़ताल से होने वाली श्रम दिनों की हानि बहुत कम हो गयी थी। लेकिन इसी अवधि में मालिकों की तरफ से तालाबन्दी, जबरन छुट्टी या मजदूरों की छुट्टियों के कारण निजी क्षेत्र में श्रम दिनों की काफी क्षति हुई। 1977 व 1978 के वर्षों में औद्योगिक सम्बन्धों पर आपातकालीन स्थिति की समाप्ति का प्रभाव पड़ा और पहले के जबरन अनुशासन के समाप्त होने के बाद हड़तालों, प्रदर्शनों, धमकियों व घेरावों का ताता-सा लग गया। शुरू में न्यूनतम वोलनस व अनिवार्य जमा-राशि के अधिनो की लेकर औद्योगिक विवाद खड़े किये गये। 1979 में हड़तालों व तालाबन्दियों से 439 लाख श्रम-दिनों की हानि हुई जो अपने आप में एक रिकार्ड था।

पिछले वर्षों में औद्योगिक विवादों तथा उनके होने वाली क्षति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

वर्ष	विवादों की संख्या	शामिल श्रमिक (लाखों में)	श्रम दिनों की हानि (लाखों में)
1982	2483	14.7	746
1983	2488	14.6	469
1984	2094	19.5	560
1985	1755	10.8	292
1986	1892	16.5	327
1987	1199	12.5	206

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1982 में थर्म-दिनो की क्षति 746 लाख को पार कर गई। इसमें अधिकांश थर्म-दिनो की क्षति वम्बई कपड़ा उद्योग में हड़ताल के कारण हुई जो काफी लम्बी अवधि तक चली थी। 1983 में थर्म-दिनो की हानि पिछले वर्ष से तो कम रही लेकिन 1981 से अधिक थी। 1984 में पुनः थर्म-दिनो की हानि बढ़ी लेकिन बाद में यह कम हुई। 1987 में 206 लाख थर्म-दिनो की हानि का अनुमान पेश किया गया है। औद्योगिक विवादों से मजदूरी की हानि व उत्पादन की हानि होती है जिससे मजदूरी के अलावा समाज को भी क्षति पहुँचती है। औद्योगिक विवाद आज के औद्योगिक जगत को काफी हानि पहुँचा रहे हैं।

औद्योगिक विवादों के प्रमुख कारण :

पूँजीव दी अर्थ-व्यवस्था में मालिकों व मजदूरों के हितों में परस्पर विरोध होने से वर्ग-संघर्ष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मालिक अधिक मुनाफा चाहते हैं और मजदूर अधिक मजदूरी चाहते हैं। मालिकों की मनोवृत्ति प्रायः कम मजदूरी देकर अधिक मुनाफा कमाने की होती है। थर्म उत्पादन का एक साधन-मात्र माना जाता है। मालिकों का मजदूरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण न होकर केवल आर्थिक दृष्टिकोण ही रहता है। इस परिस्थिति में औद्योगिक विवादों व अशांति का पाया जाना स्वाभाविक है।

औद्योगिक विवादों के उपर्युक्त आधारभूत कारणों के अलावा अन्य कारण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे मजदूरी व बोनस के प्रश्न, काम के घण्टे, छुट्टियों की मांग, उद्योग का आधुनिकीकरण, मजदूरों की छँटनी व मजदूरों को पुनः काम पर लगाये जाने की मांग, आदि। कभी-कभी राजनीतिक कारणों से ही हड़तालें हो जाती हैं। लेकिन औद्योगिक विवादों में प्रमुख कारण मजदूरी से ही सम्बन्धित होते हैं। भूतकाल में बोनस व कर्मचारियों के प्रश्नों को लेकर भी औद्योगिक विवाद होते रहे हैं।

औद्योगिक विवादों का कारणों के अनुसार विश्लेषण

भारत में औद्योगिक विवाद कई कारणों से होते हैं, जैसे मजदूरी व मत्ते, बोनस, कामिंग व छँटनी, छुट्टी व काम के घण्टे, अनुशासनहीनता व हिंसा आदि।

लगभग 1/3 विवाद मजदूरी, मत्ते व बोनस के प्रश्नों को लेकर होते हैं। दूसरा स्थान कर्मचारियों व छँटनी के प्रश्नों को लेकर होने वाले विवादों का आता है। लगभग 1/5 विवाद इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। तीसरा स्थान अनुशासन-हीनता व हिंसा के कारण होने वाले विवादों का पाया गया है।

1987 में मजदूरी व भत्ते के कारण लगभग 26% विवाद हुए, कामिक व छुट्टी के कारण 16% हुए, अनुशासनहीनता व हिंसा के कारण 16% हुए तथा शेष 41% बीनस, छुट्टी व कार्य के घंटों तथा अन्य कारणों से हुए। अन्य वर्षों में भी प्रायः इसी प्रकार के कारणों से औद्योगिक विवाद होने रहते हैं।¹

1987 में औद्योगिक विवादों से सबसे ज्यादा क्षम-दिवसों की हानि पश्चिमी बंगाल को हुई (84 लाख क्षम-दिवस) एवं दूसरा स्थान तमिलनाडु का था (23.7 लाख क्षम-दिवस)।

जितने भी औद्योगिक विवाद होते हैं, उनमें कुछ सफल होते हैं, कुछ प्राणिक रूप से सफल होते हैं एवं कुछ असफल होते हैं। जो भी हों, औद्योगिक विवादों से उत्पादन को भारी क्षति होती है और इसे खपामन्त्रव रोका जाना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्धों में निरन्तर सुधार की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

औद्योगिक विवादों में मालिकों व मजदूरों की भूमिका

भारत में मिल-मालिक हड़तालों के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। लेकिन यह पूर्णतया सही नहीं है। यदि मजदूर सभ में कोई मजदूर विरोध दिलावर्ती 'दस्तावा है तो उसे मालिक काम से घटाय कर देने हैं। परिणाम-स्वरूप वह 'बाहरी व्यक्ति' (Outsider) बन जाता है। भूत मालिकों का प्रसहानु-भूतिपूर्ण व्यवहार व उनकी दमन नीति भी मजदूरों में प्रसन्नता के लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार औद्योगिक प्रशान्ति के अनेक कारण हो सकते हैं। समस्त औद्योगिक बानावरण को ही कुछ सीमा तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। औद्योगिक विवाद केन्द्रीय व राज्यीय क्षेत्र एवं मालिकता व निजी क्षेत्र मनी में पाये जाते हैं। इस प्रकार यह समस्या विभिन्न स्तरों पर पायी जाती है।

अनेक कामकाज में हिंसा, सम्पत्ति की लूट करने, मोटरगाड़ियों को जला डगन, टेलीफोन के तार काटने तथा विरोधियों को हत्या कर डालने की घटनाएँ धर्म अगति का एक अनिवार्य अंग बन गई थीं, जो एक अग्रगण्य दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूर नेताओं में एक ऐसा नया वर्ग उन्मूल हो गया है जो सम्पत्ति के लोभ पर एवं मामूली प्रशनों पर विज्ञान प्रदर्शन करने/कराने की कला में काफी दक्ष व निपुण हो गया है। यदि औद्योगिक उत्पादन को नियमित रूप में आगे बढ़ाता है तो केन्द्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि कानून व व्यवस्था की

1. Ibid pp 162-163

स्थिति पर शीघ्र नियन्त्रण स्थापित करें तथा श्रम-सम्बन्धी अनुशासनहीनता को समाप्त करें। इसके लिए औद्योगिक सम्बन्धों के कानून में उचित संशोधन किया जाना चाहिए जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हो और जो श्रमिकों की उचित मांगों को समझ सके तथा अनुचित व अव्यक्त मांगों पर कठोरतापूर्वक नियन्त्रण रख सके।

इस सम्बन्ध में मालिक, मजदूर, राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारियों तथा आम जनता—सभी के दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हिमा के मार्ग का अवश्य परित्याग किया जाना चाहिए अन्यथा देश गम्भीर संकट में पड़ जायगा। जनता सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धों पर एक विधेयक (Bill) तैयार किया था, लेकिन मजदूर संघों ने उसका तीव्र विरोध किया। बाद में केन्द्र में कांग्रेस (आई) की सरकार बनने पर यह रुका गया कि सरकार औद्योगिक सम्बन्धों पर कोई व्यापक विधेयक नहीं लाना चाहती बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA) में ही कुछ संशोधन करना चाहती है ताकि औद्योगिक सम्बन्धों में निकट भविष्य में सुधार हो सके।

औद्योगिक विवादों को रोकने व निबटाने की पद्धति :

ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, 1929 (Trade Disputes Act, 1929) औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए 1929 में निमित्त २९९ कानून के द्वारा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य उद्योगों में भेद किया गया था। सार्वजनिक लाभ के कार्यों, जैसे रेल, डाक-तार, बिजली व पानी आदि में हड़ताल से पूर्व 14 दिन की अग्रिम सूचना देना अनिवार्य किया गया था। अन्य उद्योगों के लिए विवादों को निबटाने हेतु एक निश्चित मशीनरी घोषित की गई। अस्थायी जांच-अदालतों (Adhoc Courts of Enquiry) व समझौता-बोर्डों (Boards of Conciliation) को स्थापित करने की व्यवस्था की गई। जांच अदालत में एक या अधिक स्वतन्त्र व्यक्ति होते थे जो अपनी रिपोर्ट पेश करते थे। समझौता-बोर्ड का काम दोनों पक्षों को एक-दूसरे के समीप लाना और परस्पर समझौता कराना होता था और इसमें सफलता मिलने पर सरकार को सूचना देनी पड़ती थी।

ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, 1929 ने अनिवार्य-पंच-नियंत्रण (Compulsory arbitration) की व्यवस्था नहीं की थी। इसके अन्तर्गत विरोधी दलों में समझौता करने की ही कोशिश की जाती थी। इस अधिनियम के अनुसार उन हड़तालों व तालाबन्दियों को गैर-कानूनी घोषित किया गया जिनका उद्देश्य औद्योगिक विवादों के अलावा कुछ और होता था, अथवा जो समाज के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती थी।

इस अधिनियम से विशेष लाभ नहीं हो सका, क्योंकि व्यवहार में जाच पर ज्यादा जोर दिया गया और समझौता-बोर्ड कम स्थापित किये गए। इनमें स्थायी औद्योगिक अदालत के लिए भी व्यवस्था नहीं की गई थी।

बम्बई राज्य औद्योगिक विवादों को निवटान के कानूनों की दृष्टि से सभी राज्यों से आगे रहा है। इस राज्य में इस सम्बन्ध में कई बार कानून बनाये गये। मानिकों द्वारा श्रम-संधि को मान्यता देने की व्यवस्था की गई। मुरु में समझौते पर जोर दिया गया और बाद में 1946 के विधान में अनिवार्य-पंच-निरणय की व्यवस्था की गई। बम्बई के कानून ने एक वृहद् अखिल भारतीय कानून के लिए मर्म साध दिया था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)—यह फरवरी, 1947 में पारित किया गया था। इसमें निम्न सस्थाओं की व्यवस्था की गई थी :

(अ) कार्य-समितियाँ (Works Committees)—प्रत्येक कारखाने में जहाँ 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ एक कार्य-समिति बनाई जाती है जो मानिकों व मजदूरों के दैनिक मतभेदों को दूर करने में मदद देती है।

(आ) समझौता अधिकारी (Conciliation Officers) नियुक्त किये जाते हैं जो मानिकों व मजदूरों के बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं।

(इ) समझौता-बोर्ड व जाँच-अदालतें (Conciliation Boards and Courts of Enquiry) स्थापित की जाती हैं।

(ई) स्थायी औद्योगिक न्यायालय (Permanent Industrial Tribunals) इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। यदि समझौता अधिकारियों व बोर्डों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो मामला औद्योगिक न्यायालय को सौंप दिया जाता है। सरकार इन न्यायालय का निर्णय पूर्णतया प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार इन अधिनियम में अनिवार्य पंच-निरणय की व्यवस्था की गयी है।

1947 के अधिनियम में अनिवार्य पंच-निरणय को अपनाकर सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया, क्योंकि इससे मजदूरों का हटाना करने का अधिकार छीन लिया गया। औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए ऐच्छिक समझौतों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये तथा मजदूरों को दगा मुहारी जानी चाहिये।

औद्योगिक विवाद (श्रम-अपील-अदालत) अधिनियम, 1950 (Industrial Disputes (Labour Appellate Courts Act, 1950)—इसके अन्तर्गत 'अपील

अदालत' की स्थापना की व्यवस्था की गई जो औद्योगिक न्यायालयों व मजदूरी-बोर्डों के फैसलों पर अपीलें सुनती है। अपील-अदालत की स्थापना आवश्यक हो गई क्योंकि औद्योगिक न्यायालय विभिन्न राज्यों में विरोधी नियुक्त देने लगे थे। 'अपील-अदालत' मजदूरी बोर्ड अच्युटी भुगतान व छूटनी आदि के मामलों पर अपीलें सुनने के लिए बनाई गई थी।

1952 व 1953 में भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व श्री बी बी गिरी ने अपील-अदालत' की स्थापना का विरोध किया था। उन्होंने ऐच्छिक समझौता व ऐच्छिक पंच-नियुक्त' पर काफी बल दिया था। अनिवार्य पंच-नियुक्त का प्रयोग सार्वजनिक उपयोगिताओं (public utilities) के उद्योगों तक सीमित रखने का सुझाव दिया गया था। श्री गिरी ने सामूहिक सौदाकारी (collective bargaining) की नीति पर जोर दिया ताकि मालिकों के संगठन मजदूरों के संगठनों से विचार-विमर्श करके विभिन्न प्रश्नों का हल निकाल सकें।

औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act 1956)—1950 में संसद में एक श्रम-सम्बन्धी विधेयक (Labour Relation Bill) पेश किया गया था लेकिन वह पास नहीं हो सका। इसलिए इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (एम्प्लोमेण्ट व मिस्तेनियस प्रोविजन) एक्ट 1956 में पास किया गया। यह अधिनियम भी 'गिरी-दृष्टिकोण' के अनुसार नहीं था। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं (1) 500 रुपये प्रति माह पाने वाले व्यक्ति 'मजदूर' कहे गये। तकनीकी कर्मचारी व प्रबंध करने वाले कर्मचारी भी इस परिभाषा के अनुसार मजदूर कहलाये। (2) 'श्रम अपील अदालत' समाप्त कर दी गयी। (3) अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रकार की अदालतें व न्यायालय स्थापित किये गये—

(अ) श्रम अदालतें (Labour Courts)—ये छोटे मामलों जैसे मजदूरों को हटाने से सम्बन्धित विवादों हड़ताल की वैधानिकता, आदि मामलों पर फैसला देती हैं।

(आ) औद्योगिक न्यायालय (Industrial Tribunals)—इनके अन्तर्गत मजदूरी काम के घंटे बोर्ड छूटनी व अभिनवीकरण आदि के प्रश्न आते हैं।

(इ) राष्ट्रीय न्यायालय (National Tribunals)—ये राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार करती हैं। इससे अलावा ये उन औद्योगिक उपक्रमों के मामलों पर विचार करती हैं जो एव से अधिक राज्यों में स्थित होते हैं।

इस प्रकार इन तीन संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अनुसार मिल-मालिक मजदूरों को विवाद से असम्बद्ध किसी भी गलत आचरण को करने से रोक सकता है। सरकार को औद्योगिक फैसलों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है।

सरकार ने 5 फरवरी, 1976 को औद्योगिक अधिनियम में मजदूरों के दिनांक दिया था जिसके परिणामस्वरूप 300 या अधिक श्रमिकों को काम पर रखने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जबरन छुट्टी (lay-off), छुट्टी अवकाश कारखाना बंद करने से पूर्व सरकार ने स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया। यह कहा गया कि सरकार की तरफ से दो महीनों में उत्तर नहीं देने पर 'जबरन छुट्टी' की प्रक्रिया चाली जाएगी। यह कदम उत्पादकों द्वारा स्वेच्छा से अपनी औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों का हटाने पर रोक लगाने के लिए उठाया गया था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम ने 1982 व 1984 में मजदूरों के दिनांक है। यह यह 1600 रु. मासिक तक मजदूरों को देने वाले श्रमिकों पर लागू कर दिया गया है तथा 100 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू हो गया है, (पहले 310 या अधिक श्रमिकों वाले इकाइयों पर लागू था)। 1984 में हमने 34 वीं मजदूरों दिया गया था।

अनुशासन संहिता (Code of Discipline)

औद्योगिक विवादों के उत्पन्न होने पर उनको सुलझाना व निवृत्तता प्रदान करना आवश्यक है, उनमें ज्यादा आवश्यक एबी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है जिसमें औद्योगिक शांति बनी रहे और औद्योगिक सम्बन्धों में गंभीर रूप से सुधार हो सके। इस सम्बन्ध में निम्न प्रमुख मराठनीय मान जा सकते हैं—

गौरव से पूर्व भारतीय श्रम-सम्बन्ध के मॉडल, 1985 के मोहरे सम्मेलन में औद्योगिक अनुशासन-संहिता की आवश्यकता की स्वीकार किया गया था। इनके स्वीकार करने में औद्योगिक सम्बन्धों में थोड़ा सुधार हुआ। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—

- (1) श्रमिक व मजदूर एक-दूसरे के अधिकार व कर्तव्यों को पहचानेंगे;
- (2) किसी भी औद्योगिक मामले में एकपक्षीय या ऐच्छिक कार्यवाही नहीं की जाएगी;
- (3) मॉडल के दिनांक हटाना या नालाबन्दी नहीं हो सकेगी; (4) मजदूर-पक्ष के कार्य में श्रमिकों की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा; किसी भी प्रकार की हिंसा, प्रदर्शन, प्रमत्त दबाव, बेदमावत व बहकाने का कार्य नहीं किया जाएगा। मजदूर सम्मति को धर्म नहीं पहुँचाएँगे। वे काम में 'धीमी-गति की नीति' (go-slow policy) नहीं अपनाएँगे, (5) विवादों का निपटार के लिए प्रचलित पद्धति व व्यवस्था का ही उपयोग किया जाएगा तथा श्रमिक समन्वय से मामले तय किए जाएँगे, (6) पक्ष दोनों पर तुरन्त धर्म किया जाएगा।

ध्यान रहे कि उपरोक्त अनुशासन-संहिता कोई कानूनी पत्र नहीं है, वह एक ऐच्छिक व नैतिक आवरण का ही कोड था।

1958 में एक आचार-संहिता (a code of conduct) भी तैयार की गयी जिसके अन्तर्गत विभिन्न मजदूर संघों के परस्पर सम्बन्धों में सुधार करने का प्रयास किया गया। उस समय भारत में चार केन्द्रीय श्रम-संघों थे। उनके लिये आचार-संहिता के निम्न सिद्धान्त अपनाये गये—किसी भी उद्योग में काम करने वाला मजदूर अपनी पसन्द के किसी भी संघ में शामिल हो सकेगा, मजदूर-संघों में नियमित रूप से पदाधिकारियों के चुनाव होंगे मजदूर संघ जातिवाद सम्प्रदायवाद, आदि सकीर्ण दृष्टिकोणों से दूर रहेंगे। वे घास में हिसा व घमकी आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं कम्पनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले मजदूर-संघों का विरोध करेंगे।

औद्योगिक शांति प्रस्ताव (Industrial Truce Resolution)

अक्टूबर 1962 में चीन के हमले के बाद भारत में सर्वत्र देश के हिस्से के लिए प्रत्येक स्तर पर त्याग करने की एक लहर-सी दौड़ गई थी। नवम्बर 1962 में श्री गुलजारीलाल नन्दा की अध्यक्षता में केन्द्रीय श्रम-संघों व मानविकी के संघों की एक सभा बुलाई गयी जिसने देश की सुरक्षा के लिए अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को स्वीकार किया और उसमें एक औद्योगिक शांति-प्रस्ताव भी पास किया गया। उक्त प्रस्ताव के पाँच भाग थे—प्रथम भाग में अधिकतम उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने पर जोर दिया गया। द्वितीय भाग में औद्योगिक शांति स्थापित करने की बात कही गई। तृतीय भाग में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिरिक्त पाली (shift) में काम करने एवं अनुपस्थिति आदि कम करने का महत्व स्वीकार किया गया। चतुर्थ भाग में मूल्य-स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया गया और पाँचवें भाग में बचत बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस प्रस्ताव के स्वीकार करने से 1963 में श्रम-दिनों की हानि बहुत कम हुई थी।

जनता सरकार की औद्योगिक सम्बन्धों के लिए नीति

जनता सरकार (1977-79) ने भी औद्योगिक शांति को देश के पार्थिव विकास के लिए आवश्यक माना था। वह लोकतांत्रिक पद्धति के अन्तर्गत स्वतन्त्र व सुदृढ़ श्रमिक संघ आन्दोलन को विशिष्ट करना चाहती थी। मई, 1977 में केन्द्रीय श्रम-मन्त्री ने एक त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन बुलवाया जो पिछले छ वर्षों में स्थगित पड़ा था। इसमें विभिन्न श्रम-असत्यामियों पर विचार किया गया। इस प्रसार त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन को पुनः चालू किया गया।

सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धों पर एक व्यापक कानून बनाने का भी निर्णय किया था और इस पर सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। सामूहिक मोदकारी के लिए मजदूर-संघों को मान्यता देने तथा उनके पजीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया। सरकार ने 18 अगस्त, 1977 को § 33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस के निर्णय की घोषणा की और इसकी अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत रखी गई।

ट्रेड यूनियन व औद्योगिक विवाद (समीक्षण, बिल) 1988:—

इसके अन्तर्गत औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान रखे गये हैं:—

(i) केन्द्र व राज्यों में औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (Industrial Relations Commissions) (IRCs) स्थापित किये जायेंगे जो अम-प्रदातता के अन्तिम प्रादेशों पर जपीने सुनेंगे।

(ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम की अवहेलना करने पर बड़ी सजा दी जायेगी। से-माफ, छुटनी, लॉक-आउट, (तालाबन्दी) बन्द (closure) के गैर-कानूनी होने पर बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। लॉक-आउट का नोटिस 14 दिन का पब्लिक नोटिफिकेशन (जल-सप्लाई विच्छेद, आदि) की इकाइयों में देना होगा। लेकिन हिंसा व दलित का भय होने पर नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। अविध्य ने तालाबन्दी घोषित करना सुगम नहीं होगा।

(iii) सामूहिक नौदाकारी एजेंट अम-प्रदातता में हड़ताल/तालाबन्दी की की बचना के बारे में पता कर सकता है जिसका उत्तर 15 दिन में देना होगा। अमिक अपनी छुटनी बर्गरह के मामले सोचें अम-प्रदातता में ले जा सकेंगे, या वह मामला समन्वित-मशीनरी से उठा सकता है। समन्वित 6 महीने तक लागू माना जाता है। (वर्तमान विधान में), अब इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। एवार्ड भी 3 वर्ष तक लागू की जा सकती है (एक-एक वर्ष तक बढ़ाकर) (एक से तीन वर्ष तक)

धारा है इस समीक्षण बिल के पास होने से औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने में मदद मिलेगी।

भारत में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव

1. अमिकों की प्रवृत्ति व पूंजी में सामेदारी—भारत में मजदूरों की ओर से प्रवृत्ति में नाण लेने के निदान को स्वीकार किया गया है। कुछ प्रतिष्ठानों में मयुक्त प्रवृत्ति परिषदें (Joint management councils) काम कर रही हैं। अभी तक इनके बाधों में समानता नहीं आ पाई है। इन परिषदों को अधिक मक्ति व सकल बनाना जाना चाहिए। यदि मालिक व मजदूर दोनों मयुक्त प्रवृत्ति परिषदों के सहित व समान तो प्रवृत्ति में अमिकों की सामेदारी के विचार को अधिक प्रभाव व व्यवहार रूप दिया जा सकता है।

समाप्ति औद्योगिक शांति के लिए अमिकों को उद्योग की मेयर-पूँजी में जो हिस्सा दिया जा सकता है, जैसा कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड आदि योरोपीय देशों में किया गया है। इनमें निजी क्षेत्र में धार्मिक सत्ता के केन्द्रीकरण को कम करने में भी मदद मिलेगी। 10 जुलाई, 1985 को भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि निजी नियमित क्षेत्र को चाहिए कि वह नए पूँजी-निर्माण में मेयरों का कम से कम 5% अंश अपने अमिकों व स्टॉक को प्रदान करे। साथ में वेतन-वृद्धि में जुड़ी

परिवर्तनीय ऋणपत्र-योजना भी लागू की जायगी जिससे कम्पनी के कर्मचारियों को लाभ होगा। अक्टूबर, 1987 में कोल इण्डिया लि (CIL) तथा इसकी सहायक इकाइयों में श्रमिक संचालक नियुक्त करके प्रबन्ध में कर्मचारी-सहभागिता की स्कीम लागू की गयी है।

सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन—सामूहिक विचार-विमर्श व समझौते की नीति को अपनाने से औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा। इसके लिए श्रमिकों की एक प्रतिनिधि सौदाकारी एजेंसी निश्चित करनी होगी। जहाँ मजदूरों के कई सघ पाये जाते हैं वहाँ भी इस प्रकार की एजेंसी अवश्य होनी चाहिए। यथा-सम्भव "एक औद्योगिक इकाई या प्रतिष्ठान में एक सघ" की नीति अपनायी जानी चाहिए। लेकिन इसके मार्ग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना होगा। यदि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम में एक से अधिक श्रमिक सघ हों तो मालिकों से सामूहिक सौदाकारी करने के लिए विभिन्न सघों के प्रतिनिधियों की एक एसेम्बली/सभा बनाई जा सकती है जो श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। आज भारत में एक सघ व स्वस्थ मजदूर-सघ आन्दोलन की आवश्यकता है। न्यूनतम मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम-कल्याण कार्यों के विस्तार से मजदूर-वर्ग को अधिक सन्तोष प्राप्त होगा और वह उत्पादन बढ़ाने में अधिक सहयोग दे सकेगा।

3 मालिकों व मजदूरों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन—उद्योगपतियों व श्रमिकों के सम्बन्धों का प्रश्न अत्यन्त जटिल व गहरा रहा है। साम्यवादी दृष्टिकोण से देखने पर यह एक राजनीतिक व्यवस्था के चुनाव का प्रश्न बन जाता है। इसलिए वे धर्म-मर्ष को बढ़ाकर इसे समाजवाद की स्थापना तक ले जाना चाहते हैं। हमने भारत में मिश्रित-प्रत्यवस्था की स्वीकार की है जिसमें निजी उद्यम को औद्योगिक क्षेत्र में उचित स्थान दिया गया है। अतः उद्योगपतियों को काम करने का समुचित अवसर व वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ में उन्हें भी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए और उत्पादन-प्रणाली में 'श्रम' को उचित स्थान व आदर देना चाहिए। श्रम को प्रबन्ध व लाभ में भाग देने से औद्योगिक जगत का वातावरण बदल सकता है। सांसेजनिक उद्योगों को इस सम्बन्ध में 'आदर्श' उपस्थित करने चाहिए जो निजी क्षेत्र में भागे जाकर अपनाये जा सकें। श्रमिकों तथा उसके नेताओं को अपने 'हड़ताली दृष्टिकोण' व 'राजनीतिक व्यवहार' का बदलना होगा और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना होगा।

4 ऐच्छिक समझौते व पंच निर्णय की आवश्यकता—लोकतान्त्रिक पद्धति को अपनाने के कारण भारत को समझौते व ऐच्छिक पंच-निर्णय एवं आपसी विचार-विमर्श की नीति का पालन करके ही औद्योगिक शांति की दिशा में प्रयास करने होंगे,

लेखित समय-समय पर अनिवार्य पत्र-निर्णय भी आवश्यक हो सकता है। अतः हमें परिस्थिति के अनुसार औद्योगिक विवाद को निबटाने की पद्धति का चुनाव करना चाहिए।

5 मजदूरी, बोनस उत्पादकता व औद्योगिक शान्ति के प्रश्न परस्पर एक-दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। अतः इन पर व्यापक व समशील नैति की शीघ्र आवश्यकता है।

म रत म औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए उत्पादकता से जुड़ी बोनस (productivity-linked bonus) रेतवे कर्मचारियों, डाक, व तार विभाग के कर्मचारियों सुरक्षा, प्रतिष्ठानों आदि में लागू की गई है। सरकार ईसा, धोमी गति से काम गैर कानूनी हड़ताल, गैर-कानूनी तालाबन्दी, आदि को रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि इनसे उत्पादन को हानि होती है।

औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए अन्य सुझाव

1 मालिकों व मजदूरों के सम्बन्धों का मामला द्विपक्षीय (bipartite) मामला होता है। इनमें आपस के हितों का विरोध होता है तथा परस्पर वर्ग संघर्ष तथा शक्ति-संघर्ष पाया जाता है। सामूहिक सौदाकारी ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विरोधी हितों में आवश्यक समझौता करके किसी आम सहमति के बिन्दु तक पहुँचा जाता है। अतः सच्ची सामूहिक सौदाकारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। इसके लिए सुदृढ़ व जिम्मेदार किस्म के थमिक-सचों का होना बहुत जरूरी है।

2 थमिकों के लिये सुरक्षात्मक विधान होना चाहिये जैसे—न्यूनतम मजदूरी, कार्य के निश्चित घण्टे, वेतन सहित छुट्टियाँ, काम की न्यूनतम आयु, आदि के सम्बन्ध में कानून होना चाहिए।

3 थमिक-मध्य थमिकों की समस्याओं व आशाओं के प्रति पूर्णतया सजग होने चाहिये। सरकार का योगदान विवादों को सुलझाने में न्यूनतम रहना चाहिए एवं औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (Industrial Relations Commission) स्थापित किया जाना चाहिये जो एक स्वायत्त संस्था हो तथा औद्योगिक सम्बन्धों के विभिन्न विषयों की जाँच पड़ताल करे, ताकि गोरग्राहों का प्रभाव कम किया जा सके।

4 थमिक-सचों के पंजीकरण में बाधा नहीं डाली जानी चाहिये। साथ में अनावश्यक थमिक सचों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। क्वार्टी एजेंट या सौदाकारी एजेंट बनने के लिये मध्य का चुनाव गुप्त मतदान विधि में किया जाना चाहिये।

5 हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा देने में सामूहिक सौदाकारी का धरना बहुत बलवत् है। लेकिन विदेशी व्याकरण व अन्य असाधारण दशाओं में इन पर प्रत्यक्ष रोक

सगानी चाहिये। हिंसा व धमकी के स्थान पर सच्ची व वैधानिक ढंग की सामूहिक सोदाकारी ही औद्योगिक सम्बन्धों को स्थायी रूप से सुधार सकती है।

श्रमिक-संघों के नेताओं की एक शीर्ष संस्था (apex body) बनायी जानी चाहिये जो श्रमिक-संघों के लिये एक आचार-संहिता (Code of Conduct) तैयार करे। इससे औद्योगिक क्षेत्र में हिंसा व अनृणासनहीनता को रोकने में मदद मिलेगी। वे द्रवीय सरकार को चाहिये कि वह आवश्यक उद्योगों व सेवाओं की एक सूची तैयार करे जिनमें हड़तालें न होने दी जायें। इन उद्योगों में वास्तविक शिवायत के मामले में ऐच्छित समझौते प्रथम पक्ष-निर्णय की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिये।

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में किये गये कुछ प्रयास —

1. बीएस भुगतान अधिनियम 1965 में संशोधन करके इसके लिए वेतन की सीमा 1600 रु प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रु प्रति माह कर दी गई है ताकि इन व्यवस्था का अधिक कर्मचारी लाभ उठा सकें।

2. अलबारे के कर्मचारियों को मजदूरी में अन्तरिम राहत छेतिव मजदूरी का 15% तथा न्यूनतम राशि 90 रु प्रति माह के हिसाब से मजूर की गई है। छोटी उद्योग के श्रमिकों को भी अन्तरिम राहत दी गयी है।

3. सरकार का विचार एक औद्योगिक-सम्बन्ध-आयोग स्थापित करने का भी हो गया है।

4. विभिन्न उद्योगों के लिए निदेशीय औद्योगिक समितियाँ स्थापित की गई हैं जिनमें निम्न उद्योग मुख्य हैं रसायन इ.जी.नियरी सूती वस्त्र जूट बानान, सड़क-परिवहन सीमेंट भवन-निर्माण कोयला उद्योग आदि। इससे निदेशीय सलाहकार मशीनरी को सुदृढ़ करने में मदद मिली है।

इन समितियों की बैठकों में औद्योगिक सम्बन्धों श्रमिकों की सुरक्षा व्यावसायिक स्वास्थ्य श्रमिकों की प्रवृद्ध में सांभेदारी व सामाजिक सुरक्षा-स्कीमों आदि के बारे में चर्चा की जाती है जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। आशा है मविध्य में औद्योगिक सम्बन्धों में और सुधार आयेगा।

1982 में सरकार ने एक शिवायत-निवारण-प्राधिकरण (Grievance Settlement Authority) (GSA) की स्थापना की है जिसका उपयोग विवादों को प्रदासता में ले जाने से पूर्व किया जा सकता है।

अव अनुचित श्रम-व्यवहार क्रियाओं (Unfair Labour Practices) के लिए छ महीने तक की बंद या 100 रु जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है तथा रजिस्ट्रार गैर-वानूनी हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूर-संघ का रजिस्ट्रेशन निरस्त (cancel) कर सकता है।

हान में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. तथा माकति लि. का अनुभव है कि मालिकों, व मजदूरों के सम्बन्धों को सुधारन में वक्ता- समितियों' व 'मयुक्त प्रबन्ध परिषदें' महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। माकति उद्योग में 'मरनि परिद्वार' विस्म की सस्कृति विवसित करने का प्रयास किया है, जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों के बीच अन्तर कम किया गया है। कॉमन वस्त्र, कॉमन केन्टीन, आदि के द्वारा कर्मचारियों में भेदभाव कम किया गया है। उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क सृष्ट किए गये हैं। धर्मिकों के लिए दवा, छुट्टियों, आवास आदि की सुविधा बढ़ायी गयी है। इससे काम का नया वातावरण, नए विचार, नया जोश, आदि उत्पन्न हों सके हैं। अविष्य में नई औद्योगिक सस्कृति के विकास की दिशा में प्रयत्न जारी रहने हैं।

प्रश्न

1. भारत में औद्योगिक विवादों के प्रमुख कारण क्या हैं? इन विवादों को सुलझाने के लिये देश में उपलब्ध तन्त्र का परोक्षण कीजिये।

(Raj. Hyr. T. D. C. 1982)



श्रम-कल्याण-कार्य तथा सामाजिक सुरक्षा (Labour Welfare and Social Security)

श्रम-कल्याण-कार्य

आजकल औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर काफी ध्यान दिया जाने लगा है ताकि श्रमिक-वर्गें सन्तुष्ट रहें तथा मन लगाकर काम कर सकें।

विभिन्न देशों में 'श्रम-कल्याण' के अलग-अलग अर्थ लगाये गये हैं। सबसे विस्तृत अर्थ में श्रम-कल्याण में श्रम की सम्पूर्ण परिस्थितियाँ आ जाती हैं और इसमें श्रम-विचार व सामाजिक बीमा भी शामिल माने जाते हैं। परिभाषा के अनुसार "श्रम-कल्याण-कार्य में, मालिकों के वे ऐच्छिक प्रयत्न शामिल होते हैं जो वे प्रचलित औद्योगिक प्रणाली में कानूनों, उद्योगों के रिवाजों व बाजार की परिस्थितियों के अतिरिक्त अपने मजदूरों या फर्मचारियों के काम करने, रहने व सांस्कृतिक दशाओं को प्रभावित करने के लिये करते हैं।" इस परिभाषा में श्रम-कल्याण में मालिकों के 'ऐच्छिक प्रयत्न' ही शामिल किये गये हैं। अतः भारत जैसे देश में श्रम-कल्याण की यह परिभाषा सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ इस सम्बन्ध में वैधानिक व्यवस्था भी की गयी है। रॉयल श्रम आयोग के अनुसार, 'कल्याण' शब्द की परिभाषा लोचदार होनी चाहिए जिससे विभिन्न देशों में वहाँ के सामाजिक रिवाजों, औद्योगीकरण की दशाओं व मजदूरों के जैसाणिक विकास के अनुसार इसके विभिन्न अर्थ लगाये जा सकें।

इस प्रकार, श्रम-कल्याण कार्यों में मालिकों, सरकारों व ऐच्छिक संगठनों द्वारा किये गये वे सब कार्य शामिल होते हैं जिनसे मजदूरों की दशा सुधरती है। ये कार्य कारखानों के अन्दर हो सकते हैं अथवा बाहर हो सकते हैं। ये स्वेच्छा से किये जा सकते हैं अथवा कानून के अन्तर्गत किये जा सकते हैं।

भारत में श्रम कल्याण कार्यों की आवश्यकता

श्रम-कल्याण कार्यों से औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में मदद मिलती है और श्रम की कार्यकुशलता बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ता है। भारत में निम्न कारणों से श्रम-कल्याण कार्यों का विशेष महत्व माना गया है :

1 श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति—भारत में अभी तक अन्य देशों की तरह एक स्थायी ढंग का मजदूर-बर्ग उत्पन्न नहीं हो पाया है। यहाँ के अधिकांश मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने के कारण दिल से किसान होते हैं और प्रवृत्ति मिलने पर गाँवों में वापस जाना चाहते हैं। उनका गाँवों से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होना है इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में उनके लिये भोजन, मकान व मनोरंजन की सुविधाएँ बढ़ाकर पर्याप्त आकर्षण उत्पन्न किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा करने से मजदूर अपने आपकी औद्योगिक बानावरण के अधिक अनुकूल बना सकते हैं।

2 सुदूर स्थानों में कल्याण कार्य आवश्यक—उन बागानों, खानों व अन्य छोटे उद्योगों में, जो एकान स्थानों में स्थित हैं विशेष कल्याण-कार्यों की आवश्यकता होती है। वहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुओं की भी व्यवस्था करनी होती है।

3 श्रमिक संघों का धीमा विकास—भारत में श्रमिक संघों में मजदूरों के कल्याण के लिए अधिक कार्य नहीं किये हैं, इसलिए सरकार व मालिकों द्वारा कल्याण-कार्य करना आवश्यक हो गया है।

4 निम्न जीवन-स्तर—भारतीय मजदूर का जीवन-स्तर बहुत नीचा होता है इसलिए कल्याण कार्यों के द्वारा उनके लिए अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा व चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जाती है। कल्याण-कार्यों के अभाव में उसे सुविधाएँ नहीं मिल पाती।

श्रम-कल्याण में भाग लेने वाली संस्थाएँ व कानूनी व्यवस्था

भारत में श्रम-कल्याण कार्य देश की विधायिक व्यवस्था, केन्द्रीय व राज्य सरकारों के कार्यों, मालिकों की ऐच्छिक नियामकों, मजदूर संघों व अन्य ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये कल्याण-कार्यों पर निर्भर करता है।

श्रम-कल्याण से सम्बंधित कानून

सर्वप्रथम, फ़ैक्ट्री अधिनियम (Factory Act), 1934 में श्रम-कल्याण की व्यवस्था की गयी थी, बाद में 1948 के फ़ैक्ट्री अधिनियम में ये सुविधाएँ बढ़ायी गयीं। इनमें भोजन-गृह, शिशु-गृह, आराम-गृह, नहाने-धोने की सुविधाएँ, प्रारम्भिक सहायता का सामान आदि की व्यवस्था की गयी। इस कानून में मजदूरों के बैठने का इन्तजाम करने के लिये भी जोर दिया गया। श्रमिकों के कपड़े रखने के लिए उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था की गई। 500 या अधिक मजदूरों के कारखानों में कल्याण-प्रधिकारी नियुक्त करना आवश्यक कर दिया गया।

खान-अधिनियम, 1951 में भी खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। जहां स्थिति काम करती है वहां शिक्षा-मृह स्थापित करना आवश्यक बना दिया।

कोयला, अन्नक, कच्चा लोहा, मंगनीज, लाइमस्टोन व डोलोमाइट की खानों व बीड़ी उद्योग में श्रमिकों के आवास, दवा, मनोरंजन व अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए वैधानिक कल्याण क्षेत्र बनाये गये हैं। जिन अधिनियमों के अन्तर्गत ये उद्योग क्षेत्र हैं वे कच्चे लोहे व मंगनीज की खानों के श्रमिकों के लिए 1976 में, लाइमस्टोन व डोलोमाइट खानों के श्रमिकों के लिए 1972 में, कोयले के श्रमिकों के लिए 1947 में अन्नक के श्रमिकों के लिए 1946 में तथा बीड़ी श्रमिकों के लिए (मशोपन) 1981 में पारित हुए थे।

वागान श्रम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत वागान मालिकों को अपने श्रमिकों के लिए मकान व प्रशुताल की व्यवस्था करनी होती है। कई स्थानों पर शिक्षा व मनोरंजन व दस्तकारी की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है।

श्रम-कल्याण में भाग लेने वाली संस्थाएँ

सरकारों द्वारा किये गये कल्याण-कार्य—द्वितीय महायुद्ध के बाद केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने मजदूरों के कल्याण-कार्य में विशेष रूप से रुचि लेना प्रारम्भ किया था। केन्द्रीय सरकार ने खानों व तेल-क्षेत्रों के मजदूर एवं केन्द्रीय कारखानों के मजदूरों के लिए कुछ सुविधाएँ प्रदान की हैं। सिन्दरी खाद के कारखाना चितरजन लोकमोटिव वर्क एव मद्रास की इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री में मजदूरों के लिए मकान भोजनागार व मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। केन्द्रीय सरकार ने रेल-मजदूरों व बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है।

राज्य सरकारें, विशेषतया महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की सरकारें, श्रम-कल्याण कार्य में आगे रही हैं। बम्बई में चार श्रेणी के कल्याण केन्द्र चल रहे हैं। इन केन्द्रों में मनोरंजन, शिक्षा व स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य चलाये जाते हैं।

मालिकों द्वारा किये गये कल्याण कार्य—श्रम-कल्याण कार्य को सुचारु रूप से चलाने में मालिकों का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। भारत में मिल मालिकों को कानून के अन्तर्गत मजदूरों के कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। प्रमादित उद्योगपति कल्याण कार्य पर किता नया व्यवहार कर स्वयं संभलते हैं और इनमें विशेष रुचि नहीं दिखाते। लेकिन कुछ मिल-मालिकों के कार्य इस दिशा में काफी सराहनीय रहे हैं। बकिधम कर्नाटक मिल्स, मद्रास, दिल्ली क्लॉथ व जनरल मिल्स, दिल्ली, एक्सप्रेस मिल्स, नागपुर तथा टाटा आयरन व स्टील कम्पनी, जमशेदपुर ने अपने मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, मनोरंजन आदि की सुविधाएँ प्रदान की हैं। इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन (UMA) कलकत्ता ने श्रम-कल्याण केन्द्र खोले हैं।

कई मिल-मालिकों द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं के स्तर पानूनी आवश्यकताओं से भी काफी अच्छे पाये जाते हैं। आजकन कैंटीन व शिशु-गृह की उचित व्यवस्था पायी जाती है।

मजदूर-सघों द्वारा किये गये कल्याण-कार्य—भारत में मजदूर सघों ने श्रम-कल्याण-कार्यों में विशेष प्रगति नहीं दिखायी है। ग्रहमदाबाद टैक्मेटाइल सेक्टर एमोसियशन ने मजदूरों के लाभ के कई सामाजिक व कल्याण-कार्य किये हैं। मजदूरों के सांस्कृतिक उत्थान के प्रयत्न किये गये हैं। उनके बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी है।

श्रम-कल्याण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव—भारत में श्रम-कल्याण कार्यों में विविधता पायी जाती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में एवं एक उद्योग की विभिन्न इकाइयों में श्रम-कल्याण-कार्यों में काफी अन्तर पाया जाता है। कल्याण-कार्यों की सफलता पर्याप्त वित्तीय स्रोतों व विभिन्न पक्षों के सहयोग पर निर्भर करती है। भारत में श्रम-कल्याण-कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :

(1) फ़ैक्ट्री एक्ट, 1948 की श्रम-कल्याण सम्बन्धी धाराओं का पूरा-पूरा पालन किया जाना चाहिए।

(2) विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के कल्याण-कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे आवास-मजदूरों को विशेषतया मकानों की सुविधा, छान-मजदूरों को मकान, शिक्षा व दवा की सुविधा एवं जहाँ स्त्रियाँ काम करती हैं वहाँ शिशु-गृहों की स्थापना पर विशेष धन दिया जाना चाहिए।

(3) मजदूरों की कल्याण-समितियों में अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि कल्याण-कार्यों में अधिक प्रगति हो सके।

(4) कल्याण-प्रधिकारियों का चुनाव सावधानी से किया जाना चाहिए। इन कार्य के लिए वे व्यक्ति ही लिये जाने चाहिए जो मजदूरों का विश्वास प्राप्त कर सकें और अच्छे प्रशासक हो सकें। उन्हें मजदूरों के कल्याण में वास्तविक रुचि व उत्साह भी होना चाहिए।

(5) कोयले व अभ्रक की खानों के क्षेत्रों की तरह अन्य क्षेत्र भी स्थापित किये जाने चाहिए।

(6) सरकार द्वारा कल्याण-केन्द्रों की संस्था बढ़ायी जानी चाहिए।

(7) मजदूरों की सहकारी समितियाँ बनाई जानी चाहिए और सहकारी आधार पर मकान बनाने तथा साख्त व उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(8) मात्रिको द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं व कल्याण कार्यों को पूर्णतया स्पष्ट किया जाना चाहिए और उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ।

(9) श्रमिक-संघों का भी कल्याण-कार्य में अधिक रुचि दिखानी चाहिए ।

(10) सार्वजनिक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कल्याण कार्यों की उचित व्यवस्था करके निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों व समक्ष आदर्श उपस्थित किया जाना चाहिए ।

भारत में सामाजिक सुरक्षा¹

सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के अन्तर्गत वह सुरक्षा आती है जो एक समाज अपने सदस्यों को जोखिम से बचाने के लिए एक उपयुक्त संगठन द्वारा प्रदान करता है । बीमारी, काम के अयोग्य हो जाना प्रसूती (Maternity) दुर्घटना व मृत्यु आदि जोखिम ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक व प्रत्येक माध्यमों से मुकाबला नहीं कर सकता । अतः समाज का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने सदस्यों को इन जायिमों से बचाए और उनकी आवश्यक मदद करे ।

सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक धारणा है । इसमें सामाजिक बीमा (Social Insurance) और सामाजिक सहायता (Social Assistance) दोनों शामिल होने हैं । सामाजिक बीमा का लाभ उन व्यक्तियों को मिलता है जो इसके लिए प्रीमियम या शुल्क चुकाते हैं लेकिन सामाजिक सहायता निःशुल्क मिलती है । अतः सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा से ज्यादा व्यापक होती है । इसमें दुर्घटना का रोकना व प्रयास किया जाता है । इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक विस्तृत व व्यापक विचार-धारा होती है जो बीमारी को रोकने आदि का समान बटवारा करने एवं समस्त प्रकार की आवश्यकताओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है ।

सामाजिक सुरक्षा की उपर्युक्त परिभाषा व अनुसार इसका क्षेत्र काफी व्यापक बन जाता है । इसके अन्तर्गत एक ओर बेरोजगारी बीमारी एवं दुर्घटना का सामाजिक बीमा आ जाता है तो दूसरी ओर अस्पताल बच्चा के कल्याण एवं दवा की सुविधाएं भी आ जाती हैं जो निःशुल्क उपलब्ध होती हैं । इस प्रकार आधुनिक जीवन के तनावों व शकटों के बीच सामाजिक सुरक्षा ने स्थिरता व सुरक्षा का समावेश किया है । इसके अभाव में जीवन में अस्थिरता बढ़ जाती है और व्यक्ति स्वयं को प्रकृति व अमहाय-सा समझने लगता है । आज यह सार्वजनिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गयी है और इसके प्रचलन की सीमा को देखकर यह अनुमान

1. Report of the National Commission on Labour, 1969, Chapter 13, p. 162-82.

लगाया जा सकता है कि एक दिन में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की दिशा में कितनी प्रगति हो पाई है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की 1923 से प्रगति

भारत में अभी तक सामाजिक सुरक्षा का पूर्वापत्ति विकास नहीं हो पाया है। ब्रिटिशकाल में तो मजदूर-क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 व कुछ प्रसूति लाभ अधिनियम ही सामाजिक सुरक्षा में आते थे। अब प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) बन गया है जिसका वर्णन आगे किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और कर्मचारी प्राविडेण्ड फण्ड व विविध प्रोविजन्स अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी पारिवारिक पेंशन स्कीम 1971 एवं कोयला खान पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1971 आदि और जुड़े हैं। इन अधिनियमों का विवरण व इसके अन्तर्गत हुई प्रगति का उल्लेख नीचे किया जाता है।

1 मजदूर क्षतिपूर्ति-अधिनियम, 1923 (The Workmen's Compensation Act 1923)—स्वतन्त्रता के पूर्व सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजदूर-क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 ही मुख्य अधिनियम माना गया है। इसके अन्तर्गत मालिक को मजदूर के काम करते हुए चोट या जाने सदैव के लिए प्रयोग हो जाना तथा काम करते हुए मर जान पर मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजा औसत मासिक मजदूरी के अनुसार निकाला जाता है और चोट की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। यह उन क्षेत्रों में लागू नहीं होता जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा कार्यक्रम लागू होता है। 1984 तक यह 1000 रुपये तक मासिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों पर लागू होता था जो कारखानों, खानों, बागानों परिवहन व निर्माण रेल व अन्य विशिष्ट प्रकार के जोखिमी कार्यों में लगे होते थे। लेकिन 1984 के संशोधन के बाद अब वेतन की सीमा नहीं रह गई है। अब यह सभी पर लागू हो गया है। मृत्यु हो जाने पर श्रमिक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है जिसकी राशि विभिन्न आयु के मजदूरों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। पहले मुआवजा वेतन से जुड़ा होता था (salary-linked) लेकिन अब यह आयु से जुड़ा (age-linked) हो गया है। (1984 के संशोधन के बाद)। मृत्यु हो जाने पर न्यूनतम मुआवजा 20 हजार रुपये तथा स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने की स्थिति में 24 हजार रुपये होता है।

इतने वर्षों के बाद भी इसका पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है। छोटे उद्यमकर्त्ता व फँवरी के मासिक भारी मात्रा में मुआवजा देने में असमर्थ होते हैं। अधिनियम में चोट लगने पर श्रमिक के लिए दवा के इस्तजाम की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय श्रम प्रायोग ने सुझाव दिया था कि श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए एक केन्द्रीय कोष बनाया जाए जिसमें सभी मिल-मासिक कुल मजदूरों का कुछ प्रतिशत जमा करें। इस पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नियन्त्रण होना चाहिए। यह एक विरोधाभास है कि अयोग्य हो जाने वाला व दुर्घटनाग्रस्त हो जाने वाला

व्यक्ति कठिनाई से अपना मुआवजा ले पाता है, जबकि सरप-स या कालतू घोषित हो जाने वाला व्यक्ति अपना मुआवजा जल्दी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की स्थिति बदली जानी चाहिए।

३. प्रसूति लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act, 1961)—यह अधिनियम उन फैंक्ट्रियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 लागू होता है, प्रत्येक प्रतिष्ठान (फैंक्ट्री, खान या बागान) पर लागू होता है। राज्य इस केन्द्रीय अधिनियम को धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। प्रसूति से पूर्व व पश्चात् कुछ अवधि के लिए स्त्री-श्रमिकों को नकद प्रसूति सहायता व छुट्टी दी जाती है। प्रसूति लाभ 8-12 सप्ताह के लिए दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मेडिकल बोनस भी दिया जाता है। सभी राज्यों में इसे लागू किया जाना चाहिए।

1943 में प्रोफेसर बी पी. अदारकर ने स्वास्थ्य बीमा-योजना तैयार की थी। 1945 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के विशेषज्ञों ने अदारकर योजना की जांच की। इन्हीं के सुझावों के आधार पर बाद में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में पारित किया गया।

3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (The Employees State Insurance Act, 1948)—यह मौसमी उद्योगों को छोड़कर शक्ति का उपयोग करने वाले तथा 20 व अधिक मजदूरों को काम देने वाले अग्र्य उद्योगों (खान व रेलवे रनिंग शेड को छोड़कर) पर लागू होता है। अब यह 1,600 रु तक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों पर लागू कर दिया गया है। यह बीमारी, प्रसूति व रोज-गार छोट के लिए नकद सहायता प्रदान करता है और रोजगार छोट से मर जाने वाले अभिभावकों के लिए पेन्शन के रूप में भुगतान करता है तथा श्रमिकों को चिकित्सा का लाभ प्रदान करता है।

शुरू में यह योजना 1952 से कानपुर व दिल्ली में लागू की गई थी। विभिन्न लाभों का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है :

(अ) बीमारी लाभ—बीमारी के दिनों में अधिकतम 56 दिनों के लिए बीमा कराये हुए व्यक्ति की मजदूरी का लगभग आधा भुगतान दिया जाता है। क्षय, कोढ़, मानसिक व अन्य बीमारियों की स्थिति में 309 दिनों के लिए बीमारी की वजह से निवृत्त सहायता मिलती है।

(आ) प्रसूति लाभ—यह 12 सप्ताह के लिए 75 पैसे की फ्लैट रेट प्रतिदिन के अनुसार अथवा बीमारी के लाभ के दुगुने के रूप में, जो भी अधिक हो, के अनुसार दिया जाता है।

(इ) अयोग्यता लाभ—यह अस्थायी व स्थायी, आंशिक या कुल अयोग्यता के लिए अलग-अलग होता है।

(ई) प्राथितो को प्राप्त होने वाला लान—यह मर जाने वाले व्यक्ति के प्राथितो को दिया जाता है।

(उ) चिकित्सा लान—इसमें श्रमिक व उनके प्राथितो को (जहां प्राथित शामिल किए गए हैं) चिकित्सा के लाभ दिये जाते हैं।

31 दिसम्बर, 1986 का 90 ESI अस्पताल व 42 ESI सहायक अस्पताल (Annexes) व जिनमें 23 251 विस्तर, 1214 दवाखाने थे। इनके अन्तर्गत 63 49 लाख कर्मचारी आ चुके थे।¹

इसमें मालिकों का अशदान मजदूरी-बिस का $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा मजदूरी का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत रखा गया है। दवा पर किया गया व्यय ESIC व राज्य सरकार में परम्पर बाटा जाता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सुझाव दिया था कि 4 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अशदान से छूट दी जानी चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अभी तक यह सभी व्यक्तियों व सभी जोखिमों को अपने में शामिल नहीं कर सकी है। भविष्य में इसके अन्तर्गत बेरोजगारी का बीमा या अन्य जोखिमों भी लायी जानी चाहिए।

4 कर्मचारी प्रोविडेंट फण्ड्स तथा विविध प्रोविडेंट्स अधिनियम, 1952 The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952) — यह वस्तुतः एक नवत का कार्यक्रम है। यह अधिनियम प्रारम्भ में 1 नवम्बर 1952 से छ ० उद्योगों पर लागू किया गया था। 31 दिसम्बर, 1986 तक यह 173 उद्योगों में लागू हो चुका था। अधिनियम का उद्देश्य अनिवार्य प्रोविडेंट फण्ड की व्यवस्था करना है ताकि औद्योगिक श्रमिकों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्था की जा सके। श्रमिक की असामयिक मृत्यु के समय उसके प्राथितो को यह राशि मिल जाती है। 1 नितम्बर, 1985 से यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू हो गया है जिनमें 20 या अधिक श्रमिक काम करते हैं। जो श्रमिक एक साल तक लगातार काम कर चुकते हैं और मासिक वेतन 2,500 रुपये तक पते है उन्हें अपनी वैसिव मजदूरी का $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनिवार्य रूप से प्रोविडेंट फण्ड में देना पडना है। ऐसे श्रमिकों के लिए मासिक भी उतनी ही रकम कोष में जमा कराते हैं। सरकार ने 50 या अधिक सख्या में निमुक्त श्रमिकों के 132 उद्योगों में अशदान की दर बढाकर 8% कर दी है।

कोयला खानों, असम चाय-बागानों व समुद्री कर्मचारियों के लिए भी प्राविडेंट कोष अधिनियम अलग से बन चुके हैं।

31 दिसम्बर, 1986 के अन्त तक इस स्कीम के अन्तर्गत 1.36 करोड़ श्रमिक आ चुके थे।

पिछले वर्षों में प्रॉविडेंट फण्ड योजना का काफी विस्तार हुआ है। फिर भी अनेक संस्थान अभी तक इसके अन्तर्गत नहीं आ पाये हैं। कहीं-कहीं प्रॉविडेंट फण्ड की बकाया राशि की वसूली का प्रश्न भी पाया जाता है।

5. पारिवारिक पेन्शन स्कीम, 1971—सामयिक मृत्यु के कारण औद्योगिक कर्मचारियों के परिवारों को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोयला-खान पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1971 तथा कर्मचारी पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1971 चालू की गई है। इनकी वित्तीय व्यवस्था में मालिकों व मजदूरों के मिलावा केन्द्रीय सरकार का भी योगदान होता है। इनका संचालन-व्यय भी केन्द्रीय सरकार देती है। कोय की सदस्यता की अवधि के आधार पर पारिवारिक पेंशन की राशि 60 रु से 500 रु. प्रतिमाह तक हो सकती है।

इस प्रकार पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1971 सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया व महत्वपूर्ण प्रयास है।

6 कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 (Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976)—यह योजना कर्मचारी प्रॉविडेंट कोप के सदस्यों के लिए। अगस्त, 1976 से लागू की गई थी। इसमें एक सदस्य की मृत्यु पर जिस व्यक्ति को प्रॉविडेंट कोप की जमा राशि मिलनी होती है, उसे अनिश्चित राशि भी दी जाती है। यह अतिरिक्त धनराशि मृत व्यक्ति की पिछले तीन वर्षों की प्रॉविडेंट कोप खाते की औसत बकाया के बराबर होती है, बशर्ते की यह 1000 रुपये से कम न हो। इस योजना में अधिकतम देय राशि 10 हजार रुपये तक होती है और कर्मचारी को इसमें कोई अग्रदान नहीं करना होता है।

7 ग्रेजुटी योजना, 1972—इसके अन्तर्गत ग्रेजुटी दी जाती है। यह सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन की मजदूरी के बराबर दी जाती है और ज्यादा से ज्यादा 20 माह की मजदूरी के बराबर दी जाती है।

8 कोयला खान जमा-सम्बद्ध बीमा योजना—यह भी 1 अगस्त, 1976 से प्रारम्भ की गई थी। इसमें भी एक कर्मचारी की मृत्यु पर इसके घरवालों को अनिश्चित धनराशि मिलती है। इस स्कीम के लिए मालिक व केन्द्रीय सरकार 2:1 के अनुपात में अग्रदान देते हैं।

कोयले की खानों में श्रमिकों के लिए बोनस-योजना भी लागू की गई है जो नियमित उपस्थिति के आधार पर श्रमिकों को दी जाती है। इससे श्रमिकों को खान पर नियमित रूप से उपस्थित होने की प्रेरणा मिलती है। बोनस की राशि खान पर उपस्थिति के आधार पर निर्धारित होती है।

समन्वित सामाजिक सुरक्षा (Integrated Social Security) की आवश्यकता

राष्ट्रीय धन मायोग का विचार था कि आयामी कुछ वर्षों में धनदान में मामूली वृद्धि करके कर्मचारियों की बीमा योजना में कुछ और जोड़ने शामिल की जा सकती है। जो लोग काम पर लगे हुए थे और अब बेकार हो गये हैं, उनके लिए बेकारी का बीमा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में कोषों की आवश्यकता होती है जिनका भारत में अभाव है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की अर्ध-समिति की निम्न दो निवारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(1) एक व्यापक व एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम व कर्मचारी प्रॉविडेंट फण्ड संगठन का एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। इससे प्रशासनिक व्यय में काफी कमी आयेगी।

राष्ट्रीय धन मायोग का मत था कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की तरफ अग्रसर होने के लिए एक ही कोष में सारी राशिओं को एकत्र किया जाना चाहिये जिससे विभिन्न एजेन्सियाँ आवश्यकतानुसार विभिन्न कामों के लिए उसमें से रकम निकाल सकें। इस आधार पर प्रति वर्ष एक बजट बनाया जाना चाहिए। इन स्कैम का विलुप्त शिक्का तैयार किया जाना चाहिए। घात और पर बेरोजगार लोगों को सहायता के बतौर नकद राशि देना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके लिए विंगल घतराशि की आवश्यकता होती है जो हमारे मौलिक साधनों के कारण व्यावहारिक नहीं लगती।

प्रश्न

1 'सामाजिक सुरक्षा' से क्या तात्पर्य समझते हैं ? भारत में कुछ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्याख्या कीजिये।

(Raj Hyr. T. D C., 1989)

2 सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए और भारत में अज्ञाते गये सामाजिक सुरक्षा के उपायों को बताइये।

(Raj Hyr. T. D C., 1986)

इस प्रकार रुपये का मूल्य विदेशी मुद्राओं में काफी घट गया है। 1950 में भारत का विश्व के निर्यातों में 2% अंश था जो 1987 में घट कर 0.5% पर आ गया है। भारत के निर्यात देश की सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति (GNP) के 5% से 6% पाये जाते हैं।

नीचे की तालिका से पता चलता है कि 1985-86 में व्यापार का घाटा 8763 करोड़ रु. रहा जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक माना गया है। छठी योजना के सभी वर्षों में व्यापार का घाटा काफी उँचा रहा था। 1988-89 में व्यापार के घाटे का ताजा अनुमान 412 करोड़ रु. रखा जिससे भारत के विदेशी मुग्तान की जटिल स्थिति का पता चलता है।

पिछले वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई जाती है—

भारत का विदेशी व्यापार : 1979-80 से 1988-89 तक (करोड़ रुपये में)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	आयात	निर्यात	व्यापार की बाकी (—) घाटा (+) बचत	आयातों में प्रतिशत वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में)	निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में)
1979-80	9143	6418	(-) 2725	34.2	12.1
1980-81	12549	6711	(-) 5838	37.3	4.6
1981-82	13608	7806	(-) 5802	8.4	16.3
1982-83	14293	8803	(-) 5490	5.0	12.8
1983-84	15832	9771	(-) 6061	10.8	11.0
1984-85	17134	11744	(-) 5390	8.2	12.0
1985-86	19658	10895	(-) 8763	14.7	(-) 7.2
1986-87	20201	12452	(-) 7749	2.8	14.3
1987-88	22399	15741	(-) 6658	10.9	26.4
1988-89*	27693	20281	(-) 7412	23.6	28.8

भारत में आयातों व निर्यातों के वार्षिक परिवर्तनों में काफी अस्थिरता रही है। 1973-74 में आयात पिछले वर्ष की तुलना में 58% बढ़े एवं 1974-75 में 53% बढ़े थे। 1976-77 में ये लगभग 4% घटे थे। 1973-77 की अवधि में निर्यातों में वार्षिक वृद्धि दर 27% रही, जितनी बाद में केवल 1988-89 में प्राप्त की जा सकी है।

* Facts for You, Annual Number 1989-90, June 1989, p. 84.

छठी पञ्चवर्षीय योजना की अवधि (1980-85) में व्यापार का घाटा प्रति वर्ष लगभग 55 अरब रुपये था इससे अधिक रहा। पाँच वर्षों में यह कुल 28581 करोड़ रु रहा जो अमूलपूर्व था। इससे देश के समस्त मुश्तान की समस्या जटिल हो गई है। व्यापार का घाटा 1986-87 व 1987-88 में कम हुआ। 1988-89 में निर्यातों की वृद्धि-दर 29% तथा आयातों की वृद्धि दर 24% रही है (पिछले वर्ष की तुलना में) जिससे व्यापार का घाटा 7412 करोड़ रुपये रहा है।

भारत के प्रमुख आयात

अब हम भारत के प्रमुख आयातों व निर्यातों का वर्णन करेंगे और साथ में यह भी बतलावेगे कि आयात की वस्तुएँ किन-किन देशों से आती हैं और निर्यात की वस्तुएँ किन-किन देशों को भेजी जाती हैं।

1987-88 में आयातों की राशि लगभग 22399 करोड़ रु. रही जो पूर्व सालिका के अनुसार पिछले वर्ष से 10.9% अधिक थी। 1988-89 में आयातों की राशि के 24% बढ़ने का अनुमान है। इस प्रकार 1988-89 में आयातों की वृद्धि-दर उंची रही है।

1987-88 के आकड़ों के अनुसार हमारे आयातों में प्रथम पाँच वस्तुएँ इस क्रम में थीं - पूर्वाजित माल, पेट्रोल, पेट्रोल पदार्थ व सम्बद्ध माल, मोती, कीमती व अर्द्ध-कीमती स्टोन्स, लोहा व हस्तात एव रसायन (ओरगेनिक व इनओरगेनिक)। भारत के प्रमुख आयातों का परिचय नीचे दिया जाता है—

1. पेट्रोल, तेल तथा चिकनाई के पदार्थ (POL)—इस मद के अन्तर्गत बिना साफ किया हुआ व आंशिक रूप से साफ किया हुआ पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल की अन्य वस्तुएँ आदि आती हैं। कूड तेल से डीजल तेल, फर्नेस तेल, पेट्रोल, किरा-सनी तेल, व अन्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, जिनकी मांग को कम करना कठिन है। कच्चा तेल विशेषतया ईरान, इराक व अन्य अरब देशों से आयात किया जाता है। पिछले वर्षों में इस मद के अन्तर्गत हमारा आयात-विल काफी ऊँचा रहा है जो निम्न सालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1982-83	5622
1983-84	4832
1984-85	5409
1985-86	4989
1986-87	2797
1987-88	4083

1987-88 में हमारे घायाती में इस मद का द्वितीय स्थान रहा। देश में कूड़ तेल का उत्पादन 1980-81 में 1.05 करोड़ टन में बढ़कर 1987-78 में 3.04 करोड़ टन हो गया है जिससे कूड़ तेल के अर्थों में कुछ कमी की जा सकती है। छोटी योजना की अवधि में देश में तेल साफ करने की क्षमता के सीमित होने के कारण इम्बर्ड हाई-ब्रूड तेल का निर्यात करना पड़ा जिसने निर्यातों में वृद्धि हुई थी। 1987-88 में देश में कूड़ तेल का उत्पादन 3.0 करोड़ टन होने के बावजूद (POL) का घायात 4083 करोड़ रु का किया गया क्योंकि ऊँची कीमत वाली POL को मँदे घायल करनी पड़ी तथा डावर रु। जब भी रुपये में ऊँचा रहा। POL के घायातों का हमारे कुल घायातों में 1980-81 में 42% स्थान था जो 1985-86 में घटकर लगभग 25% तथा 1987-88 में 18% पर आ गया है।

2 पूँजीगत माल (धातु-निर्मित माल, विद्युत व गैर-विद्युत मशीनों व परिवहन का सामान) — हमारे घायातों में पूँजीगत माल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत धातु निर्मित माल, विद्युत व गैर-विद्युत मशीनों व परिवहन का आवश्यक मात्रा-मात्रा शामिल होता है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए मशीनों का आयात करना आवश्यक है। जैसे सीमेंट, चीनी आदि की मिस-मशीनों का भारत में निर्माण होने लगा है, लेकिन मात्रा भी हम कई प्रकार की मशीनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहते हैं। मशीनों यूट-ब्रिटेन अमेरिका, कनाडा पश्चिमी जर्मनी व जापान आदि से मँगवाई जाती है। 1987-88 में पूँजीगत माल का घायात लगभग 6285 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष से 15% ज्यादा था। 1987-88 में हमारे घायातों में इस मद का प्रथम स्थान रहा।

3 मीती, कीमती व अर्द्ध-कीमती स्टोन्स — 1987-88 में हमारे घायातों में इसका तीसरा स्थान रहा। इसी वर्ष इनके आयात की राशि 1994 करोड़ रु रही जो पिछले वर्ष से 33% अधिक थी। भारत से दस्तकारी के माल के अन्तर्गत इनका निर्यात भी किया जाता है।

4 लोहा व इस्पात — भारत में लोहा व इस्पात की मांग इनकी पूर्ति में अधिक रहती है इसलिए इसका भी आयात किया जाता है। मिलाई, दुर्गापुर व झरखेला में इस्पात के कारखाने स्थापित होने से इसका उत्पादन बढ़ गया है फिर भी देश की विविध किस्म की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्टील की कुछ मदों का आयात करना पड़ता है। भारत में लोहा व इस्पात इंग्लैंड, अमेरिका व पश्चिमी जर्मनी से मँगया जाता है। 1987-88 में 1273 करोड़ रुपये का लोहा व इस्पात घायल हुआ जो पिछले वर्ष से 12% कम था जिससे घायातों में इसका स्थान चतुर्थ हो गया।

निर्यात (non-traditional exports) जिसमें इन्जिनियरी का माल, कच्चा तेल, मिने-मिल ए वस्त्र व पोशाकें, चमड़ा व चमड़े की वस्तुएँ, मछली व मछली से बना मांस, तथा दस्तकारी का सामान जिनमें मोती, बीमती व चर्द बीमती स्टोन्स आते हैं। मूल्य की दृष्टि से 1987-88 में हमारे निर्यातों में प्रथम पांच मदों का अनुवार स्थान (ग्रूड नेच के निर्यातों को छोड़कर) इस प्रकार था : दस्तकारी का सामान (जिसमें मोती, बीमती व चर्द-बीमती स्टोन्स शामिल हैं) : रेडीमेड पोशाकें, इन्जिनियरी का माल, चमड़ा व चमड़े से निर्मित सामान (शूजो सहित) तथा सूती वस्त्र (Cotton fabrics)। 1987-88 में निर्यातों की राशि 15741 करोड़ रु रही जो पिछले वर्ष से 26.4% अधिक थी। 1988-89 में निर्यातों में 29% वृद्धि हुई जो उल्लेखनीय है।

विभिन्न मदों का विवरण नीचे दिया जाता है :¹

1. जूट का रस—जूट का कपड़ा (hessian) व जूट के थैलें (sacking) भारत से विदेशों को भेजे जाते हैं। जूट का मान निर्यात करने भारत बाहर प्रेष करता है क्योंकि अमेरिका व कनाडा अपने प्रमुख बाहकों में हैं। जूट के माल के अन्य बाहक इस प्रकार हैं : रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्राइविव, न्यूजीलैंड, मिस्र, जापान आदि। जूट के मान के प्रतिस्थापन-पदार्थ निर्यात से निर्यात में कटिनाई होने लगी है। बगान देश अपने जूट के मान की सप्लाई करता है। घनः भारतीय जूट की मिनो में नये मशीनें लगाकर लागत घटायी जानी चाहिए, जिससे विदेशी बाजार बने रह सकें। 1987-88 में लगभग 243 करोड़ रुपये का जूट का निर्यात मान निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष के लगभग समान ही था। यह भारत के परम्परागत निर्यातों में गिना जाता है।

2. चाय व मेट (tea and mate)—यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विश्व में चाय की माँग की स्थिरता के कारण इनके निर्यात की राशि प्रतिवर्ष घटती-बढ़ती रही है। 1987-88 में चाय का निर्यात 592 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष से मामूली ज्यादा था।

भारतीय चाय का निर्यात यू. के., रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, अफगानिस्तान, मिस्र, जर्मनी, मूडान आदि को होता है। भारत की चाय के निर्यात में श्रीलंका, कीनिया व चीन की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। घटती चाय के लिए नये बाजार ढूँढे जाने चाहिए। यह भी भारत का एक परम्परागत निर्यात माना जाता है।

3. सूती वस्त्र व रेडीमेड पोशाकें (Cotton Fabrics and Readymade garments)—भारत से सूत व सूती कपड़ा विदेशों को निर्यात होता है। इसके बाहक इस प्रकार हैं : रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राइविव, जापान, मूडान,

आदि । 1987-88 में सूती वस्त्रों (Cotton Fabrics) का निर्यात 1064 करोड़ रुपये का और रेडीमेड पोशाकों का निर्यात 1792 करोड़ रुपये का हुआ । 1987-88 में रेडीमेड पोशाकों का मुख्य की दृष्टि से निर्यातों में द्वितीय स्थान रहा तथा वस्त्रों का पाचवा स्थान रहा ।

सूती वस्त्रों के निर्यात में विदेशों में भारत की अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है । अतः सूती वस्त्र के बाजारों को कायम रखने व उनकी बढान के लिए इस उद्योग में नयी मशीनों को लगाने की आवश्यकता है । मौजिदा रूप भारत के सूती वस्त्र का चाहूँ रहा है । इनके घनाबा अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भी माग बढ सकती है ।

4 कच्चा लोहा—भारत में उच्चकोटि के कच्चे लोहे का काफी अछातर मरा पडा है । भारत से कच्चा लोहा जापान, रिपब्लिक ऑफ जेरिया, चीन व मध्यपूर्व के देशों को भेजा जाता है । 1987-88 में कच्चे लोहे का निर्यात 543 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष से कुछ कम था ।

5. चमड़ा व चमड़े का सामान (छूनी सहित)—इनका निर्यात अमेरिका, हॉलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी व फ्रांस को किया जाता है । 1987-88 में चमड़े व चमड़े के सामान के निर्यात का मुख्य 1149 करोड़ रु. था जो पिछले वर्ष से 25% अधिक था । इसी वर्ष चमड़े व इनसे निर्मित वस्तुओं के निर्यात का भी भारतीय निर्यातों में अग्रपं स्थान रहा ।

6 तेली (Oil cakes)—1987-88 में तेली का निर्यात 173 करोड़ रु. का हुआ था जो पिछले वर्ष से कुछ नीचा था ।

7. तम्बाकू—1987-88 में हमने लगभग 135 करोड़ रुपये की तम्बाकू का निर्यात किया जो पिछले वर्ष से 27% कम था । भारतीय तम्बाकू का निर्यात मलेशिया, रूस, बंगला देश, व जापान को किया जाता है । भारतीय बर्जीनिया तम्बाकू रोमिया व अमेरिका की बर्जीनिया तम्बाकू से सरती होती है, लेकिन उनकी किस्म घटिया होती है । इसलिए निर्यात बढाने के लिए इसकी किस्म में सुधार किया जाना चाहिए ।

8. कपास—भारत से छोटे रेगे की कपास ब्रिटेन व जापान को निर्यात की जाती है । यह अन्य रेगों के साथ मिलाकर प्रयुक्त की जाती है । इसका घरेलू उत्पादन बढने से उसके निर्यात को काफी प्रोत्साहन देना आवश्यक हो गया है । 1987-88 में कपास का निर्यात 96 करोड़ रु. का हुआ जो पिछले वर्ष से 53% नीचा था ।

9. काजू (Cashew Kernels)—पश्चिमी देशों में काजू की माग बहुत अधिक है । भारत पूर्वी अमेरिका के देशों जैसे मोजाम्बिक व टंजेनीका से कच्चे काजू (raw nuts) मगाता है और इनको प्रोसेस व तैयार करके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन,

बनाडा आस्ट्रेलिया नीदरलैंड पश्चिमी जर्मनी जापान आदि देशों का निर्यात करता है। महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में काजू का उत्पादन बनाया जा सकता है। हमें काजू के निर्यात में बाजील व पूर्वी अफ्रीका की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। 1987-88 में काजू का निर्यात 307 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष से कुछ कम रहा।

10 चीनी—1975-76 में भारत से 472 करोड़ रुपये की चीनी का निर्यात किया गया था जो 1973-74 के स्तर का लगभग ग्यारह गुना था। बाद के वर्षों में चीनी के निर्यात घटत बढ़ते रहे हैं। पिछले दो वर्षों में चीनी के निर्यात नगण्य रहे हैं। 1989 में नेपाल को चीनी भेजी गई है। इस में चीनी के पड़ोसी देशों में बोरी छिपे चल जाने से भी देश में अभाव उत्पन्न हुआ है।

11 इजीप्टियरो का माल—भारत से गैर परम्परागत निर्यातों में इजीप्टियरो का माल का निर्यात काफी बढ़ा है। 1987-88 में इनका निर्यात 1433 करोड़ रुपये का हुआ जो निर्यातों में तीसरे स्थान पर था। 1987-88 में इनके निर्यात 26.5% बढ़। विश्व के दानारों में मदी की दशाश्री सरक्षण की बाधाओं प्रतीक्षा के देशों के लिए भुगतान करने की कठिनाइयों व अत्यंत की वारणों से भारत से इजीप्टियरो माल के निर्यातों को बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें इनकी कीमतों व ब्यालिटी पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

12 दस्तकारी का माल तथा अन्य निर्यात—1987-88 में निर्यातों में सर्वोच्च स्थान दस्तकारी के माल (handicrafts) का रहा। इनके निर्यात में पिछले वर्षों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1975-76 में इनका निर्यात 252 करोड़ रुपये का हुआ था जो 1987-88 में लगभग 3253 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसमें रत्नों व जवाहरात (gems and jewellery) का मूल्य 2614 करोड़ रुपये रहा है।

भारत के अन्य निर्यातों में मछली व मछली-निर्मित वस्तुएँ चमड़ा व चमड़े की वस्तुएँ काफी चाबल अमाले रसायन व सहायक पदार्थ लोहा व इस्पात आदि आते हैं। 1987-88 में सामुद्रिक पदार्थों अथवा मछली व मछली के घन पदार्थों का निर्यात 525 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष से थोड़ा कम था। भारत से सामुद्रिक पदार्थों (marine products) का निर्यात बढ़ सकता है। इसमें लिए जापान हमारा प्रमुख ग्राहक है। 1987-88 में चाबल का निर्यात 325 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष से काफी अधिक था। अमालों के निर्यात का मूल्य 309 करोड़ रुपये रसायन व सहायक पदार्थों के निर्यात का मूल्य 823 करोड़ रुपये का रहा।

पिछले वर्षों में तेल साफ करने की सुविधाओं के अभाव में भारत ने कूड़ तेल का भी निर्यात किया था जिसकी राशि 1984-85 में 1563 करोड़ रुपये थी। लेकिन बाद में देश में रिफाइनरीज की स्थापना हो जाने से इसका निर्यात काफी घट गया।

निर्यातों के सम्बन्ध में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि भारत अपने माल के मालावा अपने प्राविधिक ज्ञान एवं डिजाइन व सलाहकारी सेवाओं का भी निर्यात करने लगा है। भारतीय उद्यमकर्त्ताओं ने सऊदी अरब, पाना, नाइजीरिया, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, ब्रनाडा, कोलम्बिया एवं ग्रेट ब्रिटेन तक में समुक्त उप-क्रम (Joint ventures) चालू किये हैं। भारत तेल उत्पादक देशों को वासमती चावल व मशीनरी आदि का निर्यात करने आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने लगा है। पिछले वर्षों में देश में सीमेन्ट का अभाव रहने से इसका निर्यात करने की बजाय कुछ सीमा तक दक्षिणी कोरिया, रोमानिया व पोलैण्ड से आयात भी किया गया है। भारत का चीन व पाकिस्तान से भी व्यापार होता है। हम चीन की सोपरे का तेल व लाख निर्यात करते हैं तथा बदले में पारा जस्ता, एण्टीमनी तथा दाल-चीनी आदि का आयात करते हैं।

भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियाँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार की रचनाबट (composition), दिशा (direction) व व्यापार की बाकी (balance of trade) में काफी परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में हमारे विदेशी व्यापार पर रुपये के अवमूल्यना (नितम्बर, 1949 और जून 1966), पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत किये गये आर्थिक विकास तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ा है।

यहाँ हम विशेषतया पिछले वर्षों में हुए निर्यात-व्यापार, आयात-व्यापार एवं व्यापार-संतुलन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डालेंगे।

1. भारत के निर्यात व्यापार में परिवर्तन

(1) वस्तु के अनुसार परिवर्तन—योजनाकाल में भारत के निर्यात-व्यापार में काफी परिवर्तन हुए हैं। 1950-51 में कुल निर्यातों में चाय का अंश 13.4% था जो 1987-88 में 3.8% हो गया। इसी अवधि में जूट के माल का अंश 19% से 1.5% तथा सूती वस्त्रों का 23% से 6.7% (रेडीमेड पोशाकों का 1987-88 में 11.4% अलग से) हो गया। इस प्रकार इन तीनों वस्तुओं (चाय, जूट का माल व सूती वस्त्र पोशाकों) का अंश 1950-51 में 55% से घटकर 1987-88 में 21% हो गया। 1987-88 में दस्तकारी का अंश 20.7% रहा, जो पहले नगण्य था।¹

1. Facts for You, Annual Number 1989-90, June 1989, pp. 84-88 and Economic Survey 1988-89, graph facing p. 110.

ऊपर बताया जा चुका है कि भारत अब अनेक प्रकार की नयी वस्तुओं का निर्यात करने लगा है जिनमें दस्तकारी का सामान (विशेषतया रत्न व जवाहरात) रेडीमेड पोशाकें, काजू, इन्जीनियरी का सामान, कच्चा लोहा, आदि शामिल है।

पिछले वर्षों में 1970-71 से 1987-88 की अवधि में हमारे निर्यातों की यन्त्रावट में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।¹ (कुल निर्यातों का प्रतिशत)

वस्तु का नाम	1970-71	1987-88
(1) चाय	9.0	3.8
(2) कच्चा लोहा	7.6	3.4
(3) वस्त्र व रेडीमेड पोशाक	9.0	18.1
(4) जूट-धानं व निर्मित माल	12.4	1.5
(5) इन्जीनियरी का माल	8.5	9.1

इस प्रकार 1970-71 से 1987-88 की अवधि में जूट के माल, चाय व कच्चे लोहे का निर्यातों में सापेक्ष स्थान काफी नीचा हो गया। सूती वस्त्र (पोशाक सहित) का बढ़ा तथा इन्जीनियरी के माल का लगभग समान रहा है। (9% पर)

1987-88 में कुल निर्यात 15741 करोड़ रु के हुए जिनमें रत्न व जवाहरात का 16.6%, रेडीमेड पोशाकों का 11.4%, इन्जीनियरी माल का 9.1%, चाय का 3.8%, कच्चे लोहे का 3.4%, चमड़ा व चमड़े से निर्मित माल का 7.3%, सामुद्रिक वस्तुओं का 3.3% व शेष अन्य वस्तुओं का था।

(ii) दिशा के अनुसार परिवर्तन—दिशा के अनुसार व्यापार के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पिछले वर्षों में देशों के निम्न समूहों के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं—

(1) आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के देश (OECD) : इसमें योरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के देश जैसे, फ्रांस, बेल्जियम, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, नीदरलैंड व यू.के. आते हैं तथा उत्तरी अमेरिका के कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं, एवं एशिया व ओसिनिया के आस्ट्रेलिया व जापान आते हैं।

(2) ओपेक देश (OPEC) इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वगैरह तेल-निर्यात देश आते हैं।

(3) पूर्वी योरोप के देश : इसमें जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रोमानिया, सोवियत संघ, वगैरह आते हैं।

(4) अन्य विवासशील देशों में अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका व कंटे-बियन देश आते हैं।

(5) शेष में अन्य देश आते हैं।

नीचे 1970-71 से 1987-88 की अवधि में निर्यातों में विभिन्न देशों के उपर्युक्त समूहों व प्रमुख देशों का अंश दर्शाया गया है।¹ (प्रतिशत)

देश-समूह/देश	1970-71	1987-88
(1) OECD के देश (अमेरिका, जापान सहित)	50.0	58.8
(i) अमेरिका	13.5*	18.5*
(ii) जापान	13.2*	10.3*
(2) ओपेक (OPEC) के देश	6.4	6.2
(3) पूर्वी योरोप के देश	21.0	16.5
(4) विकासशील देश (गैर-ओपेक)	20.0	14.2
(5) अन्य देश	2.6	4.3
कुल	100.0	100.0

1 Economic Survey 1988-89 p 111 के बायीं तरफ का भाग (1987-88 के लिए)

* ये व्यक्तिगत देशों के प्रतिष्ठान अंग हैं। अमेरिका व जापान दोनों OECD ग्रुप में शामिल हैं, व सोवियत संघ पूर्वी योरोप के देशों में आता है। कॉलम को जोड़ते समय इनको अलग रखना चाहिए।

तानिका से स्पष्ट होता है कि 1987-88 में भारत के निर्यातों में प्रथम स्थान अमेरिका का रहा (18.5%)। 1970-71 से 1987-88 की अवधि में सोवियत मध्य का स्थान 13.6% से घटकर 12.5% पर आ गया। जापान का स्थान 13.2% से घट कर 10.3% पर आ गया। OECD देशों का अनुमान जो लगभग 1/2 था, घट 59% पर आ गया है। इस प्रकार 1970-71 से 1987-88 की अवधि में हमारे निर्यातों में OECD देशों का स्थान बढ़ा है। पूर्वी योरोप व गैर-ओपेक देशों का घटा है। सोवियत देशों का घटा लगभग स्थिर रहा है।

2. भारत के आयात-व्यापार में परिवर्तन

(1) वस्तु के अनुसार परिवर्तन (Commodity-wise Changes)-स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय विभाजन के कारण देश के समस्त कच्चे माल व साधनों की सम्पदा कम हो गयी थी। इसलिए विदेशों से कच्चा, कच्चा उट व साधनों का आयात करना आवश्यक हो गया था। इसके अलावा भारत विदेशों से मशीनें, पेट्रोल व तेल और द्रव्य आदि का भी आयात करना था। धीरे-धीरे पचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विज्ञान के परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा व बनावट में काफी परिवर्तन आया है।

1950-51 में आयातों में मशीनरी का घटा 20.2%, कपास का 15.5%, व अनाज व अनाज में बनी वस्तुओं का 8.2% था। 1987-88 में पेट्रोल व इसकी वस्तुओं का घटा 18.2% तथा पूँजीगत माल (मशीनरी व परिवहन-उपकरण) का 28.1% हो गया।¹

1970-91 से 1987-88 के बीच आयात की वस्तुओं की संतुलित स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वह इसकी तानिका में दर्शाया गया है—

1. Economic Survey 1988-89, p 106 के दाहिने ओर का चार्ट (1987-88 के लिए)

(कुल आयातों का प्रतिशत)

वस्तु	1970-71	1987-88
1 अन्न व अन्न-निमित्त वस्तुएँ	13.0	0.1
2 उर्वरक व उर्वरक माल	6.0	2.0
3. पेट्रोल, तेल व चिकनाई	8.3	18.2
4 पूँजीगत माल (मेटल-पदार्थ, मशीनरी व परिवहन-उपकरण सहित)	24.7	28.1
योग	52.0	48.4

तालिका में स्पष्ट होता है कि अनाज, उर्वरक, पेट्रोल व पेट्रोल-पदार्थ तथा पूँजीगत माल का कुल आयातों में अंश 1970-71 व 1987-88 दोनों वर्षों में लगभग आधा रहा। (लेकिन इसी अवधि में इनके सापेक्ष स्थान में काफी परिवर्तन हुआ है। अनाज का आयातों में अंश 13% से घटकर नगण्य तथा पूँजीगत माल का 25% से बढ़कर 28% पर आ गया। लेकिन POL का स्थान 8.3% से बढ़कर 18.2% पर पहुँच गया। इस प्रकार 1987-88 में पेट्रोल, तेल व चिकनाई का आयातों में लगभग 1/5 अंश पाया गया। पूँजीगत माल का 28% अंश सर्वाधिक था।

(ii) दिशा के अनुसार परिवर्तन—अद्य तालिका में 1970-71 व 1987-88 की अवधि में विभिन्न देश-समूहों/देशों के अनुसार आयातों के प्रतिशत दिये गये हैं।¹

1. Economic Survey 1988-89 p. 107 के बायीं ओर का ग्राफ (1987-88 के लिए)

(प्रतिशत)

देश-समूह/देश	1970-71	1987-88
(1) आर्थिक सहयोग व विकास संगठन (OECD) के देश	63.7	59.8
(i) अमेरिका (ii) जापान	27.7* 5.1*	9.0* 9.5*
(2) ओपेक (OPEC) के देश	7.7	14.8
(3) पूर्वी योरोप के देश (i) रूस	13.4 6.5*	8.0 5.7*
(4) विकासशील देश (गैर-ओपेक)	14.6	17.3
(5) अन्य देश	0.6	0.1
	100.0	100.0

1987-88 में आयातों में सर्वोच्च स्थान फंडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का रहा (9.7%) तथा द्वितीय स्थान अमेरिका का (9%) रहा।

1970-71 से 1987-88 की अवधि में आयातों में OECD—समूह के देशों का अंश 2 से घटकर लगभग 60% हो गया। अमेरिका का भी 27.7% से घटकर 9% हो गया। जापान तथा ओपेक के देशों का अंश बढ़ा। रूस का अंश 6.5% से घटकर 5.7% हो गया। पूर्वी योरोप के देशों का अंश घटा तथा गैर-ओपेक विकासशील देशों का अंश थोड़ा बढ़ा।

* ये व्यक्तिगत देशों के प्रतिशत हैं। इसलिए कॉलम के जोड़ में शामिल नहीं होगा।

3. भारत का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दो वर्षों (1972-73 व 1976-77) को छोड़कर शेष अन्य वर्षों में भारत के आयातों का मूल्य निर्यातों के मूल्य से अधिक रहा है जिससे व्यापार-सन्तुलन हमारे विपक्ष में रहा। व्यापार के इस घाटे की मात्रा कभी अधिक व कभी कम रही है।

1960-61 व 1965-66 में भी व्यापार के घाटे की मात्रा काफी ऊँची रही थी। बाद के वर्षों में व्यापार का घाटा कम हुआ। 1972-73 में पहली बार व्यापार-सन्तुलन हमारे पक्ष में रहा। 1976-77 में दूसरी बार व्यापार के घाटे में 69 करोड़ रुपये की मामूली बचत रही। बाद के वर्षों में पुनः व्यापार का घाटा बढ़ता गया और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि (1980-85) में यह 28581 करोड़ रु का हुआ जिससे विदेशी भुगतान की समस्या काफी जटिल हो गई।

1985-86 के लिए व्यापार का घाटा 8763 करोड़ रु रहा जो अभूतपूर्व था। 1986-87 में यह 7749 करोड़ रुपये व 1987-88 में 6658 करोड़ रुपये रहा। ताज़ा सूचना के अनुसार व्यापार का घाटा 1988-89 में 7412 करोड़ रु रहा है। इस प्रकार 1988-89 में यह पुनः बढ़ा है।

विदेशी व्यापार में घाटा (trade deficit) रहने के कारण

भारत में निरन्तर रहने वाले व्यापार के घाटे के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं जिनका विवरण नीचे दिया जाता है—

1. देश का विभाजन—पहले बताया जा चुका है कि 1947 में देश के विभाजन से लाद्यान्न व कच्चा माल उत्पन्न करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये थे जिससे भारत में इनकी अत्यधिक कमी हो गयी थी। इस कमी की पूर्ति के लिए भारत को गेहूँ, चावल, कपास व कच्चे जूट का काफी मात्रा में आयात करना पड़ा था जिससे व्यापार-सन्तुलन भारत के विपक्ष में हो गया था।

2. लाद्यान्नों का निरन्तर अभाव—काफी वर्षों तक भारत में लाद्यान्नों की माँग देश में होने वाली अन्तरिम पूर्ति से अधिक रही थी। देश में प्रायः कम या अधिक मात्रा में अकाल व सूखे की स्थिति पार्सी गयी है। जिससे लाद्यान्नों का सकट उत्पन्न हो जाता है। मरवार को लाद्यान्नों के अभाव की पूर्ति के लिए भूतकाल में प्रतिवर्ष विदेशों से गेहूँ, माइलो (milo), चावल, आटा आदि का आयात करना पड़ा था। भूतकाल में लाद्यान्नों का अधिकांश आयात अमेरिका से पी एल. 480 के अन्तर्गत किया गया था। पिछले वर्षों में देश में लाद्यान्नों की स्थिति पहले की अपेक्षा सुधरी है जिससे लाद्यान्नों का आयात घटाना सम्भव हो सका है। लेकिन सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तथा लाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाये रखने के लिए 1984 में इनका शुद्ध आयात लगभग 24 लाख टन किया गया था। लेकिन 1985-87 में लाद्य-स्थिति के ठीक रहने के कारण शुद्ध आयात थोड़ी मात्रा में ऋणात्मक (negative) रह। अतः भूतकाल में लाद्यान्नों के आयातों ने भी व्यापार के घाटे को बढ़ाया है। 1988 में पुनः सूखे के कारण 18.7 लाख टन लाद्यान्न का आयात किया गया।

आयात-उदारता की नीति

व्यापार के घाटे के बढ़ने का एक कारण आयातों के क्षेत्र में उदार-नीति का अपनाया जाना है। 1985-88 व 1988-91 की अवधि के लिए स्वीकृत निर्णय-आयात नीति में आयात-उदारता की नीति अपनायी गयी है जिसके फलस्वरूप आयातों में काफी वृद्धि हुई है। आयात अर्थव्यवस्था के रख-रखाव के लिए तथा विकास-मूलक दो प्रकार के होते हैं। इनका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है—

3 अर्थव्यवस्था के रख-रखाव के लिए आयात (Maintenance Imports)—भारत में द्वितीय योजनाकाल से औद्योगीकरण पर काफी बल दिया गया। देश में ऐसे कई उद्योग स्थापित किये गये हैं जिनके लिए आवश्यक कच्चा माल व कल-पुर्जें विदेशों से आते हैं। उद्योगों को चालू रखने के लिए आवश्यक माल व साज-सामान का आयात करना आवश्यक होता है, अन्यथा, उत्पादन की काफी धक्का पहुँचता है। ऐसे आयातों को आसानी से कम भी नहीं किया जा सकता, बल्कि सरकार को इनके सम्बन्ध में आयात-उदारता की नीति अपनानी पड़ती है। इन आयातों के अभाव में औद्योगिक मन्दी की समस्या घोर भी जटिल हो जाती है।

4 विकासमूलक आयातों की आवश्यकता (Need for Developmental Imports)—भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए नाना प्रकार की विकास-सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमारे आयातों पर दबाव पड़ा है। हम विभिन्न किस्म की मशीनरी (विद्युत व गैर-विद्युत) एवं परिवहन के साज-सामान का आयात करना पड़ता है, हालांकि धीरे-धीरे इनके आयात का स्तर कम होता जा रहा है। कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये रासायनिक उर्वरकों का आयात करना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि देश में होने वाले उर्वरकों का उत्पादन माँग की तुलना में अपर्याप्त रहता है। देश में विभिन्न प्रलोह धातुओं (तावा, सीसा, जस्ता व ताँगा आदि) की माँग विभिन्न उद्योगों में बढ़ रही है और भारत में इनका उत्पादन माँग की तुलना में कम हो पाता है। अतः इनका आयात भी बढ़ाना पड़ा है।

5. सुरक्षा सामग्री का आयात—1962 व चीन से एवं 1965 व 1971 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण भारत की सुरक्षा-सामग्री के आयात की भी व्यवस्था करनी पड़ी है जिससे व्यापार-सन्तुलन अधिक प्रतिकूल हुआ है। हाल के वर्षों में भी सुरक्षा-व्यय बढ़ाया गया है तथा सुरक्षा-सामग्री का आयात करना पड़ा है। इस प्रकार विकास व सुरक्षा दोनों के लिए ही आयातों पर हमारी निर्भरता बढ़ी है।

6. निर्यातों की वृद्धि दर में गिरावट—1977-78 से भारत के निर्यातों में वार्षिक वृद्धि-दर काफी नीची रही है, जबकि आयातों में उदार-आयात-नीति के कारण वृद्धि की दर ऊँची रही है। 1980-81 में आयात लगभग 37% बढ़े, जबकि निर्यात

- 2 भारत के निर्यात व आयात की प्रमुख मदों का उल्लेख कीजिए। हाल ही में निर्यात सबर्द्धन हेतु अपनाई गई नीति की समीक्षा कीजिए।
(Raj II year T.D.C., 1985)
(नाट निर्यात सबर्द्धन नीति के लिए अगला अध्याय देखिए।)
 - 3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशाओं में हुए परिवर्तनों का विवेचन कीजिए।
(Raj IIyr T.D.C., 1983)
 - 4 भारत की चार प्रमुख निर्यात तथा आयात की मदें बताइये। हाल के वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति की समीक्षा कीजिए।
(Raj IIyr. T.D.C. 1980)
 - 5 भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति, मात्रा और दिशा में वर्तमान प्रवृत्तियों को विवेचना कीजिये।
(Raj IIyr. T.D.C., 1982)
 - 6 पिछले तीन दशकों में भारत के विदेशी व्यापार में क्या प्रमुख परिवर्तन हुए हैं ? व्याख्या कीजिये।
(Raj. IIyr. T.D.C., 1989)
-

विदेशी व्यापार नीति

(Foreign Trade Policy)

इस अध्याय में हम सरकार की निर्यात-नीति व आयात-नीति पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही निर्यात-संवर्धन व आयात-प्रतिस्थापना आदि व गन्ध-ध में सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों का भी विवरण दिया जायेगा।

भारत के लिए निर्यात-संवर्धन (Export Promotion) की आवश्यकता

भारत के लिए निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता निम्न कारणों से है :

1 कृषि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए—बृट के साथ एन साय जैसी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर विदेश निर्यात-बाजार के आधार पर ही किया जा सकता है। इनका उत्पादन क्षेत्र घटे हुए बाजार की स्थिति में रखकर नहीं बढ़ाया जा सकता।

2 आयातों का भुगतान करने के लिए—एन देश व निर्यात उगने आयातों के लिए भुगतान की व्यवस्था करने हैं। हमें विदेशों में पेटेंट, लेन व विदेशों के पदार्थ, मशीनें, उर्वरक, विभिन्न प्रकार का उच्च मान, स्टाव लेन, आदि का आयात करना पड़ता है। इनका भुगतान करना के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक है। अ-पकान में भुगतान की कठिनाई का विदेशी महायोग के मा-वम में कम किया जा सकता है, तथा दीर्घकाल की दृष्टि में निर्यात संवर्धन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही निर्यात व द्वारा ही आयातों का भुगतान करना सम्भव होता है।

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि राष्ट्रीय आय में 1% वृद्धि होने से आयातों में 1.2% की वृद्धि होगी है। इसलिए सार्वजनिक योजना में विदेश की वस्तुओं पर 5% प्रभु करने के लिए आयातों की मात्रा में 6% वार्षिक दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया गया था इन आयातों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए निर्यातों में वृद्धि करनी नितात आवश्यक है।

3. विदेशी ऋणों का मुण्डान करने के लिए—विदेशी ऋणों के व्यापक व मुन्यता के मुण्डान का भी तथोक्त निर्धारित बढाना ही है। 1988-89 में भारत पर ऋणों की वार्षिक किस्त व व्यापक को चुकाने का भार लगभग 2770 करोड़ रुपये आया गया है। विदेशी ऋणों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चिये गये ऋणों के मुण्डान घटेनु तेन के उतार इन की वृद्धि-दर में गिरावट बिना व्यापार में मरझाना मक प्रवृत्तियों के बढने व रिपायती महायन्त्रा के सम्बन्ध में वातावरण के विपरीत होने में भारत के समस्त विदेशी मुण्डान की कठिनाई बढने लगी है। उनका मुण्डान करने के लिए निर्धारित बढाकर विदेशी मुद्रा खर्चित करना बहुत आवश्यक हो गया है।

4. आयात-निर्भरता की घोर अप्रसर होने के लिए—देश में आर्थिक विकास व आयात-निर्भरता के स्तर को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्धारित-मंडलन आर्थिक मान्यता जना है। इसमें निर्धारित-नाल का उन्नाहन बढाना होता है तथा साथ में निर्यात-उत्पत्ती में उन्नाहकता भी बढायी जानी है। आयात-निर्भरता का एक अंग निर्धारित-मंडलन होता है तथा दूसरा आयात-प्रतिस्थापन। आयात-प्रतिस्थापन के द्वारा आयातित वस्तुओं का देश में उत्पादन करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि आयातों पर निर्भरता कम की जा सके तथा विदेशी विनिमय की रक्षा की जा सके।

जापान व दक्षिणी कोरिया न निर्धारित बढा कर आर्थिक विकास की गति काफ़ी तेज की है। उन्होंने आयात-प्रतिस्थापन का भी औद्योगिक विकास के लिए महारा दिया है। प्रायः यह कहा जाता है कि भारत के लिए निर्धारित-आयात (export-led) या निर्धारित-आयातित (export-based) औद्योगीकरण ठीक नहीं रहता क्योंकि उनकी सम्भावनाएँ सीमित हैं। भारत को घटेनु नाग पर आयातित आर्थिक विकास व औद्योगिक विकास करना चाहिए, तभी रोजगार व आम में प्रविष्टि बढि होगी। व सब शर्तें बहुत कूट नहीं है, फिर भी हमें विकास करके निर्यात (growth led export) को बढाने ही पड़ेगे। अतः 'निर्यात-आयातित विकास' की जगह विकास-आयातित निर्धारित करना भारत के ज्यादा हित में रहेगा। 'विकास-आयातित निर्धारित' की नीति को अपना कर भारत में औद्योगिक विकास व निर्धारितों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है, जो हम समय देश के लिए निर्यात आवश्यक है।

निर्धारित-मंडलन के लिये किये गये सरकारी प्रयत्न

द्वितीय महायुद्ध की अवधि में निर्धारितों पर सरकारी नियन्त्रण की नीति प्रयत्नायी गयी थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद, और विरोधना देश के विनाशन के बाद निर्धारित बढाने की नीति पर जोर दिया गया। तृतीय योजना के प्रारम्भ में तो निर्धारित बढाने की आवश्यकता और भी तीव्र रूप में प्रकट हो गयी थी, क्योंकि भारत के विदेशी विनिमय-कोष काफी घट गये थे।

सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय काम में लिए हैं, उन्हें तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है : (i) सस्याओं व सगठनों की स्थापना, (ii) राज-कोपीय प्रेरणाएँ (fiscal incentives) तथा (iii) अन्य सुविधाएँ। इनका नीचे वर्णन किया जाता है।

संस्थाओं व सगठनों की स्थापना

पिछले वर्षों में कई संस्थाओं की स्थापना की गई है ताकि निर्यातों में वृद्धि की जा सके। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा व्यापार के लिए केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Advisory Council on Trade) की स्थापना का है जो एक सलाहकारी संस्था है जिसमें व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री व सरकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। बोर्ड ने हमारे निर्यात-व्यापार को नयी दिशाएँ प्रदान की हैं, निर्यात के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया है और उत्पादन की समस्याओं का गहन अध्ययन किया है तथा उनको हल करने के व्यावहारिक उपाय सुझाये हैं। जुलाई 1983 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इनमें कई अर्थशास्त्री व विशेषज्ञ शामिल किये गये हैं। यह परिषद् आयात-निर्यात नीति व कार्यक्रम, आयात व निर्यात व्यापार नियन्त्रणों व संचालन, व्यापारिक सेवाओं के सगठन व विकास तथा निर्यात-उत्पादन के सगठन व विस्तार-सम्बन्धी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देती है।

निर्यात प्रोत्साहन में वृषको उत्पादकों व निर्यातकों का सक्रिय सहयोग लेने के लिए 18 निर्यात-संवर्द्धन-परिषदों (Export Promotion Councils) की स्थापना की गयी है। सूती वस्त्र, रेशम व रेयन वस्त्र, प्लास्टिक व लिनोलियम, काजू व काजी मिर्च, तम्बाकू, खेल का सामान, रासायनिक पदार्थ, चमड़ा या लाख, चमड़ा, इन्जीनियरी का सामान अभ्रक, मसाले, सामुद्रिक वस्तुएँ, बहुमूल्य पत्थर व जवाहरात, हथकरघा, ऊन व ऊनीवस्त्र, तैयार खाद्य-सामग्री व गलीचों के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित की गई हैं। ये इन विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात की समस्याओं पर ध्यान देती हैं और सरकार, स्थानीय अधिकारियों व सार्वजनिक संस्थाओं को निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव देती हैं। ये बाजार-सर्वेक्षण के माध्यम से विदेशी बाजारों का अध्ययन करती हैं। व्यापार शिष्टमण्डल विदेशों में भेजती हैं, विदेशों में मेलों व नुमाइशों में भाग लेती हैं, प्रचार व सूचना देने एवं किस्म नियन्त्रण आदि कार्यों में रुचि लेती हैं। इनके अतिरिक्त वस्तु-बोर्ड व विकास-परिषदें भी हैं जो विशिष्ट वस्तुओं व उद्योगों के विकास का कार्य देखती हैं। वस्तु-बोर्ड निर्यात बढ़ाने पर भी ध्यान देते हैं।

निर्यात प्रोत्साहन में मदद देने वाले अन्य सगठन इस प्रकार हैं: (i) निर्यात साख व गारन्टी निगम : जनवरी, 1964 के आरम्भ में निर्यात जोखिम बीमा निगम

को निर्यात साख व गारण्टी निगम (Export Credit and Guarantee Corporation) में बंदज दिया गया था। यह अन्य बीमा कार्यों के साथ-साथ बेको को निर्यात-वित्तो पर पुनर्वित्त के रूप में अध्ययनवाचीन निर्यात साख प्रदान करता है। इससे निर्यातको को साख की सुविधा प्राप्त हो जाती है। (ii) भारत की निर्यात जाच परिषद् (iii) राज्य व्यापार निगम (STC) (iv) खनिज व धातु व्यापार निगम (Minerals and Metals Trading Corporation); (MMTC), (v) विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान (Indian Institute of Foreign Trade), (vi) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Exim Bank)—यह जनवरी 1982 में स्थापित किया गया था। इसने IDBI से बड़े समी कार्य ले लिये हैं जो वह निर्यात-साख, निर्यात-पुनर्वित्त, आदि के सम्बन्ध में किया करता था। (vii) व्यापारिक मेलों, (viii) पंच फेसले के लिए विभिन्न निदेशालय। ये व्यापारिक प्रचार, समाचार, नुमाइशों, प्रेरणाओं व किस्म-नियन्त्रण और परिवहन को देखभाल करते हैं। राग्यों ने भी निर्यात-प्रोत्साहन-सलाहकार-बोर्ड स्थापित किये हैं। विदेशों में हमारे व्यापारिक प्रतिनिधि भी व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता देते हैं।

निर्यात माल की किस्म के नियन्त्रण के लिए भारतीय मानक संस्था (Indian Standards Institution) (ISI) ने नयी वस्तुओं के लिए मानक तय किये हैं। विदेशी व्यापार के विकास के लिए कई देशों से व्यापारिक सम्झौतों भी किये गये हैं।

6 जून, 1966 के अवमूल्यन से पूर्व सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातको को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दे रखी थी। उनको कच्चे माल व मशीनों आदि के आयात के लिए अधिकार प्राप्त थे। उत्पादन-शुल्क में छूट व आयात-शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में सुविधाएँ थी। निर्यात-साख की सहूलियतें भी थी। रेल-गाड़ों में भी यथासम्भव छूटें दी जाती थी।

रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee)

इन उपोद्यो से तृतीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में हमारे निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार ने यह देखा कि आन्तरिक मूल्य-स्तर ऊँचा होने से विदेशों में हमारा माल प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहा है। चतुर्थ योजना में निर्यात बढ़ाना आवश्यक था। इसलिए विश्व बैंक की सलाह व देश की अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर सरकार ने 6 जून, 1966 को भारतीय रुपये का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया था। इससे एक डॉलर का मूल्य 4.76 रुपये से बढ़कर 7.50 रुपये और 1 पौण्ड का मूल्य 13.33 रुपये से बढ़कर 21 रुपये हो गया था। अवमूल्यन

का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना था। निर्यात प्रोत्साहन के पहले के उपाय पूर्णतया कारगर सिद्ध नहीं हुए थे, इसलिए सरकार को वाध्य होकर अवमूल्यन करना पड़ा था। अवमूल्यन की घोषणा के साथ ही सरकार ने निर्यात-प्रोत्साहन की कुछ अन्य स्कीम समाप्त कर दी थी। निर्यात की बारह वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगा दिये गये थे और आयात-शुल्को में भी कुछ संशोधन किये गये थे। सरकार ने सोचा कि जिन वस्तुओं की मांग विदेशों में बेलोच है, उन पर निर्यात-शुल्क लगाना उचित होगा।

सरकार ने अनुभव किया कि निर्यात-समस्या का एकमात्र इलाज अवमूल्यन करना नहीं है। इसलिए अवमूल्यन के बाद की अवधि में निर्यात बढ़ाने तथा आयात-प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक कदम उठाये गये जो नीचे दिये जाते हैं—

अवमूल्यन के बाद निर्यात-संबर्द्धन के उपाय

(i) निर्यात उद्योगों को पूँजीगत माल, साज-सामान व कच्चे माल के वितरण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। (ii) 'प्राथमिकता-प्राप्त' उद्योगों को, जिनमें जूट का सामान, चाय, कहवा, सूती वस्त्र आदि शामिल हैं, अपनी पूरी आवश्यकताओं के लिए आयात-लाइसेंस दिये गये। (iii) कच्चा जूट, काजू, चपड़ा व खालों को खुले सामान्य लाइसेंस (Open General Licence) (OGL) के अन्तर्गत रखा गया ताकि इनका आयात आसानी से किया जा सके। (iv) देशी कच्चा माल, जैसे पिग लोहा, प्राइम इस्पात, टिन प्लेटें, कपास व सूत, प्लास्टिक का कच्चा माल व पोलिथिलीन आदि की उपलब्धि हेतु निर्यात इकाइयों को विशेष सुविधा दी गई। चाय के बागानों को उर्वरक व वित्त की सुविधा दी गई।

सरकार द्वारा निर्यात-संबर्द्धन के उपाय¹

1966 में अवमूल्यन के बाद से निर्यात बढ़ाने के लिए नकद सहायता, निर्यात-शुल्को में कमी एवं निर्यात-साख की व्यवस्था बढ़ाने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये गये जिनका विवरण नीचे दिया जाता है :

1. आयात-पुनर्पूर्ति या पुनर्भरती के लिए लाइसेंस (Import Replenishment Licence (REP) की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्यातकों को विशेष वस्तुओं का निर्यात करने के बदले में आवश्यक कच्चे माल व अन्य वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। आयातित माल के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (actual users) को भी अपने स्वाचालित व पूरक लाइसेंसों के अन्तर्गत निर्यात की एवज में आयात करने के अधिकार दिये गये हैं। अतः सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए आयात करने

1. Economic Survey, 1988-89, pp. 114-119.

के विशेष अधिकार दिये जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिला है। 1984-85 की आयात-नीति में पुनर्पूर्ति के इन लाइसेंसों के अन्तर्गत निर्यातकों को अधिक सुविधाएँ दी गईं। आयात की जा सकने वाली मदों का विस्तार किया गया तथा इन लाइसेंसों के तहत आयातित पूँजीगत माल की अधिकतम राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई। इस प्रकार पुनर्पूर्ति के लाइसेंसों (REP Licence) की व्यवस्था का अधिक सचीला व व्यापक बनाया गया है ताकि निर्यातकों को अधिक प्रेरणा व अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

2. नकद क्षतिपूर्क सहायता (Cash Compensatory Support) (CCS)—विभिन्न वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों को नकद सहायता भी दी गई है। यह जून 1966 में रुपये के अवमूल्यन के बाद प्रारम्भ की गई थी। आजकल इसकी अधिकतम मात्रा जोड़े गये मूल्य (Value-added) का 25% होती है जो निर्यात से प्राप्त राशि में से आयात का घटा देने से बची राशि पर प्राप्ती जाती है।

1 जुलाई 1986 से नकद क्षतिपूर्क सहायता (CCS) की एक नई स्कीम चालू की गई है। इसके अन्तर्गत आठ वस्तु-समूहों में 260 मदों को CCS की सुविधा दी गई है। ये आठ वस्तु-समूह इस प्रकार हैं : इन्जीनियरी का माल, रसायन व सहायक पदार्थ, प्लास्टिक की वस्तुएँ, कृषिगत पदार्थ व प्रोसेस की हुई फूड की मदे, चमड़े की वस्तुएँ, खेल का सामान, वस्त्र व दस्तकारी की वस्तुएँ। समय-समय पर CCS के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार नई मदे शामिल की गयी हैं।

3 शुल्क वापसी स्कीम (Duty Drawback Scheme) (DDS)—नकद क्षतिपूर्क सहायता के अलावा निर्यात वस्तुओं के इन्पुटों पर लगे आयात-शुल्कों व उत्प्रेषण शुल्कों की राशिवा वापस करने की स्कीम भी लागू रही है। इससे भी निर्यात प्रोत्साहन में मदद मिलती है। लेकिन विन्नी-कर, चुंगी-शुल्क आदि वापस नहीं किये जाते जिससे दिक्कत बनी रहती है।

सरकार ने फरवरी, 1986 से समस्त सीमा-घरों (customs houses) पर वापसी की राशि के वितरण के लिए एक नई व सरल पद्धति लागू की है। वापसी के दावे प्रस्तुत करने के चौबीस घण्टों में स्वीकृत कर दिये जाते हैं, तथा रकम निर्यातक के बैंक खाते में पन्द्रह दिन में हस्तान्तरित कर दी जाती है। 1 जून, 1986 से एक नई युक्तिगणन DDS लागू की गई है जिससे पोशाक-उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊँची हू-उ निर्माण मशीनों, आदि को लाभ प्राप्त होता है।

4. निर्यात शुल्कों में कमी—निर्यात बढ़ाने के लिए जूट कार्पेट-बैकिंग व हैमियन पर से निर्यात-शुल्क हटाया गया है। भूतकाल में जूट बैंक्स, तिरपाल तथा

निवाड, नारियल के सूत (coir yarn), पशु आहार तथा कॉफी पर से निर्यात शुल्क हटाया गया है।

5 निर्यात-साख की व्यवस्था—निर्यातकों को व्याज-मुक्त बैंक ऋण भी दिये जाते हैं, जो उनके वापसी भुगतानों की एवज में होते हैं। इससे निर्यातकों को यह शिकायत नहीं रहती कि उनके वापसी भुगतानों (Drawback payments) में विलम्ब हुआ है। अप्रैल 1986 में निर्यात-घायात बैंक के सत्वावधान में 10 करोड़ रु की पूंजी से एन निर्यात-विकास-कोष की स्थापना की गई है। इससे भी निर्यात संवर्धन में मदद मिलेगी।

6, निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन—पहले 15 निर्यातीन्मुख इन्जीनियरी उद्योगों को, बिना पूर्व इजाजत के, पांच वर्षों में उत्पादन-क्षमता में 25 प्रतिशत वृद्धि करने की छूट दी गयी थी। सामुद्रिक वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने के लिए पृथक् 'ट्रालर विकास कोष' बनाया गया जो गहरे समुद्र में काम करने के लिए ट्रालर (जहाज) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

7 सरकार ने थोड़ीन, मद्रास, कलकत्ता के समीप फाहटा, तथा नोइडा (NOIDA) में चार नये निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र (Export Processing Zones) (EPZ) स्थापित किये हैं। एक और क्षेत्र विशाखापटनम में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे निर्यातों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। निर्यात-प्रोसेसिंग क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को पांच वर्ष तक कर-अवकाश दिया जाता है।

इससे पूर्व कादला निर्यात-प्रोसेसिंग क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया था जिसमें 100% निर्यात प्रोसेसिंग इकाइया लगायी गईं एवं सान्तात्रूज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र भी स्थापित किया गया था। लेकिन इनका कार्य विशेष उत्साहवर्धक नहीं रहा है।

8 कुछ वस्तुओं के निर्यातों पर प्रतिवन्ध—सरकार निर्यात करते समय घरेलू आवश्यकताओं पर ध्यान देने का समर्थन करती है। घरेलू उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा कर निर्यात नहीं किया जाता। इसलिए सरकार ने समय-समय पर भू गफली, इसब तेल, ग्रन्थ साइन्डल, दालें, सच्ची व आलू तथा प्याज के निर्यात को नियमित व नियन्त्रित किया है। सरकार उपभोग्य वस्तुओं के निर्यात का सीमित करना चाहती है ताकि देश में इनकी कीमतें व उपलब्धि उचित स्तर पर बनी रहे। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि पिछले वर्षों में भारत से फल, साग-सब्जी, मांस आदि का निर्यात काफी बढ़ा है जिससे देश में इनका अभाव उत्पन्न हो गया है तथा ग्राम उपभोक्ता को इनकी ऊँची कीमतें देनी पड़ी है। सरकार को इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

राज्य-व्यापार नियम के पांच सहायक निगम (subsidiaries) हैं जो इस प्रकार हैं—(1) भारत का राज्य रसायन बंदवाई निगम (State Chemicals and Pharmaceutical Corporation of India Ltd. (CPC) (1) भारत का दस्तकारी व हथकरघा निर्यात निगम लि. (Handicrafts and Handloom Exports Corporation of India) (HHEC) (1) भारत का प्रोजेक्ट व उपकरण निगम लि. (Projects and Equipment Corporation of India Ltd.) (PEC) (4) भारत का काजू निगम लि. (Cashew Corporation of India Ltd. (CCI) तथा (3) भारत का केन्द्रीय कुटीर उद्योग लि. (Central Cottage Industries Corporation of India Ltd.) (CCIC)। यह HHEC का सहायक निगम है।

व्यापार विकास प्राधिकरण (Trade Development Authority)—निर्यात बढ़ाने की दिशा में व्यापार-विकास प्राधिकरण संस्था (TDA) की स्थापना एक नवीन तथा प्रगतिशील कदम कहा जा सकता है। इसका विधिवत् उद्घाटन 18 फरवरी, 1971 को किया गया था।

इस संस्था के माध्यम से निर्यात-संवर्धन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया है। निर्यात के क्षेत्र में स्थायी वृद्धि व प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि इस विषय में व्यष्टि-दृष्टिकोण (micro-approach) अपनाया जाय। निर्यात की वस्तु, निर्माता व विदेशी बाजार के सम्बन्ध में गहन अध्ययन व अन्य कार्य करके निर्यात बाजार विस्तार करना ही इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य है।

व्यापार-विकास प्राधिकारी संस्था (TDA) के कार्यकलापों में निम्न सिद्धान्तों का ध्यान रखा गया है, (1) यह उन सेवाओं को प्रदान करता है जो अन्य संस्थाओं से प्राप्त नहीं होती; (2) यह सेवाओं के स्तर में सुधार करता है, (3) यह विभिन्न सेवाओं में ताल-मेल स्थापित करता है और (4) यह निर्यातकों के लिए अनुसंधान व सूचना-केन्द्र का भी काम करता है।

निर्यात-संवर्धन के लिए सुझाव

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 1987-88 में व्यापार का घाटा 6658 करोड़ रु. व 1988-89 में 7412 करोड़ रु. रहा है। अतः यह 1988-89 में पुन बढ़ गया है। छठी पंचवर्षीय योजना की कुल अवधि (1980-85) में व्यापार का घाटा लगभग 286 अरब रुपये रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के लिए निर्यात बढ़ाना अन्यावश्यक हो गया है।

निर्यात बढ़ाने का अर्थ अत्यन्त जटिल है। यह भारत के समक्ष एक महान् चुनौती के समान है। इसका हल निकालने के लिए हमें अग्र दिशाओं में लगातार प्रयत्न करने होंगे :

1 देश में कृषिगत पदार्थों एवं औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जानी चाहिए। कृषिगत पदार्थों में चाय, कॉफी, फन, सब्जी तम्बाकू, काजू की गिरी, कपास चावल व गेहूँ, मसालों आदि का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पादन बढ़ाकर निर्यात के लायक बचती से वृद्धि की जा सकती है। रैर-परम्परागत निर्यातों जैसे इ जीनियरी माल दस्तकारी का मान रेडीमेड वस्त्र, आदि में उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया है।

2 निर्यात के लायक वस्तुओं के घरेलू उपभोग को उचित सीमा में नियन्त्रित रखना होगा। जिन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना है उनके घरेलू उपभोग की वृद्धि की दर को अवश्य नियन्त्रित करना होगा। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए यह त्याग करना आवश्यक हो गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है सरकार उपभोग वस्तुओं के निर्यात को सीमित करने के पक्ष में है। देश में उपभोक्ता के हितों की दृष्टि देकर आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के निर्यात नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। भारत में मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण स्थापित करने के बिना उपभोग्य वस्तुओं के निर्यात पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है।

3 निर्यात-उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध किया जाना चाहिए। माल की किस्म सुधारी जानी चाहिए व उत्पादन लागत घटाने परनी चाहिए जिससे विरय के बाजारों में हम प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। सरकार ने अभी तक उन वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया है जो विदेशों से आयात नहीं की जा सकती है शयबा जो आयात की वस्तुओं के प्रतिस्थापक के रूप में काम आ सकती है। अविध्य में निर्यात उद्योगों पर अधिक ध्यान देने से देश को विशेष लाभ हो सकता है।

4 निर्यातों में वस्तुओं व बाजारों के अनुसार विविधता लायी जानी चाहिए। भारत व लिए निर्यात की वस्तुओं में विविधता लाना तथा नये बाजारों की तलाश करना बहुत जरूरी हो गया है। अविध्य में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी अफ्रीका और अफ्रीका की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए मशीनों कल-पुर्जों व कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों जैसे फ्रांस ब्रिटेन फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी वगैरह को भी निर्यात बढ़ाना चाहिए। रूस व पूर्वी यूरोप के देशों को भी निर्यात बढ़ाया जा सकता है। साथ में रैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ाया जाना चाहिए।

भारत को आगामी वर्षों में निर्यात की दिशा और बनावट दोनों में काफी परिवर्तन लाना होगा। निर्यात की प्रचलित वस्तुओं का नयी दिशाया में भेजने की व्यवस्था करनी होगी और नया वस्तुओं को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों का निर्यात करने की कोशिशें करनी होंगी।

भारत प्रयत्न करके जापान व केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों से निर्यात-व्यापार काफी बढ़ा सकता है। केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों में व्यापार बढ़ाने से हमारे निर्यात-व्यापार में अधिक स्थिरता भी आयेगी। राज्य-व्यापार नियम को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए।

भारत को कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ाने का सुझावर प्राप्त है। इसके अलावा उसे लोह व इस्पात, पिंग लोहा व इस्पात की निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ाना चाहिए। भारत से गन्नी व टिस्से की मच्छलियों का निर्यात भी बढ़ाया जा सकता है। नया वस्तुओं में साइकिलों, कपड़ा सीने की मशीनों, बिजली की मोटर, मशीन टूलस, आदि का निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। भारत को खासगती धातु, फल-फूल व मछली, कच्चा लोहा, सामुद्रिक वस्तुओं तथा स्वर्ण-प्राभूपणों के निर्यात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करना चाहिए। भारत से प्रोजेक्ट व सलाहकारी सेवाओं के निर्यात भी बढ़ाये जा सकते हैं। खाड़ी के देशों व अफ्रीकी देशों को प्रोजेक्ट-निर्यात बढ़ाये जाने चाहिए। इनमें निर्माण (Construction) प्रोजेक्ट मुख्य होते हैं।

5 विकसित देश उदार नीति अपनाएँ—निर्यात बढ़ाने के समस्त प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब विकसित देश उदार आयात नीति अपनाने और विकासोन्मुख देशों की बनी हुई वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात करें। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को केवल ऋण देकर ही अपनी जिम्मेदारी की इतिथी नहीं माननी चाहिए, बल्कि अल्प-विकसित देशों का बना हुआ मांस खरीद कर भी उनको आर्थिक विकास में पर्याप्त सहयोग देना चाहिए। उन्हें आर्थिक सहायता (aid) के साथ-साथ व्यापार (trade) की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। इस बात को अधिक उपयुक्त व सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि विकासशील देशों का निर्यात-संवर्द्धन कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जबकि विकसित देश अपने यहाँ आयात-संवर्द्धन-कार्यक्रम अपनाएँ। इसके लिए विकसित देशों का संरक्षणवाद (protectionism) का परित्याग करना होगा एवं आयातों पर प्रतिबन्ध कम करने होंगे।

■ निर्यात बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन निर्यात-नीति की आवश्यकता है¹—
उद्योगपतियों का कहना है कि जब तक भारत में सयन्त्रों की लागत कम नहीं होगी

1 1970-85 की अवधि में निर्यातों के विस्तारण के लिए नवीनतम व सर्व-श्रेष्ठ लेख Deepak Nayyar, *India's Export Performance, 1970-85 EPW, Annual Number 1987*, pp. AN-73 से AN-90 (December, 1987).

इसके अलावा टण्डन समिति ने चमड़ा व चमड़े की वस्तुओं, आभूषण व हीरे, वस्त्र व कृषिगत पदार्थों आदि का निर्यात बढ़ाने के लिए पृथक सुझाव भी दिये थे। सरकार ने टण्डन समिति के सुझावों के आधार पर निर्यात-संबंधित कार्यक्रम अपनाने का प्रयास किया है।

आयात-निर्यात नीति पर आब्रिद हुसैन समिति ने दिसम्बर 1984 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1985-88 तथा 1988-91 की अवधि के लिए सरकार द्वारा आयात-निर्यात नीतियाँ घोषित की गई हैं। आब्रिद हुसैन समिति ने त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति की घोषणा करने की सलाह दी थी, ताकि इस क्षेत्र में अनिश्चितता कम की जा सके। इमने स्वचालित लाइसेन्सों की श्रेणी को समाप्त करने विनिर्माण-निर्यातकों के लिए एक आयात-निर्यातों पास बुक की स्कीम प्रारम्भ करने तथा उन उपक्रमों द्वारा आयात में भाग लेने का समर्थन किया जो उस मद के विनिर्माण से सम्बद्ध नहीं थे। समिति ने आयातों को नियमित करने के लिए प्रभुत्वों के उपयोग का समर्थन किया जिसे सरकार ने अपनी दीर्घकालीन राजदोषीय नीति में शामिल किया है।

व्यापारिक समझौते (Trade Agreements)

यह बताया जा चुका है कि भारत ने निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय काम में लिए हैं उनमें एक उपाय अन्य देशों से व्यापारिक समझौते करना भी है।

भारत ने समय-समय पर विभिन्न देशों से द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते (Bilateral Trade Agreements) किये हैं। ऐसे अधिकांश समझौते 1953 और 1954 में सम्पन्न किये गये थे। उन वर्षों में ये समझौते केवल इस प्रर्थ में द्विपक्षीय होते थे कि दोनों देश आयात व निर्यात के माल की मूची निर्धारित किया करते थे।

1958 के बाद के द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों ने रूपये में भुगतान किये जाने वाले समझौतों (Rupee Payment Agreements) का रूप ग्रहण किया है। इन द्विपक्षीय भुगतान समझौतों के अन्तर्गत समझौता करने वाले दो देश एक चालू खाते की दक़ाय के आधार पर व्यापारिक और गैर-व्यापारिक सौदों का समायोजन करते हैं। मान लीजिये, भारत व रूस में इस प्रकार का व्यापारिक समझौता होता है तो इसका आशय यह होगा कि भारत रूस से माल का आयात कर लेता है और रूस उस रकम को रूपये में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने नाम के खाते में जमा कर देता है। फिर रूस भारत से वस्तुएँ खरीदता है और उनका भुगतान इस खाते की रकम में से कर दिया जाता है। इस प्रकार एक विशेष समय में चाहे यह

छाता सन्तुलन में न हो, लेकिन एक अवधि विशेष में यह छाता अवश्य सन्तुलित होगा।

इन समझौतों की बायें-विधि से इनके निम्न उद्देश्य सामने आते हैं

(1) पूर्वी यूरोपीय देशों से प्रत्यक्ष या सीधे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना (2) विदेशी विनिमय साधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल बिना पूँजीगत मान व मौद्रिक वृद्धि मान प्राप्त करना (3) परम्परागत निर्यातों के मूल्य का स्थिर करना (4) आयातों का उपयोग निर्यातों के स्वचालित विस्तार के लिए करना (5) विदेशी विनिमय का अविवाश ग्रह प्राप्त करना व निर्यात कुछ परम्परागत निर्यात बाजारों व निर्यात वस्तुओं पर से निर्भरता कम करना (6) गैर परम्परागत निर्यातों के लिए बाजार विकसित करना।

रूपों में भुगतान करने वाले देशों से भारत के विदेशी व्यापार में प्रगति

योजनामान में भारत का पूर्वी यूरोप के देशों जैसे रूस, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया व बुल्गारिया से व्यापार काफी बढ़ा है। कुछेक वर्षों की छोड़कर रूस के साथ व्यापार सन्तुलन भारत का पक्ष में रहा है। रूस को हमारे निर्यातों की राशि वहाँ से किये गये आयातों की राशि से अधिन रही है। पूर्वी यूरोप से भारत के बढ़ते हुए व्यापार का प्रमाण इस बात में मिलता है कि 1955-56 से इस क्षेत्र में हमारे आयातों का 1.4% और निर्यातों का 0.9% ही प्राप्त हुआ था जो बढ़कर 1987-88 में आयातों का 8% और निर्यातों का 16.5% हो गया। इस प्रकार 1987-88 में हमारे आयातों का 1/12 भाग पूर्वी यूरोप के देशों से आया और हमारे निर्यातों का 1/5 भाग से कुछ कम इन देशों को भेजा गया। हमने इन देशों की परम्परागत वस्तुओं में चमड़ा व तानें, राजू, चाय व चूआ गोहा, जूट का मान व मसानो का निर्यात किया है और गैर-परम्परागत वस्तुओं में पोशाकों, जूतों, विजनी की मशीनरी व अन्य मशीनरी, धातु-निर्मित मान, दवाइयों आदि का निर्यात किया है। इनसे किये जाने वाले आयातों में गंध, रसायन, मशीनरी व साज सामान, पेट्रोल के पदार्थ तथा कागज आदि प्रमुख रहे हैं।

भारत को अपनी बदलती हुई अवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु मान व मशीन धातुओं जैसे तांबा, रंगी, सीसा व जस्ता आदि की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति रूस व अन्य देश कर सकते हैं। भारत को पूर्वी यूरोपीय देशों से व्यापार करने से काफी लाभ पहुँचा है। हम आवश्यक वस्तुओं के आयात में सुविधा मिली है और नये बाजार प्राप्त करने का सुअवसर मिला है। मध्यम व इन

देशों से भारत का व्यापार और बढ़ सकता है। हम इस से मुख्यतया कूटनेत, उद्येयक व अलौह धातु का आयात करते हैं।

आयात-प्रतिस्थापन (Import Substitution)

पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास, आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक आत्म-निर्भरता सभी दृष्टियों से आयात-प्रतिस्थापन व निर्यात-संवर्धन पर काफी जोर दिया गया है। द्वितीय योजना के प्रारम्भ में महत्त्वानुविस विकास-नीति में भारी उद्योगों पर अधिक धन देने के कारण आयात-प्रतिस्थापन पर आधारित औद्योगिक विकास की नीति पर अधिक जोर दिया गया था। बाद में कुछ सीमा तक निर्यात-आन्वित औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। यहाँ पर हम आयात-प्रतिस्थापन के विविध पहलुओं पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में भावी सम्भावनाएँ क्या हैं?

भारत में विदेशी विनिमय के अभाव और अनिश्चित विदेशी सहायता के कारण आयात-प्रतिस्थापन की आवश्यकता बढ़ी है। 1962 में चीनी आक्रमण और 1965 व 1971 में पाकिस्तान से युद्ध होने से आयात-प्रतिस्थापन देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी हो गया था।

प्रगति—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में कई नये उद्योग स्थापित किये गये हैं जिससे कुछ वस्तुओं का आयात समाप्त कर दिया गया है और कुछ का आयात काफी मात्रा में कम कर दिया गया है।

आगे की नवीनतम तालिका में कुछ वस्तुओं के आयातों का देश की कुल उपलब्ध से अनुपात (import-availability ratio) बतलाया गया है।¹ जिस सीमा तक यह अनुपात घटा है उस सीमा तक आयात-प्रतिस्थापन हुआ माना जा सकता है।

1 Isher Judge Ahluwalia, *Industrial Growth In India : Stagnation Since the Mid-Sixties*, 1985, p. 119.

वस्तु/वस्तु-समूह	1959-60	1979-80
1. वस्त्र (Textiles)	2.9	1.9
2. लकड़ी व कोक	22.1	2.9
3. कागज व कागज की वस्तुएँ	23.4	18.2
4. चमड़ा व कर की वस्तुएँ	5.4	0.1
5. रबड़ का माल	11.5	8.1
6. रसायन व रसायन वस्तुएँ	30.0	19.5
7. पेट्रोल-पदार्थ	43.9	42.3
8. धेसिक धातु	32.3	22.7
9. गैर-विद्युत मशीनरी	65.8	30.6
10. विद्युत मशीनरी	38.1	9.9
11. परिवहन-उपकरण	25.7	11.1

इस प्रकार 1959-60 से 1979-80 के दो दशकों में मशीनरी, रसायन, कागज, वस्त्र, परिवहन-उपकरण वगैरा में आयात-प्रतिस्थापन हुआ है।

हमारी अर्थव्यवस्था के अन्दर आयात-प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति लागू हो गई है। अविद्य में औद्योगिक उत्पादन में विविधता लाकर इसे और भी सुदृढ़ किया जा सकता है। मरका के सामान में भी अविद्य आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू मात्र से होने लगी है। आयात-प्रतिस्थापन की दिशा में हमारी प्रगति सम्पूर्णजनक मानी जा सकती है।

भारत में 1965-66 के बाद आयात-प्रतिस्थापन की गति धीमी हुई है। हमारा औद्योगिक विकास में योगदान कम हो गया है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। कोरिया, सिंगापुर व तैवान में भी शुरू में आयात-प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था। बाद में वहाँ भी निर्यात-संवर्द्धन पर बल दिया गया। लेकिन हमारे देश में आयात प्रतिस्थापन बहुत कुछ एकाग्रकुशल व महत्वा किम्ब का रहा है।

आयात-प्रतिस्थापन की अपनी समस्याएँ हैं जैसे शुरू में ऊँची उत्पादन-लागत, उत्पादन की अविद्य किम्ब और अकार्यकुशलता। अतः आयात प्रतिस्थापन के लिए उद्योगों के चुनाव में आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए। हम अनावश्यक आयातों का बंद करना चाहिए। विनाशिता की वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों को अदना विदेशी विनिमय स्वयं अविद्य करना चाहिए।

हम उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जिनमें आयात-प्रतिस्थापन अधिक सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। हम मशीनरी व परिवहन के साथ सामान का आयात घरेलू पूर्ति को बढ़ाकर कम करना चाहिए। लेकिन हमें अतीव धातुओं के लिए विदेशों पर काफी भीमा तक निर्भर रहना पड़ेगा। सामायिक उद्योग की प्रगति हान से समाधान के आयात में कमी की जा सकती है। अविद्य उत्पादन बनाकर आयातों का आयात कम किया जाना चाहिए।

अविद्य में अविद्य, अतीव आयात सनिज तेल, अवरक, रासायनिक पदार्थ व आयातों का आयात घरेलू उत्पादन बढ़ाकर कम किया जाना चाहिए। आयात-प्रतिस्थापन की ये दशाएँ राष्ट्र के लिए सर्वाधिक लाभकारी होंगी। सरकार का परिवहन व शक्ति का समुचित विकास करके और निजी क्षेत्र को आवश्यक प्रोत्साहन देकर घरेलू उत्पादन बढ़ाने का असक प्रयास करना चाहिए।

अतः आयात-प्रतिस्थापन के लिए दिशाएँ अविद्य स्पष्ट हो गई हैं जिनका तुरत नजी में बटना चाहिए।

आयात प्रतिस्थापन दम के लिए आद्यम्ब है, रकिन इसकी लागत पर भी ध्यान देना होगा। इसने लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकरण अपनाय की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में योजना-काल में बहुत कुछ विना सोच-समझे आयात-प्रतिस्थापन किम्ब, गया जिनमें अर्थव्यवस्था पर अविद्य भार बढ़ा है। भारत में आयात-प्रतिस्थापन काफी अहंगा रहा है। एत बाद विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक बाद से ज्यादा मूल्य के घरेलू साधन सर्व किए हैं। लेकिन आयात-

प्रतिस्थापन [रोजगार, उत्पादन व आमदनी पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। यदि चुने हुए क्षेत्रों में लागत-साम के आधार पर अधिक कार्यकुशल किस्म का आयात-प्रतिस्थापन किया जाता तो देश को अधिक लाभ हो सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि भूतकाल में निर्यात-समर्थन पर अधिक बल दिया जाता तो देश को अधिक लाभ पहुँच सकता था।

आज की स्थिति में निर्यात-मजदूर व चुने हुए क्षेत्रों में कार्यकुशल आयात-प्रतिस्थापन दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। हमने निम्नीय विनिमय मापनों का सजातीय उपयोग किया जा सकता है।

आयात-प्रतिस्थापन पर अग्रवाल-वेनस के सुझाव¹

सरकार ने जून 1979 में श्री एस. एम. अग्रवाल की अध्यक्षता में आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए सड़नीय आर्थिक व राजनीतिक नीतियों की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अक्टूबर 1980 में आयात-प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में अपनी निम्न सिफारिशें पेश की थीं

1. मजिद में पूँजी-गहन व उच्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में लाइसेंस देने समय यह देखा जाना चाहिए कि उत्पादन की इकाइयों का प्रकार अनुकूलतम, सक्षम व आर्थिक किस्म का हो, ताकि इकाई लागत कम की जा सके। प्रचलित इ-उद्योगों की विस्तार की मुजिया दी जानी चाहिए ताकि वे उत्पादन-क्षमता के पुनर्स्थापन व आधुनिकीकरण के द्वारा उत्पादन का आर्थिक स्तर प्राप्त कर सकें। इस प्रकार पैमाने की 'विफायतों' को प्राप्त करने पर ध्यान आकर्षित किया गया है जो उचित माना जा सकता है क्योंकि इससे उत्पादन-लागत कम होगी और भारत की औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुधरेगी।

2. समिति का सुझाव है कि लाइसेंस से मुक्ति/छूट की 3 करोड़ रुपये की सीमा पर संपत्तियों व उपकरणों तथा अन्य सामान की बढ़ती हुई लागतों के संदर्भ में समय-समय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

3. आयात-प्रतिस्थापन क्षेत्रों में, विनियोग, बंटवारे के निम्न, समिति का सुझाव था कि औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त 24 उद्योगों तथा अन्य 29 उद्योगों की सूची का भी विस्तार किया जाय जिन्हें 1975 में अपनी क्षमता का बिना किसी सीमा के उपयोग करने की इजाजत दी गई थी। इसमें आयात-प्रतिस्थापन वाले उद्योगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

4. पेट्रोल व खाद्य-तेल का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

5 समिति ने विदेशी उत्पादको द्वारा भारत में अपना पूँजीगत माल कम दामों पर बेचकर देश की शक्ति पहुँचाने के सम्बन्ध में भी सावधान किया है।

आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के अध्यक्ष डा सुखमोय चक्रवर्ती का मत है कि भारत को वर्तमान विदेशी मुग्तान की समस्या को हल करने के लिए उन क्षेत्रों में आयात-प्रतिस्थापन पर अधिक जोर देना चाहिए जिनमें घरेलू उत्पादन की क्षमता अधिक मात्रा में पायी जाती है। ऐसे क्षेत्र निम्नांकित हैं - इस्पात उर्वरक खाद्य-नेल आदि। डा चक्रवर्ती का कहना है कि निर्यात-मवर्द्धन से भी उदात्त आयात-प्रतिस्थापन पर भरोसा करना देश के हित में होगा।

सरकार की आयात-नीति

(Import Policy of the Government)

भारत सरकार की आयात-नीति में समय-समय पर परिवर्तन किये गये हैं। कभी यह उदार रही है तो कभी कठोर। परिस्थितियों के बदलने पर यह पुनः उदार बना दी गयी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आयात-नीति उदार रखी गयी थी जिससे आयातों में काफी वृद्धि हुई। मई 1949 में आयातों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। 1950-51 में आयातों में पुनः उदारता बरती गयी। आयातों की सूची में कई वस्तुएँ जोड़ी गईं। 1953 में भी आयात के क्षेत्र में उदार नीति अपनायी गयी थी, लेकिन कई वस्तुओं पर आयात-शुल्क बढ़ाये गए जिससे उनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। 1955-56 में भी आयात-नीति का उद्देश्य देश की आर्थिक विवाम में योगदान देना रखा गया था और कच्चे माल व मशीनों के आयात के सम्बन्ध में उदार नीति अपनायी गयी थी। इस उदार नीति के परिणामस्वरूप 1956-57 व 1957-58 में आयात अपनी चरम सीमा तक पहुँच गये थे और इन दो वर्षों में लगभग 481 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय-कोष खाली हो गए थे।

देश के समक्ष विदेशी विनिमय संकट के आने से 1957 के मध्य से उदार आयात-नीति छोड़ दी गई और आयातों पर बड़े प्रतिबन्ध लगाये गये। आयात-नियन्त्रण को केवल नवारात्मक रूप से ही नहीं देखा गया बल्कि इसे देश के औद्योगिक विकास के लिए काफी लाभदायक माना गया। इसके लिए कच्चे माल व मशीनों के आयात पर बल दिया गया। साथ में, विदेशी विनिमय की रक्षा करने के लिए उद्योगीय वस्तुओं के आयात में कमी करना भी आवश्यक समझा गया। निर्यात उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल व अन्य साज-सामान के आयात को महत्व देना स्वीकार किया गया। फरवरी, 1962 में आयात-निर्यात समिति (मुद्रालयपर समिति) ने आयात-नीति व पद्धति के सम्बन्ध में कई उपयोगी सुझाव दिये थे।

अवमूल्यन के बाद आयात-उदारता की नीति (Import Liberalisation After Devaluation)—6 जून, 1966 को रुपये के अवमूल्यन के बाद सरकार ने 59 प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को छह महीने के आघार पर कच्चा माल व अन्य आवश्यक साज-सामान मँगाने के लिए उदारतापूर्वक आयात-लाइसेंस देने की नीति अपनायी ताकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ सके और उद्योगों की अप्रयुक्त उत्पादन-क्षमता का अधिक उपयोग किया जा सके।

1967-68 व 1968-69 में जो आयात-नीति अपनायी गयी वह भी निर्यात बढ़ाने वाली थी। इससे निर्यात उद्योगों की इन्साइडों को आयात-लाइसेंस की सुविधा दी गई। आयात नीति के माध्यम से अनावश्यक आयातों पर पूर्ण प्रतिबन्ध एवं अन्य कई मदों के आयातों पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाने की नीति अपनायी गयी। इस प्रकार आयात नीति में 'प्रेरणाओं एवं सजाओं' के उचित सम्मिश्रण के कारण इसे 'Carrot and Stick' की नीति कहा गया है।

पिछले वर्षों में आयात नीति की विशेषताएँ

हम 1985-88 व 1988-91 के लिए त्रिवर्षीय निर्यात-आयात नीतियों की चर्चा करने से पूर्व 1969-85 की अवधि में अपनायी गयी आयात नीति अथवा निर्यात-आयात नीति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। ये नीचे दी जाती हैं।

1 सरकार ने उत्तरोत्तर अधिक वस्तुओं के आयातों को अपने हाथ में लेने की नीति अपनायी है। इसने लिए वस्तुओं की सूची को सरकारी सूची (canalised list) कहते हैं। इस सूची में शामिल वस्तुओं के आयात किसी सार्वजनिक एजेंसी को सौंप दिये जाते हैं। प्रति वर्ष जब आयात-निर्यात नीति घोषित की जाती है तब इस सूची में भी परिवर्तन किये जाते हैं। प्रायः कुछ नई मदें सरकारी सूची में जोड़ी जाती हैं और कुछ पुरानी मदों को इसमें से हटाया भी जाता है (decanalised)।

प्रश्न उठता है कि सरकार ने आयातों की बढ़ती हुई मात्रा को सार्वजनिक प्रबन्ध में लेने का प्रयास क्यों किया? दागली समिति ने नियन्त्रणों व सटिस्डी पर अपनी रिपोर्ट में इनके कई कारण दिये हैं जैसे आयातों के विलो में ऊँचे भाव लगाने की प्रचलित गलत प्रथाओं को रोकना समाजवादी देशों से व्यापार बढ़ाना, अभाव को दूर करने के लिए देश में शीघ्रता से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ाना, आवश्यक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करके लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करना एवं नियोजन की आवश्यकताओं के मुताबिक विदेशी व्यापार को संचालित करना, आदि।

इस प्रकार सरकार ने कई वस्तुओं के आयातों को सार्वजनिक प्रबन्ध में लेकर आयात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है। राज्य व्यापार निगम (STC) सार्वजनिक व्यापार की मुख्य एजेंसी रहा है।

2 कई प्रकार की वस्तुओं के आयातों को बन्द करने तथा कम करने की नीति अपनायी गयी है। आयातों पर नियन्त्रण के लिए तीन सूचियाँ होती हैं— निषेधात्मक (banned), प्रतिबन्धित (restricted) तथा स्वतन्त्र (free)। जो मर्दे निषेधात्मक सूची में होती है उनका आयात नहीं हो सकता। प्रतिबन्धित आयात सूची में आयात एक सीमा से अधिक नहीं किये जा सकते। स्वतन्त्र सूची को खुले जनरल लाइसेन्स (Open General Licence) (OGL) की सूची कहा जाता है जिसमें आयात की खूली इजाजत दी जाती है। इस प्रकार इन तीन सूचियों के जरिए सरकार सीमित विदेशी विनिमय का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करती है। मर्दे आवश्यकतानुसार एक सूची से दूसरी सूची में ट्रान्सफर की जाती है।

1984-85 की आयात नीति में निषेधात्मक सूची (banned list) समाप्त कर दी गई क्योंकि अब इस सूची का कोई अर्थ नहीं रह गया था। इसमें शामिल वस्तुएँ पुनर्पूर्ति लाइसेन्स (REP licences) आदि के अंतर्गत आयात करने दी जाती हैं। इसमें केवल एक मद टेली या चर्बी रह गई थी।

3 लघु उद्योगों के विकास के लिए आयात-निर्यात में विशेष सुविधाएँ दी गयी हैं ताकि वे पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकें। इनके लिए आवश्यक कच्चे मान कल-पुर्ज तथा मशीनरी आदि के आयात की व्यवस्था की जाती है। सरकार की उदार आयात नीति में इन विशेष सुविधाओं का विस्तार किया गया है। पिछले वर्षों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष रियायतें दी गयी हैं। लघु वंशाने की औद्योगिक इकाइयों के लिए पुन लाइसेंस (repeat licence) देने की सीमा बढ़ायी गयी है। इस प्रकार आयात नीति में लघु उद्योगों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इनके लिए मशीनों व मशीनी औजारों के आयात की व्यवस्था भी की गयी है।

4 अनिवार्य निर्यात कार्यक्रम का उत्तरोत्तर विस्तार किया गया है ताकि भारत के निर्यात बढ़ सकें। निर्यात उद्योगों के लिए कच्चे ताल आदि की सुविधाएँ बढ़ायी गयी हैं। 1983-84 की आयात-निर्यात नीति में 100% माल निर्यात करने वाली इकाइयों को अविन सुविधाएँ दी गयी थी। उन्हें सेकिण्ड ट्रेण्ड प्रोजेक्ट वस्तुओं, जेनरेटिंग सेट्स, पैकिंग का सामान, आदि का भी आयात करने की इजाजत दी गई थी।

इस प्रकार आयात-नीति रोजगार बढ़ाने वाली, निर्यातकों को प्रोत्साहन देने वाली तथा विदेशी विनिमय को रखा करने वाली रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश

में उत्पादन बढ़ाना तथा निर्यात-संवर्द्धन करना रहा है। कुछ विभागर हाथ के कर्मी में प्राधान-नीति का भूझाव उदारता की ओर हो रहा है।

पी. सी. एलेक्जेंडर समिति (P. C. Alexander Committee) के प्राधान-निर्यात-सम्बन्धी नीति पर सुझाव

सरकार ने प्राधान-निर्यात नीति पर सुझाव देने के लिए दूधे आंग्लस्य सचिव डॉ. पी. सी. एलेक्जेंडर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 1978 को देग की। समिति ने सुझाव दिया कि निर्यात के क्षेत्र में उत्तम नियोजन के लिए प्राधान-निर्यात नीति की प्रत्येक घटक के उचित प्रिकर्षण कीपता की जानी चाहिये। नीति कर्ष में एक बार प्राधान-नीति की कीपता कर्ष में विदेशी व्यापार नीति में अतिरिक्त व्यापारी, प्रतिस्पर्धता कम होगी, उत्पादक व निर्यातक अपने क्षेत्र में कार्यकर्मी का स्वादा अच्छा निपादन कर सकेंगे।

समिति की मुख्य विचारधारा निम्नांकित है जिसके आधार पर निम्न कर्मी की प्राधान-नीति बनायी गयी है—

1. समिति का कहना है कि प्राधान-निर्यात की केंद्रय के ही मर्दे सरकार अपने हाथ में ले जिसमें अतिरिक्त मात्रा में व्यापार के लाभ मिलें, उदनीता की अतिरिक्त अच्छी सेवा प्रदान करनी हो, अनुचित व्यापार-निर्यात रोक्की हो तथा अंतर्देशीय पूर्ति निर्माण कर्ष में की जानी हो। अन्य मर्दी की सरकार अपने अतिरिक्त क्षेत्र में होता है।

2. कर्षे माय, कुल-पुत्री व अन्य मात्र-मान्य के प्राधानों की की अंशितों में गयी मर्दा—(i) सीमित मात्रा पर अनाद दिया जाने वाला माय; तथा (ii) बहु माय जिसका प्राधान गैर दिया गया है। अंश की कुल कर्ष में अतिरिक्त दिया जाय।

3. समिति ने निम्नकर्मी के स्वाद पर विचार की अतिरिक्त कर्दामा है। समिति का सुझाव था कि प्रकल्प कीर्तित उपायों की अतिरिक्त मर्दी (assisted export) के कर्दाम के कर्दाम में 10% कीर्दाम मात्र कर्ष के अतिरिक्त माय दिया जाता चाहिये। उदाहरण कर्दाम के लिए कर्दाम मायों की अतिरिक्त कर्ष मर्दी जानी चाहिये।

4. कर्दाम प्राधानों के सम्बन्ध में कर्दाम कर्दाम प्राधान माय-अतिरिक्त (system of export licenses) कर्दाम कर्दाम है, जिसमें इसके अतिरिक्त की कर्दाम निपात है। इसमें इसे सम्बन्ध कर दिया जाता चाहिये।

5. निम्नकर्मी के लिए की जाने वाली कर्दाम कर्दाम का प्राधान अतिरिक्त कर्दाम कर्दाम जानी चाहिये।

6 निर्यात-गृहों को अपने निर्यातों पर मिला हुआ आयात करने का अधिकार जारी रखा जाना चाहिए। इन्हें प्रतिरिक्त आयात-लाइसेंस भी दिये जाने चाहिए।

7 समिति ने लघु उद्योगों को आवश्यक आयातित माल उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी सुझाव दिये ताकि इन्हे उचित भावों पर कच्चा माल मिल सके। इसके लिए लघु उद्योग-निगमों को आवश्यक सुविधाएँ देने पर जोर दिया गया।

8 आयात निर्यात के प्रमुख कंट्रोलर (CCI & E) के पद के स्थान पर विदेशी व्यापार के डाइरेक्टर-जनरल (DGFT) का पद रखा जाना चाहिए। यह कहा गया कि (DGFT) निर्यातों की समस्याओं को हल करेगा। इन न्यायनयन म अनुमती व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

इस प्रकार अलेक्जेंडर समिति ने प्रचलित आयातकों के लिए कोटा लाइसेंस पद्धति की समाप्ति, नकद सहायता को युत्तिष्ठगत करने, टेक्नोनोंजी के उदारणापूर्वक आयात करने तथा लघु उद्योगों के लिए विशेष सुविधाएँ देने से सम्बन्धित कई उपयोगी सुझाव दिये थे।

जनता शासन-काल में 1977-78 से 1979-80 के तीन वर्षों के लिए आयात नीतियां घोषित की गयी थी जिनमें आयात-उदारता का दृष्टिकोण ही अपनाया गया था। आयात नीति का उद्देश्य कृषि, उद्योग व व्यापार का विकास करना था। साथ में इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना निर्यात बढ़ाना तथा लघु उद्योगों का विकास करना भी था। इसके लिये विभिन्न प्रकार की रियायतें घोषित की गयी थी जिन्हें प्रायः के वर्षों में जारी रखा गया।

भारत में विदेशी मुग्तान की जटिल स्थिति के बावजूद पिछले वर्षों में उदार आयात नीति अपनायी गई है ताकि औद्योगिक उत्पादन व निर्यात बढ सकें। सामान्यनया व्यापार के जारी घाट की स्थिति में कठोर आयात-नीति अपनायी जाती है ताकि आयातों में कमी करके व्यापार के घाटे को कम किया जा सके। लेकिन भारत अपनी विशेष परिस्थितियों व विकास की आवश्यकताओं के कारण उदार आयात नीति का ही पालन करता रहा है।

यव हम क्रमशः 1985-88 व 1988-91 के लिए घोषित निर्यात-आयात नीतियों का वर्णन करेंगे—

(अ) 1985-88 की अवधि के लिए निर्यात-आयात नीति¹

(Exim Policy For 1985-1988)

सरकार ने 12 अप्रैल, 1985 को पहली बार 1985-88 तक के तीन वर्षों के आयात-निर्यात नीति-घोषित की थी। इससे पूर्व यह वार्षिक व्यापार पर घोषित

1. *The Economic Times*, April, 13 1985, p. 8.

की जाती थी। एक साथ त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति घोषित होने से विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अधिक निरन्तरता व निश्चितता आ सकेगी।

भारत सरकार ने तात्कालीन वित्त एवं वाणिज्य मन्त्री के अनुसार यह नीति न तो उदार है और न प्रतिबन्धात्मक बल्कि सन्तुलित है।"

इस त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन व निर्यात बढ़ाना तथा बायेंकुशा आयत-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना था। वास्तव में इसने निर्यात-सबर्द्धन व आयात प्रतिस्थापन दोनों के बीच एक उचित संतुलन व सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि आयात-निर्यात नीति तीन वर्षों के लिए घोषित की गयी थी, लेकिन लाइसेंसिंग की प्रक्रिया वार्षिक आधार पर जारी रहती गयी।

अब हम इस निर्यात-आयात नीति (एक्जिम नीति) (Exim Policy) की प्रमुख बातों का उल्लेख करते हैं।

1985-88 की निर्यात-आयात नीति की प्रमुख बातें

1. पूँजीगत वस्तुएँ (Capital goods)—घाघुनिजीकरण व निर्यात-उत्पादन के लिए मशीनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए औद्योगिक मशीनरी की 201 मर्दों की खुले जनरल या सामान्य लाइसंस (OGL) के अन्तर्गत आयात की जा सकने वाली पूँजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल कर दिया गया। इस उदार नीति के फलस्वरूप निम्न उद्योग लाभान्वित हुए—गाड़िया, तेल-क्षेत्र की सेवाएँ, घमडा इलेक्ट्रोनिक्स जूट-विनिर्माण, गारमेट, होजियरी का भाल, पेन, कैनिंग आदि। पूँजीगत वस्तुओं की 4 मर्दों को OGL से हटा दिया गया।

यह कहा गया कि 10 लाख रुपये तक की लागत के कम्प्यूटर/कम्प्यूटर आधारित सिस्टम्स उन सभी व्यक्तियों द्वारा आयात किये जा सकेंगे जो उनका उपयोग स्वयं करेंगे।

2. स्वचालित लाइसेंसिंग (Automatic Licensing) की थोड़ी समाप्त कर दी गयी और स्वचालित या अपने आप इजाजत वाली सूची (Automatic Permissible List) को खुले जनरल लाइसंस (OGL) के अन्तर्गत लाया गया। उस सूची में से 467 मर्दों को OGL में हस्तांतरित कर दिया गया और 60 मर्दों सीमित इजाजत वाली सूची (Limited Permissible List) में डाल दी गयी। इससे लघु क्षेत्र की इकाइयों को आयात-लाइसेंस लेने में आसानी हो गयी।

3. आयातों की सरकारी बाधरे में लेने के सम्बन्ध में नीति (Canalisation of Imports)—53 मर्दों की सरकारी बाधरे से मुक्त कर दिया गया (De-Canalised)। इनमें से 17 मर्दों OGL की सूची में हस्तांतरित कर दी गयीं, 20 मर्दों सीमित इजाजत वाली सूची (Limited, Permissible List) में तथा 16 प्रतिबन्धित सूची (Restricted List) में डाल दी गयीं। OGL में हस्तांतरित की जाने वाली मर्दों में सोहे व इस्पात की मर्दें, रगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूब्स आदि हैं।

देश में उपलब्ध बढ जाने के कारण कच्चे मात व कल-पुर्जों की 7 मदी को सीमित इजाजत वाली सूची से प्रतिबन्धित सूची में डाल दिया गया तथा 67 मदी को OGL/स्वचालित इजाजत वाली सूची में सीमित इजाजत वाली सूची में डाल दिया गया। इनमें कुछ मदे इस प्रकार हैं : मारबल, कृद्ध लेम्पस, कृद्ध बीडियो ईसेट बिना टप के, कुछ छपाई की स्याही आदि।

पशु चर्बी व रेनेट को निषिद्ध मद (Banned Item) माना गया।

भारत आकर बसने वाले तथा यहा उद्योग स्थापित करने वाले नोन-रेजीडेंट भारतीय (NRD) के लिए कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ायी गयीं, जैसे वे प्रतिबन्धित सूची वाली मशीनरी का भी भारत में आयात कर सकेंगे, वगैरह वही कम से कम दो वर्षों के लिए उनके द्वारा बहा निरन्तर उपयोग में लायी गयी हों।

4 अनिवार्य मदों के आयात की व्यवस्था—OGL के अन्तर्गत कुछ अनिवार्य उपभोग्य मदों का आयात जारी रख गये जैसे जीवन-रक्षक दवाइया, दांतों की मदे, जीवन-रक्षक उपकरण, मेडिकल एक्स-रे फिल्म, पुस्तकें व अध्यापन कार्य में सहायता पहुचाने वाली मदे, कुछ मसाले आदि।

5 आयात-निर्यात पास बुक स्कीम—रजिस्टर्ड निर्याता/निर्यातक जो कम से कम तीन साल से नियमित रूप से निर्यात कर रहे हैं, अब 'आयात-निर्यात पास बुक स्कीम' का लाभ उठा सकेंगे। इससे उम्मेद निर्यात-उत्पादन के लिए आवश्यक शुल्कमुक्त इन्पुटों का आयात करने में सहायता होगी। इसके लिए वास्तविक उपयोग कर्ता बनें लागू मानी जायगी। इस स्कीम के कारण प्रिमि/इम्प्रेस्ट व पुनर्पूर्ति लाइसेंस (REP Licences or Replenishment Licences) के लिए बार-बार आवदन पत्र देने की जरूरत नहीं रहेगी। पास-बुक स्कीम वालों के लिए शुल्कमुक्त आयात लाइसेंस का काम करेगी। प्रत्येक ऐसे लाइसेंस के लिए एक उपयुक्त निर्यात-आयात निमाना पड़ेगा।

निर्यात-व्यापार-घरानों को लाइसेंस लेन की सहूलियतें बढ़ाई गयी हैं।

6 निर्यात लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए—पाकिस्तान को किये जाने वाले निर्यात अन्य देशों के समकक्ष लाये गये। अब सिल्क वेस्ट, एसोटीन फिनोन आदि के निर्यात पर विचार किया जा सकेगा। इसी प्रकार रैद्योन सिगारेट मार्ग मोडियम कबोराइट तथा ऊटो के निर्यात पर (प्रजनन कार्य के लिए) विचार किया जा सकेगा।

कई प्रकार की खाली (विशेष किस्म की लोमड़ी, बिन्ती, आदि की) तथा धान, सभी किस्म के तिलहनो व दांतों के बीजों, चारकोल (कृद्ध किस्मों को छोड़कर) का निर्यात भी सामान्यतया नहीं किया जा सकेगा।

ऊपर विवरण आयात-निर्यात नीति की प्रमुख बातों का विवेचन किया गया है। व्यापार व उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इसका हार्दिक स्वागत किया था तथा इसे

काफी प्रगतिशील व सामकारी बतलाया था। नीचे इसके गुण-दोषों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है।

नयी आयात-निर्यात नीति के गुण

1. व्यापसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में नयी आयात-निर्यात नीति को टेक्नो-सोजिकल उत्पादन व आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाली नीति के रूप में सराहा गया। इसके द्वारा एक प्रगतिशील औद्योगिक व राजकोषीय नीति का क्रम जारी रखा गया।

2. इसे भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने वाली माना गया। तीन वर्षों के घोषित क्रिये जाने की वजह से यह उद्योगों में उत्पादन की दीर्घकालीन योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगी। यह कहा गया कि औद्योगिक मशीनरी की 20% मर्चों को OGL में शामिल करने से आधुनिकीकरण व निर्यात-संवर्द्धन को प्रबल बल मिलेगा।

3. उत्पादकों व निर्यातकों के लिए आयात-निर्यात पास-बुक स्कीम को लागू करने से कच्चे माल का आयात अधिक सुगम व अधिक शीघ्र होने लग जायगा जिससे बिलम्ब को दूर करने में सहायता मिलेगी। इस स्कीम को सर्वोत्तम माना गया। पास बुक स्कीम का विचार एक नया विचार है जिसके द्वारा उत्पादकों-निर्यातकों द्वारा शुरुमुक्त आयात करने में आसानी रहेगी।

पहले बतलाया जा चुका है कि त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति (1985-88) एक समुचित नीति थी। यह न तो उदार थी और न कठोर या प्रतिस्पर्ध लगाने वाली। इससे समय व लागत में किरायात हुई।

नयी आयात-निर्यात नीति की कमियाँ

1. यह त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति सातवीं योजना (1985-90) के प्रथम तीन वर्षों से सम्बन्ध रखती है, लेकिन इसमें योजना का जरा भी जिक्र नहीं है। इससे व्यापार-नीति व नियोजन-नीति में पूर्ण ताल-मेल नहीं प्रतीत होता।

2. इस नीति में निर्यातों से जुड़े आयातों को बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विदेशी धरो में निर्यातकों को निर्यातों की एज में जो पुनर्पूर्ति के लाइसेंस (replenishment licences) दिये गये हैं उनसे देश में निजी क्षेत्र के उद्योगों को आयातित कच्चे माल, कच्चे-पुर्जे आदि की सुविधा मिली है जिसका उपयोग आन्तरिक निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने में अधिक मात्रा में किया गया है। निर्यातों से जुड़े इन आयातों का उपयोग निजी क्षेत्र के एक वर्ग ने अपने लाभों को बढ़ाने में ही अधिक किया है, जिससे 'वस्तुविक उपयोगकर्ताओं' को आयात आश्वासन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाये है। इस प्रकार आयातों को निर्यातों से जोड़ने की नीति के बावजूद निर्यातों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकी, क्योंकि आयातित कच्चे माल का उपयोग घरेलू बिजली के लिए उत्पादन में ज्यादा मात्रा में किया गया।

3. संयन्त्र व मशीनरी का उदारतापूर्वक आयात करने से देश में औद्योगिक मशीनरी के निर्माताओं जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा हेवी इंजीनियरिंग निगम (BHEL and HEC) आदि के माल की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

इसी प्रकार, सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये मूल्य तक वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम के मायात की इजाजत से देश में कम्प्यूटरों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह बात अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर भी लागू होती है।

4. सब पूछा जाय तो सरकार अपनी औद्योगिक व व्यापार-नीति के माध्यम से एक ऐसे औद्योगिक ढांचे को विकसित कर रही है जिसका लाभ समाज के छोटे के 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत परिवारों को ही मिलेगा।

इस प्रकार आपुनिकीकरण, टेक्नोलॉजिकल उत्थान आदि क्रियाओं में घायतित पूँजीगत माल, बस-पुर्जो, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग बढ़ने से समस्त देश-विदेशी जो दलाल लोग नहीं मिले' क्रिया समाज के सीमित सम्पन्न व सम्प्रात वर्ग को मिलेगा ।

(आ) नई त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति, 1988-91

अप्रैल 1988 से मार्च 1991 तक की अवधि के लिए नई त्रिवर्षीय धायान-
नियान नीति 30 मार्च 1988 को घोषित की गई। इसके मुख्य उद्देश्य व प्रमुख
प्रमुख बातें नीचे दी जाती हैं—

मूढप बहुवच

(1) औद्योगिक विज्ञान को प्रोत्साहन देना और इसके लिए आवश्यक माया-
तितन पूंजीगत माल, बच्चे माल व बन्-मुर्जों की व्यवस्था करना ताकि माधुनिकी-
करण, प्चनादाजिकल विकास व उत्तरोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में
आए वृद्धि सके.

(11) कार्यकृशन् शायते प्रतिस्थापन व आत्म-निमंरता को बढ़ावा देता:

(iii) निर्धारित-प्रोत्साहन को नई प्रेरणा देना और इसके लिए प्रेरणाप्राप्तों की गतिविधियाँ व उनके प्रयासों में सहाय्य करना, एवं

(14) नीति व विधियों को सरल व युक्तिमग्न बनाना ।

नीति की प्रमुख शक्तें

(1) दम नीति ने इन्फेन्सिबल खुले सामान्य साइसेस (OGL) का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और इसमें 745 प्रतिरिक्त मर्दे शामिल की गई हैं। इनमें से 329 मर्दे लड़के माल, स्त्र-पुत्रों व अप्रमोक्ष माल की हैं, 209 लड़के जीवन-रक्षा उपकरणों की हैं, 108 जीवन-रक्षा दवाएँ हैं तथा 99 पूजीगत वस्तुएँ हैं। ये पूजीगत वस्तुएँ नियॉनोन्मुस क्षेत्र की मशीनरी से सम्बन्ध रखती हैं। इनके माध्यम से

इलेक्ट्रॉनिक्स, रेशम, चाय व बमड़ा उद्योग के लिए मशीनरी व उपकरण की सप्लाई बढ़ायी गयी है।

इससे उद्योगों के विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारतीय माल विदेशों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन सकेगा।

(2) आयात पुनः पूर्ति/पुनः भर्ती की स्कीम (REP scheme) में काफी संशोधन किये गये हैं। गैर-परम्परागत व परम्परागत दोनों प्रकार के निर्यातों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पुनः पूर्ति की स्कीम को अधिक व्यापक व उदार बनाया गया है। 10 लाख रुपये तक की पूंजीगत वस्तुएं स्वदेशी मिलप्रोसेस लिये बिना निर्यातकों द्वारा आयात की जा सकेंगी।

(3) सरकार ने निर्यातों पर से नियन्त्रण कम किये हैं। वर्तमान सूची में से 26 मशिनों को सरकारी क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है (decanalised)।

इस प्रकार, यह दूसरी त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति पहली त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति की उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी।

उदार आयात-नीति के परिणामस्वरूप 1985-86 में व्यापार का घाटा 8,763 करोड़ रुपये हो गया था। पिछले वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात काफी घटे हैं। ये 1987-88 में 6285 करोड़ रु. के रहे। इससे पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के समक्ष मन्दी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसका समुचित समाधान निकालने की आवश्यकता है।

इसलिए नई आयात-निर्यात नीति, 1988-91 का काम औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, नियमित माल की किस्म में सुधार करना, उसकी लागत कम करना व भारतीय निर्यातों को विश्व के बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। साथ में इसका एक कार्य कार्यकुशल व चुने हुए ढंग के आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना भी है। ये सब विदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियां हैं।

क्या नई आयात-निर्यात नीति निर्यात-प्रोत्साहन दे पायेगी ?

भारत में निर्यात-प्रोत्साहन की नितान्त आवश्यकता है ताकि व्यापार के घाटे को कम किया जा सके। पहले बतलाया जा चुका है कि देश में निर्यात-चालित विकास (export-led growth) की नीति के बजाय विकास-चालित निर्यात (growth-led export) की नीति ज्यादा व्यावहारिक व कारगर सिद्ध होगी। अतः हमें औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है और निर्यात बढ़ाने के उपाय करने हैं। भारत में अभी तक निर्यात की संस्कृति (export culture) पर्याप्त रूप में विकसित नहीं हो पायी है। निर्यात-वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने की समस्या है। भारतीय उत्पादकों के लिए घरेलू बाजार का आकर्षण बना हुआ है। निर्यातक अधिक निर्यात-प्रेरणाएं चाहते हैं ताकि वे निर्यात बढ़ाने में अधिक दिलचस्पी ले सकें। 1988-91 की अवधि के लिए घोषित आयात-निर्यात नीति सम्भवतया निर्यात बढ़ाने में पर्याप्त योगदान नहीं दे पायेगी क्योंकि जब तक निर्यात-संबद्ध न-नीति आत्म-निर्भर, अधिक

विकास से नहीं जुड़ पाती तब तक वास्तविक आर्थिक प्रगति की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए भारी प्रयास करना जरूरी है।

फिर भी, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में नई त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति, 1988-91 की दिशा सही प्रतीत होती है। और सरकार को इसे परिणाम दिखाने का समुचित अवसर देना होगा। इसलिए आगामी तीन वर्षों में इसमें भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

प्रश्न

- 1 वर्तमान परिस्थितियों के सदर्भ में भारत में निर्यात सबवर्द्धन क्यों आवश्यक है ? निर्यात-सबवर्द्धन के लिए प्रस्तावित गये उपायों का उल्लेख कीजिए।
(Raj. Hlyr. T.D.C., 1987)
- 2 वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में भारत में निर्यात-सबवर्द्धन क्यों आवश्यक है ? इस सम्बन्ध में जो उपाय किये गये हैं, उनका उल्लेख कीजिये।
(Raj. Hlyr. T.D.C., 1981)
- 3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : (a) विदेशी व्यापार नीति।
(Raj. Hlyr. T.D.C., 1981 & 1986)
4. नयी त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति; 1988-91 की प्रमुख बातें स्पष्ट कीजिए।
5. भारत की विदेशी व्यापार नीति पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
(Raj. Hlyr. T.D.C., 1988)

विदेशी सहायता : आकार, उपयोग व भुगतान की समस्याएँ

(Foreign Aid : Size, Utilisation & Problems of Repayment)

विदेशी साधनों के तीन प्रकार के स्रोत—निर्धन व विकासशील देश केवल अपने सीमित साधनों से तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं कर सकते। विदेशी साधनों का उपयोग करने से उन्हें काफी लाभ होता है। इन साधनों के स्रोत तीन प्रकार के होते हैं—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) आदि, एवं प्रादेशिक वित्तीय संस्थाओं जैसे एशियन विकास बैंक से प्राप्त ऋण, (ii) विदेशी सरकारों से जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, कनाडा आदि से प्राप्त ऋण व सहायता तथा (iii) विदेशी निजी कम्पनियों से अथवा बहुराष्ट्रीय निगमों (multinationals) से एवं विदेशी बैंकों से व्यापारिक कर्ज की राशिवा (commercial borrowings)। विदेशी सरकारें ऋण व अनुदान देती हैं। ऋणों को व्याज सहित लौटाना होता है तथा अनुदान भेटस्वरूप होते हैं।

विदेशी सहायता में विदेशी ऋण व अनुदान दोनों शामिल किये जाते हैं। कम व्याज पर लम्बी अवधि के ऋण रियायती सहायता के अन्तर्गत आते हैं। विदेशी सहायता में निजी विदेशी कम्पनियों के विनियोग शामिल नहीं किये जाते। विदेशी पूँजी में विदेशी संस्थाओं व सरकारी के ऋण तथा विदेशी कम्पनियों के विनियोग शामिल होते हैं, लेकिन इसमें अनुदान (grants) शामिल नहीं होते।

विकासशील देशों के लिए उपरवर्णित तीनों स्रोतों से प्राप्त विदेशी साधनों का काफी महत्व होता है। भारत ने भी तीनों स्रोतों से प्राप्त विदेशी साधनों का काफी उपयोग किया है और इससे हमारे आर्थिक विकास में सहायता मिली है।

भारत एक विकासशील देश है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय यह आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। यह कृषि, सिंचाई, उद्योग, शक्ति, परिवहन, तकनीकी

ज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में पिछड़ी दशा में था। हमने नियोजित आर्थिक विकास का मार्ग चुना और विभिन्न दिशाओं में विकास के लिए विदेशी सहायता का उपयोग करना आवश्यक समझा। प्रारम्भ में तो विदेशी सहायता की आवश्यकता आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए थी, लेकिन अब विकास की गति को बढ़ाये रखने के लिए, पुराने ऋणों का नुपतान करने के लिए तथा विदेशी व्यापार के अत्यधिक घाटे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए रियायती शर्तों पर विदेशी सहायता का मिशन आवश्यक हो गया है। नीचे भारत के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है।

भारत के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता के कारण

1. विदेशी विनिमय-संकट को टालने के लिए विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी नुपतान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपात तेजी से बढ़ जाते हैं और निर्यातों की बढ़ाते में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः देश की समस्त विदेशी विनिमय-संकट उत्पन्न हो जाता है। विदेशी विनिमय-कोष लगभग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में 'विदेशी सहायता' से ही विदेशी विनिमय संकट को टाला जा सकता है।

2. प्राकृतिक साधनों का विदोहन—भारत में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधन विद्यमान है। अभी तक उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। विदेशी पूँजी के सहयोग से हम उनका उचित रूप से विदोहन कर सकते हैं और देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा कर सकते हैं। विदेशी सहायता के अभाव में प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

3. तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति—विदेशी पूँजी के साथ-साथ हमें विदेशी तकनीकी ज्ञान व प्रबन्धनीय दक्षता भी प्राप्त होती है जिससे विशेषतया औद्योगिक क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इससे देश में तकनीकी जानकारी व प्रबन्धनीय कुशलता का भी विकास होता है, जो अन्यथा तेजी से सम्भव नहीं हो पाता।

4. भारतीय पूँजी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए—विदेशी पूँजी के अभाव में भारतीय पूँजी का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जब कोई उद्योगपति भारत में अपना बड़े पैमाने का आधुनिक उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे प्रायः मशीनें, कच्चा माल व अन्य विकास-सामग्री विदेशों से खरीदनी पड़ती है। यदि आवश्यक मात्रा में विदेशी माल न मिले तो सारा कार्यक्रम ठप्प हो सकता है। यदि आवश्यकता के अनुसार विदेशी पूँजी उपलब्ध हो जाती है तो स्वदेशी पूँजी का भी सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है।

5. परिवहन खनन व भारी उद्योगों का विकास—रेल, वन्दरगाह, बांध, सिंचाई की परियोजनाओं, खनिज-व्यवसाय एवं आधारभूत पूँजीगत उद्योगों के विकास

में ग्रन्थ देशों के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए भी विदेशी पूँजी आवश्यक होती है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की उत्पादन प्रणालियों को अपनाकर हम तेजी से औद्योगीकरण कर सकते हैं। इस तरह सभी पहलुओं पर विचार करने पर, जैसे घरेलू बचत के पूरक के रूप में, घरेलू बचत के स्तर को ऊँचा करने में और विदेशी विनिमय की कमी को दूर करने के लिए विदेशी सहायता का भारत के आर्थिक विवास में बहुत ऊँचा स्थान माना गया है।

6. पुराने ऋणों को चुकाने के लिए भी नये ऋण लेने आवश्यक हो जाते हैं। हमने योजना काल के प्रारम्भ में तथा बाद के वर्षों में विदेशों से जो ऋण लिए हैं, उनके लिए समय-समय पर ऋणों के भुगतान की भी व्यवस्था करनी पड़ी है और वह निरन्तर करनी पड़ रही है। यदि योजनाकाल में हमारी अर्थव्यवस्था काफी सबल व सुदृढ़ हो जाती तो हम अपने शक्तिरिक्त उत्पादन का निर्यात करके पुराने ऋणों का ब्याज सहित भुगतान करने में पूरी तरह समर्थ हो जाते। लेकिन कुछ कारणों से हम अपने निर्मात इतने नहीं बढ़ा सके कि चालू आयातों का भुगतान कर सकें तथा पुराने ऋणों को भी चुका सकें। ऐसी स्थिति में हमें बाध्य होकर विदेशी ऋणों के भुगतानों को आगे के लिए खिसकाना पड़ा है और इसका एक तरीका यही रहा है कि हम पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए नये ऋण लेते जाएँ। इस प्रकार हम अभी तक विदेशी सहायता पर आश्रित हैं और इससे मुक्त नहीं हो पाये हैं।

7. कुछ वर्ष पूर्व पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन, अर्थात् ओपेक (OPEC)* के द्वारा पेट्रोल के भावों में अत्यधिक वृद्धि कर देने से हमारा आयात-दिल बहुत ऊँचा हो गया था। हालांकि बाद में पेट्रोल व पेट्रोल पदार्थों के मूल्यों में कमी से हमें थोड़ी राहत मिली है। 1987-88 से पेट्रोल व सम्बद्ध पदार्थों के आयात की राशि पुनः बढ़ने लगी है। विदेशों में खाद्यान्नों व उर्वरकों के भावों में वृद्धि होने से भी आयातों की राशि बढ़ी है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए वर्तमान में भारत को रियायती शर्तों पर विदेशी सहायता की आवश्यकता है। स्वयं तेल-निर्यातक देशों से कर्ज लेने की भी व्यवस्था की गई है। मार्च, 1988 के अंत तक भारत ने ओपेक देशों से प्राप्त 1663 करोड़ रु की राशि का प्रयोग किया गया था जो कुल प्रयुक्त राशि का 3.9% था।

इस प्रकार पञ्चवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता का काफी उपयोग किया गया है। विभिन्न कारणों से आगामी वर्षों में भी विदेशी सहायता का उपयोग जारी रखना होगा।

* Organisation of Petroleum Exporting Countries इसमें ईरान, इराक, कुवैत, बाबुघाबी, सऊदी अरब तथा ओपेक स्पेशल फण्ड शामिल है।

विदेशी सहायता से कई प्रकार के लाभ मिलने के बावजूद भी इसके प्रति कई प्रकार की शिकाएँ व आशंकाएँ प्रकट की गई हैं। वास्तव में विदेशी पूँजी से कुछ कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में काफी सन्देह प्रकट किये गये थे, क्योंकि नूतनकाल में विदेशी पूँजी के साथ-साथ देश पर विदेशी राजनीतिक प्रभाव भी पड़ने लगा था। लेकिन पिछले वर्षों में आर्थिक सहायता देने वाले देशों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। साथ में विदेशी सहायता के विश्व बैंक आदि से सम्बन्धित आधार पर मिलने से कई प्रकार के पुराने सन्देह अपने आप कम हो गये हैं। पूँजी का आयात करने वाले देशों में भी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। परिणामस्वरूप, विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में पहले के सन्देह काफी कम हो गये हैं।

लेकिन बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता लेने से कुछ खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए प्रायः इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमें विदेशी सहायता से जल्दी से जल्दी मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए और आप-निर्भर अर्थव्यवस्था (self-reliant economy) का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। नवम्बर, 1981 में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) से जो 5 बिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDR)* अथवा लगभग 5,234 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करवाया था, उसको लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में सरकार की काफी आलोचना की गई थी। आलोचकों का कहना था कि भारत सरकार ने इतना बड़ा बर्ज लेकर देश का आर्थिक मंदित्व IMF को गिरवी रख दिया है। बर्ज की शर्तों पर काफी आपत्तियाँ उठायी गई थीं। इस सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति यह है कि उस समय भारत को अपने मुग्तान-पत्र को ढालने के लिए विदेशी विनिमय कोषों व विदेशी सहायता की नितान्त आवश्यकता थी। इसलिए विदेशी विनिमय साधनों की कमी को पूरा करने के लिए IMF से बर्ज लेना पड़ा था। IMF ने भारत को यह बर्ज विस्तृत-कोष-सुविधा (Extended Fund Facility) (EFF) के अन्तर्गत देना स्वीकार किया था। 1983-84 तक 3.9 बिलियन SDR तक की राशि निशालने के बाद भारत

* SDR अथवा स्पेशल ड्राइंग राइट्स अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसम्पत्ति (international reserve assets) होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं तथा सदस्यों को अन्य रिजर्व राशियों के पूरक के रूप में दिये जाते हैं। सदस्य देश SDR का उपयोग आपसी समझौतों से कई प्रकार के सौदों में कर सकते हैं। मुग्तान की जरूरत पड़ने पर सदस्य देश अपने SDR देकर आवश्यक विदेशी विनिमय प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए उनको IMF को व्याज देना होता है।

सरकार ने यह निर्णय लिया कि यह ऋण की शेष किस्त (1.1 बिलियन SDR) नहीं लेगी। सरकारी मन के अनुसार भारत के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार होने के कारण IMF कर्ज की शेष राशि नहीं ली गई। इस कर्ज में भारत को कुछ सीमा तक अपनी आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने का अवसर मिला था। वर्तमान में देश की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति काफी जटिल व तनावपूर्ण बनी हुई है और इनके ठीक करने के लिए भारी प्रयासों की आवश्यकता है।

विदेशी सहायता की कमियाँ व कठिनाइयाँ

1. बाह्य-सहायता से आर्थिक प्रगति नहीं हो पायी—कुछ विद्वानों का मत है कि विदेशी सहायता अत्यधिक मात्रा में देनी के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यह विद्वानें कुछ देशों के अत्यधिक विकास की गति को तेज नहीं कर सकीं। बनर (Baner) का विश्वास है कि निरन्तर बड़े पैमाने पर सहायता देने से सहायता देने वाला राष्ट्र निरर्थक हो जाता है। आर्थिक प्रगति के लिए त्रिग 'ग्राम-निर्माण, प्रगति और ग्राम-सम्मान' की आवश्यकता होती है वह नष्ट हो जाती है। प्रोफेसर पी. टी. बावर (P. T. Bauer) का भी यही मत है कि द्वितीय महायुद्ध के समय में विदेशी सहायता ने प्राप्तकर्ता राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति को धीमा बहाने का ब्रह्मण्य हो चुका है। विदेशी सहायता विकास के निर्धारक तथ्यों, जैसे लोगों की आर्थिक क्षमताओं व प्रवृत्तियों, उनके सु-घो, उन्हें धर्मों व प्रेरणाओं, उनकी सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं, प्राकृतिक साधनों व विदेशी बाजारों के अवसरों को अनुकूल रूप में प्रभावित नहीं करती है। बावर का मत है कि सुदूर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्व व पश्चिमी अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में कई देशों ने बिना विदेशी सहायता के काफी तेज गति से आर्थिक प्रगति की है।

विदेशी सहायता के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण काफी कटोर व एक-पक्षीय (extreme and one sided) प्रतीत होता है। व्यवहार में विकासशील देश अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता का उपयोग करते हैं तथा उससे लाभ उठाते हैं।

2. देश की स्वयंसेवा आर्थिक नीति को खतरा हो सकता है। भारत ने विभिन्न अवस्थाओं के प्रति में निर्धारित आर्थिक विकास की पद्धति अपनायी है जिसमें मार्क्स-जिनिश श्रेय के विकास को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हमारी विदेश नीति भी स्वयंसेवा के सिद्धान्त पर आधारित है। ऐसा स्थिति में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान व कम आदि देशों से लगातार आर्थिक सहायता देने से हमारी आर्थिक नीति पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक सहायता देने वाले देश प्रायः सहायता देने वाले देशों की आर्थिक नीतियों को अपने हित में मोड़ने की कोशिश करते हैं। अमेरिका बहुत सहायता देने समय निर्वा क्षेत्र को

बढ़ावा देने पर जोर देता है तथा आर्थिक नीति को उदार रखने का समर्थन करता है।

3 आयाज का निरन्तर बढ़ता हुआ भार—विदेशी पूँजी का उपयोग करने में वार्षिक व्याज व कर्ज की किस्त चुकाने का बोझ निरन्तर बढ़ता जाता है। मूलभूत व याज की समय पर अदायगी न होने से भी कठिनइयाँ उत्पन्न हो जाती है। बहुधा गुराने ऋण चुकाने के लिए नये ऋण लेने पड़ते हैं। ऋण सेवा भार क बढ़न से देश कर्ज के जाल में फँस सकता है।

4 विदेशों पर आर्थिक निर्भरता में वृद्धि—अत्यधिक मात्रा में विदेशी मशीनें, कल-पुर्जें कच्चा माल व तकनीकी जानकारी व अन्य साधन काम में लेन से हमारी विदेशों पर आर्थिक निर्भरता बढ़ जाती है। भारत आत्म-निर्भरता की तरफ अग्रसर होने की बजाय विदेशों पर आश्रित बना हुआ है।

कुछ प्रयत्नास्त्रियों का कहना है कि भारत को आन्तरिक साधनों पर ही पर्याप्त मात्रा में निर्भर रहना चाहिए। ऐसा करने से चाहे हमारे देश में विकास की गति कुछ धीमी भले ही पड़ जाय, किन्तु दीर्घकालीन दृष्टिकोण से यही मार्ग श्रेष्ठ रहेगा। विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाय जिससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़े और साथ में हमारी मूलधन व व्याज चुकाने की सामर्थ्य भी बढ़े। विदेशी सहायता में यथाशीघ्र मुक्त होने का प्रयास किया जाना चाहिए।

विदेशी सहायता व पूँजी के प्रति भारत सरकार की नीति

1948 की औद्योगिक नीति में सर्वप्रथम विदेशी पूँजी के महत्व पर प्रकाश डाला गया था और इसके सम्बन्ध में कई प्रकार के आश्वासन दिये गये थे। लेकिन इस नीति में राष्ट्रीयकरण व अन्य सरकारी नियन्त्रणों के अन्तर्गत विदेशी पूँजी का आयात आशा से बहुत कम हुआ। 5 अप्रैल, 1949 को स्व० प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोषणा की थी जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी—(1) देशी व विदेशी पूँजी के बीच कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जायेगा। विदेशी हितों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाय जायेगा (2) विदेशी विनियोगकर्ताओं को लाभ व पूँजी देश से बाहर ले जाने की अनुमति दी जायेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में देश की तत्कालीन विदेशी विनियोग स्थिति का अवश्य ध्यान रखा जायगा, (3) यदि कभी विदेशी उद्योगों व अन्य उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जायेगा। सरकार किसी भी रूप में विदेशी उद्यम को क्षति नहीं पहुँचाना चाहती और भारत के आर्थिक विकास में रचनात्मक सहयोग देने के लिए विदेशी पूँजी का स्वागत करती है।

योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में विदेशी पूँजी के महत्व को स्वीकार किया था। हमारे देश में विदेशी पूँजी लेते समय भारतीय

स्वीकृत हुई थी जिसमें से 42,347 करोड़ रुपये की राशि प्रयुक्त की गई थी।¹ इन प्रयोजनों में प्रयुक्त की गई विदेशी सहायता में अनुदानों (grants) का भूग लगभग 12 प्रतिशत (5107 करोड़ रु.) था, जो काफी नीचा माना जा सकता है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता (external assistance) की राशि (लक्ष्य व वास्तविक राशि) नीचे दी जाती है—

विदेशी सहायता की राशि²

(करोड़ रुपये में)

योजनाएँ	लक्ष्य (target)	वास्तविक प्राप्ति (actual)
प्रथम योजना	521	189
द्वितीय योजना	800	1,049
तृतीय योजना	2,200	2,423
चौथी योजना	2,435	2,426
चतुर्थ योजना	2,614	2,087
पंचम योजना	5,407	5,834
छठी योजना	9,929	8,529
सातवीं योजना, 1985-90	18,000	योजना जारी

तार्जिका से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजनाकाल से विदेशी सहायता का प्रयोग बढ़ा है। योजना में वास्तविक मार्जनात्मक व्यय के प्रतिशत के रूप में विदेशी सहायता का योगदान प्रथम योजना में 9.6%, द्वितीय योजना में 22.5%, तृतीय योजना में 28.2%, चौथी योजनाओं में 35.9% तथा चतुर्थ योजना में 12.9% रहा। पाँचवीं योजना में यह लगभग 14.8% रहा। छठी योजना, 1980-85 में यह 7.9% रहा। सातवीं योजना में विदेशों से प्राप्त होने वाली पूँजी का शुद्ध आगम (net inflow) 18000 करोड़ रु. आका गया है जो योजना में प्रस्तावित मार्जनात्मक परिव्यय का 10% होगा।

1. Report on Currency & Finance, 1987-88, Vol. I, Economic Review, p. 392
2. Report on Currency & Finance के विभिन्न अंक।

विदेशी सहायता का आगम
(Inflow of External Assistance)¹

(सकल व शुद्ध)

(करोड़ रुपये में)

	1987-88	1988-89
I सकल वितरित सहायता की राशि	5632	5369
II कुल ऋण-सेवा-भार की राशि	2623	2770
III सहायता का शुद्ध आगम (I-II)	2409	2599

विदेशी सहायता का शुद्ध आगम (net inflow of assistance) 1979-80 में 552 करोड़ रु रहा जो 1987-88 में 2409 करोड़ रु के स्तर पर रहा। 1988-89 में इसके लगभग 2600 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

मार्च, 1988 के अन्त तक प्रयुक्त की गई विदेशी सहायता में विभिन्न समस्याओं व देशों का अंश इस प्रकार था²—

ओर्गों के अनुसार प्रयुक्त सहायता (utilisation) का वितरण (मार्च 1988 तक)

	(करोड़ रुपये में)	(कुल का %)
(1) विश्व-बैंक	5710	13.5
(2) अन्तर्राष्ट्रीय विमान संघ (IDA)	10978	25.9
(3) अमेरिका	6299	14.9
(4) रूस	1826	4.3
(5) पश्चिमी बंगाल	2949	7.0
(6) संयुक्त राज्य (U.K.)	3420	8.1
(7) जापान	2768	6.5
(8) पेट्रोल निर्यातक देशों का समूह (OPEC)	1663	3.9
(9) अन्य (EEC, IFAD, ADB, व अन्य)	6734	15.9
कुल	42347	100.0

1. Economic Survey, 1988-89, p. 120.

2. Report on Currency & Finance, 1987-88, Vol. I, p. 392.

इस प्रकार मार्च, 1988 तक प्रयुक्त श्री गर्ट कुन महायन्त्रा की राशि में अमेरिका का योगदान लगभग 15 प्रतिशत था, जबकि रूस का केवल 4.3 प्रतिशत था। विश्व-बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एमोनियशन का योगदान 39.4% था। इस प्रकार भारत का दशक के अनुसार सर्वाधिक सहायता अमेरिका में मिली है।

भारत पर ऋण-सेवा-मार्ग नेनी में जाना जा रहा है। ध्यातव्य मूल्यन की निम्न वृद्धि में नियन्त्रित-प्रणाली का अर्थ अलग-अलग जाना है। 1987-88 में भारत का विदेशी ऋण पर ऋण सेवा भुगतान वाला प्रणिया (current receipts) (निर्यातों व अदृश्य मध्य से प्राप्त राशियों) का 24% हो गया है जिसमें आगामी वर्षों में और बढ़ने की सम्भावना है।¹ यह 1984-85 में 13.6% था। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों में यह काफी बढ़ा है।

पारिस्मिता में ऋण-सेवा-अनुपात भारत में जंचा है। अतः ऋण-सेवा-भार की दृष्टि में भारत की स्थिति पारिस्मिता से ना थोड़ी उन्नत है।

भारत पर विदेशी ऋण की बढ़ती राशि के सम्बन्ध में विभिन्न अनुमान करने की मिलत हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार मार्च 1988 के अन्त में विदेशी ऋण की बढ़ती राशि 5500⁰ करोड़ रुपये थी जबकि अमेरिका में वाणिज्यगत स्थित अन्तर्राष्ट्रीय-वित्त-स्थिति के अनुसार यह 90 000 करोड़ रुपये था। जा भी है यह भी निश्चित है कि भारत विदेशी ऋण के जाल में प्रविष्ट होना जा रहा है और इस सम्बन्ध में नीति-सम्बन्धी प्रभावशाली परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होते हैं। अतः ऋण की राशि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाई जान लगी है।²

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भारत ने बगना दश, झूठान उर्मा, टण्डानगिया मारीगस, नपान श्रीलंका व तन्जानिया आदि का आर्थिक महायन्त्रा प्रदान की है, जिसकी प्रयुक्त राशि मार्च, 1988 के अन्त तक 1672 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। इस अनुदानों का अग्र 1049 करोड़ रुपये था। इस प्रकार भारत विदेशी महायन्त्रा उन के माय-माय थोड़े मात्रा में देता भी रहा है।

भारतीय उद्योगों के विकास में विदेशी निजी विनियोगों

(Foreign Private Investments) का स्थान

पहले हमने विदेशी सरकारों व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का वर्णन किया है। लेकिन हमारे उद्योगों के विकास में विदेशी निजी पूँजी के विनियोग का भी स्थान रहा है। 1948 में विदेशी निजी विनियोगों की राशि 265 करोड़ रुपये थी जो मार्च 1977

1. Economic Survey, 1988-89, p 122.

अनोक मित्रा के अनुसार यह अधिक है (लगभग 30%)

2. Mainstream, August 19, 1989, p. 11.

के अर्थ में 2326 करोड़ रु. हो गई। इसमें प्रत्यक्ष विनियोग की पूँजी 920 करोड़ रु. व अन्य पूँजी 1406 करोड़ रु. थी। विभिन्न वार्षिक क्रियाओं में 2326 करोड़ रु. का वितरण इस प्रकार था : वायान 90 करोड़ रु., खनन 15 करोड़ रु., पेट्रोलियम 73 करोड़ रु., विनिर्माण 1081 करोड़ रु. तथा सेवाएँ 1067 करोड़ रु.¹

देशों के अनुसार इसका वितरण देखने से पता चलता है कि पश्चिमी जर्मनी का अंश 257 करोड़ रु., संयुक्त राज्य (UK) का 650 करोड़ रु. व अमेरिका का अंश 669 करोड़ रु. था। इस प्रकार इन तीनों देशों का अंश 1576 करोड़ रु. था जो कुल राशि का 68% (2/3 से कुछ अधिक) था।

विदेशी कम्पनियाँ तीन प्रकार की होती हैं : (1) सहायक कम्पनियाँ (Subsidiaries) जिनमें विदेशी कम्पनी का शेयर-पूँजी में 50% से अधिक अंश होता है, (2) अल्पमत वाला सामंजस्य समूह (Minority Participation Group) जिसमें यह अंश 50% या इससे कम होता है, तथा (3) शुद्ध तकनीकी सहयोग वाला समूह (Pure Technical Collaboration Group) जिनमें केवल तकनीकी सहयोग का समझौता ही पाया जाता है।

विदेशी सहयोग में प्राप्त विदेशी निजी विनियोग व प्राविधिक सहयोग अंशता है ना विदेशी औद्योगिक फर्मों व पूँजी प्राप्त करने वाले देशों के उद्यमकर्त्ताओं के बीच स्थापित होता है। भारत ने विदेशी सहयोग के काफी समझौते किये हैं। हमारे औद्योगिक विकास के लिए विदेशी तकनीकी ज्ञान का उपयोग काफी लाभकारी रहा है, क्योंकि इससे हमें विदेशों में प्रयुक्त होने वाली नवीनतम टेक्नोलोजी की जानकारी मिलती है। भारत में ऐसे समझौतों के अन्तर्गत विदेशी सहयोग व प्राविधिक सहायता से पिछले चार दशकों की अवधि में उद्योगों का एक जाल-भा बिछ गया है जिसमें भारी मात्रा में पूँजी लगाई गई है। विदेशी सहयोग से जहाँ भारत में उद्योगों की स्थापना व विकास हुआ है, वहाँ इनसे कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं जो इस प्रकार हैं

विदेशी निजी विनियोगों से उत्पन्न समस्याएँ

1. एक उद्योग के लिए कई बार विदेशी सहयोग के समझौते किये गये हैं जैसे वस्त्रों की कर्ताई-बुनाई, कई प्रकार की मशीनों एवं कागज व कागज की वस्तुओं के लिए कई बार समझौते हुए हैं। यहाँ तक कि मामूली उद्यमों की वस्तुओं के लिए

1. India's International Investment Position : 1974-75 to 1976-77, RBI Bulletin, December, 1984, pp. 877-878.

भी हमें कई बार समझाते करने पड़े हैं। भारत की विदेशी तकनीकी ज्ञान पर निर्भरता बनी हुई है। कई बार उत्पादों की अप्रगुण क्षमता के पड़े रहने पर भी नये समझौते किये गये हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता।

2 विदेशी ब्राण्डों व ट्रेड-मार्कों के उपयोग से भारतीय माल को क्षति पहुँची है। क्विन ओवलटीन बूडवर्ड ब्राइपवाटर फोर्हस ट्रूथपेस्ट भी जो फोस हालिवस आदि इसका उदाहरण हैं। भारतीय ब्राण्डों व ट्रेड मार्कों को क्षतिग्रस्त मानकर नीचा समझा जाता है जबकि यस्तु गुण की दृष्टि से देशी व विदेशी ब्राण्डों में प्रायः विषेय अंतर नहीं होता।

3 विदेशी कम्पनियों ने अंतरण कीमत (transfer pricing) के माध्यम से राखी लाभ कमाये हैं। यहुराष्ट्रीय निगमों की कई देशों में कम्पनियाँ या शाखाएँ होती हैं। वे अंतरण-कीमत के माध्यम से लाभ कमाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक कम्पनी दूसरे देश में स्थित अपनी सहोद्यम कम्पनी से ऊँचे मूल्यों पर उच्च मात्रा में वस्तुएँ तथा उच्च मूल्यों पर ग्राहक विनिर्मित माल बेचने की व्यवस्था कर लेती है। इससे उसका कुल मुनाफा कम हो जाता है जिससे उसे आय-कर कम मात्रा में देना पड़ता है। विदेशी कम्पनियाँ प्रायः आयातित वस्तुएँ माल के ऊँचे भाव लगाती हैं। दिल्ली में लोक प्रशासन के भारतीय संस्थान के प्रोफेसर एस के गोयल ने अनुमान यहुराष्ट्रीय निगम प्रतिवर्ष 220 करोड़ रुपये की विदेशी विनिर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिसका 86% उच्च भाव को ऊँचे भावों पर आयात करने में लगाया जाता है।

4 भारतीय स्वदेशी ज्ञान को कम प्रोत्साहन तथा भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन (outflow)—विदेशी तकनीकी ज्ञान को प्रत्येक स्थिति में प्राथमिकता देने से भारतीय स्वदेशी ज्ञान को अनवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। रॉयल्टी व तकनीकी कमचारियों की फीस के बतौर करोड़ों रुपये की राशि विदेशी कम्पनियाँ बाहर भेजती रही हैं। सलाह के लिए फीस व डिजाइन के व्यय प्रलग होते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी कही तो वे टीन व साइक्स स्टेण्ड तथा की डिजाइन बनाने के लिए विदेशियों से सलाह लेने की फीस दी गई है।

बालगेट फामफोटिव ने प्रति शेयर आगोश की राशि काफी ऊँची घोषित की है। कई विदेशी कम्पनियों ने भारत में लगाई गई पूँजी की तुलना में ग्राहक लाभों आदि की राशि ज्यादा भेजी है जिससे भारत में विपुल विनियोग बहुत कम व कभी कभी ऋणात्मक रहा है। उदाहरण के लिए 1968-80 की अवधि में दया उद्योग में कुल नया विदेशी विनियोग 60 करोड़ रु का हुआ जो बाहर भेजे गये लाभों व मुनाफों की राशि से कम था। अतः इस क्षेत्र में विपुल विनियोग ऋणात्मक (negative) रहा।

5 भारत में अनुसंधान व विकास (R & D) पर कम ध्यान दिया गया है— भारत में अनुसंधान पर राष्ट्रीय आय का 0.32 प्रतिशत व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका व जापान आदि में राष्ट्रीय आय का 3 प्रतिशत व्यय किया जाता है। हमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान पर अधिक व्यय करना चाहिये।

इसके अलावा विदेशी कम्पनियों के चेयरमैन व उच्चाधिकारियों के वेतन व उनको मिलने वाली सुविधायें इतनी उँची होती हैं कि वे भारत में अन्य वर्गों को प्राप्त सुख-सुविधाओं से मेल नहीं खाती। इससे अनुचित किस्म की असमानता व असन्तोष को बढ़ावा मिलता है।

हाल के वर्षों में भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों (multinationals) की क्रियाओं व गतिविधियों के सम्बन्ध में काफी धर्चा रही है। भारत सरकार ने (जनता शासन काल में) कोका-कोला व अन्तर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन्स (IBM) जैसी अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कहा था क्योंकि उन्होंने स्वयं के हितों का ज्यादा ध्यान रखा था। अमरीकी कम्प्यूटरों के चार्ज काफी उँचे रहे हैं। वर्तमान सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी कम्पनियों का सहयोग उत्पादन के जटिल क्षेत्रों में अवश्य लिया जायेगा और निर्यात सवर्द्धन क्रियाओं में इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। लेकिन सामान्य मामलों में, विदेशी कम्पनियों का अंश कुल शेयर पूँजी में 40% ही रखा जायेगा, जो विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA), 1973 के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। सरकार ने विदेशी दवाई-कम्पनियों के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत की शर्त पर जोर दिया है। इस प्रकार भारतीय हितों को ध्यान में रखकर बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया है।

विदेशी कम्पनियों की विशेष परिस्थितियों में जैसे जटिल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों, निर्यात-सवर्द्धन के लिए बड़े पैमाने की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए 40% से अधिक शेयरहोल्डिंग की इजाजत भी दी जा सकती है। वैसे भी उनको अपनी शेयर राशि घटाकर 40% तक खाने में कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है। मुदीप चौधरी ने अपने अध्ययन में बतलाया है कि हिन्दुस्तान लीवर ने नवम्बर 1977 में अपनी शेयर-राशि 85% से घटाकर 65% कर ली, लेकिन ग्रॉप्लेट के माध्यम से रासायन वनस्पति, मिला पाउडर, आदि का निर्माण करती है और सरकार ने इसे जटिल टेक्नोलॉजी के नाम पर 50% से अधिक शेयर-राशि रखने की इजाजत भी दी है। विदेशी कम्पनियों को नई दिशाओं में अपना काम बढ़ाने व विविधता लाने की इजाजत देने से भारत में लघु पैमाने की इकाइयों को काफी धक्का पहुँचा है।

भारत सरकार ने विदेशी सहायक के प्रत्येक मामले पर पृथक् से विचार करने की नीति अपनायी है। यह एक चयनित (selective) व लोचदार (flexible)

किस्म की नीति रही है। प्रोफेसर के० के० सुब्रह्मण्यम का सुझाव है कि सरकार एक ऐसी एजेंसी स्थापित करे जो विदेशी सहयोग के प्रत्येक प्रस्ताव की छानबीन करे, उसका मूल्यांकन करे उसके सम्बन्ध में आवश्यक लिखा-पढी करे तथा उस पर अपनी रिपोर्ट दे। भारत की भी जापान की भांति विदेशी तकनीक की अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालने की नीति अपनानी चाहिये। इससे नई स्वदेशी तकनीक का विकास हो सकेगा।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार विदेशी निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नीति को काफी उदार बनाया है। पहले वस्तुओं व बल पुर्जों के लिए 90% के स्वदेशीकरण (indigenisation) की शर्त होती थी जिसे निर्धारित अवधि में प्राप्त करना जरूरी माना जाता था। अब बहुराष्ट्रीय नियमों के लिये यह 90% की जगह 70% तक कर दी गई और उसे काफी लम्बी (अनिश्चित) अवधि तक लागू किया जा सकता है। रॉयल्टी के भुगतान 5 वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष के लिए कर दिये गये हैं।

इस प्रकार सरकार विदेशी निजी विनियोगों को बढ़ाने के लिए इनके प्रति उदार नीति बरतने लगी है। हाल के वर्षों में चीन ने विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग लगभग 2000 करोड़ रुपये वार्षिक प्राकपित किया है जबकि भारत के लिए इसकी मात्रा केवल 100 करोड़ रुपये वार्षिक ही रही है। अतः अब सरकार इसको बढ़ाने के लिए उदार शर्तों का पालन करने लगी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी सहायता का योगदान

हम देख चुके हैं कि योजनाकाल में विश्व की विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न देशों की सरकारों तथा विभिन्न देशों की निजी कंपनियों ने भारत को पूँजीगत सहायता प्रदान की है जिससे निम्न लाभ प्राप्त हुए हैं

1. भारत को कृषि, सिंचाई, विद्युत व परिवहन के विवास में काफी सहायता मिली है। सिंचाई से सम्बन्धित कमाण्ड-क्षेत्र-विकास परियोजनाओं में विश्व बैंक की मदद का प्रयोग किया जा रहा है।

9 औद्योगिक विकास में मदद मिली है। तेल, पेण्ट, दवा, औद्योगिक मशीनरी एल्यूमिनियम, स्वर-पदार्थों, विद्युत मशीनरी परिवहन-उपकरण, रसायन व टिकाऊ तथा विलासिता की उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने में विदेशी कंपनियों का सहयोग मिला है।

3. देश में तकनीकी व प्रबन्धकीय ज्ञान का उपयोग व विस्तार हुआ है।

4. तकनीकी ज्ञान के विस्तार से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है। टेक्नोलॉजी का समुन्नत करने का अवसर मिला है।

इस प्रकार चाहे तकनीकी दृष्टि से हम आत्म-निर्भर न हो पाये हो, लेकिन योजना बाल में हमारी तकनीकी क्षमता व शक्ति काफी बढ़ी है। अब भारत का विश्व के चोटी के औद्योगिक देशों में स्थान मना जाने लगा है।

5 पूँजी-निर्माण व विदेशी सहायता—विदेशी सहायता ने देश में विनियोग की दर को बढ़ाने में मदद दी है, हालांकि 1976-79 के तीन वर्षों में घरेलू वृद्धि की दर के समग्र विनियोग की दर से ऊँचा रहने से विदेशी पूँजी का पूँजी-निर्माण व विनियोग की बढ़ान की दृष्टि से स्थान घटकर अणुत्तरक हो गया था। जिन नीम तक देश में विनियोग की दर घरेलू वृद्धि की दर से अधिक होती है, उस नीम तक विदेशी सहायता का पूँजी-निर्माण में योगदान माना जाता है। 1980-81 के नव सिरीज के अनुसार 1987-88 में सकल विनियोग की दर 22.1%, सकल घरेलू वृद्धि की दर 20.2% से 1.9% अधिक रही है, जो धार्मिक विकास में विदेशी साधनों के योगदान की सूचक है। आठवी योजना के दृष्टिकोण प्रथम में 1990-95 के लिए शुद्ध पूँजी का योगदान GDP का 1.6% अंश गया है।

भारत के लिए विदेशी सहायता से सम्बन्धित

विभिन्न समस्याएँ या कठिनाइयाँ

विद्यमान वर्षों में विदेशी सहायता के सम्बन्ध में हमारे समक्ष कई प्रकार की समस्याएँ प्रायी हैं। इनका विवरण प्रागे दिया जाता है—

1. ऋण-सेवा-भुगतान, अर्थात् ऋणों के मूलधन व व्याज की राशि को चुकाने का भार दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप सकल विदेशी सहायता की राशि में से ऋण-सेवा-भुगतान की राशि को निकाल देने से शुद्ध विदेशी सहायता (net foreign aid) का अंश काफी कम हो गया है। ऋण-सेवा-भुगतान का भार काफी बढ़ गया है। प्रथम योजना में कुल ऋण-सेवा भुगतान की राशि लगभग 24 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर तृतीय योजनाकाल में 343 करोड़ रुपये हो गई। बाद में इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1987-88 में ऋण-सेवा-भुगतान की राशि 2623 करोड़ रुपये हो गई तथा 1988-89 के लिए यह 2770 करोड़ रुपये प्राकी गई है। ऋण-सेवा भार चालू प्राप्तियों का 1957-88 में 24% हो गया है जो सुरक्षा की सीमा 20% से अधिक है। अतः भारत विदेशी ऋणों के ढेर के कगार पर है। हम प्रभावपूर्ण नीतियाँ अपनाकर स्थिति को नियन्त्रित करना चाहिए।

अतः आठवी योजना में भुगतान की स्थिति काफी जटिल हो गई है। हमें सविचार्य में विदेशी पूँजी का अधिक प्रयास निर्यात-उद्योगों में करना चाहिए ताकि निर्यात बढ़ाकर विदेशी पूँजी का व्याज सहित भुगतान करने में सहूलियत हो सके। हमें विदेशी सहायता का उपयोग आयात-प्रतिस्थापन की वस्तुएँ बनाने में भी करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा उत्पादक बनाया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक विकास की वार्षिक दर आठ प्रतिशत से अधिक जारी रखी जा सके।

2. ऋण-राहत सहायता की आवश्यकता—विभिन्न देशों व संस्थाओं ने भारत को पिछले वर्षों में ऋण-राहत (debt relief) के रूप में काफी सहायता प्रदान की है। लेकिन यह एक तरह से नया ऋण देने के समान ही है। ऋण-राहत सहायता के निम्न रूप अपनाए गए हैं : (घ) पुनर्वित्त के लिए मांग प्रदान करके (by way of refinancing credits) इसके अनुसार पुराने ऋण चुकाने के लिए नये ऋण दिये गये हैं। फ्रांसिस्का, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, इटली व ब्रिटेन ने इस दिशा में मदद की है। (घ) मुग्तान स्थगन (postponement of payment) के जरिये भी विश्व बैंक, अमेरिका व कनाडा ने ऋण-राहत-सहायता प्रदान की है। (ङ) जापान ने कर्ज के मुग्तान की शर्तें पुनः निर्धारित की हैं 're-scheduling of payment' तथा नये कर्ज बहुत उदार शर्तों पर दिये हैं। (ड) ब्याज में राहत देकर कनाडा व पश्चिमी जर्मनी ने अनुदान (grants) प्रदान किये हैं और फ्रांसिस्का व मोरलेण्ड ने ब्याज में छूट की विधि अपनायी है। भारत के लिए ऋण-राहत की आवश्यकता इस बात को सूचित करती है कि हम अपने ऋणों का पूर्ण तरह से उपयोग नहीं कर पाये हैं जिससे हमारी मुग्तान-क्षमता पर्याप्त मात्रा में घटित नहीं हो सकी और यह अपेक्षाकृत कमजोर रह गयी है।

3. अभी तक जो सहायता मिली है उसमें बंधी-बधायी सहायता (tied aid) का अनुपात अधिक रहा है। हम पहले मुक्त सहायता (untied aid) के महत्त्व पर प्रकाश डाल चुके हैं। इससे मूलधन व ब्याज की निरस्त चुकाते में सहायता मिलनी है। बंधी-बधायी सहायता प्रोजेक्ट से बंधी रह सकती है, अथवा किसी देश के अनुसार बंधी हो सकती है। उसे निर्धारित प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत को अब तक जो विदेशी सहायता मिली है उसमें लगभग दो अंश बंधी सहायता (tied-aid) का रहा है और शेष के अंश बिना बंधी या मुक्त सहायता (untied aid) का रहा है। इस प्रकार स्वतंत्र सहायता का अंश काफी कम रहा है। इस स्थिति को बजह से विदेशी सहायता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है।

4. ऋणों के उपयोग पर विभिन्न प्रतिबन्धों से भारत को क्षति—जंगल निपटो कहा जा चुका है, गैर-प्रोजेक्ट सहायता में भी यह प्रतिबन्ध रहा है कि सहायता देने वाले देश से ही समुद्र वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए। 1964 तक हमें निदेशों में रासायनिक उर्वरक खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लेकिन बाद में जब इजाजत मिलने लगी तो अमेरिका ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि उर्वरक उद्योग में खरीदे जाए, जिससे हमें यूरोपीय बाजारों की तुलना में अमेरिका को उर्वरकों के 20 प्रतिशत ऊंचे मूल्य देने पड़े। भूतत्काल में जापान ने हमें इस्पात खेचने में आनाजानों की धी, क्योंकि हमें यह अन्य देशों को अपेक्षाकृत उच्च प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर बेच सकता था।

विदेशी सहायता के सम्बन्ध में कनाडा व ब्रिटेन का दृष्टिकोण अधिक उदार रहा है। ब्रिटेन वस्तुओं से सम्बन्धित प्रतिबंध नहीं लगाता है। कनाडा ने ऋण-राहत-सहायता प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड व बेल्जियम न व्याज की दरों न कमों की है और मुग्तान की अवधि भी बढ़ायी है।

5. भूतकाल में सहायता की स्वीकृति और सहायता के प्रयोग के बीच काफी अन्तर रहा है। इस अन्तर का एक कारण तो यह है कि प्रोजेक्ट-सहायता अधिक मात्रा में मिली है जिनसे सहायता का पूरा उपयोग करने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पहले बताया जा चुका है कि प्रोजेक्ट में कमी रह जाने से प्रान्तिगत सहायता के उपयोग में बाधा पड़ जाती है। गैर-प्रोजेक्ट सहायता के उपयोग में इतनी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं।

6. भारत में विदेशी निजी पूँजी के आयात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए कर-नौति में आवश्यक संशोधन करने होंगे। विदेशी निजी विनियमों के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए हर सम्भव उपाय काम में लेना चाहिए। विदेशों में हमारी आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अनावश्यक भ्रम फैले जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार करके हमारे दृष्टिकोण के प्रति अधिक सहयोग व महानुभूति का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। विदेशी पूँजीपति अपनी पूँजी पर पर्याप्त आय और पूँजी की सुरक्षा दोनों चाहते हैं। भारत दोनों ही दृष्टिकोण से काफी आकर्षक माना जा सकता है। लेकिन विदेशी कम्पनियों को विदेशी विनियम-नियमन अधिनियम (FERA), 1973 की शर्तों के अन्तर्गत कार्य करना होता है।

7. विकसित देशों की ओर से आर्थिक सहायता के साथ-साथ व्यापार की सुविधा प्रदान करना भी आवश्यक है। जब तक ये विकासशील देशों को व्यापार की पर्याप्त व उदार सुविधाएँ नहीं देंगे, तब तक कोरी आर्थिक सहायता ही उनका आर्थिक कल्याण नहीं कर सकेगी। इस सम्बन्ध में विकसित राष्ट्रों को चाहिए कि वे प्रमुख (आयात-कर आदि) व गैर-प्रमुख बाधाएँ (जैसे कोटा-निषारण आदि) दूर करें और विकासशील देशों के माल की अधिक मात्रा में खरीदें। ऐसा करने पर विकासशील देश अपने माल का निर्यात करके बदले में विकास सामग्री प्राप्त कर सकेंगे जिससे आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी उत्तरात्तर घटती जायेगी। अतः विकसित देशों का मरस्सरावाद की नीति में आवश्यक हीन दली चाहिए। घनी व निम्न दर्जा के बीच आर्थिक मतलबों में मरस्सरावाद का मतलब काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जब तक घनी राष्ट्र मरस्सरावाद को नहीं छोड़ेंगे तब तक विकासशील देशों का निर्यात तबों से नहीं बढ़ सकेगा।

इस से प्राप्त होने वाले ऋणों की सहायता को व्यापार से जोड़ा गया है और इसके परिणाम भी अच्छे निकले हैं, हालाँकि इस के ऋणों पर सेवा-व्यय का वार्षिक भार लगभग 12 प्रतिशत आता है। पिछले कुछ वर्षों में हम को हमारे

निर्मात काफी बड़े हैं जिससे उपर्युक्त दायित्वों को चुकाने में विशेष कठिनाई नहीं हुई है।

सोवियत संघ की सहायता से भारत की दूस्पात, पावर, वायरा व गैस जैसे आधारभूत क्षेत्रों का विकास करने में मदद मिली है। 1988 में स्वीकृत 725 करोड़ रुपये के रुज से बिन्ध्याचल यर्मल स्टेशन, चरण II, की स्थापित करने में मदद मिलेगी।

■ प्राप्त सहायता का अनुचित ढंग से उपयोग—स्वर्गीय प्रोफेसर वी आर. जेनॉय न विदेशी सहायता के सम्बन्ध में रहा था कि योजना के प्रथम पन्नाह वर्षों की अवधि में भारत को जो विदेशी सहायता मिली उसकी मात्रा बाद के वर्षों में काफी बढ़ गई। इसने काफी विनाश रूप धारण कर लिया। हमारे घरेलू माधन नियोग की दृष्टि में इसने समझ काफी फीके पड़ गये। प्रोफेसर जेनॉय न इस तान पर गहरी चिन्ता प्रकट की थी कि इतनी विशाल विदेशी सहायता के बावजूद भी देश में जनसाधारण का मला नहीं हुआ एव घनी अधिर घनी हो गये और गरीब या तो गरीब रह गये अथवा अधिर गरीब हो गये। प्रति व्यक्ति भोजन व कपड़े के उपयोग में वृद्धि नहीं हुई।

प्रश्न उठता है कि इनकी विशाल मात्रा में प्राप्त विदेशी सहायता और विदेशी नियोग कहाँ चले गए? प्रोफेसर जेनॉय का उत्तर था कि विकास की गति को तेज करने के बजाय ये विदेशी माधन अनुत्पादक औद्योगिक परियोजनाओं, नदी-घाटी और विशाल परियोजनाओं में लगा दिये गये। इन्होंने देश में उत्पादन-क्षमता का प्राथम्य उत्पन्न कर दिया और परोक्ष रूप में इन्होंने भ्रष्टाचार, विलासी जीवन ढँबी अट्टालिकाओं, सिनेमा घरों व गैर-आवश्यक सहरी सम्पत्ति की वित्तीय व्ययथा की। कुछ राशि का उपयोग स्वर्ण के आयात व चोरी से अन्य मान के आयात आदि में भी किया गया। इस प्रकार इस सहायता का लाभ सर्वसाधारण का नहीं मिल पाया। विदेशी सहायता व साधनों का इस प्रकार का दुरुपयोग एक भारी चिन्ता का विषय है।

9. अमरीका द्वारा राजनीतिक दबाव का प्रभाव—दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध छिट जान पर अपनी पाकिस्तान-समर्थन नीतियों के कारण अमेरिका न भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी थी, जिससे हमारे औद्योगिक विकास को भारी क्षति पहुँची थी, जापान ने भी भारत को आर्थिक सहायता स्वर्गित कर दी थी। लेकिन वह युद्ध के बाद पुन चालू कर दी गई। बाद में भारत अनुरोधी सम्बन्धों में नुसार होना पर अमरीकी आर्थिक सहायता भी पुन चालू कर दी गई। अमरीकी सहायता के बन्द हो जाने से हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी

मे लेने होंगे। प्रगः उन्नत व विकसित टेक्नोलोजी का उपयोग देश के लिए आवश्यक हो गया है।

प्रश्न

1. भारत के आर्थिक विकास हेतु विदेशी सहायता क्यों आवश्यक है ? इसके क्या सम्भावित खतरे हैं ?
(Raj. Ilyr. TDC. 1987)
 2. निम्नलिखित को समझाइये—
(i) पुनर्भुगतान की समस्या। (Raj Ilyr T.D.C., 1985)
 3. भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता क्यों आवश्यक है ? पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में विदेशी सहायता का मूल्यांकन कीजिये और उनकी कठिनाइयों व समस्याओं को बतलाइये।
(Raj. Ilyr. T.D.C., 1978)
-

20

पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य

(Objectives of Five Year Plans)

भारत ने लगभग चार दशक पूर्व आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया था, जिसके मूलभूत उद्देश्य थे : विकास, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता व सामाजिक न्याय। नियोजन के इसी विस्तृत ढांचे या फ्रेमवर्क के अन्तर्गत प्रत्येक योजना में नई परिस्थितियों व नई सम्भावनाओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन ली किये गये हैं।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना निर्भर करती है। हम यहाँ पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों का वर्णन करते और यह बतायेंगे कि योजनाओं में निर्धारित उद्देश्य व्यवहार में कहीं तक प्राप्त किये जा सके हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य

(Objectives)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप में यह स्पष्ट किया गया था कि अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय की प्राप्ति, जो वर्तमान दशाओं में नियोजन के स्वीकृत उद्देश्य हैं, एक-दूसरे से पृथक् विचार नहीं हैं, बल्कि परस्पर सम्बद्ध उद्देश्य हैं जिनके लिए देश को प्रयास करना चाहिए। सामान्य रूप से यही प्रथम योजना के उद्देश्य थे, लेकिन बाद में प्रत्येक योजना में तत्कालीन आर्थिक समस्याओं की ध्यान में रखकर अलग-अलग उद्देश्य निर्धारित किये गये। इन पर क्रमशः आगे प्रकाश डाला जाता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य योजना के मसौदे में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये, जैसा कि आगामी योजनाओं में किया गया। लेकिन योजना के अन्य विवरण देखकर हम इसके उद्देश्यों का भी अनुमान लगा सकते हैं : प्रथम पंचवर्षीय योजना के मसौदे में यह कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि 2,069 करोड़ रुपये निर्धारित करते समय निम्न प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया है : (1) विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को जानू करने की आवश्यकता है जो भविष्य में

अपेक्षाकृत बड़े प्रयास अर्थात् अपेक्षाकृत बड़ी आर्थिक योजना का आधार बन सक, (2) विकास के लिए देश को उपलब्ध हो सकने वाले कुल साधन, (3) विकास की गति व सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में साधनों की आवश्यकताओं में गहरा सम्बन्ध, (4) योजना से पूर्व केन्द्रीय व राज्य सरकारों के द्वारा प्रारम्भ की गई विभाजन-योजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता; और (5) द्वितीय महायुद्ध व दण्ड व विभाजन द्वारा उत्पन्न आर्थिक असन्तुलनों को ठीक करने की आवश्यकता ।

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के निम्न उद्देश्य माने जा सकते हैं सर्व-प्रथम, इसका उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था के उस असन्तुलन को दूर करना जो देश के विभाजन व द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था । दूसरा इससे जो मुख्य सन्तुलित विकास की प्रक्रिया को एक साथ चालू करने का प्रस्ताव रखा गया । जो आगे चलकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सबे धीरे जीवन-स्तर में निश्चित रूप से सुधार ला सके । इस प्रकार पहला उद्देश्य अल्पकालीन या शीघ्र दूसरा दीर्घकालीन ।

प्रथम योजना के प्रस्तावित विनियोग के प्रारूप में कृषि व सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग $\frac{1}{3}$ भाग इनके लिए निर्धारित किया गया । विद्युत-शक्ति के सृजन को भी, जो सिंचाई की वृहद् योजनाओं से सम्बद्ध हैं उच्च प्राथमिकता दी गयी । लगभग व्यय का $\frac{1}{2}$ अंश परिवहन व संचार के लिए रखा गया ।

कृषि सिंचाई, शक्ति व परिवहन के विकास पर अधिक बल देने से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर व्यय के लिए धन-राशि बहुत थोड़ी रह गई थी । सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों को पुन बसाने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया था ।

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई के साधनों का विस्तार करके एवं अन्य उपाय अपनाकर कृषिगत विकास की ओर अधिक ध्यान देना था । साथ में, शक्ति व परिवहन का विकास करके योजना के आगामी चरण में औद्योगिक विकास की भूमिका तैयार करना भी था । कृषि की प्रगति के लिए सामुदायिक विकास-कार्यक्रम को अपनाया जाना भी योजना की मुख्य विशेषता थी ।

प्रथम योजना अपने अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी सफल रही । योजना के अन्त में अर्थव्यवस्था पहले से काफी सुदृढ़ व सुस्थिर थी । द्वितीय महायुद्ध व देश के विभाजन द्वारा उत्पन्न आर्थिक असन्तुलन काफी सीमा तक दूर हो गये थे, देश की सामाजिक स्थिति सुधरी हुई थी और मूल्य स्तर भी योजना के प्रारम्भ की तुलना में नीचा हो गया था । इन सफलताओं से प्रभावित होकर द्वितीय योजना का आकार बड़ा रखा गया और उसमें औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व दिसम्बर 1954 में ही आर्थिक नीति का उद्देश्य 'समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना करना रखा गया था। द्वितीय योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय इस व्यापक लक्ष्य की ध्यान में रखा गया। द्वितीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित थे।

(1) राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि करना जिससे देश में जीवन-स्तर ऊँचा किया जा सके, (2) तीव्र गति से औद्योगीकरण करना एवं इसके लिए आधारभूत व भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देना; (3) रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि करना; (4) ग्रामदनी व घन की घसमानताओं में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना।

यह कहा गया कि ये उद्देश्य परस्पर जुड़े हुए हैं। इनको प्राप्त करने के लिए संतुलित ढंग से प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी एक उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देने से अर्थन्यवस्था को क्षति हो सकती है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए देश में आधारभूत उद्योगों एवं ऐसे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जो मशीनें बनाने की मशीनें (मातृ-मशीनें) (mother-machines) उत्पन्न कर सकें। इसके लिए लोहा व इस्पात, अलौह धातु, कोयला, सीमेंट, मरी रसायन व अन्य उद्योगों का विकास करना आवश्यक माना गया। रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम-गहन पद्धतियों का उपयोग करने की नीति का समर्थन किया गया। इनके लिए घरेलू व पारिवारिक उद्योगों के विकास पर बल दिया गया।

द्वितीय योजना का अंतिम उद्देश्य सामाजिक माना जा सकता है जो 'समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना के लिए आवश्यक माना गया। इसके लिए समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। योजना में 'समाजवादी ढंग के समाज' के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए राजकोषीय नीति (Fiscal policy) में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता स्वीकार की गयी थी। सामाजिक सेवाओं के विस्तार, भूमि-व्यवस्था में परिवर्तन, संयुक्त पूँजी वाली कंपनियों की कार्यप्रणाली व मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली में परिवर्तन, सहकारी क्षेत्रों व सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, आदि उपायों का प्रभाव एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो अधिक समानता पर आधारित हो।

द्वितीय योजना के लक्ष्यों को पाँच वर्षों की अवधि में प्राप्त करना आसान नहीं था। लेकिन इनको प्राप्त करने की दिशा में जाने बढ़ना आवश्यक माना गया। योजना के प्रारम्भिक वर्षों में देश की गम्भीर साध्य-संकट व विदेशी विनिमय-संकट का सामना करना पड़ा। अतः तृतीय योजना में पुनः कृषि-क्षेत्र को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में अपनाया गया सामान्य दृष्टिकोण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 में प्रारम्भ की गयी थी। इसके मशौदा मसौदे में योजना के उद्देश्य उस रूप में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमें वे द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्टों में पेश किये गये थे। चतुर्थ योजना के मसौदे में स्वीकार किये गये सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर इसके उद्देश्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्य दृष्टिकोण में स्थिरता के साथ विकास, राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता, सामाजिक न्याय व समानता, क्षेत्रीय असंतुलनों में बर्फी, आदि बातों पर बल दिया गया था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत सामान्य दृष्टिकोण के मध्यम से पता लगता है कि इसमें लगभग उन्हीं उद्देश्यों पर बल दिया गया जो द्वितीय व तृतीय योजनाओं में घोषित किये गये थे; जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, कृषिगत उत्पादन में वृद्धि, धार्मिक व सामाजिक समानता के लिए प्रयास करना, आदि। लेकिन पिछली योजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम व नीतियाँ सुझायी गयी थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चतुर्थ योजना में निम्न बातों पर बल दिया गया। (1) धार्मिक विकास मूल्य-स्थिरता के वातावरण में रिया जाय, (2) विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करके राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ा जाय और विकास के लिए आन्तरिक साधनों का अधिक उपयोग किया जाय; (3) औद्योगिक इकाइयों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया जाय; (4) समाज के अपेक्षाकृत निर्धन, दुर्बल व पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन उत्पन्न किये जाएँ; (5) एकाधिकार कानून व अन्य उपायों के द्वारा आर्थिक सत्ता का केन्द्रीय-करण कम किया जाय; (6) स्थानीय नियोजन में पचासवीं राज सभाओं व सहकारिताओं का अधिक उपयोग किया जाय; (7) सांवेजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रगति को सुधारा जाय; (8) निर्णय की प्रक्रिया को यथासम्भव विवेचनित बनाया जाय।

विवेचन की दृष्टि से इनमें से कोई भी बात पूर्णतया नयी नहीं है लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये तब तक उन्हें दोहराते जाना आवश्यक होता है, अथवा यो कहिये कि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं होता।

पाचवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

निर्धनता का उन्मूलन व आत्म-निर्भरता की प्राप्ति—पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ये दो उद्देश्य निर्धारित किये गये थे। इनके लिए ऊँची विकास दर, आय का उचित वितरण व बचत की घरेलू दर में अत्यधिक वृद्धि आवश्यक माने गये थे। ये दोनों उद्देश्य दीर्घकालीन विस्म के हैं, लेकिन पाँचवीं योजना में इनको प्राप्त

सातवीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र (approach paper) में प्रस्तावित उद्देश्य व नीतियाँ

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 का दृष्टिकोण-प्रपत्र जुलाई 1984 में जारी किया गया था। इसमें योजना के निम्न उद्देश्य रखे गये थे।¹

योजना में रोटी, रोज़ी व उत्पादकता (Food Work and Productivity) पर प्रमुख रूप से बल दिया गया। (1) इसके प्रमुख उद्देश्य में कृषिगत उत्पादन, विशेषतया खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करने की बात कही गई। इसके लिए सिंचाई की वर्तमान क्षमता का भरपूर उपयोग करने तथा सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने पर बल दिया गया। कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के लिए जलरी औद्योगिक आधार-शाला (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तैयार करने में पूर्वी लगाने की आवश्यकता स्वीकार की गयी।

2 नीची कृषिगत उत्पादकता के प्रदेशों व क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने तथा ग्रामीण रोजगार व गरीबी दूर करने के विभिन्न कार्यक्रम चला रहने की नीति स्वीकार की गयी। छत योजना का दूसरा उद्देश्य रोजगार का सृजन करना रहा गया। इसके लिए औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक माना गया।

3 तीसरा उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना रहा गया। उत्पादन की वर्तमान क्षमता का गहरा उपयोग करना तथा आपूर्तिशीलता व पूरक सुविधाएँ बढ़ाकर उत्पादन व उत्पादकता में सुधार करना आवश्यक माना गया। यह कहा गया कि विकास का ढांचा ऐसा बनना होगा जो रोजगार को अधिकतम कर सके। यह सातवीं योजना का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया। चावल, तिलहन व दालों के उत्पादन को यद्वाते पर अधिक जोर दिया गया। सरकार ने कार्यक्रमगतता, प्रतिस्पर्धा व आपूर्तिशीलता के आधार पर नई आर्थिक नीति निर्धारित करने का महत्व स्वीकार किया।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की प्रस्तावित राशि, 1984-85 के धूयों पर लगभग 180 000 करोड रु. सुझावी गई जो छठी योजना के मंगोषित वास्तविक परिव्यय से 80% अधिक थी। विकास के सभी क्षेत्रों में व्यय हनु पहले से अधिक धनराशि निर्धारित की गई। योजना में सन्तुलित विकास पर अधिक बल दिया गया।

इस प्रकार सातवीं योजना में कृषिगत उत्पादन बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने तथा उत्पादकता बढ़ाने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया।

1 The Approach to the Seventh Five Year Plan 1985-90, pp 1-2, बाद में अक्टूबर 1985 में जारी सातवीं योजना के सण्ड I के पृष्ठ 23 पर उद्देश्यों पर केवल एक पैरा हो दिया गया था।

सातवी योजना के धारह मुख्य लक्षण (important features) इस प्रकार रहे गये (1) नियोजन के विवेकपूर्ण व विकास में आम जनता की पूरी भागीदारी (2) उत्पादन रोजगार में अधिकतम वृद्धि (3) निर्धनता-निवारण व अन्तर्गत ग्रन्थ-प्रतिष्ठान व ग्रामीण व शहरी असमानताओं में कमी (4) भाजन में आत्म-निर्भरता व उपभोग के ऊँचे स्तरों की प्राप्ति (5) शिक्षा, स्वास्थ्य, पापण, मफाई व आवास में सामाजिक उपभोग के ऊँचे स्तर प्राप्त करना (6) निर्यात-प्रोत्साहन व आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आत्म-निर्भरता के अर्थ में वृद्धि (7) स्वेच्छित रूप से लघु परिवार का नाम अमाने पर चल तथा आर्थिक व सामाजिक नियमों में स्थितियों का रचनात्मक योगदान बढ़ाना (8) इन्फ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं व कमियों को दूर करना व इनकी क्षमता का पूरा उपयोग करना ताकि उत्पादकता बढ़ सके (9) उद्योग में कार्यकुशलता, आधुनिकीकरण व प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना (10) ऊर्जा के संरक्षण व गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर जोर देना (11) विकास-नियोजन में विज्ञान व टेक्नोलॉजी का एकीकरण करना तथा (12) परिवहन व पर्यावरण-संरक्षण व सुधार पर जोर देना।¹

स्मरण रहे कि ये धारह बिन्दु सातवी योजना के प्रमुख लक्षण, बतलाये गये हैं, केवल योजना के उद्देश्यों से भी इनका गहरा सम्बन्ध है।

आठवी पंचवर्षीय योजना (1990-95) के मुख्य उद्देश्य (20)

- (i) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कम से कम 6% वार्षिक वृद्धि,
- (ii) असमानताओं को कम करने व विकेंद्रित विकास की ओर अग्रसर होने के लिए प्रादेशिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना,
- (iii) विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करना तथा चुने हुए क्षेत्रों में गुणवत्ता व उत्तमता लाना;
- (iv) टेक्नोलॉजी, साधन-सुरक्षा व विनियोग के लिए साधनों में आत्म-निर्भरता की स्थिति लाना,
- (v) सातवी योजना के अन्त में निर्धनता के प्रत्याक्षित स्तरों को 28-30% से घटाकर आठवी योजना में 18-20% तक लाना;
- (vi) निर्धनों को रोजगार की मारण्टी देने के लिए रोजगार में सालाना 3% की वृद्धि करना,

1 The Approach to the Seventh Five Year Plan 1985-90, July 1984, pp 8-9

2 The Economic Times, September 2, 1989, page 7, Approach to Eighth Five-Year Plan.

(vii) स्त्रियों, बच्चों व अन्य कमजोर वर्गों के विकास पर विशेष बल देना;

(viii) प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि औसतन 195 किलोग्राम करना,

(ix) प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा सबको उपलब्ध करना एवं 15-35 वर्ष के आयु-समूह में निरक्षरता को मिटावा;

(x) सबके लिए साफ पेयजल उपलब्ध करना, 1995 तक बड़ी एक से दूसरे को लगन वाली बीमारियों पर काबू पाना ताकि 1000 ईस्वी तक उनको मिटाया जा सके तथा समन्वित व व्यापक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करना ताकि 2000 ईस्वी तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके तथा

(xi) विकेन्द्रीकरण, जन-साम्बेदारी व कार्यकुशलता पर विशेष रूप से बल देना।

इस प्रकार आठवी योजना में पंच बातों के चलताब चम से कम 6% विकास की दर प्राप्त करने पर बल दिया गया है। प्रादेशिक विकास, ग्राम-निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, निर्धनता-निवारण, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि, प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, पेयजल व स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार व विकेन्द्रीकरण आदि पर अधिक ध्यान देने की बात कही गयी है।

योजनाओं में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने

की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन

भारत में योजनाकाल के 38 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में घाटिब प्रगति हुई है। कुल राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। बिन्दु से बिन्दु (point to point) आधार पर 1950-51 से 1985-86 की अवधि में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर 3.6% तथा प्रति व्यक्ति आय में 1.4% रही है। 1975 से विकास की वार्षिक दर 5% हुई है जिससे विकास-गति बढ़ता है। कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। परिवहन व संचार की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। देश में पूँजीगत उद्योगों के विस्तार का तो इसी बात से पता चलता है कि वर्तमान समय में इनमें कुछ सीमा तक उत्पादन-क्षमता अग्रयुक्त बनी हुई है और पूरी क्षमता का उपयोग करने में कठिनाई हो रही है। देश में ननक प्रकार के नये नये उद्योग स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र काफी सकल व सकल हो गया है। पिछले वार्षिक-लेईस वर्षों में कृषि में अधिक उपज देने वाली किस्म का इस्तेमाल होने से कृषिगत क्षेत्र में क्रांति का प्रभाव चावल, दालों व अन्य फसलों में भी धीरे-धीरे प्रकट होने लगा है। अभी तक इसका फलदा सीमित क्षेत्र पर ही हो पाया है, हालांकि अविष्य में इसका विस्तार क्षेत्रों से किये जाते के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। भारतीय नियोजन की मन्त्रमे, बन्ने, कम्मी, ग्हर रही है कि लक्ष्यो व वास्तविक प्राप्तिषों के बीच अन्तर पाया गया है। अन्य कमियाँ इस प्रकार रही हैं :

1 बेरोजगारी व अल्परोजगार की विप्लव समस्या—देश में रोजगार के अभाव में बढ़े हैं, लेकिन साथ में बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ी है। मार्च, 1985 में 5 वर्षों से अधिक आयु के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, सामान्य स्थिति (usual status) के आधार पर, लगभग 92 लाख थी। इस प्रकार आर्थिक नियोजन देश को पूर्ण रोजगार की तरफ ले जाने में असमर्थ रहा है। देहातों में बेरोजगारी व अल्परोजगार की स्थिति दिनोदिन बिगड़ती जा रही है। सघु व कुटीर उद्योगों में आपूर्ति पद्धतियों का उपयोग होना बाकी है। इसका विस्तृत विवेचन आगे चल कर बेरोजगारी के अभाव में किया जाएगा।

2 विदेशी सहायता पर निर्भरता—आज भी विदेशों से राशन-तेल, उर्वरक, कुछ तेल व पेट्रोल आदि का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता कम होने के बजाय लगातार बढ़ती गयी है। देश पर विदेशी ऋणों व व्याज के भुगतान का वार्षिक भार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

3. आर्थिक असमानता में वृद्धि—भारतीय नियोजन ने उद्देश्यों में सबसे अधिक विकलता सामाजिक अभाव व आर्थिक असमानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में रही है। योजनाकाल में आय व धन की असमानताएँ बढ़ गयी हैं। अर्थ-व्यवस्था तो आज भी 'मिश्रित' है, लेकिन इस मिश्रण में जो तत्व है, उससे यह 'समाजवादी ढंग' की न होकर 'पूँजीवादी ढंग' की अधिक हो गयी है। देश की अर्थव्यवस्था में 'बड़े व्यवसाय' (Big Business) का प्रभाव बढ़ गया है। सरकार इस पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ रही है। देश में सांघजनिक क्षेत्र का विस्तार, उद्योगों का प्रादेशिक फैलाव, सरकार की राजकोषीय नीति व बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण आदि से भी अर्थव्यवस्था को 'समाजवादी ढंग के समाज' की ओर अग्रसर होने में विशेष मदद नहीं मिली है। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतया निजी उद्यम पर ही आधारित है, यद्यपि इस पर कई प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण व सरकारी प्रतिबंध अवश्य लगे हुए हैं।

4 मुख्य-स्तर में वृद्धि—प्रथम योजनाकाल के अन्त में मुख्य-स्तर योजना के प्रारम्भ की तुलना में कम हो गया था, लेकिन द्वितीय योजनाकाल से मुख्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि होती गयी है। यह वृद्धि तृतीय योजना व बाद के तीन वर्षों में भी जारी रही है। षष्ठ्यं पञ्चवर्षीय योजना में मुख्य-स्तर बढ़ता गया। 1973-74 व 1974-75 के वर्षों में देश को भीषण मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। 1975-76 की अवधि में मुख्य-वृद्धि की दर मामूली रही, लेकिन 1979-80 में पुनः मुद्रास्फीति ने जोर पकड़ा और समय के एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर (on point-to-point basis) बीच मुख्यों में 21.4% वृद्धि हुई। इस प्रकार देश आर्थिक स्थिरता के मातावरण में अपना विकास नहीं कर पाया। छठी योजना की अवधि (1980-85) में बीच मुख्य सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 8% व उपभोक्ता मुख्य-सूचकांकों के आधार पर 9.5% रही। अतिल भारतीय

उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक जून 1989 में 838 हो गया (आधार वर्ष 1960 = 100) इस प्रकार अब रुपये का मूल्य लगभग 12 पैसे रह गया है। देश में महंगाई की समस्या बराबर जारी है।

5. काली मुद्रा में ध्वंसिक वृद्धि—सार्वजनिक वित्त व नीति पर राष्ट्रीय सन्धान ने 'भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलुओं' पर अपनी रिपोर्ट मार्च 1985 में पेश की थी। इसमें बतसाया गया था कि 1980-81 में जिनकी घाय पर 42 करोड़ दिया गया था वह उस घाय का वित्त पर 42 लगाया जाना चाहिए था, 74.2 से 77% रही थी। 1983-84 में काली घायदमी की सीमा 31,584 से 36,786 करोड़ रु घाँकी गई थी जो सकल घरेलू उत्पात (GDP) का 18% से 21% थी। इस प्रकार 1983-84 के लिए काली घायदमी की ऊपरी सीमा लगभग 37,000 करोड़ रु थी जो कुल घरेलू उत्पात या घायदमी का 21% थी। भारत में काले घन व काली घायदमी का फैलाव दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर रोग की भाँति है जिससे खुटकारा पाना कठिन है। योजनाकाल में विभिन्न कारणों ने मिलकर देश में काली मुद्रा को बढ़ावा दिया है जिससे मुद्रास्फीति बड़ी है। इससे घाय जनता को हानि हुई है। अतः नियोजनकाल की विफलताओं में काली अर्थव्यवस्था का अनियन्त्रित प्रसार या फैलाव भी लिया जा सकता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में कुपित उत्पादन, रोजगार, नौमत, निजी हार्पों में प्राधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण, घाय के वितरण व सामाजिक स्वाय के प्राणों की लेकर लक्ष्यों व प्राप्तिओं के बीच काफी अन्तर पाये गये हैं जिन्हें अविध्य में दूर करने की आवश्यकता है।

प्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमरत्या सेन* ने अपने लेख 'How is India Doing?' में बतसाया है कि भारत में 1981 में 2/3 नागरिकों का निरक्षर पाया जाना, घाय भी जीने की औसत आयु का 52 वर्ष ही पाया जाना तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का पिछड़ा रहना, देश में निर्वनता, जातिवाद, भ्रष्टाचार व घुम्राघृत, बीमारी, गन्दगी आदि का पाया जाना गम्भीर विता के विषय है। देश में सामाजिक सेवाओं के प्रति सरकार का दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं रहा है। इसलिए साक्षरता व जीने की औसत आयु के क्षेत्रों में पीछे व थोका भारत से घाये निकल गये हैं। अतः अविध्य में भारत को प्राधिक-सामाजिक विकास की दिशा में काफी काम करना होगा।

* प्रो अमरत्या सेन पहले भारतीय हैं जिन्हें 1987 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक संगठन (IEA) का प्रेजिडेण्ट बनाया गया था।

1. Mainstream, Republic Day Number, 1983.

21

भारतीय योजनाओं में सार्वजनिक परिव्यय का रूप, 1951-85

(Pattern of Public Outlay Under
Indian Plans, 1951-85)

भारत में योजनाओं का निर्माण : योजना आयोग (Planning
Commission) व राष्ट्रीय विकास परिषद् (National
Development Council) की भूमिका

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन पर काफी चिंतन किया गया था और देश में इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया था। 1950 में लोकसभा द्वारा सविधान स्वीकृत हो जाने के बाद भारत सरकार ने मार्च, 1950 में योजना आयोग नियुक्त किया जिसका कार्य देश के भौतिक, पूँजीगत व मानवीय साधनों की जांच करना और इनमें सर्वाधिक प्रभावपूर्ण व सन्तुलित उपयोग के लिए योजनाएँ तैयार करना रखा गया था। योजना के प्रथम 14 वर्षों में भारतीय नियोजन का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्व. लालबहादुर शास्त्री ने अपने अल्प कार्यकाल में भारतीय नियोजन को अधिक प्रभावशाली और व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया। लेकिन पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के कारण देश को विकास के साथ-साथ सुरक्षा पर भी काफी धनराशि व्यय करनी पड़ी। इससे विकास कार्यों में कुछ सीमा तक बाधा पड़ी। स्व. श्रीमती गांधी के पूर्व कार्यकाल (1966-77) में नियोजन की प्रक्रिया जारी रही। मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक की अवधि में जनता सरकार ने प्राथमिक नियोजन में ग्रामीण विकास पर अधिक धनराशि आवंटित की तथा सुप्रसिद्ध ग्रंथशास्त्री डॉ. टी. टी. लकडवाला योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। दिसम्बर, 1979 में छठी योजना, 1978-83 का संशोधित प्रारूप जारी किया गया था, लेकिन जनवरी, 1980 में केन्द्र में कांग्रेस (माई) की नई सरकार ने छठी योजना के पहले वाले प्रारूप को समाप्त करके 1980-85 की अवधि के लिए नई छठी योजना का अन्तिम प्रारूप मई, 1981 में केन्द्र के समक्ष पेश किया था।

यह जानना रुचिप्रद होगा कि 1951-80 की अवधि में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय की राशि लगभग 90,300 करोड़ रुपये (प्रचलित कीमतों पर) रही। इस प्रकार योजना आयोग ने इतनी धनराशि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की। इस राशि का योजनावार आवंटन आगे के पृष्ठों में दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय के लिए 97 500 करोड़ रुपये की धन-राशि प्रस्तावित की गई थी जबकि वास्तविक परिव्यय के 1,09,292 करोड़ रु. रहने का अनुमान है। इस प्रकार जितनी धनराशि सार्वजनिक क्षेत्र में 1951-80 के 29 वर्षों में व्यय की गई, उससे अधिक राशि 1980-85 के 5 वर्षों में व्यय की गई है, हालांकि इस प्रकार की तुलना में मूल्य-परिवर्तन के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। फिर भी इससे पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय के प्रकार व आयाम का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है।

वर्तमान में (सितम्बर 1989) में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी व उपाध्यक्ष व नियोजन मंत्री श्री माधवसिंह सोलंकी हैं। अन्य सदस्यों में मानव-संसाधन विकास मंत्री, कृषि-मंत्री, ऊर्जा-मंत्री, उद्योग-मंत्री, पर्यावरण व वन मंत्री, वित्त मंत्री, कानून, न्याय व जल-साधन मंत्री तथा नियोजन राज्य-मंत्री हैं एवं पूर्णकालिक सदस्य इस प्रकार हैं :—प्रोफेसर एम. जी. के. मेनन, डॉ. राजा जे. वेल्सैमा, हितेन भाषा, भाविद हुसैन, डॉ. बाई के भस्कर, प्रो. पी. एन. श्रीवास्तव, तथा जे एस बैजल। (सदस्य-सचिव, योजना-आयोग) हैं।

स्मरण रहे कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं होती। योजना आयोग केवल एक सलाहकारी संस्था (advisory body) है और हमारी योजनाएँ अधिक विकास की केवल मार्गदर्शक मात्र होती हैं। योजना आयोग योजना का प्रारूप तैयार करके राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council या NDC) के सम्मुख प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघीय क्षेत्रों के मुख्य पात्र (chief councillors) व योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो योजना के प्रारूप व इसमें सुझाई गई विभिन्न नीतियों पर विचार-विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति के बाद ~~इन्हें संसद में प्रस्तुत किया जाता है~~ भारतीय संसद में विचारार्थ पेश की जाती है। यहाँ से स्वीकृत होने पर वह देश में लागू हो जाती है और उस पर कार्यान्वयन हो जाता है। विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने-अपने प्रदेशों के लिए पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाएँ बनाती हैं जिनके प्रकार व वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे में उन्हें आयोग के अधिकारियों से आवश्यक विचार-विमर्श करना होता है। कुछ राज्यों में नियोजन कार्य को अधिक सबल व

योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक परिष्कृत का निम्न आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार आवंटन (Sectoral allocation)¹
(युक्त सार्वजनिक परिष्कृत के प्रतिशत के रूप में)

मह	प्रथम योजना (51-56)	द्वितीय योजना (56-61)	तृतीय योजना (61-66)	चौथी योजना (66-69)	चतुर्थ योजना (69-74)	पंचम योजना (74-79)	षष्ठी योजना (80-85)	सातवीं योजना (85-90)
1. कृषि व सम्बद्ध कार्यक्रम	14.8	11.7	12.7	16.7	14.7	12.3	16.4	13.9
2. सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण	22.2	9.2	7.8	7.1	8.6	9.8	10.6	10.0
3. शक्ति	7.6	9.7	14.6	18.3	18.6	18.8	18.4	28.1*
4. उद्योग व खनन	4.9	24.1	22.9	24.7	19.7	24.3	21.7	15.5
5. परिवहन व संचार	26.4	27.0	24.6	18.5	19.5	17.4	16.8	16.2
6. सामाजिक सेवाएँ व विविध	24.1	18.3	17.4	14.7	18.9	17.4	16.1	16.3
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिष्कृत

(करोड़ रुपये में)	1,960	4,672	8,577	6,625	15,779	39,426	12,177	1,09,292
-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	----------

2. Economic Survey 1988-89, pp. S-40 व S-42 (तृतीय योजना व बाद के लिए)

* यह ऊर्जा पर व्यय-राशि का अनुपात है जिसमें शक्ति (power), पेट्रोल, गैर-परम्परागत स्रोत शामिल किये गये हैं।

* छठी योजना में कृषि व सम्बद्ध कार्यक्रम में कृषि, ग्रामीण विनास व स्पेशल क्षेत्रीय कार्यक्रम शामिल किये गये हैं।

प्रकार हमने योजना आयोग का कोई सदस्य शामिल नहीं किया गया है। परिपद ने पहले अक्टूबर 1983 व जनवरी 1984 में प्रधान मंत्री को दो रिपोर्टें पेश की थीं। मई 1987 में EAC ने "भारत में सार्वजनिक उपक्रम—कुछ सामायिक प्रश्न" पर प्रधानमंत्री को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की। यह तृतीय रिपोर्ट थी।

अक्टूबर 1983 की रिपोर्ट में आर्थिक सलाहकार परिपद ने नियोजन के विकेंद्रीकरण पर काफी बल दिया था तथा राज्य-स्तर व जिला-स्तर के बीच नियोजन के लिए एक नई मस्था—डिविजनल विकास प्राधिकरण (Divisional Development Authority) (DDA) के निर्माण का समर्थन किया था। देश में 94 DDAs स्थापित करने का सुझाव दिया गया था ताकि योजना का क्रियान्वयन सुधारा जा सके। यह प्रस्ताव किया गया कि एक DDA में लगभग 4 जिले होंगे। कृषि व जलवायु के आधार पर देश को 55 प्रदेशों (regions) में विभक्त किया गया था। यह कहा गया था कि विकास के लिए कम से कम एक तिहाई कोष DDAs के मार्फत लंचे किये जायें। DDAs के तहत नीति-नियोजन-परिपद तथा प्रोग्राम-संचालन-परिपद के गठन का भी सुझाव दिया गया था। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. बी. के. आर. बी. राव ने डिविजनल विकास प्राधिकरण के विचार का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने इसको एक अनावश्यक कड़ी बतलाया था।

जनवरी, 1984 की रिपोर्ट में परिपद ने विदेशी मुग्तानी की कठिनाई को दूर करने के लिए तेल, ऊर्जा, व्याप. खाद्य-तेल, उर्वरक, इस्पात व औद्योगिक मशीनरी में कार्यकुशल आयात-प्रतिस्थापन पर बल दिया था। पेट्रोल के स्थान पर कोयला या गैस के प्रतिस्थापन को महत्व दिया गया था। इसके अलावा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने, अनुत्पादन व गैर-योजना ध्यक्ष कम करने व विकसित तथा नई टेक्नोलोजी का उपयोग करने के सुझाव दिये गये थे। परिपद ने नये सुझाव तो नहीं दिये, लेकिन सरकार का ध्यान प्रमुख समस्याओं की ओर अवश्य आकर्षित किया था। मई 1987 में तृतीय रिपोर्ट में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिए उचित सुझाव दिये गये थे। इस सम्बन्ध में परिपद ने हॉल्टिंग कम्पनी, स्वायत्तता, लेखा-देयता, प्रदूषण-स्थिति में सुधार, मूल्य-नीति आदि पर उपयोगी सुझाव पेश किये थे।

भाषा है पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार, परिपद आर्थिक समस्याओं के उचित समाधान सुझावेगी जिससे विदेशी मुग्तान, मुद्रास्फीति, साधन-समृद्ध, काली मुद्रा, विज्ञान की गति, आदि से सम्बन्धित प्रश्नों के हल करने में विशेष मदद मिलेगी।

सार्वजनिक परिव्यय व सार्वजनिक विनियोग का अन्तर (Difference between Public Outlay and Public Investment)

सर्वप्रथम हमें सार्वजनिक परिव्यय और सार्वजनिक विनियोग में अन्तर समझना चाहिए। सार्वजनिक परिव्यय में सार्वजनिक विनियोग के अलावा चालू

2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1956 से मार्च, 1961 तक)— इसमें उद्योगों पर अधिक बल दिया गया था। वास्तव में इस योजना से भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत मानी जाती है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 4,800 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी। द्वितीय योजना के समर्थ प्रारम्भ से ही विदेशी विनिमय संकट उपस्थित हो गया था। इसलिए मई, 1958 में इसका मशोधन करना पड़ा, जिसमें योजना को दो भागों में बांट दिया गया, एक भाग 4,500 करोड़ रुपये का रखा गया और दूसरा 300 करोड़ रुपये का। प्रथम भाग में आधारभूत प्रोजेक्ट (Core projects) रखे गये जिन्हें पूरा करना आवश्यक माना गया। हम पहले बता चुके हैं कि द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय 4,672 करोड़ रुपये हुआ था।

द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय 20% बढ़ी, जबकि लक्ष्य 25% वृद्धि का रखा गया था। विकास की वार्षिक दर 4% रही। योजना के अन्त में मूल्य-स्तर 30% ऊँचा रहा। द्वितीय योजना में भुगतान-असन्तुलन तथा मुद्रास्फीति की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी थी। इस प्रकार देश में योजना के दबाव व तनाव प्रतीत होने लगे थे।

द्वितीय योजना में प्रति वर्ष कृषिगत उत्पादन 4% तथा औद्योगिक उत्पादन 6.6% बढ़ा। 1960-61 में सिंचित क्षेत्र 2.5 करोड़ हेक्टेयर हो गया। खाद्यान्नों का उत्पादन 1960-61 में 8.2 करोड़ टन हुआ था।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1961 से मार्च, 1966 तक)— इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था। लेकिन वास्तविक व्यय 8,577 करोड़ रुपये का हुआ जिसका आवंटन पहले दिया जा चुका है। तृतीय योजनाकाल की दर 2.2% रही जो लक्ष्य के आधी से भी कम थी। औद्योगिक उत्पादन प्रति वर्ष 9% बढ़ा, जबकि कृषिगत उत्पादन 1.4% वार्षिक दर से घटा (1965-69 का वर्ष अभूतपूर्व अकाल व सूखे का होने के कारण)। खाद्यान्नों का उत्पादन योजना के अन्त में 7.2 करोड़ टन रहा, जबकि लक्ष्य 10 करोड़ टन था। 1965-66 में सिंचित क्षेत्र 2.7 करोड़ हेक्टेयर हो गया था। विद्युत की प्रस्तापित क्षमता 102 लाख किलोवाट हो गयी जो लक्ष्य (127 लाख किलो-वाट) से कम थी। तृतीय योजनाकाल में मूल्य-स्तर 36.4% बढ़ा। तृतीय योजना की प्रगति काफी असन्तोषजनक रही। इस योजना में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय लगभग स्थिर रही थी।

तृतीय योजना अपने किसी भी निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी। योजना के अन्त में खाद्य-समस्या, महंगाई, बेकारी, विदेशी भुगतान की समस्या, निजी हाथों में आयिक सत्ता का बढ़ता हुआ केन्द्रीयकरण और

घास व घन की बढ़ती हुई असमानताएँ आदि देश के समक्ष विकराल रूप में उपस्थित थीं। इन समस्याओं के लिए कुछ सीमा तक दो युद्धों और 1965-66 के भूतपूर्व भूकाल व सूखे की स्थिति को भी उत्तरदायी माना जा सकता है।

4 **तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)**—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय 1 अप्रैल 1966 से प्रारम्भ नहीं की जा सकी, क्योंकि दो युद्धों व दो लगातार सूखों के कारण नियोजन के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गयी थी। कुछ विद्वानों ने 1966-69 की अवधि को योजनावकाश (plan holiday) की अवधि माना है। लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि इस अवधि में योजना-कार्य को वार्षिक योजनाओं के माध्यम से चालू रखा गया था, हलांकि विकास व विनियोग की गति काफी मन्द पड़ गयी थी।

1966-69 की अवधि में सार्वजनिक परिव्यय की कुल राशि 6,625 करोड़ रुपये रही। 1966-69 की अवधि में योजनाओं में महिम नीतियों का प्रभाव रहा। साधनों के अभाव में विकास के मामूली लक्ष्य ही रखे गये थे। फिर भी जैसे-तैसे करके योजना-कार्य को जारी रखा गया। खाद्यान्नों का उत्पादन 1965-66 में 7.2 करोड़ टन से बढ़कर 1968-69 में 9.4 करोड़ टन हो गया था। 1966-69 की अवधि में विकास की वार्षिक दर 4% रही थी।

5 **चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)**—सशोधित चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए कुल 15,902 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये एवं वास्तविक व्यय (15,779 करोड़ रुपये) लक्ष्य के समीप रहा था।

चतुर्थ योजना की आर्थिक प्रगति

चतुर्थ योजना में आर्थिक प्रगति पर बगला देश से शरणार्थियों के भारत में आने तथा वाद में भारत-पाक युद्ध का विपरीत प्रभाव पड़ा था। योजना में विकास की वार्षिक दर लगभग 3.3% रही जो लक्ष्य से कम थी। कृषिगत उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर 2.9% तथा औद्योगिक उत्पादन में 4.7% रही है।

औषधीय योजना में प्रमुख क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धियाँ लक्ष्यों की तुलना में काफी नीची रही थीं। खाद्यान्नों का उत्पादन 12.9 करोड़ टन किया जाना था जो 1973-74 में 10.5 करोड़ टन तक पहुँच सका था।

इसी प्रकार शोध, कच्चे लोहे, कच्चे पेट्रोल, रासायनिक खाद, अखबारों कागज, पिंग लोहे, नरम इस्पात, अलूह घातुओं आदि के क्षेत्रों में वास्तविक प्राप्तियाँ लक्ष्य से नीची रही। सीमेंट व अन्य उद्योगों की बगीचों, हाइड्रो टरबाइन्स, वैल्युजिक शक्ति, रेलों के साज-सामान जैसे डीजल व बिजली के इंजन एवं मालगाड़ी के डिब्बों आदि के उत्पादन में भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। लेकिन दवाइयों, मोटार, एलॉय व विशेष इस्पात और सूखी बैटरियों के लक्ष्य प्राप्त हो गये थे।

चतुर्थ योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था का लक्ष्य 850 करोड़ रुपये का रखा गया था जबकि वास्तविक राशि 2,060 करोड़ रुपये की रही जो लक्ष्य की $2\frac{1}{2}$ गुनी थी। 1972-73 व 1973-74 में अत्यधिक मूल्य-वृद्धि ने देश के समक्ष आर्थिक संकट उपस्थित कर दिया था। देश में व्यापक पैमाने पर अभाव का वातावरण फैल गया था और बड़े किसान, बड़े व्यापारी व बड़े उद्योगपति अभाव की दशाओं में मुनाफाखोरी व जमाखोरी से लाभ उठाने में लग गये थे। देश में पावर-सप्लाई, परिवहन, इस्पात, सीमेंट, खाद्यान्न, रासायनिक उर्वरक, कागज आदि का अभाव उत्पन्न हो गया था।

6. पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79)

पाँचवी योजना का प्रारूप लोकसभा में दिसम्बर, 1973 में रखा गया था। उसके बाद भीषण मुद्रास्फीति व अर्थ संकटों के कारण इसका संशोधित स्वरूप सितम्बर, 1976 में प्रस्तुत किया गया। तब तक पाँचवी योजना का लगभग आधी अवधि समाप्त हो चुकी थी। पाँचवी योजना में निर्धनता-उन्मूलन तथा आत्म-निर्भरता सम्बन्धी उद्देश्य रखे गये थे। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की व्यय की राशि 39,322 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गयी थी, जबकि वास्तविक व्यय लगभग 39,426 करोड़ रु. हुआ।

पंचम योजना में कोयला, कच्चा लोहा, खाद्यान्न, रासायनिक उर्वरक व मनोहृ धातुओं आदि के उत्पादन को बढ़ाने पर काफी बल दिया गया था।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बी. एस. मिहान्स ने योजना आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका विचार था कि पाँचवी योजना में विदेशी सहायता, माधन-मग्नह आदि के सम्बन्ध में लक्ष्य सही रूप में निर्धारित नहीं किये गये थे।

जैसा कि बाद की घटनाओं ने मिट्ट किया 1974-75 में देश आर्थिक व राजनीतिक कठिनाइयों के गम्भीर दौर में प्रवेश कर गया था। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि देश का आर्थिक प्रशासन व आर्थिक अनुशासन टूट गया है। देश में मुद्रा-स्फीति की समस्या बहुत जटिल हो गयी थी। आम जनता में असन्तोष बढ़ गया था। 25 जून, 1975 को देश में आपातकालीन स्थिति लागू की गयी और बाद में विभिन्न आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम घोषित किया गया। मार्च 1977 में केन्द्र में जनता सरकार मत्ता में आयी। उसने पाँचवी योजना के कार्यकाल को एक वर्ष पूर्व 31 मार्च, 1978 को समाप्त करके 1978-83 की अवधि के लिए छठी योजना का प्रारूप देश के समक्ष रखा। लेकिन जनवरी 1980 में पुनः कांग्रेस (आई) की सरकार के सत्ताह्व होने पर 1978-83 की योजना को निरस्त करके 1980-85 की अवधि के लिए एक नयी छठी योजना प्रस्तुत की गई थी।

पंचम योजना, 1974-79 की अवधि में आर्थिक प्रगति

पंचम योजना में विकास की वार्षिक दर 5.2% रही जो लक्ष्य (4.4%) से अधिक थी। कृषिगत उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर 4.2% तथा औद्योगिक उत्पादन में 5.9% रही।

1978-79 में खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन 13.2 करोड़ टन हुआ जो लक्ष्य (12.5 करोड़ टन) से अधिक था। कपास व जूट में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए। लेकिन तिलहन व गन्ने के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

कोयले का उत्पादन 10 $\frac{1}{2}$ करोड़ टन हुआ जो लक्ष्य से 2 करोड़ टन कम था। चीनी का उत्पादन लक्ष्य से थोड़ा अधिक हुआ। परिशुद्ध पेट्रोल पदार्थों में उत्पादन का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन 1973-74 की तुलना में उत्पादन बढ़ा। कच्चे लोहे, सीमेंट, तैयार इस्पात व बिद्युत-सृजन में 1973-74 की तुलना में उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1978-79 के लिए निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

पाँच मूल्यों में (एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के माध्यम पर) 1974-75 व 1976-77 में क्रमशः 10% व 12% की वृद्धि हुई। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दबाव पाव में से दो वर्षों में अधिक रहे। सामानों में वार्षिक वृद्धि-दर (1975-76 व 1976-77 को छोड़कर) निर्यातों की वृद्धि दर से अधिक रही।

पंचम योजना की अवधि में देश में राजनीतिक स्थिरता व तनाव की स्थिति बनी रही। मार्च 1977 में जनता सरकार गिराई हुई, लेकिन जनवरी 1980 में पुनः कांग्रेस (भाई) को केन्द्र में सत्ता प्राप्त हुई।

1979-80 की वार्षिक योजना

बदली हुई परिस्थितियों में 1979-80 की वार्षिक योजना किसी भी पंच-वर्षीय योजना का भग नहीं रही। যেসকি पहले बताया जा चुका है, 1979-80 की वार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि 12 177 करोड़ ₹ रही। 1979-80 की वार्षिक योजना जनता सरकार ने तैयार की थी। इसमें कृषि, सिंचाई, वाट-नियन्त्रण व कृषि के सहायक क्षेत्रों पर कुल परिव्यय का 27% अंश रखा गया था।

1978-80 की वार्षिक योजना की उपसंक्षिप्ता—

1979-80 में विकास की दर (—) 5.2% रही तथा पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय (1970-71 के मूल्यों पर) 7.3% घटी थी।

1979-80 की अवधि में कृषिगत उत्पादन 15.2% घटा, खाद्यान्नों का

उत्पादन 16.8% घटा तथा औद्योगिक उत्पादन 1.7% घटा। थोक मूल्यों में (एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर) 21.4% की वृद्धि हुई। इसी वर्ष आयात 34.2% तथा निर्यात 12.1% बढ़े।

इस प्रकार 1979-80 का वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी प्रतिकूल रहा। इसी अवधि में लोकसभा के आम चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस (आई) विजयी घोषित हुई। उसने जनवरी 1980 में केन्द्र में सत्ता सम्हाली। उस समय देश का इन्फ्लेशनचर काफी कमजोर स्थिति में था। कोयले, विद्युत, इस्पात व रेल-परिवहन आदि क्षेत्रों में स्थिति काफी असन्तोषजनक थी। सरकार ने छठी योजना (1980-85) में अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के विकास कार्यक्रम रखे जिन पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 का संशोधित प्रारूप मई 1981 में जारी किया गया था जिसमें राज्वैज्ञानिक क्षेत्र में परिवर्धन की राशि 97,500 करोड़ रुपये तथा विकास की वार्षिक दर 5.2 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

यह योजना भारतीय नियोजन के तीन दशकों के अनुभव के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी एवं साथ में इसमें आगामी 10-15 वर्षों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया था। योजना की पृष्ठभूमि व प्रारम्भिक दशाएँ अनुकूल नहीं थीं। 1979-80 का वर्ष सूखे का वर्ष था जिसमें कृषिगत उत्पादन घटा एवं मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हुई जो 1980-81 में भी जारी रही। देश के आधारभूत ढाँचे में, विशेषतया कोयले, परिवहन तथा शक्ति के क्षेत्रों में कई प्रकार का प्रभाव था जिससे औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। पेट्रोलियम व अन्य आयातों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने से देश के समक्ष गम्भीर भुगतान असन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो गयी थी तथा विदेशों में मन्दी की दशाएँ पाय जाने के कारण हमारे निर्यातों के बढ़ने में कठिनाई उत्पन्न हो गई थी।

इस प्रकार छठी योजना के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की सम्भावनाओं पर निम्न तीन तत्वों का विपरीत प्रभाव पड़ा है—सुद्रास्फीति आधारभूत ढाँचे की कमियाँ तथा शिथिली हुई भुगतान-असन्तुलन की स्थिति। योजना में इन समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव दिये गये थे।

विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य

योजना में विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया था। इसकी प्राप्ति करने के लिए कृषि में विकास की दर 4% तथा खनन व विनिर्माण में 7%

प्रस्तावित की गई। रोजगार में स्टेण्डर्ड व्यक्ति-वर्गों (SPY) के आधार पर, वृद्धि-दर 4.17% प्रांकी गई जो योजनाकाल में धन-शक्ति की वृद्धि-दर (15 वर्ष व अधिक के आयु-समूह के लिए 2.55%) से अधिक थी। निर्यातों में (1978-80 के मूल्यों पर) 1980-85 की अवधि में वार्षिक वृद्धि-दर 9% रखी गई जो पिछली दशकों की 6% दर से अधिक थी।

छूटी योजना में निर्धनता व बेरोजगारी को दूर करने के कार्यक्रम

निर्धनता व छूटी योजना—योजना में निर्धनता-रेखा को परिभाषित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की मात्रा 2400 इकाई तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 इकाई निर्धारित की गई जिसके आधार पर 1979-80 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 76 रु तथा शहरी क्षेत्रों में 88 रु. से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गये।

1979-80 में निर्धनता-रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात 50.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 43.3% एवं समस्त देश में 48.4% आया गया था। 1984-85 में पुनर्वितरण के बिना (without redistribution) निर्धनता-रेखा से नीचे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 40.5% शहरी क्षेत्रों में 33.7% व समस्त देश में 39% व्यक्तियों के लक्ष्य रहे गये। पुनर्वितरण सहित (with redistribution) 1984-85 में समस्त देश में तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 30% लोगों के निर्धनता की रेखा से नीचे रह जाने के अनुमान प्रस्तुत किये गये। 'पुनर्वितरण सहित' का अर्थ है भूमि, परिसम्पत्ति आदि के पुनर्वितरण के कार्यक्रम लागू करने के वाद की स्थिति।

निर्धनता उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम

निर्धनता-उन्मूलन के सम्बन्ध में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme) (IRDP) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme) (NREP) की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ये ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने से सम्बन्धित कार्यक्रम हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme) (MNP) का एक उद्देश्य निर्धनता को कम करना माना गया है। इनका मसिफ परिचय नीचे दिया जाता है।

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एग्रोविकास) (IRDP)¹

यह निर्धनता-उन्मूलन की दिशा में सबसे बड़ा कार्यक्रम माना गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्दनी बढ़ाने वाली विशेष परियोजनाएँ संचालित करने पर

1. Sixth Five Year Plan 1980-85, pp 170—172.

बल दिया गया ताकि इनका साम छूटे गये परिवारों को मिल सके। इस कार्यक्रम को देश के सभी खण्डों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया। योजना में यह कहा गया कि प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 20 हजार परिवारों में से 10-12 हजार परिवार निर्धनता की रेखा से नीचे माने जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 3000 परिवारों को विशेष रूप से सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया जिनमें से 2000 परिवारों को कृषि व सहायक क्रियाओं में, 500 परिवारों को ग्रामीण व कुटीर उद्योगों में तथा शेष 500 परिवारों को सेवा-क्षेत्र में भ्रामदनी-उत्पन्न करने वाली स्कीमों में लगाना निश्चित किया गया। योजना में निर्धनता-उन्मूलन के लिए 'परिवार-दृष्टिकोण' (household approach) अपनाया गया। IRDP के सम्बन्ध में निम्नांकित नीति अपनायी गयी

(1) प्रत्येक जिले के लिए एक पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम तैयार करना जिसे खण्डवार विकास-योजनाओं में विभक्त करना। इन योजनाओं में सिंचाई, पशु-पालन मछली-उद्योग, वन-उद्योग, बायो-गैस विकास आदि कार्यों को शामिल करना। (2) कृषि-विस्तार सेवाएँ प्रदान करना। (3) ग्राम समा की मार्फत छाँटे गए विशेष परिवारों को निर्धनता-रेखा से ऊपर उठाना। (4) द्वितीयक व तृतीयक/सेवा-क्षेत्रों के लिए भी विकास की रूपरेखा तैयार करना। (5) जिला, खण्ड व ग्राम स्तरों पर क्रियान्वयन एजेंसियों में निर्धनों को प्रतिनिधित्व देना। (6) जिला/खण्ड स्तरों पर साख योजनाएँ बनाना, विशेषतया उन लोगों के लिए जिन्हें सहायता पहुँचाई जाती है। (7) IRDP को एक ही एजेंसी के मार्फत लागू करना। (8) खण्ड स्तरीय संगठन को सुदृढ़ करना। (9) यह कार्यक्रम निर्धनता-उन्मूलन का 'परिवार-दृष्टिकोण' वाला कार्यक्रम माना गया है।

IRDP कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा 750 करोड़ रु. तथा राज्यों के द्वारा भी लगभग इतनी ही राशि व्यय के लिए रखी गई।

2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)

इसमें केन्द्र व राज्यों का 50 : 50 भागधार पर हिस्सा रखा गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्त मौसम (slack season) में निर्धन लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्यक्रम है तथा पहले के 'काम के बदले भ्रामज' का ही एक संशोधित रूप है। यह निश्चय किया गया कि इसके अन्तर्गत केन्द्र राज्यों को खाद्यान्न देगा जिसकी मात्रा ग्रामीण निर्धनों की सरया को आधार मानकर तय की जायगी।

छठी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में NREP के लिए 980 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई तथा राज्यों के लिए भी इतनी ही राशि निश्चित की गई।

3 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP)

छठी योजना में इस कार्यक्रम पर 5807 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गई तथा इसके अन्तर्गत पहले की भांति प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य,

ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास की सहायता, शहरी गन्दी वस्तियों में पर्यावरण का सुधार तथा पोषण-सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल किये गये।

योजना काल में 3.43 करोड़ व्यक्ति-वर्षों के लिए अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया ताकि सभी नये आगन्तुकों को काम दिया जा सके एवं कुछ पुराने बेरोजगार व्यक्तियों को भी काम उपलब्ध कराया जा सके।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि छठी पंचवर्षीय योजना एक 'साहसपूर्ण योजना' (bold plan) मानी जा सकती है। इसमें विकास की वार्षिक दर 5.2 प्रतिशत रखी गई जबकि 1950-51 से 1978-79 की अवधि में यह लगभग 3.5 प्रतिशत रही थी। इसमें उत्पादन के कुछ लक्ष्य भी काफी ऊँचे रखे गये थे। जैसे 1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन 15 करोड़ टन करना, कोयले का उत्पादन 1979-80 में 10.4 करोड़ टन से बढ़ाकर 1984-85 में 16.5 करोड़ टन करना, त्रूड पेट्रोलियम का 1.2 करोड़ टन से बढ़ाकर 2.2 करोड़ टन करना, सिंचित क्षेत्र में पांच वर्षों में लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर की वृद्धि करना, आदि। योजना में इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम, ऊर्जा, सीमेंट आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक विनियोगों की व्यवस्था की गई थी।

छठी योजना में आर्थिक प्रगति¹

(Economic Progress under Sixth Plan)

1. विकास की दर—छठी पंचवर्षीय योजना विकास, आधुनिकीकरण व सामाजिक न्याय की दिशा में अग्रसर होने की दृष्टि से काफी सफल मानी जा सकती है। इसमें विकास की वार्षिक दर 5.3% रही जो लक्ष्य के अनुसार ही थी। योजनाकाल में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय लगभग 3.1% वार्षिक दर से बढ़ी। कृषि में विकास की दर लक्ष्य से अधिक रही, लेकिन खनन व विनिर्माण में यह लक्ष्य से काफी नीची रही। अन्य सेवाक्षेत्रों में भी विकास की दर लक्ष्य से ऊँची रही।

छठी योजना में विकास की दर का मूल्यांकन करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसका आधार वर्ष 1979-80 काफी कमजोर वर्ष था। उस वर्ष राष्ट्रीय आय पिछले वर्ष 1978-79 की तुलना में 5.2% घटी थी। इसलिए ऐसे प्रतिकूल वर्ष को आधार वर्ष मानने से आर्थिक प्रगति अपेक्षाकृत अधिक बड़े-बड़े रूप में प्रकट हो सकती है।

1. Economic Survey 1988-89, Various tables, and Seventh Five Year Plan 1985-90, Vol 1, Chapter 1, pp. 1-7.

2. कृषिगत उत्पादन—छठी योजना में कृषिगत उत्पादन में वार्षिक उतार-चढ़ाव घाते रहे। 1980-81 में यहाँ 15.6% बढ़ा, जबकि 1982-83 में 3.3% घटा। पुनः 1983-84 में यह 13.7% बढ़ा। 1984-85 में यह 1.2% ही बढ़ा। खाद्यान्नों का उत्पादन 1979-80 में 11 करोड़ टन से बढ़कर 1984-85 में लगभग 14.6 करोड़ टन पर पहुँच गया। इस प्रकार योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। तिलहन का उत्पादन 1979-80 में 87.4 लाख टन से बढ़कर 1984-85 में 1.3 करोड़ टन हो गया जो लक्ष्य से अधिक था। जूट व मेस्ता तथा गन्ने में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रत्युत्पन्न क्षेत्रफल 1979-80 में 3.8 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 1984-85 में 5.41 करोड़ हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्रफल 5.3 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 6 करोड़ हेक्टेयर एवं उर्वरकों का उपभोग 53 लाख टन से बढ़कर 82 लाख टन हो गया। इस प्रकार उर्वरकों का उपभोग लक्ष्य से अधिक रहा, HYP में यह लक्ष्य के समीप रहा तथा सिंचाई में लक्ष्य से कुछ कम रहा।

3. औद्योगिक उत्पादन—छठी योजना में औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर का लक्ष्य 7% था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर लगभग 5.5% सालाना रही (1970 के सूचनांक के आधार पर) जो लक्ष्य से नीची थी। कोयले का उत्पादन (सिग्नाइंट सहित) 1979-80 में 10.7 करोड़ टन में बढ़कर 1984-85 में 15.5 करोड़ टन, कूड तेल का 1.2 करोड़ टन से 2.9 करोड़ टन एवं तैयार इस्पात का 69 लाख टन से बढ़कर 1982-83 में 80.5 लाख टन व 1984-85 में घटकर 77.8 लाख टन हो गया। इसी अवधि में मशीनों, औजारों, उर्वरकों, नीमेट आदि का उत्पादन बढ़ा।

इस प्रकार कूड तेल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 1984-85 में उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है जिससे इसका आयात कम करना सम्भव हो सका है। सृजित विद्युत की मात्रा 50% बढ़ी (105 अरब किलोवाट घण्टे से 157 अरब किलोवाट घण्टे तक), लेकिन यह 191 अरब KWh के लक्ष्य से कम रही।

4. विदेशी व्यापार की स्थिति—छठी योजना में प्रति वर्ष व्यापार का घाटा 55 अरब रुपये व इससे अधिक हुआ। पाँच वर्षों में कुल व्यापार का घाटा 28,581 करोड़ रु. हुआ, जिससे विदेशी विनिमय की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आयातों की राशि निर्यातों से काफी अधिक रही। इससे हमारी विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ी तथा IMF से कर्ज लेने से जटिल स्थिति का मुकाबला करना सम्भव हो सका।

1985-86 से IMF के कर्ज का मुग्तान चालू हो जाने से ऋण-सेवा-भार बढ़ने लगा है। सातवी योजना में विदेशी साधनों की दृष्टि से स्थिति काफी जटिल हो गई है।

5 मुद्रास्फीति की दर—छठी योजनावधि में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 8% रही तथा उपभोक्ता-मूल्य सूचकांक के आधार पर 9.5% रही। छठी योजना में भी भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति में गिरावट जारी रही, हालांकि अन्य देशों की तुलना में भारत का कीमतों के सम्बंध में रिकार्ड ज्यादा चिन्ताजनक नहीं है।

6 साधन-समृद्ध—छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय का लक्ष्य (1979-80 के माथों पर) 97,500 करोड़ रु. रखा गया था, जबकि प्रचलित माथों पर 109292 करोड़ रु. रहा है* जो कीमत वृद्धि के लिए समायोजित किये जाने पर डॉ. डी. टी. लक्ष्माय्या के अनुसार 20% कम बैठता है।¹ पाटे की वित्त-व्यवस्था से साधन प्राप्त करने का लक्ष्य 5,000 करोड़ रु. था जबकि वास्तविक पाटे की वित्त-व्यवस्था इसके 2 1/2 गुने से भी अधिक (13,132 करोड़ रु.) हुई। गैर-योजना व्यय के बढ़ जाने के कारण चालू राजस्व से बकाया राशि लक्ष्य से काफी कम रही है। इस प्रकार योजना की वित्तीय व्यवस्था से मुद्रास्फीति के दबाव बढ़े हैं।

7 निर्धनता व बेरोजगारी—छठी योजना में IRDP में कुल धनियोग का लक्ष्य (वैक-नर्ज-सहित) 4500 करोड़ रु. का था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 4730 करोड़ रु. की रही है। 1.5 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाना था, जबकि वास्तव में 1.65 करोड़ परिवारों को सामान्वित किया जा सका है जो लक्ष्य से अधिक रहा है।

छठी योजना में NREP के अन्तर्गत 2485 करोड़ रु. उपलब्ध किये गये जिनका 3/4 अंश काम में लिया गया। प्रति वर्ष 30 से 40 करोड़ मानव-दिवस रोजगार उत्पन्न किया गया जो लक्ष्य के अनुरूप था। ग्रामीण क्षेत्रों में दूधारीपण, सालाब, सिंचाई सड़क व स्कुल आदि से सम्बन्धित निर्माण-कार्य किये गये।

सदकार ने सातवी योजना के प्रारूप, लण्डन में बतलाया है कि भारत में निर्धनता का अनुपात 1977-78 में लगभग 48% से घटकर 1984-85 में 37% पर आ गया है। इस प्रकार निर्धन व्यक्तियों की संख्या 1977-78 में 30.7 करोड़ से घटकर 1984-85 में 27.3 करोड़ पर आ गई है। विकास की ऊँची दर व

* प्राकृतिक दुर्घटनाओं पर राहत-व्यय सहित यह 110467 करोड़ रु. रहा है।

1. D. T. Lakdawala, *Seventh Plan : Solutions and Problems*, The Economic Times, February 24, 1986.

वृषिगत उत्पानन की वृद्धि तथा IRDP, NREP, MNP व RLEGP (ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारण्टी कार्यक्रम) आदि के क्रियान्वयन से भारत में निर्धनता व बेरोजगारी घटी है।

छठी योजना में निर्धनता-उन्मूलन की दिशा में सरकार ने जो दावे किये हैं उनके सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रोफेसर राजकृष्ण व अन्य प्रमुख अर्थशास्त्रियों जैसे डॉ. सुन्दरम्, सुरेश तेन्दुल्कर, नीलकण्ठ रय, डॉ. टी. लक्ष्माबाबा तथा बी.एम. दाडेकर आदि का विचार रहा है कि इतने लोगों के द्वारा निर्धनता की रेखा को पार करने की बात सही नहीं जान पड़ती।

डॉ. टी. टी. लक्ष्माबाबा के अनुसार सरकार के निर्धनता-उन्मूलन के दावे निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं¹ —

(i) वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई है वह सभी व्यय-समूहों में समान रूप से हुई है।

(ii) निर्धनता की रेखा से जितने परिवार ऊपर आये हैं उनकी सहायता का सीधा सम्बन्ध उन पर किये गये खर्च से कर दिया गया है। लेकिन आर्थिक विकास के वितरणात्मक प्रभाव सभी वर्गों के लिए एक-से नहीं होते। IRDP के क्रियान्वयन के सभी अध्ययनों से पता चलता है कि निर्धनों को छोटने में त्रुटियाँ हुई हैं, कर्ज व अनुदान-सहायता की राशियाँ जरूरी नहीं कि उनकी ही मिले, तथा सम्भव है उनके द्वारा किया गया व्यय भी नियोजित तरीकों से नियोजित परिणाम प्राप्त करने में न हा पाया हो।

डा. नीलकण्ठ रय का कहना है कि यदि कर्ज की किस्तों को टाला जाय तो IRDP से लाभान्वित होने वाले 10% लोग ही निर्धनता की रेखा को पार करने वाले माने जा सकते हैं। 1983 के राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे ने ज्यादा आशाजनक स्थिति प्रस्तुत की है और इसी के परिणामी के आधार पर सरकार ने यह दावा किया है कि निर्धनता का अनुपात 1977-78 में 48% से घट कर 1984-85 में 37% पर आ गया है। वास्तव में 1983 के सर्वेक्षण के भाकियों की अधिक छानबीन करने की आवश्यकता है। छठी योजना में 1984-85 का लक्ष्य 18% व्यक्तियों को निर्धनता की रेखा से ऊपर लाना था। (48% से पुनर्वितरण सहित 30% पर) जबकि वस्तुतः लगभग 110% ही इस रेखा से ऊपर आ पाये हैं (48% से 37% तक)। अतः निर्धनता-उन्मूलन के सम्बन्ध में सरकारी दावों की अधिक गहराई से समीक्षा करने की आवश्यकता है।

1 D T Lakdawala, Seventh Plan II—Impact on Distribution, The Economic Times, February 25, 1986.

प्रोफसर वी एम दांडेकर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात 1971-72 में 46% से घट कर 1983 में 44.4% पर ही आ पाया है। इस प्रकार 11½ वर्षों में इसमें केवल 1.6 प्रतिशत बिंदु की ही गिरावट आयी है।¹

IRDP में स्वरोजगार पर जोर दिया गया है। अब अधिकांश विद्वानों का मत हो चला है कि मजदूरी-रोजगार पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके और सविसडों के रूप में सरकारी कोषों को नष्ट होने से बचाया जा सके। अतः विकेंद्रित आपार पर जिला-नियोजन के अन्तर्गत रोजगार की सुरक्षित परियोजनाओं को संचालित करने की आवश्यकता है।

■ ग्राम क्षेत्रों में उपलब्धियाँ—छठी योजना में कुछ ग्राम उपलब्धियाँ इस प्रकार रही—(i) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए व प्राथमिक व सहायक स्वास्थ्य के केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये, (ii) 1979-80 में लगभग 22% दम्पति परिवार नियोजन ने सुरक्षित दायरे में आ चुके थे, 1984-85 में इनकी संख्या बढ़कर 32% हो गई, (iii) 2-31 लाख गांवों में से 1.92 लाख गांवों में नियमित जन पूर्ति की जा सकी और लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया गया, (iv) 54 लाख निर्धन ग्रामीण परिवारों को रिहायशी भूखण्ड वितरित किये गये तथा 19 लाख परिवारों की भवन-निर्माण के लिए सहायता दी गई।

निष्कर्ष—इस प्रकार छठी योजना में विभिन्न क्षेत्रों में अधिक प्रगति हुई। पहली बार ऐसा प्रतीत होने लगा कि निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं को उचित नीतियाँ व सही कार्यक्रम अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। देश में नियोजन के प्रति एक नया विश्वास व उत्साह उत्पन्न हुआ। विकास की वार्षिक दर 3.5% के मार्ग को छोड़कर 1974-75 से 1984-85 की अवधि में लगभग 5% के मार्ग पर आ गई जिसे आगामी वर्षों में इसी मार्ग पर बनाये रखने का प्रयास करना है।

प्रश्न

- 1 भारतीय नियोजन में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है? क्या यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बल देने के लिए धीरे-धीरे निजी क्षेत्र की भूमिका घटाई जावे।
(Raj Iyer T D C, 1981)

उत्तर-संकेत—प्रश्न सामान्य किस्म का है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का उदाहणों के माध्यम से विवेचन करने के लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 की उद्योगों की श्रेणी A व श्रेणी B का विस्तृत उल्लेख किया जाना चाहिए।

¹ V M Dandekar Agriculture, Employment and Poverty, EPW, September 20-27, 1986 इस विषय पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण लेख माना गया है।

सरकार ने योजना के प्रारम्भिक वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभुतासम्पन्न स्थिति (Commanding position) में लाने पर जोर दिया था। हाल के वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में उदारता की नीति अपनाई गई है जिससे निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। सरकार उन्नत टेक्नोलोजी, बड़े पैमाने के उत्पादन, प्रतिस्पर्धा, व खुली अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देने लगी है एवं आर्थिक नियन्त्रणों में ढील दी जाने लगी है। काफी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है।

सातवीं योजना में कुल विनियोग का 48% सार्वजनिक क्षेत्र के लिए तथा 52% निजी क्षेत्र के लिए रखा गया है। पाचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश 42.9% तथा छठी योजना में 53% रखा गया था। सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने के लिए धीरे-धीरे निजी क्षेत्र की भूमिका का घटाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत में दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए काफी अवसर विद्यमान है। सार्वजनिक क्षेत्र आधारभूत ढांचे जैसे विद्युत, परिवहन, खनन, पूर्वाजी व आधारभूत उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जबकि निजी क्षेत्र उपमोक्ता उद्योगों, लघु उद्योगों, सड़क-माल-परिवहन, व्यापार, कृषि वर्गों में भाग ले सकता है।

2. भारत की विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग के आकार तथा तरीकों का उल्लेख कीजिए। (Raj Iyer T. D. C., 1984)

3. भारत में छठी पंचवर्षीय योजना की विस्तृत रूपरेखा बताइये।

(Raj Iyengar T. D. C., 1982)

बीस-सूत्री कार्यक्रम, अनवरत योजना व भारतीय नियोजन

(Twenty Point-Programme,
Rolling Plan & Indian Planning)

दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति काफी धीमी पड़ गई थी। 1974-75 में राष्ट्रीय आय 1970-71 के भारो पर पिछले वर्ष की तुलना में केवल 1.5 प्रतिशत ही बढ़ी एवं प्रति व्यक्ति आय 0.6 प्रतिशत घटी थी। 1973-74 व 1974-75 में प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 20% व 25% रही थी। इस दश में जम्मू-काश्मीर आर्थिक मंद्य उत्पन्न हो गया था। जीवन की आवश्यक वस्तुओं के अभाव, बढ़ती हुई कीमतों, वस्तुओं के सत्रह व मुनाफाकोरी ब्राह्मणारी तथा उत्पादन के क्षेत्रों में गतिहीनता व हड़ताल का दशाघोष आर्थिक मंद्य के साथ-साथ राजनीतिक संकट भी उत्पन्न कर दिया था। ममयन राष्ट्र राजनीतिक आन्दोलनों की लपेट में आ गया था और स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। राष्ट्र के समस्त एक महान् चुनौती की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हड़तालों व बन्द के दौर तीव्र हो गए थे। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि राष्ट्रीय अनुशासन, कर्तव्यपरायणता व कठोर परिश्रम जैसे गुण अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गए और देश में आर्थिक प्रशासन दिन-भित्त हो गया था। देश को एक सज्जन आंदोलन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।

25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 352 के अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके आपातकाल (state of emergency) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को आन्तरिक अशांति व अव्यवस्था के खतरे से बचाना था। ऐसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है समस्त वातावरण के पीछे आर्थिक मंद्य ही प्रमुख था। इसलिए जनहित में आर्थिक मुद्दों की नितान्त प्रावश्यकता थी। स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 1 जुलाई, 1975 को 20-

सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पेश किया जिस पर आपातकाल में काफी चर्चा हुई थी। मार्च 1977 में केन्द्र में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने पर इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। लेकिन जनवरी, 1980 में केन्द्र में कांग्रेस (आई) के पुनः सत्तारूढ़ होने पर 14 जनवरी, 1982 को स्व. श्रीमती गांधी ने एक सशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार उनके कार्यकाल में इस कार्यक्रम के दो रूप देश के समक्ष प्रस्तुत किये गये। 20 अगस्त 1986 को राजीव सरकार की ओर से सशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया जो इसका तृतीय संस्करण कहला सकता है। हम नीचे इनके विभिन्न बिन्दुओं का विवरण देते हैं और भारतीय नियोजन में इनकी भूमिका स्पष्ट करते हैं।

प्रथम बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जुलाई, 1975*

प्रथम 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम। जुलाई, 1975 को घोषित किया गया था। इसके विभिन्न सूत्रों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है :

(क) कल्याणकारी कार्य,

(ख) आर्थिक बुराइयों को दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रम; तथा

(ग) उत्पादन-वृद्धि तथा अर्थ-व्यवस्था के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित विविध कार्य।

(क) कल्याणकारी कार्य

इस श्रेणी में वे कार्य रखे गये जिनका उद्देश्य लोगों को शीघ्र लाभ पहुंचाना था। गांवों व शहरों में निर्धन व मध्यमवर्ग को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उनके कल्याण के लिए निम्न कार्यक्रम घोषित किये गये :

1. ग्रामीण ऋणग्रस्तता से मुक्ति—इसके अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों, लघु कृषकों तथा कारीगरों से कर्ज की बसुली पर रोक लगाने व उनकी ऋणग्रस्तता को समाप्ति का कार्यक्रम घोषित किया गया। साथ में यह भी कहा गया कि इनको कर्ज देने के लिए बैंकलपिक संस्थाओं का विकास किया जायगा ताकि गांवों के निर्धन लोगों को आवश्यक मात्रा में ऋण की सुविधा मिल सके।

* 20-सूत्री कार्यक्रम पर पूछे जाने पर 20 अगस्त, 1986 के तीसरी बार घोषित किये गये आर्थिक कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि वही प्रचलन में है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से पहले के दो कार्यक्रमों का भी अपना महत्व है। अतः उन पर भी दृष्टि डालना जरूरी है।

2 मू-जोतों पर सीमा निर्धारण, अतिरिक्त भूमि का वितरण व भूमि के रिकार्ड तैयार करना—20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भूमि-सुधारो के सीमा-निर्धारण कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया, क्योंकि इसके सफल होने पर ही भूमि के वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सकता था। यह कहा गया कि भूमि के रिकार्ड तैयार करने से भू-स्वामित्व व काश्तकारी अधिकारों के सम्बन्ध में स्पष्टि स्पष्ट हो जायेगी जिससे भूमि-सुधार कार्यक्रम लागू करने का आधार सुनिश्चित हो जायेगा। इससे वित्तीय सत्ताओं को कर्ज देने में भी सहूलियत होगी क्योंकि भूमि में, कृषकों के अधिकार स्पष्ट हो जायेंगे। सीमा-निर्धारण व अतिरिक्त भूमि का वितरण सामाजिक न्याय के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भी आवश्यक माने गये थे।

3. भूमिहीनों व श्रामीय निर्धनों के लिए आवासीय भूखण्डों की व्यवस्था—भारत में आवास की समस्या काफी गम्भीर रही है, विशेषतया भूमिहीनों व कमजोर वर्ग के लिए तो यह असहनीय रही है। 1971 से भूमिहीन श्रमिकों के लिए नि:शुल्क आवासीय भूखण्डों की प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जा रही थी। इसके लिए केन्द्रीय कार्यक्रम में इसे तीव्र गति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। भूमिहीन लोगों को आवासीय भूखण्ड देने के साथ-साथ मकान बनाने के लिए कर्ज देना भी आवश्यक माना गया।

4 बन्धुश्रम (bonded labour) को गैर-कानूनी घोषित करना—देश के विभिन्न भागों में बन्धुश्रम श्रम की समस्या पायी गयी है। इसके अन्तर्गत बन्धुश्रम गुलामी की अवस्था में जीवनयापन करते हुए पाये गये हैं। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में इसे गैर-कानूनी घोषित करने तथा बन्धुश्रम मजदूरों को मुक्त कर-कर उन्हें फिर से बसाने की बात कही गयी थी। यह समस्या आदिम जाति के लोगों में अधिक पायी गयी है। साथ में यह कहा गया कि इस पर समुचित रूप से प्रहार करने के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का विकास करना होगा, अन्यथा अनौपचारिक रूप से यह प्रथा जारी रह सकती है।

5 न्यूनतम कृषिगत मजदूरी के कानूनों की पुनः समीक्षा—हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत खेतिहर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। लेकिन श्रमिकों के असंगठित रहने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है। महंगाई बढ़ने के कारण इसमें उचित संशोधन की भी आवश्यकता रही है। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में न्यूनतम कृषिगत मजदूरी के पुनर्निर्धारण पर जोर दिया गया ताकि भूमिहीन श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

स्मरण रहे कि उपर्युक्त पाँचों कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से कृषिगत मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाने वाले थे और इनका लक्ष्य 'श्रामीय निर्धन' वर्ग की आर्थिक व सामाजिक दशा में सुधार करना था।

6. मध्यम-वर्ग को आय-कर में राहत—मध्यम-वर्ग के लिए आय-कर में छूट की सीमा 8,000 रुपये कर दी गयी। पहले यह सीमा 6,000 रुपये थी। मुद्रा-स्फीति से मध्यम-वर्ग की कठिनाइयाँ भी बढ़ी थी। इसलिए इस वर्ग को राहत पहुँचाना भी आवश्यक था।

7 होस्टलो में विद्यार्थियों को राहत—निर्धन परिवारों के छात्रों को अपने घर से बाहर अध्ययन कार्य करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए होस्टल व अन्य आवास-गृहों में नियन्त्रित भावों पर आवश्यक वस्तुएँ सुलभ कराना भी 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्य के लिए उपभोक्ता सहकारिताओं का उपयोग करने पर बल दिया गया। इनके माध्यम से विश्वविद्यालयों के होस्टलों में छात्राग्राहों वाले मसाले वनस्पति तेल, चाय साबुन, चीनी, आदि उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध कराने के कार्यक्रम रखे गये।

8 नियन्त्रित भावों पर पाठ्य-पुस्तकें व स्टेशनरी उपलब्ध कराना—विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें व स्टेशनरी नियन्त्रित भावों पर उपलब्ध कराना तथा 'बुक-बैंक' के माध्यम से निर्धन छात्र-छात्राग्राहों को इन्हें सुलभ कराना भी 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा का न्यय कम किया जा सके।

9. शहरी भूमि का समाजीकरण—इसके अन्तर्गत शहरी व शहरीकरण के योग्य भूमि का समाजीकरण, खाली पड़े भूखण्डों के स्वामित्व व अधिकारों पर सीमा तथा नये मकानों के प्लान-य क्षेत्र पर सीमा लगाने के कार्यक्रम प्राते हैं। शहरी भूमि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से कुछ व्यक्तियों ने बहुत अधिक लाभ उठाया है। इसलिए सरकार ने यह निश्चय किया कि इस सम्बन्ध में ऐसे कदम उठाये जायें कि शहरी भूमि में सट्टेबाजी रुक सके। शहरी भूमि के सोदों का काली मुद्रा से भी सम्बन्ध रहा है। इसलिए उस पर नियन्त्रण करने के लिए यह कार्यक्रम भी आवश्यक माना गया।

सरकार ने जनवरी 1976 में शहरी सीलिंग बिल सदन में पेश किया जिसके अन्तर्गत शहरी व शहरीकरण के योग्य भूमि को चार श्रेणियों में बाँटा गया और 500 से 2,000 वर्ग मीटर तक खाली भूखण्डों पर सीमा-निर्धारण घोषित किया गया। यह कहा गया कि सीमा के ऊपर के खाली भूखण्डों को सरकार मुआवजा देकर स्वयं ग्रहण कर लेगी। इस प्रकार शहरी भूमि का समाजीकरण शहरी सम्पत्ति पर सीमा-निर्धारण के अंश के रूप में अपनाया गया।

(ख) आर्थिक बुराइयों को दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रम

10 तस्करी-विरोधी कदम—भारतीय अर्थव्यवस्था तस्करी का अत्यधिक शिकार रही है। इसलिए तस्करी-विरोधी अभियान 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का

एक अनिवार्य अंग बनाया गया। इसके अन्तर्गत तस्करों की सम्पत्ति जम्न करने के कानून शामिल किये गये। तस्करों की गिरफ्तारी और तस्करी का माल जप्त करने की पुरजोर व्यवस्था करता भी आवश्यक माना गया। तस्करी का माल लाने वाल जहाजों को पकड़ने के लिए किए जाने वाले विशेष प्रयत्न भी इसी में शामिल किये गये। देश में करोड़ों रुपये का सोना व विलासिता का सामान चोरी-छिपे आता रहा है जिसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए विदेशी पर्यटकों से प्राप्त विदेशी मुद्रा व विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उपयोग करने के साथ-साथ निर्यातों का नीचा मूल्यांकन व आयातों का ऊँचा मूल्यांकन होता रहा है। भारतीय माल भी विदेशों में चोरी-छिपे ले जाया जाता है। 'ग्रामुका' (प्रान्तरिक सुरक्षा कानून) के अन्तर्गत तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करके विदेशी विनिमय बचाने के लक्ष्य रखे गये।

11. आयात-बाइसेम्सों के दुरुपयोग पर कार्यवाही—भारत में आयात लाइसेन्सों का दुरुपयोग होता रहा है। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में कानून का उल्लंघन करने वाले को बड़ी सजा देने व आयात की गयी वस्तुओं को जप्त करने की भी व्यवस्था की गयी। आयात-निर्यात कानूनों में आवश्यक सशोधन किया गया।

12. करो की चोरी रोकने से सम्बन्धित उपाय—भारतीय अर्थव्यवस्था में कई वर्षों से एक अंग 'काली अर्थव्यवस्था' (black economy) के रूप में चलता रहा है। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में इसको रोकने के लिए विलासी मन्त्रों के मूल्यांकन, करो की चोरी के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों व व्यक्तियों पर छापे व तलाशी आदि के रूप में कदम उठाने की नीति अपनायी गयी। यह सोचा गया कि इससे काला-बाजारी, माल के अनुचित संग्रह व मुनाफाखारी आदि समाज-विरोधी नियमों पर अक्रुश लगेगा और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी और सरकार की करों से प्राप्त आय बढ़ेगी। काली मुद्रा की वृद्धि व संचालन को रोकने के लिए कर-मशीनरी व कर-प्रशासन को सुदृढ़ करना भी आवश्यक समझा गया।

(ग) उत्पादन-वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था के आधारभूत-ढाँचे (infrastructure) को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित विविध कार्य

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी आवश्यक उपाय सुझाये गये जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है।

13. मुख्य नियन्त्रण के उपाय—जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, अर्थव्यवस्था में मुख्य-वृद्धि ने देश में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार उत्पन्न कर दिया था। अतएव 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में विभिन्न कदम उठाकर मूल्यों को कम करना आवश्यक माना गया। इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, बमूली व विनरए

को ठीक करना, सरकारी व्यय में कमी करना तथा अन्य कदम उठाना अत्यावश्यक समझा गया। वस्तुन, इस कार्यक्रम का आर्थिक अपराधों को रोकने के कार्यक्रमों से निष्कट का सम्बन्ध था। सरकार ने व्यापारियों को स्टॉक धोपित करने व कीमनों टांगने के लिए भी प्रेरित किया। 2 अक्टूबर 1975 से पेंसेट की वस्तुओं पर उत्पादन की निधि, शुद्ध मात्रा, वजन व मूल्य अंकित करना भी आवश्यक कर दिया गया। सरकारी व्यय अंकित होने से घाटे की वित्त-व्यवस्था बढ़ती है। अतः सरकारी व्यय को नियन्त्रित करने का भी निर्णय किया गया। मूल्यों को स्थिर करने में खाद्यान्नों की बसुली का केन्द्रीय स्थान होता है। अतः सरकार ने गेहूँ, चावल व अन्य अनाजों की खराद में वृद्धि करके बफर स्टॉक बनाने पर भी ध्यान दिया।

14 सिंचाई का विस्तार—कृषिगत उत्पादन की कुँजी सिंचाई के साधनों के पर्याप्त विकास करने में निहित होनी है। अतः 20-सत्री आर्थिक कार्यक्रम में 50 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया; विशेषतया भूमि के नीचे पाये जाने वाले जल-साधनों का विकास करने पर बल दिया गया।

15 पावर कार्यक्रम में तीव्रता—कृषिगत व औद्योगिक विकास का आधार 'पावर' को मानना अनुचित नहीं होगा। इसलिए केन्द्र के नियन्त्रण में सुपर थर्मल स्टेशनों की स्थापना करके देश को शक्ति के संकट से उबारना अत्यावश्यक माना गया। पिछले वर्षों में शक्ति के अभाव ने औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। 1975-76 में विद्युत सृजन-क्षमता में 20% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया ताकि हम अवधि के अन्त में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 22.77 मिलियन कि.लोवाट हो जाय। सरकार ने सिंगरीली, कोरवा, फरक्का व नैवेली कोयला केन्द्रों को सुपर थर्मल स्टेशन स्थापित करने के लिए चुना था।

16 हथकरघा क्षेत्र का विकास—कृषि के बाद रोजगार की दृष्टि से हथकरघा उद्योग का स्थान आता है। लगभग 70-80 लाख व्यक्ति इस पर आश्रित होकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि इस उद्योग को उचित कीमतों पर बच्चा माल नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय। हथकरघा उद्योग का विकास करने के लिए महकारी मन्थार्यों को मुहड़ करने पर बल दिया गया।

17 जनता वस्त्र अथवा नियन्त्रित वस्त्र की किस्म तथा सप्लाई में सुधार—पिछले वर्षों में जनसाधारण के काम के वस्त्र की किस्म व सप्लाई में गिरावट रही है। इसलिए नयी स्कीम में धोती-साड़ी व अन्य वस्त्रों की किस्म में सुधार करने तथा इन्हें उचित मूल्यों पर शामीण व शहरी क्षेत्रों में सुलभ कराने पर जोर दिया गया। ऐसा थमिक वर्ग व निम्न मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाने के लिए किया गया।

ध्यान धारकपिन किया तथा इन कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम की सजा दी और मार्च 1977 में केन्द्र में कांग्रेस के मत्ता से हट जाने के बाद यह कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया। ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से किसी भी कार्यक्रम की मद अपने आप में किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक नहीं थी, लेकिन इसे राजनीतिक कारणों से जनता सरकार की तरफ से मान्यता नहीं मिली। जनवरी, 1980 में कांग्रेस (मार्ड) के सत्ता में वापस आने के बाद इसे पुनर्जीवन मिला और 14 जनवरी, 1982 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सशोधित प्रस्ताव द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम घोषित किया जिसका वर्णन आगे किया गया है। राजस्थान में तो इनके साथ 20-सूत्री और जोड़ दिये गये और 'पिछड़े को पहले' आदि कार्यक्रमों पर जोर दिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्तियों को आमदनी व रोजगार के माधन मिल सकें। दूसरे 20-सूत्री कार्यक्रम का वर्णन करने से पूर्व जनता शासनकाल में बहुचर्चित अनवरत योजना के विचार का संक्षिप्त परिचय देना उचित होगा।

अनवरत योजना का विचार (The Concept of Rolling Plan)

मार्च, 1977 में केन्द्र में सत्तारूढ़ होने पर जनता सरकार ने योजना की पद्धति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जिसे अनवरत योजना कहा गया है। इसके अन्तर्गत पहले की स्थिर (static) पंचवर्षीय योजना के स्थान पर निम्न किस्म की अनवरत योजना-प्रणाली सुझाई गयी थी—

1. पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य क्षेत्रों के लिए परिच्यय व उत्पादन के सम्बन्ध में वार्षिक क्षेत्रवार लक्ष्य (annual sectoral targets) निर्धारित करना।
2. प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन चुने हुए क्षेत्रों के लिए एक और वर्ष के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित करना और इस प्रकार पंचवर्षीय योजना को अधिक व्यापक, अधिक व्यावहारिक व अधिक लचीली बनाना।

जनता सरकार ने 1978-83 की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ पेश किया था। यह कहा गया था कि 1978-79 की वार्षिक योजना के समाप्त होने पर योजना आयोग इस अवधि की प्रगति की समीक्षा करेगा और कुछ क्षेत्रों में कमियाँ पाये जाने पर अथवा अन्य नयी सूचनाओं के आधार पर पहले के लक्ष्यों में आवश्यक संशोधन करेगा और एक आगामी वर्ष 1983-84 के लिए भी लक्ष्य निश्चित करेगा। इस प्रकार हर सात देश में एक नयी पंचवर्षीय योजना तैयार रहेगी।

अनवरत योजना-पद्धति पर देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उस समय के विरोधी दलों ने इसकी वांछी आलोचना भी की। इसलिए यह आवश्यक हो जाना है

कि इसके गुण-दोषों की चर्चा की जाय ताकि पाठकों को इसके सम्बन्ध में सही स्थिति की जानकारी हो सके ।

अनवरत योजना-पद्धति के सम्भावित लाभ

1 योजना अधिक वास्तविक व लचीली होगी (Planning would be more realistic and flexible)—अनवरत-योजना के पक्ष में एक दावा यह किया गया कि इससे नियोजन की प्रक्रिया में अधिक वास्तविकता व लचीलापन आ जायेगा । पिछले वर्षों में लक्ष्यों व उपलब्धियों के बीच जो अन्तर रहे हैं अब जो काफी समय तक जारी रहे हैं, उन्हें कम किया जा सकेगा । इस प्रकार यह प्रणाली उत्तार-चढ़ाव तथा अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए ज्यादा अच्छी स्थाित होगी ।

स्वर्गोप प्रोफेसर राजकृष्ण ने अपना मत इस प्रकार रखा था कि भूतकाल में पाँच वर्षों के अनुमान काफी बेतुल्य ब-क़तोर हो जाते थे तथा साथ: वास्तविकता से काफी दूर हो जाया करते थे । माँग के अनुमान या तो अधिक ऊँचे हो जाते या अधिक नीचे हो जाते तथा हमारी अर्थव्यवस्था पर मौममी परिवर्तनों, विदेशी विनियम के अमान्य तत्प, मुद्रास्फीति की ऊँची दरों का काफी विपरीत प्रभाव पड़ता था । इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए माघी अनुमान लगाने में अधिक लचीलेपन की आवश्यकता रही है । अनवरत योजना को अपनाकर हम हर वर्ष माघी अनुमानों में आवश्यक न्यूनतम संशोधन कर सकेंगे जिससे योजना देश के लिए अधिक व्यावहारिक, वास्तविक व उपयोगी बन जायेगी ।

अनवरत योजना के लचीलेपन का यह अर्थ नहीं है कि माग के प्रत्येक माघी अनुमान (every single demand projection), प्रत्येक वित्तीय बायद (every single financial commitment) व प्रत्येक स्वीकृत परियोजना (every single project in the shelf) में प्रतिवर्ष संशोधन किया जायेगा । यह तो अनवरत योजना की धारणा का गलत अर्थ लगाना होगा । इस धारणा के पीछे यह भाव्य अग्रस्य है कि आवश्यकतानुसार किसी भी विशेष माघी अनुमान या माघी लक्ष्य को संशोधित किया जा सकेगा ताकि योजना अधिक वास्तविक रूप धारण कर सक । इस प्रकार अवधार न कुछ घाटे से माघी अनुमानों, छोटी-सी स्वीकृत परियोजनाओं व घाटेंसे वित्तीय बायदों का ही संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी ।

2 गैर-योजना व्यय व योजना-व्यय आज की भांति इकट्ठे ही प्रस्तुत किए जायेंगे—योजना आयोग अनवरत योजना बनायगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए योजना व्यय निर्धारित करेगा । वित्त-मन्त्रालय गैर-योजना व्यय निर्धारित करेगा और आज की भांति आगे भी ये दोनों इकट्ठे रूप में ही पेश किए जाते रहेंगे । इस व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आयेगा । लेकिन योजना आयोग को नयी व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी वर्ष की अनवरत योजना का मसौदा जल्दी तैयार करना होगा ताकि योजना आयोग व वित्त-मन्त्रालय के अनुमान इकट्ठे पेश किए जा सकें ।

अनवरत योजना के विचार की समीक्षा

अर्थशास्त्रियों व अन्य विचारकों ने अनवरत योजना की उपयोगिता में सन्देह व्यक्त किये थे। कुछ का मत यह था कि अनवरत योजना भारतीय नियोजन की मूलभूत कमियाँ को दूर नहीं कर पायेगी और अन्य का विचार था कि अनवरत योजना की धारणा स्वयं में तो उपयुक्त व उपयोगी है लेकिन भारत की वर्तमान परिस्थितियों में इसे पूरी तैयारी के बिना लागू करने से लाभ की बजाय हानि होने का अधिक भय है।

वैद्यनाथन व गुलाटी¹ का यह मत रहा कि भारत में योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय लिये जाने आवश्यक हैं, जिनके अभाव में योजनाओं के लाभ आम जनता को नहीं मिल पाये हैं। राजनीतिज्ञ सदैव जनता की तरह-तरह के सब्ज बाग दिखाते रह रहे हैं तथा नीकरशाही योजना के लक्ष्यों के बारे में सदैव आशंकित व उदासीन रही है। दोनों का ध्यान अधिक व्यय करने के पक्ष में तो रहा है, लेकिन किसी ने भी उचित नीतियाँ अपनाकर योजनाओं के निष्पादन पर जोर नहीं दिया। अतः अनवरत योजना हमारे नियोजन के इन दोषों तथा अन्तर्विरोधों को दूर नहीं कर पायेगी और हम सार की बात पर ध्यान न देकर योजना व ऊपरी रूप को सुधारने में ही लगे रहेंगे, जिससे समाज को अधिक लाभ नहीं होगा। अतएव हम कठोर नीतियाँ अपनाकर निहित स्वार्थी वर्ग के हितों को पीछे हटाकर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

सुरेश तेन्दुलकर² के मतानुसार भारत में 1960 की दशक की मध्य भाग से लेकर अब तक मुख्य समस्या यह रही है कि नियोजन की प्रक्रिया में कई कारणों से जनता का विश्वास उठन लगा है, जिसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है और ऐसा पहले राजनीतिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार में इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की बजाय केवल अनवरत योजना की पद्धति को लागू करना ही पसन्द किया, जिसके लिए आवश्यक तैयारी नहीं की गयी। अतः अनवरत योजना की पद्धति तो युक्तिसंगत व लाभदायक है तथा इसको स्वीकार करना योजना का परिणाम करना नहीं है। लेकिन इस पद्धति को लागू करने के लिए जिस प्रकार की तकनीकी व प्रशासनिक तैयारी होनी चाहिए तथा जिस प्रकार का सत्यामल ढांचा

1. A Vaidyanathan and I S Gulati, On Rolling Plans, EPW October 8, 1977, pp 1739-1740.
2. Suresh D Tendulkar, Planning Process, Planning Commission and Rollover Planning, EPW, October 15, 1977, pp 1777-1782.

होना चाहिए उसका भारत में नितान्त अभाव पाया गया है। अतः यहाँ पर इसकी सफलता के आसार कम हैं। अनवरत योजना की व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिज्ञों को लक्ष्यो व उनकी उपलब्धियों के बीच में खाई रहने पर लक्ष्यो को नीचा करने का बहाना मिल जायेगा, वनिस्वत इसके कि वे उपलब्धियों को ऊँचा करने का प्रयास करें।

इस प्रकार अनवरत योजना के आलोचकों का यह मत रहा है कि भारत में योजना के क्रियान्वयन (plan implementation) पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा योजना की नीतियों को व्यवहार में आवश्यक दृढ़ता व कठोरता से लागू करना चाहिए। तभी नियोजन की प्रक्रिया में जनता का विश्वास पुनः जम सकेगा जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है।

जनवरी 1980 में केन्द्र में कांग्रेस (घाई) की सरकार बनने से अनवरत योजना के विचार को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया। जिस प्रकार जनता सरकार ने प्रथम 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को निरस्त कर दिया था, उसी प्रकार कांग्रेस (घाई) सरकार ने अनवरत योजना के विचार को अस्वीकृत कर दिया (the idea of rolling plan was rolled up)। सरकार ने पहले की भाँति एक स्थिर पंचवर्षीय योजना (a fixed five year plan) का मार्ग ही अपनाया और देश में नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) लागू की गई।

सरकार ने सशोधित अथवा द्वितीय बीस-सूत्री कार्यक्रम जनवरी 1982 में घोषित किया। उस समय नई सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हो गये थे और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती गान्धी ने यह आवश्यक समझा कि प्रथम 20-सूत्री कार्यक्रम को सशोधित किया जाय ताकि यह देश की समस्याओं के हल में नये सिरे से अपना सक्रिय योगदान दे सके।

दूसरा बीस-सूत्री कार्यक्रम, जनवरी 1982

प्रथम बीस-सूत्री कार्यक्रम के कई उद्देश्य प्राप्त कर लिये गये थे तथा छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ नये विकास-कार्यक्रम रखे गये थे। इन परिस्थितियों की ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी, 1982 को दूसरा बीस-सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया जिसके विभिन्न बिन्दु इस प्रकार हैं :

1. सिंचाई की सम्भाव्यता (Irrigation potential) बढ़ाना तथा सूखी क्षेत्रों के लिए आवश्यक इन्फ्रस्टो व टेक्नोलोजी का विस्तार करना। सूखी क्षेत्रों में वर्षों पर आश्रित क्षेत्रों में नमी के सरसरा के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

2. दासों व तिलहनो का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करना।

3. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) को सुदृढ़ करना तथा इनका विस्तार करना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है तथा दूसरा कार्यक्रम काम के बढ़ते प्रनाज का सघोषित रूप है एवं इसका उद्देश्य देहातों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

4. कृषिगत भूमि पर सीमा निर्धारण को लागू करना, प्रतिरिक्त भूमि का वितरण करना भूमि के रिकार्डों को विभिन्न प्रशासनिक व कानूनी प्रणालियों व बाधाओं को दूर करके पूरी तरह तैयार करना।

5. सेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को समीक्षा करना तथा उसे प्रभावशाली तरीके से लागू करना।

6. ग्रंथुष्ठा धर्मियों को फिर से बसाना।

7. अनुसूचित जातियों व जन जातियों के विकास के लिए कार्यक्रम को तेज करना।

8. समस्याग्रस्त गाँवों में पीने के पानी की सप्लाई करना।

9. ग्रामीण परिवारों को रिहायशी प्लाट देना तथा निर्माण-सहायता-कार्य-क्रमों का विस्तार करना।

10. गंदी बस्तियों की दशा सुधारना, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रम लागू करना तथा भूमि के मूल्यों में प्रवाहित वृद्धि को रोकने के उपाय करना।

11. शक्ति-सृजन को अधिकृत करना, विद्युत-प्राधिकरणों व संस्थाओं के कार्य में सुधार करना तथा समस्त गाँवों को बिजली पहुँचाना।

12. वन लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना, सामाजिक व काम बानिबी का विस्तार करना और बायो-गैस तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना।

13. परिवार नियोजन का जन-प्रान्दोत्तन के रूप में ऐच्छिक आधार पर विकास करना।

14. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक बनाने का प्रयास करना एवं कोड, टी. बी. व ग्रंथेपन पर नियन्त्रण स्थापित करना।

15. स्त्रियों व बच्चों के लिए कल्याण-कार्यक्रमों में तेजी लाना, गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के लिए पोषण-कार्यक्रम को प्राथमिक बढ़ाना, विशेषतया आदिवासी, पहाड़ी व पिछड़े क्षेत्रों के लिए।

16. आयु-समूह 6-14 में यूनिवर्सल प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विशेषतया लड़कियों के लिए, और साथ में छात्रों व ऐच्छिक एजेन्सियों को प्रौढ-निरक्षरता दूर करने के कार्यक्रमों में शामिल करना।

17 सार्वजनिक वितरण-प्रणाली का विस्तार करना, इसके लिए उचित मूल्य की दूकानों व दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल दूकानों की व्यवस्था करना और ऐसी दूकानें स्थापित करना जो औद्योगिक श्रमिकों, छात्रों के होस्टलों और विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकों व कॉपियों की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कर सकें और देश में मुद्रा उपभोक्ता घान्दोलन का विकास किया जा सके ।

18 विनियोग की विधियों को उदार करना तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए औद्योगिक नीतियों का सुदृढ़ करना । हथकरघा, दस्तकारी, लघु व ग्रामीण उद्योगों को विकास की सभी सुविधाएँ देना तथा उनकी टेक्नोलॉजी को नवीनतम बनाना ।

19 तस्करी, सप्लायरों, जमाखोरों व कर की-खोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी रखना तथा कांसी मुद्रा पर रोक लगाना ।

20 सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य-प्रणाली में सुधार करके उनकी कार्य-कुशलता व उत्पादन-क्षमता के प्रयोग में वृद्धि करना तथा आन्तरिक लाभों का सृजन करना ।

इस प्रकार द्वितीय 20-सूत्री कार्यक्रम में छठी योजना के मुरप सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम शामिल किये गये थे । इस कार्यक्रम से समाज के कमजोर व पिछड़े लोगों की दशा सुधारने व उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलने की आशा प्रकट की गई थी ।

द्वितीय 20 सूत्री कार्यक्रम की आर्थिक नियोजन में भूमिका

जैसा कि पहले कहा जा चुका है द्वितीय 20 सूत्री कार्यक्रम में कई ऐसे बिन्दु हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किये गये थे । इसलिए यह कार्यक्रम आर्थिक नियोजन का स्थानापन्न (substitute) नहीं है बल्कि उसका सहायक व समर्थक है । फिर प्रश्न उठता है कि इस कार्यक्रम की पृष्ठ से आवश्यकता क्यों पड़ी ? विद्वानों ने इस सम्बन्ध में कई अन्य प्रश्न भी उठाये हैं, जैसे इस कार्यक्रम से नियोजन की प्रक्रिया पर अनुकूल असर होगा या प्रतिकूल; क्या इस कार्यक्रम का केवल राज-नीतिज्ञ उद्देश्य है इत्यादि ।

इन प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है । कुछ का विचार है कि देश में 20 सूत्री कार्यक्रम का अपनाया जाना आर्थिक नियोजन की विफलता का सूचक है । यदि भारत में आर्थिक नियोजन सफल होता तो मूल्य से किसी ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । इस कार्यक्रम के माने-से नियोजन पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाकर इस कार्यक्रम पर ही अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, जिससे वस्तुतः नियोजन की प्रक्रिया अपने मूल रूप में कमजोर होन लगी है ।

इसके विपरीत प्रो. पी. आर. ब्रह्मानन्द का विचार है कि इन बीस सूत्री या बीस बिन्दुओं से नियोजन को कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इस नये कार्यक्रम में उत्पादन बढ़ाने के अधिक बिन्दु हैं जो पहले वाले बीस सूत्री कार्यक्रम में नहीं थे। अतः इनका विचार है कि प्रधानमन्त्री को प्रति वर्ष, परिस्थितियों के अनुसार, एक संशोधित आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए ताकि राज्यों की सरकारों का भी, ध्यान उन नये कार्यक्रमों पर केन्द्रित हो सके। असल में भारत को एक 'रोलिंग प्लान' की जगह एक 'रोलिंग 20-सूत्री कार्यक्रम' की अधिक आवश्यकता है।

अतः यह कहना अनुचित न होगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करना निर्धन लोगों व समस्त देशवासियों के हित में होगा। लेकिन ठीक से लागू न होने पर ये 20 नारे (twenty slogans) मात्र रह सकते हैं।

प्रगति—केन्द्र व राज्यों की वार्षिक योजनाओं में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर काफी धनराशि आवंटित की गई है। 1984-85 के लिए इस कार्यक्रम पर 11,858 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया था। (4141 करोड़ रु. केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत तथा शेष राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत) जो वार्षिक योजना के कुल परिव्यय का लगभग 40% था। 1985-86 की केन्द्रीय योजना में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिए 4,900 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई जो पिछले वर्ष से 18.3% अधिक थी। यह कुल केन्द्रीय योजना की निर्धारित राशि (18,500 करोड़ रु.) का 26.5% थी। 1986-87 की केन्द्रीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम पर लगभग 6000 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई जो पिछले वर्ष की तुलना में एक हजार करोड़ रु. अधिक थी। इससे स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम को वार्षिक योजना में काफी ऊँची प्राथमिकता दी गयी है।

इस कार्यक्रम को लागू करने से कई दिशाओं में प्रगति हुई जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना, आवास-स्थलों (house-sites) की व्यवस्था, अनुसूचित जन जाति के परिवारों का उत्थान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों को लाभ पहुँचाना, पेयजल की व्यवस्था, गन्दी बस्तियों के लोगों की दशा में सुधार, वृक्षारोपण, अनुसूचित जाति के परिवारों का उत्थान, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, ग्रामीण विद्युतीकरण व पम्प सेटों की शक्ति प्रदान करना।

इनके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार-कार्यक्रम की प्रगति हुई है। शेष कार्यक्रमों, जैसे वन्ध्यकरण (sterilisations), उप-केन्द्र स्थापित करने, प्रतिरिक्त भूमि वितरण करने, निर्माण-कार्य में सहायता प्रदान करने, वन्धुआश्रम की मुक्ति व पुनर्वास व इ. डब्ल्यू. एम. मजानों की व्यवस्था करने की प्रगति धीमी रही है।

विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति काफी असमान भी रही है। 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) की प्रगति प्रांत प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय व पश्चिमी बंगाल में 1982-83 की तुलना में नीची रही थी। परिवार-नियोजन व भूमि-वितरण के कार्यक्रमों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही जो एक चिंता का विषय है।

नवीन ग्रथवा तृतीय 20-सूत्री कार्यक्रम, अगस्त 1986¹

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त, 1986) पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा था कि देश के समस्त शीघ्र सशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम पेश किया जायगा। उसी वाक्य के अनुरूप 20 अगस्त, 1986 को प्रधान-कार्यान्वयन मन्त्री ने सदन के दोनों सदनों में यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें निर्धनता-उन्मूलन पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया। इसे बीस-सूत्री कार्यक्रम का तृतीय संस्करण कहा जा सकता है। यह सर्वप्रथम 1975 में तथा दूसरी बार 1980 में पेश किया गया था। इसे सातवीं योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित (restructure) किया गया है।

नये कार्यक्रम के 20 बिन्दु इस प्रकार हैं :

1. ग्रामीण निर्धनता पर प्रहार,
2. वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों के लिए विकास सम्बन्धी नीति,
3. सिंचाई के पानी का बेहतर उपयोग,
4. अधिक भाड़ा में फसलें
5. भूमि-मुधारों को लागू करना,
6. ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम,
7. स्वच्छ पेय-जल,
8. सबके लिए स्वास्थ्य,
9. दो बच्चों के परिवार का नॉर्म,
10. शिक्षा का विस्तार,
11. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ न्याय,
12. स्त्रियों के लिए समानता,
13. युवावर्ग के लिए नये अवसर,
14. लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था,
15. गन्दी बस्तियों की दशा में सुधार,
16. वानिकी के सम्बन्ध में नयी नीति,
17. पर्यावरण की रक्षा,

1. State Bank of India Monthly Review, September, 1986, pp 462-466

18 उपभोक्ता के हितों की रक्षा,

19 गाँवों के लिए ऊर्जा, तथा

20. सवेदनशील प्रशासन (जनता की आकांक्षाओं व आशाओं के प्रति)।

विभिन्न बिन्दुओं पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि इनका सीधा सम्बन्ध देश के सामाजिक-आर्थिक विकास से है। इनको क्रियान्वित करने से खेती की पैदावार बढ़ेगी, गाँवों में गरीबी व बेरोजगारी घटेगी तथा लोगों का सामाजिक जीवन सुधरेगा।

नये बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत आवश्यक स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिये गये हैं जिनका उल्लेख सविस्तार नीचे किया जाता है। इससे प्रत्येक सूत्र पहले के कार्यक्रमों की तुलना में अधिक स्पष्ट व सुनिश्चित कर दिया गया है ताकि उसको प्राप्त करने में कठिनाई न हो तथा उसके मूल्यांकन में भी सुविधा रहे।

प्रत्येक मुख्य बिन्दु के तहत आवश्यक उप-बिन्दु (sub-points) नीचे दिये जाते हैं।

1. ग्रामीण निर्धनता पर प्रहार—(i) इस बात का प्रयास करना कि निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रम प्रत्येक गाँव में सभी गरीबों तक पहुँचे, (ii) मजदूरी रोजगार-कार्यक्रमों को क्षेत्रीय विकास व मानवीय ससाधन विकास कार्यक्रमों से समन्वित करना तथा राष्ट्रीय व सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना जैसे स्कूल के मरत सड़के, तालाब तथा ई घन व चारे के भण्डार, (iii) उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना व ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करना, (iv) हथकरघा, दस्तकारी, ग्रामीण व लघु उद्योगों को पनपाना तथा स्वरोजगार के लिए दक्षताओं (skills) में सुधार करना, एवं (v) पचायत, सहकारिताओं व स्थानीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करना।

2. वर्षा पर आश्रित खेती के लिए विकास सम्बन्धी नीति—(i) नमी की रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में सुधार करना तथा भूमि व जल-साधनों का बेहतर प्रबन्ध करना (ii) उचित व सुधरे हुए बीजों का विकास व वितरण, (iii) सूखा प्रभावित क्षेत्रों व सूखा सहायता कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करके सूखे के कुप्रभावों को कम करना।

3. सिंचाई के जल का बेहतर उपयोग—(i) जल-संग्रह क्षेत्रों (catchment areas) का विकास व डेल्टा क्षेत्रों में जल-निकासी (drainage) की व्यवस्था को सुधारना, (ii) कमान्ड क्षेत्रों में सिंचाई-प्रबन्ध में सुधार करना, (iii) पानी के जमाव, लारपन व पानी के व्यर्थ उपयोग को रोकना, (iv) सतह व भूतल जल के उपयोग में तालमेल बँडाना।

4. अधिक मात्रा में फसलें—(i) देश के पूर्वी भागों व अन्य कम उपज वाले क्षेत्रों में चावल के उत्पादन में क्रान्ति लाना, (ii) खाद्य-तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, (iii) दालों का उत्पादन बढ़ाना, (iv) फल व सब्जियों की खेती को बढ़ाना, (v) कृषि-उपज के आधुनिक संग्रह, प्रोसेसिंग व बिक्री की सुविधाओं को बढ़ाना,

(vi) पशु-पालकों को उत्पादकता बढ़ाने में सहायता देना, तथा (vii) मछली पालन व सामुद्रिक मछली उद्योग का विकास करना ।

5. भूमि-सुधारों को लागू करना—(i) भूमि-रिफॉर्म पूर्ण तरह से लागू करना, (ii) भूमि पर सीमित सम्बन्धी कानूनों को लागू करना, तथा (iii) अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना ।

6. सामोए धर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम—(i) कृषि व उद्योग में समर्पित धर्म के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून को लागू करना, (ii) वधुधर्म धर्म की प्रथा को समाप्त करने के कानूनों को पूरी तरह लागू करना, (iii) वधुधर्म धर्म को फिर से बनाने के कार्यक्रमों में ऐच्छिक एजेंसियों व मण्डलों की मदद लेना ।

7. स्वच्छ पेय जल—(i) सभी गांवों में स्वच्छ व सुरक्षित जल की सुविधा पहुंचाना, (ii) स्थानीय समुदायों को जल-पूर्ति के स्रोतों को अच्छी हानन में बनाने रखने में मदद पहुंचाना तथा (iii) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए जल-पूर्ति पर विशेष रूप से ध्यान देना ।

8. सबके लिए स्वास्थ्य—(i) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की गुरुवर्ण (quality) में सुधार करना, (ii) कोड, टी, बी., मलेरिया, मलेरिया के रोग, अर्धचन्द्र व अन्य बड़े रोगों में संघर्ष करना, (iii) मनसु जिम्मेदारों व बच्चों को रोगों में मुक्ति दिशाने के उपाय करना, (iv) सामोए क्षेत्रों में स्वास्थ्य व सफाई की सुविधाएं बढ़ाना, विशेषकर ग्रामों के लिए, तथा (v) असाहिबों के पुनर्वासन के लिए कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना ।

9. दो बच्चों के परिवार का निर्माण—(i) स्वेच्छा से दो बच्चों का निर्माण स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, (ii) माता-पिताओं में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व का भावना बढ़ाना, (iii) शिक्षा न्यून-दर घटाना, तथा (iv) मातृत्व व शिक्षा-देखभाल की सुविधाओं का विस्तार करना ।

10. शिक्षा का विस्तार—(i) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, (ii) मनी स्तरों पर शिक्षा में सुधार लाना (iii) पैर-प्रोत्साहित शिक्षा व फ़ंक्शनल (functional) साक्षरता कार्यक्रम को प्रोत्साहित देना तथा साथ में दक्षता में वृद्धि करना, (iv) प्रौढ़-साक्षरता-कार्यक्रम का बढ़ावा देना जिसमें छात्र व ऐच्छिक नम्बारे शामिल हैं, तथा (v) राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक व नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना ताकि हमारी राष्ट्रीय संरचना में योग्य महत्त्व देना योग्य ।

11. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ साथ—(i) इनके लिए बने नवोद्घातक प्रावधानों व कानूनों को लागू करना, (ii) इनके लिए आवश्यक भूमि पर इनकी कक्षा दिखाना, (iii) भूमि-आवृत्त कार्यक्रम में नया जीवन आना,

(iv) शैक्षणिक स्तरों में सुधार के लिए विशेष बोर्डिंग प्रोग्राम करना, (v) मेहतरों के गन्दे काम की समाप्ति करना तथा सफाई कर्मचारियों की पुनर्स्थापना के लिए विशेष कार्यक्रम मंचालित करना, (vi) विशेष कम्पोनेण्ट कार्यक्रम के लिए पर्याप्त कोषों व उचित निर्देशन की व्यवस्था करना, (vii) इस वर्ग को शेष समाज के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चलाना, तथा (viii) उन जन्म-जातियों को फिर से बसाना जो अपने निवास-स्थलों से उखड़ गये हैं।

12. स्त्रियों के लिए असमानता—(i) समाज में स्त्रियों के स्थान को ऊँचा करना, (ii) स्त्रियों की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना (iii) स्त्रियों के अधिकारों के बारे में ग्राम चेतना जागृत करना, (iv) स्त्रियों के प्रशिक्षण व रोजगार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना (v) स्त्रियों को सामाजिक-आर्थिक विकास व राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में समानतापूर्वक भाग लेने में सक्षम करना तथा (vi) दहेज-प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करना तथा दहेज-विरोधी कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की व्यवस्था करना।

13. युवावर्ग के लिए नये अवसर—(i) खेल व सांस्कृतिक क्रियाओं आदि में युवावर्ग के लिए अवसर बढ़ाना (ii) शारीरिक क्षमता का विकास करना (iii) युवावर्ग को राष्ट्रीय विकास की परियोजनाओं में शामिल करना जैसे गंगा की सफाई, पर्यावरण-सुरक्षा व विकास तथा ग्राम जनता की शिक्षा के कार्य आदि (iv) प्रतिभाशाली युवा-व्यक्तियों को छाटना व उनकी योग्यता के विकास को प्रोत्साहन देना, (v) राष्ट्रीय एवम्, सांस्कृतिक मूल्यों धर्म-निरपेक्षता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में युवावर्ग को शामिल करना, (vi) नेहरू युवा केन्द्रों के जाल का विस्तार करना, (vi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम व एन सी सी को सुदृढ़ करना, तथा (viii) ग्रामीण युवावर्ग के कल्याण के लिए काम करने वाली ऐच्छिक एजेंसियों को बढ़ावा देना।

14. लोगों के लिए मकान की व्यवस्था—(i) ग्रामीण निर्धनों के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था करना, (ii) भवन-निर्माण के कार्यक्रमों का विस्तार करना, तथा (iii) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भवन-निर्माण पर विशेष बल देना।

15. गन्दी बस्तियों की दशा में सुधार—(i) गन्दी बस्तियों की वृद्धि को रोकना, (ii) वर्तमान गन्दी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना, तथा (iii) शहरी क्षेत्रों में नियोजित आवास-निर्माण को प्रोत्साहन देना।

16. चानिकी (forestry) या वन लगाने के सम्बन्ध में नयी नीति (i) लोगों को शामिल करके अधिक पेड़ लगाना तथा वनों का विकास करना, (ii) जनजाति के लोगों व स्थानीय समुदायों के तकड़ी व वन-उपजों पर परम्परागत अधिकारों की रक्षा करना, (iii) व्यर्थ भूमि (wastelands) का उत्पादक उपयोग

करना, तथा (iv) पहाड़ी रेगिस्तानी व तटीय क्षेत्रों में उचित किस्म की वनस्पति उगाना ।

17 पर्यावरण की रक्षा—(i) लोगों को पर्यावरण में गिरावट के खतरों के प्रति जागरूक करना, (ii) पर्यावरण-रक्षा के लिए घाम समर्थन विकसित करना, (iii) इस बात को पहचानना कि स्थायी विकास के लिए परिवेश (ecology) को रक्षा करना बहुत जरूरी होता है, तथा (iv) परियोजनाओं के लिए स्थान का दुर्द्विमानपूर्वक चुनाव करना तथा टेक्नोलॉजी का भी सही ढंग से चुनाव करना ।

18. उपयोग के हितों की रक्षा—(i) घाम उपयोग की वस्तुओं को गरीबों को पहुँच तक लाना (ii) उपभोक्ता-हित-रक्षा ग्राम्योत्थान का निर्माण करना, (iii) विनरण-व्यवस्था को पुनर्गठित करना ताकि सन्निधी की राशि सर्वाधिक जरूरतमन्द व्यक्तियों तक पहुँच सके एवं (iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना ।

19 गाँव के लिए ऊर्जा—(i) गाँवों में उत्पादन कार्यों व उपयोगों में विद्युत सप्लाई का विस्तार करना, (ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे बायो गैस का विकास करना, तथा (iii) ग्रामीण ऊर्जा के लिए एकीकृत क्षेत्र-विशिष्ट प्रोग्रामों को प्रामाण्य देना ।

20 सवेदनशील व प्रभावी प्रशासन—(जनता की आकांक्षाओं व प्रशासनों के प्रति)—(i) विधियों को सरल बनाना, (ii) अधिकार सीधना, (iii) लेखादेयता लागू करना (iv) खण्ड से राष्ट्रीय स्तर तक मोनिटरिंग प्रणालियों का विकास करना, (v) सार्वजनिक शिकायतों को शीघ्रतापूर्वक व सहानुभूतिपूर्वक दूर करना ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नये 20-सूची कार्यक्रम में कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने ग्रामीण निर्वहन को कम करने, लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल की सुविधाएँ बढ़ाने, पर्यावरण की रक्षा करने एवं प्रशासन को अधिक सज्जिम, सवेदनशील व खुल बनाने पर अधिक जोर दिया गया है । प्रत्येक मुख्य बिन्दु के तहत कुछ उप-बिन्दु निश्चित किये गये हैं जो कुल मिलाकर लगभग 90 हो जाते हैं । इस प्रकार विभिन्न बिन्दुओं को क्रियान्वित करके लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जायगा । राज्य सरकारों को 20-सूची कार्यक्रम को लागू करने में पूरा सहयोग देने के लिए कहा गया है ताकि इसको सफल बनाया जा सके ।

नवीन अथवा तृतीय बीस-सूची कार्यक्रम की आलोचना

भारत में बीस-सूची कार्यक्रम का मिलसिला 1975 से प्रारम्भ हुआ था जो अगस्त 1986 के नये 20 सूची की घोषणा से तीसरे दौर में प्रवेश कर गया है । कुछ विद्वान तो शुरू से ही इस कार्यक्रम के आलोचक रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं के होते इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

इसरी मतासूत्र पार्टी के लिए 'राजनीतिक आवश्यकता' भले ही हो, अन्यथा योजनाओं के उद्देश्यों व कार्यक्रमों के रहते अलग से बीस या इससे अधिक प्रयत्न कम विन्दुओं को राष्ट्र के समक्ष रखने का क्या मतलब ? इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्तियों का मानना है कि बीस-मूत्रों की वजह से मूल पंचवर्षीय योजना पर से ध्यान कम हो जाता है, और ये विन्दु ही विशेषतया राज्य सरकारों के लिए, प्रमुख बन जाते हैं।

इस आलोचना के उत्तर में सरकारी दोषों में यह कहा गया है कि बीस-मूत्रों व प्राथमिक नियोजन में कोई परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि बीस-मूत्रों की 'योजना का हृदय' कहा जा सकता है। इनमें एक समय विशेष में देश की प्रमुख बीस समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, तथा उनको हल करने की दिशाएँ व कार्यक्रमों की रूपरेखा दी जाती है। आगे चलकर प्राप्त अनुभवों व नयी समस्याओं के आधार पर इनमें आवश्यक फेर-बदल किये जाते हैं और राष्ट्र का ध्यान पुनः नये 20 विन्दुओं पर केन्द्रित किया जाता है। इस प्रकार सरकार ने 'रोलिंग प्लान' का विचार तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन रोलिंग 20-विन्दु का विचार जन्म-मनजाने में अवश्य मान लिया है।

अतः बीस-मूत्री कार्यक्रम में अस्तुत कोई गम्भीर आपत्तिजनक बात नहीं प्रतीत होती। एक नजर इन विन्दुओं पर डालें तो पता लगेगा कि सरकार वाकई वर्तमान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग व जागरूक है और वह कृपित उत्पादन में वृद्धि करने, विशेषतया चावल, तिलहन व दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चिंतित है व इसके लिए प्रयत्नशील भी है। साथ में यह स्त्रियों व युवावर्ग की समस्याओं के प्रति भी सचेष्ट है। लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल की समस्याओं को हल करना चाहती है। ग्रामीण बेरोजगारी, निर्धनता, भूमि-सुधार, परिवार-नियोजन, रिहायशी मकान, गन्दी बस्तियों, मट्टघाट, पर्यावरण-रक्षा व ऊर्जा तथा प्रशासनिक समस्याओं के हल की दिशा में भी कारगर सफलता प्राप्त करने की आतुर है। ऐसा वह चाहे अपनी 'राजनीतिक छवि को सुधारने के लिए, करें प्रमत्त देश की 'सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के लिए' करें—इससे आम जनता के लिए विशेष अन्तर पड़ने वाला नहीं। क्योंकि मूल प्रश्न तो यह है कि इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कारगर प्रगति होनी चाहिए और गरीबों व ज़रूरतमन्द लोगों को किसी न किसी तरह राहत व मदद मिलनी चाहिए। अतः प्रमुख प्रश्न विभिन्न समस्याओं को हल करने की दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों व प्राप्त परिणामों का माना जाना चाहिए। इस दृष्टि से कार्यक्रम की समीक्षा आगे दी जाती है :

क्या इस नवीन बीस सूत्री कार्यक्रम में बीस बिन्दुओं का चयन बिल्कुल सही है ?

नितहास यह भी मान लें कि 20-सूत्र ही मर्यादित दृष्टि में 'साधन-सूत्र' होने हैं, तो पहला प्रश्न यह उठता है कि नये कार्यक्रम में शामिल बीस सूत्र ही सर्व-श्रेष्ठ हैं, अथवा इनसे भी कोई बेहतर चयन हो सकता था। इन सम्बन्ध में बाटा मनोद होन को पुष्टाई प्रदत्त है, क्योंकि किसी को नजर में कोई बिन्दु ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी को नजर में कोई अन्य बिन्दु विद्यमान महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, श्री बचराज मेहता का मत है कि नये कार्यक्रम में धनिकों के हितों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, और उद्योगों में धन की मार्ग-द्वारों के बारे में कोई जोर नहीं दिया गया है। इन प्रकार तथा कर्तव्य धर्मोन्मुखी (labour-oriented) नहीं है।¹ इस प्रावधान का उत्तर यह है कि चाहे इन मद को नये कार्यक्रम में स्थान न दिया गया हो, लेकिन योजना में सरकार की धन-नीति में उनकी अवस्था स्थान दिया गया है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि सरकार धन की प्रवृत्ति में मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहती है। विद्यमान वनों में कुछ मार्गदर्शक प्रवृत्तियों में हम सम्बन्ध में प्रयोग नो किन्तु यह है तथा नवित्व में उनकी प्राप्ति बढ़ाया जायगा वह इन मद की बीस सूत्रों में शामिल न किया गया हो।

हमारी मूल कठिनाई है किसानवर्ग की विकसनता

अपने बात यह है कि पंचवर्षीय योजना व बीस-सूत्री धार्मिक कार्यक्रम के अवरोध व्यवहार में विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति सन्तोषजनक नहीं है। जंगल क्षेत्र भी धूमि सम्बन्धी रिफाई पूरी तरह तैयार करने की बात कहो जा रही है तथा मौजिम के कानून क्रियावित नहीं हुआ पाव है। अनिरुद्ध भूमि का भूमिहीनों में आवंटन ठीक से नहीं हो पाया है। बंजुरा सब्सिडी को फिर से बढ़ाने की सम्मति आज भी विद्यमान है। इनके हितों की रक्षा के लिए धार्मिकों को सजा देने का प्रश्न है, प्राप्ति। जनाना क हितों की रक्षा की बात को जना है, फिर भी धार्मिक भारतीय जनताका मूल-सूचनक जन 1959 में 838 पर पहुँच गया है। यह एक प्रवृत्ति है जिसमें उपनोक्त के लिए मुद्रा की कम शक्ति का भारी हाथ हा रहा है और सरकार पर सहोदारी की अनिरुद्ध किन्ते देने की मंत्री नहीं हुई है। इनका आसार वर्ष 1960 तक से हम कह सकते हैं कि 29 वर्षों में रुपये का मूल्य घट कर 12 पैसे मात्र रह गया है। अतः मुद्रास्फीति की समस्या सुदृढ़ हो गयी है। कृषि मार्गदर्शक विवरण प्रणाली इसका पूर्ण समाधान नहीं दे सकती, हमारा इनका अपना मौजिम मोरदान अवश्य होता है।

1. वरदास मेहता, नया बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए कमजोर, राजस्थान पत्रिका, मधु-सक, 5 फ़रवरी, 1986।

इस प्रकार गाँवों में गरीबी दूर करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने के दम्बन में कई खामियाँ पायी गयी हैं जिससे गरीबों तक पूरी सरकारी मदद नहीं पहुँच पायी है। गरीबों की बजाय गैर-गरीब लोग (non-poor people) में भी सरकारी सहायता का लाभ उठा लिया है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस नये बीस-सूत्री कार्यक्रम को अधिक जोश-खरोश के साथ लागू किया जाय और इसको अधिक कामयाब बनाया जाय। मिश्रित अर्थव्यवस्था व लोकतान्त्रिक नियोजन में हमारे सामने कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं जो अधिनायकशाही तन्त्र में सम्भवतया नहीं आती। अतः आगामी वर्षों में 20 बिन्दुओं को प्राप्त करने की दिशा में अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन उद्योगपति, व्यापारी, श्रमिक, ग्राम जनता, युवावर्ग, स्त्रियो आदि सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। बीस सूत्री कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना का स्थानापन्न नहीं है, और न यह हमारी समस्याओं का कोई रामबाण इलाज है। हममें देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रमुख समस्याओं का ध्यान करके उनके समाधान पर विशेष बल देने की बात कही गयी है, जो अपने आप में कोई अनुचित नहीं है। राज्य सरकारों का ध्यान विशेष रूप से नये कार्यक्रम पर केन्द्रित किया जा रहा है ताकि वे योजनाओं के जाल-जपजाल व भूल-भुलैया में न खोकर कुछ प्रमुख मुद्दों को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दें। इसी दृष्टि से इन नये बीस बिन्दुओं की उपादेयता व सार्थकता देखी जानी चाहिए। इन योजनाओं का हृदय व सारास माना जाना चाहिए, उसका स्थानापन्न नहीं। इसके अलावा नये कार्यक्रम के बिन्दुओं को केन्द्र-बिन्दु ही माना जाना चाहिए। देश की विशालता व अनेक समस्याओं को देखते हुए 20 बने 120 बिन्दु भी दिये जा सकते हैं। वैसे भी बीस बिन्दुओं के नीचे लगभग 90 उप-बिन्दु तो दिये ही गये हैं, जिनमें से प्रत्येक को क्रियान्वित करने से ही मुख्य बीस बिन्दुओं को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक प्रगति हो सकेगी। अतः बीस बिन्दुओं की ब्यूह-रचना या रणनीति (strategy of 20 points) भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे 'एतरजिक' होने की आवश्यकता नहीं। इसका विरोध करने की हठधर्मी नहीं की जानी चाहिए।

प्रश्न

1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
(1) अगस्त 1986 का 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम।
2. 'बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम आर्थिक नियोजन में साधक नहीं बाधक है।' समीक्षा कीजिए।
3. आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में आप भारत में सर्वाधिक जनहित में किन 20 बिन्दुओं पर जोर देना चाहेंगे। सुझाव दीजिए।

सकेत—(i) साफ पेयजल की सप्लाई, (ii) चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा, (iii) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, (iv) उत्पादक रोजगार देना (v) परिवार नियोजन में एक बच्चे के नॉर्म⁹ पर बल, (vi) सहकारी संस्थाओं को सबल बनाना (vii) स्थानीय साधनों का उपयोग करके उद्योगों का शीघ्र व पर्याप्त विस्तार करना, (viii) ई घन की सप्लाई बढ़ाना, (ix) निर्माण-कार्य (Construction activity) के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र दूर करना, (x) स्थानीय संस्थाओं को जनता की कठिनाइयों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाना, (xi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यकुशल बनाना, (xii) प्रत्येक स्तर पर प्रशासन को सुरत करना व कठोर बनाना ताकि वह परिणामोन्मुख बन सके, (xiii) समाज कटकों को शीघ्र व कड़ी सजा देने का प्रावधान (xiv) कार्यकुशलता के लिए पुरस्कार व अकार्यकुशलता के लिए सजा, (xv) ग्राम जनता के काम की वस्तुओं के उत्पादन पर जोर, (xvi) श्रमिकों की दक्षता-वृद्धि के कार्यक्रमों पर जोर ताकि उनकी ग्रामदत्ती बढ़े (xvii) अनुत्पादक व्यय में कटौती (प्रत्येक स्तर पर) (xviii) मुद्रा की पूर्ति में नियोजित वृद्धि (विशेषतया वास्तविक आय में वृद्धि के अनुरूप), (xix) गांव व शहर में सफाई की नई व्यवस्था ताकि गवनी दूर करने में प्रत्येक नागरिक का सहयोग (xx) प्रत्येक स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए खुली बैठक व लोक-तांत्रिक चिन्तन व चर्चा का विस्तार । इन सुझावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90

तथा सरकार की नयी आर्थिक नीति

(Seventh Five Year Plan 1985-90 and New Economic Policy of the Government)

योजना आयोग ने सातवी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण प्रपत्र (Approach Paper) जुलाई 1985 में प्रकाशित किया था। बाद में अक्टूबर 1985 में योजना का प्रारूप दो खण्डों में प्रकाशित किया गया। खण्ड I में योजना के परिप्रेक्ष्य उद्देश्यों, व्यूहरचना, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चलराशियों की मात्राओं अथवा राष्ट्रीय व समष्टिगत-आयामों (macro-dimensions) व साधनों की चर्चा की गई एवं खण्ड II में विकास के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया। खण्ड I के प्रावधान में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी तथा उसकी भूमिका में योजना प्रयोग के उपाध्यक्ष ने सातवी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये थे।

यहाँ पर सातवी योजना के विभिन्न पहलुओं व प्रगति का उल्लेख किया जायगा। अध्याय के अन्तिम भाग में सरकार की नयी आर्थिक नीति (New Economic Policy) का भी विश्लेषण किया जायगा।

उद्देश्य (Objectives)

सातवी योजना के दृष्टिकोण-प्रपत्र में इसके उद्देश्य स्पष्ट किये गये थे। भोजन, काम व उत्पादकता (food, work and productivity) इसके तीन मुख्य बिन्दु निर्धारित किये गये थे। योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के सवसर बढ़ाने व उत्पादकता में वृद्धि करने पर जोर दिया गया, क्योंकि विकास की वर्तमान स्थिति में इन अल्पकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करके ही दीर्घकालीन लक्ष्यों की तरफ बढ़ाना सम्भव हो सकता था।

योजना में कहा गया कि लोगों को उत्पादक रोजगार देने से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे तथा आत्म-विश्वास व आत्म-सम्मान से वाम कर पायेंगे। योजना में गैर-स्फीतिकारी वृद्धि तभी हो सकती है जब कृषिगत उत्पादन, विनोप-तया खाद्यान्नों का उत्पादन, तेजी से बढ़ाया जाय। इसके लिए कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में तथा चावल, मोट अनाज, तिलहन व दालों जैसी फसलों में उत्पादकता बढ़ानी होगी। औद्योगिक विकास की दर ऊँची रखने के लिए प्राथमिक व टेक्नोलॉजी को उन्नत करने पर जोर दिया गया। विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पावर, कोयला, परिवहन तथा संचार आदि में विनियोगों से पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त करने पर जोर दिया गया।

सातवीं योजना में विकास की व्यूहरचना या रणनीति (Strategy of Development in the Seventh Plan)

सातवीं योजना की व्यूहरचना में निम्न बातों पर ध्यान आकर्षित किया गया—

1. उत्पादक रोजगार—सातवीं योजना की विकास-नीति में प्रमुख तत्व उत्पादक रोजगार का सृजन करना रखा गया। इसके लिए फसल गहनता (Cropping intensity) में वृद्धि करने का महत्व स्वीकार किया गया जो मिर्चाई की सुविधाओं के विकास, कृषि में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, (विनोपतया कम उपज वाले क्षेत्रों व लघु कृषकों के लिए) करने से सम्भव होगी तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना एवं सड़क, मकान आदि का निर्माण करने में श्रम-गहन विधियों का उपयोग करने से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। नियोजकों का विचार था कि इससे निर्धनता का दबाव कम होगा और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

2. ग्राम उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि—निर्धन-वर्ग के पास श्रम-शक्ति बटन से उपयोग-पदार्थों की मांग बढ़ेगी। इसलिए मुद्रास्फीति से बचन के लिए खाद्यान्नों खाद्य-तेलों बीनी, वस्त्र ईंधन व मकान आदि की सुविधाओं का विस्तार करने पर बल दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इनकी खरीद बफर स्टॉक बनाने व सार्वजनिक वितरण की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता भी स्वीकार की गयी।

3. पूँजी का अधिक कार्यकुशल उपयोग करना—भारत में भूतकाल में विनियोग विनियोगों से उचित प्रतिफल प्राप्त निये जाने चाहिए। पूँजी का अधिक कार्यकुशल उपयोग करने से ही विकास की दर ऊँची की जा सकती है। इसके लिए मिर्चाई विशुद्ध, परिवहन व उद्योग में समुचित का अधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया। नई क्षमता का विकास करने के स्थान पर वर्तमान क्षमता के बेहतर उपयोग पर अधिक ध्यान देने का महत्व सर्वोपरि माना गया।

4 निर्यात-संबद्ध न पर बल—विदेशी भुगतानों की कठिनाई पर काबू पाने के लिए निर्यातों को बढ़ाने के सुझाव दिये गये। इसके लिए लागत कम करने, किस्म सुधारन तथा उत्पादन का कार्यवृत्त पंमाना घटाने पर जोर दिया गया।

5 मानवीय साधनों के विकास पर जोर—सातवी योजना में शिक्षा को विकास की जरूरतों से जोड़ने, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्त्रियों व अन्य पिछड़े लोगों को विकास की प्रक्रिया में साझेदार बनाने की नीति अपनायी गयी।

6 औद्योगिक विकास की दर को ऊँचा करने के लिए लघु उद्योगों की टेक्नोलोजी को सुधारने पर बल दिया गया। विज्ञान व टेक्नोलोजी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाने के कार्यक्रम चालू किये गये।

7 विविध—सातवी योजना में हरित क्रांति का विस्तार देश के पूर्वी भागों में चावल की उत्पादकता बढ़ाने व तिलहन व दालों की पैदावार बढ़ाने व सूखी खेती तथा वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे गये। पर्यावरण की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने योजना के विवेकीकरण व नियोजन के प्रशासन में ऐच्छिक एजेंसियों का सहयोग लेने तथा पेयजल की सुविधा बढ़ाने, व-धुआ श्रम की मुक्ति व पुनर्वास ग्रामीण विकास व निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाने पर बल दिया गया। इस प्रकार सातवी योजना में निर्धनता बेरोजगारी व प्रादेशिक असंतुलनों को दूर करने पर अधिक जोर दिया गया।

विकास की दर तथा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित परिरूप का आवंटन
(Growth Rate and Allocation of Proposed Public Sector Outlay)

सातवी योजना में विकास की वांछित दर का लक्ष्य 5% रखा गया। यह पिछले दशक (1973-74 से 1984-85 तक) में प्राप्त विकास की औसत दर के अनुरूप है। लेकिन हमें यह स्मरण रखना होगा कि सातवी योजना का आधार-वर्ष (1984-85) एक सामान्य वर्ष रहा था, जबकि छठी योजना का आधार-वर्ष (1979-80) सामान्य से नीचा था। इसलिए सातवी योजना में विकास की दर के लक्ष्य को प्राप्त करना अपेक्षाकृत अधिक कठिन माना गया।

योजना में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दर के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये—

सबल उत्पत्ति के मूल्य के आधार पर
(on the basis of value of gross output)
(प्रतिशत में)

कृषि	4
विनिर्माण (manufacturing)	8
विद्युत, गैस व जल-शक्ति	12
परिवहन सेवाएँ	8

इस प्रकार सातवीं योजना में उद्योग व इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति को तेज करने पर जोर दिया गया। यह धारणा की गई कि योजना के अन्त तक कृषि, उद्योग व सेवा-क्षेत्रों में प्रत्येक का अंश राष्ट्रीय भाग्य में 1/3 हो जायगा।

सातवीं योजना में कुल विनियोग का लक्ष्य 3,22,366 करोड़ रु रखा गया जिसके 94% की व्यवस्था घरेलू स्रोतों से की जायेगी। कुल विनियोग में सार्वजनिक विनियोग का अंश 48% तथा निजी विनियोग का 52% अंश रखा गया। योजना-काल में बचत की दर के 23.3% से बढ़कर 24.5% तथा विनियोग की दर के 24.5% से बढ़कर 25.9% होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि (जिसमें चालू विकास व्यय भी शामिल है) 1,80,000 करोड़ रु निर्धारित की गई। इसमें विनियोग का अंश 1,54,218 करोड़ रु. तथा चालू व्यय 25,782 करोड़ रुपये रखा गया।

प्रस्तावित योजना परिव्यय में केन्द्र का हिस्सा 95,534 करोड़ रु., राज्यों का 80,698 करोड़ रु. तथा मधीय क्षेत्रों का 3,768 करोड़ रु रखा गया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित परिव्यय में केन्द्र का अंश राज्यों व मधीय प्रदेशों के मिले जुले अंश से अधिक रखा गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का विकास की विभिन्न मनों पर धावटन
(निकटतम)

विकास के शीर्षक	(करोड़ रु.)	प्रतिशत
(I) कृषि	10,574	5.9
(II) ग्रामीण विकास	9,074	5.0
(III) विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	3,145	1.8
(IV) सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण	16,979	9.4
(V) ऊर्जा	54,821	30.4
(VI) उद्योग व सनन	22,461	12.5
(VII) परिवहन	22,971	12.8
(VIII) संचार, सूचना व प्रसारण	6,472	3.6
(IX) विज्ञान व टेक्नोलोजी	2,466	1.4
(X) सामाजिक सेवाएँ	29,350	16.3
(XI) अन्य	1,687	0.9

कुल योग (लगभग) 1,80,000 100.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक घावटन ऊर्जा के पक्ष में (30.4%) किया गया है। कृषि, ग्रामीण विकास विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम व विचारों को मिलाकर (I से IV तक) लगभग 22% तथा सामाजिक सेवाओं पर 16.3% घावटन किया गया है। उद्योग तथा परिवहन में से प्रदेश के लिए प्रस्तावित व्यय का 1/8 भग्न रखा गया है। इस प्रकार सातवीं योजना की प्राथमिकताओं में ऊर्जा, कृषि व ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मानवीय समाधानों के विकास को समुचित व्यय दिया जाने पर अग्रिम बल दिया गया।

सार्वजनिक विनियोग के निगारों में नई शमना के विकास से ज्यादा ध्यान जानु क्षमता के रख-रखाव व प्रागुनिकीकरण पर दिया गया ताकि उद्योग में ग्रीन वृद्धि की जा सके। लेकिन यह ज़ेमे-जेंगे योजना प्राग वृद्धि ज़ेमे-जेंगे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार विनियोगों में आवश्यक फेर-बदल किया जायगा। सम्भव है पावर, कोयले व रेलवे में विनियोग नई परिवारायनों में प्रागे बनकर घोर बढ़ाने पड़े।

सातवीं योजना में कुल प्रस्तावित विनियोग की राशि (3,22,366 करोड़ र.) का घावटन इस प्रकार किया गया कृषि, विचारों व महामक क्रियाओं का भग्न 19.1%, खनन व विनिर्माण का 32.5%, विद्युत, परिवहन व संचार का 24.2% तथा सेवाओं का 24.2% रखा गया।

1984-85 के भावों पर आयनों में वार्षिक वृद्धि दर 5.8% तथा निर्माणों में 6.8% निर्धारित की गई। अग्रिम गवों की प्राप्तिमें सहित सातवीं योजना में जानु खाने में 20 हजार करोड़ र. का घाटा रहने का अनुमान लगाया गया जिसकी पूर्ति के लिए विदेशों से सहायता व ऋण लेने की आवश्यकता स्वीकार की गयी। सातवीं योजना में निर्णयना व बेरोजगारी का प्रभाव—

1. निर्णयना पर प्रभाव (Impact on Poverty)—योजना आयोग ने सातवीं योजना की अवधि में निर्णयना-उन्मुचन के सम्बन्ध में निम्न मध्य रये—

वर्ष	निर्णयना-अनुपात (प्रतिशत में)			निर्णयनों की संख्या (हज़ारों में)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1984-85	39.9	27.7	36.9	22.2	5.1	27.3
1989-90	28.2	19.3	25.8	16.9	4.2	21.1

सूखे क्षेत्रों से प्राप्त किया जायगा। देश के पूर्वी व दक्षिणी भागों के चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

प्रमुख फसलों में उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये—

1984-85 (वास्तविक स्तर)	1989-90 (लक्ष्य)
(1) समस्त खाद्यान्न (मि. टन) 150	178-183
(2) तिलहन (") 13	18
(3) गन्ना (") 180	217
(4) कपास (मि गांठे) (प्रत्येक 170 किलो) 7.5	9.5
(5) जूट व मेहटा (मि गांठे) (प्रत्येक 180 किलो) 1.5	9.5

इस प्रकार खाद्यान्नों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर $3\frac{1}{2}$ से 4% रखी गयी। योजना में सकल कृषित क्षेत्रफल 18 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ाकर 19 करोड़ हेक्टेयर करने तथा 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में प्रतिरिक्त सिंचाई का विस्तार करने पर जोर दिया गया। उर्वरकों का उपयोग 84 लाख टन से बढ़कर 1.35 करोड़ टन से 1.4 करोड़ टन के बीच हो जायगा। देश के पूर्वी भाग में चावल का उत्पादन बढ़ाने व सूखी ज़मीनें के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। तिलहन व दालों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया ताकि योजना के अन्त में चावल के मामले में सिंचाई होने लग जाय जिससे चावल का उत्पादन 6 करोड़ टन से बढ़कर 7.5 करोड़ टन हो सके तथा गेहूँ के 80% से अधिक भाग पर सिंचाई होने लग जाए।

(ii) उद्योग—सातवीं योजना में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 8% रखी गयी। खनन व विनिर्माण के लिए यह 8.3% निर्धारित की गयी। योजना में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विनाश, आधुनिकीकरण, टेक्नोलोजी के उत्थान, उत्पादकता में सुधार, लागत में कमी, नई वस्तुओं के समावेश व नुनो हुये उद्योगों में तीव्र विकास पर जोर दिया गया।

औद्योगिक विकास की वार्षिक दर को बढ़ाने के लिए औद्योगिक, विदेशी व्यापार व राजकोषीय नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किये गये। इनको अधिक उदार बनाया गया तथा अनावश्यक नियन्त्रण कम किये गये। पावर के विकास की वार्षिक दर 12.6% करने का लक्ष्य रखा गया। जबकि छठी योजना की उपलब्धि 7.8% वार्षिक रही थी।

चुने हुए उद्योगों में उत्पादन के लक्ष्य

उद्योग का नाम	1984-85	1989-90
(1) कोयला (मिलियन टन)	147.4	226
(2) कूड तेल („ „)	29	34.5
(3) चीनी („ „)	6.2	10.2
(4) वस्त्र (मिश्र व विकेन्द्रित) (घरब मीटर)	12	14.5
(5) नाइट्रोजन-उर्वरक (मि. टन)	3.9	6.6
(6) सीमेंट („ „)	30	49
(7) इस्पात (मुख्य + मिनी) („ „)	8.8	12.65
(8) विद्युत-सृजन (घरब किलोवाट घण्टे)	167	295.4
(9) इलेक्ट्रॉनिक्स (करोड़ रु.)	2,090	10,860

इस प्रकार विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं में उत्पादन के ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किये गये। सातवी योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन-भूतल को 5 गुना करने का लक्ष्य काफी आकर्षक माना जा सकता है। कूड तेल का उत्पादन 2.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 3.4 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया। सातवी योजना में हर सम्भव उपाय से औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक दर को ऊँचा करने पर जोर दिया गया।

(iii) इन्फ्रास्ट्रक्चर—योजना में पावर सप्लाई व परिवहन के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने पर जोर दिया गया ताकि कृषि व उद्योगों का विकास अधिक तेजी से हो सके। विद्युत के विकास की वार्षिक दर 12.2% रखी गई ताकि 1989-90 तक 22,245 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जा सके। रेल्वे द्वारा माल ढोने की क्षमता को 26.3 करोड़ टन से बढ़ाकर 34 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया। बड़े बन्दरगाह योजना के अन्त में 14.7 करोड़ टन माल ढोने लगेंगे जो 1984-85 में 10.7 करोड़ टन माल ढोने की स्थिति में थे। एयर इण्डिया के यात्री ट्रैफिक में 4% वार्षिक की वृद्धि तथा इण्डिया एयरलाइन्स के लिए 8% प्राप्ति भी।

(iv) शिक्षा, स्वास्थ्य, जल-भूति आदि—यह कहा गया कि 1989-90 तक 6-14 वर्ष की आयु के 92% लोग प्रारम्भिक शिक्षा पाने लगेंगे। शिक्षा में व्यवसायीकरण पर बल दिया गया। मोडल स्कूलों की स्थापना करने तथा उच्च शिक्षा व टेक्नीकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा बढ़ाने तथा योजना के अन्त तक 42% दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन के सुरक्षात्मक उपाय काम में लेने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। 1981-91 के दशक

देश की सम्पूर्ण जनता को पर्याप्त पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया ।

(v) विविध—सातवी योजना में 1 18 लाख गावों का विद्युतीकरण व 23 9 लाख पम्प सेटों को बिजली से चलाने के लक्ष्य रखे गये । गावों में बिना धुएँ के नये चूल्हे लगाने पर जोर दिया गया । प्रादेशिक असमानताओं का दूर करने पर अधिक ध्यान देने तथा प्रारम्भिक शिक्षा वृत्ति उद्योग साख आदि के विकास में पिछड़े क्षेत्रों का प्राथमिकता देने की नीति घोषित की गयी ।

इस प्रकार सातवी योजना विकास, आधुनिकीकरण व सम-निर्भरता व सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी गयी ।

सातवी योजना की वित्तीय व्यवस्था

सातवी योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रस्तावित राशि के अनुमान निम्न तालिका में दिये गये हैं—

	(करोड़ ₹ में)	कुल का प्रतिशत
1 1984-85 की कर की दरों पर चानू राजस्व से बकाया राशि	(-) 5249	(-) 2 9
2 मार्गजनिक उपक्रमों से योगदान	35485	19.7
3 बाजार ऋण (शुद्ध)	30562	17.0
4 अल्प वचनें	17916	10 0
5 राज्य प्रोविडेंट फण्ड	7327	4 1
6 वित्तीय संस्थाओं से अवधि ऋण	4639	2.6
7 विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध)	12618	7 0
8 अतिरिक्त साधन-संग्रह	44702	24.8
9. विदेशों से पूँजी का शुद्ध आगम	18000	10 0
10 घाटे की वित्त व्यवस्था	14000	7 8
11. समग्र साधन (लगभग)	1,80,000	100 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवी योजना में 10% साधन विदेशों से उधार लेकर प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गये । इस प्रकार 90% साधन घरेलू रखे गये । यह कहा गया कि 14 करोड़ हजार रुपये घाटे की वित्त व्यवस्था के रूप में प्रयुक्त

किये जायेंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का 7.8% होगा। अतिरिक्त सधन-संग्रह से 44702 करोड़ रु जुटाने के लक्ष्य रखे गये जिनमे केन्द्र का अंश 22490 करोड़ रु व शेष राज्यों का होगा। अतिरिक्त साधन-संग्रह से लगभग 1/4 वित्तीय साधन जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार केन्द्र व राज्यों दोनों को अतिरिक्त साधन-संग्रह के लिए कर व करेतर साधनों का प्रयोग करना होगा। राज्यों को राजकीय उपक्रमों के घाटे कम करने होंगे। सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान 1/5 रखा गया।

बाजार ऋणों से 17% राशि प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योजनाकाल में बचत की दर 23.3% से 24.4% व विनियोग की दर 24.5% से 25.9% (GDP का) करने व लक्ष्य निर्धारित किये गये। बचत व विनियोग की दरों की ये वृद्धिया साधारण है। इनको प्राप्त किया जा सकता है। योजना की वित्तीय व्यवस्था जोखिमपूर्ण नहीं है। प्रश्न की गई कि योजनाबद्धि में कर्जों का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से अनुपात 2 प्रतिशत बिन्दु बढ़ जायगा।

संविदाओं व गैर-योजना व्यय को नियंत्रित रखने पर जोर दिया गया।

योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. मनमोहन सिंह ने यह मत प्रकट किया था कि सातवी योजना दीर्घकालीन व्यूहरचना के एक ऐसे दायरे में बनायी गयी है जिसके अनुसार 2000 ईस्वी तक भारत से निर्धनता व निरक्षरता मिटाना देश में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना तथा लोगों की रोटी कपड़ा व मकान तथा स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना सम्भव हो सकेगा। इन प्रकार सातवी योजना में विविध के प्रति काफी आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया।

सातवी योजना की आलोचनात्मक समीक्षा

विद्वानों ने सातवी योजना की व्यूहरचना, विकास व उत्पादन के लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट किये हैं।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित विचार प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

आशाजनक दृष्टिकोण—सातवी योजना में छठी योजना के विभिन्न निधनता-उन्मूलन व रोजगार मजदूर कार्यक्रमों को प्राथमिकता बढ़ाया जायगा ताकि निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने में मदद मिल सके। इन समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में सातवी योजना में काफी आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया जिससे ऐसा लगता है कि यदि उचित नीतियों व कार्यक्रमों को सकल बनाया जाय तो 2000 ईस्वी तक देश से निर्धनता व बेरोजगारी को मिटाया जा सकता है। यह राष्ट्र के नैतिक धन व आत्म-विश्वास की जगाने व बढ़ाने की दृष्टि से काफी उत्साहवर्द्धक बात है और इस दृष्टि से सातवी योजना का स्थापित किया गया है।

अर्थशास्त्रियों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति में सदेह व्यक्त किये थे। उन्होंने योजना के प्रारम्भ में कहा था कि विकास की वार्षिक दर 5% प्राप्त करना सुगम नहीं होगा। निश्चयता व बेरोजगारी दूर करने के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों के बारे में भी सदेह प्रगट किये गये थे। कुछ विद्वानों का मत था कि योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन जुटाना कठिन होगा जिससे घाट की वित्त व्यवस्था लक्ष्य से अधिक करनी होगी और वह मुद्रास्फीति को उत्पन्न करेगी।

विदेशी भुगतान की स्थिति के भी बिगड़ने की आशंकाएँ प्रगट की गयी थी क्योंकि छठी योजना में अत्यधिक मात्रा में व्यापार के घाटे के कारण इस दिशा में तनाव उत्पन्न हो गये थे।

इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इसमें निर्धारित विकास उत्पादन के लक्ष्यों को लेकर काफी समालोचना की गई थी। लेकिन सरकार ने योजना का क्रियान्वयन चालू कर दिया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की आर्थिक नीति में भी कुछ परिवर्तन किये जिनका विवरण नीचे दिया जाता है।

सरकार की नई आर्थिक नीति

(New Economic Policy of the Government)

नियोजन के प्रारम्भ से भारत की आर्थिक नीति का आधार 'मिश्रित अर्थ-व्यवस्था' रहा है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों को विकास का समान अवसर दिया गया है। पिछले कई वर्षों से औद्योगिक नीति को उदार बनाया गया है ताकि औद्योगिक विकास की दर तेज की जा सके। लेकिन राजीव सरकार ने जनवरी 1985 में सत्ता में आने के बाद आर्थिक नीति में परिवर्तन की रफ्तार तेज कर दी जिससे आर्थिक नीति एक व्यापक चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भारत की 21 वीं सदी में प्रवेश दिलाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित व मजबूत राष्ट्र देखना चाहते हैं।

सरकार की नई आर्थिक नीति में आधुनिकीकरण टेक्नोलोजी के उत्थान बड़े पैमाने की किरायेती नये उद्योगों के विकास सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य-क्षमता में सुधार आदि पर जोर दिया गया है ताकि लागत कम की जा सके व माल की निर्यात में सुधार करके देश-विदेश में निर्यात बढ़ाया जा सके। इसमें आंतरिक प्रतिस्पर्धा व बाह्य प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ा कर अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाने पर बल दिया गया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि आर्थिक नीति को उदार बनाया जाय, बाजार की शक्तियों व निजी क्षेत्र को काम करने का अधिक अवसर दिया जाय एवं विभिन्न क्षेत्रों में चल आ रहे आर्थिक नियंत्रणों की समीक्षा की जाय और उनको आवश्यक व उत्पादन-विरोधी पाये जाने पर हटाने की व्यवस्था की जाय अथवा आवश्यकतानुसार

परिवर्तित किया जाय। इस प्रकार उपयुक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति, विदेशी व्यापार नीति व राजकोषीय-नीति में संशोधन किये हैं ताकि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। इन पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है, हालांकि इनका यथास्थान विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। यहाँ दीर्घकालीन राजकोषीय नीति (Long-term Fiscal policy) का भी परिचय दिया जाता है।

1 औद्योगिक नीति व लाइसेंस व्यवस्था में परिवर्तन—सरकार ने मार्च 1985 में 1985-86 के वार्षिक बजट में 25 उद्योगों को लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया। MRTP के अन्तर्गत बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों की सीमा 20 करोड़ रु से बढ़ाकर 100 करोड़ रु कर दी (जिससे कई कंपनियाँ MRTP अधिनियम से मुक्त हो गईं), लघु उद्योगों व सहायक औद्योगिक इकाइयों के लिए प्लांट व मशीनरी में निविद्योग की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 35 लाख रुपये व 45 लाख रुपये कर दी गई ताकि अधिक इकाइयाँ उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकें व टेक्नोलॉजी को उन्नत कर सकें।

मई 1985 में 27 उद्योगों को MRTP अधिनियम की धारा 21 व 22 से मुक्त कर दिया गया तथा दिसम्बर 1985 में इनमें से 22 उद्योगों में MRTP व FERA कंपनियों के लिए लाइसेंस-मुक्ति की सुविधा बढ़ा दी गई। अब तब कुल 40 उद्योग समूहों में ब्रॉड ब्रेडिंग की सुविधा दी गई है ताकि एक उद्योग अपने लाइसेंस के दायरे में उत्पादन करते समय माँग के अनुसार वस्तु की किस्म को बदल सके जैसे लोहिया मशीन की 150 cc का स्कूटर बनाने की इजाजत दे दी गई जो पहले 100 cc के लिए थी। दिसम्बर 1985 में ही सरकार ने परिशिष्ट I के 30 उद्योगों की नई सूची प्रकाशित की है जिसके अनुसार MRTP व FERA कंपनियों को इनमें उत्पादन-क्षमता स्थापित करने की इजाजत दी गई है, बशर्ते कि ये मर्दे सार्वजनिक क्षेत्र या लघु उद्योगों के लिए आरक्षित न हों।

सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों के सम्बन्ध में भी लचीला दृष्टिकोण अपनाया है। कुछ को आरक्षित सूची से हटाया गया है और कुछ को शामिल किया गया है। कहने का आशय यह है कि सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन किये हैं कि यह उत्पादनोन्मुख बन सके ताकि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की दर 8% से अधिक प्राप्त की जा सके।

2 त्रिवर्षीय निर्यात-आयात नीति (1985-88 व 1988-91)—सरकार ने अप्रैल 1985 में तीन वर्षों के लिए निर्यात-आयात नीति घोषित की जिसमें आयात-उदारता का दृष्टिकोण अपनाया गया ताकि निर्यात बढ़ाये जा सकें। इसके लिए औद्योगिक मशीनरी की 201 मदों की खुले-सामान्य-लाइसेंस (OGL) की सूची में डाल दिया गया। 53 मदों को सरकारी आयात-सूची से हटा दिया गया तथा "आयात-नियंत्रित वस्तु सूची" चालू की गई। उदार विदेशी व्यापार नीति के

पत्रस्वरूप औद्योगिक इकाइयों के लिए पूँजीगत माल व मध्यवर्ती माल मगाना आसान हो गया है जिससे उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है। अपेक्षाकृत दीर्घकालीन निर्यात-आयात नीति व कारण इस क्षेत्र में अनिश्चितता कम हुई है। अन्य कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं ताकि विदेशों में बसे भारतीय अपने देश में पूँजी-निवेश कर सकें। पुन 1988-91 की निर्यात-आयात नीति में उदारता का दृष्टिकोण जारी रखा गया है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके और औद्योगिक मान का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर तैयार किया जा सके।

3 दीर्घकालीन राजकोषीय या वित्तीय नीति (Long-term Fiscal Policy) (LTFP)—सरकार ने दिसम्बर 1985 में सातवें योजना की अवधि (1985-90) में मसला खाने हुए एक दीर्घकालीन राजकोषीय नीति भी संसद में घोषित की थी जिससे इस क्षेत्र में अनिश्चितताएं कम की जा सकें। इसकी मुख्य बात इस प्रकार है—

(i) इसने अनुसार पांच वर्षों के लिए घन-कर, बैयक्ति आयकर व निगम-कर की वर्तमान दरों का स्थिर कर दिया गया।

(ii) इसमें 25% निवेशों की छूट (Investment Allowance) की समाप्ति का सुझाव दिया गया लेकिन इसकी एज में विकल्प सुझाए गए जैसे करदेय मुनाफे का 20% भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जमा करा देन पर 10% व्याज मिलेगा तथा उधार की सुविधा दी जायगी।

(iii) काली मुद्रा को एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय जमा स्कीम (नया मिरीज) लागू करने का सुझाव दिया गया।

(iv) निर्यात-उत्प्रेषण व रोजगार-संवर्धन की वित्तीय व्यवस्था के लिए साधन-मग्न की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(v) छठी योजना में चानू राजस्व में बनाया राशि घनात्मक रही, लेकिन मानवी योजना में यह ऋणात्मक (Negative) रह्यो। इसलिए (LTFP) में नगर-योजना त्रय में विशेषतया मायाश्री व उर्वरते पर समिती की राशि व सुरक्षा-ध्यम में कमी करने की आवश्यकता स्वीकार की गई। समिती का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1% तक सीमित करने पर बल दिया गया।

(vi) संशोधित मूल्यवर्धित कर (Modified value-added tax) (MODVAT) लागू करने पर जोर दिया गया ताकि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम की जा सकें व उत्पादन को भी लाभ पहुंचाया जा सके।

(vii) योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रदान 1984-85 में GDP के 2.7% से बढ़ाकर 1989-90 में 4% किया जाना चाहिए।

इस प्रकार दीर्घकालीन फिस्कल नीति में केन्द्रीय सरकार ने 5 वर्षों के लिए कर-नीति के आवश्यक दिशा-निर्देश स्पष्ट किये थे। अर्थशास्त्रियों ने LTFP की

व्यापक रूप से समीक्षा की है और इसकी कमियों के वावजूद इसे देश के लिए उपयोगी माना है। यह आशा प्रगट की गई कि भारत में मध्यमकालीन कर-डॉने के निर्माण में इस नीति से काफी सहायता मिलेगी।

सरकार 'शून्य-आधार बजट-व्यवस्था' (Zero-base budgeting) को लागू करने पर भी विचार कर रही है। इसके अनुसार प्रत्येक मरचारी विभाग में परि-योजना में नये सत्र के लिए व्यय की स्वीकृति देने से पूर्व इस बात की जाच की जायगी कि आधार या प्रारम्भिक वर्ष में किन उद्देश्यों के लिए कितनी राशि के व्यय की मजूरी की गई थी और अब उन उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए कितने व्यय की स्वीकृति उचित मानी जा सकती है। यदि व्यय का प्रौचित्य सिद्ध न किया जा सका तो आधार-वर्ष का व्यय भी नामजूर किया जा सकता है, उसमें बढोतरी की बात तो दूर रही। ऐसा करने से व्यय पर नियन्त्रण करना सम्भव हो सकेगा।

हमने ऊपर सरकार की नई औद्योगिक नीति, नयी विदेशी व्यापार नीति व नयी राजकोषीय नीति की दिशाएँ स्पष्ट की हैं। इन सबका उद्देश्य एक कार्यकुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जिससे उत्पादन व उत्पादकता बढ़ सकें तथा लागत व कीमतों में कमी लाकर भारत अपने निर्यात बढ़ा सके।

जवाहर रोजगार योजना:

सरकार ने मई 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए जवाहर रोजगार योजना घोषित की है। इसके अन्तर्गत 1989-90 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए लगभग 2625 करोड़ रु व्यय किये जायेंगे जिनमें केन्द्र का भ्रंत 80% व राज्यों का 20% होगा। इसके लिए NREP व RLEGP को मिला दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण निर्वन-परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में लगभग 100 दिन तक का कार्य उपलब्ध कराया जायेगा ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। इसमें 30% भारसंग महिलाओं के लिए किया जायेगा। इस योजना से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जायेगा जिसके लिए केन्द्र वित्तीय साधनों की भीषी व्यवस्था करेगा।

पंचायतों की साधनों का आवंटन निर्जनों के अनुपात में किया जायेगा। इस कार्यक्रम से काफी आजाई लगायी जा रही है। लेकिन इसकी सफलता उत्पादक राजगार की परियोजनाओं के निर्माण व उनके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इसके लिए काफी प्रयत्न करना पड़ेगा वरना साधनों के दुरुपयोग का भय भी कम नहीं है।

नयी आर्थिक नीति की समीक्षा

विभिन्न अर्थशास्त्रियों जैसे बी. के. प्रार बी. राव, के. एन राज, डी. टी. लक्ष्मणाला, प्रमान पटनायक, आदि ने अपने भाषणों व लेखों के द्वारा उभरती हुई

नयी आर्थिक नीतियों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। जहाँ आमपक्षी विचारधारा वाले व्यक्तियों को भय है कि नयी आर्थिक नीति से निजी क्षेत्र को अनियन्त्रित विकास का अवसर मिलेगा, अर्थव्यवस्था पर एकाधिकारी घरानों व विदेशी कम्पनियों का शिकजा मजबूत हो जायेगा तथा पूँजीवाद के विकास के कारण आर्थिक असमानताएँ बढ़ेंगी, उसके दूसरी तरफ उद्योग व व्यापार के प्रतिनिधियों व अन्य व्यक्तियों का यह मानता है कि अधिकांश पुराने नियन्त्रण व नियमन नई परिस्थितियों में निरर्थक व प्रगति-प्रबोधक सिद्ध हो गये थे एवं उनको हटाने या घटाने से अर्थव्यवस्था आधुनिक, कार्यकुशल व लचीली बनेगी एवं लागते व कीमते कम होती तथा भारत की निर्यात-क्षमता विकसित होगी और देश विश्व प्रतियोगिता में टिकने की स्थिति में आ जायगा।

नीति के प्रभाव¹—प्रत्यक्ष करो में कमी करने व उदार लाइसेंस-नीति प्रदान करने से पूँजी बाजार की दशा सुधरी है। 1985 में पूँजी-निर्गम से 1889 करोड़ रुपये जुटाये गये जबकि 1984 में 1304 करोड़ रु जुटाये गए थे। लाइसेंसों की आवश्यकता कम होने पर भी लाइसेंसों की संख्या बढ़ी है। विदेशी सहयोग के समझौते अधिक हुए हैं, वित्तीय संस्थानों ने अधिक कर्ज दिये हैं तथा औद्योगिक उत्पादन की दर बढ़ी है। निजी क्षेत्र वाले उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ प्रस्तुत करने लगे हैं तथा पूँजी-गहन इकाइयाँ लगायी जाने लगी हैं एवं कार्यकुशलता व आधुनिकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

डॉ. आई. जी. पटेल के विचार

लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डाइरेक्टर डॉ. आई. जी. पटेल ने अम्बिज में 5 नवम्बर 1986 को किंग्सले मार्टिन मेमोरियल लेक्चर² में भारत सरकार की नई आर्थिक नीति पर अपने विचार प्रकट किये थे जो काफी महत्व रखते हैं। डा. पटेल का कहना है कि औद्योगिक नियन्त्रणों को कम करना, लाइसेंस-व्यवस्था को सरल बनाना प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, आधुनिकीकरण करना आदि सही दिशा में कदम हैं। लेकिन ये आर्थिक विकास व समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं मान जा सकते हैं।

हमारी मुख्य समस्या यह है कि भारत में राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों, बड़े व्यावसायिक घरानों, बड़े किसानों तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले वर्गों में परस्पर

- 1 D. T. Lakdawala, Seventh Plan II-Impact on Personal Distribution The Economic Times, February 25, 1986 (एक मध्यमिक उपयोगी व सारगर्भित लेख जिसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए)।
- 2 I. G. Patel, New Economic Policy, I, II & III, The Economic Times, November 6, 7 & 8, 1986

गहरी साठ-गाठ पायी जाती है जिससे 'शक्ति का उपयोग' अष्ट तरीकों से व स्वैच्छिक ढंग से कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है। वह पहले भी किया जाता था और नई आर्थिक नीति के बाद भी किया जाता है जिससे राजनीतिक शक्ति व आर्थिक शक्ति के परस्पर तानाबाने का लाभ एक वर्ग-विशेष तक सीमित रह गया है। अतः आवश्यकता एक नई कार्यशैली को अपनाने की है जिसमें नीति के क्रियान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जाय और सत्ता व स्वैच्छिक किस्म के उपयोग को समाप्त किया जाय।

केन्द्र को राज्यों के साथ विभिन्न प्रकार की सत्ता को बांटना चाहिए। राष्ट्र की धर्म-नीति व सांख्यिक नीति तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय नीति आदि में भी स्वैच्छिक मनमानी व भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करना चाहिए ताकि नये दृष्टिकोण का लाभ समस्त देशवासियों को मिल सके।

डॉ. पटेल का मत है कि यदि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इस दिशा में सकल प्रयास कर सकें तो भारत उन्हें 21 वीं शताब्दी में गतिमान रूप में प्रवेश अवश्य दिला देगा।

अतः हमारी दिशा व मन्तव्य स्पष्ट होने जरूरी हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि सरकार ने आर्थिक नीति को उदार बनाया है और सरकारी हस्तक्षेप कम किया है। लेकिन भारत में पूँजी का अभाव है, विदेशी मुद्रा का अभाव है व माँग की तुलना में विशेषतया, उपभोक्ता माल की सप्लाई कम है। ऐसी स्थिति में सरकारी हस्तक्षेप तो रहेगा ही। साथसे अवस्था, आयात-नियन्त्रण, विनिमय-नियन्त्रण, पूँजी-निर्गम नियन्त्रण, व मूल्य-नियन्त्रण आदि समाप्त नहीं किये जा सकते। अतः नियन्त्रणों को समाप्त करने की बजाय उनके उद्देश्यपूर्ण व कार्यकुशल संचालन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि नियोजित विकास के माध्यम से अधिकतम उत्पादन व व्यापपूर्ण वितरण किया जा सके। इन नियन्त्रणों का उपयोग निहित स्वार्थी वर्ग को लाभ पहुँचाने में न किया जाकर सर्वजनहिताय किया जाना चाहिए। सरकार को अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रणों में कमी करनी चाहिए, लेकिन नियोजन के लिए नितान्त जरूरी नियन्त्रणों को अधिक कार्यकुशल ढंग से लागू करना चाहिए। इसी में देश का कल्याण निहित है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति

इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना कार्यान्वित की जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) का दृष्टिकोण प्रपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन जून 1988 में प्रकाशित किया गया था जिसमें विशेषतया 1985-86 व 1986-87 की आर्थिक प्रगति की समीक्षा की गई थी। (1980-81 के नये सिरीज के अनुसार)।

नवीनतम सूचना के आधार पर सातवी पंचवर्षीय योजना में निम्नांकित आर्थिक प्रगति हुयी है।¹

1. विकास की दर व राष्ट्रीय आय में वृद्धि—1988-89 की आर्थिक प्रगति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सातवी पंचवर्षीय योजना में विकास की वार्षिक दर 5% प्राप्त की जा सकेगी। 1980-81 के मूल्यों पर 1985-86 में राष्ट्रीय आय 5%, 1986-87 में 3.6% तथा 1987-88 में 3.4% बढ़ी। लेकिन 1988-89 में इसके 10% तक बढ़ने की आशा है। इस प्रकार सातवी पंचवर्षीय योजना में भी विकास की वार्षिक दर के पाँचवी व छठी योजनाओं के अनुरूप ही रहने की आशा है।

2. कृषिगत उत्पादन—1985-86 में कृषिगत उत्पादन में 2.4% वृद्धि हुई, लेकिन 1986-87 व 1987-88 में क्रमशः 3.7% व 2.1% की गिरावट आयी। 1988-89 में 2.3% वृद्धि की सम्भावनाएँ व्यक्त की गई हैं। 1987-88 का वर्ष अभूतपूर्व सूखे का वर्ष माना गया है। उस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 13.8 करोड़ टन ही हो पाया था। लेकिन 1988-89 में इसके 17 करोड़ टन से अधिक के स्तर तक पहुँचने का अनुमान है। 1987-88 में तिलहनों का उत्पादन 1.24 करोड़ टन, गन्ने, का 19.7 करोड़ टन, कपास का 64.3 लाख गांठे व जूट व मेस्टा का 67.8 लाख गांठे हुआ है। कुल सिंचित क्षेत्र 1987-88 में 6.6 करोड़ हेक्टेयर हो गया था तथा उर्वरकों का उपभोग 90 लाख टन तक पहुँच गया था।

3. औद्योगिक उत्पादन—सातवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर लगभग 8.5% रही है। 1985-86 में यह 8.7%, 1986-87 में 9.1%, 1987-88 में 7.3% तथा 1988-89 में 8.8% रही है।

इस प्रकार सूखे के वर्ष में भी औद्योगिक विकास की दर 7.3% रही है, जो इस बात का प्रतीक है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था कृषिगत परिवर्तनों के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त होती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र काफी गतिमान हो गया है, और भविष्य में भी विकास की दर के ऊँचा रहने की आशा है।

4. मूल्य-स्तर, बचत व विनियोग की दरें—सातवी योजना में मुद्रास्फीति की स्थिति जारी रही है। थोक मूल्यों का सूचकांक 1987-88 में 10.6% बढ़ा (बिन्दु से बिन्दु आधार पर) और जून 1989 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 838 पर पहुँच गया जिससे 1960 = 100 की तुलना में रुपये का मूल्य घट कर 12 पैसे मात्र रह गया है।

1. Economic Survey 1988-89, Various tables

* The Economic Times, September 22, 1989, editorial.

वचन की दर 1987-88 में 20.2% व विनियोग की दर 22.1% रही है (1980-81 के नये सिरीज के आकड़ी पर, प्रचलित आधे पर) जो पहले से कुछ कम है। अतः इनका घटना एक चिंता का कारण है।

5 भुगतान समुलन पर दबाव—सातवीं योजना में भुगतान समुलन की स्थिति गम्भीर बन गयी है। रुपये का भूत विदेशी मुद्रा में काफी घट गया है। देश पर विदेशी कर्ज का भार बढ़ा है और भारत विदेशी कर्ज के जाल में प्रविष्ट होना जा रहा है। अगस्त 1989 के अन्त में स्वण व स्पेशल ड्राइंग राइट्स को छाड़कर विदेशी विनियम कोष 4600 करोड़ रुपये रह गये थे जो मार्च 1989 की तुलना में लगभग 2000 करोड़ रु कम थे। ये केवल 1½ महीने के अभाव-विल की पूर्ति कर सकते हैं। इस समय देश भुगतान समुलन की जटिल स्थिति का सामना कर रहा है। भारत को व्यापारिक कर्ज की आवश्यकता है।

इस प्रकार सातवीं योजना के अंत में देश के समक्ष मुद्रास्फीति भुगतान-समुलन व असमानता जैसी समस्याएँ दिखान हैं। लेकिन यह विशाल देश भारी जनसंख्या का बोझ उठाये विकास के पथ पर अग्रसर है और अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का अरसक प्रयास कर रहा है।

योजनाकाल में आर्थिक प्रगति 1951-89

(Economic Progress During Plan
Period, 1951-89)

भारत में योजनाकाल के लगभग चार दशक समाप्त होने में आ गये हैं। इस अवधि में हमने छ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा चार वार्षिक योजनाएँ (1966-69 तक तीन वार्षिक योजनाएँ तथा एक वार्षिक योजना 1979-80 के लिए) पूरी कर ली हैं। इस समय सातवी योजना की अन्तिम वार्षिक योजना (1989-90) पर कार्य चल रहा है। इस प्रकार भारत को लगभग चार दशकों के आर्थिक नियोजन का अनुभव प्राप्त हो चुका है। नियोजन की यह अवधि काफी लम्बी मानी जा सकती है। नीचे योजनावधि की अवधि की सफलताओं व विफलताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में 1951-89 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में योजना-परिष्कार की कुल राशि (प्रचलित मूल्यों पर) लगभग 3,64,213 करोड़ रुपये (3 लाख 64 हजार करोड़ रु) विकास की विभिन्न मंदावस्थाओं पर व्यय की गई है। 1988-89 की वार्षिक योजना का आकार 49,818 करोड़ रु रखा गया था। इस व्यय के फलस्वरूप योजनाकाल में विकास की वार्षिक दर लगभग 3.6 प्रतिशत प्राप्त की जा सकी है तथा सभी आधारभूत क्षेत्रों (basic sectors) में ऊँचे दर्जे की तकनीकी-आर्थिक आत्म-निर्भरता (techno-economic self-reliance) की दशाएँ उत्पन्न की जा सकी हैं। ये उपलब्धियाँ नियोजन के अभाव में सम्भव नहीं थीं।

इस प्रकार योजनाकाल के 38 वर्षों में उत्पादन व विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नये स्तर प्राप्त किए गए हैं। लेकिन योजनाओं के विभिन्न उद्देश्यों जैसे मूल्य-स्थिरता, आय व रोजगार में तीव्र वृद्धि, घन व आय के वितरण में समानता एवं निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में कमी आदि की प्राप्ति करने की दिशा में प्रगति बहुत मन्द व असन्तोषजनक रही है। देश में निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों ने मुद्रास्फीति की जटिल समस्या उत्पन्न कर दी है और हम आर्थिक स्थिरता के साथ विकास (growth with stability) के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। कभी-कभी

तो हम अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर न होकर इनके टोक विपरीत दिशा में चले गये हैं। ऐसा विशेषकर समाजवादी समाज की स्थापना के सम्बन्ध में हुआ है क्योंकि योजनाकाल में आर्थिक प्रगति व प्रवृत्तियों ने देश में पूँजीवादी ढंग के समाज को ही अधिक सुदृढ़ बनाया है। यह वास्तव में एक चिन्ता का विषय है, क्योंकि भारतीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में एक ऐसे समाज की स्थापना करना रहा है जिसमें सभी नागरिकों को आर्थिक व सामाजिक विकास के समान अवसर मिल सकें और आय व धन के वितरण की त्रिपमत्ताएँ समाप्त की जा सकें। यदि देश में आर्थिक सत्ता मुट्ठी भर व्यक्तियों व परिवारों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है तो हम अग्रसे सामाजिक लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं, चाहे उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में हमने कितने भी नये व बड़े कीर्तिमान क्यों न स्थापित कर लिए हों।

पहले बताया जा चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति काफी सन्तोषजनक रही, द्वितीय योजना की प्रगति भी बहुत कुछ सन्तोषजनक मानी जा सकती है, लेकिन तृतीय योजना की प्रगति से देश में निराशा व असन्तोष का वातावरण छा गया था। 1965-66 का वर्ष, जो तृतीय योजना का अन्तिम वर्ष था, अमूलपूर्व अवकाश व सूखे का वर्ष रहा, जिससे कृषिगत उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन दोनों को भारी क्षति पहुँची थी। 1962 में चीन से सघर्ष हुआ जिसमें देश पर सुरक्षा के बढ़ते हुए खर्च का भार भी पड़ा था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इस प्रकार तृतीय योजना की अवधि में देश को दो बार युद्धों की स्थिति का सामना करना पड़ा। विदेशी सहायता की अनिश्चित स्थिति व अन्य कारणों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय 1 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ नहीं की जा सकी और 1966-69 के तीन वर्षों में वार्षिक योजनाएँ ही लागू की गयीं। इसे योजनावकाश (plan holiday) की अवधि भी कहा गया है, हालाँकि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से इस अवधि में भी नियोजन की प्रक्रिया को पहले की तरह जारी रखा गया था।

इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के पाँचवें वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना पर कार्य चल रहा है। आगे के पृष्ठों में नवीनतम आँकड़ों व सूचनाओं के आधार पर योजनाकाल में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय आय के परिवर्तन¹

भारत की राष्ट्रीय आय (1970-71 के मूल्यों पर) 1950-51 में 16,731 करोड़ रुपये से बढ़कर 1985-86 में 60143 करोड़ रुपये हो गयी थी। इस प्रकार योजनाकाल के 35 वर्षों में यह लगभग 3.6 गुना हो गई। इसमें प्रति वर्ष 3.6

1. Economic Survey, 1988-89, p. S-3. व पिछले वर्षों के वार्षिक सर्वेक्षण।

प्रतिशत वृद्धि से वृद्धि हुई। 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय (1970-71 के भावों पर) 466 रुपये थी जो बढ़कर 1985-86 में 797.7 रुपये हो गयी। इस प्रकार योजनाकाल में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 1.7 गुनी हो गई। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 1.5 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। हमें यह स्मरण रखना होगा कि जिस भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कई दशाब्दियों तक वार्षिक वृद्धि की दर मुश्किल से 1% रही थी, वही अर्थव्यवस्था 1950-51 से पहले की तुलना में तिगुनी से भी अधिक रफ्तार से विकसित होती गयी। (कुल राष्ट्रीय आय की लेने पर)। अतः योजना-पूर्व अवधि की तुलना में योजनाकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की दर काफी उत्साहवर्द्धक मानी जा सकती है।

विभिन्न योजनाओं में विकास की दर के लक्ष्य व उपलब्धियाँ निम्न तालिका में दी गई हैं :

(विकास की दरें) (प्रतिशत)

	लक्ष्य	वास्तविक ¹
1. प्रथम योजना	2.1	3.6
2. द्वितीय योजना	4.5	4.0
3. तृतीय योजना	5.6	2.2
4. चतुर्थ योजना	5.7	3.4
5. पंचम योजना	4.4	5.2
6. छठी योजना	5.2	5.3
7. सातवी योजना	5.0	5.4*

1. *Economic Survey 1988-89, p. S-5* (वास्तविक वृद्धि-दर राष्ट्रीय आय के आधार पर आकी गई है।) लक्ष्यों के लिए *Sixth plan, p. 1* का उपयोग किया गया है।

* साठवी योजना के दृष्टिकोण-प्रथम के अनुसार अनुमानित।

इस प्रकार विकास की दर के लक्ष्यो व वास्तविक उपलब्धियों में अन्तर पाये गये हैं। प्रथम व पंचम पञ्चवर्षीय योजनाओं में वास्तविक विकास की दरें लक्ष्यो से ऊँची रही। तृतीय योजना में विकास की दर सबसे कम रही। छठी योजना में विकास की दर 5.3% रही है, जो लक्ष्य के अनुरूप है। सातवी योजना में भी इसके लक्ष्य से अधिक रहने का अनुमान है।

छठी योजना में विकास की वार्षिक दर 5.3% रही है एवं पाँचवी योजना में भी यह 5.2% रही थी। इसलिए अब इस बात के लिए सुनिश्चित प्रमाण मिल गया है कि 1974-75 से भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में ऊँचे विकास-पथ पर चल पड़ी है। सातवी योजना में विकास की वार्षिक दर 5% प्राप्त हो जायगी जिससे भारत 3½% वार्षिक विकास-दर वाला देश न कहला कर 5% विकास दर वाला देश कहलाने का अधिकारी बन गया है।

भारत में जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 1981 में 68.5 सक्नी करोड़ व्यक्ति हो गयी। 1989 के मध्य में यह लगभग 83 करोड़ व्यक्ति मानी जा है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से योजना काल में 1951 की तुलना में 'एक नए भारत' का निर्माण और हो गया है। 1981-85 की अवधि में संशोधित प्राकड़ो के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.1% के स्थान पर 2.2% पायी गयी है।¹ योजनाकाल में वार्षिक विकास की दर जनसंख्या की वृद्धि-दर से अधिक रही है। जनसंख्या की वृद्धि का कारण जनता के उपयोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तरों में सुधार की वजह से मृत्यु-दर में कमी का घाना रहा है। जनसंख्या की इतनी वृद्धि के बावजूद भी इस अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का 1.5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ना एक महत्वपूर्ण बात है। अतः भारतीय अर्थ-व्यवस्था योजना-काल में गतिमान हुई है, चाहे प्रगति की वार्षिक रफ्तार 1.5% (प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर) कम ही क्यों न रही हो। यह पहले की वार्षिक गतिहीनता व जड़ता की तुलना में काफी आशाजनक व उत्साहवर्द्धक मानी जा सकती है, हालांकि यह देश की आवश्यकताओं, प्राकड़ों व लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रही है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 1951-89 की अवधि में राष्ट्रीय आय लगभग 4 गुनी जनसंख्या 2½ गुनी तथा प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगुनी हो गई।

योजनाकाल में कृषि की प्रगति

नियोजन के प्रथम तीन दशकों में कृषिगत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवधि में कृषिगत उत्पादन 2.7% वार्षिक दर से बढ़ा तथा यह लगभग दुगुना

1. 'Seventh Five Year Plan' 1985-90, Mid-Term Appraisal, p. 195.

* विश्व बैंक की विकास रिपोर्टें 1989 के अनुसार।

हो गया। डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन के अनुसार भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950 से 1980 की अवधि में लगभग 2.8% वार्षिक दर बढ़ा, जबकि 1900-1950 के बीच इसकी वृद्धि-दर केवल 0.1% रही थी। इस प्रकार योजनाकाल में खाद्यान्नों का उत्पादन योजना पूर्व अवधि की तुलना में काफी तेज गति से बढ़ा है। इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक नध्य निम्न तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं :

चुनी हुई कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन¹

वस्तुएँ	1950-51	1986-87	1987-88
खाद्यान्न (मिलियन टन)	55.0	143.4	138.4
निलहन (मिलियन टन)	5.0	11.3	12.4
गन्ना (करोड़ टन)	7.0	18.6	19.7
कपास (मिलियन गांठे)	2.9	6.9	6.4
जूट (मिलियन गांठे)	3.5	8.6	6.8

भारत में कृषिगत उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। 1985-86 में खाद्यान्नों का उत्पादन 15 करोड़ टन हुआ जो पिछले वर्ष से 5 मिलियन टन अधिक था। 1987-88 में भी यह लगभग 13.8 करोड़ टन ही रहा। 1988-89 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 17 करोड़ टन से अधिक प्रस्तुत किया गया है। योजनाकाल में कपास का उत्पादन 1985-86 में 8.7 मिलियन गांठों तक तथा जूट व मेहडा का 12.7 मिलियन गांठों तक पहुँच चुका था जो बाद के दो वर्षों में घटा है। इस प्रकार विभिन्न कृषिगत पदार्थों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।

नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में कृषिगत उत्पादन को क्षेत्रफल में वृद्धि करके बढ़ाया गया था, लेकिन बाद की अवधि में कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सिंचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, शक्ति, आदि की पूर्ति बढ़ायी गयी है और ऐसा विशेषतया चुने क्षेत्रों में किया गया है। योजनाओं में बड़ी, मध्यम एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है। यह 1950-51 में 2.26 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 1987-88 में 6.63 करोड़ हेक्टेयर हो गया है।

1. Economic Survey, 1988-89, pS -15 (1986-87 व 1987-88 के लिए)।

1950-51 में अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग चालू हो नहीं हुआ था जबकि 1987-88 में ये किस्में 51.2 मिलियन हेक्टेयर में बोयी गयी थी। 1988-89 के लिए 65 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। नाइट्रोजन, फास्फट व पोटैश की खादों का कुल उपयोग 1970-71 में 21 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1987-88 में 90 लाख टन हो गया। वर्ष 1988-89 के लिए इसके उपयोग का लक्ष्य एक करोड़ टन रखा गया है। 1964-65 से गन्ने का वार्षिक उत्पादन तेजी से बढ़ा है और इसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी बढ़ी है। गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज 1955-56 में 708 किलोग्राम से बढ़कर 1985-86 में 2046 किलोग्राम हो गई है जो पहले से अठ्ठाई गुनी से अधिक है। 1987-88 में यह 1995 किलोग्राम रही है।

विद्वानों का मत है कि 1964-65 से भारतीय कृषि में विकास के साथ-साथ कई प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हो गये हैं जैसे चावल व गेहूँ के उत्पादन में असंतुलन, अनाजों व दालों के उत्पादन में असंतुलन एवं खाद्यान्नों व व्यापारिक फसलों के बीच असंतुलन। इनके अलावा हरित क्रान्ति के फलस्वरूप प्रादेशिक असंतुलन भी उत्पन्न हो गये हैं। हरित क्रान्ति के बाद की अवधि में खाद्यान्नों के अन्तर्गत 15% से कम क्षेत्रफल में 50% से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया है। देश के पूर्वी भागों में चावल का उत्पादन बढ़ाने व सूखी कृषि तथा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारी मेहनत करनी होगी।

योजनाकाल में खाद्यान्नों का ढाँचा काफी बदल गया है। यह निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

कुल खाद्यान्नों के उत्पादन का प्रतिशत

खाद्यान्न	1950-51	1986-87
गेहूँ	13	32
चावल	40	42
मोटे अनाज	30	18
दालें	17	8

इस प्रकार खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में गेहूँ का अंश काफी बढ़ा है, चावल की यथा स्थिर रहा है तथा मोटे अनाजों व दालों का काफी घटा है। प्रो सी. टी. कुरियन ने इसे निम्न विरोधों विकास कहा है क्योंकि उनके लिए मोटे अनाज का उत्पादन 30% से घट कर 18% हो रह गया है। साथ में दालों का उपयोग करने वाली जनता की दशा भी काफी शोचनीय होगई है।

योजनाकाल में उद्योग, शक्ति व परिवहन की प्रगति

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 1950-51 में 2. लाख किलोवाट से बढ़कर 1986-87 में 554 लाख किलोवाट (लगभग 24 गुनी) हो गयी है। जिन गांवों में बिजली पहुँचायी गयी, उनकी संख्या 3061 से बढ़कर 1986-87 में 412 लाख हो गयी है। शक्तिचालित पम्प सेटों की संख्या 21 हजार से बढ़कर 1987-88 में 664 लाख कर दी गयी है। रेलों की मास ढोने की क्षमता 93 करोड़ टन से बढ़ाकर 1988-89 में 332 करोड़ टन (लगभग 35 गुनी) हो गयी। जहाज-रानी में कुल टन भार क्षमता 39 लाख जी भार टी. से बढ़कर 1986-87 में 5774 लाख जी भार टी हो गई है। यह 1984-85 की तुलना में कुछ कम हो गई है।

जैसा कि औद्योगिक प्रगति के अध्याय में बताया गया है, योजनाकाल में भारत के औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है जिससे अनेक नई किस्म की वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है। देश का औद्योगिक ढांचा बदला है। 1960-61 में विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य में आधारभूत व पूँजीगत उद्योगों का अंश 38% था जो 1979-80 में 49% हो गया, मध्यवर्ती वस्तुओं में यह 21% से घटकर 16% एवं उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योगों में 41% से घटकर 35% हो गया।

1951-56 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर 5.5% रही है। योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन लगभग छ गुना हो गया है।¹

छठी योजना के विभिन्न वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में काफी उतार-चढ़ाव आते रहे। योजना में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि-दर लगभग 5.5% रही जो 7% के लक्ष्य से नीची थी। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का आधार-वर्ष 1970 की जगह 1980-81 लेने पर औद्योगिक विकास की वार्षिक दर ऊँची हो गई है। यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8.5% वार्षिक रही है जो उत्साह बढ़ाक मानी जा सकती है।

1 K L Krishna, Industrial Growth and Productivity in India, lesson 13 in Brahmananda & Panchamukhi's book 1987

37 वर्षों में महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास¹

	1950-51	1986-87	1987-88
1. तैयार इस्पात (मिलियन टन)	1 04	9.1	10.6
2. सीमेंट (मिलियन टन)	2.7	34.8	37.3
3. नाइट्रोजन उर्वरक (हजार टन N में)	9.0	5410	5466
4. कोयला (मिलियन टन)(लिग्नाइट सहित)	32.8	175.2	190.9
5. कच्चा लोहा (मिलियन टन) (गोघा को छोड़कर)	3.0	52.7	48.6
6. परिशुद्ध पेट्रोल-पदार्थ (मिलियन टन)	0.2	42.8	44.4
7. कूट तेल (मिलियन टन)	0.26	30.5	30.4

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि योजनाकाल के 37 वर्षों में तैयार इस्पात का उत्पादन दस गुना हो गया। सीमेंट का उत्पादन 14 गुना, कोयले का 6 गुना तथा कच्चे लोहे का लगभग 16 गुना हो गया है। यशीनी घौजारी का वार्षिक उत्पादन जो 1950-51 में 30 लाख टन का हुआ था, वह 1987-88 में 390 करोड़ टन का हो गया। कूट तेल का उत्पादन 1987-88 में 3.04 करोड़ टन हुआ जो काफी सराहनीय माना जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक व व्यापारिक मंत्र-विभागीय सार्वजनिक उपक्रमों में 1950-51 में कुल निविद्योग 29 करोड़ रुपयों का था जो 31 मार्च 1988 के अन्त में 71,299 करोड़ रुपयों का हो गया। इसी अवधि में इनकी इकाइया 5 से बढ़कर 221 हो गयीं। दीर्घकाल में परिणाम देने वाले कई प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। काफी वित्तम्ब व निराशाओं के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक कॉम्प्लेक्स (समूह) स्थापित किये गये हैं। इनसे निजी

1. *Economic Survey, 1988-89*, pp. S-34 & S-35.

* इसमें सकेन्दरी उत्पादकों का उत्पादन भी शामिल है।

क्षेत्र के लिए भी विकास के नये प्रवसर खुले हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्थापक।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कई इकाइयाँ लाभप्रद ढंग से चल रही हैं और उनका कार्य निजी क्षेत्र की इकाइयों से किसी भी अर्थ में घटिया नहीं माना जा सकता। फिर भी, जिन सार्वजनिक इकाइयों में घाटा हो रहा है, उनमें उत्पादकता व लाभप्रदता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि कई कठिनाइयों का बावजूद हमारा औद्योगिक ढांचा 1989-90 में 1950-51 की अपेक्षा अधिक संतुलित व अधिक विविधतापूर्ण हो गया है। औद्योगिक ढांचे में वस्त्रों व खाद्य-उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में भार घटा है, तथा इन्जीनियरी व रसायन उद्योगों का बढ़ा है। भारत का स्थान छोटी के औद्योगिक देशों में गिना जाने लगा है।

31 जनवरी 1989 को हमारे विदेशी विनिमय कोष (स्वर्ण व SDR सहित) 5967 करोड़ रुपये के थे। 1987-88 में इसकी राशि 7687 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। पिछले वर्षों में विदेशी विनिमय कोषों का उपयोग आवश्यक आयातों के लिए किया गया है।* इससे अधिक विकास करने तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली है। योजनावधि में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक, लोहा व इस्पात, मशीनी औजार चीनी व वस्त्र मिल मशीनरी, गाड़ियों, मिश्रित देशों के सूत, पेट्रोल-पदार्थ आदि में काफी सीमा तक आयात-प्रतिस्थापन किया गया है जो इन क्षेत्रों में हुई प्रगति का सूचक है।

योजनाकाल में सामाजिक सेवाओं में प्रगति

कृषि, उद्योग, शक्ति व परिवहन के क्षेत्रों में प्रगति के अलावा योजनाकाल में शिक्षा, चिकित्सा, परिवार-नियोजन, पिछड़ी जातियों के कल्याण, औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में भी प्रगति की गई है। 1950-51 में 6 से 11 वर्ष की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 43 था जो 1984-85 में 91.8 हो गया। 11-14 वर्ष की उम्र के लिए यह 13 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों व परिवार-नियोजन केन्द्रों को 1950-51 में कोई जानना तक नहीं था, जिनका अब काफी विस्तार हो गया है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्तियों का काफी विस्तार किया गया है। जीने की औसत आयु 32 वर्ष से बढ़कर 1987 में 58 वर्ष तक पहुँच गई है जो अपने आप में आयिक विकास की सूचक है, हालाँकि श्रीलंका में इसी वर्ष यह 70 वर्ष व चीन में 69 वर्ष तक पहुँच गई थी।

* अगस्त 1989 के अन्त में विदेशी विनिमय कोष (स्वर्ण व SDR के बिना) 4600 करोड़ रुपये पर आ गये हैं जो एक भारी चिंता का विषय है।

बचत व विनियोगों में प्रगति¹

याजना काल में बचत व विनियोग के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। 1950-51 में मन्त्र धरेलू बचत राष्ट्रीय आय का 10.2% (पुराने सिरीज पर) थी जो 1987-88 में 20.2% (नये सिरीज 1980-81 पर) हो गई है। सकल विनियोग अथवा सकल धरेलू पूँजी निर्माण की दर 1950-51 में 10% से बढ़कर 1987-88 में 22.1% हो गई है। बचत व विनियोग की इतनी ऊँची दर प्रायः मध्यम आय वाले देशों में देखन की मिलती है। अतः इन दिशाओं में भारत की प्रगति काफी सराहनीय रही है। लेकिन भारत में आज भी सावजनिक बचतों की मात्रा बहुत नीचा है और देश में वित्तास की आवश्यकताओं के अनुरूप सावजनिक बचतों में वृद्धि नहीं हो पाई है। देश में वित्तासिता के उपयोग पर प्रकुश लगाने की आवश्यकता है और कृषिगत क्षेत्र से अधिक साधन एकत्र करने की आवश्यकता है। 1950-51 में कुलों में प्राप्त राशि राष्ट्रीय आय का 6.6% थी जो अब 17.4% हो गई है। इस में सार्वजनिक उपयोग में व्यय की वृद्धि को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है ताकि कृषि से प्राप्त अधिक राशि का उपयोग विनियोगों को बढ़ाने में दिया जा सके। लेकिन सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण सावजनिक व्यय में कमी कर सकना अथवा भावी वृद्धि को नियन्त्रित कर सकना काफी कठिन हो गया है।

हम ऊपर नियोजन के लगभग 38 वर्षों में कृषि उद्योग विद्युत परिवहन विभिन्न सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख कर चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी उपलब्धियाँ कुछ क्षेत्रों में काफी उत्साहवर्धक व सतोषजनक रही हैं।

लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक उपलब्धियों के बावजूद योजनाओं की आर्थिक प्रगति व सम्बन्ध में काफी तीव्र आलोचनाएँ की गयी हैं। यदि हम योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियों की तुलना योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों से करें तो प्रतीत होगा कि इनके बीच काफी अंतर पाया गया है। भारतीय योजनाओं में वित्ताय व्यय के लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए जाते हैं लेकिन इनमें निर्धारित भौतिक लक्ष्य (physical targets) को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

स्मरण रहे कि भारतीय योजनाओं का लक्ष्य केवल उत्पादन में वृद्धि करना ही नहीं रहा है बल्कि साथ में वितरण की व्यवस्था में सुधार करना भी रहा है ताकि देश में न्याय के साथ आर्थिक विकास (economic growth with justice)

1 Economic Survey 1988-89 p 510 & 511 (नवीनतम सूचना के लिए)।

का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अतः हमें योजनाओं की उपलब्धियों की जाच समा-
नता व न्याय के सन्दर्भ में भी करनी चाहिए।

विभिन्न धर्मशास्त्रियों व विचारकों ने भारतीय नियोजन की असफलताओं
व कमियों पर देश का ध्यान आकषिप्त किया है। हम यहाँ पर उनका सक्षिप्त
विवेचन प्रस्तुत करते हैं।

भारतीय नियोजन की असफलताएँ अथवा कमियाँ

हम देख चुके हैं कि योजनाकाल की सम्पूर्ण अवधि में राष्ट्रीय आय में
लगभग 3.6% साताना की दर से वृद्धि हुई है, जो जनसंख्या की 2.1% वृद्धि-दर
से अधिक रही है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में 1.5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई
है। लेकिन हमारी प्रमुख विफलताएँ मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, निर्धनता एवं घन व
धाय की असमानताओं के क्षेत्रों में मानी जाती हैं। इनका विवरण नीचे दिया
जाता है।

1. कृषि में असन्तुलन (Imbalances) का उत्पन्न होना—जैसा कि पहले
बतनाया जा चुका है योजनाकाल में कृषिगत उत्पादन में खाद्यान्न व नैर-खाद्यान्न के
बीच काफी असन्तुलन उत्पन्न हो गया है। व्यावसायिक फसलों में से क्षेत्रफल निकाल
कर खाद्यान्नों में लगाया गया है। देश में गेहूँ का उत्पादन तो काफी बढ़ गया है
लेकिन दालों का उत्पादन घीमी गति से बढ़ा है। देश में दालों का निरन्तर
अभाव रहने लगा है और इनका उपभोग करने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयाँ बढ़
गयी हैं।

इसी प्रकार कपास से क्षेत्रफल हटाकर गेहूँ में लगाया गया है जिससे कपास
की पैदावार पर प्रतिवृत्त अभाव पड़ा है। इन परिवर्तनों से आगे के वर्षों के लिए
कृषिगत पैदावार के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। व्यावसायिक फसलों से
खाद्यान्नों की ओर क्षेत्रफल का सिसक जाना एक चिन्ता का विषय है। भारत की
खाद्यान्नों के साध-साध व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की भी आवश्यकता
है। अतः मिर्चाई के साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके व्यावसायिक फसलों का
उत्पादन भी बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में तिलहनो व दलहनो का उत्पादन भी
बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. मूल्य-स्तर में वृद्धि—योजना काल में देश में महंगाई के बढ़ जाने से सर्व-
साधारण की काफी कष्ट उठाने पड़े हैं। द्वितीय योजनाकाल में मूल्य-वृद्धि बालू हुई
थी, जो बाद में निरन्तर जारी रही है। 1979-80 व 1980-81 के वर्षों में थोड़े
मूल्यों में (बिन्दु से बिन्दु के आधार पर) क्रमशः 21.4% व 16.7% की वृद्धि हुई
थी जो अभूतपूर्व थी। छठी योजनावधि (1980-85) में थोड़े सूचनाओं के आधार
पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 8% तथा उपभोक्ता-मूल्य-सूचकांको के आधार पर
9.5% रही है।

1970-71 का आधार-वर्ष लेने पर थोक भावों का सूचनांक दिसम्बर, 1988 में 434.4 रहा। इस प्रकार दिसम्बर 1988 में मूल्य-स्तर 1970-71 की तुलना में 4.3 गुना हो गया था। अब इसका आधार-वर्ष 1981-82 हो गया है। 5 अगस्त, 1989 को यह 164.2 रहा। इस प्रकार थोक मूल्यों में वृद्धि जारी है।

जून, 1989 में प्रसिद्ध भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचनांक 838 पर पहुँच गया (आधार-वर्ष 1960=100)। इस प्रकार लगभग 29 वर्षों में रुपये का मूल्य घट कर 12 पैसे पर आ गया है। इसका भी नया आधार-वर्ष 1982 कर दिया गया है जिस पर जून 1989 में यह 170 था। 1960 व 1982 के सिरीज में परिवर्तन-गुणांक 4.93 है। अर्थात् 1982 के आधार वाले प्रकों को 4.93 से गुणा करके 1960 के आधार पर लाया जा सकता है। इसके बढ़ने से विशेष शर्तों व समझौते के अनुसार सरकारी कर्मचारियों व श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाना होना है। प्रथम योजना की अवधि को छोड़कर शेष योजनाकाल में मूल्य-स्तर निरन्तर बढ़ते रहे हैं। खाद्यान्नों के भाव बढ़ने से उपभोक्ता-वर्ग को बड़ा उठाने पड़े हैं और कच्चे माल के भाव बढ़ने से औद्योगिक लागतों में काफी वृद्धि हुई है। मूल्य-स्तर में वृद्धि होने से व्यापारियों को आकस्मिक लाभ प्राप्त हुए हैं और समाज में धन व धाय की असमानताएँ बढ़ी हैं। सरकार का गैर-विकास व्यय भी बढ़ा है जिससे विकास-व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मूल्य-स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारण योजनाओं में अनियन्त्रित रूप से धाते की वित्त-व्यवस्था का उपयोग करना रहा है। साथ में, खाद्यान्नों के प्रभाव ने मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार भारत में जो कुछ आर्थिक प्रगति हुई है वह अस्थिरता (instability) के आतावरण में हुई है। महंगाई बढ़ जाने से सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए कई बार महंगाई-भत्ता बढ़ाना पड़ा है। उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ने से विदेशों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति घटी है जिससे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः निरन्तर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति ने योजनाओं के समस्त अनुमानों पर काफी विपरीत प्रभाव डाला है।

3 बेरोजगारी में वृद्धि—भारतीय नियोजन के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार की मात्रा में वृद्धि करना रहा है। योजनाओं में रोजगार में वृद्धि की गयी है, लेकिन साथ में बेरोजगारी भी बढ़ी है और प्रत्येक योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या योजना के प्रारम्भ की तुलना में प्रायः अधिक पाई गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक योजना में यम बाजार में जाने वाले सभी नये श्रमिकों को काम नहीं दिया जा सका है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय नियोजन देश को 'पूर्ण रोजगार' की तरफ ले जाने में नितान्त असमर्थ रहा है। मार्च 1985 में सामान्य

लेकर जेप 11 धरत SDR की विस्तार लेने का निर्णय घोषित कर दिया गया था।

1985-86 से इस वर्ज का मुग्तान प्रारम्भ हो जाने से भारत पर ऋण-सत्वा भार काफी बढ गया है। 1987-88 में ऋण-सेवा-भार चालू प्राप्ति^{*} का 24⁰ रहा था जिसके 1989-90 तक काफी बढ जाने की सम्भावना है।

कुछ विद्वानों का मत है कि विशाल मात्रा में विदेशी सहायता का उपयोग करने के बावजूद हम में सर्वसाधारण को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। विदेशी साधनों का दुरुपयोग होने से देश में अनिश्चित उत्पादन क्षमता की समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि काफी विदेशी सहायता विशाल नदी-घाटी परियोजनाओं व अनुत्पादन किम्ब की औद्योगिक परियोजनाओं में व्यय कर दी गई है जिससे परोक्ष रूप में भ्रष्टाचार विनाशी जीवन ऊँची घट्टालिकाओं, सिनेमाघरों एवं घर आवश्यक गहरी नगरों को बढावा मिला है। कुछ राशि का उपयोग विदेशी से स्वर्ण का आयात व थोरी से अन्य मान जैसे मूनी कपडा, घादि व आयात घादि में भी किया गया है। इन विदेशी सहायता का पर्याप्त लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पाया है।

विदेशी सहायता में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विकास कार्य में मदद मिली है, लेकिन इनमें सन्देह नहीं कि सहायता का व्यय-यपूर्वक से उपयोग (wasteful use) होने से देश को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि विदेशी सहायता का मुग्तान करने में कठिनाई हो रही है। देश अभी तक विदेशी सहायता से मुक्त नहीं हो पाया है।

विदेशी सहायता का भ्रष्ट प्रथम योजनावधि में कुल सार्वजनिक 82% के 9.6% से बढकर वार्षिक योजनाओं (1966-69) की अवधि में 36% तथा पाचवी योजना में घटकर 14.8% पर आ गया था। छठी योजना (1980-85) में सार्वजनिक परिषद में विदेशी सहायता का भ्रष्ट लगभग 8% ही रहा है। इस प्रकार पिछली अवधि में योजनाओं में कुल सार्वजनिक परिषद का लगभग 1/10 भ्रष्ट ही विदेशी साधनों से प्राप्त होता रहा है। इस अर्थ में तो हमारी योजनाएँ स्वदेशी साधनों पर ज्यादा आश्रित रही हैं, लेकिन भारत को आजकल रियायती शर्तों पर भारी माना में विदेशी सहायता की आवश्यकता पडन लगी है। इस अर्थ में विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता बढी है।

* वस्तु-निर्यात व मद्रुस्य-भदों की आय का जोड चालू प्राप्ति^{*} (current receipts) कहलाता है। ऋण-सेवा-भार घातामी कुछ वर्षों में घोर बढेगा जिसमें भारत विदेशी वर्ज के पद (foreign debt trap) में पँस सकता है। सामान्यतया 20% से अधिक ऋण-सेवा-भार देश को 'वर्ज के जाल' में डाल देता है।

जून 1988 में भारत सहायता मंत्र की पेरिस में हुई बैठक में भारत का 1988-89 के लिए 63 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया गया है जो पिछले वर्ष से अधिक है। भारत आज भी विदेशों से रियायती शर्तों पर कर्ज लेने की पेशकश करता रहता है क्योंकि व्यापारिक उधार से आगे चलकर कर्ज चुकाने का भार अधिक पड़ता है। 1987-88 में ऋण सेवा मार चालू प्राप्तियों (current receipts) के अनुपात में 24% रहा है। 1989-90 व 1990-91 में भी IMF का कर्ज चुकाने की वजह से भुगतान-भुत्तलन पर भारी दबाव बना रहेगा। कहने का आशय यह है कि भारत की विदेशी सहायता पर निर्भरता आज भी कायम है।

5 धन व धन की असमानता में वृद्धि तथा निर्धनता की समस्या—पच-वर्षीय योजनाओं की अवधि में भारत में आर्थिक व सामाजिक असमानताएँ बढ़ी हैं। यह योजनाओं के निर्धारित सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों के विपरीत है। सच पूछा जाय तो देश में योजनाओं की उपलब्धियों के प्रति निराशा, असन्तोष व अग्र्य आलोचनाओं का प्रमुख कारण यही है कि योजना-काल में धनी अधिक धनी हो गये हैं एवं निर्धन या तो निर्धन रह गये हैं अथवा अधिक निर्धन हो गये हैं। योजना की नीतियों के कारण ग़ामदनी का हस्तांतरण जनसाधारण व बेतनमोगी मध्यम-वर्ग की ओर से ऊँचे व्यवसायी वर्ग की तरफ हुआ है जिससे समाज में धन व धन की असमानताएँ बढ़ गई हैं।

1977-78 में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम (bottom) 30% परिवारों का उपभोग व्यय में भण 15% मध्यम 40% परिवारों का 33% तथा चोटी (Top) व 30% परिवारों का 52% था। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भण क्रमशः 14% 32% तथा 54% व 14 प्रसार उपभोग- व्यय की असमानताएँ आज भी विद्यमान हैं। ग्रामीण परिसम्पत्तियों (rural assets) के वितरण का सकेक्षण-अनुपात लगभग 0.65 पर कायम है। इसमें साठ के दशक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्रामीण व ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग के वितरण के गुणांक क्रमशः 0.30 तथा 0.33 पर कायम हैं। अतः परिसम्पत्ति की असमानताएँ व उपभोग की असमानताएँ पहले जैसी ही बनी हुई हैं। इस सम्बन्ध में अधिक विस्तृत विवेचन गाय के प्रमाण वितरण के अध्याय में किया गया है।

देश के आर्थिक जीवन पर मुट्ठीभर उद्योगपतियों व बड़े व्यावसायिक घरानों का प्रभाव पाया जाता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था ने मुद्रास्फीति की दशाएँ उत्पन्न की हैं। आर्थिक नियन्त्रणों की ठीक से लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार भारत में नियोजन काल में हम पूँजीवादी ढंग के समाज की तरफ बढ़े हैं चाहे हम बीच में समाजवाद का कितना ही दिवारा क्यों न पीटा गया हो। आज धन व धन की असमानताएँ नियोजित विकास की अवधि के प्रारम्भ की तुलना में अधिक हो

गयी है। यद्यपि अर्थव्यवस्था आज भी मिश्रित हो बनी हुई है, लेकिन इसके मिश्रण के तत्त्व इसे समाजवादी प्रारूप की अपेक्षा पूँजीवादी प्रारूप के ही अधिक समीप ले जाने हैं।

विद्वानों का मत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चोटों के कुछ लोगों के लिए तो मजबूत या त्रियामोल प्रतीत होती है क्योंकि उनकी अनाज-समाज लाभ प्राप्त हुए हैं। लेकिन विशाल जनममुदाय के लिए यह निष्क्रिय व निष्कामी बनी हुई है, जिन्हें लाभ होने के बजाय घाटा हो गया है और जिन्हें आज अधिक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। अतः योजना के लक्ष्यों का बँटवारा भी असमान रहा है।

भारत में सम्पन्न वर्गों की उपभोग की प्रवृत्ति काफी ऊँची है जिससे वह वित्तासिता की वस्तुओं के उपभोग (conspicuous consumption) में बहुत अवश्य करता है। परिवारान्तरूप, आय का असमान बितरण अचानक से वृद्धि करने की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। आय व धन की असमानता के अन्तर विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में पाये जाने वाले अन्तरों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन की अवधि में देश समाजवाद की दिशा में विशेष प्रगति नहीं कर पाया है जिससे सामाजिक न्याय के वातावरण में विकास नहीं हो पाया है।

भारत में 1984-85 में 27.3 करोड़ व्यक्ति “निर्धनता की रेखा” से नीचे जीवन बिता रहे थे जो देश की जनसंख्या का 37% था। “निर्धनता की रेखा” के माप के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 76 रु. का उपभोग तथा शहरी क्षेत्रों में 88 रु. का उपभोग, (1979-80 के मापों पर) आधार-स्वरूप माने गए हैं। इन सीमाओं से नीचा उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गए हैं। IRDP व NREP से लाभान्वित परिवारों के आधार पर सरकार का यह दावा है कि निर्धनता का अनुपात 1977-78 में 48.4% से घट कर 1984-85 में 36.9% पर आ गया है। लेकिन जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, दिल्ली से सुरेश तेंदुलकर व पूना से नीलकण्ठ राय एवं सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री बी. एम. दांडेकर आदि का मत है कि यह दावा काफी बड़े-बड़े रूप में किया जा रहा है। IRDP के अन्तर्गत आर्थिक संरचना कम मिली है। निर्धन परिवारों का दुधारू पशु या अन्य पशु परिमपत्ति के रूप में दिये गये थे, वे कड़ियों के पास कायम नहीं रह पाये हैं। अतः नजिय में निर्धनता-उन्मूलन की दिशा में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

६ निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण में वृद्धि—सरकार की लाइसेंस-व्यवस्था के दोषपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किये जाने के कारण औद्योगिक जगत् में एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। आर्थिक सत्ता कुछ बड़े

औद्योगिक समूहों के हाथों में सिमट गई है; जैसे बिड़ला, टाटा व मफतलाल ग्रुप आदि। इन समूहों की परिसम्पत्तियों (assets) का मूल्य योजनाकाल में काफी बढ़ा है। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण से भी हम समाजवाद के अपने लक्ष्य से विमुख हो गये हैं। जैसे उत्पादन की बड़ी इकाइयों की स्थापना से बड़े पैमाने की क़िफायतें प्राप्त होती है जिससे क़मी-क़मी बड़े पैमाने की इकाइयों को प्राथमिकता दी जानी है। लेकिन सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छोटे उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक होता है, ताकि उद्यमशीलता का आवश्यक मात्रा में पैतावा व बिस्तार हो सके।

7. साधन-संग्रह के क्षेत्र में विफलताएँ—योजनाओं में साधन संग्रह के निर्धारित लक्ष्यों व वास्तविक प्राप्तियों में काफी अन्तर पाया गया है जिससे प्रकट होता है कि इस दिशा में नियोजन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं तो वास्तविक प्राप्तियाँ निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम रही हैं, और कहीं बहुत अधिक। उदाहरणार्थ तृतीय योजना में 1960-61 के करारोपण की दरो पर बालू राजस्व में 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तव में इस मद में 419 करोड़ रुपये का घाटा रहा। घाटे की वित्त-व्यवस्था लक्ष्य से अधिक रही है। तृतीय योजना में यह 1,133 करोड़ रुपये हुई जो लक्ष्य से दुगुनी थी। चतुर्थ योजना में भी घाटे की वित्त-व्यवस्था 2,060 करोड़ रुपये की हुई जो 850 करोड़ रुपये के लक्ष्य से $2\frac{1}{2}$ गुनी थी। छठी योजना 1980-85 में घाटे की वित्त-व्यवस्था का लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि वास्तविक राशि लगभग 15,684 करोड़ रुपये रही है, जो लक्ष्य के तिगुने से भी अधिक है।¹

धतः नियोजन की वित्तीय व्यवस्था स्फीतिकारी रही है। विकास व उत्पादन के लक्ष्यों व उपसन्धियों के बीच में भी अन्तर पाया गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं: एक तो लक्ष्यों का ठीक से निर्धारित नहीं किया जाता और दूसरा योजना के नियाम्बयन में कमियों का पाया जाना। इस प्रकार नियोजन-काल में योजनाओं के निर्माण व नियाम्बयन दोनों में कमियाँ रही हैं।

8 पूँजी-उत्पत्ति अनुपात (Capital-output Ratio) में वृद्धि तथा अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता के स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति—भारत में योजनाकाल में पूँजी-उत्पत्ति अनुपात 1950-51 में 3.5:1 से बढ़कर, आगे चल कर 6.2:1 तक हो गया है। जिसका अर्थ यह है कि पहले एक रुपये की उत्पत्ति कर सकने के लिए $3\frac{1}{2}$ रुपये की पूँजी की आवश्यकता होती थी, जबकि बाद में इसके लिए 6.2 रुपये

1. Seventh Five Year Plan, 1985-90, Vol. I, p. 50.

की पूँजी की आवश्यकता होने लगी, (स्थिर भावों पर) (at constant prices) । इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता के स्थिर गिरे हैं तथा अकार्यकुशलता बढ़ी है । भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर ऊँची लागत वाली व अकार्यकुशल अर्थव्यवस्था बनती गई है । इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की ऊँची दर प्राप्त करना कठिन हो गया है, क्योंकि वृद्धि की दर 22% होने तथा पूँजी-उत्पत्ति अनुपात के

6:2:1 होने पर विकास की दर $\frac{22}{6 \cdot 2} =$ लगभग 3.5% ही प्राप्त हो सकती है ।

विद्वानों का मत है कि भारत में पूँजी-उत्पत्ति-अनुपात को 6:1 से 5:1 पर लाने के लिए कृषिगत विनियोगों में वृद्धि करनी होगी । इसके लिए योजना में विनियोगों का प्रारूप कृषि के पक्ष में करना होगा ।

9. सामाजिक सेवाओं के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण का संभाव—प्रोफेसर अमरत्या सेन का विचार है कि भारत में सामाजिक सेवाओं के प्रति पुराना (कंजर्वेटिव) दृष्टिकोण रहा है ।¹ देश में 2/3 लोग निरक्षर हैं, जीने की औसत आयु 52 (वर्ष अब 58 वर्ष) पर ठहरी हुई है, तथा भारत मात्र भी निर्धनता, प्रकाश, बीमारी, गन्दगी, जातिवाद, छद्मार्थ, पृथक्ता व अराजकता की दशाओं का शिकार बना हुआ है । स्त्रियों का समाज में नीचा स्थान पाया जाता है । चीन ने सामाजिक सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया है ।

10. योजनाकाल में काली मुद्रा का प्रसार—जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत में अधिक नियन्त्रणों, करों की ऊँची दरों व करों की चोरी के कारण देश में काली मुद्रा का तेजी से फैलाव हुआ है । 1980-81 में जितनी आमदनी पर कर लगाया जाना चाहिये या उसके लगभग 3/4 भाग पर कर की चोरी की गई है रूपवा कर नहीं चुकाया गया है । 1983-84 में सकल घरेलू उत्पत्ति (GDP) का 1/5 अंश काली आमदनी का शिकार हो चुका था । भारत में काली मुद्रा पर मार्च 1985 में सांख्यिक विज्ञान व नीति पर राष्ट्रीय संस्थान (NIPFP), दिल्ली की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है । उससे पता लगता है कि समस्या काफी गहन व जटिल हो गई है ।

सरकार ने पिछले महीनों में घनी वर्ग के लोगों पर छापे मारने व तलाशी लेने की गति तेज की है ताकि काला धन व काली मुद्रा जमादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकाले जा सकें ।

11. विविध क्षेत्रों में अन्य कमियाँ—नियोजन काल में कई अन्य क्षेत्रों में

भी असफलताएँ व कमियाँ रही हैं। देश में भूमि-भुधारों के सम्बन्ध में कानून तो काफी बना दिये गये लेकिन उसको ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा सका जिससे कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। सहकारी ग्राम्योत्पन्न व संगठनों का संस्थात्मक विकास तो काफी हुआ, लेकिन इनका गुणात्मक विकास नहीं हो पाया। भूतकाल में सामुदायिक विकास क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रगति मन्द रही थी। सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्ध में कई प्रकार की कमियाँ रही हैं। पूँजी-गत वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल देने से उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाया जा सका, जिससे देश में इनका अभाव बना रहा। भूतकाल में परिणाम देने वाली परियोजनाओं पर दीर्घकाल में परिणाम देने वाली परियोजनाओं की सुरक्षा में कदम बंद दिया गया जिससे अर्थव्यवस्था में काफी तनाव व असन्तुलन उत्पन्न हो गये हैं। परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी 1975 तक विशेष सफलताएँ नहीं मिली, क्योंकि इस कार्यक्रम का महत्व काफी देर में समझा गया। इस क्षेत्र में विशेष प्रसार तृतीय योजना की अवधि में आरम्भ किए गये थे। 1951-61 की गणनाओं में परिवार-नियोजन पर साक्षरता से कम ध्यान देने के कारण देश में 'जनतेल्वा के बिफोट' की स्थिति उपस्थित हो गयी। भारतीय नियोजन में वित्तीय व्यय के सधियों की प्राप्त करने पर अधिक धन दिया गया है और भीतिक लक्ष्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है।

परस्पर में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए MRTP अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एकाधिकार-मानीय मण्डित किया था। नये उद्यमकारियों को प्रोत्साहन दिया गया तथा देश के पिछड़े हुए प्रदेशों के आर्थिक विकास पर बल देकर क्षेत्रीय व प्रादेशिक असन्तुलनों को कम करने का प्रयास किया गया तथा लघु व सीमान्त कृषकों एवं सेतिहर मजदूरों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किये गये एवं देहातो में रोजगार बढ़ाने के लिए दीर्घगामी कार्यक्रम (long term programmes) आरम्भ किये गये जो योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों के अन्तर्गत थे। गहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने पर जोर दिया गया। अब तक 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके समाज के कमजोर वर्गों को साख की अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

सारंग—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि योजना-काल में विभिन्न दिशाओं में कई महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है और उत्पादन के नये कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। वर्षों से गतिहीन व स्थिर रहने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान हुई है व साथ में आधुनिकीकरण की ओर भी प्रवृत्ति हुई है और देश में आर्थिक विकास की निरन्तर प्रक्रिया चल रही है। इसी अवधि में देश को दुर्घटना के कारण सुरक्षा का भी काफी भार उठाना पड़ा है। योजना-काल में सूखे व अवात के कारण कृषिगत अर्थव्यवस्था को समय-समय पर काफी धक्का पहुँचा है। हमें आर्थिक नियोजन के बावजूद महंगाई, बेकारी, निर्धनता, घन व श्रम की असमानता,

वाली मुद्रा, निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण तथा अपर्याप्त साधन-समृद्ध आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार नियोजन की यह अवधि सफलताओं व विफलताओं का एक अजीबोगरीब मिश्रण रही है। लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के स्तर नीचे रहे हैं तथा विकास में स्थिरता व अनिश्चितता भी पाई गई है जिसके लिए ज्यादातर भौतम की जिम्मेदार ठहराया गया है। सार्वजनिक विनियोगों को लक्ष्यों के अनुसार न बढ़ा सकने तथा आर्थिक प्रशासन की कमियों के कारण भी विकास में काफी बाधा पहुँची है।

विश्व बैंक के अनुसार 1987 के भावों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 300 डॉलर आँकी गयी है, जो 1.4% की वार्षिक दर से बढ़ने पर 2000 ईस्वी में 313 डॉलर ही हो पायेगा। स्मरण रहे कि तब भी भारत काफी निर्धन देश ही बना रहगा। अतः हमारे समक्ष विकास की गति को तेज करने की एक महान चुनौती विद्यमान है।

विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने समय-समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की सराहना की है। उनका मत है कि पिछले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मदी के वातावरण में भी भारत अपने विदेशी भुगतान को काफी सन्तुलित रख पाया है। लेकिन विश्व बैंक ने सातवी योजना (1985-90) व 1985-86 तथा 1986-87 के दो सघीय बजटों में अपनाई गई नीतियों के अन्दर में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ताजा कार्यकारी सर्वेक्षण मई 1986 में प्रस्तुत किया था उसमें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निम्न सुझाव दिये गये थे जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(i) बजट में घाटे की राशियों को बढ़ते जाने में भारत आंतरिक कर्ज को फटे में पड़ जायगा। इससे देश पर व्याज का भार काफी बढ़ जायगा। इसलिए घाटे के बजटों पर नियन्त्रण किया जाना चाहिये।

(ii) भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर काबू पाने के लिए निर्यात-समर्थन करना बहुत जरूरी है। यदि सातवी योजना में निर्यात में लगभग 68% वार्षिक वृद्धि नहीं की जा सकी, तो भारत को बड़े पैमाने पर व्यापारिक कर्ज लेने होंगे ताकि आयातों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इनसे आगे चलकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

(iii) भारत की अधिकांश समस्याओं का कारण यह है कि यहाँ बहुत से औद्योगिक सधन ऐसे हैं जिनका आकार अपर्याप्त और छोटा है जिससे लागत ऊँची आती है। सरकार ने अपनी नीतियों से कार्यकुशल फर्मों का विकास रोकती है तथा अकार्यकुशल फर्मों की सहायता देती है। फर्मों के आकार विकास व आने-जाने पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। अतः लागत, किस्म व नव परिवर्तनों पर ध्यान देने से भारत की विश्व में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ सकती है।

सरकार को उपर्युक्त सुझावों के अनुसार भाषी नियोजन को नई दिशा देनी चाहिए।

मई 1987 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट "India An Industrialising Economy in Transition" में आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने व रुपये का उचित मात्रा में अवमूल्यन करने पर जोर दिया ताकि औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात बढ़ाये जा सकें। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन करने से देश को विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ निर्यात-माल की सप्लाई बढ़ाना कठिन है। इसलिए अवमूल्यन से लाभ की वजह हानि होने का अदेशा उपादा है।

अतः हमारी प्रमुख विफलताएँ आर्थिक असमानता, बेरोजगारी व निर्धनता, बजटों के घाटे, (योजना-व्यय व गैर-योजना व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण) अकार्यकुशल सयन्त्रों की भरमार, उत्पादन की ऊँची लागत, काली मुद्रा तथा मुद्रा-स्फीति की है। भाषी योजनाओं में स्पष्ट नीतियाँ व प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करके लागू की रोटी-रोजी व आर्थिक विकास की समस्याएँ हल की जानी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से बहुत जटिल (Complex) हो गयी है। हमें रोजगार, अनाज, उत्पादकता व निर्यात बढ़ाने पर विशेष रूप से बल देना है। इनमें प्रगति हुए बिना भारतीय अर्थव्यवस्था सबट में पड़ सकती है।

प्रश्न

- 1 भारत में योजनाकाल के दौरान हुई आर्थिक प्रगति का विश्लेषण कीजिये।
(Raj Ilyr. T. D C., 1988)
- 2 भारत में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं? नियोजन की विफलताओं पर भी प्रकाश डालिये। (Raj Ilyr. T. D. C., 1989)
- 3 आर्थिक नियोजन की छः योजनाओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था अब भी दूसरों पर निर्भर तथा विभिन्न असफलताओं एवं कमियों से पीड़ित है।" इस कथन की विवेचना कीजिए। (Raj Ilyr. T. D C, 1986)
- 4 भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। (Raj Ilyr. T. D C., 1983 and 1985)
- 5 पञ्चवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। (Raj Ilyr. T. D. C., 1981)

संदर्भ

- 1 Link (A Newsweekly), August 13, 1989. articles by Dr. Malcolm S. Adiseshiah, Biplob Das Gupta and Asmi Raza

25

योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था

(Financing the Plans)

प्रत्येक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिस्यय के लिए सरकार को आवश्यक वित्तीय साधन जुटाने पड़ते हैं। इसके लिए साधन सग्रह (Resource Mobilisation) करारोपण व अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति न हो एवं कार्यकुशलता व सामाजिक न्याय का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। वित्तीय साधनों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

- (1) चालू राजस्व से बकाया राशि (Balance from Current Revenues) (BCR),
- (2) अतिरिक्त साधन-सग्रह (Additional Resource Mobilisation) (ARM),
- (3) सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान (Contribution of Public Enterprises) (प्रचलित दरो पर)
- (4) आन्तरिक ऋण (Internal Loans),
- (5) घाट की वित्त-व्यवस्था (Deficit Financing), तथा
- (6) विदेशी सहायता (Foreign Aid)।

इनमें से प्रथम पाँच साधनों से प्राप्त राशि घरेलू साधन (Domestic Resources) के अन्तर्गत आती है। हम पहले प्रत्येक साधन का अर्थ व महत्व स्पष्ट करेंगे। तत्पश्चात् विभिन्न योजनाओं में प्रत्येक साधन का वित्तीय व्यवस्था में योगदान स्पष्ट किया जाएगा।

1 चालू राजस्व से बकाया राशि—इसमें बजट के राजस्व खाते (revenue account) की वचते आती हैं। केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के करो व गैर-कर साधनों से आय प्राप्त होती है लेकिन राजस्व खाते में कई प्रकार की मदों पर गैर-योजना व्यय (Non-plan expenditure) भी किया जाता है जैसे

5. घाटे की वित्त व्यवस्था—जब कुल सरकारी व्यय (रेवेन्यू व पूँजीगत) कुल आय (रेवेन्यू व पूँजीगत) से अधिक होता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है। इसके लिए सरकार रिजर्व बैंक के पास पड़ी अपनी नकद बचावा राशियों का प्रयोग कर सकती है, अथवा रिजर्व बैंक से उधार ले सकती है जिसके लिए प्रायः ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। भारत में इस मापन का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया है जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है। वित्त-मन्त्रालय के अनुसार घाटे की वित्त व्यवस्था में 'सरकारी क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली शुद्ध डेजार की राशि' (Net RBI Credit to the Government Sector) घाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के आंकड़े सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति अणु-भ्रष्टता (बीयंकालीन व अल्पकालीन दोनों) के परिवर्तनों को सूचित करते हैं।

केवल द्वितीय योजना की अवधि को छोड़कर अन्य योजनाओं में वार्षिक घाटे की वित्त व्यवस्था का लक्ष्य से अधिक रही है। चतुर्थ योजना की अवधि में घाटे की वित्त व्यवस्था का लक्ष्य 850 करोड़ रु का था जबकि वास्तविक घाटे की वित्त व्यवस्था 2060 करोड़ रुपये रही। अन्वेषागिन व्यय का भार आ जाने के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है, जैसे वाड अकान मूवा अणु प्राकृतिक विपदाओं बुद्ध आदि की विविध परिस्थितियों के कारण अत्यधिक व्यय करना पड़ता है।

छठी योजना (1980-85) में घाटे की वित्त व्यवस्था का लक्ष्य 5 000 करोड़ रुपये का रखा गया था। नतीजतम अनुमानों के अनुसार योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था इसके तिगुने से अधिक, अर्थात् 15 684 करोड़ रु रही है।

यह साधन काफी स्फीकारि (inflationary) माना गया है लेकिन अभी तक इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका है। एक मीमा में परे घाटे की वित्त व्यवस्था आर्थिक मंदी उत्पन्न करती है। लेकिन उस मीमा को निर्धारित करना तथा उसकी वनाय रचना काफी कठिन होता है। इस पर देश के आर्थिक विकास की अवस्था, उत्पादन की सम्भावना मुद्रा की वर्तमान मन्नाई आदि का प्रभाव पड़ता है।

6 विदेशी सहायता—भारत में आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है। इसके कारण मूलभूत व व्याज के मुगलान की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। योजनाओं में उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है, फिर भी घरेलू साधनों का योगदान प्रतिगमन के रूप में अधिक रहा है। छठी योजना में विदेशी साधनों की राशि 9,929 करोड़ रुपये (विदेशी वित्तिय औषों में निकानी जाने वाली 1,000 करोड़ रुपये की राशि के अलावा) आकी गई थी, जो मार्जजिनिक क्षेत्र में प्रम्नावित कुल परिच्यय का 10.2% थी। वास्तविक राशि के 8529 करोड़ रुपये (7.7%) रहने का अनुमान है

विविध योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था
(वास्तविक राशि (करोड़ रुपये में))

सं.	प्रथम योजना ('51-56)	द्वितीय योजना ('56-61)	तृतीय योजना ('61-66)	साथिक योजनाएँ ('66-69)	चतुर्थ योजना ('69-74)	पंचम योजना ('74-79)	षष्ठि योजना ('79-80)	सप्तम योजना ('80-85)
1. बालू राजस्व से वसूली राशि	382	11 (-)	419	346	(-)236	6636	2,217	1,893
2. प्रतिरिक्त माध्यम संप्रदाय	255	1,052	2,892	908	4,280	10,300	2,115	32,970
3. सार्वजनिक उपकरणों का प्रणाल	115	167	415	398	1,431	2,583	1,696	5,810
4. आन्तरिक ऋण	686	1,439	2,113	1,890	6,538	12,424	4,132	45,635
5. घाटे की वित्त व्यवस्था	333	954	1,133	676	2,060	3,560	1,355	15,684
6. कुल घरेलू साधन	1,771	3,623	6,154	4,218	14,073	35,503	11,515	1,02,202
	(90.4%)	(77.5%)	(71.8%)	(63.6%)	(87%)	87.2%	(91.4%)	(92.3%)
7. विदेशी सहायता	189	1,049	2,423	2,410	4,087	5,209	1,086	8,529
	(9.6%)	(22.5%)	(28.2%)	(36.4%)	(13%)	(12.8)	(8.6%)	(7.7%)
8. समग्र साधन	1,960	4,672	8,577	6,628	16,160	40,712*	12,601	1,10,821

1. Report on Currency and Finance, Vol. II, 1987-88, pp. 106-107. (षष्ठि योजना व बाद के लिए)

* इसमें 1974-77 की वास्तविक स्थिति तथा 1977-79 की अनुमानित स्थिति को जोड़ दिया गया है। (Indian Economic Statistics : Public Finance, December 1988, pp. 75-78) इसके लिए RBI रिपोर्ट के 39.303 करोड़ रुपये का घाटन भी दिया गया है जिसमें 1974-75 के अनुमान बालू बौद्धों पर है तथा घाटे के वर्षों के 1975-76 की भीमतों पर है। इस राशि में 85.2% साधन घरेलू व 14.8% बाहरी पूंजी होते हैं।

काफी सराहनीय थी। घाटे की वित्त-व्यवस्था का भी उपयोग प्रथम योजना की तुलना में काफी अधिक हुआ। लेकिन यह योजना में निर्धारित 1,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य से कम रहा। द्वितीय योजना में भू-सुर पर काफी दबाव बढ गये थे और घाट की वित्त-व्यवस्था ने इसमें अपना योगदान दिया था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 7,500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन वास्तविक व्यय 8,577 करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय से 1,077 करोड़ रुपये अधिक हुआ। तृतीय योजना की वित्तीय व्यवस्था में विदेशी सहायता का योगदान 28.2% रहा। घाटे की वित्त-व्यवस्था का लक्ष्य 550 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक घाटे की व्यवस्था 1,133 करोड़ रुपये की हुई, जो लक्ष्य से दुगुनी थी। अनिर्दिष्ट साधन-मध्य 2,892 करोड़ रुपये के हुए, जबकि लक्ष्य 1,710 करोड़ रुपये का था। चालू राजस्व से बनाया राशि 419 करोड़ रुपये प्रारम्भिक (provision) रही, जबकि इस मंड के अन्तर्गत लक्ष्य 550 करोड़ रुपये जुटाने का था। इस प्रकार वस्तुतः इस मंड के अन्तर्गत 969 करोड़ रुपये की कमी रही।

तीन वार्षिक योजनाओं (1956-69) की वित्तीय व्यवस्था

इन अवधि में मन्दी के कारण करो से प्राप्त राशियाँ अनुमानों से नीचीं रही। गैर-योजना व्यय अधिक रहा, क्योंकि सरकारों बमंचालियों के सहगई नरो में वृद्धि की गयी, छाछाछो के लिए सन्धिनी दी गयी एव भवमूल्पर के बाद 1966-67 में विदेशी ऋणो पर रुपयो में देय व्याज की राशि बढ गयी थी।

1966-69 की तीन वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि 6,628 करोड़ रुपये रही। कुल साधनों का लगभग 36% विदेशी सहायता से प्राप्त किया गया, जो पहले से अधिक था। घाट की वित्त-व्यवस्था से 676 करोड़ रुपये जुटाने गये जबकि लक्ष्य 335 करोड़ रुपये का था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वित्तीय व्यवस्था

चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 15,902 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी। लेकिन व्यय की सजोषित राशि 16,160 करोड़ रुपये रही जिसकी वित्तीय व्यवस्था नीचे दी जाती है।

1 चालू राजस्व से बनाया राशि-प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इन मंड में 1,673 करोड़ रुपये प्राप्त करने का अनुमान था जो बाद में (-) 236 करोड़ रुपये रहा। भर्पात् सन्ध की तुलना में 1,909 करोड़ रुपयों की गिरावट आई। यह निम्नलिखित गैर-योजना व्यय में वृद्धि के कारण उत्पन्न हो गयी थी। सरकारी बमंचालियों के बेतन में वृद्धि, सुरक्षा व्यय में वृद्धि, प्राकृतिक विपदाओं के कारण राहत-सहायता, आद्य-सन्धिनी, वीरों इसके लिए उन्नतदायी रहे हैं।

2 **सार्वजनिक उपक्रमों का अंशदान**—केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्र-विभागीय औद्योगिक व व्यावसायिक उपक्रमों के अंशदान में इस्पात व उर्वरक उद्योगों के उत्पादन को घटका पहुँचाने से कमी आयी थी। राज्यों में भी राज्य-विजली-बोर्डों व राज्य सड़क-परिवहन-निगमों की पर्याप्त आय नहीं हुई थी। इस मद से 1,431 करोड़ रुपये मिले जो लक्ष्य में 100 करोड़ रुपये कम थे।

3 **अतिरिक्त साधन-संग्रह**—इस मद से 4,280 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो लक्ष्य से 1,082 करोड़ रुपये अधिक थे।

4 **घाटे की वित्त व्यवस्था**—घाटे की वित्त-व्यवस्था का लक्ष्य तो 850 करोड़ रुपये का था, लेकिन वास्तविक घाट की वित्त-व्यवस्था 2,060 करोड़ रुपये की रही जो लक्ष्य में दार्द गुनी अधिक थी।

5 **विदेशी सहायता**—इसके अन्तर्गत वास्तविक प्राप्ति 2,087 करोड़ रुपये की हुई जबकि लक्ष्य 2,614 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था में बाह्य सहायता का योगदान लगभग 13% रहा था।

पंचम पंचवर्षीय योजना में वित्तीय व्यवस्था

पंचम योजना 1974-79 में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की प्रस्तावित राशि 39,303 करोड़ रुपये रखी गई थी जबकि वास्तविक व्यय 40,712 करोड़ रुपये आया गया है। इस योजना में चालू राजस्व से बकाया राशि 6,636 करोड़ रु., अतिरिक्त साधन-संग्रह से 10,300 करोड़ रु., सार्वजनिक उपक्रमों से अंशदान के रूप में 2,583 करोड़ रु., आंतरिक ऋणों से 12,424 करोड़ रु., घाटे की वित्त-व्यवस्था से 3,560 करोड़ रु. एवं विदेशी सहायता में 5,209 करोड़ रु. प्राप्त होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया है।¹

पंचम योजना की वास्तविक वित्त-व्यवस्था प्रस्तावित वित्त-व्यवस्था से काफी भिन्न रही है। चालू राजस्व से बकाया राशि लक्ष्य से अधिक रही। लेकिन अतिरिक्त साधन-संग्रह लक्ष्य में कम रहा। सार्वजनिक उपक्रमों से योगदान की राशि लक्ष्य से तिगुनी रही। आंतरिक ऋण से प्राप्त राशि लगभग लक्ष्य के मुनाबिक ही रही। घाटे की वित्त-व्यवस्था लक्ष्य की $2\frac{1}{2}$ गुनी रही। विदेशी सहायता का उपयोग लक्ष्य में नीचा रहा। कुल मिलाकर पंचम पंचवर्षीय योजना की वित्त-व्यवस्था मुद्रास्फीति का बढ़ावा देने वाली रही है।

1. Indian Economic Statistics : Public Finance, December 1988, Government of India, Ministry of Finance, pp 75-78

छठी-पंचवर्षीय योजना 1980-85 की वित्त-व्यवस्था¹

(करोड़ रु. में)

विभिन्न साधन	लक्ष्य (1979-80 के भावों पर) (1)	वास्तविक स्थिति (नवीनतम अनुमान) (2)	वास्तविक प्राप्तियाँ (कुल के प्रतिशत के रूप में) (3)
(1) चालू राजस्व से बकाया राशि (1979-80 की दरों पर)	14478	1893	1.7
(2) अतिरिक्त साधन-संग्रह (अर्थात् अतिरिक्त करारोपण व सार्व- जनिक उपक्रमों की वसूलियों वृद्धि के उपायों सहित)	21302	32970	29.8
(3) सार्वजनिक उपक्रमों का भण्डान	9395	5810	5.2
(4) बाजार-भूण, मूल्य भवर्तों आदि	36396	45935	41.4
(5) धाटे की वित्त व्यवस्था	5000	15684	14.2
(6) विदेशी विनिमय कोषों को निकाशना	1000	—	—
(7) बाह्य सहायता	9929	8529	7.7
कुल राशि	97500	110821	100.0

1. Report on Currency and Finance, 1987-88, Vol. II, p. 107

तालिका से स्पष्ट होता है कि छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था में घरेलू साधनों का योगदान लगभग 89% रखा गया था। घाटे की वित्त-व्यवस्था का अर्थ 5% रखा गया था। वर्ष 1979-80 की करो की दरों पर चालू राजस्व से बकाया राशि 14 478 करोड़ ₹ रखी गई थी। अतिरिक्त-साधन-मग्नह से 21,302 करोड़ ₹ जुटाये जाने थे। योजना-परिष्करण में इस मद का योगदान 22% रखा गया था। इसके लिए सुझाव दिया गया कि सरकार को करो की बोरी को खोजना होगा, कर-प्रशामन में सुधार करना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में धनिक-बर्ग से कर वसूल करना होगा। खाद्य (food) उर्वरक निर्यात आदि के अति-मूल्य सन्निधि की राशि घटानी होगी तथा राज्य-विद्युत-बोर्डों, राज्य-मंडल-परिवहन-निगमों व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के घाटों को कम करना होगा।

छठी योजना की प्रस्तावित वित्त-व्यवस्था व वास्तविक वित्त-व्यवस्था में अंतर

पूर्व तालिका से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। ये इस प्रकार हैं:—

1- छठी योजना में चालू राजस्व से वास्तविक बकाया राशि लक्ष्य से काफी नीची रही है। इसका कारण यह है कि गंद-योजना श्रम पर नियंत्रण नहीं लगाया गया है। सुरक्षा-व्यय व्यय की असाध्यता व सौ सड़ो, जैसी मदों पर केन्द्र के कुल गंद-योजना राजस्व व्यय का लगभग 1/3 अंश व्यय हो जाता है। इस प्रकार गंद-योजना राजस्व-व्यय के बढ़ने से चालू राजस्व से बकाया राशि कम रही है।

2 सार्वजनिक उपक्रमों का असादान भी लक्ष्य से कम रहा है। इनकी प्रवृत्ति-व्ययस्था व मूल्य-नीति में उचित सुधार करके इनमें लाभ बढ़ाया जा सकता है।

3 छठी योजना में अतिरिक्त साधन-मग्नह से वित्तीय साधन लक्ष्य से 50% अधिक जुट गये थे। इनमें प्राप्त होने वाली राशि का लक्ष्य 21302 करोड़ ₹ रखा गया था जब कि वास्तविक प्राप्ति लगभग 32970 करोड़ ₹ रही है जो कुल साधन-मग्नह का लगभग 30% रही है।

4 छठी योजना में बाजार ऋण के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। इस क्षेत्र का महत्व भी अधिक उपयोग किया जायेगा। इसके माध्यम से मग्नह जुटाने की काफी सम्भावनाएँ पायी जाती हैं।

5 छठी योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था 15684 करोड़ ₹ की हुई है। यह योजना के लक्ष्य के निम्न में भी अधिक है। इससे प्रत्येक व्यवस्था में तरलता (liquidity) बढ़ती है तथा स्फीतकारी दबाव उत्पन्न हो जाते हैं। छठी योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था कुल साधन-मग्नह का 14.2% रही।

6. बाह्य सहायता का योगदान 7.7% रहा। भारत के लिए विदेशी सहायता की स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं लगती। 1985-86 से IMF के कर्ज की वापस

प्रदायगी चालू होने से अविध्य में ऋण-सेवा-भार में वृद्धि होगी। अतः हमें नियॉन-प्रोमाहन व शुनी हुई वस्तुओं के कार्यकुशल आयात-प्रतिस्थापन पर अधिक बल देना चाहिए।

7. अन्त में इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय (स्थिर भावों पर) लक्ष्य से लगभग 20% नीचा रहा है, हालांकि प्रचलित भावों पर सार्वजनिक परिव्यय की कुल राशि 1,11,000 करोड़ रु. के समीप रही है। छठी योजना की वित्तीय व्यवस्था भी भूततः स्फोटिकाएँ रही हैं। इससे पर्यव्यवस्था में मुद्रास्फोति के दबाव बड़े हैं। सरकार को घाटे की पर्यव्यवस्था से उत्पन्न मुद्रास्फोति पर नियन्त्रण करने का सतत प्रयास करना पड़ा है।

सातवीं योजना (1985-90) की प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था¹

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय के लिए 1,80,000 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गयी है जिसकी प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :—

साधन	(करोड़ रु. में)	कुल का प्रतिशत
(1) 1984-85 के कर की दरों पर चालू राजस्व से बकाया राशि	(-) 5,249	(-) 2.9
(2) सार्वजनिक उपक्रमों का अगदान	35,485	19.7
(3) बाजार से ऋण (शुद्ध)	30,562	17.0
(4) अल्प वक्त	17,916	10.0
(5) राज्य प्रोविडेंट फण्ड	7,327	4.1
(6) वित्तीय संस्थाओं से अर्वाधि-कर्ज	4,639	2.6
(7) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध)	12,618	7.0
(8) प्रतिरिक्त माधन संग्रह	44,702	24.8
(9) विदेशों से पूँजी-आगम (शुद्ध)	18,000	10.0
(10) घाटे की वित्त व्यवस्था	14,000	7.8
(11) कुल साधन	1,80,000	100.0 (लगभग)

1 Seventh Five Year Plan, 1985-90, Vol. I, pp. 52-57. प्रतिशत निकाले गये हैं।

इनमें से प्रत्येक मद की विवेक बातें नीचे दी जाती हैं :—

1. चातू राजस्व से बकाया राशि—अनुमान है कि 1980-90 की अवधि में केन्द्र जो (1984-85 के कर की दरों पर) चातू राजस्व की बकाया राशि में 12011 करोड़ रु. का घाटा रहेगा, लेकिन राज्यों को 6762 करोड़ रु. की वचन रहेगी जिससे इस मद में 5249 करोड़ रु. की ऋणात्मक राशि दिखायी गयी है जो कुल मायन-समग्र का 3% ऋणात्मक रहेगी। यह एक बिजा की स्थिति है।

2. सार्वजनिक उपक्रमों का असदान—1984-85 की दरों पर इस मद से 35,480 करोड़ रु. की राशि मिलने का अनुमान है जो कुल नाशनों का $\frac{1}{3}$ होगी। छठी योजना में 1979-80 की दरों पर इस मद से 3810 करोड़ रु. की राशि मिली थी। इससे अतिरिक्त साधन-समग्र की भाव मानिल नहीं है। भारत में राज्य सरकारों की विद्युत-बोर्डों व राज्य परिवहन निगमों में काफी घाटा होता है। अतः इन मद से इतनी बड़ी राशि जुटा पाना कठिन लगता है।

3. विविध पूँजीगत प्राप्तियों में कृषकों, सरकारी कर्मचारियों व स्थानीय मत्स्याओं आदि से कर्ज व अग्रिम राशियों की वसूतियाँ व गैर सरकारी प्रोविडेंट फण्डों की जमाएँ व अन्य जमाएँ शामिल होंगी हैं। सातवीं योजना में आन्तरिक कर्ज का योगदान लगभग $\frac{1}{2}$ भाग गया है।

4. अतिरिक्त साधन समग्र—प्रत्यक्ष व परोक्ष करों, रेलों व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से अधिक साधन जुटाये जाने हैं। केन्द्र द्वारा 22,490 करोड़ रु. के एव राज्यों द्वारा 22,212 करोड़ रु. के अतिरिक्त साधन जुटाये जायेंगे। राज्य सरकारों की इस दिशा में भारी चुनौती का सामना करना है। राज्य विद्युत मण्डलों के आगामी 5 वर्षों के सम्भावित 11,757 करोड़ रु. के घाटों को 7000 करोड़ रु. की वचनों में बदलना है। राज्य सड़क-परिवहन-निगमों के सम्भावित 1,434 करोड़ रु. के घाटों को 2200 करोड़ रु. के तानों में बदलना है। इन्हीं प्रकार सिंचाई परियोजनाओं से भी प्रतिफल प्राप्त करने हैं। ये कार्य काफी कठिन जान पड़ते हैं। सातवीं योजना में अतिरिक्त साधन-समग्र का योगदान $\frac{1}{3}$ भाग गया है।

5. विदेशों से पूँजी का शुद्ध आगम—यह प्रस्तावित परिव्यय का 10% रहा गया है। भारत की रियायती शर्तों पर विदेशों सहायता की अधिक आवश्यकता है।

6. घाटे की वित्त-व्यवस्था—यह प्रस्तावित परिव्यय का 7.8% रह्यो गयी है। लेकिन भूतकाल में यह तथ्य की $2\frac{1}{2}$ -3 गुनी रही है जिससे केवल इन तथ्य के आधार पर कोई निरास नहीं लिया जा सकता। 1983-88 के तीन वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था इस सीमा को पार कर गयी है। यह 18,463 करोड़ रु. तक पहुँच गयी है।

सातवी योजना के लिए दीर्घकालीन फिस्कल नीति की घोषणा दिसम्बर, 1985 में की गयी थी। इसमें अनुमान लगाया गया था कि कर-अनुपात (राष्ट्रीय आय का) 1984-85 में 16.3% से बढ़कर 1989-90 में 18.3% हो जायगा। सातवीं योजना के समक्ष साधनों का गहरा संकट उपस्थित हो गया है। एक तरफ सार्वजनिक उपक्रमों का भ्रश नहीं बढ़ पा रहा है जबकि भ्रान्तरिक कर्ज की राशि बहुत ऊँची हो गई है तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था भी ऊँची हो गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र में योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के प्राल्प की समीक्षा

विभिन्न योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के प्राल्प का अध्ययन करने से पता चलता है कि हम सम्बन्ध में अतिरिक्त साधन सग्रह, या तरिके ऋणों घाटे की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी सहायता का योगदान उल्लेखनीय रहा है। दुर्भाग्यवश सार्वजनिक उपक्रम विकास के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करने की दृष्टि से विफल रहे हैं। नीचे विभिन्न साधनों का योजनाओं में वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

५। (1) अतिरिक्त साधन सग्रह

(Additional Resource Mobilisation)

अतिरिक्त साधन-सग्रह का नियोजन की वित्तीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बड़ी हुई आय का उत्तरोत्तर अधिश भ्रश नियोजन के लिए उपलब्ध होने से ही विकास की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस कार्य को अतिरिक्त करारोपण (additional taxation) के द्वारा किया जा सकता है तथा साथ में सविस्ती की राशि में कमी की जा सकती है एवं उचित नीतियाँ अपनाकर सार्वजनिक उपक्रमों की वकती को बढ़ाया जा सकता है।

1950-51 में कर राजस्व राष्ट्रीय आय का लगभग 7% था जो बढ़कर 1984-85 में 16.3% पर आ गया है।

अतिरिक्त साधन सग्रह की प्रगति

(करोड़ रुपये)

प्रथम योजना	255
द्वितीय योजना	1 052
तृतीय योजना	2 892
तीन वार्षिक योजनाएँ	908
चतुर्थ योजना	4 280
पञ्चम योजना	10 300
छठी योजना	32 970
सातवी योजना (प्रस्तावित राशि)	44,702

तालिका से स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त साधन सग्रह (ARM) से छठी योजना में जुटाई गई राशि पाचवी योजना की तुलना में तिगुनी से भी अधिक थी।

अतिरिक्त साधन-सग्रह का उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। सघीय कर-राजस्व में राज्यीय कर-राजस्व की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा परोक्ष करों का योगदान ज्यादा ऊँचा रहा है। परोक्ष करों में भी सघीय उत्पादन शुल्कों की प्रगति काफी अधिक रही है। प्रथम योजना की अवधि में इनसे प्राप्त राजस्व राष्ट्रीय आय का 1% था जो तृतीय योजना में 4% हो गया। प्रत्यक्ष करों में आय-कर से राजस्व की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया है, लेकिन निगम-कर की प्रगति सराहनीय रही है। वृषिगत क्षेत्र में प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व की स्थिति सबसे ज्यादा निराशाजनक रही है। प्रथम योजना में वृषिगत प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व (कृषि-आयकर व भू-राजस्व) राष्ट्रीय आय का 0.71% था, जो बाद में काफी घट गया है। भविष्य में वृषिगत प्रत्यक्ष करों का उपयोग योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने की दृष्टि से अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई आय तथा योजनाओं के लिए साधन सग्रह—योजना-काल में कृषिगत क्षेत्र पर कर-भार नहीं बढ़ाया जा सका है। योजनाओं से इस क्षेत्र को काफी लाभ पहुँचा है। इसलिए इसे भावी विकास के लिए अधिक मात्रा में साधन प्रदान करने चाहिए। पिछले वर्षों में अधिक उपज देने वाली नस्लों के बाने एवं खाद सिंचाई व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से कुछ क्षेत्रों में वृषि की आमदनी बढ़ी है। बढ़ी हुई आय का कुछ अंश अधिक विकास में व्यवस्थित लगाया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में दो तरह के मत प्रकट किये गये हैं। एक तो यह कि सामान्य आय-कर का विस्तार कृषि-आय पर भी किया जाना चाहिए जिससे एक सीमा के बाद कृषि-आय पर भी वर्द्धमान दरों से आय-कर वसूल किया जा सके। इस मत का समर्थकों का कहना है कि आमदनी तो आमदनी है चाहे वह गैर-कृषि क्षेत्र से हो अथवा कृषि क्षेत्र से हो। इनमें कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। कृषि के व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति के जोर पकड़ने से आगे चलकर कृषि-आय व गैर-कृषि आय का भेद और भी अनुचित प्रतीत होने लगेगा। अतः ऐसे व्यक्ति कृषि-आय पर भी आय-कर लगाने का समर्थन करते हैं।

लेकिन कुछ व्यक्तियों का विचार है कि इस समय कृषि-आय पर आय-कर लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि पिछले वर्षों में ही कृषि के क्षेत्र में निविद्योग बढ़ा है और आय कर के लग जाने से यह भविष्य में हतोत्साहित होगा और कृषि में व्यवसायीकरण की प्रक्रिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कृषि-आय-कर के सम्बन्ध में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हैं। गैर-कृषि-आय-कर में

ही वर की काफी चोरी होती है, इसलिए ऐसे कर का विस्तार कृषि-भाय पर करने से कर की चोरी का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जायगा।

दूसरा मत यह है कि देहातो में ऐच्छिक वचत को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे ग्रामीण कृण-पत्र (हिबेन्चर) बेचकर, जीवन बीमा का प्रचार बढ़ाकर, बैंकिंग व डाकघरों की सुविधा पटुँचाकर लोगों को अधिक वचत के लिए प्रेरित किया जा सके। सरकार आवश्यकतानुसार कृषिगत साधनों जैसे उर्वरक व मीजार आदि के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता (subsidy) भी कम कर सकती है। इस प्रकार बँतों द्वारा ग्रामीण आय में से विकास के लिए साधन जुटाने के कई उपाय हैं जिनका यथासम्भव उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार ध्यावसायिक फसलों पर विशेष कर (cess) लगा सकती है, जोतों के आकार के अनुसार भूराजस्व की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है, इत्यादि। लेकिन इन मुक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए राजनीतिक इच्छा-शक्ति की निराल आवश्यकता है।

(2) सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ प्राप्त करना

कराचोदण से प्रतिरिक्त साधन जुटाने में कठिनाइयाँ होने के कारण सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों से अधिक वचत प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। 31 मार्च, 1988 को केन्द्रीय सरकार के गैर-विभागीय व्यावसायिक व औद्योगिक उपक्रमों में लगभग 58125 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। 1987-88 में सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में लगी पूँजी पर प्रतिशत दर (rate of return on capital employed) 12.2% प्रतिशत थी तथा इसी वर्ष कर के पश्चात् शुद्ध लाभ की राशि 2183 करोड़ रु रही जो पिछले वर्ष से अधिक थी। भविष्य में लाभ की मात्रा में और वृद्धि की जानी चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य-नीति में परिवर्तन करके, उनका लागत में कमी करके एवं प्रवन्धकीय कार्यकुशलता में सुधार लाकर प्रतिक्रिया बढ़ाये जा सकते हैं। रेल, डाक-तार विभाग, राज्य विद्युत् बोर्ड तथा सड़क-परिवहन निगमों की कार्य-प्रणाली में सुधार करके इनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाया जाना चाहिए।

(3) घाटे की वित्त-व्यवस्था

अध्याय के प्रारम्भ में बताया जा चुका है कि जब कुल सरकारी व्यय (पूँजी + राजस्व) सरकारी आय (पूँजी + राजस्व) से अधिक हो जाता है तो सरकार उनकी पूति रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेकर करती है। इसके लिए सरकार की रिजर्व बैंक के पास पड़ी हुई नकद बचाया राशियों का उपयोग किया जा सकता है एवं ट्रेजरी बिल बचकर रिजर्व बैंक से उधार लिया जा सकता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था के आकड़े सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति अग्रप्राप्तता (दीर्घ-वालीन एवं अल्पवालीन दोनों) के परिवर्तनों को सूचित करते हैं। राज्य सरकारों भी बैंकों से उधार लेकर भोवरद्वारपट्ट की प्रक्रिया के द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था का उपयोग करती रही हैं।

हम पहले बता चुके हैं कि घाटे की वित्त-व्यवस्था साधन-संग्रह का एक जोखिम से भरा हुआ साधन है। इसमें मुद्रास्फीति का भय निहित है। कृपिगत पैदावार तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की स्थिति में तो इस अस्त्र का उपयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन उत्पादन न बढ़ने पर अथवा कम बढ़ने पर यह पद्धति गम्भीर मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती है। भारतीय योजनाओं में द्वितीय योजनावधि को छोड़कर, घाटे की वित्त व्यवस्था सदैव योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रही है और यह मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण मानी गई है।

निम्न तालिका में एक साथ विभिन्न योजनाओं में घाटे की वित्त-व्यवस्था के लक्ष्यों व वास्तविक स्थिति का परिचय दिया गया है—

(करोड़ रु में)

योजना	लक्ष्य	वास्तविक स्थिति
प्रथम योजना	290	333
द्वितीय योजना	1,200	954
तृतीय योजना	550	1,133
तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)	335	676
चतुर्थ योजना	850	2,060
पंचम योजना	1,354	3,560
छठी योजना	5,000	15,684
सातवी योजना (1985-90)	14,000	1985-88 के तीन वर्षों में लगभग 18463

इस प्रकार योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था में घाटे की वित्त-व्यवस्था का काफी मात्रा में उपयोग किया गया है। छठी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की घाटे की वित्तव्यवस्था का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक घाटे की वित्त-व्यवस्था लक्ष्य के तिगुने से भी अधिक रही है। इससे अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया है। सातवी योजना के प्रथम तीन वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था योजना के लक्ष्यों को पार कर चुकी है।

(4) विदेशी सहायता

भारत में नियोजित विकास के लिए विदेशी साधनों का उपयोग किया गया है। प्रति वर्ष विनियोग की दर व बचत की दर के अन्तर के बराबर विदेशी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता का उपयोग पहले की पंचवर्षीय योजना से अधिक मात्रा में किया गया है। परिणामस्वरूप, देश पर ऋण-सेवा का भार बढ़ता गया है। भारत राज भी विदेशी सहायता पर आश्रित है।

विदेशी सहायता के भार को अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब हमें पुराने ऋणों का नुगतान करने के लिए नये ऋण लेने पड़ रहे हैं। अनुयोजना में विदेशी सहायता की मात्रा को ऋण की श्रदायगी व व्याज की निकालकर योजना के धन में योजना के प्रारम्भ के स्तर की तुलना में घावा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। भारत रियायती गनों पर विदेशी सहायता से मुक्त होना चाहता है। लेकिन मूँड तेल व पेट्रोल-पदार्थों के भावों में वृद्धि होने से छठी योजना की अवधि (1980-85) में हमें पुनः अर्थिक माना में विदेशी सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। नवम्बर, 1981 में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 बिलियन SDR, अथवा 5,234 करोड़ रुपये, का ऋण मंजूर करवाया था ताकि नुगतान-असन्तुलन की समस्या का सामना किया जा सके। बाद में इसमें से 3.9 बिलियन SDR का उपयोग करके शेष 1.1 बिलियन SDR की किस्त न लेन का निर्णय घोषित किया गया था।

भावी योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए सुझाव

भारत में सार्वजनिक बचतों (Public savings) में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि मावजनिक विनियोगों के लिए अधिक साधन जुटाए जा सकें। वित्त के कुछ नये बात इन प्रकार हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए—

(i) चुन हुए ढग पर सस्मिडी की राशि कम की जानी चाहिए। ज्वरको माद्य (food), निर्यातों, निम्नित वस्त्र, आदि पर अनमान दरा पर सस्मिडी की राशिया काफी ऊँची हैं और ये काफी बढ़ गई है। 1989-90 के बजट अनुमानों में साठाल्ना पर सस्मिडी की राशि 2,200 करोड़ रु. तथा उर्वरकों पर 3651 करोड़ रु. एवं निर्यातों पर 1621 करोड़ रु. रखी गयी है। सस्मिडी का वित्तीय भार आज भी काफी ऊँचा बना हुआ है। प्रयत्न करके विभिन्न सस्मिडी की राशिया में कमी की जानी चाहिए ताकि योजना के लिए अर्थिक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकें। इसके लिए साठाल्नों व उर्वरकों के भावों में वृद्धि करनी होगी।

(ii) केन्द्रीय मावजनिक क्षेत्र व औद्योगिक व व्यावसायिक उपक्रमों का वर्तमान मध्य में (रु. के बाद) कम प्रतिफल मिलता है जिसमें वृद्धि की जानी चाहिए और इनके लिए इनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जाना चाहिए तथा मूल्य-नीति में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय व राज्य परिवहन उपक्रमा, राज्य व मिचार्ड व विद्युत-परि-याजनाओं व इनके अन्य उपक्रमों के प्रतिष्ठान भी बढ़ाये जाने चाहिए। राज्यों व मिचार्ड के उपक्रमा तथा राज्य विद्युत-मण्डलों से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का नुदा होता है। प्रत मिचार्ड व विद्युत-परिपोजनाओं के बाट कम किए जाने चाहिए। 198-89 में राज्य संरक्षण परिवहन उपक्रमों को 272 करोड़ रु. व राज्य विद्युत बाडों को 2702 करोड़ रु. का बाटा होन का अनुमान है जो 1989-90 में बढ़े। इसमें स्थिति की कमनीरता का अनुमान लगाया जा सकता है।

(iv) भू-राजस्व में वर्द्धमान दर से सरचार्ज जोड़े जाने चाहिए।

(v) बाजार में आने वाले कृषिगत माल पर उपकर (cess) लगाया जाना चाहिए और

(vi) भूमि व सम्पत्ति के स्वामियों के पूँजीगत लाभों का एक अंश सरकार को प्राप्त होना चाहिए। करो की वसूली में सुधार किया जाना चाहिए।

गैर-योजना धन्य की वृद्धि में कमी की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र के अन्तर्गत हानि वाले विलासी उपभोग में कमी की जानी चाहिए। मौद्रिक नीति व राज-राणीय नीति का समन्वित उपयोग करके साधन-समृद्ध गैर-स्फीतिकारी (non-inflationary) बनाया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान उत्पादन-क्षमता का अधिक उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के लिए साधन जुटाने की दिशा में अधिक प्रगति हो सके।

इस प्रकार भावी योजनाओं में सार्वजनिक व्ययों को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को राजस्व खाते में व्ययों तथा सरकारी उपक्रमों से मुक्त बचतें होंगे। योजनाओं के वित्तीय साधन जुटाने की समस्या बहुत गंभीर मानी गयी है। यह गैर-स्फीतिकारी होनी चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भावी नियोजन की बहुत कुछ सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार योजना के लिए गैर-स्फीतिकारी ढंग से साधन जुटा पाती है अथवा नहीं।

प्रश्न

- 1 भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय स्रोतों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिये। (Raj Iyer T D C, 1987)

उत्तर-मकेत—सातवीं योजना में एक लाख अस्सी हजार करोड़ रु के प्रस्तावित सार्वजनिक परिव्यय की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का अंशदान 1/5 आन्तरिक ऋण (विविध साधन) का 2/5, अतिरिक्त साधन-समृद्ध का 1/4 विदेशी पूँजी का 1/10 व घाटे की वित्त व्यवस्था का 7.8% का लगभग 1/13 रखा गया है। चालू राजस्व से बढ़ाया राशि के 3% आस्पादमक रहने का अनुमान है।

20 मई, 1987 को योजना आयोग की एक बैठक में सातवीं योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए गैर-स्फीतिकारी साधन बढ़ाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा राजा जे वेल्सेया ने पेपर पर विचार किया गया और निम्न निर्णय लिये गये

(1) खाद्यान्नों व उर्वरकों पर से सब्सिडी घटायी जायेगी।

(2) कर-अनुपात (tax-ratio) (राष्ट्रीय आय से अनुपात के रूप में) सातवीं योजना के अन्त तक 2 प्रतिशत बिन्दु बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे, ये बातें पहले भी की जा चुकी हैं और कोई नई नहीं हैं।

The Economic Time के 14 दिसम्बर 1987 के अंक में प्रकाशित सूचना के अनुसार सातवी योजना के समस्त वित्तीय साधनों का अभाव उत्पन्न हो गया है। 1985-88 तक के तीन वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था 14000 करोड़ रु के ऋण से 4463 करोड़ रु अधिक हो चुकी है तथा सावजनिक उपक्रमों (के. ड. व. राज्य दोनों) का अग्रदान इसी अवधि में ऋण का 40% ही हो पाया है तथा सम्भवतः पाँच वर्षों में 50% तक ही पहुँच पायेगा। केन्द्रीय बजट में अतःतुलन पैदा हो गया है। पूँजीगत प्राप्ति से राजस्व-घाटों की पूर्ति को जाने लगी है जो एक भारी राजकोषाय त्रुटि व अतःतुलन का परिचायक है।

- 2 योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने की दृष्टि से निम्नलिखित का विवेचन कीजिए—
(i) घाट की वित्त व्यवस्था (deficit financing) (ii) विदेशी सहायता।
- 3 भारतीय योजनाओं में साधन संप्रदा की दृष्टि से किन मदों का विशेष योगदान रहा है? इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण दीजिए।
- 4 छठी योजना व सातवी योजना की वित्तीय व्यवस्था की तुलना कीजिए एवं इनके अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- 5 मन्त्रिपरिषद् की रिपोर्टों में निम्नलिखित—
(i) घाटे की वित्त व्यवस्था

(Raj Hys T D C 1988)

भारत में आय का असमान वितरण (Unequal Distribution of Income in India)

भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण के आंकड़े लम्बी अवधि के लिए नहीं मिलते, इसलिए हमें राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के द्वारा उपभोग-व्यय (Consumption expenditure) के आंकड़ों का उपयोग करना होता है जो 1973-74 तक नियमित रूप से प्रति वर्ष इकट्ठे किये जाते रहे तथा बाद में प्रति पाच वर्षों के अन्तर से इकट्ठे किये जाते रहे हैं। आगे चलकर 1977-78 व 1983 की अवधि के उपभोग-व्यय के वितरण के आंकड़ों का उपयोग किया गया है ताकि भारत में उपभोग की असमानता की जानकारी हो सके।

लेकिन इससे पूर्व हम विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए 1975-76 की अवधि से सम्बन्धित आय के वितरण के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो निम्न तालिका में दिये गये हैं—

भारत के लिए आय की असमानता की सारणी, ¹ 1975-76

पारिवारिक आय के खण्ड (नीचे से) (1)	1975-76 आय का प्रतिशत (2)	परिवारों का संचयी (cumulative) प्रतिशत (3)	1975-76 में आय का वास्तविक वितरण (संचयी) (4)
निम्नतम 20%	7.0	20	7.0
दूसरा 20%	9.2	40	16.2
तीसरा 20%	13.9	60	30.1
चौथा 20%	20.5	80	50.6
चोटी के या सर्वोच्च 20%	49.4	100	100.0

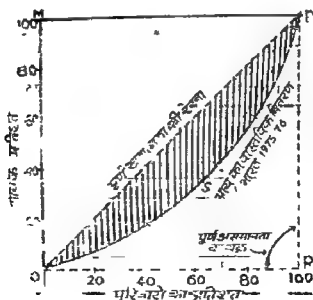
1. World Development Report 1989, p. 222, table 30 on Income Distribution.

विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सारणी में यह भी बताया गया है कि भारत में चोटी के 10% परिवार कुल आय का 33.6% अथवा लगभग 1/3 अंश प्राप्त करते हैं।

उपयुक्त तालिका से पता चलता है कि भारत में 1975-76 में निम्नतम आय वाले 20 प्रतिशत परिवारों के पास कुल आय का केवल 7 प्रतिशत अंश था, जबकि चोटी के 20 प्रतिशत परिवारों के पास 49.4 प्रतिशत आय अथवा आधी आय थी। इसी प्रकार तालिका से हम अन्य खण्डों के लिए भी कुल आय का अंश देख सकते हैं।

अतः उपयुक्त सारणी से भारत में आय की असमानता की जानकारी हो सकती है। सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवार 7 प्रतिशत आय पर गुजारा करते हैं, जबकि सबसे धनी 20 प्रतिशत परिवार लगभग आधी आय का लाभ उठाते हैं।

सारणी के कॉलम (3) व (4) का उपयोग करके आय के वितरण का वक्र बनाया जा सकता है जो लोरेन्ज-वक्र (Lorenz curve) कहलाता है। लोरेन्ज



वक्र कॉन्ट्राड लोरेन्ज (Contrad Lorenz) के नाम पर है जो एक प्रमरीकी सांख्यिक था जिसने 1905 में एक चित्र पर जनसंख्या-समूहों व सापेक्ष आय के अंशों के बीच परस्पर सम्बन्ध बतलाया था।

अतः यह वक्र प्रायः आय की असमानता के अध्ययन में प्रयुक्त होता है—

स्पष्टीकरण

चित्र में OR—अक्ष पर परिवारों के प्रतिशत मापे गए हैं तथा OM—अक्ष पर आय के प्रतिशत लिये गये हैं। दोनों तरफ संचयी प्रतिशतों को लेकर बिन्दु प्रकट करने पर OSP लोरेन्ज-वक्र बनता है जो प्राय की असमानता का सूचक है। OP पूर्ण समानता की रेखा है जिसका अर्थ है 10%, परिवारों के पास 10% आय है तथा 20% परिवारों के पास 20% आय है (आदि) तथा ORP पूर्ण असमानता की रेखा है, अर्थात् एक परिवार के पास समस्त राष्ट्र की आमदनी है और शेष के पास कुछ भी नहीं है।

OP व OSP के बीच के क्षेत्रफल का माप जिनी-अनुपात (Gini-ratio) या सकेन्द्रण-अनुपात (Concentration-ratio) कहा जाता है, जो प्राय की असमानता का माप कहलाता है। जब OSP वक्र बायीं ओर खिसकता है तो असमानता बढ़ती है और जब यह बायीं ओर OP की तरफ खिसकता है तो असमानता घटती है। हम आगे चलकर उपभोग-व्यय के वितरण का उल्लेख करते समय जिनी-अनुपात या सूचकांक का उपयोग करेंगे। इसका माप लगभग 0.34 आता है। इसकी गणना की विधि इस अध्याय के अंत में एक परिशिष्ट में दी गई है जिसका आवश्यकता-नुसार उपयोग किया जा सकता है। जिनी-अनुपात इटली के सांख्यिक सी. जिनी ने 1912 में विकसित किया था।

भारत में उपभोग-व्यय में असमानता

(Inequality in Consumption-expenditure in India)

जैसा कि पहले कहा जा चुका है भारत में प्राय की असमानता के अध्ययन में उपभोग-व्यय की असमानता का अध्ययन राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

1977-78 में उपभोग-व्यय की असमानता को सूचित करने वाला जिनी-अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 0.336 रहा तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 0.345 रहा। विभिन्न वर्षों के लिए इन अनुपातों में मामूली उतार-चढ़ाव आते रहे हैं जिनसे दीर्घकालीन प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निश्चित स्थिति का पता नहीं लग पाता है। फिर भी 1951 में जिनी-अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 0.334 व शहरी क्षेत्रों के लिए 0.384 रहा था जिससे पता चलता है कि 1951 से 1977-78 की अवधि में

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग-व्यय की असमानता मामूली बढ़ी तथा शहरी क्षेत्रों में मामूली घटी। कुल मिलाकर असमानता यथावत् जारी रही है।

यह ध्यान देने की बात है कि खाद्यान्नों के उपभोग-व्यय में असमानता का अनुपात ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल उपभोग-व्यय की असमानता के अनुपात से नीचा रहा एवं वस्त्रों के उपभोग में यह अपेक्षाकृत ऊँचा रहा। ये निम्न तालिका में दर्शाए गये हैं

क्षेत्रों	जिनी अनुपात 1977-78 ¹		समस्त उपभोग-व्यय
	खाद्यान्न	वस्त्र	
ग्रामीण	0.131	0.582	0.336
शहरी	0.077	0.607	0.345

चूँकि नीची आयदरती पर कुल व्यय का मोजन पर व्यय होने वाला अनुपात ऊँचा होता है, इसलिए आयदरती के बढ़ने पर यह अनुपात घटता जाता है। प्रत खाद्य-व्यय की असमानता कुल व्यय की असमानता से नीची होती है। वस्त्रों पर व्यय की असमानता अधिक होती है क्योंकि खाद्यान्नों के भाव बढ़ने से वस्त्रों पर व्यय के लिए धनराशि घट जाती है जिससे निर्धन व निम्न-मध्यम व मध्यम श्रेणी के लोगो की वस्त्र पर उपभोग-व्यय घटाना पड़ता है।

प्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय की असमानता का अनुपात कुछ राज्यों के लिये 1977-78 की अवधि के लिए नीचे दिया जाता है :

1977-78 (जिनी-अनुपात)			
(क) सर्वाधिक	राजस्थान	ग्रामीण	शहरी
	भारत	0.465	
	केरल	0.336	0.395
	भारत		0.345
(ख) न्यूनतम	बिहार	0.258	
	जम्मू-कश्मीर		0.294

इस प्रकार 1977-78 में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यय की असमानता का अनुपात राजस्थान में अधिकतम तथा शहरी क्षेत्रों में केरल में अधिकतम रहा।

1 R. M. Sundrum, *Growth and Income Distribution in India ; Policy and Performance Since Independence*, 1987, p. 139. मागे का अधिकांश विवेचन इसके अध्याय 6 व अध्याय 10 पर प्रापारित है।

गामीण क्षेत्रों में न्यूनतम अनुपात बिहार में तथा शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम जम्मू-कश्मीर में रहा।

एत. पी. गुप्ता व के. एत. (योजना आयोग)द्वारा के अनुसार उपभोग-व्यय के लिए जिनी-गुणोत्तर या अनुपात 1977-78 व 1981 के लिए इस प्रकार रहे :

वर्ष	गामीण	शहरी
1977-78	0.337	0.351
1981	0.297	0.132

इस प्रकार 1977-78 से 1981 की अवधि में उपभोग-व्यय में जिनी-अनुपात शहरी व गामीण दोनों क्षेत्रों में कुछ कम हुआ है लेकिन यह शहरी क्षेत्रों में गामीण क्षेत्रों से अधिक पाया गया है।

भारत में आय व उपभोग व्यय के असमान वितरण के कारण

भारत में पूँजीवादी मिश्रित व नियोजित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक विकास किया जा रहा है। आर्थिक विकास के प्रारम्भिक वर्षों में बहुधा आय की असमानता बढ़ती है। विकास के अधिकारण लाभ सम्पन्न वर्ग को मिलते हैं और निर्धन लोग विकास के लाभों से वंचित हो जाते हैं। भारत में आय की वर्तमान असमानता के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है :

1. गामीण क्षेत्रों में भूमि का असमान वितरण .—आय व व्यय के लिए वितरण की असमानता का प्रधान कारण परिसम्पत्तियों के वितरण की असमानता माना गया है। गामीण क्षेत्रों में भूमि ही परिसम्पत्ति का मुख्य रूप होती है। इसके अलावा पशु, ट्रैक्टर, मीज़ार आदि भी परिसम्पत्ति के अन्तर्गत आते हैं। गामीण क्षेत्रों में भूमि के वितरण की असमानता में योजनाकाल में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। 1960-61 में 1 हेक्टेयर तक की जोते 41% थीं जिनके अन्तर्गत जोते गये क्षेत्र का 7% अंश पाया गया था। इसी वर्ष 10 हेक्टेयर की जोते 5% थी, तबिन इनके अन्तर्गत 31% क्षेत्रफल पाया गया था। इस प्रकार भूमि के वितरण में कार्यशील जोतों के अनुसार भारी असमानता थी। 1980-81 में 1 हेक्टेयर तक की जोतों का अंश बढ़कर 56.5% हो गया और इनके अन्तर्गत वृद्धित क्षेत्र 12% हो गया, जबकि 10 हेक्टेयर से अधिक की जोतों का अंश 2.4% लेकिन क्षेत्रफल 23% पाया गया। इस प्रकार योजनाकाल के बीस वर्षों में भूमि का वितरण असमान बना रहा। बड़े भूस्वामी सिंचाई, बीज, उर्वरक, साख, आदि की सुविधाओं का लघु व सीमांत कृषकों तथा सेमिहर मजदूरों की तुलना में अधिक लाभ उठा पाते हैं। इससे

उनकी ग्रामदनी का स्तर भी अपेक्षाकृत ऊँचा होता है। हरित क्रान्ति का लाभ भी उन्होंने उठाया है।

भूमि सुधार कानूनों ने भूमि के वितरण को बदलने की दृष्टि से विशेष सफलता हासिल नहीं की है। जापान, तैवान व दक्षिण कोरिया में परिसम्पत्तियों का प्राथमिक वितरण काफी समान कर दिया गया था जिससे विकास के दौरान उन देशों में आय की असमानता में गिरावट आयी है।

भारत में कार्यशील जोतों के वितरण का जिनी-अनुपात 1970-71 में 0.6207 तथा 1980-81 में 0.6063 रहा है। भूत भूमि के वितरण में असमानता कुछ कम हुयी है, लेकिन फिर भी यह काफी ऊँची है और आज भी बनी हुयी है। राजनीतिक सत्ता पर भूस्वामियों का विशेष प्रभाव होने के कारण भूमि के सम्बन्ध (Land-relations) अधिक प्रगतिशील नहीं बन पाये है। विस्तृत क्षेत्रों में मौखिक काश्तकारी, फसल-बटाई प्रणाली, भूमिहीन काश्तकारों की पिछड़ी हुयी आर्थिक दशा, वन्धुप्राथमिकी की शोषणमूलक काम की दशाएँ आज भी व्याप्त है। भारत में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, परिसम्पत्ति के वितरण की भारी असमानता वहाँ आय की असमानता का मुख्य कारण रही है।

2. औद्योगिक जगत ने बड़े व्यावसायिक घरानों का परिसम्पत्ति पर अधिकार-पहले बताया जा चुका है कि देश के छोटी के 10 औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्ति 1936-87 से 18638 करोड़ रु. थी। इसमें पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुयी है। इन 10 औद्योगिक घरानों का निजी क्षेत्र की परिसम्पत्ति के बड़े अंश पर अधिकार पाया जाता है। टाटा-बिड़ला औद्योगिक घरानों के पास इन 10 घरानों की परिसम्पत्ति का लगभग आधा अंश पाया जाता है।* औद्योगिक घरानों में पारिवारिक प्रबन्ध की शैली चलती है जिनमें कुछ व्यक्तियों को निर्णय लेने के सम्बन्ध में व्यापक विस्म के अधिकार होते हैं जिनका उपयोग करने से समाज में असमानता को बढावा मिलता है। बड़ी कम्पनियों के छोटी के प्रबन्धकों के वेतन भत्ते व अन्य देय राशियाँ इतनी ऊँची होती हैं कि वे देश की औसत आय से कहीं मेल नहीं खाती। यही बात बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रबन्धकों, संचालकों

* 1986-87 में टाटा की परिसम्पत्ति का मूल्य 4940 करोड़ रु व बिड़ला की परिसम्पत्ति का 4771 करोड़ रु. पाया गया। इन दोनों घरानों की परिसम्पत्ति का मूल्य 11 व्यावसायिक घरानों (रिलायन्स, जे. के. सिनानिया, थापर, मफलतलाल, मोदी, सार्वजनिक एण्ड टूथ्रो, एम. ए. चिदाम्बरम व बजाज सहित) की परिसम्पत्ति का 52% था।

The Economic Times, May 4, 1989.

मैनेजिंग डाइरेक्टरो, चेयरमैनो, आदि पर लागू होती हैं। इस प्रकार भारत में दो अलग-अलग किस्म के सप्ताह पाये जाते हैं—एक बड़े लोगों का और दूसरा छोटे लोगों का। इनमें विशाल अन्तर—सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि, देखने को मिलते हैं।

3 शिक्षा के अवसरों में असमानता.—भारत में शिक्षा का काफी फैलाव हुआ है। शिक्षा का विस्तार एक समताकारी तत्व माना गया है। इससे लोगों की शैक्षणिक असमानता कम होती है। लेकिन आज भी उच्च शिक्षा पर ज्यादातर कुलीन व सम्भ्रान्त परिवारों की सत्ता का अधिक प्रभाव देखा जाता है और वे ही इनका अधिक लाभ उठा पाते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग उच्च शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, चाहे उनको रिजर्वेशन के कुछ लाभ भए ही मिल जाए। रिजर्वेशन में भी इन वर्गों के छोटी व लोग ही अधिक लाभ उठा पाते हैं। इस प्रकार शिक्षा, विज्ञान व टेक्नोलॉजी के लाभों का असमान वितरण होने से आय की असमानता में वाछित कमी नहीं हो पायी है।

4 काली मुद्रा का प्रसार—भारत में एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था (a parallel economy) चल रही है जो कर-चोरी, रिस्कन भ्रष्टाचार, व अनेक प्रकार गैर-कानूनी कान घन्घे से बनी है। 1983-84 में काली मुद्रा की राशि 32 हजार करोड़ रु से 37 हजार करोड़ रु के बीच में थी जो राष्ट्रीय आय का 18% से 21% थी। सर माल्कम आदिशौमा ने 1984-85 के लिए इसका अनुमान 80000 करोड़ रु दिया है जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 40% है।¹ योजनाकाल में काली मुद्रा का अत्यधिक विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति में आय की असमानता का घटना स्वभाविक है।

5 आय की अधिकतम वस्तुनतम सीमाओं का निर्धारण न होने से असमानता का कोई भी अन्तर पाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यहाँ कोई राष्ट्रीय आय-नीति नहीं है। ऐसी स्थिति में असमानता को कम करना कठिन है।

6 मजदूरी व्याज, किराये व मुनाफों पर किसी प्रकार का नियमन व प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए आय की असमानताएँ बढ़ती जाती हैं। सरकार ने आय-कर में कई प्रकार की छूटें दे रखी हैं जिनका लाभ ऊँची आयदनी वाले लोगों को अधिक मिलता है। उदाहरण के लिए, सरकार नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) खरीदने पर आय कर में छूट देती है। इस प्रकार NSC खरीदने वाले को सर्वप्रथम आयकर में छूट मिल जाती है। उसके बाद उसको व्याज मिलता है जिससे उसको आयदनी प्राप्त होती है। विद्वानों का मत है कि इस तरह भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो पहले किसी तरह आयदनी जुटा लेता है, फिर उस आयदनी से नई आयदनी पैदा करता जाता है जिससे उसके पास आयदनी का

विस्तार होता जाता है। ऐसे समाज में आय की विषमता न बढ़ेगी तो और क्या होगा ?

7. विविध कारण :—भारत में अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगे हुये हैं। राजनीतिक नेता, सरकारी अफसर, बड़े व्यवसायी, बड़े किसान व बड़े व्यापारी मिल कर विभिन्न प्रकार के कानूनों का उपयोग अपने हितों की भांने बढ़ाने में करते हैं। इनमें सर्वसाधारण के हितों की अपेक्षा की जाती है। बड़े किसान उर्वरक सन्निधि का लाभ उठाते हैं और अनाज के यमूली मूल्य ऊँचे करवा लेते हैं। इससे उनके हितों की तो पुष्टि हो जाती है, लेकिन देश पर गैर-योजना व्यय का भार बढ़ जाता है।

इस प्रकार भारत में ऊँची लागत वाली उद्यार्थकृताय अर्थव्यवस्था के मंचालन में मुद्रास्फोति को दृष्टाएं सर्वे विद्यमान रहती हैं। पाठों की अर्थव्यवस्था के कारण मुद्रा का प्रसार करना होता है जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है और मांग व पूर्ति का सतुवन बिगड़ जाता है। कृहने का माशय यह है भारत की तथाकथित नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, आयात-निर्मात, बचत-विनियोग वृद्धि-गत व प्रौद्योगिक क्षेत्रों, लघु व वृहद् क्षेत्रों में कहीं भी विवेकशील व उत्पादक नीतियों का क्रियाव्ययन दिखलाई नहीं देता। इसलिए जो बड़े राजनीतिक सधर्म करके अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, वह तो अपनी आमदनी को बढ़ा लेता है, चाहे इस प्रक्रिया में व अन्य बर्षों को क्षति पहुँचा बैठे।

आय के असमान वितरण को ठीक करने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय

1. प्रगतिशील आयकर.—कुछ वर्ष पूर्व भारत में आयकर की अधिकतम सीमान्त दर काफी ऊँची थी। लेकिन सरकार ने इसमें बर्षों करके कर-राजस्व को बढ़ान की नीति अपनायी है। 1989-90 के केन्द्रीय बजट के अनुसार अब एक लाख रुपय से अधिक की आय पर आयकर की दर 50% है तथा 50 हजार रु करदय आय से ऊपर की श्रेणी में आयकर पर 8% रोजगार-सरचाज होने से आयकर की अधिकतम सीमान्त दर इस समय 54% है। भारत में प्रत्यक्ष करों की काफी घरी होनी है जिसका राकन के लिए कर-प्रशामन की सुदृढ बनाया गया है।

2. व्यावसायिक व व्यापारिक प्रविष्ठानों पर छूटे, तत्परशिर्षा, जत्तियाँ, आचान व कानूनी कार्यवाइर्षा—सरकार काले घन व काली मुद्रा को बाहर निकालन के लिए व्यावसायिक व प्रौद्योगिक प्रविष्ठानों पर छूप डलवाती है तथा उनसे छुपायो गयी आय पर कर वनून करन का प्रयान करती है। यह एक लम्बी व जटिल प्रक्रिया है और इसमें डिलार्ई आने से कठिनाइर्षा उत्पन्न हो सकती है।

3 सरकार ने मूधिसुधार सम्बन्धी कानून बनाये हैं जिनकी यजह से काननकारों के हितों की रक्षा की गयी है। काश्तकारी प्रधा में सुधार करने से कुछ

सीमा तक कास्तकारों को भूमि का स्वामी बनने का अवसर मिला है। लेकिन 'सीलिंग कानून' व्यावहारिक में ठीक से लागू नहीं हो पाया है।

4. सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के अन्तर्गत गरीबी दूर करने के लिए परिसम्पत्ति वितरण का कार्यक्रम अपनाया है जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NRLP), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार भारती कार्यक्रम (RLEGP) आदि के माध्यम से मजदूरी रोजगार (Wage-employment) बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसे जवाहर रोजगार योजना (JRY) में मिला दिया गया है। इस प्रकार गरीबी दूर करने व रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रमों के माध्यम से आय की असमानता को कम करने के प्रयास जारी हैं।

5 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (Social Security Measures) के माध्यम से आय के वितरण को ठीक करने का प्रयास किए जा रहे हैं। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, प्रभृति-सहायता, बुढ़ापा, आदि के लिए सहायता पहुँचाकर लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

6. कीमत-नियन्त्रण व वस्तु-वितरण की सार्वजनिक प्रणाली अपनाकर निर्यन्त-वर्ग के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। अनाज, चीनी, खाद्य-तेल, व अन्य मजदूरी-वस्तुओं (Wage-goods) का उत्पादन बढ़ाकर व राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके निर्यन्त-वर्गों को कम कीमतों पर आवश्यक वस्तुएँ भी सप्लाई करने से उसकी क्रयशक्ति की रक्षा की जा सकती है।

7 सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार व एकाधिकार पर नियन्त्रण भारत में समाजवादी समाज की ओर अग्रसर होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया है तथा एकाधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए MRTP अधिनियम, 1969 बनाया गया है। इनसे निजी क्षेत्र की क्रियाएँ सीमित हुई हैं। लेकिन देश में आय की असमानता को कम करने की दृष्टि से विशेष अग्रगण्य अभाव सामने नहीं आया है।

भारत में आय की असमानता को कम करने के लिए आगामी दशक के लिए उपयोगी सुझाव

1 आय की असमानता घटत-परिसम्पत्ति के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। अतः जब तक समाज में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भूमि, धूँजी, आदि का वितरण असमिका समान नहीं बनाया जाता तब तक आय की असमानता कम नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यकतानुसार सहकारी संगठन का विस्तार किया जा सकता है एवं सार्वजनिक उपक्रमों में व निजी उपक्रमों में आय की प्रवृत्ति, धूँजी व लाभ में समता

की व्यवस्था की जा सकती है। अतः पूँजी के स्वामित्व के फैलाव या विकिरण की कोशिश की जानी चाहिए, जैसा कि कई यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, इटली, आदि में किया गया है।

2 प्राधुनिक टेक्नालोजी पैमाने की उत्पादों व प्रतिस्पर्धा (मान्तरिक व बाह्य) को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को अत्यधिक उत्पादक कार्यकुशल व विकासमूल बनाया जाना चाहिए जिससे 'रोटी की बाँटने से पूर्व' इसका आकार बड़ सके। कुछ विद्वानों का मत है कि 'वितरण की बिलासिता' अमीर मुल्क ही भोग सकते हैं। इसका अर्थ है कि गरीब मुल्क पहले अपने उत्पादन को ठीक करें, तभी आगे चलकर उनका वितरण ठीक हो पायेगा।

3 भारत को आगामी वर्षों में अपनी सम्पूर्ण शक्ति स्थायी हिस्म के रोजगार के अक्षर बढ़ाने में लगानी चाहिए। इसके लिए सीमित वित्तीय साधनों को प्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मजदूरी-रोजगार (wage-employment) को बढ़ाने में लगाना चाहिए ताकि सांशुदायिक परिसम्पत्तियों—सड़कों, नहरों, तलाबों, स्कूलों, मन्दिरों, चिकित्सा-मकानों, आदि का निर्माण किया जा सके और देश में उत्पादन क्षमता बढ़े। यह सब करने के लिए जिला व खण्ड-स्तरीय नियोजन के अन्तर्गत सुदृढ़ परियोजनाओं के अक्षर की आवश्यकता है जिसे विशाल प्रामीण समुदाय के सहयोग से कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े तथा साथ में उपभोग्य वस्तुओं की सप्लाई भी। इस विनाश रणनीति से सम्भवतः अधिक सहायता मिल पायेगी।

प्रश्न

1 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(1) भारत में आय का असमान वितरण।

2 'आय व समानता के साथ विकास करने की दृष्टि से भारत की स्थिति कैसी रही है? असमानता को कम करने के लिए कौन से उपायों का सहारा लिया गया है?

परिशिष्ट

1975-76 के लिए भारत में आय के वितरण के लिए जिनी-अनुपात (Gini-Ratio) की गणना की विधि :—

$100p_i$ (1)	आय का प्रतिशत (2)	$100Z_i$ (3)	$100(Z_i + Z_{i-1})$ (4)	$10^4 p_i (Z_i + Z_{i-1})$ (5) = (1) × (4)
20	7	7	7	140
20	9.2	16.2	23.2	464
20	13.9	30.1	46.3	926
20	20.5	50.6	80.7	1614
20	49.4	100.0	150.6	3012
				जोड़ 6156

जिनी-अनुपात (Gini-Ratio) या $G = 1 - \sum p_i (Z_i + Z_{i-1})$
 $= 1 - 0.6156 = 0.3844$ है।

[यहाँ तालिका में कॉलम (5) का जोड़

$$\sum 10^4 p_i (Z_i + Z_{i-1}) = 6156$$

$$\therefore \sum p_i (Z_i + Z_{i-1}) = \frac{6156}{10000} = 0.6156]$$

स्मरण रहे कि $G = 0$ पूर्ण समानता, तथा $G = 1$ पूर्ण असमानता को सूचित करते हैं।

तालिका के निर्माण का स्पष्टीकरण :

प्रथम कॉलम $100 p_i$ है, अर्थात् प्रतिशत के रूप में परिवारों के पाँच खण्ड दिये गये हैं। निम्नतम 20% परिवारों के पास 7% आय है तथा सबसे अमीर 20% के पास 49.4% आयदनी है।

कॉलम (3) में आय के संचयी (Cumulative) प्रतिशत दर्शाये गये हैं। प्रत्येक प्रतिशत निकालने के लिए उससे पूर्व का संचयी प्रतिशत जोड़ दिया जाता है जैसे 30.1 प्राप्त करने के लिए 16.2 में 13.9 जोड़ा गया है, आदि।

कॉलम (4) में $100 (Z_1 + Z_{1-1})$ दर्शाया गया है, अर्थात् कॉलम (3) की पाय-पास की दो मंदां जोड़त जाते हैं, जैसे $23.2 = 7 + 16.2$, तथा $46.3 = 16.2 + 30.1$ इत्यादि। कॉलम (5) = कॉलम (1) \times कॉलम (4) है $= 100 p_1 \times 100 (Z_1 + Z_{1-1}) = 10^4 p_1 (Z_1 + Z_{1-1}) = 10^4 p_1 (Z_1 + Z_{1-1})$ जो कॉलम (5) का जोड़ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

भारत में 1980-81 के लिए कार्यशील जोड़ों के वितरण सम्बन्धी आकड़ों का उपयोग करके निम्नी अनुपात या सबेदण-अनुपात शात कीजिए—

जोतों की क्रिम	कुल जोतों का (प्रतिशत)	उनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का (प्रतिशत)
सीमान्त जोतें	56.3	12
लघु जोतें	18	14
अर्द्ध-मध्यम जोतें	14	21
मध्यम जोतें	9.1	30
बड़ी जोतें	2.4	23
कुल	100.0	100.0

[जिनी गुणांक या अनुपात = 0.6063] उत्तर

आदि में जरूरत से ज्यादा व्यक्तियों के लगे रहने से प्रति व्यक्ति नीची आमदनी के कारण अल्परोजगार या अर्द्ध-रोजगार की दशा पायी जाती है।

अल्परोजगार के दो रूप—(i) दृश्य तथा (ii) अदृश्य

(i) दृश्य (Visible)—दृश्य अल्परोजगार मापा जा सकता है। यह मुश्त मौसम व कृषिगत क्षेत्र में या देहातो में स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों व ऐतिहासिक मजदूरों में पाया जाता है।

(ii) अदृश्य (Invisible)—अदृश्य अल्परोजगार का प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर बतसाया गया था यह स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों में वर्षभर पाया जा सकता है और अपर्याप्त काम (insufficient work) के कारण यह नीची उत्पन्न दक्षता व नीची आमदनी के रूप में प्रगट होता है। इसका परोक्ष माप करने के लिए हम लागे से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या वे प्रतिरिक्त काम करना चाहेंगे? इस प्रश्न के उत्तर पर अल्परोजगार का माप निर्भर करेगा। यह प्रश्न कृषि व गैर-कृषि में लगे स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों व मजदूरों पर काम में लगे श्रमिकों (नियमित मजदूरों तथा आकस्मिक (Casual) मजदूरों दोनों प्रकार के श्रमिकों) से तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लगे आकस्मिक मजदूरों वाले श्रमिकों से पूछा जा सकता है।

भारत में कृषि-कार्यों में लगे आकस्मिक श्रमिकों में अल्परोजगार की मात्रा 1983 में 33%- 9% तक पायी गयी थी। यह काफी ऊँची थी। वे प्रतिरिक्त काम करने को काफी सीमा तक तैयार थे।

विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप

जैसा कि प्रारम्भ में सकेत किया गया है विकसित व उद्योग-प्रधान पूँजीवादी देशों में बेरोजगारी का स्वरूप उपर्युक्त स्थिति से बिल्कुल भिन्न होता है। वहाँ प्रायः प्रभावपूर्ण मांग की कमी (lack of effective demand) के कारण कल-कारखाने बन्द हो जाते हैं और माँग में वृद्धि करने के उपाय अपनाने पर वे पुनः चालू हो जाते हैं। वहाँ पूँजी की कमी से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह पूँजी के उपयोग की कमी से उत्पन्न होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है भारत जैसे देशों में पूँजी की कमी के कारण श्रम-शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अतः हमें विकासशील व विकसित देशों की बेरोजगारी की स्थिति के इस मूलभूत अन्तर पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत जैसे देशों में प्रभावपूर्ण माँग की कमी से बेरोजगारी की दशा उत्पन्न नहीं होती। यहाँ भी 'माँग की कमी' कारण इन्जीनियरी तथा अन्य उद्योगों में बेरोजगारी की दशा पायी जा सकती है। लेकिन देश में व्यापक रूप से फैली हुई बेरोजगारी का मूल कारण पूँजी का अभाव माना जाता है, न कि पूँजी के उपयोग का अभाव।

अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या मूलतः अल्प-विकास (under-development) की समस्या ही मानी जा सकती है। अतः देश के तीव्र आर्थिक विकास से ही अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और जन-शक्ति के आधिव्यय की समस्या हल की जा सकती है। भारत में भी विनिवेश तथा देहातों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की अनेक सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जिनका उपयोग करने से विशाल जन-समूह को लाभप्रद रोजगार मिल सकता है। यह एक विचित्र रिस्म का विरोधाभास है कि एक तरफ देश में अनेक प्रकार के काम करने वाली पड़े हैं और दूसरी तरफ काम करने वाले काफी लोग बेकार बंटे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देश में इस प्रकार का आर्थिक नियोजन अपनाया जाय जिससे नाना प्रकार के कामों में विशाल जन समुदाय को लगाया जा सके। इस सम्बन्ध में सरकार को विशेष रूप से सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लोकतान्त्रिक देश में लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की ही मानी जानी है।

भारत में बेरोजगारी का माप

भारत में बेरोजगारी व अल्परोजगार की समस्या व्यापक रूप से फैली हुई है। देहातों में अल्प-रोजगार (under-employment) की समस्या का विशेष प्रभाव है और शहरों में खुली बेरोजगारी की समस्या पायी जाती है। इन दोनों को हम एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि जब देहातों में अल्प-रोजगार की स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है तो लोग वहाँ से परेशान होकर रोजगार की तलाश में नगरो व महानगरो की तरफ धल पड़ते हैं, अर्थात् पढ़ूँचने पर खुली बेरोजगारी की स्थिति अधिक जटिल हो जाती है। देहातों में अशिक्षित व अदक्ष (unskilled) श्रम की बेरोजगारी की समस्या अधिक तीव्र होती है तो शहरों में शिक्षित व दक्ष (skilled) श्रम की बेरोजगारी की समस्या विशेषरूप से तीव्र होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इंजीनियर व डाक्टर भी बेरोजगारी के शिकार पाये जाते हैं, जो वास्तव में एक चिन्ता का विषय है। बेरोजगारी कहीं भी और किसी भी वर्ग में क्यों न हो, यह समाज पर एक असहनीय भार के रूप में होती है। यह मानव को निराश कर देती है और उसके नैतिक बल में गिरावट लाती है। बेरोजगार व्यक्ति समाज के लिए खतरा भी बन सकता है। अतः इस समस्या का हर सम्भव तरीके से मुकाबला किया जाना चाहिए। समस्या का उचित समाधान ढूँढने से पूर्व हमें इसके आकार-प्रकार व इसकी प्रकृति आदि से पूर्णतया परिचित होना चाहिए।

पहले योजना आयोग प्रत्येक योजना के प्रारम्भ में रोजगारों की सत्या (backlog of unemployed), योजनाकाल में अर्थिक-शक्ति की वृद्धि, अर्थात् नए श्रमिकों की सत्या एवं योजना में किए गए सार्वजनिक विनियोगों से उत्पन्न प्रतिरिक्त

रोजगार के आँकड़े प्रकाशित करता था, लेकिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी व अल्प-रोजगार के माप के सम्बन्ध में सुनिश्चित व सही परिभाषा व मापदण्डों का लेकर काफी मतभेद रहा और जनगणना, राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण व रोजगार विनिमयालयों के रोजगार सम्बन्धी आँकड़ों में काफी अन्तर होने से यह महसूस किया गया कि इन सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए योजना आयोग ने अगस्त 1969 में प्रो. एम. एस. दांतवाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जिसे यह कार्य सौंपा गया कि वह बेरोजगारी के अनुमानों पर आवश्यक सलाह दे ताकि इस क्षेत्र में आँकड़े अधिक सुनिश्चित व नीति-निर्धारण की दृष्टि से अधिक सार्थक व उपयोगी बनाये जा सकें।

समिति ने मई 1970 में योजना आयोग को अपनी मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की राय में योजना आयोग को भूतकाल में बेरोजगारी व अल्प-रोजगार का अनुमान लगाने के लिए जो आँकड़े उपलब्ध थे, वे अपर्याप्त थे और उन पर आश्रित निष्कर्षों में त्रुटि की भाषा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। समिति ने राय दी कि भारत में श्रम-शक्ति के विभिन्न स्रोतों जैसे प्रदेश, जिला, आयु, ग्रामीण-शहरी क्षेत्र, श्रमिक का वर्ग व शिक्षा-दीक्षा आदि का अध्ययन करके विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों की माँग का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाया कि एक वर्ष के विभिन्न मौसमों में एक से श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़¹

बेरोजगारी से सम्बद्ध तीन धारणाएँ—राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन ने अपने 27वें दौर (1972-73) से रोजगार व बेरोजगारी के पञ्चवर्षीय सर्वेक्षणों में निम्न परिभाषाओं व अवधारणाओं का उपयोग किया था—

(1) सामान्य स्थिति से सम्बद्ध विचार या धारणा (Usual Status concept)

इस विचार के अनुसार सामान्य कार्य की स्थिति (usual activity status) देखी जाती है, जैसे एक व्यक्ति रोजगार प्राप्त है अथवा बेरोजगार है, अथवा श्रम-शक्ति के बाहर है। इससे कार्य की स्थिति एक दिन या एक सप्ताह से अधिक लम्बी अवधि के लिए निर्धारित की जाती है। एन. एस. एस. के 38वें दौर, 1983 के

¹ Seventh Five Year Plan 1985-90, Vol. II, October 1985, Chapter 5, & NSS 38th Round, (January—December 1983). Report No. 341, published in November, 1987 (Revised)

निए यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिना तक के लिए सीमित की गई थी। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी स्थायी या दीर्घकालीन बेरोजगारी को सूचित करती है और यह व्यक्तियों की मस्या में मापी जाती है।

(ii) साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध विचार (Weekly Status concept)

इस विचार के अनुसार कार्य की स्थिति (activity status) पिछले सात दिना की अवधि के सन्दर्भ में निर्धारित की जाती है। इसके अनुसार वह व्यक्ति राजगार प्राप्त माना जाता है जो किसी लाभप्रद व्यवसाय में लगा होता है तथा एक सप्ताह की सबसे अधिक अवधि में किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे काम करने की रिपॉर्ट देता है। जो व्यक्ति सप्ताह-अवधि में एक घण्टे भी काम नहीं कर पाता, वह काम की तलाश में रहता है या काम के लिए उपलब्ध रहता है वह बेरोजगार माना जाता है।

(iii) दैनिक स्थिति से सम्बद्ध विचार (Daily Status concept)

दैनिक स्थिति से सम्बद्ध विचार में एक व्यक्ति के काम की स्थिति पिछले 7 दिना में प्रत्येक दिन के लिए रिकार्ड की जाती है। जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे लेकिन चार घण्टे से कम तक का काम कर पाता है उसे आधे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। यदि वह एक दिन में चार या अधिक घण्टे काम कर पाता तो वह पूरे दिन के लिए काम में लगा गिना जाता है। इसे चानु दिन के अनुसार स्थिति (Current Day Status) वाली बेरोजगारी भी कहा जाता है।

एनी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में बेरोजगारी के अनुमान उपयुक्त तीनों धारणाओं या विचारों के अनुसार उपलब्ध किये गये थे। सामान्य स्थिति वाली बेरोजगारी (usual status unemployment) दीर्घकालीन बेरोजगारी अर्थात् स्थायी बेरोजगारी (chronic unemployment) को सूचित करती है और यह व्यक्ति की संध्या में मापी जाती है। यह माप उनके लिए ज्यादा उपयुक्त होता है जो नियमित काम के रोजगार की तलाश में रहते हैं जैसे शिक्षित व दक्ष व्यक्ति जो अस्थायी व अनियमित रूप का काम ((casual work) स्वीकार नहीं करते। साप्ताहिक स्थिति व दैनिक स्थिति वाले बेरोजगारी के अनुमान मौसमी व आंशिक बेरोजगारी तथा अल्परोजगार की स्थिति को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करते हैं। वे सर्वेक्षण की अवधि में प्रत्येक प्रति सप्ताह व प्रति दिन पाए जाने वाले बेरोजगार लोग की असंत संध्या को प्रकट करते हैं। दैनिक स्थिति वाली बेरोजगारी का माप बेरोजगारी को एक अल्पकालीन व अस्थायी माप माना गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवेदन में दैनिक स्थिति वाली बेरोजगारी के आंकड़ों पर अधिक बल दिया गया था। मार्च 1980 में 5 व अधिक वर्ष की आयु

के 2.1 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार माने गये थे। 1977-78 में श्रम-शक्ति का 8.27% बेरोजगार माना गया था। इसी वर्ष केरल में बेरोजगारी की दर 25.7% व राजस्थान में 3% घाती गई थी। देश के माध्य बेरोजगार व्यक्ति केवल चार राज्यों में केन्द्रित पाये गये थे, जिनके नाम इस प्रकार थे - तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल व महाराष्ट्र।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के प्रतिवेदन में बेरोजगारी के आंकड़े

सातवीं योजना के प्रतिवेदन में सामान्य स्थिति वाली बेरोजगारी (usual status unemployment) के आँकड़ों पर अधिक ध्यान केन्द्रित दिया गया। इसमें सामान्य बेरोजगार पाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गयी। सामान्य स्थिति वाली बेरोजगारी की सन्दर्भ-प्रवृत्ति 365 दिनों की होती है। सातवीं योजना के प्रतिवेदन में दैनिक स्थिति व साप्ताहिक स्थिति वाली बेरोजगारी के आँकड़े नहीं दिये गये क्योंकि उस समय तक ये आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये थे।

सामान्य स्थिति (usual status) वाली बेरोजगारी के आँकड़ों के लिए राष्ट्रीय सेंसस सर्वे के 32वें दौर (प्रवृत्ति 1977-78) तथा 38वें दौर (प्रवृत्ति जनवरी-जून 1983) को आधार बनाया गया।

32वें दौर की सूचना के आधार पर मार्च 1985 में 5 वर्षों का अवधि के अनु-समूह में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की संख्या 13.9 मिलियन व्यक्ति आती गई। लेकिन 38वें दौर की सूचना के आधार पर मार्च 1985 के लिए यह केवल 9.2 मिलियन हो आती गई।

विभिन्न श्रेणियों के अनुसार बेरोजगारी के अनुमान इस प्रकार दिये गये हैं¹

मार्च 1985 की सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी के अनुमान

आधार :—38वाँ दौर (जनवरी-जून 1983)*

अनु-समूह

(5 व अधिक वर्षों) (सालों में)

(i) ग्रामीण पुरुष	37.6
(ii) .. स्त्रियाँ	12.1
(iii) शहरी पुरुष	32.5
(iv) .. स्त्रियाँ	9.8

कुल

92.0

1. Seventh Five Yr. Plan 1985-90, Vol. II, p. 113 and p. 121.

* बाद में प्राप्त सूचना के आधार पर इन्हें जनवरी-जून 1983 के अनु-समूह कर दिया गया।

इस प्रकार पुरुषों में बेरोजगारी स्त्रियों की तुलना में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक पायी गई है। 1983 में सामान्य स्थिति वाली बेरोजगारी समस्त भारत के लिए भ्रम-शक्ति का 3% आती गई।

सातवी योजना की अवधि के लिए 5 वर्ष व अधिक आयु-समूह के लिए लगभग 48.6 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करने की आवश्यकता बतलाई गई।

हमरण रहे कि सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का सम्बन्ध वर्ष भर या दीर्घकालीन बेरोजगारी से होता है। मत. इनकी समस्या नीची होती है, जबकि दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है।

प्रथम राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 38वें दौर (1983) के दैनिक स्थिति की बेरोजगारी के आंकड़े भी उपलब्ध हो गये हैं। इनके अनुसार ग्रामीण पुरुष-वर्ग में (Rural males) 5 व अधिक वर्ष की आयु में दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दर (बेरोजगार व्यक्ति कुल व्यक्तियों के अनुपात के रूप में) 1983 में 4.5% रही, जबकि 1972-73 में यह 4.3% रही थी।

शहरी पुरुष-वर्ग में दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दर 1983 में 5.5% रही, जबकि 1972-73 में यह 4.7% व 1977-78 में 5.6% रही थी।

1983 में सामान्य स्थिति (usual status) के अनुसार बेरोजगारी की दर (5 व अधिक वर्ष के आयु-समूह में) समस्त भारत में ग्रामीण पुरुषों में 1.33%, ग्रामीण महिलाओं के लिए 0.41%, शहरी पुरुषों के लिए 3.5% तथा शहरी महिलाओं के लिए 1% रही। केरल के लिए ये प्रतिशत काफी ऊँचे पाये गये हैं (4% से 7% के बीच)।¹

सातवी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत बेरोजगारी के आँकड़ों का स्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना में मिला रहा है। छठी योजना के आँकड़ों में ग्राम-रोजगार के क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया था, जब कि सातवी योजना में सालभर बेकार रहने वाले व्यक्तियों पर ही सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया गया।

1. NSS, 38th Round, Report No. 341, November, 1987.

अब हम भारत में बेरोजगारी की विभिन्न किस्मों का वर्णन करते हैं—

भारत में बेरोजगारी की किस्में

भारत में बेरोजगारी के निम्न रूप देखने को मिलते हैं :—

1. ग्रामीण अल्प-रोजगार (Rural Under-employment)—अल्प-रोजगार का स्वरूप इतना जटिल है कि विभिन्न देशों एवं विभिन्न समयों में इसके अलग-अलग अर्थ लगाये गये हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है इसे दृश्य व अदृश्य दो भागों में बाँटा गया है। प्रायः दृश्य अल्प-रोजगार (visible under-employment) में थोड़े समय के लिए काम मिल पाता है, जबकि अदृश्य-रोजगार (invisible under-employment) में कम आमदनी हो पाती है, क्योंकि श्रमिकों की दक्षता का पूरा उपयोग नहीं होता। इसे छिपी हुई बेकारी भी कहते हैं। इस प्रकार दृश्य अल्प-रोजगार में काम की अवधि कम होती है एवं अदृश्य अल्प-रोजगार में आमदनी कम होती है।

भारत जैसे कृषि-प्रधान तथा जनाधिक्य वाले देश में ग्रामीण अल्प-रोजगार की समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर होती है और भूमिहीन श्रमिक, छोटे कृषक, ग्रामीण कारीगर, मांभूली रूप से शिक्षित ग्रामीण युवक आदि इसके शिकार पाये जाते हैं। लेकिन देश में बेरोजगारी के अन्य रूप भी पाये जाते हैं जिनका परिचय नीचे दिया जाता है।

2. संरचनात्मक या ढाचेगत बेरोजगारी (Structural Unemployment)—जैसा कि प्रारम्भ में बताया गया है, इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था की संरचना ही ऐसी होती है जिससे प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर इतने नहीं खुलते कि सभी रोजगार चाहने वालों को काम पर लगाया जा सके। इस प्रकार कुछ काम के दृष्टिकोण व्यक्तियों को बेकार रहना पड़ता है। यह स्थिति दक्ष व अदक्ष, शिक्षित व अशिक्षित, ग्रामीण व शहरी सभी प्रकार के श्रमिकों में देखने को मिल सकती है। भारत में अदक्ष श्रमिक बेरोजगार पाये जाते हैं। लेकिन शिक्षित एवं तकनीकी श्रेणी के व्यक्ति भी इसके शिकार पाये जाते हैं। वह समस्या अर्थव्यवस्था के ढाँचे से सम्बन्ध रखती है। यह भूमि, पूँजी, उद्यम व प्रबन्ध जैसे साधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अतः इसे संरचनात्मक बेकारी कहा गया है। इसका देश के आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। विकास की गति को तीव्र करके ही रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाये जा सकते हैं।

3. चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—यह स्थिति प्रायः

उद्योग-प्रधान तथा विकसित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में विशेष रूप से देखने को मिलती है जहाँ मांग में कमी के कारण कुछ उद्योग अल्पकाल के लिए बन्द हो जाते हैं और देश में आर्थिक मंदी दृढ़ जाती है। दुर्भाग्यवश भारत में भी समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्र में मंदी का बाढ़ावरण उत्पन्न हो जाने से कुछ उद्योगों में चक्रीय बेरोजगारी का प्रभाव देखा गया है। विशेष रूप से सूती-वस्त्र उद्योग व हथौलीय उद्योग इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें कई कारणों से उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, जैसे कृषिगत कच्चे माल का घमाव, विदेशों से आयात किये जाने वाले बल-पुर्जों व आवश्यक कच्चे माल का घमाव, देश में माँग की कमी, आदि। 1975 में देश में मोटरकारों, रेफ्रिजरेटर्स, एयर-कण्डीशनर्स, बिजली के पक्षों आदि की भाग घट जाने से इनसे सम्बन्धित कारखानों में उत्पादन-क्षमता का कम प्रयोग होना प्रारम्भ हो गया था जिससे थमिकों में बेरोजगारी की दशा उत्पन्न हो गई थी। 1976-77 के केन्द्रीय बजट में उत्पादन-शुल्कों में कमी करके इन उद्योगों में माँग को बढ़ाने का प्रयास किया गया। मोटरकारों के अलग से भी मूल्य घटाये गये थे। इस प्रकार भारत में समय-समय पर चक्रीय बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिलती है और यह बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देती है। 1982 में सरकार ने ट्रक व ट्रैक्टरों की माँग बढ़ाने के लिए अधिक कर्ज की सुविधा प्रदान की ताकि इन उद्योगों में मंदी न आए।

4. टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी (Technological Unemployment)—

इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पादन में श्रम बचाने वाली विधियों (Labour-saving techniques) का उपयोग करने से आर्थिक क्रिया के किसी भी क्षेत्र कृषि उद्योग, परिवहन, विज्ञान व कार्यालयों आदि में उत्पन्न हो सकती है, जैसे कृषि में यन्त्रीकरण से यह कृषि में फैल जाती है, एक उद्योगों में आधुनिकीकरण करने तथा स्वचालित यन्त्रों का उपयोग बढ़ाने से यह उद्योगों में उत्पन्न हो जाती है। उद्योगों में माल की किम्मत मुधारने एवं लागत कम करने के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक होता है। लेकिन इससे कुछ थमिक बेकार भी होते हैं। भारत ने घीमो शक्ति से आधुनिकीकरण करने की नीति अपनाई है। अतः आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कुछ सीमा तक इस प्रकार की बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ सकता है।

जब एक अल्पविकसित व पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी के निम्न स्तर को छोड़कर उच्च स्तर की ओर बढ़ना चाहती है तो जनश्रमिकों की स्थिति उसके मार्ग में रोड़ा बन जाती है। वास्तव में, भारत काफी समय से इसी दुविधा में पड़ा हुआ है। हमें इस समस्या का समाधान ढूँढना होगा तथा अपने साधनों के अनुकूल ही उत्पादन की विधियों को अपनाना होगा। भारत के लिए श्रम-बहन पद्धतियों को

अपनाने की अधिक आवश्यकता है। प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने आयुनिर्भीकरण, नई टेक्नोलॉजी, उत्पादन के बड़े पैमाने को अपनाकर पैमाने की विकायते प्राप्त करने, आन्तरिक व विदेशी प्रतियोगिता को बढ़ाने, आदि पर जोर दिया है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी आधुनिक बन सके। इसके लिए कुछ वर्ष पूर्व नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (मार्च 1985) व नई टेक्स्टाइल नीति (जून 1985) घोषित की गई थी। इनसे माल की किस्म तथा लागत व कीमत कम करने में मदद मिलेगी जो स्वागत के योग्य है। लेकिन रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से इनके प्रभावों के सम्बन्ध में कुछ मन्देह भी प्रकट किये गये हैं।

भारत में बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण

यदि कोई यह पूछे कि लगभग चार दशकों तक योजनाओं को कार्यान्वित करने के बाव भी देश में बेरोजगारी क्यों विद्यमान है तो उत्तर दिया जायगा कि इस घटना में जनसंख्या तेजी से बढ़ी जिससे विशाल मात्रा में नये लोग श्रम-बाजार में प्रविष्ट हो गये देश का आर्थिक विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया, कृषि में नवीन विधियों का उपयोग पिछले लगभग 25 वर्षों से ही विशेष रूप से प्रारम्भ हुआ है, ग्रामीण औद्योगीकरण की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई है, सरकार के पास विकास के लिए साधनों का अभाव रहा है एवं देश की शिक्षा-प्रणाली का नियोजित आर्थिक विकास से आवश्यक तालमेल स्थापित नहीं हो पाया है। देश के विभिन्न भागों में समय समय पर प्राकृतिक विपत्तियों के आने से भी बेरोजगारी बढ़ जाती है। देश के सामाजिक पिछड़ेपन ने श्रम की गतिशीलता में बाधा डाली है। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों का परिचय नीचे दिया जाता है—

1 जनसंख्या की तीव्र वृद्धि—भारत में जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण श्रम-शक्ति के आधिकार्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 1985-90 की अवधि के लिए 15-59 वर्ष के आयु-समूह में श्रम-शक्ति के सम्बन्ध में 2.55% सालाना वृद्धि का अनुमान लगाया गया था एवं इस समूह में पाँच वर्षों में श्रम-शक्ति के 3.6 करोड़ व्यक्तियों के बढ़ने का अनुमान प्रस्तुत किया गया था। 5 वर्ष व अधिक के आयु-समूह में श्रम-शक्ति में 3.9 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान प्रस्तुत किया गया। यदि देश का आर्थिक विकास जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में कम होता है तो बेरोजगारी की समस्या का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कई दशकियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की दशा रही थी। प्राचीन कुटीर उद्योग धन्धों का पतन होने से उनमें सलग लोगों को भारी क्षति पहुँची थी। लेकिन उनके स्थान पर देश में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योग तेजी से नहीं बन पाये थे। बड़े पैमाने के उद्योगों में कम लोगों को ही रोजगार दिया जा सका था।

प्रोफेसर के. सुन्दरम ने अनुमान लगाया है कि भारत में श्रम-शक्ति 1981 में 30.3 करोड़ से बढ़कर 1991 में 38 करोड़ व 2001 में 47.6 करोड़ हो जायेगी क्योंकि इन वर्षों में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। उनका मत है कि 1990 में प्रारम्भ होने वाले दशक में प्रतिवर्ष श्रम-शक्ति में एक करोड़ व्यक्ति की वृद्धि हो सकती है। अतः जनसंख्या व श्रम-शक्ति में विस्फोटक स्थिति होने से बेरोजगारी में भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

2. सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोगों का अभाव—सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी-निवेश के बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होती है। देश में 1965 के बाद सार्वजनिक विनियोग व सार्वजनिक व्यय में वार्षिक वृद्धि-दर पहले से कम हुई है जिससे इन्फ्रा-स्ट्रक्चर व उद्योगों के विकास पर प्रतिवृत्त अंतर पड़ा है तथा साथ में रोजगार भी कम बढ़ पाया है। आन्तरिक मुद्रास्फीति व विदेशी सहायता की अनिश्चितता तथा मुद्रा के परिणामस्वरूप पूँजी-निवेश पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ा और उसमें गतिहीनता की दशा उत्पन्न हो गयी। ऐसी स्थिति में विनियोग के अभाव के कारण रोजगार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। हमारे देश में सार्वजनिक विनियोग व निजी विनियोग एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। इसलिए सार्वजनिक विनियोगों की घीमी वृद्धि से निजी विनियोगों की वृद्धि पर भी विपरीत असर पड़ता है। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण विनियोग की वृद्धि-दर ही घीमी रही है। इससे रोजगार के अवसर तेजी से व पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ पाये हैं।

3. पूँजी गहन परियोजनाओं पर अधिक जोर—द्वितीय योजना के प्रारम्भ से हमने आधारभूत उद्योगों (basic industries) के विकास पर अधिक जोर दिया जिससे भारी इन्जीनियरी, भारी रसायन, आदि उद्योगों में पूँजी तो अधिक लगायी गयी, लेकिन उनमें रोजगार के अवसर ज्यादा नहीं बढ़ पाये। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से आर्थिक नियोजन की महलानीवित-नीति में, 'भारी उद्योगों को प्राथमिकता' देना अनुचित नहीं था, लेकिन अल्पकाल में उसके प्रभाव रोजगार पर प्रतिवृत्त रहे। वैसे उन नीति से रोजगार बढ़ाने के लिए कुटीर व ग्रामीण उद्योगों को पनपाने की बात कही गई थी, लेकिन उस दिशा में सफल प्रयास नहीं किये जा सके जिससे बेरोजगारी बढी। भूतकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों पर सक्रिय रूप से ध्यान नहीं दिया गया जिससे इनके द्वारा बेरोजगारी दूर करने में पर्याप्त रूप से मदद नहीं मिल सकी। भविष्य में ग्रामीण व लघु उद्योगों को रोजगार बढ़ाने का मुख्य साधन बनाना होगा।

4. कृषिगत विकास का अभाव—कृषिगत विकास में पर्याप्त मात्रा में तेजी, नियमितता व स्थिरता आने से ही अन्य क्षेत्रों में विकास का आधार सुदृढ़ हो सकता

है। भारत में कृषिगत विकास की गति धीमी रही है। 1949-50 से 1983-84 के बीच कृषि में विकास की वार्षिक दर 2.6% रही है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में कृषिगत उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। जब तक खाद्यान्न, कपास, जूट, तिलहन व गन्ने आदि की पैदावार द्रुत गति से नहीं बढ़ती, तब तक कृषि व गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से नहीं बढ़ सकते। इसलिए कृषिगत विकास की धीमी गति न बेरोजगारी की स्थिति में सुधार नहीं होना दिया।

5. शिक्षा प्रणाली व आर्थिक विकास में परस्पर तालमेल का अभाव—वर्षों तक चर्चा करने के बाद भी देश की शिक्षा-प्रणाली को आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं ढाला जा सका है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 'स्व-रोजगार' (self-employment) को बढ़ावा न देकर 'रोजगार तलाश करने वालों' (employment-seekers or Job-seekers) को अधिक बढ़ावा देती है जिससे समस्या जटिल हो जाती है। यह बात दक्ष व अदक्ष दोनों प्रकार के श्रमिकों पर लागू होती है।

6. निजी क्षेत्र के समस्त अभिरिचयता व सरकारी नियन्त्रणों की भरमार—निजी क्षेत्र के समर्थकों का कहना है कि सरकारी नीतियाँ निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करती हैं जिससे वह रोजगार के अवसर बढ़ाने में अपना पूरा योगदान नहीं दे पाता। भूतकाल में सरकार की कर-नीति विनियोग को प्रोत्साहन देने वाली नहीं रही है। निजी क्षेत्र के समर्थकों का कहना है कि देश में अनेक प्रकार के औद्योगिक नियन्त्रण लगे हुए हैं जिससे उनको अपने कार्यों को बढ़ाने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि देश में निजी क्षेत्र के विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण होता तो वह रोजगार बढ़ाने में ज्यादा योगदान दे सकता था।

श्रीमती ईशर जज अहलूवालिया ने बतलाया है कि भारत में प्रचलित औद्योगिक नीति सम्बन्धी फ्रेमवर्क (औद्योगिक लाइसेंस नीति, आयात नीति, कोमत-नियन्त्रण, विदेशी कम्पनियों से सहयोग के समझौते व टक्नोलोजी-प्रसारण सम्बन्धी समझौतों) की वजह से औद्योगिक जगत में अनावश्यक विलम्ब व अकार्यकुशलता को बढ़ावा मिला तथा 1965 के बाद औद्योगिक विकास की गति धीमी पड़ गई।¹ राजीव सरकार ने इन कमियों को दूर करने की दिशा में कई कदम उठाये हैं तथा अनावश्यक नियन्त्रणों व नियमनों पर पुनर्विचार करके उनको कम किया जा रहा है

1. Isher Judge Ahluwalia, *Industrial Growth in India*, 1985, Chapter 8.

ताकि औद्योगिक विकास व रोजगार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सके। औद्योगिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जा रहा है कि व्यापार में नौकरशाही व सरकारी अफसरों की तरफ से पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण निजी क्षेत्र को उदार नीतियों का पूरा लाभ नहीं मिल सका है। अतः इस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है।

7 रोजगार नीति व श्रम-शक्ति नियोजन (Man-power Planning) का अभाव—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का औद्योगिक विकास करने का प्रयास किया गया, लेकिन योजनाओं में रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई व्यापक व प्रगतिशील नीति नहीं अपनाई जा सकी। श्रम-शक्ति नियोजन की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई। परिणामस्वरूप देश में रोजगार बढ़ने के बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ी है।

भारत में नियोजन तथा रोजगार (Planning & Employment in India)

1. प्रथम योजना—भारतीय नियोजन के उद्देश्यों में सर्वप्रथम रोजगार बढ़ाने पर बल दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारी की समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 1953 से बेकारी की समस्या के अधिक उग्र हो जाने से प्रथम योजना में 309 करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की गई जिससे लोगों को विभिन्न दिशाओं में अधिक रोजगार प्रदान किया जा सके। इसके लिए भारी हूबू कार्यक्रम घोषित किया गया जिसमें नष्ट उद्योगों का विकास, सड़कों का निर्माण, अल्पविक्री की नियुक्ति, आदि कार्यक्रम शामिल किये गये थे।

प्रथम योजना में लगभग 70 लाख व्यक्तियों को प्रतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के बावजूद भी योजना के अन्त में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई थी।

2. द्वितीय योजना—द्वितीय योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई लेकिन साथ में रोजगार बढ़ाने के लिए कुटीर व परेलू उद्योगों के विकास का भी महत्व स्थानार किया गया। योजना में कहा गया कि सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि योजना के अन्त में बेरोजगारी न बढ़े, योजनाकाल में सभी नये काम चाहने वाले व्यक्तियों को काम पर लगाया जा सके। लेकिन बाद में साधनों के अभाव के कारण द्वितीय योजना का आकार घटाना पड़ा जिससे योजना के अन्त में बेरोजगारी बढ़ी।

3. तृतीय योजना—तृतीय योजना में 1 करोड़ 40 लाख व्यक्तियों को प्रतिरिक्त रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि श्रम-शक्ति में जुड़ने वाले

खेतिहर श्रमिक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, आदि। इसके अलावा न्यूनतम प्रादश्यकताओं की पूर्ति के कार्यक्रम में निम्न कार्य सुभाषित गये : प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्रामीण जल सप्लाई, भूमिहीनों के लिए रिहायशी भू-खण्डों की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण व शहरों में गन्दी बस्तियों का सुधार, आदि।

निर्माण सम्बन्धी कार्य काफी श्रम गहन होते हैं। देश में मजदूरी पर रोजगार व स्व-रोजगार दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार की गई। यह भी कहा गया कि कृषि में बिना सोचे-समझे यन्त्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में रोजगार नीति व कार्यक्रम—छठी योजना की अवधि में कुल 4.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की समस्या पानी पड़ी थी। 1979-80 में देश में 15.1 करोड़ स्टैंडर्ड व्यक्ति-वर्ष (Standard Person-years) (SPY) का रोजगार मिला हुआ था जिसे 1984-85 तक 18.5 करोड़ स्टैंडर्ड व्यक्ति-वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया था। एक स्टैंडर्ड व्यक्ति-वर्ष 273 कार्यकारी दिनों (working days) का होता है एवं एक दिन में आठ घण्टे काम करना होता है। इस प्रकार छठी योजना की अवधि में 3.4 करोड़ व्यक्ति-वर्ष का रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम रहे गये थे जिसमें प्रत्येक कृषि व सहायक क्षेत्रों में 1.5 करोड़ व्यक्ति-वर्ष का अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था। शेष अतिरिक्त रोजगार के अवसर खनन, विनिर्माण व अन्य क्रियाओं में उत्पन्न करने के लक्ष्य रहे गये थे। छठी योजना में रोजगार में वार्षिक वृद्धि की दर 4.2% निर्धारित की गई थी, जबकि श्रम-शक्ति में वार्षिक वृद्धि दर 2.54% आती गई थी। इस प्रकार रोजगार में वृद्धि-दर श्रम-शक्ति की वृद्धि-दर से अधिक रही गई थी।

योजना के अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के बड़े कार्यक्रम निम्न विराम के रूप में गये।

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development programme) (IRDP) —यह मूलतः ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का काम करने का कार्यक्रम है। छठी योजना में इसे दश के सभी खण्डों में फैलाने का लक्ष्य रखा गया था। यह कहा गया कि प्रत्येक खण्ड में 3000 निर्धन परिवारों को कृषि व गैर-कृषि व्यवसायों में काम दिया जायगा। प्रतिवर्ष 600 परिवारों को काम देने की व्यवस्था रखी गयी एवं प्रत्येक खण्ड पर 5 वर्ष की अवधि में 35 लाख रु. राजी व्यय-हैतु निर्धारित की गई।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में गरीबों को पशु, कृषिगत उपकरण व अन्य साधन देने की नीति घोषित की गई। यह कहा गया कि खेतिहर मजदूरों को सीमा-निधारण से प्राप्त अनिश्चित भूमि आवंटित की जायगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 में रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य व प्रस्तावित नीति

सातवीं योजना के प्रारम्भ में 92 लाख व्यक्ति वर्ष भर के लिए बेरोजगार माने गये तथा योजनाकाल में श्रम-व्यक्ति में 3.9 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार योजना में 4.86 करोड़ व्यक्तियों को काम देने की समस्या स्वीकार की गयी।

अनुमान लगाया गया कि योजनाकाल में 4.04 करोड़ स्टेण्डर्ड व्यक्ति-वर्ष का प्रतिरिक्त रोजगार उत्पन्न किया जा सकेगा। इस प्रकार रोजगार में वार्षिक वृद्धि-दर 3.99% घाटी गयी। एकले रूप में प्रतिरिक्त रोजगार 1.8 करोड़ व्यक्ति-वर्ष तथा विनिर्माण में 67 लाख व्यक्ति-वर्ष दान कामनुमान लगाया गया। रूप में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कम्पाइण्ड हावर्स्टर का प्रयोग सीमित रूप से पर बंध दिया गया।

सातवीं योजना में प्रतिरिक्त रोजगार के अवसरों की मुख्य दिशाएँ

(i) सिंचाई का विकास व उसका पूरा उपयोग, सूखी खेती में उपलब्ध टेक्नोलॉजी का प्रयोग, चावल, मोटे अनाजों, दाल व तिलहन की पैदावार में वृद्धि भूमि पर क्षार को दूर करके उसमें सुधार करना, पशु-पालन, मछली-पालन व वृक्षा-रोपण का विस्तार।

(ii) उर्वरक, कीटनाशक इवाई व कुपिगत मशीनरी का विस्तार, आवश्यक उपमोक्षा माल के उत्पादन में वृद्धि, इलेक्ट्रोनिक्स व मोटरमाई उद्योग का विकास व सहायक उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाना।

(iii) लघु उद्योगों का विस्तार करना। हाथ करघा उद्योग में 1984-85 में 75 लाख व्यक्ति कार्यरत थे। सातवीं योजना में 24 लाख व्यक्तियों का इसमें प्रतिरिक्त रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था।

(iv) सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण व कम्पाउ एरिया विकास (CDA) के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया गया।

(v) भवन-निर्माण (Housing) रोजगार-गहन किया जाना है। इसे गहरी व घट्ट-गहरी क्षेत्रों में तेजी से चलाने पर जोर दिया गया।

(vi) परिवहन में—विशेषतया ग्रामीण सड़क, आन्तरिक जल-परिवहन (देगी नावों), सड़क-परिवहन व समुद्री जहाज निर्माण। इनकी मरम्मत व पुराने जहाजों को ठोड़ने आदि में रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार की गई।

इस प्रकार सातवीं योजना में रोजगार बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया। 'भोजन, काम व उत्पादकता' से सातवीं योजना के तीन केन्द्र-बिन्दु माने गये।

जिला-उद्योग केन्द्रों के माध्यम से लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत निर्धारित व्यय की राशि का उपयोग उद्यमकर्त्ताओं द्वारा वेको से लिए गये वज्र पर 25% पूँजीगत अनुदान देने में किया गया है।

6 राज्य सरकारों द्वारा विशेष रोजगार कार्यक्रम

महाराष्ट्र में 1972 से रोजगार भारती कार्यक्रम चल रहा है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में धन्य व शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों का रोजगार दिया जाता है। इसके लिए वहाँ 1977 में रोजगार भारती अधिनियम बनाया गया था प्रति वर कई करोड़ धन-दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है। अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रदान किये हैं जिनसे रोजगार लोगों को लाभ पहुँचा है।

इस प्रकार देश में पिछले वर्षों में रोजगार बनाम कृषि कार्यक्रमों में ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है तथा योजना में विकसित-कार्यक्रमों से भी रोजगार में वृद्धि हुई है।

जवाहर रोजगार योजना (JRY)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से जवाहर रोजगार योजना पृथक् के नवी रोजगार कार्यक्रमों की तुलना में सबसे बड़ा प्रयास है। इसके अन्तर्गत 1989-90 में लगभग 2625 करोड़ रु. व्यय किये जायेंगे जिनमें केन्द्र का अंश 80% व राज्यों का 20% रखा गया है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) इनके द्वारा ग्रामीण निर्धन-परिवारों में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इसमें पहले के NREP व RLEGP कार्यक्रम मिला दिये गये हैं।

(3) यह योजना ग्राम-पंचायतों के मार्फत कार्यान्वित की जायेगी। इसके लिए केन्द्र सीधे पंचायतों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा। पंचायत-स्तर पर रोजगार के कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं की देख-रेख में चलाये जायेंगे। राज्यों का उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही होगा, बल्कि वे भी अपने हिस्से का योगदान करेंगे।

(4) इस योजना में 30% भारक्षेत्र ग्रामीण महिलाओं के लिए रखा गया है।

(5) केन्द्रीय सहायता का राज्यों में आवंटन ग्रामीण निर्धनों की संख्या के अनुपात में किया जायेगा, राज्यों से जिला-स्तर पर कोषों का आवंटन पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जायेगा तथा जिलों के प्रत्येक ग्राम पंचायत को कोषों का आवंटन गाँव की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(6) जिला-स्तर के कुल आवंटन का 6% SC/ST के लिए इन्दिरा आवास योजना में इस्तेमाल किया जायेगा। धनराशि का व्यय उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण, सामाजिक बानिजी, सड़क व भवन-निर्माण, आदि में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक किया जायेगा।

क्या JRY बेकारी हटाने में सफल होगी ?

JRY ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की सबसे बड़ी योजना है। इसके अन्तर्गत सभी गांवों को शामिल करने का कार्यक्रम है। NREP/RLEGP में 59% गांव ही शामिल किये जा सके हैं। सभी गांवों को शामिल करने की बात आकर्षक लगती है, लेकिन इससे कई प्रकार की कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं—

(i) इससे साधन सारे देश में थोड़े-थोड़े ही उपलब्ध किये जा सकेंगे, जैसे गुजरात में 44% पंचायतों में से प्रत्येक को वर्ष में 25 हजार रुपये ही मिल पायेंगे। इनमें बहुत थोड़ा रोजगार होउत्पन्न हो जाएगा क्योंकि 12 500 रुपये ही मजदूरी के लिए मिल पायेंगे, शेष सामान में लग जायेंगे। इतने से ध्येसैएक गांव में 100 बेवत 11 व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा।

(ii) जहूरतमद गांवों को जहां बेकारी ज्यादा है, वहां पर्याप्त साधन नहीं मिल पायेंगे।

(iii) पंचायतों में धनी लोगों का प्रभाव अधिक पाया जाता है जिससे साधन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी।

(iv) राज्यों का सीधा योगदान न होने से केन्द्र का इस योजना में प्रभाव बढ़ जायगा जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कमजोर पड़ जायगी।

(v) JRY में भी नियोजन का पक्ष कमजोर बना हुआ है जैसा कि NREP व RLEGP में था। इसे किसी जिला या खण्ड स्तरीय योजना से नहीं जोड़ा गया है। इससे सामुदायिक परिसम्पत्ति के निर्माण में कठिनाई आयेंगी क्योंकि उसके लिए भूमि-सेना जैसी बड़ी योजना जरूरी होती है। इसलिए प्रोजेक्टों के व्यय की व्यवस्था के अभाव व अन्य प्रकार के नियोजन के अभाव में JRY से ज्यादा सफलता की आशा करना कठिन है।

NREP व RLEGP के धातु कार्यक्रमों के लिए धन की उचित व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। कहीं ऐसा न किहो JRY को लागू करने के दौरान उनको नजर-अंदाज कर दिया जाय।

इसलिए JRY का अधिक्य छाठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके स्वरूप व स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी (Educated Unemployment in India)

कुछ लेखकों द्वारा मध्यमवर्गीय बेरोजगारी (middle class unemployment) भी कहते हैं। भारत में शिक्षित वर्ग में बेकारी की समस्या काफी गम्भीर है। वैसे

इंजीनियरों में डिग्री व डिप्लोमा-होल्डरों की बेकारी का सम्बन्ध प्रायः प्रौद्योगिक मन्दी से माना जाता है। लेकिन शिक्षित वर्ग में बेकारी के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में शिक्षा का विस्तार अधिक तेजी से हुआ है। रोजगार विनिमयालयों के रजिस्ट्रारों में लाखों मैट्रिक व उच्च योग्यता वाले आवेदकों के नाम दर्ज पाये जाते हैं। इनमें उन शिक्षित व्यक्तियों की सहायता भी जोड़ी जानी चाहिए जो किसी कारण से अपना नाम रोजगार विनिमयालयों में दर्ज नहीं करा पाते हैं। प्रायः से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति पश्चिमी बंगाल, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल व बिहार में पाये जाते हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के प्रतिवेदन के अनुसार 1985 के प्रारम्भ में NSS के आकड़ों के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 47 लाख थी (23वें दौर के अनुसार)। इसमें मैट्रिक/हायर सैकण्डरी पास व्यक्तियों की संख्या 35 लाख तथा स्नातक व प्राविधिक डिप्लोमा-होल्डरों की संख्या 12 लाख थी।

1985 के प्रारम्भ में शिक्षित श्रम-शक्ति लगभग 3 करोड़ व्यक्ति थी जिसके 1990 के प्रारम्भ तक बढ़कर 4.1 करोड़ व्यक्ति हो जाने का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार सातवीं योजना में शिक्षित श्रम-शक्ति (आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जन-संख्या) 1.1 करोड़ बढ़ जायेगी। अतः शिक्षित वर्ग को रोजगार प्रदान करने की समस्या काफी जटिल मानी गई है।

देश में रोजगार विनिमयालयों के ताज़ा आकड़ों के अनुसार जून 1988 के अन्त में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 167 लाख थी जिसमें 97 लाख मैट्रिक पास थे जो कुल शिक्षित बेरोजगारों का 58% था। 1982 में कुल शिक्षित बेरोजगार 98 लाख थे जिनमें मैट्रिक पास 56 लाख (57%) थे।¹

भारत में शिक्षित बेकारी के सम्बन्ध में एक विरोधाभास पाया जाता है। एक तरफ तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति बेकार पाये जाते हैं तो दूसरी तरफ प्राथमिक विकास के लिए आवश्यक दक्षता वाले व्यक्तियों की कमी बनी रहती है, जैसे अनुमनी इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरों, इलुमिनेशन, फिटर्स, टर्नर्स, डॉक्टर-सर्जन, पैरा-मैडिकल कर्मचारियों, विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों व प्रोफेसर्स और गणित व विज्ञान विषयों में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों, स्टेनो-ग्राफर्स तथा लेखाकारों का प्रायः अभाव पाया जाता है। इस अभाव को पूर्ति पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रायः यह भी देखने में आया है कि कुछ तथाकथिक शिक्षित व्यक्ति न केवल बेरोजगार होते हैं, बल्कि वे रोजगार पाने के साधक भी नहीं होते, क्योंकि उनमें काम

1. The Economic Times, August 27, 1989.

करने की योग्यता व दक्षता बहुत नीचे स्तर की होती है। ऐसा सम्भवतः इसलिए होता है कि उन्होंने अध्ययन-काल में जैसे-तैसे डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित विषयों का मज़ी प्रकार से अध्ययन नहीं किया जिससे उनका ज्ञान मामूली व घटिया किस्म का रह गया। आजकल कला, वाणिज्य व विज्ञान के ऐसे अनेक विद्यार्थी पाये जाते हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों की स्टेण्डर्ड रचनाएँ छर्द तक नहीं। ऐसी स्थिति में उनका ज्ञान उन्हें जीवन में सफल नहीं बना सकता और उन्हें पर्याप्त आत्म-विश्वास भी नहीं द सकता।

शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव

1 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालयों की तरफ जाने की वर्तमान प्रवृत्ति में कमी की जा सके और माध्यमिक स्तर छोड़ते समय विद्यार्थी को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाय जिसका रोजगार की दृष्टि से महत्व हो।

वर्तमान समय में भारतीय ग्रेजुएट (स्नातक), बी. ए. व बी. एससी की डिग्री के होते हुए भी तकनीकी व व्यावसायिक योग्यता के अभाव में रोजगार के लाभक नहीं हो पाते हैं। इस स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विद्यार्थी एम. ए. व एम. एससी, पाठ्यक्रमों की तरफ न जाकर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभप्रद रोजगार की तरफ जा सकें। इससे उनका व समाज दोनों का हित-वर्धन होगा।

2 दसवी कक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (vocational courses) के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोलोटक्निक्स, व कृषि-स्कूलों आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि माध्यमिक शिक्षा में भी रोजगार की तरफ प्रवृत्ति लानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों व स्कूलों में फसलों की जुताई बागवानी, लघु मिथार्ड आदि का ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार शहरी स्कूलों में टाइप-राइटिंग व स्टेनोग्राफी पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। इस तरह शिक्षा के वर्तमान साहित्यिक भ्रूणव की जगह विकासशील अव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षित बेरोजगारी का संकट कुछ सीमा तक कम हो जायगा।

3 इंजीनियरी व तकनीकी विशेषज्ञों एवं अन्य शिक्षित व्यक्तियों के लिए सरकारी सहायता से लघु उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे देश लोगों के लिए स्वराजगार के अवसर खुलेंगे जिनमें यथासम्भव अधिक वृद्धि की जानी चाहिए।

4. विश्वविद्यालय रोजगार सूचना व निर्देश-संस्थानों की सुदृढ़ करके इन्हें रोजगार एजेंसियों के समीप लाना चाहिए।

5 ग्रामीण ग्रथव्यवस्था का विकास इस तरह से किया जाना चाहिए कि लोगो को देहाती क्षेत्रों में विविध प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में रोजगार मिल सके ।

6 बैंकिंग व बीमा आदि कार्यों के विकास से काफी शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के नये अवसर खुल सकते हैं ।

हम आगे आकर बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो सामान्य सुझाव देगे उसमें से अधिकांश सुझाव शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने पर भी लागू होंगे । सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की एक स्कीम 1983 से लागू की है । इसके अन्तर्गत 25 हजार रु तक का कर्ज दिया जाता है । केन्द्रीय बजट में 1984-85 के लिए 25 करोड़ रु का प्रावधान किया गया था, ताकि उत्तमकर्ताओं द्वारा लिये गये बैंक-ऋण पर इस राशि में से 25% तक पूंजीगत सस्मिडी दी जा सके ।

शिक्षा-प्रणाली के माध्यम से आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता व चरित्र सम्पत्तियों गुणों का समुचित रूप से विकास किया जाना चाहिए । शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की परिस्थितियां उत्पन्न करती है । शिक्षा के ढांचे में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि समाज में आवश्यक दक्षताएँ प्रोत्साहित की जा सकें तथा अनावश्यक दक्षताएँ हतोत्साहित की जा सकें । किसी भी कार्य के लिए योग्यताओं को भी इस प्रकार से बदला जाना चाहिए कि उनके लिए अनावश्यक रूप से 'ऊंची योग्यताओं' का दबाव कम किया जा सके । वर्तमान सरकार नई शिक्षा प्रणाली पर विचार कर रही है । साथ में नौकरियों को यथासम्भव डिग्रियों से पृथक् करने की चर्चा भी हाती रही है । आशा है इस दिशा में कुछ प्रगति होगी ।

सातवाँ पंचवर्षीय योजना, 1985-90 में शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में नीति—बैत सामान्य बेरोजगारी के हन से शिक्षित बेरोजगारी का भी अग्रत समाधान निकलता है । तबिन मानवी योजना में शिक्षित व्यक्तियों के लिए निम्न दिशाओं में रोजगार बढ़ाने व प्रयास किये जायेंगे ।

1. ग्रथव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं के विस्तार व तबनालो-निकन प्रगति से शिक्षित मानवीय शक्ति के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । मण्डित व अमण्डित क्षेत्रों में मैट्रिक/हायर सेकण्डरी परीक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए काम के अवसर बढ़ेंगे । उद्योग, बैंकिंग, पब्लिशिंग, संचार व सार्वजनिक सेवाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए काम के अवसर उत्पन्न होंगे ।

2. तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर-प्रणाली, न्यूक्लियर विज्ञान, पर्यावरण-इन्जीनियरी, बायो-इन्जीनियरी व ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों से सम्बन्धित क्षेत्रों में नया काम मिलेगा।

3. तकनीकी व्यक्तियों को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक रोजगार मिलेगा। सामुद्रिक संपदा की खोज व विद्योद्भूत में तकनीकी जानकारों की माँग होगी।

4. ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रमों में शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर खुलेंगे। इन्हें स्वरोजगार के विविध कार्यों में भी प्रतिरिक्त काम-धन्दा मिल सकेगा।

जैसा कि पहले बताया गया है शिक्षित बेरोजगार भुवावर्ग के लिए स्वरोजगार की नई स्कीम अगस्त 1983 से चालू की गई जिसके अन्तर्गत 1983-84 में 25 लाख व्यक्तियों को काम देने का लक्ष्य रखा गया था। यह स्कीम (DICs) के माध्यम से क्रियान्वित की गई है।

क्या भारतीय योजनाओं में रोजगार सम्बन्धी नीति दोषपूर्ण रही है ?

पहले बताया जा चुका है कि भारतीय नियोजन में रोजगार बढ़ाने पर संदेह बन दिया गया है और इसके लिए ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम (RWP) तथा ग्रामीण रोजगार की सीमा व प्रभावी परिणाम देने वाली योजना (कैश स्कीम) (Crash Scheme for Rural Employment) (CSRE) आदि कार्यक्रमों पर धन-राशि व्यय की गई है जिससे कुछ सीमा तक रोजगार के नये अवसर खुले हैं। यदि योजनाओं में रोजगार बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाता, तो सम्भवतः आज बेरोजगारी की स्थिति और भी बदतर होती।

मातृश्री योजना के प्रारम्भ में 5 वर्ष व अधिक के आयु-समूह में लगभग 92 लाख व्यक्तिमा की बेरोजगारी (सामान्य स्टैटम के अनुसार) की समस्या मुँह बाये आई है जिसमें कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि भारत में पिछले लगभग बार दशका में आयुध नियोजन रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से विफल रहा है। योजना-काल में बेरोजगारी की समस्या के बने रहने तथा बढ़ने के लिए निम्न कारण उत्तरदायी मान जा सकते हैं—

1. पूँजी-गहन विधियों पर अधिक जोर—विद्वानों का मत है कि भारत में योजनाकाल में पूँजी-गहन विधियों (capital intensive methods) के इस्तेमाल पर अधिक जोर देने के कारण रोजगार के अवसरों का पर्याप्त रूप से विस्तार नहीं किया जा सका है। द्वितीय योजना के प्रारम्भ से विकास की महत्वानोबिस नीति के

नहीं कर पायी है। इसका कारण यह है कि काफी विनियोग पूँजी-गहन क्रियाओं में किया गया है जिनमें रोजगार की वृद्धि बहुत सीमित मात्रा में हो पाती है। ध्यान देने की बात यह है कि देश में वित्तीय साधन तो मौजूद हैं लेकिन आवश्यकता है उनको एकत्र करने व उनका सदुपयोग करने की। भारत में काला घन व काली मुड़ा विशाल मात्रा में उपलब्ध हो गये हैं। कृपिगत क्षत्र से कर जुगाकर अधिक साधन एकत्र किये जा सकते हैं जिसके लिए राज समिति ने सिफारिशें प्रस्तुत की थी। लेकिन अभी तक राजनीतिक कारणों से इस दिशा में सक्रिय प्रयास नहीं किये गये हैं। भारत में अनुपादक सरकारी खर्च में भी कमी की जानी चाहिए। सरकारी उपक्रमों से अधिक लाभ अर्जित किया जाना चाहिए। प्रति वित्तीय साधन को जुटाकर विनियोग की दर ऊँची रखी जा सकती है। विनियोग की दर को बढ़ाए बिना रोजगार के अवसर बढ़ाना सम्भव नहीं है। लेकिन साथ में विनियोग का प्रारूप भी मजबूत गहन बनाया जाना चाहिए ताकि उसमें से अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त किया जा सके। इसके लिए वृषि सहायक उद्योगों व विकर्षित पशु उद्योगों के विकास के लिए अधिक धनराशि नियत की जानी चाहिए। छाठवी योजना में विनियोग की दर 24.9% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा रोजगार में 3% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

2 जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण—भारत में 1971-81 में जनसंख्या की वृद्धि दर 2.2% रही है। देशव्यापी परिवार नियोजन अभियान चला कर इसमें कमी की जानी चाहिए। हालांकि अगले 15-20 वर्षों में जिन व्यक्तियों का काम घर लगाना है व तो अब तक जम से चके हैं। लेकिन जम दर का घटाने का विशेष महत्व है जिसमें अधिक ढील नहीं दी जानी चाहिए।

3 जन शक्ति नियोजन की आवश्यकता (Need for Manpower planning)—प्राथमिक शिक्षित व दक्ष जनशक्ति के सम्बंध में नियोजन की आवश्यकता पर विषय रूप से बल दिया जाने लगा है। यदि शिक्षित व दक्ष जन शक्ति की पूर्ति अथवा व्यवस्था में उत्पन्न मांग के अनुसार होती रहती है तो व्यक्ति व समाज दोनों का लाभ पश्चान्ना है। व्यक्ति को अपने भविष्य के सम्बंध में निश्चय व तत्काल समय यह विश्वास होता है कि उसका प्रशिक्षण का उचित उपयोग हो जायगा और वह लाभप्रद रूप में काम कर सकेगा। समाज को यह लाभ होता है कि वह शिक्षा का विकास प्राथमिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार कर सकता है। इनमें वृद्धि प्रति चिन्तना का अवसर आती है। लेकिन जनशक्ति नियोजन की सफलता अभी तक नहीं है कि वह मांग मांग का अपेक्षाकृत सही अनुमान लगाकर पूर्ति की व्यवस्था के लिए आवश्यक सुझाव दे। यदि नियोजन में त्रुटि के कारण भविष्य में दम धमिकों का अभाव रहता है तो अव्यवस्था के विकास को धक्का पहुँचता है। यदि दी व प्रशिक्षित जन शक्ति आवश्यकता से धीनी ज्यादा रहती है तो उसके उपयोग की व्यवस्था कर सकना विषय कठिन नहीं होता।

चूँकि समस्त जन शक्ति एक-सी नहीं होती इसलिए जनशक्ति-नियोजन में विभिन्न श्रेणियों जैसे डॉक्टरों नर्सों इन्जीनियरों, कृषि-स्नातकों एवं दस्तकारों आदि पर उनकी अलग-अलग शिक्षा व विशिष्टीकरण के अनुसार विचार किया जाता है। शिक्षित व दक्ष जन-शक्ति के आधिक्य की स्थिति को टाटने के लिए इस प्रकार का नियोजन करना बहुत आवश्यक माना गया है।

4 योजनाओं में विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन (Change in the Pattern of Investment in the Plans) — अब तक हमारी योजनाओं में विशेषतया द्वितीय योजना के आरम्भ से आधारभूत व भारी उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया है। इससे अर्थव्यवस्था के भावी विकास का आधार तो सुदृढ़ हो गया लेकिन रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ सके हैं। अब हम इस स्थिति में पहुँच गये हैं कि रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर अधिक ध्यान दे सके। इसके लिए आम ज़रूरत की उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों में विशेष रूप से विनियोग करना होगा जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ सकें और दूसरी तरफ मुद्रास्फीति पर भी नियन्त्रण स्थापित किया जा सकेगा। आशा है भावी योजनाओं में जन-साधारण की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जायेगा और उनके वितरण की व्यवस्था भी सुधारी जायेगी।

स्पष्ट है कि हमें बड़े उद्योगों के स्थान पर ग्रामीण व लघु उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देना होगा और ऐसी टेक्नोलॉजी चुननी होगी जो अधिक मात्रा में श्रम का उपयोग कर सके। इस सम्बन्ध में मध्यवर्ती या बीच की टेक्नोलॉजी (intermediate technology) को अपनाने पर अधिक बल देना चाहिए जो रोजगार बढ़ाने वाला होती है।

5 हरित क्रांति और रोजगार की समस्याएँ—1966 से कृषि में अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम एवं बहु फसल कार्यक्रम अपनाया गया है। भविष्य में सिंचाई के लघु साधनों का विस्तार करके एवं रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयों आदि का उपयोग करके कृषि में अल्परोजगार की समस्या कम की जा सकती है। भारतीय कृषि में टेक्नोलॉजी निम्न स्तर की छोड़कर उच्च स्तर की ओर अग्रसर होने लगी है। इससे कृषिगत उत्पादकता व आय में वृद्धि हुई है। कृषि के व्यवसायीकरण से कृषिगत विनियोगों में वृद्धि हो रही है। अधिक विनियोग से अधिक रोजगार की सम्भावनाओं का खुलना भी स्वाभाविक है। अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम अधिक क्षेत्रों में अपनाने से अधिक श्रमिकों को काम मिलेगा क्योंकि इससे सिंचाई खाद कीटनाशक दवाइयों व उपयोग बिजली आदि सभी कृषिगत क्रियाओं में श्रम की मांग बढ़ेगी। कृषि में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ेगी। बहु-फसल कार्यक्रम से भी कृषि में श्रम की मांग बढ़ेगी।

6 कृषि में स्थायी परिवर्तनों का रोजगार पर प्रभाव—भारत में भूमि पर सीमा-निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने से भी कुछ

सीमा तक रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं तथा निर्धनता कम की जा सकती है। कृषि में सस्थायित्व व तकनीकी परिवर्तन साथ साथ होने चाहिए। एक तरफ भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिए तथा दूसरी तरफ सिंचाई, उर्वरक, बीज, खाद आदि का तेजी से विस्तार करके कृषिगत उत्पादनता बढ़ायी जानी चाहिए। इनसे कृषिगत विकास की दर बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है जो एक उचित प्रवृत्ति है। कूड प्रोसेसिंग जियासी में उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं जिनमें मजदूरी में भी वृद्धि की जा सकेगी।

7. ग्रामीण औद्योगीकरण—ग्रामीण बिद्युतीकरण से विकेंद्रित आधार पर लघु व मध्यम स्तर की उद्योगों के विस्तार की आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। विभिन्न ग्रामीण उद्योगों का विकास करके देहातों में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। ग्रामीण बिद्युतीकरण से इसमें काफी मदद मिलेगी।

8. कृषि के विभिन्न सहायक घ-घों का विकास—सर्वद से भारतीय कृषक कृषि के साथ-साथ अन्य सहायक क्रियाओं में भी सतन्त्र रहा है। घाज देश में पशु-पालन, भेड़-पालन, सूअर-पालन, मुर्गी-पालन, आदि के विकास के लिए धीरे भी अनुसृत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। इनसे कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

9. ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के विस्तार की आवश्यकता—पहले बत गया था चुका है कि भारत में गम्भीर किस्म की मौसमी बेरोजगारी वाले प्रदेशों से खेतिहर श्रमिकों, अनुसूचित व आदिम जातियों, आदि के लोगों को रोजगार देने तथा साथ में उत्पादक परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण कार्यक्रमों का पृथक् से भी चलाने की आवश्यकता है। देहातों में ऐसे अनेक कार्य किये जा सकते हैं जिनसे पूँजी का निर्माण होता है। ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए लोगों को काम की गारंटी भी दी जा सकती है।

10. गाँवों में रोजगारोन्मुख नियोजन (Employment-Oriented Planning for Villages) की आवश्यकता—गाँवों में दस व घदस, शिक्षित व अशिक्षित, पुरुष व स्त्री सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है गाँवों को ठीक से बसाने की एक उनका समुचित दिशा देने की। गाँव में इन्जीनियरों, ओवरसियरों, डॉक्टरों, प्रव्यापकों डाक्टर-बालुओं, व डाकियों, मोटर चालकों, मित्रियों, छोटे उद्यमकर्ताओं व अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार की काफी सम्भावनाएँ निहित हैं। गाँवों में स्टोरेज, परिवहन व बिजली की सुविधाओं का विस्तार करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। जब लाखों गाँवों के निर्माण का कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जायगा तो कौन-कौन से अनेक प्रकार के नये काम खुलेंगे जिनकी गिनती लगाना कठिन है। अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि देहातों की तरफ पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में देहात आकर्षण के केन्द्र न होकर मात्र उजड़ते हुए स्थल बन

गये हैं। विलुप्तीकरण में गांवों में प्राथमिक जीवन की सभी सुविधाएँ पहुँचायी जा सकती हैं और धीरे-धीरे वहाँ की जन-शक्ति को उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। स्मरण रहे कि हमारे लक्ष्य केवल 'मजदूरी पर राजगार' के अवसर उत्पन्न करना मात्र नहीं हैं, बल्कि साथ में 'स्वरोजगार के अनेक अवसर' भी उत्पन्न करना है।

11 शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माध्यमिक शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जाना चाहिए और शिक्षा को मयामम्बव व्यावसायिक मोड़ देना चाहिए। जब तक शिक्षा प्रणाली का आर्थिक विकास की आवश्यकताओं से पूरा ताल-मेल नहीं बैठेगा, तब तक शिक्षा प्रणाली की देन समाज के लिए भ्रष्टाचार व असन्तुष्टि की ही जन्म देगी। अतः माध्यमिक शिक्षा को समाप्त करने के तुरन्त बाद ही अधिकांश छात्र-छात्राओं को रोजगार की तरफ ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। एम एस सी एम ई एम बी बी एस, पी एच डी आदि डिग्रियों के लिए सीमित लोगों की कठोर चयन से भर्ती की जानी चाहिए। मध्यम श्रेणी के पाठ्यक्रम (middle-level courses) प्रकाशन, मुद्रण, टूरिज्म, बीमा, नैवा-पद्धति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, फोटोग्राफी, स्टेजड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, पशु-पालन, मछली-पालन, टार्विज, वाहन-चालक, आदि के लिए चलाय जाय चाहिए ताकि इनमें अधिन शिक्षित लोगों को काम दिया जा सके।

12 सामाजिक परिवर्तन—देहातों में समुक्त परिवार-प्रणाली, जाति-प्रथा व सामाजिक असमानताओं के कारण श्रम की गतिशीलता के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ रहती हैं। अविष्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास से इन सामाजिक बन्धनों का प्रभाव कम हो जायेगा और श्रम की गतिशीलता बढ़ेगी। सामाजिक कठोरताओं व बन्धनों के घटने से कुछ वर्गों के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो सकेंगे।

13 रोजगार प्रदान करने वाले विनिमयालयों का विस्तार—मालिक व मजदूर में अधिक निकट का सम्पर्क स्थापित करने के लिए रोजगार विनिमयालयों का विस्तार की भी आवश्यकता है। मालिकों को इन कार्यालयों की सेवाओं का अधिन मात्रा में उपयोग करना चाहिए। साथ में इनके कुशल संचालन की भी आवश्यकता है।

14 महाराष्ट्र रोजगार-गारण्टी स्कीम के नमूने पर अन्य राज्यों में कार्य-क्रम बनाये जाएँ—महाराष्ट्र में 1972-73 से रोजगार-गारण्टी स्कीम लागू की गई थी। इसके अन्तर्गत गाँवों में रोजगार चाहने वालों को रोजगार की गारण्टी दी जाती है। राज्य विधान सभा में अगस्त 1977 में रोजगार-गारण्टी बिल पारित करने से वैधानिक रूप द दिया गया था। काम की गारण्टी अदस श्रमिकों को दी जाती है। इससे ग्रामीण रोजगार व विकास में मदद मिली है। ज्यादातर काम सिचाई-कार्यों में दिया गया है। महाराष्ट्र में यह स्कीम 1974 से काफी प्रगति पर

आधार पर पूंजी-निर्माण के कार्यों को संचालित करे। इससे रोजगार में स्थायित्व आयेगा, ग्रामीण जनता की उद्यमशक्ति बढ़ेगी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा, उत्पादन बढ़ेगा तथा विकास के सभी में ग्रामीण-निर्धन प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकेंगे।

चूँकि पिछले वर्षों में इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन व थाईलैण्ड में रोजगार के 'विशिष्ट कार्यक्रमों के बिना' रोजगार बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, अतः भारत को भी योजना के माध्यम से ही रोजगार बढ़ाने का गरुर प्रयास करना चाहिए। यदि जिला-स्तर पर नियोजन को सुदृढ़ किया जाय और रोजगार परि-योजनाओं का चुनाव व नियन्त्रण दृढ़तापूर्वक किया जाय तो रोजगार बढ़ाने में निश्चिन्त रूप से अधिक सफलता मिलेगी।

बेरोजगारी की समस्या भारत के समक्ष एक महान चुनौती है। भारत को इसका हल निकालने के लिए भारी प्रयास करना होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP), स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवावर्ग के प्रशिक्षण (TRYSEM), शिक्षित बेरोजगार युवा-वर्ग के लिए स्वरोजगार की स्कीम, तथा ग्रामीण-भूमिहीन-रोजगार-गारण्टी-कार्यक्रम (RLEGP) के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया गया है ताकि न केवल संपूर्ण नई श्रम-शक्ति को काम मिल सके बल्कि बेरोजगारी की पुरानी वकामा मात्रा (backlog) में भी कुछ कमी की जा सके।

अब जवाहर-रोजगार-योजना के माध्यम से ग्रामीण निर्धन-परिवारों में रोजगार की गारण्टी देने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया है जिससे रोजगार बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसके लिए नियोजन का अभाव दूर करना होगा।

भारत सरकार के सामने भी एक दुविधा की स्थिति है। वह उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजी के विकास, आधुनिकीकरण, उत्पादन के बड़े पैमाने, पैमाने की किफायतें प्राप्त करने व प्रतियोगिता को बढ़ाने पर जोर देना चाहती है। इसके लिए नई कम्प्यूटर नीति (नवम्बर 1984), नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (मार्च 1985) व नई टेक्सटाइल नीति (जून 1985) आदि घोषित की गई हैं। इनसे लागतें घटाने में तो मदद मिलेगी, लेकिन इस बात में सन्निक सदेह है कि इससे रोजगार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो सकेगी या नहीं। अतः भारत को कृषि व पारिवारिक उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। आठवीं योजना में रोजगार में 3% सालाना वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। 2000 ईस्वी में भारत के समक्ष करोड़ों नर-नारियों को रोजगार देने की जटिल समस्या विद्यमान रहेगी।

प्रश्न

1. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) भारत में जिला-दर-में बेरोजगारी की समीक्षा,

(Raj. II Yr. T. D. C., 1987)

(ii) भारत में ग्रन्थ-रोजगार,

(Raj. II Yr. T. D. C., 1984, 1985 & 1988)

(iii) भारत में धन शक्ति तथा

(iv) भारतीय ग्रन्थ-वस्था में ग्रन्थ रोजगार ।

(Raj. II Yr. T. D. C., 1980)

2. "भारत बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है ।" भारतीय सन्दर्भ में इस समस्या के कारणों, निराकरण के कार्यक्रमों तथा हमारे समाधान के समुचित उपायों की विवेचना कीजिए ।

(Raj. II Yr. T. D. C., 1981)

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण (Approach to Eighth Five Year Plan)

योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-1995) के दृष्टिकोण-प्रपत्र के संशोधित रूप को अपनी 29 अगस्त 1989 की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें आठवीं योजना के उद्देश्यों, स्वरूप, लक्ष्यों व विकास के आयामों पर एक अध्याय में प्रकाश डाला गया है।¹

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता व परिवेश-सन्तुलन व स्थिरता प्राप्त करना रहा है। आर्थिक विकास के माध्यम से सामग्रिक रोजगार, भोजन, जल, वस्त्र व आवास, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास करने का प्रयास निरन्तर जारी रहा है।

घृष्टभूमि.—सातवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पत्ति (Gross Domestic Product) (GDP) में औसत वृद्धि दर 5.4% प्राप्त होने की आशा है। अस्सी के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर पहले से ऊँची रही है। हाल के वर्षों में कृषिगत विकास कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि की बजाय उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुआ है। देश के पूर्वी भाग में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन में 8% से अधिक वृद्धि-दर रही है। उर्वरकों व सुपर फॉसिल मावर समन्धों जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुछ क्षेत्रों में भारतीय उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी हो गये हैं। आधार ढांचे की कमियाँ व बन्धन कम हुए हैं। सातवीं योजना में विद्युत-सृजन पहले से 60% अधिक हुआ है। 1986-87 से निर्यातों में वृद्धि-दर (मात्रा के रूप में) औसतन 10% वार्षिक रही है। निर्धनता का अनुपात 1961-62 में 54% से घटकर 1983-84 में 37% पर आ गया तथा सातवीं योजना के अन्त में इसके 30% से कम रहने की सम्भावना है।

1. यह The Economic Times, September 2, 1989 में पृष्ठ 7 पर छपा गया है जिसका यहाँ उपयोग किया गया है।

लेकिन अर्थ-व्यवस्था में कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियाँ भी उभरी हैं जिनका सामना देश का धाड़वी योजना में करना होगा। सबसे प्रथम जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 2.1% जारी है। प्रति वय जनसंख्या 16-17 मिलियन बढ़ जाती है। कुल गति 2.5% मानना बढ़ रही है जबकि राजस्व 2% मानना बढ़ रहा है जो कम है। महाराष्ट्र एक तेज गति से बढ़ रहा है। हम प्रतापी के अन्त तक राज्यों जनसंख्या के 30 करोड़ होने की आशा है। प्राथमिक अन्तर बढ़े हुए हैं। अमि ऊँचा माधनो व सन्निध-पन्थों के उपयोग का वर्तमान पद्धति में कई दोष हैं। पूँजा अन्तर्गत अनुपात ऊँचा बना हुआ है और ऊँचा का उपयोग भी अस्वाभाविक बना हुआ है। देश पर व्याज व ऋण भार ऊँचा हो गया है। अ-भुगतान-अनुवर्तन-का तरफ काफी चिंता बना हुयी है। शिक्षा व संस्कृति में ऐसे परिवर्तन आ रही हैं जो देश का एकता की तरफ ल जा सकें।

इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आठवी पंचवर्षीय योजना के निम्न उद्देश्य (Objectives) रखे गए हैं।

उद्देश्य — विकास व आधुनिकीकरण

(i) सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 6% वार्षिक वृद्धि-दर प्राप्त करना (at least 6% annual growth rate)

(ii) अस्तमानताओं को कम करने व विकसित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।

(iii) विनिर्माण (manufacturing) के क्षेत्र में बढ़ती हुई सीमाओं तक अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का दमक प्राप्त करना और चुन चुन हुए क्षेत्रों में उत्तमता व गुण-वत्ता हासिल करना,

(iv) टक्कोपोजी साथ सुरक्षा व विनिर्माण के साधनों में आम निभरता प्राप्त करना

(v) बसलती हुई अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए और उनके अनुकूल देश की अर्थव्यवस्था को ढालने के लिए इसको अधिक सक्षम बनाना

निधनता-उन्मुख व समानता

(vi) सातवा योजना के अन्त में निधनता अनुपात 28-30% से घटाकर आठवी योजना के अन्त में 18-20% तक लाना

(vii) राजस्व में 3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना ताकि निधनों को रोजगार का सारनी मिल सकें तथा

(viii) निधनों बच्चों व अर्थ कमजोर समूहों के विकास पर विशेष रूप से जोर देना।

गाठवीं योजना में 1989-90 के भावों पर कुल विनियोग 645,000-650,000 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है जिसमें सार्वजनिक विनियोग लगभग 300,000 करोड़ रु. तथा सार्वजनिक परिवहन लगभग 350,000 करोड़ रु. होगा। इतने साधन प्राप्त करने के लिए कर सक्त घरेलू उत्पत्ति (GDP) का अनुपात 11% से बढ़कर 18-9% करना होगा। (1-9% वृद्धि) यह कार्य काफी दुष्कर प्रतीत होता है। हालांकि असम्भव नहीं है।

गाठवीं पंचवर्षीय योजना में सुझायी गयी व्यूहरचनाएँ (Strategies)

(1) निर्पन्ता-निवारण व रोजगार-संबर्द्धन—कार्यक्रमों पर नये सिरे से जोर दिया जायगा ताकि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की उत्पादकता व धानदानी में वृद्धि की जा सके। मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम चलाया जायगा ताकि लोगों को 'काम का अधिकार' दिया जा सके। स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जायेंगे तथा दक्षता का विकास किया जायगा।

(2) निर्धनोन्मुख सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए साधनों का उत्पादन बढ़ाया जायगा।

कृषि के विविधीकरण व कृषि आधारित उद्योगों व प्रोसेसिंग का विकास किया जायगा ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। प्रादेशिक शक्ति को, भूमि-विकास कार्यक्रम, वैज्ञानिक जल-प्रबंध, भूमि-विकास कार्यक्रम, जल-प्रबंध, भूमि सर्वोत्तम उपयोग व नए फसल-प्रारूप विकसित किये जायेंगे।

(3) ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण सड़को, आवास व स्वास्थ्य की सुविधाओं, साफ पेयजल व तकनीकी शिक्षा आदि का विकास किया जायगा।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर दिया जायगा।

(4) लघु पैमाने के उद्योगों के विकास को ऊंची प्राथमिकता दी जायगी ताकि रोजगार तेजी से बढ़ सके।

(5) पर्यावरण की सुरक्षा व परिवेश-मतुलन के लिए विकास-प्रयासों को नया मोड़ दिया जायगा।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तनों व प्रवृत्तियों पर अधिक नजर रखी जायगी ताकि भारत तीव्र गति से आर्थिक विकास की प्रक्रिया जारी रख सके।

(7) ऊंची विकास की दर प्राप्त करने के लिए साधनों के उपयोग की कार्यकुशलता बढ़ानी होगी, बचत व विनियोग की दरें बढ़ानी होंगी (GDP से) निर्मात की वृद्धि-दर ऊंची करनी होगी।

निम्न तालिका में कुछ प्रमुख लक्ष्य दिये गये हैं जिन्हें आठवी योजना में प्राप्त करना होगा ताकि विकास की वार्षिक दर कम से कम 6% उपलब्ध हो सके।

तालिका 1

6% विकास-दर के लिए निम्न समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक

समष्टिगत आर्थिक मुद्दे	आठवी योजना (प्रत्याशित औसत)	आठवी योजना (औसत प्रारम्भिक अनुमान)
(1) बढमान पूँजी-उत्पत्ति अनुपात (ICOR)	4.30	4.15
(2) कुल बचत (GDP का %)	21.1	23.3
निजी निरमित घरेलू सार्वजनिक	1.8 16.9 2.4	2.0 17.7 3.6
(3) कुल विनियोग (GDP का %)	23.1	24.9
(4) शुद्ध पूँजी का आयात (GDP का %)	2.0	1.6
(5) निर्यात-अनुपात (GDP का %)	17.0	18.9
(6) सार्वजनिक उपभोग (GDP का %)	12.1	13.3
(7) निर्यात वृद्धि (मात्रा में % प्रतिवर्ष)	7-7.5	11.5

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि आठवी योजना में निम्न समष्टिगत वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत जरूरी माना गया है ताकि विकास की वार्षिक दर कम से कम 6% हो सके।

(1) सीमान्त पूँजी-उत्पत्ति-अनुपात 4.3 से घटाकर 4.15 करना होगा। राष्ट्रीय लेखों के नये सिरीज के अनुसार यह सातवी योजना में 4.3 रहा जिसे आठवी योजना में घटाकर 4.15 पर लाना होगा। इसके लिए निम्न कदम उठाने होंगे :—

(अ) श्रम व माल (men and materials) की उत्पादकता बढ़ानी होगी। इसके लिए हर प्रकार की फिजूलखर्ची समाप्त करनी होगी तथा साधनों का सर्वोत्तम भावटन करना होगा। सभी क्षेत्रों में प्रस्थापित समताओं का पूरा उपयोग करना होगा। (आ) नीचे ICOR वाले क्षेत्रों में विनियोग को ऊँची प्राथमिकता देनी होगी ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। इसके लिए ग्रामीण व लघु उद्योगों व अन्य श्रम-गहन क्रियाओं पर बल देना होगा। (इ) प्रोजेक्टों को जल्दी पूरा करने के कार्य को उचित प्राथमिकता देनी होगी। वितरण-प्रणाली के रिसावों व हानियों (leakages and losses) को न्यूनतम करना होगा तथा निर्माण व संचालन टेक्नोलोजी का कार्यकुशल उपयोग करना होगा। (ई) ऊर्जा के उपयोग में कार्यकुशलता बढ़ाने से भी ICOR नीचा आयेगा। (उ) सार्वजनिक विनियोग की प्राथमिकताओं, लाइसेंस व व्यापार प्रणालियों, प्रशासित मूल्यों, करों, अनुसंधान व विकास, गुणवत्ता-नियन्त्रण व टेक्नोलोजिकल उत्थान, आदि सभी दिशाओं में कार्यकुशलता के ऊँचे स्तर प्राप्त करने से ही ICOR घटाया जा सकेगा।

इस प्रकार आठवी पंचवर्षीय योजना में ICOR घटाना होगा ताकि एक रुपये की उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए, स्थिर मूल्यों पर, कम पूँजी की मात्रा से काम चलाया जा सके।

वचन की दर 21.1% से बढ़ाकर 23.3% करनी होगी तथा विनियोग की दर 23.1% से बढ़ाकर 24.9% करनी होगी। निर्यात की वार्षिक दर 7-7½% (मात्रा के रूप में) से बढ़ाकर 11.5-12% वार्षिक करनी होगी। आठवी योजना में मूल्य-स्थिरता पर भी जोर दिया गया है।

निम्न तालिका में पाठवी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास का प्रारूप दिया गया है -

क्षेत्र	जोड़ गये मूल्य में विकास की दर 1981-82 से 1987-88 तक	1990-91 से 1994-95 तक का अनुमानित	कुल GDP में अंश 1989-90	1994-95
1 कृषि	17	30	30.6	26.6
2 खनन	9.5	9.0	3.7	4.3
3 विनिर्माण	8.2	9.0	20.8	23.9
4 निर्माण	3.1	4.0	4.2	3.8
5 विद्युत	9.4	10.0	2.2	2.7
6 परिवहन	7.7	7.8	5.6	6.1
7 संचार	6.3	10.5	0.8	0.9
8 सेवाएँ	5.7	5.8	32.1	31.7
कुल GDP	4.9	6.0	100.0	100.0

तालिका के प्रमुख निष्कर्ष -

(1) पाठवी पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विभाग की वार्षिक दर 3% रखी

गयी है, जबकि 1981-82 से 1987-88 तक यह 1.7% रही थी, तार्किक 1988-89 व 1989-90 के अनुमान शामिल करने पर यह 2.8% आती है।

(2) विनिर्माण में बिजली की दर 9% मुभासी मधी है जो पूर्व अनुमान के अनुरूप है।

(3) साठवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1994-95 में अल्पवयस्कता में भारी संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Change) की सम्भावना व्यक्त की गई है क्योंकि उच्च लागत लागत व विनिर्माण का GDI में अंश 28.2% हो जाएगा जो कृषि के 26.6% के अंश से अधिक होगा। ऐसा पहली बार दर्शाया गया है।

इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन के एक नये दौर में प्रवेश करने जा रही है, जहाँ खनिज व विनिर्माण का राष्ट्रीय आय में अंश कृषि से भी अधिक होने की आशा है।

भारत में जनसंख्या की दृष्टि से स्थिति के काफी बदल रहे की आशा है। जो राज्य जनसंख्या-नियोजन में पीछे रह गए हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश जम्मू-काश्मीर व मिजोरम, उनमें स्त्री-शिक्षा बढ़ाने, शिशु मृत्यु-दर घटाने, तथा माता व शिशु की अधिक देखभाल करने की आवश्यकता है ताकि परिवार का आकार कम किया जा सके।

इस प्रकार साठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जा सकता है।

साठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रश्न (Approach paper) की समीक्षा

इसमें छह साठवीं पंचवर्षीय योजना के संस्थापक-प्रश्न में से पाँच मुख्य प्रश्नों का उल्लेख किया है। उनमें प्रथम प्रश्न है कि हमें कम से कम 0% वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य स्थापित करना होता है और अन्य लक्ष्य जैसे वस्ती की दर, विनिर्माण की दर निर्यात वृद्धि-दर आदि, इसे प्राप्त करने की दृष्टि से प्रेरणक बिंदु बनने के।

- 1 "State of Indian Economy, Document in Mainstream, August, 19, 1969, pp. 11-12; D. T. Lakshwala, *Decentralised Planning must be given a fair trial in the Economic Times*, July 6, 1969 and S. P. Gupta, *Growth Target for VII Plan in Financial Express*, August 7, 1969.

विभिन्न विद्वानों ने साठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-प्रपत्र के पूर्ण रूपों पर अपने विचार प्रकट किये हैं जिनमें उनकी भावी भारतीय नियोजन पर विचार-धारा का पता चलता है। दृष्टिकोण-प्रपत्र में उद्देश्यों, व्यूहरचनाओं व विकास के आयामों के सम्बन्ध में कोई विशेष नहीं बात नजर नहीं आती। सब पूछा जाय तो साठवीं योजना पूर्ण याजनाधो, विशेषतया सातवीं योजना, का विस्तार मात्र प्रतीत होती है।

साठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र के सम्बन्ध में निम्न समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है :

(1) इसमें देश की वर्तमान गम्भीर आर्थिक स्थिति का परिचय, झलक व समाधान नहीं प्रतीत होते :—

इस समय, अर्थात् साठवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ण सध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था गम्भीर संकट में पड़ी हुयी है जिसका सामना इस दृष्टिकोण-प्रपत्र से नहीं लगता। सरकार राजकोषीय संकट का सामना कर रही है। राजस्व-घाटे की पूर्ति पूँजी-साठे से की जाती है जिसके लिए उधार का आश्रय लिया जाता है। इससे ऋण-सेवा भार बहुत बड़ गया है।

(अ) देश पर विदेशी कर्ज की राशि 1 लाख करोड़ रुपये की सीमा पार कर चुकी है। ऋण-सेवा भार चालू प्राप्तिशी (Current receipts) का 30% तक हो गया है, जो सुरक्षित सीमा (20%) से काफी ऊँचा है। विदेशी कर्ज का भार बढन से अन्तर्गोष्ठीय एजेन्सियों व्यापारिक बैंकों व विदेशी सरकारों का हमारी आर्थिक नीतियों पर दबाव बढने का भय उत्पन्न हो गया है।

(ब) सरकार का ऋण (योजना व गैर-योजना) काफी बड़ गया है। केन्द्रीय सरकार का योजना-व्यय 1980-81 में लगभग 9 हजार करोड़ रु. से बढकर 1989-90 बजट-प्रनुमानों में लगभग 28 हजार करोड़ रु तथा गैर-योजना व्यय लगभग 13 हजार करोड़ रु से बढकर 54 हजार करोड़ रु हो गया है। इस प्रकार गैर-योजना व्यय योजना-व्यय से अधिक तेज गति से बढा है। कुल व्यय में योजना-व्यय का अंश 1980-81 में 41% था जो घटकर 1989-90 में 34% पर आ गया है। इसी अवधि में केन्द्रीय व राज्यीय नद्विपदी की राशि 3160 करोड़ रु से बढकर 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है। केन्द्रीय ऋणों पर व्याज के जुगतान 2500 करोड़ रु से बढकर 17 हजार करोड़ रु. तक हो गये हैं। भारत सरकार का सुरक्षा व्यय 13 हजार करोड़ रु. तक पहुँच गया है। इस प्रकार 1989-90 में भारतीय अर्थव्यवस्था ऋण के फँदे में फँस गयी है। राज योजना की वित्तीय व्यवस्था उधार व घाट की वित्त-व्यवस्था से की जानी है जो एक चिन्ता का विषय है। उपभाग-व्यय तेज गति से बढ रहा है।

देश में परोक्ष करो या भार उठाने से ग्राम जनता की दिक्कतें बढ़ी हैं। सवा क्षेत्र से ग्रामदनी के बढ़ने की रफ्तार वृषिगत व औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

(स) औद्योगिक विकास की दर तो ऊँची रही है लेकिन ऊर्जा गहन व श्रामगत-गहन विकास होने से इसने मुगतान सन्तुलन बढ़ाया है। एक वर्ग-विशेष के लाभ के लिए उत्पादन का ढाँचा काम कर रहा है। ग्राम जनता के काम की वस्तुओं का उत्पादन सीमित मात्रा में बढ़ गया है जबकि विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक तेज गति से बढ़ा है। इस प्रकार भारत में विवृत-विस्म का व ग्राम आदमी के हितों के विपरीत विस्म का विकास जोर पकड़ता जा रहा है।

(द) महगाई के कारण भारतीय रुपये का मूल्य जून 1989 में 1960 की तुलना में केवल 12 पैसे रह गया है। रुपये का विदेशी विनिमय मूल्य डालर जर्मन मार्क स्टर्लिंग येन आदि में काफी गिर गया है और लगातार गिरता जा रहा है। अतः इन विविध प्रकार की समस्याओं के प्रति आठवी योजना के दृष्टिकोण-प्रपत्र में पर्याप्त जागरूकता प्रगत होनी चाहिए थी जो नहीं हो पायी हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आठवी योजना दश को अधिक सकट के गर्त में से निकालने के बजाय इसे उसमें घोर गहरा फँसा देगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नया मार्ग अपनाने की आवश्यकता है जिसका उल्लेख दृष्टिकोण-प्रपत्र में नहीं मिलता।

(2) डा एस पी गुप्ता का कहना है कि 6% विकास की दर प्राप्त करने के लिए केवल बचत की दर व वर्तमान पूँजी-उत्पत्ति अनुपात (ICOR) पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सावजनिक क्षेत्र से वित्तीय बचतों व साधनों की उपलब्धि मुगतान सन्तुलन आदि पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा।

भारत में घाट की वित्त व्यवस्था विदेशी मुगतान-खाते में चालू खाते का घाटा (Current account deficit) आदि बहुत ऊँचे हो गये हैं। भारत में नोट छापकर बजट के घाटे की पूर्ति की सीमा बहुत ऊँची हो गई है। इसलिए बचत की दर को बढ़ाने में काफी कठिनाई का सामना करना होगा। कहने का आशय है कि आठवी योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए आवश्यक साधन जुटा पाना कठिन होगा। इसलिए विकास की दर का तथ्य 6% से कम रखना सम्भवतः ज्यादा व्यावहारिक व वास्तविक होता।

निष्कर्ष —

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में देश गम्भीर आर्थिक सकट के दौर में गुजर रहा है। अतः आठवी पंचवर्षीय योजना में नियोजन की

नीतियों में प्रामुख्य-मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई है। सरकार को सम्पूर्ण प्रथमत्र ग्राम जनता के हितों की तरफ मोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रायश्चित्त पर भारी अंकुश लगाना होगा, विशेषतया बिल्दासी उपयोग को बढ़ाने वाले प्रायश्चित्तों को कम करना होगा। अजडूरी-प्रायश्चित्त नीति निर्वाचित करके ग्राम जनता को मुद्रास्फीति की कठिनाइयों से बचाना होगा। साधनजनिक व्यय की वृद्धि को सीमित करके उधार व घाट की वित्त-व्यवस्था के उपयोग में कमी करनी होगी। इस प्रकार जन-प्रमर्शक प्रगतिशील नीतियाँ अपनाकर भारत को आत्म-निर्भर आर्थिक विकास के लक्ष्य की ओर पुनः अग्रसर होना चाहिए ताकि नियोजन में जनता की भास्था बढ़ सके और भारत समता, विकास, आत्म निर्भरता व आधुनिकीकरण की दिशा में अधिक सुनिश्चित प्रगति कर सके।

राजस्थान के आर्थिक व मानवीय साधन : भूमि, जल, पशु, खनिज-पदार्थ व जनसंख्या (Economic and Human Resources of Rajasthan : Land, Water, Cattle, Minerals and Population)

राजस्थान का गौरवमय इतिहास

राजस्थान का भारत के इतिहास में एक गौरवमय स्थान रहा है। यहाँ की पवित्र भूमि ने महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी व साहसी योद्धाओं को जन्म दिया है। उनके वीरतापूर्ण एवं त्याग से ओत प्रोत कार्य अनेक ऐतिहासिक तथा काव्य-कृतियों में विद्यमान हैं जो भावी युगों में देशवासियों को प्रेरणा देते रहेंगे। टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक : *Annals and Antiquities of Rajasthan* के पृष्ठ यहाँ के वीरों की अनेक गुण-गाथाओं से भरे हुए हैं। वीरोचित कार्यों एवं शौर्य की यह परम्परा प्राच्युनिक राजस्थान का 'आध्यात्मिक आधार' (spiritual base) मानी जा सकती है। जहाँ एक तरफ राजस्थान की इतनी उच्च ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परम्पराएँ रही हैं, वहाँ दूसरी तरफ इसी भूमि को यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि यहाँ के उद्यमकर्तृओं ने देश के विभिन्न भागों में जाकर उद्योग व व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन्होंने विदेशों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित किये हैं। राजस्थान ने ही बिड़ला, बॉम्बे, सिंधानिया, सूरजमल नागरमल, आदि उद्योगपतियों व व्यावसायिक समूहों को जन्म दिया है। यहाँ के शिल्पकार व कारीगर पत्थर, संगमरमर, लकड़ी, पीतल, सोना चांदी, चीनी मिट्टी, चमड़ा व वस्त्र पर अपनी कलाकृतियों में बेजोड़ हैं और देश-विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। वे आज भी अपनी प्रतिभा को न केवल कायम रखे हुए हैं, बल्कि अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। साथ में हमें यह भी स्मरण रखना है कि प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यहाँ जन-साधारण को समय-समय पर आर्थिक

जीवन में कई प्रकार के कष्टों को भी झेलना पड़ा है। प्रति वर्ष राज्य के किसी न किसी भाग में सूखे व अकाल की काली छाया पड़ती रहती है। राज्य सरकार के लिए अकाल राहत कार्यों का बड़ा महत्व है। इनके द्वारा अकाल पीड़ित लोगों के लिए रोजगार व साधनों की व्यवस्था की जाती है। साथ में पेयजल की सप्लाई भी बढ़ायी जाती है, तथा पशुओं के लिए चारे का इन्तजाम किया जाता है। राज्य बाढ़ से भी सतिप्रस्त होता रहा है। इस अध्याय में हम राजस्थान के भौतिक वातावरण व प्राकृतिक साधनों का संक्षिप्त परिचय देकर राज्य की जनसंख्या सम्बन्धी स्थिति का वर्णन करेंगे।

राजस्थान का निर्माण

वर्तमान राजस्थान राज्य एकीकरण की एक लम्बी प्रक्रिया के बाद बन पाया है। यह प्रक्रिया 17 मार्च 1948 को प्रारम्भ होकर 1956 में समाप्त हुई थी। शुरू में 17 मार्च 1948 को धनवर, भरतपुर, धौलपुर व करोली राज्यों एवं नौमराना की चोफगिरी को मिलाकर मध्य संध बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को मध्य पड़ोसी राज्य, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक इस संध में मिल गये। इससे पूर्व-राजस्थान का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया। मध्य संध के निर्माण के एक माह बाद उसमें उदयपुर शामिल हो गया। 30 मार्च 1949 तक पहले के राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व जोधपुर भी शामिल हो गये और इस प्रकार बृहद् राजस्थान का निर्माण हुआ। छोटी अवस्था में सिरोही राज्य का कुछ भाग इसमें मिला दिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने पर अजमेर राज्य, पहले बम्बई राज्य का साबु रोड जालुका एवं पहले के मध्य भारत का सुनत बापा प्रदेश राजस्थान में मिल गये और कोटा जिले का मिरोज उप-खण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया।

भौगोलिक वातावरण

(घ) स्थिति, सीमा क्षेत्रफल व प्राकृतिक वसा—राजस्थान भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में $23^{\circ}3'$ से $30^{\circ}12'$ उत्तरी प्रक्षालांश एवं $69^{\circ}30'$ से $78^{\circ}17'$ पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह सहा प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की पश्चिमी व उत्तरी सीमाएं पश्चिमी पाकिस्तान की पूर्वी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। इससे उत्तर व उत्तर-पूर्व में पंजाब व उत्तर-प्रदेश पूर्व व दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्य हैं। इसका क्षेत्रफल समस्त भारत के क्षेत्रफल का लगभग दसवां भाग है (10.4%)। 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 3.43 करोड़ थी जो भारत की कुल जनसंख्या का 5% थी। 1911-91 में इसमें लगभग 33% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में समस्त भारत की वृद्धि दर 25% थी। इस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि की दर वार्षिक 1.5%

भारत की तुलना में 8 प्रतिशत बिन्दु अधिक रही है, जो वास्तव में एक चिंता का विषय है।

राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर भारत और पश्चिमी पाकिस्तान एक-दूसरे के समक्ष लगभग 1070 किलोमीटर की दूरी तक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान व पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की सीमा मूलतः प्राकृतिक है और यह थार के रेगिस्तान में से गुजरती है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और यातायात की कठिनाइयाँ भी पायी जाती हैं। इस क्षेत्र की इन प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण ही सीमा सुरक्षा पर व्यय की मात्रा अधिक होती है और इस क्षेत्र में सड़कें व रेलें बनाना भी आवश्यक है जिससे युद्ध व संधर्ष के समय सैनिक व सैनिक साज-सामान सुगमता पूर्वक भेजे जा सकें। वैसे सीमा पर रेगिस्तान के आ जाने में इस पर कुछ प्राकृतिक रोक ही लग जाती है लेकिन 1965 के भारत-पाक संधर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यातायात की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाकर शत्रु राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक सीमा का भी उल्लंघन किया जा सकता है।

अरावली पहाड़—राजस्थान की भौतिक विशेषताओं पर अरावली पहाड़ का बड़ा प्रभाव पड़ा है। अरावली पर्वतमालाएँ राज्य को चीरती हुई दक्षिण पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक फैली हुई हैं, इनका दक्षिणी पश्चिमी छोर माउण्ट आबू के समीप है और इनका उत्तरी-पूर्वी भाग खेनडी के समीप समाप्त होता है। अरावली पर्वत-मालाओं ने राजस्थान को प्राकृतिक भागों में बाँट दिया है—राजस्थान का 3/5 भाग अरावली के उत्तर-पश्चिम में पड़ता है और 2/5 भाग दक्षिण पूर्व में। इनका जलवायु पर भी असर पड़ता है। ये पश्चिम में आने वाली मिट्टी को भी रोकते हैं।

पश्चिमी राजस्थान—अरावली के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से मरा हुआ है। इसमें जनसंख्या कम है। इस प्रदेश का पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान (Thar Desert) कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर के कुछ हिस्सों के निवासियों को रेगिस्तान के शुष्क जीवन का सामना करना पड़ता है। गंगानगर के कुछ भागों को छोड़कर इस प्रदेश में घास वही भी बहुत दुर्लभ है। इस प्रदेश में प्रायः अकाल पड़ा करते हैं। काफी दूर तक यात्रा करने पर भी वनस्पति का नामोनिशान नहीं दिखाई देता। केवल सावन की घास ही नहीं वही नजर आती है। पशुओं के लिए यह घास ईंधन का स्रोत भी जाती है। रेगिस्तान का निर्माण अरब सागर व बच्छा के रण की दिशा से आने वाली उत्तरी-पश्चिमी हवाओं से हुआ है जो आने साथ मिट्टी के साथ आती हैं।

हम प्रायः चल कर देखेंगे कि रेगिस्तान की इस समस्या का समाधान इन्दिरा गांधी नहर (पहले राजस्थान नहर कहानी थी) है जो समस्त प्रदेश को हरा-भरा कर दगी।

दक्षिण-पूर्वी राजस्थान—इस भाग में उपजाऊ भूमि पाई जाती है तथा नदियाँ बहती हैं। इसी भाग में उदयपुर (मेवाड़) का प्रदेश है जो 'राजस्थान का हृदय' कहलाता है। नासवाड़ा जिले का दक्षिणी व पूर्वी भाग अत्यन्त सुन्दर है। वर्षा के तुरन्त बाद यह बहुत घाकपंक हो जाता है। बनास व चम्बल नदियाँ राजस्थान के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। इस प्रदेश में कोटा व बून्देली के क्षेत्र हैं जो 'पठार' का प्रदेश बनाते हैं। भरतपुर के मैदानी भाग इसी में आते हैं।

नदियाँ व झीलें—राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग में केवल सूनी नदी ही काम की है। इसका उद्गम अजमेर के पास पुष्कर घाटी के समीप होता है और यह पश्चिम में बहती हुई दक्षिण-पश्चिमी भाग में 370 किलोमीटर तक बहकर बच्छ के रण में प्रवेश करती है। पहले कहा जा चुका है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में नदियों का विशेष स्थान है। चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चम्बल घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में विशेष महत्व रखती है। चम्बल के बाद बनास नदी का स्थान आता है। यह कुम्भलगढ़ जिले के पास अरावली से निकलकर लगभग 480 किलोमीटर बहकर चम्बल में मिल जाती है। बाणगंगा जयपुर के पास से निकलकर पूर्वी भाग में बहती हुई (भरतपुर व धौलपुर में से) यमुना में मिलती। माही नदी मुख्यतया गुजरात की नदी है, लेकिन यह कुछ दूरी तक बीसवाड़ा में तथा डगरपुर की सीमा पर बहती है।

राजस्थान में साँभर व डीडवाना में नमक की झीलें हैं। राज्य अपनी कृत्रिम झीलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उदयपुर की जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी गयी है। दूसरी झील राजसमन्द है। यह प्रकाल-सहायता कार्य का काफी पुराना नमूना प्रस्तुत करती है। तीसरी झील उदयसागर है। पिछोला झील भी काफी महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा फतहसागर झील है। अजमेर में अन्नासागर झील काफी प्रसिद्ध झीलों में से एक मानी गई है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। अजमेर में दो झीलें हैं। ओपपुर, झलवार, व माउण्ट घाबू में भी झीलें हैं। ये स्पन पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण के केन्द्र हैं। माउण्ट घाबू का नक्की तालाब काफी सुन्दर व शमनीय है।

(प्रा.) जलवायु—राजस्थान की जलवायु का एक विशेष लक्षण यह है कि यहाँ तापक्रम में भारी अन्तर पाया जाता है। यहाँ जितना काल में बहुत ठण्ड पड़ती है और नई स्थानों पर तापक्रम हिम-बिन्दु में भी नीचे आ जाता है और पाला पड़ जाता है। दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत तेज पड़ती है। पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश माना जाता है।

सभी राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में सामान्य वर्षा का स्तर (51 सेंटीमीटर) न्यूनतम स्तर का माना गया है। यहाँ वर्षा का वितरण असामान्य व अनिश्चित किस्म का रहता है। यहाँ पर सामान्य वर्षा अलावाड़ा जिले की पहाड़ियों में 100

सेन्टीमीटर तक होती है। जबकि जैसलमेर जिले के रेगिस्तान में यह 16 सेन्टीमीटर तक होती है।

(इ) मिट्टी व वनस्पति—राजस्थान की मिट्टियों को मुख्यतया सात भागों में बाँटा गया है -

1. रेगिस्तानी मिट्टी—राजस्थान में यह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। घरावल्लो में पश्चिम में राज्य के समस्त भागों में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसमें प्रमुख जिले इस प्रकार हैं : श्री गंगानगर, पुरू, भुंभुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर तथा सीकर। यह काफी अनुपजाऊ होती है।

2. भूरी-पीली (रेगिस्तानी मिट्टी) —यह बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर व भुंभुनू जिलों में पायी जाती है। इस मिट्टी में फोस्फेट का अंश ऊँचा होता है।

3. लाल व पीली मिट्टी—यह उदयपुर, भीलवाड़ा, व अजमेर जिलों के पश्चिमी भाग में पायी जाती है। इस मिट्टी में कार्बोनेट व ह्यूमस तत्व कम मात्रा में पाया जाता है।

4. फेरुजिनस (Ferruginous) लाल मिट्टी—यह मिट्टी उदयपुर जिलों के मध्य व दक्षिणी भाग में एवं सम्पूर्ण डूंगरपुर जिले में पायी जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है।

5. मिश्रित लाल व काली मिट्टी—यह मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व भीलवाड़ा के पूर्वी भागों में मिलती है।

6. मध्यम भेरी की काली मिट्टी—यह भामनौर पर कोटा, ब दी व झालावाड़ जिलों में पायी जाती है।

7. नद्यारी मिट्टी (Alluvial Soils)—यह मुख्यतः अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल व ह्यूमस कम होती है।

वनस्पति—राजस्थान में कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में मामूली वनस्पति से लेकर घरावल्लो के पूर्व व दक्षिण पूर्व में पतझड़ व सदाबहार किस्म के जंगल पाये जाते हैं। राज्य के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के लगभग 6-3% भाग में वन पाये जाते हैं। पंजाब की छोड़कर देश में सबसे कम वन-सम्पदा राजस्थान की ही मानी जाती है। वनों के अन्तर्गत कम क्षेत्रफल के कारण राज्य में ई वन व औद्योगिक लकड़ी की माँग को पूर्ति कर सकना कठिन रहता है। पश्चिमी राजस्थान में वनों का नितान्त अभाव पाया जाता है।

राजस्थान का पशु-धन

राजस्थान के लिए पशु-सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्र का 55 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ जीविकोपार्जन का

मुख्य मात्तन पशुपालन करना है। इससे राज्य की झुद्ध धरेलु उत्पाति का 12% से अधिक अग प्राप्त होता है। राजस्थान मे देश के पशु धन का 7% तथा भेडों का 30% अग पाया जाता है। राज्य में देश के दुध उत्पादन का 11% तथा ऊन के उत्पादन का 40% प्राप्त होता है। पशुधों का सख्या 1977 में 4.14 करोड से बढ़कर 1983 में 4.95 करोड हो गई थी। इस प्रकार इस अवधि मे पशुधों की सख्या मे 19.65% की वृद्धि हुई। विशेष वृद्धि बकरी, भेड, व बैन (नर-माडा) मे हुई है। 1983 मे पशुधों का वर्गीकरण इस प्रकार था : गोधन (गाय-बैल) 1.35 करोड, बैन बैलों सहित 60.34 लाख, भेड भेड 133.9 लाख, बकरी-बकरे 1.54 करोड तथा अन्य 12 लाख।

राजस्थान मे पशुधों की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पायी जाती हैं। भागीरी बैन भाग होने मे बहुत सुस्त पाये गये हैं। ये प्रतिवर्ष हजारों की सख्या मे राजस्थान से बाहर भी भेजे जाते हैं। राज्य सरकार ने राठी, थारथारकर अथवा भागीरी नस्लों वाले धेडों मे चुने हुए दंग पर पशुधों के प्रजनन (selective breeding) की नीति अपनायी है। इसके अन्तर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुधों को चुना जाता है। कान्केज, गिर, हरियाणा व मातवी नस्लों के लिए चुने हुए दंग पर (सिलेक्टिव) तथा 'कोत वीडिय' दोनों विधियों के आधार पर पशुधों की नस्ल-विकास का काम किया जाता है। कोत वीडिय मे दूसरी नस्ल के उत्तम पशुधों का प्रजनन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह पशुधों की उत्पादकता बढ़ाने मे मदद देता है।

देश मे ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अग अकेले राजस्थान में उत्पन्न होता है। राजस्थान मे भेडा की निम्न 8 नस्लें हैं : चोकला, भागरा, नाली, पूगल, जैमलमेरी, मारवाडी, मालपुरा तथा सोनाडी। इनमे प्रथम तीन बीकारर की प्रमुख नस्लें हैं। जोरपुर की मारवाडी नस्ल अग्रहूर है। चोकला भेड से बस्त्रों की ऊन प्राप्त होता है। नाली नस्ल का ऊन दोनों मे काम आता है। राज्य मे 1951 में भेडा की सख्या 53.9 लाख थी जो 1963 मे बढ़कर 133.9 लाख हो गई। राजस्थान मे देश की कुल भेडों का लगभग 30% अग होने पर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 40% अग प्राप्त होता है। इसमे स्पष्ट है कि यहाँ प्रति भेड ऊन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। यहाँ प्रति भेड लगभग 1 1/2 किगो ऊन प्राप्त होता है, जबकि समस्त देश का औसत केवल 0.9 किगो माना गया है। नस्ल सुधार कार्यक्रम मे मारवाडी, जैमलमेरी व भागरा भेडों को 'सिलेक्टिव वीडिय' स्कीम मे लिया गया है। इसके लिए उभो नस्ल के चुने हुए भेडे प्रयुक्त किये जाते हैं। नाली, चोकला, सोनाडी व मालपुरा नस्लों का विकास 'जोम वीडिय' के माध्यम से किया जाता है जिसमे दूसरी नस्ल के उत्तम भेडे प्रजनन हेतु प्रयुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार भेडों मे गुणात्मक सुधार करने के लिए दोना प्रकार के प्रजनन या उत्पाति पर जोर दिया जाता है। राज्य मे 1984-85 मे 1 1/2 करोड किलोग्राम ऊन उत्पन्न किया गया

भा। राज्य में लगभग 1½ लाख परिवार उन के उत्पादन में संलग्न हैं। माड़ौर, सीकर, जोधपुर व भीलवाड़ा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उन-आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है। बोटल व सार्स माधोपुर में बनरियों की मदद का दूध व मांस दोनों दृष्टियों में उत्तम ग्राही गयी है। राज्य में ऊंटों की बड़ी गर्धों पायी जाती हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि लगभग भारत में औसत की तुलना में अधिक है। राजस्थान से प्रतिदिन बायी धड़े अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं।

राजस्थान में कृषि के साथ जीविकोपार्जन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन पशु-पालन हो है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था की कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकार को पशुपालन के विकास पर काफी ध्यान देना चाहिए। राज्य के निवासियों की भाग बढ़ावे के लिए पशु-धन के विकास पर ज्यादा धन देना उचित होगा। पाली, चारा (उत्पादन एवं संचय) आदि के निवारण से पशु-सम्पत्ति को अधिक उत्पादन बनाया जा सकता है। अनाज व सूरा पड़ जाते से पिछले वर्षों में बड़ी चार राजस्थान के पशुओं को अन्न भोजना/ से जाना पड़ा और पशु-धन को काफी क्षति पहुँची। लेकिन अब राज्य में भी कठिनाइयों होने के कारण वहाँ पशुओं को भोजना सुविधा होता जा रहा है। राज्य में पाली व चारे की सुविधाएँ बढ़ाकर अर्द्धशुष्क व शुष्क प्रदेशों में भेड़-प्रायः व अन्य पशुओं का विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान में ऐसे उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ हैं जैसे ऊन का उद्योग कुम्ह व कुम्ह-निर्मित पदार्थ, मांस का उद्योग, चमड़े का उद्योग, घट्टाई का उद्योग। यदि पशु-धन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाये तो सरकार व जनता दोनों की भाग में वृद्धि हो सकती है।

राजस्थान सहकारी डेयरी सघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास में संलग्न है। जनवरी 1989 के अंत में राज्य में डेयरी सघ 10 व अध्यधीतन के (chilling centres) 21 थे। डेयरी सघों की प्रति दिन की औसत क्षमता 9 लाख लीटर तथा अध्यधीतन केन्द्रों की 4 10 लाख लीटर थी।

जनवरी 1989 के अंत में दूध उत्पादन की सहकारी समितियाँ 4312 थी तथा उनके कुल सदस्य 31 1639 दूध उत्पादन में। 1988-89 में जनवरी 1989 तक प्रतिदिन दूध का औसत संग्रहण 2 36 लाख लीटर हो पाया था।¹ हाल में 'तत्त रसगुले' का उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। इससे अनाज सरस पीर व 90 दिन तक सरस व हो जाने वाले "टेट्रापैक दूध" (Tetrapak milk) के उत्पादन की भी योजना है।²

1. भावधन्य अध्ययन (Budget Study) 1989-90 पृष्ठ 76-77।

2. बजट-मापण 23 मार्च, 1989 पृ 24

राज्य में पशु पालन व डेयरी विकास के सम्बन्ध में नीति व राजकीय प्रयास — राज्य में पशु पालन व डेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण रुढ़म उठाये गये हैं। दश विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई है। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए प्रजनन की उत्तम विधियाँ अपनायी गयी हैं। कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। पशुओं में बीमारी की रोक-थाम का इन्तजाम किया गया है। इसके लिए पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं।

प्रतिदिन दूध के सक्कलन की व्यवस्था की गई है। जैसा कि ऊपर कहा गया है 10 डेयरी सप्लय तगये जा चुके हैं तथा 24 घनशोषन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दूध का उत्पादन करने वालों की सहकारी समितियाँ बनायी गयी हैं। उनको सन्तुलित पशु-आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है।

पशु-पालकों की आर्थिक दशा सुधरने के लिए 1 अप्रैल 1986 को भारतीय एग्री इण्डस्ट्रीज फाउंडेशन (BAIF) की सहायता से जोस-ब्र डिग के लिए 50 केन्द्र स्थापित करने का समझौता किया गया है। ये केन्द्र भीलवाड़ा, कोटा, बूंदो, उदयपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में स्थापित किये जा रहे हैं।

इस प्रकार सरकार पशुओं की नस्ल सुधार, पशु-चिकित्सा, पशु पालकों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने तथा पशुधन की अतिवृद्धि करके राज्य की आय बढान का प्रयास कर रही है। इससे राज्य के परिवर्षी भागों को विशेष लाभ हा रहा है।

राजस्थान में खनिज पदार्थों का विकास¹

राजस्थान खनिज पदार्थों का खजानाखण्ड (museum of minerals) माना गया है। बिहार के बाद खनिज सम्पदा में राजस्थान की ही पिनती होती है। राजस्थान में 50 से अधिक खनिज पाये जाते हैं। अधात्विक खनिजों (non-metallic minerals) के उत्पादन मूल्या में भारत में इसका प्रथम स्थान है तथा धात्विक खनिजों के उत्पादन मूल्या में चौथा स्थान है। प्रचलित कीमतों पर (at current prices) सन 1983-84 में 181.3 करोड़ रुपये की घामदनी हुई थी जो राज्य की गृह घरेलू उत्पाति (NSDP) का 2.45 प्रतिशत थी, जो बढकर 1987-88 में 322.4 करोड़ रुप हो गई जो राज्य की गृह घरेलू उत्पाति का 3.39 प्रतिशत थी। अभी तक राज्य में खनन का उद्योग घोषित नहीं किया गया है।

इस समय राज्य में लगभग छ. धात्विक (metallic) और बीस अधात्विक (non-metallic) औद्योगिक खनिजों के निकालन का कार्य जारी है। धात्विक समूह

1. धाय-मयक मध्यम, 1989-90, पृ. 112 तथा एम. बी. माधुर समिति (भाटवी पञ्चवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरेचना (strategy) पर उच्चाधिकार समिति) रिपोर्ट नं० I, पृ. 35-37.

में मुख्य खनिज इस प्रकार है—सीसा, जस्ता, चाँदी, केडमियम (रामे से मिलता-जुलता), मैंगनीज, बुल्फासाइट (टंगस्टन उत्पन्न करने वाला खनिज पदार्थ) व कच्चा सोडा। अवाविक समूह के मुख्य खनिज निम्नांकित हैं—ऐसबेस्टस (asbestos), बेराइट्स barytes), केलसाइट, चायना बले, डोसोमाइट, पन्ना (emerald), फेंस-पार, फायर बले, फ्लोराइट, रत्नमणिका सामड़ा (garnet), मुत्तानी (मिट्टी (fuller's earth), सडिया मिट्टी (gypsum), रोक-फॉस्फेट, लाइमास्टोन, सगमरमर (marble), अन्नक, बार्डोज, सिलिका मिट्टी, घोषा पत्थर (soapstone), पाइरो-पिताइट, व बरमीबूलाइट। इनके अलावा क्रोफाइट, क्राइनाइट (kyanite), तात व पीली ओक्रेस (ochres), स्टेडस्टोन व टुरमेलाइन (tourmaline) का भी पौड़ा मात्रा में उत्पादन होता है। मन्नेसाइट के विस्तृत भण्डारों का भी पता लगाया गया है और उनके व्यापिक उपयोग की ध्यान-बीन जारी है। उडुपुनुर के समीप भामर-कोटरा (Jhamar-Kotra) की खानों से राज फॉस्फेट के उत्पादन से राज्य ने खनिज विकास के क्षेत्र में एक नया कदम रखा है। दो राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. के तत्वावधान में रॉक-फॉस्फेट के खनन का कार्य किया जा रहा है।

भारत में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो एमरेल्ड गार्नेट (अबोजिब व जेम दोनों किस्मों का), सीसा, जस्ता, केडमियम व चाँदी का उत्पादन करता है। राजस्थान कई खनिजों के उत्पादन में देश में अग्रणी है जैसे चाँदी, बुल्फासाइट, ऐसबेस्टस, केलसाइट, फेंसपार, जिप्सम, सीसा, जस्ता, रोक-फॉस्फेट आदि।

खनिज ईंधनों (mineral fuels) में पलाना की लिग्नाइट की खानें प्राचीन हैं, जिनमें काफी वर्षों से काम होना रहा है। बीकानेर के गुदा क्षेत्र में लिग्नाइट के लगभग 1 1/2 करोड़ टन के भण्डार अनुमानित किये गये हैं। मई 1983 की सूचना के अनुसार जंतलमेर जिले में घोटाक नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया गया है। यहाँ एक घरब धनमीटर में प्राकृतिक गैस मिली है। इस गैस में सीमेन्ट प्लांट और विद्युत गृह स्थपित करने की योजना है। घोटाक के बाद सोडेंवाला व लोनेवाला में काम शुरू किया जायेगा। मार्च 1984 की सूचना के अनुसार जंतलमेर में करीब 145 किलोमीटर दूर सदेवाला में तेल का बड़ा भण्डार मिला है। तेल व प्राकृतिक गैस अयोग ने जून 1983 के अन्त में वहाँ खुदाई का काम शुरू किया था। जंतलमेर में तेल व प्राकृतिक गैस अयोग एक हिलियम गैस प्लान्ट लगाने का विचार कर रहा है। सदेवला से पाक सोमा के बीच करीब छह किलोमीटर की ही दूरी है। रमपुरा-प्रागुचा में जिक व भीसे के विपुल भण्डार मिलने से राजस्थान में भारत सरकार ने एक जिक स्मेल्टर प्लान्ट लगाने की स्वीकृति दे दी है जिसकी लागत लगभग 366 करोड़ रु. अनुमानित है। इस हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड

कार्यान्विन करेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के याँव केसरपुरा (प्रनापगढ) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय है। इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है।

हाल में जंसलमेर जिले के सोनू खंड में 500 मिलियन टन स्टील थ्रेड लाइन-स्टील के भण्डारों का पता लगाया गया है। इसके उपयोग से घायात कम होगा तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी।¹

नीचे विभिन्न खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

धात्विक खनिज (Metallic Minerals)

(i) ताँबा—खेतड़ी की ताँबे की खानें सिधाना से रघुनाथपुर तक फैली हुई हैं। राज्य के अन्य भागों में भी ताँबे के भण्डारों का सर्वेक्षण किया गया है। दरीबा के समीप का क्षेत्र भी उल्लेखनीय है। भुम्भनू जिले के खेतड़ी में ताँबा निकाला जाता है। नीलवाड़ा जिले में भी ताँबे का क्षेत्र है। सिरौही जिले में घाड़ रोड के समीप मोना, जस्ता व ताँबा पाये गये हैं। उदयपुर जिले के बजली क्षेत्र में ताँबे के भण्डार मिले हैं।

खेतड़ी के समीप ताँबे के बड़े भण्डार हैं। इनका उपयोग करके गलाने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इससे उपोत्पत्ति (by-product) के रूप में स-पथूरिक एसिड प्राप्त होगी और थोड़ी चाँदी व सोने की मात्रा भी उपलब्ध होगी। स-पथूरिक एसिड प्राप्त होने से सुपरफॉस्फेट का उत्पादन भी बसू किया जा सकेगा।

राजस्थान में कच्चे ताँबे (copper ore) का उत्पादन 1988 में 18 लाख टन अनुमानित है, जबकि 1987 में 16.94 लाख टन का उत्पादन हुआ था।

(ii) सीसा व जस्ता—उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर जावर स्थान पर सीसे व जस्ते की खानें स्थित हैं। सीसे के डले गलाने के लिए बिहार भेज दिये जाते हैं और जस्ते के डले जो पहले जापान भेज दिये जाते थे, अब देवारी (उदयपुर के पास) में जस्ता गलाने के समय में प्रयुक्त किये जाते हैं। इस काम के संचालन के लिए 'डी हि दुस्तान लिमिटेड', देवारी की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जस्ता गलाने की उपोत्पत्ति के रूप में सुपरफॉस्फेट एसिड व कैडमियम प्राप्त होते हैं। स-पथूरिक एसिड का उपयोग सुपरफॉस्फेट के उत्पादन में किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है रामपुरा-धामुचा में जस्ते व सीसे के विपुल भण्डार मिले हैं जिससे एक ज़िंक स्मेल्टर संचालन लगाया जा रहा है।

1988 में राजस्थान में सीसे के डलों का उत्पादन 36 हजार टन, जस्ते के डलों का 109 हजार टन और चाँदी का 18890 किलोग्राम अनुमानित है।

1. बजट भाषण 1989-90, 23 मार्च, 1989, पृ. 41 (हिन्दी में)

(iii) कच्चा लोहा—राजस्थान में थोड़ी मात्रा में कच्चा लोहा जयपुर उदयपुर भू भूतू सीकर, व धूलवर जिलों में पाया जाता है। मूँथ मण्डार जयपुर व उदयपुर जिलों में स्थित है। 1988 में कच्चे लोहे का उत्पादन 65 हजार टन हुआ था।

(iv) मैंगनीज—बागवाडा जिले में घटिया किस्म की मैंगनीज पाई गई है। राज्य में मैंगनीज का उत्पादन बहुत कम हो पाया है।

(v) टंगस्टन (शीलाइट खनिज)—तागौर जिले में डेगना के पास पहाड़ियों में टंगस्टन के मण्डार विद्यमान हैं। हाल में एक सर्वेक्षण से इन मण्डारों की पुष्टि हुई है। यहाँ पर टंगस्टन की किस्म भी काफी अच्छी बताई जा रही है। पापी जिले में टंगस्टन के मण्डार मिले हैं। टंगस्टन का उपयोग एल्युम तथा स्पेशल स्टील के निर्माण में होता है। यह विद्युत के साज सामान में भी प्रयुक्त किया जाता है। टंगस्टन रक्षा विभाग को सप्लाई किया जाता है। 1988 में राजस्थान में 32 टन टंगस्टन के डलो या उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष के उत्पादन से कुछ अधिक था। भारत में टंगस्टन के उत्पादन का बड़ा अंश राजस्थान से ही प्राप्त होता है।

औद्योगिक व अधात्विक खनिज

(Industrial and Non Metallic Minerals)

इन खनिजों का वर्णन निम्न समूहों में विभाजित करके किया जा सकता है—

(प्र) पृथक करने के काम आने वाले खनिज ताकिक ताप का प्रभाव न पड़े (Insulants) ताप सहन करने में मदद देने वाले खनिज (refractories) व धोनी मिट्टी के घटन बनाने में काम आने वाले खनिज (ceramic minerals)। इस समूह में निम्न खनिज शामिल होते हैं।

(i) ऐसबेस्टस—ऐसबेस्टस का उपयोग ऐसबेस्टस सीमेन्ट, छत की चट्टों पाइप आदि बनाने में किया जाता है। 1988 में 30 हजार टन ऐसबेस्टस का उत्पादन हुआ था।

(ii) फेल्सपार (Felspar)—यह काच, मिट्टी के घटन आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। देश में फेल्सपार की कुल उपलब्धता का लगभग 7% राजस्थान में उत्पन्न होता है यह मुख्यतया अजमेर में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में तिरोही, उदयपुर धूलवर और पाली जिलों में भी पाया जाता है। 1988 में इसका उत्पादन 25 हजार टन हुआ था।

(iii) सिलिका रेत (Silica Sand)—यह पाँच उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आती है। यह प्रधिकारण जयपुर और बूँदी जिलों में निष्कायी जाती है।

(iv) क्वाट्रंज—यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है। यह झज्जर, सीकर, सिरोंही व झज्जर जिलों में मिलता है।

(v) मैग्नेसाइट—यह रिफ़ाइनरी ईंटों के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यह घोही माथा में काँच के उद्योगों में भी काम आता है। यह झज्जर जिले में भी पाया जाता है।

(vi) वरमीक्यूलाइट—झज्जर जिले में एक खान से दोड़ी मात्रा में वरमीक्यूलाइट निकाला जाता है। इस पर ध्वनि का प्रभाव नहीं होता। यह ताप व ध्वनि का अच्छा इन्स्यूलेटर होता है।

(vii) बाल्स्टोनाइट—यह एक नवीन खनिज है जिसके उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। यह सिरॉनिक उद्योग में काँचो काम आता है। यह पेट व कापड़ उद्योग में भी प्रयुक्त होता है। यह सिरोंही जिले में मिलता है।

(viii) चायना ब्लेक बाल्स्टोनाइट ब्लेक—यह बर्तन बनाने व विद्युत इन्स्यूलेटर के रूप में काम आता है। यह सवाई माधोपुर, सीकर, झज्जर, नागौर व जाँसीर जिलों में पाया जाता है।

(ix) फायर ब्लेक—यह फायर ईंट, स्लाब्स आदि बनाने में काम आती है। यह दीबाग़ेर जिले में पायी जाती है।

(x) डोलोमाइट—यह झज्जर, झज्जर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर जिलों में निकाला जाता है। यह चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने में भी काम आता है।

(xi) इलेक्ट्रॉनिक व घाणविक खनिज—इस समूह में अन्नक व बेरिल आते हैं।

(i) अन्नक (mica)—राजस्थान में अन्नक की खानें भीलवाड़ा, टोंक, झज्जर, जयपुर व उदयपुर जिलों में पायी जाती हैं। अन्नक विद्युत सज-सामानों में प्रयुक्त होता है। यह रबर टायरों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है।

बिहार व झारखण्ड प्रदेश के बाद अन्नक के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान आता है। भारत का लगभग एक-चौथाई अन्नक राजस्थान में उत्पन्न होता है। 1988 के अनुमानों के अनुसार अन्नक का उत्पादन 6 लाख टन हुआ जो विद्युत वयं से अधिक था।

(ii) घाणविक खनिज—घाणविक खनिजों में भी राजस्थान की स्थिति उमाह्वर्द्धक मानी जाती है। झज्जर व राजगढ़ की खानों में लिथियम की कुछ मात्रा मिली है। उदयपुर के समीप यूरेनियम की खोज की जा रही है। राजस्थान बेरिल का भी प्रमुख उत्पादक है।

(इ) कीमती पत्थर व अभ्रजिप्त (Gem Stones and Abrasives) :

(1) पन्ना (Emerald)—अजमेर व उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर एमरल्ड मिलता है। पिछले वर्षों में इसका उत्पादन काफी घट गया है।

(11) गारनेट—यह अजमेर, भीलवाड़ा व गोक जिलों में पाया जाता है। इसकी दो किस्में होती हैं—एक तो एब्रसिव और दूसरी जैम। राजस्थान में इसकी दोनों किस्में पायी जाती हैं।

(ई) उर्वरक खनिज—इस समूह में जिप्सम राँक-फॉस्फेट व पाइराइट्स आते हैं।

(1) जिप्सम—राजस्थान में जिप्सम के काफी भण्डार भरे पड़े हैं। देश में कुल उत्पादन का लगभग 90% राजस्थान के हिस्से में धाया है। जिप्सम की खानें बीकानेर, श्रीगंगानगर, बुरु, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर व पाली जिलों में पाई जाती हैं। पहले यह भवन-प्लास्टर में ज्यादा प्रयुक्त होती थी, अब यह उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जाती है। यह सीमेंट उद्योग में भी प्रयुक्त होती है। देश में गन्धक की कमी होने से जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण बहुत उपयोगी माना जा सकता है।

(11) राँक फॉस्फेट—उदयपुर के समीप राँक फॉस्फेट के विशाल भण्डारों की खोज ने राजस्थान के खनिज इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। पहले यह जैसलमेर जिले में बिरमेनिया स्थान पर ढूँढा गया था। झामर-कोटड़ा के भण्डार बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं। अन्य छोटे-छोटे भण्डार भी पाये गये हैं। झामर-कोटड़ा क्षेत्र में उत्पादन माच, 1961 से प्रारम्भ हो गया था। राँक फॉस्फेट का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में किया जा रहा है। 1969 में राज्य में लगभग 69 हजार टन राँक फॉस्फेट का उत्पादन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इससे विदेशी विनिमय की काफी बचत हुई है। 1988 में राँक फॉस्फेट का उत्पादन 450 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष से कम था। राँक-फॉस्फेट की बिक्री से राज्य सरकार को 1988 में 206 करोड़ रुपये की आय हुई थी। राँक-फॉस्फेट के परिशोधन के लिए एक बड़ा संयंत्र लगाने की योजना है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट सोफरा माइन्स, फास द्वारा तैयार कर ई गई है।

(111) पाइराइट्स (Pyrites)—गोक जिले में मलादीपुरा में पाइराइट्स की काफी मात्रा उपलब्ध हुई है। इसमें गन्धक का भ्रूल निकाला जा सकता है। गन्धक का भ्रूल या तेजाब उर्वरक उद्योग में काम आता है। उदयपुर के समीप राँक-फॉस्फेट के भण्डारों व मलादीपुरा की पाइराइट्स का उपयोग करके राज्य में एक उर्वरक कम्प्लेक्स या समूह स्थापित किया जा सकता है।

(व) रसायन उद्योग के खनिज—इस समूह में लाइमस्टोन, फ्लोसपार व पिराइट्स आते हैं।

(i) लाइमस्टोन का चूना पत्थर—सोमाग्य से राजस्थान की सीमेंट के उत्पादन के लिए लाइमस्टोन के विस्तृत भण्डार प्राप्त हैं। नौ सीमेंट के प्लांट—लाहोरी, सवाई माधोपुर (चित्तौड़गढ़, डारोली, उदयपुर), निम्बाहेडा (चित्तौड़ जिला), मोड़क (कोटा) बनाम (सिरोही), ब्यावर व कोटा में चले रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में राज्य में सीमेंट का उत्पादन काफी बढ़ा है। राज्य के विभिन्न भागों में लाइमस्टोन के पाये जाने से सीमेंट के उद्योग का बलिष्ठ उद्भव है। जैसलमेर, उदयपुर, बासवाडा (चित्तौड़गढ़), भीलवाडा (सिरोही) व पाली जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में लाइमस्टोन की ताल मात्रा व धोणी निश्चित करने के लिए प्रोसेपेक्टिंग का कार्य चल रहा है।

(ii) फ्लोर्सपार (Fluorspar) डूंगरपुर जिले में माडो की-पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार के भण्डार पाये गये हैं। इसका विकास पहले के वर्षों में राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम के द्वारा किया गया है। यह फ्लोर्सपार स्टील मैटेल्स में व हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पादन बनाने में काम आता है। राज्य में 1988 में चार हजार टन फ्लोराइट का उत्पादन हुआ था।

(iii) बेराइटस—यह तल के कुम्भों की ड्रिलिंग के दौरान घोल या कीचड़ बनाने के काम आता है। यह पेंट लिथोपेन उद्योग तथा बेरियम रसायनों में प्रयुक्त होता है। यह कागज व रबड़ उद्योग में भी काम आता है। यह झलसर जिले में तथा नाथद्वारा के समीप मिलता है।

(क) छोटे खनिज (Minor Minerals)

(1) बे-टोनाइट—यह एक प्रकार की मिट्टी होती है। यह ड्रिलिंग मट तैयार करने व सौंदर्य प्रसन्न वस्तुओं (cosmetics) के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह बाबमेर जिले में पाया जाता है।

(ii) फुलर'स मिट्टी (Fuller's earth)—बीकानेर व जायपुर जिले में इसके भण्डार पाये जाते हैं। यह चिकनाहट की लोच लेती है और तेल से रंगीन पदार्थ हटाने में प्रयुक्त होती है।

(iii) संग-रमर, ग्रोनाइट व अन्य भवन निर्माण के पत्थर—मकराने का संगमरमर ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त किया गया था। नागौर, पाली, सिरोही, बीबी, उदयपुर व जयपुर जिलों में संगमरमर की प्राप्ति के अन्य स्थान भी मिले हैं। जालौर जिले में गुलाबी रंग का ग्रोनाइट पत्थर पाया जाता है। राज्य के विभिन्न भागों में सैंडस्टोन व लाइमस्टोन पाये जाते हैं।

(ए) विविध

(1) घोषा पत्थर टेल्क व पाइरोपिताइट—राजस्थान इनका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र माना गया है। ये खनिज टेल्कम पाउडर, सिलीन आदि बनाने में प्रमुख होते हैं। ये उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाडा व डूंगरपुर जिलों में पाये जाते हैं।

(ii) केल्साइट—यह रसायन के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह कागज, दस्त्र, चीनी मिट्टी उद्योग, पेंट इत्यादि में काम आता है। यह सोकर जिले में प्राप्त होता है। लेकिन कुछ मात्रा सिरोही, पाली, जयपुर व उदयपुर जिलों में भी निकाली जाती है।

(iii) ओकर्स (Ochres) (साल और पीले)—ये खनिज पिगमेंट होते हैं जो घुलने नहीं है और रंग बनाने, सीमेंट, रबड़, प्लास्टिक आदि उद्योगों में काम आते हैं। यह चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर मिलता है। यह कुछ ग्रन्थ जिलों में भी मिलता है।

(iv) नमक—राजस्थान में सामर झील में काफी नमक उत्पन्न किया जाता है। डीडवाना, पचपदरा व लूनकरनसर भी नमक के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र माने गये हैं।

खनिज ईंधन (Mineral Fuels)

राजस्थान खनिज ईंधन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। प्रायः बीकानेर जिले में पलाना के लिग्नाइट कोयले के भण्डारों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन यहाँ 1969 में आग लग जाने से एक खान को बन्द करना पड़ा था। पलाना में लिग्नाइट भण्डार के कुछ क्षेत्र और ढूँढ गये हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यहाँ एक थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी है। अब सरकार ने इस थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का काम नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को सौंप दिया है। यहाँ कायला प्रचुर मात्रा में पाये जाने के कारण 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। बीकानेर, नागौर व बाड़मेर जिलों में लगभग 25 करोड़ टन लिग्नाइट (भूरा कोयला) के भण्डार आये गये हैं। इस भण्डार में राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है।

राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योग (Mineral-based Industries in Rajasthan)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। राज्य में सीमेंट, उर्वरक, रसायन व अन्य उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। हम नीचे पिछले वर्षों की प्रगति व भावी सम्भावनाओं का उल्लेख करते हैं—

1. जस्ता व गलाई सपत्र (Zinc Smelter Plant)—उदयपुर के समीप देवारी नामक स्थान पर 18 हजार टन की प्रारम्भिक क्षमता से एक जिक स्मेल्टर प्लांट चालू किया गया है। ऊँची किस्म का जस्ता तैयार करने के साथ-साथ वह उद्योगिकी के रूप में बेडमियम व गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) भी तैयार करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से सुपरफॉस्फेट तैयार किया जायेगा।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है रामपुरा-छागुचा में ट्रिब व सोले के पर्याप्त भण्डार पाये जाने से भारत सरकार ने राजस्थान में ट्रिब स्मेल्टर संयंत्र लगाने की स्वीकृति दे दी है जिसे हिन्दुस्तान ट्रिब लि. कार्यान्वित करेगा।

2. निम्वाहेडा में एक सीमेंट का कारखाना डाला गया है। राज्य में सीमेंट के नौ बड़े कारखाने हो गये हैं। भविष्य में नये कारखाने भी स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में सीमेंट के छोटे मयत्र (Mini cement Plants) भी लगाये गये हैं।

3. सेतड़ी ताम्बा गलाने का मयत्र (Copper Smelter Plant)—सेतड़ी में ताम्बा गलाने के मयत्र की क्षमता 30 हजार टन है जो भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है जिसका उपयोग करने के लिए अन्य उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।

4. जैसा कि पहले कहा जा चुका है उदयपुर के समीप आमर-कोटड़ा क्षेत्र में प्राप्त रॉक-फॉस्फेट के भण्डारों का उपयोग काठे मुपर-फॉस्फेट का उत्पादन किया जा सकेगा। सीकर (सतादीपुरा) में फाइराइट्स के भण्डारों का उपयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन की जा सकेगी जिसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जायेगा।

इन प्रकार राज्य में कई तरह के मुपरफॉस्फेट के उत्पादन में वृद्धि होने से विकास की नया मोड़ मिलेगा।

5. नोम-का-थाना में निम्नी क्षेत्र में बने-बागिन प्लाट स्थापित किया गया है।

6 कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम ने डूंगरपुर में माहों की घाट नामक स्थान पर पञ्चोर्नगर बेनिफिशियेशन प्लाट प्रारम्भ किया था जिसमें रमायन उद्योगों को बढ़ावा मिला है।

7. जालोर में एक ड्रेनाइट पॉलिमिड फेक्ट्री राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम के अधिकार में भी गई थी जिसका विकास किया गया है।

8. अन्य—इनके अलावा हाई-टेक प्रिंसीपल ग्लास, जोधपुर में ग्लास व ग्लास प्रोडक्ट्स, फेक्टरी पॉटरी कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर में फायर ब्रिक्, स्टोन बेयर व फाइर, नूपास माइनिंग वर्क्स, जीतवाड़ा में ब्रिक् माइका इन्सुलेशन ब्रिक् तथा जयपुर ग्लास गैर पॉटरी व वर्क्स जयपुर में आरम्भ बनी है।

सबर्ट मायोपुर में साद का का-थाना नहीं लगाया जायगा क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि में यह स्थान उपयुक्त नहीं पाया गया है। इसलिए अब यह कारखाना गटेपान में लगाया जायगा, जिसके लिए निर्णय लिया जा चुका है।

बीकानेर में बरमिहमर में निम्नाइट के भण्डारों का विनोदन करने के सम्बन्ध में नेदनी निम्नाइट से समझौता किया गया है। इस पर भी निर्णय होना है। यहाँ निम्नाइट का बैज्ञानिक दृष्टि से विनोदन किया जायगा जिससे पर्यावरण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

सुरतराई के पास २५ मीटर में 18 मिलियन वर्गसेक फीट गैस का भण्डार मिला है जिसमें से वर्तमान में 5 मिलियन क्यूबिक फीट का ही उपयोग हो पा रहा है। यहाँ एक पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है।

मावी सम्भावनाएँ

1 कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण का समय लगाने पर सक्रिय रूप से विचार रिया जाना चाहिए।

2 उदयपुर में एक पिंग सोहा समन्वय लगाने की आवश्यकता है। वहाँ निरटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे सोहे का उपयोग किया जा सकता है।

3 निम्न स्तरों की जिप्सम से टीबारी के बाई बनाये जा सकते हैं जिसके पूर्व-निर्मित-मकान (Pre fabricated-House) बनाकर कुछ सामान्य तक मकान समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

उत्तम सेलेनाइट के भण्डारों का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस व अन्य उद्योगों का विकास करने में किया जाना चाहिए।

4 फ्लैस्फार, क्वार्ट्ज व चिक्नी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानों की स्थापना का क्षेत्र बड़ा सकता है। सिलिका के उपयोग से कंक्रीट के उपयोग का विस्तार किया जा सकता है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में लौहा, सोडा व जस्ता एवं सम्बद्ध धातुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भारत में इनका निर्यात घटका है अतः राज्य को इनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और केन्द्र को इनमें अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में सुपर-फोस्फेट का उत्पादन के बढ़ने से उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ सकती है जिससे कृषि-जन उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। लाइमस्टोन का उत्पादन बढ़ाकर सीमेंट व स्टील उद्योग का लाभ पहुँचाया जा सकता है।

राज्य की खनिज नीति

परिवहन व शक्ति के सधन के विकास में राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास की सम्पन्नता बढ़ रही है। राज्य में खनिज विकास के लिए 1978 में नई खनिज नीति घोषित की गई थी। इसमें खनिज पदार्थों की भाज हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर जोर दिया गया था। इसमें सड़कों के मास्टर प्लान बनाने विज्ञानी उपलब्ध कराने व खनन कार्य के लिए बैंको, सहकारी सम्पत्तियों तथा राजस्थान वित्त निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। इनमें कहा गया कि छांट प-प रियोज को ऋण दिया जायगा तथा अधिधान खनिजों जैसे लाइमस्टोन, लगमरमर आदि के पट्टे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर दिये जायेंगे।

राज्य में खनिजों के विकास के लिए नवम्बर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) स्थापित किया गया है। पहले यह कार्य

RIMDC के अन्तर्गत किया जाता था। रोक-पॉइंट के खनन के लिए राजस्थान राज्य खान व खनन निमिटेड कार्यरत है। एम. बी. माथुर समिति ने खनन-विकास के लिए निम्न सुझाव दिये हैं¹:-

(i) खनन की दृष्टीय घोषित कर देना चाहिए ताकि इसकी भी राजकीय मान व प्रेरणाएं मिल सकें।

(ii) खनन व नूतन संचालक की खनी खनन सौजहांड छेवों का बड़ा पैमाने पर नूतनीय नक्सा बनवाना चाहिए।

(iii) रामगज, मोडक व धानावाह क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लाइमस्टोन की नूतफूट व अर्थों का पट्टे हैं जिनमें पोज़ालाना (Puzzalana) लीमेंट बन सकती है बहरों कि इन पर उत्पादन-शुल्क घटाया जाय। इससे रोज़गार बढ़ेगा तथा सरकार को आमदनी होगी।

(iv) बिहार सरकार की भांति अन्नक की राजकीय व केन्द्रीय दिवरी कर से मुक्त रखा जाय;

(v) खनन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बढ़ाया जाय।

(vi) खनन विभाग को खानों के पट्टे देने व लगान तथा रायन्टी इकट्ठा करने के अलावा खनिज पदार्थों के भण्डारण, खेती, छाड़ि के बारे में शिक्षण सूचना रखनी चाहिए, एवं

(vii) खनन निर्माण छात्रों का उपयोग करने के लिए निर्माण-उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इसके लिए नमि-रूपान्तरण, अक्षांश नियमों व दिन छाड़ि की अजम्हा बढ़ाकर निर्माण-उद्योग को आगे बढाना चाहिए। इससे राज्य में उत्पादनकर भी मजबूत होगा।

आगे है इन सुझावों का कार्यान्वित किया जायगा।

राजस्थान में ऊर्जा का विकास

(Energy Development in Rajasthan)

आदिक विकास में ऊर्जा का केन्द्रीय स्थान होता है। ऊर्जा के छाय दो भागों में बांटे जाते हैं।

1. परम्परागत स्रोत (Conventional Sources)—इसमें खर-विद्युत, बर्मल-पावर (बादल गैस, व ठेल से उत्पन्न), व अणु शक्ति से उत्पन्न पावर शामिल हात हैं।

2. गैर-परम्परागत स्रोत (Non-conventional Sources)—इसमें लकड़ी, बायो-गैस, सौर-ऊर्जा (solar energy), निष्पुंस चून्हा, पवन चक्की, बर्मल शामिल होते हैं।

1. यू.डी.एन. रिपोर्ट, जून, 1989, अग्न 1, पृ. 36-37.

राजस्थान में प्रति व्यक्ति व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग 95 किलोवाट घण्टे प्रति घण्टा है, जबकि समस्त देश का औसत 134 किलोवाट घण्टे (KWH) है। यतः समस्त भारत व राजस्थान के बीच ऊर्जा के उपयोग के अन्तर को कम करने की आवश्यकता है।

1989 के मध्य में राजस्थान में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता लगभग 2500 मेगावाट के स्तर तक पहुँच चुकी है। इसमें लगभग आधी जल विद्युत शक्ति तथा आधी थर्मल पवर है। जल विद्युत परियोजनाएँ जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है इस प्रकार हैं :

भाखड़ा मातल, व्यास इकाई I व इकाई II चम्बल परियोजना (गांधी सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर), माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान में मिनी हाइडल स्कीमों के विकास की भावी सम्भावनाएँ भी हैं। मन्सूफगढ़ मिनी हाइडल स्कीम से राज्य को लाभ होगा।

थर्मल परियोजनाओं में सतपुड़ा, सिंगरौली, राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र, कोटा I व II तथा कोटा थर्मल पावर सयन हैं।

नई थर्मल परियोजनाएँ

राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोटा जिले में अन्ता (Anta) शहर में एक नई स्थापित पावर स्टेशन (केन्द्रीय क्षेत्र में) स्थापित करने जा रहा है जिसकी क्षमता 600 मेगावाट करने की आशा है (फिलहाल 430 मेगावाट है)। यह परियोजना सातवी योजना के अन्त तक तैयार हो जायेगी। इस प्रकार नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की पलाना लिग्नाइट की खानों का उपयोग करके एक थर्मल प्लांट स्थापित करने का काम सौंपा गया है। इसमें 60 मेगावाट की दो यूनिट लगाने का प्रस्ताव तो केन्द्र ने मंजूर कर दिया था, लेकिन प्रचुर मात्रा में कोयला मिलने से वहाँ 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ स्थापित करने के नये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं।

यह परियोजना व पलाना लिग्नाइट परियोजना के चालू हो जाने पर राजस्थान में पावर-संकट कम हो जायेगा। आठवी व नवी पंचवर्षीय योजना में बिजली की मांग की पूर्ति के लिए पाँच थर्मल या तापीय योजनाएँ चालू की जायेंगी इसके लिए कोटा तृतीय चरण, चित्तौड़गढ़, भाटलगढ़, सूरतगढ़ एवं धौलपुर के लिए योजनाएँ भारत सरकार को प्रेषित की गई हैं।

रावतमाटा में भारत सरकार द्वारा 235 मेगावाट की दो इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, जबकि 500 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयाँ स्थापित करने पर सिद्धान्ततः सहमति प्रकट की जा चुकी है। इस प्रकार रावतमाटा से 2470 मेगावाट विद्युत उत्पादित होगी और यह देश का सबसे बड़ा 'अणु बिजली कॉम्प्लेक्स' बन सकेगा।

सम्भार ने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए राजस्थान ऊर्जा-विकास एजेंसी (Raj. Energy Dev. Agency) (REDA) की स्थापना की है।

1989-90 में 7000 सोलर-लूकर्स वितरित किये जायेंगे तथा 900 सोलर-ऊर्जा चार्जिंग रोड लाइटें लगायी जायेंगी। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चारा विजय हेतु 100 पवन चक्कियाँ लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जोधपुर क्षेत्र में 30 भेगावाट का सोलर-घर्मित मयत्र लगाने का प्रस्ताव है।¹

पिछले वर्षों में राज्य में काफी समस्या में निधूम चलते स्थापित बिजली के हैं। इनका विस्तार किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की काफी सान होगी। इस प्रकार गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास कार्य भी जारी है।

राजस्थान में जनसंख्या की स्थिति

य समस्या का आकार एक वृद्धि—1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 3.43 करोड़ व्यक्ति दर्ज है। 1971 में यह लगभग 2.58 करोड़ व्यक्ति थी। 1971-81 की अवधि में राज्य की जनसंख्या में लगभग 85 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 33 प्रतिशत है। इसी अवधि में समस्त भारत में जनसंख्या की वृद्धि 25 प्रतिशत रही। इस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि-दर समस्त भारत से 8 प्रतिशत बिन्दु अधिक रही है। निम्न तालिका में 1941 से 1981 तक की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या की दस वर्षों की वृद्धि का परिचय दिया गया है।²

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	दस वर्षों की वृद्धि दर (%)
1941	1.39	18.0
1951	1.59	15.2
1961	2.01	26.2
1971	2.58	27.8
1981	3.43	33.0

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 1941-81 के बीच राजस्थान की जनसंख्या 1.39 करोड़ व्यक्तियों से बढ़कर 3.43 करोड़ व्यक्ति हुई। राज्य में 1981 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 919 थी। यह राज्य का लिंग-अनुपात (sex ratio) बढ्ता है। भारत राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। राज्य में अनुसूचित व जनजातियों की संख्या काफी ऊँची है। 1979 में यह कुल जनसंख्या का 8% थी। 1981 में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21.05% थी। इस प्रकार क्षेत्र में राजस्थान में 10 में से 2 व्यक्ति शहरों में तथा 8 व्यक्ति

1 बजट-वार्ष, 23 मार्च, 1989, पृ. 11-12.

2. Some facts about Rajasthan, 1987, P. 24.

गाँवों में निवास करते हैं। 1981 में 11 शहरों में जनसंख्या एक लाख से ऊपर पायी गई जो अध्याय के अन्त में परिशिष्ट 2 में दी गई है।

1971-81 की अवधि में राज्य में विभिन्न जिलों में जनसंख्या की वृद्धि-दर में काफी अन्तर पाये गये थे। बीकानेर जिले में जनसंख्या की वृद्धि पर 48.1% रही, जो सर्वाधिक थी और भीलवाड़ा जिले में यह 24.2% रही जो न्यूनतम थी।¹

राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर (लगभग 33%) समस्त भारत की वृद्धि-दर (25%) से काफी अधिक रही है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि राज्य सामाजिक व प्राथमिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और बाहर से लोग आकर बस गये हैं। 1981 में राज्य की जनसंख्या का 30.48% मुख्य श्रमिकों (main workers) की श्रेणी में तथा 6.13% सीमान्त श्रमिकों (marginal workers) की श्रेणी में पाया गया था।

राजस्थान में पिछड़ी जातियों व जनजातियों के लोगों की भी सहायता काफी है। राज्य में शिक्षा का भी प्रभाव है। इस प्रकार भविष्य में राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर को नियन्त्रित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान बीकानेर और गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, कोटा, बाँसवाड़ा व जालौर जिलों पर दिया जाना चाहिए जहाँ 1971-81 की अवधि में जनसंख्या 35% से अधिक बढ़ी। (देखिए परिशिष्ट 1)। जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक उपायों का वर्णन जनसंख्या के अध्याय में किया जा चुका है। प्रोफेसर के सुन्दरम ने बताया है कि राजस्थान में परिवार नियोजन अपनाते वाले दम्पतियों का प्रतिशत 1983 में 15.7 था जो वर्ष 2000 तक बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 31% हो सकेगा, जबकि समस्त राज्यों के लिए उस वर्ष के लिए लक्ष्य 60% रखा गया है।² इस प्रकार लक्ष्य की तुलना में राजस्थान की उपलब्धि काफी ही रह पायेगी। इसलिए राज्य में परिवार-नियोजन की दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1981 में राजस्थान की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत थी। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1981 से प्रति वर्ग किलोमीटर 100 व्यक्ति पाया गया है, जबकि 1971 में यह 75 था। राज्य के विभिन्न जिलों में जनसंख्या के घनत्व में भी भारी अन्तर पाया जाता है, जैसे जैसलमेर के रेगिस्तानी भागों में यह 6 है, जबकि जयपुर जिले में यह 242 व्यक्ति है।

राज्य में 1981 की जनगणना के अनुसार लगभग 24.4 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे। इसमें पुरुषों का प्रतिशत 36.3 तथा स्त्रियों का 11.4 था। इस प्रकार

1. विभिन्न जिलों में हुई जनसंख्या की वृद्धि का विवरण इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

2. K. Sundaram, article in EPW, August 25, 1984, p. 1481.

ग्राम भी राज्य में २ व्यक्ति निरक्षर हैं, जबकि भारत में इसका अनुपात ३ है। राजस्थान के सम्बन्ध में यह उत्तेजनीय है कि 1981 में भी वहाँ की ग्रामीण स्त्रियों में केवल 5.5% ही साक्षर थीं। सशरता की स्थिति शहरी में बेहतर है, जहाँ 1981 में 60.6% पुरुष व 34.5% स्त्रियाँ साक्षर थीं। अतः गाँवों में महिला-श्रम की साक्षर व शिक्षित बनने की नितान्त आवश्यकता है। इसके शादी की उम्र भी बढ़ेगी तथा परिवार नियोजन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। देहातो में महिलाओं में फैली हुयी व्यापक निरक्षरता राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगति में बाधक मानी जा सकती है।

श्रम क्षमता का व्यावसायिक वितरण¹

राज्य में 1971 में कुल श्रम-शक्ति जनसंख्या का 34.1% थी जो 1981 में 36.6% हो गई। इसमें मुख्य श्रमिक व सीमान्त श्रमिक दोनों को शामिल कर लिया गया है। इसे काम में भाग लेने की दर (work participation rate) भी कहते हैं।

कुल श्रमिकों का विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार वितरण तालिका में दर्शाया गया है—

औद्योगिक क्षेत्र	1971	1981 (प्रतिशत में)
I कृषक	64.9	64.5
II सैतिहर मजदूर	9.3	8.5
III वन्यधन, मछली, वन, आदि	2.5	2.8
IV खनन व पत्थर निकालना	0.4	0.7

1. 1971 के आँकड़ों के लिए Report of the Committee on Unemployment, May 1973, p. 344, तथा 1981 के लिए Census of India 1981, Series 18, Rajasthan Part II, Special Report and Table Based on 5 Percent Sample Data p. 87 का उपयोग किया गया है।

V (घ) घरेलू उद्योग	3.4	3.0
(घा) घरेलू उद्योग के भलावा उद्योग	3.2	5.0
VI निर्माण (construction)	1.3	1.7
VII व्यापार व वाणिज्य	4.4	4.4
VIII परिवहन, संप्रदा व संचार	2.0	2.1
IX अन्य सेवाएँ	8.5	7.3
कुल (संगमन)	100.0	100.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1971 में कृषि व सहायक क्रियाओं में (श्रेणी I से III तक) 76.7% श्रमिक लगे हुए थे जो 1981 में 75.8% हो गये। खनन व उद्योगों में (श्रेणी IV व V) 7% से 8.7% हो गये एवं अन्य में (श्रेणी VI से IX तक) 16.2% से 15.5% हो गये।

इस प्रकार 1981 में कृषि व सहायक क्रियाओं में श्रम शक्ति का अनुपात 1971 की तुलना में लगभग 1% कम हुआ, खनन व उद्योगों में यह 1.7% बढ़ा तथा निर्माण व सेवाओं में मामूली घटा है।

1981 में राजस्थान में श्रम-शक्ति के व्यावसायिक वितरण में 1971 की तुलना में जो परिवर्तन आया है, वह एक सही दिशा में होने वाला परिवर्तन माना जा सकता है। इससे राज्य में कृषि के भलावा अन्य क्रियाओं की प्रगति भलवती है। भाषा है प्राणामी वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास से यह प्रवृत्ति और जोर पकड़ेगी।

मानवीय साधनों से सम्बन्धित उपयुक्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान में एक तरफ जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान में कृषिगत विकास व

औद्योगिक विकास की गति को तेज करके लोगों की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है। भाग के अध्यायो में हम इन पहलुओं पर अधिक प्रकाश डालेंगे।

परिशिष्ट—1

1971-81 की अवधि में जिलों की जनसंख्या की वृद्धि की दस-वर्षीय दरें
(प्रतिशत में)

बीकानेर	48.1	उदयपुर	30.7
गंगानगर	45.6	चित्तौड़गढ़	30.4
बाड़मेर	44.4	नागौर	29.0
जोधपुर	44.8	सवाई माधोपुर	28.7
जैसलमेर	44.8	भुवनेश्वर	30.4
जयपुर	38.5	डूंगरपुर	28.8
कोटा	36.6	सिरोही	27.9
बीसवाड़ा	35.4	भरतपुर	26.1
जालौर	35.2	धोलपुर	27.3
बुह	34.9	अलवर	26.2
सीकर	32.1	भालावाड़	25.8
पाली	31.4	बजमेर	25.5
बूंदी	30.7	टोंक	25.2
		मीलवाड़ा	24.2

[समस्त राजस्थान 33.0]

1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 11 शहरों की जनसंख्या एक लाख के ऊपर रही है, जो अग्र प्रकार है :

1. Some Facts about Rajasthan, 1987, pp 10-11. (DES, Jaipur)

राजस्थान का कृषिगत विकास

(Agricultural Development of Rajasthan)

राजस्थान की व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। 1987-88 में राज्य की आय (प्रचलित भावों पर) लगभग 9502 करोड़ रुपये थी जिसमें कृषि का योगदान 4146 करोड़ रुपये, अर्थात् लगभग 43.6 प्रतिशत था। 1970-71 की कीमतों पर देने पर कृषि का योगदान राज्य की कुल आय में 1987-88 में 45.7% आया है।¹ इस प्रकार स्थिर भावों पर कृषि (पशुधन सहित) का योगदान राज्य की कुल आय (SDP) में लगभग आधा भाग होता है। 1987-88 में अनुपूर्व मूलों के कारण यह लगभग 46% रहा था। राज्य की कृषिगत आय में काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की कृषिगत आय अस्थिर (unstable) है और इस पर अकालों की काफी छाप निरन्तर पड़ती रहती है :

(घ) भूमि का उपयोग—निम्न तालिका में 1951-52 व 1986-87 के वर्षों में राजस्थान में भूमि के उपयोग का परिवर्तन दर्शाया गया है :

राजस्थान में भूमि का उपयोग²

वर्गीकरण	(साल हैक्टयर में) 1951-52	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत	(साल हैक्टयर में 1986-87	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत
1 रिपोर्टिंग क्षेत्रफल	342.8	100.0	342.3	100.0
2. वन	11.6	3.4	22.5	6.6
3. कृषि के लिए उपयुक्त*	89.8	26.2	63.1	18.4
4 कृषि योग्य अन्य भूमि	90.0	26.3	57.5	16.8
5. चरणीय भूमि	58.3	17.0	44.9	13.1
6. शुद्ध कृषि भूमि	93.1	27.1	154.3	45.1
7. एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र	4.4	1.3	22.1	6.5**
8. सकल कृषि क्षेत्र	97.4	28.2	176.4	51.6

1. आय-व्यय अध्ययन (DES) 1989-90 p. 52 & p. 54.

2. 10 years of Agricultural Statistics Rajasthan, 1977-78 to 1986-87, DES, Jaipur, July, 1988, p. 2.

* इसमें निम्नांकित क्षेत्र शामिल किये गये हैं :

(i) गैर-कृषिगत उपयोगों में मराई गई भूमि, (ii) वज्र व अकृष्य भूमि, (iii) स्टाई चरागाह व अन्य चराई की भूमि तथा (iv) विविध पेड़ों, फसलों व कृषि की भूमि।

1986-87 में एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 6.5% तथा शुद्ध कृषि क्षेत्र का 14.3% था।

तालिका से यह पता चलता है कि राजस्थान में 1986-87 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 3 42 करोड़ हेक्टेयर भूमि था। शुद्ध कृषित क्षेत्र (net area sown) इसका 45.1 प्रतिशत था जो 1951-52 में केवल 27 प्रतिशत था। यह 1951-52 में 93 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1986-87 में 154.3 लाख हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार योजना काल में राज्य में नई भूमि पर खेती का काफी विस्तार किया गया है। एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र 1951-52 में 4.4 लाख हेक्टेयर था जो 1986-87 में 22.1 लाख हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार मिर्चाई के साधनों का विकास होने से राज्य में गहन कृषि का भी विकास किया गया है। परिणामस्वरूप कुल कृषित क्षेत्र (total cropped area) जो 1951-52 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 28.4% था, वह 1986-87 में 51.6% हो गया। राज्य में घाज भी दोनों का क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 6.6% मात्र है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि (Culturable Waste Land) व परती भूमि (Fallow Land) (मद 4—मद 5) 30 प्रतिशत है। मविध्य में इसमें से कुछ क्षेत्र कृषि में लाया जा सकता है। अतः राज्य में विस्तृत व गहन दोनों प्रकार की कृषि के विकास की भावी सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

1986-87 में शुद्ध कृषित क्षेत्र 1.54 करोड़ हेक्टेयर रहा, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 45.1% था। 1986-87 में सकल कृषित क्षेत्र (gross cropped area) 17.6 करोड़ हेक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग 52% था।

राजस्थान में 1985-86 में कायशील जोतों का विवरण¹

जोतों की किस्में	जोतों की संख्या (लाख में)	कुल का %,	समाया हुआ ! क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	कुल का %
1 सोनामन जोत (1 हेक्टेयर तक)	13.6	28.6	6.4	3.1
2 लघु जोतें (1-2 हे)	9.2	19.3	13.3	6.4
3 मनु-मगन (2-4 हे)	9.8	20.6	27.9	13.5
4 मगन (4-10 तक हे)	9.9	20.8	61.2	29.6
5 बड़ी (10 हे से ज्यादा)	5.1	10.7	97.9	47.4
कुल	47.6	100.0	206.7	100.0

तालिका में स्पष्ट होता है कि राज्य में कायशील जोतों का विवरण काफी बरमान है। एक हेक्टेयर तक की जोतें कुल जोतों का लगभग 29% हैं, लेकिन

1. Some facts About Rajasthan, 1987, p. 33.
(प्रसिद्ध निबन्धों से हैं)

इसमें कुल क्षेत्रफल का केवल 3.1% भाग ही समाया हुआ है। इसके विपरीत 10 हैक्टेयर से ऊपर की जमीनें लगभग 11% हैं, जबकि इनमें 47% क्षेत्र समाया हुआ है। 1970-71 में राजस्थान में कार्यशील जमीनें का औसत आकार 5.45 हैक्टेयर था, जो समस्त भारत के औसत आकार 2.28 हैक्टेयर का 2½ गुना था, एवं सभी राज्यों की तुलना में यह सर्वाधिक था। 1985-86 में राजस्थान के जमीनें का औसत आकार घटकर 4.34 हैक्टेयर पर आ गया है तथा इसी वर्ष भू-जमीनें की कुल संख्या 47.63 लाख थी जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ 6 लाख 71 हजार हैक्टेयर समाया हुआ था।

शुष्क प्रदेश में सिंचाई का महत्व—राजस्थान में शुष्क प्रदेश (arid region) में पानी की सुविधा का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बीकानेर व गगानगर जिले में मुख्य अन्तर यही है कि गगानगर जिले को गंग नहर से सिंचाई की सुविधा मिली हुई है। बीकानेर जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र गगानगर जिले से ज्यादा होते हुए भी कृषि क्षेत्र उससे कम है। कृषि योग्य बज्र भूमि बीकानेर जिले में ज्यादा है। गगानगर जिले में लगभग 25 तरह की फसलें बोई जाती हैं, जबकि बीकानेर में 5 या 6 तरह की। पशुपालन भी गगानगर जिले में ज्यादा उन्नत है। कपास, गन्ना, तिलहन गेहूँ, चावल आदि की फसलें होती हैं।

(आ) सिंचित क्षेत्र—राजस्थान में नहरों, तालाबों व कुएँ आदि साधनों की सहायता से सिंचाई की जाती है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र (gross irrigated area) 1951-52 में 11.7 लाख हैक्टेयर था जो 1985-86 में 38.6 लाख हैक्टेयर हो गया। 1986-87 में यह 43.5 लाख हैक्टेयर रहा। विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र¹

(लाख हैक्टेयर में)

वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ व अन्य साधन	योग
1951-52	2.2	0.8	7.0	10.0
1985-86	15.1	1.0	22.5	38.6
1986-87	16.4	1.4	25.7	43.5

1. Budget Study 1989-90, p. 76. (1985-86 व 1986-87 के लिए)

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1986-87 में नहरों की सिंचाई 1951-52 की तुलना में लगभग $7\frac{1}{2}$ गुना हो गई। लेकिन राज्य में आज भी सिंचाई के साधनों में कुआँ व ट्यूबवेल का सर्वोच्च स्थान है, जो लगभग 60% है।

1951-52 में कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्रफल का 12% था जो बढ़कर 1970-71 में 14.7% तथा 1986-87 में 24.6% हो गया। इस प्रकार योजनाकाल में राज्य में सिंचाई के साधनों का काफी विस्तार हुआ है और सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषि क्षेत्रफल का 12% से बढ़कर 24-25% हो गया है।

राज्य में अधिक मात्रा में सिंचित फसलों में गन्ना, बटास, जौ व गेहूँ का स्थान प्राता है और उवार, बाजरा व मूँगफली का स्थान काफी कम सिंचित फसलों में आता है। राज्य में सिंचाई के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इसके लिए सिंचाई के क्षेत्र में भारी मात्रा में पूँजी लगाने की आवश्यकता है। 1986-87 में खाद्यान्नों की फसलों में 27.8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई जो कुल सिंचित क्षेत्रफल 43.5 लाख हेक्टेयर का 64% थी।

पिछले वर्षों में राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (net irrigated area) लगभग 32 लाख हेक्टेयर रहा है। 1986-87 में यह बढ़कर 34.2 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार 1986-87 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 34.2 लाख हेक्टेयर व सकल सिंचित क्षेत्रफल 43.5 लाख हेक्टेयर पाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 9.3 लाख हेक्टेयर भूमि में एक से अधिक बार सिंचाई की गई।

$\frac{\text{सकल सिंचित क्षेत्रफल}}{\text{शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल}} = \text{सिंचाई की गहनता (irrigation intensity)}$ कहलाती है,

जो 1986-87 के लिए $\frac{43.5}{34.2} = 1.27$ रही। यह 1971-72 में $\frac{31.7}{27.6} = 1.15$

रही थी। इसकी ओर बढ़ाने की आवश्यकता है।

राजस्थान की बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ तथा सिंचाई की वृहद् परियोजनाएँ

(अ) राजस्थान की बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

1. झालडा नाल परियोजना में हिस्सा,
2. चम्पल परियोजना में हिस्सा,
3. व्यान परियोजना
4. माही परियोजना

(आ) सिंचाई की वृहद् परियोजनाएँ जिन पर कार्य किया जा रहा है —
वृहद् परियोजनाओं के अन्तर्गत कमान्ड क्षेत्रों में 1 हजार हेक्टेयर से अधिक होगा है।

हैं। तृतीय अवस्था में जवाहरसागर बाँध बनाया जा रहा है। चम्बल परियोजना से राजस्थान में मुख्यतया बोंटा व बूंदी जिलों में सिंचाई की सुविधा बढेगी। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी के जमाव, क्षारयुक्त भूमि व पानी के मिट्टी में सोख लिए जाने, आदि की समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे सिंचाई की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। विश्व बैंक की सहायक सस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की सहायता से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिकीकरण व पानी के निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। छठी योजना (1980-85) की अवधि में राण प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा लिपट स्कीम के चालू कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी थी। चम्बल परियोजना के नये कार्यक्रमों में बूंदी शाखा का विस्तार, काटा जलाशय को ऊँचा करना तथा डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन बक्स शामिल किये गये हैं। अब चम्बल परियोजना का कार्य पूरा हो गया है। इससे 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है।

3 व्यास परियोजना (Beas Project)—यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की मिमी-जुली बहुउद्देश्यीय योजना है। इस योजना में सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है। इसकी निम्न इकाइयाँ हैं : (1) व्यास सतलज बड़ी, (2) पोंग स्थान पर व्यास नदी पर बाँध तथा (3) व्यास ट्रान्समिशन प्रणाली। पहली इकाई में पाण्डाह (Pandoh) नामक स्थान पर एक बाँध, दो सुरंगें, सात मील लम्बी खुली हाइडल चैनल (बगो से सुन्दरनगर तक) एवं एक शक्ति-सयंत्र (देहर स्थान पर) शामिल किया गया है।

दूसरी इकाई में पोंग बाध का उद्देश्य राजस्थान के लिए पानी एकत्र रखना है। इससे पंजाब हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। इसमें एक शक्ति-सयंत्र को स्थापित करने की भी योजना है। इसका निर्माण कार्य व्यास-निपुनण मण्डल की दम्प-रेख में सम्पन्न किया जा रहा है। राजस्थान को व्यास परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई का लाभ नहीं मिलेगा। यह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल-सप्लाई करेगी। इस योजना के तीनों राज्यों में 21 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना से राजस्थान राज्य को 150 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी।

रावी-व्यास नदी जल-विवाद¹—पिछले दो दशकों से रावी-व्यास नदी जल-विवाद चबता आ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय जल-विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1986

1. मंगलाल सुरेका, "पंजाब व राजस्थान आने सामने" राजस्थान पत्रिका, 6 जून, 1986, तथा "इराडी पचाट की असहनीय कार्यवाही," राजस्थान पत्रिका, 26 मई, 1987.

पंजाब समझौते को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इसके अन्तर्गत इराही धायोग का गठन किया गया जिसे दो कार्य सौंपे गये थे :—

(1) यह निर्धारित करना कि पंजाब, राजस्थान व हरियाणा के हिसान 1 जुलाई को रावी-व्यास नदियों का कितना-कितना पानी उपयोग में ला रहे थे नाकि कम से कम उनका पानी उनको मिलता रहे। (पंजाब समझौते के पैरा 9 (1) के अनुसार)

(ii) धायोग यह निर्णय करेगा कि पंजाब व हरियाणा के बाकी बचे हुए अपने हिस्से में से कितना पानी किस राज्य (पंजाब व हरियाणा) को मिलेगा। धायोग का यह निर्णय केवल इन्हीं दो राज्यों पर लागू होगा। (पंजाब समझौते पैरा 9 (2) के अनुसार)

इस प्रकार इराही धायोग की नियुक्ति किसी स्वतन्त्र न्यायिक निर्णय के लिए नहीं की गई थी। बल्कि लोगोवाल-राजीव पंजाब समझौते में किये गये राजनीतिक निर्णय को लागू करने में मदद देने के लिए की गई थी।

पंजाब का यह तर्क रहा है कि रावी-व्यास नदियाँ राजस्थान से होकर नहीं गुजरती, इसलिए इनके पानी पर राजस्थान का कोई अधिकार नहीं है। वस्तु-स्थिति यह है कि पंजाब व हरियाणा के धायोमी विवाद में राजस्थान को अनावश्यक रूप से घसीट लिया गया है। राजस्थान सिंध नदी का प्रदेश है और इस प्रकार इन नदियों के पानी का पूरा मागीशर जाना जाना चाहिए। राजस्थान के विशाल रेग-स्थान व मूला क्षेत्रों का सिंचाई के लिए पानी की निरन्तर आवश्यकता है।

इराही धायोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1987 में पेश कर दी थी जिसके अनुसार पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के पानी के हिस्से इस प्रकार निश्चित किये गये थे—

	नये निर्धारित अंश	पूर्व अंश
(1) पंजाब :	50 साल एकड़ फुट	42.2 साल एकड़ फुट
(2) हरियाणा :	38 साल 30 हजार एकड़ फुट	35 साल " "
(3) राजस्थान :	86 साल एकड़ फुट	86 साल " "

इस प्रकार इराही धायोग की निष्कारिता से पंजाब व हरियाणा के हिस्से बचे हैं तथा राजस्थान का घटावत रहा है। इससे राजस्थान का वास्तविक अंश रावी-व्यास पानी से 3% कम हो गया है। इस बात को लेकर राजस्थान में असन्तोष है क्योंकि राज्य में प्रायः सूखा पड़ता रहता है और यहाँ की जन की आवश्यकता काफी अधिक है। इसलिए राजस्थान का हिस्सा भी आनुषंगिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन पंजाब समझौते के अन्तर्गत अतिरिक्त पानी पंजाब व हरियाणा में ही विभाजित होना था। इसलिए राजस्थान सरकार असमंजस की स्थिति में पड़ गयी है।

4. माही बहाल सागर परियोजना— यह राजस्थान व गुजरात की मिनी-जुनी परियोजना है। इससे दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात में सिंचाई की

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (Indira Gandhi Canal Project)
का विवरण—यह पहले राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर यह विश्व की सबसे लम्बी सिंचाई प्रणालियों (irrigation systems) में से एक पानी जायेगी। यह थार के रेगिस्तान के बड़े भू भाग को हरा-भरा बना देगी तथा गंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर जिलों में पूर्ण विकास होने पर चरण I व II में समतल नहरी प्रवाह क्षेत्र तथा लिफ्ट नहरी प्रवाह क्षेत्र को मिलाकर 13 88 चरवा लगभग 14 लाख हेक्टर में सिंचाई करेगी तथा पास के क्षेत्रों के लिए पैप जल सप्लाई करेगी।

प्रथम चरण में 5-78 लाख हेक्टर में तथा द्वितीय चरण में 8 10 लाख हेक्टर में सिंचाई की क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गये हैं,¹

प्रथम चरण (Stage I) के तहत 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर (जो पंजाब में व्यास व सतलज नदियों के संगम पर हरी के बांध से प्रारम्भ होगी) 169 किलोमीटर लम्बी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3075 किलोमीटर में वितरिकाओं के निर्माण-कार्य चल गये थे जो पूरा होने में आ गये हैं। द्वितीय चरण (Stage II) में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर (189 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक) तथा 4800 किलोमीटर में वितरिकाओं के निर्माण कार्य चले गये हैं। 1 जनवरी 1987 को मुख्य नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया गया था। हिमालय की गगनचुम्बी बर्फीली चट्टानों से हिंडों की दूर प्यासे छोर तक पहुँचने के लिए राजस्थान में जोड़नवादी जल का पहुँचाना एक भव्य प्रयास की मुख्य परिणति है। इसके साथ ही वितरिकाओं का निर्माण कार्य भी कराया गया है। मुख्य नहर पर मिट्टी की खुदाई का काम पूरा हो चुका है तथा वितरक-प्रणालियों पर भी आंशिक रूप से मिट्टी की खुदाई का काम किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कुल सम्भावित लागत 1186 करोड़ रुपये आँकी गई है जिनमें प्रथम चरण की लागत का अनुमान 255 करोड़ रुपये व द्वितीय चरण का 931 करोड़ रुपये है।

जैसलमेर जिले की समृद्ध बनाने में लाठी सिरोज के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। यहाँ पानी पहुँचत ही खेती होने लगेगी। वैसे भी यहाँ मामूली दरसात से सीढ़ण घात पैदा होती है जो पशुओं के लिए पोषक माना जाता है। मोहनगढ़ से आगे राजस्थान नहर के अंतिम छोर से सीढ़ण शाखा निकाली जा रही है। यह 90 किलोमीटर लम्बी होगी और लाठी सिरोज क्षेत्र में सिंचाई करेगी। ताजा सूचना के अनुसार राजस्थान नहर का पानी सदियों से प्यासे पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के करीब 18 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है। पानी के बभाव में वीरान पड़े हुए मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों एवं पशु-

1 Indira Gandhi Nahar Project, February 1988, (IGN बोर्ड का प्रावधान)

पक्षियों को पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को मिर्चाई की सुविधा मिली है। अन्न परियोजना का बाडमेर में गहरा राट तक बनाने की व्यवस्था मिल गयी है।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से राज्य में गेहूँ, कपास व तिलहन की पैदावार काफी बढ़ेगी। नये उद्योग, नये नगर, नई बस्तियाँ ये सब इस नहर के ही वरदान होंगे। नहरी क्षेत्र से लाखों व्यक्तियों को बसान का कार्यक्रम है। इसके लिए 'मास्टर प्लान' पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की यह विशेषता है कि इससे पहसी द्वार नई भूमि पर खेती की जा सकेगी। इससे रावी-व्यास व जल का ज्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कपास क्षेत्र में निरन्तर पत्तों के कारण झाल राहत-व्यय में काफी कमी की जा सकेगी। इसमें विश्व बैंक की सहायता से भूमि का विकास-कार्य किया जा रहा है। इसलिए इस परियोजना का महत्व काफी बढ़ गया है। इस परियोजना का पूरा होना पर सम्पन्न दण लाभान्वित होगा।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है एक अनिश्चित गगाननहर (लीसवा ग्राम) के निर्माण का काम चल रहा है। मुख्य नहर के बाहिरी छोर से एक और बड़ी शाखा दोधा भी निकाली जायेगी जिसका निर्माण-कार्य भी हाथ में लिया जा रहा है। इन दोनों शाखाओं से जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही वर्षों में चमक उठेगा।

योजना के कार्यक्रमों को पूरा करने में सीमेन्ट व कोयले का अभाव बाधा डाल रहे हैं। इस नहर में लिफ्ट सिंचाई (जलोत्थान) स्कीम को कार्यान्वित करने की भी योजना बनायी गई है ताकि राज्य के पश्चिमी भाग को सिंचाई के लिए जल मिल सके। मुख्य नहर से 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इन लिफ्ट नहरों में पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। एक बार के लिफ्ट में पानी को 60 मीटर ऊपर चढ़ा सकते हैं। जोधपुर को लिफ्ट नहर योजना से 1992 में पानी मिलेगा। 6 लिफ्ट नहरों के नाम इस प्रकार हैं

(1) बीकानेर-सूणकरणसर लिफ्ट नहर—इससे बीकानेर शहर का पानी मिलेगा।

(2) गजनेर लिफ्ट नहर

(3) सहवा लिफ्ट-नहर—इससे कई गाँवों के अलावा भरदार शहर व तारानगर को पानी मिलेगा।

(4) कोलायन लिफ्ट नहर

(5) फलीदास लिफ्ट नहर

(6) पोखरण लिफ्ट नहर

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना में चार के बड़े क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा पत्तों के पेड़ों का विस्तार किया जा सकेगा। राज्य सरकार चाहती है कि इस परियोजना को केन्द्र पूरा कर क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में वित्तीय व्यय की आवश्यकता है। अन्न-मत्तज-यमुना लिफ्ट (SYL) की भाँति इसका वित्तीय भार भी केन्द्र को बहन करना चाहिए। इससे राज्य के आर्थिक विकास में विभिन्न

प्रकार से मदद मिलेगी जैसे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कृषिगत उपज में वृद्धि, बिजली के उत्पादन में वृद्धि, पेयजल की सफ़ाई में वृद्धि, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, मछली-पालन को प्रोत्साहन, परिवहन का विकास, घनाज की मण्डियों का निर्माण, पशु-पालन का विकास, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, आदि।

2. ग्रन्थ बृहद् सिंचाई की परियोजनाएँ—जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि इस समय सिंचाई की निम्न 8 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है : गुडगांव नहर ओखला जलाशय, मर्मदा, जालम (जनजाति उपयोग के अन्तर्गत), पीन बांध, बीतलपुर (जिला टोक), मोहर फोहर तथा सिंध मुल।

जवाई परियोजना—यह सिंचाई की मध्यम दर्जे की परियोजना है। जवाई नदी मारवाड़ की प्रसिद्ध लूनी नदी की सहायक है। यह जोधपुर डिवीजन के दक्षिण में बहती है। जवाई बांध पश्चिमी रेलवे की दिल्ली-महमदाबाद रेल लाइन पर रेलवे स्टेशन से कोई तीन किलोमीटर दूर घरावली पर्वत की गोद में स्थित है। इसका निर्माण-कार्य मई 1946 में जोधपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा उम्मेद-सिंह ने करवाया था जो 1951-52 में पूरा हो गया था। इस परियोजना पर 26 करोड़ रु की लागत आई थी। जवाई बांध को तिरोही, पाली, जालोर व जोधपुर जिलों की प्याऊ बतलाया गया है, क्योंकि इससे चार जिलों की प्याऊ बुझाई जाती है। इस बांध में पाली जिले के 33 गांवों तथा जालोर जिले के 24 गांवों की जमीन सीधी जाती है। पाली जिले में 20 हजार हेक्टेयर भूमि तथा जालोर जिले में 15 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है।

जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे अभी तक तिरोही जिले को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने जवाई कमांड एरिया की नहरों के आधुनिकीकरण की एक योजना अपने हाथ में ली है जिसके अन्तर्गत नहरों को पक्का करवाने, उनकी क्षमता को बढ़ाने आदि से सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे। जवाई परियोजना के पानी का अधिकतम उपयोग हो सकेगा।

सिंचाई की मध्यम परियोजनाएँ जिन पर काम जारी है—सिंचाई की निम्न मध्यम परियोजनाओं पर काम जारी है जिनके पूरा होने पर 74 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सम्भावना उत्पन्न हो जायगी।

इनमें तीन परियोजनाएँ धनगढ डाइवर्जन, बस्ती तथा मोमुंडा चित्तोडगढ जिले को लाभ पहुंचायेगी : दो परियोजनाएँ : मेवा फोहर व कोठारी भीलवाडा जिले को, भीमसागर व हरीशचन्द्र सागर भालावाड जिले को, सोम-कामला-धम्बा डूंगरपुर जिले को, सोम-बागदारे उदयपुर जिले को तथा पचाना सवाई माधोपुर जिले को लाभ पहुंचायेगी।

सिंचाई की मध्यम परियोजनाओं के लिए राजस्थान को अन्तराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी (USAID) से कर्ज प्राप्त हुआ है। भविष्य में सिंचाई-

व्यवस्था का प्रावधानीकरण भी किया जाएगा। राज्य में घाघर कंट्रोल व भरतपुर ट्रेन वर्क व बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में कार्य किया गया है।

राज्य में सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार पर वर्ष 1989-90 में 159.90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जो वर्ष की कुल योजना का लगभग 20 प्रतिशत है। इसमें 63 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तथा 19 करोड़ रुपये माही बराजमागर परियोजना के शामिल हैं।

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट होता है कि राज्य में कृषि व मत्स्य मिचाई की नई परियोजनाओं के लिए विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जिनका उपयोग करके राज्य की कृषिगत घण्टाश्रमता को अधिक स्थिरता व सफलता प्रदान की जा सकती है।

(इ) राजस्थान में फसलों का ढांचा (Cropping Pattern in Rajasthan) — राजस्थान में खाद्यान्नों की फसलों में घनाज में बाजरा, ज्वार, भेड़ू, मक्का, जौ, मोटे अनाज व चावल एवं दालों में चन्दा, तुर, अमरबी की दालें व अमरबी की दालें शामिल हैं एवं गेहूँ-खाद्यान्नों की फसलों में तिलहन में गहूँ व सरसों, झलसी, मूँगफली व हरण्डी एवं अन्य में कपास, तम्बाकू, सन, यन्ना, हल्दी, घनिया, मिर्च, घालू, अदरक, अजीम व ग्वार आदि शामिल हैं।

1986-87 में कुल कृषि क्षेत्रफल 1.76 करोड़ हेक्टेयर था। इसका विभिन्न फसलों के अनुसार विवरण नीचे दिया जाता है :¹

	(लाख हेक्टेयर)	कुल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत
1. घनाज	95.7	54.2
2. दालें	32.1	18.2
3. तिलहन	15.0	8.5

1. 10 years of Agricultural Statistics Rajasthan, 1977-78 to 1986-87, July, 1988, (DES Jaipur), pp 11-15—घाघे फसलों के उपादन के आंकड़े भी ज्यादातर इसी पर आधारित हैं।

4 कपास	3 6	2 0
5 अन्य	36 0	17 0
कुल	176 4	100 0 (लगभग)

तालिका से स्पष्ट होना है कि 1986 87 में 72.4 प्रतिशत क्षेत्रफल साद्यन्नों की फसलों (अनाज व दालों के अन्तर्गत या और शेष 27.6 प्रतिशत गैर-साद्यन्नों की फसलों के अन्तर्गत था। राज्य में कुल कृषि क्षेत्र के साथ से कुछ अधिक भाग पर अनाज बोया जाता है और $\frac{1}{3}$ भाग पर दालें बोयी जाती हैं। स्मरण रहे कि राज्य के लगभग $\frac{1}{3}$ क्षेत्रफल में एकले बाजरे की खेती की जाती है। राज्य में तिलहन गन्ना व कपास की पैदावार होने से इनसे सम्बन्धित उद्योगों (तेल उद्योग चीनी व गूठ उद्योग सूती वस्त्र उद्योग) का विकास किया जा सकता है। मसालों में लाल मिर्च, जीरा घनिया तथा हल्दी के उत्पादन का भी महत्व है। इनके उत्पादन में कृषकों की अच्छी प्राप्ति होती है। राज्य में ग्वार, तम्बाकू, अफीम, आदि की भी पैदावार होती है। ग्वार के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का $\frac{1}{8}$ भाग पाया जाता है।

1952 53 में साद्यन्नों के अन्तर्गत कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 91.6 प्रतिशत तथा गैर-साद्यन्नों में 8.4 प्रतिशत था। 1986 87 में ये प्रतिशत क्रमशः लगभग 72 व 28 हो गये थे। इस प्रकार 1952 53 से 1986 87 में 34 वर्षों की अवधि में फसलों के ढांचे में काफी परिवर्तन हुआ है। साद्यन्नों व अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत घटा है और गैर साद्यन्नों में बढ़ा है।

(ई) राजस्थान में कृषित उत्पादन—राजस्थान में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में उस वा महत्वपूर्ण स्थान बाजरा गेहूँ मक्का जो उधार दाल तिल मूँग-फली व कपास का है। लेकिन क्षेत्रफल में प्रति वर्ष मौसमी परिवर्तनों के कारण काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। प्रमुख फसलों का मालिफ्त विवरण नीचे दिया जाता है

1 गेहूँ—राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने की दृष्टि से भारत में पाँचवा सबसे बड़ा राज्य है। विशेष रूप से गगानगर भरतपुर कोटा अलवर व चित्तौड़गढ़ जिलों में गेहूँ की खेती की जाती है। 1986 87 में राज्य में लगभग 10.5% कृषित भूमि पर गेहूँ बोया गया था और अनाज के वन उत्पादन का लगभग 58.2% गेहूँ था। गेहूँ रबी की फसल है। 1986 87 में गेहूँ का उत्पादन 34 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष 1985 86 में 39.2 लाख टन हुआ था जो अब तक का सर्वाधिक

उत्पादन था। गोहूँ का प्रति हैक्टियर उत्पादन 1986-87 में 1845 किलोग्राम रहा जो पिछले वर्ष से कम था। राज्य में गोहूँ की सोना-बल्याण, मैक्सिकन सोनेरा, कोहीनूर आदि विकसित किस्में बोयी जाती हैं जो कम सिंचाई के क्षेत्रों में भी काफी फसल देती हैं।

2. चना—उत्तर-प्रदेश के बाद चना उत्पादन करने में राजस्थान का नम्बर आता है। इसके प्रमुख जिले गगानधर, अलवर, भरतपुर, जयपुर व सर्वाई माधोपुर हैं। राज्य का $\frac{3}{4}$ चना इन्हीं जिलों में उत्पन्न किया जाता है। 1986-87 में चने का उत्पादन 76 लाख टन हुआ था जबकि इसके पिछले वर्ष 1985-86 में 162 लाख टन हुआ था जो सर्वाधिक था। 1986-87 में राज्य की 8% कृषित भूमि पर चना बोया गया था तथा कुल दालों के उत्पादन में इसका अंश 87% रहा था।

3. बाजरा—बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है। देश में कुल बाजरे की उपज का 2.1% ($\frac{1}{5}$ अंश) राजस्थान में उत्पन्न होता है। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जयपुर व नागौर जिलों में राज्य का अधिकांश बाजरा उत्पन्न होता है। राज्य में बाजरे का उत्पादन बहुत घटता बढ़ता रहता है। 1986-87 में बाजरे का उत्पादन 101 लाख टन हुआ था जबकि 1983-84 में 245 लाख टन हुआ था जो सर्वाधिक था। यह खरीफ की फसल है। 1986-87 में कुल कृषित क्षेत्रफल के 30% भाग में बाजरा बोया गया था तथा अनाजों की कुल पैदावार में इसका अंश 17.4% रहा था। बाजरे की प्रति हैक्टियर उपज 1986-87 में 192 किलोग्राम रही जबकि 1983-84 में 491 किलोग्राम रही थी। इस प्रकार इसमें काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

4. जौ—उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान जौ उत्पन्न करने वाले राज्यों में आता है। देश का चौथाया जौ राजस्थान में पैदा होता है। यह जयपुर, उदयपुर, अलवर, टोंक व भीलवाड़ा में उत्पन्न होता है। आजकल नई किस्मों का प्रचलन भी हो गया है जैसे ज्योति, भार एस-6 आदि। 1986-87 में जौ का उत्पादन 4.1 लाख टन हुआ जबकि 1977-78 में 6.6 लाख टन हुआ था जो सर्वाधिक था।

5. मक्का—देश में कुल मक्का की पैदावार का $\frac{1}{10}$ अंश राजस्थान में होता है। यह उदपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में पैदा की जाती है। 1986-87 में मक्के का उत्पादन 6.5 लाख टन हुआ जबकि 1983-84 में 12.3 लाख टन हुआ जो सर्वाधिक था।

6. सरसो, राई व तिल—राज्य में सरसो व राई का उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा होता है। पहले सरसो अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा श्री गगानधर जिलों में पैदा होती थी, लेकिन अब कृषि विस्तार कार्यक्रमों के फलस्वरूप यह

जालोर, सिरोंही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा व बूंदेल जिलों में भी होते लगी है। 1986-87 में सरसों व राई का उत्पादन 6.5 लाख टन हुआ जबकि 1984-85 में 8.7 लाख टन हुआ जो सर्वाधिक था। तिल के उत्पादन में राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है। पाली जिले में भी काफी तिल होता है। 1986-87 में तिल का उत्पादन 27 हजार टन हुआ जबकि 1984-85 में 73 हजार टन रहा था जो सर्वाधिक था। राज्य में प्रमुखी, तारामोरा, सोयाबीन आदि का भी उत्पादन होता है। 1986-87 में सोयाबीन का उत्पादन 39,214 टन हुआ था जो पहले से अधिक था।

खाद्यान्नों का उत्पादन—राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। राज्य में 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख टन हुआ था जो बटकर 1960-61 में 45.5 लाख टन, तथा 1965-66 में बटकर 38.4 लाख टन पर आ गया था। 1970-71 में यह 88.4 लाख टन तक पहुँच गया था जो 1974-75 में बटकर 49.8 लाख टन पर आ गया। उसके बाद के वर्षों में भी उत्पादन में उतार-चढ़ाव आते रहे। 1983-84 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार एक करोड़ टन की पार कर गया। उसके बाद के वर्षों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

1983-84 से 1988-89 तक खाद्यान्नों का उत्पादन¹

वर्ष	(लाख टनों में)
1983-84	100.8
1984-85	67.9
1985-86	81.3
1986-87	67.9
1987-88	48.0
1988-89	100.8

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1983-84 में खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार 1 करोड़ टन की सीमा की पार कर गया जो बाद में इससे नीचे घूमता रहा और 1987-88 के अमृतपूर्व सूखे व अकाल के कारण 48 लाख टन पर आ गया। लेकिन 1988-89 में इसके पुनः 1 करोड़ टन के समीप रहने की आशा है। इस प्रकार एक वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन का स्तर पुनः दुगुना होना एक असामान्य स्थिति का परिचायक है।

1. *Economic Survey 1988-89*, p. S-19, & *Raj Budget Study 1989-90*, p. 74

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में स्थिरता लाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए सिंचाई का विस्तार किया जाना चाहिए।

नीचे राज्य में कृषिगत उत्पादन के सूचकांक दिये जाते हैं¹—

कृषिगत उत्पादन के सूचकांक (1979-80 में 1981-82 = 100)

वर्ष	खद्यान्न फसलें	प्रत्याद्यान्न फसलें	समस्त वस्तुएं
1980-81	102.1	91.6	100.1
1985-86	132.2	163.0	138.0
1986-87 (अन्तिम)	102.9	172.5	116.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1979-80 से 1981-82 तक के त्रिवर्षीय औसत = 100 की तुलना में 1985-86 में सभी फसलों का उत्पादन लगभग 38% बढ़ा खाद्यान्न फसलों की तुलना में प्रत्याद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक बढ़ा है। राज्य में विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की दरें²

राजस्थान में 1967-68 से 1975-76 तथा 1976-77 से 1984-85 की अवधियों में कृषिगत विकास की चतुर्वृद्धि दरें इस प्रकार रहीं :

अवधि I : 1967-68 से 1975-76

अवधि II : 1976-77 से 1984-85

	क्षेत्रफल		उत्पादकता		उत्पादन	
	I	II	I	II	I	II
(i) घनाज	(-)0.15	1.4	2.6	3.1	2.4	4.6
(ii) सभी दालें	2.8	(-)1.9	(-)0.5	(-)1.3	2.3	(-)3.1
(iii) सभी तिलहन	0.9	7.2	7.5	7.2	8.5	14.9

1. 10 Years of Agricultural Statistics, Rajasthan, DES, Jaipur, pp. 37-38.

2. प्राथमिक अध्ययन, 1986-87, पृष्ठ 107 (दशमसह के बाद एक स्थान तक)

(iv) गन्ना	5.4	(-)-6.5	17.6	(-)-0.05	24.1	(-)-6.6
(v) कपास	2.9	1.5	7.2	1.0	10.4	2.5

तानिका से पता चलता है कि अनाज के सम्बन्ध में द्वितीय अवधि में क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में पहली अवधि की तुलना में अधिक तेज गति से वृद्धि हुई है। दालों में क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता तीनों दृष्टियों में द्वितीय अवधि प्रथम अवधि की तुलना में निरुपलब्ध रही। द्वितीय अवधि में यह श्रृंखलात्मक रही। सभी तिलहनो में उत्पादन की वृद्धि दर पहले से तेज हुई है। गन्ने की स्थिति भी क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता सभी दृष्टियों से प्रथम अवधि की तुलना में बिगड़ी है और विकास की वांछित दरें श्रृंखलात्मक रही हैं। कपास में भी द्वितीय अवधि प्रथम अवधि की तुलना में घटिया रही है।

राजस्थान में खाद्यान्नों के विकास व सिंचाई की दृष्टि से भारत की सदृश में स्थिति¹—

यहाँ भारतीय सदृश में राजस्थान की खाद्यान्नों में विकास की दर (क्षेत्रफल, उत्पादन व प्रति हेक्टर उपज) सभी सबल सिंचित क्षेत्रफल सबल कुपित क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में दर्शाये गये हैं। अवधि 1979-80 से 1985-86 तक की ली गई है (त्रिवर्षीय औसत, समाप्त होने वाले वर्ष के आधार पर अन्तिम वर्ष जैसे 1979-80 एवं 1985-86 के पर)।

	खाद्यान्नों में विकास की दर 1979-80 से 1985-86 तक (त्रिवर्षीय औसत लेने पर समाप्त होने वाले वर्ष पर)			सकल सिंचित क्षेत्रफल सबल कुपित क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	प्रति हेक्टर उपज (Yield)	वर्ष अंत 1979-80 (त्रिवर्षीय औसत)	वर्ष अंत 1983-84 (त्रिवर्षीय औसत)
राजस्थान	0.67	4.35	3.66	21.1	21.2
समस्त भारत	0.14	3.35	3.21	27.8	29.7

1. Seventh Five Year Plan, Mid-Term Appraisal, 1988, p. 97.

इस प्रकार खाद्य-पौधों के सम्बन्ध में विकास की दर राजस्थान में समस्त भारत की तुलना में 1979-80 से 1985-86 की अवधि में बेहतर रही है। राज्य कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का 1983-84 में 21% रहा जबकि भारत में यह 30% के समीप पहुँच गया था।

(उ) कृषिगत विकास की नयी नीति का उपयोग अथवा राजस्थान में हरित-क्रांति—ग्रन्थ राज्यों की नीति राजस्थान में भी हरित-क्रांति का प्रारम्भ 1965-66 से हुआ था। इसके अन्तर्गत चुने हुए क्षेत्रों में गहन कृषि विकास के कार्यक्रम अपनाए गए हैं। सकर-बाजरा, उवार, मक्का एवं ताड़बुग घान व मैक्मिकन गेहूँ के अन्तर्गत नया क्षेत्र लाया गया है। सर्वाई माधोपुर, टोक व बंदी जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम लागू किया गया है। राज्य में किसानों ने सकर बाजरा व मैक्मिकन गेहूँ का उपयोग किया है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 1985-86 में 27.4 लाख हेक्टेयर भूमि (शरीर + रबी) आ चुकी थी। 1987-88 में यह थोड़ी घट गई थी। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत व सुघरी हुई किस्मों अन्तर्गत बीजों का वितरण किया गया है। रासायनिक उर्वरकों का वितरण 1987-88 में 214 हजार टन हुआ जो बढ़कर 1988-89 में 301 हजार टन हो जायगा।

राज्य के कृषि विभाग अनुसंधान मण्डल ने आर.एस. 31-1 गेहूँ निकाला है जो सूखे का मुकाबला कर सकता है। इसने लालबहादुर नामक गेहूँ के बीज की एक ट्रिपल इयार्फ किस्म भी पैदा की है। दुर्गापुर में जो की एक नयी इयार्फ किस्म उत्पन्न की गयी है। बारानी क्षेत्रों में बोने के लिए आर. एफ. 6 नामक जो का बीज तैयार किया गया है।

भूतकाल में कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम (ARDC) ने राज्य में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था की है। निगम ने नये कुओं के निर्माण, पुराने कुओं को गहरा करने, पम्प-सेट स्थापित करने तथा ग्रन्थ लघु सिंचाई कार्यक्रमों में मदद पहुँचायी है। अब यह कार्य नाबाड के द्वारा किया जाता है।

सहकारी ढङ्ग में वृद्धि—राज्य में अब लगभग 99% ग्राम तथा 87% कृषक परिवार सहकारिता के क्षेत्र में आ चुके हैं। वर्ष 1989-90 में 150 करोड़ रु के अल्पकालीन, 8 करोड़ रु के मध्यमकालीन तथा 32.50 करोड़ रु के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जाने की योजना है।

कृषि उद्योग निगम (Agro-Industries Corporation)

अगस्त, 1969 में केन्द्रीय व राज्य सरकार की साझेदारी में एक कृषि-उद्योग-निगम की स्थापना की गयी थी। यह निम्न कार्यों में सलग्न रहा है : कृषिगत औजारों

का निर्माण करना, गहरी रिफ्यूज को प्रोसेस करना, बेरोजगार टेक्नोवेटो को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे स्वरोजगार के अन्तर्गत कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित कर सकें। छद्म योजना में निगम के कार्य बढ़ाये गये हैं।

समूह व सीमान्त कृषकों के लिए कार्यक्रम

भूतकाल में भारत सरकार ने समूह कृषकों सीमान्त कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों के लिये मार्गदर्शी परियोजनाएँ (pilot projects) स्वीकृत की हैं। राजस्थान में समूह कृषकों के लिए भरतपुर, उदयपुर, व धनसकर में तीन परियोजनाएँ चालू की गई हैं। सीमान्त कृषकों व खेतिहर मजदूरों के लिए अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में कार्य किया गया है। प्रत्येक जिले में समूह कृषक-विकास एजेंसी को 1-50 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये हैं। सीमान्त कृषकों व भूमिहीन श्रमिकों के लिए प्रत्येक जिले में व्यय का प्रावधान एक करोड़ रुपये रखा गया है। अब यह कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) में मिला दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की पहचान व अनुदान देकर लाभ पहुँचाया जाता है।

क्षेत्रीय व ग्राम विकास-कार्यक्रम

(घ) कमाण्ड क्षेत्र विकास (Command Area Development)—राज्य सरकार ने पाँचवी योजना में इकीकृत कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल किया था। वैसे इस कार्यक्रम पर अतुल्य योजना की अवधि में भी कुछ सीमा तक बल दिया गया था। इसके अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम तथा खान्देश कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता है :

(1) इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र विकास-कार्यक्रम—इसमें निम्न प्रकार के कार्य-क्रम प्राति हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल का उपयोग करने के लिए आवश्यक है—

(अ) भूमि को समतल करना;

(आ) पानी की नालियों को पक्का करना,

(इ) सड़क, बिछा, मण्डियों का विकास, ग्रामीण जल सप्लाई, कृषि व पशु-पालन। इन कार्यों को संचालित करने में विश्व बैंक की सहायक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से मदद ली गई है।

(2) खान्देश कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम—यहाँ पर कार्य 1974-75 में चालू किया गया था। इस क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम इन्दिरा गाँधी क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम से थोड़े भिन्न हैं, क्योंकि यह एक पहले से बसा हुआ इलाका था, जहाँ लम्बी अवधि से रेवेन्यू प्रशासन चला आ रहा था। सामाजिक सेवाओं का कुछ सीमा तक विकास हो चुका था। अतः इस क्षेत्र में जल का अधिकतम उपयोग करने के

लिए उचित जल को निकास प्रणाली (drainage system) का विकास किया जाना चाहिए तथा जगली घास पात को उखाड़ने की समस्या का हल किया जाना चाहिए। अन्य कार्यक्रमों में 'वृक्षारोपण, कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के विकास, प्रोसेसिंग उद्योग प्रामोण गोदाम व प्रामोण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी विश्व बैंक से सहायता ली गई है। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम की अवधि जून 1982 में समाप्त हो गई थी लेकिन इसे छठी योजनावधि में जारी रखा गया था।

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक व भारत सरकार की मदद से क्षेत्र विकास-कमिशनरी की देख-रेख में किया जाता है। इससे इन इलाकों के आर्थिक विकास में काफी मदद मिलती है। गंग नहर प्रणाली व उत्तरी पश्चिमी भाखड़ा नहर प्रणाली में भी कमाण्ड क्षेत्र विकास-कार्यक्रम लागू किया गया है।

(घा) राजस्थान में सूखा-सम्भाव्य क्षेत्रफल कार्यक्रम एवं मरु विकास कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) in Rajasthan)—1974-79 की अवधि में DPAP कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर व नागौर जिले (विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम में), तथा पाली जालोर, बाहमेर, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले एवं राज्य की छह तहसीले (उदयपुर जिले की खेरवाड़ा भीम व देवगढ़, अजमेर जिले की ब्यावर तथा भुंभुनू जिले की घिडावा भुंभुनू तहसीले) शामिल की गई है। इनमें बांसवाड़ा डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र थे। छठी योजना (1980-85) की अवधि में ये कार्यक्रम डूंगरपुर व बांसवाड़ा के जनजाति जिलों तथा उदयपुर की भीम, देवगढ़ तथा खेरवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर जिले की ब्यावर तहसील तक सीमित कर दिये गये। सातवी योजना में इनमें कुल 30 खण्ड शामिल हैं। DPAP के अन्तर्गत भूसुरक्षण व वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जाता है। DPAP के जिलों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम स्वोक्त जिला सूबा प्रूफिंग योजनाओं में शामिल माने जाते हैं। इनके विकास से सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को लाभ पहुँचता है।

1973-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप इसे मजबूत करने के लिए मरु विकास कार्यक्रम (DDP) का श्रीगणेश किया गया। DDP रेगिस्तानी का मरु जिलों के लिए होते हैं। इन क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं :—मिट्टी व जल संरक्षण मरु प्रदेश में पानी को रोकने के लिए खडीनों (Khadeens) तथा DPAP क्षेत्रों में एनीकटो (anicutts) का निर्माण, भूतल के जल का विकास खुले कुओं व नलकूपों का विकास, वृक्षारोपण, मेड-पालन का विकास, पशु पालन व डेयरी विकास सिंचाई व विद्युत विकास आदि। DDP के अन्तर्गत

परिवेश सतुलन (ecological balance) के लिए भूमि, जल व पेड़ों के सतुलित विकास का प्रयास किया जाता है। यह कार्यक्रम राज्य के 11 मरुस्थलीय जिलों में चलाया जा रहा है और वर्ष 1985-86 से पूर्णतया केन्द्र-प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है और वर्ष 1985-86 से पूर्णतया केन्द्र-प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत चलाया गया है। अतः इसका सम्पूर्ण भार केन्द्र वहन करने लगा है। 1986-87 में इस कार्यक्रम हेतु 30 करोड़ रु. का प्रावधान था, जबकि 1987-88 के लिए इस बढ़ाकर 40 करोड़ रु. कर दिया गया।

(इ) डेयरी या दुग्ध विकास (Dairy Development)—पहले बताया जा चुका है कि राजस्थान में पशु-धन के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। राज्य के 6 पूर्वी जिलों में विश्व बैंक की सहायता से डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान डेयरी विकास निगम (RDDC) की देख-रेख में चल रहे हैं। अन्य जिलों में डेयरी विकास के कार्यक्रम सम्बन्धित विभाग की देख-रेख में चल रहे हैं। 1979-80 तक जोधपुर बोकारन, प्रजमेर व झलवा म चार डेयरी सयत्र काम कर रहे थे। जनवरी 1989 के अंत तक डेयरी सयत्रों की संख्या 11 हो गयी थी। इनके कार्यों में दूध एकत्र करना, उत्पादकों की सहकारी समितियाँ बनाना, आवश्यक दुग्ध पदार्थ तैयार करना आदि आते हैं। अब तक राज्य में 14 घवशीवन (दूध ठण्डा करने के) सयत्र (chilling plants) स्थापित किये जा चुके हैं।

राज्य में दूध उत्पादक सहकारी-समितियाँ स्थापित की गयी हैं। दूध का दैनिक संचालन काफी बढ़ाया गया है।

भारतीय डेयरी निगम को 6 वर्ष के लिए आपरेशन प्लन 2 की 68 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तुत की गई जिसकी स्वीकृति मिल गई थी। इस योजना के अंतर्गत चार नये दुग्ध सयत्र व 14 घवशीवन के इ बनाने तथा अंशित दुग्ध-संचालन 10 लाख लीटर प्रति दिन करने का कार्यक्रम है।

(ई) मैसिब कार्यक्रम (Massive Programme)—इस कार्यक्रम का उद्देश्य लघु एवं सीमांत वृक्षों द्वारा कृषिगत उत्पादन बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत प्रति पंचायत समिति को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है जिसमें लघु सिंचाई पर 3.5 लाख रुपये व दो से कम हल व छोटे अनाज के वितरण पर 0.5 लाख रुपये तथा भूमि विकास कार्यों के लिए 1 लाख रुपये नियत होते हैं। इससे लघु व सीमांत कृषकों को सिंचाई के लिए अनुदान की सुविधा प्राप्त हुई है।

(उ) सूखी खेती, शारयुक्त भूमि में सुधार व फलों का विकास—सूखी खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार के माध्यम से सूखी खेती को उन्नत विधियाँ आगाने के लिए प्रेरित करने का नक्ष्य रखा गया है। सूखी खेती के प्रदर्शन आयोजित होने से 14 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। शारयुक्त व लवणीय भूमि के सुधार के लिए कार्यक्रम रणे जात है। राज्य में नाबाट के सहयोग से फलों

के नये बगीचे लगाने का कार्यक्रम है इससे कमजोर वर्ग के किसानों का लाभ पहुँचाया जायगा। मजदूरों की सेती की बढ़ावा देने के लिए किसानों का मिनीक्रेडिट विनरित किये जायेंगे।

राज्य में कृषिगत विकास के सम्बन्ध में मुख्य निष्कर्ष

राजस्थान में कृषिगत विकास के उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, मिचार्ट की मृत्विज्ञान बढ़ी है, एवं कृषि-विकास की नई नीति को लागू किया गया है। राज्य में उन्नत बीज, खाद मिचार्ट, कीटनाशक दवाई आदि इन्पुटों का उपयोग बढ़ाकर प्रति हैक्टर उपज में वृद्धि की जानी चाहिए। अकाम व मूंग की स्थिति का सुनाबला करन के लिए भी मिचार्ट का विस्तार किया जाना चाहिए।

कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशु-धन के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले बतलाया जा चुका है कि राजस्थान में पशु धन के विकास के लिए पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार राज्य हरित क्रान्ति (green revolution) व सफ़ेद-माथ श्वेत क्रान्ति (white revolution) करन की दिशि में भी आ गया है। राज्य में ट्रैक्टरों के उपयोग के बढ़न से कृषिगत कार्यों को पचाव की भांति कुछ सीमा तक नया स्वरूप मिलन लगा है।

प्राज्ञा है मविध्य में सिचाई की बढ़ती हुई सुविधाओं के फलस्वरूप राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था की अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। राज्य में आधुनिक कृषि की आर अवसर होने के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। विभिन्न कृषिगत माधनों की सफ़ाई बढ़ाकर एवं मस्यमान व मूमि-मुद्रा माधन का कृषि के क्षेत्र में समुचित विकास का साथ प्रमस्त किया जाना चाहिए। राज्य में घटिया मिट्टी व जल-माधन की समस्या है। मूखी सेती की विविधा का प्रयोग करके राज्य में कृषि का विकास किया जाना चाहिए। विद्वानों का मत है कि राज्य में कृषिगत अनुसन्धान पर स्थानीय आश्रयताओं के अनुसार अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। दाला, निवहन आदि का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य में बराहों की बढ़ाकर मरुभूमि में पशु धन का विकास किया जाना चाहिए। जोधपुर में 'काजरी' (CAZRI) (Central Arid Zone Research Institute) मूख प्रदेशों की विभिन्न कृषिगत समस्याओं के अध्ययन में कार्यरत है। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के पूरा हो जाने पर जलमय जिये में भी कृषिगत पैदावार तेजी से बढ़ेगी। अतः राज्य का कृषिगत मविध्य उज्जवल बनाया जाना चाहिए।

प्रश्न

1. राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन कीजिए ।
(Raj II yr TDC , 1984 & 1987)
 2. पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राजस्थान के कृषि विकास की विवेचना कीजिए । (Raj II yr TDC , 1988, व ऐसा ही प्रश्न 1985 में)
 3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
 - (i) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना,
 - (ii) बम्बल परियोजना,
 - (iii) राजस्थान में डेयरी विकास-कार्यक्रम,
 - (iv) राजस्थान में कमाह क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
 - (v) सूखा खभाव्य क्षेत्र विकास-कार्यक्रम तथा मरु-विकास कार्यक्रम,
 - (vi) राजस्थान में कृषि-विकास । (Raj. II yr. TDC , 1989)
-

राजस्थान में भूमि-सुधार¹

(Land Reforms in Rajasthan)

राज्य में भूमि-व्यवस्था का परिचय

मार्च सन् 1949 में राजस्थान के निर्माण से पूर्व इसमें कई छोटे छोटे राज्य थे जिनमें शासकों ने भूमि विभिन्न व्यक्तियों को जैसे, जागीरदारों, जमींदारों व बिस्वेदारों को दे रखी थी जो वास्तवकारों से लगान वसूल करके उसका बहुत छोटा भाग राज्य को देते थे। राज्य के कुल 8 36 करोड़ एकड़ क्षेत्रफल में से लगभग 60 प्रतिशत भूमि ऐसे व्यक्तियों के पास थी और शेष 40 प्रतिशत खालसा भूमि के वास्तवकारों का राज्य से सीधा सम्बन्ध पाया जाता था। मध्यस्थ-वर्ग की विशाल सहाय के कारण वास्तवकारों की दशा बड़ी दयनीय हो गयी थी। वे वास्तवकारों से लगान व लाग-बाग के रूप में काफी मात्रा वसूल कर लेते थे।

डॉ० दूल्हन ने जागीर क्षेत्रों की कुछ लाग-भागों अथवा उपरों (Cesses) की सूची दी है। 29 तरह की लाग-भागों में से चार भूमि/पशु धन पर आधारित हैं, तीन स्वयंसेवक भूमिधारियों या जबरन श्रम से सम्बद्ध हैं तथा शेष बाईस सामाजिक शोषण पर आधारित हैं एवं इनमें इस तरह की लाग-भागें हैं जैसे 'म'ताजी की गैट', 'माईजी का हाथ खर्च' व ये जन्म से मृत्यु तथा स्वेच्छा व उत्तरव आदि सभी अवसरों को शामिल करती हैं जिसमें जागीरदार या स्वयं कृषक भाग लेते हैं।²

राजस्थान में भूमि-सुधार का कार्य मध्यस्थों की शक्ति व प्रभाव विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में प्रचलित भूमि-व्यवस्थाओं, रेवेन्यू प्रशासन की कुशल या एव-सी व्यवस्था के अभाव एवं विश्वस्त भूमि रिवाजों के अभाव के कारण और भी पचीस

- 1 Report of the National Commission on Agriculture, 1976, pp 97-98, pp 129-130, pp 141-142.
2. Quoted in Vidya Sagar & Kanta Ahuja Rural Transformation in a Developing Economy, 1986

हो गया था। इन सब कठिनाइयों के बादजूद यहाँ पर भूमि-सुधार का कार्य काफी सफलतापूर्वक किया गया है। इस विषय में जो कानून बनाये गये हैं, वे सुदृढ़ हैं और उनमें काफी मूझ-बूझ से काम लिया गया है। लेकिन भूमि-सुधारों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण काम घीमा रहा है और क्रियान्वयन की दिक्कतें व कमियाँ महसूस की गई हैं।

राजस्थान राज्य के खन जाने के बाद नये राज्य के समस्त दो समस्याएँ थीं। एक तो मध्यस्थों को हटाना और दूसरा काश्तकारी कानून में समानता लाना जिससे काश्तकारों के हितों की रक्षा हो सके। दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए (The Rajasthan Protection of Tenants Ordinance 1949 जारी किया गया। जिसमें काश्तकारों की बेदखली से रक्षा की गयी। 1951 में सरकार ने (Rajasthan Produce Rents Regulating Act जारी किया गया जिसमें मध्यस्थों के द्वारा काश्तकारों से ली जाने वाली राशि कुल उपज की जगहा के ज्यादा $\frac{1}{4}$ रखी गयी। ऐसे ही उद्देश्यों के लिए Agricultural Rents Control Act 1952 पास किया गया जो बाद में रद्द करना पड़ा। लेकिन इसकी धाराएँ Rajasthan Agricultural Rent Control Act, 1954 में शामिल कर ली गयी। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मध्यस्थ-वर्ग मासगुजारी के दगुने से ज्यादा सगान वसूल नहीं कर सकेगा। बाद में राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 (Rajasthan Tenancy Act, 1955) बनाया गया जो एक व्यापक कानून है। इसमें काश्तकारों की विभिन्न श्रेणियाँ रखी गयी हैं। इसमें काश्तकारों को अधिकार देने, जोतों के हस्तांतरण व क्रय-विक्रय, लगान को निश्चित करने और इसको वसूल करने के ढग को निर्धारित करने की व्यवस्था की गयी है। इनमें उन दशाघो को बतलाया गया है जिनमें काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है और अगरो को निपटाने के लिए अनातों की स्थापना की गयी है। बाद में इसकी कई धाराओं में संशोधन किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 के अनुसार सगान की राशि मास-गुजारी या न-राजन्व के $1\frac{1}{2}$ गुने से 3 गुने तक निर्धारित की गई (जहाँ लगान नकद दिया जाना था)। यदि भूमि की खुदकाशत के लिए आवश्यकता हो तो काश्तकार को बेदखल किया जा सकता था, बशर्ते कि काश्तकार के पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि हो। गैर-पुनर्ग्रहण वाले क्षेत्रों (non-resumable areas) में काश्तकारों व उप-काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार या सातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। भू-स्वामा को दिया जाने वाला मुदाबजा लिखित भूमि के लगान का 20 गुना तथा अनिश्चित-भूमि का 15 गुना निश्चित किया गया।

राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की कई धाराओं में संशोधन के लिए राजस्थान काश्तकारी बिल 1972 में पज किया गया था जिस कई वर्षों बाद पास किया गया।

जागीरदार एक मध्यम होता था जो कानूनकार से कुछ उपज का एक बड़ा भाग लेता था और बेगार' व 'लाग-बाग' ऊपर से लिया करता था। जागीर क्षेत्रों में बेदखली का दोनवाला था। जागीरदार नूमि का अग्र-विक्रय तो नहीं कर सकते थे, लेकिन सोदानी और फौजदारी अधिकारों व प्रभुत्व के कारण ये प्रजा पर काफ़ी अत्याचार करते थे। इनके द्वारा ली जाने वाली कई प्रकार की लाग-बागों का मकत धंधा के प्रारम्भ में दिया जा चुका है।

राज्य विधान सभा ने राजस्थान नूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (The Rajasthan Land Reform and Resumption of Jagir Act, 1951) पारित कर दिया। कुछ जागीरदारों ने 'स्टे आर्डर' लाकर लगभग दो वर्ष तक इसे लागू होने से रोक दिया। तत्पश्चात् स्वर्गीय श्री नरहरी और स्वर्गीय श्री पन्त के प्रयत्नों से फैसला किया गया और जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के लिए इसे निष्पत्ति की गयी। मुआवजा प्राधार वर्ष की विगुड आय (net income) का सात गुना रखा गया। यह 2½ प्रतिशत वार्षिक व्याज पर 15 समान किश्तों में चुकाना निश्चित किया गया। जिन जागीरदारों की कुल आय 5,000 रुपये से अधिक नहीं थी, उनका विगुड आय के पाँच से सवारह गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया। अन्य जागीरदारों को विगुड आय के दोगुने से चार गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया।

धार्मिक जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से आरम्भ हुआ। 1 नवम्बर, 1959 में 5000 रुपये से ऊपर की आय वाली ऐसी जागीरों और 1 अगस्त, 1960 से 1000 रुपये से ऊपर की आय की जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया। 1 जुलाई 1963 में निम्नतम श्रेणी की जागीरों का भी पुनर्ग्रहण किया जा चुका है। अतः अब धार्मिक व गैर-धार्मिक सभी जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। पुनर्ग्रहण की प्रयत्न लगभग 1971 तक लगभग 51.3 करोड़ इ. आकी गयी थी। इनमें मुआवजा व पुनर्वास अनुदान, इन पर व्याज, स्थायी वार्षिक जागीर स्थापन व पेंशन शामिल है। इनके अतिरिक्त भी राज्य को कुछ व्यय करना होगा।

2 जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा का अन्त—राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी अन्ततन अधिनियम 1 नवम्बर 1959 से लागू किया गया। यह प्रथा राजस्थान के लगभग 5,000 गाँवों में, तथा 10 जिलों (नरतपुर, पालपुर, पालपुर, गगानगर, जयपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर, कोटा व सीकर) में फैली हुई थी। गगानगर जिले की कुछ विशेष समस्याएँ थीं। जमींदार व बिस्वेदार भी काश्तकारों से मनमना लगान लेते थे, वे उन्हें बेदखल कर देते थे और उनका अधिक शोषण करते थे। इस प्रथा के समाप्त होने में कानूनकार का सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया है।

The Rajasthan Land Reform and Acquisition of Land Ovaer's Estates Act, 1963 के अन्तर्गत राजस्थान में विहीन होने वाले राज्यों के शासकों की सम्पत्ति सन की व्यवस्था भी कर दी गई। इस प्रकार राजस्थान में मध्यस्थ वर्ग को पूर्णतया सम्पन्न कर दिया गया।

राजस्थान में भूमि सुधारों का प्रभाव

हम नीचे राजस्थान में भूमि सुधारों व काररकारी कानून के प्रभावों का विवरण देते हैं।

भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों ने कृषिकार की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न किये हैं। लेकिन कानूनों को लागू करने में गम्भीर कमियाँ भी रह गयी हैं। राजस्थान में कृषिकारों को खातेदारी अधिकार मिलने से वे भूमि के मालिक जैसे हो गये हैं। जागीरदारों ने खुदकास्त के अन्तर्गत कुछ भूमि रख ली, लेकिन उसकी मात्रा पहले के बल जागीर क्षेत्र की मात्रा की तुलना में थोड़ी पायी गई है।

जागीरदारों ने बिज्ञा, उपहार प्रयत्न आदि में काफी भूमि का हस्तान्तरण किया है। ऐसा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के लागू होने से पूर्व किया गया है।

जागीरों के समाप्त करने से जागीरदारों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। मध्यम और उच्च के ठिकाने तो अल्पसंख्यक थे। उनके ठिकानेदार कोई भी उपघोषी काम करना अपनी प्रतिष्ठा के लिये तैयार नहीं थे। इससे उनका मानसिक व नैतिक पतन हो गया था। अधिकांश जागीरदार अब तेजी में लग गये हैं। इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

राजस्थान कृषिकारों का कानून, 1955 के लागू होने के समय 10 प्रतिशत कृषिकारों को खातेदारी अधिकारों के समान अधिकार प्राप्त थे लेकिन अब सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। यह स्थिति बहुत सन्तोषप्रद है। राज्य में गैर खातेदार कृषिकारों की संख्या अधिक नहीं है।

उप-कृषिकारों (Sub tenants) के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रमुख कृषिकार (tenant in chief) इनसे नौकरनामा लिखाकर कृषि करवाते हैं और इनका ओपण करते हैं। इस प्रकार उप-कृषिकार प्रमुख कृषिकारों की दया पर आश्रित हैं। प्रमुख कृषिकार इनमें उर्ज के रूप में अर्द्धांश खपान लेते हैं और उन्हें बाँटने जब वेदखस कर देते हैं। फसल-बटाई (crop-sharing) अनुचित रूप में प्रचलित है। इस प्रकार अब प्रमुख कृषिकार उन ओपण के तरीकों का उपयोग उप-कृषिकारों पर करने लग गये हैं जिनका उपयोग पहले स्वयं भू-स्वामी उन पर किया करते थे। यह एक निराशाजनक स्थिति है। इसका समुचित खयाल होना चाहिए, सभी भूमि को जोड़ने वाला सच्चा भू-स्वामी हो सकेगा।

श्री अमीर राव, तत्कालीन सयुक्त सचिव, योजना आयोग ने राजस्थान में भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मध्यस्थों की समाप्ति व सम्बन्धित कार्यों, जैसे मुदनाशत के धावटन के लिए धावेदन-पत्रों का अन्तिम

निवटारा, दावो (Claims) को तैयार करना, मुद्दावजे के लिए दावे को अंतिम रूप देने एवं मुद्दावजा व पुनर्वास-अनुदान चुकाने के सम्बन्ध में बड़ी धीमी प्रगति रही है। इस बात की विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है कि जागीरदारों व मध्यस्थों के पास खुदकाशन में कितनी भूमि है, कितनी भूमि पर कास्तकारों ने खातेदारी भविष्यकार ग्रहण किये हैं और कितने शेष किसम की है।¹

सरकारी स्पष्टीकरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उपकास्तकारी व फसल बटाई को रोकना सदैव सम्भव नहीं है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में भूस्वामी स्वयं बीमारी व अन्य कारणों से भूमि को जोतने की स्थिति में नहीं होता है और कमी-कमी दूसरों से बेल की जोड़ी अथवा अन्य माधन लेने के लिए साभेदारी स्वीकार करनी होती है। अतः आवश्यक दशाओं में इन्हें कृपिगत उत्पादन के हित में स्वीकार करने का समर्थन दिया गया है।

दैनिक न्यूनतम मजदूरी—राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर पुनः निर्धारित की गई है। 1 मार्च 1987 से अशुशल (unskilled) श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर 14 रु, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 15.5 रु व कुशल श्रमिकों के लिए 17 रु कर दी गई है।

राजस्थान में सीलिंग कानून की काफी अवहेलना की गई है। जब 3 नवम्बर 1969 को अनूपगढ़ में भूमि की नीलामी चालू हुई तो किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। सरकार नीलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी लेकिन इससे भूमि हीनो को भूमि नहीं मिल सकती थी। इस स्थिति में राजनीतिक दलों ने सभ्य चालू कर दिया था। बाद में सरकार ने जहरी क्षेत्र में नीलामी बंद कर दी और भूमिहीनों को निश्चित भावों पर भूमि देने का निर्णय किया। 3 एकड़ में नीचे की भूमि पर खुदाहली-कर (betterment levy) समाप्त कर दिया गया, बपास पर उपकर नहीं लिया गया और भूराजस्व की वृद्धि नहीं की गयी।

निष्कर्ष—यह दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान में सीलिंग कानून बड़ाई से लागू नहीं किया गया जिससे अतिरिक्त (Surplus) भूमि कम मात्रा में ही मिल पायी। सरकार भूमि सुधारों को लागू करना चाहती है। लेकिन इनके मार्ग में आने वाली व्यावहारिक बाधनाइयों का जाल बिछ गया है। वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक व कानूनी ढाँचों के अंतर्गत भूमि का कोई विशेष पुनर्वितरण सम्भव नहीं प्रतीत होता। ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों का सुझाव है कि निधन स्रोतों की प्राथिक दशा सुधारन के लिए वैकल्पिक उपाय ढूँढ़े जाने व हिण जिससे उनको रोजगार मिले तथा आमदनी बढ़ाने का अवसर मिले। भूमि के पुनर्वितरण से इनकी समस्या का पूरा समाधान निकाल सकना सम्भव नहीं प्रतीत होता। राजस्थान में भूमि के

1 *Implementation of Land Reforms, Planning Commission, New Delhi, August 1966, pp 120-28.*

वितरण का जिनीगुणांक (gini-coefficient) 1953-54 में 0.69 था जो 1971-72 में 0.61 पर घा गया।* इस प्रकार भूमि के वितरण की असमानता में मामूली गिरावट आयी है। राज्य में खेतिहर श्रमिकों की संख्या 1961 में 22 लाख से बढ़कर 1981 में 48 लाख हो गयी है। 1961 व 1971 के बीच में तो इनकी संख्या दुगुनी से अधिक हो गयी थी। इस प्रकार राज्य में खेतिहर श्रमिकों की समस्या काफी बड़ी है।

भारत में भूमि सुधारों का उद्देश्य कमी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। इसके अन्तर्गत गांवों में शक्ति-सन्तुलन मिलन व भूमिहीनों के पक्ष में नहीं है। इसलिये बारम्बार भूमि सुधारों को लागू करने पर जोर देना का विशेष अर्थ नहीं निकलता। अतः निर्धन लोगों के कल्याण के लिए वैकल्पिक प्रयास करने जरूरी हैं। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार ने नियमित अथवा स्वराजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ बनयी हैं। इनमें कम्पोजिट लोन स्कीम, महिलाओं के लिए गृह उद्योग दम्पकारों के लिए रोजगार, शिक्षितों के लिए स्वरोजगार, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पंचेज कार्यक्रम, गहरी गरीब लोगों के लिए स्वराजगार के कार्यक्रम, आदि शामिल हैं।

प्रश्न

1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

(i) राजस्थान में भूमि-सुधार

(Raj II Year TDC, 1986 व 87)

(ii) आपके राज्य में भूमि-सुधार

(Raj II Year TDC, 1982)

- 2 राजस्थान सरकार ने 1948 के पश्चात् जो प्रमुख भूमि-सुधार किये हैं, उनकी विशेषताएँ संक्षेप में लिखिए और बतलाइए कि इनसे कृषक का अधिक दूर कितना उन्नत हुआ है ?

* जिनी-अनुपात या गुणांक के माप की विधि आय की असमानता में अध्ययन में विस्तार से समझायी गयी है।

राजस्थान में अकाल व सूखा (Famines and Droughts in Rajasthan)

राजस्थान के लिए अकाल व अनाह बहुत प्राण-पङ्काली जटिल हैं। यहाँ के ग्रामीण जीवन में इनका काफी दामन गं गहरा रहा है। राज्य के कई जिले प्रायः अकाल से प्रभावित होते रहते हैं। सरकार अकाल राज्य कार्य योजना है तथा लोगों की मूल-व्याप में करने नहीं देती। पशु-पक्षी के लिए भी यथामान्य पानी व चारा की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है। कभी-कभी अकाल अचानक रूप धारण कर लेता है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों की भारी प्रयास करना होता है। 1985-86 का अकाल काफी भयंकर था। इसमें पालपुर की डोडकर 27 म में 26 जिलों की अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसमें राज्य के 26859 गाँव लगभग 2 करोड़ 19 लाख जनसंख्या व तीन करोड़ में अधिक पशु प्रभावित हुए थे। 1986-87 की अवधि में राज्य के 27 जिलों की 194 तहसीलों में 31,942 गाँवों की 2.53 करोड़ जनसंख्या सूखे की गम्भीर स्थिति में प्रभावित हुयी थी। पुनः 1987-88 में सभी 27 जिले अकाल से प्रभावित हुए। इस वर्ष 36,252 गाँव व 3.17 करोड़ व्यक्ति अकाल से प्रभावित हुए। सरकार ने विभिन्न जिलों में अकाल-राहत कार्य चालू किये और चारे, पानी, अनाज, आदि की सहाई बढ़ाने का भरसक प्रयास किया।¹ इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या राजस्थान की अग्रव्यवस्था से गहरी जुड़ी हुई है जिससे इसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

अकाल के क्षेत्र/जिले

सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि राजस्थान में अकाल के कौन-से क्षेत्र प्रमुख हैं। ऐसे विभिन्न वर्षों में अकाल से प्रभावित होने वाले जिलों की संख्या अलग-अलग होती है, फिर भी राजस्थान का दक्षिणी भाग तो प्रायः अकाल की

घट म आता ही रहता है। अकाल के सम्बन्ध में निम्न दोहा मशहूर माना गया है। इसमें अकाल के प्रदर्शों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।¹

“पग पृगल, घट, कोटछे बाटु बाटमेर
जोय सादे जोयपुर, टावां जंसलमेर ॥”

इसका अर्थ यह है कि अकाल ने पंर पृगल (धीरानेर) में, घट कोटडा (धारव ड) में, मुजाएँ बाटमेर (मालानी) में स्थायी रूप में हैं। लेकिन उत्पादन करने पर यह जोयपुर में भी मिल जाता है एवं जंसलमेर में तो इसका खाम टिकता (ढावो) है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के निम्न 11 जिलों को महत्त्वपूर्ण माना है। इनमें राज्य के क्षेत्रफल का 60% तथा जनसंख्या का 40% भाग शामिल है। इन ग्यारह जिलों की लगभग दो लाख चौ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि में प्रायः अकाल एक घनकाई में हमान की तरह जमा बँठा रहता है। ये 11 जिले इस प्रकार हैं : जंसलमेर, बाँसगरे बीकानेर जोयपुर, गगनगर नागौर, बूड़, पाली, जालौर, सीकर व भुंभुन। इन जिलों की २५ भूमि अकाल जैसे दानव के बर्षों में जकड़ी हुई है। इन क्षेत्रों में सर्वा कम व घनिष्ठमान होती है। बहने जल व भूमि के नीचे जल की कमी होती है। पानी के साथ बनकर उठ जाने की रणरार तेज होती है। प्रौद्योगिक्य में प्रायः धूम्रमरी आपियाँ चलती हैं एवं बानु मिट्टी का हवा से बटाव होता रहता है। दुनिया के अन्य भागों में महत्त्वपूर्ण की तुलना में राजस्थान के महत्त्वपूर्ण में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है जिससे यहाँ पर अकाल की समस्या का प्रतिक जटिल होना स्वाभाविक है।

पिछले दो दशकों में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षतिः—

यह कहना सच न होगा कि राजस्थान में प्रतिवर्ष किसी-न-किसी अकाल व अभाव की स्थिति प्रकट पायी जाती है। यही नहीं बल्कि 1968-69 से 1987-88 तक के दो दशकों में से 7 वर्षों में 26 जिलों में एवं 2 वर्षों में 27 जिलों में अकाल की दशाएँ पायी गई हैं। 26 जिलों के अकाल वाले वर्ष इस प्रकार थे: 1968-69, 1972-73, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-86। 1986-87 व 1987-88 में सम्पूर्ण 27 जिलों में अकाल पड़ा है। अन्य वर्षों में भी स्थिति काफी गम्भीर रही है। 1974-75 में अकाल से 25 जिले, 1978-79 में 24 जिले तथा 1969-70 में 23 जिले प्रभावित हुए थे। इस प्रकार

- 1 मई द प्रहमद ला का लेख, मुकाबला कोई आताम नहीं, राजस्थान पत्रिका अकाल राहन परिशिष्ट, 24 अप्रैल, 1986, पृष्ठ 4
- 2 Budget Study 1989-90, DES, Rajasthan, Jaipur, p.64.

राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल की कार्ती छाया निरन्तर मडराती रहती है जिससे काफी जनसंख्या व पशुधन पर बुरा असर पड़ता है और सरकार को राहत कार्यों पर व्यय करना पड़ता है एवं भू-राजस्व की वसूली में भी बीज दनी पड़ती है। 1985-86 में 125 करोड़ रुपये के भू-राजस्व (land revenue) की वसूली रोकनी पड़ी थी।

पिछले वर्षों में पानी का अकाल विशेष रूप से पाया गया है। इससे जन-जीवन व पशुधन दोनों पर दुर्भाव पड़ा है। सरकार अनाज के अभाव को तो अधिक प्रामाणी से दूर कर सकती है लेकिन पानी का अभाव इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता।

अकाल सूखे व अभाव की समस्या के कारण

निरन्तर पड़ने वाले अकाल प्रकृति व पुरुष के बीच संघर्ष की दशा को सूचित करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते हैं लेकिन साथ में प्राधिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों को भी काफी सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इन पर नीचे प्रकाश डाला जाता है —

1 प्राकृतिक कारण—

(अ) घरातल की घनावट जलवायु बर्बरह—दूर दूर तक फैला मरुस्थल या मरु प्रदेश जहाँ भ्रोम ऋतु में तपती धरती तपता आसमान तपत इंसान व तपते पशु-सब नियति के जाल में फसे हैं जिससे छटकारा पाना कठिन है, क्योंकि 11 मरुस्थलीय जिलों में सर्वत्र बालू के टीले हैं तथा धरती के नाचे व इसकी सतह पर जल का निता त अभाव है। हम पहले बतला चुके हैं कि इन बर्बरह जिलों की दो लाख बी हज़ार वर्ग किलोमीटर भूमि इस मरुदानव के पंजों में जकड़ी हुई है।

इन क्षेत्रों में हवा से मिट्टी का कटाव निरन्तर होता रहता है जिससे रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे चल कर अन्य राज्यों की उपज ऊँ धरती को भी इससे खतरा हो सकता है।

(आ) वर्षा की कमी अनियमितता व अनिश्चितता—अकाल व सूखे की स्थिति का प्रधान कारण मानसून का विफल होना माना गया है। राजस्थान के उपर्युक्त 11 मरुस्थलीय जिलों में साल भर में मासान्यतया वर्षा पचास सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। जैसलमेर में औसतम 16 से भी वर्षा ही हो पाती है। पिछले 100 वर्षों में यहाँ केवल 25 वर्ष बारिश हुई जिससे इस इलाके में वर्षा के अभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः आवश्यकता के अनुसार वर्षा का न होना, कभी-कभी वर्षा का बिलकुल न होना तथा कभी देर से होना, ये सब अकाल व सूखे की स्थितियों को बन्म देते हैं। अभाव की ये स्थितियाँ कभी-कभी नियन्त्रण से बाहर हान लाती हैं। तब लाख-लाख जन मवेशियों को लम्बर निकटवर्ती राज्यों में चारे

व पानी की तलाश से पलायन करने लगते हैं। इससे पशु-धन की हानि भी होती है। कभी-कभी निकटवर्ती राज्यों में भी अभाव व सूखे के कारण उनमें पशुओं के प्रवेश से कोई लाभ नहीं होती, बल्कि पड़ोसी राज्य इसका विरोध भी करते हैं।

2 **आर्थिक कारण**—आर्थिक विकास के अभाव से भी अकास व सूखे की समस्या अधिक जटिल होनी गयी है। मरुप्रदेश व मरु जैसे प्रदेशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। जनसंख्या के बढ़ने से आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ा है। लोगों के लिए रोटी-रोजी की समस्या काफी गम्भीर हो गयी है। परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ है तथा सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि को उन्नत करने में बाधा पहुँचती है। बाबू मिट्टी अनुपजाऊ होती है। जोधपुर की सैंट्रल एरिड जोन ग्लिस चरटोड्यूट (बाबरी) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार खारे का कमी का कारण बढ़ती हुई पशु-मरणा है। 1972-77 की अवधि में पशुओं की संख्या 44.5 लाख बढ़ी है जिसमें प्रति पशु चराई की भूमि घट गई है। जनसंख्या का दबाव बढ़ने से अधिक मृमि पर खेतों की जाने लगी है जिससे सन्तुलित विकास में बाधा पहुँचती है। पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं उगाया जाता। चारा के अभाव में इसके दाम बढ़ जाते हैं जिससे दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में कृषिगत उत्पादकता नीची पायी जाती है जिससे कृषकों की आमदनी कम होती है। सहायक बन्धों के अभाव में आमदनी बढ़ा सकना भी मुमकिन नहीं होता। अतः बेरोज़गारी व अल्परोज़गार की समस्या भी काफी तीव्र हो गई है। लघु कृषकों व सीमान्त कृषकों भूमिहीन किसानों व ग्रामीण कारखानों के अर्थ का पूरा उपयोग नहीं हो पाता जिससे अकास के समय इनकी आर्थिक हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। सरकार राहत कार्य चलाकर इन लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करती है।

3 **सामाजिक कारण**—जलाने की संकटों के अभाव की समस्या काफी जटिल रूप धारण कर चुकी है। लोगों ने अब धूम्र पेड़ काट डाले हैं व अनियमित चराई से मिट्टी के कटाव की समस्या को तानावर दिया है। वृक्ष भूमि, वन, जल आदि का परस्पर सन्तुलन बिगड़ जाने से परिवेश असन्तुलन (ecological imbalance) की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए उचित उल्लेख व भूमि प्रबंध की आवश्यकता है।

4 **राजनीतिक कारण**—अकास व सूखे की समस्या का सम्बन्ध राजनीतिक कारणों से भी माना गया है। विभिन्न योजनाओं की अवधि में सरकार ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यों की वजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया जिससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण तेजी से घटने नहीं बढ़ सका है।

फनस्वरूप राशन-कार्डों पर किया गया अथ दीर्घकालीन दृष्टि में प्रतिफल नहीं दे पाया है और प्रकाली को रोकने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित रही है। यदि प्रारम्भ में ही सुनियोजित तरीके से अकाल से लड़ने का प्रयास किया जाना तो इस अनचाहे मेहमान को अपने घर बापस भेजना सम्भव हो सकता था। लेकिन प्रशासनिक कमियों कारण यह जमर बँठा हुआ है और जाने का नाम नहीं लेता।

इस प्रकार अकाल व मृत की समस्या प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक कारणों की देन है। राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनों की कमी रही है जिससे वह राज्य को अकाल के दानव से मुक्त नहीं करा सकी है। फिर भी कई प्रकार के राशन कार्यक्रम चलाकर सरकार लोगों को अन्वेष्याम से मरने नहीं देनी और अकाल से जूझने के लिए मर्दव कृप-सकल्प रहनी है, जैसा कि निम्न विवरण में स्पष्ट हो जायगा।

राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या के हल के लिए सरकारी प्रयास विशेषतया 1985-86 1986-87 व 1987-88 की स्थिति के संदर्भ में

राजस्थान में अकाल की समस्या एक अन्तरकालीन समस्या नहीं है। बल्कि एक दीर्घकालीन समस्या है। अतः इस समस्या का स्थायी हल तो दीर्घकाल में ही सम्भव हो सकता है। फिर भी राज्य सरकार ने इसके हल के लिए भूतकाल में प्रयास किये हैं और वर्तमान में भी प्रयास जारी हैं। आगामी वर्षों में भी इस समस्या के समाधान के लिए निरन्तर प्रयास जारी रहन होंगे।

अकाल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में सरकार की मुख्य नीति राशन कार्य चालू करने की रही है। इसके लिए केन्द्र में वित्तीय महायना देन की माग की जाती है। वित्तीय साधनों के आधार पर भू संरक्षण, सडर-निर्माण, पाठशाला व औपशालय निर्माण, मिचार्ड के लिए वृक्षों के निर्माण तालाबों व अन्य मिचार्ड के साधनों के निर्माण व उनकी मरम्मत तथा रक्षारख जल की सप्लाई बढ़ाने (ताकि लोगों का पेय जल उपलब्ध किया जा सके तथा पशुओं की भी पीने का पानी मिल सके) एवं चारे की उपलब्धि बढ़ाने जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि लोगों को रोजगार व आमदनी मिल सके एवं उत्पादक सामुदायिक परि-सम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके।

राज्य सरकार ने अकाल की समस्या के हल के लिए निम्न दिशाओं में प्रयास किए हैं। राज्य में विभिन्न योजना संगठन की स्थापना 1971 में की गई थी। इसकी तरफ से विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मूंगा समूह (गम्माजित) क्षेत्रीय कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम आदि

और इसने 27 मे से 26 जिलों को प्रभावित किया था। इससे राज्य की 2 करोड़ 19 लाख जनसंख्या व 3 करोड़ से अधिक पशु प्रभावित हुए थे। अकाल के समय पीने के पानी, पशुओं के लिए चारे व मनुष्यों के लिए अन्न का अभाव उत्पन्न हो जाता है।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 1985 से 15 जुलाई 1985 तक विभिन्न प्रकार के अकाल राहत कार्य संचालित किये थे जिससे लोगों के लिए रोजगार व आमदनी की व्यवस्था की जा सकी है तथा कई स्थानों में टैंकरो बैलगाड़ियों, जूटगाड़ियों, आदि की सहायता से पीने का पानी पहुँचाया गया था। एवं पशुओं के लिए चारे व पानी की सुविधा बढ़ायी गयी थी। जैसलमेर जिले ने दिसम्बर 1985 से मार्च 1986 तक के चार महीनों में 1 1/2 लाख बिबटल घास कटवा कर सूखा ग्रस्त जिलों को भेजी गयी थी और इससे राज्य सरकार को करीब 2 करोड़ रु की नकद धारा हुई थी। जैसलमेर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 125 किलोमीटर लम्बी व 25-30 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी पर 'सेवरण' घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है। यह 45 डिग्री सेल्सियस तक व तापमान में उग व पनप सकती है। इस पट्टी पर 50 से 80 लाख बिबटल घास रहती है। यह पशुओं के लिए पोषिक आहार होती है। सरकार को जैसलमेर के इस घास के खजाने का विस्तार करना चाहिए। मई 1986 में 7 लाख 63 हजार अधिकारी को अकाल-राहत कार्यों में रोजगार मिल सका था।

1985-86 में अकाल-राहत कार्यों की दो विशेषताएँ रही : (1) मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में किया गया तथा भारत सरकार से जो सहायता मिली उसे सामग्री के अंश के रूप में व्यय किया गया। भारत सरकार ने 35.81 करोड़ रु. अकाल राहत सहायता के बगैर उपलब्ध किये जिसमें 22.50 करोड़ रु. का अनाज नि:शुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी शामिल थी। इससे लोगों को रोजगार दे पाना सम्भव हो सका है।

(2) दूसरी विशेषता यह थी कि स्थायी महत्व एवं उत्पादक किस्म के कार्यों को प्राथमिकता दी गई ताकि सिंचनी, भू संरक्षण, वन एवं सड़क निर्माण के कार्यों का भली-भाँति विस्तार किया जा सके।

मार्च, 1986 तक विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए 125 करोड़ रुपये के राहत कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी। इसमें सर्वाधिक राशि (65 करोड़ रुपये) सिंचनी कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान था। दूसरा स्थान सड़क

निर्माण कार्यों को किया गया। उनके बाद भू-सुरक्षण, बनों के विस्तार व विरासत घाटि का स्थान आता है।

स्मरण रहे कि अधिकांश राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) के अन्तर्गत किये गये। रोजगार देने में भूमिहीन श्रमिकों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई थी।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी व्यापक निर्माण कार्यक्रम हाथ में लिये गए थे। इसके लिए उनकी विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा व जन-जाति विकास, घाटि से एवं भूमिहीन श्रमिक रोजगार यादवी याचना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई थी ताकि पाठशाला-भवनों आदि का निर्माण कराया जा सके। अन्य कार्य पट्टदार घर पंचायत घर ग्रोपवालय भवन, पंचायत की दफ्तरे, पंचजल कुओं का निर्माण, कुओं को गहरा कराने, सरासरी नाली एवं सड़क सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा तालाब की मरम्मत व गहरा कराने आदि के कार्य सम्मिलित हैं।

ये कार्य सामान्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व अकाल राहत कार्य के अतिरिक्त थे।

1986-87 के भीषण अकाल से सम्बंधित राहत-कार्य¹

1986-87 के भीषण-अकाल का दुष्प्रभाव 31922 गाँवों 2 53 करोड़ लोगों व 3 27 करोड़ एकड़ों पर पड़ा था।

अकाल राहत कार्य निम्न विभागों द्वारा चलाये गये थे :

(i) राहत विभाग, (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत, (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग, (iv) सिचाई विभाग, (v) वन-विभाग, (vi) पंचायत समितियों के माध्यम से।

राहत कार्यों में कुओं के निर्माण, भवन-निर्माण, सिचाई के कार्य, सड़क-निर्माण, भू-सुरक्षण, आदि शामिल थे। जून 1987 में 14 73 लाख लोगों को राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने राजस्थान को राहत सहायता के बगैर 2 लाख टन गेहूँ आवंटित किया था।

अगस्त 1987 में राज्य सरकार ने अकाल से निपटने के लिए निम्न उपाय घोषित किये थे:—

1 राहत कार्यों पर त-हाल मजदूरी की दर 7 ल. ख. बढ़ाने की घोषणा की गई।

1 राजस्थान पत्रिका, 10 जून, 1987, पृ 1.

2 राजस्थान पत्रिका, 20 अगस्त 1987

2 अतिरिक्त क्षेत्रों में लगान व सहकारी बजों की वसूलियाँ तुरन्त स्थगित करने का फैसला लिया गया।

जिन गाँवों में लगातार चार साल से अनाज पट रहा था वहाँ एक साल का लगान माफ करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। अत्याधिक सहकारी बजों को मध्याह्निक बजों में परिवर्तित किया गया।

3 राठी, धारपारवर, वाकरेज आदि उन्नत नस्ल की मायो को बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया। इसके अनुसार ऐसी मायो को विशेष रूप से गगानगर के कैंपो में रखा गया जहाँ उन्हें चारा पानी दवाइयाँ आदि उपलब्ध हो और साथ में उनका दूध बिक सके। स्वयं सेवी समूहों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया। इन्होंने चारे का वितरण करने में मदद की। चारे के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी प्रदान की।

4 एक सी ट्यूब-वैल जो उस समय उपयोग में नहीं आ रहे थे उनका विद्युतीकरण करके चारा उगाने का काम करने का निर्णय लिया गया।

5 सूरतगढ़ व जैतसर कृषि कामों में चारा उगाय की व्यवस्था की गयी।

6 पीने के पानी के लिए जयपुर जोधपुर उदयपुर, आबू, पाली, राजसमन्द भरतपुर, भजमेर ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरों में हैण्ड पम्प व ट्यूब वैल खुदवाने का काम प्रारम्भ किया गया।

7 सार्वजनिक वितरण की दूकानों की संख्या बढ़ायी गयी। आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमणशील दूकानें खोली गईं।

8 पंजाब व हरियाणा से चारा खरीदने की व्यवस्था की गई।

9 अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा पहुँचाने के लिए केंद्र जो अनुदान देता है उसे 30 रु प्रति किंटल से बढ़ कर माछे का वास्तविक खर्च वहन करने की सिफारिश की गई। सरकार ने एक बृहद् आपात योजना को लागू करने का निश्चय किया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अकास की समस्या राज्य सरकार के समक्ष एक महान चुनौती है। सरकार ने राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रमुख कठिनाई वित्त के अभाव की रही है। सरकार केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है ताकि सूखे पर काबू पाया जा सके। 1984-86 में गुजरात व मध्य प्रदेश में भी सूखा पड़ने के कारण राजस्थान से पशुओं का निष्क्रमण वहाँ नहीं हो पाया था और दो लाख से अधिक पशुओं को जैसलमेर के चारागृहों में भेजा गया था और उनका लिए वहाँ पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की गयी थी। दधारू पशुओं को पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी तथा गाँवों में पेयजल की व्यवस्था बढ़ायी गयी थी। 1986-87 के अनाज का मुकाबला करने के लिए सरकार को पुनः सक्रिय होना पड़ा था और विभिन्न राहत कार्यों पर निर्माण-कार्य चलाये गये थे। ये राहत

कार्य उन 1987 के बाद भी वृद्ध अवधि तक जारी रखने पड़े थे। राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत कार्यों के लिए सहायता मांगी थी।

1987-88 के अकाल में राहत-कार्य¹—

जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1987-88 में 27 जिलों को प्रतापदन्त घोषित किया गया। इसमें 36252 गाँव प्रभावित हुए जिनमें 3.17 करोड़ जन-संख्या प्रभाव की कपेट में आ गई। इनकी विधाल जनसंख्या की जीविस्पोषण के माध्यम उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य था। इस अकाल में 3 लाख राहत कार्य प्रारम्भ कर कुल 42.4 करोड़ मानव-दिवस का कार्य सञ्चित किया गया। सूना-प्रवाह पर 1987-88 में 599 करोड़ रु व्यय हुए तथा वर्ष 1988-89 में लगभग 361 करोड़ रुपये व्यय हुए जिनमें गैर² का मूल्य भी शामिल है। राज्य ने केन्द्रीय सहायता के अनिवारित स्वयं के माध्यमों में करोड़ों रुपये व्यय किये। सूना-प्रवाह पर इन 16 महीनों में (1987-88 व बाद में) जो राशि व्यय की गई वह गन चार दशकों में अकाल राहत सहायता पर व्यय की गई कुल राशि से भी बहुत अधिक रही है।

निष्कर्ष—राजस्थान पर प्रायः अकाल के काले बादल छाये रहते हैं। विद्वानों का मत है कि राज्य को अकाल से पूर्णतया छुटकारा मिलना तो कठिन जान पड़ता है लेकिन सतत प्रयास करने पर अकालों की संभावना व इनमें होने वाली क्षति में कमी अवश्य की जा सकती है और की जानी चाहिए। इसके लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की अत्यंत दृष्टि से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए जैसे नहर के दूसरे छरण के संशोधित रूप को पूरा करना, समाप्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना तथा रुक पाय पूरे करना ताकि उनके लाभ प्राप्त आदमों तक शीघ्र पहुँच सकें। इसके लिए प्रशासन को सुदृढ़ करना होगा।

2. योजना में शामिल विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, सामान्य राष्ट्रीय धर्म या राजस्व कार्यक्रमों, अकाल राहत कार्यक्रमों, पचासवें के विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में परस्पर प्रभावपूर्ण तात्कालिक स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक सामुदायिक परिस्थितियों के निर्माण में तेजी लार्गी जा सके।

3. सुनी नदी के क्षेत्र (बेमाल) का भी विकास किया जाना चाहिए। यह मरु-प्रदेश की मुख्य नदी है तथा अच्छी खादी में गिरती है। यदि सिंचाई, वृक्षा-रोपण, मू-मरसाए व गाँवों में सड़क व भवन निर्माण के कार्यों को द्रुत बनाया जा सके तो राजस्थान में ग्रामीण जनता की खुशहाली दृढ़ सकती है। इस समय का सदा

1. दूर-मापन 1989-90, पृ. 4¹

है जब जिला व खण्ड स्तर पर विकास के विभिन्न स्पष्ट, व्यावहारिक व लाभकारी कार्यक्रम संचालित करके हम विभिन्न प्रदेशों की अर्थव्यवस्थाओं को अकाल मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक ग्रामोण जनसहयोग की शर्त भी स्वीकार करनी होगी।

4 अकाल राहत केन्द्रों में मजदूरों की उपस्थिति के 'मास्टर रोल' ठीक से बनाये जाने चाहिए। उनमें मनमाने नाम भर कर रकम हड़ाने से समाज को लाभ नहीं हो सकता। अकाल राहत कार्यों में स्कूल, डिस्पेंसरी सड़क आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। राहत केन्द्रों की व्यवस्था में सुधार करने से लोगों की रोटी-रोजी की समस्या एक साथ हल हो सकती है। इसलिए अकाल राहत कार्यों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ायी जानी चाहिए। इनके सम्बन्ध में आये दिन विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं व कमियों के समाचार मिलते रहते हैं जिससे प्रभावित लोगों को पूरी राहत नहीं मिल पाती। अकाल राहत-कार्यों पर व्यय दूरके लोगों को रोजगार देने, पशुधन को बचाने वारा उपलब्ध कराने योग्य पट्टे व ने, कुपोषण व बीमारियों से बचाने तथा कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान दिया जाता है। अतः इस धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करके अकालग्रस्त क्षेत्रों को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया जाना चाहिए।

प्रश्न

1. "राजस्थान में अकाल - समस्या व समाधान" पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
2. क्या राजस्थान को अकालों की काली छाया से कभी मुक्ति मिल पायेगी ?
3. राजस्थान में अकाल-समस्या के निवारण हेतु कोई स्थाई कार्यक्रम सुझाइए।

विकास से स्पष्ट होता है कि 1984-85 में भी राजस्थान का भारत की औद्योगिक घटपटवस्था में काफी नीचा स्थान था। इस वर्ष सनस्त भारत में पंजीकृत फैक्ट्रियों का 2.8% राजस्थान में था, जबकि महाराष्ट्र में 15.7% था। फैक्ट्री रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का घाटा 2.8% था, जबकि महाराष्ट्र का 16.0% था। विनिर्माण के द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य (net value added) में राजस्थान का घाटा 2.6% था जबकि महाराष्ट्र का 22.8% था। इन प्रकार जोड़े गये शुद्ध मूल्य में भारत में जहाँ महाराष्ट्र का घाटा 1.9 से भी अधिक था वहीं राजस्थान का केवल 1/40 ही था। फैक्ट्री क्षेत्र में जोड़ा गया मूल्य राजस्थान में 1960-61 में सनस्त भारत का 1% था जो 1970-71 में 2.1, तथा 1984-85 में 2.6% हो गया। इस तरह राजस्थान का स्थान औद्योगिक दृष्टि से काफी नीचे घाटा है लेकिन जोड़े गए मूल्य में इसकी स्थिति घटत हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व उड़ीसा से बेहतर मानी गयी है।

राज्य में 1951 में 103 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थी जिनमें लगभग 18 हजार व्यक्ति काम पाते हुए थे और केवल 9 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। 1984-85 में रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या 2701 विनियोजित पूँजी की राशि लगभग 3092 करोड़ रुपये, अधिकारी की संख्या 1.72 लाख तथा विनिर्माण द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य (net value added) की राशि 550 करोड़ रुपये रही थी। 1987-88 में स्थिर कीमतों (1970-71) पर राज्य की आय का 10.8% अंश खनन व विनिर्माण (पंजीकृत व गैर-पंजीकृत) से प्राप्त हुआ था। इसमें खनन का घाटा 2.4% तथा विनिर्माण (manufacturing) का घाटा 8.45% था। इस वर्ष राज्य की आय स्थिर कीमतों पर लगभग 2383 करोड़ रुपये हुई थी तथा खनन व विनिर्माण से लगभग 259 करोड़ रुपये हुई थी।¹ राजस्थान में तपु इकाइयों में ज्यादातर, प्रति तपु इकाइयाँ (सबसे व मनीनरी में 25 हजार रुपये तक का विनियोग) पायी गई हैं। घावी से अधिक इकाइयाँ धातु पदार्थों, खनन की वस्तुओं व अनादिक सनिज पदार्थों के निर्माण में लगी हुई है।

सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगीकरण के लिए विद्युत-सूत्र पर काफी बल दिया है। नाखडा व अम्बन परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। घर्षण व डीजल विद्युत सत्रों की भी स्थापना की गयी है। राज्य में धातु-शक्ति का भी विकास किया गया है। प्रधान योजना के प्रारम्भ में शक्ति की उपस्थिति केवल 11 मेगावाट थी जो 1989 के मध्य में 2500 मेगावाट (प्रस्तावित अंश) हो गई है। इस प्रकार पानी की व्यवस्था का भी कई नगरी व गाँवों में विस्तार किया गया है। सड़कों का निर्माण किया गया है और उद्यम-वर्तियों को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं जिनका सम्बन्ध भूमि के भावटन, विद्युत

की दरो, बिजली-बंद व चुराई एव वित्तीय सहायता व पूँजी-सन्निधि आदि से रहा है। इन रियायतों के फलस्वरूप राज्य में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफी बढ़ी है। 1987 में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 9665 हो गई थी जिनमें कुल रोजगार 2.25 लाख व्यक्तियों को मिला हुआ था।

1980 में राज्य में 20 सूती व सिन्थेटिक रेशे की इकाइयाँ, 10 ऊनी, 3 चीनी, 5 सीमेंट, 3 मिनी सीमेंट की इकाइयाँ, एक टेक्सटाइल फ़ैक्ट्री, एक टायर व ट्यूब फ़ैक्ट्री, 9 वनस्पति तेल की मिलें, 20 इंजीनियरी की औद्योगिक इकाइयाँ तथा 5 खनिज-आधारित बड़ी व मध्यम थ्रेशो की इकाइयाँ हो गई थी। इनके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 7 औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं— हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., इन्स्ट्रु-मेन्टेशन लि., हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लि., मॉडर्न बैकरोज एव राज. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेण्ट्स लि.। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगों का लगभग 2% अंश पाया जाता है।

राजस्थान में इस समय लगभग 400 बड़े एव मध्यम दर्जे के उद्योग लगे हुए हैं। दिसम्बर 1988 के अन्त में उद्योग-विभाग में पंजीकृत सधु पैमाने के उद्योगों व कारीगरों की इकाइयों की संख्या 1.42 लाख थी जिनमें 668 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया था तथा 5.25 लाख व्यक्ति काम पाये हुए थे।¹

राजस्थान का औद्योगिक ढाँचा (Industrial Structure of Rajasthan)

औद्योगिक ढाँचे में उपयोग-आधारित वर्गीकरण (use-based Classification) के अनुसार निम्न चार प्रकार के उद्योगों का संक्षेप महत्व देखा जाता है।

- (1) आधारभूत वस्तुओं के उद्योग (Basic Goods Industries)
- (2) पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग (Capital Goods Industries)
- (3) मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग (Intermediate Goods Industries)
- (4) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग (Consumer Goods Industries)

राजस्थान में इनमें से प्रत्येक की स्थिति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

(1) आधारभूत वस्तुओं के उद्योग—इस थ्रेशो में प्रमुख उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं— सीमेंट, बेसिक रसायन, लोहा व इस्पात, उर्वरक व कीटनाशक, तांबा पीतल अल्युमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह धातु, नमक एव विद्युत।

(1) सीमेंट—1988 में राज्य में सीमेंट की 9 बड़ी इकाइयाँ थीं। सीमेंट के कारखाने सवाई माधोपुर, लासेरी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, श्यावर व

कोटा में निजी क्षेत्र में तथा रीवा से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) (मंगलम सीमेंट लि.) तथा बनाव (सिरोही) (स्ट्रा प्रोडक्ट्स, जे. के. ग्रुप का) में चल रहे हैं। राज्य में सीमेंट के और कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं। राज्य में मिनी सीमेंट प्लांट भी लगाये गये हैं जिनसे सिरोही, बामवाड़ा व जयपुर जिलों में सीमेंट का उत्पादन होने लगा है।

(ii) रासायनिक उद्योग—इसमें मुख्यतया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना आता है। यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। डीडवाना में नमक का भी उत्पादन होता है। कोटा में श्रीराम केमिकल इन्डस्ट्रीज लि. भी इसी श्रेणी में आता है। उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी एल्कलाइज एण्ड केमिकल्स लि., अलवर भी आधारभूत उद्योगों की सूची में आते हैं।

घौलपुर में समुक्त क्षेत्र में रीको व IDL केमिकल्स लि., हृदराबाद के परस्पर सहायग से, दो राजस्थान अक्सप्लोजिभल एण्ड केमिकल्स लि., की स्थापना की गई है जहाँ विस्फोटक (detonators) बनाये जाते हैं। यहाँ मार्च 1981 में उत्पादन चालू किया गया था।

(iii) डूंगरपुर जिल में माँडो-कौ-पाल नामक स्थान पर पलासंपार बनेफिशियेशन प्लांट लगाया गया है जो पलासंपार उत्पन्न करता है। यह इस्पात बनाने में प्रयुक्त होता है।

(iv) राज्य में उदयपुर में जस्ता गलाने का समग्र (हिन्दुस्तान जिंक लि.) तथा खेतड़ी में तांबा गलाने का समग्र (हिन्दुस्तान कापर लि.) कार्यरत हैं। इस प्रकार राज्य में आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत सीमेंट, रसायन, उर्वरक तथा तांबा व जस्ता के कारखाने चल रहे हैं।

(2) पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग—पूँजीगत उद्योगों की सूची में औद्योगिक मशीनरी, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर, मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी, विद्युत बम्प्यूटर व पुर्जें, बैगन (रेल परिवहन का साज-सामान) वगैरह आते हैं। भरतपुर में सिस्को बैगन फैक्ट्री है। अजमेर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. (HMT Limited) तथा कोटा में इस्ट्रूगन्टेशन लि. है। जयपुर में नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लि. में बॉन वियरिंग एवं ग्रोको लीलेण्ड लि., अलवर में व्यापारिक वाहन बनाये जाते हैं तथा कुछ और इन्जीनियरिंग उद्योग भी हैं। इस प्रकार राजस्थान में पूँजीगत वस्तुओं व भी कारखाने हैं।

(3) मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग—इस श्रेणी के उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं : कॉटन जिनिंग, क्लीनिंग व वेल्डिंग, सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग, ऊन की सफाई, रंगाई व ब्लीचिंग, चमड़े की रंगाई व तैयारी, टायर-ट्यूब, पेंट, व वार्निश आदि। जयपुर में पानी व विजली के मीटर बनाये जाते हैं। उदयपुर के पास कांकरोली में जे. के. टायर्स का कारखाना चालू किया गया है जिसमें आर्टो-मोबाइल टायर व ट्यूब्स बनाये जाते हैं।

(4) उपनोक्ता वस्तुओं के उद्योग—राजस्थान में सूती वस्त्र, मिथेटिक वस्त्र चीनी गुग्गु वनस्पत धी व वनस्पति तेल, साबुन, क्रीकरी, टेलीविजन सेट्स, माइकिल के पुर्वे जूने (बनडे व खड के) स्कूटर्स व मोपेड (केल्विनेटर्स ग्रॉफे इडिया लि) ऊनी मान (वीकानेर, चूरु व लाहनु), बीडी (मयूर बीडी उद्योग, टाक) आदि उपनोक्ता वस्तुओं के उद्योग आते हैं।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सभी प्रकार के उत्पाद-आधारित उद्योग (use-based industries) की इकाया पाई जाती है, हालांकि राज्य का समस्त देश की औद्योगिक पर्याप्तता में आज भी नीचा स्थान है। योजनाकाल में इन विभिन्न ध्येयों के उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गये मूल्य आदि में बदला है जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

पंक्ती क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक ध्येयों का योगदान¹

उद्योगों की श्रेणी	रोजगार में भ्रज (प्रतिशत)		जोड़े गये मूल्य में भ्रज (प्रतिशत)	
	1970	1980-81	1970	1980-81
1. आधारभूत वस्तुओं के उद्योग	30.0	34.6	39.0	51.4
2. पूंजीगत " " "	21.5	14.3	18.1	15.5
3. मध्यवर्ती " " "	5.4	15.6	2.8	9.0
4. उपनोक्ता " " "	43.1	35.5	39.4	24.1
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0
कुल मात्रा	1.12 लाख	1.92 लाख	62.4 करोड़ रु.	370 करोड़ रु.

1 Industrial Structure of Rajasthan, 1970, and A.S.I. 1980-81 (Rajasthan) (DES) के प्रांकियों के आधार पर प्रतिशत निकाले गये हैं।

तातिका से पता चलता है कि 1980 से 1970-81 की अवधि में राजस्थान में आधारभूत उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गये मूल्य में बढ़ा है, पूँजीगत उद्योगों का पटा है, मध्यवर्ती उद्योगों का काफी बढ़ा है तथा उपभोक्ता-उद्योगों का पटा है। 1980-81 में आधारभूत उद्योगों का अंश जोड़े गये मूल्य में लगभग $\frac{1}{3}$ व उपभोक्ता-उद्योगों का $\frac{1}{4}$ पाया गया है। आधारभूत उद्योगों के योगदान में बढ़ने के पीछे मुख्य कारण विद्युत का इस श्रेणी में शामिल होना है।

उद्योगों का साधन-आधारित वर्गीकरण (Input-based Classification of Industries)—उद्योगों का अध्ययन इन्पुटों के आधार पर वर्गीकरण करने भी किया जा सकता है जैसे—कृषि-आधारित, वन-आधारित, पशुधन-आधारित, खनिज पदार्थ-आधारित व रसायन-आधारित आदि। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

1. कृषि-आधारित व फूड-प्रोसेसिंग उद्योग—व्यापक अर्थ में कृषि-आधारित उद्योगों में खाद्य-पदार्थ, दुग्ध-पदार्थ व मांस-पदार्थ शामिल किये जाते हैं लेकिन सखीएँ अर्थ में इस श्रेणी में कृषिगत वच्चे माल पर आधारित उद्योग आते हैं, जैसे फॉटन जिनिंग व प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ, सूती वषड़ा उद्योग, (कतारई व बुनाई) (खादी, हथकरघा, शक्तिनरघा व मिलनरघा), रेशम उद्योग तिलहन पर आधारित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग, साबुन उद्योग, गन्ने पर आधारित गुड़, खडसारी व चीनी, अचार-मुरब्बा, दाल मिल, देकरी व कॉ-फेक्सनरी उद्योग, आदि। इसी में गुपारी, चूर्ण, पाली की महदी व बासवाडा का आम-पापड़, बीकानेर के पापड़-मुजिया, जोधपुर-नागौर क्षेत्र की मेथी, झालावाड़ व गजानगर के रसदार फल, भायू-सिरोही क्षेत्र के टमाटर तथा पुष्कर के मुलाय के फूल, सन्जी व फल आदि आते हैं।

2. वन-आधारित उद्योग—इसमें लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, रमड, मोद, रात, सास आदि पर आधारित उद्योग आते हैं।

3. पशु-धन आधारित उद्योग—राजस्थान में पशु-धन आधारित उद्योगों में ऊन, दूध, दूध से बने पदार्थ, चमड़ा, खालें, हड्डियाँ व मांस आदि शामिल होते हैं।

4. खनिज-पदार्थ आधारित उद्योग—(अ) धातु-आधारित जैसे इस्पात उद्योग, मशीनरी, परिवहन का सामान (वैनन), धातु से बनी वस्तुएँ जैसे इस्पात का फर्नीचर, मोटर-साइकिल आदि।

(अ) अधातु खनिज उद्योग (non-metallic mineral industries)—इसमें पत्थर व मारबल से बनी वस्तुएँ, बाँच व बाँच का सामान, चायना बत्ते व सिरेमिक की इकाइयाँ, एस्बेस्ट्स, सीमेंट, सीमेंट पाइप आदि आते हैं।

राजस्थान में कृषि-आधारित, खनिज-आधारित, व पशु-आधारित उद्योगों का बड़ा महत्त्व है। इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं

का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। इस समय राज्य में 23 सूती वस्त्र मिलें हैं, तीन चीनी के बड़े कारखाने हैं तथा वेजिटेबल ऑयल व वनस्पति तेल की कई फैक्ट्रियां हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग¹ (Public Sector Industries in Rajasthan)

(अ) राजस्थान सरकार के औद्योगिक उपक्रम (Industrial Undertakings of Rajasthan Government)

राज्य सरकार के निम्न औद्योगिक उपक्रमों में उत्पादन किया जाता है—

(1) बी गगानगर शुगर मिल्स लि., श्री गगानगर—जनवरी 1957 में 'बीकानेर औद्योगिक निगम लि.' का नाम बदलकर 'बी गगानगर शुगर मिल्स लि.' रखा गया था। 1986-87 में इसकी अधिकृत पूँजी 2.5 करोड़ रु. थी जो 50 रु. प्रति शेयर के अनुसार 5 लाख शेयरों में विभक्त थी। इसमें परिसर्त पूँजी लगभग 2.23 करोड़ रु. थी।

कम्पनी वर्तमान में निम्न इकाइयों का संचालन कर रही है :

1. शुगर फैक्ट्री, श्री गगानगर, जहाँ गन्ने एवं चुकन्दर से चीनी का उत्पादन किया जाता है।

2. श्री गगानगर एंव अटारू में स्थित डिस्टिलरीज व राज्य के अन्य भागों में स्थित मदिरा गृह/डिस्टिलरीज में शोधित स्प्रिट (rectified spirit) का उत्पादन किया जाता है। मदिरा-गृहों से लाइसेंस-शुदा व्यापारियों का मदिरा सप्लाई की जाती है।

3. कोटा व उदयपुर डिवीजन के जनजाति क्षेत्र में देशी मदिरा की दुकानों का संचालन तथा,

4. हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर में काच का सामान, बोतलों व रेलवे जॉइंट बनाये जाते हैं।

इन चारों प्रकार की इकाइयों से कम्पनी का 1985-86 में कर से पूर्व लाभ 11.2 लाख रुपये व 1986-87 में 20.4 लाख रुपये प्राप्त हुए। 1985-86 में पानी की कमी, अकाल व पायरोला नामक कीड़े के कारण चीनी के उत्पादन को घटका लगा।

1 विस्तृत विवरण अगले अध्याय में दिया गया है। यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

स्रोत : Public Enterprises Profile, 1986-87, Bureau of Public Enterprises, State Enterprises Department, Government of Rajasthan, Jaipur, July, 1988

घोतपुर की हार्डिंक ग्लास फैक्ट्री को । जुलाई, 1986 से लीज पर चलाया जा रहा है । यह मंदिरा विमान के लिए बोतलों का उत्पादन करता है ।

(ii) राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना—इसके अन्तर्गत निम्न तीन इकाइयाँ आती हैं :

(क) सोडियम सल्फेट वर्क्स, (ख) सोडियम सल्फेट प्लान्ट, (ग) सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री ।

(क) सोडियम सल्फेट वर्क्स—नमक की ब्यारो में सर्दी के मौसम में सल्फेट भ्रतग होकर घीरे-घीरे परतों में जम जाता है 10-12 वर्षों में यह परत मोटी हो जाती है जिसे नूड सोडियम सल्फेट कहा जाता है । यह सल्फेट सल्फाइड उत्पादन के काम आता है जो विभागीय सल्फाइड इकाई में प्रयुक्त किया जाता है ।

(ख) सोडियम सल्फेट प्लान्ट—ब्राइन से सोडियम सल्फेट निकालकर शुद्ध नमक बनाने की योजना 1960 से शुरू की गई थी । सितम्बर 1981 से यह समय मैसर्स डीडवाना केमिकल्स प्राइवेट लि. को 31.9 लाख रु के वार्षिक लीज पर दिया गया । भव विवाद के कारण यह प्लान्ट बन्द पड़ा है ।

(ग) सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री—सोडियम सल्फाइड नूड सल्फेट व कोयले की रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है । यह 1966 में शुरू किया गया था । सोडियम सल्फाइड चमड़ा व रंगाई उद्योग में काम आता है । इसे पिछले वर्षों में घाटा उठाना पड़ा है ।

(iii) राजकीय सबल स्रोत, डीडवाना व पंचपदरा—डीडवाना का नमक स्रोत 1910 एकड़ में फैला है । वर्तमान में 400 ब्यारे पुरतनी देशवासियों द्वारा तथा 800 ब्यारे त्रिगांग द्वारा दिये गये 10 वर्ष के लीज पर कार्यरत हैं । स्रोत के दोनों तरफ बाघ लगाकर वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है । यह पानी रिसकर नमक उत्पादन क्षेत्र में आता है । इस पानी को ब्राइन कहा जाता है । डीडवाना के ब्राइन में नमक के अलावा सोडियम सल्फेट प्रचुर मात्रा में मिला हुआ होता है जिससे यहाँ बनने वाला नमक अधिकतर राने के काम नहीं आता ।

पंचपदरा स्रोत 32 वर्गमील में फैला है । यहाँ नमक के उत्पादन की क्षमता 6 लाख ट्विंटल सालाना है । नमक का उत्पादन पुरतनी खारवालों के द्वारा किया जाता है ।

(iv) स्टेट यूसन मिल्स, बीकानेर—1968 में बीकानेर में 1,200 तक्कए लगाकर एक ऊनी मिल स्थापित की गई थी जो गलीचे, बनियान, बन्दल तथा बुनाई का ऊनी घागा तैयार करती है ।

लगातार घाटे में चलने के कारण जून, 1976 में इसे मैसर्स जगन्नाथ जीवन मल वूलन मिल्स प्रा. लि. को 10 वर्ष के लिए 18.12 लाख रुपये वार्षिक लाइसेंस राशि पर पट्टे पर दिया गया था । लेकिन समय पर पट्टा राशि न मिलने के

कारण अप्रैल 1986 में न्यायालय से आदेश प्राप्त करके इस सरकार ने पुनः अपने हाथ में ले लिया है तथा इसके विनियम की कार्यवाही चल रही है।

(v) चूरू व लाडनू की वस्टेड स्पिनिंग मिल्स भी राजस्थान सरकार के औद्योगिक उपक्रमों में आती हैं। ये राजस्थान लघु उद्योग निगम में चालू की हैं। ये ऊन की बत्तई करती हैं। चूरू में राजस्थान वूल कॉम्बर्स नामक इकाई भी इसी निगम में स्थापित की है।

(vi) राजस्थान स्टेट टेनरीज लि., टोक—टोक में एक लेदर टेनरी राज्य उपक्रम विभाग में अन्तर्गत स्थापित की गयी है। यह लेदर फोम, स्किन/हार्डस व सोल लेदर तैयार करती है। इसका मुख्य उत्पाद मेड की खाल से तैयार किया गया चमड़ा है जिसे देश-विदेश में बेचा जाता है। चमड़े का प्रयोग चमड़े के बत्तन, दस्ताने तथा बैग आदि बनाने में किया जाता है। कुल माल का लगभग 50% विदेशों को निर्यात किया जाता है। टैनरी की वित्तीय दशा बहुत खराब है। इसे 1983-84 में 62.7 लाख रु., 1984-85 में 44.1 लाख रु., 1985-86 में 55 लाख रु., व 1986-87 में 52.8 लाख रु. का घाटा हुआ है। श्री भार्ग. एस. कावडिया की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की थी ताकि कंपनी की दशा सुधारी जा सके।

(vii) फ्लोर्सपार बेनेफिशियेशन प्लांट, भाड़ी-की-पाल, डूंगरपुर जिला— राजस्थान राज्य औद्योगिक व खनिज विकास निगम (अब राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि. अथवा रीको) ने डूंगरपुर जिले में भाड़ी-की-पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनेफिशियेशन संयन्त्र डाला है। यहाँ एसिड ग्रेड का फ्लोर्सपार तैयार किया जाता है। फ्लोर्सपार धातुकार्मिक उद्योगों में एक महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। यह इस्पात बनाने व फाउण्ड्री कार्य में प्रयुक्त होता है। इस प्लांट पर उत्पादन-कार्य जारी है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

(भा) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सात औद्योगिक उपक्रम या संस्थान (Industrial Undertakings of the Central Government)

(1) हिन्दुस्तान जिंक लि., देवारी, (उदयपुर)—भारत सरकार ने 10 जनवरी, 1966 को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की थी। उदयपुर के पास जावर नामक स्थान पर सीसे व जस्ते के भण्डार पाये गये हैं। जस्ते के डले जिंक स्मेल्टर में प्रयुक्त किये जाते हैं जो देवारी में स्थित हैं। यह उदयपुर के समीप है। सीसे के डले बिहार के टुन्डू स्थान में गलाने के लिए भेज दिये जाते हैं। जस्ता-सीसा गलाने से सल्फ्यूरिक एसिड भी प्राप्त होता है जिससे सिंगल सुपर-फॉस्फेट पार बनाया जाता है। इस प्रकार यहाँ जिंक बेडमियम, चादी, सिंगल सुपर फॉस्फेट व अन्यक का तेजाब प्रादि उत्पन्न किये जाते हैं। स्मरण रहे कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने

(f) सांभर सॉल्ट्स लि—यह हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लि की सहायक संस्था है। इसने 1964 से कार्यारम्भ कर दिया था। इसने द्वारा कई तरह के नमक तैयार किये जाते हैं। सांभर भील 90 वर्गमील में फैली है। सांभर सॉल्ट्स में 60% अमल हिन्दुस्तान सॉल्ट्स का तथा 40% राजस्थान सरकार का है। इसे पिछले वर्षों में घाटा उठाना पड़ा है। 1987-88 में 45 लाख रुपये का घाटा हुआ है।

(g) मॉडर्न बेकरीज इण्डिया लि. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। यह मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि. के अन्तर्गत है। यह 13 ब्रेड इकाइयाँ संचालित करती है।

(h) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेण्ट्स लि—यह बनवपुर में स्थित है। इसमें भारत सरकार का 51% अंश है तथा शेप रीको का है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टस्टर्स बनाये जाते हैं। इसे 1987-88 में कर के पश्चात 42 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है जो पहले से अधिक है।

यह ध्यान देने की बात है कि विभिन्न राज्यों के बीच केन्द्रीय सरकार ने उपक्रमों में विनियोगों का वितरण काफी असमान रहा है। 1966-67 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजस्थान में किया गया पूँजी-विनियोजन लगभग 17 करोड़ रुपये था जो ब्रह्मपुर 1977-78 में 277 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार पिछले वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमों में विनियोग की राशि बढ़ायी है। 1985 में राजस्थान का समस्त राज्यों के केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों में 1.4% अंश था जबकि मध्यप्रदेश व उड़ीसा आदि में इसका उद्योगों की स्थापना के कारण यह प्रतिशत काफी ऊँचा था। यह एक उत्साहवर्धक बात है कि पिछले वर्षों में राजस्थान में केन्द्रीय सरकार की तरफ से औद्योगिक उपक्रमों में विनियोगों की राशि बढ़ी है। राष्ट्रीय धर्मल पावर लिमिटेड द्वारा अन्ता (कोटा) में गैस-आधारित पावर प्रोजेक्ट लगाने जाने पर राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र में विनियोगों की राशि और बढ़ेगी।

पिछले वर्षों में राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है तथा इसमें विविधता भी आयी है। अब राजस्थान में सिन्थेटिक यार्न, सीमेन्ट टी बी सेट्स व मिक्चर ट्यूब्स, रसायनों व उर्वरकों, टायर व ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जस्ता, ताँबा, कॉपर फायर एण्ड लेमिन्ट व अन्य कई प्रकार की मर्चे बनने लगी हैं। राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में देश में 5% योगदान होता है। राज्य में अति लघु, लघु व मध्यम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयाँ 140 हैं जिनमें 6 हजार व्यक्ति रगे हैं तथा 50 करोड़ रु की पूँजी लगी है।

मिवाडी में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की प्रगति—राज्य में मिवाडी औद्योगिक क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय है। यहाँ मई, 1987 में (Kienzie Indian Samay-Ltd) द्वारा क्वाट्रज क्वाक टाटमिग मूलभूत का उत्पादन करने के लिए एक

प्लास्टिक का सामान, रसायन, तेल, फर्नीचर, आदि वस्तुएं बनाने में संलग्न हैं।

राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास

विभिन्न योजनाओं में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय तथा कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया जाता है।

राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक व्यय में सर्वोच्च प्राथमिकता "सिंचाई व शक्ति" को दी गई है। 'उद्योग व खनन' पर व्यय की राशि कुल सार्वजनिक परिव्यय का काफी नीचा घन रही है। यह निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

योजनाओं में उद्योग व खनन पर परिव्यय¹

योजना	सार्वजनिक क्षेत्र में कुल वास्तविक परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उद्योग व खनन पर परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उद्योग व खनन पर कुल परिव्यय का %
I	54	0.46	0.8
II	103	3.37	3.3
III	213	3.31	1.6
तीन वार्षिक योजनाएँ : (1966-69)	137	2.06	1.5
IV	309	8.55	2.8
V (1974-79)	858	34.53	4.0
वार्षिक योजना (1979-80)	290	11.87	4.1
VI (1980-85)	2131	83.66	3.9
VII (1985-90)			
(प्रस्तावित)	3000	190.52	6.35
1985-88	1600	70.0	4.4
1988-89	710	29.0	4.1
1989-90	705	39.3	4.95 या 5.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि छठी योजना की अवधि (1980-85) में उद्योग व खनन पर किया गया परिव्यय कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का 3.9%

1. माय-व्ययक अध्ययन, 1989-90, राजस्थान, पृष्ठ 48 व पृष्ठ 123-124.

रहा। सप्तवीं योजना (1985-90) की अवधि में इसे बढ़ाकर 6.4% रखने का प्रावधान किया गया था। 1989-90 की वार्षिक योजना में उद्योग व सन्त के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का लगभग 5% ही आवंटित किया गया है।

माधुर समिति ने सिफारिश की है कि आठवीं पञ्चवर्षीय योजना में प्रभावित सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित किया जाना। (रिपोर्ट, सन् 1 पृ. 47)

1969 से राजस्थान के औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियाँ

1. चतुर्थ योजनाकाल में औद्योगिक विकास

राजस्थान की चतुर्थ योजना में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्रगति से प्रगति हुई थी। पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1968 में 1846 से बढ़कर 1973 के अन्त में 2800 हो गई थी। 1969 में राजस्थान राज्य औद्योगिक सन्त विकास निगम (RIMDC) स्थापित किया गया था। निगम ने औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया था। योजना के अन्त में वनस्पति तेल, उर्वरकों, ताम्रचान सूत, सीमेंट व बॉल बियरिंग का उत्पादन योजना के आरम्भ की तुलना में बढ़ा था।

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 16 जिले चिह्ने हुए घाटित किये गये जिनमें से 6 जिलों को पूँजी-निवेश में 15 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान (मन्मिडी) के लिए चुना गया था। चतुर्थ योजना की अवधि में जामर-कोटरा में रॉक-फॉस्फेट का उत्पादन चालू हुआ जिससे आगे चल कर विकास के नये अवसर सृष्टे।

2. पाँचवीं पञ्चवर्षीय योजना 1974-79 व बाद में औद्योगिक विकास

इन अवधि में लघु-उद्योगों, हस्तशिल्प एवं खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया। औद्योगिक विकास के लिए कई प्रकार की रिमायनों प्रदान की गईं जैसे चुगी शुल्क से मुक्ति, विद्युत-शुल्क के अनुदान की छूट, बिजली-की एज में ब्याज-मुक्त कर्ज, आदि।

RIMDC (अब RIICO) RFC RAJSICO (राजस्थान लघु उद्योग निगम) व जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centres) (DICs) ने औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान की है। इनके कार्यों पर आगे चल कर प्रकाश डाला गया है। रीको की स्वयं 3 परियोजनाएँ (टी बी, वाच एम्बेसी व राजस्थान कम्युनिकेशन) हैं तथा इसमें समुक्त क्षेत्र में कई परियोजनाओं की स्थापित करने में मदद दी है। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने गरीबा प्रतियोगिता केन्द्रों व हस्त-शिल्प को सहायता प्रदान की है। 1976 में हथकरघा विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। सूती खादी व ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं इनमें अधिक लोगो को रोजगार दिया गया है। सूती खादी का उत्पादन 1977-78 में 37 लाख ट. से बढ़कर 1986-87 में 6 करोड़ ट. ऊनी खादी का 3.7 करोड़ ट. से बढ़कर

17.6 करोड़ रु. तथा ग्रामीण उद्योगों का 7.5 करोड़ रु. से बढ़कर 104 करोड़ रु. हो गया है।¹

3 छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 में औद्योगिक विकास

छठी योजना में उद्योगों व खनन के विकास पर 83.7 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई जिसमें से ग्रामीण उद्योगों पर 23.2 करोड़ रु. मध्यम व बड़े उद्योगों पर 44.1 करोड़ रु. व खनन पर 16.4 करोड़ रु. व्यय किये गये।

सरकार ने उद्योगों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सन्निधि व विद्युत की सुविधाओं का विस्तार किया है। 1979 में समस्त औद्योगिक वस्तियों का काम रीलों को सौंप दिया गया था।

27 जिलों में से 16 जिला को भारत सरकार ने विनियोग सन्निधि प्रदान की तथा शेष 11 जिलों को (1 अप्रैल 1983 से) राज्य सरकार ने सन्निधि की सुविधा प्रदान की।

राज्य में लघु उद्योगों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है। दिसम्बर 1988 के अंत में उद्योग विभाग के द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों व टाइनरी इकाइयों की संख्या लगभग 1.42 लाख थी जिनमें विनियोग की राशि 668 करोड़ रु. व रोजगार 5.25 लाख व्यक्तियों को मिला हुआ था।

छठी योजना के अंत में रीलों के स्वयं के 3 प्रोजेक्ट व 29 संयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्ट तथा 100 सहायता-प्राप्त क्षेत्र के प्रोजेक्ट चले रहे थे। योजना के अंत में रीलों के पास 161 औद्योगिक वस्तियाँ थी।

राजस्थान वित्त निगम ने छठी योजना की अवधि में 172 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता वितरित की। 1984-85 में राजस्थान लघु उद्योग निगम 30 गरीबी प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा था। राजकीय उपग्राम विभाग ने नमक खानों आदि के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है। 1984 में हाथकरघा विकास निगम स्थापित किया गया था 1979-80 में हाथकरघे के वस्त्र का उत्पादन 14.7 लाख मीटर से बढ़कर 1984-85 में 46 लाख मीटर, सूती खादी का 3.3 करोड़ रु. से बढ़ कर 5.1 करोड़ रु., तथा ऊनी खादी का 10 करोड़ रु. से बढ़ कर 11.8 करोड़ रु. हो गया। ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन 12.2 करोड़ रु. से बढ़ कर 74 करोड़ रु. हो गया। इसी अवधि में ग्रामीण उद्योगों में रोजगार 37 हजार व्यक्तियों से बढ़ कर 1.77 लाख हो गया।

पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर लघु उद्योगों का विकास

विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास के लिए वास्तविक व्यय की राशियाँ इस प्रकार रही—

1. 10 years of Industrial & Mineral Statistics Rajasthan 1977-78 to 1986-87, August 1988, DES Jaipur, pp 17-18

(लाख रुपये में)

I योजना	32.4
II योजना	325.3
III योजना	198.2
तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	31.4
IV योजना	87.7
V योजना	395.0
VI योजना	2318.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास के लिए काफी धनराशि व्यय की गई थी। छठी योजना में इनके विकास पर लगभग 23.2 करोड़ रु व्यय किये गये हैं।

लघु उद्योगों को कम व्याज पर ऋजं दिये गये हैं तथा कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक बस्तियों का विकास किया गया है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु इकाइयों के भाल की वित्री की व्यवस्था करता है। इसने गलीचा प्रशिक्षण केन्द्रों तथा हस्तशिल्प के विकास में सहायता देने के अलावा सांगानेर हवाई अड्डे पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (Air Cargo Complex) की स्थापना में भी योगदान दिया है। कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हस्तकला वस्तुओं, जवाहरात, सिले-तिलाये वस्त्रों, गलीचों, आदि के निर्यात में वृद्धि हुई है।

1986-87 में राज्य में खादी उद्योगों में 1.44 लाख व्यक्ति रोजगार (पूर्णकालिक व अर्धकालिक) पाये हुए थे तथा ग्रामीण उद्योगों में 2.23 लाख व्यक्ति कार्यरत थे।

राज्य के विभिन्न भागों में हथकरपा, हस्तशिल्प, खादी, ग्रामीण उद्योगों व लघु उद्योगों के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं।

राजस्थान में जिलेवार फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन की स्थिति

राज्य में जिलेवार फैक्ट्रियों का वितरण बहुत असंतुलित पाया जाता है। 1982-83 में राज्य में 2368 फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना का अध्ययन करने से पता चलता है कि लगभग 3/4 फैक्ट्रियाँ निम्न 7 जिलों में केन्द्रित थी—

जिला	1982-83 में फैक्ट्रियों की संख्या
1 जयपुर	546
2 श्री गंगानगर	257
3 पाली	172
4 अजमेर	184
5 जोधपुर	232
6 उदयपुर	177
7. कोटा	133
सात जिलों का जोड़	1701 (कुल का 72%)

इसी अवधि में जैसलमेर जिले में फैक्ट्रियों की संख्या 3, हंगरपुर में 2, जालौर में 2, भुवनेश्वर में 7, सिरौही में 11 तथा झालावाड़ में 7 थी। 1982-83 में आठ जिलों में जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, पाली, जोधपुर, उदयपुर व भीलवाड़ा जिलों में फैक्ट्रियों में लगभग 1.85 लाख व्यक्ति काम पाये हुए थे, जो कुल फैक्ट्री रोजगार का लगभग 82% या 4/5 अंश था। जेप 19 जिलों में केवल 1/5 फैक्ट्री रोजगार मिला हुआ था। 1970 से 1982-83 के बीच पाली व उदयपुर जिलों का औद्योगिक स्थान ऊँचा हुआ है। लेकिन फैक्ट्री-रोजगार के हिसाब से प्रथम चार स्थान जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर व अजमेर को ही मिले हुए हैं। अतः ये राजस्थान के अपेक्षाकृत अधिक विकसित जिले माने जा सकते हैं। पाली जिले में सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई व ब्लोबिंग का काम बड़ा है तथा उदयपुर जिले में अधात्विक खनिज पदार्थों का काम बड़ा है। राज्य के अधिकांश जिले आधुनिक फैक्ट्री उत्पादन की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए माने जाते हैं।

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए रियायतें व सुविधाएँ¹

(Concessions & Facilities for Industrial Development in the State)

पिछली दो दशकियों में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें, सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। राज्य का उद्योग-निदेशालय (Directorate of Industries) सधु व कुटीर उद्योगों की प्रगति का कार्य देखता है। इसके द्वारा सधु इनाइयों का पंजीकरण किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल का आवंटन करने की सिफारिश करता है। इसी के अन्तर्गत 27 (भीलपुर सहित) जिला-उद्योग-केन्द्र (District Industries Centres) (DICs) काम कर रहे हैं जिनमें RFC, RIICO व RSIC तथा व्यापारिक बैंकों के प्रतिनिधि संचालन कार्य में भाग ले रहे हैं।

राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में तथा उद्यमकर्ताओं को पूंजी की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है—

1. भूमि का आवंटन—राज्य सरकार ने चुने हुए स्थानों पर उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े भू-क्षेत्र निर्धारित किये हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों (industrial areas) में उद्योगों को 99 वर्ष के 'लीज' पर भूमि आवंटित की जाती है। भूमि आवंटन की दरें विभिन्न क्षेत्रों में प्रलग-प्रलग रखी गयी हैं। ये पिछड़े जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम हैं। 30 औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन की दरें संशोधित की गई हैं। अब ये प्रति वर्ग मीटर 15 रुपये (फतेहनगर, प्रतापगढ़ व

1. RIICO Newsletter, July 1989, pp. 1-8.

खण्डसा में) से 60 रुपये (बालोतरा, पाली (चतुर्थ चरण) तथा मेवाड (उदयपुर में) को गई हैं।

2 औद्योगिक वस्तिषा व औद्योगिक क्षेत्र—(रीको) (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिमय निगम लि.) ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये हैं। इनमें पावर सड़क, जल व पानी के विकास की सुविधाएं दी गई हैं। इसके द्वारा विकसित किये गये क्षेत्र जयपुर (विश्वकर्मा, मासवीय), कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर अजमेर, पाली, चिडावा, पिलानी, बून्दो, टोक, निवाई, सीकर, बालोतरा बाडमेर, सादुनपुर व चित्तौड़गढ़ आदि में स्थित हैं। प्रव तः रीको ने 174 औद्योगिक क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य अपने ऊपर लिया है। विभिन्न स्थानों में उद्योगों को दस हजार से अधिक भूखण्ड (plots) आवंटित किये जा चुके हैं।

व्यापारिक वस्तिषो में नीचे दुकान व ऊपर रिहायशी मकान की व्यवस्था हाती है। रीको ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए जयपुर व पिलानी में कार्यात्मक वस्तिषा (functional estates) विकसित की हैं।

मिवाडी औद्योगिक क्षेत्र में काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका है। यह अपनी क्षमता के उच्च शिखर पर पहुँच गया है। अब वहाँ पर्यावरण-सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ने लगी हैं। रीको सस्ता झाल औद्योगिक क्षेत्रों को बेचने का कार्य भी संचालित करता है। मिवाडी औद्योगिक क्षेत्र की ही कुछ प्रतिरिक्त भूमि को भी रीको ने अलवर नगर विकास न्यास को बेचा है।

3. वित्तीय सहायता—उद्योगों को वित्तीय सहायता राज्य सरकार के उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम, भारतीय स्टेट बैंक व इसके सहायक बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम (RFC) लघु व मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन कर्ज देता है जिनकी राशि प्रति इकाई 2 हजार रु. से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है। अब यह बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गयी है। कर्ज देने की कई स्कीम हैं जैसे कम्पाजिट टर्म लोन उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण (सिंगल वाहन), होटल वज, डीजल जेनरेटिंग के लिए कर्ज, टेक्नोशियन सहायता स्कीम, अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अप्रोग्य व्यक्तियों तथा डॉक्टरों के लिए स्कीम। एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्म के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये रखी गई है। RFC अपनी उदार ऋण योजना (Soft Loan Scheme) के अन्तर्गत 2 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक की राशि लघु इकाइयों को भूमि खरीदने, फैक्ट्री का भवन बनाने व सयन्त्र तथा मशीनरी खरीदने के लिए कर्ज के रूप में देता है (टेक्नोक्रेडिट को 5 लाख रु. तक)। टेक्नोशियन को 5 लाख रुपये तक कर्ज (बिना मार्जिन रखें) दिये जाते हैं।

कम्पोजिट टर्म लोन योजना के अन्तर्गत 2 हजार रु से 25 हजार रु तक का ऋजं दस्तकारी व उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है।

अब रीको 90 लाख रुपये तक के अवधि-ऋजं (term-loans) प्रदान कर सकता है। व्यापारिक बैंक 80 लाख रुपये तक के ऋजं दे सकते हैं। इस प्रकार RFC RILCO व व्यापारिक बैंक एक साथ 200 लाख रुपये तक का ऋजं (RFC की सीमा के घटने पर यह भी बढ़ गयी है) प्रदान कर सकते हैं जिसमें 300 लाख रुपये तक की लागत के प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवस्था सम्भव हो सकती है। जग राशि शायर बेचकर जुटायी जा सकती है। उद्योग विभाग भी 25 000 रुपये तक ऋजं लघु इकाइयों को उपलब्ध करता है।

रीको व RFC के द्वारा वित्री कर की राशि व बराबर व्याज-मुक्त ऋण (Interest free loans) भी दिये जाते हैं। राज्य सरकार ने 5 मार्च 1987 से 31 मार्च 1992 तक की अवधि के लिए उद्योगों को वित्री कर से कुछ वर्षों के लिए मुक्त व आस्थगन रखने की नई प्रेरणादायक स्कीम भी घोषित की है।

4. विद्युत की सप्लाई बढ़ायी गई है एवं इस दिशा में प्रगति जारी है। विद्युत-प्रणाली पर रिबेट दी जाती है। जन-सप्लाई व कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई गयी है।

5 करो में राहत (Tax Relief)—सरकार ने कारखानों में लगायी जाने वाली मशीनरी को कुछ गैर शुल्क से मुक्त किया है। कच्चे माल पर भी यह छूट दी गयी है। राज्य सरकार ने मशीनों व कच्चे माल पर वित्री-कर की छूट दी है। विद्युत-शुल्क में भी छूट दी गयी है। अब वित्री-कर से छूट आस्थगन की नई स्कीम लागू की गई है।

6 राजस्थान के पिछड़े जिलों का औद्योगिक विकास—जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य में 16 जिलों की औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है। ये जिले इस प्रकार हैं—जानौर, नागौर, जोधपुर, बूंदी, मोरार झालावाड़ा टोंक अलवर, सिरोंही, उदयपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा भुवनेश्वर, जैतलमेर, व बाड़मेर। सितम्बर 1988 तक 27 जिलों में से 16 को भारत सरकार की तरफ से विनियोग-सम्मिती दी जाती थी (जो बाद में बढ़ कर दी गई) तथा शेष 11 जिलों को राज्य सरकार की तरफ से दी जानी रही है।

सम्मिती की व्यवस्था—पहले केन्द्रीय सम्मिती की व्यवस्था में पिछड़े जिलों का तीन श्रेणियाँ A, B तथा C के अन्तर्गत विभक्त किया गया था जो इस प्रकार थे—(A) इनका अन्तर्गत 25% सम्मिती जैतलमेर, सिरोंही बूंदी व बाड़मेर जिलों के लिए रखी गयी थी। ये मुख्य उद्योग जिले (No industries Districts (NIDs) घोषित किये गये। सम्मिती की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये रखी गई।

(B) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सन्निही पांच जिलों बाँसवाड़ा, भलवर, मोनवाड़ा, जोगपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गयी तथा इसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपये रखी गयी। (C) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सन्निही सात जिलों बाँसवाड़ा, दूंगरपुर, जालौर, भालवाड़, भुभुनू, सोकर व टोंक के लिए थी तथा सन्निही की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये रखी गई थी।

इस प्रकार केन्द्रीय सन्निही की नई व्यवस्था काफी लचीली थी। शेष 11 जिलों—भजमर, भरतपुर, बूंदो, बोकानेर, चित्तौगढ़, जयपुर, गगानगर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, व धौलपुर के लिए राज्य सरकार सन्निही देती रही है जो हट्टी व मध्यम इकाइयों के लिए 10% (अधिकतम 10 लाख रु.) एवं लघु इकाइयों के लिए 15% (अधिकतम 3 लाख रु.) (अनुसूचित जाति/अनजाति के लिए लघु इकाइयों पर 20%, तथा नन्ही (tiny) इकाइयों के लिए 25% रखी गई है। निम्न क्षेत्रों की सन्निही नहीं दी जाती। मत्स्य (भलवर), महधर (जोगपुर), जयपुर के विश्वकर्मा व मालवीय तथा मेवाड़ (उदयपुर)। सार्वजनिक वित्तीय सत्प्राप्त पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करती है।

1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च 1990 तक के लिए व्याज-मुक्त बिक्री कर कर्ज-व्यवस्था (Interest-free sales-tax loan scheme) भी जारी है। इस कर्ज के दिशा-निर्देश नीचे दिये जाते हैं—

(अ) बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए स्थिर परिसम्पत्ति का 8 प्रतिशत कर्ज, अधिकतम राशि 50 लाख रुपये तक, (आ) मध्यम धरोहरों के उद्योगों के लिए स्थिर परिसम्पत्ति का 15%, तथा अधिकतम सीमा 50 लाख रु. तक, (इ) लघु उद्योगों के लिए स्थिर परिसम्पत्तियों का 25% कर्ज तथा अधिकतम सीमा 50 लाख रु. तक, (ई) एक विकास खण्ड में 1.5 करोड़ या ऊपर के स्थिर पूँजी-विनियोग से पहली बार स्थापित की जान वाली औद्योगिक इकाई (Pioneering industry) को अधिकतम 1 करोड़ रु. तक, (उ) 25 करोड़ रु. व अधिक के स्थिर पूँजी विनियोग से स्थापित किये जान वाले प्रतिष्ठामूलक उद्योग (prestigious industry) के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक कर्ज भ्रयवा इतना ही कर्ज एक शुरू के उद्योग (pioneering industry) के लिए जिसमें 10 करोड़ रुपये तक का विनियोग हो।

इस व्याज-मुक्त बिक्री-वर की स्कीम के कर्ज का भुगतान पांच समान किस्तों में देय होगा और यह वितरण की तिथि के छठे वर्ष से चालू होगा।

23 मई 1987 का मुख्य मंत्री ने नये उद्योगों को उत्पादित माल पर बिक्री कर में 31 मार्च 1992 तक रियायतें देन की घोषणा की थी। 5 मार्च 1987 के बाद उत्पादन में आने वाले बाले सनो नये उद्योगों को पिछड़े जिलों में सात वर्ष तक उत्पादित माल पर यह छूट दी गई। जब कि विकसित जिलों में यह पांच वर्ष तक दी गई। यह छूट आइसक्रीम, बड़े सीमेंट, प्लाट, होटल तथा अधिक बिद्युत की गणन वाली इकाइयों को नहीं दी गई।

पिछड़े जिलों में छोटे उद्योगों के लिए छूट की सीमा उनकी स्थायी परिसम्पत्ति की 100% तक मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए 90% तक तथा विकसित जिलों के लिए ये सीमाएँ क्रमशः 85% व 75% तक रखी गईं।

योजना के अन्तर्गत 'पायनिवरिंग' व 'प्रेस्टीजियस' उद्योगों को यह सुविधा दी अतिरिक्त वर्षों के लिए दी गयी। उद्योगों को बिक्री कर-मुक्ति के वजाय बिक्री कर-प्रास्पन्न (Sales Tax Deferment) की सुविधा भी दी गई है।

(7) विभिन्न निगमों का राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोग निगम लिमिटेड प्रथम रीको—

यह नवम्बर, 1979 में स्थापित किया गया था। इससे पूर्व राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम (RIMDC) 1969 में स्थापित किया गया था। बाद में नवम्बर में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) के प्रलग से स्थापित होने के बाद रीको का कार्य क्षेत्र औद्योगिक विकास तक सीमित कर दिया गया। रीको के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं : (i) यह औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों का निर्माण करता है। (ii) सार्वजनिक समुक्त व सहायता-प्राप्त क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएँ स्थापित करता है। (iii) औद्योगिक उपक्रमों की शेयर पूँजी में भाग लेता है, शेयरों का प्रमिगोपन (underwrite) करता है तथा स्वयं औद्योगिक परियोजनाओं का संचालन कर सकता है। (iv) यह उद्यमकर्त्ताओं को कई प्रकार की रियायतें, सुविधायें व प्रेरणाएँ देता है। इस प्रकार राज्य के औद्योगिक विकास में इसका योगदान निरन्तर बढ़ता जा रहा है। (v) यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाता है तथा तकनीकी मार्ग-दर्शन करता है। यह वस्तुओं, क्षेत्रों व साधनों का सर्वेक्षण करवाता है। सरकार ने इसके वित्तीय साधनों में वृद्धि की है। 31 मार्च, 1984 को इसकी अधिकृत पूँजी 50 करोड़ रुपये व परिदत्त पूँजी 37.145 करोड़ रुपये थी। इसने डिबेन्चर वेचकर भी साधन जुटाए हैं तथा इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त व सीड पूँजी सहायता मिलती है।

सितम्बर, 1976 में IDBI ने रीको की वित्तीय मस्या के रूप में मान्यता प्रदान की थी जिससे इसकी विनियोग-सम्बन्धी क्रियामों में काफी वृद्धि हुई है। साधारणतया रीको समुक्त-क्षेत्र (Joint sector) की परियोजनाओं की शेयर पूँजी (equity) में 26% भाग लेता है (जहाँ 49% शेयर प्रब्लिक क्षेत्रों के क्षेत्रों में) तथा सहायता-प्राप्त परियोजनाओं (assisted projects) की 10% से 15% तक शेयर-पूँजी लेता है। इसके द्वारा 3 करोड़ रु. से अधिक राशि की परियोजनाओं को कर्ज नहीं दिया जाता बल्कि उनकी इक्विटी में भाग लिया जाता है।

इसकी दो सहायक कम्पनियाँ (subsidiary companies) इस प्रकार हैं :

- (1) राजस्थान कम्प्यूनिक्सेन्स लि., (ii) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि.। एक नई सहायक कम्पनी L. G. Telecom/Limited 20 मई, 1988 को पञ्जीकृत हुई है।

1987-88 में रीको के कुल 186 प्रोजेक्ट उत्पादन में एक 79 त्रिमास्यन में थे। इनमें से तीन प्रोजेक्ट स्वयं के क्षेत्र में, कुछ संयुक्त क्षेत्र में व शेष सहायता प्राप्त क्षेत्र में हैं। इनसे काफी प्रोजेक्ट पिछड़े क्षेत्रों में लगाये गए हैं तथा कुछ जन-आति क्षत्रा में भी लगाये गए हैं। इस प्रकार रीको पिछड़े क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों व विकास के लिए प्रयत्नशील रहा है।

रीको की स्वयं की तीन परियोजनायें इस प्रकार हैं : टी. बी., घड़ी व ट-वे रेडिया मचान-उत्तरण परियोजनायें। टी-बी, इकाई में टेलीविजन सेट्स का उत्पादन बढ़ा है तथा 51 सेंटीमीटर नरग, 51 सेंटीमीटर रमीन व 37 सेंटीमीटर मिनी टी बी सेट्स बनाये गये हैं।

रीको की वाच एसेम्बली इकाई में लाउडस्पीकर, डिजिटल वॉक, विद्युत इमरजेंसी लाइट्स आदि के निर्माण की योजना बनायी है। घड़ियों के उत्पादन की क्षमता आई-साथ से 3.6 लाख करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

रीको ने संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। 1986-87 में 33 इकाइयों में उत्पादन चालू हो गया था, कुछ त्रिमास्यन की स्थिति में थी तथा कुछ पाइप-वाइन में थी, अर्थात् विचाराधीन थी। संयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्टों में अधिकांश इकाइया कापेट यार्न व सिन्थेटिक यार्न बनाती हैं। इनमें कुछ के नाम व स्थान सारांश के अंत में एक परिशिष्ट में दिये गये हैं। रीको ने स्वयं के क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र), संयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजेक्टों में विदेशी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। आशा है रीको के प्रयत्नों से अभिव्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास होगा तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा।

31 मार्च, 1989 को रीको से वित्तीय सहायता प्राप्त 22 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट उत्पादन में आ चुके थे। इनमें से 11 निवाही, 6 जयपुर, 2 उदयपुर, तथा एक-एक अजमेर, झतवर व कोटा में स्थित थे। इनमें से कुछ बड़े प्रोजेक्टों के नाम इस प्रकार हैं, परताप राजस्थान कॉरर फोइस एण्ड सेमीकंड्स लि. जयपुर, माम-टल इण्डिया लि., निवाही, नोवा मैग्नेटिक लि. (चरण I), निवाही तथा टेलेट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स लि. निवाही।

अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट त्रिमास्यन व विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस प्रकार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है।

रीको ने 1987-88 में कुल लगभग 39.1 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वाहन की तथा 24.9 करोड़ रु. की वित्तिल की जो पिछले वर्ष में क्रमशः 33.8

रियम 8 सहरा में स्थापित किये गये हैं। इसने फर्नीचर बनाने का केन्द्र जयपुर में चालू किया है।

(iv) राज्य उपक्रम विभाग (State Enterprises Department)—इसकी दख-रेख में निम्न इकाइयाँ संचालित की जा रही हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डोडवाना, राजकीय लवण श्रोत, डोडवाना व पंचपदरा, राजस्थान स्टेट टेन-रीज लि टोक, गमानगर शुगर मिल्स लि. श्रीगगनगर, (हाई-टेक प्रिंसीजन ग्लास लि. धौलपुर सहित) तथा राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर। इनका सक्षिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है।

(v) ग्राम सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता¹

प्रखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने राजस्थान को बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण इस प्रकार है—

(प्र) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) ने राजस्थान को 1948-88 की अवधि में लगभग 251 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की। तथा 190 करोड़ रुपये की वितरित की। मार्च, 1988 तक कुल वितरित सहायता में राजस्थान का भूँष केवल 5.8% था जबकि महाराष्ट्र का 15.3% था।

(घा) भारतीय औद्योगिक सार्वजनिक वित्त निगम (ICICI) ने मार्च, 1988 तक राजस्थान को लगभग 261 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकार की तथा 195 करोड़ रुपये की वितरित की। अब तक की वितरित राशि में राजस्थान का भूँष 4.2% तथा महाराष्ट्र का 25.8% रहा।

(इ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने 1964-88 की अवधि में राजस्थान को लगभग 1114 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत हुई तथा 836 करोड़ रु की वितरित हुई। अब तक की वितरित राशि में राजस्थान का भूँष 4.4% तथा महाराष्ट्र का 14.6% रहा। इस प्रकार देश की वित्तीय संस्थाओं ने अब तक राजस्थान को बहुत कम मात्रा में वित्तीय सहायता वितरित की है। इसका कारण राजस्थान से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रोजेक्टों का भूँष भी माना गया है।

राजस्थान में जनता सरकार की औद्योगिक नीति, जून 1978—राज्य में जनता सरकार ने 24 जून, 1978 की अपनी नई औद्योगिक नीति घोषित की थी। इस नीति की कुछ बातें आज भी उपयोगी हैं। इसलिए इसका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है। इसमें उद्योगों में प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित किया गया था, क्षेत्रीय

1 Report on Development Banking in India, 1987-88, IDBI pp. 100-115

असन्तुलन को कम करने के उपाय बतसाये गये थे उद्योगों को दी जाने वाली सहायताएँ व सुविधाएँ स्पष्ट की गई थीं और बीमार औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सहायता के बारे में नीति निर्धारित की गई थी।

(i) उद्योगों में प्राथमिकता का क्रम—उद्योगों का प्राथमिकता के क्रम में खादी प्रामोद्योग हथकरघा व हस्तशिल्प को सबसे ऊपर रखा गया था। उसके बाद एक साल रुपये तक की पूँजी वाले उद्योग फिर क्रमशः 10 लाख रु. व 50 लाख रुपये वाले उद्योग तथा अन्त में बृहद् उद्योग रते गये थे।

(ii) क्षेत्रीय प्राथमिकता का क्रम—क्षेत्रीय असमानताएँ कम करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ तय की गयी थीं। इनका क्रम इस प्रकार रखा गया था : पहल गाँव फिर भद्र-शहरी क्षेत्र तथा अन्त में शहर। नये सार्वजनिक व समुक्त क्षेत्र के उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगाने का निश्चय किया गया था।

स्थानीय माधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था। श्रम प्रधान उद्योगों को पूँजी प्रधान उद्योगों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया था।

(iii) सार्वजनिक उद्योग—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए राजस्थान प्रबन्धन सेवा-संघ (Rajasthan Management Cadre) बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक व्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज बनाने का प्रस्ताव किया गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता व कार्य-प्रणाली की निरन्तर समीक्षा करेगा। समुक्त क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी पूँजी में 10% सरकारी सहयोग की नीति घोषित की गई थी।

(iv) बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रति नीति—जिस औद्योगिक इकाई में कुल क्षमता का 20% से कम उत्पादन हो रहा हो तथा जो घाटे में चल रही हो व जिसने पिछले तीन वर्षों से व्याज या मूलधन का भुगतान न किया हो, वह बीमार या बंरा इकाई मानी गई थी। इनके सम्बन्ध में यह कहा गया था कि ऐसी इकाई को उद्योग-निदेशन प्रमाण-पत्र देना। रक़ुता का तारण होजा जायेगा। राज-स्थान वित्त निगम ऐसी इकाइयों के ऋणों के भुगतान की दूसरी तिथि निर्धारित करेगा (reschedule)। ऐसी इकाइयों से की गई सरकारी खरीद का भुगतान एक माह के भीतर कर दिया जायेगा। मरणागती लगीद में भी ऐसी इकाइयों के माल को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) नयी सहायताएँ व सुविधाएँ—औद्योगिक नीति में यह भी कहा गया था कि उद्योगों के लिए आवश्यक मोचर भूमि जिलाधीन ग्राम पंचायत की सिपारिश पर रूपान्तरित (convert) करेंगे। स्वयं का उद्योग लगाने पर किसान की सातेदारी की 500 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण अपने आप माना जायेगा। इसके लिए

केवल परिवर्तन शुल्क जमा कराना होगा। दाल मिल, चावल मिल आदि को 25 हजार से कम आयवादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने पर बिजली खर्च में 25% सब्सिडी देने की नीति घोषित की गई थी।

अब राज्य में कांग्रेस (भाई) सरकार पर राजस्थान के औद्योगीकरण की जिम्मेदारी है। आशा है विभिन्न प्रकार की रियायतों व सुविधाओं का लाभ मिलने से राज्य की प्रगति औद्योगीकरण की दिशा में अधिक तेज गति से हो सकेगी। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है राज्य में रीको राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम उद्योग-निदेशालय आदि औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्षों में उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय पूँजीगत सन्धि और राज्यीय पूँजीगत सन्धि का काफी विस्तार किया गया। विदेशों में बसे भारतीयों को राजस्थान में पूँजी लगाने के लिए आकर्षित किया गया है।

राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूह रचना

(Industrial Strategy During Seventh Plan of Rajasthan)¹

राज्य के योजना विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्राथम्यतापूर्वक करके दिल्ली में भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था। उसमें 1985-90 की अवधि के लिए औद्योगिक विभाग की व्यूह रचना के सम्बन्ध में निम्न बातों का समावेश किया गया था। राज्य सरकार ने पृथक् से सातवीं योजना में औद्योगिक व्यूह रचना की घोषणा नहीं की है। इसलिए औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में किसी व्यवस्थित व अनुमोदित नीति के अभाव में निम्न बातों का श्रेयतात्मक हो माना जाता चाहिए।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य—इस बात पर बल दिया गया कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जायगा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायेंगे प्रादेशिक असन्तुलनों को कम किया जायगा परम्परागत शिल्पकलाओं का विकास किया जायगा, उद्यमकर्त्ताओं को सहायता दी जायगी तथा औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास व विस्तार दिया जायेगा।

1 Draft Seventh Five Year Plan (1985-90) and Annual Plan 1985-86 Planning Department Chapter 15, on Industrial Development.

ग्रोटिंग्स लाइन को पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य में सीमेंट के प्लांट बढ़ाये जा सकें। दिल्ली-ग्रहमदावाद तथा जयपुर-नवाई माधोपुर सीटर ग्रेज लाइनों को ब्राड गेज लाइनों में बदलने से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में रेल की लाइनें विद्युत में औद्योगिक विकास में सहामाता मिलनी।

यह स्वीकार किया गया कि मानवी योजना में औद्योगिक व्यूहरेचना व नीति को कार्यान्वित करने व सुफल बनाने के लिए काफी वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी। इसने लिए सरकार व निजी उद्यमकर्ताओं (स्वदेशी व प्रवासी) को मिल-जुल कर काम करना होगा।

मार्च 1987 में राज्य के मुख्य मंत्री ने औद्योगीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। जिसकी विष्णुनाथ नौचे दी जाती है :¹—

1. रीको एक 'वन बिस्को सर्विस' बालू करेगा जिसके तहत उद्यमकर्ताओं की आवश्यक महामात्रा समयबद्ध मारणी के अनुसार एक साथ एक स्थान पर प्रदाता की जायगी।

2. रीको ग। वित्त निधम तथा उद्योग-विभाग राज्य के अन्दर व बाहर अभियान चला कर उद्योगों को प्रार्थित करने का प्रयास करेगे।

3. 1987-88 में RFC व RIICO लगभग 100 करोड़ रु. का व्यवधि-प्राप्त होने जिसका लाभ लघु व मध्यम यंत्रों के उद्योग उठायेगे।

4. डीजल जनरेटिंग सेट के लिए 'आपनि नो नॉटिफिकेट' (NOC) जारी करने की विधि सरल की जायगी। इसके लिए विद्युत-शुल्क में भी राहत दी जायगी।

5. भवन षट्टे स्वीकृत करने का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर खनिज आध-रित उद्योगों का लोभ मान से विनाश किया जायगा।

6. कृषि व पशु-पन पर आधारीत उद्योगों का भूमि, विद्युत-वनकगन, कर्ज आदि में प्राथमिकता दी जायगी। इनकी अनिरित कर-राहत भी दिया जायगा।

7. धन-मूल्य उद्योगों का भूमि बाबर वनकगन व कर्ज में प्राथमिकता दी जायगी। उनका कर-राहत भी दिया जायगा।

8. हरा उद्योगों का कर-राहत दिया जायगा तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बांडों की सेवाओं का लाभ उठाया जायगा।

9. सरकार की वर्तमान क्रय-नीति (Purchase policy) का विस्तार किया जायगा ताकि ग्यानीय उद्योग उसका लाभ उठा सकें।

10. नयी इन्क्यूबेटिव इकाइयों को समिती बढ़ाई जायेगी। 5 करोड़ रु. से अधिक निर पुँजी व विनियोग वाली इकाई को 25% समिती, अथवा 25 साल रु. की गति दी जायगी (जो भी कम हो) एवं 5 करोड़ रु. से कम वाली इकाइयों

के लिए 15% सस्मिडी अथवा 15 लाख रु की राशि रखी गयी है। यह लाभ सातवी योजना के अन्त तक दिया गया।

11 नार्बार्ड की सहायता से 1987-88 में 10 हजार लघु व लघुतम (tiny) इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी।

12 निर्धन हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचत-कोष-स्कीम लागू की जायगी।

13 उद्यमशीलता-विकास-केन्द्र स्थापित किया जायगा तथा

14 विकसित जिलों में नये उद्योगों को 5 वर्ष के लिए तथा पिछड़े जिलों में 7 वर्ष के लिए बिजली-कर से मुक्त रक्ता जायगा।

जहाँ एक भी बड़ा उद्योग नहीं है वहाँ यह सुविधा क्रमशः 7 वर्ष व 9 वर्ष के लिए होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत घोषणा हाल में राज्य सरकार ने की है जिस पर 'रियायती व प्रेरणाओं' के खण्ड में प्रकाश डाला गया है।

इस प्रकार औद्योगीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक व नया कार्यक्रम अपनाया है।

राज्य में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ —

राज्य में कृषि-आधारित वन-आधारित लनिज-पदार्थ-आधारित पशु-आधारित उद्योगों के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का भविष्य भी उज्ज्वल है। नीचे औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं का परिचय दिया जाता है —

(1) राजकोट (Rajasthan Consultancy Organisation) के जैसलमेर व सिरोंही जिलों के सर्वेक्षण के परिणाम —

राजकोट ने एक अध्ययन के द्वारा जैसलमेर जिले में जैसलमेर व पोकरन तथा सिरोंही जिले में भावू रोड व सिरोंही रोड औद्योगिक विकास केन्द्र छाटे हैं। जैसलमेर जिले के लिए जो औद्योगिक प्रोजेक्ट सुझाये गये हैं वे इस प्रकार हैं। उपलब्ध लाइमस्टोन के आधार पर एक बड़ा सीमेन्ट सयन्त्र स्थानीय ऊर्जा पर आधारित एक 'ब्रड'-बस्टेड स्पिनिंग मिल तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए एक थ्री स्टार होटल (72 कमरों की क्षमता वाले एक एयर कण्डीशन होटल)। इसके अलावा स्थानीय औद्योगिक साधनों का उपयोग करके निम्न लघु उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं 'मार्बल प्रोसेसिंग ऊनी व छादी कॉम्प्लेक्स, ऊनी यार्न रगई, हाथ से बने ऊनी गलीचे, कार्पेट फिनिशिंग, तुम्बा तेल प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डों का चूरा, हाइड्रोटेड चूना आदि।

इसी प्रकार सिरोंही जिले के लिए निम्न उद्योग सुझाये गये हैं एक बड़ा सीमेन्ट प्लांट तथा मिनी-सीमेन्ट प्लाण्ट्स क्योंकि यहाँ भी सीमेन्ट ग्रेड वाला लाइम-स्टोन काफी मात्रा में पाया जाता है। मार्बल की बटाई व पॉलिश एवं मार्बल की टाइल बनाने की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। इनके अलावा एक एच. टी इन्सुलेटर प्लांट पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

तेसे ही अध्ययन चुरू व बाढमेर जिलों के लिए किये गये हैं।

(ii) रीको द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में 400 करोड़ रुपये के विनियोजन के कार्यक्रम।

रीको ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों में 400 करोड़ रुपये का नया विनियोजन करने के कार्यक्रम तैयार किये थे। इस समय उन उद्योगों में राजस्थान का अंश 5 प्रतिशत है। यह भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. कोटा की वजह से है जिसकी वार्षिक बिक्री 100 करोड़ रुपये के लगभग है।

रीको ने इस क्षेत्र में स्वयं प्रोजेक्ट लगाना, तथा निजी क्षेत्र में विनियोजन का प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम रखे थे। निगम इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधायें देता है। जो विशेष रियायतें व सुविधायें भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर व पिलानी जैसे स्थानों को इन उद्योगों के लिए दी गई हैं, वे अन्य स्थानों को भी दी गयी हैं। ये इस प्रकार है, भूमिक की लागत पर 20% की रिबेट, औद्योगिक भूमि के छावटन में प्राथमिकता, समय-प्रति बित्तीय सहायता कार्यक्रम, सम्भावना-सर्वेक्षणों पर सस्तिडी व इक्विटी में हिस्सा, आदि।

जनवरी, 1986 से समस्त इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को केवल 4% बिक्रीकर देने की सुविधा प्रदान की गई। मातृ योजना की पूरी अवधि तक इस क्षेत्र में नये उद्योगों का बक्री-कर से 5 वर्षों के लिए मुक्ति दी गयी।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स केन्द्र के रूप में उभरा है। अब निगर राजस्थान-हरियाणा सीमा पर शाहजहांपुर में एक नया इलेक्ट्रोनिक्स केन्द्र विकसित कर रहा है। आबू राड (सिरोही जिला) में भी इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग विकसित किये जा सकते हैं।

प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए बल्लिजी व पोलिटेक्नीक का विकास किया जा रहा है। रीको ने अपना टी वी यूनिट अपनी सहायक कंपनी राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. को सौंप दिया है। रीको ने ग्रामीण स्वचालित एमचेंजेज व कम्प्यूनिक्शन रिमोवर्स के लिए आशय-पत्र (letter of intent) प्राप्त किये हैं और इनकी स्थापना की जा रही है।

आगामी वर्षों के लिए उद्यमकर्ता निम्न उद्योगों को स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं - रंगीन टी वी ट्यूब के दो प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रोनिक्स पी. ए. बी. एक्स. प्रणालियों के तीन प्रोजेक्ट, टेलीफोन उपकरणों के 2 प्रोजेक्ट, पब्लिक टेलीफोन प्रणालियां, प्रदूषण-गोनिटरिंग-उपकरण, हाइब्रिड सरकिट्स, डोट मैट्रिक्स प्रिंटेड मोड्यूल एण्ड यू.एच.एफ. रेडियो रिसेल्वर्स। इसके अलावा सेमटस इण्डिया लि. भिवाड़ी ने औद्योगिक क्षेत्र में ग्लास-शेलिंग (glass shells) का प्रोजेक्ट चालू किया है। इन सबके कारण पूंजी-विनियोजन बढ़ रहा है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास के मार्ग में बाधाएँ

1. रेलों का विकास—राज्य में मीटर गेज रेलवे का अत्यधिक विस्तार होने से माल की ढुलाई में बाधा पड़ती है। केवल जगतपुर कोटा व मवाई माधपुर ही ब्राड गेज लाइन पर स्थित हैं। कोटा-चित्तौड़गढ़ की ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन से जोड़ने पर 5 बड़ी सीमेंट की इकाइयाँ स्थापित की जा सकनी हैं जिनमें एक सुपर सीमेंट सयन्त्र भी शामिल है। दिन्दी-ग्रहमदाबाद तथा जयपुर-मवाई माधपुर मीटर गेज लाइनों को ब्रॉडगेज लाइनों में बदल देने से औद्योगिक विकास के नये अवसर खुल सकते हैं। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में नई रेल-लाइनों बिछाने से औद्योगिक विकास का आधार-ढाँचा सुदृढ़ हो सकता है।

2 राज्य में विद्युत की दरों में कमी व पूर्ति में वृद्धि की आवश्यकता—राज्य में बिगली की दरें अन्य राज्यों में अधिक हैं। ये इन्क्यूबेटर-यूनिट व टूरिंगटो-मैटलर्जिकल उद्योगों में कम की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य में उद्योगों के लिए बिगली का अभाव भी पाया जाता है। राज्य की मातृकी योजना में विद्युत के विकास के लिए 927.5 करोड़ रु का प्रावधान किया गया था जो कुल योजना के व्यय का 31% था। योजना में माटरी जन-विद्युत परियोजना, छोटा तापीय विद्युत घर अनूपगढ़ पन-विजली व पन्ना लिमिटेड योजना वगैरह पर धनराशि व्यय करने राज्य में विद्युत की प्रत्यापित क्षमता में वृद्धि करने के कार्यक्रम रले गये थे।

3. पिछले वर्षों में राज्य में औद्योगिक सम्बन्धों में भी गिरावट आयी थी। भूतकाल में श्रीराम रेयौन्स कोटा को औद्योगिक विवाद के कारण काफी हानि उठानी पड़ी है। भरतपुर में मिन्को बैगन फैक्ट्री में तनावबन्दी से धति हुई है। कोटा, अलवर, भरतपुर व जयपुर जिलों में काफी लघु इकाइयाँ हड़ता के कारण बन्द हुयी हैं। मजदूर-संघों में परम्परा स्पर्धा व बोनस की मांग के कारण औद्योगिक विवाद बढ़े हैं। अतः सरकार को एक सक्रिय तथा 'यावहारिक' अम-नीति अपनानी चाहिए ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे और राज्य में प्रचामी उद्यमकर्त्ताओं को उद्योग लगाने के लिए काफी सहायता में आकर्षित किया जा सके।

4 हाल में राजस्थान वित्त निगम की कर्जों की वापसी की अदादगी में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसके कारणों को जांच की जानी चाहिए ताकि REC की समय पर पुराने कर्जों का नुगतान निल सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त मायूर सन्धि के प्रमुख सुझाव व सिफारिशें—

1. High Power Committee Report on Strategy for Industrial Development In Eighth Five Year Plan, Vol I 1989., Govt. of Rajasthan, Ch. V—Thrust Areas and Ch. VI—Conclusions pp. 31-48.

आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की ब्यूहरचना पर माथुर समिति (प्रध्यक्ष प्रोफसर एम वी माथुर) ने अपनी रिपोर्ट मुख्य मंत्री को 26 जून, 1989 का पेश की। इसमें औद्योगिक विकास के नये क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में विकास की नीतियों व आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

1 राज्य के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग प्रकार के उद्योग विकसित किये जाने चाहिए, जैसे, दक्षिणी राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग, पश्चिम में महार-तिब्बत क्षेत्र में कृषि-प्रोसेसिंग उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग तथा अर्धविकसित पश्चिमी जिलों में दक्षता-आधारित हस्तशिल्प उद्योग विकसित किये जाने चाहिए। जैतलमेर क्षेत्रों में स्टील ग्रैंड लाइमस्टोन व गैस-आधारित औद्योगिक इकाइयाँ भी विकसित की जा सकती हैं।

2 समिति ने जिन औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना है वे निम्नलिखित बताये हैं—इलेक्ट्रोनिक्स, कृषि आधारित व फूड-प्रोसेसिंग, खनन व खनिज-पदार्थ, पर्यटन (tourism) रतनमणि व जवाहरात उद्योग, तथा दस्तकारियों (थमडा व चमड़े की वस्तुओं सहित)।

3 आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% भाग औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जो वर्तमान स्तर का (प्रतिशत में) लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

4. वर्तमान में विनिर्माण (Manufacturing) का राज्य की आमदनी में लगभग 8-9% अंश है जिसे बढ़ाकर आठवीं योजना में 12% करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5 राज्य सरकार को उद्योगों को दो जाने वाली वर्तमान रियायतों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य सेवाओं की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। उन उद्योगों के विकास पर ज़ार देना चाहिए जिनमें राज्य को विशेष लाभ प्राप्त है जैसे पशु आधारित उद्योग व पर्यटन जवाहरात व आभूषण, खनिज-पदार्थ दस्तकारियाँ।

6 भविष्य में रोकों को औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए सभी भूमि प्रयाप्त करनी चाहिए जब वह अत्यावश्यक हो। जहाँ आगामी कुछ वर्षों में कोई उद्योग नहीं लगना है वहाँ भूमि को अयाप्त नहीं करना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

7. उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद को राज्य के औद्योगिक विकास की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से अपनी बैठक करनी चाहिए।

8. सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक सार्वजनिक उपक्रम, चयन बोर्ड (Selection Board) गठित किया जाना चाहिए जो कर्मचारियों के चयन की व्यवस्था करे।

9. भ्रष्टाचार को बिक्री-कर से मुक्त कर देना चाहिए जैसा कि बिहार सरकार ने किया है।

10. चमड़े व दस्तकारियों के लिए टेक्नोलोजी मिशन स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमारे शिल्पकारों को आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलोजी का लाभ मिल सके। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के साधन मिलाने होंगे जैसे उद्योग-निदेशालय, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी व ग्रामीण विकास एजेंसी पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग आदि।

माधुर समिति ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र में अधिक तेजी से प्रगति हो सकेगी। राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए अन्य सुझाव—

1971 से 1985 की अवधि में राजस्थान में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर (आधार-वर्ष 1970 = 100) 6% रही (इसमें विनिर्माण, खनन व विद्युत तीनों को शामिल किया गया है)। भविष्य में इसको और तेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में फैक्ट्री क्षेत्र व गैर-फैक्ट्री क्षेत्र दोनों में औद्योगिक माल का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान का समस्त भारत के फैक्ट्री-क्षेत्र में भ्रश 3% से अधिक करने के लिए काफी प्रयास करना होगा।

(1) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पूँजी-सन्निधि की व्यवस्था को पुन-जीवित करना—

सितम्बर 1988 के बाद राज्य में केन्द्रीय पूँजी-सन्निधि की स्कीम बंद कर दी गई जिससे पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पिछड़े इलाकों में लघु व मध्यम पैमाने की इकाइयों की स्थापना पर पूँजी-सन्निधि की सुविधा से काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अक्टूबर, 1988 से केन्द्रीय सन्निधि के बन्द होने से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण छा गया है। पहले पूर्णतया उद्योग/विहीन जिले में एक करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये की सन्निधि मिलने से उसकी स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिलता था। राजस्थान में केन्द्रीय सन्निधि की राशि 1981-82 में 2 करोड़ रु.

1. देखिए मेरे द्वारा प्रेषित लेख, (Industrial Structure and Industrial Incentives in Rajasthan, in Development of Rajasthan Challenge and Response, (Edited by Ashok Bapna, SID, Rajasthan Chapter, Jaipur) 1989, Ch. 9. pp. 166-167.

स दशकर 1984-85 में 8 करोड़ रु हो गई थी। इससे उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहन मिला था।

केन्द्रीय सभिन्धी स्तान व क्रवदूबर 1988 में दद हान के बाद अन्य राज्यों ने अपन सिष्ठ धवों के औद्योगिक विकास के लिए अपनी-अपनी नयी औद्योगिक नीतियां धाधित की ताकि इनम विकास की गति का बनाव रखा जा सके। उदाहरण के लिए, पन्चिमा बंगाल ने राजकीय सभिन्धी 15% से 30% कर दी जबकि केन्द्रीय सभिन्धी 10% से 15% तक हो थी। तमिलनाडु, ने पिछड़े "तालुकों" में राजकाय सभिन्धी देना चातू कर दिया। उत्तर प्रदेश ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए 10 करोड़ रु का एक उपक्रम-कीय (Venture fund) स्थापित किया है। हरियाणा ने पावर-होमिन्धी 50 हजार रु से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी ताकि उद्यमकर्ता अपन डोजल जेनरटिंग सेट लगा सकें।

इस प्रकार अन्य राज्यों ने कन्द्रीय सभिन्धी के घनाव को दूर करने का प्रयास किया है। राजस्थान को भी औद्योगिक रियायतों व प्रेरणाओं का एक नया पैकेज धोधित करना चाहिए ताकि हमारे राज्य से अन्य राज्यों की धार उद्योग व उद्योगपनियों का पलायन रुक सके। बंटे प्रतिधायी किस्म की सन्धिटी देन की होड अपन धाप में सहीं नहीं हाठी, लेकिन जब अन्य राज्य अपनी तरफ उद्यमकर्ताओं का आकर्षित करन लगे ता हमारे लिए भी उनसे धनिक आनर्पक रियायतें देन व घनाव काई विकल्प नहीं रह जाता।

(2) राज्य सरकार को बिभी-कर से मुक्ति, बिभी-कर आस्थगत, आदि की स्कीमों को द्दव्दर में सक्रिय रूप से लातू करता चाहिए। कोपो का घनाव हमम बानक नहीं हान देना चाहिए।

(3) उद्यमकर्ताओं की कायगीत पूंजी (Working Capital) की आवाय-कताओं का पूरा किया जाना चाहिए।

(4) उद्यमकर्ताओं पर लगे घनागमक नियन्त्रणों का भार कम किया जाना चाहिए। ताकि वे उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे सकें। इन सम्बन्ध में उद्यम-कताना स लगे बाउचीन की जानी चाहिए।

(5) विकास-केन्द्रों (growth-Centres) की नयी नीति में उद्योगों के लिए विकास-केन्द्रों का चयन पूरे माधानी से किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में घ्याप्त औद्योगिक गिरान की आनानता कम की जा सके और सकुचित विकास का लफ़ प्राप्त किया जा सके।

(6) घ्याप्तमभव पूंजी-महन उद्योगों के स्थापन पर अन-महन उद्योगों का धनिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(7) इन्फ्रस्ट्रक्चर—धावर, परिवहन जग, आदि का विकास तेगो से पूरा किया जाना चाहिए।

स्मरण रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, पूँजीगत सन्निधि की सुविधा, कर्ज की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करो की छूट, आदि अपने आप में औद्योगिक विकास की आवश्यक शर्तें हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। औद्योगिक विकास की उचित गति प्रदान करने के लिए सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियायती कर्ज, पूँजीगत-सन्निधि, नवीन व उन्नत टेक्नोलॉजी, उचित औद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त माल व बिजली की सुविधाएँ आदि सभी जरूरी हैं। लेकिन इनसे भी अधिक जरूरी है उचित औद्योगिक नियोजन जो निम्न चीजों को परिनामित करेगा :—

- (i) कृषि व उद्योग के बीच किस प्रकार की कड़ी हो,
- (ii) विभिन्न उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ी हो,
- (iii) विभिन्न जिलों, क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच किस प्रकार की कड़ी हो,
- (iv) उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र के बीच बटवारा किस प्रकार का हो,
- (v) एक वर्षीय, पंचवर्षीय व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन में समन्वय किया जाये।

उपयुक्त ढंग पर 'बैज्ञानिक' औद्योगिक नियोजन व "प्रखर" औद्योगिक व्यूहत्वता से ही औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है।

परिशिष्ट

(i) वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कुछ परियोजनाएँ इस प्रकार हैं

नाम व स्थान	उत्पादित वस्तु का नाम
1. बाँसवाड़ा सिन्टैक्स लि., बाँसवाड़ा	सिन्थेटिक यार्न
2. स्टैण्डर्ड वूलन्स लि., जोधपुर	कापेट यार्न (रग्स इकाई)
3. परताप राजस्थान स्पेशल स्टील लि., जयपुर	स्पेशल स्टील
4. भीलवाड़ा वूलटैक्स लि., भीलवाड़ा	कापेट यार्न (रग्स इकाई)
5. जयपुर सिन्टैक्स लि., बहरोडा	सिन्थेटिक यार्न
6. भरावली इस्पात लि., भलवर	स्पेशल स्टील (रग्स इकाई)
7. श्री राजस्थान सिन्टैक्स लि., डूंगरपुर	सिन्थेटिक यार्न
8. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., जयपुर	दवाएँ
9. राजस्थान ग्लायोक्सल लि., उदयपुर	ग्लायोक्सल (रग्स इकाई)
10. मॉडर्न थ्रेड्स इण्डिया लि., भीलवाड़ा	औद्योगिक धागा
11. राजस्थान वूलटैक्स लि., जयपुर	कापेट यार्न (रग्स इकाई)
12. जयपुर पोरीस्पिन लि., रीमस	सिन्थेटिक यार्न

- 13 राजस्थान एक्सप्लोजिव्स
एण्ड केमिकल्स लि., धौलपुर विस्फोटक
(detonators)
- 14 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड
इन्स्ट्रुमेंटेशन लि., जयपुर विद्युत मिल्क
टेस्टर (tester)
- (दूध विश्लेषक यन्त्र, इसे केन्द्रीय उपकरण भी माना गया है)
- 15 इरबी टक्सटाइल्स लि., जोधपुर सिन्थेटिक यार्न
- 16 लिस्पति फाइबरस एण्ड इण्डिया लि., झाड़ू रोड सिन्थेटिक यार्न
- 17 श्री ली सिन्थेटिक लि., उदयपुर " "
- 18 परताप राजस्थान कॉपर
फॉयल्स लि., जयपुर कॉपर फॉयल्स (foils) एण्ड
लैमिनेट्स (Laminates) (रंगण इकाई)
- 19 सर्राफ सिन्थेटिक (राजस्थान लि.) मलबर सिन्थेटिक यार्न
- 20 लेम्प्स एण्ड साइटिंग्स लि. मलबर श्री एस एस लेम्प्स (रंगण इकाई)
- 21 सुपर सिन्कोटेक्स (इण्डिया) लि., गुलाबपुरा सिन्थेटिक यार्न
- 22 कल्याण मुन्दम सीमेन्ट उद्योग, बासवाडा (रंगण इकाई)
- 23 श्री पाइप्स लि. हमीरगढ (जिला भीलवाडा)
- 24 स्वेडेशी सीमेन्ट लि., कोटपूतली

इन प्रकार समुक्त क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ सिन्थेटिक यार्न बनाती हैं एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।

(ii) रीको की सहायता-प्राप्त क्षेत्र की इकाइयाँ

(Assisted Sector Units)

रीको ने समुक्त क्षेत्र के अलावा सहायता-प्राप्त क्षेत्र की परियोजनाओं (Assisted Sector projects) को भी प्रोत्साहित किया है जिनमें कई इकाइयों में उत्पादन चालू हो गया है, कुछ क्रियान्वयन की प्रवस्था में हैं तथा कुछ इकाइयाँ प्लानहाल पाइप-लाइन में हैं। जिन इकाइयों में उत्पादन चालू हो गया है उनमें सूती व ऊनी उद्योगों, गैस-सिलेण्डर बनाने वाली इकाइयाँ, वनस्पति तथा प्रिंटाइट व सगमरस्टर आदि की इकाइयाँ हैं। वित्तीय साधनों के अभाव के कारण आजकल रीको समुक्त क्षेत्र की तुलना में सहायता-प्राप्त क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देन लगा है, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में पूँजी लगानी होती है।

रीको ने कुछ बड़ी सहायता प्राप्त इकाइयों की स्थापना में योगदान दिया है व अग्र प्रकार है :—

नाम व स्थान	उत्पादित वस्तु
1. मगलम् सीमेण्ट्स लि., मोडक (कोटा)	सीमेट
2. भजम पेपर मिल्स लि., भिवाडी	सिन्थेटिक यार्न
3. बेल्विनेटसं ग्रौफ इण्डिया लि., अलवर	रेफ्रिजरेटर्स व मोपेड
4. सेम्टस इन्डिया लि., भिवाडी	टी वी की पिक्चर ट्यूब
5. परसरामपुरिया सिन्थेटिक्स लि., भिवाडी	फिलाभेट यार्न की टेक्स्टाइलिंग
6. मोदी एल्केलीज एण्ड केमिकल्स लि. अलवर	कॉस्टिक सोडा व सहायक पदार्थ
7. इण्डेग (Indag) रबर लि., भिवाडी	कोल्ड टायर रिट्रॉडिंग

प्रश्न

- निम्न निगमों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए.—
 - (i) राजस्थान वित्त निगम,
 - (ii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम (रीको)
 - (iii) राजस्थान सधु उद्योग निगम
- योजनाकाल में राजस्थान के औद्योगिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियों की जाँच कीजिए। क्या आपकी राय में राज्य में भावी औद्योगिक विकास की स्थापक सम्भावनाएँ विद्यमान हैं? (Raj. 11 yr. T.D.C. 1980)
- पञ्चवर्षीय योजनाओं में राजस्थान की औद्योगिक प्रगति की समीक्षा कीजिए। राज्य के औद्योगिक विकास में राज्य सरकार की क्या भूमिका रही है? (Raj. 11yr. T. D. C., 1981)

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम

(Public Enterprises in Rajasthan)

योजनाबद्ध विधायन में सार्वजनिक उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। वे न केवल प्रासार-शक्ति के निर्माण में मदद देते हैं, बल्कि विद्युत क्षेत्रों के औद्योगिक विस्तार, योजना-समर्थन, नियंत्रण-उत्पत्ति व कई प्रकार से जन-व्यापक में सहयोग देते हैं।

पिछले अध्याय में बताया गया था कि राजस्थान में सार्वजनिक उपकरणों को दो भागों में बांटा जा सकता है (अ) केन्द्रीय सरकार के द्वारा स्थापित जिनमें उद्योग (आ) राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उद्योग।

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरण¹ — 19८5 में राजस्थान में कुल केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का 1.4% घन लगा था, जबकि 1970 में यह केवल 0.9% ही था। केन्द्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों में हिन्दुस्तान जिंक लि (देवारी, उदयपुर), हिन्दुस्तान कॉपर लि. (लिनडो), हिन्दुस्तान मर्यादित ट्यूब, अजमेर, इन्दूर-मेटल लि., कोटा, मायर्स सांन्ड्स लि. (हिन्दुस्तान सांन्ड्स, नि. की सहायक) मोहन बेकरीज (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर तथा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लि., बनारसपुरा, अजमेर के समीप (इसमें भारत सरकार का घन 51% है, इसे रीको की समुक्त क्षेत्र की इकाइयों में भी दिखाया गया है) गिने जाते हैं। 1987-88 में हिन्दुस्तान कॉपर लि को मूनापा हस्ता धा। एच एम टी लि. इन्जीनियरी, मुरझा व शाहन उद्योग व लिए प्रिंसीपल ग्राइण्डिंग मशीनों का उत्पादन करती है। जैसाकि पिछले अध्याय में बताया गया था, राष्ट्रीय घनस पावर निगम (NTPC) द्वारा कम्पा (कोटा) में गैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना में राज्य में केन्द्रीय विनियोगों में वृद्धि हुई है।

विभिन्न इकाइयों का मधुस्थ विवरण नीचे दिया जाता है

(1) हिन्दुस्तान जिंक लि — इसका स्तम्भ 2 खानों (दोनों राजस्थान में, एक मायस्रदण में तथा एक उडाया में) तथा 3 स्मल्टर्स है (एक राजस्थान, एक

1. Public Enterprises Survey, 1987-88, Vol 3, Part 1. 3। याच 1986 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का इकाइयों (केन्द्रीय क्षेत्र) में 715 करोड़ 41 लाख घन का पूँजी-विनियोजन किया गया (परिचा, 7-1187)

यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में शामिल की जाती है। इसे 1987-88 में 42 लाख रुपये का शुद्ध मूनाफा हुआ था।

अन्य—राजस्थान इयूम व फार्मिस्यूटिकल्स लि. की स्थापना नवम्बर 1978 में प्रधान कम्पनी IDPL की सहायक इकाई के रूप में रीको के साथ मयुक्त क्षेत्र में की गई थी। इसे लगातार घाटा उठाना पड़ा है। बिक्री के बार्डर में मिलने से उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है तथा छोटे उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। कम्पनी को कार्यशील पूँजी की कमी का भी सामना करना पड़ा है।

(घा) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1986-87 में इनकी संख्या 39 थी। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है:

(i) बंधानिक निगम/बोर्ड—इनकी संख्या 8 थी। इस श्रेणी में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (RSEB), राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान वित्त निगम राजस्थान राज्य बेयरहार्जिस निगम, राजस्थान हार्जिस बोर्ड तथा राजस्थान भूमि विकास निगम आते हैं।

(ii) पञ्जीकृत कम्पनियाँ—इनकी संख्या 16 थी और ये कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पञ्जीकृत हुयी थी। इनके नाम इस प्रकार हैं: बी गगानगर शूगर मिल्स लि स्टेट टेनरीज लि., स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि., रीको, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राज्य होटल निगम लि., पर्यटन विकास निगम लि., राज्य बीज निगम लि., कृषि-उद्योग निगम लि., सिज व कन्स्ट्रक्शन लि. तथा हथकरघा विकास निगम लि., जल साधन विकास निगम लि., राज्य वन विकास निगम लि., राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. तथा राज्य टेक्स्टाइल विकास निगम लि.। इनमें कई इकाइयों के नामों में निगम के बाद 'लिमिटेड' शब्द आने से ये कम्पनी संगठन में शामिल हो गई हैं।

(iii) पञ्जीकृत सहकारी समितियाँ—इस श्रेणी की 13 इकाइयाँ इस प्रकार थी: अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. राज्य मुनकर सहकारी सघ लि सहकारी डेयरी फेडरेशन लि., सहकारी भेड व कल विपणन फेडरेशन लि., राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन लि., सहकारी उपयोग सघ लि., श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि., केशोरायपाटन, तीन सहकारी स्थानिक मिल्स (गुलाबपुरा, गगानगर तथा हनुमानगढ़) सहकारी हार्जिस वित्त समिति लि., विलहन प्रोसेसिंग मिल्स, गजसिंहपुर, तथा जनजाति क्षेत्र विकास सघ लि.।

(iv) विभागीय उपक्रम—इस श्रेणी में निम्न 4 उपक्रम लिय गये हैं केमिकल वर्क्स (सोडियम सल्फेट फैक्ट्री), डीडबाना, सल्फेट वर्क्स, डीडबाना, राजकाय नमक वर्क्स, डीडबाना तथा राजकीय नमक वर्क्स, पंचपदरा।

इदृशा सार्वजनिक उपक्रमों में सहकारी संगठनों को शामिल नहीं किया जाता और इनमें वैधानिक निगम बोर्ड पजीकृत कंपनियों व विनागोय उपक्रमों को ही शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रम विभाग (सार्वजनिक उपक्रमों के स्रोत) द्वारा प्रकाशित "Public Enterprises Profile" में सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय उपलब्धियों में सहकारी इकाइयों को भी शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ इन सभी की इकट्ठी उपलब्धियों की सर्वा की जाती है।

सार्वजनिक उपक्रमों का पूँजीगत ढाँचा—1986-87 में इनमें (उपस्थित 39 उपक्रमों में) कुल लगायी गयी पूँजी (Capital employed)¹ 2781 करोड़ रु थी तथा कुल विनियोजित पूँजी (Capital invested)² 1779.6 करोड़ रुपय थी।

1986-87 में पूँजी व अवधि-वर्ज के रूप में कुल विनियोगों की दृष्टि में 89.5% धरा निम्न 9 उपक्रमों में था

राज्य विद्युत मण्डल भूमि विकास निगम आवागमन मण्डल, राजस्थान वित्त निगम व सीके। राज्य विद्युत बोर्ड का कुल घाटो में 72.0% धरा था। कुल घाटो का 89% धरा राज्य विद्युत बोर्ड भूमि विकास निगम राज्य सड़क परिवहन निगम, सहकारी डेपरी मध लि० तथा श्री केजोरामपाटन सहकारी मूलर मिल्स लि० का था।

स्मरण रहे कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (RSEB), राजस्थान हाउसिंग बोर्ड तथा राजस्थान हथकरघा विकास निगम लि बिना गेयर पूँजी या इक्विटी के मन्वसित किये जा रहे हैं। इन्हें अवधि-वर्ज पर प्राप्ति रहना पड़ता है।

राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों में पिछले वर्षों में वर्ज व गेयर पूँजी का अनुपात (debt-equity ratio) लगभग 8 : 1 रहा है जो काफी ऊँचा माना जा सकता है।

वित्तीय कार्य-सिद्धि (Financial Performance)—राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय कार्य-सिद्धि बहुत कमजोर रही है जो निम्न आकड़ों में प्रकट होती है।

- 1 लगायी गयी पूँजी (Capital employed) में शुद्ध मंदिर परिमन्मन्ति—चालू परिसम्पत्तियाँ धाती है।
- 2 विनियोजित पूँजी (Capital invested) में परिदत्त पूँजी—निम्न व मरप्लस + अवधि-वर्ज—संचयी घाटे (accumulated losses) घाटे हैं।
 $\text{नट वर्थ (net worth)} = \text{विनियोजित पूँजी} - \text{अवधि वर्ज घाटो}$

वर्ष	कर में पूर्व लाभ हानि (करान्त) (Losses before tax)		
1980-81	1	1985-86	(-) 97.0
1981-82	- 4	1986-87	(-) 16.0
1982-83	- 34		
1983-84	- 52		
1984-85	- 88	1980-87 तक मूल वर्षों में	
छठा मासिक मूल (-) 235		कुल घाटा = 306 करोड़ रु	

यस प्रकार छठी योजना के पांच वर्षों में कर में पूर्व घाट की कुल राशि 235 करोड़ रु की है जिसमें लगभग 90% घाटा अर्द्धत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का था। इन राजस्थान के मासिक उपक्रमों में मासिक घाटा होने का कारण राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल है।

राजस्थान में मासिक उपक्रमों का विकास में विनिर्माण पूर्ण पर प्रतिक्रिया की दर (मार्गदर्शकों में पूर्व केवल मुद्रा का दर) निम्न तालिका में दिया जा रहा है ¹

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
राजस्थान	0.61%	(-) 1.48%	4.49%	3.55%
भारत	10.1%	10.8%	10.6%	7.0%

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में मासिक उपक्रमों में लगे पूंजी पर प्रतिक्रिया की दर 1983-87 का अवधि में काफी नाचा था। यह 1986-87 में 3.55% रहा। इस निम्नरीत समस्या के लिए ऊँचा रखा है। इस प्रकार राजस्थान के मासिक उपक्रमों में प्रतिक्रिया की दर का नाचा रखा एक चिन्ता का विषय है।

1 Public Enterprises Profile- 1986-87 BPE Govt of Raj
1988 p 8

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ की माया नेट वर्थ (net worth)¹ (परिदत्त पूँजी + रिजर्व व सरप्लस—संचयी घाटे) के अनुपात के रूप में :—वित्तीय कार्य-सिद्धि के अध्ययन में वर के पश्चात् शुद्ध लाभ को शुद्ध वर्थ के अनुपात के रूप में भी देखा जा सकता है। राजस्थान में चार वर्षों की स्थिति बहुत गम्भीर रही है जो निम्न आंकड़ों में स्पष्ट हो जाती है—

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
राजस्थान	(-) 7.5%	(-) 14%	(-) 8.9%	(-) 2.3%
भारत	1.6%	2.7%	2.8%	3.4%

इस प्रकार राजस्थान में 1984-85 में विशुद्ध घाटा शुद्ध वर्थ का 14% तथा 1986-87 में 2.3% रहा। स्मरण रहे कि यहाँ नेट वर्थ में राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को दिया गया कर्ज भी ऋण-पूँजी ही मान लिया गया है। यदि इस नेट वर्थ में शामिल नहीं किया जाता तो शुद्ध घाटों का अनुपात नेट वर्थ में बहुत ऊँचा निकलता, जैसा कि स्वयं यूरोप न अपनी पूर्ण रिपोर्टों में दर्शाया था।

हालांकि 1986-87 में समग्र रूप से वित्तीय कार्य-सिद्धि निराशाजनक रही, फिर भी निम्न 5 उपक्रमों ने मुनाफा अर्जित किया, जैसे राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य देयरहाउसिंग निगम, राजस्थान वित्त निगम, राज्य रानन विकास निगम लि., तथा रीको।

राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की गम्भीर वित्तीय दशा के कारण—सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य-सिद्धि का मूल्यांकन केवल ग्राम-हानि के आकड़ों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनका रोजगार, उत्पादन, पिछड़े क्षेत्रों के विकास व सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि, आदि के रूप में भी योगदान देखा जाना चाहिए। लेकिन इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि यथासम्भव उनके वित्तीय घाटे कम किये जा सकें। इसलिए घाटे के कारणों का उपक्रमानुसार अध्ययन किया जाना चाहिए। उपक्रमों में कई कारणों से घाटे हो सकते हैं जैसे गलत परियोजना (wrong project) का चुनाव, पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धि का अभाव, मांग को कमी, प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ, गलत मूल्य-नीति, आवश्यकता से अधिक श्रमिकों की नियुक्ति, ग़राब श्रम-सम्बन्ध, आदि।

राज्य विद्युत मण्डल के घाटों का कारण

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की भारी मात्रा में घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ा है। 1983-84 में 44 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जो बढ़कर 1986-87 में 90 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसका संचयी घाटा काफी ऊँचा हो गया है।

1. राज्य विद्युत मण्डल को राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण उनकी विशेष प्रकृति के कारण ऋण-पूँजी मान लिया गया है।

1 इनने जारी घाटे का मुख्य कारण यह है कि साधनों में निरन्तर वृद्धि होती गई है जबकि विद्युत-प्रभुत्व (electricity tariffs) में घातुपात्रिक वृद्धि नहीं हो पायी है। अगस्त 1985 में विद्युत-प्रभुत्व में वृद्धि की गई थी, लेकिन इसके अच्छे परिणाम 1985-86 व 1986-87 के वर्षों में मिले। फिर भी घाटे की दशा जारी रही। उसका प्रभाव यह है कि राज्य विद्युत मण्डल को घाटा कम करने में जारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

2 राजस्थान में विद्युत में ट्रान्समिशन व वितरण की हानि का अनुपात 26.54% था है, जबकि समस्त देश का औसत 21.7% था है। अनुमान है कि यदि राजस्थान में ट्रान्समिशन व वितरण की हानि का घन राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाय तो विद्युत मण्डल का वार्षिक घाटा 18 करोड़ रु कम हो जायगा। ट्रान्समिशन व वितरण का घाटा 1% कम होने पर 3½ करोड़ रु बचन होती है।

3 राजस्थान में विद्युत इकाइयों में धार्मिक व्यवसायों में ज्यादा लोभ है। इन इकाइयों में प्रतिरिक्त श्रम की समस्या पायी जाती है। इकाइयों के वार्षिक सर्वेक्षण (एम्प्लॉयमेंट सर्वे), 1984-85 के अनुसार राजस्थान में कुल पेशेवर धर्म-कारियों का लगभग 26% अर्ध विद्युत में लगा था, जबकि समस्त देश के लिए यह औसत 11.5% था। 1984-85 में ही राजस्थान में पूँजी-उत्पत्ति अनुपात¹ विद्युत-क्षेत्र में 1:½ : 1 पाया गया जबकि भारत के लिए यह 8:7:1 रहा था।

इस प्रकार विद्युत मंडल को ऊँचे पूँजी-उत्पत्ति-अनुपात व प्रतिरिक्त श्रम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जलपुर व अजमेर के निर्माता मण्डलों में हजारों तकनीकी व दक्ष धार्मिक मीठे हैं, फिर भी 132 व 220 क की लाइनों का निर्माण करने के लिए प्रायोजन ठेकेदारों की करीबी रूपरेखा दिये गये हैं। ऐसी दशा में घाटा होना स्वाभाविक है।

4 विद्युत के वित्तों की राशि सही नहीं होती। बिजली की चोरी होने से कम राशि के वित्त बनाये जाते हैं। 1987 में विद्युत मंडल ने कोटा की एक फर्म का मामला सर्वोच्च कोर्ट में उठा है जिसमें 17 करोड़ रु. के ऋण की राशि का मुहताब विद्युत मंडल को प्राप्त होगा। हालांकि यह राशि 24 समस्त बिजली में वसूल की जायगा, फिर भी स्पष्ट है कि बिजली की चोरी रोकने का प्रयास करने में स्थिति सुधरनी और इसे दक्षिण में और सुधारा जाना चाहिए।

सांख्यिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव—सांख्यिक उपक्रमों की दशा का सुधारण के लिए अर्जुन नन गुप्ता समिति व अना रिपोर्ट पर की सी. जो मास्यद्विक पत्रिका Mainstream के मार्च, 14 व 21

1. पूँजी उत्पत्ति अनुपात ज्ञाने के लिए स्थिर पूँजी में इन्हें जोड़े रूप मूल्य का भाग दिया गया है।

1987 के प्रंको में प्रकाशित हुयी थी। मई, 1987 में प्रोफेसर मुखर्जी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) ने प्रधान मंत्री को Public Enterprise in India . Some Current Issues पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को केन्द्र व राज्य स्तरों पर अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे।

चक्रवर्ती समिति का मत है कि अलग अलग क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों व अलग-अलग इकाइयों की समस्याओं के हल के लिए विशिष्ट समाधान ढूँढने होंगे। समिति ने उत्पादन क्षमता के उपयोग को बढ़ाने पर बल दिया है।

जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार राजस्थान की नियोजित अर्थव्यवस्था में भी सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता व उपसम्पत्तियों का महत्व है। इसलिए इनकी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उपक्रमानुसार कार्यक्रम बनाये जाने आवश्यक है। पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव सामने आये हैं जिन्हें कार्यान्वित करने से स्थिति में अवश्य सुधार होगा :

1. प्रमुख अधिकारियों व प्रबन्ध संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि—सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों व पूर्णकालिक प्रबन्ध संचालकों को कम से कम पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। “प्रबन्ध में व्यवसायीकरण” की नितान्त आवश्यकता है। दो वर्ष तक की अवधि के डेप्यूटेशन पर अध्यक्षों व प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के प्रबन्ध में दक्षता व निरन्तरता नहीं आ पाती।

2. स्वायत्तता (Autonomy)—सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे उपक्रम के हित में शीघ्रता से सही निर्णय ले सकें। मन्त्रालय व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध में उचित ताल-मेल होना चाहिए।

3. लेखादेयता (Accountability)—जहाँ एक तरफ प्रबन्ध में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, वहाँ दूसरी तरफ प्रबन्धकों पर कार्य-सिद्धि के सम्बन्ध में अधिक जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। इसको कारगर बनाने के लिए प्रबन्धकों से मेमो-रेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MOUs) कराये जाने चाहिए, जिनमें आवश्यक विचार-विमर्श के बाद उत्पादन के लक्ष्य, लागू के लक्ष्य आदि का वर्णन होना चाहिए। ऐसा केन्द्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग या कोयला उद्योग में चालू किया गया है, हालांकि उसके परिणामों का मूल्यांकन करने में अभी समय लगेगा।

स्वायत्तता व लेखादेयता के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में प्रतियोगी वातावरण में काम करने वाली इकाइयों व अन्य प्रकार की इकाइयों में अन्तर किया जाना चाहिए।

4 औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों में श्रम को प्रवन्ध व पूर्णता में सम्मेलनारी दी जानी चाहिए जिससे श्रमिकों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ने में अधिक योगदान मिलेगा। इस दिशा में मजदूर-संघों का समुचित सहयोग वांछित होगा।¹

5 प्रतिरिक्त श्रमिकों की समस्या का समाधान यह होना चाहिए कि उनको प्रशिक्षण देकर अन्य प्रकार की क्रियाओं में लगाया जाना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों की क्रियाओं का विविधीकरण (diversification) किया जाना चाहिए।

6 निरन्तर घाटा उठाने वाले इकाइयों को बन्द कर देना चाहिए तथा श्रमिकों को अन्य कामों में लगाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने कर्षों पर लेनी चाहिए।

7 घने हुए उपक्रमों के 'निजीकरण' (privatisation) का प्रयास किया जाना चाहिए। यह प्रारम्भ में प्रवन्ध में किया जा सकता है तथा बाद में स्वामित्व में। यदि घाटा उठाने वाली इकाइयों को वार्षिक "सीज" की निर्धारित राशि पर निजी कंपनियों/निजी व्यक्तियों द्वारा चलाने का निर्णय किया जाय तो उसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में सोवियत संघ, डी.डी.आर. तथा राजकीय ऊनी मिल, वीकानेर का अनुभव बहुत सुखद व उत्साहवर्धक नहीं रहा है क्योंकि 'सीज' की राशि का जुगतान न होने से न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है।

8 राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विस्तृत अध्ययन करवाना चाहिए जिनमें पिछले तीन-चार सालों से लगातार घाटा हो रहा है और भविष्य में भी वित्तीय स्थिति के सुधरने के आसार नहीं हैं। उनकी रिपोर्टों पर शीघ्र उचित कार्यवाही होनी चाहिए।

9 जिस प्रकार केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र पर एक प्रवेत पत्र तैयार कर रहा है, उसी प्रकार राज्य सरकार को भी इनके सम्बन्ध में एक प्रवेत पत्र बनवाना चाहिए जिनमें उनकी मूल समस्याओं पर उपक्रमानुसार विचार किया जाय तथा भविष्य में सुधार के लिए सुझाव पेश किये जाएँ। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष—आशा है उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर राजस्थान में आगामी वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय दशा में सुधार होगा जिससे इनके भावी

1. "Workers" participation in management along with issue of equity shares as bonus is proposed as means of increasing the morale of the workers and raising productivity", Chakravarty report, May 1987.

विकास के लिए साधन जुटाने में मदद मिलेगी। पिछले वर्षों में इनमें घाटे की दशा के पाये जाने के कारण आम जनता में इनकी उपयोगिता व उत्पादेयता के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया है जिसे दूर करने के लिए इनमें प्रबन्धकीय कार्यकुशलता का विकास करना आवश्यक हो गया है। एक मजबूत, कार्यकुशल व प्रावैगिक सार्वजनिक क्षेत्र नियोजित घर्षणवस्था का 'हृदय' होता है तथा एक दुर्बल, प्रकार्यकुशल व गतिहीन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन को निष्प्राण बना देता है। अतः इस क्षेत्र को अधिक सजीव व अधिक सबस बनाना सभी के हित में होगा।

प्रश्न

1. राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय कार्यसिद्धि का परिचय दीजिए तथा इसको सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए।
2. राजस्थान राज्य-विद्युत बोर्ड को निरन्तर घाटा क्यों होता है? इन घाटों को कम करने के सम्बन्ध में व्यावहारिक सुझाव दीजिए।

35

राजस्थान में आर्थिक नियोजन

(Economic Planning in Rajasthan)

नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान की आर्थिक स्थिति

पहले बतलाया जा चुका है कि राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश' (a backward region in a backward economy) माना गया है। राज्य में वर्षों का वार्षिक औसत कम रहता है और उत्तर-पश्चिमी व पश्चिमी मार्गों में बहुत कम वर्षा होने एवं बारूक रेगिस्तान पाये जाने के कारण आर्थिक विकास में काफी कठिनाइयाँ घानी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन केवल 29 लाख टन हुआ था और 1951-52 में कुल रिपोटिंग क्षेत्र का लगभग 27% भाग ही झुंड बोया गया क्षेत्र (net area sown) था। उस समय सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हेक्टेयर था जो कुल कृषि क्षेत्रफल का केवल 12% था।

राज्य में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का बड़ा अभाव था। 1950-51 के अन्त में विद्युत की प्रस्तावित क्षमता केवल 8 मेगावाट थी और 42 स्थावरी को ही बिजली मिली हुई थी। केवल 17,339 किलोमीटर में सड़कें थीं। सबक, पानी व बिजली के अभाव में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था।

राज्य शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ था। 1950-51 के अन्त में 6-11 वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाने वालों का अनुपात 16.6%, 11-14 वर्ष की उम्र वालों में 5.4% एवं 14-17 वर्ष की उम्र वालों में 1.8% ही था। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का भी पता लगता है। 1950-51 के अन्त में अस्पताल में रोगियों की बिस्तरों की संख्या केवल 5,720 थी। परिवार नियोजन केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) की स्थापना ही नहीं हुई थी। अस्पतालों व दवाखानों की संख्या भी बहुत सीमित थी। एनोर्बिक अस्पताल 234 व डिस्पेन्सरी 156 तथा आयुर्वेदिक अस्पताल 14 व डिस्पेन्सरी 33 ही थे।

इस अध्याय में हम नियोजित विकास के 38 वर्षों (1951-89) की प्रगति का वर्णन करेंगे। विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये व्यय पर भी प्रकाश डाला जायेगा।

राजस्थान में नियोजित विकास के 38 वर्ष

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्थान का निर्माण 19 छोटे-छोटे राज्यों व तीन चीफशिप् के एकीकरण से हुआ था। ये राज्य आकार, जनसंख्या, राजनीतिक महत्व, प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी भिन्न व असमान स्तर वाले थे। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में प्रारम्भ होकर 1956 में पूरी हुई। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य एकीकरण की समस्याओं में उलझा हुआ था। उस समय राज्य में भावी विकास का अनुमान लगाने के लिए आधारभूत आंकड़ों का भी नितांत अभाव था।

राजस्थान में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय की राशियाँ निम्न तालिका में दी गई हैं।¹

तालिका 1.

(करोड़ रुपये में)

प्रस्तावित व्यय की राशि	वास्तविक व्यय की राशि
प्रथम योजना	54.5
द्वितीय योजना	105.3
तृतीय योजना	236.0
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	132.7
चतुर्थ योजना	306.2
पंचम योजना	847.2
वर्ष 1979-80 की योजना	275.0
छठी योजना (1980-85)	2,025
सातवीं योजना (1985-90)	3000
1985-88	1600
1988-89	710
1989-90	795
	योजना जारी

तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि 54 करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना में 103 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में 213 करोड़ रुपये, 1966-69 के तीन वर्षों में 137 करोड़ रुपये व चतुर्थ योजना में 309 करोड़ रुपये हो गई। पान्चवी योजना की अवधि में राज्य सरकार ने सार्व-

1. धाय व्ययक अध्ययन, 1989-90, पृ. 46 व 48 तथा पृ. 123-124 (DES) Jaipur).

जनिक क्षेत्र में व्यय हेतु 847 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था, लेकिन वास्तविक व्यय की राशि 858 करोड़ रुपये रही।

1979-80 की वार्षिक योजना में 290 करोड़ रुपये व्यय हुये। छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रु. रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय लगभग 2131 करोड़ रु. रहा है।

सातवीं योजना का आकार 3000 करोड़ रु. रखा गया था जो छठी योजना में लगभग 48 प्रतिशत अधिक था। ताजा अनुमानों के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय लगभग 3105 करोड़ रु. रहेगा।

आगे तालिका 2 में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक व्यय का विभिन्न भदों पर आवंटन दर्शाया गया है। इसमें हमने वास्तविक व्यय का आवंटन को ही लिया है, केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) का ही प्रस्तावित आवंटन दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई व शक्ति को दी गई है जो उचित मानी जा सकती है। प्रथम योजना में कुल व्यय का 58.3% सिंचाई व शक्ति पर व्यय किया गया जो पंचम योजना में भी लगभग उतना ही (57.2%) रहा। छठी योजना में यह 52.6% रहा। कृषि सहकारिता व सामुदायिक विकास पर प्रथम योजना में लगभग 13% व्यय हुआ, जो छठी योजना में 11.4 रहा। राज्य सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, चिकित्सा, जल सप्लाई) की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ था। अतः इनके विकास को भी ऊँची प्राथमिकता दी गई है। प्रथम योजना के कुल व्यय के 17% से प्रारम्भ वाले चतुर्थ योजना में इसे 24% तक पहुँचा दिया गया था। पंचम योजना में यह पुनः 17.4% पर आ गया तथा छठी योजना में 20% रहा। इस प्रकार राजस्थान एक तरफ सिंचाई व बिजली का विकास करने में लगा रहा और दूसरी तरफ इसने जन-बलाए के लिए सामाजिक सेवाओं के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता दी है।

पिछले 38 वर्षों में विभिन्न पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक व्यय के आवंटन का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी योजनाओं की प्राथमिकताएँ लगभग एक सी रही हैं। योजनाओं में सार्वजनिक व्यय का लगभग आधा भाग सिंचाई व शक्ति पर तथा 1/5 भाग सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया जाता रहा है।

अब हम विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय एवं प्रगति का उल्लेख करेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में आधारेभूत आँकड़ों का अभाव होते हुए भी योजना की प्राथमिकताएँ बिल्कुल स्पष्ट थीं। योजना का प्रमुख लक्ष्य सिंचाई की सुविधाओं

योजनाओं में सांख्यिक व्यय की स्थिति¹
(कुल वास्तविक व्यय में %)

विकास का शीर्षक	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चौथी योजना	पाँचम योजना	1979-80	छठी योजना 80-85 (प्रस्तावित)	सातवीं योजना 85-90
1. कृषि व सहायक कार्यक्रम	6.6	11.0	11.3	14.6	8.2	9.3	17.6	10.2 ²
2. सहकारिता व सामुदायिक विकास	6.0	14.0	8.0	3.7	2.7	1.8	1.6	1.5
3. सिंचाई व शक्ति	58.3	37.2	54.4	60.6	58.4	57.2	54.8	53.7
4. उद्योग व खनन	0.8	3.3	1.4	1.5	2.6	4.0	4.1	3.9
5. परिवहन, संचार व पर्यटन	10.3	9.8	4.7	3.2	3.2	9.8	7.8	11.8
6. सामाजिक सेवाएँ	16.9	23.6	19.7	15.0	24.0	17.4	13.7	19.8
7. विविध	1.1	1.1	0.5	0.9	0.9	0.5	0.4	0.5
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	54.1	102.7	212.7	136.8	308.8	857.6	290.2	2130.7
								3000.0

1. आय-व्ययक अध्ययन राजस्थान, 1989-90, p. 48 तथा p. 123-124. (प्रतिशत निकाले गये हैं)

2. इसमें कृषि, सम्बद्ध सेवाएँ व ग्रामीण विकास पर व्यय शामिल है।

में वृद्धि करना था, इसलिए प्रथम योजना में साखटा व अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई की परिचायनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम योजना में 64.5 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय 54.1 करोड़ रुपये हुआ, जिसका विभिन्न मदों पर वितरण पहले दिया जा चुका है।

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में कुल व्यय का 58.3% सिंचाई व शक्ति पर खर्च किया गया। प्रथम योजना में कृषि क्षेत्रफल के विस्तार एवं सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होने से साखटाओं का उत्पादन 1955-56 में 42.4 लाख टन हुआ था। सिंचित क्षेत्रफल 15.93 लाख हेक्टेयर हो गया था। शक्ति की प्रस्तापित क्षमता 15 मेगावाट है। यद्यपि जो योजना के प्रारम्भ की शुरुआत में लगभग दुगुनी थी। योजना में 17% व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया गया जिससे शिक्षा व चिकित्सा आदि की सुविधाओं का विस्तार हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

जब द्वितीय योजना का निर्माण किया गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हो गयी थी। इसलिए इस योजना का आकार बड़ा रखा गया। सिंचाई व शक्ति पर आवश्यक धन देना जारी रखा गया और इस अवधि में सिंचाई व शक्ति के कुछ बड़े कार्यक्रमों को चालू किया गया। जागीरदारी, जमींदारी व विस्वेदारी प्रथाओं की समाप्ति से गांवों में सामंती प्रथा का मिटाने की दशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

द्वितीय योजना में 105.3 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान रखा गया था। लेकिन योजना में वास्तविक व्यय 102.7 करोड़ रुपये का हुआ जिसका विभिन्न मदों पर प्रतिशत आवंटन पहले दिया जा चुका है।

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में कुल वास्तविक व्यय का 37.2% सिंचाई व शक्ति पर किया गया जो प्रथम योजना की शुरुआत में नीचा था। सामाजिक सेवाओं पर लगभग 24% राशि व्यय की गयी। उद्योग व खनन पर केवल 3.3% राशि ही व्यय की गयी।

द्वितीय योजना में साखटाओं के धनसंचय अनिच्छित उत्पादन समझौता काफी बढ़े लेकिन 1960-61 में भोजप की प्रतिवृत्तता के कारण वास्तविक उत्पादन 45.5 लाख टन हो हुआ था। 1955-56 के उत्पादन से थोड़ा ही अधिक था। प्रतिवृत्त उत्पादन समझौता का वास्तविक साम 1961-62 में मिला, जबकि साखटाओं का वास्तविक उत्पादन बढ़कर 55.7 लाख टन हो गया था। द्वितीय योजना के अन्त में विविध क्षेत्र 17.5 लाख हेक्टेयर हो गया था। विद्युत की प्रस्तापित क्षमता 1960-61 में 1955-56 की शुरुआत में चौगुनी से भी अधिक हो गई थी। 1960-61 के अन्त में विद्युत की प्रस्तापित क्षमता 60 मेगावाट हो गयी थी। सामाजिक सेवाओं

का भी विस्तार किया गया और शहरी क्षेत्रों में जल की पूर्ति के कार्यक्रम लागू किये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)

तृतीय योजना के प्रारम्भ में राज्य में आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा काफी सीमा तक तैयार हो गया था। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो जाने से गहन कृषि की पद्धतियों का उपयोग करना सम्भव हो गया था। शक्ति व यातायात का विकास होने से उद्योगों की स्थापना करना सम्भव हो गया था। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप प्रशिक्षित व योग्यता-प्राप्त शक्तियों की अधिक उपलब्धि होने लग गई थी। इन सब बातों के कारण तृतीय योजना का आकार द्वितीय योजना का लगभग दुगुना रखा गया और 236 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय लगभग 213 करोड़ रु. ही हो पाया जिसका विवरण तालिका 2 में दिया जा चुका है।

उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजना में सिंचाई व शक्ति पर कुल व्यय का लगभग 54% अंश व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 20% किया गया जो पहले से मात्रा की दृष्टि से काफी अधिक था। 1962 में चीनी सरकारों के बाद समस्त राष्ट्र में कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया और चुने हुए क्षेत्रों में गहन विकास की नीति अपनायी गयी। इसके लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम (I. A. D. P.) तथा पेंकेज प्रोग्राम एंव गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (I. A. A. P.) व तीव्र प्रभाव दिखाने वाले कार्यक्रम (crash programmes) अपनाये गये ताकि उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सके। तृतीय योजना में काफी तनाव व दबाव की स्थिति रहने से पहले के विनियोगों से शीघ्र प्रतिकूल प्राप्त करने की नीति अपनायी गयी। इसलिए चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया और पुराने लाभों को सुदृढ़ करने की दिशा में अधिक प्रयास किये गये।

तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति

तृतीय योजना की प्रगति वित्तीय दृष्टि से तो सन्तोषजनक रही, लेकिन इस अवधि में बार-बार एंव व्यापक रूप में मकाल व प्रभाव की परिस्थितियों ने अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाव डाले। 1963-64 व 1965-66 के अकालों की मीषणता अमृतपूर्व थी। खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1961-62 में 55.7 लाख टन के स्तर पर पहुँच चुका था, वह 1965-66 में केवल 38.4 लाख टन हो रह गया। यदि इन समस्याधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय तो तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक मानी जा सकती है।

1965-66 में सिंचित क्षेत्र 20.7 लाख हेक्टेयर हो गया जो 1960-61 की तुलना में लगभग 3.2 लाख हेक्टेयर अधिक था। गांधीसागर क्षेत्र में वर्षा के अभाव

के कारण उत्पन्न गम्भीर कठिनाइयों के बावजूद शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 65 मेगावाट से बढ़कर 96 मेगावाट (इयूटी) हो गयी। योजनाओं के अन्त में 1,242 स्थानों में बिजली की व्यवस्था कर दी गयी। शक्ति के क्षेत्र में किये गये विनियोगों का पूरा लाभ तृतीय योजना की अवधि में नहीं मिल पाया क्योंकि सतपुड़ा, राणाप्रताप सागर व भाखड़ा (दाहिने भाग) की बड़ी परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हो गया था। इसके लाभ 1966-67 से आगे की अवधि में मिल सके। योजना के अन्तिम वर्षों में शक्ति के अभाव व औद्योगिक विकास को धक्का पहुँचा, यद्यपि विकास का आधारभूत ढाँचा बहुत कुछ सुधर चुका था।

सम्भवतः तृतीय योजना में सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्राप्त किये गये। राज्य में शिक्षा का विकास हुआ। चिकित्सा की सुविधाओं के विस्तार एवं बीमारियों के नियन्त्रण व उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। योजनाकाल में तीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गये और कई शहरों व गांवों में जल-पूर्ति के कार्यक्रम लागू किये गये। विकास के विस्तृत कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया गया।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)

1965 में पाकिस्तान से संपर्क के बाद विदेशी सहायता के सम्बन्ध में काफी अनिश्चितता की दशा उत्पन्न हो गयी और 1965-66 व 1966-67 में लगातार दो वर्षों तक सूखा व प्रकाश घटने से विकास के लिए उपलब्ध साधनों का अभाव रहा जिससे चतुष्ष पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1966 में प्रारम्भ नहीं की जा सकी। 1966-69 की अवधि में वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित करके नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखा गया। इस अवधि में पुराने लानों को बनाये रखने एवं विनियोगों से शीघ्र प्रतिकूल प्राप्त करने के प्रयास किये गये।

साद्य स्थिति के जटिल होने के कारण कृषि में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम अपनाये गये। शक्ति के क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए बिजली की लाइनों के निर्माण पर जोर दिया गया। साधनों के अभाव के कारण शिक्षा, चिकित्सा व सड़कों के विकास पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया जा सका। ग्रामीण जल-पूर्ति का कार्य ज्यादा तजी से प्रगति नहीं कर सका।

तीन वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय लगभग 137 करोड़ रुपये का हुआ, जिसका आवंटन तालिका 2 में दिया गया है।

उस तालिका से प्रतीत होता है कि कुल व्यय का लगभग 61% सिंचाई व शक्ति पर हुआ और सामाजिक सेवाओं पर 15.5% हुआ। इस प्रकार सिंचाई व शक्ति को पहले से दी जाने वाली प्राथमिकता में और वृद्धि की गयी। सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले प्रतिशत व्यय में द्वितीय व तृतीय योजनाओं की तुलना में

कमी हो गयी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधनों के अभाव में इस अवधि में योजनाओं की प्राथमिकताओं में मामूली फेरबदल करना आवश्यक हो गया था।

तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में आर्थिक प्रगति

ऊपर बताया जा चुका है कि 1966-67 के तीन वर्षों में से दो वर्ष 1966-67 व 1968-69 अकाल व सूखे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुँची थी।

अनेक बठिनाइयों के बावजूद भी वार्षिक योजनाओं की अवधि में कुछ क्षेत्रों में प्रगति जारी रही। 1967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन 66 लाख टन हुआ जबकि 1966-67 में 43.5 लाख टन हुआ था। 1968-69 में खाद्यान्नों का उत्पादन पुनः घटकर 35.5 लाख टन पर आ गया। शक्ति की क्षमता तृतीय योजना के अन्त में 96 मेगावाट से बढ़कर 1968-69 के अन्त में 174 मेगावाट हो गयी थी। 1967-68 में ग्रीष्मकाल परियोजना के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो जाने से पिछले वर्षों में की गयी विद्युत शक्ति की कटौतियाँ हटा ली गयी और औद्योगिक क्षेत्र में विनियोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं।

तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति जारी रही। स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा। बोम रियो पर नियन्त्रण व परिवार नियोजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। ग्रामीण जल-पूर्ति व शहरी जल-पूर्ति के कार्यक्रम आगे बढ़ाये गये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1969 में प्रारम्भ हो गयी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था। विकास के क्रम में बाधा न हो इसके लिए वार्षिक योजनाएँ जारी रखी गयीं। योजना में 306 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 309 करोड़ रुपये का हुआ जिसका आवंटन तालिका 2 में दिया जा चुका है। इस योजना में मा 58.4 प्रतिशत राशि निचाई व शक्ति पर व्यय की गई। सामाजिक सेवाओं पर 24 प्रतिशत व्यय हुआ जो प्रतिगत की दृष्टि से पुनः द्वितीय योजना के स्तर पर आ गया था।

पूर्व योजना की भाँति चतुर्थ योजना में भी आर्थिक विकास की अधिकतम दर प्राप्त करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएँ बढ़ाने तथा राजस्थान नहर व चम्बल कमान्ड क्षेत्रों का विकास करने और गरीब लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था। इसके लिए चालू परियोजनाओं व कार्यक्रमों को पूरा करना आवश्यक समझा गया। योजना में निचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई ताकि कृषिगत विकास का आधार सुदृढ़ हो सके।

चतुर्थ योजना की उपलब्धियाँ

राज्य की चतुर्थ योजना की अवधि में प्रतिकूल मौसमों व भूकालों का सामना करना पड़ा। फिर भी अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1968-69 में 5.24 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1973-74 में 10.54 लाख हेक्टेयर कर दिया गया। 1968-69 में सामान्यिक उर्वरकों का उपयोग 30 हजार टन से बढ़कर 1973-74 में लगभग 74 हजार टन हो गया। 1973-74 में खाद्यान्नों का उत्पादन 67.2 लाख टन रहा जो 1970-71 के 88.4 लाख टन से काफी कम था। 1968-69 में सभी साधनों से कुल सिंचाई क्षेत्रफल 21.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1973-74 में 26.2 लाख हेक्टेयर हो गया था।

पावर की प्रस्थापित क्षमता 1968-69 में 174 मेगावाट से बढ़कर 1973-74 में 432 मेगावाट पर आ गई थी।

चतुर्थ योजना की अवधि में बज्रपति तेल, सीमेंट, पावर बेल्स, सूती धागे, चीनी एवं ताइलोन के धागे आदि के उद्योग स्थापित किये गये। दिल्ली की कमी व प्रग्नेस साधनों के बावजूद औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। राज्य में केन्द्रीय सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनियोग की राशि 1966-67 में 17 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 100 करोड़ रुपये हो गयी थी। चतुर्थ योजना की अवधि के अन्त में मामूर-कोटडा की खानों से प्राप्त रॉक-फॉस्फेट से 6.23 करोड़ रुपये की प्राय हुई। योजना में ताँबा, कच्चे लोहे, धातव, चाँदी, लोहे व कैल्साइट का उत्पादन बढ़ा था।

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप—राज्य सरकार ने जुलाई, 1973 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके योजना आयोग के समक्ष पेश किया था। इसमें राज्य की योजना का आकार 635 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था। लेकिन वास्तविक धन की कुल राशि 858 करोड़ रु. रही। यह योजना के प्रारूप में प्रस्तावित राशि से काफी अधिक थी।

उद्देश्य व मूल नीति—विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये गये ताकि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुँचे। उनकी रोजगार देने व उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया गया। राज्य में कृषि, पशु-पालन, उद्योग व मनन का विकास किया गया।

कृषि-नियोजन में प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने की नीति अपनायी गयी। राज्य में पशु-पालन के विकास की विस्तार सम्भावनाएँ हैं इसके लिए चरागाहों व चारे का विकास करने पर बल दिया गया। मृत्ति के नीचे के जल (ground water) का विशेष रूप से प्रयोग करने पर जोर दिया गया क्योंकि राज्य में सतह के जल (surface water) की मात्रा सीमित पायी जाती है।

कृषि के लिए कृषि व पशु-पालन के विकास के लिए साग की गुविधा बढ़ाने, भूमि को समतल करने, भू-संरक्षण व सूखी मेती के वायंत्रमो को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इसके लिए चम्बल व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई के क्षेत्रों का समन्वित ढंग से विकास करना तथा इनमें सड़क व मण्डियों का निर्माण, विद्युतीकरण, व वैज्ञानिक कृषि की पद्धतियाँ अपनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। चम्बल क्षेत्र में पानी के नििकास की समस्या, मिट्टी के क्षारपन व नहर में बोझ (घास-पात) की अनियन्त्रित बढ़ोतरी को रोकने के लिए विश्व बैंक की सहायता का उपयोग करने पर बल दिया गया।

पाँचवी योजना में आर्थिक प्रगति

पाँचवी योजना में स्थिर भावों पर (1970-71 में मूल्यों पर) राज्य की घरेलू उत्पत्ति में प्रतिवर्ष 5.2% तथा प्रति व्यक्ति आय में 2.1% वृद्धि हुई।¹ 1979 में राज्य में गम्भीर सूखे की स्थिति पायी गयी थी।

कृषि व सम्बद्ध क्रियाओं की प्रगति—खाद्यान्नों का उत्पादन 1973-74 में 67.2 लाख टन से बढ़कर 1978-79 में 77.80 लाख टन हो गया। तिलहन, गन्ना व कसम के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी।

अधिक उपज देने वाली किस्मों का फैलाव 1973-74 में 10.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1978-79 में 15.8 लाख हेक्टेयर में हो गया। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 0.73 लाख टन से बढ़कर 1.34 लाख टन हो गया। सकल सिंचित क्षेत्रफल 26.8 लाख टन हेक्टेयर से बढ़कर 30.4 लाख हेक्टेयर हो गया।

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 810.8 मेगावाट से बढ़कर 959.6 मेगावाट हो गयी।

औद्योगिक क्षेत्र में 'रीको' RFC, 'राजसीको' व जिला-उद्योग केन्द्रों (DICs) ने औद्योगिक विकास में भाग लिया। सूती खादी, ऊनी खादी व ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन व रोजगार बढ़ा। राज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये।

1. पाँचवी योजना व छठी योजना के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति (SDP) व प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े वर्षवार इस अध्याय के परिशिष्ट में दिये गये हैं। हमने औसत वृद्धि-दर का सूत्र प्रयुक्त किया है। इसके लिए प्रति वर्ष के प्रतिशत परिवर्तनों का ज्यामितीय औसत (Geometric mean) निकाला गया है। राज्य की कुल आय व प्रति व्यक्ति आय के लिए DES, जयपुर से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) :

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है छठी पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिश्रम 2025 करोड़ रु रखा गया था। लेकिन कुल योजना-व्यय लगभग 2131 करोड़ रु रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का 52.6% सिंचाई व शक्ति पर तथा 19.8% सामाजिक सेवाओं पर किया गया जो पूर्व योजनाओं की भांति ही था। कृषि, ग्रामीण विकास व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता पर 11.4% व्यय किया गया। उद्योग व खनन पर केवल 3.9% ही व्यय हुआ।

इस प्रकार छठी योजना में भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढाँचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुदृढ़ करने का प्रयास जारी रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति

राज्य की आय अथवा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) छठी योजना में 1970-71 की कीमतों पर 6.9% वार्षिक बढ़ी। इस प्रकार विकास की वार्षिक दर सतोषप्रद रही। प्रति व्यक्ति आय (स्थिर भावों पर) 1979-80 में 522 रुपये से बढ़कर 1984-85 में 639 रुपये हो गई। छठी योजना की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर भावों पर 4.1% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई।

कृषि—1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन 79.1 लाख टन हुआ जबकि 1979-80 में 52.4 लाख टन हुआ था। 1984-85 में तिलहन का उत्पादन 12.3 लाख टन, गन्ने का 13.7 लाख टन तथा कपास का 4.4 लाख गांठे हुआ था। वर्ष 1983-84 की छोड़कर अन्य वर्षों में मानसून कमजोर व अनियमित रहा था। जिससे चार वर्षों में राज्य में अकाल व सूखे का कुप्रभाव पड़ा था।

1984-85 में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 26.9 लाख हेक्टेयर भूमि आ चुकी थी तथा उर्वरकों का विन्यास 2 लाख टन से कुछ अधिक हो गया था।

छठी योजना में लगभग 21 लाख हेक्टेयर भूमि में प्रतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का विकास किया गया। राज्य में डेयरी का विकास किया गया तथा ऊन का उत्पादन 127 लाख किलोग्राम से बढ़कर योजना के अंत में 156 लाख किलोग्राम हो गया था।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से छठी योजना में 7.1 लाख परिवार सामान्वित हुए जिनमें बांधे से ज्यादा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की गई।

1. Budget Study 1989-90 (DES), March, 1989 एवं D. E. S., जयपुर द्वारा उपलब्ध अन्व आकड़े जो 1977-78 से 1986-87 की दस वर्षों की अवधि के लिए 1988 में जारी किये गये हैं।

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 1979-80 में 1032 82 मेगावाट से बढ़कर 1984-85 में 1747 86 मेगावाट हो गई।

योजना के आरम्भ में 38% गांवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी थी जो 1984-85 में 58% के स्तर तक पहुँच गई। राज्य में नायो-गैस सड़कों का विस्तार किया गया जिनमें मोबैर का उपयोग होता है।

उद्योग—राज्य में विनियोग-समिती का विस्तार किया गया गया रीको ने समुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। मार्च 1985 में राज्य में 29 समुक्त क्षेत्र की इकाइयों में उत्पादन कार्य चालू हो गया था।

खादी (मूतों व ऊनी), ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा आदि में उत्पादन बढ़ा तथा ग्रामीण उद्योगों में रोजगार 62 हजार व्यक्तियों से बढ़कर 17 लाख व्यक्ति हो गया। राज्य में खनिज पदार्थों में रोब-फॉस्फेट, जिप्सम, आदि का उत्पादन बढ़ाया गया।

विविध—राज्य में सड़कों का विस्तार किया गया है। सामान्य शिक्षा का अधिक फैलाव हुआ है। अस्पतालों की संख्या 171 से बढ़कर 186 हो गई है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सड़कों, प्रारम्भिक शिक्षा, पेयजल आदि का विस्तार किया गया है।

इन प्रकार छठी योजना की अवधि में राज्य का आर्थिक व सामाजिक इन्फ्रा-स्ट्रक्चर सुदृढ़ हुआ है। लेकिन राज्य में भ्रूकाल व भ्रमाय की समस्या के कारण ग्रामीण जनता को निरंतर बाढ़ी बरतों का सामना करना पड़ा है और राज्य सरकार के सामने भ्रूकाल राहत की समस्या बहुत जटिल रूप में विद्यमान रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में सांख्यिक परिचय का प्रस्तावित आवंटन

(प्रस्तावित)

	(करोड़ रु में)	(कुल का प्रतिशत)
(1) कृषि व सहायक क्रियाएँ एवं ग्रामीण विकास	290 3	9 7
(2) सहकारिता	46 2	15

(3) सिंचाई-बाढ़-नियन्त्रण व शक्ति ¹	1608.5	53.7
(4) उद्योग व खनन	190.5	6.3
(5) परिवहन	153.3	5.1
(6) सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ	674.7	22.5
(7) विविध	36.5	1.2
	3000.0	100.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवी योजना का आकार 3000 करोड़ रु. का स्वीकृत किया गया था। यह छठी योजना के लिए स्वीकृत धनराशि से 48% अधिक था। सातवी योजना में भी आधी से कुछ अधिक राशि (54%) सिंचाई बाढ़-नियन्त्रण व विद्युत के विकास पर तथा 1/5 से अधिक राशि (22.5%) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर व्यय के लिए निर्धारित की गई। इस प्रकार योजना में बिजली, खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादन व रोजगार में वृद्धि पर जोर दिया गया।

यह कहा गया कि सातवी योजना के लिए लगभग 1140 करोड़ रु. की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी तथा राज्य सरकार को 1000 करोड़ रु. के अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे।

सातवी योजना में विद्युत उत्पादन क्षमता को 1713 मेगावाट से बढ़कर 2660 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। अतः इसमें 62% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में 4.38 साल हैकटेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। 1500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50% गाँवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, आदि का विकास करने के कार्यक्रम रने गये। इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों के लिए कई प्रकार की छूटें व रियायतें दी गईं।

1. इसमें शक्ति का अंश 927.5 करोड़ रु. है जो कुल व्यय का 31% है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का अनुमानित आवंटन¹

1985-88 के वास्तविक व्यय, 1988-89 के अनुमानित व्यय व 1989-90 के प्रस्तावित व्यय के आधार पर आगे की तालिका में राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का विभिन्न क्षेत्रों में सम्भावित आवंटन प्रस्तुत किया गया है। इससे सातवीं योजना में सार्वजनिक व्यय के प्राप्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का स्वरूप
(करोड़ रु में)

	1985-88 (वास्तविक)	1988-89 (अनुमानित)	1989-90 (प्रस्तावित)	1985-90 (अनुमानित)	कुल का %
1. कृषि व सहायक क्रियाएँ पानीय विकास व सहकारिता	189.1	95.5	95.5	380.1	12.2
2. विचार, बाढ़ नियंत्रण व शक्ति	899.8	336.0	375.3	1611.1	51.9
3. उद्योग व खनिज.....	70.0	29.0	39.3	138.3	4.5
4 परिवहन	59.1	48.1	36.0	143.2	4.6
5. सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ	315.5	182.6	225.7	723.8	23.3
6. शिक्षा (अज्ञानिन व शारीरिक सेवाएँ, प्रणामनिक सुधार, मेवात विकास, आदि)	65.6	18.1	23.1	107.8	3.5
ग्रह दशमलव के एक स्थान तक लेन के कारण लगभग कुल योग	1600.0	710.0	795.0	3105.0	100.0

1. माय-व्ययक अध्ययन 1989-90, पृ. 48 व पृ. 123-124.

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना में सम्भावित व्यय 3105 करोड़ रु. आका गया है जो प्रस्तावित व्यय से अधिक होगा। इसका 52% सिंचाई व शक्ति पर तथा 23% सामाजिक सेवाओं पर व्यय होने की सम्भावना है। इस प्रकार 3/4 व्यय इन दो मर्दों के अन्तर्गत होगा। सतत व उद्योग पर कुल सावजनिक व्यय का 4.5% होने का अनुमान है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति विशेषतया (1985-86 की अवधि में)—दर्जाय से सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्ष भीषण अकाल व घनाव के वर्ष रहे। प्रथम वर्ष में 26 जिले अकाल से प्रभावित हुए तथा 1986-87 व 1987-88 में प्रत्येक में समस्त 27 जिले अकाल व सूखे की चपेट में रहे।

1987-88 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) घट गई। कलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय भी 1987-88 में 58३ रुपये पर आ गई जो 1984-85 के 639 रुपये से भी कम थी। 1985-88 की अवधि में स्थिर भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में प्रतिवर्ष १% की गिरावट आई तथा प्रति व्यक्ति आय 3% वार्षिक दर से घटी।

साधारणों का उत्पादन 1987-88 में 48 लाख टन पर आ गया जबकि 1985-86 में यह 81.3 लाख टन रहा था। लेकिन 1988-89 में इसके बढकर 1 करोड़ टन की सीमा की पार कर जाने का अनुमान है।

तिलहन का उत्पादन 1987-88 में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा था। 1988-89 में इसने 15.8 लाख टन होने की आशा है। 1988-89 में गन्ने व कपास के उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि होगी। कपास का उत्पादन तो 1988-89 में सम्भवतः पिछले वर्ष की तुलना में दुगुने से भी अधिक रहने की आशा है। 1987-88 में कपास का उत्पादन 2.18 लाख गान्ठे हुआ था जबकि 1988-89 में 5.47 लाख गान्ठे रहने की सम्भावना है।

1986-87 में कुल विविध क्षेत्रों में 43.5 लाख हेक्टेयर रहा जब कि 1984-85 में यह 38.3 लाख हेक्टेयर रहा था।

पावर व औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति—

1984-85 में विद्युत की कुल प्रस्थापित शक्ति 1747.86 मेगावाट थी जो 1988-89 में लगभग 2500 मेगावाट तक पहुँच गई है। 1989-90 में इसमें और वृद्धि की आशा है। इन वृद्धि में कोटा परमल चरण II की दो इकाइयों (माही हाइडन व वर हाउस-2) की दो इकाइयों (अन्तः) गंत पावर

स्टेशन व 'रिहन्द' सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हिस्सा मिलने, आदि से मदद मिलेगी। इस प्रकार राजस्थान की पावर-स्थिति काफी सुधर रही है।

राज्य में मिवाडी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों का विकास किया जा रहा है। 1988-89 में ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन 120 करोड़ रुपये होने की आशा है तथा इनमें रोजगार बढ़ कर 26 लाख व्यक्तियों तक हो जाने का अनुमान है। सूती व ऊनी खादी का उत्पादन 1988-89 में 2550 करोड़ रु. रहने की आशा है।

राज्य में 1989-90 में ग्रामीण निधनों को जवाहर-योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में उपलब्ध साधनों पर आधारित औद्योगिक विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को अधिक गतिमान बनाने का प्रयत्न करेगी।

अब हम योजनाकाल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व संक्षेप में जनता शासन-काल की अन्त्योदय योजना का परिचय देंगे। सम्भवतः आगे चल कर इस प्रकार के प्रयोग से लाभ उठाया जा सके।

जनता सरकार का निधनता को दूर करने की दिशा में अन्त्योदय कार्यक्रम

राज्य में जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निधनता को दूर करने की दिशा में "अन्त्योदय कार्यक्रम" अपनाया गया था। इस कार्यक्रम ने अन्त्योदय का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। राजस्थान को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में अप्रगती होने का सीमावर्ष प्राप्त हुआ था जो एक सराहनीय बात थी। इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, इसलिए यहाँ इसका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है।

अन्त्योदय कार्यक्रम गांधीवादी कार्यक्रम की एक कड़ी माना जा सकता है। यह 1977-78 से प्रारम्भ किया गया था। इसमें प्रत्येक गाँव से सबसे अधिक निधन पाँच परिवार चुने जाते थे जिनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता था। राज्य में लगभग 33 हजार गाँव हैं। इन निधनतम परिवारों का चयन ग्राम-सभाओं व गाँव के लोगों की सलाह से किया गया था। इनको सहकारी व व्यापारिक ढंग से कुछ उपलब्ध कराये जाते थे ताकि वे दुधारू पशु-पालन, भैंस बकरी आदि खरीद सकें या भेड़-पालन व सूअर-पालन कर सकें अथवा बैलगाड़ी या बैल ऊटगाड़ी या कहीं-कहीं रिक्शा आदि भी खरीद सकें अथवा दस्तकारी, कुटीर उद्योगों को स्थापित करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इन्हे कृषि के लिए

भूमि भी दी जा सकती थी। इस प्रकार यह सबसे गरीब वर्ग के लोगों को प्राथमिक दृष्टि से साधन प्रदान करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने का एक उत्तम तरीका माना गया था। ऐसे लोग योजनाकाल में विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये थे और विकास के लाभ कुछ सम्पन्न व भद्र-सम्पन्न परिवारों तक ही सिमट कर रह गये थे।

ग्रन्थोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन निर्धन परिवारों का जन्म किया जाता था उनकी प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपये से भी कम होती थी, हानात्मक उच्च समय प्रति व्यक्ति प्रति माह 55 रुपये से कम थाय थाये व्यक्ति निर्धनता की रखा से नीचे माने गये थे।

ग्रन्थोदय योजना में भूमिहीन व्यक्तियों व ग्रामीण दस्तकारों को अधिक लाभ मिलने की आशा थी। ये लोग सर्वोच्च प्राथमिकता दृष्टि योग्य भूमि को देते हैं और बाद में पशु-पालन, कुटीर-उद्योग, हथकरघा उद्योग, आदि को महत्व देते हैं। जनता सरकार का विचार था कि यदि इन कार्यक्रम के लिए बनी मात्रा में जनसंख्या की व्यवस्था की जा सके तो राज्य में निर्धनता को दूर किया जा सकता है।

लन्दन के समाचार-पत्र "दी इकोनोमिस्ट" ने यह मत प्रकट किया था कि "ग्रन्थोदय योजना" को गांधी के सम्पन्न सूत्राचार्यों से कोई छत्रा नहीं है, जैसा कि भूमि-पुष्पार के कार्यक्रम को रहा है। 'ग्रन्थोदय योजना' व 'समग्र ग्रामोदय योजना' को योजना की नई शैली का आधार बनाने का प्रयोजन यही था कि हमारी योजनाएँ ग्रामो-मुख, गरीबो-मुख, रोजगारो-मुख व कुटीर उद्योगो-मुख बनें, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को अती अधिक दशा सुधारने का उत्तम अवसर मिले, जो उन्हें पूर्व योजनाओं में नहीं मिल पाया था।

बीस मकल्पों की घोषणा

राज्य में कांग्रेस (आई) सरकार के पुनः मत्तारुद्ध हो जाने पर 'ग्रन्थोदय कार्यक्रम' के स्थान पर नव 20 सूची आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया गया है। 1985-86 में बीस सूची कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रु के व्यय की व्यवस्था की गई थी जो योजना में प्रस्तुत विन व्यय का 70% थी। सितम्बर 1981 में मुख्यमंत्री श्री शिखरराज माथुर की सरकार ने 'विद्धे को पहने' कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 मकल्पों को पुरा करने पर जो जोर दिया था। ये बीस मकल्प इस प्रकार थे : (1) पूरे चुनाव, (2) नई शिक्षा, (3) सत्ता न्याय, (4) गरीब को छप्पर, (5) छोटा परिवार, (6) नई ऊर्जा (7) राजस्थान नहर, (8) कोटा थर्मल, (9) जंगल में मगल, (10) ग्राम तक सड़क, (11) खेत में बिजली, (12) पीन का पानो, (13) विद्धे का पहने, (14) विकलांग कन्याएँ, (15) नगरीय मुक्ति, (16) राष्ट्रीय एकता,

(17) डेयरी विकास, (18) पूर्वी पालन, (19) कृषि व सहकारिता और (20) हस्त-शिल्प एवं उद्योग ।

पिछड़े को पहले' अभियान अन्त्योदय का ही एक विकसित स्वरूप माना जा सकता है । अन्त्योदय गाँव के सबसे पिछड़े पाँच परिवारों के आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम था, जबकि पिछड़े को पहले' ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया था ।

राजस्थान में योजनाकाल के 38 वर्षों (1951-89) में आर्थिक प्रगति¹

राजस्थान में योजनाकाल में आर्थिक प्रगति हुई है, फिर भी यह राज्य भारत में सबसे ज्यादा निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है । हम नीचे संक्षेप में 1951 से 1989 तक की अवधि में हुई आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेंगे जिससे पता चलेगा कि राजस्थान न 38 वर्षों में राज्य की आमदनी (state income), कृषिगत उत्पादन, सिंचाई शक्ति औद्योगिक विकास, सड़क जिला, बिजली जल-सप्लाई आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति की है । लेकिन आगामी वर्षों में विकास की यात्रा व विकास की प्रक्रिया को अधिक तेज करना है ।

1. राज्य की आय में वृद्धि—योजनाकाल के प्रथम दो दशकों में राज्य की आय लगभग दुगुनी हो गई थी । बाद में राज्य की आय के आँकड़े 1970-71 के भावों पर दिये जाने लगे । इनके अनुसार राज्य की आय 1970-71 में 1637 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 में 2383 करोड़ रुपये (स्थिर कीमतों पर) हो गई है । 1986-87 में यह 2524 करोड़ रुपये रही थी । लेकिन प्रतिव्यक्ति आय 1970-71 में 651 रुपये थी जो स्थिर मूल्यों पर 1986-87 में 634 रुपये तथा 1987-88 में 583 रुपये रही है । यह एक निराशाजनक स्थिति है । 1970-71 से 1987-88 के 17 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में एक विशेष बात उल्लेखनीय है । यह 1970-71 में 651 रु. थी । बाद में केवल 1982-83 तथा 1983-84 को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में यह स्थिर भावों पर 651 रु. से कम रही है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास में घीमेदन व गतिहीनता की शिकायत की गई है । वैसे भी हम देख चुके हैं कि स्थिर भावों पर पाँचवी योजना व छठी योजना में राज्य की घरेलू उत्पत्ति/आय में क्रमशः 5.2% व 6.9% वार्षिक वृद्धि की दरें प्राप्त की गई हैं । इसलिए 1970-71 की प्रति व्यक्ति आय को लेकर आगे चलने पर विकास की गति काफी निराशाजनक लगती है । वैसे पाँचवी व छठी योजनाओं में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि-दरें (स्थिर भावों पर) क्रमशः 2.1% व 4.1% रही हैं, जिन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है ।

1. आय-व्यय अध्ययन, 1989-90, आर्थिक समीक्षा, 1988-89, पृ. 71-96 एवं Shri S. K. Bhargava, Director, DES, का लेख "A Note on Perspective For Eighth Five year Plan, June 1989, (DES Jaipur)

छठी योजना में राज्य की अर्थव्यवस्था में 6.9% सालाना की दर से वृद्धि हुई थी। चूंकि 1979-80 का आधार-वर्ष काफी कमजोर रहा था, इसलिए यह वृद्धि प्रतिशतपूर्वक मानी जा सकती है। वास्तव में 1984-85 वर्ष में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (Net State Domestic Product) 48% घटी थी। लेकिन 1982-83 में यह 16% तथा 1983-84 में 8.6% बढ़ी थी। यद्यपि छठी योजना में वार्षिक विकास की दर 6.9% रही, लेकिन इस लक्ष्यी अवधि में प्राप्त कर सकना काफी कठिन होगा क्योंकि कृषिगत उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव घटने से राज्य की आयदमी भी प्रभावित होती रहती है। राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अस्थिर व अनिश्चित किम्ब की है।

2. कृषिगत उत्पादन व सिंचाई—राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 29.5 लाख टन हुआ था जो 1983-84 में 100.8 लाख टन हो गया (लगभग एक करोड़ टन)। लेकिन 1987-88 में यह घट कर 48 लाख टन पर आ गया। एक 1988-89 में इसके पुनः 1 करोड़ टन रहने की सम्भावना बतलाई गयी है। राज्य में अकाल व सूखे के कारण उत्पादन घटा है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रफल 1950-51 में 10 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1986-87 में 43.5 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया था। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र चार गुना से अधिक हो गया, फिर भी राज्य का 77% अथवा 3/4 कृषि क्षेत्रफल मानसून की दया पर आश्रित रहता है। राज्य में प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं जिन्हें सिंचाई का विस्तार करके ही कम किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई की प्रतिशत सम्भाव्यता 51.5 लाख हेक्टेयर आधी गयी है जिसमें से 27.5 लाख हेक्टेयर में पृष्ठ व मध्यम साधनों से तथा 24 लाख हेक्टेयर में लघु साधनों में मानी गयी ॥

राज्य में अधिक उपज देने वाली किम्बों का उपयोग बढ़ रहा है। 1968-69 में ये किम्बे 5.24 लाख हेक्टेयर में बोई गई जिनके 1988-89 में लगभग 30 लाख हेक्टेयर में पैदा दिये जान की आशा है। मुचरे हुए बीजों का वितरण भी किया गया है। रासायनिक खाद का उपयोग 1951-52 में केवल 324 टन हुआ था जो बढ़कर 1988-89 में 3 लाख टन (सम्भवित) पर पहुँच गया है। कपास का उत्पादन 1988-89 में 5.47 लाख गीठों (प्रति गीठ = 170 किलोग्राम) रहने की आशा है जबकि 1987-88 में 2.18 लाख गीठों ही हुआ था। राज्य में सिंचाई के माधनों के विस्तार से खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। जैसा कि पहले बताया गया है कि राज्यभर में सकल कृषि क्षेत्रफल 1951-52 में रिपोटिंग क्षेत्रफल के 28% से बढ़कर 1986-87 में 52% हो गया है। जिससे राज्य में विस्तृत मेती की प्राप्ति का परिचय मिलता है।

राज्य में योजनाकाल में डेयरी का विकास किया गया है। राज्य में डेयरी समर्थों की संख्या 30 लाख है तथा औसत दैनिक दुग्ध सग्रह का स्तर 8.25 लाख

मीटर है जिसके 1988-89 तक 10 60 लाख मीटर प्रति दिन होने का अनुमान है। राज्य में दुग्ध सड़कारी समितियों का विकास किया गया है।

3.. विद्युत-शक्ति की प्रगति—राज्य में 1950-51 में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 8 मेगावाट थी। यह 1988-89 में बढ़कर लगभग 2500 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित क्षमता काफी बढ़ी है। राज्य में बिजली प्राप्त स्थानों की संख्या 42 से बढ़कर मार्च, 1989 तक 24039 तथा शक्ति-चालित कुओं (wells energised) की संख्या 1038 से बढ़कर 3 2 लाख से कुछ अधिक हो गयी है। शक्ति की प्रस्थापित क्षमता की वृद्धि में प्रमुख योगदान कोटा थर्मल चरण II की प्रथम इकाई, माही हाइडल पावर हाउस-2, घन्टा गंस पावर स्टेशन, इकाई I व II, तथा रिहन्द सुपर-थर्मल पावर स्टेशन में राज्य के हिस्से में दिया है। भविष्य में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता के बढ़ने की ओर सम्भावनाएँ हैं।

4. औद्योगिक विकास—पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि योजना की प्रगति में राज्य में कई नये कारखाने खोले गये हैं जिससे वजीकृत फैक्ट्रियाँ 1949 में 207 से बढ़कर 1988 के अन्त में 10512 हो गई हैं। राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1951 में 2.58 लाख टन से बढ़कर 1988 में 40.3 लाख टन (लगभग 16 गुना) हो गया है। चीनी का उत्पादन 1951 में 1.5 हजार टन से बढ़कर 1987 में 23 हजार टन व 1988 में 5 हजार टन हो गया है। सूती वस्त्र और सूत का उत्पादन बढ़ा है। राज्य में बॉल बियरिंग व बीजकी के मीटर बनने लगे हैं जिसकी संख्या 1988 में क्रमशः 139 लाख व 868 हजार हो गई थी। राज्य में नमक का उत्पादन भी पहले से बढ़ा है। 1988 में नमक का उत्पादन 10.4 लाख टन हुआ जबकि 1971 में यह 5.5 लाख टन हुआ था।

1971 से 1985 तक औद्योगिक उत्पादन-सूचकांक (आधार वर्ष 1970 = 100) में वार्षिक वृद्धि पर विनिर्माण (manufacturing) में 3.7% रही एवं औद्योगिक विकास की दर 6% रही।

5. सड़कों का विकास—राज्य में 1950-51 के अन्त में सड़कों की लम्बाई 17,339 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1987-88 में 53523 किलोमीटर हो गयी है। इस प्रकार सड़कों की लम्बाई लगभग तिगुनी हो गई है। 1960-61 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई 7.72 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1987-88 में 15.64 किलोमीटर हो गई, लेकिन फिर भी यह 1984-85 में समस्त भारत के औसत स्तर 53.92 किलोमीटर से नीची हो थी। 1987-88 के अंत तक 1500 व अधिक जनसंख्या वाले 86% गाँव तथा 1000-1500 जनसंख्या वाले 6.-% गाँव सड़कों से जोड़ दिये गये थे।

6 शिक्षा की प्रगति—3 000 व ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गाँवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिये गये हैं। सभी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। राज्य के सभी जिलों में कालेज स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य में बिड़ला इस्टीमेट ग्रैंट माइन्स व टेक्नोलॉजी (पिलानी और मालवीय रीजनल इन्फोर्मेसियम बॉलड (बदपुर) क स्थापित हो जाने से टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ गई हैं। राज्य में पोलिटेक्नीक संस्थाएँ भी स्थापित की गई। राज्य में वर्ष 1986-87 में 137 कॉलेज उच्च शिक्षा में सलमान से जिनमें 67 राजकीय थे तथा 70 सहायता प्राप्त कॉलेज थे। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 5 इन्जीनियरिंग कॉलेज व 13 पोलिटेक्नीक कार्यरत हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। राज्य में साक्षरता का अनुपात 1961 में 15.2% से बढ़कर 1981 में 24.4% हो गया है। समस्त भारत के लिए साक्षरता का अनुपात = 36.3%) इस प्रकार योजनाकाल में शिक्षण संस्थाओं का काफी विकास किया गया है। जुलाई 1987 से राज्य में घजमेर, काटा व बीकानेर में नये विश्वविद्यालय चालू किये गये हैं। 1950-51 में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की भर्ती 3 30 लाख थी जो बढ़कर 1988-89 में 47.8 लाख हो गई है। फिर भी लाखों बच्चे (6-11 वर्ष की आयु) अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

7 चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र में प्रगति—राज्य में मलेरिया व चेचक धारि पर काफी मात्रा में नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। राज्य की 1977 में चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। अस्पतालों में रोगियों के लिए इलाजों की सख्या बढ़ायी गई है और चिकित्सा की सुविधा भी बढ़ी है। सभी पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। 1951-52 में अस्पतालों व डिस्पेंसरियों एवं मानव व बाल-कल्याण केन्द्रों की संख्या 418 थी जो 1986-87 में बढ़कर 1961 हो गई है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 593 अस्पतालों की 208 डिस्पेंसरियों की संख्या 1044 व मानव व बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या 111 थी। इनके अलावा 92 उपसेन्ट्र भी कार्यरत थे। शहरी के मुख्य अस्पतालों की मोडर्नाइज की कम करने की दृष्टि से 5 सेंटेंनाइड अस्पताल भी चालू किये गये हैं।

मात्र 1990 तक 32400 गाँवों में पेयजल की सुविधा हो आयगी।

राज्य में नगरों व गाँवों में जल-सप्लाई की व्यवस्था में सुधार किया गया है।

8 राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) की प्रगति—IRDP नियन्त्रण कम करने से सम्भव कार्यक्रम है। 1977-78 के मूल्यांकन पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 63 रु (ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा 75 रु (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति नियम मान गये थे, जिनका अनुपात राजस्व के लिए

33.5% आंध्र प्रा. हाताफि यो. के लिए यह 50% बिहार के लिए 57½% परिवर्ती बंगाल के लिए 52½% तथा तमिलनाडु के लिए 52% आंध्र प्रा. इस प्रकार राजस्थान कम निचल माना गया है।

छठी योजना में IRDP के माध्यम से निर्धन वर्ग की गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रयास किये गये हैं लेकिन उनमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी है। डॉ. सी एच हनुमन्थ राव ने अनुमान लगाया है कि राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 1977-78 में 33.5% से बढ़कर 1983-84 में 36.6% हो गया है। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें उपरोक्त अवधि में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात (Poverty ratio) बढ़ा है, जबकि अन्य राज्यों व समस्त भारत में यह घटा है।¹

1948 में जयपुर जिले (मार्कन ग्रहज व मार्कन) व जोधपुर (मार्कन नगार्ड) जिलों में IRDP की प्रगति के सर्वेक्षण हुए थे जिनमें प्राप्त परिणाम सन्तोषजनक स्थिति के सूचक नहीं हैं। जयपुर जिले में 14.7% परिवार तथा जोधपुर जिले में 21.4% परिवार जो गरीबी मान किये गये थे, वस्तुतः गरीब नहीं थे। जयपुर के अध्ययन में बताया गया है कि 54% बच्चें लेंने वाले ने अपने पशु बेच दिये अथवा उनके पशु मर गए। उनसे चारे की कमी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। केवल 18% बच्चें लेंने वाले ही निर्धनता की रेखा को पार कर पाये हैं। गेहूँ, बजरी, घास के सम्बन्ध में स्थिति काफी खराब रही है। इस प्रकार IRDP की उपलब्धियाँ सीमित ही रही हैं। राजस्थान के योजना विभाग की सूचना के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में 7.1 लाख परिवारों को IRDP से लाभ पहुँचा है जिनमें लगभग आठ अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं।

फरवरी 1989 तक 137 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। 1989-90 में इस कार्यक्रम के लिए 30.6 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है। लाभान्वित होने वाले परिवारों के मात के विविध की व्यवस्था भी की जा रही है।

9. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)—इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। प्रधान-राहत के कार्य भी कराये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओं का निर्माण, स्कूल बनाने, विद्युत्तरिधियों, ग्रामीण सड़कों, तहसुलियाई के साधनों व मूत्र-रक्षण के कार्य किये जाते हैं।

1. C. H. Hanumantha Rao, *Changes in Rural Poverty in India* Mainstream, January, 11, 1986, p 11.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP), ट्रांसमै. मैसिव कार्यक्रम (समुद्र कृषि के लिए), मरुविकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास, रेवादन रिवल्वमेंशन कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास, मेवात विकास आदि के लिए धनराशि व्यय की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। 1989-90 में राष्ट्रीय स्तर पर 2.5 लाख व्यक्तियों को 120 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायगा। अन्य कार्यक्रमों से 1.2 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया जायगा। इसके अलावा जवाहर-रोजगार-योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय निपटन परिवारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जायगा।

सारांश—योजनाकाल में 38 वर्षों की वार्षिक प्रगति से राज्य में आधारभूत ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुदृढ़ हुआ है। बिजली की सुविधाएँ बढ़ी हैं, विद्युत की प्रत्यापित क्षमता बढ़ी है और राज्य औद्योगिक विकास के नये कार्यक्रम बनाने की स्थिति में आ गया है। रोको ने समुद्र क्षेत्र में कई इकाइयों स्थापित की हैं। जिनमें से कई इकाइयों में उत्पादन नाश चालू हुआ है। RFC समुद्र मत्स्य उद्योगों को काफी मात्रा में दीक्षणीय बजट देने लगा है।

संविन राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर 1961-71 में 27.8% से बढ़ कर 1971-81 में लगभग 33% हो गई है, जो नियोजन की विफलता की सूचक है। राज्य में कृषिगत उत्पादन में काफी उत्तार-चढ़ाव आने रहने हैं। प्रतिवर्ष राज्य में अकाल व अभाव की स्थिति बनी रहती है। विद्युत की मृजन-क्षमता के बढ़ने पर भी कृषिगत व औद्योगिक कामों के लिए प्रायः विद्युत की कमी बनी रहती है जिससे कृषि व उद्योगों दोनों के विकास में बाधा पहुँचती है। पर्यटन का विकास भी अपर्याप्त मात्रा में हुआ है।

हम नीचे राजस्थान के विकास में प्रमुख बाधक तत्वों का संक्षेप काके जाही विकास के लिए आवश्यक व आवश्यक नृमान्य देदे ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के कारण

(Causes of Slow Growth of the Economy of Rajasthan)

नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान को 'एक पिछड़ा हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश' (A backward region in a backward economy) कहा जाता था। इस समय यह राज्य आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक व अन्य दृष्टियों से देश के अन्य भागों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था। पिछले 38 वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगति होने से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विच्छेदन में कमी आयी है। लेकिन अभी तक इस दिशा में बहुत कार्य करना होय है। हम पहले बताता चुके हैं कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 में 651 रु. रही थी जो बाद में, स्थिर दरों पर, 1982-83 व 1983-84 को छोड़ कर 1987-88 तक किसी भी वर्ष इससे अधिक नहीं रही। बल्कि 1982-83 में यह 652 रु. पर ही रही। इससे

राज्य की घीमी वार्षिक प्रगति का ही नहीं, बल्कि वार्षिक गतिहीनता की दशा का भी पता लगता है। स्मरण रहे कि पाँचवीं व छठी योजनाओं में राज्य की कुल वार्षिक क्रमशः 5.2% व 6.9% वार्षिक दर से बढ़ने से यह भ्रम हो सकता है कि राज्य में वार्षिक प्रगति घीमी नहीं है। लेकिन राज्य में 1974-75 से 1987-88 तक के 14 वर्षों में से 11 वर्षों में प्रकाश व प्रभाव की स्थिति पायी गयी। 1987-88 में 27 जिलों में प्रकाश व सुखा पड़ा और इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में (स्थिर भावों में) काफी गिरावट आयी है।

अतः वर्षों से राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के स्तर के पास-पास ही मडराती रही है जिससे राज्य में घीमी प्रगति का ही आभास होता है। इसके कारणों पर आगे प्रकाश डाला गया है। ये तत्त्व ही राज्य के आर्थिक विकास में बाधक हैं।

1 प्राकृतिक बाधाएँ—पहले बतलाया जा चुका है कि अरावली पर्वतमालाओं के पश्चिम में धार का रेगिस्तानी प्रदेश है जिसमें वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। इससे कृषि-कार्यों में बहुत बाधा पहुँचती है।

विभिन्न प्राकृतिक बाधाएँ इस प्रकार हैं—

(1) वर्षा की अनिश्चितता सुखा प्रकाश आदि—राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत मात्रा कई राज्यों की तुलना में कम है। वर्षा की अनिश्चितता व अनियमितता समस्त भारत की विशेषता है, लेकिन इसका विशेष अनुभाव राजस्थान पर पड़ता रहा है। राज्य में वर्षा का सामान्य वार्षिक औसत 59 सेन्टीमीटर माना गया है जो जैसलमेर में 15 सेन्टीमीटर से आसावाड़ जिले में 104 सेन्टीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ एक ही समय में राज्य के कुछ भागों में अतिवृष्टि के पसत्यरूप बाढ़ के कारण जान-माल की भारी हानि देखी जाती है तो दूसरी तरफ अनावृष्टि व सूखे के कारण लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता और पानी व चार व प्रभाव में पशुधन को भी भारी क्षति पहुँचती है। भूतकाल में राज्य से प्रतिवर्ष पशुधन का मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की निष्क्रमण हुआ है। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की राहत कार्य (relief works) चालू करने पड़ते हैं और भू-राजस्व आदि को छूटें देनी पड़ती है। वर्षा की कमी के कारण राजस्थान में हर वर्ष किसी न किसी धान में प्रकाश की स्थिति अवश्य पायी जाती है। जमीन-जमी प्रकाश की व्यापकता व तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की प्रवधि में एक वर्ष को छोड़कर बाकी सभी वर्षों में राज्य में सूखे की स्थिति रही। अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनों के कारण राज्य को विकास के सफट का सामना करना पड़ता है। सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1987-88 प्रकाश की चपेट में रहे हैं।

ग्रामों के बाग़ान लोग रोज़गार की तलब में इधर उधर घटकने लगते हैं तथा पशुओं के लिए भी चारे व पानी का भारी सफ़ट उत्पन्न हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के पशु-पालकों का जीवन कितना कष्टमय व निराशाओं से भरा हुआ है। सरकार को ग्राम राज्यों से चार की खरीद करनी होती है। लेकिन प्रत्यक्ष वह पयप्ति नहीं होती और फलस्वरूप चारा महंग हो जाता है। इससे दूध के भावों पर भी भारी असर पड़ता है।

(ii) पीने के पानी का अभाव—राज्य के कई जिलों में भूमि के नीचे पानी बहुत गहराई पर निकलता है, यद्यपि कभी-कभी भूमि के नीचे जल बिल्कुल ही नहीं निकलता और कुछ दशाओं में खारा पानी (Brackish water) निकलता है जो किसी भी काम का नहीं होता। इस प्रकार पीने के पानी के अभाव में लोगों को काफी दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमें अनावश्यक मात्रा में श्रम, शक्ति व साधन नष्ट हो जाते हैं। सूख की स्थिति में तो ग्रामों में गर्मों व प्यास से कभी-कभी मनुष्य व पशु मौत के शिकार हो जाते हैं। गाँवों में पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार राज्य में आज भी काफी गाँव ऐसे हैं जिनमें पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पायी है। राज्य सरकार हैब्ड पम्प व नलकुप तैयार करने पर काफी खर्च कर रही है। बाकी गाँवों में पेयजल की कठिनाई दूर करने का प्रयास जारी है। सरकार की ट्रकों व टैंकरो की सहायता से गाँवों में पेयजल पहुँचाना होता है। इसके अलावा प्राइवेट ट्रकों, ऊँटगाड़ियों व बैलगाड़ियों का भी पेयजल को पहुँचाने में उपयोग किया जाता है।

(iii) भूमि का कटाव—राज्य में तेज़ हवा के कारण भूमि के कटाव की भी गम्भीर समस्या पायी जाती है। पशुओं के द्वारा अनियमित चरवाई के कारण घास की घन्तिम पत्ती लक साफ कर दी जाती है जिससे भूमि का कटाव और भी तेज़ हो जाता है। इस प्रकार वर्षा की कमी व अनियमितता, भूमि के नीचे पानी की कमी और मिट्टी के कटाव ने राज्य को कभी-कालों से मुक्त नहीं होने दिया है।

2 सिंचाई के साधनों का अभाव—यद्यपि योजनाकाल में सिंचित क्षेत्र लगभग 4 गुना हो गया है, तथापि आज भी कुल जोड़े-बोये क्षेत्र का चौथाया से कुछ कम भाग 22% ही सिंचाई के अन्तर्गत आ पाया है। राज्य का तीन-चौथाया कृषित क्षेत्र मानसून की दशा पर आश्रित रहता है। सिंचाई के अभाव में एक ही अधिक फसलें बोना सम्भव नहीं हो पाता और गहन कृषि की पद्धतियों को अपनाने में भी कठिनाई होती है। फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए रासायनिक साद के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है।

3 विद्युत शक्ति का अभाव—राज्य में योजनाकाल में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता भी 8 मेगावाट से बढ़कर 1989 के मध्य में लगभग 2500 मेगावाट कर दी गई है, लेकिन चम्बल क्षेत्र में वर्षाभाव के कारण पिछले वर्षों में विद्युत की पूर्ति में

लिए कई कारण बतलाये गये हैं। लेकिन एक कारण यह है कि विभिन्न वस्तुओं के उपभोग के मुख्य केन्द्र राजस्थान के बाहर पाये जाते हैं जिससे टिकाऊ या गैर-टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं अथवा उत्पादक व पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन राजस्थान में न किया जाकर देश के पूर्वी व पश्चिमी प्रदेशों में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी उद्योगों की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों में गये और उन्होंने राजस्थान में आज़ तक पर्याप्त मात्रा में रुचि नहीं दिखायी। राज्य के सभी मुख्य मंत्री प्रवासी उद्यमकर्त्ताओं को राजस्थान के औद्योगीकरण में सहयोग देने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं। लेकिन उसका वांछित रूप से आशाजनक व उत्साहवर्धक परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। भविष्य में उनकी शकाग्रि व शिकायतों का उचित समाधान निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए समय-समय पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक समस्याएँ सामने आ सकें।

7. सरकार के पास वित्तीय साधनों का अभाव—आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षों में विकास-कार्यों एवं प्रकल्प-सहायता-कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थाओं व जनता से काफी कर्ज लिया है जिसकी कुल बकाया राशि 31 मार्च 1989 के अंत तक 4:69 करोड़ रुपये हो गयी थी जिसमें केन्द्रीय ऋणों की राशि 2889 करोड़ रु. या लगभग 62% थी। आन्तरिक कर्ज की राशि 871 करोड़ रु. व प्रोविडेंट फंड आदि की 809 करोड़ रु. थी।¹ इस प्रकार राज्य पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियों का भार काफी ऊँचा है। आनकल नए केन्द्रीय ऋण पुराने ऋणों की प्रदायगी में प्रयुक्त होने लगे हैं। 1988-89 में केन्द्रीय कर्ज की प्राप्ति 543 करोड़ रु. व प्रदायगी 211 करोड़ रु. रही। इस प्रकार शुद्ध कर्ज की प्राप्ति लगभग 332 करोड़ रु. रही। अतः राजस्थान कर्ज के भार से काफी दब गया है। केन्द्रीय सहायता भी ऋणों के पुनर्मुँगतान में प्रयुक्त हो जाती है। इससे राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति का बतल चलता है। राज्य को नयी योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दशा में सरकार के समस्त वित्तीय साधनों को जुटाने की जटिल समस्या उपस्थित हो गई है। सिंचाई व विद्युत आदि क्षेत्रों में किये गये विनियोगों से उचित प्रतिकूल नहीं मिलने से गृह्य वित्तीय संकट बना रहता है। वित्तीय साधनों की हानि को कम करने के लिए सरकार ने गिराबिन्दी को समाप्त कर दिया है। इससे राज्य-आवकारी

1. Report on Currency & Finance 1987-88, Vol II, P.142.
मार्च 1989 के अंत के लिए बजट-अनुमान है।

कर से पुनः ग्रन्थी ग्रामदनी होने लगी है। 1989-90 के बजट में इससे 184 करोड़ रु. का आय का अनुमान लगाया गया है।

8 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बेरोजगारी व अल्प-रोजगार की समस्याएँ— 1971-81 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 33% की वृद्धि हुई जो भारत में घातक वृद्धि (25 प्रतिशत) से 8% बिन्दु अधिक थी। राज्य में रोजगार के साधनों के अभाव में बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमान है। छठी योजना से प्रारम्भ में राज्य में (श्रम-शक्ति के 3% बेरोजगारी की दर पर) 4.22 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। अकाल के वर्षों में बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो जाती है। लोग यथासंभव रोजगार के लिए शहरों की तरफ आते-समते हैं जिससे शहरों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। राज्य में अनुसूचित जाति व आदिम जाति के कल्याण की समस्या भी बहुत जटिल है। इसका सामाजिक पहलू भी है। अतः उनको हल करने के लिए कई दिशाओं में प्रयत्न करने आवश्यक हो गये हैं।

9 धीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण—उपयुक्त तत्वों के अभाव में राज्य के आर्थिक विकास में अन्य तत्व भी बाधक रहे हैं, जैसे गाँवों का सामाजिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एवं पर्याप्त जन-सहयोग की कमी। इनमें से कुछ कारण तो समस्त देश में धीमी आर्थिक प्रगति के लिए उत्तरदायी रहे हैं। लेकिन राजस्थान का सामग्री वातावरण, सामाजिक पिछड़ापन, जाति-प्रथा, ऊँच-नीच का भेदभाव एवं शिक्षा की कमी आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करते रहे हैं। योजना-का 1 पर जितना व्यय किया जाता है, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। साधनों के अभाव की स्थिति में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

राजस्थान की धीमी आर्थिक प्रगति के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करने के बाद अब हम राज्य में आर्थिक प्रगति को तेज करने के उपायों के बारे में आवश्यक सुझाव देते हैं।

भविष्य में आर्थिक प्रगति को तेज करने के उपायों के बारे में सुझाव

(Suggestions for Measures Towards Rapid Economic Growth in Future)

राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण-कार्य जारी है। वर्तमान में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम, वर्ष 1989-90 की योजना पर कार्य जारी है। अतः हमें भूतकाल के अनुभवों से लाभ उठाकर आगे नियोजन को अधिक सक्रिय व सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ताकि राज्य में विकास की गति तेज की जा सके। इस सम्बन्ध में अग्र सुझाव दिये जा सकते हैं :

1 **घाणिक सर्वेक्षण**—राज्य में आणिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में होने चाहिए जिससे औद्योगिक व खनिज विकास की मावी सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके। सर्वेक्षणों से आवश्यक आकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। घाणिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् (NCAER) ने राज्य के लिए 1974-89 की अवधि के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की थी जिसमें राज्य के भावी विकास के लिए काफी उपयोगी सुझाव दिये गये थे। एम. बी. माथुर समिति ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यवहरचना निर्धारित करने के लिए अपनी जून, 1989 की रिपोर्ट में कई उपयोगी सुझाव दिये हैं।

2 **सूखे से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास**—राज्य में निरंतर पढ़ने वाले प्रकालों से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए सिंचाई के साधनों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। राज्य के सभी प्रकार के साधनों से अन्तिम सिंचाई की सम्भाव्यता 51.50 लाख हैक्टेयर आती गई है जिसमें से अभी तक लगभग 40 लाख हैक्टेयर क्षमता का विकास किया गया है। ग्राम-मन्डल में सिंचाई के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जिसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी बढ़ायी जानी चाहिए और ट्यूब-वells के समीप चारे को जमा करने के लिए 'फॉइर बैंक' बनाने चाहिए। सिंचाई के विस्तार का एक प्रतिभूल प्रभाव यह पड़ा है कि गंग नहर अथवा इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्र में जहाँ कुछ वर्ष पूर्व चराई के मैदानों में 'सवन' (sevan) घास उपलब्ध हो जाती थी, अब वहाँ सेती का विस्तार होने से घास की भाषा काफी कम हो गई है और पशुओं को सुदूर के स्थानों में चराई के लिए ले जाना पड़ता है। इसलिए राज्य में चार का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। इस दिशा में डेयरी विकास निगम, राजस्थान गो-मदक सच व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्राधिकारी चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

3 **राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में भू-संरक्षण व जल-व्यवस्था**—राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के विकास की सम्भावनाएँ सीमित होने में उपलब्ध नमी के संरक्षण व कुशल उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फसलों का ऐसा प्रारूप अपनाया होगा जो कम नमी के अनुकूल हो इसके लिए बन्डिंग या कट्टर बन्डिंग की विधि जयदा उपयुक्त होगी, बनिस्वन टरसिंग (terracing), रिज-मेकिंग (ridge making), चेक-डैम (check dam), के नियमन, आदि के। वन्य क्षेत्रों में चरन की फसल कम वर्षा के समय भी हो सकती है। हवा को रोकने से पठ व भाड़ियाँ भी लाभप्रद हो सकती हैं। शुष्क प्रदेशों में कँर आदि के पठ बहुत उपयोगी मिट्टी हो सकते हैं। कुछ रणायी घास की जिसमें मृदा-समक टुबड़ियों का काम कर सकते हैं। इन टुबड़ियों व भीष में सेती की जा सकती है। इनसे सही फसलों की रक्षा होती है। मिट्टी का हवा से हन वाला बटाव रकता है और नमी

पर नियन्त्रण हो पाता है। इन सरसण के उपायों से शुष्क प्रदेश में फसलों के उत्पादन को बढ़ान में बहुत मदद मिलेगी।

4. पेयजल की सुविधा—राज्य के जिन क्षेत्रों में पेयजल का अभाव पाया जाता है, उनमें जल-पूर्ति के कार्यक्रम तभी स लागू करने होंगे। खारे पानी की पट्टी में पढ़न वाले क्षेत्रों के लिए गांवों के समूह के लिए क्षेत्रीय योजनाएँ बनानी पड़ेगी और पास के इलाकों में नलो व जरिए पानी पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। जहाँ पानी गहराई में उपलब्ध है और मनुष्य व पशुओं के पीने योग्य है, वहाँ अधिक सस्या में ट्यूब वेल लगाने होंगे। कुछ क्षेत्रों में नए कुएँ खोदने और पुराने कुओं का गहरा करने से भी काफी सीमा तक पेयजल की समस्या हल हो सकती है।

5 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास—इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में नयी वस्तियाँ बसानी हैं जिनमें काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अतः इस क्षेत्र में मिट्टी के सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण पानी की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सब पृच्छा जाय तो मरुभूमि का कल्याण हम नहर को पूरा करने पर निर्भर करता है। इस योजना के पूरा हो जाने पर सारा प्रदेश हरा-भरा हो जायगा और सारी धरती लहलहा उठेगी। अतः केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर यथासम्भव शीघ्रता से इस परियोजना के दोनों चरणों का पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक विलम्ब होने से अविष्य में परियोजना की लागत और बढ़ जायेगी और अन्त्य कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। राज्य सरकार चाहती है कि नारी वित्तीय धन की आवश्यकता के कारण इस केन्द्र द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

प्रवाल-राहत बायों में सड़क निर्माण के नाम पर काफी रुपया प्रतिवर्ष व्यय होना रहा है लेकिन सड़कें ठीक में नहीं बन पायी हैं। यदि यही धनराशि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने में लगती तो राज्य के लिए ज्यादा अच्छा होता। इस प्रकार साधनों के अभाव की स्थिति में भी साधनों का दुरुपयोग होना वास्तव में एक विनोद का विषय है और वह प्रभावपूर्ण निोजन के अभाव का सूचक है।

निरन्तर सुसाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण-निर्माण-कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। ये कार्यक्रम जसलमेर, बाड़मेर, जाधपुर, पाली, जालौर, नागौर, चूरु, बीकानेर, बाँसवाड़ा, व डूंगरपुर जिलों में लागू किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सड़क, लघु सिंचाई, वृक्षारोपण, चरागाह विकास, ग्राम्य-जल सप्लाई योजना आदि पर बत देन से प्रकालों की जीवणता में कमी होगी और लोगों

को अधिक रोजगार मिलेगा। राज्य से श्रकत रहित कार्यों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए।

6 आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास—ग्रामी तक राजस्थान में आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ है। राज्य में कृषिगत उत्पादन बढ़ाने से कृषि-आधारित उद्योगों (agro-based industries) व फूड प्रोसेसिंग उद्योगों जैसे तेल उद्योग, कॉटन जिनिंग व प्रोसेसिंग, सड़सारी उद्योग, ब्रेड, बिस्कुट, फलों एवं सब्जियों को डिब्बों में भरने, मेथी, पापड़ भुजिया, शबेत, मसालों, आदि का विकास किया जा सकता है। भोलवाडा विसीड व भालावाड में शालिकरघों का विस्तार किया जा सकता है। लकड़ी आधारित उद्योग भी डूंगरपुर, व भालावाड में स्थापित किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में लकड़ी की पेटियाँ, कांड-बोर्ड- ग्रीवारो के हल्ये, लकड़ी चोरने आदि के उद्योग, गिनाये जा सकते हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों में चीनी मिट्टी के बरतन, अभ्रक की पिसाई, मारबल कटिंग व ड्रेसिंग, ईंट बनाना, काँच के बरतन, केल्शियम नाइट्रेट, केल्शियम बसोराइट, गारनेट ड्रेसिंग आदि का विकास किया जा सकता है। रसायन उद्योगों में साबुन, पेंट-वानिश, प्लास्टिक, बूट पॉलिश आदि का विकास सम्भव है। धातु-आधारित उद्योगों में शीट मेटल राज्य का सामान्य उद्योग रहा है। अविविध म कृषि के ग्रीवार, तारों का निर्माण, आटा मिलें, स्टील फर्नीचर, स्टीव, कुर्कस, ताले साइकिल व बिलोने आदि बनाये जा सकते हैं। विविध समूह में खेल का सामान, बर्त, आइसक्रीम, सिले-सिलाये घरेलू गलीचो, जूतों, दुग्ध-बदार्थ आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। राज्य में रतन-जवाहरात व आभूषणों, नाना प्रकार की वस्तुकारियों, पर्यटन आदि के विकास के अवसर विद्यमान हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए।

इस प्रकार विभिन्न किस्मों के उद्योगों का विस्तार करके उपमोक्षा-माल व ग्रन्थ पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि भी जा सकती है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास के भी काफी अवसर हैं।

7 प्वासो उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करना—औद्योगिक विकास में उद्योगपतियों से अधिक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उन्हें नये उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए। राजस्थान के कुछ उद्योगपति अन्य राज्यों में उद्योगों को काफी अगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें अपने राज्य में आकर उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज की परिवर्तित परिस्थितियों में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की नीति का विशेष अर्थ नहीं रह गया है, बल्कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के शीघ्र व पर्याप्त विकास एवं विस्तार की नीति अपनायी जानी चाहिए। निजी उद्योगपतियों में उद्योगों के स्थापन, ६-चालन व विक्रय की जा योग्यता है, उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। हम अनियन्त्रित पूँजीवाद की शोषण-श्रवृत्ति एवं सार्वजनिक क्षेत्र को

प्रवायंकुशलता व अर्थमंथ्यता के बोध का कोई अधिक सही एवं व्यावहारिक मार्ग न होना चाहिए। देश के आर्थिक विकास में दोनों क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए समुक्त क्षेत्र का विकास करना भी उचित होगा। रीको के द्वारा समुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने से राज्य में आने वाले वर्षों में औद्योगिक विनियोगों में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।

8. वित्तीय साधनों में वृद्धि—पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य के पास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी रहती है। इनमें वृद्धि करना अत्यावश्यक है। इसके लिए सिचाई व विद्युत-परियोजनाओं में किये गये पुराने विनियोगों से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होंगे। जिन क्षेत्रों व जिन वर्गों की आमदनी बढ़ी है, उनसे अधिक साधन जुटाने होंगे और भविष्य में अपव्ययपूर्ण खर्च को रोकना होगा। राज्य को आन्तरिक साधनों के समूह पर अधिक बल देना चाहिए। गैर योजना व्यय की वृद्धि पर रोक न लग सकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति काफी शोचनीय हो गई है। 1986-87 में राज्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने व बोनस देने से 92 करोड़ रु का प्रतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा था और 1989 के प्रारम्भ में राज्य कर्मचारियों की लम्बा हड़ताल के बाद जो समझौता किया गया है उसका वार्षिक भार लगभग 114 करोड़ रुपये आका गया है। इस प्रकार राज्य के राजस्व का बड़ा भाग प्रशासन पर व्यय हो जाता है। जिससे विकास कार्यों के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहने लगा है। सरकार ने पानी, बिजली व बसों के किराये बढ़ाकर साधन-संग्रह करने का प्रयास किया है, लेकिन इससे सबसे अधिक पर भार बढ़ा है। विभिन्न परियोजनाओं की लागत कम करने व प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

9. राज्य की पशुधन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए—राजस्थान में पशुपालन एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है। इससे राज्य की आय में लगभग 13% का योगदान मिलता है, लेकिन योजना के परिचय का 1% से कम भाग पशुपालन पर खर्च किया जाता है। अतः इस अनुसुलन को कम करने की आवश्यकता है। पशुधन के विकास पर अधिक विनियोजन करने की आवश्यकता है।

10. पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए—राजस्थान में कई पर्यटक-स्थल हैं जहाँ किले, मन्दिर (जैसे माउण्ट आबू में देलवाड़ा का सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर आदि) भौत, पर्वतीय, प्रदेश, वन, पुरानी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कला-कृतियाँ आदि दर्शनीय हैं। इनको देख कर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित होते हैं। अतः पर्यटन-विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए जयपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदला जाना चाहिए ताकि सीधी चार्टर उड़ानें इस शहर तक हो सकें। इसके लिए पर्यटन-निदेशालय को अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न करने होंगे। दस्तकारियों का विकास करना होगा। गाइडों व टैक्सी-ड्राइवर्स की

मलत घाटों पर प्रबुध समाना होगा जिनके समर्थ में विदेशी पर्यटक घाने ही बहुत निराश हो जाते हैं। राज्य मे पर्यटन को उत्तम धोषित करने का कदम सराहनीय रहा है।

11. जिलास्तराेय नियोजन को सक्रिय रूप देकर स्थानीय साधनों का अधिक कारगर उपयोग किया जाना चाहिए तथा विकेन्द्रित नियोजन को सफल बनाया जाना चाहिए। नियोजन की तकनीक मे सुधार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्राथमिक क्षेत्रों मे नये सिरे से सामन-साम अध्ययन किये जाने चाहिए। IRDP व NREP के लिए परियोजनाओं का चयन सही ढंग से किया जाना चाहिए। जब जवाहर-रोजगार-योजना को सफल बनाने तथा पवायनी राज-संस्थाओं को सक्रिय करने के लिए जिला, तहसील व ग्राम-स्तर पर परियोजनाओं के चयन का महत्व बढ़ गया है। इस सम्बन्ध मे नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता बढ़ गयी है ताकि वित्तीय साधनों का उपयोग रोका जा सके और उत्पादक रोजगार बढ़ाया जा सके।

12 ग्राम सुन्दाब—विकास की प्रक्रिया मे आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों मे समुचित ताल-मेल बंढना जाना चाहिए। राज्य में शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किया जाना चाहिए और प्रशासनिक कुशलता मे भी सुधार किया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि नियोजन का एक महत्वपूर्ण सहाय सामाजिक अक्षमताओं को भी कम करना है जिनके लिए राज्य मे अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों व हस्त्रिजनों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाने होंगे। प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि करने की नीति के साथ-साथ कार्यकुशल व ईमानदार व्यक्तियों के लिए उचित प्रेरणाएँ व पुरस्कार एवं प्रशंसा-कुशल व बेईमान व्यक्तियों के लिए पर्याप्त व कड़ी सजाओं की व्यवस्था होनी चाहिये। ये बातें काफी जानी-बूझी हैं। लेकिन आवश्यकता है इनकी व्यवहार मे लागू करने की, जिसमे विकास की गति तेज की जा सके तथा सभी क्षेत्रों मे उत्पादन व कार्यकुशलता बढ़ायी जा सके।

13 राज्य नियोजन व विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने तथा पंचवर्षीय योजना का समुचित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता—कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) गठित किया गया था। लेकिन उतने योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन मे अभी तक कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं निभायी है। सरकार को केन्द्र से आवश्यक विचार-विमर्श करके इसे अधिक सक्रिय बनाना चाहिए। योजना आयोग को नीति इसका भी पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि राज्य की विभिन्न समस्याओं के विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों में गहन अध्ययन करके राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके।

राज्य का योजना विभाग पंचवर्षीय योजना का आरूप तैयार करके दिल्ली में योजना आयोग को भेज करता है जिसमें आवश्यक कटौतों व संशोधन करके योजना आयोग अपनी स्वीकृति दे देता है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का संगोषित व अन्तिम रूप फिर से विस्तृत रूप से तैयार करने की कोशिश नहीं होती बल्कि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही योजना की प्रक्रिया जैत-तैत जारी रखी जाती है। इससे नियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक दोषकासीन परिप्रेक्ष्य या दृष्टि का अभाव सर्वत्र बना रहता है। यहाँ तक कि पंचवर्षीय दृष्टि भी ठीक से सामने नहीं आ पाती है। 10 या 15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य का तो बड़ी नामोनिगान भी नहीं नजर आता। अतः अविद्य अ आवश्यक संशोधन के बाद पंचवर्षीय योजना का अन्तिम यमोदा भी विस्तारपूर्वक जरूर तैयार किया जाना चाहिए। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किये जाने चाहिए। राजस्थान में भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक धन की राशि के आधार पर एक पंचवर्षीय योजना का दशरेवार संशोधन व नया आरूप तैयार किया जाना चाहिए। उलने विकास व उन्नयन के लक्ष्यों के अलावा उनको प्राप्त करने की नीतियों व उपायों पर अधिक प्रकाश डाला जाना चाहिए। ऐसा करने से राज्य में नियोजन की भूमिका अधिक सख्त व सार्थक बन सकेगी। इस समय राज्य में बहुत कुछ वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही काम चलाया जाता रहा है जो काफी नहीं है।

यहाँ भी गुजरात की भाँति औद्योगिक योजना को अधिक वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए बाकी तकनीकी कार्य करना होगा, जैसे विभिन्न उद्योगों के बीच कड़ियों को स्थापित करना (inter industry linkages), विभिन्न जिलों या प्रदेशों के बीच औद्योगिक कड़ियों स्थापित करना, कृषि व उद्योगों के बीच कड़ी स्थापित करना, औद्योगिक सप्लाय व प्रबंध के नए ढाँचे तैयार करना, प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाना सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबन्ध-मयस्था में सुधार करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर व उद्योगों के बीच कड़ी स्थापित करना, टेक्नोलोजी मिशनो का औद्योगिक विकास में उपयोग करना, आदि, आदि। अभी तक इस प्रकार के औद्योगिक नियोजन का निराल अभाव रहा है और बहुत कुछ ऐच्छिक किस्म के निर्णयों से काम चलाया जाता रहा है। आशय है 1990-2000 की अवधि में आठवीं व नवी पंचवर्षीय योजनाएँ पहले की काम चलाऊ प्रवृत्तियों व प्रक्रियाओं से मुक्त होकर वैज्ञानिक व तकनीकी नियोजन का मार्ग ग्रहण कर पायेगी जिनके अभाव में नियोजन एक मुसावे व झुलावे के अलावा और कुछ नहीं है, बल्कि वह एक तरह से रुढ़ पूँजीवादी बाजार-तन्त्र से भी बदतर है।

इन्दिरा गांधी नहर व समस्त कमाण्ड क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने से राज्य को काफी लाभ प्राप्त होगा। राज्य में खनिज-सम्पदा,

देवरी विकास व पशु धन के विकास की वांछी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। राज्य सरकार चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का उपयोग घास उगाने के लिए भी करना होगा। इस दिशा में अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार कोई कारण नहीं कि मनियोजित व अधिक सक्रिय ढंग में धाने बढ़ने पर राज्य अपना वार्षिक विकास अधिक तेज गति से न कर सके।

परिशिष्ट 1

पाचवी योजना, छठी योजना व सातवी योजना के प्रथम तीन वर्षों में राजस्थान राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) व प्रति व्यक्ति आय (1970-71) के आधारों के आधार पर विकास की वार्षिक दरें

पाचवी योजना (1974-79) वर्ष	राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) (करोड़ रु.) (निकटतम)	SDP में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)	राज्य की प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)
(आधार वर्ष) 1973-74	1550		567	
1974-75	1399	(-) 10	496	(-) 12.5
1975-76	1711	22.3	589	18.7
1976-77	1826	6.7	611	3.7
1977-78	1906	4.4	615	0.7

1. वार्षिक व सक्रियिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर, मार्च, 1989 में जारी किये गये नवीनतम आंकड़ों के आधार पर। योजनाकाल में वार्षिक वृद्धि-दर निकालने के लिए प्रतिवर्ष के प्रतिशत परिवर्तनों का ज्यामितीय औसत लिया गया है।

सातवी योजना (1985-88 तक)

आधार वर्ष 1984-85 1985-86	2413	—	639	—
	2417	0.2	623	(-) 2.5
1986-87	2524	4.4	634	1.8
1987-88	2383	(-) 5.6	583	(-) 8.0
(इ) VII योजना में 1985-88 के वर्षों में औसत वृद्धि दर		(-) 0.5		(-) 3

परिशिष्ट 2

राजस्थान में छठी योजना की अवधि में विकास की वार्षिक दर निकालने की विधि का विवरण

पिछली तालिका के आधार पर स्थिर मूल्यों (1970-71 के भावों) पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) में वार्षिक परिवर्तन नीचे दिये गये हैं।

आधार वर्ष (1979-80)	SDP में परिवर्तन % (1)	सूचनाक (2)	सूचनाओं के लाग (Logs) (3)
1980-81	6.0	106.0	2.0253
1981-82	10.8	110.8	2.0445
1982-83	16.1	116.1	2.0611

राजस्थान के बजट व राज्य की वित्तीय स्थिति

(Rajasthan Budget and State Finances)

वर्तमान स्थिति का परिचय

योजनाकाल में राजस्थान के वित्तीय ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय में राज्य की बजट-सम्बन्धी प्रवृत्तियों (budgetary trends), नवें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट (1989-90 के लिए) द्वारा राज्य की तरफ किये गये वित्तीय हस्तान्तरणों तथा राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला जायगा। निरन्तर चलने वाले घाटों व मूँच के कारण राज्य की वित्तीय दशा काफी कमजोर रही है। राज्य के मुद्दह आर्थिक विकास व केन्द्र की तरफ से अधिक वित्तीय सहायता से राजस्थान की आर्थिक मजिद्वी उज्ज्वल बनायी जा सकती है।

1989-90 के बजट-अनुमानों के अनुसार राजस्व-खाते में घाटा 75.8 करोड़ रु. व पूँजी-खाते में बचत 124.6 करोड़ रु. दिखायी गयी है। इस प्रकार समग्र बजट 48.8 करोड़ रु. दिखायी गयी है। 1988-89 के बजट में रहे 148.7 करोड़ रु. के घाटे की गारंटी करके 1989-90 की अवधि के लिए कुल घाटे की राशि लगभग 100 करोड़ रु. हो जायेगी है। सरकारी कर्मचारियों की लम्बी हट्टाल के बाद जो समझौता किया गया है उसका आर्थिक वित्तीय भार लगभग 114 करोड़ रु. का आका गया है। इनके अतिरिक्त 1989-90 में लगभग 28 करोड़ रुपये के हरियर्स का भार है, लेकिन वर्ष 1989-90 में नई मूँच 104 करोड़ रु. का हो करना है जिससे इस वर्ष के अंत में सम्भावित घाटा 204 करोड़ (100 + 104) रुपये होने का अनुमान है।¹

अब हम राजस्व-खाते में आय व्यय की प्रवृत्तियों पूँजी-खाते में आय-व्यय की प्रवृत्तियों, मार्बजनिब कर्ज के भार आदि पर प्रकाश डालेंगे।

राजस्व खाते में आय की प्रवृत्तियाँ¹

(Trends in Receipts under Revenue-account)

राजस्व खाते में विभिन्न प्राप्तियों को तीन श्रेणियों में बाटा जाता है—

कर-राजस्व अन्तर राजस्व तथा सहायतायें अनुदान (grants-in aid)

1 कर राजस्व—इसके अन्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करो में हिस्सा तथा स्वयं राज्य में लगाय गये करो का राजस्व दिखाया जाता है। आजकल राजस्थान को ग्रन्थ राज्यों की भाँति केन्द्रीय आयकर व सघीय उत्पादन-शुल्क में अंश प्राप्त होता है। राज्य को स्वयं के प्रदेश में लगाये गये निम्न करो से राजस्व की प्राप्ति होती है : भू-राजस्व (land revenue), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, राज्य आदकारी (state excise), बिक्री कर (sales tax) वाहनो पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, विद्युत् पर कर व शुल्क तथा अन्य कर य महसूल। अन्य करो में मनोरजन कर, व्यापारिक फसलों पर उपकर वगैरा शामिल हैं।

1951-52 में कुल कर राजस्व की प्राप्ति 11.6 करोड़ रु. हुयी जो बढकर 1961-62 में 29 करोड़ रु. 1971-72 में 109 करोड़ रु., 1981-82 में 508 करोड़ रु. तथा 1987-88 में 1183 करोड़ रु. हो गयी 1989-90 के बजट-अनुमानों में कर-राजस्व से 1586 करोड़ रु. की राशि दिखायी गयी है।

करो को प्रत्यक्ष व परोक्ष दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष करो का भार किसी दूसरे पर नहीं खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करो का खिसकाया जा सकता है। राजस्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष करो से राजस्व प्राप्त होता है उनमें निम्न शामिल हैं : मुख्यतया केन्द्रीय आयकर में अंश, भू-राजस्व (land revenues), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा अचल सम्पत्ति पर कर। परोक्ष करो (indirect taxes) में निम्न कर आते हैं : सघीय आदकारी या उत्पादन-शुल्को में अंश, राजकीय आदकारी, बिक्री कर व हनो पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, विद्युत्-शुल्क, मनोरजन कर तथा व्यापारिक फसलों पर उपकर।

1971-72 में कुल कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करो का अंश 29% था जो 1987-88 में 15.6% हो गया। 1989-90 के बजट-अनुमानों में इसके लगभग 14.8% रहने का अनुमान है। इस प्रकार कर राजस्व में प्रत्यक्ष करो का योगदान घटता गया है और परोक्ष करो का बढ़ता गया है। पिछले वर्षों में परोक्ष करो का अंश लगभग 85% रहा है।

1 नीतिगत आकड़े आयव्ययक अध्ययन, 1989-90 से लिये गये हैं।

कर राजस्व का विश्लेषण—निम्न तालिका में विभिन्न वर्गों के लिए कर राजस्व में विभिन्न मदों का योगदान का विवरण दिया जाता है

शोधक	1971-72		1987 88		1989 90	
	(Accounts)		(Accounts)		(B E)	
	(लक्ष करोड़ रु.)	(प्रतिशत)	(लक्ष करोड़ रु.)	(%)	बजट अनुमान (करोड़ रु.)	(%)
1 केंद्रीय करों में अंश	43.3	39.7	410.3	34.7	588.1	37.0
2 राज्य कर राजस्व	65.7	60.3	772.5	65.3	998.1	63.0
(i) मूल राजस्व	8.6	7.9	22.6	1.9	27.1	1.7
(ii) इन्कम व रजि स्ट्रेशन शुल्क	3.5	3.2	39.9	3.4	49.6	3.1
(iii) राज्य प्राधिकारी	9.4	8.6	127.3	10.8	184.0	11.6
(iv) विद्या-भर	33.1	30.4	450.5	8.1	575.0	36.3
(v) वाहनों पर कर	3.8	3.5	84.3	7.1	102.3	6.4
(vi) अन्य	7.3	6.7	47.8	4.0	60.1	3.8
कुल कर राजस्व	109.0	100.0	1182.8	100.0	1586.2	100.0

तालिका से पता चलता है कि 1971-72 में कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों का अंश 40% था जबकि 1989-90 के बजट-अनुमानों में यह कर 37% पर आ गया है। इस प्रकार राज्य सरकारों का कर राजस्व का अंश 60% से बढ़कर 63% हो गया है। मूल राजस्व का अंश काफी घट गया है। 1971-72 में 8%

से घटकर 1989-90 के बजट-अनुमानों में 1.7% पर आ गया है। इसी अवधि में बिजली-कर का योगदान 30% से बढ़कर 36% पर आ गया है।

राजस्व राज्य के कर राजस्व में बिजली-कर का स्थान प्रथम है। 1989-90 के बजट में राज्य का स्वयं का कुल कर-राजस्व 998 करोड़ रु. था। जिसमें बिजली-कर 575 करोड़ रु. अर्थात् 58% है। इस प्रकार राज्य की करो से प्राप्त राशि बिजली-कर की सर्वोपरिता है। दूसरा स्थान राज्य आवकियों का तथा तीसरा वाहनों पर कर का है। भूमि-मुधारों के कलस्वरूप भू-राजस्व का योगदान कुल कर-राजस्व में केवल 1.7% रह गया है।

2 अ-कर राजस्व (Non Tax Revenue)—राजस्व-स्रोतों में आय का यह दूसरा स्रोत है। सहायताधन अनुदान (grants-in-aid) जो केन्द्र से प्राप्त होते हैं वे भी इसी के अन्तर्गत दिखाये जाते हैं, हालांकि उनकी राशि उंची होने से उनका विवेचन अलग से भी किया जाता है। अ-कर राजस्व की आय निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत दिखायी जाती है : व्याज की प्राप्ति, सामाजिक एवं साम. सामान्य सेवाओं से प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाओं, प्राथमिक सेवाओं व अन्य से प्राप्त राशि, एवं सहायताधन अनुदान।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत निम्न मदें शामिल होती हैं : (i) शिक्षा, कला व संस्कृति, (ii) विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण, (iii) जलपूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास तथा (iv) अन्य। प्राथमिक सेवाओं में निम्न मदें आती हैं : (i) सड़क निर्माण, (ii) वित्तीय व अन्य जीवन, (iii) उद्योग, सामाजिक व सड़क उद्योग, (iv) वृहद् एवं मध्यम निर्माण, (v) अतीव धातु, खनन व धातु कार्मिक उद्योग व (vi) अन्य।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है सहायताधन अनुदान भी अ-कर राजस्व के अन्तर्गत ही दिखाये जाते हैं।

अ-कर राजस्व का वर्गीकरण 1972-73 से बदला गया है। 1951-52 में अ-कर राजस्व की राशि (सहायताधन अनुदानों सहित) 4.4 करोड़ रु. थी जो बढ़कर 1961-62 में 17 करोड़ रु. 1971-72 में 76 करोड़ रु. व 1981-82 में 349.7 करोड़ रु. हो गई। 1987-88 में अ-कर राजस्व की राशि 1000 करोड़ रु. रही तथा 1989-90 के बजट अनुमानों में 938 करोड़ रु. आंकी गई है। यह सभी सहायताधन अनुदानों में वृद्धि करने से हुयी है।

राजस्व-स्रोतों में आय के इन तीन स्रोतों का योगदान प्रत्येक साल का दर्शाया गया है :

(प्रतिशत में)

	1987-88	1989-90
	(लेखे में)	(बजट-अनुमानों में)
(i) कर-राजस्व	54.2	62.8
(ii) अ-कर राजस्व	16.9	15.8
(iii) सहायताय अनुदान	28.9	21.4
	<hr/> 100.0	<hr/> 100.0
कुल राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)	<hr/> 2183	<hr/> 2524

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्व-स्त्रोतों की कुल प्राप्ति में सहायताय अनुदानों का वश 1989-90 के बजट-अनुमानों में लगभग 1/5 आंका गया है जो 1987-88 से कम है।

राजस्थान में कुल कर-राजस्व की घरेलू उत्पत्ति से अनुपात

निम्न तालिका में 1971-72, 1981-82 तथा 1986-87 के लिए राज्य में कुल कर-राजस्व व राज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर) काफ़ी दिये गये हैं—

(करोड़ रु.)

	1971-72	1981-82	1987-88
1. कुल कर-राजस्व	109	508	1183
2. राज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर)	1534	4978	9502
3. कुल कर-राजस्व का राज्य की आय से अनुपात	7.1%	10.2%	12.5%

इस प्रकार कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करों में अंश सहित) राज्य की आय का 1987-88 में 12.5% रहा जो 1971-72 की तुलना में लगभग 5% अधिक था।

राज्य में कर-प्रयास की सोच (Effort of tax effort in the State)—दो वर्षों के बीच कुल कर-राजस्व की प्रतिशत वृद्धि में राज्य की आय की प्रतिशत वृद्धि

का भाग देने से जो परिणाम आता है उसे राज्य के कर-प्रयास की सोच कहा जाता है। गणना प्रचलित मूल्यों के आधार पर की जाती है।

राजस्थान में 1960-61 से 1970-71 के बीच कर-प्रयास की सोच 1.5 रही थी। 1971-72 से 1987-88 के बीच यह 1.90 रही। इसका अर्थ यह है कि राज्य में कर-प्रयास लोचदार रहा है। कुल कर-राजस्व की प्रतिशत वृद्धि राज्य की आय की प्रतिशत वृद्धि से अधिक रही है। इस प्रकार राज्य ने करों से अधिक आय जुटाने की दिशा में प्रगति दर्शायी है। यदि कर-प्रयास की सोच एक से कम होती तो राज्य अपने कर-प्रयास में निछाड़ा हुआ माना जाता है। समय के दो विद्यमान पर आधारित होने के कारण कर-प्रयास की सोच काफी बदलती रहती। 1971-72 से 1981-82 की अवधि लेने पर यह 1.63 आती है। अतः कुल मिलाकर राजस्थान में कर-प्रयास की सोच बढ़ी बढ़ी है।

राजस्व-खाते में व्यय की प्रवृत्तियाँ

(Trends in Expenditure in Revenue Account)

राजस्व-व्यय को निम्न शीपको के अन्तर्गत दिया जाता है :

1 सामान्य सेवाओं पर व्यय—इसमें राज्य के अंगों (organs of state) पर व्यय (मंत्री परिषद, विधान सभा, व्याय प्रशासन, निर्वाचन आदि), राजकीय सेवाएँ (कर समूची व्यय) प्रमाण परिशोधन व स्वायत्त संगठन, प्रशासनिक सेवाएँ, पेंशन व विविध सामान्य सेवाएँ तथा सहायतायें अनुदान (जो राज्य सरकार देती है) शामिल होते हैं।

2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय—इसमें निम्न मदों का व्यय आता है :

(i) शिक्षा खेल-कला एवं शस्त्रुति, (ii) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (iii) जलपूर्ति, सफाई आवास व ग्रहणी विकास, (iv) श्रमिक व श्रमक-कल्याण, (v) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, समाज कल्याण व पोषाहार।

3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय—इसमें निम्न मदें शामिल होती हैं : (i) कृषि व सम्बद्ध सेवाएँ, (ii) ग्रामीण विकास व विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, (iii) उद्योग व खनिज, (iv) सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण व ऊर्जा, (v) परिवहन, (vi) विज्ञान, टेक्नोलॉजी व पर्यावरण तथा (vii) सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

1951-52 में कुल राजस्व-व्यय 17.2 करोड़ रु. हुआ जो बढ़ कर 1961-62 में 52 करोड़ रु., 1971-72 में 203 करोड़ रु. व 1981-82 में 823 करोड़ रु. हो गया। 1987-88 में राजस्व व्यय 2539 करोड़ रु. हुआ जिसके 1989-90 के वज्र-अनुमानों में 2600 करोड़ रु. रहने का अनुमान है।

1989-90 में राजस्व-व्यय का सर्वाधिक अंश लगभग 39% सामाजिक सेवाओं पर, 37% सामान्य सेवाओं पर तथा शेष 24% आर्थिक सेवाओं पर व्यय हेतु रखा गया था :

नीचे 1987-88 (वास्तविक व्यय) व 1989-90 (बजट-अनुमानों) के लिए कुछ व्यय की मदों पर कुल राजस्व व्यय का अनुपात दर्शाया गया है :

शीर्षक	1987-88		1989-90	
	लेखे (A/Cs) कुल (करोड़ रु.)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	(बजट- अनुमान) (करोड़ रु.)	कुल राजस्व- व्यय का प्रतिशत
1. ऋण-परिपोषण व व्याज का भुगतान (सामान्य सेवाओं में)	298.7	11.8	431.1	16.6
2. शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति (सामाजिक सेवाओं में)	473.3	18.6	196.4	23.0
3. सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण व ऊर्जा (आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत)	256.3	10.1	599.2	7.6
4. प्रशासनिक सेवाएँ (सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत)	174.6	6.9	224.6	8.6
(ग्रन्थ सहित) कुल राजस्व-व्यय (Total Revenue Exp.)	2539		2600	

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य का ऋण भार इतना बढ़ गया है कि कुल राजस्व-व्यय का लगभग 16-17 प्रतिशत ऋण-भुगतान व व्याज के भुगतान पर लग जाता है। लगभग 1/4 व्यय शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति नाम की मद पर होता है। प्रशासनिक सेवाओं पर कुल राजस्व-व्यय का लगभग 9% व्यय होने लग गया है।

राजस्व-व्यय को (i) विकास-व्यय व (ii) अ-विकास व्यय में भी विभाजित किया जाता है। 1951-52 में विकास व्यय कुल राजस्व व्यय का 42% हुआ

करता था जो 1971-72 में 58%, 1981-82 में 70% व 1987-88 में 75% रहा, लेकिन 1989-90 के बजट-अनुमानों में लगभग 63% ही रखा गया है।

इस प्रकार योजनाकाल में विकास-व्यय का अनुपात बढ़ा है। लेकिन 1989-90 के बजट-अनुमानों में 1987-88 के वास्तविक व्यय की तुलना में यह लगभग 12% घटा है जो एक चिंता का विषय है।

1973-74 में राजस्व व्यय के प्रस्तुतीकरण का रूप बदल गया है। जता कि ऊपर स्पष्ट किया गया है अब यह सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर दिखाया जाता है।

राजस्व खाते में घाटा

राजस्थान में राजस्व-खाते में 1951-52 में 1.2 करोड़ रु का घाटा हुआ था जो 1971-72 में 17.9 करोड़ रु रहा। 1981-82 में राजस्व खाते में 35.6 करोड़ रु का अमूलपूर्व घाटा रहा तथा 1989-90 के बजट-अनुमानों में 76 करोड़ रु का घाटा दिखाया गया है। राज्य प्रशासकों से समझौता करने में राज्य पर 114 करोड़ रु का वित्तीय भार आया है जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और कमजोर हो गई है।

राजस्व-खाते के प्रतिरिक्त खन देन

(Transactions outside the Revenue Account)

(क) प्राप्तियाँ (Receipts)—राजस्व-खाते के अलावा अन्य प्राप्तियाँ निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखायी जाती हैं :

(i) स्थायी ऋण (Permanent debt)—इसके अन्तर्गत जनता से लिये गये बाजार ऋण शामिल किये जाते हैं। ये व्याज वाले व बिना व्याज वाले दो प्रकार के होते हैं। ये विकास-कर्ज होते हैं जो राज्य की विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए जारी किये जाते हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये 'प्लोटिंग-ऋण' या अल्पकालीन ऋण भी शामिल किये जाते हैं।

(ii) घटपड़ाशील ऋण (Floating debt)—इनकी मात्रा राज्य के व्यय के माध्यमों व प्राप्तिशक्ती पर निर्भर करती है। ये काफी परिवर्तनशील होते हैं।

(iii) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (Loans from the Central Government)—राज्य सरकार के केंद्रीय सरकार से भी ऋण लेती है। ऐसा प्रचलन भी प्रायः है जब भारतीय रिजर्व बैंक से सी गई प्रोवरहाउट की राशि का चुकाने के लिए केंद्र ने राज्य को ऋण दिये हैं।

(iv) अन्य ऋण (Other Loans)—इसमें राज्य सरकार द्वारा सांकेतिक वित्तीय सन्धियों से लिये जाने वाले ऋण शामिल होते हैं।

(v) सार्वजनिक लेखा (Public Account)—इस शीर्षक से प्राप्त राशि काफी ऊँची होती है। इसमें अ-कोषीय ऋण (un funded debt) व अन्य ऋणों की प्राप्तियाँ आती हैं।

(vi) ऋण व अग्रिम (Loans and Advance)—राज्य सरकार को सामान्य सेवाओं सामाजिक सेवाओं व धार्मिक सेवाओं के धनगत दिये गये कर्ज की राशि प्राप्त होती है—वह इस शीर्षक के नीचे दिखाई जाती है।

नीचे 1987-88 व 1989 90 (बजट-अनुमानों) की अवधि के लिए राजस्व खाते के अतिरिक्त कुल प्राप्त राशियों का उल्लेख किया गया है (इनमें से चुकाई गई राशियाँ नहीं घटाई गई हैं)।— (करोड़ रु में)

शीर्षक	1987-88 (लेखे)	1989 90 (बजट-अनुमान)
(i) स्थायी ऋण	119 0	165.2
(ii) घलपकालीन ऋण (Floating debt)	498 6	500 0
(iii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	553 7	407 2
(iv) अन्य ऋण " " "	16 3	29 8
(v) सार्वजनिक लेखा (अ-कोषीय ऋण व अन्य ऋण)	4726 8	3145 8
(vi) ऋण व अग्रिम	43 8	61.2
(vii) प्राकृतिकता निधि	—	—
	5958 2	5309 2

इस प्रकार राजस्व-खाते के अलावा अन्य प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे के अन्तर्गत ऋण, जमाओं व भुगतान के सौदों की राशियाँ सर्वाधिक होती हैं। इसके अलावा केन्द्र से लिये गये ऋण व बाजार से लिये गये स्थायी व अल्पकालीन ऋणों का भी काफी महत्व होता है। कहने का तात्पर्य है यह कि इनमें विभिन्न प्रकार के ऋणों की राशियाँ घाती हैं। दूसरी मद—“ऋण व अग्रिम” के अन्तर्गत सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं को दिये गये ऋणों की रिकवरी की राशियाँ घाती हैं।

(ख) राजस्व-खाते के अलावा वितरण (disbursements) की अन्य राशियाँ—इसके अन्तर्गत पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) तथा स्थायी ऋण, अल्पकालीन ऋण, केन्द्र सरकार को चुकाये गये ऋण अन्य ऋण, सार्वजनिक लेखा, ऋण व अग्रिम वगैरह के अन्तर्गत किये गये वापसी भुगतानों की राशियाँ घाती हैं। पूँजीगत व्यय राजस्व-व्यय की याति सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं की विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इसका प्रयोजन परिसम्पत्ति का निर्माण करना होता है।

राजस्व-खाते के अलावा वितरण की राशियाँ 1984-85 (लेखे) व 1987-88 (बजट) के लिए निम्न तालिका में दिखायी गयी हैं ताकि विभिन्न मदों के प्रकार की जानकारी हो सके :—

वितरण (disbursements)

	1987-88	1989-90
	(लेखे)	(बजट-प्रनुमान)
(i) पूँजीगत व्यय (शुद्ध)	400.2	~ 441.7
(ii) स्थायी ऋण.....	23.9	22.8
(iii) अल्पकालीन ऋण....	447.9	500.0
(iv) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण.....	223.8	163.2
(v) अन्य ऋण.....	6.1	8.3
(vi) सार्वजनिक लेखा (अ-कोपीय ऋण व जमाएँ)	4379.5	3906.4
(vii) ऋण व अग्रिम.....	190.8	142.2
(viii) आकस्मिकता निधि का विनियोग (Appropriation to Contingency Fund) —		—

कुल वितरण (Total Disbursement) 5672.2

5184.6

तालिका में स्पष्ट होता है कि विवरण-पक्ष की ओर भी सर्वोपरि राशि 'सार्वजनिक नेमे' की ही होती है। इसके अलावा पूँजीगत व्यय, स्थायी ऋण व अल्पकालीन ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों को चुकाने की राशिया दिखायी जाती है। इस प्रकार विभिन्न किस्म के ऋणों के पुनर्मुँगटान की राशिमें इस खाते के 'विवरण' पक्ष में शामिल होती है।

राजस्व-खाते के अतिरिक्त बचत (+) या घाटा (-)

पिछले वर्षों में राजस्व-खाते के अतिरिक्त बचाया की राशिया निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :—

	(करोड़ रु.)
1981-82	(-) 28.3
1984-85	(+) 61.6
1987-88	(+) 286.1
1988-89 (सं. अनुमान)	221.7
1989-90 (बजट-अनुमान)	124.6

इस प्रकार पिछले वर्षों में राजस्व-खाते के अलावा अन्य सैन-देनों में अग्र्य वर्षों में बचत की स्थिति रही है। जिन वर्षों में राजस्व-खाते व इसके अलावा अन्य सैन-देनों में अग्र्य दोनों में घाटा होता है, उन वर्षों में समग्र घाटा बहुत ऊँचा रहता है जो प्राये दिखाया गया है।

समग्र घाटे या बचत की स्थिति—1981-82 (लेख) से 1989-90 (बजट-अनुमानों) तक समग्र घाटे या बचत की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :¹

बचत (+) या घाटा (-)

वर्ष	(करोड़ रु. में)
1981-82 (लेख)	(+) 5.9
1982-83 (")	(+) 23.2
1983-84 (")	(+) 8.9

1. Budget Study 1989-90 व पूर्व वर्षों के लिए, DES, Jaipur, and Budget Speech 1989-90, 23 मार्च 1989, पृ. 51-52.

काफी चरमरा गयी थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने बजट-भाषण में नये कर लगाने के स्थान पर करो की बेहतर वसूली व करो के अपवचन को रोकने पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया।

बिक्री-कर के सम्बन्ध में कुछ सरलीकरण के उपाय घोषित किये गये हैं। जो व्यापारी कर मुक्त व कर दी हुई (tax-paid) वस्तुओं में लगे हैं उन्हें रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार दो वर्षों में लगभग २० हजार खुदरा व्यापारी रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिये गये हैं। इनका व्यापारिक क्षेत्रों में स्वागत किया गया है।

जो व्यापारी 10 लाख से ऊपर की बिक्री दिखाते रहे हैं, यदि वे अपनी करदेय बिक्री की राशि में 15% वृद्धि कर दें, तो उन्हें भी नई स्वकर-निर्धारण स्कीम में ले लिया जायगा। राजस्थान बिक्री-कर (मशीन) बिल, 1989 पेश किया गया है ताकि इसमें उचित मशीन किया जा सके।

ट्रैक्टर होवर पाट पर कर की दर 10% से घटा कर 4% कर दी गयी है। गुट, वनस्पति वी, व सल परकर कम किये गये हैं। रत्नों व स्टोन्स पर कर कम किये गये हैं। हीरो पर बिक्री-कर में छूट दी गई है। पतंग, पतंग-बोरी व पतंग-चरखी पर कर हटाया गया है। शक्ति करवी के कल-पुत्रों आदि पर कर कम किया गया है। हाथ से बने ऊनी रोयेदार गलीचों, झड़ू व बास की टोकरीयों को बिक्री-कर में छूट दी गई है। दैनिक उपयोग की बर्द मर्दों जैसे हस्ती सोक, घमचूर, माचिस, बर्तन, मैदा, सिलाई के घागे आदि पर करो में ५ मी की गयी है। इसी प्रकार सानुन, ब्लेड, पेन, घर्भण, स्क्रूडी बंग आदि अन्य वस्तुओं पर कर घटाये गये हैं।

इस प्रकार 1989-90 के बजट में घाम उपभोक्ता के लिए करो में काफी राहत दी गई है।

1989-90 के अब में कुल घटा लगभग 204 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जिसे क्लिहाल अपूरित छोड़ा गया है। इस घाटे की पूर्ति वस्तुओं पर सेव कर (consignment tax) लगा कर, करो की बेहतर वसूली करके, बकाया वजों की वसूली करके, केन्द्रीय सरकार से अधिक धनराशि प्राप्त करके अनुपादक व गैर-आवश्यक व्यय में कटौत, आदि करके पूरा की जायगी। वित्तीय अनुशासन व सरकारी व्यय पर ~~का~~ का सहारा लिया जायगा।

1. Budget Study 19 ^{स्पष्ट होता है कि राज्य वित्तीय सचट ने दीर से गुजर}
 Budget Speech 1989- ^{कठिनाइयाँ हैं :-}

(1) 1989-90 के बजट में विकास-व्यय कुल राजस्व-व्यय का 63% रह गया है जबकि 1987-88 में यह 75% था। इस प्रकार गैर-विकास के अनुपात का बढ़ना उचित नहीं है।

(2) राज्य पर व्याज की अदायगी व ऋण चुकाने का भार बहुत बढ़ गया है। यह 1985-86 में 201 करोड़ रु था जिसके 1989-90 में बढ़ कर 431 करोड़ रु. होने का अनुमान है। इस प्रकार चार वर्षों की अल्पावधि में यह दूगुने से अधिक हो गया है।

(3) इसी प्रकार प्रशासनिक सेवाओं (लोक सेवा आयोग, सचिवालय, जिला प्रशासन, ट्रेंजरी, पुलिस, जेल, प्रिटिंग आदि) पर व्यय 1985-86 में 138 करोड़ रु से बढ़ कर 1989-90 में 225 करोड़ रु हो जाने का अनुमान है। 1989-90 में राज्य के स्वयं के कर-साधनों से 998 करोड़ रु के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है। केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 588 करोड़ रु के राजस्व का अनुमान है। इस प्रकार स्वयं के कर-राजस्व का लगभग 22.5% प्रशासन पर व्यय किया जाता है जो काफी ऊँचा है।

व्याज की अदायगी व ऋण-परिशोधन तथा प्रशासनिक सेवाओं पर राज्य के स्वयं के कर-राजस्व का 66%, अथवा $2\frac{1}{3}$, लग जाता है जिससे अन्य कार्यों के लिए साधन बहुत सीमित रह जाते हैं।

(4) राज्य पर मार्च 1989 के अंत में बर्ज की बकाया राशि 4569 करोड़ रु. थी जिसमें केन्द्रीय सरकार के बर्जों की राशि 2889 करोड़ रु. थी। इस प्रकार राज्य की केन्द्रीय बर्जों पर निर्भरता बहुत अधिक है। केन्द्र द्वारा समस्त 25 राज्यों को दिया गया कुल बकाया बजट मार्च 1989 तक 56173 करोड़ रु था जिसमें राजस्थान का भ्रश 5.1% था। अतः राज्य पर ऋण चुकाने का भार असह्य हो जाता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति काफी नाजुक व असन्तोषजनक है। इसी वजह से सरकार के बारम्बार केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता की मांग करनी पड़ती है, चाहे वह ममला योजना के लिए अधिक सहायता देने के रूप में रखा जाय, अथवा प्रकाल व सूखे के लिए राहत-सहायता बढ़ाने के रूप में रखा जाय, अथवा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता देने के रूप में रखा जाय अथवा पुराने ऋणों में कमी करने के रूप में पेश किया जाय अथवा केन्द्र वा कुछ ऋणों की समाप्ति के लिए निवेदन किया जाय। राज्य का वित्तीय मकड़ सर्वावर्धित है और इसके लिए राज्य वा केन्द्र की तरफ झुटना स्वाभाविक है।

कुछ क्षेत्रों में यह चर्चा रही है कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि आयोग की सिफारिशें

सानचे व छाटचे वित्त आयोगों की मिकारिगों के अनुसार राजस्थान का अंश

विभिन्न मदें	मतर्से वित्त आयगा के अनुसार	छाटचे विन आयों के अनुसार	
		(अय-कर के निश्चित मे न लगन पर)	(अय-कर के निश्चित मे लगने पर)
1 अय-कर की विभाज्य आय मे राजस्थान का अंश	विनिश्चित क बिना 4 364% मिश्चित सहित 4 362%	अवकाश (मिश्चित के बिना) 4 547%	अवकाश (मिश्चित सहित) 4 545%
2 मधोय उत्पादन-गुल्म मे राजस्थान का अंश	4 813%	4 695% 1 940% मे (केवल 1984-85 के लिए)	(40% अंश मे मे) बाय 5% मे
3 अनिश्चित उत्पादन शुल्को मे (बन्ध चीनी व मन्दाकू)	4 729%	4 817%	
4 रल यन्त्री किरायो पर कर की एवज मे अनुदान की विभाज्य आय मे	5 48%	4 87%	
5 सहायनार्य-अनुदान	—	42 63 करोड रु. (1984-85 तथा 1985-86 के लिए हो, अन्य तीन बरों के लिए नहीं)	
6 राहत-उपय के लिए माहित मनी अनुदान	—	8 375 करोड रु. (वार्षिक) अथवा 41.88 (1984-89 के लिए)	

7 केन्द्रीय सरकार के ऋणों की वापस ब्याजयोगी में राहत	137.98 करोड़ रु. (1979-84 के लिए)	239.41 करोड़ रु. (1985-89 की अवधि के लिए)
8 प्रशासन को समुन्नत करने व विशेष समस्याओं के लिए	19.29 करोड़ रु.	53.48 करोड़ रु. (1984-89 के लिए) इसमें से 10 करोड़ रु विशेष समस्याओं के लिए थे।

सातवें वित्त आयोग ने कुल केन्द्रीय राजस्व का 26% भ्रष्ट, भर्पाव 20843 करोड़ रु. राज्यों को हस्तान्तरित किये थे। इसमें करों, शाल्को व सहायताय-अनुदानों की राशिया शामिल हैं। आठवें वित्त आयोग ने कुल केन्द्रीय राजस्व का 24.1%, भर्पाव 39452 करोड़ रु. सभी राज्यों को हस्तान्तरित किये।

अनुमान है कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान के पक्ष में हस्तान्तरण की कुल राशि 1676.17 करोड़ रु. आयेंगी, जो कुल हस्तान्तरण-राशि (39452 करोड़ रु.) का 4.25% बनती है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल हस्तान्तरणों में राजस्थान का भ्रष्ट 5.8%, तथा सातवें वित्त आयोग के अनुसार 4.33% रहा था। इस प्रकार वित्त-विरोधियों का कहना है कि आठवें वित्त आयोग ने कुल हस्तान्तरणों में राजस्थान का बराबर से कम (4.25%) कर दिया है जो आठवें वित्त आयोग का राज्य के प्रति कठोर व अनुदार दृष्टिकोण का परिचायक है।

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कुल हस्तान्तरणों में असा की दृष्टि से चाहे राजस्थान का हिस्सा कुछ कम हुआ हो, लेकिन मानावक दृष्टि से सातवें वित्त आयोग की हस्तान्तरण राशि (922.1 करोड़ रु.) के मुकाबले आठवें वित्त आयोग की हस्तान्तरण राशि (1676.17 करोड़ रु.) 82% अधिक थी। मुख्यमंत्री श्री शिवचरण भायूर ने राजस्थान विधान सभा में 17 अक्टूबर 1984 को कहा था कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य को केन्द्रीय करों में 1538.11 करोड़ रु मिलेंगे, जबकि सातवें वित्त आयोग के अनुसार 902.81 करोड़ रु. ही मिले थे। सातवें वित्त आयोग के अनुदान सहायताय-अनुदान के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला था, जबकि आठवें वित्त आयोग के अनुसार 42.63 करोड़ रु. मिले। सातवें वित्त आयोग ने प्रशासनिक सुधार के लिए 19.29 करोड़ रु. दिये,

जबकि आठवें वित्त आयोग ने 53.48 करोड़ रु दिये। सातवें वित्त आयोग ने माजिन मनी अनुदान नहीं दिया था, जबकि आठवें वित्त आयोग ने 41.88 करोड़ रु दिये। इस प्रकार श्री माथुर का कहना था कि आठवें वित्त आयोग की सफा-रिशो को राजस्थान के लिए अनुदार नहीं कहा जा सकता।

लेकिन यह भी सत्य है कि केन्द्र से राजस्थान को अधिक राशि के हस्तान्तरण के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति उत्तरोत्तर कमजोर होती गयी है। इस सम्बन्ध में एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि यदि आयकर व सघीय उत्पादन शुल्क के अणों के राज्यों में वितरण के आधार में जनसंख्या को जो उँचा भार दिया गया है (वर्द्ध विन्दुओं पर सम्बद्ध राशियों को जनसंख्या से गुणा करने के कारण) यदि वह भार नहीं दिया जाता, (घर्षान् सम्बद्ध राशि जैव प्रति व्यक्ति आय के विलोम, वगैरा को जनसंख्या से गुणा न किया जाता) तो राजस्थान का अंश वितरणीय राशि में अधिक आ सकता था।

हेमलता राव ने अपने लेख में बतलाया है कि आठवें वित्त आयोग के प्रति-मानों व सूत्र के अनुसार राजस्थान का केन्द्रीय करो में औसत अंश 59.1% आता है जबकि जनसंख्या वाला भार हटा देने पर यह 7.45% हो जाता है।¹ इसलिए राज्य का प्रतिशत अंश बढ़ाने के लिए जनसंख्या का आयकर व उत्पादन-शुल्क के वितरण में विभिन्न विन्दुओं पर दिये जाने वाले भार (जहाँ जहाँ जनसंख्या से गुणा किया जाता है जैसे प्रति व्यक्ति आय के विलोम × जनसंख्या आदि) को हटाने का सुझाव दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या जनसंख्या व भार का समाप्त करना उचित होगा? जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है उनको आयोग के सूत्र से लाभ मिला है जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, वगैरा। इसलिए जनसंख्या के भार को हटाने से ये राज्य विरोध प्रगट करेंगे। ऐसे जनसंख्या को भार देने से मानवीय आवश्यकताओं को भार निरस्त है जो कुछ सीमा तक उचित माना जा सकता है। लेकिन केन्द्रीय हस्तान्तरणों में ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक राज्य अपनी पसन्द का कोई न कोई आधार लेना चाहता है जैसे कोई क्षेत्रफल को, कोई जनजाति व पहाड़ों जाति को ज्यादा भार देना चाहते हैं। इसलिए सभी राज्यों को एक साथ लाभ पहुँचाने वाला कोई भी आधार चुन सकना कठिन है।

राजस्थान में आधे दिन अकाल व सूखा पड़ता रहता है। इफास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सड़क, बिजली व पानी की व्यवस्था को ठीक करना भी

1. Hemlata Rao, Eighth Finance Panel : New Criteria of Fiscal Transfers, in the Economic Times September 17, 1984, table

आवश्यक है। इसलिए राज्य के हित में जनसंख्या का आधार उपयुक्त नहीं माना जाता, बल्कि अकाल-राहत सहायता की आवश्यकता की सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य को विशेष रूप में अनुदान मिलने चाहिए जो गैर-योजना क्षेत्र में हो। पिछले वर्षों में राज्य के अकाल-सहायता के बनौर अरबों रुपये की धनगति व्यय की है। यह धन-राशि उस गैर-योजना अनुदानों (non-plan grants in-aid) के रूप में मिलनी चाहिए थी। तब तो राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार सम्भव हो सकता है।

केन्द्र से राजस्थान की तरफ प्रति व्यक्ति बजट-सम्बन्धी

हस्तान्तरण की राशि

(Per Capita Budgetary Transfers from Centre to Rajasthan)

के के जोर व फाई एल. गलाटी ने 19.6-1981 की अवधि के लिए केन्द्र से राज्यों की तरफ किये जाने वाले विविध श्रेणी के हस्तान्तरणों की प्रति व्यक्ति राशियों का विस्तृत अध्ययन किया है।¹ वैधानिक (statutory) हस्तान्तरणों के विषय में आवश्यक सिफारिशों वित्त आयोग किया करते हैं जिनमें आय-कर, सपीप-उत्पादन शुल्कों आदि में राज्यों के भ्रम निश्चिन किये जाते हैं तथा महादमार्ग अनुदान की राशियाँ निश्चिन की जाती हैं तथा ऋणों के सम्बन्ध में राहत की राशि निर्धारित की जाती है। योजना हस्तान्तरणों की निश्चिन फार्मूले के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाता है। अन्य हस्तान्तरण केन्द्रीय मंत्री मण्डल के निर्णय पर आधारित होते हैं, जिन अकाल व बड़ राहत सहायता, आदि।

1956-1981 तक के 25 वर्षों की अवधि में राजस्थान की प्रति व्यक्ति हस्तान्तरण की राशि 1738 रुपये रही, जो नीची आय वाले अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार से लगभग 600 रुपये अधिक थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति हस्तान्तरण राशि की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति इन राज्यों से बेहतर रही है। यह कहना गलत होगा कि प्रति व्यक्ति हस्तान्तरण की राशि में राजस्थान के हिस्से की अनदेखी हुयी है। बल्कि सब प्रष्टा जाय तो राजस्थान की तरफ प्रति व्यक्ति बजट-सम्बन्धी हस्तान्तरण सू० पी० मध्य प्रदेश व बिहार से अधिक रहे हैं।

नवें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट (1989-90 के लिए) का राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव—

1 George Gulari, Centre-State Resource Transfers 1951-84. An Appraisal, in EPW, February 16, 1985.

			(करोड़ रु. में) (लगभग)
(1) घायबर में हिस्सा	4.773%	4.775%	143
	(सिविक्म सहित)	(सिविक्म के बिना)	
(2) 40% उत्पादन शुल्क में घटा	5.097%	326
(3) 5% घाटे के राज्यों को दी जाने वाली उत्पादन-शुल्क राशि में हिस्सा	3.946%	32
(4) बिजली की एवज में प्रति-रिक्त उत्पादन शुल्क	4.636%	69
(5) रेल यात्री किराये पर निरस्त कर की एवज में अनुदान में हिस्सा	4.772	5
(6) राहत-व्यय की विरा-व्यवस्था के लिए सौमान्य-राशि (margin money)		8
(7) राजस्व-घाटे की पूर्ति के लिए सहामता-अनुदान (गैर-योजना)		39
(8) मपप्रैडेशन-अनुदान (गैर-योजना)		6
(9) विभिन्न समस्याओं-शुप-राहत (गैर-योजना)		23
कुल			651

राजस्थान के हिस्से में कुल हस्तान्तरण-राशि का 4.77% आया है, जबकि पश्चिमी बंगाल के हिस्से में यह 15.83% आया है जो सर्वाधिक है। कुल हस्तान्तरण-राशि 13662 करोड़ रु. रही यही है। आठवें वित्त आयोग के अनुसार कुल हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश 4.25% आया था। इस प्रकार 1989-90 के लिए यह थोड़ा बढ़ा है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान घाटे में ही रहा है।

के० के० जॉर्ज ने नवें वित्त आयोग की प्रथम एवाडें के मूल्यांकन¹ में बतलाया है कि निचयिता का आधार लेने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान

घाटे में रहे हैं। इस आधार से भी कुछ धनी राज्य ही लाभ में रहे, जैसे महाराष्ट्र, जहाँ गरीबों का सबेन्द्रण पाया जाता है तथा साथ में गरीबी वस्ती में रहने वालों का भी।

राजस्थान के लिए 1989-90 में प्रति व्यक्ति हस्तान्तरण की रशि 190 रुपये प्रायी है, जबकि उड़ीसा के लिए यह 235 रुपये मध्य प्रदेश के लिए 183 रुपये तथा उत्तर प्रदेश के लिए 195 रुपये रही है। समस्त राज्यों के हस्तान्तरण को 100 माना जाय, तो नवें वित्त आयोग के अनुसार हस्तान्तरणों का सूचना राजस्थान के लिए 94, मध्य प्रदेश के लिए 91 तथा उत्तर प्रदेश के लिए 97 रहा है। इस प्रकार इन कम आय वाले राज्यों को नवें वित्त आयोग ने कम मात्रा में वित्तीय हस्तान्तरण किये हैं। राजस्थान को हस्तान्तरण के बाद भी राजस्व-वृद्धि नहीं मिल पायेगी जिससे उसमें प्रति व्यक्ति योजना व्यय का स्तर नीचे रह पायेगा। इस प्रकार राजस्थान का अंश कुल हस्तान्तरणों में 4.77% होने पर भी वह सापेक्षिक दृष्टि से छोटा घाटे में ही रहा है क्योंकि ज्यादा वित्तीय साधन धनी राज्यों की तरफ ही गये हैं।

अगस्त 1989 में ए० एन० सिन्हा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, पटना के निदेशक प्रोफेसर प्रधान एच० प्रसाद ने बतलाया है कि नवें वित्त आयोग ने पद्धति सम्बन्धी बड़ी भूल की है और इकोनोमेट्रिक मॉडल की सही ढंग से नहीं लगाने से राज्यों के राजस्व के अनुमान बाकी त्रुटिपूर्ण आ गये हैं, जिससे कई राज्यों को हस्तान्तरण में घाटा उठाना पड़ा है। सम्भवतः इन भूल सुधार से आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में कम आय वाले राज्यों को कुछ अधिक धनराशि आवंटित की जा सके।

राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव

हम पहले देख चुके हैं कि वर्तमान में राजस्थान वित्तीय संकट के दौर में गुजर रहा है। 1989-90 के अंत में समग्र घाटे में बढ़ कर 204 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। इसके वित्त-व्यय की उचित व्यवस्था करना बठिन जान पड़ता है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि राज्य की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति कोई एक दो वर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दीर्घकाल से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का इकट्ठा दुष्परिणाम है। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के बाद स्थिर भावों पर बढ़ने का नाम नहीं लेती। इतनी लम्बी अवधि में प्रति व्यक्ति आय का ठहराव विकास की अवधि-धोमी रफ्तार को ही सूचित करता है।

1968-69 से 1987-88 तक के 20 वर्षों में राज्य में 16 वर्ष अवकाल व सूखे की दशाएँ पायी गईं। इनमें से 12 वर्षों में अकाल ने 20 से अधिक जिलों का

प्रभावित किया। इसमें स्पष्ट होता है कि राज्य निरन्तर बजाल की विमोचिका से जूझता रहा है जिसमें इसके राजस्व को काफी क्षति हुयी है और व्यय-भार में वृद्धि हुयी है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य बजाल की समस्या पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर पाया है। राज्य को पंचवर्षीय योजनाएँ बजालों के सफट को बम नहीं कर पायी हैं। राज्य में निरन्तर जल, चार, अनाज व रोजगार का अभाव बना रहता है। धन राज्य के आर्थिक विकास के कार्यक्रम पर नये तरे से विचार करने की आवश्यकता है।

राज्य की वित्तीय दशा को आगामी वर्षों में ठीक करने के लिए निम्न उपाय सुझाये जा सकते हैं:—

1. वित्तीय साधन बढ़ाने के लिए बिजली कर व घण्य करों की वसुली में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके बिजली-कर की आय काफी बढ़ायी जा सकती है। बिजली कर की बढ़ावा राशियाँ वसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य के कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करों में भग सहित) का 2/5 भग बिजली-कर से प्राप्त होता है। 1989-90 के बजट-घनमानों में बिजली-कर से 575 करोड़ रु के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यदि इसमें 10% वृद्धि की जा सके तो लगभग 60 करोड़ रु की राशि जुटायी जा सकती है।

2. कृषि-क्षेत्र में कर-भार में वृद्धि—विद्यते वर्षों में भू-राजस्व का योगदान घट कर कुल कर-राजस्व का 2% हो गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई से लाभ हुआ है उनमें व्यापारिक फसलों पर उपकर (cess) बढ़ा कर तथा सिंचाई की दरों में वृद्धि करके कृषिगत क्षेत्र से आयवृद्धि बढ़ायी जा सकती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जिन वर्गों को लाभ प्राप्त होता है उन्हें करो के रूप में अधिक योगदान देना चाहिए।

3. देश में उत्पादन व आय बढ़ाने से केन्द्र की आयकर व उत्पादन शक्तों से आय बढ़ेगी जिसमें राज्यों के हिस्से में केन्द्रीय करो की अधिक राशि आयेगी। इसलिए केन्द्र को आर्थिक विकास की गति को तेज करने का प्रयास करना चाहिए।

4. राज्य सड़क परिवहन, राज्य सिंचाई की योजनाओं, राज्य विद्युत अण्डल व अन्य राजकीय उपक्रमों की प्रगति-व्यवस्था में सुधार करके इनके धाटों को कम करने अथवा लाभप्रदता के स्तर को ऊँचा उठाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अनेक स्तरों पर प्रशासन को बड़ा करना होगा ताकि अकार्यकुशलता व भ्रष्टाचार को समाप्त करके ऊँचे प्रनिफल प्राप्त किये जा सकें।

ग्रामीण विकास को जिला-नियोजन से जोड़ने की आवश्यकता है। मध्य में अधिक ध्यान मजदूरी-रोजगार (wage-employment) को बढ़ाकर सामुदायिक परिवर्धन के निमाण पर जोर देना चाहिए। जब तक सुदृढ़ कार्यक्रम उपलब्ध

(iv) राहत वार्यों व अन्य वार्यक्रमों के लिए प्राप्त 721 करोड़ रु की ऋण-राशि का प्रपलेखन (write-off) करने के लिए आयोग को सम्मोचतापूर्वक विचार करना चाहिए।

(v) अल्प वक़्त में एकत्र घन राशि जो राश्यों की ऋण के रूप में दी जाती है उस अनवरत ऋण (perpetual loan) मान लिया जाना चाहिए क्योंकि इसका अधिकार भाग विद्युत व सिबाई परियोजनाओं में लगाया जाता है।

(vi) राज्य विद्युत महसूल की मार्च 1989 तक दिये गये 106५ करोड़ रुपये के राज्य-ऋण को केन्द्र द्वारा साधारण व्याज दर पर स्थायी ऋण (अनवरत ऋण) में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सुझावों से स्पष्ट होता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाने होंगे।

इस प्रकार राज्य सरकार की एक तरफ वित्तीय साधनों की बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरी तरफ परियोजनाओं के उचित चयन, उचित वित्तियाम्बदन व उचित प्रबंध व देलभास के जरिये उन्हें सामर्थ्य बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे भविष्य में सरकारी खजाने पर भार बनने की बजाय उसमें योगदान दे सकें।

निष्कर्ष—वर्तमान में राज्य की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध राज्य के दीर्घ-कालीन आर्थिक विकास से है। राज्य को अपने आर्थिक साधनों विशेषकर पशुधन, मजिन्न-पदार्थ, घादि का सदुपयोग करके आमदनी बढ़ानी चाहिए ताकि रोजगार बढ़े और मावी आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाया जा सकें। प्रायः वित्त-विशेषज्ञ राज्य की बाधाहीन वित्तीय दशा के लिए वित्त प्रायोग की निवारिणी की जिम्मेदार टहराने की कोशिश करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण रहता है कि केन्द्रीय हस्तान्तरणों से राज्य का घन नीचा रहता है और राज्य व हितों का बलिदान कर दिया गया है तथा उनकी अनदेखी कर दी गई है, घादि।

इसमें तो दो बातें नहीं हो सकती कि अधिक वित्तीय साधनों का उपयोग करने में विकास व प्रगति प्रबलतर सुलभ हैं। इनके अभाव में विकास प्रबल हो जाता है। लेकिन वित्तीय साधनों के हस्तान्तरण का प्रतीत तब कोई ऐसा फामूला नहीं निकला है जो सभी राज्यों को समान रूप से स्वीकार्य हो। इसका कारण यह है कि अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न किस्म की होती हैं। इसलिए सभी राज्यों को वृन्द से उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन मिलना सम्भव नहीं होता। इसलिए केंद्र का काम सीमित साधनों का उचित आवंटन व हस्तान्तरण करना माना गया है।

अतः नविष्ट म केंद्र को राजस्थान को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और अमान-राहत व सुधारों को पूरा करने के लिए वृन्द से मिलनी चाहिए ताकि राज्य

(iii) राज्य की वित्तीय स्थिति ।

(iv) राजस्थान का योजनाकाल में कर-प्रयास ।

3. राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है । इसको सुदृढ़ करने की कोई सुनिश्चित, व्यावहारिक व समयबद्ध योजना प्रस्तुत कीजिए ।
 4. राजस्थान के 1989-90 के बजट का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।
 5. राजस्थान के राजस्व-स्त्रोतों में आय की प्रमुख मदों का संक्षेप सहित वर्णन कीजिए ।
 6. राजस्थान के राजस्व-स्त्रोतों में कृषि की तीन प्रमुख मदों स्पष्टतया समझाइए । क्या उनमें कृषि वृद्धि लादित मानी जा सकती है ?
-

इन्से गेजगार व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य (Value-added) का लगभग 85% अंश प्राप्त होता था।

2 1951 में विनिर्माण व सतन में श्रम-शक्ति का 95% अंश लगा हुआ था। 1950-51 में राष्ट्रीय आय का 14% उद्योगों से प्राप्त हुआ था।

3 भगवती व देसाई के अनुसार 1947 तक भारत परिवहन व संचार की दृष्टि में काफी प्रगति कर चुका था। सड़कों की संख्या लगभग 3 लाख मील थी।

4 विदेशी निजी विनियोग की राशि 1948 में 320 करोड़ रुपये थी जिसका लगभग चौथाया अंश खनन व विनिर्माण में लगा हुआ था।

5, 1948 में कॉस्टल सोडा साइक्ल, एमोनिया सल्फेट, शीट काच व प्लैटिनियम की मांग की पूर्ति काफी मात्रा में विदेशों से प्राप्त करके की जाती थी।

6 1947 में आधुनिक पैंक्ट्री क्षेत्र में 20 लाख श्रमिक कार्यरत थे जो कुल श्रम शक्ति का 2% था।

यहां इन लक्ष्यों में कालांतर में कोई परिवर्तन हुए हैं ?

सारांश का भारत 1947 के भारत की तुलना में काफी भिन्न है। कृषिगत क्षेत्र में कुछ सीमा तक भूमि सुधार हुए हैं तथा मध्यस्थ-वर्ग को समाप्त किया गया है। सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशक दवाइयों आदि साधनों का भी विस्तार किया गया है। इसने कृषि का तकनीकी आधार सुदृढ़ हुआ है।

औद्योगिक क्षेत्र में काफी विविधता आयी है। पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन व उत्पादन-क्षमता काफी बढ़ी है। भारत की गिनती विश्व के चुने हुए औद्योगिक राष्ट्रों में होने लगी है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कारखानों का विकास किया गया है। औद्योगिक प्रगति का असर हमारे निर्यातों पर भी पड़ा है। हम काफी मात्रा में विनिर्मित माल का निर्यात करने लगे हैं।

योजनाकाल में विकास की वार्षिक दर लगभग 3.6% रही है जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कई दशाब्दियों तक यह मुश्किल 1.1% रही थी। मध्यम से विकास की दर का बढ़ाया जा सकता है तथा बढ़ाया जाना चाहिए। छठी पंच-वर्षीय योजना में विकास की वार्षिक दर 5.3% रही है जो लक्ष्य के अनुकूल है। सातवी योजना (1980-90) में विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य 5% रखा गया है जिम्मे प्राप्त होने की आशा है। आठवी योजना (1990-95) के लिए दृष्टिकोण प्रपत्र (Approach Document) में विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य कम से कम 6% सुझाया गया है।

प्रश्न 2 भारत में श्रम शक्ति के वितरणिक वितरण को सरल करें। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ?

व्यवसाय में केवल 2% व्यक्ति लगे हुए थे एवं जापान में 12 प्रतिशत व्यक्ति लगे हुए थे। वार्षिक वितरण के सम्बन्ध में निम्न निष्कर्ष ध्यान देने योग्य हैं।

(अ) भारत में काफी लम्बी अवधि के बाद 1981 में व्यावसायिक वितरण मामूली बढ़ता है। 1981 में कृषि व महायक क्रियाओं में सम्बन्धित शक्ति का लगभग 3.3% घटा है जो एक नई व अनुकूल प्रवृत्ति का सूचक है।

(ब) कृषि से अम-शक्ति को हटाकर अन्य आर्थिक क्रियाओं की तरफ भेजने की विधि भारत के लिए प्राणव्यवहारिक विद्य होगी। हमें कृषि में ही अधिक व्यक्तियों को काम देना है। अतः ग्रामीण निर्माण कार्यों का विस्तार करना होगा—बाँध, नहर, सड़क, सृष्टारोपण, भू-सुरक्षण आदि कार्यों का विस्तार करने से देहाती में ही अधिक लोगो को काम दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। इससे शहरो पर प्रभावशाली रूप से धनभार नहीं बढ़ेगा।

(स) ग्रामीण औद्योगीकरण अव्यावश्यक है। गाँवों में आधुनिक ढंग के लघु उद्योगों का जाल बिछाने से औद्योगीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। आर्थिक विकास से रोज़गार (परिवहन, बैंक बीमा, व्यक्तिगत सेवा-कार्य जैसे—दर्जी, नार्स, घोंसी आदि) का विकास व विस्तार होना भी स्वाभाविक है।

प्रश्न 3 भारतीय अवस्था में बेरोजगारी व अल्परोजगार की मात्रा, स्वरूप व कारणों पर प्रकाश डालें। सरकार ने योजनाओं में इन समस्याओं को हल करने के लिए कौन से उपाय काम में लिये हैं।

उत्तर संहत—भारत में बेरोजगारी व अल्प-रोजगार दोनों की दशाएँ पाई जाती हैं। पाणिबारीक क्षेत्रों पर वितरित श्रमिक काम करते हैं वे प्रायः आवश्यकता से अधिक हात है जिससे उन्हें पूरा काम नहीं मिल पाता एवं उनकी आमदनी भी कम होती है। इसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेकारी या अल्प-रोजगार की स्थिति कहते हैं। यहाँ श्रम की सीमान्त उत्पादकता नीची पायी जाती है। भारत में स्वयं के रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है।

दातवाला समिति ने बेरोजगार व्यक्तियों के आकड़ों में सुधार करने के सम्बन्ध में कई सुझाव दिये थे। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक पाँचवर्ष के अन्त में इसके धारम्भ की तुलना में अधिक पायी गई है। इसका अर्थ है कि देश में प्रत्येक योजना में नयी श्रम शक्ति को पूरा काम नहीं मिल पाया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के आँकड़ों के अनुसार मार्च 1985 में सामान्य स्टेटस (usual status) के अनुसार 5 वर्ष व अधिक के आयु समूह में बेरोजगारी की मात्रा 92 लाख व्यक्तियों (NSS के 38वें दौर की सूचना के अनुसार)। NSS के 32वें दौर के आधार पर 1977-78 में अम-शक्ति का 8.2% बेरोजगारी का शिखर था। केरल में बेरोजगारी की दर 25.7% थी तथा देश के प्रायः बेरोजगार व्यक्ति तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल व महाराष्ट्र में पाये गये थे।

आलू दैनिक स्थिति के अनुसार 1983 में भारत में बेरोजगारी की दर 4.79% रही, जबकि 1972-73 में यह 4.75% थी। 1983 में केरल में बेरोजगारी की दर 13.4% तथा तमिलनाडु में 12.0% थी। इस प्रकार इन दोनों राज्यों में बेरोजगारी का दबाव सर्वाधिक पाया गया।

देश में जनसंख्या की तीव्र गति में वृद्धि, (1971-81) की अवधि में 25 प्रतिशत), रोजगार नीति का अभाव, पैसे का अभाव ग्रामीण औद्योगिकरण का अभाव जिला व खण्ड नियोजन का अभाव दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली आदि कारण इस समस्या के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। जब श्रम-शक्ति की पूर्ति इसकी मांग से अधिक होती है तब श्रम-बाजार में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जिससे बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

सरकार ने योजनाओं व विभिन्न विभाग कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया है। ग्रामीण-निर्माण कार्यक्रम (RWP) में देहानी जनता को काम देने का प्रयास किया गया है। 1971-72 में ग्रामीण रोजगार के लिए 'कंस स्कोम' (CSRE) आलू की गयी थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में 1000 व्यक्तियों को प्रति माह 100 रुपये मजदूरी पर 10 महीने का काम देने का कार्यक्रम रखा गया था। 1973-74 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी ताकि 5 लाख निर्दल बेरोजगारों को काम पर लगाया जा सके।

सातवीं योजना 1985-90 को भी रोजगारों पुनर्बनाया गया है। इसमें 40.4 मिलियन व्यक्ति वर्ष का प्रतिरक्त रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सम्पूर्ण नई श्रम शक्ति को काम देने के असावा पहलू के बेकार व्यक्तियों में से भा कुछ को काम दिया जा सके। इसके लिए गाँवों का आर्थिक विकास करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तैयार किया है जिसमें देश के सभी विकास खण्ड शामिल किए गए हैं। इनमें गाँवों में सुख वृषिगत मोतम में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यह पहलू के काम के अदन अनाज का ही एक संगोषित रूप है। स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवा वगैरे विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षण देने की नीति अपनायी गयी है। इस ट्राइम (TRYSEM) (Training Rural Youth for Self Employment) कार्यक्रम कहा गया गया है।

गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी व यन्त्र (Rural Landless Employment Guarantee Programme) (RLEGP) भी आलू किया गया है। इसका साम ग्रामीण श्रमिकों को मिलने लगा है। यह महाराष्ट्र की रोजगार गारण्टी स्कीम के नमूने पर है और इसका सम्पूर्ण अर्थ व द्रव्य करता है।

1989-90 की अवधि के लिए ग्रामीण रोजगार का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है जिसे जवाहर रोजगार योजना (JRY) का नाम दिया गया है। इस पर 2625 करोड़ रु की घनराशि व्यय की जायगी जिसमें केन्द्र का अंश 80% व राज्यों का 20% होगा। इसमें NREP व RLEGP को भी धिला दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहैया करना है ताकि उनकी आयदानी बढ़ सके। इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायतों के माध्यम से सारे देश में लागू किया जाएगा जिसके लिए कोप केन्द्र से सीधे पंचायतों को दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण की व्यवस्था है। इतनी विज्ञान घनराशि का सदुपयोग करने तथा उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए जिला, खण्ड व ग्राम स्तर उत्पादक रोजगार की परियोजनाओं का निर्माण करने की नितान्त आवश्यकता है जिनके अभाव में कोपों का सदुपयोग करना कठिन होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कोपों का आवंटन निर्भरता के अनुसार तय किया जाएगा।

आशा है इस योजना से रोजगार-संवर्धन में विशेष सहाय मिलेगी और इसे आठवी योजना में अधिक व्यवस्थित रूप में संचालित किया जाएगा।

प्रश्न 4 भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति की मधीम प्रवृत्तियाँ दीजिए।

उत्तर-संकेतः—भारत में लाइसेंस नीति में फरवरी 1970 में मशीन किया गया था जिसमें दत्त समिति की सिफारिशों का समावेश था। उद्योगों के निम्न क्षेत्र घोषित किए गए थे—(i) मूल या प्रमुख (core) उद्योगों की सूची जिसमें आधारभूत, मूल सामग्रियों व केन्द्रीय महत्व के उद्योग आते गए थे। (ii) 5 करोड़ रुपये में ऊपर के क्षेत्र को 'मशीन विनियोग' का क्षेत्र कहा गया था। (iii) 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रु. के बीच वाले क्षेत्र को मध्यम क्षेत्र (middle sector) कहा गया था। इस नीति में लघु उद्योगों के विकास व छिछटे क्षेत्रों के औद्योगिक विनाश पर रोक दिया गया था।

2 फरवरी, 1973 की लाइसेंस नीति में पुनः संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य पारस्परिक योजना में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाना था। इनमें 19 उद्योगों की एक सूची शामिल की गई जिसमें बड़े उद्योग समूहों को प्राथमिकता देने दिया गया। उस सूची में मूल उद्योगों (core industries) व सम्बद्ध उद्योग आये गये। अपेक्षाकृत बड़े समूह की परिभाषा में 35 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति की सीमा के स्थान पर 20 करोड़ रुपये कर दिये गये। सरकार ने समुक्त क्षेत्र के विचार को प्राथमिकता देने का निश्चय दोहराया। इस नीति में बड़े औद्योगिक समूहों को प्राथमिकता देने का अवसर दिया गया। कुछ विद्वानों का मत था कि इससे आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण घटने की बजाय बढ़ेगा। बाद में वर्षों में उदार लाइसेंस नीति ही अपनाई गई है। मार्च 1978 में औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए दृष्ट की सीमा

(exemption limit) एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दी गई। मई 1983 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया। जून 1988 में इस सीमा को पुनः बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह सीमा 50 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे काफी सरायों में नई परियोजनाएँ हाथ में ली जायेंगी। वित्तीय सस्थाएँ मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं की अधिक गहराई से जाँच-पड़ताल करेंगी।

सरकार ने अप्रैल 1982 में लाइसेंस नीति को और उदार बनाया। बड़े औद्योगिक घरानों व विदेशी कंपनियों के लिए जाँच और क्षेत्रों में पिछले पाँच वर्षों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन से ऊपर 33.3% क्षमता की इजाजत दी गई जो पहले के 25% अतिरिक्त उत्पादन की छूट के बराबर थी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य निर्यात-संवर्धन आयात-प्रतिस्पर्धा, पैमाने की विफायता का लाभ उठाना व टेक्नोलॉजी को उन्नत करना था। 1985-86 के वार्षिक बजट में MRTP कंपनियों के लिए परिमर्पण की सीमा 20 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. कर दी गई तथा 25 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

सरकार ने 40 मदों में छोड़ बीजिंग की नोनि लागू की है जैव बिजली के पत्ते, गाँड़ों के टायर ट्यूब, बाँच, सीमेंट, पल-सबजी व प्रोसेस्ड फूड, आदि। इनमें बाजार मूल्य के अनुसार वस्तु-मिश्रण बदला जा सकेगा। उसके लिए नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार ने कुछ वस्तुओं के लिए न्यूनतम उत्पादन-क्षमताएँ घोषित की हैं जिन तक उत्पन्न न बढ़ाया जा सकता है नाकि लागतें कम की जा सकें। ऐसा सीलिंग पछो, बिजली के ट्रांसफार्मेटो, कार्बन ब्लैक आदि के लिए किया गया है।

नई सरकार औद्योगिक नियंत्रणों को कम करके प्रतिस्पर्धा, आधुनिकीकरण, नई टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने की विफायता आदि प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए लाइसेंस नीति को अधिक उदार बनाया गया है जो उदार आर्थिक नीति का प्रमुख भाग है।

प्रश्न 5 विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इस सम्बन्ध में आवश्यक ध्यांक दे दीजिए।

उत्तर सकेत—भारत में 1988-89 में आयात की राशि 27693 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष से 2.6% अधिक थी। निर्यात की राशि 20481 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष से 28.8% अधिक थी। इस प्रकार 1988-89 में व्यापार का घाटा 7412 करोड़ रु. का रहा जो पिछले वर्ष के 6608 करोड़ रु. से अधिक था।

(प्र) निर्यात व्यापार में परिवर्तन (a) वस्तु के अनुसार—1970-71 में चाय का अंश 9% था जो घटकर 1987-88 में 3.8% हो गया। दूध व रेडीमेड

पोशाको (cotton fabrics + readymade garments) का 9% से बढ़कर 18.1% हो गया। जूट व जूट से निर्मित माल का 12.4% से घटकर 1.5% पर आ गया। इजीप्टीयरी माल का अंश भी घटा है।

(ii) दिशा के अनुसार—1970-71 से 1987-88 के बीच हमारे निर्यात-व्यापार में जापान का अंश 13.2% से घटकर 10.3% हो गया। पूर्वी सोरोपीय देशों का घटकर 16.5% पर आ गया। निर्यात व्यापार में अमेरिका का अंश बढ़ा है। इस प्रकार हमारा व्यापार अमेरिका व रूस से बढ़ा है। 1987-88 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा तथा कुल निर्यात में इसका अंश 18.5% रहा।

(घा) आयात व्यापार में परिवर्तन (1) वस्तु के अनुसार—1970-71 से 1987-88 के बीच में काफी परिवर्तन हुआ है। 1987-88 में आयातों में पेट्रोल, तेल व पिकनाई (POL) का अंश पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर 18.2% पर गया।

(ii) दिशा के अनुसार—घोषक व जापान से आयात बढ़ा है। 1970-71 से 1987-88 के बीच जापान से हमारे आयात 5.1% से बढ़कर 9.5% हो गये और घोषक से 7.7% से बढ़कर 14.8% हो गये।

(इ) व्यापार की धाड़ी—व्यापार का घाटा 1988-89 में लगभग 7412 करोड़ रु रहा जो पिछले वर्ष से लगभग 750 करोड़ रु घट चुका। वैसे 1980-81 से ही व्यापार का घाटा प्रति वर्ष 55 अरब रुपये व इससे अधिक रहा है। छठी योजना में व्यापार का कुल घाटा 28581 करोड़ रुपये रहा जिससे देश के समक्ष विदेशी भुगतान की समस्या उत्पन्न हो गई।

प्रश्न 6 विदेशी सहायता की मात्रा, उपयोग व भुगतान की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर—संकेत—रिजर्व बैंक की 1987-88 की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 1988 के अन्त तक कुल 61,441 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता स्वीकृत हुई थी जिसमें 42,347 करोड़ रुपये की राशि प्रयुक्त की जा सकी थी।

1988-89 में विदेशी सहायता के शुद्ध आगम (net inflow of assistance) की राशि 2599 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है।

विदेशी सहायता का उपयोग औद्योगिक विकास, परिवहन के विकास व कृषिगत विकास आदि के लिए किया गया है। भूतवाल में पी एस. 480 के अन्तगत खेती के रिमाइनी आयात से खाद्य-स्थिति को सुधारा जा सका था। विदेशी तकनीकी ज्ञान व दक्षता का भी उपयोग किया गया है।

पिछले वर्षों में विदेशी ऋणों के ब्याज व मूलधन की किस्म के भुगतान का सबूत खड़ा हो गया है। यह अन्न तालिका में दर्शाया गया है :

के लिए समुचित धाँचों के अनुसार विदेशी सहायता की राशि 5,209 करोड़ रु. (कुल का 12.8% तथा घाटे की वित्त व्यवस्था 3,560 करोड़ रु. की रही।

विदेशी सहायता के उपयोग में पुनर्निर्माण की समस्या तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। इन प्रकार भारतीय नियोजन में वित्तीय व्यवस्था स्फीतिकारी प्रमाणित हुई है। छठी योजना 1980-85 के घाटे की वित्त-व्यवस्था का लक्ष्य 5 000 करोड़ रु. का था, लेकिन वास्तव में यह 15 684 करोड़ रु. की रही जो लक्ष्य के तिगुने से भी कुछ अधिक थी। विदेशी सहायता के लिए प्रावधान 9 929 करोड़ रु. का था जबकि वास्तव में यह 8,529 करोड़ रु. प्राप्त की गई।

सातवीं योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था से 14000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रथम तीन वार्षिक योजनाओं (1985-88 की अवधि के लिए) में इससे अधिक घाटे की वित्त-व्यवस्था की जा चुकी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की भी मार्गदर्शक क्षेत्र में 3,50 000 करोड़ रुपये के परिवर्धन के लिए माघन जुटान का भारी प्रयास करना होगा। इसके लिए घरेलू बचत की दर में वृद्धि करनी होगी। इस 21.1% में बढ़ाकर 23.3% किया जाना है।

प्रश्न 9. भारत में निरोजक काल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।

उत्तर-संकेंद्र—भारत में योजनाकाल के लगभग चार दशक पूरे हो गये हैं इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है।

राष्ट्रीय आय 1985-86 में 1950-51 की तुलना में (1970-71) के भावों पर लगभग 3.6 गुनी हो गई। इसमें प्रतिवर्ष औसतन 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। देश की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ से बढ़कर 1981 में लगभग 68.4 करोड़ व्यक्ति तथा 1989 में लगभग 82-83 करोड़ व्यक्ति हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 466 रु. में बढ़कर 1985-86 में 798 रु. हो गयी है (1970-71 के भावों पर)। इस प्रकार इसमें 1.5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर में वृद्धि हुई। अब राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष बदलकर 1980-81 कर दिया गया है। 1987-88 में 1980-81 के भावों पर राष्ट्रीय आय 150573 करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय 1918 रुपये घाँकी गयी है।

खाद्यान्नों का उत्पन्न 1950-51 में 55 मिलियन टन से बढ़कर 1987-88 में 138 मिलियन टन हो गया तथा 1988-89 के लिए उत्पादन का अनुमान ऊँचा (लगभग 170 मि. टन) लगाया गया है। निरहन का 5 मिलियन टन से 1987-88 में 12.4 मिलियन टन एवं कपास का 2.9 मिलियन गाँठों में 6.43 मिलियन गाँठों हो गया है। देश में कृषिगत क्षेत्र में अधिक उन्नत बनानी किम्बो, रासायनिक खाद, ट्रैक्टर, पम्प, कीटनाशक दवाइयों आदि का काफी विस्तार किया गया है।

1950-51 से 1978-79 की अवधि में कुचिगत उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 2.7% रही है। पाँचवी योजना की अवधि (1974-79) में यह 4.2% रही। घावल की प्रति हेक्टेयर उरज 1950-51 में 6.7 क्विंटल से बढ़कर 1987-88 में 14.7 क्विंटल तथा गेहूँ की 6.6 क्विंटल से बढ़कर लगभग 20 क्विंटल हो गई है।

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता के 1950-51 में 23 लाख किलोवाट से बढ़कर 1986-87 में 554 लाख किलोवाट (लगभग 24 गुना) हो जाने का अनुमान है। तैयार इस्पात का उत्पादन 1950-51 में 10 लाख टन से बढ़कर 1987-88 में 106.5 लाख टन (मैकडरी उत्पादकों का उत्पादन शामिल करने पर) हो गया है। क्रूड तेल का उत्पादन इसी अवधि में 2.6 लाख टन से बढ़कर 3 करोड़ टन हो गया है। देश में मल्य मिनिमम इजन, मोटरगाड़ियों, साइकिलों, विभिन्न विस्म की मशीनरी, रासायनिक खाद कोयला, सीमेंट, प्लास्टिक सोडा, कच्चा लोहा बर्गरा का उत्पादन काफी बढ़ा है। 1951-86 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन छ गुना हो गया है। 1970 के दशक में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 4.2% रही थी जो बढ़कर 1980-81 में 1986-87 तक 7.6% हो गई।

घरेलू बचत की दर 1980-81 में 21.2 प्रतिशत (राष्ट्रीय आय का) से घटकर 1987-88 में 20.2 प्रतिशत हो गई 1986-87 में यह 21.6% रही थी। विनियोग की दर 1980-81 में 22.7 प्रतिशत से घट कर 1987-88 में 22.1 प्रतिशत हो गई। यह 1986-87 में 23.4% रही थी। राष्ट्रीय आय के नये सिरीज के अनुसार जिसका आधार वर्ष अब 1980-81 कर दिया गया है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का तजी से विस्तार हुआ है। 1950-51 में इनमें कुल विनियोग 29 करोड़ रुपए का था जो 1987-88 के अन्त तक लगभग 71299 करोड़ रुपए हो गया है। देश में कई नई वस्तुओं का उत्पादन चालू हुआ है। फिर भी मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी, विदेशी सहायता के कारण पुनर्मुग्तान की समस्याएँ, प्राथिक सत्ता का निजी हाथों में केन्द्रीकरण व एकाधिकार, साधन सत्रह की कठिनाइयाँ, काले धन व काली मुद्रा आदि समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिनका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए।

प्रश्न 10 राजस्थान का योजना-काल में कुचिगत विकास सही दिशा में हुआ है। क्या आप इस मन से सहमत हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर-सर्वेक्षक—राज्य में 1951-52 में सकल कुचिगत क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 28% था जो बढ़कर 1980-87 में 52.0% हो गया है। इस प्रकार राज्य में विस्तृत सती का क्षेत्रफल काफी बढ़ा है।

सकल मिचित क्षेत्रफल 1951-52 में 11.7 लाख हेक्टेयर था जो 1986-87 में 43.51 लाख हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार योजनाकाल में मिचित क्षेत्रफल लगभग चौगुना हो गया है।

1950-51 में खद्योतों का उत्पादन 30 लाख टन हुआ था जो 1983-84 में लगभग एक करोड़ टन रहा। 1984-85 व 1985-86 में यह प्रति वर्ष लगभग 79 लाख टन रहा। सूने के कारण 1986-87 में 67 लाख टन व 1987-88 में 48 लाख टन रहा लेकिन 1988-89 में इसमें पुनः 1 करोड़ टन की सीमा को पार करने की श्रमा है।

राज्य में कृषिगत विकास की नई नीति का विस्तार जारी है। राज्य में अधिकांश उपज देने वाली किस्मों का क्षतिपूर्ति तथा रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाया गया है।

राज्य में मुख्य समस्या कृषिगत उत्पादकता का बढाना की है। सिंचाई व साधनों का तेजी से विस्तार करने की भी आवश्यकता है।

विश्व बैंक ने इंदिरा गांधी नहर तथा चम्पल कमान्ड क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान किए हैं। चम्पल सिंचन क्षेत्र में जल के बहाव की व्यवस्था कराने, सडक बनाने नहरों के रख रखाव व भूमि के विकास के लिए इस ऋण का उपयोग किया गया है तथा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरों को पक्का बनाने लगी की समतल करने टीलों के निर्माण को रोकने वृक्षारोपण कराने व गांवों के विकास के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।

प्रश्न 11 राजस्थान में योजनाबद्ध में औद्योगिक प्रगति का ध्यान कीजिए।

उत्तर सकेत—राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। 1987-88 में खनन व निर्माण (प्रीप्रोडक्शन व गैरप्रीप्रोडक्शन (mining and manufacturing) से राज्य की कुल आय का 18% (1970-71 कीमतों पर) प्राप्त हुआ था।

योजनाबद्ध में प्रोद्युक्त की उपलब्धि बढाने में औद्योगिक विकास की भूमिका तैयार हो गयी है। 1950-51 में शक्ति की उपलब्धि 8 मेगावाट थी जो 1989 के मध्य में 2500 मेगावाट (प्रस्तावित क्षमता) हो गयी है।

राज्य में चीनी सीमेंट, यूरिया, सुपर फास्फेट, सूती वस्त्र सूत, गॉन-बिमारग, पानी बिजली व मोटरों नमक आदि का उत्पादन किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ कारखाने चल रहे हैं जैसे राजस्थान सरकार की दल राम में श्रीगंगानगर नगर मिल में धोलपुर में हाई-स्क प्रसिद्धि स्लाम फेक्ट्री जोर में चमड का कारखाना माडो-की पाल (डूंगरपुर जिले में) पलोगवार बजि-निमिदजन प्लांट, चुरू व लाडनू में बस्टेड ऊनी मिल बीकानेर में ऊनी मिल व होडवाना में बेमिजन वस्त्र चल रहे हैं। भारत सरकार के निम्न उपक्रम हैं—(i) हिंदुस्तान लिमिटेड उदयपुर (ii) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राठौर (iii) इस्ट्रुमेण्टेशन लिमिटेड (iv) एन एम टी लिमिटेड अजमेर व (v) सीमेंट लिमिटेड लि

(vi) मॉडर्न बेकरीज तथा (vii) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लि है जो वोटा इन्स्ट्रुमेंटेशन लि की सह एक इकाई (रीको का सहयोग) है।

राजस्थान में केन्द्रीय विनियोग सांख्यिक क्षेत्र में 1966-67 में 17 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1985 में 648 करोड़ रुपये हो गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने स्मूटर प्लान्ट चमड़े के कारखाने व रॉक फोस्फेट के विकास के लिए ऋज दिया है। राज्य में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। कृषि-पदार्थ आधारित, खनिज-आधारित उद्योगों जैसे व जवाहरात, इस्तकारी व पर्यटन, ग्राह्य का विकास किया जाना चाहिए। राज्य में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन की प्रगति इस प्रकार रही। सीमेंट का उत्पादन 1951 में 2.58 लाख टन से बढ़कर 1988 में 40.3 लाख टन हो गया। सूती वस्त्र व सूत का उत्पादन भी काफी बढ़ा है।

राज्य में इंजीनियरी, रासायनिक व इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों का विकास किया जा सकता है। सरकार को प्रत्नीय व लघु उद्योगों के विकास की एक व्यावहारिक योजना तैयार करके उसे निवट मविष्य में कार्यान्वित करना चाहिए ताकि राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए प्रमुखतया तमक का उत्पादन छोटी इकाइयों में बिधा जाना चाहिए। जनता सरकार ने जून, 1978 में अपनी नई औद्योगिक नीति घोषित की थी जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास करना था। राज्य में अणुशक्ति सीलैंड की तरफ से भलवर में ट्रको के चेसिस बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। रीको की मदद से समुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है।

1984-85 के लिए उद्योगों के वाषिक (सर्वेक्षण (फैक्ट्री क्षेत्र) की ताजा सूचना के अनुसार राज्य की 2701 फैक्ट्रियों में 2.2 लाख नमचारी कार्यरत थे (धमिक + अग्र्य कर्मचारी) इनमें कुल स्थिर पूंजी 2448 करोड़ रुपये लगी हुयी थी और शुद्ध जोडा गया मूल्य (net value added) 550 करोड़ रुपये का था। राज्य में फैक्ट्रियों में लगान कुल कर्मचारियों का 25.7% अकेले विद्युत में लगा हुआ था, जबकि समस्त भारत के लिए यह औसत 11.5% आया था। इस प्रकार राज्य में विद्युत क्षेत्र में नमचारियों का अनुपात बहुत ऊँचा है। शुद्ध जोडे गये मूल्य के आधार पर राजस्थान का औद्योगिक आधार (industrial base) 1984-85 में इस प्रकार पाया गया कुल देश में मिश्रित देशों के वस्त्र, सूती वस्त्र, अत्याधिक खनिज वस्तुएँ परिवहन उपकरण रासायनिक पदार्थ मशीनरी मशीनों और भार आदि। 1984-85 में राज्य में उद्योगों का विनिष्ठीकरण गुणांक (coefficient of specialisation) 0.234 पाया गया है जो नीचा है और यह बताता है कि राज्य में औद्योगिक विविधीकरण का गुणांक 0.766 होने से कई प्रकार के उद्योग विवसित होने लगे हैं। नवम्बर 1988 में हिन्दुस्तान बिक लि ने भीलवाडा जिले में रामपुरा में गुचा सीसा जराया माइनिंग कॉम्प्लेक्स पर काम चालू किया है।

प्रश्न 12. सरकार की खाद्य-नीति का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देश के लिए उचित खाद्य-नीति का सुभाव दीजिये।

उत्तर-संक्षेप—सरकार की खाद्य-नीति—1973 में सरकार के द्वारा गेहूँ के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की नीति घोषित की गई थी, लेकिन प्राथमिक तैयारी के अभाव व कई प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण यह पूर्णतया विफल रही। 1974 में व्यापारियों से लेवी के रूप में अनाज निर्धारित भावों पर उनकी कुल खरीद का आधा भाग लेने की नीति अपनाई गई। 1978 में गेहूँ का खरीद-मूल्य 105 रुपये प्रति बिंदल रखा गया जो काफी ऊँचा था। 1975 में कृषकों से लेवी के रूप में गेहूँ की खरीद करके स्टॉक बनाने की नई नीति लागू की गई। गेहूँ का वसूली मूल्य पहले जितना ही रखा गया। 1976 में उत्पादकों से लेवी वसूल की गई। अगस्त, 1977 में जनता सरकार ने खाद्य स्थिति अच्छी होने से उत्पादकों पर लेवी समाप्त कर दी और गेहूँ के बमूली मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बदल दिया तथा गेहूँ की क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त कर दी। हाल में 1990-91 की बिक्री की मौसम के लिए गेहूँ के वसूली मूल्य 200 रुपये प्रति बिंदल रखे गये हैं जो पहले से 17 रुपये प्रति बिंदल अधिक हैं। पिछले वर्षों में इनमें लगातार वृद्धि होती रही है।

सरकार की खाद्य-नीति में निम्नलिखित का विस्तार से वर्णन करें।

- (i) खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था,
 - (ii) खाद्यान्नों के लिए आयात की व्यवस्था,
 - (iii) भारतीय खाद्य निगम की क्रियाएँ,
 - (iv) उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (कृषि में हरित क्रांति, आदि)
- सरकार खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक रखने का प्रयास करती है।

भारत के लिए उचित खाद्य नीति के मुख्य तत्व इस प्रकार होने चाहिए—

1. कृषकों को अनाज के प्रेरणादायक मूल्य (incentive prices) मिलें ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिल सके,
2. सरकार निर्धारित भावों पर अनाज खरीदकर बफर स्टॉक जमा करे ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चलाया जा सके,
3. समाज में गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अदेखा-कृत नीचे भावों पर अनाज नियमित रूप से उपलब्ध किया जाना चाहिए,
4. खाद्यान्नों में जमाखोरी व मजह को रोका जाना चाहिए;
5. उत्पादन बढ़ाने के प्रयास निरन्तर जारी रहने चाहिए; तथा
6. आवश्यकतानुसार विदेशों से अनाज का आयात करके खाद्यान्नों के अभाव को दूर किया जाना चाहिए।

इन तत्वों पर ध्यान देने में उचित सावधानीति निर्धारित की जा सकती है।

प्रश्न 13. भारत में 1923 से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में हुई प्रगति का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर सकेत—सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वह सुरक्षा आती है जो एक समाज अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की जोखिमों जैसे बीमारी, काम के अयोग्य हो जाने, बेकारी, वृद्धि, मृत्यु व प्रसूति आदि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए देता है। यह एक व्यक्ति इन जोखिमों का मुकाबला नहीं कर सकता। अतः सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें सामाजिक बीमा व सामाजिक सहायता दोनों कार्यक्रम शामिल होते हैं। पहले कर्मचारियों को प्रीमियम के रूप में धनराशि देनी होती है, जबकि सामाजिक सहायता निशुल्क प्रदान की जाती है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्न अधिनियम बनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत कई प्रकार की जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है। इनका आगे विश्लेषण किया गया है—

1. मजदूर-कतिपय अधिनियम, 1923—इसके अन्तर्गत मालिक मजदूर को उस स्थिति में मुआवजा देना है जबकि काम करते हुए उसे चोट या जाए वह सदैव के लिए अयोग्य हो जाय अथवा उसकी मृत्यु हो जाये। हाल में यह 1984 में संशोधित किया गया है। यह पहले 1000 रु मासिक तक वेतन वाले श्रमिकों पर लागू होता था जो सीमा अब हटा दी गई है। मुआवजे की दरें बिल्कुल भिन्न होती हैं। इस नियम का पूर्ण तरह से पालन किया जाना चाहिए। अब मुआवजा आयु से जोड़ा गया है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948—यह उन स्थायी पंक्तिधर्मों पर लागू होने है जो शक्ति का उपयोग करती हैं और जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियुक्त होते हैं। इसके अन्तर्गत चिकित्सा-लाभ, बीमारी के दिनों में नगद राशि, प्रसूती के समय काम करते समय चोट या जान पर मिकन वाला मुआवजा तथा चोट से मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को वेतन वन की व्यवस्था आती है। ए. ए. की जाती डिमिशनगिवी कम रही है। अब यह 1600 रुपये मासिक वेतन तक वाले लोगों पर लागू हो गया है।

3. कर्मचारी प्रोविडेंट फण्ड व विविध प्रोविडन्स अधिनियम, 1952—यह दिसम्बर 1986 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत के 173 राज्यों पर लागू हो गया था। यह सरकारी प्रतिष्ठानों के 50 से कम तथा बिना शक्ति की सहायता से चलाय जाने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता। साधारणतया मालिक मालिक मजदूरों व महुँगाई मत्ते का 6% प्रतिगत अक्षदान देते हैं जो 123 राज्यों में 8 प्रतिगत कर दिया गया है। देश में काफ़ी कमचारी इस योजना का लाभ उठा रहे

विवादों को रोकने व निपटाने की प्रणाली—भारत में औद्योगिक विवादों को निपटाने की वैधानिक व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत की गई है जिसे 1956 व 1965 में संशोधित किया गया है। इसमें निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं—

(अ) चर्च समितियों की स्थापना—प्रत्येक कारखाने में जहाँ 100 से अधिक श्रमिक काम करते हैं वहाँ एक चर्चा समिति बनाई जाती है जो मालिकों व मजदूरों के दैनिक मतभेदों को दूर करने में मदद करती है। देश के कई प्रतिष्ठानों में वस्तु समितियाँ काम कर रही हैं।

(आ) समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड व जाच-न्यायालय—स्थापित किये जाते हैं। इनका काम दोनों पक्षों में समझौता कराना होता है।

(इ) स्थायी औद्योगिक न्यायालय—समझौते की प्रक्रिया के विफल हो जाने पर मामला औद्योगिक न्यायालय को सौंपा जाता है जिसका निर्णय लागू किया जाता है। जन 1947 में अनिवार्य पक्ष-निर्णय (compulsory arbitration) की व्यवस्था की गई थी। स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री गिरी ने इसके स्थान पर सामूहिक सौदाकारी (collective bargaining) का समर्थन किया था जिसमें मालिक व मजदूर आपस में विचार विमर्श करते हैं।

1950 में औद्योगिक न्यायालयों के निर्णयों पर अपील सुनने के लिए अपील न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। 1956 के संशोधन के अनुसार अपील न्यायालय समाप्त कर दिये गये हैं। हम संशोधन के अनुसार निम्न न्यायालय स्थापित हुए हैं—

(i) श्रम अदालतें—ये मजदूरों को हटाने व हड़ताल की वैधानिकता जैसे औद्योगिक विवादों को लते हैं।

(ii) औद्योगिक न्यायालय—ये मजदूरों, काम के घंटे, बोनस, छुट्टी व प्राधुनिकीकरण के प्रश्न लते हैं।

(iii) राष्ट्रीय न्यायालय—इनकी स्थापना राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों व एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक उद्यमों के मामलों पर विचार करने के लिए की गयी है।

केंद्रीय औद्योगिक सम्बन्धों की आवश्यक मशीनरी केंद्रीय मूल्स श्रम-कमिशनर के संगठन के द्वारा संचालित होती है। सार्वजनिक उपयोगिता सम्बन्धी सेवा प्रतिष्ठानों में समझौते की कार्यवाही चालू करना (आपसी बातचीत के विफल होने पर) अनिवार्य होता है। केंद्रीय क्षेत्र में विवादों पर निर्णय देने के लिए 7 औद्योगिक न्यायालय व श्रम-न्यायालय हैं। राज्यों में ये अलग से स्थापित किये गये हैं।

सरकार ने ट्रेड यूनियन व औद्योगिक विवाद (संशोधन) बिल 1988 संसद में पेश किया है जिसमें निम्न बातों पर बल दिया गया है :

(i) औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों (IRC) की केन्द्र व राज्यों में स्थापना करना, (ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम की अवहेलना करने पर भालिबों को कड़ी सजा देना (कंड संहिता); (iii) अनेक मजदूर-संघों की स्थिति को समाप्त करना; तथा (iv) धातुगतिक नेतृत्व का विकास करना ।

सरकार ने इस बिल में 100 से ऊपर श्रमिकों वाली इकाइयों में एक ट्रेड यूनियन में कम से कम 10% सदस्यता की शर्त रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक मानी है ताकि अनेक मजदूर संघ न बनें । लॉक आउट घोषित करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना होगा । गैर-कानूनी ले-आफ, छेड़नी, लॉक-आउट व पैकट्री बन्द करने पर कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है । श्रमिक अपनी छेड़नी बंद करने के मामले सीधे श्रम अदालत में ले जा सकते हैं । धम-धमाल के निर्णयों पर सर्वोच्च IRC सुनेंगे ।

औद्योगिक विवादादी को उत्पन्न होने से रोकने के लिए श्रमिकों की दवा सुधारी जानी चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाना चाहिए, श्रमिकों को प्रबन्ध व काम में हिस्सा देना चाहिए और मानिको-मजदूरों दोनों का दृष्टिकोण बदलना चाहिए । उत्पादन व उत्पादकता को निरन्तर बढ़ाने के लिए औद्योगिक शान्ति स्थापित करना नितांत आवश्यक है । हमें यथासम्भव समस्याओं व ऐच्छित पंचनिर्णय पर ही अधिक बल देना चाहिए ।

प्रश्न 15 भारत के आयात व निर्यात की प्रमुख मशो का विवेचन कीजिए तथा व्यापार-संतुलन की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए । सरकार को निर्यात-संवर्धन के लिए कौन से उपाय काम में लेने चाहिए ?

उत्तर-संकेत—हाल के वर्षों में भारत के आयात व निर्यात में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । 1988-89 में आयात की राशि 27693 करोड़ रु. तथा निर्यात की 20281 करोड़ रु. रही, जिससे व्यापार में 7412 करोड़ रु. का घाटा हुआ जो पिछले वर्ष से लगभग 700 करोड़ रु. अधिक था ।

आयात की मशें

1. पूँजीगत माल—1987-88 में 6285 करोड़ रु. का आयात किया गया इसमें मशीनरी, परिवहन-उपकरण वगैरा आते हैं । जो पिछले वर्ष से 15% ज्यादा था ।

2. पेट्रोल व पेट्रोल-युक्त—इस मद के आयात पर 1987-88 में 4083 करोड़ रु. तथा 1986-87 में 2797 करोड़ रु. व्यय किये गये ।

3 अनाज व अनाज से बने पदार्थ—1987-88 में अनाज व इसके निर्मित पदार्थों के आयात पर 33 करोड़ रु व्यय किये गये, जबकि 1975-76 में 1343 करोड़ रु व्यय किये गये थे। देश की खाद्य स्थिति ठीक रहने से अनाज के आयातों में कमी कर सकना सम्भव हो सका है। लेकिन 1988 में पुनः आयात बढ़ाना पड़ा है।

4 उर्वरक व उर्वरक सामान—1987-88 में तैयार व ऋड उर्वरकों के आयात की कुल राशि 310 करोड़ रु रही जो पिछले वर्ष से काफी कम थी।

5 लोहा व इस्पात—1987-88 में लोहे व इस्पात के आयात पर 12.3 करोड़ रु व्यय किये गये जो पिछले वर्ष से कम थे।

निर्यात की घटे

1987-88 में भारत के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 26.4% बढ़े। 1973-74 से 1976-77 तक निर्यातों में वार्षिक औसत वृद्धि-दर 27% रही थी। विश्व के बाजारों में भारतीय माल के माव बढ़ने से यह उपलब्धि सम्भव हो सकी थी। लेकिन 1985-86 में निर्यात पिछले वर्ष से थोड़े कम रहे थे।

1987-88 में निर्यातों में चार प्रमुख वस्तुओं की क्रमानुसार स्थिति इस प्रकार रही:

	करोड़ रुपये
1 दस्तकारी का माल	3253
2 रेडीमेड पोशाकें	1792
3 इन्जीनियरी का माल	1433
4 चमड़ा व चमड़े की वस्तुएं (जुती सहित)	1149

भारत के परम्परागत निर्यातों में पटसन के माल व चाय का स्थान आता है। निर्यातों में विशेष वृद्धि इन्जीनियरी के माल, खसी, सूती वस्त्र व रेडीमेड पोशाकों में हुई है। मछली व मछली से तैयार माल, तम्बाकू तथा दस्तकारी के माल के निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है। 1987-88 में निर्यातों में वृद्धि दर 26.4% तथा 1988-89 में 28.8% रही। भविष्य में भी निर्यातों में वार्षिक वृद्धि-दर काफी ऊँची रहनी होगी ताकि भुगतान-असंतुलन से उत्पन्न बठिनाइयों को कम किया जा सके।

निर्यात बढ़ाने के लिए सुझाव—(1) निर्यात के योग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाय और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विश्व के बाजारों में भेजा जाय, (2) निर्यात शुल्कों में आवश्यकतानुसार कमी की जाय, (3) निर्यातकों को वार्षिक सह्यता व कच्चे माल के आयात की सुविधा दी जाय, (4) भविष्य में इन्जीनियरी के माल, दस्तकारी के सामान, चमड़े की वस्तुएं, सामुद्रिक पदार्थ, आदि का निर्यात बढ़ाया जाय।

प्रश्न 16. राजस्थान की खनिज-सम्पदा पर मजिष्ठा रिपोर्टों लिखिए ।

उत्तर—संकेत—राजस्थान की खनिज-स्थिति—राजस्थान खनिज पदार्थों का प्रजायवधर (Museum of minerals) माना गया है। भारत में इसका स्थान बिहार के बाद आता है। देश में सीमा-जस्ता, रॉक-फॉस्फेट, पन्ना व गारनेट की सम्पूर्ण उत्पत्ति राजस्थान में ही केन्द्रित है। राज्य में एस्वेस्टम घीसा पत्थर, पेंसिलार चादी एवं अभ्रक का काफी उत्पादन होता है।

खनिज पदार्थों का वृषिगत विकास (रीटनाराक दवाइयाँ, ग्रीजार आदि) औद्योगिक विकास विदेशी मुद्रा अर्जित करने व बचाने, रोजगार बढ़ाने तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की दृष्टि से काफी महत्व है।

राज्य में 35 प्रकार के खनिज एवं इमारती पत्थर व समरमर आदि पाये जाते हैं। राजस्थान में तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन एस्वेस्टम, बेल्माइट, अभ्रक, फनसं ग्रयं (मुस्तानी मिट्टी), स्क्वम, ब्राइट्स व कई प्रकार की मिट्टियाँ (बाइना बले) आदि मिलते हैं। बेराइट्स खनिज पेंट कागज व रबड़ उद्योग में काम आता है। मोल्स्टोनाइट पदार्थ चीनी मिट्टी के वर्तन पत्रों व टाइलों में काम आता है। ओकर खनिज लाल व पीली किस्म का होता है। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में मोडो-की-पाल नामक स्थान पर पनीमंवार रेनफिशियेशन प्लांट (मयत्र) लगाया गया है।

फरवरी, 1975 में लेतडी में तांबा गलाने के सयन्त्र का उद्घाटन किया गया था। उदयपुर जिले में भ्रामर-कोटरा स्थान पर रॉक-फॉस्फेट के प्रमाणात भण्डार 37 करोड़ टन तक के आँके गये हैं। वही 1969 में उत्पादन प्रारम्भ हो गया था। इसमें फॉस्फेट-युक्त उर्वरक का उत्पादन में वृद्धि हुई है। मई 1983 में जैसलमेर जिले के घोटाह नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया गया है। इस गैस से सीमेन्ट प्लांट व विद्युत-गृह स्थापित किये जा सकते हैं। मार्च 1984 की सूचना के अनुसार जैसलमेर से करीब 145 किलोमीटर दूर सादेवाला में तेल का अपार भण्डार मिला है। बीकानेर, नागौर व बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट (भूरे कोयले) के काफी बड़े भण्डार आँके गये हैं।

राज्य में खनिज पदार्थों के विकास के लिए सस्ती विद्युत, परिवहन व जल के विकास की आवश्यकता है। खानों के पट्टे देने के साथ-साथ इनके उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खनिज पदार्थों का पता लगाने, इन्हें निकालने, गलाने व सम्बन्धित उद्योगों का विकास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों का उपयोग करके एक दीर्घकालीन खनिज-विकास योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में 1979 से राजस्थान राज्य-खनिज विकास-निगम (RSMDC) सक्रिय रूप में काम कर रहा है। भारत सरकार ने रामपुरा-घागुचा में सीसा व जस्ता के भण्डार पर आधारित 366 करोड़ रु की स्मेल्टिंग परियोजना स्वीकृत की है। इससे

राज्य में सीमेंट व जस्ते की गलाने की क्षमता काफी बढ़ जायेगी। इस पर काम 20 नवम्बर 1988 से चालू हो गया है।

हाल में जमलमेर जिले के ग्राम सोनु (Sonu) में साइमण्टोन के प्रचुर भण्डार मिले हैं। जिला पाली में टक्कन पाया गया है जो रक्षा-उत्पादन में काम आता है।

बोकारो जिले में बरसिहसर में लिग्नाइट का भण्डार पाये गये हैं जिनके साधारण पर एक कमल पावर प्लांट लगाया जा सकता है। गोटा में सफेद सीमेंट का कारखाना लगाया जा चुका है। साथ में 2 बड़े पोर्टलैंड सीमेंट के कारखाने एवं एक 'ऑयल-वेल' (oil well) सीमेंट तथा "सल्फेट रेजिस्टेंट" (sulphate resistant) सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना स्थापित करने की योजना है जो भारत में अपनी तरह का एक मात्र कारखाना होगा। राज्य में निम्न खेती के रॉक फॉस्फेट को उच्च खेती में बढ़ाने की परियोजना चालू की जायेगी।

राजस्थान में दरीबा, राजपुरा, देवूमनी और पुरबनेरा के कई हिस्सों में ताबा, सीसा व जम्मा के भण्डार मिले हैं। राजस्थान के ग्रीनस्टोन इलाके में ताबा और सीने के भण्डारों का पता लगाने में सफलता मिली है।

परिशिष्ट-2

राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर

(Objective and Short Questions and Answers on
Rajasthan's Economy)

नीचे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ व लघु उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं तथा उन्हें छासानों से स्मरण रखा जा सके तथा उनको एक स्थान पर एक साथ पढ़कर राज्य के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में व्यापक, सही व अधिक सुनिश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्नों के उत्तरों में आकड़ों के अलावा विषय की मूल बातों को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। आशा है इस परिशिष्ट का अध्ययन सभी के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा।

1. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान है ?
(अ) तृतीय, (ब) द्वितीय, (स) चतुर्थ, (द) प्रथम [ब]
[मध्य प्रदेश के बाद]
2. राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ?
(अ) 15% (ब) लगभग 17% (स) लगभग 10% (द) 9% [स]
3. राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना अंश है ?
(अ) 10% (ब) 4% (स) 13% (द) 5% [द]
4. 1981 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी ?
(अ) 3 34 करोड़ (ब) 3 43 करोड़ (स) 4 3 करोड़
(द) 4 32 करोड़ [ब]
5. 1971-81 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि-दर बताइए ?
(अ) 35% (ब) 26% (स) 33% (द) 25% [स]
6. राजस्थान में 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है ?
(अ) 110 व्यक्ति (ब) 104 व्यक्ति (स) 200 व्यक्ति
(द) 100 व्यक्ति [द]

7 राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों में साक्षरता-अनुपात क्या है ?

(अ) 25% (ब) 15% (स) 5.5% (द) 5% [स]

8. राज्य में 1971-81 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि हुई व कितनी हुई ?

उत्तर—बीकानेर जिले में 48.1%

9 राज्य में 1971-81 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या की न्यूनतम वृद्धि हुई व कितनी हुई ?

उत्तर—सीलवाड़ा जिले में, 24.2%

10. राजस्थान की जनसंख्या के लिए 2001 में कितना होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया है ?

(अ) 6 करोड़ (ब) 5.6 करोड़ (स) 7 करोड़

(द) 5 करोड़

[ब]

(स्रोत : Population Projections of Rajasthan, DES, Jaipur, 1987)

11. राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। (समय 150 मिनटों में)

उत्तर—राष्ट्रीय सम्पन्न सर्वेक्षण के 32वें दौर के अनुसार 1977-78 की अवधि के लिए दैनिक स्टेटस के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी की दर (श्रम-शक्ति में अनुपात) 2.99% थी। उस वर्ष समस्त भारत के बेरोजगारी का 1.92% राजस्थान में पाया गया था।

एन एस एस के 38वें दौर (जनवरी-दिसम्बर 1983) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष-वर्ग में बेरोजगारों का प्रतिशत दैनिक स्टेटस के अनुसार 5 वर्ष व अधिक के कुल व्यक्तियों का 2.16% तथा महिला-वर्ग में 0.64% पाया गया।¹ इस प्रकार राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी यह केरल, तमिलनाडु आन्ध्र-प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में पायी गयी है। "दैनिक स्टेट की धारणा" में एक व्यक्ति की काम करने की स्थिति निम्नलिखित 7 दिनों में प्रतिदिन के लिए रिकार्ड की जाती है। प्रति दिन कम से कम एक घण्टे से चार घण्टे तक काम करने वाला व्यक्ति प्रायः दिन कायूरत माना जाता है और चार घण्टे या इससे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति पूरे दिन कायूरत माना जाता है।

1. NSSO Report No 341, November 1987, सामान्य स्टेटस (usual status) के अनुसार पुरुषों के लिए 0.33% व स्त्रियों के लिए 0.05% घस में (समायोजित) (सम्मिश्रित स्टेटस की छोड़कर)।

12. राजस्थान में बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय लिखिए ।

उत्तर—ग्रामीण विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी कम होगी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माफ़त स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा रही है। NREP, RLGP, ट्राइसंग व अनाल-रहित सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। 1989-90 में ग्रामीण निर्धन-परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है जिससे NREP व RLGP को मिला दिया गया है।

13 राजस्थान में निर्धनता की स्थिति स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर—1977-78 के आँकड़ों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 65 रु. (ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा 75 रु. (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गये। 1983-84 के आँकड़ों पर ये सीमाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 101 रुपये 80 पैसे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 117 रुपये 0 पैसे कर दी गयी। सातवीं योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष व्यय की सीमा 6400 रुपये रखी गयी है जिससे नीचा व्यय करने वाले परिवार निर्धन माने गये हैं। पहले यह सीमा 3400 रुपये थी।

सातवीं योजना के टेक्नीकल नोट (योजना आयोग, जून 1986) के अनुसार राजस्थान में 1977-78 में निर्धनता-अनुपात 33.6% था जो 1983-84 में घटकर 34.3% हो गया। इस अर्थ में समस्त भारत के लिए यह 48.3% से घटकर 37.4% पर आ गया था। इस प्रकार भारत में निर्धनता का अनुपात घटा, लेकिन राजस्थान में यह थोड़ा बढ़ा था। डा. सी. एच. हनुमन्त राव के एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त अर्थ में यह 33.5% से बढ़कर 36.6% हो गया था अर्थात् लगभग 3% बढ़ गया था जो वास्तव में एक चिंता का विषय है; क्योंकि अन्य सभी राज्यों में यह घटा है। केलोरी को आधार-स्वरूप लेने पर राजस्थान में निर्धनता-अनुपात नीचा आया है क्योंकि बाजरे में केलोरी की मात्रा अधिक पायी जाती है जो यहाँ का मुख्य अनाज है।

14 राजस्थान में प्रायः अकाल क्यों पड़ते हैं ?

उत्तर—विछले चार वर्षों में, 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में लगातार राज्य में वर्षा का अभाव रहा है। वर्षों से चले आ रहे हवा व पानी में मिट्टी के कटाव से उपजाऊ भूमि बेकार होती गई है। अनियन्त्रित चराई वृक्षों की कटाई व जल-प्रबन्ध के अभाव से परिवेश-असंतुलन (ecological imbalance) उत्पन्न हो गया है। 'वृक्ष नहीं, पानी नहीं', 'वृक्ष नहीं, उपजाऊ भूमि नहीं' का दुष्चक्र चल रहा है। जल, वृक्ष, मिट्टी आदि के परस्पर संतुलन बिगड़ गये हैं जिससे मनुष्य व पशु दोनों पर भारी विपदा आ गयी है। 1986-87 व 1987-88 में सभी 28 जिले अनालप्रसन्न प्रभावित किये गये थे।

15. सरकार अकाल राहत सहायता में कौन-से कार्यक्रम चलाती है ?

उत्तर—अकाल राहत-विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन-विभाग, तथा पंचायतो आदि के मार्फत विविध प्रकार के निर्माण-कार्यों पर स्कूल भवनो, सड़कों, तालाबो आदि का निर्माण या सम्मत लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जाता है। काम के बदले मजदूरी का कुछ अंश अनाज के रूप में दिया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था टंकियों, टैंकरो, टुबो, घँसगाड़ियो, जँटगाड़ियो वगैरा का उपयोग करके की जाती है। पशुओं के लिए चारे की सप्लाई बढ़ाई जाती है। चारे की खरीद विभिन्न राज्यों से करके जरूरत के केंद्रों में पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। चारे पर परिवहन सब्सिडी दी जाती है।

16. 1987-88 के अकाल की विशेष बातों का उल्लेख करें।

उत्तर—इससे सन्ती 27 जिले प्रभावित हुए। प्रभावित गाँवों की संख्या 36252 तथा जनसंख्या 3.17 करोड़ रही। राज्य सरकार ने 7.54 करोड़ रुपये की भूराजस्व की वसूली रोक दी। पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी राज्य के सभी जिले अकालग्रस्त घोषित किये गये। कृषिगत उत्पादन पर काफी प्रतिशूल प्रभाव पड़ा है। 1987-88 में खाद्यान्नों का उत्पादन घट कर 48 लाख टन के स्तर पर आ गया था।

17. राजस्थान के प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए।

उत्तर—ताँबा, सीसा व जस्ता, टंगस्टन, लाइमस्टोन, सगमरमर का पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, भवन-निर्माण के पत्थर, रॉक-फोस्फेट, भुवानी मिट्टी प्लोसंपार, मादि।

18. हाल के वर्षों में राजस्थान में कौन-से खनिज-मण्डारों का पता चला है ?

उत्तर—जैसलमेर जिले में थोठारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया जाता है। रामपुरा घागुचा में जस्ते व सीसे के विपुल भण्डार मिले हैं। बीकानेर जिले में बरसिहपुर में लिम्नाइट के भण्डार मिले हैं जिनसे धर्मल पावर प्लांट लगाया जा सकता है। नितौडगढ़ जिले के नाँव केसरपुरा (प्रत पगढ) के निकट छोटे की खोख उल्लेखनीय है। बीकानेर, नागौर व बाडमेर जिलों में लिम्नाइट के भण्डार मिले हैं। जैसलमेर जिले में लाइमस्टोन तथा पाली जिले में टंगस्टन के भण्डार प्राप्त हुए हैं।

19. राजस्थान में सकल कृषिगत क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र की मात्रा बताइए।

उत्तर—1986-87 के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल 176.4 लाख हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 52% था। इसी वर्ष सकल सिंचित क्षेत्रफल

43.5 लाख हैक्टेयर रहा जो कुल कृषित क्षेत्रफल का 24% था। 1960-61 में यह 15% था। इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा है।

2. राजस्थान की खरीफ की फसलों के नाम लिखिए—

उत्तर—धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, खरीफ की दालें जैसे तुर, मूंग, मोठ, चोला, उड़द।

21. राजस्थान की रबी की फसलों के नाम लिखिए—

उत्तर—गेहूँ जो चना, रबी की अन्य दालें जैसे मसूर की दाल, आदि।

22. राजस्थान में गहूँ बाजरा, व धान की खेती किन जिलों में प्रमुखतया की जाती है ?

उत्तर—(अ) गेहूँ—गगानगर, झलवर कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर व चित्तौड़गढ़।

(आ) बाजरा—झलवर, भरतपुर जयपुर भूमनूँ, नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर व टोंक।

(इ) धान—गगानगर, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर, व झालावाड़।

23. राजस्थान में व्यापारिक फसलों या नकद फसलों के नाम लिखिए।

उत्तर—तिलहन-तिल, सरसो, झलसी, मूँगफली, अरण्डी, सोयाबीन आदि। कपास, गन्ना तम्बाकू, लालमिर्च, मालू, धनिया, जीरा आदि।

24. राजस्थान की खाद्य फसलों की विशेषता का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—कुल कृषित क्षेत्रफल के आधे भाग पर घनाजो की फसलें होती हैं। घनाजो में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के सम्मर्गत पाया जाता है, यह घनाजो के क्षेत्रफल के आधे भाग में, अथवा कुल कृषित क्षेत्रफल के लगभग 25% या 1/4 भाग पर बोया जाता है। 1986-87 में बाजरा 52.8 लाख हैक्टेयर में बोया गया तथा कुल कृषित क्षेत्रफल 176.4 लाख हैक्टेयर था। इस प्रकार इस वर्ष तो बाजरे के सम्मर्गत क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का 30% रहा।

25. राजस्थान में योजनाकाल में खाद्यान्न के उत्पादन में क्या परिवर्तन हुए ?

उत्तर—राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 30 लाख टन से बढ़कर 1983-84 में लगभग 1 करोड़ टन हो गया था। इसमें वार्षिक उत्पन्न-चढ़ाव बहुत धीरे-धीरे रहा है। 1987-88 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 48 लाख टन लगाया गया है। 1985-87 के लिए सम्मोचित अनुमान 68 लाख टन लगाया गया है। 1988-89 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 100.75 लाख टन (1 करोड़ टन से अधिक) प्रस्तुत किया गया है। प्रायः खरीफ की फसल मक्का व सूखे का शिकार हो जाती है जिससे उत्पादन घट

जाता है। पिछले वर्षों में रबी में खाद्यान्नों का उत्पादन खराब क खाद्यान्नों से प्रभावित रहा है।

26. राजस्थान में कृषि-युक्त इन्पुटों पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए।

उत्तर—(i) खाद्य-पदार्थ—दुग्ध-पदार्थ, फल व सब्जियाँ, (दिल्ली के मजार-मरवा) आटा-मिलें दान-मिलें बेकरी, चीनी, गुड़, देशी खाड़, वनस्पति घी, खाद्य-तेल, बरौंग। इसी में जोधपुर, बनासौर क्षेत्र की मेथी, पाली की महुदी, पुष्कर क्षेत्र के फल सब्जों व गुन्ना के फूल बाँसवाड़ा का आम-बापड़ व बीकानेर के पापड़-मुजिया पाते हैं।

(ii) तम्बाकू पदार्थ—जरदा, बीड़ी।

(iii) कौटन प्रोसेसिंग व कौटन वस्त्र—जिनिम व प्रेसिंग फैब्रिक्, कताई व बुनाई, रंगाई छपाई व इलीक्ट्रिक (बुनाई के लिए कई प्रकार की टेक्नोलोजी प्रयुक्त होती है जैसे हथकरघा शक्ति करघा, मिल करघा, बरौंग)

(iv) रेशम का उद्योग।

(v) टेक्स्टाइल वस्तुएँ—गलीचे, निटिंग मिलें, गार्मेंट, रेनकोट, बपड़े के जूते।

एग्रो उद्योगों (agro industries) के व्यापक अर्थ में पशु-आधारित व वन-उद्योगों के अलावा कृषि के लिए इन्पुट तैयार करने वाले उद्योगों जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, ट्रैक्टर, कृषिगत मशीन आदि को भी शामिल किया जाता है। लेकिन सखीण अर्थ में कृषि के बच्चे माल पर आधारित उद्योग लिखे जाते हैं।

27 राजस्थान में सूनी वस्त्र मिलों के स्थान बताइए।

उत्तर—ये पाली, मोतबाड़ा, विशनगढ़, ध्यावर, श्री गंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा व मकानो मढ़ी में स्थित हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 23 बतायी गई है। इनमें से 17 निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में व 3 सहकारी क्षेत्र में हैं।

28. राजस्थान के पशुधन की विशेषता बताइए तथा इस पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए।

उत्तर—1983 में राज्य में पशुधन की संख्या 4.95 करोड़ हो गयी थी। राज्य में पशुधन की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पायी जाती हैं। राजस्थान में भेड़ों की उत्तम नस्लें पायी जाती हैं, जैसे बीकानेर की माली, चाकला व मायरा, जैसलमेर की जैसलमेरी व जाधपुर की मारवाड़ी।

पशुधन पर आधारित उद्योग—डेयरी उद्योग दूध व दूध से बने पदार्थ, ऊन, माँस, चमड़ा, हड्डी। राज्य में पशुधन का विकास करके लोगों को रोजगार दिया

जा सकती है व आमदनी बढ़ायी जा सकती है। ये कृषि के सहायक उद्योगों के रूप में भी विकसित किया जा सकते हैं।

29 राजस्थान की बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के नाम लिखिए।

उत्तर—राजस्थान का निम्न बहुराज्यीय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में हिस्सा है—

- (i) भाखड़ा-नागल (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)
- (ii) चम्बल (मध्य-प्रदेश व राजस्थान)
- (iii) व्यास (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)
- (iv) माही बजाजसागर (गुजरात व राजस्थान)।

30 माही बजाजसागर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर—इसका निर्माण बाँसवाड़ा के समीप किया गया है। यह कुल 80 हजार हेक्टेयर में सिंचाई कर सकेगी। पावर हाउस न 1 पर 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ जनवरी, 1986 में चालू कर दी गई हैं।

पावर हाउस न 2 पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयाँ बनायी जा रही हैं। सातवी योजना में पूरा हो जाने पर राजस्थान में पावर सप्लाई भी बढ़ जायेगी।

31 राजस्थान की बृहद सिंचाई की परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं ? इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की प्रगति का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर—राजस्थान की बृहद सिंचाई की परियोजनाओं (जिनके नीचे कमांड क्षेत्र 10 हजार हेक्टेयर से अधिक होगा) में निम्नलिखित हैं—

1. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना,

2. गुडगाव

3. मोखला जलाशय

4. नर्बदा, 5. जाखम व धौन बाघ (पंजाब) 7. मोहर फीडर 8. सिधमुख 9. बीसलपुर (जिला टोंक) इन सभी पर कार्य प्रगति पर है।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना में मुख्य नहर व्यास-सतलज के संगम पर हरीके बाध से प्रारम्भ होती है। इसे बाढमेर में गढ़रा रोड तक ले जाया जायेगा। फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुख्य नहर की लम्बाई 445 किलोमीटर है। इस पर लगभग 30 वर्षों से कार्य किया जा रहा। मुख्य नहर 1 जनवरी 1987 तक अपने मुद्दूर छोर तक पहुँचा दी गई है। इसके पूरा होने पर 13.88 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी तथा अनाज, मक्का, कपास, तिलहन, आदि की पैदावार बढ़ेगी। द्वितीय चरण की स्कीम में साहूवा, गजनेर, कोलायत, फलीडी, पोरन व बाढमेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (जलोत्थान योजनाओं के द्वारा 60 मीटर ऊँचाई तक नहरी पानी को ऊँचा उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी।

1986-87 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से 5.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई। जनवरी 1988 में योजना आयोग की बैठक में यह संकेत दिया गया कि 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए प्रति वर्ष इस परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपये उपलब्ध किये जायेंगे।

इस परियोजना की दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण की लागत 255 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण की लागत 931 करोड़ रुपये रखी गयी है (कुल 1186 करोड़ रुपये)। वितरण-प्रणाली की दोनों चरणों की सम्वाई 7875 किलोमीटर होगी, जिसमें बहाव-क्षेत्र (flow area) व लिफ्ट क्षेत्र क्रमशः 5568 किलोमीटर व 2307 किलोमीटर होंगे (स्रोत, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, पावरी, 1988, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड द्वारा जारी)।

32. थार मरुस्थल (Thar desert) का प्रदेश बताइए।

उत्तर—परावली के पश्चिम व उत्तर-पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से भरा है। इसका सुदूर पश्चिमी भाग (western-most part) 'थार मरुस्थल' कहलाता है जो पाकिस्तान की सीमा पर बल्च के रेत के सहारे-सहारे पंजाब तक फैला है। बाणेश्वर, जैमलमेर व बीकानेर के कुछ भागों में बड़े-बड़े टीले पाये जाते हैं। यहाँ के निवासियों को शुष्क जाड़न का सामना करना पड़ता है। यह भारत का सबसे अधिक गर्म प्रदेश माना जाता है। इसमें कहीं हरियाली नजर नहीं आती। मीषण जलवायु, कम वर्षा, सुदूर प्रदेश व कठोर जीवन मरुस्थल की विशेषताएँ हैं।

33. राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइए।

उत्तर—राज्य के निम्न 11 जिले मरुस्थलीय या रेगिस्तानी जिले कहलाते हैं। इनमें राज्य का 60% क्षेत्रफल तथा 40% जनसंख्या शामिल होते हैं। ये जिले इस प्रकार हैं—जैमलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, नागौर, चूरु, पाली, जालोर, श्रीरंग तथा मन्सूर।

34. मर-विकास-परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—मर विकास परियोजनाओं (DDP) का उद्देश्य रेगिस्तान की माधं या फँसव की शेरना तथा यह प्रदेश का आर्थिक विकास करना है। 1985-86 से यह पुनर्स्थापना कृत्रिम-कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य प्रमुख हैं : नमूनाकरण, जलिकी या वन-विकास, भूतल जल विकास (ground water development), भेड़ व ऊँट-विकास, पेयजल स्कीम व लघु सिंचाई की योजनाएँ। 1988-89 के लिए मर विकास कार्यक्रम के लिए 37 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है।

35. राजस्थान व गुजरात-समाहित क्षेत्र कार्यक्रम का परिचय दीजिए।

उत्तर—इस DPAP में शामिल माना जाता है। यह 1970-71 में प्रारम्भ किया गया था। इनके अन्तर्गत पहलू कई जिले शामिल किये गये थे, लेकिन छोटी

योजना में इसे निम्न प्रदेशों तक सीमित कर दिया गया क्योंकि अन्य प्रदेशों में मरू-विकास-कार्यक्रम चालू हो गया। DPAP के क्षेत्र इस प्रकार है - डूंगरपुर व बासवाड़ा के जनजाति के जिले, उदयपुर जिले की भीम, देवगढ़ व खेरवाड़ा तहसीलें तथा अजमेर जिले की ब्यावर तहसील। DPAP के अन्तर्गत भू-संरक्षण, लघु सिंचाई व वृक्षारोपण पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व ग्रामिणों की बढ़ायी जाती है। 1988-89 में इस कार्यक्रम पर 5 करोड़ रु के व्यय का प्रावधान किया गया था। इसके अन्तर्गत कुल 30 ब्लॉक (blocks) हैं। DDP व DPAP कार्यक्रमों में पंचायतों का अधिक सहयोग लिया जाना चाहिए।

36 राजस्थान के सन्दर्भ में व्यर्थ भू-खण्डों (wastelands) की समस्या का रूप स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—1986-87 में राजस्थान में लगभग 57.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृषियोग्य व्यर्थ भू-खण्ड थे, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 17% अंश था। व्यर्थ भू-खण्ड व परती भूमि का योग 30% था। परती भूमि किन्हीं कारणों से बिना वास्तविक उपयोग की जा रही है। व्यर्थ भू-खण्डों के कई रूप होते हैं जैसे कन्दराएँ व गहरी पतली घाटियाँ (ravines), बालू रेत के टीले, जलमग्न क्षेत्र, क्षारयुक्त व लवणयुक्त भू-खण्ड, जनजाति क्षेत्रों में भूमि खेती वाले भू-खण्ड, आदि। व्यर्थ भू-खण्डों की समस्या के उद्भव होने का कारण अत्यधिक चराई, वृक्षों की अघाघु घटाव से फाट डालना तथा फलस्वरूप परिवेश-संतुलन को नष्ट कर डालना है। भूमि का 'बचर' हो जाने से मिट्टी का कटाव प्रारम्भ हो जाता है। वन-विभाग, रेवेन्यू-विभाग, व पंचायतों को व्यर्थ भू-खण्डों का उपयोग करके पशुओं के लिए चारे, ग्रामीणों के लिए जलाने की सक्की उद्योगों के लिए बन्धे आल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। राजस्थान में व्यर्थ भू-खण्डों की समस्या को हल करने हेतु राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गई है। व्यर्थ भू-खण्डों का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा इनके सदुपयोग के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता पशु आदि सामानाधिकृत हो सके।

37 राजस्थान में सीमेंट, चीनी, सिन्थेटिक यार्न व रसायन-उद्योगों के विभिन्न स्थान बताइए।

उत्तर—(अ) राजस्थान में सीमेंट के कारखाने निम्न स्थानों में हैं :—

सवाई माधोपुर, लासेरी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहुटा गोटन (नागौर) (सफेद सीमेंट समग्र), मोडव (कोटा) वनास (सिरोही) ब्यावर तथा कोटा। इस प्रकार सफेद सीमेंट सहित राज्य में सीमेंट की 10 बड़ी इकाइयाँ हैं।

मिनी सीमेंट प्लांट सिरोही (निहवाड़ा), बासवाड़ा व कोटपूतली में स्थित हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास की भावी सम्भावनाएँ भी हैं।

(घा) चीनी—भूपालसागर (चिस्तीडण्ड), श्रीगणनगर, व केशारःपटना । इस प्रकार राज्य में चीनी के 3 बड़े कारखाने चल रहे हैं ।

(इ) सिन्थेटिक धान—बासवाडा, बहरोड, डूंगरपुर, रीगस, जोधपुर, भावुरोट उदयपुर, असलवर, गुलाबपुरा, (रीको द्वारा समुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्रों में)

(ई) रसायन-उद्योग—डीडवाना में रसायन वर्क्स सांभर सोल्डस, सांभर, श्री राम फर्टिलाइजर्स, कोटा, उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स उदयपुर, राजस्थान एक्सप्लोजिव्स व केमिकल्स लि., जोधपुर (विस्फोटक (detonators) बनाता है), मोदी अल्केमोज एण्ड केमिकल्स लि., असलवर, हिन्दुस्तान जिंक लि., देवारी, उदयपुर, हिन्दुस्तान कापर लि., खेन्डी आदि ।

38 राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों का उत्प्रेषण कीजिए ।

उत्तर—इन्हें धात्विक (metallic) व अधात्विक (non metallic) दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है :

(i) धात्विक खनिज आधारित उद्योग—इस्पात उद्योग जो कच्चे लोहे, चूने व पत्थर, हीलोमाइड, धर्म पर आधारित है । इसके अलावा स्टील फर्नीचर, मशीनरी व औजारों का निर्माण आदि ।

(ii) अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योगों में निम्न आते हैं—सीमेंट, स्टोन वस्तु उद्योग, काच व काँच का सामान, चायना बसे पर आधारित चीनी मिट्टी के बरतन, एस्बेस्टस व मोमेट के पाइप/पदांश आदि ।

39 राजस्थान के औद्योगिक जीवन में लघु उद्योगों की क्या भूमिका है ?

उत्तर—जुलाई 1980 में लघु उद्योगों के लिए सयन एवं मशीनरी में निर्यात की सीमा बढ़ा कर 20 लाख रु. कर दी गई थी । मार्च 1985 में यह पुनः बढ़ाकर 35 लाख रुपये की गई थी । 1980-81 में यहाँ फैक्ट्री क्षेत्र में लघु इकाइयों की संख्या लगभग 90% थी । इनमें फैक्ट्री रोजगार का 36% तथा सभी फैक्ट्रियों में लगे उत्पादक पूँजी का $\frac{1}{10}$ भाग लगा हुआ था । इस प्रकार इनका रोजगार में जैसा अग्र पाया गया है । फैक्ट्री क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं ।

40 राजस्थान की प्रमुख दस्तकारी श्रवण हस्तशिल्प की वस्तुओं का परिचय दीजिए ।

उत्तर—जयपुर के मूल्यवान व अद्भुत-मूल्यवान रत्नों एवं सोन चाँदी के वस्तुओं का भूषण, पीतल की खुदाई व मोनाकारी के बरतन, चास से बनी चूड़ियाँ, मगमरमर की मूर्तियाँ, बारीकरी की जूतियाँ (मोजेटिया व नायरे) रुद्ध पॉन्टरी की नाना प्रकार की वस्तुएँ, सावानरी व बगल प्रिन्ट के वस्त्र, मिट्टी के सिस्तीन, चन्दन

व हाथी दाँत से बनी वस्तुएँ सहूरिए, चूनडियाँ व छोडनियाँ, गलीचे (बीकानेर व जयपुर के), जोधपुर के बादसे, ऊँट की खाल से बनी कलात्मक वस्तुएँ, लकड़ी के खिलौने नाथद्वारा की 'पिछवाइयाँ' तथा फड' (वस्त्र पर पेंटिंग की कलाकृतियाँ), सलमा-सितारे व गोटे किनारी के काम से युक्त परिधान । इस प्रकार वस्त्र, लकड़ो, खाल, घातु, सोने चाँदी आदि पर हस्तशिल्प व अद्भुत कारीगरों का काम राजस्थान के कुटार उद्योगों की अपनी विशेषता है । इनका काफी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है । राजस्थान से गलीचों का निर्यात होता है ।

41. राजस्थान में जन-जाति-अर्थव्यवस्था (tribal economy) की मुख्य विशेषताएँ लिखिए ।

उत्तर—1981 की जनगणना के अनुसार सोगों की संख्या राजस्थान में 41.8 लाख थी । इसके अन्तर्गत अघोषित जनजाति (denotified tribes) के 0.8 लाख व्यक्ति भी थे । राज्य में 10 घुमक्कड़ (खानाबदोश) व 13 अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजातियाँ निवास करती हैं । अधिकांश जनजाति के लोग बासवाड़ा व डूंगरपुर के पूरे जिलों में तथा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोंही जिलों की कुछ तहसीलों में रहते हैं ।

1981 में राज्य में जनजाति के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 12.2% थी (सारे देश का औसत 8% था) । 1980-81 में जनजाति के पाँच जिलों में 45% आदिवासियों के पास एक हेक्टेयर से कम कृषियोग्य जमीन थी । औसत जमीन 1.7 हेक्टेयर पायी गयी (राज्य का औसत 4.4 हेक्टेयर) । इस प्रकार इनके पास जमीन का आकार छोटा पाया जाता है । इनके लिए दस्तकारी का अभाव पाया जाता है । परिवहन की कठिनाई होती है । सिंचाई व पेयजल की कमी होती है । इनका जीवन जंगलों में लकड़ी की कटाई पर आश्रित होता है । प्रायः राहत कार्यों पर इनको मजदूरी पर काम दिया जाता है । ये आर्थिक शोषण, सामाजिक पिछड़ेपन व कुरीतियों, अ-विश्वास, कुपोषण, अशिक्षा, वर्गों के शिकार पाये जाते हैं । इनमें बहु-विवाह (polygamy) की प्रथा पायी जाती है ।

42 राज्य सरकार की जनजाति विकास-योजनाओं का स्पष्टीकरण दीजिए ।

उत्तर—राज्य सरकार जनजाति-विकास के लिए चार प्रकार की योजनाएँ संचालित कर रही है जो इस प्रकार हैं—

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र—यह 1974-75 से प्रारम्भ की गई थी । इसके अन्तर्गत 4409 गाँव आते हैं । इसके अन्तर्गत अधिकांश राशि सिंचाई, पावर, फल-विकास, 'बेर-बॉर्डिंग', सामुदायिक सिंचाई (डीजल पम्पिंग सेट द्वारा) कृषि-वैज्ञानिकी के कार्यों पर किया जाता है । इस उपयोजना के अन्तर्गत 1989-90 के लिए 119.4 करोड़ रुपये की राशि व्यय के लिए रखी गयी है । आदिवासियों को

बीज व उर्वरकों का वितरण भी किया जाता है। भविष्य में कुम्भों को गहरा करने, बीजल पम्प-सेटों के वितरण, सामुदायिक व्यय भूखण्ड विकास कार्यक्रम, पशु-प्रजनन सुधार कार्यक्रम, मुर्गीपालन कार्यक्रम, वन्य कार्यक्रम, रेशम कार्यक्रम, लघु व कुटीर उद्योग, प्रतियोगिता प्रतियोगियों में कोविग कार्यक्रम तथा बायो गैस मयत्र की स्थापना व मदक-निर्माण पर ध्यान दिया जायगा।

2 परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा)—यह 1978-79 में प्रारम्भ किया गया। इसमें 13 जिलों के लगभग दस लाख व्यक्ति शामिल हैं। माडों की संख्या 2939 है। इसमें विशेष केन्द्रीय सहायता (special central assistance) के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के लिए 36 करोड़ रु का प्रादधान किया गया था।

3 सहिष्णु विकास कार्यक्रम—यह 1977-78 में लागू किया गया है। इसमें 435 गांवों के 50 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे। यह कार्यक्रम छोटा डिले की निशानेज व शाहवाह पंचायत समितियों में महारिवा आदिम जाति (primitive tribe) को लाभ पहुंचायेगा। 1988-89 में विशेष केन्द्रीय सहायता 20 लाख रु. की रखी गई थी। प्रस्तावित व्यय का 47% शिक्षा पर तथा 28% लघु सिंचाई पर व्यय किया जायगा ताकि महारिवा कृषिगत परिवारों का सिंचाई की सुविधा मिल सके तथा उनमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके।

4 खिलरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम—यह जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (Tribe Area Development Department) (TADD) के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। 1988-89 के लिए 70 लाख रु की व्यवस्था की गई थी।

राजस्थान में 41.8 लाख जनजाति के लोगों में से 27.5 लाख लोगों को जनजाति उप-योजना, माडा व महारिवा कार्यक्रमों में लाभान्वित किया जा रहा है जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। शेष 14.3 लाख खिलरी जनजाति के लोगों को (TADD) के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

43. राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रीय व अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का परिचय दीजिए।

उत्तर—(1) ग्राम विकास कार्यक्रम (DDP)

(ii) मूल्य सम्मानित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)

(iii) कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP)

(अ) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम : इसी को समनल बनाना, पानी की नालियों को पक्का करना, मटक, मण्डो, जल सप्लाई, कृषि पशु पालन आदि।

(घा) ग्राम कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम—उचित ड्रेनेज, वृक्षारोपण, जली घास-पान उगाहना, बोदाम नवन-निर्माण आदि।

(iv) मैमिव कार्यक्रम : लघु व सीमान्त वृषको को नल-रूप के लिए कर्ज व सम्मिही ।

(v) सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) (Border Area Development Programme)

(vi) मेदात विकास भरतपुर व अलतर म मेन यादुल्य क्षेत्रो के लिए । 1989-90 मे 1 15 करोड व की राशि मेदात विकास बोड के लिए निर्धारित की गयी है ।

(vii) डेयरी विकास

(viii) सामाजिक यानिकी—सडक, नहर प्रादि के किनारे-किनारे कन्दरा क्षेत्रा मे वायुयान से बीजारापण ।

(xi) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) . निर्धनता-उन्मूलन कार्य कन, स्वराजगार के जवसरो मे वृद्धि परिसम्पत्ति का विनरण यानिकी का तव । कूटयाही, धलगाही, बकरी भैस, सिलाई की यानिकी का वितरण । यह 1978-79 स चलाया जा रहा है । फरवरी 1989 तव 1 37 परिवार लाभान्वित, 1989-90 के लिए 35 6 करोड रुपय का प्रावधान 30% महिलायो को लाभान्वित किया जायगा । इनके माल की विक्री की व्यवस्था मे सुधार किया जायगा ।

(x) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) 1988-89 म 20 करोड रुपये का प्रावधान, 60 लाख मानव-दिक्स रोजगार का लक्ष्य ।

(xi) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP) : 1988-89 मे 22'9 करोड रुपये प्रस्तावित, 75 लाख मानव दिक्स रोजगार का सृजन ।

(xii) ग्रामीण-मैस समग्र योजना तथा निर्धूम चुल्हा योजना, गाँवों के लाभार्थ ।

1989-90 के लिए (NREP) व (RLEGP) को भिला दिया गया है । यह ग्रामीण रोजगार का विन्तुन कार्यक्रम जवाहर-रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाया जायगा ताकि ग्रामीण निधन परिवारो मे रोजगार व लाभदनों का विस्तार किया जा सके ।

44 राजस्थान मे विकास सन्ध्याधों का डल्लेख कीडिए ।

उत्तर—(क) ग्रामीण विकास विभाग तथा विभिष्ट आयोजनता संगठन (Special Schemes Organisation) (SSO) द्वारा मरुविकास कार्यक्रम, सूखा सम्प्रावित क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन राजगार गारन्टी कार्यक्रम व ट्राइसम का संचालन किया जाता है । ध्ययं मूय-लण्ये के विकास का कार्यक्रम राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किया जाता है । सामाजिक यानिकी कार्यक्रम वन विभाग द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है । उद्योगों

प्रकाश व सूखे के कारण राज्य की प्रति व्यक्ति आय गतिहीन बना हुयी है। (राजस्थान के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के नवीनतम आकड़ों के अनुसार)

चूँकि काफी लम्बी अवधि तक प्रति व्यक्ति आय, स्थिर भावों पर, गतिहीन बनी रही, इसलिए लोगों में यह धारणा जोर पकड़ती गई कि राजस्थान आर्थिक गतिहीनता का शिकार हो गया है। लेकिन सशोधित आकड़ों के आधार पर पाचवी योजना में प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर) 2 1% वार्षिक तथा छठी योजना (1980-85) में 4 1% व पंद्रहवाँ, जो आर्थिक प्रगति की परिचायक है। लेकिन पिछले चार वर्षों से लगातार अनाल व सूखा पड़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुँची है। अतः राज्य का आर्थिक विकास काफी अनिश्चित व प्रस्थिर गति से हो रहा है। यह अविष्य के लिए एक गम्भीर चुनौती है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1987-88 में 583 रुपये आकी गयी है जो 1970-71 के 651 रुपये के स्तर से कम है। यह स्थिति वास्तव में एक भारी चिन्ता का विषय है।

50 राजस्थान की पावर की स्थिति बताइए।

उत्तर—1989 के मध्य में राजस्थान में विद्युत-सृजन-क्षमता लगभग 2 00 मेगावाट हो गयी है। राज्य में लगभग आधी सृजन क्षमता जन विद्युत (हाइडल पावर) की तथा आधी थर्मल पावर की रही है। कुछ विद्युत-उत्पादन स्थानों पर पर डीजल व थर्मल से भी हाता है।

(अ) जल-विद्युत के स्रोत इस प्रकार हैं :

(i) भाखड़ा-नागल, (ii) व्यास, इकाई I व इकाई II, (iii) माधो नहर (iv) राणा प्रताप सागर (v) जवाहर सागर। (तीनों चम्बल परियोजना के अन्तर्गत)। (vi) माही बराज सागर पावर हाउस न।

(आ) थर्मल परियोजना—(i) सतपुड़ा, (ii) सिंगरोली, (iii) राजस्थान अणु-शक्ति केन्द्र, कोटा I व II, (iv) कोटा थर्मल पावर सदन।

राज्य में सातवी योजना के अन्त तक विद्युत की कमी के दूर हो जाने की आशा है।

51. राजस्थान किस प्रकार विद्युत-सृजन-क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ?

अथवा

राजस्थान में विद्युत-सृजन-क्षमता बढ़ाने के नये प्रयासों का परिचय दीजिए।

उत्तर—(1) कोटा थर्मल परियोजना के द्वितीय चरण तथा माही परियोजना के पावर हाउस न. 2 का कार्य प्रगति पर है। इन दोनों परियोजनाओं के 1989-90 में

पूरा होने की धारा है। कोटा थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण (stage I) को 1983 में चालू किया गया था। इसमें 110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ थी। द्वितीय चरण (stage II) में 210 मेगावाट की 2 इकाइयाँ होगी, जिनमें से 210 मेगावाट की प्रथम इकाई 25 सितम्बर 1988 को चालू कर दी गई। इसी क्रम की द्वितीय इकाई 1989-90 में चालू की जायगी। कोटा थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की भावी सम्पन्नता व विकास का स्तम्भ माना जा सकता है। (ii) धनूपगढ़ लघु विद्युत परियोजना के प्रथम व द्वितीय विद्युत गृहों से निकट भविष्य में पावर को सप्लाई बढ़ेगी। (iii) पलाना थर्मल विद्युत गृह से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के कार्यक्रम की योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। यह परियोजना कार्यान्वयन हेतु नैवेली लिमिटेड का कॉपोरेशन को सौंपी गयी है। इसकी क्षमता बढ़ायी जा सकती है। (iv) राज्य सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कॉपोरेशन को अन्त में गैस पर आधारित 430 मेगावाट की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध करा दी है। इसकी क्षमता भी बढ़ायी जा सकती है। साथ ही पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इस परियोजना के क्रियान्वयन से राजस्थान में विद्युत की कमी काफी सीमा तक दूर की जायगी। जनवरी व फरवरी 1989 में 88 मेगावाट की दो इकाइयाँ चालू कर दी गई हैं।

52 राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का परिचय दीजिए।

उत्तर—1985-86 के अंत तक राज्य में सहकारी समितियों की संख्या 19076 तथा सदस्य संख्या 61 लाख व्यक्ति हो गयी थी। प्राथमिक कृषि-साख समितियाँ 5267 तथा सदस्य संख्या 42.9 लाख थी। राज्य में 99% ग्राम व 87% कृषक परिवार सहकारिता के दायरे में आ चुके हैं। सहकारी ऋणों (ग्रुपबैंकालोन, मध्यमकालोन तथा दीर्घकालीन) के सम्बन्ध में 1989-90 के लिए कुल 190-50 करोड़ रु के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से ग्रुपबैंकालोन ऋणों की राशि 150 करोड़ रु होगी।

53 राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता के नये कार्यक्रम बताइए।

उत्तर—(i) कोटा में सोडाबोन से प्रतिदिन 200 टन तेल निष्कासने के कारखाने की स्थापना की जायगी। इससे कोट, बूंदी, अजल बाड़, चित्तौड़ व बांसवाड़ा के 50 हजार कारखाने को लाभ होगा।

(ii) गगानगर (2), जालौर, नागौर, भुम्कनू व सुवाई माधोपुर में सरसों के छसयन लगाने का कार्यक्रम है। सरसों, रायडा, व तोरिया की सप्लाई से कृषकों की आमदनी बढ़ेगी।

(iii) गगानगर में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र की मिल स्थापित की जायेगी जिसमें आयातित मशीनरी का उपयोग होगा। इससे रोजगार में वृद्धि होगी। इस प्रकार अनरपति तेल व वस्त्रोद्योग में सहकारिता का प्रयोग करने के कार्यक्रम हैं।

54 राजस्थान की सातवीं याजना में सार्वजनिक परिवहन का प्रस्तावित प्रायटन बताइए।

उत्तर—टूटि ग्रामीण विकास व गृहकारिता पर 13% बिजुई व शक्ति पर 54%, उद्योग व खनन पर 6% परिवहन पर 4%, सामाजिक सेवाओं पर 21% तथा जेए 1% अन्य पर रखा गया है। इस प्रकार बिजुई व शक्ति व विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है।

55 राजस्थान में विश्वी-मन्य की दृष्टि में चार बड़े खनिजों के नाम लिखिए।

उत्तर—समथरमर रोक फास्फेट मैडस्टोन व तांबा।

56 रीको का परिचयात्मक विवरण दीजिए।

उत्तर—राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व नियंत्रण निगम लि अथवा रीको नवम्बर 1979 में स्थापित किया गया था। इससे पूर्व राजस्थान राज्य औद्योगिक व खनन विकास निगम 1969 में स्थापित किया गया था जिससे राजस्थान राज्य खनन-विकास निगम बनाने के लिए 1979 में रीको की स्थापना की गई। रीको के कार्य इस प्रकार हैं। (i) औद्योगिक क्षेत्रों/वस्तियों का निर्माण करना, (ii) सांख्यिकीय सयुक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, (iii) औद्योगिक क्षेत्रों/अभिजातन में भाग लेना, (iv) औद्योगिक विकास के लिए मधेक्षण करवाना व प्रोजेक्ट तैयार करवाना (v) रियायतों व प्रेरणाओं की व्यवस्था करना। रीको का स्वयं की तीन परियोजनाएँ इस प्रकार हैं—71 वीं थडी दूने रेडियो मवार उदकरण परियोजना। राजस्थान इन्फ्रस्ट्रक्चर लि. व राजस्थान कम्प्यूटिकेशन लि इसकी दो सहायक कम्पनियाँ हैं।

57 'सयुक्त क्षेत्र' की धारणा स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—'सयुक्त क्षेत्र' के अन्तर्गत एक औद्योगिक इकाई में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों का एक साथ अस्तित्व होता है। प्रायः पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र से आती है तथा प्रत्यक्ष निजी हाथों में होता है। 'सयुक्त क्षेत्र' का समर्थन सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की कमियों को दूर करने के लिए किया गया है। निजी क्षेत्र में प्रायिक सत्ता के व दायजकरण को कम करने के लिए सयुक्त क्षेत्र के विकास का समर्थन किया गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के मिले जुले प्रयास से उत्पन्न होता है। चाटी को निजी कम्पनियों को सयुक्त क्षेत्र में लाने से कई प्रकार की समस्याएँ हल हो जाती हैं। सयुक्त क्षेत्र में लाकर इनका विकास करने व पैमाने की किरायतें प्राप्त करने से समस्त समाज को लाभ पहुँचता है। इनका तकनीकी विकास सुगम हो जाता है। गवर्णीकरण नियम बिना उद्योगों को सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित करने का सरल विधि सयुक्त क्षेत्र का विकास करने की होती है।

58 सार्वजनिक क्षेत्र सयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र में अन्तर करें।

उत्तर—मार्बेजनिश क्षेत्र में औद्योगिक इकाई का स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंध पूर्णतया सरकार के अधिकार में होता है, जैसे राजस्थान में गगानगर गुमर मिल लि. मार्बेजनिश क्षेत्र की इकाई है। मयूक्त क्षेत्र में राजस्थान का (रीको के माध्यम से इक्विटी में 26% अंश होता है। इसका प्रबंध निजी हाथों में भी जाना है। महामता-प्राप्त क्षेत्र में रीको का इक्विटी माफेयर पूंजी में प्रायः 10-15% अंश होता है। ये औद्योगिक विकास के लिए स्थापित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं।

59. राजस्थान में 'मयूक्त क्षेत्र' में औद्योगिक प्रगति का परिचय दीजिए।

उत्तर—राज्य में पिछले वर्षों में मयूक्त क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया है। मयूक्त क्षेत्र में कई इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न हैं। इनमें कई इकाइयाँ कंपेंट यान तथा फिथरिंग यान बना रही हैं। जेय इकाइयाँ रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं। राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एण्ड केमिकल्स लि., घालपुर में 'डिफ्लाटर्स' (detonators) बनाय जात हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. बनारसपुरासपुर में विद्युत मिश्र टेस्टर (tester) (दुप-विद्युतक-यंत्र) बनाय जाते हैं। यह इकाई बोटा इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. की सहायक होने के ताने केन्द्रीय इकाई के अन्तर्गत भी आ सकती है। परमाणु राजस्थान कॉपर फॉयल्स लि. जयपुर कॉपर फॉयल्स (Copper foils) व लेमिनेट्स (lam plates) बनाता है। इन सब का बड़ा बटिनाइडों के कारण राज्य में मयूक्त क्षेत्र का विकास की गति धीमी पड़ गयी है। इसका बूझ इकाइयाँ कम हो गई हैं जिससे इन क्षेत्र को घटका पड़ेगा है।

60. राजस्थान बिल निगम व राज्य के वित्त विभाग में अन्तर स्तिए।

उत्तर—राजस्थान बिल निगम 1955 में तबु व मरयम श्रेणी के उद्योगों को विलोय सहायता देने के लिए स्थापित किया गया था। यह इसकी प्रति इकाई सहायता की सीमा बहुत 60 लाख रुपये का हो गई है। यह परिवहन व हाटल के बिल भी कर देता है। उदाहरण के तौर पर इसका काम काफी बड़ा है।

राज्य का वित्त विभाग राज्य के सचिवालय में एक विभाग होता है जो सरकार के वित्त मन्त्रालयी मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह बजट-निर्माण में सहायता देता है तथा सरकारी आय व्यय का हिसाब रखता है। वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष वित्त-प्रयोग के मसल एह विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें 5 वर्षों की अवधि के लिए आय-व्यय के अनुमान होते हैं जिनके आधार पर आयोग राज्य की विलोय आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है।

61. 'राजनीको' की भूमिका समझाइए।

उत्तर—“राजमीकी” का पूरा अर्थ है राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) यह 1964 में स्थापित किया गया था। यह कच्चे माल जैसे कोयला/कोक, इस्पात, सीमेंट जस्ता प्रादि का वितरण करता है। इसने दस्तकारी के एम्पोरियम तथा गलीचा-प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये हैं। इसने चुरू व सादरू में ऊनी मिलें, टोक में मयूर बीटो पंक्ट्री, तेहू की पत्तियों के मयूर की व्यवस्था तथा सागानेर एयर पोर्ट पर निर्यात की सुविधा के लिए एक ‘एयर कर्गो कॉम्प्लेक्स’ स्थापित किया है। राजमीकी लघु उद्योगों के विभाग के लिए कार्य करता है।

62 राजस्थान के आर्थिक जीवन में खादी व ग्रामोद्योगों का क्या स्थान है ?

उत्तर—राज्य में सूती व ऊनी खादी का उत्पादन होता है। 1987-88 में लगभग 21.8 करोड़ रु की खादी का उत्पादन हुआ था। इस उद्योग में काफी लोग औद्योगिक व पूर्णकालिक काम पाये हुए हैं। ग्रामोद्योगों में घानी का तेल, गुड़ व खादमारी, हाथ का कागज, जलछाई तेल से बनी साबुन, चमड़े की वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी-पालन व घान का हाथ से कूटकर छिलका हटाने प्रादिके काम शामिल हैं। ग्रामोद्योगों के उत्पादन का मूल्य 1987-88 में 1165 करोड़ रु. हुआ था जिसके 1988-89 में बढ़कर 120 करोड़ रु हो जाने का अनुमान है। खादी व ग्रामोद्योगों का रोजगार, आयदनी व निर्धनता-निवारण कार्यक्रमों की दृष्टि से बहुत महत्व है। ये ग्रामवासियों के आर्थिक जीवन का आधार स्तम्भ है।

63. राजस्थान सरकार ने नये उद्योगों को बिजली-कर में क्या छूट दी है ?

उत्तर—राज्य सरकार की मई 1987 की घोषणा के अनुसार पिछड़े जिलों में नये उद्योगों को सात वर्ष तक तथा विकसित जिलों में पाँच वर्ष तक बिजली-कर की छूट रहेगी। छूट की सीमा पिछड़े जिलों में छोटे उद्योगों के लिए स्थायी परिसम्पत्ति का सी प्रतिशत तथा बड़े उद्योगों के लिए 90% तक होगी। विकसित जिलों के लिए ये क्रमशः 85% व 75% तक होंगी। ‘पारमिटियरिंग’ व ‘प्रेस्टीजियस’ उद्योगों के लिए 2 अनतिरिक्त वर्षों की बिजली-कर की छूट रहेगी। 10 साल समय में अधिक विनियोजन वाले उद्योगों को कर भुक्ति के बजाय कर-प्रास्थगन (tax-deferment) की सुविधा भी प्रप्त हो सकेगी जिसके लिए सम्बन्धित इकाई को अपना विकल्प देना होगा।

64 1989-90 के अन्त तक राजस्थान के वज्रट में अधूरित घाटे की राजि कितनी रही होगी ? उसको पूरा करने के क्या उपाय हैं ?

उत्तर—1989-90 के अन्त में कुल 204 करोड़ रु का अधूरित घाटा दिखाया गया है। इसमें 1988-89 का 100 करोड़ रुपये का घाटा भी जोड़

लिया गया है। यह घाटा कुछ सीमा तक जाने वाले वर्ष के दौरान कर तथा वफाया रकम की हेरफेर वसूली, केन्द्र में अधिक प्राप्तियों, गैर-आवश्यक व अनुत्पादक खर्च में कमी आदि से पूरा किया जायगा। विनोद अनुशासन को अधिक प्रभावी व मृदुल किया जायगा तथा नरकागे व्यव पर कड़ा नियन्त्रण रखा जायगा। लेकिन यह कार्य कभी कठिन प्रतीत होता है। राज्य की विनीय दशा काफी चिन्ताजनक व डीवा-होन स्थिति में है।

65 राजस्थान राज्य के श्वय के प्रमुख करों के नाम लिखिए। इनमें सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है।

उत्तर—बित्री-कर, न्यू-राजस्व, राजकीय आबकारी शुल्क, स्टम्प व रेजिस्ट्रेशन, दाहनों पर कर तथा मनोरंजन कर। बित्री-कर से सर्वाधिक आय होती है जो 1989-90 के बजट-अनुमानों में राज्य के कुल कर-राजस्व का 36% भागी गयी है। (575 करोड़ रु. की राशि जो कुल राजस्व 1586 करोड़ रु. का लगभग 36% है)।

66. राजस्थान में पंक्तों क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक वस्तुएं कौन-कौन सी उत्पादित होती हैं?

उत्तर—सीमेंट, चीनी, मरिया, मुपर फोस्फेट, दाल डिस्ट्रिक्ट, बिछूठ माटर, नमक, पोलिटेन्टर घागा आदि।

67 निम्नलिखित व्यक्ति जिन पक्षों पर काम कर रहे हैं?

(i) श्री एन. के. पी. मान्दे,

(ii) डा. राजा, जे. चेन्नैया,

(iii) डा. वार्ड, के. जलक,

(iv) प्रोफेसर सुबोध बज्जरी

उत्तर—(i) नवें दिन आयोग के अध्यक्ष,

(ii) योजना आयोग व नवें दिन आयोग के सदस्य,

(iii) योजना आयोग के सदस्य,

(iv) प्रधान मंत्री की आर्थिक मन्त्रालय परिषद् (EAC) के अध्यक्ष तथा दिल्ली स्थित इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर।

68. राजस्थान में कुछ नये इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के नाम व स्थान बताइए।

उत्तर—(i) कीन्जल इण्डियन सामे लि., भिवाही (Kienzle Indian Samay Ltd., Bhiwadi) यहाँ क्वार्टेज क्वांक टाटमिग सुवेमेट का उत्पादन किया जायगा।

(ii) राजस्थान टेलीफोन इन्फस्ट्रुक्च लि. भिवाही में इलेक्ट्रॉनिक पुम दटन टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया जायगा।

(iii) एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड मैग्नेटिक्स लि., उदयपुर में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटों में याददास्त का काम करने हेतु 'पंचोपी डिस्क्रेट्स' बनाये जायेंगे।

(iv) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन लि., जयपुर-विद्युत् मिल्क टेंस्टर (द्वय विश्लेषक यन्त्र) (एक केन्द्रीय प्रोजेक्ट रीको के सहभाग में)

(v) इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स लि., भिवाड़ी—कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स (resistors)

69 'औद्योगिक प्रमिष्ठानों के आयोजन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—राजस्थान में रीफो राजस्थान वित्त निगम व उद्योग-निर्देशानय के तत्वावधान में देश के अन्य भागों में जाकर उद्योगपतियों को राजस्थान में आकर उद्योग लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इन औद्योगिक प्रमिष्ठानों में सरकारी प्रतिनिधियों व उद्यमकर्त्ताओं की धामने-सामने बातचीत होती है और त्रिभिन्न शक्तियों/आशक्तियों का समाधान किया जाता है। ऐसे औद्योगिक प्रमिष्ठान पिछले दिनों बम्बई, कलकत्ता, भुवनाहटी व जिलोग आदि में चलाये गये हैं। इनके माध्यम से सरकार नये उद्यमकर्त्ताओं से सम्पर्क कर पायी है।

70 'आर्थिक क्षेत्र में उदारता की नीति' से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—राष्ट्रीय सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में 'उदारता' की नीति अपनायी है। इसके प्रभुगत अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रणों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाता है। सरकार ने आयात-नियंत्रण, कर-नीति व औद्योगिक नीति व लाइसेन्स-व्यवस्था को पहले से अधिक उदार बनाया है। आयात-नियंत्रण नीति त्रिवर्षीय "की गई है तथा उदार आयात-नीति अपनायी गई है। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति (1985-90 के लिए) भी घोषित की गई है। प्रत्यक्ष-करों की दरें कम की गई हैं। 'आर्थिक उदारता' के व्यापक रूप से आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ायी जाती है और उत्पादन का पैमाना बढ़ाकर लागत कम करने का प्रयास किया जाता है।

71 क्या राजस्थान में पंचवर्षीय योजना का वर्तमान स्वरूप को भंग करके केवल अकाल निवारण हेतु एक पंचवर्षीय कार्यक्रम या योजना को कार्यान्वित करना अधिक श्रेयस्कर होगा ?

उत्तर—केन्द्रीय नियोजन की पद्धति के अन्तर्गत राज्य स्तर पर भी योजना के वर्तमान स्वरूप को ही जारी रखना लाभप्रद होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा सुदृढ़ विवरण नहीं प्रतीत होता। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का समतुलित व शीघ्र विकास करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राज्य के आर्थिक विकास कार्यक्रम को इस तरह ढाला जाना चाहिए कि यह अकाल व सूखे में हमें पर्याप्तम्बव राहत देना सके।

72. राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई बताइए।

उत्तर—[1986-87 में 15.10 किलोमीटर]

73. राजस्थान में 1985-86 में प्रति व्यक्ति पावर का उपभोग बताइए।

उत्तर—[1985-86 में 124 किलोवाट घंटे]

74. राजस्थान में जिलो, तहसीलो, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों व गांवों की संख्या बताइए।

[जिले = 27, तहसीलें = 207, पंचायत समितियां = 237, ग्राम-पंचायतें = 7353 कुल गांव = 37,124]

75. नवें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार 1989-90 वर्ष के लिए राजस्थान को क्या वित्तीय प्राप्तियां होंगी ?

1989-90 वर्ष के लिए प्रस्ताव

उत्तर—राजस्थान का अंश

(करोड़ रु. में)

1. आयकर में हिस्सा	4.773% तथा 4.775% (सिद्धि सहित) (सिद्धि के बिना)	142.8
2. 40% उत्पादन शुल्क में हिस्सा	5.097%	326.7
3. 5% घाटे के राज्यों को दो जाने वाली उत्पादन शुल्क की राशि में हिस्सा	3.946%	31.6
4. बिनाकर की एवज में प्रति-रिक्त उत्पादन शुल्क (बग्घा, चीनी व तम्बाकू)	4.636%	69.1
5. रेल यात्री किराये पर निरस्त कर की एवज में अनुदान में हिस्सा	4.772%	4.5
गैर-योजना अनुदान (Non-Plan Grants)		
(i) राहत-संच की वित्त-अवस्था के लिए सीमान्त-राशि (margin money)	16.75 (करोड़ रुपये का आधा)	8.4
(ii) राजस्व-घाटे की पूर्ति के लिए सहायता-अनुदान		38.8
(iii) स्टेण्डर्ड ऊंचे करने के लिए सहायता-अनुदान (upgradation)		6.1
(iv) विशेष समस्याओं के लिए		23.4
कुल (लगभग)		651.3

केन्द्र से राज्यों की तरफ कुल हस्तान्तरण की राशि 13662 करोड़ रु अनुमानित है जिसमें राजस्थान का अंश 477% रखा गया है। के० वे० जॉर्ज के एक अध्ययन से पता चलता है कि नवे वित्त आयोग की सिफारिशों से कम ग्रामदनी वाले राज्य जैसे बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत घाटे में रहे हैं, और यही व सम्पन्न राज्यों को अधिक वित्तीय साधन हस्तान्तरित हुए हैं। इस आयोग ने जो 'इकोनोमेट्रिक मॉडल' अपनाया है उसमें गम्भीर गलती रह गई है। अतः संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

'निर्धनता' का आधार सने से महाराष्ट्र जैसे राज्य ही पायदे में रहे हैं, जहाँ निर्धनो व गरीबी बस्ती के नियामितियों का सर्वेक्षण अधिक है। आयोग ने 'आदर्शात्मक दृष्टिकोण' को लागू करने के लिए जिस गणितीय मॉडल के आधार पर विभिन्न राज्यों की राजस्व आय व राजस्व-व्यय के 1989-90 के लिए अनुमान तैयार किये हैं, वे वास्तविकता से बहुत दूर लगते हैं जिससे साधनों के राज्यवार आवंटन पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

परिशिष्ट-3

चुने हुए आंकड़े (Selected Data)

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय व राजस्थानी अर्थव्यवस्था पर एक पाठ्य-पुस्तक है। अतः इसमें आंकड़ों की कई तालिकाएँ दी गयी हैं। पाठको से यह प्रवेक्षा नहीं की जानी कि वे उन्हें याद करें। अध्ययन के समय तालिकाएँ सामने रहती हैं एवं उनके आधार पर प्रमुख निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पाठको को उनमें से अपने काम के इसके-दुबके आंकड़े छांटने का सही प्रभ्यास अवश्य होना चाहिए।

विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रश्नोत्तर लिखते समय आंकड़ों के सम्बन्ध में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके मार्ग-दर्शन के लिए तथा उनकी असुविधा को दूर करने के लिए यहाँ चुने हुए आंकड़े एक ही जगह दिये जाते हैं जिन पर विशेष ध्यान देना उपयोगी रहेगा। अधिकांश आंकड़े भारत सरकार के Economic Survey 1988-89, Seventh Five Year Plan 1985-90 (Mid-Term Appraisal), 1988 तथा राजस्थान के आर्थिक अध्ययन, 1989-90 से संकलित किये गये हैं।

विद्यार्थियों को आंकड़े देते समय उनकी अवधि, मात्रा, सस्यता तथा इकाई का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी मिलियन, लाख व करोड़ का उपयोग सही सही नहीं करते, जिससे उन्हें ऊँचे अंक प्राप्त करने में कठिनाई हो जाती है तथा उनके उत्तरों में गम्भीर दोष उत्पन्न हो जाता है। यह स्मरण रखना होगा कि आंकड़ों की पूरी तालिकाएँ देने की बजाय चुने हुए महत्वपूर्ण आंकड़े ही पर्याप्त रहने हैं। पूरी तालिकाएँ देना न तो सम्भव है और न आवश्यक ही। परीक्षा में नकल करके आंकड़ों की तालिकाएँ देने से कोई लाभ नहीं क्योंकि उससे परीक्षक के मन में संदेह बढ़ता है। उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए चुने हुए, सही व सुनिश्चित आंकड़ों को ही पर्याप्त माना जाता है।

बहुधा विद्यार्थी यह निश्चित नहीं कर पाते कि अपने प्रश्न के उत्तर में वे कौन-से आंकड़े दें तथा कौन से न दें। इस सम्बन्ध में 'सामान्य बुद्धि' (Common-sense) से काम लेने पर आवश्यक आंकड़ों का आसानी से चयन किया जा सकता है। जैसे—अर्थ-शक्ति का वर्णन करते समय यह बताया जाना चाहिए कि भारत में

श्रम-शक्ति जनसह्या का जितना प्रतिशत है, तथा नई पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कितने लोग श्रम-शक्ति में शामिल थे, इत्यादि। इसी प्रकार जनसह्या-नियन्त्रण व परिवार-नियोजन के विवेचन में जन्म-दर व मृत्यु-दर का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए।

योजना-काल में आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते समय राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि-दर (स्विपर भावो पर), खाद्यान्नों के उत्पादन, इस्पात, कोयला, इंधन तेल सीमेन्ट विद्युत उधरक सिंचाई आदि से सम्बन्धित प्रमुख मॉडिओ का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए।

सुलना की दृष्टि से प्रतिशतों एवं अनुपातों का उपयोग करना बहुत मासान व लाभकारी होता है। अतः हम प्रमुख आँकड़ों का उल्लेख करते हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन—1950-51 में 5 1/2 करोड़ टन में बढ़कर 1987-88 में लगभग 13 8 करोड़ टन हो गया। 1988-89 में खाद्यान्नों का उत्पादन अनुकूल मौसम के कारण सम्भवतः 17 करोड़ टन से भी अधिक रहेगा।

दालों का उत्पादन—1955-56 में 1 2 करोड़ टन तथा 1987-88 में 1 10 करोड़ टन। अतः इनके उत्पादन में गतिहीनता अथवा स्थिरता की दशा रही है। 1985-86 में दालों का उत्पादन 1 34 करोड़ टन हुआ था।

HYV का क्षेत्रफल 1970-71 में 1 54 करोड़ हैक्टेयर में बढ़कर 1987-88 में लगभग 5 1 करोड़ हैक्टेयर हो गया। 1987-88 में सिंचित क्षेत्रफल 6 63 करोड़ हैक्टेयर था जिसमें 2 70 करोड़ हैक्टेयर में बड़े व मध्यम साधनों से तथा 3 93 करोड़ हैक्टेयर में लघु साधनों से सिंचाई की गई। तीनों प्रकार की रासायनिक खादों (NPK) का उपयोग 1970-71 में 21 8 लाख टन में बढ़कर 1987-88 में 90 लाख टन हो गया।

खाद्यान्नों का शुद्ध आयात—1966 में 1 करोड़ टन, 1978 से 1980 तक ऋणात्मक (Negative) आयात, अर्थात् आयात से निर्यात अधिक। 1983 में 40 7 लाख टन तथा 1984 में 23 7 लाख टन आयात किये गये। देश की खाद्य-स्थिति में सुधार होने से 1985 में आयात पुनः 3 5 लाख टन तथा 1986 एवं 1987 में भी मामूली ऋणात्मक (Negative) रहे। 1988 में खाद्यान्नों का आयात 18 7 लाख टन हुआ है।

सरकारी खरीद (Procurement)—1987 में लगभग 1 6 करोड़ टन तथा 1988 में 1 4 करोड़ टन। इन्हीं वर्षों में सार्वजनिक वितरण की मात्रा प्रतिवर्ष 1 8 करोड़ टन रही (काम के बदले अनाज की मात्रा शामिल करने)।

कृषिगत उत्पादन में वृद्धि दर—

(विद्यमान वर्ष की तुलना में)

(प्रतिशत में)

भागी उत्तार-चढ़ाव, जैसे

1979-80 में (—) 15.2

1980-81 में (+) 15.6

1984-85 में (+) 1.2

1985-86 में (+) 2.4

1986-87 में (—) 3.7

1987-88 में (—) 2.1

1988-89 में (+) 23 (RBI वार्षिक रिपोर्ट)

जनसंख्या, धन-शक्ति आदि—1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68.5 करोड़ व्यक्ति है। 1971-81 की अवधि में जनसंख्या में 25% वृद्धि हुई। 1989 में जनसंख्या लगभग 8. करोड़ मानी जा सकती है जो 1951 की तुलना में दुगुनी से अधिक है। धन, जनसंख्या की दृष्टि से योजनाकाल में 'एक नए भारत' का निर्माण और हो गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 के प्रतिवेदन के अनुसार मार्च 1985 में सामान्य स्टेटस के अनुसार अम-शक्ति 5 वर्ष व अधिक की आयु में 30.5 करोड़ व्यक्ति थी, जिसके मार्च 1990 में 34.5 करोड़ व्यक्ति (वार्षिक वृद्धि दर 2.46%) हो जाने का अनुमान है। धन-शक्ति के अनुसार 15 वर्ष व अधिक की आयु के लिए तथा 12-59 वर्ष के आयु-समूह के लिए भी प्रस्तुत किए गये हैं। 1971 में धन-शक्ति का 72.1% कृषि व सहायक क्रियाओं में समान था, तथा 10 प्रतिशत विनिर्माण व खनन में समान था। 1981 की जनगणना के अनुसार कृषि व सहायक क्रियाओं का अंश 58.8% तथा विनिर्माण व खनन का 11.9% हो गया था। जन-शक्ति 1978 में 33.3 प्रति हजार हो गयी थी। 1978 में मृत्यु-दर 14.2 प्रति हजार थी, तथा जनसंख्या की वृद्धि-दर 19 प्रति हजार थी, अर्थात् 1.9 % थी।

मार्च 1985 में बेरोजगारी की मात्रा (सामान्य स्टेटस के अनुसार), अर्थात् वर्गमर की बेरोजगारी की मात्रा 92 लाख व्यक्ति थी जिसमें लगभग 50 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 42 लाख शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार थे।

1977-78 में देश में धन-शक्ति का 8.2 प्रतिशत बेरोजगारी का शिकार था। केन्द्रीय मंद् 25.7 प्रतिशत था। इसके बेरोजगार व्यक्ति चार राज्यों (अमिनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल व महाराष्ट्र) में थे।

औद्योगिक वित्त—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) ने 1987-88 (बुर्ग-78) में लगभग 351 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता मंजूर की तथा 730

करोड़ रु. की वितरित की। 1948-1988 के 40 वर्षों में स्वीकृत सहायता = 5,306 करोड़ रु. तथा वितरित की गयी राशि = 3,612 करोड़ रु. रही।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 1988-89 (जुलाई-जून) में स्वीकृत सहायता = 4,747 करोड़ रु. तथा वितरित सहायता = 3,381 करोड़ रु. रही। 1964-89 के 25 वर्षों में स्वीकृत सहायता = 34,400 करोड़ रु. तथा वितरित राशि = 25,112 करोड़ रु. रही (गारंटियों सहित)

मजदूर संघों की स्थिति—31 दिसम्बर 1980 को भारत में मजदूर-संघों की सत्यापित सदस्यता (Verified membership) 61.3 लाख थी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) की सदस्य संख्या 22 लाख 36 हजार सर्वाधिक थी तथा दूसरे नम्बर पर भारतीय मजदूर संघ था, जिसकी सदस्य संख्या 12 लाख 11 हजार थी।

विदेशी व्यापार

व्यापार का घाटा (Trade deficit) : (करोड़ रु. में)

1980-81	5838	छठी योजना (1980-85)
1985-86	8763	में कुल व्यापार का घाटा
1986-87	7748	= 28581 करोड़ रु.
1987-88	6658	अथवा 285.8 अरब रुपये
1988-89	7412	

(करोड़ रु.)

वर्ष	आयात	निर्यात
1987-88	22199	15741
1988-89	27693	20281

जनवरी 1989 को विदेशी विनिमय कोष (स्वर्ण, स्पेशल ड्राइंग राइट्स व विदेशी विनिमय परिसम्पत्तियों सहित) = 5967 करोड़ रु. (वर्तमान में केवल 3 1/2 महीने के आयात के साधक)

अगस्त 1989 तक लगभग 2000 करोड़ रु. की गिरावट (मार्च 1989 की तुलना में)

1987-88 की अवधि में भारत के चार प्रमुख आयात (करोड़ रु. में)

(1) पूँजीगत माल	= 6285
(2) पेट्रोल पेट्रोल-पदार्थ व सम्बद्ध माल	= 4083
(3) मोती कीमती व अर्द्ध कीमती स्टोन्स	= 1994
(4) लोहा व इस्पात	= 1273

1987-88 में भारत के चार प्रमुख निर्यात (करोड़ रु. में) (कूड़ तेल के अलावा)

(1) दस्तकारी का माल	= 3253
(2) रेडीमेड पोशाकें	= 1792

(3) इन्व्हीनियरी का माल = 1433

(4) चमड़ा व चमड़े के सामान = 1149

विदेशी सहायता—मार्च 1988 तक प्रयुक्त विदेशी सहायता की राशि 42,347 करोड़ रु

ऋण-सेवा-राशि (मूलधन + व्याज) 1988-89 = 2770 करोड़ रु । 1987-88 में ऋण-सेवा भुगतान चालू प्राप्तियों (current receipts) का 24% जो कुछ विद्वानों के अनुसार अब 30% हो गया है । भारत विदेशी कर्ज के जाल में फँसता जा रहा है । ऋण-सेवा राशि की सुरक्षित सीमा 20% मानी गई है ।

राष्ट्रीय आय तथा योजना में आर्थिक प्रगति

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति 19 0-51 = 16731 करोड़ रु. { (1970-71 के मूल्यों पर) }
(साधन लागत पर) 1985-86 = 60143 करोड़ रु { (3.6 गुनी)

प्रति व्यक्ति आय 1950-51 = 466.0 रुपये }
1985-86 = 797.7 रुपये }

1950-51 से 1985-86 के बीच NNP की वार्षिक वृद्धि-दर 3.6% } (स्थिर
प्रति व्यक्ति NNP 1.5% } मूल्यों पर)

विकास की वार्षिक दर—(1970-71 के मूल्यों पर) साधन-लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति का परिवर्तन (प्रतिशत में)

योजनाओं में प्राप्त विकास की वार्षिक दरें—

विभिन्न योजनाएँ

I	II	III	वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	IV	V	1979-80	VI	VII
							(1981-85)	(सक्षय)
3.6	4.0	2.2	4.0	3.4	5.2	(-) 5.2	4.9	5.0

1980-81 के भाषों पर

1985-86 5.0

1986-87 3.6

1987-88 3.4

1988-89 10.0 (RBI वार्षिक रिपोर्ट)

सर्वाधिक विकास की वार्षिक दर पाँचवी योजना की अवधि में 5.2% रही तथा न्यूनतम तृतीय योजना (1961-66) की अवधि में 2.2% रही । सातवी योजना में 5.4% पाँकी गई है ।

राजस्थान का आर्थिक विकास¹

1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 3.43 करोड़ व्यक्ति ।

(लाख टन में)

खाद्यान्नों का उत्पादन

1983-84	100.8
1984-85	79.1
1985-86	81.3
1986-87	67.9
1987-88	48.0
1988-89	100.75

सकल सिंचित भूमि 1986-87 में 43.5 लाख हेक्टर, कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 24%, 1989 के मध्य में विद्युत की प्रस्तापित क्षमता = लगभग 2500 मेगावाट, रेक्टिफाई फंक्शनों की संख्या, 1987 में = 10512 इनमें रोजगार = 2.36 लाख व्यक्ति ।

औद्योगिक उत्पादन	वर्ष (1988)
1. सीमेंट	40.3 लाख टन
2. चीनी	5 हजार टन
3. बाल विस्फुरक	13.9 लाख इकाई
4. नमक	10.4 लाख टन
5. विद्युत मीटर	8.7 लाख इकाई
राज्य की आय (State Income)	(1970-71 के मावों पर)

	1970-71	1986-87	1987-88
1 राज्य की आय (करोड़ रुपये में)	1654	2524	2383
2 प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)	651	634	583

स्विर मावों पर छठी पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 6.9% (गोपनीय GDP के आधार पर) सालाना रही । 1979-80 का आधार-वर्ष चयन होने में छठी योजना में विकास की दर इतनी ऊँची हो सकी है ।

1. स्रोत—आय-व्यय अध्ययन 1989-90 (आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर, मार्च 1989, तथा इसी की दस वार्षिक प्रगति-विवरण (1977-87) के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की तालिकाएँ ।

**राज्य की योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में
वास्तविक व्यय की राशियाँ
(करोड़ रुपये में)**

I	II	III	वार्षिक योजनाएँ	IV	V
54	103	213	137	309	858
1979-80 (वार्षिक योजना) 290	VI 2031	VII (प्रस्तावित) 3000	1985-88 1600	1988-89 710	1989-90 (प्रस्तावित) 795

31 मार्च 1989 को राजस्थान पर बकाया कर्ज की राशि

= 4569 करोड़ रु.

केन्द्रीय कर्ज की बकाया राशि = 2889 करोड़ रु

पिछले वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज की शुद्ध राशि ऋणात्मक (negative) रही, यवान् जितनी राशि कर्ज के रूप में मिली उससे अधिक राशि मूलधन व व्याज के रूप में चुकानी पड़ी।

निर्धनता-अनुपात में परिवर्तन (ग्रामीण) प्रतिशत में

	1977-78	1983-84
1 राजस्थान	33.5	36.6
2 बिहार	57.8	51.4
3 उत्तर प्रदेश	50.0	46.5
4 समस्त भारत	51.2	40.4

स्रोत CH Hanumantha Rao, *Changes in Rural Poverty in India* Mainstream January 11 1986)

राजस्थान में निर्धनता अनुपात बड़ा जबकि अन्य सभी राज्यों तथा देश में घटा है।

के सुदूरम में अध्ययन के अनुसार

राजस्थान में 1983 में दम्पतियों का वह अनुपात जो प्रभावपूर्ण तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सका था (effectively protected)

महान, जो परिवार-नियोजन के उपाय अपना रहा था = 15.7%

2000 में सम्भावित = 31%

2000 में सभी राज्यों के लिए लक्ष्य = 60%

अतः वर्षे 2000 में भी राजस्थान में परिवार-नियोजन अपनाते वाले सम्पत्तियों का प्रतिशत कम ही रहेगा। राजस्थान में परिवार-नियोजन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

1981 में राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का अनुपात 5½% रहा जो एक चिंता का विषय है।

राज्य सरकार की नई आर्थिक नीतियाँ

आधार—आधुनिकीकरण, नई टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने का उत्पादन, लाइसेंस नीति, वस्त्र-नीति व त्रिवर्षीय आयात-नीति में उदारता। नई कम्प्यूटर नीति, नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, नई वस्त्र नीति, आदि का भूराय कार्यक्रमल औद्योगिक उत्पादन व निर्यात-वृद्धि की ओर, प्रत्यक्ष करों में कमी। नई दीर्घकालीन राजकोपीय नीति, नई वृद्धिगत नीति आदि की घोषणा।

1990 के बाद वार्षिक अन्व-वृद्धि की वृद्धि = लगभग 1 करोड़ धरति।

आर्थिक सलाहकार परिषद् (Economic Advisory Council)

8 जुलाई, 1988 का पुनर्गठित EAC के सदस्य इस प्रकार हैं :

- 1 प्रोफेसर सुलमोय चत्रवर्ती (अध्यक्ष)
 - 2 डा. के. एन. राज
 - 3 डा. एस. एम. जोहल (S. S. Jhal)
 4. डा. सी. चमराजन (उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक)
 - 5 डा. किरित पारीग
- (इसमें योजना-आयोग से कोई सदस्य नहीं लिया गया है।)
- डा. एम. आर. शाशिम परिषद् के सचिव होंगे।

डा. चत्रवर्ती की स्टेट्स राज्य-स्तर के मंत्री की होंगी। पुनर्गठित परिषद् का कार्यकाल 2 वर्ष का रखा गया है।

माननीय पंचवर्षीय योजना के 'भोजन काम व उत्पादनता' (food, work and productivity) पर जोर, बिनाम की वार्षिक दर का लक्ष्य लगभग 5%, मार्गजनित्र क्षेत्र में परिवर्धन की राशि छोटी योजना में काफी अधिक, निर्धनता, बेरोजगारी आदि को हल करने के प्रयास, 1994-95 तक निर्धनता की रेखा में नीचे के व्यक्तियों का अनुपात 10% से कम करने का लक्ष्य, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (NEP) पर विशेष बल। योजना के लिए वित्तीय माधनों का संकट, बढ़ते व्यापार के घाटे के कारण अविष्य में विदेशी मुद्रातन् की सम्मीर समस्या की सम्मा-

वना विदेशी सहायता के क्षेत्र में अनिश्चितता, शीघ्र व कुशल आयात-प्रतिस्थापन व निर्यात-संवर्द्धन की आवश्यकता। देश के आर्थिक विकास पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का बढ़ता हुआ प्रभाव। जापान, पश्चिमी जर्मनी व सोवियत संघ से उदार शर्तों पर सहायता प्राप्त।

2 अगस्त, 1988 से भारतीय योजना आयोग के सदस्य—

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी—अध्यक्ष

श्री साधुबोसिह सोलंकी, उपाध्यक्ष व योजना एवं प्रोग्राम क्रियान्वयन मंत्री अन्य सदस्य इस प्रकार हैं—

मन्त्री-सदस्य (Ministerial members)

1. वित्त मंत्री श्री एस. बी. चन्हाण

2. कृषि-मंत्री श्री भजनलाल

3. ऊर्जा-मंत्री श्री वसन्त साठे

4. उद्योग-मंत्री श्री जे. वेंगलराव

5. मानवीय संसाधन विकास मंत्री श्री पी. शिवशंकर

6. कानून, न्याय व जल-साधन मंत्री श्री बी. शंकरानन्द

7. पर्यावरण व वानिकी मंत्री श्री जेड. धार. धन्सारी

8. नियोजन व प्रोग्राम क्रियान्वयन राज्य मंत्री श्री बिरेनसिंह

एण्टी (Engti)

पूर्णकालिक सदस्य (Full time members)

1. प्रोफेसर एम. जी. के. मेनन

2. डा. राजा जे. चेल्सैमा

3. श्री आबिद हुसैन

4. श्री हितेन भाया

5. डा. वाई. के. मलिक तथा

6. प्रोफेसर पी. एन श्रीवास्तव।

7. श्री जे. एस. वेंजल (सदस्य-सचिव)

इस प्रकार उपर्युक्त सूची के अनुसार पुनर्गठित योजना आयोग में अध्यक्ष व सदस्य-सचिव सहित कुल 17 सदस्य हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के दृष्टिकोण-प्रपत्र (Approach-paper) के प्रमुख तथ्य—

विकास की वार्षिक दर कम से कम 6%

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय की राशि = 350000 करोड़ रु (1989-90 के मूल्यों पर)

रोजगार में वृद्धि-दर = 3% सालाना
 निर्यात वृद्धि-दर = 12%, मात्रा (Volume) के रूप में,
 बढ़ा हुआ पूँजी-उत्पत्ति अनुपात (ICOR)
 4.3 से घटकर 4.15
 वृद्धि GDP का 21.1% से बढ़कर 23.3%
 निर्यात-अनुपात = 18% आठवी योजना के अंत में
 प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि
 वर्तमान स्तर = 175 किलो वार्षिक
 1994-95 में = 195 " "
 (स्रोत : The Economic Times September 2, 1989)

(9) Sukhamoy Chakravarty, **Development Planning : The Indian Experience** 1987

(10) एल एन. नाथूरामबा, भारतीय अर्थशास्त्र, 23 वा सस्करण
सितम्बर, 1989 (लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, हॉस्पिटल रोड आगरा)

(B) रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि—

(1) World Development Report, 1989 (for various economic indicators relating to India) (o u p)

(2) Eighth Five year plan—Approach Paper August 1989.

(3) First Report of the Ninth Finance Commission July 1988

(4) Economic Survey (1988-89) (Ministry of Finance (Economic Division)

(5) Budget Study 1989-90 (DES, Raj, Jaipur) March, 1989

(6) Some Facts about Rajasthan, 1987 (DES)

(7) High power committee Report on Strategy for Industrial Development In Eighth Five Year Plan, Vol. I and Vol II (both) (Prof M V Mathur—Chairman) June, 1989

(8) S K Bhargava, A Note on Perspective For Eighth Five year Plan (Raj) (DES, Jaipur) 1989

(C) लेख—

(1) V M Dandekar, Agriculture, Employment and Poverty, EPW, September 20-27, 1986

(2) Prabhat Patnaik, Recent Growth Experience of the Indian Economy, Some Comments EPW, Annual Number 1987, (published in December, 1987)

(3) Deepak Nayyar, India's Export Performance 1970-85 Underlying Factors and Constraints EPW, Annual Number, 1987.

- (4) D.T. Lakdawala, Decentralised Planning must be given a fair trial, *The Economic times Mid—week Review*, Approach to Eighth Plan, July 6, 1989.
 - (5) S. P. Gupta, Growth Target for VIII Plan, *Financial Express*, August 7, 1989 (very good article on constraints to high economic growth)
 - (6) *The State and Development Planning in India*, edited by Terry Byres, (to be published in 1990) (London Conference papers, Particularly by Ajit Mazoomdar, Prabhat Patnaik & Vijay Joshi and IMD title
-